



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 9, 1991/माघ 20, 1912

No. 6]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 9, 1991/MAGHA 20, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं  
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India other than  
the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1991

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 18th January, 1991

का.आ. 406—केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973  
(1974 का 2) की धारा 21 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों  
का प्रयोग करते हुए, श्री बी.एल. काला, अधिवक्ता, दिल्ली को रणजीत  
सिंह और अन्य के विरुद्ध दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा संचालित मामला  
आर सी सी 2/80 सी आई ए (ए)/सी बी आई. के. जा मंशन  
न्यायालय/दिल्ली विचारण न्यायालय में लम्बित है और दिल्ली मध्य राज्य  
क्षेत्र में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण या अपील न्यायालयों में उम्मी मामलों  
में उद्भूत अपील, पुनरीक्षण आवेदन या अन्य मामलों के अभियोजन  
के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

S.O. 406.—In exercise of the powers conferred by sub-  
section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure,  
1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints  
Shri B. L. Kala, Advocate, Delhi as Special Public Prosecu-  
tor for conducting the prosecution of the case being RC-2/  
80 CIU(A)/CBI, instigated by the Delhi Special Police Estab-  
lishment against Sh. Ranjit Singh and others, pending in  
Sessions Court/Trial Court Delhi and appeals, revisions or  
other matters arising out of the same case in revisional or  
appellate courts, established by the law in Union Territory  
of Delhi.

[संख्या 225/41/86-ए की डी -II]

[No. 225/41/86-AVD II]

का आ. 407 :—केन्द्रीय सरकार, बंड प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा पदम शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एन. एस. माथुर, अधिवक्ता, दिल्ली को रणजीत सिंह और अन्य के विरुद्ध दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा संचालित मामला आर.सी.सं. 2/80 सी.आई.यू. (ए)/सी.बी.आई. के, नो सेशन न्यायालय/दिल्ली विचारण न्यायालय में लम्बित है और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में बिधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण या अपील न्यायालयों में उसी मामले से उद्भूत अपील, पुनरीक्षण आश्रयों या अन्य मामलों के अभियोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[संख्या 225/2/84-ए वी.डी.-II]

S.O. 407.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri N. S. Mathur, Advocate, Delhi as Special Public Prosecutor for conducting the prosecution of the case being RC 2/80-CIU(A)/CBI, instituted by the Delhi Special Police Establishment against Shri Ranjit Singh and others, pending in Sessions Court/Trial Court Delhi and appeals, revisions or other matters arising out of the same case in revisional or appellate courts, established by the law in Union Territory of Delhi.

[No. 225/2/84-AVD-II]

आदेश

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1991

का. आ. 408 :—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम संख्या 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य सरकार की सहमति से (अधिसूचना संख्या 3/सी. 4-10197/90-एच(पी), दिनांक 15-10-90 दिल्ली) विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार निम्नलिखित अपराधों के अन्वेषण के लिए संपूर्ण बिहार राज्य पर करती है।

(क) कांड संख्या 55/90, दिनांक 8-5-90, भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम संख्या 45) की धारा 379 के अधीन, धनबाद रेलवे पुलिस थाना से संबंधित।

(ख) उपर्युक्त मामला कांड संख्या 55/90, दिनांक 8-6-90 के संबंध में ऊपर उल्लिखित एक या अधिक अपराधों और उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गये किसी अन्य अपराध या किसी अपराधों के बारे में संसक्त प्रवृत्त बुद्धि और पर्यवेक्षण।

[संख्या 228/43/90-ए.वी.डी.-I I]

ए.सी. शर्मा, अवसर सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd January, 1991

S.O. 408.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946), the Central Government, with the consent of the State Government of Bihar vide Order No. 3/C4-10197/90 H(P) dated 6-10-90 hereby extends the powers and jurisdiction of the Members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Bihar for investigation of the following offences, namely:—

- (a) Offences punishable under Section 379 of the Indian Penal Code (45 of 1860) in regard to theft of ammunitions from Military Special Goods Train on June 8, 1990 relating to the case No. 55/90 dated 8-6-90 registered at Railway Police Station, Dhanbad (Bihar).
- (b) Attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with one or more of the offences mentioned above and any other offence or offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228/43/90-AVD-II]

A. C. SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 91

का. आ. 409 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परस्पर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय संपरीक्षा तथा लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक महा लेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में—

(I) नियम 3 के उपनियम (1) में,—

(1) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ग)” “महगाई राहत” से नियम 55क में यथा परिभाषित राहत अभिप्रेत है :—

(II) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्

“(च) “कुटुम्ब पेंशन” से नियम 54 के अधीन अनुज्ञेय “कुटुम्ब-पेंशन, 1964” अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत महगाई राहत नहीं है”;

(III) खंड (ण) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात् :—

“(ण) “पेंशन” के अन्तर्गत तब के सिवाय उपदान आता है जब पेंशन शब्द का प्रयोग उपदान से भिन्नता सूचित करने के लिए किया जाता है किन्तु इसके अन्तर्गत महगाई राहत नहीं है”।

(2) नियम 55 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“55क. पेंशन कुटुम्ब पेंशन पर महगाई राहत

(i) कीमत वृद्धि के लिए राहत पेंशन भोगियों और कुटुम्ब पेंशन भोगियों को महगाई राहत के रूप में ऐसी वरी पर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए दी जा सकेगी जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर विनिश्चित करें।

(ii) यदि कोई पेंशनभोगी केन्द्रीय या राज्य सरकार या भारत या विदेश में उनके अधीन किसी निगम/कंपनी/नियामक/बैंक के अधीन पुनः नियोजित है जिसके अन्तर्गत ऐसे निगम/कंपनी

निकाय/बैंक में स्थायी शामिल भी है, तो यह ऐसे पुनःनियोजन की अवधि के दौरान पेशन या कुटुम्ब पेशन पर मंहगाई राहत प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

- (iii) केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारी जो नियम 37 के निबंधानुसार स्थायी रूप से शामिल हो जाते हैं और जो नियम 37क के निबंधानुसार अनुपातत मासिक पेशन के स्थान पर एक मुश्त रकम के संदाय का विकल्प देते हैं, मंहगाई राहत के लिए पात्र नहीं होंगे।

(3) नियम 72 में—

- (i) उपनियम (4) में, "दो मास" शब्दों के स्थान पर, "चार मास" शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) उपनियम (6) में, "दो मास" शब्दों के स्थान पर, "चार मास" शब्द रखे जाएंगे; और
- (ख) "संपदा निदेशालय की जिम्मेवारी होगी" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

"ऐसी किसी रकम को जो सेवानिवृत्ति के पश्चात् चार मास से अधिक सरकारी आवास रखने के लिए अनुज्ञप्ति फीम के भुद्धे शोध्य हो गई है और जो अंगदान है, पेशनभोगी की सहमति के बिना, मंहगाई राहत से सम्पदा निदेशालय द्वारा सम्बद्ध लेखा अधिकारी की मार्फत वसूल किए जाने का आदेश दिया जा सकेगा। ऐसे मामलों में किसी मंहगाई राहत का संवितरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे शोध्यों की पूर्ण वसूली न कर ली गई हो।"

[सं. 42(30)-पी.एण्डपी.डब्ल्यू./80-ई.]

स्वर्ण दास, उप सचिव

टिप्पण :—केन्द्रीय सिविल सेवा पेशन नियम, 1972 का प्रा. स. 934, तारीख 1-4-1972 के रूप में प्रकाशित किए गए थे। इन नियमों का चौथा संस्करण (जुलाई, 1988 तक संशोधित) 1988 में प्रकाशित किया गया था। ये नियम पेशन और पेशनभोगी कल्याण विभाग की वर्णित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे:—

New Delhi, the 22nd January, 1991

S.O. 409.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) Amendment Rules, 1991.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Pension Rules, 1972,—

(1) In sub-rule (1) of rule 3,—

(i) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

"(cc) 'dearness relief' means relief as defined in rule 55 A;"

(ii) for clause (f) the following clause shall be substituted, namely:—

"'family pension' means 'family pension, 1964' admissible under rule 54 but does not include dearness relief;"

(iii) for clause (o) the following clause shall be substituted, namely:—

"(o) 'Pension' includes gratuity except when term pension is used in contradistinction gratuity but does not include dearness relief,"

(2) after rule 55, the following rule shall be inserted, namely:—

"55A. DEARNESS RELIEF ON PENSION/FAMILY PENSION

(i) Relief against price rise may be granted to the pensioners and family pensioners in the form of dearness relief at such rates and subject to such conditions as the Central Government may specify from time to time.

(ii) If a pensioner is re-employed under the Central or State Government or a corporation/company/body/bank under them in India or abroad including permanent absorption in such corporation/company/body/bank, he shall not be eligible to draw dearness relief on pension/family pension during the period of such re-employment.

(iii) The Central Government employees who get permanently absorbed in terms of rule 37 and opt for lumpsum payment in lieu of pro-rata monthly pension in terms of rule 37, shall not be eligible for dearness relief."

(3) In rule 72,—

(i) in sub-rule (4), for the words "two months" the words "four months" shall be substituted;

(ii) (a) in sub-rule (6) for the words "two months, the words "four months" shall be substituted; and

(b) after the word "Estate" the following shall be added, namely:—

"Any amount becoming due on account of licence fee for retention of Government accommodation beyond four months after retirement and remaining unpaid may be ordered to be recovered by the Directorate of Estates through the concerned Accounts Officer from the dearness relief without the consent of the pensioner. In such cases no dearness relief shall be disturbed until full recovery of such dues have been made."

[No. 42(30)-P&PW/89-E]

SWARN DAS, Dy. Secy.

Note:—The Central Civil Services Rules, 1972 were published under office order No. 934 dated 1-4-1972. The fourth edition of these rules (amended upto July 1988) published during 1988. These rules were amended under the notification of Pension and Pensionary Welfare Department.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वैकिक प्रभाग)

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1991

का.आ.410 :—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिशों पर, एनद्वादा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबन्ध पंजाब एण्ड सिंध बैंक पर अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए, जहाँ तक उनका संबंध गिरवीदार के रूप में भौमसे डाइनामिक फोर्जिस इंडिया लिमिटेड के शेयरों को अपने पास रखने से है, लागू नहीं होंगे।

[सं. 15/12/90-वी.प्रो.-III]

प्राण नाथ, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 22nd January, 1991

S.O. 410.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act shall not apply to Punjab & Sind Bank for a period of two years from the date of notification, insofar as they relate to its holding of the shares of M/s. Dynamatic Forgings India Limited as pledgee.

[No. 15/12/90-B.O.-III]

PRAN NATH, Under Secy.

समाहृतिय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, मध्य प्रदेश

अधिसूचना संख्या 229/1990

इन्दौर, 31 दिसम्बर, 1990

का.आ.411 :—समाहृतिय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इन्दौर के श्री मोहनलाल (अनु.जनजाति), अधीक्षक, समूह "ख", निवृत्त आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30-11-1990 (अपराह्ण) को गामकीय सेवा से निवृत्त हो गये।

[फा. सं. II(3)8-मोप/89/30]

बालकृष्ण अग्रवाल, समाहर्ता

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE, M.P.

NOTIFICATION NO. 229/1990

Indore, the 31st December, 1990

S.O. 411.—Shri Mohanlal (ST), Superintendent, Central Excise Group 'B' of Indore Collectorate having attained the age of superannuation, retired from Government service on 30-11-90 (AN).

[F. No. II(3)8-Con/89/30]

B. K. AGARWAL, Collector

वार्णज्य मन्त्रालय

(मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1991

का.आ.412 :—मैमर्स श्री श्रीबराय टावर्स, 15-ए, नारीमन प्वाइन्ट, बम्बई, मार्फत ईस्ट इंडिया होटल्स लि. 7 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली को मानक अतिरिक्त उपसाधित, मयोजनों (सलगन सूची के अनुसार) के साथ हाउसकीपिंग मात्र सामान के आयात के लिए 2,85,000 रुपये (दो लाख पचासी हजार रुपये मात्र) लागत बीमा भाड़ा मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं. पीपी 1510252 सी/XX/13/एन/89/एम एल. एम. दिनांक 19-10-89 मजूर किया गया था। प्रार्थी ने मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति खो गई/गुम हो गई है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि मूल आयात लाइसेंस अनाइस्टिड बैंक आफ इंडिया जनपथ, नई दिल्ली में पंजीकृत था और उस पर 1,37,669 रुपये) एक लाख सैतिस हजार छ सौ उनहत्तर रुपये मात्र) लागत बीमा-भाड़ा मूल्य का उपयोग करना शेष था।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसहारी ने उपयुक्त न्यायिक प्राधिकारी के साथ विधिबद्ध रूप से गपथ तैरार एक शपथपत्र दाखिल किया

है। तदनुसार मैं सन्तुष्ट मैं कि मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति म पी/पी/1510252 दिनांक 19-10-89 आवेदक से खो गई है। समय-समय पर यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-56 की उपधारा 9(1) (घ) के अन्तर्गत प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैमर्स श्रीबराय टावर्स, 15ए, नारीमन प्वाइन्ट, बम्बई, मार्फत ईस्ट इंडिया होटल्स लि., 7-शाम नाथ मार्ग, दिल्ली को जारी की गई उक्त मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति की एतद्वारा रद्द किया जाता है।

3. मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति पार्टी को अलग से जारी की जा रही है।

[फा. सं. 18/256/89-90/एम.एल.एस.]

बी.आर. अहीर, उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात,

कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

## MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

## ORDER

New Delhi, the 24th January, 1991

S.O. 412.—M/s. The Oberoi Towers, 15-A, Nariman Point, Bombay C/O East India Hotels Ltd., 7, Sham Nath Marg, Delhi was granted an Import Licence No. P/P/1510252 C/XX/13/H/89/MLS dated 19-10-1989 for a c.i.f. value of Rs. 2,85,000 (Rupees Two Lakh, Eighty Five thousands only) for the import of house-keeping equipment with standard spares accessories, attachments (as per list attached). The applicant has applied for issue of duplicate Exchange Control Purposes Copy on the ground that the original Exchange Control Purposes Copy has been misplaced/lost. It is further stated that the Original Import Licence was registered with United Bank of India, Janpath, New Delhi and having a balance unutilised c.i.f. value of Rs. 1,37,669 (Rupees One Lakh, Thirty Seven thousands, Six hundred Sixty Nine only)

2. In support of their contention, the licensee have filed an affidavit duly sworn in before appropriate judicial authority. I am accordingly satisfied that the original Exchange Control Purposes Copy No. P/P/1510252 dt. 19-10-89 has been lost by the applicant. In exercise of the powers conferred under Sub Clause 9(1)(d) of the Import (Control) Order, 1955 dt. 7-12-56 as amended from time to time, the said Exchange Control Purposes Copy issued to M/s. The Oberoi Towers, 15-A, Nariman Point, Bombay C/o East India Hotels Ltd., 7, Sham Nath Marg, Delhi is hereby cancelled.

3 A duplicate copy of the Exchange Control Purposes Copy is being issued to the party separately.

[F. No. 18/256/89-90/MLS]

B. R. AHIR, Dy. Chief Controller of Imports &amp; Exports.

For Chief Controller of Imports and Exports

## MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 15th January, 1991

## CORRIGENDUM

S.O. 413.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 2143 dated the 18th July, 1990, published in the Gazette of India, part II, section 3, sub-section (ii) dated the 11th August, 1990 at pages 3612 to 3614,—

at page 3613, in the Schedule against serial number 7, in column Area in hectares for "3,080" read "3,000".

[No. 43015/8/90-LSW]

B. B. RAO, Under Secy.



## पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग)

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1991

का.भा. 414 :-पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ 1 में उल्लिखित प्राधिकारी को उक्त सारणी के स्तंभ में उनके सामने बनाये गये क्षेत्र के भीतर उक्त अधिनियम के तहत "सक्षम प्राधिकारी" के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

## सारणी

व्यक्ति का नाम	पता	क्षेत्राधिकार
1	2	3
विशेष तहसीलदार (भूमि अधिग्रहण) सेवा एवं प्राकृतिक गैस आयोग	पब्लिक आफिस रोड वेलिपालयम नागापट्टिनम तंजावूर जिला तमिलनाडु	समिलनाडु का सम्पूर्ण राज्य

[सं. ओ.-11021/8/89-ओ.एन.जी.जी.]

## MINISTRY OF PETROLEUM &amp; CHEMICALS

(Department of Petroleum and Natural Gas)

New Delhi the 21st January, 1991

S.O.414 —In pursuance of clause (a) of Section-2 of the Petroleum and Minerals Pipe Lines (Acquisition of Right of user in and) Act 1962 (50 of 1962) the Central Govt. hereby authorises the authority mentioned in Column 1 of the schedule below to perform the functions of the "COMPETENT AUTHORITY" under the said Act within the areas mentioned in the corresponding entry in the column 3 of the said schedule.

## SCHEDULE

Name of Person	Address	Territorial jurisdiction
1	2	3
Special Tahsildar (Land Acquisition) ONGC	Public Office Road Velipalayam Nagapattinam Thanjavur District Tamilnadu	State of whole Tamilnadu

[No. O-11021/8/89-ONG/D.-III]

## पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1991

का. भा. 415.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ओ. एन जी सी गैस टर्मिनल गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड रिसीबींग स्टेशन, अहमदनगर पेट्रोलियम परिवहन के लिए पाईपलाईन गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड सूत्र द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनुसूची में अंकित भूमि में उपयोग का अधि-कार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आदेश एतद्वारा घोषित किया है।

वर्तते कि उक्त भूमि में हिनबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप मध्यम अधिकारी सेवा तथा प्राकृतिक गैस आयोग, हजारा प्रोजेक्ट 60 मुवाय नगर सोसायटी, घोडदोड रोड गुरन को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति बिनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

## SCHEDULE

ओ. एन. जी. सी. गैस टर्मिनल से गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड रिसेविंग स्टेशन अडाजन तक पाईपलाइन बिछाने के लिए।

Pipeline from O.N.G.C. Gas Terminal to Gujarat Gas Company Limited Receiving station at Adajan.

राज्य गुजरात जिला सुरत तालुका -- चोरासी

State : Gujarat District : Surat Taluka : Chorasi

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	घर	प्रतिघर
भाटपोर	433	0	11	80
	434	0	16	20
	435	0	28	60
	438	0	11	20
	439	0	15	00
तापी नदी	0	62	80	
	477	0	01	50
	478	0	16	80
	480	0	01	92
	479	0	01	28
	481	0	16	00
	482	0	13	80
	495	0	17	92
	494	0	23	12
	497	0	34	57
	503	0	08	00
	504	0	90	00

Village	Block No.	H.	Are	Prati Arc
Bhatpore	433	0	11	80
	434	0	16	20
	435	0	28	60
	438	0	11	20
	439	0	15	00
Tapi River	0	62	80	
	477	0	01	50
	478	0	16	80
	480	0	01	92
	479	0	01	28
	481	0	16	00
	482	0	13	80
	495	0	17	92
	494	0	23	12
	497	0	34	56
	503	0	08	00
	504	0	90	00

[No. O-11027/184/90-ONG/D.III]

[सं. ओ.-11027/184/90-ओ. एन. जी./ओ.-III]

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS  
New Delhi, the 24th January, 1991

S.O. 415.—Where it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from O.N.G.C. Gas Terminal to Gujarat Gas Company Limited, Receiving Station at Adajan in Gujarat State, Pipeline should be laid by the Gujarat Gas Company Limited, Surat.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Hazira Project, 'Prahar', 60 Subhashnagar Society, Ghod-Dod Road, Surat.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

का. प्रा. 415:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ओ.एन.जी.सी. गैस टर्मिनल से गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड रिसेविंग स्टेशन अडाजन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईप लाइन गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड सुरत द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

आर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी जमीनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एन.एन.जी.सी. में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग होते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एन.एन.जी.सी. द्वारा घोषित किया है।

अतः कि उक्त भूमि में हित रख कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी तथा प्राकृतिक गैस आयोग, हजिरा प्रोजेक्ट 60 सुभाष नगर सोसायटी छोधदोड रोड, सुरत को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

श्री. एन. जी. सी. गैस टर्मिनल से गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड रिसिविंग स्टेशन अडाजन तक पाईपलाइन बिछाने के लिए।  
राज्य : गुजरात जिला : सूरत तालुका : चोरासी

गांव	सर्वेक्षण	हेक्टर	अ.रे	प्रतिआरे
अडाजन	तापी नदी	2	02	40
	708	0	12	00
	601	0	04	00
	600/ए	0	04	00
	सरकारी रोड	3	55	80

[सं. ओ.-11027/185/90-ओ. एन. जी. डी. III]

S.O. 416.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from O.N.G.C. Gas Terminal, Gujarat Gas Company Limited, Receiving Station at Adajan in Gujarat State, Pipeline should be laid by the Gujarat Gas Company Limited, Surat.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Hazira Project, "Prahar", 60 Subhashnagar Society, Ghod-Dod Road, Surat.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

## SCHEDULE

Pipeline from O.N.G.C. Gas Terminal to Gujarat Gas Company Limited, Receiving Station at Adajan.

State : Gujarat. District : Surat Taluka : Chorasi

Village	Survey No.	H.	Are.	Prati Are.
Adajan	Tapi River	2	02	40
	708	0	12	00
	601	0	04	00
	600/A	0	04	00
	Govt. Road	3	55	80

[No. O-11027/185/90-ONG.-D. III]

का. आ. 417.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में श्री. एन. जी. सी. गैस टर्मिनल से गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड रिसिविंग स्टेशन अडाजन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाइन गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड सूरत द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग हजिरा प्रोजेक्ट 60 सुभाष नगर सोसायटी घोंडदोड रोड, सूरत को इन अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा और ऐसा आक्षेप कहने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी बिधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

श्री. एन. जी. सी. गैस टर्मिनल से गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड रिसिविंग स्टेशन अडाजन तक पाईपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : सूरत : तालुका : चोरासी

गांव	सर्वेक्षण	हे.	आरे प्रति	आर
पाल	तापी नदी	4	07	60

[सं. ओ.-11027/186/90 ओ. एन. जी.-डी III]

S.O. 417.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from O.N.G.C. Gas Terminal to Gujarat Gas Company Limited, Receiving Station at Adajan in Gujarat State, Pipeline should be laid by the Gujarat Gas Company Limited, Surat.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Hazira Project, "Prahar", 60 Subhashnagar Society, Ghod-Dod Road, Surat.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

## SCHEDULE

Pipeline from O.N.G.C. Gas Terminal to Gujarat Gas Company Limited, Receiving Station at Adajan.

State : Gujarat District : Surat Taluka : Chorasi.

Village	Survey No.	H.	Are.	Prati Are.
Pal	Tapi River	4	07	60

[No. O-11027/186/90-ONG-D. III]

का. आ. 418.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ओ. एन. जी. एन. हजिरा से (कृमको बाऊंड्री) आर. पी. एल. कम्प्लेक्स हजिरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाइन रिलायन्स पेट्रोकेमिकल्स हजिरा द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आग्रह एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग हजिरा प्रोजेक्ट 60 मुभाप नगर सोसाईटी घोडदोड रोड सुरत को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

#### अनुसूची

ओ. एन. जी. सी. हजिरा से कृमको बाऊंड्री) आर. पी. एल. कम्प्लेक्स हजिरा तक पाईप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला : सुरत	तालुका : चोरासी			
गांव	सर्वे नंबर	हे.	आरे.	से.	आरे
भाटपोर	556	0	10		00
	556	0	02		20
	556	0	07		20
	556	0	15		60
	556	0	16		00
	556	0	12		00
	373	0	15		60

[सं. ओ-11027/194-ओ. एन. जी.-डी. III]  
बी. एस. नागर, सक्षम अधिकारी

S.O. 418.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from ONGC Hazira to (Kribhco boundry) R.P.L. Complex Hazira in Gujarat State pipeline should be laid by the Reliance Petrochemicals Ltd. Hazira.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Hazira Project, "Prahari", 60 Subhashnagar Society, Ghod-Dod Road, Surat.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

#### SCHEDULE

Pipeline from O.N.G.C. Hazira to (Kribhco boundry) R.P.L. Complex Hazira

State : Gujarat District : Surat Taluka : Chorasi

Village	Survey No.	H.	Are.	Centi Are.
Bhatpore	556	0	10	00
	556	0	02	20
	556	0	07	20
	556	0	15	60
	556	0	16	00
	556	0	12	00
	373	0	15	60

[No. O-11027/194/90-ONG.-D. III]

V.S. NAGAR, Competent Authority

का. आ. सं. 419.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ओ. एन. जी. एस. हजिरा से (कृमको बाऊंड्री) आर. पी. एल. कम्प्लेक्स हजिरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाइन रिलायन्स पेट्रोकेमिकल्स हजिरा द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आग्रह एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, हजिरा प्रोजेक्ट 60 मुभाप नगर सोसाईटी घोडदोड रोड, सुरत को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

#### अनुसूची

ओ. एन. जी. एस. हजिरा से (कृमको बाऊंड्री) आर. पी. एल. कम्प्लेक्स हजिरा तक पाईपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : सुरत तालुका : चोरासी

गांव	सर्वे नंबर	हे.	आरे.	से.	आरे
कवास	255/ए	0	22		25
	255/बी	0	35		52
कृमको जमीन		2	33		40

[सं. ओ-11027/195/90-ओ. एन. जी.-डी. III]

के विवेकानन्द, डेस्क अधिकारी

S.O. 419.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from ONGC Hazira to (Kribhco boundary) R.P.L. Complex Hazira in Gujarat State pipeline should be laid by the Reliance Petrochemicals Ltd. Hazira.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Hazira Project, "Prahar", 60 Subhashnagar Society, Ghod-Dod Road, Surat.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

#### SCHEDULE

Pipeline from ONGC Hazira to (Kribhco boundry R.P.L. Complex Ltd

State: Gujarat. District : Surat Taluka : Chorasai

Village	Survey No.	H.	Are.	Centi-are.
Kaas	255/A	0	22	24
	255/B	0	35	52
	Kribhco land	2	33	40

गैस प्रायोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

रीवा—3 से नादा-1 तक

राज्य : गुजरात पाईप लाईन जिला : ब्रौच तालुका : जमभूसर

गांव	ब्लाक	हे	भार	सेन्टियर
1	2	3	4	5
नादा	1639	2	40	50
	1594	0	04	16
	1595	0	08	32
	1591	0	02	08
	1593	0	06	24
	1599	0	08	32
	1600	0	09	88
	1601	0	05	20
	1602	0	01	60
	1640	0	60	32
	1396	0	03	12
	1395	0	03	12
	1393	0	04	16
	1392	0	03	12
	1391	0	12	48
	1390	0	14	56
	1388	0	02	86
	1389	0	01	28
	1387	0	04	68

अनुसूची

श्री. एन. जी. सी. गैस टर्मिनल से गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड रिसीविंग स्टेशन अडाजन तक पाईपलाईन बिछाने के लिए।  
राज्य : गुजरात जिला : सूरत तालुका : चोरासी

गांव	सर्वेनंबर	हेक्टर	अ.र.	प्रतिभारे
अडाजन	तापी नदी	2	02	40
	708	0	12	00
	601	0	04	00
	600/ए	0	04	00
	सरकारी रोड	3	55	80

[स. श्र. -11027/185/90-श्री. एन. जी. सी. III]

S.O. 416.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from O.N.G.C. Gas Terminal, Gujarat Gas Company Limited, Receiving Station at Adajan in Gujarat State, Pipeline should be laid by the Gujarat Gas Company Limited, Surat.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Hazira Project, "Prahar", 60 Subhashnagar Society, Ghod-Dod Road, Surat.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

#### SCHEDULE

Pipeline from O.N.G.C. Gas Terminal to Gujarat Gas Company Limited, Receiving Station at Adajan.

State : Gujarat. District : Surat Taluka : Chorasai

Village	Survey No.	H.	Are.	Prati Are.
Adajan	Tapi River	2	02	40
	708	0	12	00
	601	0	04	00
	600/A	0	04	00
	Govt. Road	3	55	80

[No. O-11027/185/90-ONG.-D. III]

का. श्र. 417.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में श्री. एन. जी. सी. गैस टर्मिनल से गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड रिसीविंग स्टेशन अडाजन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड सूरत द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी साईनो को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वाक्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवादी कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाने के लिए आक्षेप सहित अधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग हजीरा प्रोजेक्ट 60 सुभाष नगर सोसायटी घोडदोड रोड, सूरत को इन अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा और ऐसा आक्षेप कहने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

श्री. एन. जी. सी. गैस टर्मिनल से गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड रिसीविंग स्टेशन अडाजन तक पाईपलाईन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : सूरत तालुका : चोरासी

गांव	सर्वेनंबर	हे.	भारे प्रति	भार
पाल	तापी नदी	4	07	60

[स. श्र. -11027/186/90 श्री. एन. जी. -श्री III]

S.O. 417.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from O.N.G.C. Gas Terminal to Gujarat Gas Company Limited, Receiving Station at Adajan in Gujarat State, Pipeline should be laid by the Gujarat Gas Company Limited, Surat.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Hazira Project, "Prahar", 60 Subhashnagar Society, Ghod-Dod Road, Surat.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

#### SCHEDULE

Pipeline from O.N.G.C. Gas Terminal to Gujarat Gas Company Limited, Receiving Station at Adajan.

State : Gujarat District : Surat Taluka : Chorasai.

Village	Survey No.	H.	Are.	Prati Are.
Pal	Tapi River	4	07	60

[No. O-11027/186/90-ONG-D. III]

New Delhi, the 25th January, 1991

S.O. 420.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1490 dated 26-5-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from all encumbrances.

## SCHEDULE

Pipeline from RENA-3 to NADA-1.

State : Gujarat District - Bharuch Taluka : Jambusar

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Nada	1639	2	40	50
	1594	0	04	16
	1595	0	08	32
	1591	0	02	08
	1593	0	06	24
	1599	0	08	32
	1600	0	09	88
	1601	0	05	20
	1602	0	01	60
	1640	0	60	32
	1396	0	03	12
	1395	0	03	12
	1393	0	04	16
	1392	0	03	12
	1391	0	12	48
	1390	0	14	56
	1388	0	02	86
	1389	0	01	28
	1387	0	04	68
	1386	0	04	68
	1385	0	03	12
	1383	0	06	76
	1381	0	09	36
	1380	0	15	60
	1411	0	07	28
	1410	0	02	08
	1409	0	02	08
	1408	0	01	30
	1407	0	04	16
	1406	0	07	28

1	2	3	4	5
	1405	0	03	12
	1404	0	06	24
	1428	0	03	12
	1564	0	05	72
	1562	0	03	15
	1561	0	02	86
	1560	0	05	20
	1559	0	10	40
	1522	0	01	28
	1527	0	25	20
	1526	0	00	64
	1523	0	01	32
	1520	0	01	92

[No. O-11027/40/90-ONG. D.-III]

का. 421.—यस : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में राजस रो पी से ए.ई.सी. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार प्रजित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार प्रजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वर्तते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग निर्माण और देखभाल प्रमाण मकरपुरा रोड, वडोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

राजस नं टी पी से ए. ई. सी. तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : दसकोई

गांव	प्लॉक नं.	हेक्टेयर	घर	सेन्टीयर
बीबीपुर	50 पी	0	02	25
	32	0	07	80
	35	0	05	10
	36	0	01	80
	34	0	13	80
	18	0	07	05
	22	0	11	25
	17	0	18	60
	10	0	13	05

[सं. ओ.-11027/187/90-ओ. एन. जी. डी.-III]

राज्य : गुजरात	जिला : सूरत	तालुका : चोरासी
गांव	सर्वे नंबर	हे. आरे. से. आरे.
भाटपोर	556	0 10 00
	556	0 02 20
	556	0 07 20
	556	0 15 60
	556	0 16 00
	556	0 12 00
	373	0 15 60

[सं. ओ.-11027/194-ओ. एन. जी.-डी. III  
बी.एस. नागर, सक्षम अधिकारी]

S.O. 418.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from ONGC Hazira to (Kribha boundary) R.P.L. Complex Hazira in Gujarat State pipeline should be laid by the Reliance Petrochemicals Ltd. Hazira.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Hazira Project, "Prahm", 60 Subhashnagar Society, Ghod-Dod Road, Surat.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार प्रजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वर्तते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग, हजिरा प्रोजेक्ट 60 मुभाप नगर सोसाइटी घोड डोड रोड, सूरत को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

ओ. एन. जी. एस. हजिरा से (कृष्णको आऊडी) आर पी

एन. कम्प्लेक्स हजिरा तक पाईपलाईन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : सूरत तालुका : चोरासी

गांव	सर्वे नंबर	हे	आरे	से आरे
कवाम	255/ए	0	22	25
	255/बी	0	35	52
कृष्णको जमीन		2	33	40

[सं. ओ.-11027/195/90-ओ. एन. जी.-डी. III]

के विवेकानन्द, हेल्थ अधिकारी

S.O. 421.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Ranasan T.P. to A.E.C. gas line in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

#### SCHEDULE

Pipeline from Ranasan T.P. to A.E.C.

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Dascroi

Village	Block No.	Hec- tare	Are	Centi- tiare
Bibipur	50/P	0	02	25
	32	0	07	80
	35	0	05	10
	36	0	01	80
	34	0	13	80
	18	0	07	05
	22	0	11	25
	17	0	18	60
	10	0	13	05

[No O-11027/187/90-ONG D III]

का भा 422 —यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन ए आई से पानी इंजनशन हीडर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी ज़मीनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय्य धर्मसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः धन पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्त कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पर्य्यप्त लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सभ्य प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बडोदा -9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति बिलिविधतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी कृत्रिम व्यवसायी की मार्फत।

#### धर्मसूची

जी एन. ए. आई से पानी इंजनशन हीडर तथा पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य गुजरात जिला धरुच तालुका. वाग्रा

गांव	ब्लॉक नं	ह	आर	से.
मुकेर	2 पी	0	09	10
	1	0	10	14
	119	0	04	16
	118	0	04	25
	116	0	41	21
	115	0	02	08
	113	0	00	80
	91	0	05	20
	90/ए/बी	0	12	52
	92/ए/बी	0	01	25
	87	0	22	30
	85	0	03	17
	86	0	10	35
	81	0	17	68
	82	0	00	32
	86	0	00	85
	65	0	19	76
	64	0	20	80
	63	0	03	04

[स ओ -11027/188/90 ओ एन जी-डी -III]

S.O. 422.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from GNAI to Water Injection Header in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

#### SCHEDULE

Pipeline from GNAI to Water Injection Header

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hec- tare	Are	Centi- tiare
1	2	3	4	5
Muller	2/P	0	09	10
	1	0	10	14
	119	0	04	16

1	2	3	4	5
	118	0	04	25
	116	0	41	21
	115	0	02	08
	113	0	00	80
	91	0	05	20
	90/A/B	0	12	52
	92/A/B	0	01	52
	87	0	22	30
	85	0	03	17
	86	0	10	35
	81	0	17	68
	82	0	00	32
	66	0	00	85
	65	0	19	76
	64	0	20	80
	63	0	03	04

[No. O-11027/188/90-ONG. D. III]

का. प्रा. 234 :—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी. एन. डी. डी. से जी. एन. डी. सी. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आग्रह एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा-9, को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट : यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

जी. एन. डी. डी. से जी. एन. डी. सी. तक पाईप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : वागरा

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर	से.
गंधार	322/ए/बी	1	29	97

[सं. ओ.-11027/189/90-ओ. एन. जी.-डी. III]

S.O. 423.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from GNDD to GNDC in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (59 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

## SCHEDULE

Pipeline from GNDD to GNDC.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centiare
Gandhar	322/A/B	1	29	97

[No. O-11027/189/90-ONG. D-III]

का. प्रा. 424 :—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सी पी एल गंधार से अपीको टायर्स तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आग्रह एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट : यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

सीपीएल, गंधार से एतयो टायर्स तक पाईप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तहसील : वागरा

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर	से.
अकोट	38	0	15	95
	26	0	22	45



1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
						29	0	28	90
	27	0	07	85		28	0	26	40
	29	0	28	90		17	0	15	80
	28	0	26	40		16	0	13	40
	17	0	15	80		15	0	10	95
	16	0	13	40		14	0	31	85
	15	0	10	95		11	0	03	42
	14	0	31	85		13	0	00	01
	11	0	03	42		80	0	10	91
	13	0	00	09		81	0	24	91
	80	0	10	91		77/A	0	00	28
	81	0	24	91		84/A	0	35	70
	77/ए	0	00	28		85	0	30	80
	84/ए	0	35	70		86	0	08	95
	85	0	30	80		87	0	06	45
	86	0	08	95		88	0	04	75
	87	0	06	45		Cart track	0	03	55
	88	0	04	75		102	0	01	55
	कार्टट्रेक	0	03	55		99	0	72	29
	102	0	01	55		116	0	04	25
	99	0	72	29		117	0	15	00
	116	0	04	25		120/A	0	10	95
	117	0	15	00		118/A	0	11	90
	120/ए	0	10	95					
	118/ए	0	11	90					

[सं. ओ.-11027/190/90-ओ एन जी-डी-III]

S.O. 424.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from CPF-Gandhar to Apollo Tyres in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and National Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

## SCHEDULE

Pipeline from CPF Gandhar to Apollo Tyres.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hec- tare	Are	Cent- tlaire
Ankot	38	0	15	95
	26	0	22	45
	27	0	07	85

[No. O-11027/190/90-ONG.-D. III]

का. भा. 425 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी. एन. सी. जी. से जी. जी. एस. II तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

यतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बनते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आशेष सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के माफ़त।

## अनुसूची

जी. एन. सी. जी. से जी. जी. एस. II तक पाईप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : वावरा

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	भार.	सेन्टी
केशवान	337	0	07	02
	कार्टट्रेक	0	03	25
	167	0	07	28
	168	0	09	62

1	2	3	4	5
	165	0	08	32
	177	0	08	58
	178	0	19	24
	179	0	00	28
	180	0	17	16
	181	0	06	50
	182	0	13	46
	188	0	00	06
	189	0	18	72
	192	0	07	80
	110	0	07	54
	109	0	05	98
	108	0	14	56

[सं. ओ.-11027/191/90 ओ. एन. जी.-डी.-III]

S.O. 425.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from GNGC to GGS-II in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

#### SCHEDULE

Pipeline from GNGC To GGS. II

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Keshwan	337	0	07	02
	Cart track	0	03	25
	167	0	07	28
	168	0	09	62
	165	0	08	32
	177	0	08	58
	178	0	19	24
	179	0	00	28
	180	0	17	16
	181	0	06	50
	182	0	18	46
	188	0	00	06
	189	0	18	72
	192	0	07	80
	110	0	07	54
	109	0	05	98
	108	0	14	56

[No. O-11027/191/90-ONG.-D. III]

का. आ. 426.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में मुलेर 'टी' बिन्दु से जी जी एस-II तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी गुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

#### अनुसूची]

मुलेर टी बिन्दु से जी जी एस तक पाइप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात

जिला : भरुच

तालुका : वागरा

गांव	ब्लाक नं.	हे.	अर	सेटीयर
पालडी	261/ए	0	06	24
	272	0	10	40
	55	0	05	20
	269	0	05	20

[सं. ओ.-11027/192/90-ओ एन जी.-डी.-III]

S.O. 426.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Muller 'T' Point to GGS-II in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

## SCHEDULE

Pipeline from Muller 'T' Point to GGS II

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cent-iare
Paldi	261/A	0	06	24
	272	0	10	40
	55	0	05	20
	269	0	05	20

[No. O-11027/192/90-ONG. D. III]

का.भा 427 —यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन जी बी से जी एन.डी.एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाव्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राण्य एतद्वारा घोषित किया है।

अतः कि उक्त भूमि में हितवन्त कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ीवा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट. यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

जी एन जी.बी से जी एन डी एफ तक पाईप लाइन बिछाने के लिए  
राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : वाग्रा

गाव	ब्लॉक नं.	हे	आर	सेंटीयर
पालडी	357	0	03	38
	358	0	14	56
	359	0	07	28
	345	0	17	68
	348	0	06	50
	331	0	03	25
	338	0	04	16
	337	0	31	20
	406	0	93	43

[स ओ-11027/193/90-ओ एन जी-डी-III]

S.O. 427.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from GNGB to GNDF in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission,

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

## SCHEDULE

Pipeline from GNGB To GNDF

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cent-iare
Paldi	357	0	03	38
	358	0	14	56
	359	0	07	28
	345	0	17	68
	348	0	06	50
	331	0	03	25
	338	0	04	16
	337	0	31	20
	406	0	93	43

[No. O-11027/193/90-ONG-D. III]

का.भा 423 —यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन जी बी से जी एन डी एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाव्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राण्य एतद्वारा घोषित किया है।

अतः कि उक्त भूमि में हितवन्त कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ीवा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट. यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

धनुसूची				
जी.एम.सी.जी. से जी.जी.एस.-II तथा पाईप लाईन बिछाने के लिए				
राज्य : गुजरात	जिला : वरुच	तालुका : वाधरा		
गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर.	सेटीयर
पालंढी	190	0	11	18
	195	0	07	80
	194	0	05	20
	200	0	08	45
	199	0	03	25
	201	0	24	18
	209	0	13	65
	208	0	10	66
	212	0	07	80
	213	0	18	46
	214	0	27	04
	216/ए	0	08	45
	279	0	20	80
	284	0	11	70
	277/ए	0	17	36
	277/बी	0	02	80

[सं. ओ.-11027/197/90-ओ एन जी ओ-II]

S.O. 428.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from GNCG to GGS II in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

## SCHEDULE

Pipeline from GNCG To GGS II

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Paldi	190	0	11	18
	195	0	07	80
	194	0	05	20

2	3	4	5
200	0	08	45
199	0	03	25
201	0	24	18
209	0	13	65
208	0	10	66
212	0	07	80
213	0	18	46
214	0	27	04
216/A	0	08	45
279	0	20	80
284	0	11	70
277/A	0	17	36
277/N	0	02	80

[No. O-11027/197/90-ONG. -D-III]

का.घा 429 —यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में चोकारी टी बिन्दू से जिपको तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन लेन तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध धनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 का उपधारा द्वारा प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

वर्णन कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आशेष सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, यकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और एसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

## धनुसूची

चोकारी टी बिन्दू से जिपको तक पाईप लाईन बिछाने के लिए । (नया)

राज्य : गुजरात	जिला : बड़ौदा	तालुक : वादरा		
गाव	सर्वे नं.	हे.	आर	सेटीयर
1	2	3	4	5
अवका	243	0	10	80
	240	0	18	60
	239	0	12	60
	232	0	06	80
	231	0	20	00
	काटे ट्रैक	0	02	00
	225	0	15	60
	226	5	16	00
	काटे ट्रैक	0	03	60
	194	0	01	25
	183	0	13	75
	184	0	13	00

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	185	0	20	75		239	0	12	60
	179	0	15	25		232	0	06	80
	काटे ट्रैक	0	02	20		231	0	20	00
	172	0	01	20		Cart track	0	02	00
	173	0	20	00		225	0	15	60
	171	0	06	00		226	0	16	00
	170	0	27	00		Cart track	0	03	60
	166	0	15	60		194	0	01	25
	165	0	02	50		183	0	13	75
	422	0	15	40		184	0	13	00
	423	0	03	00		185	0	20	75
	421	0	01	26		179	0	15	25
	424	0	12	36		Cart track	0	02	20
	425	0	13	87		172	0	01	20
	काटे ट्रैक	0	03	00		173	0	20	00
	405	0	05	21		171	0	06	00
	काटे ट्रैक	0	03	87		170	0	27	00
	404	0	09	75		166	0	15	60
	431	0	00	50		165	0	02	50
	403	0	22	25		422	0	15	40
	399	0	04	05		423	0	03	00
	398	0	00	25		421	0	01	26
	400	0	09	00		424	0	12	36
	393	0	16	00		425	0	13	87
	445	0	06	00		Cart track	0	03	00
						405	0	05	21
						Cart track	0	03	87
						404	0	09	75
						431	0	00	50
						403	0	22	25
						399	0	04	00
						398	0	00	25
						400	0	09	00
						393	0	16	00
						445	0	06	00

[स. ओ-11027/202/90-ओ एन जी-डी-III]

S.O. 429.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Chokari 'T' Point to Ankleshwar GIPCO in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission,

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

## SCHEDULE

Pipeline from Chokari 'T' Point to Unera

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Padra

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Dabka	243	0	10	80
	240	0	18	64

[No. O-11027/202/90-ONG.-D. III]

का.भा. 430 —या केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ई.पी.एस. से अक-लेम्वर सी टी एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यह: यह प्रतीत होता है कि ऐसी साधनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एनएनएल अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एनएल द्वारा घोषित किया है।

बशत कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सहित अधिकारी तेल तथा गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड बडोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट। यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

ई.पी.एम. से अंकलेश्वर सी टी एफ तक पाईप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात

जिला व तालुका : भरुच

गांव	ब्लाक नं.	हे.	आर	मेंटीयर
1	2	3	4	5
एकसाल	2	0	77	53
	3	0	17	70
	27	0	51	92
	26	0	19	00
	67	0	31	45
	कार्ट ट्रैक	0	03	00
	131	0	06	00
	132	0	06	50
	135	0	07	00
	129	0	04	50
	137	0	07	11
	138	0	02	90
	136	0	00	09
	139	0	14	51
	142	0	05	40
	140	0	11	10
	114 ए बी	0	09	90
	113	0	20	90
	110	0	00	50
	111	0	28	31
	कार्ट ट्रैक	0	04	20
	252	0	02	75
	250	0	17	85
	251	0	09	45
	249	0	28	50
	248	0	24	60
	247	0	00	05
	243	0	06	51
	242	0	00	52
	317	0	04	20
	320	0	00	05
	319	0	07	45
	318	0	09	20
	325	0	25	80
	326	0	17	30
	327	0	04	30

[स. ओ-11027/206/90-ओ.एन.जी.-डी.-III]

S.O. 430.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from EPS to Ankleshwar CTF in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the

Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

## SCHEDULE

Pipeline from E.P.S. To Ankleshwar CTF.

State : Gujarat District &amp; Taluka : Bharuch

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Ekshal	2	0	77	53
	3	0	17	70
	27	0	51	92
	26	0	19	00
	67	0	31	45
	Cart track	0	03	00
	131	0	06	00
	132	0	06	50
	135	0	07	00
	129	0	04	50
	137	0	07	11
	138	0	02	90
	136	0	00	09
	139	0	14	51
	142	0	05	40
	140	0	11	10
	114/B	0	09	90
	113	0	20	90
	110	0	00	50
	111	0	28	31
	Cart track	0	04	20
	252	0	02	75
	250	0	17	85
	251	0	09	45
	249	0	28	50
	248	0	24	60
	247	0	00	05
	243	0	06	51
	242	0	00	52
	317	0	04	20
	320	0	00	05
	319	0	07	45
	318	0	09	20
	325	0	25	80
	326	0	17	30
	327	0	04	30

[No. O-11027/206/90-ONG-D-III]

का.आ. 431.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ई.पी.एम. से अंकलेश्वर सी टी एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अन्तर्मुखी में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 को उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

#### अनुसूची

ई पी एस से अंकलेश्वर सी टी एफ तक पाइप लाइन बिछाने के लिए राज्य : गुजरात

#### जिला-तालुका-भरुच

गांव	सर्वे नं.	हे.	आर.	सेटीयर
1	2	3	4	5
डभूत	277	0	07	80
	278	0	23	55
	279	0	05	00
	280	0	07	30
	286	0	18	00
	285	0	11	45
	284	0	14	30
	283	0	05	80
	266	0	19	45
	267	0	19	45
	261	0	09	00
	260	0	10	25
	259	0	09	71
	258	0	15	70
	302	0	00	14
	303	0	22	20
गाडावाट	0	07	20	
304	0	31	00	
306	0	08	90	
305	0	08	55	
310	0	30	05	
322	0	04	45	
321	0	50	40	
333	0	08	40	
317	0	04	30	
334	0	21	55	
335	0	12	28	
336	0	03	40	

1	2	3	4	5
	338	0	00	48
	337	0	50	25
	375	0	47	05
	376	0	04	50
	369	0	33	20
	370	0	11	80
गाडावाट	0	04	20	
438	0	22	30	
439	0	15	20	
320	0	13	10	

[स. ओ.-11027/207/90-ओ एन जीडी-111]

S.O. 431.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from EPS to Ankleshwar CTF in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

#### SCHEDULE

Pipeline from E.P.S. To Ankleshwar CTF.

State : Gujarat District & Taluka : Bharuch

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Bhadbhut	277	0	07	80
	278	0	23	55
	279	0	05	00
	280	0	07	30
	286	0	18	00
	285	0	11	45
	284	0	14	30
	283	0	05	80
	266	0	19	45
	267	0	19	45
	261	0	09	00
	260	0	10	25
	259	0	09	71
	258	0	15	70
	302	0	00	14
	303	0	22	20

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Cart track	0	07	20		265	0	13	26
	304	0	31	00		गाडा बाट	0	05	00
	306	0	08	90		242	0	12	30
	305	0	08	55		239	0	42	80
	310	0	30	05		238	0	37	96
	322	0	04	45		286	0	38	40
	321	0	50	40		237	0	13	44
	333	0	08	40		236	0	12	40
	317	0	04	30		235	0	26	95
	334	0	21	55		234	0	21	50
	335	0	12	28		297	0	22	00
	336	0	03	40		298	0	13	20
	338	0	00	48		299	0	30	10
	337	0	50	25		329	0	12	80
	375	0	47	05		328	0	11	15
	376	0	04	50		321	0	17	00
	369	0	33	20		326	0	10	52
	370	0	11	80		332	0	00	30
	Cart track	0	04	20		331	0	24	96
	438	0	22	30		338	0	09	85
	439	0	15	20		420	1	44	80
	320	0	13	10		419	0	14	00
						418	0	15	20
						417	0	09	90
						3	0	03	60
						24	0	13	79
						25	0	16	00
						23	0	15	80
						27	0	22	21
						28	0	00	30
						31	0	15	75

[No. O-11027/207/90-ONG.-D. III]

का.भा. 4.12 --यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ईपीएस से अकलेश्वर सीटीएफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाईन तैल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अन्य अर्थ, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रयुक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

अतः कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के लोच पाइप लाइन बिछाने के लिए आशय सक्षम प्राधिकारी, तैल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशय करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

ई पी एस से अकलेश्वर सीटीएफ तक पाइप लाईन बिछाने के लिए राज्य : गुजरात जिला : मरुच तासुका : बागरा

गांव	प्लॉक नं.	है.	आर.	सेटी
1	2	3	4	5
मोजवक	261	0	45	20
	263	0	22	35
	264	0	09	56
गाडाबाट		0	12	60

[सं. ओ - 11027/208/90-ओ. एन. जी.-डी III]

के. विवेकानन्द, हेल्थ अधिकारी

S.O. 432.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from EPS to Ankleshwar CTF in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

AND whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.



## SCHEDULE

Pipeline from E P S. To Ankleshwar CTH.

State - Gujarat District - Bharuch Taluka - Vagra

Village	Block No.	Hec- tare	Are	Cent- tiare
1	2	3	4	5
Khojbal	261	0	45	20
	263	0	22	35
	264	0	09	56
	Cart track	0	12	60
	265	0	13	26
	Cart track	0	05	00
	242	0	12	30
	239	0	42	80
	238	0	37	96
	286	0	38	40
	237	0	13	44
	236	0	12	40
	235	0	26	95
	234	0	21	50
	297	0	22	00
	298	0	13	20
	299	0	30	10
	329	0	12	80
	328	0	11	15
	327	0	17	00
	326	0	10	52
	332	0	00	30
	331	0	24	96
	338	0	09	85
	420	0	44	80
	419	0	14	00
	418	0	15	20
	417	0	09	90
	3	0	03	60
	24	0	13	79
	25	0	16	00
	23	0	15	80
	27	0	22	21
	28	0	00	30
	31	0	15	75

[No. O-11027/208/90-ONG-D. III]

K VIVEKANAND, Desk Officer

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग)

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1991

का आ 433—यन पेट्रोलियम और खनिज पादप लाइन (भूमि से उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ 2881 तारीख 1-11-1990 और शुद्धीपत्र का आ 1 199 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को महाराष्ट्र राज्य में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड रिकॉयनरी, माहल बम्बई से कैराग्राम तक (पातालगंगा औद्योगिक क्षेत्र, ताल्लुका खालापूर जिला रायगड, राज्य महाराष्ट्र) तथा कैराग्राम से माहल बम्बई तक नाफता के परिवहन के लिए दो पादप लाइन चेंबूर पातालगंगा

पादपलाइन्स लिमिटेड बम्बई के द्वारा बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राणय घोषित कर दिया था।

और यन सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार का रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यन. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पादप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होन की बजाय चेंबूर पतालगंगा पादपलाइन्स लिमिटेड, बम्बई में सभा बाधाओं में मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, माहल, बम्बई से कैराग्राम तक पातालगंगा औद्योगिक क्षेत्र, ताल्लुका खालापूर, जिला रायगड, राज्य महाराष्ट्र पादप लाइन बिछाने के लिए।

धाम	सर्वे न. गेट न	हिस्सा न	क्षेत्र-धार-सेटीयर
धाम—प्राविबली	33	2 पैकी	00-00-43
ताल्लुका—खालापूर	34	1 पैकी	00-00-08
जिला—रायगड	34	2 पैकी	00-00-12
राज्य—महाराष्ट्र	40	4 पैकी	00-00-80
	36	0 पैकी	00-00-28
	37	0 पैकी	00-00-25
	39	1 पैकी	00-00-05
	39	4 पैकी	00-00-07
	54	5 पैकी	00-00-52
	50	1 पैकी	00-00-63
	51	0 पैकी	00-00-90
	49	0 पैकी	00-00-04
	48	3 पैकी	00-00-41
	47	2 पैकी	00-00-42
	44	0 पैकी	00-01-05
	70	2 पैकी	00-00-24
	58	2 पैकी	00-00-15
	71	1 पैकी	00-00-25
	72	0 पैकी	00-00-37
	73	1 पैकी	00-00-54
	73	2 पैकी	00-00-34
	76	1 पैकी	00-00-27
	80	1 पैकी	00-00-50
	80	2 पैकी	00-00-20
	81	1 पैकी	00-00-18
	81	2 पैकी	00-00-38
	103	1 पैकी	00-00-42
	104	0 पैकी	00-00-56
	111	2 पैकी	00-01-50
	124	2 पैकी	00-01-28
	132	4 पैकी	00-00-60

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

## SCHEDULE

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 1st February, 1991

S.O. 433.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2881 dated 1-11-1990 and erratum No. S.O. dated 1-11-1990 under sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962). The Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for the transport of Naphthalene return stream from Refinery of Bharat Petroleum Corporation Limited, Mathul Bombay to Village Karia in Patalganga Industrial Area, Taluka Khalapur, District Raigad in the Maharashtra State to the Chembur Patalganga Pipelines Limited, Bombay;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted a report to the Government:

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in said lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests of the date of the publication of this declaration in the Chembur Patalganga Pipelines Limited free from all encumbrances.

Pipelines from Refinery of Bharat Petroleum Corporation Ltd. Mathul, Bombay to Village Karia in Patalganga Industrial Area, Taluka Khalapur, District Raigad in Maharashtra State.

Village	S. No./ Gat No.	Hissa No.	Area Hector- Are- Centaire
Village Ambivali	33	2 Part	00 00 43
Taluka Khalapur	34	1 Part	00 00 08
District Raigad	34	2 Part	00 00 12
State Maharashtra	40	4 Part	00 00 80
	36	0 Part	00 00 28
	37	0 Part	00 00 25
	39	1 Part	00 00 05
	39	4 Part	00 00 07
	54	5 Part	00 00 52
	50	1 Part	00 00 63
	51	0 Part	00 00 90
	49	0 Part	00 00 04
	48	3 Part	00 00 41
	47	2 Part	00 00 42
	44	0 Part	00 01 05
	70	2 Part	00 00 24
	58	2 Part	00 00 45
	71	1 Part	00 00 25
	72	0 Part	00 00 37
	73	1 Part	00 00 54
	73	2 Part	00 00 34
	76	1 Part	00 00 28
	80	1 Part	00 00 50
	80	2 Part	00 00 20
	81	1 Part	00 00 18
	81	2 Part	00 00 38
	103	1 Part	00 00 42
	104	0 Part	00 00 56
	111	2 Part	00 00 50
	124	2 Part	00 01 28
	132	4 Part	00 00 60

[No. P-32015/2/90-Dist.]

## शुद्धिपत्र

का आ 434 - निम्नलिखित अनुसूची में रकबा 1 से 9 में लिखे हुए शब्दों और संख्या भारत सरकार की अधिसूचना नं. का आ 2881 तारीख 1-11-1990 भारत का राजपत्र भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) 10 नवम्बर, 1990 पृष्ठ 4849 से 4850 से प्रकाशित हुए अधिसूचना की अनुसूची में छपे हैं। इसके वजह निम्नलिखित अनुसूची, रकबा 10 से 18 में लिखे हुए शब्दों और संख्या पढ़ना।

## प्रसारित किया गया वर्णन

अ. नं.	ग्राम	तालुका	जिला	म. नं.	हि. नं.	गट नं.	क्षेत्र हे.-आर.-सेन्टेयर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंबिवली	खालापूर	रायगड	90	1 पैकी	00	01
				90	पैकी		
				90	2 ब पैकी		
				90	3 पैकी		
				111	1 पैकी	00	24
				111	2 पैकी		
				111	2 पैकी		
				111	4 पैकी		
				197	1 पैकी	00	01
				107	1 पैकी		
				107	1 पैकी		

## प्रसारित होने का वर्णन

अ. नं.	ग्राम	तालुका	जिला	सं. नं.	हि. नं.	गट नं.	क्षेत्र हे-आर-सेन्टीयर	
10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	आबिदला	खालापूर	रायगड	90	1 पैका	00	01	00
				90	2 अ पैकी			
				90	2 ब पैकी			
				90	3 पैका			
				111	1 पैकी	00	24	00
				111	2 पैकी			
				111	3 पैका			
				111	4 पैका			
				107	1 पैकी	00	01	06
				107	2 पैका			
				107	3 पैकी			

[सं. पी-32015/2/90/वित्त]

का आ. 435.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2662 तारीख 1-11-1990 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को महाराष्ट्र राज्य में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड रिफायनरी, माहुल बम्बई से कैरा ग्राम तक (पातालगंगा औद्योगिक क्षेत्र, ताल्लुक खालापूर, जिला रायगड, राज्य महाराष्ट्र) तथा कैरा ग्राम से माहुल बम्बई तक नाफ्ता के परिवहन के लिए दो पाईप लाइन चेंबूर पातालगंगा पाइपलाइन्स लिमिटेड बम्बई द्वारा बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधिन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय चेंबूर पातालगंगा पाइपलाइन्स लिमिटेड, बम्बई में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को नहित होगा।

## अनुसूची

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, माहुल, बम्बई से कैराग्राम तक पातालगंगा औद्योगिक क्षेत्र, ताल्लुक खालापूर, जिला रायगड, राज्य महाराष्ट्र पाइप लाइन बिछाने के लिए।

ग्राम	मर्वे नं. गेट नं०	हिस्सा नं०	क्षेत्र हेक्टर-आर-सेन्टीयर
ग्राम—वासोदे	193	0 पैका	00-00-30
(मोहोपाडा)	4	0 पैका	00-01-08
ताल्लुका—खालापूर	3	0 पैका	00-02-64
जिला—रायगड	2	0 पैका	00-01-32
राज्य—महाराष्ट्र	192	0 पैका	00-04-98

[सं. पी-32015/3/90-वित्त]

S.O. 435.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2882 dated 1-11-1990 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962). The Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for the transport of Naphtha/its return stream from Refinery of Bharat Petroleum Corporation Limited Mahul Bombay to village Kaira in Patalganga Industrial Area, Taluka Khalapur, District Raigad in the Maharashtra State to the Chembur Patalganga Pipelines Limited, Bombay;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Submitted a report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests of the date of the publication of this declaration in the Chembur Patalganga Pipelines Limited free from all encumbrances.

## SCHEDULE

Pipeline from Refinery of Bharat Petroleum Corporation Ltd., Manul, Bombay to Village Kaira in Patalganga Industrial Area, Taluka Khalapur, District Raigad in Maharashtra State.

Village	S. No./ Gat No.	Hissa No.	Area Hector- Are Centiare
Village—Wasambe		0 Part	00-00-30
(Mohopada)	193		
Taluka Khalapur	4	0 Part	00-01-08
District Raigad	3	0 Part	00-02-64
State Maharashtra	2	0 Part	00-01-32
	192	0 Part	00-04-98

[No.P.-32015/3/90-Dist.]

का. भा. 436—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रजनन) अधिनियम 1962 (1962 का 5) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. भा. सं. 3086 तारीख 1-11-1990 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न भूमियों में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को महाराष्ट्र राज्य में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड रिफायनरी, माहुल, बम्बई से कैराग्राम तक (पतालंगंगा औद्योगिक क्षेत्र, तालुका खालापूर, जिला रायगड, राज्य महाराष्ट्र) तथा कैराग्राम से माहुल बम्बई तक नाफ्था के परिवहन के लिए दो पाइप लाइन चेंबर पतालंगंगा पाइपलाइन्स लिमिटेड बम्बई द्वारा बिछाने के लिए प्रजित करने का प्रस्ताव आशय घोषित कर दिया था।

और यतः मध्य प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आते, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न भूमियों में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार प्रजित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न भूमियों में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आते उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों के उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय चेंबर पतालंगंगा पाइपलाइन्स लिमिटेड, बम्बई में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप से, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, माहुल, बम्बई से कैराग्राम तक पतालंगंगा औद्योगिक क्षेत्र, तालुका खालापूर, जिला रायगड, राज्य महाराष्ट्र पाइपलाइन बिछाने के लिए

ग्राम	सर्वे नं. गट नं.	हिस्सा नं.	क्षेत्र हेक्टर आर-मैट्रिक
ग्राम—पानशिल	53	1 पैकी	00-02-75
तालुका—खालापूर	53	2 पैकी	00-00-40
जिला—रायगड	54	4 पैकी	00-05-82
राज्य—महाराष्ट्र	56	0 पैकी	00-01-26
	56	0 पैकी	00-02-76
	59	2 पैकी	00-06-36
	59	1 पैकी	00-01-44
	59	3 पैकी	00-00-24
	59	4 पैकी	00-00-84
	63	3 पैकी	00-02-82
	63	4 B पैकी	00-02-34
	63	4 A पैकी	00-01-56
	104	2 पैकी	00-01-38
	104	3(2) पैकी	00-02-16
	105	0 पैकी	00-04-44
	106	4 पैकी	00-04-62
	106	1 पैकी	00-03-78
	99	0 पैकी	00-05-76
	96	0 पैकी	00-02-28
	94	0 पैकी	00-01-74

[सं. पी-32015/4/90-विषय]

S.O. 436.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2882 dated 1-11-1990 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962). The Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipe lines for the transport of Naphtha/its return stream from Refinery of Bharat Petroleum Naphtha/its return stream from Refinery of Bharat Petroleum Corporation Limited Mahul Bombay to village Kaira in Patalganga Industrial Area, Taluka Khalapur, District Raigad in the Maharashtra State to the Chembur Patalganga Pipelines Limited, Bombay;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Submitted a report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in said lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests of the date of the publication of this declaration in the Chembur Patalganga Pipelines Limited free from all encumbrances.

#### SCHEDULE

Pipelines from Refinery of Bharat Petroleum Corporation Ltd., Mahul, Bombay to Village Kaira in Patalganga Industrial Area, Taluka Khalapur, District Raigad in Maharashtra State.

Village	S. No./ Gat No.	Hissa No.	Area Hector- Are- Centaire
Panshil Taluka Khalapur	53	1 Part	00-02-75
Dist. Raigad	53	2 Part	00-00-40
State Maharashtra	54	4 Part	00-05-82
	56	0 Part	00-01-26
	56	0 Part	00-02-76
	59	2 Part	00-06-36
	59	1 Part	00-01-44
	59	3 Part	00-00-24
	59	4 Part	00-00-84
	63	3 Part	00-02-82
	63	4 B Part	00-02-34
	63	4 A Part	00-01-56
	104	2 Part	00-01-38
	104	3 (2) Part	00-02-16
	105	0 Part	00-04-44
	106	4 Part	00-04-62
	106	1 Part	00-03-78
	99	0 Part	00-05-76
	96	0 Part	00-02-28
	94	0 Part	00-01-74

[No. P-32015/4/90-Dist.]

का. भा. 437.—यह: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. भा. स 3101 तारीख 1-11-1990 और अधिवक्ता का भा. स तारीख 199 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को महाराष्ट्र राज्य में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड रिफायनरी, माहुल बम्बई से कैरा ग्राम तक (पतालगा आधुनिक क्षेत्र, तालुका खालापुर, जिला रायगड, राज्य महाराष्ट्र) तथा कैराग्राम से माहुल बम्बई तक नापथा के परिवहन के लिए दो पाइप लाइन चेंबुर पातालगा पाइपलाइन्स लिमिटेड बम्बई द्वारा बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यह मन्त्रम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है

और आगे, यह केन्द्रीय सरकार ने उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय चेंबुर पातालगा पाइपलाइन्स लिमिटेड, बम्बई में, सभी बाधाओं में सुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अतः सूचित

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, माहुल, बम्बई से कैरा ग्राम तक पातालगा आधुनिक क्षेत्र, तालुका खालापुर, जिला रायगड, राज्य महाराष्ट्र पाइप लाइन बिछाने के लिए

क्षेत्र			
ग्राम	सर्वे न/गट न	हिस्सा न	हेक्टर-आर-सेंटेयर
ग्राम—आकुरी	99	4 अ-1	00-03-90
तालुका पनवेल			
जिला रायगड			
राज्य महाराष्ट्र			

[स पी-32015/19/90-विज]  
सहादेव राम, अवर सचिव

S.O. 437.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No 3101 dated 1-11-1990 and erratum No. S.O. dated 199 under sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) The Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for the transport of Naphtha/it's return stream from Refinery of Bharat Petroleum Corporation Limited, Mahul Bombay to Village Kaira in Patalganga Industrial Area, Taluka Khalapur, District Raigad in the Maharashtra State to the Chembur Patalganga Pipelines Limited, Bombay;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Submitted a report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests of the date of the publication of this declaration in the Chembur Patalganga Pipelines Limited free from all encumbrances.

#### SCHEDULE

Pipelines from Refinery of Bharat Petroleum Corporation Ltd., Mahul, Bombay to Village Kaira in Patalganga Industrial Area, Taluka Khalapur, District Raigad in Maharashtra State.

Village	S. No./ Gat No.	Hissa No.	Area Hector- Are- Centaire
Village : Akurli Taluka : Panvel District : Raigad State : Maharashtra	99	4A-1	00-03-90

[No. P-32015/19/90-Dist.]

SAHADEO RAM, Under Secy.

S.O.438—Read words and figures shown in columns 1 to 9 to the schedule given below appearing in the schedule annexed to the Government of India Notification No. S.O. 3101 dated 1-11-1990 published in the Gazette of India Part-II Section 3 Sub-section (ii) dated 17-11-1990 on pages 497/10 as "words and figures" shown in columns 10 to 18 to the schedule given below.

#### SCHEDULE

Sr No. of the No. Village	Taluka	District	S No.	Hissa No	Gat No	Area	
						H Arc	C Arc
1	2	3	4	5	6	7	8 9
01 Akurli	Panvel	Raigad	—	4A-1	Part	00-07-00	
			—	4A-2	Part	00-08-00	

Sl. No.	Name of the village	Taluka	District	S.No	Hisa No.	Gal No	Area	
							H A/c	C A/c
10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Akurli	Panvel	Raigad	99	4A-1	Part	00-07-00	
				99	4A-2	Pat	00-08-00	

[P-32015/19/90 Dist.]

गृहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1991

का.प्रा.439—यत् निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कसिय संशोधन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार नीचे वर्णित क्षेत्रों के बारे में दिल्ली ग्रहण योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित करती है जो दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबन्धों के अनुसार दिनांक 14-7-90 के नोटिस न.एफ.20(18)/88-एम पी द्वारा प्रकाशित किये गये थे, जिसमें उक्त नियम की धारा 11-क की उप-धारा 3 में अपेक्षित आपत्तियाँ सुझाव, उक्त नोटिस की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर आमंत्रित किये गये थे,

और यत् उक्त प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए और यत् केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली ग्रहण योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

धतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की उक्त ग्रहण योजना में एतद्वारा निम्नांकित संशोधन करती है।

संशोधन

"जोन-1-1 (नरेला क्षेत्र) में आने वाले, उत्तर में कोंडली-नरेला रोड, पूर्व में 220 के वी उच्च वोल्टता लाइन तथा पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में नहरी डिस्ट्रीब्यूटरी से घिरे हुए लगभग 268 हेक्टेयर (662 एकड़) माप के क्षेत्र के भूमि उपयोग को "कृषि-क्षरित" से बदलकर इस प्रकार किया जाता है —

- (क) रिहायशी उपयोग—158 हेक्टेयर
- (ख) सार्वजनिक और अर्धसार्वजनिक सुविधाएँ—56 हेक्टेयर
- (ग) मनोरंजनार्थक—27 हेक्टेयर
- (घ) सम्पूलेषण (रोड 40 मीटर और अधिक)—27 हेक्टेयर

[स के -13011/9/90-डी.बी.सी.ए/1 बी)]

अर्जुन देव, अध्वर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT  
(Delhi Division)

New Delhi, the 17th January, 1991

S.O. 439.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan regarding the areas mentioned hereunder, were published with Notice No. F. 20(18)/88-MP dated 14-7-90 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section II-A of the said Act, within thirty days from the date of the said Notice;

And whereas no objection/suggestions were received from the public with regard to the said proposed modifications and whereas the Central Government have decided to modify the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan;

Now, whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section II-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

## MODIFICATIONS

"The land use of an area measuring about 268 hec. (662 acres) falling in Zone I-1 (Narela Area), bounded by Kondli-Narela road in North 220 KV high tension lines in East and Nehri Distributory in West and South-West, is changed from 'Agricultural green' to

(a) Residential use	—158 hect.
(b) Public & Semi-public facilities	—56 hect.
(c) Recreational	—27 hect
(d) Circulation (Road 40 m. and above)	—27 hect.
Total	—268 hect.

[No. K-13011/9/90-DDVA/IB]

ARJAN DEV, Under Secy.

वायु विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1991

का.प्रा.440—इस मंत्रालय की दिनांक 4 जनवरी, 1991 और 14 जनवरी, 1991 की समसंख्यक अधिसूचनाओं में प्राणिक संशोधन करते हुए इस समिति का मुख्यालय बम्बई के स्थान पर नई दिल्ली में होगा जैसा कि 4-1-1991 की अधिसूचना के पैरा 3 में बताया गया है।

[सं. ए बी-15013/9/89-एस एस बी]

रवीन्द्र गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 24th January, 1991

S.O. 440.—In partial modification of this Ministry's Notifications of even number dated 4th January, 1991 and 14th January, 1991, the Headquarters of the Committee will be at New Delhi instead of Bombay as mentioned in para 3 of Notification dated 4-1-1991

[No. AV 15013/9/89-SSV]

RAVINDRA GUPTA, Jt Secy.

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1991

New Delhi, the 25th January, 1991

का. प्रा. 441—वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) के खंड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री बी.के. गोस्वामी के स्थान पर, श्री योगेश चन्द्र महानिदेशक (पर्यटन) को एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के निदेशक पदों में निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा.सं. ए. बी-18013/1/88-ए.ए. (पार्टे)]

ओ.पी. अग्रवाल, प्रवर सचिव

S.O. 441.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953), the Central Government hereby appoints Shri Yogesh Chandra, Director General (Tourism) as a Director on the Board of Directors of Air India and Indian Airlines, vice Shri B. K. Goswami.

[F. No. AV. 18013/1/88-AA (Pt.)]

O. P. AGGARWAL, Under Secy.

## आद्य एवं नागरिक पूति मंत्रालय

(नागरिक पूति विभाग)

भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1991

का. प्रा. 442.— भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 4 के उपविनियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एमबहारा अधिसूचित करती है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे स्वीकृत कर दिए गए हैं।

## अनुसूची

क्रम सं.	लाइसेंस संख्या	लागू होने की अवधि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तु प्रक्रम और सम्बद्ध भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सी.एम./एल.-2106733	90-04-16	एंकर इलेक्ट्रोनिक्स एंड इलेक्ट्रीकल्स, खेर गाम रोड, खेर गाम, बलसाड	बेनेट टाइप रोघन लैम्प होल्डर (बोरी पकड़) IS : 1258-1979
2	सी.एम./एल.-2106834	90-04-16	स्मूथनिक केबल (प्रा.) लि., सर्वे नं. 310 ई, एन. एच. नं. 7, मेन रोड, कालाकल गांव, तालुक गजयल, जिला मेहक	1100 बी तक कार्यकारी बोल्टता के लिए उत्प्रेक्षित पीवीसी रोघित (हैवी ह्यूटी) केबल IS : 01554-1976
3	सी.एम./एल.-2106935	90-04-16	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग एन्टरप्राइजेज, प्लॉट नं. 5, जी घाई डी सी एस्टेट, नरोडा, अहमदाबाद	मोनोसेट पम्प IS : 090/9-1979
4	सी.एम./एल.-2107028	90-04-16	टेम्पल सीमेन्ट प्रा. लि., डा. पृथ्वी पुरा, तहसील जयतरन, जिला पाली (राजस्थान)	साधारण पोर्टलैंड सीमेन्ट IS : 00269-1976
5	सी.एम./एल.-2107129	90-04-16	टाइटन पालीट्यूब्स, 10-बीबी बागान लेन, कलकत्ता-700015	उच्च घनत्व पालीथीन पाइप IS : 04984-1987
6	सी.एम./एल.-2107230	90-04-16	लायड बिटुमेन्स प्राइवेट्स, बी-788, धम्बादूर इंडस्ट्रियल एस्टेट, मद्रास-600058	कांच रेशा आधारित कोलनार पिक्च और बिटुमेन्स नमक IS : 07193-1970
7	सी.एम./एल.-2107331	90-04-16	सिगलाइट (इंडिया) प्रा. लि., बी-167, दूसरा करण पीनया इंड. एस्टेट, बंगलौर-560058	मोपेड, स्कूटर और मोटर साइकिल सवारों के लिए एनबी टाइप सुरक्षा हेलमेट IS : 04151-1982
8	सी.एम./एल.-2107432	90-04-16	सुमित इंड कसाबोरेशन, 46-बी, मली पंच घाटे स्ट्रीट मिलखा, जिला हावड़ा	2 कि. घा. के 2 टाइप तुवाहा अग्निशामक यंत्र- IS : 02878-86
9	सी.एम./एल.-2107533	90-04-16	इटीनारेटेंड फायर प्रोटेक्शन प्रा. लि. राजलूरीपाडा, जलपाईगुडी-73501	अग्निशामन के लिए यांत्रिक भाग उत्पन्न करने के लिए भाग सामग्री टाइप - फ्लूरोप्रोटीन भाग- IS : 04989-1987
10	सी.एम./एल.-2107634	90-04-16	विक्रम इंडस्ट्रीज, डी-208, सेक्टर 10, नोएडा (उ.प्र.)	प्र. वे. गै. के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस बल्ब- IS : 04246-1984

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11. सीएम/एल-2107735	90-04-18	राजस्थान पेट्रोकेमिकल्स, 7, मुकेश कालोनी, मुवर्गनपुरी इंड. एरिया, जयपुर - 302006	वैराफिन मोम टाइप - 3 IS : 04654-1974	
12. सीएम/एल-2107836	90-05-01	इयमंड सीमेंट (प्रो.) मैसूर सीमेंट लि ग्राम मडोरा जिला झांसी (उ. प्र.)	पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट- IS : 01489-76	
13. सीएम/एल-2107937	90-04-16	वि इंडियन स्टील एंड वायर प्राइवेट लि., इंदरानगर, जयपुर	पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के लिए प्रतिबल युक्त प्रलेपित लंब, 3-प्लाई, 3 मिमी पवनाम के लंब IS : 06006-1983	
14. सीएम/एल-2108030	90-04-16	कर्नाटक फारेस्ट डवलपमेंट लि., सेट्टीपूज लेटेक्स फैक्टरीविलीनीली, पुदुदुर जालुक, जो के (कर्नाटक)	अमोनिया परिरक्षित सान्द्र प्राकृतिक गैस लेटेनस ग्रेड एच ए केबल- IS : 05430-1981	
15. सीएम/एल-2108131	90-04-16	शिव शक्ति सीमेंट प्राइवेट इंडस्ट्रीज प्रा. लि., प्लॉट नं. 47 से 55 इंड. एस्टेट, जिला भद्रमवनगर	कंक्रीट पाइप (प्रबलन सहित और रहित) एनपी 2 800 मि. केबल- IS : 00458-1971	
16. सीएम/एल-2108232	90-04-16	दुगर इंडस्ट्रीज, ए-5 फंक्शनल इलेक्ट्रानिकम ईस्ट भोसारी, पुणे - 411026	5 और 15 एम्प के 250 वो के तीन पिन प्लग लचकीली सामग्री से बने- IS : 065338-1971	
17. सीएम/एल-2108333	09-04-16	बन्धकांत एंड कं., 89, यूनिट इंड. एस्टेट, बूसरा तल, डा. भारपी रोड, मुलुन्व (प.) पो. बा. नं. 7774, बम्बई - 400080	4.5 कि ग्रा धारिता 02 टाइप अग्निशामक यंत्र- IS : 02878-1986	
18. सीएम/एल-2108434	90-04-16	नवशक्ति कैमिकल्स इंडस्ट्रीज, एफ-3, रोड नं. 9, भाई डी ए मजारा, हेवराबाद पूर्व - 501507	नीलिंग साध- IS : 00868-1956	
19. सीएम/एल-2108535	90-04-16	निम्मी कैमि, डी नं. 8-9-32 हूसरी लेन, नेहरू नगर, गुदुर - 522001	औद्योगिक प्रयोजनों के लिए संश्लिष्ट डिजिट टाइप 3 केबल IS : 04956-1977	
20. सीएम/एल-2108636	90-04-16	सर्वे पेस्टीसाइड्स कारपोरेशन लि., अरिकिरी वाला, कौबूर के पास, जिला पश्चिम गोदावरी	एन्डोसल्फान 35% ईसी फार्मूलेशन- IS : 04323-1980	
21. सीएम/एल-2108737	90-04-16	सर्वे पेस्टीसाइड्स लि., अरिकिरी वाला, जिला पश्चिम गोदावरी	बी एच सी डी पी 10%(गामा भाइसोमर) 1.3 प्रतिशत IS : 00561-1978	
22. सीएम/एल-2108838	90-04-16	किसान इंडेस्टीसाइड्स कं., सी-4 इंड. एस्टेट, विजयवाड़ा	एन्डोसल्फान ईसी- IS : 04323-1980	
23. सीएम/एल-2108939	90-05-01	बहुमवर्त सीमेंट प्रा. लि., 170 ग्राम बलोपुर, भाघना कानपुर (देहात) 209203	साधारण पोर्टलैंड सीमेंट- IS : 00269-1976	
24. सीएम/एल-2109032	90-05-01	अतुल प्राइवेट मोरपी रोड, राहत गांव, जिला अमरावती	कंक्रीट पाइप (प्रबलन सहित अथवा रहित) श्रेणी एनपी 2 IS : 00458-1971	
25. सीएम/एल-2109133	90-05-01	कृष्णा सीमेंट (प्रा.) लि., ग्राम- मंडूकूर, डा.- कंसवतल, जिला सुन्डरगढ़ - 770034	पोर्टलैंड हायड्रस सीमेंट- IS : 00455-1976	
26. सीएम/एल-2109234	80-05-01	सिमसूर कंक्रीट प्रा. लि., गांव और डा. तिलपट, फरीदाबाद	शिरोपरि प्रेषण के लिए एन्थुमिनिम कालक IS : 00398-1976	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	सीएम/एल-2109335	90-05-01	मिमसूर बडकटम प्रा. लि., गांव और डा. निलपट फरीदाबाद	गिरोपरि प्रेषण के लिए अस्वीकृत इस्पात प्रबलित एल्युमिनियम- IS. 00398-1976
28	सीएम/एल-2109416	90-05-01	समलेश्वरी कौशु प्राइवेट डी-1/8 इंड एस्टेट, महीसपेट जिला, बेकानल (उड़ीसा)	बनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किया के सीकोर कन्स्टर- IS. 10325-1982
29	सीएम/एल-2109537	90-05-01	ट्रापिकल एग्रो सिस्टम्स लि., 530/2 बी बनधाम रोड, एम्बाटूर, मद्रास - 600058	आइसोप्राटयुगन डब्ल्यू पी- IS 11995-1987
30	सीएम/एल-2109638	90-05-01	श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड, प्लॉट नं. 91, लायस पैसिल के पास दहिसार चैक नाला, बम्बई - 400088	भरेलू धूरसाई के डिजेंट पाउडर ग्रेड 1 कवल- IS 04955-1982
31	सीएम/एल-2109779	90-05-01	जिमल इंडस्ट्रियल सेपटी इन्विपमेट कारपो., ए-1-851/1 जीआईडीसी मकारपुरा इंड एस्टेट बडोवा - 390010	अग्निशामन के लिए साधारण टाइप शुल्क रासा- यनिक पाउडर- IS 04308-1982
32	सीएम/एल-2109840	90-05-01	नशनल जनरल इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि., 9वां सील का पत्थर जीटी रोड, मोहनगर, गाजियाबाद (उ.प्र.)	कक्रोट प्रबलन के लिए इस्पात के उच्च सामर्थ्य (बिहृत सॉफ्ट और ताव)- IS 01786-1985
33	सीएम/एल-2109941	90-05-01	राजकोट इंडस्ट्रिक कार. लिस्ट प्रोडक्त्स यूनिज लि बूध सागर मार्ग, राजकोट - 360003	मक्खनिया पूष पाउडर- IS. 01105-1980
34	सीएम/एल-2110017	90-05-01	ग्रोन टिम्बर इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि., डा. - लिज्जत जिला मून (नागालैंड)	प्लाईवुड डब्ल्यू धार ग्रेड केवल- IS 00303-1975
35	सीएम/एल-2110118	90-05-01	एस एन कैमिकल्स इंडस्ट्रीज पी-25, गर्वमेट इंड एस्टेट महरोली रोड, गुडगांव - 122001	आइमिथोएट ईसी- IS 03903-1975
36	सीएम/एल-2110219	90-05-01	एस एन कैमिकल्स इंडस्ट्रीज, पी-25, गर्वमेट इंड एस्टेट महरोली रोड, गुडगांव - 122001	मोनोकोटोफास एसएल- IS 08074-1983
37	सीएम/एल-2110320	90-05-01	"	मैलाथियोन ईसी- IS. 02567-1978
38	सीएम/एल-2110421	90-05-01	इलेक्ट्रोकेबल्स इंडस्ट्रीज, 35-फोर्डस कालोनी, इंड एरिया स्ट्रीट नं. 6, जीटी रोड, गाहबरा, दिल्ली - 115032	एल्युमिनियम या तांबा चालक सहित खोलदार खोलरहित पीवीसी रोधित केबल- IS. 00694-1977
39	सीएम/एल-2110522	90-05-01	रमेश एच राजेश बायने प्रा. लि., 125-126 इंडस्ट्रियल एस्टेट मेहतपुर, जिला ऊना (हि.प्र.) - 174315	बाड़े के लिए तहतोक्त इस्पात प्रबलित कांटेबलर तार IS 00278-1978
40	सीएम/एल-2110623	90-05-01	गंधार वार्यम एंड केबल्स प्रा. लि., एफ-57, रिको इंड एरिया, अजमेर रोड, बेकर (राज.) - 305901	गिरोपरि प्रेषण के लिए इस्पात प्रबलित एल्यु- मिनियम चालक- IS: 00398-1976
41	सीएम/एल-2110724	90-05-01	अस्कोर्ट इजी क अक्सर रोड, महिला डिग्री कालेज, कनवल, हरिद्वार - 244408	गिरोपरि प्रेषण के लिए इस्पात प्रबलित एल्यु- मिनियम चालक- IS. 00398-1976
42	सीएम/एल-2110825	90-05-01	स्काटोन इलेक्ट्रिकल्स (आई) इंड एरिया एनआईटी, फरीदाबाद - 121001	रंगीन तांबे सहित इलेक्ट्रो रोधित नम्य केबल, ईपी रोधित, सामान्य प्रयोजन- IS 09968-1981
43	सीएम/एल-2110920	90-05-01	मोहन एल्युमिनियम प्रा. लि., 9वां सील का पत्थर, पुराभा मद्रास रोड, पो. नं. 4978, बंगलौर - 560049	अत्यधिक उच्च चोस्टता के लिए इस्पात प्रबलित एल्युमिनियम चालक- IS. 00398-1982

(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
44. सीएम/एल-2111019	90-05-01	तापी प्रीस्ट्रेस्ट प्राइडस प्रा. लि., तापी नदी का किनारा अंजला, तालुक: यवल, जिला-जलगांव, (महाराष्ट्र)	गैरबेलनायक, पूर्वप्रतिबलित कंक्रीट पाइप साइज 450 मिमी से 800 मिमी-- IS: 00784-1978	
45. सीएम/एल-2111120	90-05-01	पाइनर एक्सपोर्ट प्रा. लि., 228-बी, इंड. एरिया "ए" लुधियाना	डीजल इंजन उद्योगिक एक मिलिडर जलशीर्षित- IS: 11170-1985	
46. सीएम/एल-2111120	90-05-01	रमन पैकेजर्स (प्रा.) लि., ग्रा- संडोली, डा. बाडी, जिला सोलन (हि. प्र.)	कनस्पति के लिए एचडपीई के आघात 2 कि. मी. केवल IS: 10840-1986	
47. सीएम/एल-2111322	90-05-01	के सी एंड कं., बी- 42, इंड. एस्टेट, जोधपुर	वाष्पक वायु कूलर (डेजर्ट कूलर)- IS: 03315-1974	
48. सीएम/एल-2111423	90-05-01	डेक्को इलेक्ट्रिक इंस्ट्रुमेंट्स, एफ- 101 श्रीपाल इंड. एस्टेट एसवी रोड, जोशीवाड़ा त्रिज जोगेश्वरी, पश्चिम. बम्बई- 400102	नानइटर लासिंग टाइप के लिए फ्लश टाइप स्विच सॉकेट आउटलेट-- IS: 04615-1968	
49. सीएम/एल-2111524	90-05-01	ईथल इलेक्ट्रिकल्स, 58 जयसिंहपुर इंड काप एस्टेट लि., जयसिंहपुर तहसील शिरडी, जिला-कोल्हापुर 416101	मोनोब्लाक पम्प-- IS: 09079-1979	
50. सीएम/एल-2111625	90-05-01	कृष्णा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रुमेंट्स, डी- 19 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज - 1, नई दिल्ली - 110020	1100 वी तक कार्यकारी कंक्टता के लिए खोलदार/खोलरहित पीवीसी रोधित केबल-- IS: 00694-1977	
51. सीएम/एल-2111726	09-05-01	गुप्ता रबड इंडस्ट्रीज, 4वां कि.मी, दिल्ली रोड, सहरनपुर- 247001	रबड की कनेक्शन और उत्पादन पट्ट (उष्मा- प्रतिरोधी पट्ट) चौड़ाई 1200 मिमी तक-- IS: 01891-1978	
52. सीएम/एल-2111827	90-05-01	निखिलदीप नेबल्स, 29/4 बागपल्ली रोड, होसूर जिला धरमपुरी- 635109	शिरोपरि प्रेषण के लिए एल्यूमिनियम के लड़दार चालक-- IS: 00398-1976	
53. सीएम/एल-2111928	90-05-01	निखिलदीप नेबल्स, 29/4 बागपल्ली रोड, होसूर जिला धरमपुरी- 635109	शिरोपरि प्रेषण के लिए जर्म्त कृत इस्पात प्रबलित एल्यूमिनियम के चालक IS: 00398-1976	
54. सीएम/एल-2112021	90-05-01	दि तमिलनाडू एग्रो इंड. कारपो. लि., प्लॉट नं. 18 एंड 112 नार्थ फेज इंड. एस्टेट, एम्बाटटर, मद्रास- 600098	ब्यूटाक्लोर ईसी-- IS: 09356-1980	
55. सीएम/एल-2112122	90-05-01	भारत पल्बराइजिंग मिल्स लि., अंधेरी कुर्ला चकला नाका, बम्बई- 400093	आइसोप्रोप्टोरान डल्लूप- IS: 11995-1987	
56. सीएम/एल-2112223	90-05-01	कोकण पेस्टीसाइड्स, प्लॉट नं. ए- 4, एम आई डी सी, महाद, जिला रिणाद	डाइमिथोएट ईसी-- IS: 03903-1984	
57. सीएम/एल-2112324	90-05-01	नेशनल आर्गेनिक कौमीकल्स इंस्ट्रुमेंट्स लि., ए- 1 लोटे परशुराम एरिया, तालेंखंड, जिला रत्नगिरी	फास्फोमिडान-- IS: 06177-1981	
58. सीएम/एल-2112425	90-05-01	देवीदयाल इलेक्ट्रानिक्स वार्म्स लि., पोखरन रोड नं. 2, ठाणे- 400601	निमज्ज्य मोटर के लिए टोर अनीईड कृत चालक सहित पीवीसी रोधित वेष्टन तार-- IS: 08783-1978	
59. सीएम/एल-2112526	90-05-01	एक्सेस्ट कंप्यूटर कार्बन प्रा. लि., कालाकल ग्राम गजवल तालुक, जिला मेदक	हस्तलेखन के लिए कार्बन पेपर ग्रेड ए केबल-- IS: 03450-1976	
60. सीएम/एल-2112627	90-05-01	बालाजी एंटरप्राइजेज (प्रा. लि.), 48- इंड. एरिया, जोशीवाड़ा, जयपुर	सरचना इस्पात में बेल्लन हेतु डलवा विलेट इंगट (साधारण किस्म) IS: 06915-1978	
61. सीएम/एल-2112728	90-05-01	सर्जिमेट (इंडिया) लि., नं. 39, 5वां कस हौमिसंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया, एटडीबेला, जिला बंगलौर	आपरेशन को मेज द्रवचालित बड़ी-- IS: 05291-1961	

## MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

## BUREAU OF INDIAN STANDARDS

New Delhi, the 11th January, 1991

S O. 442:—In pursuance of sub-regulation (5) of regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given in the following schedule.

## SCHEDULE

List of Licences Granted During April, 1990.

Sl. No.	CM/L-No.	Operative date	Name & Address of the Party	Article/process	IS : No./Part
1.	CM/L-2106733	90-04-16	Anchor Electronics & Electricals Kher Gam Road Kher Gam Valsad	Baynat type insulating lamp holders (Cord Grip)	IS : 01258-79 Pt. Sc.
2.	CM/L-2106834	90-04-16	Sputnik Cable (P) Ltd. Survey No. 310 E. N.H. No. 7 Main Road Kalakkal Village, Talluk Gajwal Distt. Medak	PVC insulated (Heavy duty cables suitable for working voltages upto and including 1100 volts	IS : 01554-76 PT 01 Sc
3.	CM/L-2106935	90-04-16	Electrical Engineering Enterprises Plot No. 5 GIDC Estate Naroda Ahmedabad	Monoset Pumps	IS : 09079-79 Pt Sc
4.	CM/L-2107028	90-04-01	Temple Cement Pvt. Ltd., PO Prathvi Pura Tehsil Jaitaran Distt. Pali (Rajasthan)	Ordinary Portland Cement	IS : 00269-76 Pt Sc
5.	CM/L-2107129	90-04-16	Titan Polytubes 10 Bibi Gagan Lane Calcutta-700015	HLP Pipe	IS : 04984-87 Pt Sc
6.	CM/L-2107230	90-04-16	Lloyd Bitumens Products B-76b, Ambattur Indl. Estate Madras 600058	Glass Fibre Base Coal tar Pitch and Bitumen Felts	IS : 07193-70
7.	CM/L-2107331	90-04-16	Ciglite (India) Pvt. Ltd. B-167, Second Stage Peenya Indl. Estate Bangalore 560058	NV type protective helmet S for Mopeds, scooter & motor cycle riders, size 540 mm	IS : 04151-82 Pt Sc
8.	CM/L-2107432	90-04-16	Sumi Indl. Corpon. 46-B, Mali Panchghare Street Liluah Distt. Howrah	2 Kg Co2 type portable fire extinguishers	IS : 02878-86 Pt Sc
9.	CM/L-2107533	90-04-16	Integrated fire protection Pvt. Ltd. Rajturipara Jalpaiguri 735101	Foam concentrate for producing Mechanical foam for fire fighting type fluoroprotien foam	IS : 04989-87 Pt 03 Sc
10.	CM/L-2107634	90-04-16	Vikram Industries D-206, Sector X Noida UP	Domestic Stoves for use with LPG, double burners	IS : 04246-84 Pt Sc
11.	CM/L-2107735	90-04-16	Rajasthan Petro Chemicals 7 Mukesh Colony Sudershan Pura Indl. Area Jaipur-302006	Paraffin Wax Type 3	IS : 04654-74 Pt Sc
12.	CM/L-2107836	90-05-01	Dimond Cements (Prop. Mysore Cement Ltd. Village Madora Distt. Jhansi (UP)	Portland Pozzolana Cement	IS : 01489-76 Pt Sc

Sl. No.	CM/L-No.	Operative Date	Name & Address of the Party	Product	IS : No./Part
13.	CM/L-2107937	90-04-16	The Indian Steel & Wire Product Ltd. Jamshedpur-831008	Uncoated stress relieved strands for Prestressed concrete strands of designations upto and including 3-ply, 3mm	IS : 06005-83 Pt Sc
14.	CM/L-2108030	90-04-16	Karnataka Forest Dev. Corpn. Ltd. Centrifuge Latex Factory Bililele Putter Talluk D.K. (Karnataka)	Ammonia Preserved concentrated, Natural rubber latex, Grade ha only	IS : 05430-81 Pt Sc
15.	CM/L-2108131	90-04-16	Shiva Shakti Cement Pipe Industries Pvt. Ltd. Plot N. 47 to 55 Indl. Estate Distt. Ahmednagar	Concrete pipes (with & without reinforcement) NP2 800 M only	IS : 00458-71 Pt Sc
16.	CM/L-2108232	90-04-16	Dagar Industries A-5, Functional Electronics EST Bhosari Pune-411026	Three pin plugs of 5A and 15A, 250V, Made of resilient materials	IS : 06538-71 Pt Sc
17.	CM/L-2108333	90-04-16	Chandrakant & Co. 89, Unique Indl. Estate (New) Second Floor Dr. R.P. Road Mulund (W), Post Box 7774 Bombay-400080	4.5 kg capacity only CO2 type portable fire extinguish	IS : 02878-86 Pt Sc
18.	CM/L-2108434	90-04-16	Navshakti Chemical Industries F-3 B, Road No. 9 Ida Nacharam Hyderabad East - 501507	Sealing Wax	IS : 00868-56 Pt Sc
19.	CM/L-2108535	90-04-16	Nimi Chems D No. 8-9-32 Second lane Nehru Nagar Guntur-522001	Synthetic detergent for industrial purposes type 3 only	IS : 04956-77 Pt Sc
20.	CM/L-2108636	90-04-16	Southern Pesticides Corpn. Ltd. Arikirevala Nar Kovvur, Distt. West Godawari	Endosulfan 35 per cent EC formulation	IS : 04323-80 Pt Sc
21.	CM/L-2108737	90-04-16	Southern Pesticides Corpn. Ltd. Arikirevala Distt. West Godawari	BHC DP 10 per cent (Gamma-Isomer 1.3 per cent)	IS : 00561-78 Pt Sc
22.	CM/L-2108838	90-04-16	Kitsan Insecticides Co. C-14, Indl. Estate Vijalwada-520007	Endosulfan EC	IS : 04323-80 Pt Sc
23.	CM/L-2108939	90-05-01	Brahmavarta Cements Pvt. Ltd. 170, Village Bahlopur Mandhana Kanpur (Dehat) 209203	Ordinary Portland Cement	IS : 00269-76 Pt Sc
24.	CM/L-2109032	90-05-01	Atul Pipes Morshi Road Rahat Gaon Distt. Amravati	Concrete pipe with & without reinforcement class NP2	IS : 00458-71 Pt Sc
25.	CM/L-2109133	90-05-01	Krishna Cement (P) Ltd. Village Mandiakudar PO Kansbahal Distt. Sundargarh-770034	Portland Slag Cement	IS : 00455-76 Pt Sc
26.	CM/L-2109234	90-05-01	Simsur Conductors Pvt. Ltd. Village & PO Tilpat Faridabad	Aluminium conductors for overhead transmission purpose	IS : 00398-76 Pt 01 Sc
27.	CM/L-2109335	90-05-01	Simsur Conductors Pvt. Ltd. PO Tilpat Faridabad	Aluminium conductors galvanized steel reinforced or overhead transmission purposes	IS : 00398-76 Pt 02 Sc

Sl. No.	CM/L-No.	Operative Date	Name & Address of the Party	Product	IS : No./Part
28.	CM/L-2109436	90-05-01	Samaleswari Cashew Products D-1/6, Indl. Estate Mahisapat Distt. Dhenkanal (Orissa)	15 cg square tins for vanaspati and edible oils	IS : 10325-82 Pt Sc
29.	CM/L-2101537	90-05-01	Tropiol Agro Systems Ltd. 530-2-B, Vangaara Road, Ambattur Madras-600058	Isoproturon WP	IS : 11995-87 Pt Sc
30.	CM/L-210638	90-05-01	Shri Mahila Griha Udyog Lijjat Paad Plot No. 91 Near Lion Pencil Dahisar Check Naka Bombay-400068	Household Laundry Detergent powder grade 1 only	IS : 04955-82 Pt Sc
31.	CM/L-2109739	90-05-01	Vimal Indl. Safety Equipment Corpn. A-1-851/1, GIDC Pott Box No. 783 Makarpura Indl. Area Baroda-390010	Ordinary type dry chemical powder for fire fighting	IS : 04308-82 Pt Sc
32.	CM/L-2109840	90-05-01	National General Industries (P) Ltd. 9th Milestone- G.T. Road, Mohan Nagar Ghaziabad (UP)	High strength deformed steel bars and wires for concrete reinforcement	IS : 01786-85 Pt Sc
33.	CM/L-2109941	90-05-01	Rajkot Distt. Co.Op. Milk Producers Union Ltd. Dudh Sagar Marg Rajkot 360003	Skim milk powder	IS : 001165-86 Pt Sc
34.	CM/L-2110017	90-05-01	Green Timber Industries (P) Ltd. PO Tizit Distt. Mun (Nagaland)	Plywood wwr grade only	IS : 00303-75 Pt Sc
35.	CM/L-2110118	90-05-01	S.N. Chemical Industries B-25, Govt. Indl. Estate Mehrauli Road Gurgaon-122001	Dimethoate EC	IS : 03903-75 Pt Sc
36.	CM/L-2110119	90-05-01	S.N. Chemical Industries B-25, Govt. Indl. Estate Mehrauli Road Gurgaon-122001	Monocrotophos SL	IS : 08074-83 Pt Sc
37.	CM/L-210370	90-05-01	S.N. Chemicals Industries B-25, Govt. Indl. Estate Mehrauli Road Gurgaon-122001	Malathion EC	IS : 02567-78 Pt Sc
38.	CM/L-2110421	90-05-01	Electro Cable Industries 35, Priests Colony Indl Area Street No. 5 G.T. Road Shahdara Delhi-110032	PVC insulated unsheathed or sheathed cables with copper or Aluminium conductors	IS : 00694-77 Pt Sc
39.	CM/L-2110522	90-05-01	Rakesh & Rajesh Wires Pvt. Ltd. 125-126, Indl. Estate Mehat Pur Distt. Una (HP) 174315	Galvanized steel barbed wire for fencing	IS : 00278-78 Pt Sc
40.	CM/L-2110523	90-05-01	Gandhar Wire & Cables Pvt. Ltd. F-57, RICO Indl. Area Ajmer Road Barwar (Rajasthan) 305901	Aluminium conductors galvanized steel reinforced for overhead transmission	IS : 00398-76 Pt 02 Sc
41.	CM/L-2110724	90-05-01	Askort Engg. Co. Aksar Road Mahila Degree College Kankhal Hardwar-244408	Aluminium conductors galvanized steel reinforced for overhead transmission	IS : 00398-76 Pt 02 Sc

Sl. No.	CM/L-No.	Operative Date	Name & Address of the Party	Product	IS : No./Part
42.	CM/L-211025	90-05-01	Styrene Electrical (I) G-42-43, Indl. Area N.I.T. Faridabad Faridabad-121001	Elastomer insulated flexible cables with tinned copper EP insulated for general purpose	IS : 09968-81 Pt 02 Sc
43.	CM/L-211026	90-05-01	Mohan Aluminium Pvt. Ltd. 9th Milestone Old Madras Road PB No. 4976 Bangalore-560049	Aluminium conductors galvanized steel reinforced for extra high voltage	IS : 00398-82 Pt 05 Sc
44.	CM/L-2111019	90-05-01	Tapi Prestressed Products Pvt. Ltd. Bank of River Tapi Anjala Taluka-Yawal Distt. Jalgaon (Maharashtra)	Non cylindrical type prestressed concrete pipe size 450 mm to 800 mm	IS : 00784-78 Pt Sc
45.	CM/L-2111120	90-05-01	Pioneer Exports Pvt. Ltd. 228-B, Indl. Area 'A' Ludhiana	Diesel engine vertical single cylinder water cooled	IS : 11170-85 Pt Sc
46.	CM/L-2111221	90-05-01	Raman Packages (P) Ltd. Village Sandoli PO Bassi Distt. Solan (HP)	HDPE containers for vanaspathi 2kg only	IS : 10840-86 Pt Sc
47.	CM/L-2111322	90-05-01	Kay Cee & Co. B-42, Indl. Estate Jodhpur	Evaporative air cooler (desert cooler)	IS : 03315-74 Pt Sc
48.	CM/L-2111423	90-05-01	Decco Electric Industries F-101, Shripal Indl. Estate S.V. Road Oshiwara Bridge Jogeswari West, Bombay-400102	Flush type switch sockets outlets for non-interlocking type	IS : 04615-68 Pt Sc
49.	CM/L-2111524	90-05-01	Eagle Electricals 53 Jay Singhpur Indl. Co-op. Estate Ltd. Jay Singh Pur, Teh. Shurchi Distt. Kolhapur-416001	Monoblock pumpsets	IS : 09079-79 Pt Sc
50.	CM/L-2111625	90-05-01	Krishna Electrical Industries D-19, Okhla Indl. Area Phase I New Delhi-110020	PVC insulated unsheathed or sheathed cables for working voltages up to and including 1100 volts	IS : 00694-77 Pt Sc
51.	CM/L-2111726	90-05-01	Gupta Rubber Industries 4th Km, Delhi Road Saharanpur-247001	Rubber conveyor and elevator belting (heat resistance belting) of width upto and including 1200 mm	IS : 01891-78 Pt 02 Sc
52.	CM/L-2111827	90-05-01	Nikhildeep Cables 29/4, Begapalli Road Hosur Distt. Dharampur-1635109	Aluminium stranded conductors for overhead transmission purposes	IS : 00398-76 Pt 01 Sc
53.	CM/L-2111928	90-05-01	Nikhil Deep Cables 29/4, Begapalli Road Hosur Distt. Dharampur-1635109	Aluminium conductors galvanized steel reinforced for overhead transmission purposes	IS : 00398-76 Pt 02 Sc
54.	CM/L-2112021	90-05-01	The Tamil Nadu Agro Inds. Corp. Ltd. Plot Nos. 18 & 112 North Phase Ambattur Madras-600098	Butachlor EC	IS : 09356-80 Pt Sc
55.	CM/L-2112122	90-05-01	Bharat Pulverising Mills Ltd. Andheri-Kurla Road Chakala Naka Andheri (E) Bombay-400093	Isoproturon WP	IS : 11995-87 Pt Sc
56.	CM/L-2112223	90-05-01	Konkan Pesticides Plot No. A-4 MIDC Mahad Distt. Raigad	Dimethate EC	IS : 03903-84 Pt Sc

1	2	3	4	5	6
57. CM/L-2112314	90-05-01	National organic chemical Industries Ltd. A-1, Lote Parashram Area Talkhel Distt. Ratnagiri	Phosphamidon WSC	IS : 06177-81 Pt Sc	
58. CM/L-2112425	90-05-01	Dev. ayal Electronics Wires Ltd. Pakhara Road No. 2 Thane-400601	PVC insulated winding wires with solid annealed copper conductor for submersible motors	IS : 08783-79 Pt Sc	
59. CM/L-2112526	90-05-01	Everest Composite Carbons Pvt Ltd Kalakkal Village Gajwal Taluk Distt. Meerut	Carbon paper handwriting grade only	IS : 03450-76 Pt Sc	
60. CM/L-2112627	90-05-01	Balaji Enterprises (P) Ltd. 48( Indl. Area Jhotwala Jaipur-302012	Cast billets ingots for rolling into structural steels (ordinary quality)	IS : 06915-78 Pt Sc	
61. CM/L-2112728	90-05-01	Surgiment (India) Ltd. No. 39, 5th cross Honnasandra Indl. area attibela Distt. Bangalore	Operation tables, hydraulic, major	IS : 05291-69 Pt Sc	

[No. CMD/13 : 11]

का.आ. 443 —भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 4 के उपविनियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्-  
द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्वीकृत कर दिए गए हैं—

## अनुसूची

क्र. सं. लाइसेंस संख्या	लागू होने की अवधि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तु/प्रक्रम और सम्बद्ध भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
1. सीएम/एल-2112829	90-05-01	चमक होल्डिंग लि., 8/7, एम.टी.एच रोड, अम्बासूर, मद्रास-600098	क्रीकट प्रबलन के लिए एचएसडी सरिए और तार, 16 मिमी से 25 मिमी तक ग्रेड Fe—415 IS—01786—85
2. सीएम/एल-2112930	90-05-01	नेशनल प्लाईवुड इंडस्ट्रीज लि., मकुम रोड, तिनसुकिया (असम)—786125	क्रीकट के शटिंग के कार्य के लिए प्लाईवुड IS—04990—81
3. सीएम/एल-2113023	90-05-16	नवीन एन्टरप्राइजेज, 117, जी.टी. रोड ज्ञानी बांडर, डा. चिकम्बरपुर, साहिबाबाद (उ.प्र.)	1100 वो. तक कार्यकारी वोल्टता के लिए एल्यूमीनियम चालकों सहित खोलदार/खोल- रहित पीवीसी रोधित केबल IS—00694—77
4. सीएम/एल-2113124	90-05-16	एवरेस्ट कम्प्यूटर कार्बोन्स प्रा. लि. कालाकल पाम, गजवल, तालुक, जिला मेडक (आ.प्र.)	टाइपराइटिंग के लिए कार्बन पेपर ग्रेड 3 IS—01551—76
5. सीएम/एल-2113225	90-05-16	एटलस इंडस्ट्रीज, 71 लक्ष्मी उद्योग, नगर, जी.टी. करनाल रोड, दिल्ली	टाइप एसी सवातन पखे 230 वो एक फेज 50 हर्टज IS:02312-67
6. सीएम/एल-2113326	90-05-16	अभिषेक स्टील्स लि., गंडाला मोमापल्ली बायो टाकिमपेट मेडकल मंडल, रंगारडुडी जिला-500014	संरचना इस्पात (मानक किस्म) IS—00226—75
7. सीएम/एल-2113427	90-05-16	जनरल इंजीनियरिंग कं., 1/42, मेदुपलायम रोड, कवन्डापलायम, कोयम्बटूर-641030	कुछ प्रयोजनों के लिए, साफ, ठंडे, ताजे पानी हेतु क्षैतिज अपकेन्द्रीपम्प IS—06595—80
8. सीएम/एल-2113528	90-05-16	अशोक वायर्स प्राइवेट्स, चौक भीत नगर, जालंधर	बाड़े के लिए जस्तीकृत इस्पात के तार IS—00278—78

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9. सीएम/एल-2113629	90-05-16	प्रकाश इंडस्ट्री, 136/140-98 इंडस्ट्रियल एरिया-1, चंडीगढ़	डोर क्लोजर (ब्रॉड चालन) द्वारा नियंत्रित पंच नाम-2 IS:-03564-75	
10. सीएम/एल-2113730	90-05-16	हनुमान टिन फैक्ट्री, 12 बी इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोवाम, जयपुर	वनस्पति, खाद्य तेल और बेकरी मोयन के पैकिंग के लिए 15 किग्रा के चौकोर कनस्तर IS:-10325-89	
11. सीएम/एल-2113831	90-05-16	अभिषेक स्टील्स लि., गूडला पांचामपल्ली, वाया हाकिमपेट, मडकल मंडल, जिला-रंगारेड्डी-500014	संरचना इस्पात (साधारण किस्म) IS: 019177-75	
12. सीएम/एल-2113932	90-05-16	सूची स्टील्स लि., डा. एवं रेलवे स्टेशन सरदार नगर, गोरखपुर	संरचना इस्पात (मानक किस्म) में बेल्सन हेतु छलवां क्लिपेट इंगट ग्रेड 1 और 2 IS:-06914-78	
13. सीएम/एल-2114025	90-05-16	सराया स्टील्स लि., पो एवं रेलवे स्टेशन सरदार नगर, गोरखपुर	संरचना इस्पात (साधारण किस्म) में बेल्सन हेतु छलवां क्लिपेट इंगट ग्रेड 1 और 2 IS:-06915-78	
14. सीएम/एल-2114126	90-05-16	लिफ्ट घाल इंजीनियर्स (प्रा.) लि. ए-34 जी.टी करमाल रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110033	1 टन, 2 टन और 5 टन क्षमता के अजीर धिरनी ब्लाक IS:-03832-86	
15. सीएम/एल-2114227	90-05-16	ए.के.जी. इंडस्ट्रीज, बी-64 ओधला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020	रोधन सामग्री के दृढ़ सादे कंड्यूट, साइज 25 मिमी श्रेणी मध्यम IS:-09537-83	
16. सीएम/एल-2114328	90-05-16	बी.ई.सी. इंडस्ट्रीज, सी-108, मायापुरी इंड. एरिया, फेज-II नई दिल्ली-110064	वृद्ध घघ्रात्विक कंड्यूट, विद्युत संस्थापन के लिए साइज 20 और 25 मिमी IS:-02507-73	
17. सीएम/एल-2114429	90-05-16	ए.के. एन्टरप्राइजेज, 507/50 जैसोर रोड, कलकत्ता-700016	सोडा धम्ल टाइप ग्रनिन शामक के लिए रिफिल IS:-05490-77	
18. सीएम/एल-2114530	90-05-16	हातिम कार्बन कं. प्रा.लि., 90 रिफल स्ट्रीट, कलकत्ता-700016	इलेक्ट्रो ग्रेफाइट ग्रेड हेतु बिजली की मशीन हेतु कार्बन ब्रश IS:-03003-78	
19. सीएम/एल-2114631	90-05-16	हिमसन मेटल गंज स्टील वर्क्स (रजि.) कपूरथला रोड, जालंधर (पंजाब)-144002	छलवां पीतल के बिज टैप साइज 15 और 20 मिमी IS:-00781-84	
20. सीएम/एल-2114732	90-05-16	चनमा स्टील ट्यूब्स प्रा.लि., प्लॉट नं. 10 सेक्टर-III परधान (हि.प्र.)	संरचना प्रयोजन हेतु इस्पात के पाइप सादे सिरे ग्रेड 1, 210 श्रेणी मध्यम IS:-01161-79	
21. सीएम/एल-2114833	90-05-16	लक्ष्मी इंडस्ट्रीज, 11-बी प्राइवेट इंड. एम्प्लेट कुरची कोयम्बतूर-641021	एक फेजी मोटर IS:-00996-79	
22. सीएम/एल-2114934	90-05-16	जिन्दल पाइपस लि., 22 स मील, दिल्ली हापुड़ रोड, पो.बा. जिन्दल नगर, गाजियाबाद	जलकूप के लिए इस्पात के पाइप साइज 300 मिमी एनबी, सादे बल्ल सिरे ग्रेड-415 IS:-04270-83	
23. सीएम/एल-2115027	90-05-16	बेलपार्क कं. प्रा.लि., बी.-195, फेज-II नोएडा (उ.प्र.)-201305	मुहर पेड की स्याही, ग्रेड बी IS:-00393-85	
24. सीएम/एल-2115128	90-05-16	लूजल जट मिल्स (प्रा. एकता लि.) डा. चंगेल, जि. हावड़ा (पं.बं.)-711308	सीमेंट पैकिंग के लिए हल्के पटसन के कट्टे IS:-12154-87	
25. सीएम/एल-2115229	90-05-16	हुगली मिल्स प्रोजेक्ट्स लि. (इकाई हुकुमचंद जट मिल) डा. हाजीनगर, जि. 24 परगना उत्तर (प.बं.)	सीमेंट पैकिंग के लिए हल्के पटसन के कट्टे IS:-12154-87	
26. सीएम/एल-2115330	90-05-16	लामेघेय मैच्य (प्रा.) लि., 10 के.एन. मुखर्जी रोड, तालपुकर, 24 परगना	407 ग्रा मी. <sup>2</sup> , 85×39 ररपुलिन कपड़े से उत्पादित परतदार पटसन के बोरे IS:-07406-84	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27. सीएम/एल-2115431	90-05-16	गर्ग फास्टनेस, 34, जी.एन.टी. रोड माधवराम, मद्रास-600113	स्लेप हैड रिबेट, साइज 6 से 16 मिमी व्यास IS : 07406-84	
28. सीएम/एल-2115532	90-05-16	नेहल केवल इंडस्ट्रीज, सी-3/3 जीआईडीसी मिल रोड, नाडियाड जि. केवरा (गुजरात)	1100 वत तक कार्यकारी बोस्टता के लिए पीवीसी रोधित केवल, एल्युमीनियम तांबा चालकों सहित IS : IS-00694-77	
29. सीएम/एल-2115633	90-05-16	विरल इन्वेंटानिक्स प्रा.लि., डी-7 एमआईडीसी एमवेड, नासिक-422010	मोटर बाहनों के लिए तांबा चालक खोल रहित पीवीसी रोधित केवल IS : 02465-84	
30. सीएम/एल-2115734	90-05-16	अनिल एजीमियरिंग वर्क्स, जी.टी. रोड, दिल्ली आई पास करमाल (हरियाणा)	कृषि प्रयोजनों के लिए अपक्रेमी पम्प हेतु सीम फेजी स्विचरेल पिजरी प्रेरण मोटर 3.7 किवा श्रेणी ए रोधन सहित IS : 07538-75	
31. सीएम/एल-211835	90-05-16	कास्मिक इंडस्ट्रीज, 119 सोनल हैवी इंड. एस्टेट रामचन्द्रन लेन (एक्स) मलाड (प) बम्बई-400064	घरेलू और ऐसे ही प्रयोजनों के लिए 250 वो, 5 और 15 एसी पलश माउन्टिंग स्विच प्रेरण परिपथ स्विच को छोड़कर IS : 03854-66	
32. सीएम/एल-2115936	90-05-16	गार्डन प्लेवार्गिंग इंड, शक्ति इंड. एस्टेट यूनिट नं. ए-249, दूसरा तल, सरोजिनी नायडू, मुलुख (प), बम्बई-400080	कोलतार रंग निर्मितियां ठोस टाइ केवल IS : 05346-75	
33. सीएम/एल-2116029	90-05-16	असिता केवल इंडस्ट्रीज, ए-88, स्ट्रीट नं. 23, लक्ष्मपुरी दिल्ली-111005	पोलीएस्टर टेप सेपरेटर और तांबा चालक सहित सामान्य प्रयोजन के रबड़ कंपाउंड सहित बेल्टिंग केवल IS : 09857-81	
34. सीएम/एल-2116130	90-05-16	महालक्ष्मी केवल इंडस्ट्रीज, नं. 3, इंडस्ट्रियल एरिया, तिलक नगर नई दिल्ली-110019	1100 वो तक कार्यकारी बोस्टता हेतु कवचित/अकवचित पीवीसी रोधित (हैवी ड्यूटी) केवल IS : 01554-76	
35. सीएम/एल-2116231	90-05-16	पौलीकैब प्राइमर्स प्रा.लि., आदित्यपुर इंड. एरिया, प्लाट नं. सी-15, दूसरी फेज, जमशेदपुर-83219	11 वो तक कार्यकारी बोस्टता हेतु एल्युमीनियम चालक सहित खोलदार/खोलरहित पीवीसी रोधित केवल IS : 00694-77	
36. सीएम/एल-2116332	90-05-16	महालक्ष्मी केवल इंडस्ट्रीज नं. 3, इंड. एरिया तिलक नगर, नई दिल्ली-110018	11 वो तक कार्यकारी बोस्टता हेतु एल्युमीनियम चालक सहित खोलदार/खोलरहित पीवीसी रोधित केवल, तांबा चालक सहित IS : 00694-77	
37. सीएम/एल-2116433	90-05-16	विजय केबल्स, 44-ए दितशाद गार्डन, शाहदरा दिल्ली-110095	11 वो तक कार्यकारी बोस्टता हेतु एल्युमीनियम चालक सहित खोलदार/खोलरहित पीवीसी रोधित केवल, तांबा चालक सहित IS : 00694-77	
38. सीएम/एल-2116534	90-05-16	विमला इंडस्ट्रीज, बी-14, गली नं. 7 आनंद पब्लि, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005	अजस्तीकृत 20 लिटर धारिता के स्टील ड्रम ग्रेड बी, और बी2 IS : 02552-79	
39. सीएम/एल-2116635	90-05-16	श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक शेतकारी संघ लि. इंड. एरिया, हनुमान गढ़ जंक्शन श्री गंगानगर जिला	मखनिया दूध पाउडर स्प्रे शुष्कित IS : 01165-86	
40. सीएम/एल-2116736	90-05-16	दुजोबासा सीमेंट लि. इंड. एरिया, खंडेला, जि. सीकर (राज.)	माधारण पोर्टलैंड सीमेंट IS : 00269-76	
41. सीएम/एल-2116867	90-05-16	कृष्ण कंठकर्तरे, एफ-96, रोड नं. 7 बी.के. आई. एरिया, जयपुर-302013	शिरोपरि प्रेषण के लिए एल्युमीनियम के लड़वार चालक IS : 00398-73	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42. सीएम/एल-2116938	90-05-16	मधुषी ट्रेडर्स पेट्रोल पम्प, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर	कांच रेशा प्रबलित प्लास्टिक (जीआरपी) फलश की टंकी, 10 लिटर धारिता IS : 07231-84	
43. सीएम/एल-2117031	90-05-16	गुप्ता कैमीकल्स प्रा. लि., बी-144 रोड नं. 9 निम्बकर्मा इंड. एरिया, जयपुर-302013	कार्बोराइल 50 प्रतिशत द्रव्यमानानुसार, डब्ल्यू डी पी फार्मूलेशन IS : 07121-73	
44. सीएम/एल-2117132	90-05-16	गुप्ता कैमीकल्स प्रा. लि., बी-144, रोड नं. 9, बी.के. आई एरिया, जयपुर-302013	कार्बोराइल 5% (मात्रानुसार) और 10% (मात्रानुसार) डी पी फार्मूलेशन IS : 07122-84	
45. सीएम/एल-2117233	40-05-16	भूपेन्द्र हिंजेस, (प्रा.) लि., 114, इंड. एरिया, फेज-1, चंडीगढ़	इस्पात के कब्जे (मध्यम भार) साइज 75 मिमी 100 मिमी, 125 मिमी IS : 01341-81	
46. सीएम/एल-2117334	90-05-16	सिटिजन पेंट्स, 3-बी, शिवनगर, बटाला रोड, अमृतसर (पंजाब)	डिस्टम्पर तेल, इमल्शन, मध्यम रंग रेज केवल IS : 00428-69	
47. सीएम/एल-2117435	90-05-16	जीकोइन्डोविथर्स, ग्रीत फेलस के आगे लुधियाना (पंजाब)-144003	हस्त चालित नेपसैक छिड़काव यंत्र, गैरदाब रोकने टाइप IS : 01970-82	
48. सीएम/एल-2117536	90-05-16	मिलोएग्रो इंडस्ट्रीज लि., ग्राम-जोरसारी, जिला-पटियाला (पंजाब)	बीएचसी गामाआइसोमर 6.5 प्रतिशत (मात्रानुसार) डब्ल्यू डी पी फार्मूलेशन IS : 00562-78	
49. सीएम/एल-2117637	90-05-16	पंजाब पेट्रोसाइन्स इंड काप-सोसायटी लि., चंडीगढ़-रोपड़ रोड, खानपुर सहस्रसिख-खरार जि. रोपड़ (पंजाब)	बीएचसी 10% (गामाआइसोमर 1.3% मात्रानुसार) डी पी फार्मूलेशन IS : 00561-78	
50. सीएम/एल-2117738	90-05-16	इशा कैमीकल माइफो न्यूट्रिएन्ट्स प्रा. लि., लेन-2, फेज-2, सिडको इंड. काम्पलेक्स बारी ब्राह्मण, जम्मू	जिक सल्फेट, कृषि ग्रेड IS : 08249-76	
51. सीएम/एल-2117839	90-05-16	पुष्पा जी एल एस लैम्प वर्क्स नं. 1456 रोड गणपति मोस्ट, कोयम्बतूर-641006	टगस्टन फ्लामेंट सामान्य सेवा बिजली के बल्ब, 250 वो एक कुंडली/कुंडलित कुंडली और 100 वाट तक बी 22 डी टोपी सहित IS : 00418-78	
52. सीएम/एल-2117940	90-05-16	पी.के. बाहुबलम वर्क्स आर.एस. नं. 374, मद्रास बंगलोर ट्रंक रोड, वर्धराजपुरम, मद्रास-602103	एच एस डी एरिए 7 मिमी से 22 मिमी तक एफ ई 415 IS : 01786-85	
53. सीएम/एल-2118033	90-05-16	उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज लि., ताती सिलवाई रांची-835103	लाकड कुंडली वैण्टन रस्सी 25 मिमी IS : 03629-78	
54. सीएम/एल-2118134	90-05-16	सूरज वनस्पति लि., ए-26, यूपी एस आई डी सी इंड. एरिया सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर (उ.प्र.)	वनस्पति IS : 10633-86	
55. सीएम/एल-2118235	90-06-01	फील्डमैन इंजीनियरिंग प्रा. लि., अजी इंड. एरिया, जीआईडीसी फेज-2 100 फिट मैन रोड, राजकोट-360003	अपकेन्द्र पम्प IS : 06595-80	
56. सीएम/एल-2118336	90-06-01	स्वीटेक इंजीनियर्स प्रा. लि., सी-120, सैक्टर 2, नोएडा (उ.प्र.)-201301	औद्योगिक प्रयोग के लिये सिलवाई मशीन IS : 12109-87	
57. सीएम/एल-2118437	90-06-01	गोविन्द केबल इंडस्ट्रीज - 207-ए, पटपड़गंज, दिल्ली-110092	1100 वो तक कार्यकारी अल्लोस्टोमर रोधित केबल IS : 09968-81	
58. सीएम/एल-2118538	90-06-01	शशि रबड़ फोम इंडस्ट्रीज, डब्ल्यू जैड-55 नारायणा गांव, दिल्ली-110028	लेटेक्स फोम रबड़ प्राइवेट्स टाइप क्रोड वाली ग्रेड एफ केबल IS : 01741-60	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59 सी एम/एल-2118639	90-06-01	आशी लैम्प प्रा. लि. , 554 पूनमेल्ली हाई रोड अरम्बक्कम, मद्रास-600106	सामान्य सेवा टंगस्टन तंतू, बिजली लैम्प IS : 00418--78	
60 सी एम/एल-2118740	90-06-01	आर.बी. जोधा मल एड कं. प्रा लि टोपा शेखरियान, जम्मू	संरचना इस्पात (मानक किस्म) में बैलून हेतु सतत द्वि-बिलेट IS : 00914--79	
61. सी एम/एल-2118841	90-06-01	एस.टी.पी. लि , 26 लेक रोड भंडूप बम्बई-400078	सड़क के लिये बिटुमेन इमल्शन टाइप : टाइप शी प्र जमने वाला सीमेट IS : 08887--78	
62. सी एम/एल-2118942	90-06-01	मेहतपुर पेकेजिंग प्रा.लि., 128 इंडस्ट्रियल एरिया, मेहतपुर (जि. ) ऊना (हि. प्र. )	उर्वरक पैकिंग के लिये परदार पटसन के बोरे IS : 07406--84	
63 सी एम/एल-2119035	90-06-01	आल इंडिया मैडीकल कारपोरेशन ए.आई.एम.सी. सिमपोली रोड, बोरिवली (प) बम्बई-400092	फेनबलरेट 20% (मात्रानुसार) ई सी फार्मूलेशन IS : 11997--87	
64. सी एम/एल-2119136	90-06-01	वर्धमान पावर प्रा. लि. , जी-849 रोड नं. 14, बीकेआई एरिया, जयपुर-302013	शिरोपरि प्रेषण के लिये एल्यूमिनियम के लड़दार चालक IS : 00398--76	
65. सी एम/एल-2119237	90-06-01	वर्धमान पावर प्रा. लि. जी.-849, रोड नं. 14 बी.के.आई. एरिया, जयपुर-302013	शिरोपरि प्रेषण के लिये जस्तीकृत इस्पात प्रबलित एल्यूमिनियम के चालक IS : 00398--76	
66. सी एम/एल-2119338	90-06-01	नेशनल एग्रो कैंमीकल्स, सी-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पटना-800013	फास्फोमिडान, 85 % मात्रानुसार, डब्ल्यू एस सी फार्मूलेशन IS : 06177--81	
67. सी एम/एल-2119439	90-06-01	अंबिका प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, 38/39, जय बीबी रोड, घूसूरी, हावड़ा	एक गठन वाली रजदकृत जलसह कपड़ा IS : 05915--70	
68. सी एम/एल-2119540	90-06-01	गणेश एग्रो इंडस्ट्रीज ग्रा. वेदपुर, कलोल-सेहसाना हाईवे नं. 8 तालुक काडी जिला-मेहसाना-452705	नुकी- दातेदार टाइप पावर थ्रेशर की सुरक्षा अपेक्षाएं रेटिंग II किवा (15 अश्वशक्ति) क.प्र.मि. रेंज 500-700 IS : 09020--79	
69. सी एम/एल-2119641	90-06-01	पीटर इंजीनियरिंग कं. (रजि.) ए-133 वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली-110052	घरेलू प्रयोजनों के लिये सिलाई मशीन हाथ और पैर चालित IS : 01610--81	
70. सी एम/एल-2119742	90-06-01	गर्ग फास्टनर्स, 34 जी.एन.टी. रोड, माधवराय, मद्रास-600110	स्नैप हैड रिबेट IS : 01929--82	
71. सी एम/एल-2119843	90-06-01	तुलसी फाऊंड्रीज एंड फॉर्जिंग्स (यूनिट) इंड. एस्टेट, कोलापल्ली, पो.आ.बा. नं. 20 शोरानूर, शोरानूर (केरल)-679122	टेन्जड फावड़ा, 1 6 किग्रा बिना हल्ये का IS : 01759--86	
72 सी एम/एल-2119944	90-06-01	एल्विन इलैक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, 78 काकड़ इंड. एस्टेट, लेडी जमशेदजी रोड, माहिम, बम्बई-400016	घरेलू और ऐसी ही प्रयोजनों के लिये 5 ए, 250 बो, ए सी केवल पलश टाइप बनने स्विच IS : 03854--66	
73 सी एम/एल-2120020	90-06-01	राज पाइप्स लि. , ई-8 एम आई डी सी इंड एरिया, हिंगना रोड, नागपुर-440016	रोधन सामग्री के दृढ़ सादा कंड्यूट साइज 20 मिमी टाइप-मध्यम केवल IS : 09537--83	
74. सी एम/एल-2120121	90-06-01	साफिरे इंड प्रा.लि., बी.-491 इंड. एरिया, भिवाडी जि. अलवर	पूराने 33.3 लिटर कुल धारिता वाले द्र पे में के सिलिंडरों का नवीनीकरण और परीक्षण IS : 03196--82	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
75. सी एम/एल-2120222	90-06-01	गंधार बायर्स एंड केथल प्रा. लि., ए-57, रिकोर्ड्स, एरिया, अजमेर रोड ब्यावर (राज.) -305901	गिरोपरि प्रेषण के लिये एल्यूमिनियम के लहदार चालक IS : 00398--76	
76. सी एम/एल-2120224	90-06-01	सर्वाटिया कंस्ट्रक्शंस प्रा. लि., 111, ईड, एरिया, जलवाड़ा, जयपुर-303012	गिरोपरि प्रेषण के लिये जस्ताकृत इस्पात प्रचलित एल्यूमिनियम के लहदार चालक IS : 00398-76	
77. सी एम/एल-2120424	90-06-01	एसोसिएटेड रबड़ इंडस्ट्रीज, 12/1 देवी मंदिर रोड, पो. सा. लिलुहा, हावड़ा	एचडोपीई पाइप श्रेणी 3 से 110 मिमी तक श्रेणी 4 110 मिमी तक श्रेणी 5 110 मिमी तक IS : 04984--87	
78. सी एम/एल-2120525	90-06-01	बजरंग भार्गव एंड स्टील कं. लि., 100 ए. बी. सिन रोड, तिरुवोट्टीयूर मद्रास-600019	क्रीट प्रचलन हेतु एचएचडी मरिण साइज 110 मिमी से 32 मिमी तक ग्रेड एफ ई-415 IS : 01786--85	
79. सी एम/एल-2120626	90-06-01	गुजराल वैक्स, ए 2/III, जी आई डी सी, फेज-2, घेतवा, जिला अहमदाबाद-382445	पैराफिन मोम टाइप 3 IS : 04654--74	
80. सी एम/एल-2120727	90-06-01	पावरफोन इंडस्ट्रीज, प्लॉट नं. 45, फेज-II, बादली इंडस्ट्रियल एस्टेट, दिल्ली-110042	ब पे गै के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस बूल्हा IS : 04654--74	
81. सी एम/एल-2120828	90-06-01	डायमंड सीमेंट, डा. नरसिंहपुर जि. दमोह (म. प्र.)-470061	43 ग्रेड साधारण पोर्टलैंड सीमेंट IS : 08112--76	
82. सी एम/एल-2120929	90-06-01	पीथरलाइट बायर प्राइवेट्स लि., पाथिरापल्ली, एल्लपी (केरल)	केवल कयचन हेतु जस्ताकृत मृदु इस्पात के बार IS 03975--79	
83. सी एम/एल-2121022	90-06-01	सोम इल्कट्रो मैकेनिकल इंडस्ट्रीज सी-13 पनकी इंडस्ट्रियल एरिया, साइट-1, कानपुर	एसी टाइप एक फेजी संवाती पंपे, साइज 450 मिमी, 220/240 वो, 50 हर्ट्ज श्रेणी ए रोशन सहित IS 02312--67	
84. सी एम/एल-2121123	90-06-01	अग्रवाल स्टील रि-रोलर्स इंड, एस्टेट, उर्ला, रायपुर (म. प्र.)	संरचना इस्पात (मानक विस्म) IS : 00226--75	
85. सी एम/एल-2121224	90-06-01	गौरव एलाइन्स प्रा. लि. 17/6 सील का पथर, दिल्ली मथुरा रोड, करनाबाद	ब पे गै के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस बूल्हा IS : 04246--84	
86. सी एम/एल-2121325	90-06-01	जे. डी. कास्टिंग एंड फोर्जिंग (प्रा.) लि. बनारस रोड, कोणा, हावड़ा	मल, गंदे पानी और संवातन के लिए सी आई स्प्रिंकलर और आकेट पाइप साइज-1100 मिमि एनबी केवल IS 1729--79	
87. सी एम/एल-2121426	90-06-01	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. सॉरी टर्मिनल, सॉरी, बम्बई-400015	हवा में छिड़का जाने वाला कीटनाशी (पाइरेथ्रीन, मैलाथियान मिश्रित संगठन केवल) IS : 01824--78	
88. सी एम/एल-2121527	90-06-01	होर्ली निटर्स, 16 सी. ए. जी. काम्प्लेक्स बाइपेट, तिरुपुर-638001	तावी बुनी बनियान साइज 75-110 से भी फाइन टाइप-आर एन और आरएनएम् IS : 04964--80	
89. सी एम/एल-2121628	90-06-01	एशियन इंडस्ट्रीज, बी-25 सेक्टर-7, नौएडा, गाजियाबाद (उ. प्र.)	संरचना इस्पात की धातु आर्क ब्रिटिंग के लिए आवरित इलैक्ट्रोड IS : 00814-74	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
90 सी एम/एल-2121729	90-06-01	भारत पुलवराइजिंग मिल्स लि., प्लॉट नं. 6 कामा हंड. एस्टेट, गोरेगोव (पू.) बम्बई-400062	एंड्रोमोर्फोन 35% फार्मिलेशन रिबेकिंग केवल IS : 04323--67	
91. सी एम/एल-2121830	90-06-01	कृषि रसायन (बिहार), बेला हंड एस्टेट, एम आई सी, मुजफ्फरपुर--843116	मिथनालफॉस 25 % (मात्रानुसार) ईसी फाम्ट-जन IS : 08028--76	
92. सी एम/एल-2121931	90-06-01	अंजु हंडस्ट्रीज, डब्ल्यू जैड मावीपुर गांव दिल्ली	कोलतार खाद्य रंग निर्मितिया और मिश्रण IS : 05346--75	
93 सी एम/एल-2122024	90-06-01	श्री मरबती स्टील ट्यूब्स लि., मकर वेड इंडस्ट्रियल एस्टेट, माइलम रोड, पांडिचेरी	सामान्य हजीतिथरी प्रयोग के लिए इस्पात की पाइप IS : 03601--84	
94 सी एम/एल-2122125	90-06-01	स्वाभ एज इंडस्ट्रीज, 29, डोगसघाईडीसी स्कीम फेज-II घोखला हंड. एस्टेट, नई दिल्ली-110020	निरापद कोष्ण परतवार मोटर वाहन ड्राफ्ट के बिज ग्रीड के लिए कोष्ण को छोड़कर IS : 02553--71	
95 सी एम/एल-2122226	90-06-01	लेमी बैग मैन्यु प्रा. लि., 10 किमी मुखर्जी रोड, तालपुर, बेरकपुर जि. 24 परगना	380 ग्र./मी.--, 68--39 के हर्पुलिन धातु से बने परतवार पटसन के बोरे IS : 07406--86	
96 सी एम/एल-2122327	90-06-01	माइती पेट्रोल, सी-13, फोकल प्लांट, जालंधर	लकड़ी प्राइमर, छुड़ा दिया जाने वाला तैयार गुदा रोधन IS : 03536--66	
97. सी एम/एल-2122438	90-06-01	कमरहट्टी कं. लि., 907, बाहमरोड कमरहट्टी कलकत्ता-700058	पटसन कैनवस, 680 ग्र./मिमी.- जल सह या भ्रमह पटसन कैनवस को छोड़कर IS : 10036--82	
98 सी एम/एल-2122529	90-06-01	जैसको पम्प प्रा. लि., राजपुर गाम, मेहमाता हाइवे, रत्नसंड़ी तालकाड़ी के पास जि. मेहमाता	निमज्जय पम्पमैट IS : 08034--89	
99 सी एम/एल-2122630	90-06-01	गोल्डन मैन्यु. कं., ए-7/2, मिलमिल हंड. एरिया, शाहदरा, दिल्ली-110032	1100 बो तक कार्यकारी बोल्डता के लिए पीवीसी रोधन (हैवी ड्यूटी) बिजली की केवल IS : 01554--76	
100 सी एम/एल-2122731	90-06-01	वैरासाउन्ट केबल कारपोरेशन, 45/14, प्रहलादपुर, बबाना रोड, दिल्ली-110042	एल्यूमीनियम और तांबा बालक सहित कबचिन/ अकबचिन पीवीसी रोधन हैवी ड्यूटी बिजली की केवल IS : 01554--76	
101 सी एम/एल-2122832	90-06-01	इडिया जूट हंड इंडस्ट्रीज लि., 3, बिलियम कैरे रोड, श्रीरामपुर, हुगली-712301	पटसन हर्पुलिन कपडा 380 ग्र/मी- IS : 07407--80	
102 सी एम/एल-2122933	90-06-01	हिममत मेटल एंड स्टील वर्क्स (राजि), कपूरथला रोड, जालंधर शहर-144002	फेबल साइज 15 मिमी, 20 मिमी और 25 मिमी IS : 02692--78	
103 सी एम/एल-2123026	90-06-01	इडिया जूट एंड इंडस्ट्रीज लि., 3, बिलियम कैरे रोड, श्रीरामपुर-712201	पटसन हर्पुलिन कपडा 407 ग्र/मी-- 85--39 IS : 07407--844	

[सं. के. प्र. बि./13 : 11]

S.O. 443 In pursuance of sub-regulation (5) of regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given in the following schedule

## SCHEDULE

List of Licences Granted during month of May, 1990

CM/L-No.	Operative date	Name and Address of the Party	Article/Process	IS:No./Part
1. CM/L-2112829	90-25-01	Chamak Holdings Ltd., 8/7, M.T.H. Road, Ambattur, Madras 600098	HDS Bars and wires for Concrete Reinforcement sizes from 16 mm upto & including 25 mm grade FE-415	IS:01786-85 Pt Sc
2. CM/L-2112930	90-05-01	National Plywood Industries Ltd., Nakum Road, Tinsukia, (Assam) 7861125	Plywood for concrete shuttering work	IS:04990-81 Pt Sc
3. CM/L-2113023	90-05-16	Naveen Enterprises, 117, G.T. Road, Giani Border P.O. Chikamberpur Sahibabad (UP)	PVC insulated electric Cables, sheathed/unsheathed with aluminium conductor for working voltages upto & including 1100 volts.	IS:00694-77 Pt Sc
4. CM/L-2113124	90-05-16	Everest computer Carbons Pvt. Ltd., Kallakal Village, Gajwel Taluq, Distt. Medak (AP)	Carbon paper for typewriting grade-3	IS:01551-76 Pt Sc
5. CM/L-2113225	90-05-16	Atlas Industries, 71, Laghu Udyog Nagar G.T. Karnal, Road Delhi	Propeller type AC ventilating fans, 230 V single phase 50 HZ with class-E insulation and of size 300 mm and 450 MM only.	IS:02312-67 Pt Sc
6. CM/L-2113326	90-05-16	Abhishek Steels Ltd., Bundla Pocham, pally via Hakimpeth, Medchal Manal Ranga Reddy Distt. 500014.	Structural Steel (Standard quality)	IS : 00226-75 Pt Sc
7. CM/L-2113427	90-05-16	General Engg. Co., 1/4, Mettupalayam Road, Kavandampalayam, Coimbatore-6411030	Horizontal Centrifugal Pumps for clear, cold, fresh water for agricultural purposes.	IS:06595-80 Pt Sc
8. CM/L-2113528	90-05-16	Asoka Wire Products Chowk Preet Nagar, Tanda Road, Jalandhar	Galvanized steel barbed wire for fencing.	IS : 00278-78 Pt Sc
9. CM/L-2113629	90-05-16	Prakash Industries, 136/140-98 Industrial Area-I, Chandigarh	Door Closers (Hydraulically regulated), Univesal Type, Designation 2	IS:03564-75 Pt Sc
10. CM/L-2113730	90-05-16	Hanuman Tin Factory, 12B, Industrial Estate, Bais Godam, Jaipur	15 Kg square tins for packing vanaspati Edible oil and bakery shortenings	IS:10325-89 Pt Sc
11. CM/L-2113831	90-05-16	Abhishek Steel Ltd., Gundla Pochampally, Via Hakimpet, Medchal Mandal, Distt. Rangareddy 500014.	Structural Steel (Ordinary Quality)	IS:01977-75 Pt Sc
12. CM/L-2113932	90-05-16	Surya Steel Ltd., P.O. and Railway Station Sardar Nagar Gorakhpur	Cast billet ingots for rolling into structural steel (standard quality) Grade 1 and 2	IS:06914-78 Pt Sc
13. CM/L-2114025	90-05-16	Saraya Steel Ltd., P.O. & Rly Stn. Sardar Nagar, Gorakhpur	Cast billet ingots for rolling into structural steel (ordinary quality) Grade 1 and 2	IS:06915/-78 Pt Sc
14. CM/L-2114126	90-05-16	Lift All Engineers (P) Ltd., A-34 G.T. Karnal Road, Industrial Area Delhi-110033	1T, 2T, & 5T Capacity chain pulley Blocks	IS:03832-86 Pt Sc
15. CM/L-2114227	90-05-16	A K.G. Industries, B-64, Okhla Indl. Area, Phase I, New Delhi-110020	Rigid plan conduits of insulating materials size 25 mm, class medium	IS:09537-83 Pt03 Sc

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16. CM/L-2114328	90-05-16	B.E.C. Industries C-108 Mayapuri Indl. Area, New Delhi-110064	Rigid Non-metallic conduit TS for electrical installation size 20 and 25 MM.	IS:02509-73 Pt Sc
17. CM/L-2114429	90-05-16	A.K. Enterprises 507/50 Jessore Road, Calcutta-700074	Refill for soda-acid portable fire Extinguisher	IS:05490-77 Pt 01 Sc
18. CM/L-2114530	90-05-16	Hatim Carbon Co. Pvt. Ltd. 90 Ripon Street, Calcutta-700016	Carbon brushes for electrical machines for electro graphite grade	IS:03003-78 Pt03 Sc
19. CM/L-2114631	90-05-16	Himson metal & Steel Works (Rdgd.) Kapurthla Road Jalandhar (Punjab) 144022	Cast Brass BIB Taps size 15 & 20 MM	IS:00781-84 Pt Sc
20. CM/L-2114732	90-05-16	Chanana steel Tubs Pvt. Ltd. Plot No. 10 Sector III Parwanoo (HP)	Steel Tubs for Structural Purposes, Black, Plain ends of grade Yst 210, class Medium	IS:01161-79 Pt Sc
21. CM/L-2114833	90-05-16	Laxmi Industries 11-D, Private Ind. Estate, Kuruchi Coimatore-641021	Single Phase Motors	IS:00996-79 Pt Sc
22. CM/L-2114934	90-05-16	Jindal Pips Ltd. 22nd Mile, Delhi Hapur Road, P. O. Jindal Nagar Ghaziabad (UP)	Steel Tubes for water Wells, ERW of sizes upto and including 300 MM MB, Plain and belled ends, Grade 410	IS:04270-83 Pt Sc
23. CM/L-2115027	90-05-16	Chefark Co. Pvt. Ltd. B-195, Phase II Noida (UP) 201305	Stamp Pad Ink, Grade B	IS:00393-85 Pt Sc
24. CM/L-2115128	90-05-16	Ludlow Jute Mills (Prop Aket A Ltd.) P.O. Chengali, Distt. Howrah (WB) 711308	Light weight Jute Bags for packing Cement.	IS:12154-87 Pt Sc.
25. CM/L-2115229	90-05-16	Hooghly Mills Projects Ltd. (Unit-Hukumchand Jute Mill) P.O. Hazinagar Distt. 24 Parganas North (WB)	Light weight Jute Bages for packing Cement.	IS:12154-87 Pt Sc
26. CM/L-2115330	90-05-16	Lamybag Manufacturer (P) Ltd. 10 K.N. Mukherjee Road Talpukur 24 Parganas	Laminated Jute Bags Manufactured from 4076/M SQ, 85x39 Tarpaulin Fabric	IS:07406-84 Pt 01 Sc
27. CM/L-2115431	90-05-16	Garg Fastners 34, G.N.T. Road Madhavaram Madras 600113	Snap-Head Rivets, Sizes 6 to 16 MM Dia	IS:02155-82 Pt Sc
28. CM/L-2115532	90-05-61	Nehal Cable Industries C-3/9 GIDC Mill Road Nadiad Distt. Kaira (Gujarat)	PVC Insulate unsheathed cables for working voltages upto and including 1100 V with copper or Aluminium, Conductors	IS:00694-77 Pt Sc
29. CM/L-2115633	90-05-16	Viral Electronics Pvt. Ltd. D-7, MIDC Ambad Nasik 422010	PVC Insulated Unsheathed General purpose automobile cable with Conductors	IS:20465-84 Pt Sc
30. CM/L-2115734	90-05-16	Anil Engineering Works G.T. Road. Delhi by Pass Karnal (Haryana)	Three-Phase squirrel cage induction motors for cetrifugal pumps for agricultural applications 3.7 KW with Class A Insulation	IS:07538-75 Pt Sc
31. CM/L-2115835	90-05-16	Cosmic Industries 119 Sonal Heavy Indl. Estate Ram Chandra Lane (Ext) Mulad (West) Bombay 400064	250V 5 & 15 AC Flush Mounting switches or domestic and similar Purposes excluding switches for AC Inductive Circuits	IS:03854-66 Pt Sc
32. CM/L-2115936	90-05-16	Garden Flavouring Inds Shanti Indl. Estate Unit No A-249 Second floor Sarojini Naidu Road Mullund (W) Bombay 4000080	Coal Tar Food Colour Preparations, Solid Type only	IS:05346-75 Pt Sc

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33. CM/L-2116029	90-05-16	Alita Cable Industries S-88 Street No. 23 Braham Puri Delhi-111005	Welding Cables with General purpose Rubber Compound with polyester Tape separator and Copper conduc- tor.	IS:09857-81 Pt Sc
34. CM/L-2116130	90-05-16	Mahalaxmi Cable Inds No. 3 Indl Area Tilak Nagar. New Delhi 110018	PVC Insulated (Heavy Duty ) Cables for working volt ages upto and including 1100 V armoured/unarmoured Cables.	IS:01554-76 Pt 01 Sc
35. CM/L-2116231	90-05-16	Polycab Premiers Pvt. Ltd. Adityn Pur Ind Area Plot No. C-15 Second Phase Jamshedpur 832109	PVC Insulated Sheathed/Unshathed clabes for working voltages upto and including 1100 V. and with Aluminum conductors.	IS:00694-77 Pt Sc
36. CM/L-2116332	90-05-16	Mahalaxmi Cable Industries No. , Indl. Area Tilak Nagar. New Delhi 110018	PVC insulted cables for working voltages upto and including 1100 V sheathed and unsheathed with aluminium & Copper Conductor.	IS:00694-77 Pt Sc
37. CM/L-2116433	90-05-16	Vijay Cables 44-A Dilshad Garden Shahdara Delhi-110095	PVC insulated cables for working voltages upto & including 1100 V Unshathed and sheathed with Aluminium & Copper Conductor.	IS:00694-77 Pt Sc
38. CM/L-2116534	90-05-16	Vimla Industries B-14 Gali No. 7 Anand Parbat New Rohtak Road. New Delhi 1100025	Ungalvanized 20 Litre Capacity Steel Drums of Grade B1 & B2	IS:02552-79 Pt Sc
39. CM/L-2116635	90-05-16	Shree Ganganagar Zila Dugdh Utpadak Sehkari Sangh Ltd Indl Area Hanuman Garh Junction Shree Ganganagar Distt.	Skim Milk Powder, Spray Dried.	IS:01165-86 Pt Sc
40. CM/L-2116736	90-05-16	Dujodwala Cement Ltd Indl Area Khandla Distt. Sikar (Rajasthan)	Ordinary Portland Cement	IS:00269-76 Pt Sc
41. CM/L-2116837	90-05-16	Krishna Conductors F-96 Road No. 7 V.K.I. Area Jaipur 302013	Aluminium Stranded Conductors for overhead transmission purposes.	IS:00398-76 Pt 01 Sc
42. CM/L-2116938	90-05-16	Madhushree Traders Petrol Pump Bharat Petroleum Corpn Residency Road, Jodhpur.	Glass Fibre Refinforced Plastic (GRP) Flushing Cistern, Low-level, 10 Litre Capacity	IS:07231-84 Pt Sc
43. CM/L-2117031	90-05-16	Gupta Chemicals Pvt. Ltd. B-144, Road, No. 9 Vishwakarma Indl. Area Jaipur 302013	Carbaryl, 50 per cent (M/M) WDP Formulation	IS:07121-73 Pt Sc
44. CM/L-2117132	90-05-16	Gupta Chemicals Pvt. Ltd. B-144, Road No. 9 V.K.I. Area Jaipur 302013	Carbaryl 5 Percent (M/M) and 10 Percent (M/M) DP Formulation	IS:07122-84 Pt Sc
45. CM/L-2117233	90-05-16	Bhupinder Hinges (P) Ltd. 114 Indl. Area Phase 1 Chandigarh	Steel Butt Hinges (Medium Weight) sizes 75 MM, 100 mm, 125 MM	IS:01341-81 Pt Sc
46. CM/L-2117334	90-05-16	Citizen Paints 3-B, Shiv Nagar Batala Nagar, Amritsar (Punjab)	Distemper, Oil Emulsion, Medium Colour Range Only	IS:00428-69 Pt Sc
47. CM/L-2117435	90-05-16	GECO Engineers Near Preet Palce Ludhiana (Punjab) 141003	Hand Operated Compression Knapsack Sprayer, Non-Pressure retaining type	IS:01970-82 Pt 01 Sc
48. CM/L-2117536	90-05-16	Trilo Agro Industries Pvt. Ltd. Village Jhormari Distt. Patiala (Punjab)	BHC, Gamma-Isomer 6.5% (M/M) WDP Formulation	IS:00562-78 Pt Sc



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
49.	CM/L-2117637	90-05-16	Punjab Pesticides Indl. Co-Op. Society Ltd, Chandigarh-Ropar Road Khanpur, Tehsil-Kharar Distt. Ropar (PB)	BHC, 10% (Gamma Isomer 1.3% M/M) DP Formulation	IS:00561-78 Pt Sc
50.	CM/L-2117738	90-05-16	Isha Chemical Micronutrients Pvt. Ltd. Lane II Phase II SIDCO Indl. complex Bari Brahamana, Jammu.	Zinc Sulphate, Agricultural Grade	IS:08249-76 Pt Sc
51.	CM/L-2117839	90-05-16	Pushpa GLS Lamps Works No. 1456 Sathi Road Ganpathy Post Coimbatore-641006	Tungsten Filament General Service Electric Lamps 250 V Single Coil/Coiled upto and including 100 W with B22D CAP	IS:00418-78 Pt Sc
52.	CM/L-2117940	90-05-16	P.K. Vaduvammal (Works) R.S.No. 374 Madras-Bangalore Trunk Road, Varadharajapuram Madras-602103	HSD Bars of Sizes from 8 MM to 22 MM of Grade Fe 415	IS:01786-85 Pt Sc
53.	CM/L-2118033	90-05-16	Usha Martin Industries Ltd. Tatisilwai Ranchi-835103	Locked Coil Winding Ropes upto 25 MM	IS:03626-78 Pt Sc
54.	CM/L-2118134	90-05-16	Suraj Vanaspati Ltd, A-26 UPSIDC Indl. Area Sikanderabad Distt. Bulandshahr (UP)	Vanaspati	IS:10633-86 Pt Sc
55.	CM/L-2118235	90-06-01	Fieldman Engineering Pvt. Ltd. AJI Indl. Area GIDC Phase-II 100 Feet Main Road Rajkot-360003	Centrifugal Pumps	IS:06595-80 Pt Sc
56.	CM/L-2118336	90-06-01	Sewtec Engineers Pvt. Ltd. C-120, Sector 2 Noida-201301 (UP)	Light duty Sewing Machine heads for Industrial Use	IS:12109-87 Pt Sc
57.	CM/L-2118437	90-06-01	Govind Cable Industries 207-A, Patpar Ganj Delhi-110092	Elastomer Insulated Flexible Cables for working voltage upto & including 1100 V	IS:09968-81 Pt 01 Sc
58.	CM/L-2118538	90-06-01	Shashi Rubber Foam Industries WZ-550 Naraina Village New Delhi-110028	Latex Foam Rubber Products Type Cored, Grade F only	IS:01741-60 Pt Sc
59.	CM/L-2118639	90-06-01	Asahi Lamps Pvt. Ltd. 554 Poonamalle High Road Arumbakkam Madras-600106	General Service Tungsten Filament Electric Lamps	IS:00418-78 Pt Sc
60.	CM/L-2118740	90-06-01	R.B. Jodha Mal & Co. Pvt. Ltd. Tope Sherkhanian, Jammu	Continuously Cast Billets for Rolling into Structural Steel (Standard Quality)	IS:06914-78 Pt Sc
61.	CM/L-2118841	90-06-01	S.T.P. Ltd. 26, Lake Road Bhandup Bombay-400078	Bitumen Emulsion for Roads, Cationic Type, Type Rapid Setting (RS)	IS:08887-78 Pt Sc
62.	CM/L-2118942	90-06-01	Mehatpur Packages Pvt.Ltd. 128 Indl. Area Mehatpur Distt. Una (HP)	Laminated Jute Bags for Packing Fertilizers	IS:07406-84 Pt 01 Sc
63.	CM/L-2119035	90-06-01	All India Medical Corpn. A.I.M.C. Simpoli Road Borivli (W) Bombay-400092	Fenvelerate 20% (M/M) EC Formulation	IS:11997-87 Pt Sc

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
64. CM/L-2119136	90-06-01	Vardhman Power Pvt. Ltd. G-849 Road No. 14 VKI Area Jaipur-302013	Aluminium stranded Conductors for Overhead transmission purposes	IS:00398-76 Pt 01 Sc	
65. CM/L-2119237	90-06-01	Vardhman Power Pvt. Ltd. G-849, Road No. 14 V.K.I. Area Jaipur-302013	Aluminium Conductors Galvanized steel reinforced for overhead transmission purposes	IS:00398-76 Pt 02 Sc	
66. CM/L-2119338	90-06-01	National Agro Chemicals C-2, Industrial Area Patna-800013	Phosphamidon, 85% (M/M) WSC Formulation	IS:06177-81 Pt Sc	
67. CML/-2119439	90-06-01	Ambica Processing Industries, 38/39, Jai Bibi Road Ghusury Howrah	Single Texture Rubberized, Water-Proof Fabric	IS : 05915-70 Pt. Sc	
68. CM/L-2119540	90-06-01	Gaanesh Agro Industries, Village Vadpura, Kalol-Mehasana Highway No. 8 Taluka Kadi Distt. Mehsana-382705	Safety Requirements of Power Threshers, Spike Toothed Cylinder Type of Rating 11KW (15 HP) RPM Range-500720	IS : 09020-79 Pt. Sc	
69. CM/L-2119641	90-06-01	Peter Engineering Co. (Regd.) A-133, Wazirpur Indl. Area Delhi-110052	Sewing Machine for Household pur- poses, Hand and Foot operated only	IS : 01610-81 Pt. Sc	
70. CM/L-2119742	90-06-01	Garg Fastners, 34, G.N.T. Road Madhavaram Madras-600110	Snap Head Rivets from 12 to 24 MM. diameter	IS : 01929-82 Pt. Sc	
71. CM/L-2119843	90-06-01	Tulsi Foundries & Forgings (Unit 1), Indl. Estate, Kolappully, P.B. No. 20 Shoranur Shoranur 679122-(Kerala)	Fanged Powrah, 1.6 Kg. without handle	IS : 01759-86 Pt. Sc	
72. CM/L-2119944	90-06-01	Allwyn Electrical Industries, 78 Kakad Indl. Estate, Lady Jamshedji Road, Mahim, Bombay-400016	5A, 250 V, AC only Flush Type one way Switches for domestic & similar purposes	IS : 03854-66 Pt. Sc	
73. CM/L-2120020	90-06-01	Raj Pipes Ltd., E-8 MIDC Indl. Area, Hingna Road, Nagpur-440016	Rigid Plain Conduits of Insulating Materials Size 20 MM. Type Medium only	IS : 09537-83 Pt. 03 Sc	
74. CM/L2120121	90-06-01	Sapphire India Pvt. Ltd. B-491, Ind. Area, Bhiwadi, Distt. Alwar	Reconditioning & Testing of old 33.3 Litres Water capacity LPG Cylinder	IS : 03196-82 Pt. Sc	
75. CM/L-2120222	90-06-01	Gandhar Wire & Cables Pvt. Ltd., F-57, Riico Indl. Area, Ajmer Road, Beawar 305901.-(Rajasthan)	Aluminium Stranded Conductors for Overhead transmission purposes	IS : 00398-76 Pt. 01 Sc	
76. CM/L-21200323	90-06-01	Lakhotia Conductors Pvt. Ltd., 111 Indl. Area, Jhotwara, Jaipur-302012	Aluminium Stranded Conductors, Galvanized Steel Reinforced for Overhead Transmission purposes	IS : 00398-76 Pt. 02 Sc	
77. CM/L-2120424	90-06-01	Associated & Polymer Industries, 12/1, Devi Mandir Lane, P.O. Liluah Howrah	HDPE Pipes Class 3 upto and including 110 MM Class 4 upto and including 110MM and Class 5 upto and including 110 MM.	IS : 04984-987 Pt. Sc	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
78	CM/L-2120525	90-60-01	Bajrangball Iron & Steel Co. Ltd., 100 A. Basin Road, Tiruvottiyur, Madras-600019	HSD Bars of Sizes 10 mm. upto and including 32 mm, Grade Fe 415 for concrete reinforcement.	IS : 01786--85 Pt. Sc.
79.	CM/L-2120626	90-06-01	Gujarat Waxes, A-2/III, GIDC, Phase-II Vatva, Distt. Ahmedabad-382445	Paraffin Wax, Type 3	IS : 04654- 74 Pt. Sc.
80.	CM/L-2120727	90-06-01	Powercone Industries, Plot No. 45, Phase-II Badli Indl. Estate, Delhi-110042.	Domestic Stoves for use with LPG.	IS : 04246--84 Pt. Sc.
81.	CM/L-2120828	90-06-01	Diamond Cement, P.O. Narsigarh, Distt. Damoh (MP) 470661.	43 Grade Ordinary Portland Cement.	IS:08112- 76 Pt. Sc.
82.	CM/L-2120929	90-06-01	Pearlite Wire Product Ltd., Pathirapally.  Alleppey (Kerala).	Mild Steel Wires, Galvanized, for Armouring of Cables 1.40 mm.	IS : 03975--79 Pt. Sc.
83.	CM/L-2121022	90-06-01	Som Electro Mechanical Industries Ltd., C-13 Panki Indl., Area Site-I Kanpur.	AC Propeller Type single Phase ventij- lating Fans, Size 450 MM., 220/240V, 50HZ with Class A insulation.	IS : 02312 -67 Pt. Sc.
84.	CM/L-2121123	90-06-01	Agrawal Steel Re-Rollers, Indl. Estate., Urla Raipur (M.P.).	Structural Steel (Standard Quality).	IS : 00226--75 Pt. Sc.
85.	CM/L-2121224	90-06-01	Gorav Appliances Pvt. Ltd., 17/6, Milestone, Delhi Mathura Road, Faridabad.	Domestic Gas Stoves for Use with LPG Double Burner.	IS : 04246--84 Pt. Sc.
86.	CM/L-2121325	90-06-01	J.D. Casting & Forgings (P) Ltd., Banaras Road, Kona, Howrah.	CI Spigot and Socket Soil Waste and Ventilating Pipes of Sizes 100 mm. NB only.	IS : 01729- 79 Pt. Sc.
87.	CM/L-2121426	90-06-01	Hindustan Petroleum Corpn. Ltd., Sewree Terminal I, Sewree, Bombay-400015	Insecticide Space Spray (Pyrethrin, Malathion Mixed Composition only).	IS : 01824--78 Pt. Sc.
88.	CM/L-2121527	90-06-01	Holi Knitters, 16 C.A.G. Complex, Khaderpet, Tirupur-638601.	Plain Knitted Cotton Vests Size 75-110 Cm Fine Type RN & RNS.	IS : 04964- -80 Pt. Sc.
89.	CM/L-2121628	90-06-01	Asian Industries, B-25 Sector-VII, Noida, Ghaziabad (U.P.).	Covered Electrodes for Metal Arc Welding of Structural Steel.	IS : 00814- 74 Pt. Sc.
90.	CM/L-2121729	90-06-01	Bharat Pulverising Mills Ltd., Plot No. 6, Cama Indl. Estate Goregaon (E), Bombay-400062	Endosulfan 35% EC Formulation Repacking only.	IS : 04323- 67 Pt. Sc.
91	CM/L-2121830	90-06-01	Krishi Rasayan (Bihar), Bela, Indl Estate, MIC. Muzaffarpur-843116	Quinalphos, 25% (M/M) EC Formula- tion	IS : 08028--76 Pt. Sc.
92.	CM/L-2121931	90-06-01	Ankur Industries, WE-317 Madipur Village, Delhi.	Coal Tar Food Colour preparations and Mixtures.	IS : 05346--75 Pt. Sc.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
93.	CM/L-2122024	90-06-01	Sri Sarbati Steel Tubes Ltd., Sedarpet Ind. Estate, Mailam Road, Pondicherry.	Steel Tubes for General Engineering Purposes.	IS : 03601—84 Pt. Sc.
94.	CM/L-2122125	90-06-01	Glass Age Industries, 29 DSIDC Scheme 1, Phase-II, Okhla Ind. Estate, New Delhi-110020	Safety Glass, Laminated Excluding Glass for Wind Shields for Auto- mobile Application.	IS : 02553--71 Pt. Sc.
95.	CM/L-2122226	90-06-01	Lamy Bag Manufacturers Pvt. Ltd., 10 Km. Mukherji Road, Talpukur Barrackpore Distt. 24 Parganas.	Laminated Jute Bags Manufactured from 380 G/MSQ, 68X39 Tarpauline Fabric.	IS : 07406—86 Pt. 02 Sc.
96.	CM/L-2122327	90-06-01	Sawahney Paints, C-13, Focal Point. Jalandhar City.	Ready Mixed Paints Brushi NG Wood Primer-Pink.	IS : 03536—66 Pt. Sc.
97.	CM/L-2122428	90-06-01	Kamarhatti Co. Ltd., 907 Graham Road, Kamarhatti, Calcutta-700058	Jute Canvas 660 G/MM SWQ Exclud- ing Water, Proof or not Proofed Jute Canvas.	IS : 10036—82 Pt. 02 Sc.
98.	CM/L-2122529	90-06-01	Jasco Pump Pvt. Ltd., Rajpur Gam, Mehsana Highway, Near Ratna Mandi Talkadi, Distt. Mehsana.	Submersible Pumpsets.	IS : 08034—89 Pt. Sc.
99.	CM/L-2122630	90-01-01	Golden Manufacturing Co., A-7/2, Jhilmil Ind. Area., Shahdara, Delhi-110032	PVC Insulated (Heavy Duty Electric Cables for working Voltages upto and Including 1100 V.	IS : 01554—76 Pt 01 Sc.
100.	CM/L-2122731	90-06-01	Paramount Cable Corpn. , 45/14, Prahlad Pur, Bawana Road, Delhi-110042.	PVC Insulated Heavy duty Electric Cables: Armoured and Unarmoured with Aluminium Copper Conductors.	IS : 01554—76 Pt 01. Sc.
101.	CM/L-2122832	90-06-01	India Jute & Industries Ltd., 3, William Carey Road, Serampore., Hooghly-712201	Jute Tarpaulin Fabric 380 G/M SQ.	IS : 07407—80 Pt 03 Sc.
102.	CM/L-2122933	90-06-01	Himson Metal & Steel Works (Regd.) Kapurthala Road, Jalandhar City-144002	Ferrules of Sizes 15 MM, 20 MM & 25 MM.	IS : 02692—78 Pt. Sc.
103.	CM/L-2123026	90-06-01	The India Jute & Industries Ltd., 3, William Carey Road, Serampore, Hooghly (WB).	Jute Tarpaulin Fabric, 407 G/M SQ, 85X39.	IS : 07407—80 Pt 02 Sc.

का. प्रा. 444.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 4 के उपविनियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण अनुसूची में नीचे दिए गए बेंचबिहृत कर दिए गए हैं।

## अनुसूची

क्र.सं.	लाइसेंस संख्या	लागू होने की अवधि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तु/प्रक्रम और संबद्ध भारतीय मानक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सीएम/एल-2123127	90-06-16	वि एलिंगम मिक्स कं. लि., कपूर गंज, कानपुर सूती कोशिकीय कमीज का कपड़ा	IS : 01144-80	
2.	सीएम/एल-2123228	90-06-16	गेंजेंस वाटर प्रूफ वर्क्स (प्रा.) लि. 166 वरीर रोड, चौहाटी, राजपुर, पीएस सोनापुर, डा. जगवल, 24 परगना (ब) (प.ब.)	380 ग्रा./मी. <sup>2</sup> 68 × 39 टारपुलिम कपड़े के परतदार बोरे	IS : 07406-66
3.	सीएम/एल-2123329	90-06-16	गेंजेंस वाटर प्रूफ वर्क्स (प्रा.) लि. 166 वरीर रोड, चौहाटी, राजपुर, पीएस, सोनापुर, डा. जगवल, 24 परगना (ब) (प.ब.)	407 ग्रा./मी. <sup>2</sup> टारपुलिम कपड़े से उत्पाद परतदार बोरे	IS : 07406-84
4.	सीएम/एल-2123430	90-06-16	जयश्री फाइबर प्राइवेट लि., प्रा.—आलमपुर डा. अर्जुन सौरी जि.—हावड़ा	तीनलक्ष हाइडरलेड पॉलीप्रोलीन के रस्से 24 मि.मी. तक व्यास	IS : 05175-82
5.	सीएम/एल-2123531	90-06-16	सीलेंट एंड गैसकेट, प्लॉट नं. 24 कनेहू प्रा., डा. बाया बड़ा गांव मेवाल ताल्लुक जि.—पुण-412106	ग्लैड पैकिंग एम्बेस्टर ग्रेड 1, 32 मिमी. तक व्यास	IS : 04687-80
6.	सीएम/एल-2123632	90-06-16	पीकी इलक्ट्रानिक्स एंड इलक्ट्रिकल्स, 3 एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया बाणें-बेलापुर रोड, पो. बा. 78 ठाणे-400601	नासिकाकार बलीरेसेट लेम्प 40 वा.	IS : 02418-77
7.	सीएम/एल-2123733	90-06-16	सिलवेक्स केबल्स कं. प्रा. लि. साकी विहार रोड, बम्बई-400072	1100 बो कि कार्यकारी तांबा और एल्यु-मिनियम जालकों वाली पीवीसी रोधित केबल	IS : 01554-76
8.	सीएम/एल-2123834	90-06-16	हरियाणा मीटर्स (इंडिया) ए-2 सैक्टर-एक्स नौएडा, जि. गाजियाबाद	एसी बिजली के मीटर, तीन फेजी संपूर्ण धारा, श्रेणी 20 रेटित मानक आधारभूत धारा 10, 20 और 30 एम्प	IS : 00722-77
9.	सीएम/एल-2123935	90-06-16	सिलवेक्स केबल्स कं. (प्रा.) लि. साकी विहार रोड बम्बई-400072	तम्य केबल सहित, एक/बहु कोड़ वाली पीवीसी केबल, अम्ल ताप पर उपयोग की केबल को छोड़कर	IS : 00694-77
10.	सीएम/एल-2124028	90-06-16	कुमार इंजी. कं. सुखरामनगर के पीछे आजाद डेयरी रोड के पास रजियाल ग्रहमबाबाद	फुट बाल्व साइज 50, 650, 80 और 100 मिमी पेंच कसे सिरे केबल	IS : 10805-86
11.	सीएम/एल-2124129	90-06-16	सूर्य पावर लि., ए-161 एंड 462, मल्स्य इंड. एरिया, अल्वर-301030	1100 बो तक कार्यकारी एल्युमिनियम जालकों वाली कवचित/अकवचित जाल-कायल संक्षपातीय रोधित पीवीसी के कोल वाली	IS : 07098-77
12.	सीएम/एल-2124230	90-06-16	गुंज पेट्रोकम (प्रा.) लि., प्लॉट नं. 17/20 एमआईडीसी तलीजा, रायगढ़ (महाराष्ट्र)	नया विद्युत रोधन तेल	IS : 00335-83

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. सीएम/एल-2124331	90-06-16	जीको इलेक्ट्रिकल कारपो. 191 दावा कालोनी, पो. बा. नं. 487, इंड. एरिया, जालंधर	अनिलकुपरिपथ वियोजक, 6 ए, 240/415 घो, एम 9 झुटी संवर्ग	IS : 08828-78	
14. सीएम/एल-2124432	90-06-16	कोबर केबल्स (प्रा.) लि, कठोडिया इंड. सेंटर, 25/3 गली नं. 17, विश्वास नगर, शाहपुरा, दिल्ली-110032	1100 बो तक कार्यकारी बोल्टता के लिए एल्युमिनियम और तांबा आलकोषानी पीवीसी रोहित केबल्स	IS : 00694-76	
15. सीएम/एल-2124533	90-06-16	मिरलस एंड इलस्ट्रो कैमीकल्स एमग्राई- डीसी एरिया, मिराज जि.-सांगली (महाराष्ट्र) पिन-416410	बहुप्रयोगी शुष्क बैटरियां (भार 20 साइज केवल 1.5 बो)	IS : 08144-76	
16. सीएम/एल-2124634	90-06-16	लाइफ बैटरीज (प्रा.) लि, कैंटोनमेंट रोड कटक रोड, उड़ीसा-753001	मोटर वाहनो हेतु सीसा अम्ल संचायक बैटरियां, 6 बो, 135 ए.एच	IS : 07372-74	
17. सीएम/एल-2124735	90-06-16	रामा घेयर इंडस्ट्रीज, ए-89 घोखला इंड. एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110020	टावर काबल (अलौह) टाइप 4 केवल	IS : 00204-78	
18. सीएम/एल-2124836	90-06-16	नामपाल इलेक्ट्रिक एंड रेडियो कं. सी-108, नारायण इंड एरिया, फेज-II नई दिल्ली-110028	(i) 750 वाट की एल्युमीनियम सरल प्लेट और ठलवां जोड़े की तल प्लेट वाली टाप स्थायी बिजली की इस्तरियां (ii) 600वां गैर तापस्थायी	IS : 00386-85	
19. सीएम/एल-2124937	90-06-16	किलोस्कर आयल इंजन लि. नश्मण राव किलोस्कर रोड, खडकी, पुणे -411003	क्षुधि प्रयोजनो के लिए बीजल इंजन मोनोसेट पम्प	11501-86	
20. सीएम/एल-2115030	90-06-16	देवी दयाल एंड महिम्ना केबल्स (प्रा) लि., खसरा नं. 61, प्रा. एण्ड हा. मटियाल, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली- 110059	1100 बो तक कार्यकारी बोल्टता के लिए एल्युमिनियम और तांबा आलकों धानी पीवीसी रोहित केबल	IS : 00694-77	
21. सीएम/एल-2125131	90-06-16	शानकतो इंडस्ट्रीज, बी-50 नंबरबुवन इंड. इन्स्टेट, महाकली केम्प रोड, अंधेरी बम्बई-400093	एक फेजी मोटर 180, वा 220, 230 घो, 50 हर्टज 28 एरूप संघारित, प्रेरण रत 1440 व.प्र.मि., श्रेणी ई रोघन	IS : 00996-79	
22. सीएम/एल-2125232	90-06-16	सूर्या ज्योति डिवाइसेज लि., मा. आन- लोन डा. कुराली, जिला रोपड़	य पीवीसी पाइप 110 मिमी तक व्यास श्रेणी I और III	IS : 04985-81	
23. सीएम/एल-2125333	90-06-16	प्रोटोक्लर इंडी. प्रा. लि., 426 नासिक पुणे हाइवे आकन, जिला पुणे- 410501	निमज्जय मोटर 3.7 किवा घोषित धारा 8.5 एम्प बैट टाइप	IS : 0928-79	
24. सीएम/एल-2125434	90-06-16	श्री वेंकटेश्वर टिन कंटेनर्स शेड नं. 18, इंड. ख. एरिया, कट्टर शादनगर तालुक, महबूब नगर जिला	बेकरी मोयन धी वनस्पति तेल की पैकिंग के लिए 15 कि.ग्रा. के चौकोर कनस्तर	IS : 10325-89	
25. सीएम/एल-2125535	90-06-16	कावेरी एन्टरप्राइजेज, 75 इंड.; एरिया जोतबाड़ा, जयपुर-302012	बेकरी मोयन धी वनस्पति तेल की पैकिंग के लिए 15 कि.ग्रा. के चौकोर कनस्तर	IS : 103225-89	
26. सीएम/एल-2125636	90-06-16	अंबिका एन्टरप्राइजेज, 16/1 गांव कोटला, दिल्ली-110091	द्र १ गै के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस चूल्हा, दो बर्नरों वाला	IS : 04246-84	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. सीएम/एल-2125737	90-06-16	एवरेस्ट कंप्यूटर कार्बन प्रा. लि., पा-फल्साकल, कजवल तालुक जिला मेडक	टाइपराइटर के सूती रिबन, टाइप 1, मध्यम स्पाही लगे	IS : 04174-77	
28. सीएम/एल-2125838	90-06-16	नवशक्ति कैमीकल्स, एफ-3 बी रोड नं. 9, भाई डी ड नाचाराम हैदराबाद (पूर्व) तालुक रंगारेड्डी 501507	मुहर पैड के लिए स्पाही ग्रेड ए केवल	IS : 00393-85	
29. सीएम/एल-2125939	90-06-16	जे बी एफ इंडस्ट्रीज लि., प्लाट नं. 84/2 और 3, पीआईपीडीआई सी इंड. एस्टेट के सामने, किफुम्बकम गांव बाहुलर कम्यून, पांछेचेरी	ट्राइकलोगे इयाइली टाइप I और II	IS : 00245-70	
30. सीएम/एल-2126032	90-06-16	मैनुथल फील्ड कारपोरेशन बिल्डिंग न. 108 बाई नं. 8 बैस्पुनवल किडिन- गूर पंचायत पलाई (केरल) 886584	कुक्कुट आहार टाइप बीएसएफ और बीएफएफ केवल	IS : 01374-79	
31. सीएम/एल-2126133	90-06-16	दुआ एसोसिएट्स 3237/1 स्ट्रीट नं. 3 न्यू जनता नगर, अरोड़ा पैलेस के सामने लुधियाना	बिजली की इस्तरियां, 750 वा, 250 वा, सी आई तल प्लेट	IS : 00366-85	
32. सीएम/एल-2126234	90-06-16	भार. के. डिवाइस प्रा.लि., राजपुरा रोड बहादुरगढ़, पटियाला (पंजाब)	इस्पात के कच्चे	IS : 01341-81	
33. सीएम/एल-2126735	90-06-16	हिमाचल मिल्क प्राइवेट्स (प्रा.) लि., रामपुर रोड, ग्रा. कुंजा, पूनाटासाहिब (हि. प्रा.)-73025	मक्खनिया दूध	IS : 1165-86	
34. सीएम/एल-2126436	90-06-16	रेडियो एंड इलेक्ट्रिकल लि., 98 सिन रोड सिस्वोटिदुबूर, मद्रास-6000019	घाउटडोर टाइप वितरण ट्रांसफार्मर, तीन फेजी 100 किवाएम से 11 किवा/433 को तक ओएनएन शीतलन, विक्टर ग्रुप आई	IS : 01180-81	
35. सीएम/एल-2126537	90-06-16	पंजाब आयरन एंड स्टील कं. (प्रा.) लि., जी टी रोड, जालंधर कैंट	क्रॉकट प्रबलन के लिए उच्च सामर्थ्य इस्पात की सरिंग और तार सांकेतिक माइज 25 मिमी	IS : 1786-85	
36. सीएम/एल-2126638	90-06-16	न्यू काश्मीर स्टील रोलिंग मिल, 2 राइंड एरिया गंगवाल, जम्मू मधी	संरचना इस्पात (मानक किस्म) समान कोण माइज 30×20 मिमी से 65× 65 मिमी तक	IS : 00226-75	
37. सीएम/एल-2216739	90-06-16	दुआ इलेक्ट्रिकल्स 3237/1 स्ट्रीट नं. 3, न्यू जनता, अरोड़ा पैलेस के सामने, मिल रोड, लुधियाना	ताप स्थायी वाली बिजली की इस्तरियां ढलवां लीहे की तल प्लेट	IS : 00366-85	
38. सीएम/एल-6840	90-06-16	रघुपति एनर्जिज, 16/5 मयूरा रोड, फरीदा गढ़	इने गै के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस बूल्हा	IS : 4246-84	
39. सीएम/एल-2126941	90-06-16	क्या अद्योग, बी-1 फोकल प्वाइंट बस्ता (पंजाब) 141401	मिश्रित पशु आहार टाइप 2 केवल	IS : 02052-79	
40. सीएम/एल-2127034	90-06-16	मार्शन इंडी इंडस्ट्रीज (रजि.) बी-10 इंड. फोकल प्वाइंट, नवां शहर जिला जालंधर	ढलवां लीहे की फलश की टंकियां	IS : 00774-84	
41. सीएम/एल-2127135	90-06-16	भारत वास्त्वस, 1-18 डी एल एफ इंड. एरिया फेज-I फरीदाबाद-121005	संपीकृत गैस मिलिडर के लिए वाल्व	IS : 3224-79	
42. सीएम/एल-2127230	90-06-16	राम चेंबर इंडस्ट्रीज, ए-89 मोखला इंड. एरिया, फेज-III नई दिल्ली-110020	खिसकने वाले बरबाजे के लिए काबले (एलड्राप) टाइप 3	IS : 02681-79	

1	2	3	4	5	6
43.	सीएम/एल-7337	90-06-16	धू हंडिया बायर पंड केवल इंडस्ट्रीज, 41 और 42 गंगवाल, इंड. एरिया फेज III, जम्मू	एसीएसएमर बालक मात सड़	IS : 00398-76
44.	सीएम/एल-2127438	90-06-16	राम बेयर इंडस्ट्रीज, ए-89 भोखला इंड. एरिया, फेज III, नई दिल्ली-110020	वरबाजे के हथे	IS : 00208-87
45.	सीएम/एल-2127539	90-06-16	पदमसारथ सिलिन्डर्स एंड फोर्जिंग्स प्रा. लि., इंडस्ट्रियल जवेलपमेंट एरिया रैनीगुटा, जिला चित्तौड़ ( छा. प्र. )	द्वपै गैस सिलिन्डर	IS : 03196-82
46.	सीएम/एल-2127640	90-06-06	विभी लि., पराम्बूर बैरकस रोड मद्रास-600012	पॉलीएस्टर मिश्रित कमीज का कपड़ा संघटन 67:33 द्रव्यमान 175 ग्र. मी 2	IS : 09517-86
47.	सीएम/एल-2127741	90-07-01	क्रॉप हैल्व प्राइवेट लि., बी-31/1 इंड एरिया मेरठ रोड, गाजियाबाद पिन-201003	बलोरोगाहरिफांस ईसी	IS : 08944-78
48.	सीएम/एल-2127842	90-07-01	ययाम स्टील इंडस्ट्रीज, 220/3/1, जी. टी. रोड ( उ. ) बूसूरी, हावड़ा-711107	संरचना इस्पात ( मानक किस्म )	IS : 00226-75
49.	सीएम/एल-2127943	90-07-01	ययाम स्टील इंडस्ट्रीज, 220/3/1/जी. टी. रोड ( उ. ) बूसूरी, हावड़ा-711107	सीटीबी सरिए	IS : 01786-85
50.	सीएम/एल-2128036	90-07-01	मधुसूदन स्टील्स एंड रोलिंग वर्क्स, रेलवे स्टेशन के पास, बा. नरोडा/भद्रमदाबाद-382330	वरबाजों, बिड़कियों और संघातियों के लिए तप्त बेल्जित इस्पात सेक्शन	IS : 07452-82
51.	सीएम/एल-2128137	90-07-01	साइट सार्ज्ड इलेक्ट्रानिक्स, ए-128, बजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052	1100 बी तक कार्यकारी बोल्डता के लिए लोबा और एल्यूमीनियम बालकों बाली पीबीसी रोहित केवल	IS : 00694-77
52.	सीएम/एल-8238	90-07-01	बंगलौर बायर राइ मिल, ब्लाइट फोल्ड रोड, महादेव पुरा बा., बंगलौर-560048	धातु मार्क बेल्जिंग इलेक्ट्रोड कोड के सार के लिए मृदु इस्पात ( मान रिमिग किस्म )	IS : 2879-75
53.	सीएम/एल-8339	90-07-01	श्री राम बीजल्स ( इंडिया ) सी 68 फाउंड्री नगर, आगरा	अपकेव्री जल पम्प	IS : 06595-80
54.	सीएम/एल-2128440	90-07-01	बाबू लाल बजाज धायरन फाउंड्री उद्योग नगर नूवाबन, मथुरा ( उ. प्र. )	मल, गंधे पानी और संघातन के लिए पाइप फिटिंग और सहयोग के लिए बाबू के साथ में डले लोहे स्पिगट और सकिट	IS : 01729-79
55.	सीएम/एल-2138541	90-07-01	गोमती प्लास्टिक प्रा. लि. प्लाट नं. 16 और 17 सेंटर 21, यूपीएसआईसीसी इंड. एरिया जगदीशपुर, सुरतानपुर ( उ. प्र. )	पेयजल की आपूर्ति के लिए उच्च बनत्व पालीथीन पाइप	IS : 04984-87
56.	सीएम/एल-2128642	90-07-01	अमेठी इंजीनियरिंग इंड., 88 कालिदास रोड, एमनगर कोयम्बतूर-641009	कृषि प्रयोजनों के लिए तीन फेजी प्रेरण मोट. 4 धेणो ए रोधन	IS : 07538-75
57.	सीएम/एल-2128743	90-07-01	रेनबो बेल्स, 187 पटपड़गंज, दिल्ली-110092	1100 बी तक कार्यकारी बोल्डता के लिए अल्प ताप उपयोग हेतु पीबीसी रोहित हैवी इयूटी केवल	IS : 01554-76



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
58.	सीएम/एल-2128844	90-07-01	रेनबो केबल्स, 187 पटपड़गंज दिल्ली—110092	1100 बो तक कार्यकारी बोर्डता के लिए पीवीसी रोधित केबिलस	IS: 00094-77
59.	सीएम/एल-2128945	90-07-01	मायूर भाइक्रो मोटर्स एंड एप्प्लाइड प्रा. लि. बिजली के घरेलू खाद्य मिक्सर और गेड नं. ए-1/36, जी आईडीसी इंड. एस्टेट, बापी (गुजरात) 390195	ग्राइंडर	IS: 04250-80
60.	सीएम/एल-2129038	90-07-01	एल्फॉन, 4 इंड. एरिया, मंसौर	शिरोपरि प्रेषण के लिए एसीएमआर चालक	IS: 00398-76
61.	सीएम/एल-9139	90-07-01	स्वास्तिक कंडक्टर, बी-311 (ए) शेड नं. 10 बी के आई एरिया, जयपुर—302013	शिरोपरि प्रेषण के लिए एसी चालक	IS: 00398-76
62.	सीएम/एल-2129240	90-07-01	एस एन पालीमर्स (प्रा.) लि., डा. एच. ग्राम फुलवारी जिला—जलपाईगुडी	यूपीवीसी पाइप श्रेणी II और III	IS 04985-80
63.	सीएम/एल-2129341	90-07-01	एस. पा एस्टेट्स एंड जेज, खसरा नं. 28/6/5 ब्राह्मरी स्कूल के पास, ग्रा. बादली दिल्ली—110043	खिड़की के फ्रेम 42 प्रयोग के लिए पुद्दी	IS: 00419-67
64.	सीएम/एल-2129442	90-07-01	मोमार्क इंजीनियर्स, 110 बीएसआईडीसी शेड मोखला, फेज-1 दिल्ली—110020	अनिज भरे खोलदार तापन एलॉमेंट 1.5 किवा	IS: 04169-83
65.	सीएम/एल-2129543	90-07-01	डेल्टा जूट एंड इंड लि., मानिक पुर डा. डेल्टा मिल्ल, जिला हावड़ा—711309	पटमन टाईपुलिन कपड़ा 380 ग्राम मी. 2	IS: 07407-80
66.	सीएम/एल-2129644	90-07-01	नार्थ बुक जूट कं. लि., वेद यादव टी चाम्पडानी मुगली—712222	खाद्यान्न पैकिंग के लिए बी-टिबल पटसन के बीरे	IS: 02560-84
67.	सीएम/एल-2129745	90-07-01	वि. मुगली मिल्ल कं. लि., यूनिट गोंडल पाड़ा जूट मिल्ल डा. गोंडल पाड़ा जि. मुगली	सीमेंट पैकिंग के लिए हलके पटसन के कट्टे	IS: 02154-87
68.	सीएम/एल-2129840	90-07-01	बंगाल सिविडस एंड कंटेनर्स (प्रा. लि., मसोर एबेन्स्यू यू. गुरपुर 12, (जिला बर्धमान (प. बं.))	इ पै गैस सिलिण्डर	IS: 03190-82
69.	सीएम/एल-2129947	90-07-01	सिंह एंड सिंह, 100 एक इंड. एस्टेट गोविन्दपुरा, भोपाल—462023	एक ड्रम वाली छुप्पी केटिंग मशीन के लिए स्याही	IS: 01333-78

[सं. के.प्र.क्र. / 13 : 11]

S. O. 444 :—In pursuance of sub regulation (5) of regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulation of 1988. The Bureau of Indian Standards, hereby notified the grant of licences particulars of which are given in the following Schedule.

## SCHEDULE

## List of Licences Granted During Month June, 1990.

Sl. CM/L-No. No.	Operative Date	Name & Address of the Party	Article/process	IS : No./Part
1.	CM/L-2123127	90-06-16 The Elgin Mills Co. Ltd., Cooper Ganj., Kanpur.	Cotton Cellular Shirting.	IS: 01144—80 Pt. Sc.

1	2	3	4	5	6
2.	CM/L-2123228	90-06-16	Ganges Waterproof Works (P) Ltd., 166, Darir Road, Chowhati, Rajpur P.S. Sonarpur, P.O. South Jagaddal, 24 Parganas (South) West Bengal.	Laminated Bag 380 G/M SQ 68X39 Tarpaulin Fabric.	IS : 07406—86 Pt. 02 Sc.
3.	CM/L-2123329	90-06-16	Ganges Waterproof Works (P) Ltd., 166 Darir Road, Chowhati, Rajpur P.S. Sonarpur, P.O. South Jagaddal, Distt. 24 Parganas (WB).	Laminated Bags Manufactured from 407 G/M SQ Tarpaulin Fabric.	IS : 07406—84 Pt. 01 Sc.
4.	CM/L-2123430	90-06-16	Jayshree Fibre Products Ltd., Village Alam pur, P.O. Andulmouri, Distt. Howrah	Polypropylene Ropes Three Standard Houser Laid, upto and including 24 MM. Dia.	IS : 05175—82 Pt. Sc.
5.	CM/L-2123531	90-06-16	Sealants & Gaskets Industries, Plot No. 24, Kaneh Village Post, Via Vadgaon, Mawal Mawal Taluka Distt. Ponna-412106	Gland Packing Asbestos Grade I upto 32 MM Dia.	IS : 04687—80 Pt. Sc.
6.	CM/L-2123632	90-06-16	Peico Electronics & Electricals Ltd., 3 MIDC Indl. Area, Thane-Belapur Road, Post Box No. 79, Thane-400601	Tubular Fluorescent Lamps for 40 W.	IS : 02418—77 Pt. Sc.
7.	CM/L-2123733	90-06-16	Sylvex Cables Co. (P) Ltd., Saki Vihar Road, Bombay-400072	PVC Insulated and Sheathe D Heavy Duty Cables with Aluminium and Copper Conductors for Working Volt- ages upto & Inc. 1100 V.	IS : 01554—76 Pt. 01 Sc.
8.	CM/L-2123834	90-06-16	Haryana Meters (India), A-2 Sector X, Noida, Distt. Ghaziabad.	AC Electricity Meters Three Phase whole Current Class 2, Rated Standard Basic Currents 10.20 and 30A	IS : 0072—77 Pt. 03 Sc.
9.	CM/L-2123935	90-06-16	Sylvex Cable Co. Pvt. Ltd., Saki Vihar Road, Bombay-400072.	Single/Multicare, PVC Insulated Sheathed/Unsheathed Cables Includ- ing Flexible Cords Excluding Cable for use under Low Temp.	IS : 00694—77 Pt. Sc.
10.	CM/L-2124028	90-06-16	Kumar Engg. Co., Behind Sukhram Nagar Near Azad Dairy Road Rakhial, Ahmedabad-380 023	Foot Valves of sizes 50MM 60MM, 80MM and 100 MM Screwed ends only	IS : 10805—86 Pt. Sc.
11.	CM/L-2124129	90-06-16	Surya Power Ltd., A-461 and 462 Matsya Indl. Area, Alwar-301 030	Crosslinked Polyethylene Insulated PVC sheathed armoured/unarmoured with aluminium conductors for voltages upto & Inc. 1100,	IS : 07098—77 Pt. 01 Sc.
12.	CM/L-2124230	90-06-16	Guj Petrochem (P) Ltd., Plot No. 17/20-21, MIDC Taloja, Raigad (Maharashtra)	New Insulating Oils	IS : 003,5—83 Pt. Sc.
13.	CM/L-2124331	90-06-16	Geco Electrical Corpn. 191, Dada Colony, Post Box No. 487, Indl. Area, Jalandhar City.	Miniature Circuit Breaker S, 6A: 240/415 V, Category of duty M9	IS : 08828—78 Pt. Sc.

1	2	3	4	5	6
14. CM/L-2124432	90-06-16	Cobra Cables (P) Ltd., Kathotia Indl. Centre, 25/3, Gali No. 17, Vishwas Nagar, Shahdara, Delhi-110 032	PVC Insulated Cables for working Voltages upto and including 1100 V Sheathed & unsheathed with Aluminium & Copper Conductors	IS : 00694—77 Pt. Sc.	
15. CM/L-2124533	90-06-16	Minerals & Electrochemicals , Midc Area, Miraj, Distt. Sangli (Maharashtra)-416 410	Multipurpose dry batteries S(R20 size only) 1.5V	IS : 08144—76 Pt. Sc.	
16. CM/L-2124634	90-06-16	Life Batteries (P) Ltd., Cantonment Road, Cuttack (Orissa)-753 001	Lead Acid Storage Batteries for Motor Vehicles for 6 Volt , 135 AH	IS : 07372—74 Pt. Sc.	
17. CM/L-2124735	90-06-16	Rama Chair Industries, A-89, Okhla Indl. Area, Phase-II, New Delhi-110 020.	Tower Bolts (Non-Ferrous) Type 4 only	IS : 00204—78 Pt. 02 Sc.	
18. CM/L-2124836	90-06-16	Nagpal Electric and Radio Co. C-108, Naraina Indl. Area, Phase-I, New Delhi-110 028	(i) 750 Watt Thermostatic Electric Irons with Aluminium Sole Plate and Cast Iron sole plate. (ii) 600 W Non-Thermostatic	IS : 00366—85 Pt. Sc.	
19. CM/L-2124937	90-06-16	Kirloskar Oil Engines Ltd. Laxman Rao Kirloskar Road, Khadki, Pune-411 003	Diesel Engine Monoset pump for Agricultural purposes	IS : 11501—86 Pt. Sc.	
20. CM/L-2125030	90-06-16	Devidayal & Mahindra Cables (P) Ltd. Khasara No. 61, Village & Post Matiala Najafgarh Road, New Delhi-110059.	PVC Insulated Cables for working voltages upto and including 1100 V. Sheathed & unsheathed with Alumi- nium and Copper conductor	IS : 00694—77 Pt. Sc.	
21. CM/L-2125131	90-06-16	Shanco Industries, B-50, Nandabhuvan Indl. Estate, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Bombay-400093	Single-Phase Motors of 180 W, 220-230V, 50HZ, 2, 8A, Capacitor Start, Induction Run, 1440 RPM, E Class Insulation.	IS : 00996—79 Pt. Sc.	
22. CM/L-2125232	90-06-16	Surya Jyoti Devices India Pvt. Ltd., Village Chanalon , Post Kurali, Distt. Ropar.	UPVC Pipes upto & Including 110MM dia Class I & III	IS : 04985—81 Pt. Sc.	
23. CM/L-2125333	90-06-16	Protecto Engg. Pvt. Ltd., 4266, Nasik-Pune Highway , Chakan, Distt. Pune-410501	Submersible Motors, 3.7KW declared current 8.5A, Wet type	IS : 09283—79 Pt. Sc.	
24. CM/L-2125434	90-06-16	Shree Venkateshwara Tin Containers Shed No. 18, Indl. Dev. Area, Kotnur, Shad Nagar Taluk, Mehboob Nagar Distt.	15 Kg. square tins for PAC king ghee, Vanaspati, edible oils & bakery shor- tenings	IS : 10325—89 Pt. Sc.	
25. CM/L-2125535	90-06-16	Kaveri Enterprises, 75, Indl. Area, Jhotwara, Jaipur-302012.	15 Kg. Square Tins for PAC king ghee, Vanaspati, edible oils and bakery shortenings	IS : 10325—89 Pt. Sc.	
26. CM/L-2125636	90-06-16	Ambika Enterprises, 16/1, Village Kotla, Delhi-110091.	Domestic stoves for use with LPG. stainless steel body, double burner.	IS : 04246—84 Pt. Sc.	
27. CM/L-2125737	90-06-16	Everest Computer Carbons Pvt. Ltd., Kallakal Village, Gajwal Taluk Distt. Medak	Typewriter Ribbons Cotton, Type I, medium inking only.	IS : 04174—77 Pt. Sc.	
28. CM/L-2125838	90-06-16	Nav Shakti Chemical Industries F-3 B, Road No. 9, IDA Nacharam, Hyderabad East Taluk, Distt. Rangareddy-501507	Ink-Stamp Pad, Grade A only	IS : 00393—85 Pt. Sc.	

1	2	3	4	5	6
29. CM/L-2125939	90-06-16	JBF Industries Ltd., Plot No. 84/2 & 3, Op. PIPDIC Indl. Estate, Kirumampakkam Village, Bahur Commune, Pondicherry.	Trichloroethylene, Type I and II	IS : 00245—70 Pt. Sc.	
30. CM/L-2126032	90-06-16	Manual Feeds Corporation, Building No. 108, Ward No. 8, Cherupunkal, Kidangoor , Panchayat, Palai (Kerala) 686584	Poultry Feeds, type BST and BFF only	IS : 01374—79 Pt. Sc.	
31. CM/L-2126133	90-06-16	Dua Associates, 3237/1, Street No. 3, New Janta Nagar, Opposite Arora Palace, Ludhiana.	Electric Irons, 750 W, 230 V.C.I. base plate.	IS : 00366—85 Pt. Sc.	
32. CM/L-2126234	90-06-16	R.K. Devices Pvt. Ltd., Rajpura Road, Bahadurgarh, Patiala (Punjab).	Steel Butt Hinges	IS : 01341—81 Pt. Sc.	
33. CM/L-2126335	90-06-16	Himachal Milk Products (P) Ltd. Rampur Road, Village Kunja, Poonta Sahib (HP) 173025	Skimmed Milk Powder	IS : 01165—86 Pt. Sc.	
34. CM/L-2126436	90-06-16	Radio & Electricals Ltd. 96, Basin Road, Tiruvottiyur, Madras-600019.	Outdoor type distribution transformer, Three phase upto and including 100KVA 11KV 433V. Onan Cooling Victor Group DY11	IS : 01180—81 Pt. 01 Sc.	
35. CM/L-2126537	90-06-16	Punjab Iron & Steel Co. (P) G.T. Road, Jalandhar Cantt.	High strength deformed steel bars and Wires for concrete reinforcement , for nominal sizes 8MM upto and incl. 25MM.	IS : 01786—85 Pt. Sc.	
36. CM/L-2126638	90-06-16	New Kashmir Steel Rolling Mills 2nd Indl. Area, Gangyal, Jammu Tawi.	Structural Steel (Standard quality) Equal Angle size 20x20 mm upto and including 65x65 mm only.	IS : 00226—75 Pt. Sc.	
37. CM/L-2126739	90-06-16	Dua Electricals 3237/1, Street No. 3, New Janta Nagar, Opposite Arora Palace, Gill Road, Ludhiana.	Thermostatic Electric Irons, 750 W, 230 V, Cast Iron base Plate.	IS : 00366—85 Pt. Sc.	
38. CM/L-2126840	90-06-16	Raghupati Appliances 16/5, Mathura Road, Faridabad.	Domestic Stoves for use With LPG	IS : 04246—84 Pt. Sc.	
39. CM/L-2126941	90-06-16	Usha Udyog, P-1, Focal Point, Khanna (Punjab) 141401 Modern Engineers	Compounded feed for cattle type 2 only.	IS 02052—79 Pt. Sc.	
40. CM/L-2127034	90-06-16	Industries (Regd.) B-10, Indl. Focal Point , Nava Shahar, Distt. Jalandhar.	Cast Iron Flushing Cisterns	IS : 0774—84 Pt. Sc.	
41. CM/L-2127135	90-06-16	Bharat Valves I-18, DFL Indl. Area, Phase I, Faridabad-121005.	Valve Fittings for compressed gas Cylinders	IS : 03224—79 Pt. Sc.	
42. CM/L-2127236	90-06-16	Rama Chair Industries, A-89, Okhla Indl. Area, Phase II, New Delhi-110020.	Slicing bolts (ALDROP) Type 3	IS : 02681—79 Pt. Sc.	

1	2	3	4	5	6
43. CM/L-2127337	90-06-16	New India Wire & Cable Industries 41 & 42, Gangyal, Industrial Area, Phase III, Jammu.	ACSR Conductors Seven Strands	IS : 00398—76 Pt. 02 Sc.	
44. CM/L-2127438	90-06-16	Rama Chair Industries, A-89, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020	Door Handles Type 4	IS : 00208—87 Pt. Sc.	
45. CM/L-2127539	90-06-16	Padmasarathy Cylinders & Forgings Pvt. Ltd. Indl. Dev. Area, Renigunta Distt. Chittoor (AP) 517520	LPG Cylinders	IS : 03196—82 Pt. Sc.	
46. CM/L-2127640	90-07-01	Binny Ltd. Perambur Barracks Road, Madras-600012.	Polyester Blend Suitings Composition 67 : 33 Mass 175 G/M SQ	IS : 09517—86 Pt. Sc.	
47. CM/L-2127741	90-07-01	Crop Health Products Ltd. D-31/1, Indl. Area, Meerut Road, Ghaziabad-201003.	Chloropyrifos EQ	IS : 08944—78 Pt. Sc.	
48. CM/L-2127842	90-07-01	Shyam Steel Industries, 220/3/1, G.T. Road (N), Ghusuri, Howrah-711107.	Structural Steels (Standard Quality)	IS : 00226—75 Pt. Sc.	
49. CM/L-2127943	90-07-01	Shyam Steel Industries, 220/3/1, G.T. Road (N) Ghusuri, Howrah-711107.	CTD Bars	IS : 01786—85 Pt. Sc.	
50. CM/L-2128036	90-07-01	Madhusudan Steels Re-Rolling Works near Railway Station, P.O. Naroda, Ahmedabad-382330	Hot Rolled Steel Sections for Doors, Windows and ventilators.	IS : 07452—82 Pt. Sc.	
51. CM/L-2128137	90-07-01	Sight Sound Electronics, A-128, Wazirpur Indl. Area, Delhi-110052.	PVC Insulated Cables with Aluminium and copper conductors for working voltages upto and including 1100 volts	IS : 00694—77 Pt. Sc.	
52. CM/L-2128238	90-07-01	Bangalore Wire Rod Mill White field Road, Mahadeva Pura Post, Bangalore-560048.	Mild Steel for Metal ARC Welding Electrode Core Wire (Non Rimming quality.	IS : 02879—75 Pt. Sc.	
53. CM/L-2128339	90-07-01	Shri Ram Diesels (India) C-66, Foundry Nagar, Agra.	Centrifugal Water Pumps	IS : 06595—80 Pt. Sc.	
54. CM/L-2128440	90-07-01	Babu Lal Bajaj Iron Foundry Udyog Nagar, Viindavan, Mathera (UP)	Sand Cast Iron Spigot and Socket Soil Waste and ventilating pipe fittings and Accessories.	IS : 01729—79 Pt. Sc.	
55. CM/L-2128541	90-07-01	Gomati Plastic Pvt. Ltd. Plot No. 16 & 17, Sector 21, UPSIDC Indl. Area, Jagdishpur, Sultanpur (UP)	High Density Polyethylene Pipes for Potable water supplies.	IS : 04984—87 Pt. Sc.	
56. CM/L-2128642	90-07-01	Aarathi Engg. Inds. 88, Kalidas Road, Ramnagar, Coimbatore-641009	Three Phase Induction Motors for agricultural applications class A Insulation.	IS : 07538—75 Pt. Sc.	
57. CM/L-2128743	90-07-01	Rainbow Cables, 187, Patpar Ganj Delhi-110092.	PVC insulated heavy duty cables for working voltages upto and including 1100 V for use under low temperature applications.	IS : 01554—76 Pt. 01 Sc.	
58. CM/L-2128844	90-07-01	Rainbow Cables 187 Patpat Ganj	PVC Insulated Cables for working voltages upto and including 1100 volts	IS : 00694—77 Pt. Sc.	

1	2	3	4	5	6
59. CM/L-2128945	90-07-01	Mathur Micro Motors & Appliances Pvt. Ltd. Shed No. A-1/36 GIDC Indl. Estate Vapi (Gujarat) 396190.		Domestic Electric Food Mixers and Grinders.	IS : 04250—80 Pt. Sc.
60. CM/L-2129038	90-07-01	Alcons 4. Indl. Area, Mandysaur.		ACSR conductors for overhead transmission purpose.	IS : 00398—76 Pt. 02 Sc.
61. CM/L-2129139	90-07-01	Swastika Conductors B-311(A) Road No. 16, VKI Area, Jaipur-302013.		AAC conductors for overhead transmission.	IS : 00298—76 Pt. 01 Sc.
62. CM/L-2129240	90-07-01	S.N. Polymers (P) Ltd. P.O. & Village Fulbari Distt. Jalpaiguri.		UPVC Pipes Class II and III	IS : 04985—80 Pt. Sc.
63. CM/L-2129341	90-07-01	S. Rupta Enterprises, Khasra No. 28/6/5 Near Primary School, Village Badli, Delhi-110042.		Putty for use on window frames	IS : 00419—67 Pt. Sc.
64. CM/L-2129442	90-07-01	Monarch Engineers, 110, DS IDC Shed, Okhla Phase I, New Delhi-110020.		Mineral Filled sheathed heating elements 1.5KW.	IS : 04150—83 Pt. Sc.
65. CM/L-2129543	90-07-01	Delta Jute & Inds. Ltd., Manickpore, PO Delta Mill, Distt. Howrah 711309.		Jute Tarpaulin Fabric 380G M SQ	IS : 07407—80 Pt. 03 Sc.
66. CM/L-2129644	90-07-01	North Brook Jute Co. Ltd. Bridyabati Champdani, Hooghly-712222		B-Twirl Jute Bags for packing food grains	IS : 02566—84 Pt. Sc.
67. CM/L-2129745	90-07-01	The Hooghly Mills Co. Ltd., Unit Gondal Para Jute Mill, PO Gondal Para, Distt. Hooghly.		Light weight jute bags for packing cement.	IS : 01154—87 Pt. Sc.
68. CM/L-2129846	90-07-01	Bengal Cylinders & Containers (P) Ltd. Nasser Avenue, Durgapur-12, Distt. Burdwan (WB).		LPG gas cylinders.	IS : 03196—82
69. CM/L-2129947	90-07-01	Singh & Singh, 100 F. Indl. Estate, Govind Pura, Bhopal-462023.		Duplicating ink for single drum rotary machine.	IS : 01333—78 Pt. Sc.

[No. CMD/13 : 11]

का.भा. 445 :-- भारतीय मानक भ्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 4 के उपविनियम (5) के अनुसरण में भारतीय भ्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे स्वीकृत कर दिए गए हैं :

## अनुसूची

क्रम सं.	लाइसेंस संख्या	लाभ होने की प्रवधि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तु/प्रक्रम और सम्बद्ध भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सीएम/एल-2140733	1990-08-16	रेलिस इंडिया लि, डा बड़ोदा रेयन, उद्यता 394220	कृषि प्रयोजनों के लिए छोटे साइज के स्पार्क प्रज्ज्वलन इंजन आईएस : 07347-74

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 सीएम/एल-2140334	1990-08-16	महाराष्ट्र वेल्थरेड्स लि , बी-28 एमआईडी सी एड एरिया कमलेखर, मंगरपुर	धातु आर्क वेल्डिंग हेतु भारतरत्न इलेक्ट्रोड आईएस 08814-84 (भाग 2)	
3 सीएम/एल-2140335	1990-08-16	भोपाल पेस्टीसाइड्स प्रा लि , शेड नं 10, इड एस्टेट गोविन्दपुरा, भोपाल 461022	आईसोप्रोपूरान डब्ल्यूपी आईएस 11995-87	
4 सीएम/एल-2141028	1990-08-16	बनमोर केबल्स एड कडक्टर्स, 30, इड एरिया बनमोर, जि मुरैना	1100 बोल्ट कार्यकारी बोल्टला के लिए एल्यूमी- नियम धातुको बाले पीवीसी रोधित हेवी ड्यूटी खोलवार अकवचिन बिजली की केबल आईएस 01554-76 (भाग 2)	
5 सीएम/एल-214129	1990-08-16	गोयनका टी वेस्ट इंडस्ट्रीज, 2-ई गुरुदासवत्ता गार्डन लेन, कलकत्ता 700007	बाय फी पेटियो के लिए प्लाईवुड के बत्ते आईएस 00010-76	
6 सीएम/एल-2141430	1990-08-16	हिन्दुस्तान पेट्रोकेमिकल्स, खमरा नं 218, या मोछापुर बरपुर, नई दिल्ली 110046	भौतिक विद्मेन, ग्रेड 85/251 90/15, 115/15 केबल आईएस 00702-01	
7 सीएम/एल-2141331	1990-08-16	दातार स्विचगीयर प्रा लि , एफ-8 डी रोड, एम आईडी सी, अमबाड, नामिक 422001	भतिलघु वायु वियोज्य पणिव वियोजक, आईएस . 08828-78	
8 सीएम/एल-2141432	1990-08-16	मोखर केबल्स 8 कडक्टर्स प्रा लि , 39 इड एस्टेट भाम्नी मैदान, गुवाहाटी 781021	1100 बोल्ट कार्यकारी बोल्टला के लिए खोल- वार और खालरहित पीवीसी रोधित केबल, आईएस 00694-77	
9 सीएम/एल-2141513	1990-08-16	धरेन्द्र आईस्क्रीम लि , 908 जीआईडीसी इजी स्टैंड, सेक्टर 28, गांधीनगर 382028	आईस्क्रीम, आईएस 02802-64	
10 सीएम/एल-2141534	1990-08-16	रेटेरिया लमिनेटर्स लि , 493 जी टी रोड, साहिबपुर, हावड़ा	उर्वरक पैकिंग के लिए परतवार पटसन के कट्टे, 407 ग्रा/मी <sup>2</sup> आईएस . 07406-84 भाग 1	
11 सीएम/एल-2141735	1990-08-16	कॉफिंग पेस्टीसाइड्स प्रो वर्ल्ड पोलिमोमार्गेनिक्स प्रा लि , ए-4, एम आईडी सी महाब जिला-रायगढ़	एड सिलिकाई सी आईएस . 04321-80	
12 सीएम/एल-2141886	1990-08-16	सोलर मिडीकेट , डूंगरी, जि बनसाड 390375	एडोसिलिकाई सी आई एस 04323-80	
13 सीएम/एल-2141437	1990-08-16	रपम इंडस्ट्रीज, गली 12 दूसरा तल, बनपयाम इडस्टेट, बीरा वेसाई रोड, बरसाड रोड के सामने, बम्बई 400045	तांबा और एल्यूमिनियम धातुको सहित एक क्रोड वाली पी वी सी रोधित खोल रहित नम्य केबल, आईएस 00458-71	
14 सीएम/एल-2142030	1990-08-16	नेशनल प्राइडर्स, मिरमो गाय डा भंडारा रोड बरबी जि भंडारा	क्रीट पाइप, 15×250 मिमी साइज आई एस . 00458-71	
15 सीएम/एल-2142131	1990-08-16	पाम रॉक होम एप्लाइसेज, 560/1 मिथरोड अम्बापुर, मन्नास-600098	भापवाली इस्तर, रेटिंग 230 वो, 1000 वा, आई एस . 06290-86	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	सी एम/एल-2142232	1990-08-16	वरुण एंटर प्राइजेज 17 पार्वती नगर, टोक रोड, जयपुर	साफ, ताजे ठंडे पानी के लिए निमज्जय पम्प सेट आई एम 08034-76
17	सी एम/एल-2142333	1990-08-16	केसोराम सीमट्स, बसत नगर जि. करीम नगर 505187	4: ग्रेड साधारण पोर्टलैंड सीमट आई एस 08112-76
18	सी एम/एल-2142434	1990-08-16	साबर कंकटर्स प्रा लि, साबर केबल्स के पाम मज्दगारी जिन के सामने, हिम्मतनगर 385001	प्रिरोपरि प्रेषण के लिए एल्युमिनियम चालक आई एम 00398-76 भाग 1
19	सी एम/एल-2142535	1990-08-16	श्री निवास इंडस्ट्रीज, 272/1 सी, मेदतूपसावम रोड, कायम्बतूर 641043	साफ, ठंडे, पाजे पानी के लिए मोनो सेट पम्प आई एस 09079-79
20	सी एम/एल-2142636	1990-08-16	आरबी एंटरप्राइजेज, मण्ड रोड, मूजकर नगर 251003	18 लिटर के चौकोर कन्स्टर, चौड़ा मुँह आई एम 00916-75
21	सी एम/एल-2142737	1990-08-16	पाठल कैमीकल्स प्रा लि ए-1/48 जी आई डी सी नन्दसारी इंडस्ट्रीज एस्टेट, नन्दसारी जिन-बड़ीदा 311640	फेनिलरेट ईसी आई एस 11997-87
22	सी एम/एल-2142838	1990-08-16	डाटा केबल्स प्रा लि, केन्द्र इंड एरिया, डा गोबन्द नगर, धनबाद	1100 वो तक कार्यकारी बोलटमा के लिए इलेक्ट्रोमर रोहित केबल आई एम 09958-81 भाग 1]
23	सी एम/एल-2142939	1990-08-16	लक्ष्मी इंडस्ट्रीज प्लाट न बी-19, एम आई डी सी कुवाल जिला सिधुपुर	क्रीट पाइप आई एम 00458-71
24	सी एम/एल-2143032	1990-08-16	स्टर्लिंग रिरोलिंग मिल्स लि, बोलशेड रोड ठाणे	उच्च सामर्थ्य के विद्युत सारिण आई एम 01784-83
25	सी एम/एल-2143133	1990-08-16	पोशाक लि, पानीले, तहसील हलोल, जि पंचमहल	आईसोप्रोटायुटॉन तकनीकी ग्रेड आई एम 12004-87
26	सी एम/एल-2143234	1990-08-16	रॉ रबडस (इंडिया) 18/24 गली न. 4 के सामने धनव पर्वत, इंड एरिया, न्यू रोहसक रोड, नई दिल्ली	बिजली की इस्तरियां आई एम 00355-85
27	सी एम/एल-2143335	1990-08-16	एल.इंड विट्रुमेन कापम्लेक्स (इंडिया) प्रा. लि डा आर गोपालपुर, जि 24 परगना	सडक के लिए निट्रुमेन पायस (धनाधन टाइप) आई एम 08887-87
28	सी एम/एल-2143436	1990-08-16	पोशाक लि, पानीले, तहसील हलोल पंचमहल	आईसोप्रोटायुटॉन, डब्ल्यू पी आई एस 11995-87
29	सी एम/एल-2143537	1990-08-16	गंगा लैम्पस एंड ड्युक्स प्रा. लि, आरसी सेन्टर, न 67/1, कनकपुरा रोड, बंगलौर 560078	सामान्य प्रमाणित का बिजु नविकार फ्लोरेसेट लैम्प आई एम 02418-77 भाग 1
30	सी एम/एल-2143638	1990-08-16	न्यू कीम प्लास्टिक लि, 54 इंड एरिया, कलौदाबाद	क्रीट के लिए अपमिश्रण आई एस 09103-79
31	सी एम/एल-2143739	1990-08-16	पारेख केबल्स प्रा लि, ए-1/171, जीआई डी सी अवलेखर जि भद्रक—190332	एसी एस आर चालक आई एम 00398-76 भाग 2



1	3	3	4	5
32	सी.एम./एल-2143840	1990-08-16	हेमल इलेक्ट्रिकल्स प्रा.लि., एन रिच रोड नं. 12 आ. काकीपुरा शिवदासपुरा 303903	एसी एस आर चालक आई एम : 00398-76
33	सी.एम./एल-2143941	1990-08-16	अर्चना इंडस्ट्रीज, 286 साठे रोड, गांधीपुरम, कोयम्बतूर 641012	निमज्जय पम्प सेट के लिए मोटर, वेट टाइप सर्विंग बी, तीन फेजी आई एम : 04800-68 भाग 5
34	सी.एम./एल-2144034	1990-08-16	जयपुर मेटल एंड इलेक्ट्रिकल्स प्रा.लि., रेलवे स्टेशन के पास, जयपुर 302006	अधिक ताप हेतु इनेमल चढ़े गोल्ड बेयटन तार टाइप आई एम : 00398-76 भाग 2
35	सी.एम./एल-2144135	1990-08-16	इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड मैनु. कं., जी-8 से टर 11 नौएडा जि. गाजियाबाद	एसीएस आर चालक आई एम : 00398-78 भाग 2
36	सी.एम./एल-2144236	1990-08-16	स्टेरिया केमिनेटर्स प्रा.लि., 493 जी टी रोड, साहिबपुर हावड़ा	उर्ध्वक वीकश के लिए परस्पर पट्टन के कटटे, 380 वा/मी <sup>2</sup> टारगुलिन कपड़ा, आई एम : 04246-84
37	सी.एम./एल-2144337	1990-08-16	डास्टन इंडस्ट्रीज सी-429, सेक्टर 10 नौएडा (उत्तर प्रदेश)	द्रोणी के साथ प्रयुक्त धरेलू चूल्हा आई एम : 04245-84
38	सी.एम./एल-2144433	1990-09-16	समिलता इलेक्ट्रिकल्स, एस पी 24, इंड. एस्टेट अम्बाला मद्रास 600058	पावर ट्रांसफार्मर रेटिंग 150 के बी ए से 500 केबीए आई एम : 02036-77 भाग 1
39	सी.एम./एल-2144539	1990-09-01	सावर कंडक्टर्स प्रा.लि., सहकारी जिम के सामने श्यामलाल जी रोड, हिम्मत नगर जि. साबरकाटा	ए सी एस आर चालक आई एम : 00398-76 भाग 2
40	सी.एम./एल-2144640	1990-09-01	खटाक जंकर लि., प्लॉट नं. 5000, एस्टेट अकलेश्वर 393002	डाइकलसराबॉम ईसी आई एम : 05277-78
41	सी.एम./एल-2144741	1990-09-16	बालाजी एन्डरप्राइजेज प्रा.लि., 48 इंड. एरिया, जोषवाड़ा जयपुर	छलवा पिपेट इंगट आई एम : 01914-78
42	सी.एम./एल-2144842	1990-09-01	मार्की केबल्स प्रा.लि., प्लॉट नं. ए-55-56 स्टिम, मित्तार-गिरडी रोड, मित्तार जि. नासिक 422100	1100 बोतक कार्यकारी बोल्डना के लिए पीवीसी रोधन हैवीइयेटी केबल आई एम : 01554-76 भाग 1
43	सी.एम./एल-2144943	1990-09-01	जूनागढ़ डेयरी (मै गूजरका डेयरी डवलपमेंट कारपो. लि., की एक इकाई) अफ्फार मैदान, जूनागढ़ 362001	सकलिया दूध पाउडर आई एम : 01165-86
44	सी.एम./एल-2145040	1990-09-01	वसंत इस्पात उद्योग प्रा.लि., 57 इंड एस्टेट भागला (उ.प्र.)	सामान्य प्रयोजनों के लिए इंडल इंसुल नं. 3,7 कि. वा. से 7.38 कि. वा. आई एम : 1001-81
45	सी.एम./एल-2145137	1990-09-01	एम के वेट्रो प्रॉडक्ट्स (प्रा.) लि., प्रा. सोफ्टा हरफोमी तमहील पलवल फरीदाबाद	औद्योगिक बिटुमन ग्रेड 85/25, 90/15 आई एम : 00702-88

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46. सी एम/एल-2145239	1990-09-01	कमला इंजीनियरिंग वर्क्स, पंजाब नेशनल बैंक के पास, इस्लामियाबाद जि.-कुश्नोत्र	पामर ओशर की सुरक्षा अधेक्षण, 10 अश्वशक्ति रेटिंग आई एस : 09020-79	
47. सी एम/एल-2145339	1999-09-01	पारुल कैमीकल्स प्रा लि , ए 1/96 जी आई डी सी नन्दमारी इंड एस्टेट, नन्दमारी, जि० बड़ोदा 39134	इंडो सल्फान डी पी आई एस : 04322-67	
48. सी एम/एल-2145440	1990-09-01	इर्ले ट्रंकल इंड एलाइड मैन्यु कं , कजी-8 सेक्टर-11, नोएडा (जि.-गाजियाबाद)	ए सी एम भार चालक आई एस : 00398-76 भाग 1	
49. सी एम/एल-2145541	1990-09-01	डायमंड कैमीकल्स, ग्राम-मुंडका , दिल्ली-41	पैराफिन मोम आई एस : 04554-74	
50. सी एम/एल-2145642	199-04-09-01	शार्प हैजरीज , 61-ए 14 रमानिया कोलोमी,(न्यु नं. 4) तिरुपुर 638602	सादा बुनी सूती बनियान आई एस : 04964-80	
51. सी एम/एल-2145743	1990-09-01	लक्ष्मी स्माल कोटेज इंडस्ट्रीज, 14 एन एस कोणार्क स्ट्रीट, जवाहर्नगर, मद्रास 625011	गैर वाब स्टोव, बहुबली वाला आई एस : 02980-86	
52. सी एम/एल-2145844	1990-09-01	खड्गलु जंकर लि. , प्लॉट नं. 3000, जी आई डी सी एस्टेट, ग्रंथलेश्वर 393002	फास्पोमिडान, डब्ल्यू एस सी आई एस : 06177-81	
53. सी एम/एल-2145945	1990-09-01	मीनामजिया इंडस्ट्रीज, 82 रामपूति रोड बडामालपुरम, 6 ए शिवकासी, बडामालपुरम	डिब्बीबंद निरापव दियासलाई आई एस : 02653-80	
54. सी एम/एल-2146038	1990-09-01	कुमार इंजी. कं. , सुखराम नगर के पीछे, रखैल अहमदाबाद 380023	कृषि प्रयोजनों के लिए ताजा, साफ ठंडे पानी हेतु मोनो सैट पम्प आई एस : 09079-89	
55. सी एम/एल-2146139	1990-09-01	अजीत काटन गिनिंग प्रेसिंग, डाल एंड स्टील रोलिंग मिल्स, जी टी रोड, मंडी गोबिन्दगढ़ (पंजाब)	उच्च समायर्थ के विकृतसरिए आई एस : 01786-85	
56. सी एम/एल-2146240	1990-09-01	यू के इंडस्ट्रीज, एल/46, जी आई डी सी न्यू वाटर टैंक के पास, उज्जैन, अहमदाबाद	कृषि प्रयोजनों के लिए ताजा, साफ, ठंडे पानी हेतु मोनो सैट पम्प आई एस : 09079-89	
57. सी एम/एल-2146341	1990-09-01	प्रवीन ट्रेडिंग कार्पोरेशन, सी. 24, ब्रड एरिया पटना-800013	ए सी ए भार चालक आई एस : 0039882 भाग 5	
58. सी एम/एल-2146442	1990-09-01	हावड़ा मिल्स कं. लि. , 493/सी जी टी रोड (ब) हावड़ा-711102	सीमेंट पैकिंग के लिए हल्के कट्टे आई एस : 12154-87	
59. सी एम/एल-2146543	1990-09-01	श्री दुर्गा केबल्स प्रा.लि. , 28 इंड. , एस्टेट जगतपुर जि.कटक (उड़ीसा)	1100 बो तक कार्यकारी बोस्टता के लिए खोलवार, अकवचित पी पी सी रोधित हैवी इग्नीटी विजली के केबल आई एस : 01554-76 भाग 1	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
60. सी एम/एल-2146544	1990-09-01	गुप्ता केबल्स (प्रा.) लि., स्टेशन रोड भुवनेश्वर 751006	एएसी चालक ग्राई एम : 00398-79 भाग 4	
61. सी एम/एल-2146745	1990-09-01	एम जी एन केबल इंडस्ट्रीज, ई-59 फेज 8 मोहाली	ए सी एस ग्रार चालक ग्राई एस : 00398-76 भाग 2	
62. सी एम/एल-2146846	1990-09-01.	मिथैटिक एस्फेन्ट, 139 जवाहर इंड. एस्टेट पनवेल 410206	सड़के के लिए ट्रिमेन पायम, धनायन टाइप, मध्यम सैटिंग ग्राई एस: 08837-78	
63. सी एम/एल-2146947	1990-09-01	हार्डिरो बाल्व, 2991 त्रिनगर बिस्नी 110035	टू पैर के साथ प्रयुक्त घरेलू गिलर ग्राई एम : 11480-85	
64. सी एम/एल-2147040	1990-09-01	श्री मोनाथी कैमीकल्स, 436/2 बिम्बाकोटी रोड सिवकासी 626123	पैराफिन मोम टाइप 3 ग्राई एस : 04654-74	
65. सी एम/एल-2147141	1990-09-01	बितावनशाह जूट मिल्स, बितावनशाह जि.-बिशाखापटनम 531162	मीथेन पैकिंग के लिए पटमन मसिलेट युनिट्स कट्टे ग्राई एस : 12174-87	
66. सी एम/एल-2147242	1990-09-01	बी ए कैमीकल एंड सल्फर इंडस्ट्रीज, प्लॉट ए/148 एम ग्राई डी सी, डोम बिबिली जि.-डोणे	सल्फर भुरकास वर्ण ग्राई एम : 06444-79	
67. सी एम/एल-2147343	1990-09-01	इंडस्ट्रियल पेन्ट एंड बार्निश, प्रा.-सजीवाया घाटा बिलाड जि.-घार(म.प्र.)	प्राग्मिक हेतु हवा से सूखने पेड आक्साइड, जिक क्रोम तैयार शुद्ध रोगन, ग्राई एम : 02074-79	
68. सी एम/एल-2147444	1990-09-01	राकी इंडस्ट्रीज, 2-113 पीथापुरम रोड, रमनयापेटा, काकीनाड़ा 533009	पाद छिड़काव यंत्र, ट्रिगर सहित टाइप ग्राई एम : 03652	
69. सी एम/एल-2147545	1990-09-01	राकी इंडस्ट्रीज, 2-113 पातापुरम रोड, रमनयापेटा काकीनाड़ा 533009	हस्तचालित मैनल तैलसैक छिड़काव यंत्र 16 लिटर धारिता, टाइप ए ग्राई एम : 03906-82 भाग 1	
70. सी एम/एल-2147646	1990-09-01	प्लांट प्रोटेक्शन प्रॉडक्ट्स लि., कोडावनूर, कोडावनूर मंडलम जि.-नैल्लोर	थायरम इन्व्यू डी पी ग्राई एम : 04766-82	
71. सी एम/एल-2147747	1990-09-01	थांगम फेब्रिकेटर्स, 1/4 -डी, एनीमूथु पिल्लायर कोडलस्ट्रीट, विरधूनगर 626001	पी बनस्पति, तेलों और बेकरी भोगन हेतु 15 किग्रा. के चौकोर कनस्तर ग्राई एम : 10325-89	
72. सी एम/एल-2147818	1990-09-01	ईस्ट कोस्ट स्टील लि., बुडाल्लूर रोड. पिल्लयारकुपमंडा बिहोर कम्पून पांडचेरी 607402	सतत ठोके बिलेट इंगट (मामक गुणता) ग्रेड 1 और 2 ग्राई एम : 06914-78	

S.O. 443 :—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, The Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given the following Schedule.

## SCHEDULE

## List of Licences Granted During the Month of August, 1990

S. No.	CM/L No.	Operative Date	Name & Address of the Party	Article/Process	IS : No/Part
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	CM/L -2140733	1990-08-16	Rallis India Ltd. PO Baroda Rayon Udhna-394220	Small size Spark Ignition Engines for Agricultural Purposes	07347-74
2.	CM/L -2140834	1990-08-16	Maharashtra Weldaid Ltd. B-28, MIDC Indl. Area Kalmeshwar Nagpur (MS)	Covered Electrodes for Metal Arc Welding	00814-74 (Part-II)
3.	CM/L -2140935	1990-08-16	Bhopal Pesticides Pvt. Ltd., Shed No. 10 Indl. Estate Govindpura Bhopal-462022	Isoproton WP	11995-87
4.	CM/L -2141028	1990-08-16	Banmore Cable, & Conductor 30, Indl. Area Banmore, Distt. Morena	PVC Insulated heavy duty and PVC Sheathed Unarmoured Electric Cables with Aluminium conductors for working voltages upto and including 1100 V	01554-76 (Part-I)
5.	CM/L -2141129	1990-08-16	Goenka Teachest Industries 2-E, Garudas Datta Garden Lane Calcutta-700007	Teachest Plywood panels	00010-76 (Part-II)
6.	CM/L -2141230	1990-08-16	Hindustan Petro Chemicals Khasra No. 218 Village Mithapur Badar Pur New Delhi-110044	Indl. Bitumen Grade 85/25, 90/15 and 115/15 only	00702-61
7.	CM/L -2141331	1990-08-16	Datar Switchgear Pvt. Ltd. F-8, D. Road MIDC Ambad Nasik-422001	Miniature Air break circuits Breakers	06858-78
8.	CM/L -2141432	1990-08-16	Lohar's Cable, & Conductors Pvt. Ltd., 39, Indl. Estate Mamun Malan Guwahati-781021	PVC Insulated Cables sheathed and unsheathed working voltages upto and including 1100 volts	00694-77
9.	CM/L -2141533	1990-08-01	Dharmendra ICE Cream Ltd. 908, GIDC Engg. Estate Sector 28 Gandhinagar-382028	Ice Cream	07802-64
10.	CM/L -2141634	1990-08-16	Rateria Laminators Pvt. Ltd. 493, G.T. Road Shibpur Howrah	Laminated Jute bags for packing Fertilizers 407 G/M SQ	7406-84 (Part-I)
11.	CM/L -2141735	1990-08-16	Koonkan Pesticides Prop. Varun Polymers Organics Ltd. A-4, MIDC Mahad Distt. Raigadh	Endosulphan EC	04323-80

1	2	3	4	5	6
12. CM/L-2141836	1990-08-16	Solar Syndicate Dongri Distt. Valsad-396375	Encosulphan EC		04323—80
13. CM/L-2141937	1990-08-16	Roopam Industries Gala 12, Second Floor Ghanshyam Indl. Estate Veera Desai Road off Varsad Road, Andheri (W) Bombay-400058	Single core PVC insulated unsheathed flexible cables with copper conductors and Aluminium conductors	CO694—77	
14. CM/L-2142030	1990-08-16	National Products Sirsi Village PO Bhandara Road Warthi Distt. Bhandara-441905	Concrete Pipes 150 x 250 MM Size		00458—71
15. CM/L-2142131	1990-08-16	Pam Rock Home Appliances 560/1, MTh Road Ambattur Madras-600098	Steam Irons Ratings 230 V 1000 W		06290—86
16. CM/L-2142232	1990-08-16	Varun Enterprises 17, Parvati Nagar Tonk Road Jaipur	Submersible Pumpsets for Clear, Cold Fresh Water		08034—76
17. CM/L-2142333	1990-08-16	Keshoram Cements Vasant Nagar Distt. Karim Nagar-505187	Ordinary portland cement 43 Grade		08112—76
18. CM/L-2142434	1990-08-16	Sabar conductors Pvt. Ltd. Near Sabar Cables Opp. Sehkari Gin Himmatnagar-383001	Aluminium conductors for overhead Transmission purpose		00398—76 (Part-I)
19. CM/L-2142535	1990-08-16	Shri Nivas Industries 272/1-C, Mettupalayam Road Coimbatore-641043	Monoset pumps for clear, cold, fresh water		09079—79
20. CM/L-2142636	1990-08-16	Aar Bee Enterprises Meerut Road Muzaffarnagar-251003	18 Litre square tins wide mouth		00916—75
21. CM/L-2142737	1990-08-16	Parul Chemicals Pvt. Ltd. A-1/96, GIDC Nandesari Indl. Estate Nandesari Distt. Baroda-381640	Fenvalerate EC		11997—87
22. CM/L-2142838	1990-08-16	Data Cables Pvt. Ltd. Kandara Indl. Area Post Govind Pur Dhanbari	Elastomer Insulated Cables for working voltages upto and including 1100 V		09968—81 (Part-I)
23. CM/L-2142939	1990-08-16	Laxmi Industries Plot No. B-19 MIDC Area Kunal Distt. Sindhudurg	Concrete Pipes		00458—71
24. CM/L-2143032	1990-08-16	Steel Rolling Mills Ltd. Kolshet Road Thane	High Strength Deformed Bars		001786—85
25. CM/L-2143133	1990-08-16	Paushak Ltd. Panclay Tal-Halol Distt. Panchmahal	Isoproturon Technical		12004—87

1	2	3	4	5	6
26. CM/L—2143234	1990-08-16	Raw Rubbers (India) 18/24, Opp. Gali No. 4 Anand Parvat Indl. Area New Rohtak Road New Delhi-110005	Electric Fuses	00366—85	
27. CM/L—2143335	1990-08-16	Allied Bitumen Complex (India) Pvt. Ltd. PO R. Gopal Pur Distt. 24 Parganas	Bitumen Emulsion for Roads (Cationic Type)	08887—87	
28. CM/L—2143436	1990-08-16	Paushak Ltd. Panelay Tal-Halol Distt. Panchmahal	Isoproturon WP	11995—87	
29. CM/L—2143537	1990-08-16	Ganga Lamps & Tubes Pvt. Ltd. R.C. Centre No. 67/3 Kanakapura Road Bangalore-560078	Tubular Fluorescent Lamps for General Lighting Services	02418—77 (Part-I)	
30. CM/L—2143638	1990-08-16	Nuchem Plastic Ltd. 54, Indl. Area Faridabad-121001	Admixture for Concrete	09103—79	
31. CM/L—2143739	1990-08-16	Parekh Cables Pvt. Ltd. A-1/171 GIDC Ankleshwar Distt. Bharuch-393002	ACSR Conductors	00398—76 (Part-II)	
32. CM/L—2143840	1990-08-16	Hemant Electricals Pvt. Ltd. N.H. Road No. 12 Village Kilkipura PO Sheodas Pura-303903	ACSR Conductors	00398—76 (Part-I)	
33. CM/L—2143941	1990-08-16	Archana Industries 286, Sathy Road Gandhi Puram Coimbatore-641012	Motors for Submersible Pumpsets Wet Type Category B Three Phase	09283—79	
34. CM/L—2144034	1990-08-16	Jaipur Metals & Electricals Pvt. Ltd. Near Railway Station Jaipur-302006	Enamelled Round winding wires for Elevated Temperatures Type 1	04800—68 (Part-V)	
35. CM/L—2144135	1990-08-16	Electrical & Allied Mfg. Co. G-8, Sector XI NOIDA Distt. Ghaziabad	ACSR Conductors	00398—76 (Part-II)	
36. CM/L—2144236	1990-08-01	Retoria Laminators (P) Ltd. 493, G.T. Road Shibpur Howrah	Laminated Jute Bags for Packing Fertilizers 380 G/M SQ Tarpaulin Fabrics	07406—86 (Part-II)	
37. CM/L—2144337	1990-08-16	Delton Industries C-429 Sector-X NOIDA (UP)	Domestic Stoves for Use with LPG	04246—84	
38. CM/L—2144438	1990-08-01	Tamilnadu Electricals SP 24, Incl. Estate Ambattur Madras-600058	Power Transformers Rating 150 KVA to 500 KVA	07026—77 (Part-I)	
39. CM/L—2144539	1990-09-01	Sabar Conductors Pvt. Ltd. Opp. Sehkari Gin Shamalaji Road Himmatnagar Distt. Sabarkantha	ACSR Conductors	00398—76 (Part-II)	

1	2	3	4	5	6
40. CM/L—2144640	1990-09-01	Khatau Junker Ltd. Plot No. 3000 GIDC Estate Ankleshwar-393002	Dichlorvos, EC	05277—78	
41. CM/L—2144741	1990-09-01	Balji Enterprises Pvt. Ltd. 48, Indl. Area Jhotwara Jaipur-302012	Cast Billets Ingots	06914—78	
42. CM/L 2144842	1990-09-01	Marco Cables Pvt. Ltd. Plot No. A-55-56 STICE, Sinnar-Sirdi Road Sinnar Distt. Nasik-422103	PVC Insulated Heavy Duty Electric Cables for Working Voltages upto and including 1100 V	01554—76 (Part-I)	
43. CM/L 2144943	1990-09-01	Junagadh Dairy (Unit of M/s Gujrat Dairy Dev. Corpn. Ltd.) Jaffar Maidan Junagadh-362001	Skimmed Milk Powder	01165—86	
44. CM/L 2145036	1990-09-01	Basant Ispat Udyog Pvt. Ltd. 57, Indl. Estate Agra (UP)	Diesel Engines for General Purposes 3.7 KW to 7.36 KW	10081—81	
45. CM/L 2145137	1990-09-01	M.K. Petro Products (P) Ltd. Village Softa Harfoli Teh. Palwal Distt. Faridabad	Indl. Bitumen Grade 85/25, 90/15	00702—88	
46. CM/L 2145238	1990-09-01	Kamla Engineering Works Near Punjab National Bank Ismaila Bad Distt. Kurukshetra	Safety Requirements for Power Threshers 10 HP Rating	09026—79	
47. CM/L—2145339	1990-09-01	Parul Chemical Pvt. Ltd. A-1/96, GIDC Nandesari Indl. Estate Nandesari Distt. Baroda-391340	Endosulphan DP	04322—67	
48. CM/L 2145440	1990-09-01	Electrical & Allied Mfg. Co. G-8, Sector XI Noida (Distt. Ghaziabad)	ACSR Conductors	00398—76 (Part-I)	
49. CM/L—2145541	1990-09-01	Diamond Chemicals 723, Village Mundka Delhi-110041	Paraffin Wax	04654—74	
50. CM/L—2145642	1990-09-01	Sharp Hosiery 81-A/4, Ramalah Colony (New No. 4) Tirupur-638602	Plain Knitted Cotton Vests	04964—80	
51. CM/L—2145743	1990-09-01	Lakshmi Small Cottage Industries 14, N.S. Konark Street Jaihindupuram Madurai-625011	Nonpressure Stoves Multiwick Type	02980—86	
52. CM/L—2145844	1990-09-01	Khatau Junker Ltd. Plot No. 3000 GIDC Estate Ankleshwar-393002	Phosphamidon WSC	06177—81	
53. CM/L 2145945	1990-09-01	Meenambiga Match Industries 82, Ramamoorthy Road Vadamalapuram Via Sivakasi Vadamalapuram	Safety Matches in Boxes	02653—80	
54. CM/L—2146038	1990-09-01	Kumar Engg. Co. Behind Sukhran Nagar Near Azad Dairy Rakhial Ahmedabad-380023	Monoset Pumps for Clear, Cold fresh water for Agricultural purpose	09079—89	

1	2	3	4	5	6
55. CM/L—2146139	1990-09-01	Ajit Cotton Ginning Pressing Dal & Steel Rolling Mills G. T. Road Mandi Govindgarh (Punjab)	High Strength Deformed Steel Bars	01786—85	
56. CM/L—2146240	1990-09-01	U.K. Industries L/46, GIDC Near New Water Tank Odhav Ahmedabad	Monoset Pumps for Clear, Cold Fresh water for Agricultural Purposes	09079—89	
57. CM/L—2146341	1990-09-01	Praveen Trading Corporation C-24, Indl. Area Patna-800013	ACSR Conductors	00378—82 (Part-V)	
58. CM/L—2146442	1990-09-01	Howrah Mills Co. Ltd. 493/C, G T. Road (South) Howrah-711102	Light Weight Bags for Packing Cements	12154—87	
59. CM/L—2146543	1990-09-01	Sri Durga Cables (P) Ltd. 28, Indl. Estate Jagat Pur Distt. Cuttack (Orissa)	PVC Insulated Sheathed Unarmoured Heavy Duty Electric Cables for Working Voltages upto and including 1100 Volts	01554—76 (Part-I)	
60. CM/L—2146644	1990-09-01	Gupta Cables (P) Ltd. Station Road Bhuvaneshwar-751006	AAC Conductors	00398—79 (Part-IV)	
61. CM/L—2146745	1990-09-01	SGN Cable Industries Pvt. Ltd. E-59, Phase VIII Mohali	ACSR Conductors	00398—76 (Part-II)	
62. CM/L—2146846	1990-09-01	Synthetic Asphalts 139, Jawahar Indl. Estate Panvel-410206	Bitumen Emulsion for Roads 'Cationic Type' Medium Setting	08887-78	
63. CM/L—2146947	1990-09-01	Hydro Valve 2991, Tri Nagar Delhi-110035	Domestic Griller for use with LPG	11480—85	
64. CM/L—2147040	1990-09-01	Sri Meenakshi Chemicals 436/2, Vembakottai Road Sithurajapuram Sivakasi-626123	Paraffin Wax Type 3	04654—74	
65. CM/L—2147141	1990-09-01	Chitavalisah Jute Mills Chitavalisah Distt. Visakhapatnam-531162	Jute Synthetic 'Union' Bags for Packing Cement	12174—87	
66. CM/L—2147242	1990-09-01	V.A. Chemical & Sulphar Inds. Plot A/148 MIDC Dombivli Distt. Thane	Sulphar Dusting Powder	06444—79	
67. CM/L—2147343	1990-09-01	Indl. Paints & Varnishes Gram Sejvaya Ghata Billad Distt. Dhar (MP)	Ready Mixed Paints Air Drying Red Oxide Zinc Chrome Priming	02074—79	
68. CM/L—2147444	1990-09-01	Raki Industries 2-113, Pithapuram Road Ramanayyapeta Kakinada-533009	Foot Sprayers with Trigger Type	03652—82	
69. CM/L—2147545	1990-09-01	Raki Industries 2-113, Pithapuram Road Ramanayyapeta Kakinada-533009	Hand Operated Continuous Knapsack Sprayer 16 Litre Capacity Type-A	03906—82 (Part-I)	
70. CM/L—2147646	1990-09-01	Plant Protection Products Pvt. Ltd. Kodavalur Kodavalur Mandalam Distt. Nellore	Thiram WDP	04766—82	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
71. CM/L-2147747	1990-09-01	Thangam Fabricators 1/4-D Animuthu Pillayar Koil Street, Virdhunagar-626001	15 Kg Square Tins for Ghee, Vanaspatti, Oils and Bakery Shortening	10325-89	
72. CM/L-2147848	1990-09-01	East Coast Steel Ltd., Cuddalore Road, Pillayararkuppam Post, Bahour Commune Pondicherry-607402	Continuously cast Billet Ingots (Standard Quality) Grade 1 & 2	06914-78	

[No. CMD/13 : 11]

क्र. घा. 446 :—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियमन, 1988 के विनियम 4 के उपविनियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे स्वीकृत कर दिए गए हैं :

## अनुसूची

क्र. सं	लाइसेंस की संख्या	लागू होने की अवधि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तु/प्रकार और सम्बद्ध भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सीएम/एल-2087250	90-03-01	प्रोसवाल फूड्स लि., 7ए से 13ए, इंडस्ट्रियल एरिया, खलीलाबाद, जिला बस्ती ( उ. प्र. )	वनस्पति IS : 10653-1988
2.	सीएम/एल-2087351	90-03-16	मिनर्वा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, 30,महेन्द्र राय, लेन, गोबरा, कलकत्ता-700048	सोडा-ग्राम बुनाहूय अग्निशामक हेतु रिफिल IS : 05490-1977
3.	सीएम/एल-2087452	90-03-16	सी प्रार आई इंडस्ट्रियल, 12, शारदा देवी स्ट्रीट, रामकृष्ण पुरम, गणपति, कोयम्बतूर-641006	पेच और फ्लेज टाइप फुट वाल्व IS : 10805-1986
4.	सीएम/एल-2087553	90-03-16	मेनन एंड मेनन प्रा. लि., विक्रम नगर, कोल्हापुर, कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	साफ ठंडे, ताजे पानी के लिए अतिज अपकेन्द्री पम्प IS : 06595-1980
5.	सीएम/एल-2087654	90-03-01	शालीमार इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज लि., पर्वी सघपुर, कलाम रोड, बलसाड (गुजरात)	फ्लश टिंग माउंट टाइप स्विच साफेट माउंटलेट 250 वो. 5ए और 15 एम्प IS : 04615-1968
6.	सीएम/एल-2087755	90-03-01	-वही-	फ्लश माउंटिंग गैर शटर वाले साफेट माउंटलेट 250 वो. 5 ए और 15 एम्प IS : 01293-1967
7.	सीएम/एल-2087856	90-03-16	सिरी राम एंड संस, 7531/1, लेल मिल मार्ग, रामनगर, नई दिल्ली-110055	श्रेणी ई रोधन के एक फेजी छोटे एसीमीटर IS : 00996-1979
8.	सीएम/एल-2087957	90-03-01	शालिनी एंटरप्राइजेज, 1-2 डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया, 2 मयूरा रोड करीबाबाद	द्रव्य के साथ प्रयुक्त बरेल कृत्रिम रेंज IS : 4760-1971
9.	सीएम/एल-2088050	90-03-16	एस एंड ए मोटर्स (प्रा.) लि., एफ-21 ओबला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1 नई दिल्ली-110020	श्रेणी ई रोधन के एक फेजी छोटे एसी मीटर (केवल वायु कूलर में प्रयोग हेतु) IS : 00996-1979
10.	सीएम/एल-2088151	90-03-16	भास्ति रबड़ उद्योग, बी-69, सेक्टर 5 नोएडा (जिला गाजियाबाद)-201301	जल के लिए रबड़ की हीज टाइप 2 केबल IS : 00444-1987

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	सीएम/एल-2088252	90-03-18	सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज, खसरा नं. 106/17, ग्राम पूठकला, दिल्ली-110041	इपीए के साथ प्रयुक्त घरेलू बूझा IS : 04246-1984
12	सीएम/एल-2088353	90-03-16	गोल्डन मैन्यूफैक्चरिंग कं., पू-7/2, मिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-110032	1100 बो तक कार्यकारी मोल्टता के लिए पीबीसी रोहित केबल IS : 00894-1977
13	सीएम/एल-2088454	90-03-16	इंटर गैस एप्लाइसेज प्रा. लि., सी-113, सेक्टर 2, मोएडा जिला गाजिबाद- 201391	इपीए के साथ प्रयुक्त घरेलू बूझा IS : 042446-1984
14	सीएम/एल-2088555	90-03-16	लिखा इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स, प्लॉट नं. 1207, ग्राम एंड डा. रिताला, दिल्ली-110034	इपीए के साथ प्रयुक्त घरेलू बूझा IS : 04246-1984
15	सीएम/एल-2088656	90-03-16	वेद पेपर सिस्टमस, सी-221, सेक्टर 10, मोएडा-201301	टेलीप्रिटर के लिए कागज के पेज रोल IS : 09031-1979
16	सीएम/एल-2088757	90-03-18	एल.पी. मुकुण्ठन एंड सन, 115-के, बी. के. रोड, पेलाभेडु, कोयम्बतूर-641004	पीबीसी वेल्डन तार टाइप सी रोशन IS : 08783-1978
17	सीएम/एल-2088858	90-03-16	परफेक्ट इंजीनियरिंग कं., 136, पाइनियर मिल्स, पेलाभेडु, कोयम्बतूर-641004	खेपी बी रोशन के फेजी मोटर IS : 00996-1979
18	सीएम/एल-2088959	90-03-16	इनलप इंडिया लि, धम्बातूर फेक्टरी, धम्बातूर, मद्रास-600053	हल्के व्यापारिक वाहन, बस, ट्रक और ट्रैक्टर के टायर IS : 10914-1988
19	सीएम/एल-2089052	90-03-16	दि आईआईसी पम्प लि., राजामंगलम, विलीवकम, मद्रास-600049	साफ डबे, ताजे पानी के लिए नियन्त्रण पम्प सेट IS : 08034-1989
20	सीएम/एल-2089153	90-03-16	प्रशांत सिलिडर्स (प्रा.) लि., 35-बी, बीर संघारा इंडस्ट्रियल एरिया, हिस्सागोडी, डा., 19वां किमी, होसुर रोड, बंगलूर-562158	अमोनिया (निर्जल) हेतु बेसिडत ग्रुप कार्बन इस्पात गैस सिलिंडर IS : 07680-1985
21	सीएम/एल-2089254	90-03-16	भारत पेट्रोसाइड्स मैन्युफैक्चरिंग कं., ई-17 बीएसआईसी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, मांगलोर, दिल्ली	मिक्नालफॉस IS : 08028-1987
22	सीएम/एल-2089355	90-03-16	सुतार कैमिकल्स (प्रा.) लि., रानीताल, जिला बालासोड-756111	बीएससी डीपी IS : 00561-1978
23	सीएम/एल-2089456	90-03-16	प्रिंसीजम ब्लकिंग (इं.) लि., दिषा घाट, परना-800011	एक फेजी 240 बो वाट घंटा मीटर IS : 00722-1977
24	सीएम/एल-2089557	90-03-16	जैनस मिनरल्स, 27-ए, इंडस्ट्रियल एरिया, फतेहाबाद (हरियाणा)-125050	एलिट्रन ईसी IS : 01307-1982
25	सीएम/एल-2089658	90-03-08	जैन स मिनरल्स 27-ए, इंडस्ट्रियल एरिया, फतेहाबाद (हरियाणा)--125050	शुद्धामिथोट ईसी IS : 03903-1978
26	सीएम/एल-2089759	90-03-16	बिराग कैमिकल इंडस्ट्रीज, सी-1/193, फेज 2, जीआईडीसी बाल्वा, अहमदाबाद-382445	पैराफिन मोम, टाइप 3 IS:-04654-1974

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27. सीएम/एल-2089860	90-03-16	कैमोकार्बो इंडस्ट्रीज, पुराना बम्बई पुना रोड, खैर गांव, डा. कांभवा जिला ठाणे-400605	कैल्शियम प्रोपियोनेट, खाद्य ग्रेड IS:-06031-1971	
28. सीएम/एल-2089961	90-03-16	आविश्य प्रलॉयज लि , डा. नेलगावेंची, कटक-753015	सरबता इस्पात (मानक गुणता) में बेरलन हेतु डलबा इंगट पड 2 केवल IS:-06914-1978	
29. सीएम/एल-2090037	90-03-16	प्रीमियर सैन्स, 45/22, गुम्बना इंडस्ट्रियल एस्टेट, 6ठा ब्लॉक राजाजी नगर, बंगलौर-560010	जीएसएस बलब 60 वा 250 बो IS:-00418-1978	
30. सीएम/एल- 090138	90-03-16	प्रिंसीजन इलेक्ट्रीकल्स, - 134-135, एनप्रार मनीष इंडस्ट्रियल एस्टेट नवधर बसाई (पू) जिला ठाणे	गेर शटर वाले सॉकेट फाउटलेट शटर लगे सॉकेट फाउटलेट तीन पिन प्लग बीएससी भुरकभ वर्ण IS:-1293-1978	
31. सीएम/एल-2090239	90-03-16	शीतला एप्रो इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि., ए-1, कैमीकल कॉम्प्लेक्स, बाराबंकी (उ.प्र.)	बीएससी भुरकभ वर्ण IS:-00561-1978	
32. सीएम/एल-2090340	90-03-16	साहूनी रबर्स, 81, तलांगपुर फोटवा, नई दिल्ली- 110043	द्रवों हेतु रबड़ की नम्य नली तांकितिक व्यास 6 4 मिमी IS:-10908-1984	
33. सीएम/एल-2090441	90-03-16	जेतावत बायर रोस, प्रा.लि., 403, उला इंडस्ट्रियल एरिया, गयपुर (म.प्र.) 493221	जहाजरानी प्रयोजनों के लिए जस्तीकृत इस्पात की गोथ कड़ी वाली तार रस्सी IS:-02581-1977	
34. सीएम/एल-2090542	90-03-16	गुरुकृपा इंजीनियर्स, सी-3/23, एनप्रार जीआईडीसी कार्वालय जीआईडीसी एस्टेट, मावि- याव-387001	निमज्ज्य पम्पसेट IS:-08034-1989	
35. सीएम/एल-2090643	90-03-16	मार्कफीड एप्रो कैमीकल्स, 7 और 8 बी, इंडस्ट्रियल एस्टेट, एसएएस नगर, मोहाली-160051	ग्राहसोप्रोट्युरान IS:-11995-1987	
36. सीएम/एल-2090744	90-03-16	मैटल बर्न, 70 ए, नारकेलडागा, मैन रोड, कलकत्ता-700054	द्रवों के साथ प्रयुक्त घरेलू बूल्हे। IS:-04246-1984	
37. सीएम/एल-2090845	90-03-16	सूरज इंडस्ट्रीज, मानसा रोड, भटिडा	खवण से ग्लेज किए पाइप, ग्रेड ए IS:-00651-1980	
38. सीएम/एल-2090046	90-03-16	हीटराइट इलेक्ट्रिकल्स प्रा.लि., गठ नं. 907/2 पुने-नागर रोड, ग्राम समोसुण्डी तालुकाशीरूर, जिला पुणे	घबल संभारण टाइप पानी गर्म करने के बिजली के हीटर 15 लिटर धारिता IS:-02082-1985	
39. सीएम/एल-20901039	90-03-16	सोल-रे एप्लाइड प्रा.लि., 29/2 खरडी गांव, जिला-पुणे	घबल, संभारण टाइप पानी गर्म करने के बिजली के हीटर 25 लिटर धारिता IS:-02082-1985	
40. सीएम/एल-2091140	90-03-16	सनफनींग प्रायरेन एंड स्टील कं लि , डा. बंढारा रोड, जिला संभारा-441905	कार्बन इस्पात सरिण IS:-01875-1978	
41. सीएम/एल-2091241	90-03-16	यूनिवर्सल वायर्स एंड इंडस्ट्रीज, डी-3, इंडस्ट्रियल एरिया, पटना-800013	गिरोपरि प्रेषण हेतु एफ्युमीनियम मिश्रधातु के खालक IS:-00398-1979	
42. सीएम/एल-2091342	90-03-16	परफेक्ट कंटेनर्स, क. सं. 4/1, मिग पुरा, मिरा रोड, मुमकुर-572106	वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किघ्रा के बोकोर कनस्तर IS:-10325-1989	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43. सीएम/एल-2091443	90-03-16	बी बरल इंडस्ट्रीज, बी निवास पुरम, कोयम्बतूर में रोड, घरनाली-638654	तीन फेजी नियन्त्रण मोटर IS-09283-1979	
44. सीएम/एल-2091544	90-03-16	हाइटैक, 59, धाडागम रोड, वलेंडकीपसायम, कोयम्बतूर-25	तीन फेजी नियन्त्रण पम्पसेट IS-09283-1979	
45. सीएम/एल-2091645	90-03-16	मोरबी बेजीटेबल प्रोडक्ट्स लि., बेजीटेबल रोड, मोरबी	वनस्पति घोर खाद्य तेलों हेतु 15 किग्र के चौकोर कमस्तर IS-10325-1989	
46. सीएम/एल-2091746	90-03-16	दीपक इंडस्ट्रीज, बी-150, सेक्टर 6, नौएडा 20131	इस्पात के टक्करदार कब्जे IS-01341-1981	
47. सीएम/एल-2091847	90-03-16	गर्ग जश्नेत, खसस न 152, ग्राम रँडाला, दिल्ली	प्रणोदक टाइप एसी, सवारी के श्रेणी ई रोखन IS-02312-1967	
48. सीएम/एल-2091948	90-03-16	परमोंकिंग, ए-24, नारायण इंडस्ट्रियल एरिया, फेज I, नई दिल्ली-110028	गर्म हवा वाले पंखे श्रेणी ई रोखन IS 04283-1983	
49. सीएम/एल-2092041	90-03-16	ठुकराल मेकेमिकल वर्क्स, वशमेश नगर, सरहिन्द (पंजाब)	ताजे ठंडे साफ पानी के लिए क्षैतिज अपकेन्द्री पम्प IS 06595-1980	
50. सीएम/एल-2092142	90-03-16	घग्गा कन्टेनर्स प्रा. लि., प्लॉट नं. 98, एलपीएसआईबीसी इंडस्ट्रियल एरिया, बड्डी, तहसील नालगढ़, जिला सोलम (हि. प्र.)	वनस्पति के लिए एक्सीपीई घाघान (केवल 5 किगो के लिए) IS : 10840-1986	
51. सीएम/एल-2092243	90-03-16	एस. बी. इंजीनियरिंग वर्क्स, न्यू कालोनी, घमन नगर, टांडा रोड, जालंधर शहर	ताजे, ठंडे, साफ पानी के लिए क्षैतिज अपकेन्द्री IS : 06595-1980	
52. सीएम/एल-2092344	90-03-16	यूनाइटेड केबल इंडस्ट्रीज, ए-14, सेक्टर 4, नौएडा-201303	1100 घंटा तक कार्यकारी चालकता के लिए इले- स्टोमर रोधित केबल IS: 09968-1981	
53. सीएम/एल-2092445	90-03-16	उद्योगी माउलर्स (प्रा) लि., बुनी भाटी, डा. पोखरा, जिला हावड़ा	स्कूटर और मोटर साइकिल सवारी के लिए सुरक्षा हैलमेट IS : 04151-1982	
54. सीएम/एल-2092546	90-03-16	पंजाब आनन्द बैटरीज, ए-9 एंड 10, इंडस्ट्रियल एस्टेट, एस एस नगर, मोहाली-160055	बहुदेशीय गैल्व बैटरियां IS : 08144-1976	
55. सीएम/एल-2092647	90-03-16	दि इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लि., इन्द्रा नगर, जमशेदपुर-831008	पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट हेतु बालेदार तार IS : 06003-1983	
56. सीएम/एल-2092748	90-03-16	मिनर्वा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स, 30, महेन्द्र राय लेन, गोबरा, कलकत्ता-700046	झाय टाइप के सुबाह्य अग्निशामक यंत्र के रिफिल IS : 05490-1977	
57. सीएम/एल-2092849	90-03-16	दि इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लि., इन्द्रा नगर, जमशेदपुर-831008	पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट हेतु सादा कठोर कंक्रीट इस्पात IS 01785-1983	
58. सीएम/एल-2092950	90-04-01	एंगल इंडस्ट्रीज, पुरन्दरपुर, डा. बर्नीपुर, जिला 24 परगना (प. बं.)	एंगस्टन नुतु वाले सामान्य सेवा बल्ब IS: 00418-1978	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59	सीएम/एल-2093043	90-04-01	प्राल्मिज फाईबर ग्लास एंड प्लास्टिक्स लि, प्लाट नं. 455, एमआईसीसी रोड, बंसोली (टीटीसी), गण-400701	दोबीसी पाइप, श्रेणी 2 IS 04985-1981
60	सीएम/एल-2093144	90-04-01	एलोरा घाट इंडस्ट्रीज 108-बी पार्वती डब्ल्यू एस्टेट, पहला तल, सम मिल कपाउंड लोअर पारेल, बम्बई-400013	मनहू एवं फलन टाइप गैर शटर वाले, लोम पिन सॉकेट ब्राउटलैट, 5 ए और 15ए IS 01293-1988
61	सीएम/एल-2093245	90-04-01	सी.जे. इंडस्ट्रीज, बी-3, आनन्दी इंडस्ट्रियल एरिया, बीपी काम रोड भायन्दर (पू)-401105	फलन टाइप गैर शटर टाइप सॉकेट ब्राउटलैट 250 बी 5 एम्प IS 01293-1988
62	सीएम/एल-2093346	90-04-01	—वही—	प्रेरण परिपथ हेतु स्विचों को छोड़ कर फलन टाइप स्विच IS 03854-1966
63	सीएम/एल-2093447	90-04-01	अर्जुन एंटरप्राइजेज, बसरा नं. 76, ग्राम रामहोला डा नांगलोई, नई दिल्ली-110041	1100 बी तक कार्यकारी बोस्टन हेतु दोबीसी रोडिंग खोलवार/खोलरहित केबल IS 00694-1977
64	सीएम/एल-2093548	90-04-01	पावर फैन इंडस्ट्रीज, 187, ब्रह्म समाज रोड, कलकत्ता-700060	प्रणोदक टाइप एसी सवाती पंखे IS : 02312-1967
65	सीएम/एल-2093649	90-04-01	एक्सप्रेस केबल प्रा लि, निओरा पो, बानापुर जिला पटना	गिरोपरि प्रेषण के लिए एल्यूमीनियम के लड़खार चालक IS 00398-1976
66	सीएम/एल-2093750	90-04-01	खटाऊ जूकर लि प्लाट नं. 3000, जीआईसीसी एस्टेट पो बा न 40, अकलेश्वर	मोनोफोटोफॉर्म एस एस IS 08074-1983
67	सीएम/एल-2093851	90-04-01	श्यामला पाइप एंड फिटिंग्स सी-9 एंड सी10, अगलोर रोड बरेली-583101	दोबीसी पाइप श्रेणी 2 IS 04985-1981
68	सीएम/एल-2093952	90-04-01	गोरी लेम्प वर्क्स 12 एस एम रॉय रोड, कलकत्ता-700039	टंगस्टन नंगु सामान्य प्रयोजन हेतु बल्ब IS 00418-1978
69	सीएम/एल-2094045	90-04-01	खटाऊ जूकर लि प्लाट नं. 3000, जीआईसीसी एस्टेट, पो बा न 40 अकलेश्वर	डाइमिपोएट ईसी IS 03903-1984
70	सीएम/एल-2094146	90-04-01	मार्बल स्विच मैथिल क शेड नं. 15 और 16 इंडस्ट्रियल एस्टेट कटन-753010	मनहू माउंटिंग टाइप शटर टाइप सॉकेट ब्राउटलैट IS 01293-1987
71	सीएम/एल-2094247	90-04-01	कण्ठा कैमिकल इंडस्ट्रीज लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेट वरारी भागलपुर-812003	मैथाथियस डीपा IS : 02569-1978
72	सीएम/एल-2094248	90-04-01	दि टाटा आयर्न एंड स्टील कं लि, विशा डा. दिवाघाट पटना-800011	सॉकेट प्रबलन के लिए पंचगुंठी सरिण और तार IS 01786-1985
73	सीएम/एल-2094449	90-04-01	रेखा स्टील इंडस्ट्रीज इनकाम्पकम ग्राम मन्नाम 600041	मरचना इस्पात (मानक गणना) IS 00226-1975
74	सीएम/एल-2094550	90-04-01	यू एम/ए एम 370, मार्कोट रोड, कोडाम्बकम, मन्नार-600024	अच्छा प्रकार टाइप पानी गर्म करने के लीटर IS 02082-1985

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
75. सीएम/एल-2094651	90-04-01	इंडिया मीटर्स लि., प्लॉट नं. 14, ईड. एस्टेट, एम्बादूर, महाराष्ट्र-600058	लीन केजी चार तार बाट, बंदा मीटर IS: 00722-1977	
76. सीएम/एल-2094752	90-04-01	ल्यूमिनोस लैम्प्स लि., क्रम सं. 207, बोनथापल्ली ग्राम चारसापुर तालुका जिला मेडक	टंगस्टन तटु सामान्य सेवा बल्ब IS: 00418-1978	
77. सीएम/एल-2094853	90-04-01	स्वास्तिक लेबोरेट्रीज, 28-26-3, कुरमियाह स्ट्रीट विजया टाकीज के पास विजयवाड़ा-520002	रोगाणुनाशक द्रव श्रेणी ए ग्रैंड 1, 1ए, 2, 2ए, 3 और 3 ए टाइप सामान्य IS: 01061-1982	
78. सीएम/एल-2094954	90-04-01	नेशनल आर्गेनिक कैमीकल्स इंडस्ट्रीज, लि., प्लॉट नं. ए-1, लोट परशराम इंडस्ट्रियल एरिया तालुका खेड, जिला रत्नगिरि-415722	डाइक्लोरोबाल ई सी IS: 05277-1978	
79. सीएम/एल-2095047	90-04-01	आनंदजी केबल्स, प्लॉट नं. 124, पहला तल, मेराल, को-आप इंड एस्टेट, मथुरादास वासनजी रोड, साकीनाका, अंधेरी (पू.) बम्बई-400059	1100 बी तक कार्यकारी वोल्टता के लिए पी. वी.सी. रोहित (हैवी ड्यूटी) बिजली की केबल IS: 01554-1976	
80. सीएम/एल-2095148	90-04-01	हार्ड स्पीड एप्लाइन्सेज (प्रा. लि., 907/2, पुणे-नागर रोड, ससावाडी तहसील सिरूर, जिला पुणे	घबल, घंडारण टाइप पानी गर्म करने के बिजली के हीटर IS: 02082-1985	
81. सीएम/एल-2095249	90-04-01	गयत इलेक्ट्रोकेल्स, जे 99-98, विष्णू गार्डन, नई दिल्ली-110018	पानी गरम करने की बिजली के निमज्ज्य हीटर एक किंवा और दो किंवा रेटिंग IS: 00368-1983	
82. सीएम/एल-2095350	90-04-01	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि., दिल्ली सीमेंट ग्राइन्डिंग यूनिट, मोखला इंड. एरिया, फेज 1, नई दिल्ली-110020	साधारण पोर्टलैंड सीमेंट IS: 00269-1976	
83. सीएम/एल-2095451	90-04-01	गोल्ड स्टार कडकटर्स, चौराहटा, रीवा-486001	जीस्तीकृत इस्पात प्रबलन हेतु एल्युमिनियम के बालक IS: 00398-1976	
84. सी.एम/एल-2095552	90-04-01	जीप इंडस्ट्रियल सिंक्रिटेड लि., 28, साउथ रोड, इमाहाबाद	प्लास्टिक के शीर्ष सहित पूर्ण कोकस किए एल्युमिनियम का रोगम किए फलैश लाइट IS: 02083-1978	
85. सीएम/एल-2095653	90-04-01	लुधियाना स्टोल रोलिंग मिल्स, जी टी रोड, मिलर गज, लुधियाना (पंजाब)	बंकीट प्रबलन के लिए एल एस डी सरिंग और तार IS: 01786-1985	
86. सीएम/एल-2095754	90-04-01	आय इंडिया मेकिकल कारपोरेशन, सिपोली रोड, कस्तूर पार्क के पास, बोरिवली (पू.) बम्बई-400097	साइपरसेप्टीव ईसी IS: 12016-1987	
87. सीएम/एल-2095855	90-04-01	मोपाल पैस्टीसाइट्स, प्लॉट नं. 10, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोबिंदपुरा, मोपाल -462023	कार्बोनाइज्ड, भुरकम गुण IS: 07122-1984	
88. सीएम/एल-2095956	90-04-01	भारत ओरेस्टिक एप्लाइन्सेज, एफ-44, सेक्टर 4, नोएडा, जिला गाजियाबाद	प्रदीप के साथ चरेकू गैस बल्ब IS: 04246-1984	
89. सीएम/एल-2096049	90-04-01	एस टी पी लि., 26, लोक रोड, भादूप, बम्बई-400078	बिटुमेन पायस (एनायनीय टाइप) IS: 03117-1985	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
90. सीएम/एल-2096150	90-04-01	रामा इंडस्ट्रीज, 148, ईस्ट कोस्ट रोड, इजम्बलम, मद्रास-600041	प्रयोग के साथ घरेलू गैस बूल्हा IS: 04246-1984	
91. सीएम/एल-2096251	90-04-01	स्टील थोरोरिटी प्राफ इंडिया लि., भिलाई इस्पात संयंत्र रिसर्च एंड कंट्रोल प्रयोग- शाला भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई-490001	फर्निचिंग और प्रेसिंग के लिए तप्त बेल्सित इस्पात की प्लेट और बर्द IS: 03747-1982	
92. सीएम/एल-2096352	90-04-01	ईस्टर्न इजोनियरिंग कारपोरेशन, 16 पद्मा बोध गार्डन लेन, विलुभाह, हावड़ा-711204	एस्वेस्टास सीमेंट बाइ पाइप सहित सी भाई विलगनीय जोड़ साइज 200 मिमी ध्यास IS: 08794-1978	
93. सीएम/एल-2096453	90-04-01	हेमराजानी ट्यूब्स (प्रा) लि., कोडामुगुड गांव, बीबी नगर मंडल, जिला नालगोंडा	संरचना प्रयोजनों के लिए इस्पात के पाइप प्रेड बार्ड एस टी, श्रेणी हल्की, मध्यम और भारी साइज, 65 मिमी से 180 मिमी तक IS: 01161-1979	
94. सीएम/एल-2096554	90-04-01	जमक होल्डिंग्स लि., 8/7 एम टी एच रोड, अम्नाटूर, मद्रास-600098	संरचना इस्पात (मानक किस्म) IS: 00226-1975	
95. सीएम/एल-2096655	90-04-01	हेमराजानी ट्यूब्स प्रा. लि., कोडामुगुड गांव, बीबी नगर मंडल, जिला नालगोंडा	इस्पात पाइप, ई.धार. डब्ल्यू, श्रेणी हल्की, मध्यम, भारी, साइज 65 से 180 मिमी एम. बी काले साइ सिरे IS: 01230-1979	
96. सीएम/एल-2096756	90-04-01	वेस्ट इजोनियर्स, 59. बी, बाडागम रोड वेनेसीपलायम, कोयम्बतूर	निमज्ज्य पम्प के लिए 3 फेजी, 415 50 हर्ट्ज 3.7 रेडिंग बेट टाइप संयंत्र बी IS: 09283-1979	
97. सीएम/एल-2096857	90-04-01	वेगा इजोनियर्स, 11/बी-1 जगन्नाथ एस्टेट, गुजरात काटालिंग कं के पास, रक्षियाल अहमदाबाद-380023	मोनोसेट पम्पसेट IS: 09079-1989	
98. सीएम/एल-2096958	90-04-01	सेवी केबल इंडस्ट्रीज, 627/4/69 शंकर गली विजवास नगर, शाहपुरा, दिल्ली-110032	1100 बी तक कार्यकारी बोस्टला के लिए तांबा एल्यूमीनियम तालकों सहित खोलदार और खोल रहित पी पी सी रोहित केबल IS: 00694-1977	
99. सीएम/एल-2097051	90-04-01	बिड्ज इलेक्ट्रीकल्स (प्रा.) लि., 29, कलकागंज रोड, दिल्ली-110007	गर्म हवा के पंप, 2000 बी, 230 बी, 50 हर्ट्ज ऐसी श्रेणी ई रोघम सहित IS: 04283-1981	
100. सीएम/एल-2097152	90-03-16	ज्योति एवम् उद्योग (इंडिया) प्रा. लि ए-108 सेक्टर 5 नोएडा, जिला गाजियाबाद	विद्युत प्रयोजनों के लिए एवम् की अट्टाहवा IS: 05424-1969	
101. सीएम/एल-2097253	90-04-01	पूजा केबल्स प्रा. लि., 1-ए सेक्टर डब्ल्यूबी इंडस्ट्रियल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल-462023	1100 बी बी तक कार्यकारी बोस्टला के लिए अक्षयचित और कक्षित पी पी सी रोहित (ईवी इयूटी) केबल IS: 1554-1976	
102. सीएम/एल-2097354	90-04-01	पंजाब पेस्ट्रीसाइड्स इंडस्ट्रियल कॉ-ऑप. सोसाइटी लि. चंडीगढ़ रोपड़ मार्ग, खानपुर तहसील, अरुण, जिला रोपड़	डाइमिनीएट 30% ई. सी. फार्मूलेशन IS: 03903-1984	
103. सीएम/एल-2097455	90-04-01	—गहरी—	एंडोसल्फान 35% ईसी फार्मूलेशन IS: 04323-1980	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
104. सीएम/एल-2097558	90-04-01	साहनी पेन्स, सी-13, फोकल प्वाइंट जालंधर-140044	शुष्क डिस्टेंपर, हल्की रंग रेंज IS: 00427-1965	
105. सी.एम/एल-2097657	90-04-01	जगत स्टील्स प्रा. लि., पुराना सिनेमा रोड, अमरा 141401	संरचना इस्पात में बेल्सन हेतु (मानक किस्म) इसे बिले म इगट ग्रेड IS: 06914-1978	
106. सीएम/एल-2097758	90-04-01	साहनी पेन्स, सी-13, फोकल प्वाइंट, जालंधर-140004	डिस्टेंपर, तेज इमल्शन मध्यम रंग रेंज, केवल IS: 00428-1969	
107. सीएम/एल-2097859	90-04-01	बीकानेर इंजीनियरिंग (फाउंड्री) वर्क्स, एफ-444, बी. के. आई. एरिया, रोड न. 12, जयपुर-302013	एसी दाब पाइप के साथ प्रयुक्त बिलगनीय जोड़ साइज 160 मिमी तक श्रेणी 10 केवल IS: 08794-1978	
108. सीएम/एल-2097960	90-04-01	अनोक कंकटर्स माई गुर टी ए-व्याश जिला सुरत	एसी एम ग्रार चालक IS: 00398-1976	
109. सी.एम/एल-2098053	90 04 01	—वही—	ए एसी चालक IS: 00398-1976	
110. सीएम/एल-2098154	90-04-01	सोलेंसो कैमीकल्स प्रा. लि., प्लॉट नं. ई-56 एम आई डी सी एरिया, चन्द्रपुर(म.रा.)	घिरजक चूणं स्वायत्तक ग्रेड 2 IS: 01065/-1971	
111. सी.एम/एल-2098255	90-04-01	मिरोही एस्टर प्राइजेंज, सी-43/2, अधिमन्डू एनी मोहम पुरी, मौज पुर, दिल्ली-110053	अपेरी के साथ प्रयुक्त चरैलू चूल्हा IS: 04246-1984	
112. सीएम/एल-2098356	90-04-01	के टी फाउन्ड्री, बी-139, फेज I मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली	अपेरी के साथ प्रयुक्त चरैलू चूल्हा स्टेनलेस इस्पात आकार, पुहरा बर्नर IS: 04246-1984	
113. सीएम/एल-2098457	90-04-01	भारव सीमेंट इंडस्ट्रीज प्रा. लि., ई-12, अम्बाजी इंडस्ट्रियल एरिया, आर्ष रोड-307036	साधारण पोर्टलैंड सीमेंट IS: 00269-1976	
114. सीएम/एल-2098558	90-04-01	शिवालिक फर्टिलाइजर्स एंड कैमीकल्स पुरारानी रोड अमपुर, जिला नैनीताल	इसि ग्रेड जिस सफेद IS: 08249-1976	
115. सीएम/एल-2098659	90-04-01	रौकी निटर्स, 216 पी.एन. रोड, निरपुर-638602	सादी बुनी बिनियान ग्रार.एम. और ग्रार एन एस ग्रेड 24 जो साइज 75 और 110 सेमी IS: 04964-1980	
116. सीएम/एल-2098760	90-04-01	प्लाट प्रोटेक्शन एफ-6, इंड! एस्टेट, अमरावती रोड, गुडर-522034	कैपल बंध धानेदार कोरेट 10% IS: 09359-1980	
117. सीएम/एल-2098861	90-04-01	मॉडर्न रोजिन एंड टरपेन्टाइन फैक्ट्री, डॉ. मीरान साहिब, जम्मू तबी 181101	गम रोजिन ग्रेड एम केवल IS: 00553-1984	
118. सीएम/एल-2098962	90-04-01	बैकफील्ड, 234, एम! एस. सी! बांस रोड, नाकताला, कलकत्ता-700047	राइजोबियम निबेरी ब्रव, मोभिथा, हुरा चना कासा चना, मटर और सोयाबीन के लिए IS: 08268-1986	
119. सीएम/एल-2099055	90-04-01	सुलसी डोमेस्टिक एक्वाइलेज, 30-ए, पुराना इंड! एरिया, अमर (राजस्थान)	इपरी के साथ प्रयुक्त चरैलू गैस चूल्हा IS: 11480-1985	
120. सीएम/एल-209156	90-04-01	इंडस्ट्रियल रबड़ प्रॉडक्ट्स, ए-21/22, इंड. एस्टेट, गुण्डी, मद्रास-600032	अपेरी के लिए रबड़ की मध्य मसो साइज 6.4 मिमी. केवल IS: 10908-1984	
121. सीएम/एल-2099257	90-04-01	गंगाधरम एक्वाइलेज लि., 143, पुर्बुपकम गांव, कालाम्पकम वडाळ रोड, जिला चिगलपुट	चरैलू ग्रेडर चुकर IS: 02347-1987	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
122. सीएम/एल-2099358	90-04-01	बैकटेश्वर एप्रो कैमोकल्स एंड मिनरल्स लि., 37-एफ, बेलाचेरी मेन रोड, बेलाचेरी, मद्रास-600042	क्लोरीमीक्रेट क्लोराइड एकव्यस 50% जलीय विलयन पुनः पैकिंग के लिए IS : 08962-1978	
123. सीएम/एल-2099459	90-04-01	ट्राइलो एप्रो इंडस्ट्रीज प्रा. लि., ग्राम एवं डा. भरमरी, जिला पटियाला, (पंजाब)	बीएचसी गामा ग्राइसोमर 1 3% मिमी. फार्मु- लेशन IS : 00561-1978	
124. सीएम/एल-2099560	90-04-01	एम.बी. कमर्शियल सिंडीकेट्स, 64, गौस गंज, लखनऊ-226018	हस्त चालित नेपसैक छिड़कीय यंत्र, इस्टेट टाइप, 16 लीटर धारिता वाले पीतल/प्लास्टिक की टंकी सहित IS : 03906-1982	
125. सीएम/एल-2099861	90-04-01	ट्राइलो एप्रो इंडस्ट्रीज प्रा. लि., ग्राम एवं डा. भरमरी, जिला पटियाला (पंजाब)	मैथायियान 25% डब्ल्यू डीपी फार्मुलेशन IS : 02569-1978	
126. सीएम/एल-2099762	90-04-01	वीना एन्टरप्राइजेज, प्लॉट नं. 71, फेज 3, घाटोतक, त्रिजयवाड़ा-520007	प्रेमर कुकर के लिए गैसकेट IS : 07466-1974	
127. सीएम/एल-2099864	90-04-01	नरेश रबड़ कं., 86, आईडोसी महारौली रोड, गुडगांव (हरियाणा)	लेटेक्स फोम रबड़, उत्पाद, ग्रेड एसी ग्रीर ई केवल IS : 01741-1960	
128. सीएम/एल-2099984	90-04-01	दक्कन एन्टरप्राइजेज (प्रा.) लि., बी/58, 59 और 60 एपी बालानगर, बल्लम नगर, ताल्लूक, जिला रंगारेड्डी (आ. प्र.)	गैसमेन, जलमेन और मयजल के लिए रबड़ की सीलिंग रिग, टाइप 3, प्राकृतिक रबड़ केवल IS : 05382-1985	
129. सीएम/एल-2100014	90-04-01	श्रीमशक्ति एन्टरप्राइजेज, 151/44, दूसरा चौराहा, मेन 8, बसंत नगर, (प.) बंगलौर-560052	श्रीयोगिक प्रयोजनों के लिए संश्लिष्ट डिटर्जेंट टाइप 3 केवल IS : 4956-1977	
130. सीएम/एल-2100115	90-04-01	बरोनी प्राइवेट प्रा. लि., 41-बी ई इंडस्ट्रियल एरिया, बरोनी, डा., तिलरप, बेगूसराय-851112	वैराफिन मोम, टाइप 3 IS : 04654-1974	
131. सीएम/एल-2100216	90-04-01	वि प्लांटेशन कारपोरेशन ऑफ केरल लि., बेट्टीलापई एस्टेट, कलाडी प्लांटेशन, (डा.) भलवाय, एर्नाकुलम जिला	श्रीमोनिया परिवर्धित प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स IS : 05430-1981	
132. सीएम/एल-2100317	90-04-01	संगमेशिया कं. प्रा. लि., 5, ग्रहमव सामूजी स्ट्रीट, लिथुग्राह, हावड़ा	संरचना इस्पात (मानक किस्म) IS : 00226-1975	
133. सीएम/एल-2100418	90-04-01	बंगलौर वायर रॉड मिल, मूहट फील्ड रोड, महादेव पुरा पोस्ट, बंगलौर-560048	कार्बन इस्पात तार छड़ ग्रेड एक्स, आई. एफ, जी ग्रीर एच IS : 07974-1974	
134. सीएम/एल-2100519	90-04-01	भोपाल पेस्टीसाइड्स, प्लॉट नं. 10, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोविन्दपुरा, भोपाल (एम पी)	कार्बोराइल 50% डब्ल्यू डीपी फार्मुलेशन धूमि छिड़काव ग्रेड केवल IS : 07121-1973	
135. सीएम/एल-2100620	90-04-01	पंजाब पेस्टीसाइड्स इंड. को-ऑप. सोसाइटी लि., खानपुर, खरोर जिला रोपड़ (पंजाब)	एल्लुन 30% ईसी फार्मुलेशन IS : 01307-1982	
136. सीएम/एल-2100721	90-04-01	सत्तार संस पैकेजिंग कारपोरेशन, 1-7-69, सरोजिनी बेदी रोड, सिर्कबराबाद-500003	व्यापारिक उच्च विस्फोटो के लिए नालीदार रेशा बोर्ड बोक्स IS : 10212-1986	
137. सीएम/एल-2100822	90-04-01	कुमार इंडस्ट्रीज (मेन स्विच डिवीजन), खसरा नं. 33/9 और 33/12 बबाना रोड, धमयपुर (शाहजवाब गांव के पास), दिल्ली-110042	वायु वियोज्य स्विच और पुनः तार लगाने वाले प्यूज की संयुक्त इकाइयां IS : 10027-1981	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
138. सीएम/एल-2100923	90-04-18	हुधा बावर्स, स्ट्रीट नं. 12, वसुभेन नगर गिल रोड, मुधियाना		230 बो. 750 बा, तापस्यायी बिजली की इस्तरि, डलवा इस्पात आधार प्लेट सहित— IS : 00336-1985
139. सी एम/एल-2101016	90-04-16	अशोक रबड़ मशीन्स, बस्ती रोड, सरहिन्द (पंजाब)		ब्रव चालम से नियंत्रित और बलोजर यूनीवर्सल टाइप साइज परमाणु 2— IS : 03564-1986
140. सी एम/एल-2101117	90-04-18	हिन्द मैटल, मस्जिद वाली जली, कैंज पुरा रोड, बटाला (पंजाब)		रिफ्लेक्स बाल्ब दोनों सिरी पर फ्लैज वाले साइज 80 मि.मी. से 100 मि. मी.— IS : 10805-1986
141. सी एम/एल-2101218	90-04-16	नार्थ वेस्ट स्विचगियर लि., 14/ 3, मथुरा रोड, फरीदाबाद-121003		थरेलु और ऐसे ही प्रयोजनों के लिए ऐसी प्रेरण परिपथ 250 बो., ए सी फ्लश माउन्टिंग स्विच— IS : 03854-1986
142. सी एम/एल-2101319	90-04-18	कौशल इंडस्ट्रीज, 12/65, मागला बालचंद मुल्हाई, आगरा-282005		छुट बाल्ब, साइज 80 मिमी, केबल पेंच कसे सिरे— IS : 10805-1986
143. सी एम/एल-2101420	90-04-18	यू. पी. एस्वेल्स लि., पो. मोहनलाल बंज, जिला लखनऊ-227305		प्लास्टिकृत पी वी सी पाइप, श्रेणी 1, 160 मि मी केबल, श्रेणी 2 140 मिमी और 160 मिमी केबल— IS : 04985-1981
144. सी एम/एल-21015021	90-04-18	एम एच आई केबल्स एंड कंडक्टर्स प्रा. लि., पुराना हुजारी बाग रोड, रांची-834001		प्रति उच्च बोल्डता के लिए अस्तीकृत इस्पात प्रबलित एल्युमीनियम चालक (400 किबो और अधिक)— IS : 00398-1982
145. सीएम/एल 2101622	90-04-18	बकटेश्वर एग्री कैमिकल्स एंड मिनेरल्स लि. 37 एफ बेलाचेरी मेन रोड, बेलाचेरी मद्रास-600042		कार्बोहाजिर 50% द्रव्यमानानुसार डब्ल्यूडीपी फार्मूलेशन (पुनः पैकिंग केबल) IS : 08446-1977
146. सी एम/एल-2101723	90-04-18	—वही—		फ्लुवसोगेन 45 प्रतिशत द्रव्यमानानुसार ई सी केबल पुनः पैकिंग— IS : 08959-1978
147. सी एम/एल-2101824	90-04-18	—वही—		ट्राइडोमार्क 20 प्रतिशत द्रव्यमानानुसार ई सी केबल पुनः पैकिंग— IS : 08656-1980
148. सी एम/एल-2101925	90-04-18	—वही—		साइपरटेन्शन 10 प्रतिशत द्रव्यमानानुसार केबल पुनः पैकिंग के लिए— IS : 12016-1987

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
149. सी एम/एल-2102018	90-04-16	एम एंड इंडस्ट्रीज, मनोहरपुर बिल्डी रोड, बकुली, जिला हुगली (प. बं.)		बाय की पेटियो के लिए धातु की कटिंग— IS: 00010-1976
150. सी एम/एल-2102119	90-04-16	दीप्ति सोमेट्स प्रा. लि., थिम्मा सात्रा गांव, मचुरी होबली, डोडेबल्लापुरा ताल्लुक, बंगलौर जिला		साधारण पोर्टलैण्ड सीमेंट— IS: 00269-1976
151. सी एम/एल-2102220	90-04-16	मोहन जूट बैग्स मैन्फ. कं., 14 एंड 15, उर्ला इंड. एस्टेट, रायपुर-003221		उर्वरक की पैकिंग के लिए 85 x 39 टरपुलिन कपड़े से उत्पादित परतदार पटसन के कट्टे— IS: 07406-1984
152. सी एम/एल-2102321	90-04-16	राय इन्सुलेशन क. प्रा. लि., प्लाट फील्ड मेन रोड, प्लाट फील्ड, बंगलौर-560066		टगस्टन तंतु सामान्य सेवा बिजली के तन्त्र के लिए टोपी बी-22/25 x 28— IS: 09206-1979
153. सी एम/एल-2102422	90-04-16	पैगोडा केबल्स (प्रा.) लि., 511/1 ई 4 बी, स्ट्रीट नं. 3, विष्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032		1100 को तक कार्यकारी बोल्डता के लिए खोलवार और खोल रहित एल्यूमीनियम की तांबा जालकों रहित पी बी सी रोहित केबल— IS: 00694-1977
154. सी एम/एल-2102523	90-04-16	वि नेशनल इंसुलेटेड केबल कं. प्रा. लि. , शाम नगर, डा. अथपुर, जिला 24 परगना		85 सी अपरेशन के लिए निमज्ज्य मोटर के लिए पी बी सी रोहित बोल्डन तार— IS 08783-1978
155. सी एम/एल-2102624	90-04-16	यूनाइटेड केबल्स, 162, जी एम ई सी. अम्बर गांव, जिला वलसाड (गुजरात)		1100 को कार्यकारी बोल्डता के लिए तांबा जालको सहित खोलवार/खोल रहित पी बी सी रोहित केबल— IS: 00694-1977
156. सी एम/एल-2102725	90-04-16	—पहिली—		1100 को तक कार्यकारी बोल्डता के लिए विभिन्न अकबधित पी बी सी रोहित (डिप्टी इयटी) उपयुक्त केबल— IS 1554-1976
157. सी एम/एल-21028026	90-04-16	स्मृति केबल्स इंडस्ट्रीज, 26/ए, सतनाम एस्टेट, नागरबाल, हनुमान रोड रजियाल, अहमदाबाद		1100 को तक कार्यकारी के लिए खोलवार और खोल रहित एल्यूमीनियम की तांबा जालकों सहित पी बी सी रोहित केबल— IS 00694-1977
158. सी एम/एल-2102927	90-04-16	मैगनेक इंडिया लि., 71/4, मजफगढ़ रोड, मर्च दिल्ली-110013		230 को, 750 वा, तापस्थायी बिजली की इन्वर्टर, हले लोहे के आधार सहित— IS: 00366-1985
159. सी एम/एल-2103020	90-04-16	पुष्पा एजेंसीज, टी पी नं. 214, वैबर जीवन हिल्स, बंगलौर-560046		सूती बमियाल— IS 5488-1980

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
160. सीएम/एल-2103121	90-04-16	वि एलमिन मिल्स कं. लि., 11/6, श्रीमती प्रभाती बागला रोड, कूपर गंज, कानपुर-208001-	सूनी प्रिंस IS: 00177—1977	
161. सीएम/एल-2103222	90-04-16	हैदराबाद केमिकल सप्लाय प्रा. लि., ए-24/25, एसिस्टेंट प्रा. इंडस्ट्रियल एस्टेट, बाला नगर, हैदराबाद-500037	कार्बोनाजिम (एमबीसी) 5% इथ्यलानासुसार, इथ्युडीपी सांद्र कार्बोलेशन IS: 08446-1977	
162. सीएम/एल-2103323	90-04-16	मेहसाना टिन फैक्ट्री, 21, श्रीधरबीसी इंड, एस्टेट, हाइवे रोड, मेहसाना-384002	18-लिटर के खुले मुंह थोकोर कनस्टर IS: 00916—1975	
163. सीएम/एल-2103424	90-04-16	सुपर सोनिक इंड. कॉम्पलेक्स, संयुक्तपुञ्ज लेटेक्स युनिट परम्पलूर, मुवाट्ट पुसा, जिल्ला एर्नाकुलम (केरल)	ग्रामोनिया परिलक्षित सांद्र प्राकृतिक रबड़ सेटेक्स ग्रेड एचए IS: 05430—1981	
164. सीएम/एल-2103525	90-04-16	वि केरल सिरेमिक्स लि. (केम्पोलिम डीवीजन) कुम्मा, क्विलॉन-691501	हल्का कॅम्पोलिम ग्रेड I (केवल कागज लेपन उद्योग के लिए) ग्रेड 2 और 3 केवल IS: 00505—1978	
165. सीएम/एल-2103626	90-04-16	साल चन्द बालम्ब एंड सस, 13/1, बुलबुलहर रोड, गाजियाबाद (उ.प्र.)	लक्षण से ग्लेजिफ स्टोन बेसिन पाइप पाइप 300 मिमी तक, ग्रेड ए IS: 00651—1980	
166. सीएम/एल-2103727	90-04-16	दिल्ली धायरन एंड स्टील कं. लि., जी.टी. रोड, गाजियाबाद (उ.प्र.)	कंक्रिट प्रबलन के लिए इस्पात के विकृत सॉलिंग और तार साइज 8 मिमी से 32 मिमी, ग्रेड 415 IS: 01786—1985	
167. सीएम/एल-2103828	90-04-16	जिम्बल धायरन एंड स्टील कं. लि., बी-6, तारापुर इंडियन एरिया, नवापुर रोड, भोयसर-401506	संरचना इस्पात में बेल्स के लिए सनन 3/4 इंच ट IS: 06914—1978	
168. सीएम/एल-2103929	90-04-16	पू. रॉयल सैक्स (प्रा) लि., ए.टी. रोड, जालान नगर, बिबू गढ़ (धनस)	407 ग्रामि. <sup>2</sup> 85×39 टरपुलिन कपड़े से उत्पा- दित परतवार पटसन के बोरे IS: 07406—1984	
169. सीएम/एल-2104022	90-04-16	—वही—	380 ग्रामि. <sup>2</sup> टरपुलिन कपड़े से उत्पादित परत- वार पटसन के बोरे IS: 07406—1986	
170. सीएम/एल-2104123	90-04-16	प्रताप प्लास्टिक्स लि., 1, कुंदन बाई लेम, सिमूग्राह, हावड़ा	407 ग्रामि. <sup>2</sup> 85×39 टरपुलिन कपड़े से उत्पा- दित परतवार पटसन के बोरे IS: 07406—1984	
171. सीएम/एल-2104224	90-04-16	पंजाब धानेव लेम्प इंडस्ट्रीज लि., इय. प्रोफल प्लाईट, फेज 19, एमएएम नगर, जिला रोपड़	नामान्य प्रकाश सेवा के लिए नलिकाकार पनोरेसेट लेम्प 36 वा, 220 वा, 6500 केल्ब, जी. एच 3, स्टार्टर के साथ प्रयुक्त दो-पिन वाली टोपी IS: 02418—1977	
172. सीएम/एल-2104325	90-04-16	केपसम्स इंटरनेशनल (इ.), सोडस रोड, साही पुर इंडस्ट्रीज एरिया, जलंधर-144004	गन मेटल के गेट वाल्व धोपी I पेंच फसे गिरे काश्न 15 मिमी 50 मिमी तक IS: 00778—1984	
173. सीएम/एल-2104426	90-04-16	बैस्ट एंड क्राम्पटन इंजीनियरिंग लि., 781, पिरुवोट्टियूर, हाई रोड, मन्नार-600081	कुछ प्रयोजनों के लिए शाफ, टडे नाजे पामी के लिए मोनो पम्प IS: 09079—1989	
174. सीएम/एल-2104527	90-04-16	एशियाटिक फास्फीजन लि., 26, 27, 28, फोर शोर रोड, शिवपुर, हावड़ा	बेल्सिंग के लिए रैनुथल ब्लो पाइप और ब्लो कलिंग के लिए रैनुथल ब्लो पाईप IS: 07653—1978	

355

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
175. सीएम/एल-2104628	90-04-16	रोडमास्टर स्टील स्ट्रुप्स लि., ग्राम धालवाला, मुनीभी रेती हंड. एरिया, आधिकेस-249201	अत्यंत बेतलित अल्प कार्बन इस्पात की चट्ट और पत्ती IS: 00513--1986	
176. सीएम/एल-2104729	90-04-16	मैक्स स्विचगोयर प्रा. लि., 19वां किलोमीटर, पठानकोट रोड, पो. बा. नं. 52, जालंधर	650 कैंसी, 32 एम्प से अनधिक वायु वियोज्य स्विच और पुनः तार लगाने वाले टाइप के फ्यूज IS: 10027--1981	
177. सीएम/एल-2104830	90-04-16	शिवास इंडस्ट्रीज, इंद्रा मिल कंपाउंड जिम्नोमी मंडी, भागशा-282004	कूटबालस्व सांकेतिक साहज, 80 मिमी पेंच कसे सिरे केबल रोगन की गई किस्म IS: 10805--1986	
178. सीएम/एल-2104931	90-04-16	महाराष्ट्र केबल इंडस्ट्रीज, घोड नं. 1, 49/2, हंड एरिया, कमल मेनुकैचरिंग कंपाउंड, मेन रोड, उल्हासनगर-421004	1100 बो तक कार्यकारी बोल्टता के लिए तांबा चालकों सहित खोलदार और खोल रहित पीवी रोहित केबल IS: 00694-1977	
179. सीएम/एल-2105024	90-04-16	केंद्रोल केबल इंडस्ट्रीज, 14-22/ए, भंसा हंड. एरिया, साकी बिहार रोड, बम्बई-400072	1100 बो तक कार्यकारी बोल्टता के लिए तांबा और एल्युमीनियम चालकों सहित खोलदार/खोल रहित पीवीसी रोहित केबल IS 00694--1977	
180. सीएम/एल-2105125	90-04-16	अनु केबल्स, ग्राम गगनामा, जिला भजमेर (राजस्थान)	शिरोपरि प्रेषण के लिए एल्युमीनियम के लड़दार चालक IS: 00398--1976	
181. सीएम/एल-2105226	90-04-16	पीवीसी लि., 95, हंड. एरिया, झोटवाड़ा, जयपुर -302102	1/2 किग्रा और 1 किग्रा वनस्पति के लिए नम्य पैक IS: 11352--1985	
182. सीएम/एल-2105327	90-04-16	हेमन्त इलेक्ट्रीकल्स प्रा. लि., एनएच नं. 12 ग्राम किकिया पुरा, डा. शिवोवासपुरा, शिवोवासपुरा-303903	शिरोपरि प्रेषणों के लिए जस्तीकृत इस्पात प्रबलित एल्युमीनियम के चालक IS: 00398--1976	
183. सीएम/एल-2105428	90-04-16	लेसर केबल्स प्रा. लि., 8, गिरीश घोष रोड पातीपुकर, कलकत्ता-700048	1100 बो तक कार्यकारी बोल्टता के लिए तांबा या एल्युमीनियम चालकों सहित खोल दार या खोल- रहित पीवीसी रोहित केबल IS: 0069-1977	
184. सीएम/एल-2105529	90-04-16	डनलप इंडिया लि., डा. साहा गंज जिला हुगली (पं. बं.)	ट्रक, बस और हल्के ट्रक के टायर IS: 10914-1988	
185. सीएम/एल-2105630	90-04-16	लेसर केबल्स प्रा. लि., 8, गिरीश घोष रोड, पातीपुकर, कलकत्ता-700048	1100 बो तक कार्यकारी बोल्टता के लिए तांबा चालकों सहित प्रकवचित पीवीसी रोहित (हैवी ड्यूटी) केबल IS: 01554--1976	
186. सीएम/एल-2105731	90-04-16	उड़ीसा प्लास्टिक प्रोसेसिंग, लि., ओ. टी. रोड, बयलासोर 756001,	पय जल आपूर्ति के लिए यूवीसी पाइप IS: 04985-1981	
187. सीएम/एल-2105832	90-04-16	जगदीश एंजी. इंडस्ट्रीज, प्लॉट नं. 377, जीआईडीसी, अली हंड. एस्टेट, राजकोट-360003	मोनोमोट पम्प IS: 09079--1979	
188. सीएम/एल-2105933	90-04-16	ट्राइडेंट ट्यूब्स लि., सी-22/25, हाजीपुर हंड. एरिया, हाजीपुर, जिला बगाली (बिहार)	पय जल आपूर्ति, भय जल और औद्योगिक बुद्धि लावों के लिए एक्सीपीई के पाइप IS: 04984--1987	
189. सीएम/एल-2106026	90-04-16	श्री बारात इंडस्ट्रीज, श्रीनिवासपुरम, 95 एन. कोयम्बतूर मेन रोड, अवनाशी-638654	ठंडे, ताजे, माफ पानी के लिए निमज्ज्य पम्प सेट IS: 080034--1976	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
190. सीएम/एल-2106127	90-04-16	जगदेव मकेनिक वर्क्स, शाम नगर, पटियाला रोड, राजपुरा (पंजाब)	डोर क्लोजर (द्वय चालान द्वारा नियंत्रित) साइज पवनम 2, यूनीवर्सल टाइप IS: 03564--1986	
191. सीएम/एल-2106228	90-04-16	भोरका इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लि. महावेकपुरागढ़ा., फर्हाइटफील्ड रोड, बंगलौर-560048	एसीएमआर हेतु इस्तेमाल की जाए IS: 00398--1976	
192. सीएम/एल-2106329	90-04-16	मागरण पेट्स (प्रा.) लि., 46, फजल गंज, कानपुर-208012	प्राइमिंग के लिए हवा में सूखने वाला सीमांत शुद्ध रेड प्राक्साइड जिक कोम रोगन IS: 02074--1979	
193. सीएम/एल-2106430	90-04-16	--वही--	सामान्य प्रयोजनों के लिए एल्युमीनियम रोगन, कुहरे भाषान में IS: 02339--1963	
194. सीएम/एल-2106531	90-04-16	--वही--	भवनों के छत पर प्रयोग के लिए किनिशिंग हेतु संश्लिष्ट इनेमल IS: 00133--1985	
195. सीएम/एल-2106632	90-04-16	मागरण पेट्स (प्रा.) लि., 46, फजल गंज, कानपुर-208012	भवनों के बाहर किनिशिंग हेतु हवा में सूखने वाली संश्लिष्ट वानिष IS: 00524--1983	

[सं. के प्रवि/13: 11]

S.O. 446.—In pursuance of sub-regulation (5) of regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given in the following Schedule.

## SCHEDULE

## List of Licences Granted during March 1990

Sl. No.	CM/L-No.	Operative date	Name & Address of the Party	Article/process	IS : No./Part
1	2	3	4	5	6
1.	CM/L 2087250	90-03-01	Oswal Foods Ltd. 7A to 13A, Indl. Area Khalilabad Distt. Basti (UP)	Vanaspathi	IS : 10633--86
2.	CM/L-2087751	90-03-16	Minerva Fire Protection System, 30, Mahendra Roy Lane, Gobinda, Calcutta-700046	Refill for Soda Acid Portable Fire Extinguishers	IS : 05490--77 Pt 01 Sc
3.	CM/L 2137452	90-03-16	C.R.I. Industries, 12 Sarada Devi Street, Ramakrishna Puram, Ganapathy, Coimbatore-641006	Screw and Flange Type Foot valves	IS : 10805--86 Pt Sc
4.	CM/L-2087553	90-03-16	Menon & Menon Pvt Ltd. Vikram Nagar, Kolhapur, Kolhapur (MS)	Horizontal Centrifugal pumps for Clear, Cold, Fresh Water	IS : 06595--80 Pt Sc
5.	CM/L-2037654	90-03-01	Shalimar Electronic Industries Ltd. Pardisandhpore, Kailash Road, Valsad (Gujarat)	Flush mounting type switch sockets outlets 250 volts AC 5A and 15A	IS : 04615--68 Pt Sc

1	2	3	4	5	6
6	CM/L 2087755	90-03-01	Shalimar Electronic Industries Ltd., Pardi Sandhpore, Kailash Road), Valsad (Gujarat)	Flush Mounting non-shuttered sockets outlets 250 Volts 5A and 15A three pin plugs	IS 01293-67 Pt Sc
7	CM/L 2087856	90-03-16	Sri Ram & Sons, 7531/1, Tel Mill Marg, Ramnagar, New Delhi-110055	Single phase small AC motors of Class E Insulation	IS : 00996-79 Pt Sc
8	CM/L-2087957	90-03-01	Shalini Enterprises, 1-2, DLF Indl. Area, II Mathura Road, Faridabad	Domestic Cooking Ranges for use with LPG	IS : 04760-71 Pt Sc
9	CM/L-2088050	90-03-16	S & A Motors (P) Ltd., F/21, Okhla Indl. Area Phase I New Delhi-110020	Single Phase Small AC Motors Class E Insulation (for use in air cooler only)	IS : 00996-79 Pt Sc
10	CM/L-2088151	90-03-16	Maruti Rubber Udyog, B-69, Sector V, Noida (Distt Ghaziabad-201301)	Rubber Water Hose type 2 only	IS : 00444-87 Pt Sc
11	CM/L-2088252	90-03-16	Sidhartha Industries, Khasra No 106/17, Village Poothkalan, Delhi-110041	Domestic Stoves for use with LPG	IS : 04246-84 Pt Sc
12	CM/L-2088353	90-03-16	Golden Manufacturing Co., A-7/2, Jhilmil Indl Area, Shahdara, Delhi 110032	PVC Insulated Cables for Working Voltages upto and including 1100 V	IS : 00694-77 Pt Sc
13	CM/L-2088454	90-03-16	Inter Gas Appliances Pvt Ltd., C-113, Sector II Noida, Distt Ghaziabad-201301	Domestic Stoves for use with LPG	IS : 04246-84 Pt Sc
14	CM/L-2088555	90-03-16	Libra Indl. Components, Plot No. 1207, Village & PO Rithala, Delhi-110034	Domestic Stoves for use with LPG	IS : 04246-84 Pt Sc
15	CM/L-2088656	90-03-16	Ved Paper Systems, C 221, Sector X, Noida-201301	Teleprinter Paper Page Rolls	IS : 03031-79 Pt Sc
16	CM/L-2088757	90-03-16	I P Muthukrishnan & Son, 115-K, V.K. Road, Peelamedu, Coimbatore-641004	PVC wiring wires type C Insulation	IS : 08783-78 Pt Sc
17	CM/L-2088858	90-03-16	Perfect Engineering Co., 136, Pioneer Mills Peelamedu, Coimbatore-641004	Single Phase Motors Class B Insulation	IS : 00996-79 Pt Sc
18	CM/L-2088959	90-03-16	Dunlop India Ltd, Ambattur Factory Ambattur, Madras-600053	Light Commercial Vehicle Buses, Trucks and Trailer S tyres	IS : 10914-88 Pt 02 Lc
19	CM/L-2089052	90-03-16	The I A E C Pumps Ltd, Rajamangalam Villivakkam, Madras-600049	Submersible pumpsets for clear, cold, freshwater	IS : 08034-89 Pt Sc
20	CM/L-2089153	90-03-16	Phrashantha Cylinders (P.) Ltd., 35-B, Veer Sandhra Indl area, Herbbagodi Post, 19th Km Hosur Road, Bangalore-562158	Welded Low Carbon Steel Gas Cylinder for Ammonia (Anhydrous)	IS : 07680-85 Pt Sc
21	CM/L-2089254	90-03-16	Bharat Pesticides Manufacturing Co. E-17, DSIDC Indl. Complex, Nangloi Delhi	Quinalphos EC	IS : 08028-87 Pt Sc
22	CM/L-2089355		Sutar Chemicals (P) Ltd, Ranital, Distt. Balasore-756111	BHC DP	IS : 00561-78 Pt Sc

1	2	3	4	5	6
23.	CM/L-2089456	90-03-16	Precision Blanking (I) Ltd. Digha Ghat Patna 800011	Single Phase 240 V Watt hour Meter	IS : 00722—77 Pt 02 Sc
24.	CM/L-2089557	90-03-16	Jainsons Minerals 27-A, Indl. Area Fatehabad (Haryana) 125050	Aldrin EC	IS : 01307—82 Pt Sc
25.	CM/L-2089658	90-03-16	Jain Sons Minerals 27-A, Indl. Area Fatehabad (Haryana) 125050	Dimethoate EC	IS : 03903—78 Pt Sc
26.	CM/L-2089759	90-03-16	Chirag Chemical Industries C-1/193, Phase II GIDC Vatva Ahmedabad 382445	Paraffin Wax Type 3	IS : 04654—74 Pt Sc
27.	CM/L-2089860	90-03-16	Chemofarbe Industries Old Bomay Poona Road Khair Gaon PO Kalva Distt. Thane 400605	Calcium Propionate Food Grade	IS : 06031—71 Pt Sc
28.	LM/L-2089961	90-03-16	Aditya Alloys Ltd. At PO Telengapentha Cuttack 753015	Cast Billet Ingots for Rolling into Structural Steels (Standard Quality) Grade 2 only	IS : 06914—78 Pt Sc
29.	CM/L-2090037	90-03-16	Premier Lamps 45/22, Gubbanna Indl. Estate 6th Block Rajaji Nagar Bangalore 560010	GLS Lamps 60W 250V	IS : 00418—78 Pt Sc
30.	CM/L-2090138	90-0-16	Precision Electricals 134-135, NR Manish Indl. Estate Navghar Vasai (E)- Distt. Thane	Non Shuttered Sockets Outlets Shuttered Socket Outlets three pin plugs	IS : 01293—67 Pt So
31.	CM/L-2090239	90-03-16	Sheetla Agro Industries (P) Ltd. A-1, Chemical Complex Barabanki (UP)	BHC Dusting Powder	IS : 00561—75 Pt Sc
32.	CM/L-2090340	90-03-16	Sahni Rubbers 81, Talangpur Kotla New Delhi-110043	Flexible Rubber Tubing For LPG Nominal bore 6.4 mm	IS : 10908 —84 Pt Sc
33.	CM/L-2090441	90-03-16	Khetawat Wire Ropes Pvt. Ltd. 403, Urla Indl. Area Raipur (M.P.) 493221	Round Stranded Galvanized Steel wire Ropes for Shipping Purposes Type Round Strand	IS : 02581—77 Pt Sc
34.	CM/L-2090542	90-03-16	Gurukrupa Engineers C-3/23, NR GIDC Office GIDC Estate Nadiad 387001	Submersible Pumpsets	IS : 08034—89 Pt Sc
35.	CM/L-2090643	90-03-16	Markfed Agro Chemicals 7 & 8B, Indl. Estate Sas Nagar Mohali 160051	Isoproturon WP	IS : 11995—87 Pt Sc
36.	CM/L-2090744	90-03-16	Metal Burn 70A, Narkeldanga Main Road Calcutta 700054	Domestic Stoves for use with LPG	IS : 04246—84 Pt Sc
37.	CM/L-2090845	90-03-16	Suraj Industries Mansa Road Bhatinda	Salt Glazed Stoneware Pipes Grade A	IS : 00651—80 Pt Sc
38.	CM/L-2090946	90-03-16	Heatrite Electricals Pvt. Ltd. Gath No. 907/2 Pune-Nagar Road Village Sansundi Tallukashipur Disit. Pune.	Stationery Storage type Electric Water Heaters 15 Litre Capacity	IS : 02082—85 Pt Sc



1	2	3	4	5	6
39.	CM/L-2091039	90-03-16	Sol-Ray Appliances Pvt. Ltd. 29/2, Kharadi Village Distt. Pune	Stationery Storage type electric water Heaters 25 litre capacity	IS : 02082—85 Pt Sc
40.	CM/L-2091140	90-03-16	Sunflag Iron & Steel Co. Ltd. PO Bhandara Road, Distt. Bhandara 441905	Carbon Steel Bars	IS : 01875—78 Pt Sc
41.	CM/L-2091241	90-03-16	Universal Wires & Industries D-3, Indl. Area Patna 800013	Alluminium Alloy Conductors for overhead Transmission purposes	IS : 00398—79 Pt 04 Sc
42.	CM/L-2091342	90-03-16	Perfect Containers S.No. 4/1, Liaga Pura Sira Road Tumkur 572106	15 kg Square tins for Vanaspati and edible oils	IS : 10325—89 Pt Sc
43.	CM/L-2091443	90-03-16	Sree Barat Industries Srinivasa Puram Coimbatore Main Road Avanashi 638654	Three phase submersible Motors	IS : 09283—79 P Sc
44.	CM/L-2091544	90-03-16	Hitech 59, Thadaggam Road Velandipalayam Coimbatore 25	Three phase submersible pumpsets	IS : 09283—79 Pt Sc
45.	CM/L-2091645	90-03-16	Morvi Vegetable Products. Ltd. Vegetable Road Morvi	15 kg square tins for Vanaspati and edible oils	IS : 10325—89 Pt Sc
46.	CM/L-2091746	90-03-16	Deepak Industries B-150, Sector VI Noida 201301	Steel Butt Hinges	IS : 13041—81 Pt Sc
47.	CM/L-2091847	90-03-16	Garg Udyog Khasra No. 152 Village Rithala Delhi	Propeller type AC ventilating fans class E insulation	IS : 02312—67 Pt Sc
48.	CM/L-2091948	90-03-16	Thermoking A-24, Narnina Indl. Area Phase 1 New Delhi 110028	Hot Air Fans Class E Insulation	IS : 04283—81 Pt Sc
49.	CM/L-2092041	90-03-16	Thukral Mechanical Works Dashmesh Nagar Sirhind (Punjab)	Horizontal centrifugal pumps for clear, cold, fresh water	IS : 06595—80 Pt Sc
50.	CM/L-2092142	90-03-16	Amba containers Pvt. Ltd. Plot No. 96 HPSIDC Indl. Area Baddi Teh Nalagarh Distt. Solan (HP)	HDPE containers for Vanaspati (For 5 kg. only)	IS : 10840—86 Pt Sc
51.	CM/L-2092243	90-03-16	S.B. Engg. Works New Colony Aman Nagar Tanda Road Jalandhar City	Horizontal centrifugal pumps for clear, cold, fresh water	IS : 06595—80 Pt Sc
52.	CM/L-2092344	90-03-16	United Cable Industries A-14, Sector IV Noida 201301	Elastometer insulated cables for working voltages upto and including 1100 volts	IS : 09968—81 Pt 01 Sc
53.	CM/L-2092445	90-03-16	Udyogi Moulders (P) Ltd. Chuni Bhati PO Podra Distt. Howrah	Protective Helmets for Scooters and Motor Cycle Riders NV Type	IS : 04151—82 Pt Sc
54.	CM/L-2092546	00-03-16	Panjab Anand Batteries A-9 & 10, Indl. Estate Sas Nagar Mohall 160055	Multipurpose Dry Batteries	IS : 08144—76 Pt Sc
55.	CM/L-2092647	90-03-16	The Indian Steel & Wire Products Ltd. Indra Nagar Jamshedpur 831008	Indented wires for prestressed concrete	IS : 06003—83 Pt Sc

1	2	3	4	5	6
56. CM/L-2092748	90-03-16	Minerva Fire Protection Systems 30, Mahendra Roy Lane Gobra Calcutta 700046	Refill for foam type portable fire extinguishers	IS : 05490—77 Pt 02 Sc	
57. CM/L-2092849	90-03-16	The Indian Steel & Wire Products Ltd. Indra Nagar Jamshedpur 831008	Plain Hard drawn steel wires for prestressed concrete	IS : 01785—83 Pt 01 Sc	
58. CM/L-2092950	90-04-01	Engel Industries Purandarpur PO Barni Pur Distt. 24 Parganas (WB)	Tungsten Filaments general services electric lamps	IS : 00418—78 Pt Sc	
59. CM/L-2093043	90-04-01	Allwin Fibre Glass & Plastics Ltd. Plot No. R-455 MIDC Rabale Ghansoli (TTC) Thane 400701	UPVC Pipes Class 2	IS : 09485—81 Pt Sc	
60. CM/L-2093144	90-04-01	Ellora Art Industries 108-B, Parvati Indl. Estate First Floor Sun Mill Compound, Lower Parel Bombay-400013	Surface and flush type non shuttered three pin sockets outlets 5A and 5A	IS : 01293—88 Pt Sc	
61. CM/L-2093245	90-04-01	C.J. Industries B-3, Anandi Indl. Area B.P. Cross Road Bhayander (East) 401105	Flush type non shuttered sockets outlets 250V 5A	IS : 01293—88 Pt Sc	
62. CM/L-2093346	90-04-01	C.J. Industries B-3, Anandi Indl. Estate Balaram Patil Cross Road Bhayander (East) 401105	Flush type switches excluding switches for inductive circuits	IS : 03854—66 Pt Sc	
63. CM/L-2093447	90-04-01	Ajanta Enterprises Khasra No. 76 Village Ramhola PO Nangloi New Delhi-110041	PVC Insulated Sheathed/unsheathed cables for working voltages upto and including 1100 volts	IS : 00694—77 Pt Sc	
64. CM/L-2093548	90-04-01	Polar Fan Industries 167, Brahmo Samaj Road Calcutta 700060	Propeller type AC ventilating Fans	IS : 02312—67 Pt Sc	
65. CM/L-2093649	90-04-01	Express Cable Pvt. Ltd. Neora Post Danapur Distt. Patna	Aluminium Stranded conductors for overhead transmission purposes	IS : 00398—76 Pt 01 Sc	
66. CM/L-2093750	90-04-01	Khatau Junker Ltd. Plot No. 3000 GIDC Estate PB No. 40 Ankleshwar	Monocrotophos SL	IS : 08074—83 PT Sc	
67. CM/L-2093851	90-04-01	Shyamala Pipes & Fittings C-9 & 10, Indl. Estate Bangalore Road Bellary 583101	UPVC Pipes Class 2	IS : 04985—81 PT Sc	
68. CM/L-2093952	90-04-01	Glory Lamp Works 12, S.N. Roy Road Calcutta 700038	Tungsten Filament General Purpose electric lamps	IS : 00418—78 Pt Sc	
69. CM/L-2094045	90-04-01	Khatau Junker Ltd. Plot No. 3000 GIDC Estate PB No. 40 Ankleshwar	Dimethiate FC	IS : 03903—84 PT Sc	
70. CM/L-2094146	90-04-01	Modern Switch Mfg. Co. Shed No. 15 & 16 Indl. Estate Cuttack 753010	Surface Mounting type shuttered socket outlets	IS : 01293—67 Pt Sc	
71. CM/L-2094247	90-04-01	Krishna Chemical Industries Large Indl. Estate Barari Bhagalpur 812003	Malathion DP	IS : 02568—78 Pt Sc	

1	2	3	4	5	6
72. CM/L-2094348	90-04-01	The Tata Iron & Steel Co. Ltd. D. Digha PO Digaghat Patna 800011	HSD Steel bars and wires for concrete reinforcement	IS : 01786—85 Pt Sc	
73. CM/L-2094449	90-04-01	Hammam Steel Industries Inchambakkam Village Madras 8600041	Structural Steel (Standard Quality) )	IS : 00226—75 Pt Sc	
74. CM L-2094550	90-04-01	U.M.A.S. 379, Arcot Road Kodambakkam Madras 600024	Stationary Storage Type electric water heaters	IS : 02082—85 Pt Sc	
75. CM/L-2094651	90-04-01	India Meters Ltd. Plot No. 14 Indl. Estate Ambattur Madras 600058	Three phase four wire watt hour Meters	IS : 00722—77 Pt 03 Sc	
76. CM/L-2094752	90-04-01	Lumino Lamps Ltd. S.No. 207, Bonthapalli Village Narsapur Taluk Distt. Medak	Tungsten Filament General service Lamps	IS : 00418—78 Pt Sc	
77. CM/L-2094853	90-04-01	Swastik Laboratories 28-26-3, Kurmalah Street NR Vijaya Talkies Vijaywada 520002	Disinfectant fluids Class A Grade 1, 1A, 2, 2A, 3 and 3A type normal	IS : 01061—82 Pt Sc	
78. CM/L-2094954	90-04-01	National Organic Chemical Industries Ltd. Plot No. A-1, Lote Parshram Indl. Area Talluka Khed Distt. Ratnagiri 415722	Dichlorovos EC	IS : 05277—78 Pt Sc	
79. CM/L-2095047	90-04-01	Anandji Cables Plot No. 124, First Floor Marol Co-op. Indl. Estate Mathuradas Vasanji Road, Sakinaka, Andheri (E) Bombay 400059	PVC insulated (Heavy Duty ) electric cables for working voltages upto and including 1100 volts.	IS : 01554—76 Pt 01 Sc	
80. CM/L-2095148	90-04-01	Hi-Speed Appliances (P) Ltd. 907/2, Pune-Nagar Road Sanaswadi Teh. Sirur Distt. Pune	Stationary Storage type electric water heaters	IS : 02082-85 Pt Sc	
81. CM/L-2095249	90-04-01	Rayat Electricals J-99-98, Vishnu Garden New Delhi-110018	Electric immersion water heaters one KW and two KW rating	IS : 00368—83 Pt Sc	
82. CM/L-2095350	90-04-01	Cement Corporation of India Ltd. Delhi Cement Grinding Unit Okhla Indl. Area Phase I New Delhi-110020	Ordinary Portland Cement	IS : 00269—76 Pt Sc	
83. CM/L-2095451	90-04-01	Gold Star Conductors Chorahata Rewa 486001	Aluminium conductors Galvanized steel reinforced	IS : 00398—76 Pt 02 Sc	
84. CM/L-2095552	90-04-01	Geep Industrial Syndicate Ltd. 28, South Road Allahabad	Aluminium painted prefocussed flush Lights with plastic head	IS : 02083—78 Pt Sc	
85. CM/L-2095653	90-04-01	Ludhiana Steel Rolling Mills G.T. Road [ Miler Ganj Ludhiana (Punjab)	HSD Steel bars and wires for concrete reinforcement	IS : 01786—85 Pt Sc	

1	2	3	4	5	6
86. CM/L-2095754	90-04-01	All India Medical Corpn. Simpoli Road Near Kastur Park Borivli (W) Bombay 400092		Cypermethrin EC	IS : 12016—87 Pt Sc
87. CM/L-2095855	90-04-01	Bhopal Pesticides Shed No. 10 Indl. Estate Govindpura Bhopal 462023		Carbaryl dusting powder	IS : 07122—84 Pt Sc
88. CM/L-2095956	90-04-01	Bharat Domestic Appliances F-44, Sector IV Noida Distt. Ghaziabad		Domestic stoves for use with LPG	IS : 04246—84 Pt Sc
89. CM/L-2096049	90-04-01	STP Ltd. 26, Lake Road Bhandup Bombay 400078		Bitumen emulsion (Anionic type)	IS : 03117—65 Pt Sc
90. CM/L-2096150	90-04-01	Rama Industries 146, East Coast Road Injambakkam Madras 600041		Domestic Gas Stoves for use with LPG	IS : 04246—84 Pt Sc
91. CM/L-2096251	90-04-01	Steel Authority of India Ltd. Bhilai Steel Plant Research & control Laboratory Bhilai Steel Plant Bhilai 490001		Hot rolled steel plates and sheets for flanging and pressing	IS : 03747—82 Pt Sc
92. CM/L-2096352	90-04-01	Eastern Engineering Corpn. 16, Padma Ghosh Garden Lane Liluah Howrah 711204		CIDetachable joints for use with asbestos cement pressure pipes of size upto and including 200 mm dia	IS : 08794—78 Pt Sc
93. CM/L-2096453	90-04-01	Hemrajani Tubes (P) Ltd. Kondamuguru Village Bibi Nagar Mandal Distt. Nalgonda		Steel tubes for structural purposes, ERW, grade YS T-210, Class light, medium and heavy; of sizes 65mm upto and including 150MMNB	IS : 01161—79 Pt Sc
94. CM/L-2096554	90-04-01	Chamak holding Ltd. 8/7, MTH Road Ambattur Madras 600098.		Structural steel (standard quality)	IS : 00226—75 Pt Sc
95. CM/L-2096655	90-04-01	Hemrajani Tubes (P) Ltd. Kundamugudu Village Bibi Nagar Mandal Distt. Nalgonda		Steel tubes, ERW-class light medium and heavy; sizes 65mm upto and incl uding 150MM NB; Black Plain ends	IS : 01239—79 Pt 01 Sc
96. CM/L-2096756	90-04-01	Best Engineers 59B, Thadagam Road Velandipalayam Coimbatore		3 Phase, 415, 50 HZ motors for submersible Pumpsets 3.7 kw rating wet type category B	IS : 9283—79 Pt Sc
97. CM/L-2096857	90-04-01	Vega Engineers 11/B-1, Jagannath Estate Near Gujarat Bottling Co. Rakhial Ahmedabad 380023		Monoset pumpsets	IS : 09079—89 Pt Sc
98. CM/L-2096958	90-04-01	Sethi Cable Industries 627/4/65, Shankar Gali Vishwas Nagar Shahdara Delhi 110032.		PVC insulated unsheathed and shea- thed cables with copper or aluomi- nium voltages upto & including 1100V	IS : 00694—77 Pt Sc
99. CM/L-2097051	90-04-01	Ditz Electricals (I) Ltd. 29, Malkaganj road Delhi 110007		Hot air fans single phase 2000 w, 230 v, 50 HZ AC with class E Insulation	

1	2	3	4	5	6
100. CM/L-2097152	90-03-16	Jyoti Rubber Udyog (India) Pvt. Ltd. A-108, Sector V Noida Distt. Ghaziabad	Rubber Mats for electrical purposes	IS : 05424-62 Pt Sc	
101. CM/L-2097253	90-04-01	Pooja Cables Pvt. Ltd. 1-A/WB Sector Industrial Area Govindpura Bhopal 462023	PVC Insulated (heavy duty electric cables for working voltages upto and including 1100V armoured and unarmoured	IS : 01554-76 P5 01 Sc	
102. CM/L-2097354	90-04-01	Punjab Pesticides Indl. P. Society Ltd. Chandigarh Ropar Road Khanpur Tehsil Khror Distt. Ropar.	Dimethoate 30 EC formulation	IS : 03903-84 Pt Sc	
103. CM/L-2097455	90-04-01	Punjab Pesticides Indl. P. Society Ltd. Chandigarh Ropar Road Khapur Tehsil Khror Distt. Ropar.	Endosulfan 35 % EC formulation	IS : 04323-80 Pt. Sc	
104. CM/L-2097556	90-04-01	Sawhney Paints C-13, Focal Point Jalandhar 144004	Distemper Dry or Shades light colour range	IS : 00428-65 Pt Sc	
105. CM/L-2097657	90-04-01	Jagat Steel Pvt. Ltd. Old Linema Road Khanna 141401	Cast Billet ingots, grade I for rolling into structural steel (standard quality)	IS : 06914-78 Pt Sc	
106. CM/L-2097758	90-04-01	Sawhney Paints C-13, Focal Point Jalandhar 144004	Distemper, Oil emulsion of shades medium colour range only.	IS : 00428-69 Pt. Sc	
107. CM/L-2097859	90-04-01	Bikaner Engineering (Foundry Works) F-444/V.K.I. Area Road No. 12, Jaipur 302012	Detachable joints for use with AC pressure pipes, sizes upto and including 150mm, Class 10 only	IS : 08794-78 Pt Sc	
108. CM/L-2097960	90-04-01	Ashok conductors Mai pur TA Vyara Distt. Surat.	ACSR conductors	IS : 00398-76 Pt 02 Sc	
109. CM/L-2098053	90-04-01	Ashok conductors Mai pur TA Vyara Distt. Surat	AAC conductors	IS : 00398-76 Pt 01 Sc	
110. CM/L-2098154	90-04-01	Solano Chemicals Pvt. Ltd. Plot No. E 56 MIDC Area Chandrapur (MS)	Bleaching powder stable grade 2	IS : 01065-71 Pt Sc	
111. CM/L-2098255	90-04-01	Sirohi Enterprises C 43/2 Abhimanyu Gali Mohan puri Mauj pur Delhi 110053.	Domestic stoves for use with LPG	IS : 04246-84 Pt Sc	
112. CM/L-2098356	90-04-01	K.T.M Foundry B 139, Phase I Mayapuri Indl. Area New Delhi.	Domestic stoves for use with LPG, stainless steel body, double burners	IS : 04246-84	
113. CM/L-2098457	90-04-01	Bhairav Cement Industries Pvt. Ltd. E-12, Ambaji Ind. Area Abu Road 307036	Ordinary port and cement	IS : 00269-76 Pt Sc	
114. CM/L-2098558	90-04-01	Shivalik Fertilisers & Chemicals Bhurarani Road [ Rudrapur Distt. Nainital	Zinc sulphate agricultural grade	IS : 08249-76 P tc	
115. CM/L-2098659	90-04-01	Rockey knitters 216, P.N. Road Tirupur 638602.	Plain knitted cotton vest type RN & RNS[, Gauge 24 G sizes 75 to 110 cm	IS : 04964-80 Pt Sc	
116. CM/L-2098760	90-04-01	Plant Protection Industries F-6, Indl. Estate Amrawati Road Gfintur 522034.	Phorate granules 10 % encapsulated	IS : 09359-80 Pt Sc	

1	2	3	4	5	6
117. CM/L-2098961	90-04-01	Madera Resin & Turpentine Factory PO Miran Sahib Jammu Tawi 181101	Gum rosin, grade M only	IS : 00553—84 Pt Sc	
118. CM/L-2098962	90-04-01	Bacfield 243, N.S.C. Bose Road Naktala Calcutta 700047	Rhizobium inoculants for nine crops namely lentil, green gram, red gram, black gram, pea, soyabean.,	IS : 08268—86 Pt Sc	
119. CM/L-2099055	90-04-01	Tulsi Domestic appliances 30A, Old Indl. Area Alwar (Rajasthan)	Domestic grillers for use with LPG	IS : 11480—85 Pt. Sc	
120. CM/L-2099156	90-04-01	Industrial Rubber Products A-21/22, Indl. Estate Guindy Madras 600032.	Flexible rubber tubing for LPG of sizes 6.4 mm dia only.	IS : 10908—84 Pt Sc	
121. CM/L-2099257	90-04-01	Gangadharam Appliances Ltd. 143, Pudupakkam Village Kalamakkam Vadalu Road Distt. Chingleput	Domestic pressure cookers stainless Steel	IS : 02347—87 Pt Sc	
122. CM/L-2099358	90-04-01	Venkateshwara Agro Chemicals & Minerals Ltd. 37-F, Velachery Main Road Velachery Madras 600042	Chlormequat chloride aqueous solutions 50% mm repacking only	IS : 08962—78 Pt Sc	
123. CM/L-2099459	90-04-01	Trilo Agro Industries Pvt. Ltd. Village & PO Jharmari Distt. Patiala (PB).	BHC DP gamma isomer 1.3% mm formulation	IS : 00561—78 Pt Sc	
124. CM/L-2099560	90-04-01	M.B. Commercial Syndicates 64, Gaus Ganj Wazir Ganj Lucknow 226018	Hand operated knapsack SP rayer. instant type 16 litres capacity with Brass/plastic tank	IS : 03906—82 Pt 01 Sc	
125. CM/L-2099651	90-04-01	Trilo Agro Industries Pvt. Ltd. Village & PO Jharmari Distt. Patiala (Punjab)	Malathion 25% WDP formulation [	IS : 02569—78 Pt. Sc	
126. CM/L-2099762	90-04-10	Veena Enterprises Plot No. 61 Phase III Auto Nagar Vijaywada 520007	Rubber gasket for pressure cooker	IJ : 07466—74 Pt Sc	
127. CM/L-2099863	90-04-01	Narash Rubber Co. 86, IDC Mehrauli Road Gurgaon (Haryana)	Latex foam rubber products, grade A, C & E only.	IS : 01741—60 Pt Sc	
128. CM/L-2099964	90-04-01	Dcean Enterprises (P) Ltd. B/58, 59 & 60 APIE Bala Nagar Vallabh Nagar Talluk Distt. Rangareddy (AP)	Rubber sealing rings for gas mains, water mains and sewers, type 2 and type 3, Natural rubber only.	IS : 05382—85 Pt Sc	
129. CM/L-2100014	90-04-01	Om Shukthi Enterprises 151/44, Second Cross VIII Main Vasantha Nagar (West) Bangalore 560052	Synthetic Detergents for industrial purposes, type 3 only	IS : 04956—77 Pt Sc	
130. CM/L-2100115	90-04-01	Barauni Wax Products Pvt. Ltd. 41-D, Indl. Area Barauni Post Tijrath Begusarai 851112.	Paraffin wax, type 3	IS : 04654—74 Pt Sc	
131. CM/L-2100216	90-04-01	The Plantation Corpn. of Kerala Ltd. Vettilappai Estate Kalady Plantation (PO) Via Alwayae Ennnakulam Distt.	Ammonia preserved concentrated natural rubber latex, type HA	IS : 05430—81 Pt Sc	

1	2	3	4	5	6
132.	CM/L-2100317	90-04-01	Sanganeria Co. Pvt. Ltd. 5 Ahmed Mamoojee Street Liluah Howrah	Structural Steel (Standard Quality)	IS : 00226—75 Pt Sc
133.	CM/L-2100418	90-04-01	Bangalore Wire Rod Mills White Field Road Mahadev Pura Post Bangalore 560048	Carbon Steel wire rods, grade X, E, F, G and H	IS : 07974—74 Pt Sc
134.	CM/L-2100519	90-04-01	Bhopal Pesticides Shed No. 10, Indl. Estate, Govindpura Bhopal (MP)	Carbaryl 50% WDP formulation, Ground Spray Grade only	IS : 07121—73 Pt Sc
135.	CM/L-2100620	90-04-01	Punjab Pesticides Indl. Co-op. Society Ltd. Khanpur Khror Distt. Ropar (Punjab)	Aldrin 30% EC formulation	IS : 01307—82 Pt Sc
136.	CM/L-2100721	90-04-16	Sattar Sons Packaging Corpn. 1-7-69, Sarojini Devi Road Secunderabad 500003.	Corrugated fibreboard boxes for commercial high explosives	IS : 10212—86 Pt 01 Sc
137.	CM/L-2100822	90-04-16	Kumar Industries (Main Switch Division) Khasra No. 33/9 and 33/12 Bawana Road Samai Pur (Near Shahbad Village) Delhi 110042.	Composite units of air break switches and rewirable fuses	IS : 10027—81 Pt Sc
138.	CM/L-2100923	90-04-16	Dua brothers Street No. 12 Dashmesh Nagar Gill Road Ludhiana	230V, 750W thermostatic electric irons with cast iron base plate	IS : 00366—85 Pt Sc
139.	CM/L-2101016	90-04-16	Ashok Rubber Machines Bassi Road Sirhind (Punjab).	Hydraulically regulated Door closure, Universal type, size designation 2	IS : 03564—86 Pt Sc
140.	CM/L-2101117	90-04-16	Hind Metals Masjid Wali Gali Faiz Pura Road Batala (Punjab)	Reflux valves, both ends flanged of sizes 80 mm and 100 mm	IS : 10805—86 Pt Sc
141.	CM/L-2101218	90-04-16	North West Switchgear Ltd. 14/3, Mathura Road Faridabad 121003	250V, 5A, AC flush mounting switches for domestic and similar purposes excluding switches for AC inductive circuits	IS : 03854—66 Pt Sc
142.	CM/L-2101319	90-04-16	Kaushal Industries 12/65, Nagla Balchand Nunhai Agra 282006	Foot valves, 80 mm size, screwed end only	IS : 10805—86 Pt Sc
143.	CM/L-2101420	90-04-16	U.P. Asbestos Ltd. PO Mohanjai Ganj Distt. Lucknow 227305	Unplasticized PVC pipes class 1, 160 mm only class 2, 140 mm & 160 mm only.	IS : 04985—81 Pt Sc
144.	CM/L-2101521	90-04-16	MHI Cables & Conductors Pvt. Ltd. Old Hazari Bagh Road Ranchi 834001	Aluminium conductors, galvanized steel reinforced for extra high voltage (400 KV and above)	IS : 00398—82 Pt 05 Sc
145.	CM/L-2101622	90-04-16	Venkateshwara Agro Chemicals & Minerals Ltd. 37F Vellachery Main Road Vellacherry Madras 600042.	Carbendazim 50% mm WDP formulations (Repacking only)	IS : 08446—77 Pt Sc
146.	CM/L-2101723	90-04-16	Venkateshwara Agro Chemicals & Minerals Ltd. 37F, Vellacherry Main Road Vellacherry Madras 600042.	Fluchlorain 45% (mm) EC, repacking only	IS : 08959—78 Pt Sc

1	2	3	4	5	6
147. CM/L-2101824	90-04-16	Venkateshwara Agro Chemicals & Minerals Ltd. 37F, Vellacherry Road Vellacherry Madras 600042.		Tridemorph 20% mm EC repacking only.	IS : 09656—80 Pt Sc
148. CM/L-2101925	90-04-16	Venkateshwara Agric Chemicals & Minerals Ltd. 37F, Vellacherry main Road Vellacherry Madras 600042.		Cypermethrin 10% mm EC repacking only	IS : 12016—87 Pt Sc
149. CM/L-2102018	90-04-16	M & A Industries Manohar Pur Delhi Road Dankuni Distt. Hooghly (WB).		Teachest Metal Fittings	IS : 00010—76 Pt 04 Sc
150. CM/L-2102119	90-04-16	Deepthi Cements Pvt. Ltd. Thimma Sandra Village Maduri Hobbli Doddeballapura Taluk Bangalore Distt.		Ordinary portland cement	IS : 00269—76 Pt Sc
151. CM/L-2102220	90-04-16	Mohan Jute Bags Mfg. Co. 14 & 15, Urla Indl. Estate Raipur 493221		Laminated jute bags for packing fertilizers, manufactured from 407 GM Sq, 85 × 39 tarpaulin fabric.	IS : 07406—84 Pt 01 Sc
152. CM/L-2102321	90-04-16	Rao Insulating Co. Pvt. Ltd. White Field Main Road White Field Bangalore 560066.		Caps for tungsten filament general service electric lamps B-22/25 × 26	IS : 09206—79 Pt Sc
153. CM/L-2102422	90-04-16	Pagoda Cables (P) Ltd. 511/1 E4B Street No. 3 Vishwas Nagar Shahdara, Delhi 110032.		PVC insulated cables for working voltages upto and including 1100 volts, sheathed and unsheathed with aluminium & copper cond.	IS : 00694—77 Pt Sc
154. CM/L-2102523	90-04-16	The National Insulated Cable Co. of India Ltd. Sham Nagar PO, Athpur Distt. 24 Parganas		PVC insulated winding wires for submersible motors for 85 C operation.	IS : 08783—78 Pt Sc
155. CM/L-2102624	90-04-16	United Cables 162, GIDC Umber Gaon Distt. Valsad (Gujarat)		PVC insulated unsheathed/sheathed cables with copper conductors for working voltages upto and including 1100V	IS : 00694—77 Pt Sc
156. CM/L-2102725	90-04-16	United Cables 162, GIDC Umber Gaon Distt. Valsad (Gujarat)		PVC insulated (Heavy duty cables) suitable for working voltages upto including 1100 Volts, Armoured/unarmoured	IS : 01554—76 Pt 01 Sc
157. CM/L-2102826	90-04-16	Smruti Cables Industries 26/A, Satnam Estate Nagarwal, Hanuman Road Rakhiyal, Ahmedabad		PVC insulated sheathed/unsheathed cables for working voltages upto and including 1100V with copper or aluminium conductors	IS : 00694—77 Pt Sc
158. CM/L-2102927	90-04-16	Meritco India Ltd. 71/4, Nazafgarh Road New Delhi 110015.		230V, 750W, Thermostatic electric iron with cast iron base plate	IS : 00366—85 Pt Sc
159. CM/L-2103020	90-04-16	Pushpa Agencies TP N. 214 Devar Jeevana Halli Bangalore 560045		Cotton yarn waste	IS : 05485—80 Pt Sc
160. CM/L-2103121	90-04-16	The Elgin Mills Co. Ltd. 11/6, Shrimati Parbati Bagla Rd. Copper Ganj Kanpur 208001.		Cotton Drills	IS : 00177—77 Pt Sc



1	2	3	4	5	6
161. CM/L-2103222	90-04-16	Hyderabad Chemicals Supplies Pvt. Ltd. A-24/25, Assisted Pvt. Indl. Estate Bala Nagar Hyderabad 500037.	Carbendazim (MBC) 50% mm WDP concentrate formulation	IS : 08446—67 Pt Sc	
162. CM/L-2103323	90-04-16	Mehsana Tin Factory 21, GIDC Indl. Estate Highway Road Mehsana 384002.	18 litre square tins open mouthed only	IS : 00916—75 Pt Sc	
163. CM/L-2103424	90-4-16	Super Sonic Indl. Complex Centrifuged Latex Unit Perumballoor PO Muvattupuzha Distt. Enrakulam (Kerala).	Ammonia preserved concentrate, Natural Rubber latex, grade HA	IS : 05430—81 Pt Sc	
164. CM/L-2103525	90-04-16	The Kerala Ceramics Ltd. (Kaolin Division) Kundara Quilon 601501	Light Kaolin, grade 1 (for paper coating industry only) grade 2 & grade 3 only)	IS : 00505—78 Pt Sc	
165. CM/L-2103626	90-04-16	Lal Chand Anand & Sons 13/1, Bulandshahr Road Ghaziabad (UP)	Salt glazed stoneware pipes of sizes upto and including 300 mm, grade A	IS : 00651—80 Pt Sc	
166. CM/L-2103727	90-04-16	Delhi Iron & Steel Co. Ltd. G.T. Road Ghaziabad (UP)	High strength deformed steel bars and wires for concrete reinforcements of sizes 8mm upto and including 32 mm, grade Fe 415	IS : 01786—85 Pt Sc	
167. CM/L-2103828	90-04-16	Jindal Iron & Steel Co. Ltd. B-6, Tarapur Indl. Area Navapur Road Boisar 401506	Continuously cast ingots for rolling into structural steel	IS : 06914—78 Pt Sc	
168. CM/L-2103929	90-04-16	Purbanchal Sacks (P) Ltd. A.T. Road Jalan Nagar Dibrugarh (Assam)	Laminated jute bags, manufactured from 407 G/M sq 85 × 39 tarpaulin fabric	IS : 07406—84 Pt 01 Sc	
169. CM/L-2104022	90-04-16	Purbanchal Sacks (P. Ltd. A.T. Road Jalam Nagar (N) Dibrugarh (Assam)	Laminated Jute bags, manufactured from 380 G/M sq 68 × 39 tarpaulin fabric	IS : 07406—86 Pt 02 Sc	
170. CM/L-2104123	90-04-16	Pratap Plastics Ltd. 1, Kundan bye Lane Liluah Howrah	Laminated Jute bags for packing fertilizers manufactured from 407 G/M sq 85 × 39 tarpaulin fabric	IS : 07406—84 Pt 01 Sc	
171. CM/L-2104224	90-04-16	Punjab Anand Lamps Industries Ltd. Indl. Focal Point Phase 19, Sas Nagar Distt. Ropar	Tubular fluorescent lamps for General lighting service, 36W, 220 V, 6500 K GH3 bi-pin caps to be used with starter	IS : 02418—77 Pt Sc	
172. CM/L-2104325	90-04-16	Kapsons International (I) Sodal Road Sahi pur Industries Area Jalandhar 144004	Gun metal gate valves class 1, screwed end size 15mm upto and including 50 mm	IS : 00778—84 Pt Sc	
173. CM/L-2104426	90-04-16	Best & Crompton Engg. Ltd. 781, Thiruvottiyur High Road Madras 600081.	Mono pumps for clear, cold, fresh water for Agricultural purposes	IS : 09079—89 Pt Sc	
174. CM/L-2104527	90-04-16	Asiatic Oxygen Ltd. 26, 27, 28, Fore Shore Road Shibpur Howrah	Manual blow pipe for welding (high pressure) and manual blow pipe for cutting (low pressure)	IS : 07653—75 Pt Sc	
175. CM/L-2104628	90-04-16	Roadmaster Steel Strips Ltd. Village Dhalwala Munikireti Indl. Area Rishikesh 249201.	Cold rolled low carbon steel sheets and strips	IS : 00513—86 Pt Sc	

1	2	3	4	5	6
176. CM/L-2104729	90-04-16	Mex switchgears Pvt. Ltd. 19th Kilometer Pathankot Road Post Box No. 52. Jalandhar	Composite units of air break switches and rewirable type fuses for voltages not exceeding 650 V AC, 32 A	IS : 10027—81 Pt Sc	
177. CM/L-2104830	90-04-16	Shivas Industries Indra Mill Compound Jeoni Mandi Agra 282004	Foot valves, nominal size 80 mm, screwed ends, painted variety only	IS : 10805—86 Pt Sc	
178. CM/L-2104931	90-04-16	Maharashtra Cable Industries Shed No. 1 49/2, Indl. Area Kamal Manufacturing compound Main Road Ulhasnagar 421004	PVC insulated unsheathed/sheathed cables for working voltages upto and including 1100V with copper conductors	IS : 00694—77 Pt Sc	
179. CM/L-2105024	90-04-16	Control Cable Industries 14-22/A, Ansa Indl. Area Saki Vihar Road Bombay 400072	PVC insulated unsheathed/sheathed cables for working voltages upto and including 1100V with copper or aluminium conductors	IS : 00694—77 Pt Sc	
180. CM/L-2105125	90-04-16	Anu Cables Village Gagwana Distt. Ajmer (Rajasthan)	Aluminium stranded conductors for overhead transmission purposes	IS: 00398—76 Pt 01 Sc	
181. CM/L-2105226	90-04-16	PVP Ltd. 95, Indl. Area Jhotwara Jaipur 302102	Flexible packs for packing of Vanaspati 1/2 kg and 1 Kg pack	IS : 11352—85 Pt Sc	
182. CM/L-2105327	90-04-16	Hemanta Electricals Pvt. Ltd. NH No. 12 Village Kikila Pura PO Sheodaspura Sheodaspura 303903	Aluminium conductors galvanized steel reinforced for overhead transmission purposes	IS : 00398—76 Pt 02 Sc	
183. CM/L-2105428	90-04-16	Laser Cables Pvt. Ltd. 8, Girish Ghose Road Patipukur Calcutta 700048	PVC insulated sheathed or unsheathed cables for working voltages upto and including 1100 V with copper or aluminium conductors	IS : 00694—77 Pt Sc	
184. CM/L-2105529	90-04-16	Dunlop India Ltd.) PO Saha Ganj Distt. Hooghly (WB)	Truck, Bus and light truck tyres	IS : 10914—88 Pt 02 Sc	
185. CM/L-2105630	90-04-16	Laser Cables Pvt. Ltd. 8, Girishchandra Ghose Road Patipukur Calcutta 700048	PVC insulated (Heavy Duty) cables for working voltages upto and including 1100 V, unarmoured with copper conductor	IS : 01554—76 Pt 01 Sc	
186. CM/L-2105731	90-04-16	Orissa Plastic Processings Ltd. O.T. Road Balasore 756001.	UPVC pipes for potable water supplies, 63mm to 110mm, class 3	IS : 04985—81 Pt Sc	
187. CM/L-2105832	90-04-16	Jagdish Engg. Industries Plot No. 377, GIDC Aji Indl. Estate Rajkot 360003	Monoset pumps	IS : 09079—79 Pt Sc	
188. CM/L-2105933	90-04-16	Tripdent Tubes Ltd. C-22/25, Hazipur Indl. Area Hazipur Distt. Vaishali (Bihar)	HDPE pipes for Potable water supplies sewage and industrial effluents	IS : 04984—87 Pt Sc	
189. CM/L-2106026	90-04-16	Sree Barat Industries Sreenivasapuram 95 N, Coimbatore Main Road Avanashi 638654	Submersible pumpsets for clear, cold fresh water.	IS : 08034—76 Pt Sc	
190. CM/L-2106127	90-04-16	Jagdev Mechanic Works Sham Nagar Patiala Road Rajpura (punjab)	Door Closure (Hydraulically regulated) size designation 2, Universal type	IS : 03564—86 Pt Sc	

1	2	3	4	5	6
191. CM/L-2106228	90-04-16	Bhoruka Engineering Industries Ltd. Mahadevpura Post Whitefield Road Bangalore 560048.	Steel core wire for ACSR	IS : 03398-76 Pt 02 Sc	
192. CM/L-2106329	90-04-16	Nagrath Paints (P) Ltd. 46, Fazal Ganj Kanpur 208012	Ready mixed paint, air drying, red-oxide zinc chrome, priming	IS : 02074—79 Pt Sc	
193. CM/L-2106430	90-04-16	Nagrath Paints (P) Ltd. 46, Fazal Ganj Kanpur 208012.	Aluminium paints for general purposes, in dual container	IS : 02339—63 Pt Sc	
194. CM/L-2106531	90-04-16	Nagrath Paints (P) Ltd. 46, Fazal Ganj Kanpur 208012.	Synthetic Enamel, interior finishing only	IS : 00133—75 Pt Sc	
195. CM/L-2106632	90-04-16	Nagrath Paints (P) Ltd. 46, Fazal Ganj Kanpur 208012.	Varnish, Finishing, exterior, synthetic air-drying	IS : 00524—83 Pt Sc	

[No. CMD/13 : 11]

का.भा. 447:—भारतीय मानक भूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 4 के उपविध 5 के अनुसरण में भारतीय मानक भूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिये गये हैं, वे स्वीकृत कर दिये गये हैं:

## अनुसूची

क्र. सं.	लाइसेंस संख्या	लागू होने की अवधि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तु/प्रक्रम और सम्बद्ध भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सी एम/एल-2130023	90-07-16	मै. रतन साहूको न्यूट्रिफेन्ट प्रा. लि., मुन्वैन गंज, लखनऊ-रायबरेली रोड, रायबरेली	जिक सल्फेट, कृषि ग्रेड आई एस : 08249-1974
2.	सी एम/एल-2130174	90-07-16	तारामानिक केबल्स प्रा. लि., एफ-118 सेक्टर 8, नौगडा	7 लड़ तक एसीएसभार बालक आई एस : 00898-76 (भाग 1)
3.	सी एम/एल-2130223	90-07-01	बन्दरनगर कैमीकल्स एंड मिनेरल्स प्रा. लि., बन्दरनगर, ग्राम सिलकोरा, गुड़गांव	वनस्पति तेलों के विरंजन के भारतीय मूल की विरंजक मृदा आई एस : 01965-72
4.	सी एम/एल-2130326	90-07-16	रिलायन्स इंजीनियरिंग प्रा. लि., 118/ए-1 आसबेस्वर इंडस्ट्रियल एस्टेट, पीनया II स्टेज, बंगलौर-560058	निमज्जय मोटर के वाइडिंग हेतु तांबा बालकों सहित पीवीसी रोहित बेल्डम तार रोधन टाइट 5 मोटार्ड ग्रेड 1 आई एस : 08783-79
5.	सी एम/एल-2130427	90-07-16	रायसोमी इंजीनियरिंग वर्क्स ए/91 इंडस्ट्रियल एस्टेट जलगांव पिन 425003	कृषि प्रयोजनों के लिये साफ ताजे टंडे पानी हेतु मोमोसेट पम्प आई एस : 09079-79
6.	सी एम/एल-2130528	90-07-16	एमबीएच पम्पस लि 3 भीरा काप इंड. एस्टेट दाहेसर चौक बाकामिरा, जिला ठाणे-401104	निमज्जय मोटर के लिये मोटर 3. 7 किवा संवर्ध बी, बेट टाइट आई एस : 09283-79
7.	सी एम/एल-2130629	90-07-16	श्री विप्लव इंजीनियरिंग कं., 1095 प्रविताशी रोड, पीएन पलास-कोयम्बतूर	निमज्जय मोटर के लिये मोटर 9. 3 किवा, संवर्ध बी बेट टाइट आई एस : 09283-79
8.	सी एम/एल-2130730	90-07-16	नंदी इंडस्ट्रीज, 51 पी एन बलायम रोड, के. आर. पुरम गणपति, कोयम्बतूर पिन-641006	कृषि उपयोगों के लिये लीम फेजी स्विपरिस पिजरी प्रेरण मोटर अपकेन्डी पम्प आई एस : 07533-75

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9. सी एम/एल-2130831	90-07-16	म्योर सेफ ग्लास बर्कर्स प्रा. लि. जलमुरा महेश तला, जिला 24 परगना	प्रायः कीकृत निरापद कांच, बिड स्क्रीन उपयोगों को छोड़कर] आई एस : 02563—71	
10. सी एम/एल-2130932	90-07-16	नार्थ ब्रुक जूट कं. लि., विद्यावती, चम्पनेनी, हृण्णी (प. बं.) पिन-712221	सीमेंट पैकिंग के लिये पटसन के कट्टे] आई एस : 02500—82	
11. सी एम/एल-2131023	90-07-16	पशुपति उद्योग लि., नेशनल हाईवे आ-गजंगलपुर जि-अंजुलमूरी, हावड़ा	केवल कवचन के लिये जस्ती कृत इस्पात के टप आई एस : 3975—83	
12. सी एम/एल-2131126	90-07-16	पाइनीयर सैटल इंडस्ट्रीज, सी-4 इंडस्ट्रियल एस्टेट भारसुगुडा जिला-सम्बलपुर-768205	एल्यूमिनियम मिश्र धातु के लड़दार चालक आई एस : 00398—79	
13. सी एम/एल-2131328	90-07-16	फूजी लैम्पस चप्पा निकाड बाया चिनाबनम, जि. कोट्टायम (कोरल)-686533	जीएलएस बल्ब, 250 बो, 100 वा तक रेटिंग आईएस : 00418-78	
14. सी एम/एल-2131328	90-07-16	सोनी लैम्पस सैल्यू कं., कुङ्कुटी, अनंगमैली जिला अर्नाकुलम-683576	जीएलएस बल्ब, 520 बो, 40 वा रेटिंग आई एस : 00418—78	
15. सी एम/एल-2131429	90-07-16	जयश्री केबल एंड इंजी. वर्क्स, कंजनबियूर जिला-गोमूर मेट्टूर डेम-636404 है	1100 वत तक कार्यकारी बोस्टता के लिये पीबीसी रोहित हैवी इयूटी बिजली की केबल आई एस : 01554—76(भाग 1)	
16. सी एम/एल-2131580	90-07-16	किसान फ्लास्टिक (प्रा.) लि., बेन्नूर रोड, चिन्तामणि जिला-कोलार (कर्नाटक)-563125	अप्लास्टिक पीवीसी पाइप, श्रेणी 3 110 मिमी तक] आई एस : 04985—81	
17. सी एम/एल-2131631	90-07-16	एच. के. मन्दिर एंड कं., वेस्ट पटेल नगर के सामने, आई दिल्ली-110008	रोगन और वानिश के लिये बुश, चपटे साइज 100 मिमी आई एस : 00384—79	
18. सी एम/एल-2131732	90-07-16	खटाऊ जुकर लि., प्लाट नं. 3000, जीआईडीसी, अंकलेश्वर	मैलाधियान 50% ईसी फार्मेशन आई एस : 02567—78	
19. सी एम/एल-2131833	90-07-16	किलास्कर ब्रदर्स लि., उज्जैन रोड, रेलवे स्टेशन के सामने देवास-453001	मिमज्जय पम्पसेट के लिये मोटर] आई एस : 9283—79	
20. सी एम/एल-2131934	90-07-16	भारय इक्वुपमेंट्स मेन रोड, गणपति कोयम्बतूर-641006	ट्रिवल टाइप जैट अपकेन्ट्री पम्प संयोजन] आई एस : 12223—87	
21. सी एम/एल-2132027	90-07-16	जिन्दल (इंडिया) लि., 4 धरमतला रोड, डा. बेन्नूरमट, जिला हावड़ा (प. बं.)	आईडलर और पट्टा कनवेयर के लिये इस्पात की नलियां आई एस : 09295—83	
22. सी एम/एल-2132128	90-07-16	बोल्गा फ्राटो एसेसरीज, 126 भारत नगर, शाहपुर बेलगाम-590009	मोपेड, स्कूटर और मोटर साइकिल के लिये रस्ती हैनमेट आई एस : 04151—82	
23. सी एम/एल-2132229	90-07-16	निरान टिन इंडस्ट्रीज द्वारा उमेश इंजी. वर्क्स प्लाट नं. 196/8, बापी पेपर मिल के पास, जी आई डीसी, बापी (गुजरात)	बी, बनस्पति और खाद्य तेलों और श्रेकरी मोयन के लिये 15 कि. ग्रा. के चौकोर कनस्तर आई एस : 10325—87	
24. सी एम/एल-2132330	90-07-16	बामोदर सीमेंट एंड स्लैग लि., मधुकुंडा, पोस्ट-मुनूरी, जिला-पुछलिया (प. बं.)	पोर्टलैंड धातुमल सीमेंट] आई एस : 03455—76	
25. सी एम/एल-213431	90-07-16	मंजू इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज लि., 12 किमी पोलबी रोड, मुलामचाम पट्टी, कोयम्बतूर-641021	साफ ठंडे, ताजे पानी के लिये निमज्जय पम्प सेट आई एस : 08034—76	
26. सी एम/एल-2132532	90-07-16	श्रीनिवास पाउन्ड्री, अमीनाकुलम रोड, पीएन पलायम, कोयम्बतूर-641037	जैट अपकेन्ट्री पम्प संयोजन आई एस : 12225—87	
27. सी एम/एल-2132633	90-07-16	यूनिवर्सल इंजीनियर्स, 14 मानुपुम्बल, इंड. एस्टेट, इन्ड्रानगर के पास, अमरायवाडी, अहमदाबाद-380026	साफ, ठंडे, ताजे पानी के लिये निमज्जय पम्प सेट] आई एस : 08034—87	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28. सी एम/एल-2132734	90-07-16	पारखी एप्रो इक्वीपमेंट्स, विख्या पार्क, सोसायटी रामजी मंदिर के पास, निकोल-नरोडा रोड, अहमदाबाद-382350	हस्त चालित धूर्णी पीठ पर लादी जाने वाली भूरकाव यंत्र आई एस: 05135-74(भाग 1)	
29. सी एम/एल-2132835	90-07-16	जय किशन वाम मल जूट प्राइवेट प्रा. लि., रूपसा, जिला-बालासोर (उड़ीसा) पिन-756028	पटसन की सूतली किस्म 2.7 और 8 आई एस: 01912-84	
30. सी एम/एल-2132936	90-07-16	बाम्बे फूड्स प्रा. लि., अटरगाम, सुरत-395004	गोबर गैस झूलहा आई एस: 8749-78	
31. सी एम/एल-2133029	90-07-16	भारत टिन इंडस्ट्रीज, ग्रा-पहाड़कलां, बंडीगढ़ रोड, राजपुरा (पंजाब)	घी, वनस्पति, खाद्य तेल और बेकरी मोयन के लिये 15 कि.ग्रा. के चौकोर कनस्तर आई एस: 0325-89	
32. सी एम/एल-2133130	90-07-16	टाप प्राइवेट्स हस्तीन नगर, गुंजारी, घनेरा तानुक, ग्रा-खोमत जिला-बनासकांठा-385545	पत्र कुडस मिठाइयाँ (इंजेस) आई एस: 09806-78	
33. सी एम/एल-2133231	90-07-16	ग्रामन्द कैमिकल्स वर्क्स, 185-186 एनसीएसी इंड., एरिया तपुजाना, हटिया, रांची-834003	एल्यूमिनो फेरिक, ग्रेड 2, केवल आई एस: 00299-80	
34. सी एम/एल-2133332	90-07-16	ए. के. मैन्यु. प्रा. लि., नीलरकुटी, इम्फाल, मणिपुर	घी, वनस्पति, खाद्य तेल और बेकरी मोयन के लिये 15 कि.ग्रा. के चौकोर कनस्तर आई एस: 10325-89	
35. सी एम/एल-2133433	90-07-16	ग्रामिका कंडक्टर्स प्रा. लि., 4 और 5 ए मालवीय इंड. एरिया, जयपुर-302017	शिरोपरि प्रेषण के लिये एसीएसआर बालक आई एस: 00398-76(भाग 1)	
36. सी एम/एल-2133534	90-07-16	बंडारी केबल्स प्रा. लि., एन.एच. रोड नं. 12, ग्रा-कलकीपुर, डा. शिवदासपुर जयपुर-303903	शिरोपरि प्रेषण के लिये एसीएसआर बालक आई एस: 00398-76(भाग 1)	
37. सी एम/एल-2133535	90-07-16	फेलकन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स प्रा. लि., खसरा नं. 358 ग्रा-आली, मथुरा रोड, बवरपुर, नई दिल्ली-110044	1100 तक कार्यकारी बोल्टता के लिये पीवीसी रोधित केवल आई एस: 00694-77	
38. सी एम/एल-2133786	90-07-16	देवीदास गोपाल कृष्ण लि., गांधी रोड, भोगा जिला फरीदकोट	मिश्रित पशु आहार टाइप 2 केवल आई एस: 02052-79	
39. सी एम/एल-2133837	90-07-16	एशिएटिक कंडक्टर्स वर्क्स, सी-236 इंडस्ट्रियल एरिया बुलन्दशहर रोड, गाजियाबाद	7 लड़ तक एसीएसआर बालक आई एस: 0398-74	
40. सी एम/एल-2133938	90-07-16	अग्रवाल एप्रो इंडस्ट्रीज, ग्रा-भुसीपुरा, भोगा लुधियाना, जी टी रोड, भोगा-142001	मिश्रित पशु आहार, टाइप 2 केवल आई एस: 02052-79	
41. सी एम/एल-2134031	90-07-16	इन्सूलन बाष्पा फॉबर मिल, ग्रा. आमापुर, डा. सारनाथ, जिला-वाराणसी (उ.प्र.)	मिश्रित पशु आहार, टाइप 2 केवल आई एस: 2052-79	
42. सी एम/एल-2134132	90-07-16	अर्बित केबल्स प्रा. लि., पो. बाक्स नं. 104, एम आईडीसी मोमारी पुणे-411026	मोटर वाहनों के लिए तांबा चालने वाली एक कोड वाली पीवीसी रोधित केवल आई एस: 2465-84	
43. सी एम/एल-2134233	90-07-16	हाम स्टार इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लि., बी-41 सैक्टर-4, नोएडा	अवश मझार, टाइप हीटर, 25 लिटर धारिता आई एस: 2082-85	
44. सी एम/एल-2134334	90-07-16	एम्डी सीमेंट प्रा. लि., डा. कल्याणपुर, ग्रा.: उदयपुर, जिला: धनबाद (बिहार)	साधारण पोर्टलैंड सीमेंट आई एस: 2269-78	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
45. सीएम/एल--2134435	90-07-16	किसान फिल्टर्स प्रा. लि., ग्राम : सैबपुर, सहस्रोल: बेराबासी, जिला पटियाला (पंजाब)	मिश्रित पशु आहार, टाइप 2 केवल आईएम : 2032--79	
46. सीएम/एल--2134536	90-07-16	केरल सोल्वेंट एक्स्ट्रैक्शन लि., 228 साल्वेस्ट रोड, हरिजनलकुडा (केरल) 680121	मिश्रित पशु आहार, टाइप 2 केवल आईएम : 2052--79	
47. सीएम/एल--2134637	90-07-16	सैक्स कोराना इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंट प्रा. लि., गोपालपुर ग्राम, बाहरी रिंग रोड, दिल्ली	जलमय बताने के लिए मीमेंट में मिलाया जाने वाला यौगिक (पूर्ण रूप में) आईएम : 02645--75	
48. सीएम/एल--2134733	90-07-16	साकरी इलेक्ट्रिकल प्रा. लि., बुन्वावन कोटान्थ तिरुवेल्ला (केरल) 689615	घरेलू और ऐसीही प्रयोजनों के लिए स्विच, पलश टाइप, 5 एम्प, 250 वा एम्पी केवल आईएम : 03354--83	
49. सीएम/एल--2134859	90-07-16	फैरोकोन, मोहाबी बाला इंडस्ट्रियल एरिया, सहारनपुर रोड, बेहराटून	पूर्व ठले भेनहोल के कंक्रीट के गोल चौकोर और घायताकार टाइप के बकन, हुल्का, मध्यम और और हवी ड्यूटी आईएम : 09356--80	
50. सीएम/एल--2134940	90-07-16	एसीआई (एग्रो कैंमिकल इंडस्ट्रीज) प्रा. लि., पूनामेली घावडी रोड, कोम्पेटी, मद्रास-600077	ब्यूटाकलोर ईसी आईएम : 09356--80	
51. सीएम/एल--2135033	90-07-16	प्रोमियर हो एक्वाइसिज, क्रम संख्या 245/2 जी.एन.टी. रोड, पेट्टी कूपन, चम्पे इण्ड्री-601201	द्रवित पेट्रोलियम गैस के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस बल्बा आईएम : 04246--86	
52. सीएम/एल--2135134	90-07-16	एस.एन. कैमकल्स इंडस्ट्रीज, बी-35, गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल एस्टेट, महरोली रोड, गुडगांव-122001	मिथाइल पैराथियान ईसी आईएम : 02865--78	
53. सीएम/एल--2135235	90-07-16	गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, पेस्टीसाइड्स फार्मूलेशन यूनिट, आई टी आई के पास, एन. एच 88, गोडल-360311	मोनोकोटोफॉस, एस एल आईएम : 08074--83	
54. सीएम/एल--2135326	90-07-16	ब्रिजकुटैबसटाइल, 68 खैबर पास, सिबिल लाइन्स, दिल्ली	बाब सवेरी आसंजी कपड़ा टेप आईएम : 03887--77	
55. सीएम/एल--2135437	90-07-16	नवलखा एग्रो इन्फ्रामैन्ट्स, 38 शंकरनाथ सेट रोड, पुणे-411037	पैडल वालित धाम के और, एक व्यक्ति द्वारा जालित टाइप आईएम : 03327--82	
56. सीएम/एल--2135533	90-07-16	सोलर मिडिकेट, इंगरी, जिला बलसाड़-396375	कार्बोहाजिम डब्ल्यू.डीपी आईएम : 03446--77	
57. सीएम/एल--2135639	90-07-16	इलेक्ट्रो फैब्रिक, शेड नं. 5, इंडस्ट्रियल एरिया, डा. बीहीकल फॅक्ट्री, रिचार्ड, जयलपुर-482009	पावर और शर के लिए सुरक्षा अपेक्षाएं 3.7 किवा 5 अश्वशक्ति आईएम : 09020--79	
58. सीएम/एल-2133740	90-07-16	एन.एन. कैमिकल्स इंडस्ट्रीज, बी-125, गवर्न. इंड. एस्टेट, महरोली रोड, गुडगांव-122001	कार्बोहाजिम डब्ल्यू.डीपी आईएम : 03446--77	
59. सीएम/एल --2133841	90-07-16	गुजरा एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, रनिया रोड, सिरसा-125055	पावर और शर के लिए सुरक्षा अपेक्षाएं 3.7 किवा (5 अश्वशक्ति) आईएम : 09020--79	
60. सीएम/एल --2133942	90-03-17	कांटीमोटर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, ई-3, मार्बर्न इंड. एस्टेट, बहादुरगढ़-124507	एक फेज, दो तार, सम्पूर्ण धारा, वाट घटा मोटर आईएम : 00722--77 (भाग 2)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
61. सीएम/एल--2136035	90-08-01	मनाशी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज नं. 8, जॉ टी करनाल रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110033	पानी गर्म करने का बिजली का निमज्जय हीटर, 1000 वा, 230 एसि आईएस : 00368--83	
62. सीएम/एल--2136136	90-08-01	इंडियन ह्यूमस पाइप कं. लि., करारी, सांसि	गैर वेल्डनाकार पूर्व प्रतिलबलित कंक्रीट पाइप आईएस : 03784--78	
63. सीएम/एल--2136337	90-08-01	सीएट टायर्स प्राफ इंडिया लि., 82 एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, मातपुर, नासिक-422007	ट्रक, बस लाइट ट्रक टायर, विकर्ण प्लार्ड टायर आईएस : 10914--83 (भाग 2)	
64. सीएम/एल--2136333	90-08-01	जय इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज यूनिट नं. 24, नूतन कैमीकल कंपाउंड, सैकेण्ड फ्लोर, बालभाट रोड, गोरेगांव (प), बम्बई-400062	तीन पिन सॉकेट घाउटलेट, 5 और 15 एम्प, 250 वा, फलम टाइप आईएस : 01293--88	
65. सीएम/एल--2136439	90-08-01	एस. कुमार लि., 3-ए इंडस्ट्रियल एरिया नं. 2, ए.बी. रोड, वेवास	पॉलिएस्टर मिश्रित कमीज का कपड़ा आईएस : 09317--86	
66. सीएम/एल--2136540	90-08-01	प्रोग्रेसिव सीमेन्ट लि., इंड. एरिया, पालाडे, जिला झुजारीबाग-829119	पोर्टलैंड धातुमल सीमेन्ट आईएस : 00455--76	
67. सीएम/एल--2136641	90-08-01	मकाली इजीनियरिंग वर्क्स, भमटा रोड, बाल्टी कुरी, हावड़ा	जल, गैस, मलजल के लिए क्षतिज 6ल लोह के दुहरा फ्लैज वाले पाइप आईएस : 07181--74	
68. सीएम/एल--2136742	90-08-01	शिल्पा रिरोलर्स प्रा. लि., प्लाट नं. 3, बंजारा लेखाउट कामटी रोड, नागपुर	संरचना इस्पात (मानककिस्म) आईएस : 00226--75	
69. सीएम/एल--2136843	90-08-01	किशन चन्द एंड संस, डी-9 कृष्णानगर, दिल्ली-110051	हथकरघे का पट्टी का कपड़ा गैर निजीमत आईएस : 00363--88	
70. सीएम/एल--2136944	90-08-01	टेक्नोमैटिक, 35 मरिजव लेन, जंगपुर भोशाल मार्केट, मई दिल्ली-110014	तापस्थापी बिजली की इस्तारिया आईएस : 0366--83	
71. सीएम/एल--2137037	80-08-01	जैन इंडस्ट्रीज लाइटिंग कारपोरेश, बी-70/22 डीएसआईडीसी कामलेक्स, लारेंस रोड, दिल्ली	सजावटी लाइटिंग घाउटफिट, भवनों के आन्तर प्रयोग के लिए उपयुक्त आईएस : 05077-69	
72. सीएम/एल--2137133	90-08-01	शिल्पा रिरोलर्स प्रा. लि., प्लाट नं. 3, बंजारा लेखाउट कामटी रोड, नागपुर	कंक्रीट प्रबलन के लिए उच्च इस्पात सामर्थ्य के लिए सरिये और तार	
73. सीएम/एल--2137239	90-08-01	मकाली इजीनियरिंग वर्क्स, भमटा रोड, बाल्टीकुरी, हावड़ा	जल, गैस और जल-मल के लिए दाब पाइप हेतु सीआई पाइप फिटिंग, कालर केवल आईएस : 01533--76	
74. सीएम/एल--2137340	90-08-01	मकाली इजीनियरिंग वर्क्स, भमटा रोड, बाल्टीकुरी, हावड़ा	जल, गैस और मल-जल के लिए उष्माक्षर ढले लोहे के दाब पाइप आईएस : 01537--76	
75. सीएम/एल--2137441	90-08-01	वि असम ट्यूब्स लि., अमीन गांव, गुवाहाटी-781031	कंक्रीट प्रबलन के लिए उच्च सामर्थ्य इस्पात सरिये और तार आईएस : 01786--83	
76. सीएम/एल--2137542	90-08-01	पोलर फैब इंडस्ट्रीज लि., 167, ब्रह्म समाज रोड, कलकत्ता-700060	छत के बिजली के पंखे और रेगुलेटर आईएस : 00374--79	
77. सीएम/एल--2137643	90-08-01	इलेक्ट्रोटेक इंडस्ट्रीज, 79 जेसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, कामा का पुर रोड, 11 वां किमी, बंगलौर-560062	अचल, भंडारण टाइप पानी गर्म करने के बिजली का हीटर आईएस : 02082--85	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
78. सीएम/एल—2137744	90-08-01	साउथ इंडिया स्टील इंडस्ट्रीज, प्रा. लि., प्लाट फील्ड रोड, बंगलोर-560066	कंक्रीट प्रबलन के लिए उच्च सामर्थ्य इस्पात के सरिफ और तार आईएस : 01786—85	
79. सीएम/एल—2137845	90-08-01	हिन्दू स्टील, एन-73, एम आईडीसी, हिंगाना, नागपुर	संरचना इस्पात (मानक इस्पात किस्म) आईएस : 00226—75	
80. सीएम/एल—2137946	90-08-01	महाराष्ट्र वेल्डेड इंडस्ट्रियल एरिया, कमलेश्वर, नागपुर (महाराष्ट्र)	धातु भार्क वेल्डेड हेतु आवरित इन्वेट्रोड आईएस : 03814—74 (भाग 1)	
81. सीएम/एल—2133039	90-08-01	शारदा होमएप्लाइड सेज (प्रा.) लि., 1/118, पुराना महावलीपुरम रोड, सेवाराग गांव, वेरुगुडी, मन्नारम-600096	ड्र. वे. गैस के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस धूलहा आईएस : 04246—84	
82. सीएम/एल—2133140	90-08-01	धमीजा इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, साइट ए, बाइ पास, मथुरा	मल के लिए साकेट और स्पिंगट सिरों सहित बलवां लोहे के पाइप आईएस : 01729—79	
83. सीएम/एल—2133241	90-08-01..	भूमि सुधार कैमोकल्स इंडस्ट्रीज, 7-ए फोकल प्लाट, इंडस्ट्रियल एरिया, संगरूर-148001	कृषि ग्रेड जिक सर्फेट आईएस : 08249—76	
84. सीएम/एल—2139342	90-08-01	बिन्दल एप्रो कैम लि., प्लाट नं. 19, न्यू इंडस्ट्रियल एरिया, मंडी दीप, जिला रायसेना-462046	खाद्य तेलों और वनस्पति की पैकिंग के लिए नम्य पैक आईएस : 11352—83	
85. सीएम/एल—2138443	90-08-01	यूनियन इंडिया लि., एफ-127, सेक्टर 8, मोएडा, जिला गाजियाबाद	जल आपूर्ति के लिए पीबीसी पाइप	
86. सीएम/एल—2136544	90-08-01	यूनिवर्सल इंजीनियर्स, 13-14, मेनुपनबाल, इंडस्ट्रियल एस्टेट, इन्फानगर के पास, भमरायबाड़-380026	निमज्जय पम्प के मोटर संवर्ग बी आईएस : 09283—79	
87. सीएम/एल—2138645	90-08-01	डाटा केबल्स प्रा. लि., केन्द्र इंडस्ट्रियल एरिया, डा. गोविन्दपुर, धनबाद	उष्मा प्रतिरोधी इलेक्ट्रोमर आईएस : 09968—81 (भाग II)	
88. सीएम/एल—2133746	90-08-01	वि ब्रिटिश मशीनरी सप्लायर्स कं., 17-ए इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू टाउनशिप, फरीबाबाद-120001	घरेलू कार्यों के लिए सिलार्ड मशीन, हस्त चालित	
89. सीएम/एल—2138847	90-08-01	लीडरलैम्प, एंड इलेक्ट्रिकल्स वेल्नूर चारवेल्लूर लि. त्रिचूर (केरल)-680321	टंगस्टन फिलामेंट, 230 बोल्ट, 100वा आईएस : 00418—78	
90. सीएम/एल—2138948	90-08-01	विमाइल ट्यूब्स प्रा. लि., सी-19, यूपी एस आईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, जिला मथुरा	जल आपूर्ति के लिए पीबीसी पाइप आईएस : 04985—81	
91. सीएम/एल—2139041	90-08-01	जय सिलिन्डर्स लि., ए-30, इंडस्ट्रियल एरिया, सिकन्दाबाद (उ.प्र.)	5 लिटरधारिता के ग्रुप इस्पात कार्बन वेल्डित गैस सिलिन्डर आईएस : 01610—81	
92. सीएम/एल—2139142	90-08-01	पाल ब्रदर्स एंड कं. बी-99 धर्जपुर इंडस्ट्रियल एरिया बिल्ली-110052	घरेलू कार्यों के लिए सिलार्ड मशीन हस्त चालित आईएस : 01610-81	
93. सीएम/एल—2139243	90-08-01	बी.एस. पम्पस एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, ईशापुर, रोड, बासनगर, हावड़ा-711105	लैडिंग वाल्व एलटीबी-2 ग्रेड टाइप-ए आईएस : 0390-83	
94. सीएम/एल—2139344	90-08-01	स्टील प्रोपर्टी प्रा. लि., राजरकेला स्टाल प्लांट, राजरकेला-769011	प्रतप्त वेल्डन हेतु तप्त वेल्डित कार्बन इस्पात पत्ती आईएस : 11413-84	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
95. सीएम/एल-2139445	90-08-01	नफर चन्द्र जूट मिल्स लि., भूतनाथ कोले रोड, डा. कनकिनारा जिला-24 परगना	खाद्यान्न पैकिंग के लिए बी-टिबल आईएस : 02560-84	
96. सीएम/एल-2139346	90-08-01	नफर चन्द्र जूट मिल्स लि., भूतनाथ कोले रोड, डा. कनकिनारा जिला-24 परगना	पटसन टरपुलिन कपड़ा आईएस : 07407-80 भाग-III)	
97. सीएम/एल-2139647	90-08-01	इ.जी. ओ.ई.जी.नियरिंग कं. डिप्टी गंज, बुलन्द शहर (उप्र)	पावर प्रेशर की सुरक्षा अपेक्षाएं प्रेसर हैमरिख टाइप 7.5 कि.बा. आईएस : 09020-79	
98. सीएम/एल-2139748	90-08-01	देसाई इंजीनियरिंग प्रा. लि., 553/बी, कोलधन पुर रोड, खेड शिवपुर पुणे-412205	पावर सॉल के लिए शट संघारित आईएस : 02834-86	
99. सीएम/एल-2139849	90-08-01	सुमेक्स कैमीकल्स लि., स्टेट हाईवे नं. 6 डा. बाबली जिला बालसाह (गुजरात)	फेनोलेनरेट, ईसी आईएस : 11997-87	
100. सीएम/एल-2139950	90-08-01	सुमेक्स कैमीकल्स लि., स्टेट हाईवे नं. 6 डा. बाबली जिला बालसाह (गुजरात)	म्यूटाक्लोर, ईसी आईएस : 09336-80	
101. सीएम/एल-2140020	90-08-01	कैमी कल्स, 17/ए बीटी मेट्रू स्ट्रीट, बेल्गोर-632012	कोलनार खाद्यरंग निर्मितियां ठोस आईएस : 05340-75	
102. सीएम/एल-2140127	90-08-01	दि माइन्ट कंस्ट्रक्शन कं. लि., 63, कमलापलायम त्रिबी रोड, कोयम्बतूर-414002	जल, रस और मलजल के लिए बिजलीवैलकित इस्पात के पाइप आईएस : 3889-81	
103. सीएम/एल-2140228	90-08-01	स्टील अचारिटी आफ इंडिया, भुनापुर स्टील प्लांट-713203	हल्ट बेल्डित काबन इस्पात, पत्ती आईएस : 01079-78	
104. सीएम/एल-2140329	90-08-01	धिसाह इंडस्ट्रीज, गुरू की नगरी मंडी गोबिंदगढ़ (पंजाब)	परचन इस्पात (मानक किस्म) आईएस : 00226-75	
105. सीएम/एल-2140439	90-08-01	पी. एस. इंडस्ट्रीज, प्लांट नं. 3 मंतोछपूरा जलंधर	एम सी आई पाइप फिटिंग समान एक्सचर की साकेट और ग्रुनियम आईएस : 01879-75	
106. सीएम/एल-2140531	90-08-01	हिंदुस्तान सेनेट्री बेयर एंड इंडस्ट्रीज लि., कृष्णा पुरम, ब्राह्ममण पल्ली बी बी नूर-508126	कमोड (वाटरक्लोसेट) 10 लिटर धारिता वाली अल्प स्तर, साइकनीय टाइप फलश की टंकिया आईएस : 03774-84	
107. सीएम/एल-2140632	90-08-01	कृषि रसायन, नेशनल हावे नं. 5 डा. रानीताल पर, बालसोड़ पिन-750111	मिथाइल पैराथियाम ईसी	

[सं. के प्र वि/13 : 11]]

S.O. 447. —In pursuance of Sub-regulation (5) of regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (certification) Regulations, 1988, The Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given in the following schedule.

## SCHEDULE

List of Licences granted during the month of July 1990

Sl. No.	CM/L-No.	Operative Date	Name & Address of the Party	Article/Process	IS : No./Part
1	2	3	4	5	6
1.	CM/L-2130023	90-06-16	Ratan Microelectronics Pvt. Ltd. Kundanganj Lucknow-Rae Bareilly Road Rae Bareilly	Zinc Sulphate, Agricultural Grade	08249-76

1	2	3	4	5	6
2. CM/L-2130224	90-07-16	Taramanik Cables Pvt. Ltd. F-118, Sector VIII Noida 201301	ACSR Conductors upto 7 Strands	00398-76 (Part I)	
3. CM/L-2130225	90-07-01	Chander Nagar Chemicals & MI Nerals (P) Ltd. Chander Nagar, Village Silokra Gurgaon-122001	Bleaching Earths of Indian origin used for bleaching Vegetable Oils,	01965-72	
4. CM/L-2130326	90-07-16	Reliance Engineers Pvt. Ltd. No. 118/A-1, Vasaveswara Indl. Estate Peenya II Stage Bangalore 560059	PVC Insulated Winding Wires for Submersible Motors with copper conductors Insulation Type 5 Thickness Grade I	08783-87	
5. CM/L-2130427	90-07-16	Raisoni Engineering Works A/91, Indl. Estate Jalgaon 425003	Monoset Pumps for Clear, Cold Fresh water for Agricultural Purposes.	09079-79	
6. CM/L-2130528	90-07-16	M.B.H. Pumps Pvt. Ltd. 3, Meera Co-op. Indl. Estate near Dahisar Chuk Naka Mira Distt. Thane 401104	Motors for Submersible pumps 3.7 kw Category B Wet Type	09283-79	
7. CM/L-2130629	90-07-16	Sri Vigneshwara Engineering Co. 1095, Avanashi Road, P.N. Palayam Coimbatore 641037	Motors for Submersible pumps 9.3 kw Category B Wet Type	09283-79	
8. CM/L-2130730	90-07-16	Nandi Industries 51 P.N. Palayam Road K.R. Puram Coimbatore 641006	Three Phase Squirrel Cage Induction Motors for Centrifugal Pumps for Agricultural Application 2. kw class a Insulation	07539-75	
9. CM/L-2130831	90-07-16	Sure Safe Glass Works Pvt. Ltd. Jalkhura Mahesh Tala Distt. 24 Parganas 743352	Toughened Safety Glass Except for Wind Screen Application	02553-71	
10. CM/L-2130932	90-07-16	North Brook Jute Co. Ltd. Briilyabati Champadani Hooghly (WB) 712221	Jute Bags for Packing Cement	02590-82	
11. CM/L-2130125	90-07-16	Pashupati Udyog Ltd. National Highway 6 Village Jangalpur PO Andulmouri Howrah	Galvanized Tapes for Armourings Cables	03975-83	
12. CM/L-2131126	90-07-16	Pioneer Metal Industries C-4, Indl. Estate Jharsubuda Distt. Sambalpur 768205	Aluminium Alloy Stranded Conductors	00398-79 (Part IV)	
13. CM/L-2131227	90-07-16	Fuji Lamps Channa Nikad Via Chinsevanam Distt. Kottayam (Kerala) 686533	GLS Lamps 250 Volts upto 100 W Rating	00418-78	
14. CM/L-2131328	90-07-16	Sony Lamps Mfg. Co. Kurukutti Angamaliy Distt. Ernakulam-683576	GLS Lamps 250 Volts upto 60 W Rating	00418-78	
15. CM/L-2131429	90-07-16	Jayashri Cables & Engs. Works Kunjandiyur PO Gonur Mettur Dam 636404	PVC Insulated Heavy Duty Electric cables for working voltages upto and including 1100 Volts	01554-76 (Part I)	
16. CM/L-2131530	90-07-16	Kisan Plastics (P) Ltd. Chelur Road Chintamani Distt. Kolar (Karnataka) 563125	Unplasticized PVC Pipes Glass 3 upto and including 110 MM	04985-81	
17. CM/L-2131631	90-07-16	H.K. Mahindra & Co. 2167/17, Khampur Opp. West Patel Nagar New Delhi-110008	Brushes for Paints and Varnishes Flat Size upto 100 MM	00384-79	

1	2	3	4	5	6
18. CM/L-2131732	90-07-16	Khatana Junker Ltd. Plot No. 3000 GIDC Ankleshwar	Malathion 50 Percent EC Formulation		0567-78
19. CM/L-2131833	90-07-16	Kinloskar Bros. Ltd. Ujjain Road Opp. Railway Station Dewas 453001	Motors for submersible pumpsets		09238-79
20. CM/L-2131934	90-07-16	Bharath Equipments 1-A, K.R. Puram Main Road Ganapaty Coimbatore 641006	Twin type jet centrifugal pumps Combination		1222-87
21. CM/L-2132027	90-07-16	Jindal (India) Ltd. 4, Dharmatalla Road PO Belurmath Distt. Howrah (WB)	Steel Tubes for Idlers for Belt Conveyors		09295-83
22. CM/L-2132128	90-07-16	Volga Auto Accessories 126, Bharat Nagar Shahpur Belgaum 590003	Protective Helmets for Mopeds Scooters and Motorcycle riders		04151-82
23. CM/L-2132229	90-07-16	Biraj Tin Industries C/o Umesh Engg. Works Plot No. 196/8 Near Vapi Paper Mills GIDC Vapi (Gujarat)	15 KG Square Tins for Packing Ghee, Banaspoti, Edible Oils and Bakery Shortenings		10225-89
24. CM/L-2132330	90-07-16	Damodar Cement & Slag Ltd. Madhukunda PO Sunuri Distt. Purulia (WB)	Portland Slag Cement		00455-76
25. CM/L-2132431	90-07-16	Manju Electrical Industries Ltd. 12 Km, Pollachi Road Malumacham Patti Coimbatore 641021	Submersible Pumpsets for Clear, Cold, Fresh Water		08034-76
26. CM/L-2132532	90-07-16	Sri Srinivasa Foundry Aminankulam Road P.N. Palayam Coimbatore 641037	Jet Centrifugal Pumps Combination		12225-87
27. CM/L-2182633	90-07-16	Universal Engineers 14, Manupunchal Indl. Estate Near Indira Nagar Amraiwadi Ahmedabad 380026	Submersible Pumpsets for Clear, Cold, Fresh Water		08034-89
28. CM/L-2132734	90-07-16	Parikh Agro Equipments Divya Park Society Near Ramji Mandir, Nikol-Naroda Road Ahmedabad 332350	Hand Rotary Duster Belly Mounted type		05135-74 (Part I)
29. CM/L-2132835	90-07-16	Jaikishan Das Mal Jute Products Pvt. Ltd. Rupsa Distt. Balasore (Orissa) 756028	Country Jute Twine of variety 2 7 & 8 only		01912-84
30. CM/L-2132936	90-07-16	Bombay Foods Pvt. Ltd. Katargam Surat 395004	Gobar Gas Stoves		08749-78
31. CM/L-2133029	90-07-16	Bharat Tin Industries Village Pebarkalan Chandigarh Road Rajpura (Punjab)	15 Kg Square Tins for Ghee, Vanaspoti, Edible Oils and Bakery Shortenings		10325-89
32. CM/L-2133130	90-07-16	Top Products Hatin Nagar Gundarl Dhanera Taluk Via Khimat Distt. Banaskantha 365545	Pan Goods Confectionery (Dragees)		08806-78

1	2	3	4	5	6
33. CM/L-2133231	90-07-16	Anand Chemical Works 185-186, Ancillary Indl. Area Tapudana Hatia Ranchi 834003	Alumind Ferric Grade 2 only		00299-80
34. CM/L-2133332	90-07-16	A.K. Manufacturing Pvt. Ltd. Nilakhuti Imphal Manipur	15 KG Square Tins for Ghee, vanaspati, Edible Oils and Bakery Shortenings		10325-89
35. CM/L-2133433	90-07-16	Anamica Conductprs Pvt. Ltd. 4 & 5 A Malviya Indl. Area Jaipur 302017	ACSR Conductors for Overhead Transmission Purposes		00398-76 (Part II)
36. CM/L-2133534	90-07-16	Bhandari Cables Pvt. Ltd. N.H. Road No. 12 Village Kilkipura PO Sheodas Pura Jaipur 303903	AAC Conductors for Overhead Transmission		00398-76 (Part I)
37. CM/L-2133635	90-07-16	Falcon Electronic Conctors Pvt Ltd. Khasra No. 358 Village Ali Mathura Road Badarpur New Delhi 110044	PVG Insulated Cables for Working voltages upto and Including 1100 Volts		00504-77
38. CM/L-2133736	90-07-16	Devi Das Gopal Krishan Ltd. Gandhi Road MOGA Distt. Fariqkot 142001	Compounded Feeds for Cattle type 2 Only		02052-79
39. CM/L-2133837	90-07-16	Asiatic Conductors C-236, Indl. Area Bullandshar Road Ghaziabad	ACSR Conductors upto 7 Strands		00398-76 (Part II)
40. CM/L-2133933	90-07-16	Aggarwal Agro Industries Village Buchipura Moga Ludhiana G.T. Road Moga 142001	Compounded Feeds for Cattles type 2 only		02052-79
41. CM/L-2134031	90-07-16	Jhunjunwala Fodder Mills Village Asha Pur PO Sarnath Distt. Varanasi (UP)	Compounded Feeds for Cattles type 2 only		02052-79
42. CM/L-2134132	90-07-16	Avanti Cables Pvt. Ltd. PB NO. 104 MIDC Bhosari Pune 411026	Single core PVC Insulated Cable for Motor Vehicles with Copper Conductors		02465-84
43. CM/L-2134233	90-07-16	Hot Star Electricals Pvt. Ltd. B-41, Sector V Noida	Stationery Storage type 25 Litre capacity		020-82-85
44. CM/L-2134334	90-07-16	Esdee Cement (P) Ltd. Post Kulyanpur Village Udaipur Distt. Dhanbad (Bihar)	Ordinary Portland Cement		00269-76
45. CM/L-2134435	90-07-16	Kissan Feeds Pvt. Ltd. Village Said Pur Thshil Derabassi Distt. Patiala (Punjab)	Compounded Feed for Cattle Type 2 Only		02052-79
46. CM/L-2134536	90-07-16	Kerala Solvent Extractions Ltd. 22a, Solvent Road Irinjalakuda (Kerala) 680121	Compounded Feeds for Cattle Type 2 Only		02052-79
47. CM/L-2134637	90-07-16	Max Corona Engineers & Consultants Pvt. Ltd. Gopalpur Village Outer Ring Road Delhi 110007	Integral Cement Waterproofing Compound (Powder Form)		02645-75

1	2	3	4	5	6
48. CM/L-2134738	90-07-16	Sakri Electrical Industries Pvt. Ltd. Vrindavanam Kottanad Tiruvalla (Kerala) 699615	switches for Domestic and Similar purpose Flush Type SAMP 250 Volts AC Only	03854-83	
49. CM/L-2134839	90-07-16	Ferrocon Mohaccwala Indl. Area Saharan Pur Road Dehradun	Circular Rectangular and Square Type and of Light, Medium and Heavy Duty Precast Concrete Manhole Covers	12592-88	
50. CM/L-2134940	90-07-16	ACI (Agro Chemical Industries) Pvt. Ltd. Poonamallee Avadi Road Kaduvetty Madras 600077	Butachlor EC	09356-80	
51. CM/L-2135033	90-07-16	Premier Home Appliances S. No. 245/2 G.N.T. Road Pethikuppam Gummidipundi 601201	Domestic Gas Stoves for Use with LPG	04246-84	
52. CM/L-2135134	90-07-16	S.N. Chemical Industries B-25, Govt. Indl. Estate Mehrauli Road Gurgaon 122001	Methyl Parathion EC	02865-78	
53. CM/L-2135235	90-07-16	Gujarat Agro Industries Corporation Ltd. Pesticide Formulation Unit Near ITI N.H. No. 88 Gondal 360311	Monocrotophos SL	08074-83	
54. CM/L-2135336	90-07-16	Brij Textile 68, Khyber Pass Civil Lines Delhi 110054	Pressure Sensitive Adhesive Cloth Tape Type 1 Only	02687-77	
55. CM/L-2135437	90-07-16	Navalakha Agro Equipments 38, Shankar Seth Road Pune 411037	Padal Operated Paddy Threshers One person operated type only	03327-82	
56. CM/L-2135538	90-07-16	Solar Syndicate Dungri Distt. Valsad 396375	Carbendazim Wdp	08446-77	
57. CM/L-2135639	90-07-16	Electro Fabric Shed No. 5 Indl. Area PO Vehicle Factory Richhai Jabalpur 482009	Safety Requirements for Power Threshers Rating 3.7 KW (5HP)	09020-79	
58. CM/L-2135740	90-07-16	S.N. Chemical Industries B-25, Govt. Indl. Estate Mehrauli Road Gurgaon 122001	Carbendazim WDP	08446-77	
59. CM/L-2135841	90-07-16	Gupta Agricultural Industries Rania Road Sirsa 125055	Safety Requirements for Power Threshers Syndicator Type of rating 22 KW (30 HP)	09020-79	
60. CM/L-2135942	90-07-16	Contimenters & Electricals E-3, Modern Indl. Estate Bahadurgarh 124507	Single Phase two wire whole current Watt Hour Meter Class 2	00722-77 (Part II)	
61. CM/L-2136035	90-08-10	Manashi Electrical Industries No. 1, G.T. Karnal Road Indl. Area Delhi 110033	Electric Immersion Water Heaters 1000 W 230 AC	00368-83	

1	2	3	4	5	6
62. CM/L-2136136	90-08-10	Indian Hume Pipe Co. Ltd. Karari Jhansi	Prestressed Concrete Pipes Non Cylindrical	00748-78 ..	
63. CM/L-2136237	90-08-10	Ceat Tyres of India Ltd. 82, Midc Indl. Estate Satpur Nasik 422007	Truck, Bus, Light Truck Tyres Diagonal Ply Type	10914-88 (Part 1D)	
64. CM/L-2136338	90-08-10	Jay Electric Industries Unit No. 24 Nutan Chemical Compound Second Floor, Valbhat Road Gor-gaon (W) Bombay 400062	Three Pin Sockets Outlets 5 and 15 AMP 250 Volts Flush Type	01293-88	
65. CM/L-2136439	90-08-01	S. Kumars Ltd. 3-A, Indl. Area No. 2 A.B. Road Dewas	Polyester Blend Suitings	09517-86	
66. CM/L-2136540	90-08-01	Progressive Cement Ltd. Indl. Area Patratu Distt. Hazaribagh 829119	Portland Slag Cements	00455-76	
67. CM/L-2136641	90-08-01	Makali Engineering Works Amta Road Baltikuri Howrah	Horizontally Cast Iron Double Flanged Pipes for Water, Gas and Sewage	07181-74	
68. CM/L-2136742	90-08-01	Shilpa Re Rollers Pvt. Ltd. Plot No. 3, Wanjra Layout Kamptee Road Nagpur	Structural Steel (Standard Quality)	00226-75	
69. CM/L-2136843	90-08-01	Kishan Chand & Sons D-9, Krishan Nagar Delhi 110051	Handloom Cotton Bandage Cloth Non Sterilized	00868-88	
70. CM/L-2136944	90-08-01	Technomatic 35, Masjid Lane Jangpura Bhogal Market New Delhi 110014	Electric Irons Thermostatic	00366-85	
71. CM/L-2137037	90-08-01	Jain Industrial Lighting Corpn. B-70/22, DSIDC Complex Lawrence Road Dellil	Decorative Lighting Outfits Suitable for Indoor Use	0507769	
72. CM/L-2137133	90-08-01	Shilpa Re-Rollers Pvt. Ltd. Plot No 3, Wanjra Layout Kamptee Road Nagpur	High Strength Deformed Steel Bars and wires for Concrete Reinforcements	01786-85	
73. CM/L-2137239	90-08-01	Makali Engineering Works Amta Road Baltikuri Howrah	CI Fittings, Collars Only for Pressure Pipes for Water, Gas and Sewage	01533-76 (Part I to XXII)	
74. CM/L-2137340	90-08-01	Makali Engineering Works Amta Road Baltikuri Howrah	Vertically Cast Iron Pressure Pipes for Water, Gas and Sewage	01537-76	
75. CM/L-2137441	90-08-01	The Assam Tubes Ltd. Amingaon Guwahati 781031	High Strength Deformed Steel Bars and Wires for Concrete Reinforcements	01786-85	
76. CM/L-2137542	90-08-01	Polar Fan Industries Ltd. 167 Brahmosamaj Road Calcutta 700060	Electric Ceiling Fans and Regulators	00374-79	
77. CM/L-2137643	90-08-01	Electrotek Industries 79, J.C. Indl. Estate Kakakapura Road 11th KM Bangalore 560062	Stationery Storage Type Electric Water Heaters 15 Litre Capacity	02082-85	

1	2	3	4	5	6
78.	CM/L-2137744	90-08-01	South India Steel Industries (P) Ltd. Whitefield Road Bangalore 560066	High Strength Deformed Steel Bars for Concrete Reinforcement	01786-85
79.	CM/L-2137845	90-08-01	Hind Steel N-73, MIDC Hingna Road Nagpur	Structural Steel (Standard Quality)	00226-75
80.	CM/L-2137946	90-08-01	Maharashtra Weldaids Ltd. B-28, MIDC Indl. Area Kamleshwar Nagpur (MS)	Covered Electrodes for Metal Arc Welding	00814-74 (Part 1)
81.	CM/L-2133089	90-08-01	Sarda Home Appliance(P) Ltd. 1/118, Old Mahabalipuram Road Scevaram,Village Perungudi Madras 600096	Domestic Gas stoves for Use with LPG	04246-84
82.	CM/L-2133140	90-08-01	Dhamija Indl. Corpn. S-5, Indl. Area site A Bye Pass Mathura	Cast Iron Soil Pipes with Socket and Spigot Ends	01729-79
83.	CM/L-2133241	90-08-01	Bhoomi Sudhar Chemical Industries 7-A, Focal Point Indl. Area Sangrur 148001	Zinc Sulphate, Agricultural Grade	08249-76
84.	CM/L-2138342	90-08-01	Bindal Agro Chem Ltd. Plot No. 19-B New Indl. Area Mandi Deep Distt. Raisen 462046	Flexible Packs for Packing of Edible Oils and Vanaspati	11352-85
85.	CM/L-2138443	90-08-01	Unimin India Ltd. F-127, Sector VIII Noida (Distt. Ghaziabad)	UPVC Pipes for Potable Water Supplies	04985-88
86.	CM/L-2138541	90-08-01	Universal Engineers 13-14, Manupanchal Indl. Estate Near Indira Nagar Amraiwadi Road Ahmedabad 380026	Motors for Submersible Pumps Category B 415 Volts Wet Type	09283-79
87.	CM/L-2138645	90-08-01	Data Cables Pvt. Ltd. Kandra Indl. Area Post Govindpur Dhanbad	Heat Resistant Elastometer	09968-81 (Part II)
88.	CM/L-2138746	90-08-01	The British Machinery Supplies Co. 17-A, Indl. Area New Township Faridabad 121001	Sewing Machines for Household Purposes Handoperated	01610-81
89.	CM/L-2138847	90-08-01	Leader Lamps & Electricals Valoor Charuvallloor PO Distt. Trichur (Kerala) 680321	Tungsten Filaments SLS Lamps 230 Volts 100 W	00418-78
90.	CM/L-2138948	90-08-01	Vinyl Tubes Pvt. Ltd. C-19, UPSIDC Indl. Area Kosikalan Distt. Mathura	UPVC Pipes for Potable Water Supplies	04985-81
91.	CM/L-2139041	90-08-01	Jay Cylinders Ltd. A-30, Indl. Area Sikandrabad (UP)	Welded Low Carbon Gas Cylinders of Water Capacity 10+33.3 Litres	03196-82
92.	CM/L-2139142	90-08-01	Paul Eros & Co. B-99, —Wazirpur Indl Area Delhi 110052	Sewing Machines for Household Hand Operated Type	01610-81

1	2	3	4	5	6
93. CM/L-2139248	90-08-01	Venus Pumps & Engineering Works Ichapur Road Dasnagar Howrah 711105	Landings Valves LTB-2 Grade Type A	05290-83	
94. CM/L-2149344	90-08-01	Steel Authority of India Ltd. Rourkela Steel Plant Rourkela 769011	Hot Rolled Carbon Steel Strip for Cold Rolling Purposes	11513-85	
95. CM/L-2139445	90-08-01	Naffar Candra Jute Mills Ltd. Bhutnath Kole Road PO Kankinara Distt. 24 Parganas	B-Twil Jute Bags for Packing Food Grains	02566-84	
96. CM/L-2139546	90-08-01	Naffar Chandra Jute Mills Ltd. Bhutnath Kole Road PO Kankinara Distt. 24 Parganas	Jute Tarpaulin Fabric 360G/M SQ 68 X 69	07407-86 (Part III)	
97. CM/L-2139647	90-08-01	EGO Engineering Co. Deputy Ganj Bulandshahr (UP)	Safety Requirements for Power Threshers Hammer Mill Type 7.5 KW	09020-79	
98. CM/L-2139748	90-08-01	Desai Engineering Pvt. Ltd. 553/B, Kondhan Pur Road Khed Shiva Pur Pune 412205	Shunt Capacitors for Power Systems	02834-86	
99. CM/L-2139849	90-08-01	Sumex Chemicals Ltd. State Highway No. 6 PO Bhadeli Distt. Valsad (Gujarat) 396080	Fenvalerate EC	11997-87	
100. CM/L-2139950	90-08-01	Sumex Chemicals Ltd. State Highway No. 6 PO Bhadeli Distt. Valsad 396030	Butchlor EC	09356-80	
101. CM/L-2140026	90-08-01	SAME Chemicals 17/A, B.T. Mettu Street Vellore 632012	Coaltar Food Colour Preparation Solid Only	05346-75	
102. CM/L-2140127	90-08-01	The Modern Construction Co. Ltd. 63, Kannampalayam Trichy Road Coimbatore 641402	Electrically Welded Steel Pipes of Water, Gas and Sewage	03569-81	
103. CM/L-2140228	90-08-01	Steel Authority of India Ltd. Durgapur Steel Plant Durgapur 713203	Hot Rolled Carbon Steel Sheets, Strips	01079-78	
104. CM/L-2140329	90-08-01	Dhiman Industries Guru Ki Nagri Mandi Govindgarh (Punjab)	Structural Steel (Standard Quality)	00226-75	
105. CM/L-2140430	90-08-01	P.S. Industries Plot No. 3 Santokh Pura Jalandhar	M.C.I. Pipe Fittings Equal Elbows, Tee, Socket and Unions	01879-75	
106. CM/L-2140531	90-08-01	Hindustan Sanitaryware & In- dustries Ltd. Krishna Puram Brahmanpalli Bibi Nasar 508126	Flushing Cisterns for Water Closets Vitercus China Low Level Syphonic Type 10 Litre Capacity	00774-84	
107. CM/L-2140632	90-08-01	Krishi Rasayan National Highway No. 5 AT/PO Ranital Balasore 756111	Methyl Parathion EC	08960-78	



नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1991

का.आ. 448 --भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1985 के विनियम 4 के उपविनियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि निम्न लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए वे स्वीकृत कर दिए गए हैं :

## अनुसूची

क्र.सं.	लाइसेंस संख्या	लागू होने की अवधि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	भारतीय मानक की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सीएम/एल-2158247	1990-10-01	प्रिमियर न्यूट्रीशन , 55-ए/56 ईड. एरिया, नं. 1, ए. बी. रोड, देवास-455001	मक्खनिया दूध	01165-86
2.	सीएम/एल-2158348	1990-10-16	आरकोटेक्चरल एंड, बी-163, फेज II, नोएडा, जि. गाजियाबाद (उ.प्र.)	सामान्य प्रयोजन के लिए फर्श बिछाने हेतु सी.मेंट की टाइल	01237-80
3.	सीएम/एल-2158449	1990-10-16	भंडारी केबल्स एंड कंडक्टर्स, 15.5 कि.मी. बेलगाम, बेनगुरला रोड, आर. 5. 127 शिनोली, ताल्लुक चांद गढ़, जि. कोल्हापुर- 416508	ए एस सी आर चालक	0398-76 (भाग : 1)
4.	सीएम/एल-2158550	1990-10-16	नवकार केबल्स एंड कंडक्टर्स, 15वां किमी, बेलगाम, बेनगुरला रोड, शिनोली ताल्लुक चांद गढ़, जि. कोल्हापुर-416508	ए एस सी आर चालक	00398-76 (भाग-1)
5.	सीएम/एल-2158651	1990-10-16	नवकार केबल्स एंड कंडक्टर्स, 15वां कि.मी. बेलगाम, बेनगुरला रोड, शिनोली ताल्लुक चांद गढ़, जि. कोल्हापुर-416508	जस्तीकृत इस्पात प्रबलित एल्युमीनियम चालक	0038-76 (भाग-2)
6.	सीएम/एल-2158752	1990-10-16	प्रभु स्टील इंड लि., 159-60 स्माल फैक्ट्री, एरिया, बगावगंज, नागपुर	बेल्डनीय संरचना इस्पात ग्रेड एफ ई 410 डब्ल्यू.ए.	02062-84
7.	सीएम/एल-2158853	1990-10-16	एल्युमीनियम को टिंग मैन्यु. आफ इंडिया, शेड नं. 3/1 रोड नं. 1ए, ईड. एस्टेट गोविंदपुरा भोपाल-462023	जल सह और तभीसह बनाने में प्रयुक्त बिटुमेन प्रिमियर	03384-86
8.	सीएम/एल-2158954	1990-10-16	समा स्टील इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि., दिल्ली रोड, बाबुआ, डा. बामुनारी, जि. हुगली (पं. बं.)	संरचना इस्पात (मानक किस्म)	00226-75
9.	सीएम/एल-2159047	1990-10-16	समा स्टील इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि., दिल्ली रोड, बाबुआ, डा. बामुनारी जि. हुगली (पं. बं.)	सी टी डी सरिफ	01786-85
10.	सीएम/एल-2159148	1990-10-16	मास्टर होम एम्पलाईसेज प्लांट नं. 136/2 प्राइमरी स्कूल के सामने, प्रा-बादली, दिल्ली-110042	ब्र पे गै के साथ प्रयुक्त घरेलू चूल्हे	04246-84
11.	सीएम/एल-2159249	1990-10-16	शेषशिला सीमेंट प्रा. लि. 315 शारदाहल्ली या., सीएन हाली ताल्लुक,, जि. तुमकुर	साधारण पोर्टलैंड सीमेंट	00269-76
12.	सीएम/एल-2159350	1990-10-16	टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि., 127 कट्टाडोंगारोड काकीनाडा, जि. फिमापाड़ा	ट्रक और बस के टायर	10914-88
13.	सीएम/एल-2159451	1990-10-16	हैक्स्ट इंडिया लि., प्लाट नं. 3601-15 एच 6301 से 14, जी. आई. डी. सी. एस्टेट, अंकलेश्वर (गुजरात)	एंडोसल्फान ईसी	04323-80

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14. सीएम/एल-2159552	1990-10-16	आंध्र हस्पात लि., 31 कि. मी. का पथर, हैदराबाद-वाराणसी रोड, काडा, मधु. ग्रा. बा. बी.बी. नगर लि. नलगोडा	मीट जी मणि	01786-85	
15. सीएम/एल-2159653	1990-10-16	जनमस मिनरल्स, 27 ए.इ.ए. एरिया, फतेहाबाद-125050	गुटाकलोर, ईसा	09756-80	
16. सीएम/एल-2159754	1990-10-01	परिजात कैमिकल इंड., ई-11, बक. इंड. एस्टेट, वाराणसी-221006	रोगाणुनाश ब्रक. शेर्पा ए. ग्रेड 3, टाइप-सामान्य और विन्टर	01061-82	
17. सीएम/एल-2159855	1990-10-16	वि. टिन कंपनी, 61 डाका रोड (बी. टी. रोड, पूर्व) हा. मोहारा के लिए 15 कि. ग्रा. के चौकोर कनसरा मुधियाना	वनस्पति, खाद्य तेल और बेकरी मोयन	0325-89	
18. सीएम/एल-2159956	1990-10-16	इंडो सैम इंडस्ट्रिज, 33 आनंद इंड. एस्टेट, मोहननगर भाजियाबाव (उ.प्र.)	लेटेक्स फोम रबर उत्पाद टाइप फोड वाले ग्रेड "एफ" केवल	01741-80	
19. सीएम/एल-2160032	1990-10-16	काकू स्टील मिल, ग्रा.-टी.डी.सरा, जि. राजनंद गांव (म.प्र.)	मी. टी. बी. एरिये	0186-80	
20. सीएम/एल-2160133	1990-10-16	एल्यूमिनियम केदल्ट एंड कंजटल ए-82 इंड. एस्टेट राजाजीनगर बंगलौर-560044	ए एस सी प्रार बालक	IS: सं. भाग (6) 00398-76 (Part I)	
21. सीएम/एल-2160234	1990-10-16	एल. बी. टी. कंटेनर्स बी-464 इंड. एस्टेट गोकुल रोड, हुबली	बी, वनस्पति, खाद्य तेलों और बेकरी मोयन के लिए 15 कि. ग्रा. के चौकोर कनसरा	10735-89	
22. सीएम/एल-2160335	1990-10-16	एल. बी. टी. कंटेनर्स बी-464 इंड. एस्टेट, गोकुल रोड, हुबली	18 लिटर के चौकोर कनसरा	00916-76	
23. सीएम/एल-2160436	1990-10-16	बेस्मिन इन्डस्ट्रियल इंड. ए-37 जी. टी. कारनाल रोड, इंड. एरिया दिल्ली-110033	बिजली की हस्पाती	00966-85	
24. सीएम/एल-2160537	1990-10-16	कंसोलिडेटेड स्टील एंड एलॉय लि. 35-38 इंड. एरिया, बनभोर, जि. मुरेना (म.प्र.)	संरचना हस्पात (मानक किस्म)	00226-75	
25. सीएम/एल-2160638	1990-10-16	कंसोलिडेटेड स्टील एंड एलॉय लि. 35-38 इंड. एरिया, बनभोर, जि. मुरेना (म.प्र.)	वेल्डिंग संरचना हस्पात रेल एफई 410 डब्ल्यू.ए.	01062-84	
26. सीएम/एल-2160739	1990-10-16	मोहना स्टील लि. महादेव पुरा डा.0 व्हाइट फेल्ड रोड, बंगलौर-560048	धातु प्रॉक वेल्डिंग के फोडतार हेतु मुधु हस्पात	02079-75	
27. सीएम/एल-2160840	1990-10-16	शक्ति कंक्रीट प्रा. लि. सी-40 अमोस इंड. एरिया लखनऊ	कंक्रीट पाइप एन पी 150 और 300 मिमी. साइज केवल	00458-71	
28. सीएम/एल-2160941	1990-10-16	वेनरा जूट मिल ए यूनिट ऑफ राजनंद कामशियल (प्रा. लि.) जगतवल जि. 24 परगना (प. बं.)	खाद्य रीफ्रिज के लि. बो टिबल पटसन के बारे	02566-84	
29. सीएम/एल-2161034	1990-10-16	कमारहट्टी कं. लि. 907 ग्राहम रोड, कमारहट्टी, कलकत्ता-700058	407 ग्रा/मी पटसन तरपुलिन कपडा	07407-80 (भाग-2)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	सं एम/एल-2161135	1990-10-16	कलिंगा कौन्सिल इंड एस 1/82 भानुबेसर (नया) इंड. एस्टेट भुवनेश्वर	सॉमेट को जल सह बनाने के लिए मिलाया जाने वाला योशिक	02648-75
31	सी एम/एल-2161236	1990-10-16	सुवेय्या फाउन्ड्री 1205 से 1208, अविनाशी रोड, पी एन पलायम कोयम्बतूर-641022	कृषि प्रयोजनों के लिए साफ, ठंडे ठाजे पानी हेतु गोमोसॉट पम्प	09079-79
32	सं एम/एल-2161337	1990-10-16	सुकु इन्विक्पमेन्ट एंड इंड. 211/1 कुरुडामपलायम इडिगारी रोड, नरगो कालोनी डा. कोयम्बतूर	निमज्जय पम्पसेट	08034-70
33	सी एम/एल-2161438	1990-10-16	ग्रीनफील्ड पाइपस (प्रा.) लि भेरठ रोड, भवाना-250401	पेय जल आपूर्ति हेतु अप्तास्टिकृत पी बी सी पाइप साइज 63 मिमी से 180 मिमी श्रेणी 2	04985-88
34	सी एम/एल-2161539	1990-11-01	दिव्युरतान इंसेकटीसाइन्स लि. डा. रसायनी जि. रायगढ़-410207	अयूटाकसोर, तमर्नीकी ग्रेड	09355-80
35	सं एम/एल-2161640	1990-11-01	संजना केबल्स प्रा. लि. 9/80 गंगा बागिचा विश्वासनगर, दिल्ली-110032	निमज्जय पम्पसेट के लिए पी बी सी रोहित ब्रेडन तार	08783-78
36	सं एम/एल-2161741	1990-11-01	नार्थ वेस्ट स्विचगैर लि 14/3 मथुरा रोड फरीदाबाद-121003	तीन साकेट आउटलेट	01293-88
37	सी एम/एल-2161842	1990-11-01	नक्षत्र कौन्सिल प्रा. लि. ई-3 यू पी एस आई डी सी इंड. एरिया बेगमपुरा डा. मंजूरपुर जि मुजफ्फरनगर	जिक सॉफ्टे कृषि ग्रेड	08249-70
38	सी एम/एल-2161943	1990-11-01	ए टी पी लि. पी-46 हाइड रोड एक्स्टेंशन कलकत्ता-700084	जल सह और रिसाव रोधी बनाने के लिए विट्रिफाई योशिक	01580-89
39	सी एम/एल-2162036	1990-11-01	आनंद गैटल जर्पे, सी-143 नारायणा इंड एरिया नई दिल्ली-110028	1100 बी तक कार्यकारी वोल्टता के लिए पी बी सी रोहित (डिफेंसुटी) बिजली (भाग 1) की केवल	01554-76
40	सी एम/एल-2162137	1990-11-01	श्री साईं बाबा स्टील इंड. 275/3 श्रीधर रोड, श्रीधर, अहमदाबाद	मरकता इस्पात (मानक किस्म)	00226-75
41	सी एम/एल-2162238	1990-11-01	सुपिन एनो फौसीकस (इंडिया) प्रा. लि 243/पी जी आई डी सी पनोको जि. अरुण (गुजरात)	फौसीकमिडॉन 85% एम एल	06177-81
41	सी एम/एल-2162339	1990-11-01	वैको केबल्स प्रा. लि प्लॉट नं. ए-55-56 स्टिन मिलार मिर्जा रोड, मिर्जा-422103	1100 बी तक कार्यकारी वोल्टता के लिए पी बी सी रोहित खोल सल्लि/ खोल रहिल, बाठरी और अन्य एप उपयोगों को छोड़कर	00694-77
43	सी एम/एल-2162440	1990-11-01	प्लास्टिक डाइस क कृष्णा नगर एम नं. 22 बी मोथडी स्टेशन देवतार, चेन्नै, तमिळुनाडु-400088	मिनी के घरेलू खाद्य मिश्रण 500 वा. 230 वा	01250-30
44	सं एम/एल-2162541	1990-11-01	गोल्ड डेजोनिफे, 110 डी एस आई डी सी रोड्स मोखला फेज-1 नई दिल्ली-110020	फ्लोरेसेंट लैम्प के लिए ब्रैलास्ट 40 वा रेटिंग	01534-77 (भाग-1)
45	सी एम/एल-2162642	1990-11-01	कॉन्फेरेटिव कोटल फीड प्लांट 88 इंड एरिया जोधवाडा अधपुर-302012	मिश्रित पशु आहार टाइट 2 केवल	02052-79

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. सी एम/एल-2162743	1990-11-01	गुजरात काप प्राइवट सीड्स प्रोडर्स फेड लि प्लॉट नं. 1103/1104 तीसरा फेज जी आई डी सी बापी 396195	नस्सिम के लिए नम्य पैक, एक किग्रा बारिश		11952-85
47. सी एम/एल-2162844	1990-11-01	जोतिग्र स्टॉल एंड ट्यूब्स लि 14/3 मथूरा रोड, फरीदाबाद-121003	यांत्रिक और सामान्य प्रयोगों के लिए इस्पात के पाइप, टाइप ई आर डब्ल्यू, थ्रेड डब्ल्यू टी 200		03601-84
48. सी एम/एल-2162945	1990-11-01	सुवेक्स कैमिकल्स लि, स्टेट हाइवे नं. 6 बा. बाबली जि. जि० बलसाङ-396030	एम्बोसलफान ई सी		04323-80
49. सी एम/एल-2163038	1990-11-01	गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कारपो. लि., पेस्टीसाइड कार्मिलेशन यूनिट, आई टी आई के पास, एन एच नं. 8 बी. गोंडल 360311	माइपरमेथिन 25% ड्रममालानुसार ई सी		12016-87
50. सी एम/एल-2163139	1990-11-01	बास्कर एग्रो कैमिकल्स प्रा. लि., 94/1 लूकानपेट घा. मलकापुर पंचायत, नलगोड़ा जि.	मिक्चरफॉस ई सी		08028-87
51. सी एम/एल-2163240	1990-11-01	वि पंजाब पेन्ट कलर एंड वार्निश वर्क्स, 123/529 फजर्गज, कानपुर-208012	विस्टम्पर तैल इमल्शन		00428-89
52. सी एम/एल-2163341	1990-11-01	मोहन जुट मिल लि., सारंगगढ़ रोड, रायगढ़	मीमेंट पैकिंग के लिए हल्के पटसन के कट्टे		12154-87
53. सी एम/एल-2163442	1990-11-01	हेक्स्ट इंडिया लि., प्लॉट नं. 3501—15 और 6301—14 जी आई डी सी एस्टेट, पो. बा. नं. 138, ग्रंजलेखर-393002	कार्बोबाजिम 5% डब्ल्यू पी		08446-77
54. सी एम/एल-2163543	1990-11-01	बी साईबाबा इंडस्ट्रीज, 257/3, प्रीधव रोड, प्रीधव, ग्रहमवाबाद-382410	सी टी डी सॉलर		01786-852
55. सी एम/एल-2163644	1990-11-01	थॉप्स हंजी लि., 850/2 जी आई डी सी मकरपुरा, बडोदरा-390010	निमज्जय पम्पसेट		08034-89
56. सी एम/एल-2163745	1990-11-01	स्वदेश एस्टरप्राइजेज एंड कैमिकल इंड. 111/108ए पोखरपुर, कानपुर	ग्राइसोप्रोट्यूशन 75% डब्ल्यू पी		11995-87
57. सी एम/एल-2163846	1990-11-01	स्वदेशी सीमेंट प्रा. लि., रणतुंगपुरम, तहसील—कोटपुलमी, जि. जयपुर-303121	माधारण पोर्ट लैंड सीमेंट		00269-276

[सं के प्र वि/13 : 11]

New Delhi, the 14th January, 1991

S.O. 448.—In pursuance of sub-regulation (5) of regulation 4 of the Bureau of Indian standards (certification) Regulations, 1938, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given in the following Schedule.

## SCHEDULE

List of Licences Granted During the Month of October 1990

No.	CM/L- No.	Operative Date	Name & Address of the Party	Article/Process	IS: No./Part
1	2	3	4	5	6
1.	CM/L-2158247	1990-10-01	Premier Nutritions 55-A/56, Indl. Area No. 1 A.B. Road Devas 455001	Skim Milk Powder	01165-86

1	2	3	4	5	6
2. CM/L-2158348	90-10-16	Architectural Aid, B-163, Phase II, Noida, Distt. Ghaziabad (UP)		Cement Concrete Flooring Tiles for General Purposes	01237-80
3. CM/L-2158449	90-10-16	Bhandari Cables & Conductors, 15.5 Km, Belgaum, Vengurla Road, R. 5.127 Shinoli, Talluk Chand Garh, Distt. Kolhapur-416508		ASCR Conductors	0398-76 (Part 1)
4. CM/L-2158550	90-10-16	Naykar Cables & Conductors 15th Km, Belgaum, Shinoli, Talluk Chand Garh, Distt. Kolhapur-416508		ASCR Conductors	00398-76 (Part 2)
5. CM/L-2158651	90-10-16	Naykar Cables & Conductors, 15th Km, Belgaum Vengurla Road, Shinoli, Talluk Chand Garh, Distt. Kolhapur-416508		Aluminium Conductors Galvan- ized Steel Reinforced	00398-76 (Part 1)
6. CM/L-2158752	90-10-16	Prabhu Steel Inds. Ltd. 159-160, Small Factory Area, Bagadganj, Nagpur-440008		Weldable Structural Steel Grade FE 410 WA	02062-84
7. CM/L-2158853	90-10-16	Aluminium Coating Mfrs. of India, Shed No. 3/I, Road No. 1A, Indl. Estate Govindpura, Bhopal 462023		Bitumen Primer for use in Water-proofing and Damp Proofing	03384-86
8. CM/L-2158954	90-10-16	Sama Steel Inds. (P) Ltd. Delhi Road, Bhadua, PO Bamunari, Distt. Hooghly (WB)		Structural Steels (Standard Quality)	00226-75
9. CM/L-2159047	90-10-16	Sama Steel Industries (P) Ltd., Delhi Road, Bhadua, PO Bamunari, Distt. Hooghly (WB)		CTD Bars	01786-85
10. CM/L-2159148	90-10-16	Master Home Appliances, Plot No. 136/2, Nr. Primary School, Village Badli, Delhi-110042		Domestic Stoves for use with LPG	04246-84
11. CM/L-2159249	90-10-16	Seshasaila Cements Pvt. Ltd 315, Sadarahalli Village, CN Hali Talluk, Distt. Tunkur,		Ordinary Portland Cement	00269-76
12. CM/L-2159350	90-10-16	Tyre Corporation of India Ltd. 127, Kattadanga Road, Kankinara, PO Fingapara, Distt. 24 Parganas		Truck and Bus Tyres	10914-88 (Part 2)
13. CM/L-2159451	90-10-16	Hoechst India Ltd., Plot No. 3601-15 & 6301 to 14, Gide Estate, Ankleshwar (Gujarat)		Endosulphan EC	04323-80
14. CM/L-2159552	90-10-16	Andhra Ispat Ltd. 31 Km Stone, Hyderabad-Varangal, Road, Konda Maduvu Village, PO BB Nagar, Distt. Nalgonda		CTD Bars	01786-85

1	2	3	4	5	6
15.	CM/L-2159653	90-10-16	Jainsons Minerals, 27 A, Indl. Area, Fatehabad-125050	Butachlor EC	09356-80
16.	CM/L-2159754	90-10-01	Parijat Chemical Inds., D-11, Big Indl. Estate, Varanasi-221006	Disinfectant Fluids Class A Grade 3 Type Normal and Winter	01061-82
17.	CM/L-2159855	90-10-16	The Tin Company, 61 Daba Road (G.T. Road East), PO Lohara, Ludhiana	15 Kg Square Tins for Ghee, Vanaspati, Edible Oils and Bakery Shortenings	10325-89
18.	CM/L-2159956	90-10-16	Indo Sham Inds., 33, Anand Indl. Estate, Mohan Nagar, Ghaziabad (UP)	Latex Foam Rubber Products Type Cored Grade "F" only	01741-60
	CM/L-2160032	90-10-16	Kakku Steel Mills, Village Tedesara, Distt Rajnangaon (MP)	CTD Barrs	01786-16
20.	CM/L-2160133	90-10-16	Aluminium Cables & Conductors, A-82, Indl. Estate, Rajaji Nagar, Bangalore 560044	ASCR Conductors	00398-76 (Part 1)
21.	CM/L-2160234	90-10-16	L.V.T. Containers, B-464, Indl. Estate, Gokul Road, Hubli-580030	15 KG Square Tins for Ghee, Vanaspati, Edible Oils and Bakery Shortenings	10325-89
22.	CM/L-2160335	90-10-16	L.V.T. Containers, B- 464, Indl. Estate, Gokul Road, Hubli-580030	18 Litre Square Tins	00916-75
23.	CM/L-2160436	90-10-16	Champion Electrical Inds., A-37, G.T. Karnal Road Indl. Area Delhi-110033	Electric Iron 750W 230 V AC	00366-85
24.	CM/L-2160537	90-10-16	Consolidated Steels Alloys Ltd., 35-38, Indl. Area, Banmore, Distt. Morena (MP)	Structural Steel (Standard Quality)	00226-76
25.	CM/L-2160638	90-10-16	Consolidated Steels & Alloys Ltd., 35-38, Indl. Area Banmore, Distt. Morena (MP)	Weldable Structural Steel Grade FE 410 WA	02062-86
26.	CM/L-2160739	90-10-16	Bhoruka Steel Ltd., Mahadev Pura, Post Whitefield Road, Bangalore-560048	Mild Steel for Metal ARC Welding Electrodes Core Wires	02876-75
27.	CM/L-21608 0	90-10-16	Shakti Concrete Pvt. Ltd., C-40, Amausi Indl. Area, Lucknow	Concrete Pipes NP 2 150 & 300 MM Size only	00458-71
28.	CM/L-2160941	90-10-16	Megna Jute Mills, A Unit of Gajanand Commercial (P) Ltd., PO Jagatdal, Distt. 24 Parganas (WB)	B-Twill Jute Bags for Packing Food Grains	02566-84
29.	CM/L-2161034	90-10-16	Kamarhatty Company Ltd., 907, Graham Road, Kamarhatty Calcutta-770058	Jute Tarpaulin Fabric 407 GM SQ	07407-80 (Part 2)

1	2	3	4	5	6
30. CM/L-2161135	1990-10-16	Kalinga Chemical Inds. S-3/82, Mancheswar (Now) Indl. Estate Bhubaneswar 751010	Integral Cement Water Proofing Compound	02645-75	
31. CM/L-2161236	1990-10-16	Subbiah Foundry 1205 to 1208 Avanashi Road PN Palayam Coimbatore 641037	Monoset Pumps for Clear, Cold, Fresh water for Agricultural Purposes	08079-79	
32. CM/L-2161337	1990-10-16	Suku Equipments & Inds. 211/1, Kurudampalayam Edigarai Road Nggo Colony PO Coimbatore 641022	Submersible Pumpsets	08034-76	
33. CM/L-2161438	1990-10-16	Greenfield Pipes (P) Ltd. Meerut Road Mawana 250401	Unplasticized PVC Pipes for Potable Water Supplies Size 63 MM to 180 MM Class 2	04985-88	
34. CM/L-2161539	1990-11-01	Hindustan Insecticides Ltd. PO Rasayani Distt. Raigadh 410207	Butachlor Technical	09355-80	
35. CM/L-2161640	1990-11-01	Ajanta Cables Pvt. Ltd. 9/80, Gali Bagichi Vishwas Nagar Delhi 110032	PVC Insulated Winding Wires for Submersible Motors	08783-78	
36. CM/L-2161741	1990-11-01	North West Switchgear Ltd. 14/3, Mathura Road Faridabad 121003	Three Pin Socket Outlets 250 V, 6AMP	01293-88	
37. CM/L-2161842	1990-11-01	Chakradhar Chemicals Pvt. Ltd. E-3, Upside Indl. Area Bagraj Pur PO Manjarpur Distt. Muzaffarnagar	Zinc Sulphate, Agricultural Grade	08249-76	
38. CM/L-2161943	1990-11-01	STP Ltd. P-46, Hide Road Extension Calcutta 700088	Bitumenous Compound for Water Proofing and Caulking Purposes	01580-69	
39. CM/L-2162036	1990-11-01	Anand Metal Works C-143, Naraina Indl. Area New Delhi 110028	PVC Insulated (Heavy Duty) Electric Cables for Working Voltages upto and Including	01554-76 (Part 1)	
40. CM/L-2162137	1990-11-01	Shri Sai Baba Steel Inds. 275/3, Odhav Road Odhav Ahmedabad 382410	Structural Steel (Standard Quality)	00226-75	
41. CM/L-2162238	1990-11-01	Lupin Agro Chemicals (India) Pvt. Ltd. 242/P, GIDC Panoli Distt. Bharuch (Gujarat)	Phosphamidon 85% SL	06177-81	
42. CM/L-2162339	1990-11-01	Marco Cables Pvt. Ltd. Plot No. A-55-56 Stice Sinar, Sirdi Road Sinnar 422103	PVC Insulated Sheathed/Unsheathed Cables upto and Including 1100 V Excluding Outdoor and Low Temperature Applications	00694-77	
43. CM/L-2162440	1990-11-01	Plastic Dyes Co. Krishna Bhavan S.No. 22 B Gowandi Station Road Deonar, Chembur Bombay 400088	Domestic Electric Food Mixers 500 W 230 Volts	04250-80	
44. CM/L-2162541	1990-11-01	Monarch Engineers 110, DSIDC Shades Okhla Phase I New Delhi 110020	Balasts for Fluorescent Lamps 40 Watts Rating	01534-77 (Part 1)	

1	2	3	4	5	6
45.	CM/L-2162642	1990-11-01	Co-Operative Cattlefield Plant, 88, Indl., Area Jhotwara Jaipur 302012	Compounded Feeds for Cattle Type 2 Only	02052-79
46.	CM/L-2162743	1990-11-01	Gujarat Co-Op. Oil Seeds Gro- wers Fed. Ltd. Plot No 1103/1104 Third Phase GIDC Vapi 396195	Flexible Packs for Packing Vanaspati One kg Capacity	11352-85
47.	CM/L-2162844	1990-11-01	Jotindra Steel & Tubes Ltd. 14/3, Mathura Road Faridabad 121003	Steel Tubes for Mechanical and General Engineering Purposes Type ERW Grade WT200	03601-84
48.	CM/L-2162945	1990-11-01	Sumex Chemicals Ltd. State Highway No. 6 PO Bhadeli Distt. Valsad 396030	Endosulphan FC	04323-80
49.	CM/L-2163038	1990-11-01	Gujarat Agro Industries Corpn. Ltd. Pesticide Formulation Unit Near ITI NH No. 8 B Gondal 360311	Cypermethrin 25% M/M EC	12016-87
50.	CM/L-2163139	1990-11-01	Bhaskar Agro Chemicals Pvt. Ltd. 94/1, Toophranpet Village Malkapur Panchayat Nalgonda Distt.	Quinalphos EC	08028-87
51.	CM/L-2163240	1990-11-01	The Punjab Paint Colour & Varnish Works 123/529, Fazal Ganj Kanpur 208012	Distemper Oil Emulsion	00428-69
52.	CM/L-2163341	1990-11-01	Mohan Jute Mills Ltd. Sarangarh Road Raigadh (MP) 496004	Light Weight Jute Bags for Packing Cement	12154-87
53.	CM/L-2163442	1990-11-01	Hochst India Ltd. Plot No. 3501-15 & 6301-14 GIDC Estate PN No. 136 Ankleshwar 393002	Carbendazim 50% WP	08446-77
54.	CM/L-2163543	1990-11-01	Shree Saibaba Industries 257/3, Odhav Road Odhav Ahmedabad 382410	CTD Bars	01786-85
55.	CM/L-2163644	1990-11-01	Shroffs Engineering Ltd. 850/2, GIDC Makar Pura Vadodara 390010	Submersible Pumpsets	08034-89
56.	CM/L-2163745	1990-11-01	Swadesh Enterprises & Chemical Inds. 111/108-A Pokhar Pur Kanpur	Isoproturon 75% WP	11995-87
57.	CM/L-2163846	1990-11-01	Swadeshi Cement Ltd. Rungtapuram Tehsil Kotputli Dist. Jaipur 303121	Ordinary Portland Cement	00269-76



का भा. 449 -- भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1985 के विनियम 4 के उपविनियम (3) के अनुसूचन में भारतीय मानक ब्यूरो एलबुद्धारा अधिष्ठाित करता है कि जिन लाइसेंसें के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे स्वीकृत कर दिए गए हैं।

## अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या	लागू होने की तारीख	लाइसेंसधारी का नाम और पता	लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया और सम्बद्ध भारतीय मानक की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2163947	90-11-01	निलोन निर्माण लि., ब्लाइड सीमेंट प्रोजेक्ट, भरोलिया नगर, ग्रा एवं डा-गोटन जि--मानीर	मफेद पोर्टलैंड सीमेंट आई एस : 08042-78
2.	2164040	90-11-16	एम. एन. कैमिकल्स इंडस्ट्रीज, बी-25 गवर्नमेंट एस्टेट, महरोली, रोड, गुडगांव	फिब्रालफॉर्म ई सी
3.	2164141	90-11-16	कमानी इंडस्ट्रीज, बी-25 गवर्नमेंट इंड एरिया, महरोली रोड, गुडगांव	1100 बो तक कार्यकारी बोल्डता के लिए तांबा चालकों वाली पी बी सी रोधित केबल
4.	2164242	90-11-16	दशमुख केबल्स, प्लाट नं. 52 इंड एरिया उल्हासनगर, जिला--ठाणे	तांबा और एल्युमिनियम चालकों वाली पी बी सी रोधित और पी बी सी का जोल चड़ी केबल
5.	2164343	90-11-16	प्रोप्रिसेव इंड कारपो. उल्हासनगर जिला--ठाणे-421002	अग्नि उष्ण बोल्डता के लिए (400 कि. वा और अधि) ए सी ए धार चालक
6.	2164444	90-11-16	किसान इंसेपटीसाइड्स कं सी 14, इंड एस्टेट, विजयवाड़ा-520007	फिब्रालफॉर्म ई सी
7.	2164545	90-11-16	किसान इंसेपटीसाइड्स कं., सी 14, इंड एस्टेट, विजयवाड़ा-520007	काबोडाजिम बल्यू डी पी सी
8.]	2164646	90-11-16	किसान इंसेपटीसाइड्स कं., सी - 14, इंड एस्टेट, विजयवाड़ा - 520007	मोमोकोटोफॉस एस एस आई एस : 08074-83
9.	2164747	90-11-16	कमकीया परमेस्वरी इंजीनियरी प्रा. लि (। सर्च नं. 773, खाराराम गांव, संगारेड्डी तालुक, जिला मेडक	द्रवित पैट्रोलियम गैस सिलिन्डरो का रिकंडीशनिंग आई एस : 03198-82
10.]	2164848	90-11-16	विजय केबल इंडस्ट्रीज, बी-7, बी-8, सेक्टर 1, तोण्डा	1100 बो तक कार्यकारी बोल्डता हेतु जालिकावत पॉलीथीन (एस एस पी ई) रोधित और पीबीसी का आई एस : 07098 - 77 (भाग 1)
11.	2164949	90-11-16	प्रवर्तक जूट मिल्स लि., कमारहट्टी बी. टी. रोड, कलकत्ता - 700058	380 ग्रा/मी पटसन टारपुलिन आई एस 07407-80 (भाग III)
12.]	2165042	90-11-16	सेन्चुरी सैफिनेटर्स, 103/25, कोरली रोड, शिवपुर, हावड़ा-बप	उर्वरक पैकिंग के लिए 407 ग्रा/मी टारपुलिन के परतदार पटसन के कट्टे आई एस : 07046-84 (भाग 1)।
13.]	2165143	90-11-16	सेन्चुरी सैफिनेटर्स, 103/25 कोरली रोड, शिवपुर, हावड़ा (प ब )	380 ग्रा/मी टारपुलिन के परतदार पटसन के कट्टे आई एस : 07406-86 (भाग II)
14.]	2165244	90-11-16	लुथी अलैक्ट्रिकल्स लि., नरोडा रोड, कल्याण मिल्स के पास, अहमदाबाद - 380025	415 बो 50 टर्टेज 7.5 किवा, तीन फेजी प्रेरण मोटर श्रेणी बी 1430 च म मि आई एस : 00325 - 78

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	2165345	90-11-16	स्पेस एन्टरप्राइजेज, 10 न्यू टेनमिल पुरा, अमनसर	बिजली के नियन्त्रण हीटर 100 और 2000 वा आई एस : 00368-83
16	2165446	90-11-16	अहिरा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स मैन्युफैक्चरर्स लि., प्लॉट नं. 58 (एसपी) 11वां साउथ रोड अम्बात्पूर इड. एस्टेट अम्बात्पूर, मद्रास - 600058	संरचना इस्पात की धातु आर्क वेल्डिंग हेतु आवरित इलेक्ट्रोड आई एस : 00814-74 (भाग 1)
17	2165547	90-11-16	त्रिवेणी कास्टिंग्स (प्रा.) लि., प्लॉट नं. 51-52, सेक्टर 5, परवाना (हि. प्र.)	संरचना इस्पात (मानक किस्म) में वेल्डिंग हेतु उलवां विलेट इंगट आई एस : 06914-78
18	2165648	90-11-16	त्रिवेणी कास्टिंग्स (प्रा.) लि., प्लॉट नं. 51-52, सेक्टर 5, परवाना (हि. प्र.)	संरचना इस्पात में वेल्डिंग हेतु उलवां विलेट इंगट ग्रेड 1 और 2 मानक किस्म आई एस : 06915-78
19	2165749	90-11-16	मैसूर मिनरल्स लि., बामेश पुरा, जिला हसन, (कर्नाटक)	लवण से ग्लेज किए स्टोनबेअर के पाइप ग्रेड ए 100 सी साइज आई एस : 00651-80
20	2165850	90-11-16	स्टील मथारिटी आफ इंडिया लि., भिलाई इस्पात संयंत्र	सामान्य प्रयोजन हेतु मृदु इस्पात की तार छड़ आई एस : 07887-75
21	2165951	90-11-16	दीवान इंस्टीट्यूट (रजि.), 308/5-ए, गुरुजाबा बाग, पुराना रोहतास रोड, नई दिल्ली - 35	भारी वस्तुओं हेतु फर्श स्प्रिंग ब्रव आसन द्वारा नियंत्रित आई एस : 06315-86
22	2166044	90-11-16	हाटस्टार इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लि., बी-1 सेक्टर 5, नोएडा	लगातार पानी गर्म करने के बिजली के हीटर एक लिटर धारिता, 3 किवा रेटिंग संरचना इस्पात (मानक किस्म) आई एस : 00226-75
23	2166145	90-11-16	स्टालिंग रिरोलिंग मिल्स लि., कोयोट रोड, ठाण	
24	2166246	90-11-16	मार्सेन (इंडिया) इंस्टीट्यूट अलाना कंपाउंड, एवीपाडापोली स्टेशन के सामने, डा. एन. एम. रोडम बम्बई - 400011	कोलतार आधारित निर्मितियां, ठोस पाइप
25	2166347	90-11-16	बिकट्री प्रायवट वर्क्स लि., पी-26 बनारस रोड, सालकिया, हावड़ा - 711106	मल, गंदे जल और संवातन पाइप हेतु बाष्प के सांके में डब्ले स्पिगट और साकेट आई एस : 01729-79
26	2166448	90-11-16	जयलक्ष्मी सप्लाय कारपो., 8 परालाडांगा रोड, कलकत्ता - 700039	केमबस के बूट, रखड़ का तल्ला आई एस : 03736-83
27	2166549	90-11-16	वि गौरीपुर क. लि., पोस्ट आफिस गौरीफा, 24 परगना (उ)	ए-ट्रिबल पटसन के बीरे आई एस : 01943-64
28	2166650	90-11-16	एनके टिम्बर इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि., नं. 283/2, पुराना महावलीपुरम रोड, कोट्टीमायम, मद्रास - 600096	इमारती लकड़ी के पैन्लीकृत और ग्लेज किए गट्टर, डोर गट्टर, सजावटी कर्णबोर्ड वाले केवल आई एस 001003-77 (भाग 1)
29	2166751	90-11-16	राजिन्कर पाइप्स लि., 23वां किमी का पथर, कालपी रोड, रनिया के पास ग्राम जिरौरा के पास डा - रायपुर, जुबिल, कानपुर बेहात	एमएस पाइप, ई आर डब्ल्यू पेच कसे, साकेट चक्रे और सांके सिरे वाले
30	2166852	90-11-16	एवरशाइन वेग्ट एंड कौमीकल्स इड, डब्ल्यू - 19 घोखला इड. एरिया, फेज - II, नई दिल्ली - 110020	वांछित रंग के शुष्क डिस्टम्पर   आई एस : 00427-65

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31. 2166953	90-11-16	प्रोसवाल वनस्पति एंड एलाइड इंड, प्रा प्रोसवाल वूलन मिल्स लि., जी. टी. रोड शेखपुर, लुधियाना - 141003	वनस्पति पैकिंग के लिए नम्य पैक 1 कि ग्रा धारिता आईएस : 11352-85	
32. 2167046	90-11-16	वि गौरीपुर कं० लि., डा-गोरीफा, 24 परगना (उ.)	खाद्यान्न पैकिंग हेतु बी टिबल पटसन के बीरे आईएस : 02566-84	
33. 2167147	90-11-16	नेशनल फार्म कैमीकल्स, बी-16, ई.ए. एरिया, यू पी आई एस आई बी सी, सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर (उ० प्र.)	एन्डोसल्फान, ईसी आईएस : 04323-80	
34. 2167248	90-11-	महावीर वनस्पति कं., खरार, जिला रोपड़ (पंजाब)	वनस्पति पैकिंग के लिए नम्य पैक, 1 किग्रा. धारिता आईएस : 11352-85	
35. 2167348	90-12-01	जैम इंडस्ट्रीज, योगेश्वर मठ मार्ग, टिकैतराज तालुक, लखनऊ - 226006	1100 बी कि कार्यकारी बोल्डता हेतु एल्यू- मिनियम चालकों वाली पीबीसी रोहित बोल्ड सहित और बोल्ड रहित केबलें आईएस : 00694-77	
36. 2167450	90-12-01	बंगलौर पेस्टीसाइड्स लि., 16वां किमी, तुमकूर रोड, बंगलौर - 560073	केपटेन डब्ल्यू बी पी आईएस : 11785-86	
37. 2167551	90-12-01	राजश्री फूड्स प्रा. लि., नं. 17, प्लेटफार्म रोड, बंगलौर - 560020	बिस्कुट (मैरी क्रिस्ट) आईएस : 01011-81	
38. 2167652	90-12-01	विलियम एंड विलसन पेन्ट्स, 65 मैक्सी रोड, आई टी आई कॉलेज, उज्जैन (म. प्र.)	ब्लैक जापान, टाइप ए केबल आईएस : 00341-73	
39. 2167753	90-12-01	एक्सपो एंटर प्राइजेज, 380-81, गली माता वाली, तेजीबाड़ा - 11 दिल्ली - 110006	एअर कंडीशनर एसी परीपक्ष के साथ प्रयुक्त तापस्थापी, 230 बी, 25 एम्प तापमान + 15 से 300 से आईएस : 11338-85	
40. 2167854	90-12-01	सजिमेन्ट्स लि., नं० 39 पांचवां क्रॉस, वाम सांघा इंड. एरिया, वामसांघा, भाटी बेरा, बंगलौर जिला	द्रव्यालित आपरेशन की भेज (माइनर) आईएस : 06106-71	
41. 2167955	90-12-01	ए. के. प्राइजेज, 507-50, जस्तौर रोड, कलकत्ता - 700074	मुवाहय अग्निशामकों के लिए रिफिल आईएस : 05490-77 (भाग 2)	
42. 2168048	90-12-01	वि हुगली मिल्स कं० लि., (वेबरली जट मिल की ईकाई) डा-अधपुर जि. 24 परगना पि. - 743138	मीमेंट पैकिंग हेतु हल्के पटसन के कट्टे आईएस : 12134-87	
43. 2168149	90-12-01	जी एम एसोसिएट्स प्रा. लि., प्लाट नं. 79, वाली रोड, फरीदाबाद (हरियाणा)	पूर्ण प्रबलित कच्ची पाइप, 600 मिमी, 800 मिमी और 900, 1200 मिमी आईएस : 00784-78	
44. 2168250	90-12-01	वैस्टन इलेक्ट्रॉनिक्स लि., 240 ओखला इंड. एस्टेट, नई दिल्ली - 110020	सीटीवी अभिप्राही/सीटू. ऑन आईएस : 10662-83	
45. 2168351	90-12-01	मार्कंडेय प्रसाद राधाकृष्ण प्रसाद, 56 दशरथ घोष लेन, हावड़ा - 711001	मल गंदे जल और संवाती पाइप हेतु जालू के साथ में ठले मोहों के स्पिगट और पाइप आईएस : 01729 - 79	
46. 2168452	90-12-01	फिनोलेक्स केबल्स लि., 26/27 बम्बई-पुणे रोड, पिम्परी, पुणे	निमज्ज्य पम्पसीट हेतु पीबीसी रोहित ब्रेन्डताए, ग्रेड ए, टाइप 2 आईएस : 08783-78	
47. 2168553	90-12-01	टाइगर सैल्स इंडस्ट्रीज, 12 एसएन रॉय रोड, कलकत्ता - 700036	सामान्य प्रकाश सेवा हेतु टंगस्टन बल्ब, 15 से 100 बी एक कुंडली आईएस : 00418-78	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48	2168654	90-12-01	बैंग्लेज इंडिया, जेब व्यास चौक, राउरकेला, जिला - सुन्वरगढ़ (उड़ीसा) पिन-769041	हथ करघे की सूती गांज प्रयशोपी गैर निर्जमिन ग्राई एस : 00758-88
49.	2168755	90-12-01	बैंग्लेज (इंडिया) वेशव्याम चौक, राउरकेला जिला- सुन्वरगढ़ (उड़ीसा) पिन - 769041	हथकरघे की सूती पट्टी का कपड़ा, गैर निर्जमिन ग्राई एस : 00863-88
50.	2168856	90-12-01	एस. एच. एन्टरप्राइजेज, समानरोज स्टील वर्क्स कम्पाउंड, नारायण कोल्ड स्टोरेज के सामने	वनस्पति और खाद्य तेलों हेतु 15 किग्र. के बोकोर कमस्तर ग्राई एस : 10325-89
51.	2168957	90-12-01	कम्फर्ट एप्लाइसेज, 10292, मानकपुरा, करौल बाग, नई दिल्ली - 110005	बिजली की इस्तरियां, 75 वां 230 बो डलबा लोडों की तल प्लेट सहित तापस्थायी ग्राई एस : 00366-85
52.	2169050	90-12-01	खला इलेक्ट्रिकल्स, 8065, स्टीट न. 8, मुल्तानी बागडा, पहाड़गंज, नई दिल्ली - 110055	बिजली की इस्तरियां, 75 वां 230 बो एल्यु-मिनियम की तल प्लेट सहित ग्राई एस : 00366-85
53.	2169151	90-12-01	सुवर्ण कैंपिस्टर्स प्रा. लि., 12-ए एमआईसीसी एरिया, इस्लामपुर, जिला-सांगली, महाराष्ट्र - 431803	पावर रेंज हेतु शॉट सधारित्र 415/440 बो. 15 और 25 केवाएम्पार ग्राई एस : 02834-86
54.	2169252	90-12-01	सेनको पावीमर्ने, 19/51, बाजार गली, विश्रवाम नगर, माहूवरा, दिल्ली - 110092	विद्युत सस्यापन हेतु कंड्यूट वृह साथे कंड्यूट 25 मिमी साइज, मध्यम यालिकी विकृति ग्राई एस : 09537-83 (भाग 3)

[म के प्र नि/1311]

S.O.449-- In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 3 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulation, 1985, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences of particulars of which are given in the following schedule:

## SCHEDULE

## List of Licences Granted During the Month of November 1990

SJ. No.	CM/L-No.	Operative Date	Name & Address of the Party	Article/Process	IS : No./Part
1.	2163947	90-11-01	Nilon Nirman Ltd. White Cement Project Bholotia Nagar Village & PO Gotan Distt. Nagaur-342902	White Portland Cement	08042 : 78
2.	2164040	90-11-16	S.N. Chemical Industries B-25, Govt. Indl. Estate Mehrauli Road, Gurgaon-122001	Quinalphos EC	08028 : 87
3	2164141	90-11-16	Kamani Industries C/3-3, GIDC Estate Mill Road Nadiad-387001	PVC Insulated Unsheathed Cables with Copper Conductors for working Voltage upto and Including 100 V	00694 : 77
4	2164242	90-11-16	Deshmukh Cables Plot No. 52 Industrial Area O.P. Section, Khemani Ulhas Nagar Distt. Thane-421002	PVC Insulated and Sheathed Cables with Aluminium and Copper Conductors Including Cables for Outdoor Application	00694 : 77
5.	2164343	90-11-16	Progressive Indl. Corpn. Old Hazari Bagh Road Ranchi-834001.	ACSR Conductors for Extra high Voltages (400 KV and above)	00839 : 82 (Part V)

1	2	3	4	5	6
6. 2164444	90-11-16	Ksian Insecticides Co. C-14, Indl. Estate Vijaywada-520007	Quinalphos EC	08028 : 87	
7. 2164545	90-11-16	Kisan Insecticides Co. C-14, Indl. Estate Vijaywada-520007	Carbendazim WDPC	08446 : 77	
8. 2164646	90-11-16	Kisan Insecticides Co. C-14, Indl. Estate Vijaywada-520007.	Monocrotophos SL	08074 : 83	
9. 2164747	90-11-16	Kanyaka Parameshwari Engg. Pvt/Ltd. Survey No. 773 Rudraram Village Sangareddy Talluk Disst. Medak (AP)	Reconditioning of LPG Cylinders	03196 : 82	
10. 2164848	90-11-01	Vijay Cable Industries B-7, B-8, Sector I Noida (UP)	Cross Linked Polythelene (SLPE) Insulated and PVC Sheathed Cables for working Voltages upto and including 1100 Volts	07098 : 77 (Part 1)	
11. 2164949	90-11-16	Prabartak Jute Mills Ltd. Kamarhati B.T. Road Calcutta-700058	Jute Tarpaulin Fabric 380G/M SQ	07407 : 80 (Part-III)	
12. 2165042	90-11-16	Century Laminators 103/25, Foreshore road Shibpur Howrah	Laminated Jute Bags for Packing Fertilizers 407 G/M SQ	07406 : 84 (Part I)	
13. 2165143	90-11-16	Century Laminators 103/25, Foreshore Road Shibpur Howrah (WB)	Laminated Jute Bags for Packing Fertilizers 380 G/M SQ	07406 : 86 (Part II)	
14. 2165244	90-11-16	Lubi Electricals Ltd., Naroda Road Near Kalyan Mills Ahmedabad-380025	Three phase Induction Motors 415 Volts 50 HZ 7.5 KW Class B 1440 RPM	00325 : 78	
15. 2165345	90-11-16	Space Enterprises 10, New Tensil Pura Amritsar	Electric Immersion water Heater 1000 and 2000 W	00368 : 83	
16. 2165446	90-11-16	Ahura welding Electrodes Man UFACTURERS Ltd., Plot No. 58 (SP) 11th South Road Ambattur Indl. Estate Ambattur Madras-600058	Covered Electrodes for Metal ARC Welding of Structural Steel	00814 : 74 (Part 1)	
17. 2165547	90-11-16	Triveni Castings (P) Ltd., Plot No. 51-52 Sector V Parwanoo (HP)	Cast Billet Ingots for Rolling Into Structural steel (Standard Quality)	06914 : 78	
18. 2165648	90-11-16	Triveni Castings (P) Ltd., Plot No. 51-52 Sector V Parwanoo (HP)	Cast Billet ingots for rolling into structural Steel Grade 1 and 2 Standard Quality.	06915 : 78	
19. 2165749	90-11-16	Mysore Minerals Ltd., Bagesh Pura Arsikere Talluk Hasan Distt. (Karnataka)	Salt Glazed Stoneware Pipes Grade A 100 M Size	00651 : 80	
20. 2165850	90-11-16	Steel Authority of India Ltd. Bhilai Steel Plant	Mild Steel wire Rods for General Purposes 5 to 12 MM Dia	07887 : 75	
21. 2165951	90-11-16	Diwan Industries (Regd.) 308/5-A Shehzada Bagh Old Rohtak Road, New Delhi-1110035	Floor Springs (Hydraulically Regulated) for Heavy Doors	06315 : 86	

1	2	3	4	5	6
22. 2166044	90-11-16	Hot Star Electricals Pvt. Ltd., B-41, Sector V Noida (UP)	Electric Instantaneous water Heaters (Closed Type) one Litre Capacity 3 KW rating.	08978-85	
23. 2166145	90-11-16	Sterling re-rolling Mills Ltd., Kolshet Road, Thane (MS)	Structural Steel (Standard Quality)	00226 : 75	
24. 2166246	90-11-16	Marson (I) Industries Allana Compound Opp. Agripadapoli Station Dr. A.N. Road, Bombay-400011	Coaltar Food Colour Preparation Solid type	05346 : 75	
25. 2166347	90-11-16	Victory Iron Works Ltd., P-26, Benaras Road Salkia Howrah-711106	Sand Cast Iron Spigot and Socket Soil, Waste and Ventilating Pipes Size 100 MM	01729 : 79	
26. 2166448	90-11-16	Jaylakami Supply Corpn., 8, Pagladanga Road Calcutta-700039.	Canvas Boots, Rubber Sole	03736 : 83	
27. 2166549	90-11-16	The Gorepore Co. Ltd., PO Gorifa 24 Parganas (North)	A-Twill Jute Bags	01943 : 64	
28. 216650	90-11-16	Enkay Timber Industries (P) Ltd., No. 283/2, Old Mahabalipuram Road Kottivakkam Madras-600096.	Timber Panelled and Glazed Shutteres, Door Shutters, Veneered Partical Board only	01003 : 77 (Part-1)	
29. 2166751	90-11-16	Rajinder Pipes Ltd., 23rd KM Stone, Kalp Road NH-2, Indl. Area Nr. Rania, Village Chiraura PO Raipur, Kukhat Kanpur Dehat	M.S. Tubes ERW Black only, Screwed, Socketed and Plainends size 15 MM to 100 MM	01239 : 79 (Part 1)	
30. 2166852	90-11-16	Evershine Paint & Chemical I NDS. W-19, Okhala Indl. Area Phase-II, New Delhi-110020.	Distember, Dry, Colour as Required	00427 : 65	
31. 2166953	90-11-16	Oswal Vanaspati & Allied Inds. Prop. Oswal Wollen Mills Ltd., G.T. Road, Sherpur Ludhiana-141003	Flexible pack, one KG Capacity for Packing Vanaspati	11352 : 85	
32. 2167046	90-11-16	The Gorepore Co. Ltd. PO Gorifa 24 Parganas (North)	B-Twill jute Bags for packing Food Grains	02566 : 84	
33. 2167147	90-11-16	National Farm Chemicals B-16, Indl. Area UPSIDC Sikandarabad, Distt. Bulandshahr (UP)	Ednosulphan EC	04323 : 80	
34. 2167248	90-11-16	Mahavir Vanaspati Co. Kharar Distt Ropar (Punjab)	Flexible Packs One KG Capacity for packing Vanaspati.	11352 : 85	
35. 2167349	90-12-01	GEM Industries Yogeshwar Math Marg Tikait Rai Talav Lucknow-226004	PVC Insulated Sheathed and Unsheathed cables with Aluminium conductors for Voltages upto and including 1100 V	00694 : 77	
36. 2167450	90-12-01	Bangalore Pesticides Ltd., 16th KM Tumkur Road Bangalore-560073.	Captan WDP	11785 : 86	
37. 2167551	90-12-01	Rajashri Foods Pvt. Ltd. No. 17, Platform Road Bangalore-560020.	Biscuits (Marie Variety)	01011 : 81	
38. 2167652	90-12-01	William & Wilson Paints 65, Mexi Road Opp. ITI College Uggain (MP)	Black Japan, Type A Only	00341 : 73	

1	2	3	4	5	6
39. 2167753	90-12-01	Expo Enterprises, 380-81, Gali Matawali, Teliwara, Delhi-110006	Thermostat for use with air Conditioners AC Circuits 250V 25 AMP Temperature $\pm 15$ to $\pm 30$ Deg C	11338 : 85	
40. 2167854	90-12-01	Surgiments Ltd., No. 39 Fifth Corss, Bommasandra Indl. Area, Bommasandra Attibela Bangalore Distt.	Hyrdaulic Operation Table Minor	06106 : 71	
41. 2167955	90-12-01	A.K. Enterprise, 507/50, Jassore Road, Calcutta-700074.	Refill for Portable fire Extinguishers Foam Type	05490 : 77 (Type II)	
42. 2168048	90-12-01	The Hooghly Mills Co. Ltd., (Unit Waverly Jute Mills) PO Athpur Distt. 24 Parganas-743128	Light weight Jute Babs for Packing Cements	12154 : 87	
43. 2168149	90-12-01	GM. Associates Pvt. Ltd., Plot No. 79, Pali Road, Faridabad (Haryana)	Prestressed Concrete Pipes 600 MM, 800 mm, 900 MM and 1200 MM Size	00784 : 78	
44. 2168250	90-12-01	Western Electronics Ltd., 240, Okhala Indl. Estate, New Delhi-110020.	CTV Receivers/Cetron V	10662 : 83	
45. 2168351	90-12-01	Marcandy Prasad Radhakrishna Prasad, 46, Dashrath Ghosh Lane, Howrah-711001	Sand, Cast Iron Spigot and Socket Soil waste and Ventilating Pipes 100MM Size	01729 : 79	
46. 2168452	90-12-01	Finolex Cables Ltd., 26-27, Bombay-Pune Road, Pimpri, Pune-411018	PVC Insulated winding wires for Sumbersible Motors Grade one Type Two	08783 : 78	
47. 2168553	90-12-01	Tiger Lamps Industries 12, S.N. Roy Road Calcutta-700038.	Tungsten Filament General Service Electric Lamps 15 to 100 W, 230 V Single Coil.	00418 : 78	
48. 2168654	90-12-01	Bandage (India), Ved Vyas Chowk, Rourkela Distt. Sundergarh (Orissa)-769041	Handloom Cotton Gauge Absorbent, Non-sterilized	00758 : 88	
49. 2168755	90-12-01	Bandage (India) Ved Vyas Chowk, Rourkela Distt. Sundergarh (Orissa) 769041	Handloom Cotton Bandage Cloth Non-sterilized	00863 : 88	
50. 2168856	90-12-01	S.H. Enterprises Amand Raj Steel Works Compound, Opp. Narayan Cold Storage G.T. Road, Amritsar (PB)	15 Kg Square Tins for Vanaspati and Edible Oils	10325 : 89	
51. 2168957	90-12-01	Comfort Appliances 10292, Manakpura, Karol Bagh New Delhi-110005	Electric Irons 750 W, 230 V Thermostatic with cast iron Sole Plate	00366 : 85	
52. 2169050	90-12-01	Khanna Electricals, 8065, Street No. 8, Multani Dhanda, Pahar Ganj, New Delhi-110055.	Electric Irons, 750W, 230 V Thermostatic with Aluminium alloy sole Plate.	00366 : 85	
53. 2169151	90-12-01	Sudarshan Capacitors Pvt. Ltd., A12, MIDC Area Islampur Distt. Sangli (Maharashtra)-431803.	Shunt Capacitors for Power Systems 415/440 V, 15 and 25 KVAR	02834 : 86	
54. 2169252	90-12-01	Sanco Polymers 9/51, Bazar Gali Vishwas Nagar Shahdara, Delhi-110092.	Conduits for Electrical Installation Rigid Plan Conducuits 25 MM Siic, Medium, Mechanical Stress	09537 : 83 (Part-III)	

क्रा.क्रा. 450:- भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम 1988 के विनियम, 4 के उपविनियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एनई आई प्रधिसूचन करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे स्वीकृत कर दिए गए हैं :

## अनुसूची

क्रा.क्रा. नं०	लाइसेंस की प्रवधि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	भारतीय मानक की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सी एम/एल-2147949	1990-09-01	अमृत एक्टूजन् प्रा.लि., 110 ग/2, इड. एरिया 1, पीथमपुर, जि. धार (म.प्र.)	पेय जल आपूर्ति के लिए यू पी वी सी पाइप साइज 63 से 160 मिमी.	04985-88
2. सी एम/एल-2148042	1990-09-16	किशनचंद एंड संस, डो-9 कृष्णानगन, दिल्ली -110051	हथकरघे की सूती गॉज, प्रचण्डी गैर- निर्जर्मित	00758-88
3. सी एम/एल-2148143	1990-09-16	राजी इंडस्ट्रीज, 2-113 पीथमपुरम रोड, रैमप्यापिड काकीनाडा (आ.प्र.)-533009	रॉकर्स छिड़काव यंत्र	03062-82
4. सी एम/एल-2148244	1990-09-16	गुजरात वायर प्राइवेट्स, अनुपम नर्सरी के पास, गोपालपुरा, बागरी एनएच 8 आनंद-388001	शिरोपरि प्रेषण के लिए एसीएसआर बालक	00398-76 (भाग 2)
5. सी एम/एल-2148345	1990-09-16	गुजरात वायर प्राइवेट्स, अनुपम नर्सरी के सामने, गोपालपुरा बागशी एन.एच. 8, तालुक आनंद (गुजरात) 388001	शिरोपरि प्रेषण के लिए पूर्ण एल्यूमिनियम बालक	00398-76 (भाग 1)
6. सी एम/एल-2148446	1990-09-01	बी.के. ए. इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि., 14/5 मथुरा रोड, फरीदाबाद-121003	टवी के वय प्रोफा जूट्स, स्टैन्डर्ड इस्पात का ढांचा, दो बर्नर बाला	04246-84
7. सी एम/एल-2148547	1990-09-16	जम्मोनी इड. लि., ईकाई-विलिंगडन जूट मिल्स, डा.-रिषरा, जि. हुगली (प.ब.) 712228	सीमेंट पैकिंग के लिए पटसन के हूके कट्टे	12154-87
8. सी एम/एल-2148648	1990-09-16	भारत स्टील कं., टिंगराई लूगरीजन रोड, तिनसुकिया 786125	संरचना इस्पात (सामान्य किस्म)	00236-75
9. सी एम/एल-2148749	1990-09-16	भारत स्टील कं., टिंगराई लूगरीजन रोड, तिनसुकिया 786125	उच्च सामान्य के विकृत सरिये	01786-83
10. सी एम/एल-2148850	1990-09-16	नफ्फारचन्द्र जूट मिल्स लि., भूतनाथ कोले रोड, कमकारिया, जि. 24 परगना (प.ब.)	एन्ड्रुसल पटसन के बोरे	01943-64
11. सी एम/एल-2148951	1990-09-16	तिरुपति लैमिनेटर्स 66/2, सलकिया स्कूल रोड, हावड़ा-711106	उर्बरक पैकिंग के लिए 407 ग्रा. भी 85X39 टारपुलिन कपड़े से उत्पादित परतदार पटसन के बोरे	07406-84 भाग 1
12. सी एम/एल-2149044	1990-09-16	तिरुपति लैमिनेटर्स, 66/2, सलकिया स्कूल रोड, हावड़ा-711106	उर्बरक पैकिंग के लिए 380 ग्रा. भी 1 60X39 टारपुलिन कपड़े से उत्पादित परतदार पटसन के बोरे	07406-86 भाग 1



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. सी.एम./एल-2149145	1990-09-10	गोविन्द लैमिनेटर्स, 493 जी.टी. रोड, बंगाल जूट मिल, शिवपुर, हावड़ा	उर्वरक पैकिंग के लिए 407 ग्रा.मी. 2; 85×39 टारपुलिन कपड़े से उत्पादित परतदार पटसन के बोरे	07406-84
14. सी.एम./एल-2149246	1990-09-16	गोविन्द लैमिनेटर्स, 493 जी.टी. रोड, बंगाल जूट मिल, शिवपुर, हावड़ा	उर्वरक पैकिंग के लिए 380 ग्रा.मी. 2, 68×39 टारपुलिन कपड़े से उत्पादित परतदार पटसन के बोरे	07406-86
15. सी.एम./एल-2149347	1990-09-16	विजाल स्केल इंडस्ट्रीज, महाशक्ति इंड. एस्टेट, भाग 2, निकोल टोलनाका के पास, प्रार. जे. किमारीवाला के पीछे, अहमदाबाद	बायो गैस के साथ प्रयुक्त बूल्हे, डलवां लोहे के रोगन किए	08749-88
16. सी.एम./एल-2149448	1990-09-16	बाजाज सेवाश्रम लि., पुराना स्टेशन रोड, उदयपुर -313001	केश तेल, टाइट 3 केवल	07123-84
17. सी.एम./एल-2149549	1990-09-16	गुडलक स्टील ट्र्यूम्स (प्रा.) लि., ए-45 इंड. एरिया, सिकन्दराबाद, जि. बुलन्दशहर-203205	मृदु इस्पात के पाइप	01339-79
18. सी.एम./एल-2149650	1990-09-16	गुडलक स्टील ट्र्यूम्स (प्रा.) लि., ए-45 इंड. एरिया, सिकन्दराबाद जि.-बुलन्दशहर-203205	सामान्य इंजीनियरी प्रयोजन के लिए इस्पात के पाइप	03601-84
19. सी.एम./एल-2149751	1990-09-16	गुडलक स्टील ट्र्यूम्स (प्रा.) लि., ए-45 इंड. एरिया, सिकन्दराबाद, जि.-बुलन्दशहर 203205	संरचना प्रयोजन के लिए इस्पात के पाइप	01161-79
20. सी.एम./एल-2149852	1990-09-16	भास्कर एग्रो कौमीकल्स प्रा. लि., 94/1, तूफानपेट प्रा, मलकापुर पंचायत, छोटपाल मंडल, नलगोडा जि.	मोनोक्रोटोफॉम, एस.एस.	08074-83
21. सी.एम./एल-2149953	1990-09-16	भास्कर एग्रो कौमीकल्स प्रा. लि., 94/1 तूफानपेट प्रा, मलका पुर पंचायत छोटपाल मंडल, नलगोडा जि.	एंडोसल्फान ईसी फारमूलेशन	04323-80
22. सी.एम./एल-2150029	1990-09-16	कोकण पेस्टीसाइड्स, प्रो. ब्रह्म पॉलीमोल प्रा. लि. लि., एम-4 एम आई.डी.सी., रायगढ़-402301	केनबेलरेट 20% ईसी फारमूलेशन	11977-87
23. सी.एम./एल-2150130	1990-09-16	बावेरी स्टील्स प्रा. लि., साइट-71, सी आई टी बी इंड. मध्यवर्ग, 2 रा फेज, बंगलौर हुमकुर रोड ले-आउट, यशवंतपुर, बंगलौर-560022	रेजर के ब्लेड लिए के अक्षय बेल्सिन सर्टिफिकेट इस्पात की प्लेटियां, मोटाई मध्यम, चौड़ाई-22.40 मिमी.	09294-79
24. सी.एम./एल-2150231	1990-09-16	गोतम सोमेंट्स प्रा. लि., कोनानमी प्रा., पीडुगुराल्ला मंडल, गुंटूर (प्रा. प्र.)	साधारण पोर्टलैंड सीमेंट	00269-76
25. सी.एम./एल-2150332	1990-09-16	गोतम सोमेंट्स प्रा. लि., कोनानमी प्रा., पीडुगुराल्ला मंडल, गुंटूर (प्रा. प्र.)	डाइकोफॉल 18.5% (द्रव्यमानुसार) ईसी फारमूलेशन	05279-69

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26. सी एम/एल-2150433	1990-09-16	श्री विविजय सीमेंट कं. लि., दिविजय प्रा. बाया जामनगर, बाया जामनगर 361140	सलफेट प्रतिरोधी पोर्टलैंड सीमेंट	12330-88	
27. सी एम/एल-2150534	1990-09-16	बी.एम.पीटर्स प्रा. लि., 84 भ्रमन नगर इंड. एरिया, जालंधर-144004	जल के मीटर, घरेलू टाइप	00779-78	]
28. सी एम/एल-2150635	1990-08-16	एडुरेट पम्पस् प्रा. लि., 8/बी/2, सेक्टर 8, इंडस्ट्रियल एस्टेट, ए.बी.रोड, देवास-455001	कृषि प्रयोजनों के लिए बाफ, ताजा, ठंडे पानी के लिए ऑटिज अपकेन्ट्री पम्प	06595-80	
29. सी एम/एल-2150736	1990-09-16	टैक्नो इलेक्ट्रिकल्स, प्लॉट नं. ए-18, आई.बी.ए., कुकाट पल्ली, रंगारेड्डी नगर, बालानगर टाउनशिप, हैदराबाद-500037	कृषि प्रयोजनों के लिए साफ ठंडे ताजे पानी के लिए मोनो सैंट पम्प	09079-89	
30. सी एम/एल-21 0837	1990-09-16	क्राऊन इंडस्ट्रीज, (188-91 इंड. एस्टेट, साण्खी (महा.) 416416	फ्लैश लाइट के लिए शुष्क बैटरिया	002 03-84	
31. सी एम/एल-2150938	1990-09-16	गंगा पाइप मेन्यू कं., ब्ल्यू-24/पी, एम.आई.बी.सी., सादूर मही. 413512	पेय जल आपूर्ति के लिए यूपीवीसी पाइप श्रेणी 2, 63 से 110 मि. साइज केबल	04985-88	
32. सी एम/एल-2151031	1990-09-16	मीरा सीमेंट प्राइवेट्स, प्लॉट नं. 14, एम.आई.बी.सी. इंड. एरिया, लोहार जं.-यवतमाल	कंक्रीट पाइप, एन पी 2 श्रेणी, साइज 450, 600 और 800 मिमी.	00458-71	
33. सी एम/एल-2151132	1990-09-16	मेटल इंडिया प्रॉडक्ट्स, इंड. एरिया, हावरस (उ.प्र.) 204101	बरवाजे के हथ्ये, टाइप 4	00208-87	
34. सी एम/एल-2151233	1990-09-16	एम.के. इलेक्ट्रिकल इंडिया लि., बी-17, पहला मेन रोड, इंड एस्टेट अम्बाला, मद्रास 600058	लवकीली सामग्री से बने तीन पिन प्लग	00538-71	
35. सी एम/एल-2151334	1990-09-16	स्टील इंजीनियर्स, 203 कविगुरु रवीन्द्र पथ, कचरापाड़ा, 24 परगना (प.बं.)	इस्पात की खिचकिया और संवाती	01038-83	
36. सी एम/एल-2151435	1990-09-16	इलेक्ट्रिकल मेन्यू. फेब्रिकर कं. लि., 138 जेसोर रोड, कलकत्ता 700055	शक्ति उच्च बोल्टता के लिए जस्तीकृत इस्पात प्रबलित एल्यूमिनियम बालक	00398-82 (भाग I)	
37. सी एम/एल-2151536	1990-09-16	सरार्फ मेटल, ए-45 मारीगोर इंड. एरिया, कूसरा फेज, बासनी, जोधपुर	43 ग्रेड सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट	08112-76	
38. सी एम/एल-2151637	1990-10-01	बीमस इंजी. कं., 139 पाइनियर मिल्स रोड, पीकामेड, पालीमेड, कोयम्बरूर 641004	कृषि प्रयोजनों के लिए अपकेन्ट्री पम्प हेतु तीस फीट स्त्रिल पिजरी प्रेरण मोटर	07538-75	
39. सी एम/एल-2151738	1990-10-01	बाकाई बैटरीज प्रा. लि., सिकन्दरपुर अनूपसहर, अलीगढ़	बहुउद्देशीय शुष्क बैटरी पदनाम आर 6, आर-14 और आर 20,	08144-78	
40. सी एम/एल-2151839	1990-10-01	कृष्ण कंडक्टर्स, एफ-98 रोड 7, बी के आई एरिया, जयपुर 302013	शिरोपरि प्रेरण के लिए जरतीकृत इस्पात प्रबलित एल्यूमिनियम बालक	00398-76	
41. सी एम/एल-2151940	1990-10-01	सुविष्णा एप्लाइड्स, ए-38, जी.एल.एफ. इंड. एरिया 1, फरीदाबाद 121003	ब्रेके के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस बूझों, सी.आर.सी. चदर, निकिल/क्रोमियम और स्टेनलैस इस्पात का हांचा, सी. आई बर्न सस्टि	04240-84	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42. सी एम/एल-2152033	1990-10-01	दि जनरल इलेक्ट्रिक कं. प्रा. लि. इंडिया लि, कृषि प्रयोजनों के लिए साफ, ठंडे पानी हेतु मोनोस्टेड पम्प एल.एफ.नं. 508, और 509/1 पोलाची, मेनरोड, इधारानी, कोयम्बतूर 041021			09079-89
43. सी एम/एल-2152134	1990-10-01	एन.सी.एल. इंड. लि., सिम्हापुरी, मेदटापल्ली, नलगोड जि (भा.प्र.)		सल्फेट प्रतिरोधी पोर्टलैंड सीमेंट	12330-88
44. सी एम/एल-2152235	1990-10-01	टाइम्स होजरी, 2 लक्ष्मी नगर, तिरुपुर 638602		साबी बूनी बनियास टाइप भार.एन. और भार.एन.एस. साइज 75 से 1150 सेमी. गेज 24 भा. 1	04964-80
45. सी एम/एल-2152330	1990-10-01	मिनर्वा डीजल इंजिन प्रा. लि., सी-67 फाउन्ट्री नगर, सागरा		ओरिजल स्पेकोन्डी पम्प	08598-80
46. सी एम/एल-2152437	1990-10-01	दीपक केबल (इंडिया) प्रा. लि., नं. 1 इंड एस्टेट, तुमकुर, (कन टक) 572102		शिरोपरि प्रेषण के लिए अस्तीकृत इस्पात प्रचलित एल्युमिनियम चालक	00398-78
47. सी एम/एल-2152538	1990-10-01	गोविन्द केबल इंडस्ट्रीज, 207-ए, पटयु गंज, बिल्ली 110092		1100 बी तक कार्यकारी बोस्टता के लिए पी.बी.सी. रोहित (हैवी ड्यूटी) बिजली की केबल	01554-76
48. सी एम/एल-2152639	1990-10-01	श्रीम संस केबल कं., प्रा. और डा. हैदरपुर, बिल्ली		1100 बी तक कार्यकारी बोस्टता के लिए पी.बी.सी. रोहित (हैवी ड्यूटी) बिजली की केबल	01554-76
49. सी एम/एल-2152740	1990-10-01	एन.सी. केबल इंडस्ट्रीज प्रा. लि., ए-1, सेक्टर 3, मोएडा गाजियाबाद		1100 बी तक कार्यकारी बोस्टता के लिए पी.बी.सी. रोहित केबल	00694-77
50. सी एम/एल-215291	1990-10-01	एम सी. केबल इंडस्ट्रीज प्रा. लि., ए-1 सेक्टर 3, मोएडा जि-गाजियाबाद		1100 बी तक कार्यकारी बोस्टता के लिए पी.बी.सी. रोहित (हैवी ड्यूटी) बिजली की केबल	01554-76
51. सी एम/एल-2152942	1990-10-01	सुपर बर्नर इंडस्ट्रीज, 357/29 ओकार नगर "बी" जिनगर, बिल्ली 110035		प्रवेग के साथ प्रयुक्त धरेलू गैस बूला, स्टेनलेस इस्पात और निकिल/क्रोमियम डीप्रा	04248-84
52. सी एम/एल-2153035	1990-10-01	जिवाणिक एप्रो पेल्स प्रा. लि., बी-59 फेज 7, एस ए एस नगर मोहाली (जि-रोपड़) पंजाब		फ्रेन बेलरेट 20 : (प्र/प्र) ईसी फार्मूलेशन	11997-87
53. सी एम/एल-2153136	1990-10-01	सिनसार्गेनिक पेल्स प्रा. लि., 85 और 86 इंड. एरिया, बिलाई 090020		इनेमल, धवनों के बाहर प्रयुक्त फिनिशिंग हेतु संवर्ग 2 और 14	02933-75
54. सी एम/एल-2153237	1990-10-01	हेमा पेस्टीमाइज, बिजौरान रोड (रेलवे क्रॉसिंग के पास), झड़ीत (जि.-मेरठ) 256011		सिन्डिग 20 : (प्र/प्र) ईसी फार्मूलेशन	00632-78
55. सी एम/एल-2153338	1990-10-01	राजस्थान केबल एंड कंडक्टर प्रा. लि. ए-90 (बी), रोड नं. 1-बी.के.पार्क, एरिया, जयपुर 302013		शिरोपरि प्रेषण के लिए एल्युमिनियम के छड़दार चालक	00398-78
56. सी एम/एल-2153439	1990-10-01	कैपेट कैमीकल्स प्रा. लि., प्लॉट नं. 82/1 जी आई बी सी. एस्टेट बेतवा, अहमदाबाद		बी.एच.सी. 50% डबल्यूडीपी फार्मूलेशन	00562-78
57. सी एम/एल-2153540	1990-10-01	कनकारिया कैमीकल्स इंड. लि., 118 जी.आई.बी.सी. एस्टेट, कालेज		पैराफिन मोम टाइप 3 केबल	04054-74

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
58	सी एम/एल-2153641	1990-10-01	लूथिन एग्रीकैमोकल्स (इण्डिया) प्रा. लि., मेनकोजेंब, 75. (द्र/व) घाघ्रणीय जूण 24/वी जो भाई. जी. सी. पनोली, जि.-भरुच (गुजरात)		08708-78
59	सी एम/एल-2153742	1990-10-01	शिव कैमोकल्स, प्लाट नं. बी-40 एम. भाई. जी. सी. एरिया दीथन, जि. धौरगाबाद 431108	विरंजक जूण, स्थायी, ग्रेड 2 केबल ;	01005-71
60.	सी एम/एल-2153843	1990-10-01	पूरानी टेक्स, 227 अजिवाशी रोड तिरुपुर 638603	सादा बुनी बनियान, धार एन. श्रीर आर एन एस टाइप, साइज, 75 से 110 गेज 24 या.	04904-80
61.	सी एम/एल-2153944	1990-10-01	लक्ष्मानी इंडस्ट्रीज, प्लाट नं 8 और 9 ए 1 सेक्टर इड, एरिया, गोविन्द पुरा, भीपाल 462023	पावर एंड शर की सुरक्षा प्रपेक्षार्ण, नुकीले बालेवार टाइप, 5 म. म (3, 7किवा) रेडिंग	09020-79
62.	सी एम/एल-2154037	1990-10-01	अजमेर फूड प्रॉडक्ट्स (प्रा.) लि., एक 65-66 इड एरिया, पर्वतपुरा, अजमेर 305002	बिस्कुट	01011-81
63.	सी एम/एल-2154138	1990-10-01	दि घा प्र डेयरी डव काप फेडरेशन लि., गूध पाउडर मिलक प्रॉडक्ट्स फौक्ट्री, लालागेट, हैबराबाद 500017		01165-86
64.	सी एम/एल-2154239	1990-10-01	ए. सी. एम. ई. सोप वर्क्स, राममंथिर रोड, गोरेगांव बम्बई 400104	बरेलू कपड़े धोने का डिजॉेंट	04955-82
65.	सी एम/एल-2154340	1990-10-01	ए सी. एम. ई. सोप वर्क्स, राम मंदिर रोड, गोरेगांव (प) बम्बई 400104	धुलाई का साबुन, टाइप 2 (बिन्ट सोप)	00285-74
66.	सी एम/एल-2154441	1990-10-16	बघालिटी ट्यूब्स लि., बिन्दकी रोड, फतेहपुर (उ.प्र.)	एम एम पाइप, ई धार इल्यू, काला और जस्तीकृत सादा और पेचकता (भाग 1) साफेक लगे सिरे हल्का, मध्यम और भारी	01239-79
67.	सी एम/एल-2154542	1990-10-01	राजिन्दर पाइप्स लि., 23 किमी. स्टोन, बिरोदा रनिया जि. कानपुर देहात	इस्पात पाइप काले, सादा और ग्रेड 1- सरचना प्रयोजन हेतु	01161-79
68.	सी एम/एल-2154643	1990-10-01	किंग बैटरीज, एन. एच. नं. 6 बा. बराहपाली, सम्बलपुर 768003	सीसा अम्ल बैटरी, मोटर वाहन हेतु 13 बो 60 ए स्वच रेडि	07372-74
69.	सी एम/एल-2154744	1990-10-01	पैरामाउण्ट इंक, नं. 1 मंगेश स्टील, टी नगर, मद्रास 600017	स्वचालित लाइन वोल्टता सशोणक (स्टेप टाइप)	08448-89
70.	सी एम/एल-2154845	1990-10-01	गणपति वायर एंड कंडक्टर्स, गोला का मंदिर महाराजपुरा, एयरपोर्ट खालियर 474005	शिरोपरि प्रेषण के लिए जस्तीकृत इस्पात प्रबलित एल्युमीनियम चालक	00398-76 (भाग 2)
71.	सी एम/एल-2154946	1990-10-01	इलेक्ट्रिक जम्प मैक्यूकैन्वर (इण्डिया) लि. 1 ताराटोला रोड, गांजनरी, कलकत्ता 700024	सामान्य प्रकाश सेवा के लिए नलिकाकार फ्योरेसेल्ट द्युब	02418-77 (भाग 1)
72	सी एम/एल-2155039	1990-10-01	संगर इंड कारपोरेशन, साइबियान रोड, संगर (पंजाब)	शिरोपरि प्रेषण हेतु जस्तीकृत इस्पात प्रबलित एल्युमीनियम चालक	00398-76 (भाग 2)
73	सी एम/एल-2155140	1990-10-01	पुष्कर पेंट इंडस्ट्रीज, 19 वां किमी. स्टोन ; रायबरेली रोड, मोहनलाल गंज लखनऊ	सामान्य प्रयोजन हेतु एल्युमीनियम रोगन	02339-63

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
74.	सीएम/एल-2155241	1990-10-01	पुष्कर पेन्ट इंडस्ट्रीज, 19 बां किमी स्टोन, रायबरेली रोड, मोहनलाल गंज, लखनऊ	तैयार शुद्ध रोगन ब्रश से करने वाला, बिड़मतीय कालाभ सीसा ग्रुप क्षार और उष्मा प्रतिक्रिया	00158-81
75.	सीएम/एल-2155342	1990-10-01	पुष्कर पेन्ट इंडस्ट्रीज, 19 बां किमी स्टोन रायबरेली रोड, मोहनलाल गंज, लखनऊ	इनेमल, धवनों के धावर प्रयुक्त फिनि- शिंग हेतु संश्लिष्ट वाछित रंग का	00133-75
76.	सीएम/एल-2155441	1990-10-01	पुष्कर पेन्ट इंडस्ट्रीज, 19 बां किमी स्टोन, रायबरेली रोड, मोहनलाल गंज, लखनऊ	तैयार शुद्ध रोगन, ब्रश से करने वाला लकड़ी प्राइमर, गुलाबी	03536-66
77.	सीएम/एल-2155544	1990-10-01	पुष्कर पेन्ट इंडस्ट्रीज, 19 बां किमी स्टोन, रायबरेली रोड, मोहनलाल गंज, लखनऊ	तैयार शुद्ध रोगन ब्रश से करने वाला, कम क्षयकदार, भारतीय मानक रंगों के अनुसूच सामान्य प्रयोजन हेतु	00123-62
78.	सीएम/एल-2155645	1990-10-01	पुष्कर पेन्ट इंडस्ट्रीज, 19 बां किमी स्टोन, रायबरेली रोड, मोहनलाल गंज, लखनऊ	तैयार शुद्ध रोगन, हवा में सूखने वाला रेड आक्साइड-जिफ आक्साइड क्रोम, प्राइमिंग	02074-79
79.	सीएम/एल-2155746	1990-10-01	कॉन्क्टर इलेक्ट्रिकल्स, 4सी, गवर्न. इंड. एस्टेट, कांठीवाली (प) बम्बई -400067	1100 बो तक कार्यकारी बोलवता के लिए पी वी सी रोहित और खोलवार (हैवी ड्यूटी) केवल	01554-76
80.	सीएम/एल-2155847	1990-10-01	स्वास्तिक पम्पस लि., प्लॉट नं. 3417, फेज 4, जी.आई.डी.सी. वेतवा, अहमदाबाद-382445	मोनोब्लॉक पम्पसेट	09079-79
81.	सीएम/एल-2155948	1990-10-01	दि मार्च ब्रुक जूट कं.लि., विशाखती, चम्पडेनी (जि. दुर्गली) 712221	एन्ट्रिक्स पटसन के बोरे	0194364
82.	सीएम/एल-2156041	1990-10-01	उर्दूमा एक्सट्रैज लि., गणेशपुर, इंड. एस्टेट, बालसोड-756015	सिचाई प्रयोजनों के लिए एल्यूमीनियम मिश्र धातु के एक्स्ट्रूडिड पाइप 1 इंच 75 मिमी	07092-87
83.	सीएम/एल-2156142	1990-10-01	किलोस्कर ब्रवर्स लि., रेलवे स्टेशन के रेलवे उज्जैन रोड, देवास (म.प्र.)	जैट अपकेन्द्री पम्प संयोजन	12225-87
84.	सीएम/एल-2156243	1990-10-01	एम.एस. इंडस्ट्रीज, 4-5-6 विनाल मार्किट वेक्सेन्ट, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली-110009	ड्र पे गै के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस बूल्हा निकिल और क्रोमियम लेपित और स्टेन- ले इस्पात का ढाँचा	04240-84
85.	सीएम/एल-2156344कु	1990-10-01	म्यू एलाइड एल पी जी एल/हमेज, 226 ए वी गौडली, बिशन नगर, दिल्ली-110051	ड्र पी गै के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस बूल्हा निकिल/क्रोमियम लेपित	04246-84
86.	सीएम/एल-2156445	1990-10-01	शुभ टायर स्टील प्रा.लि., प्लॉट नं. 14, सेक्टर 1, एंड एरिया, परबान् 173220	संरचना इस्पात में वेल्डन हेतु डब्ले थ्रिलेट इंगट (मानक किस्म) ग्रेड 1 और 2	06914-78
87.	सीएम/एल-2156546	1990-10-01	एबरेस्ट प्लास्टिक प्रा.लि., जी.आई.डी.सी. के पास, बामनगौर तालक अटोलिया, जिला-मुरेन्द्र नगर	यू पी वी सी पाइप श्रेणी 2 63 से 180 मिमी तक	04985-88
88.	सीएम/एल-2156647	1990-10-01	कृष्णा एन्टरप्राइजेज, बाईपा रोड, सोलन (हि.प्र.)	शिरोपरि प्रेषण के लिए एल्यूमीनियम के लड़दार बालक	00198-60
89.	सीएम/एल-2156748	1990-10-01	जैनगर मिनरल्स, 27-ए इंड. एरिया, फतेहाबाद (हरियाणा) 125050	मिथाइल पैराथियान, 50% ईसी	5-78

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
90. सी एम/एल-2156849	1990-10-01	जैन सत्य मिमरल्ल, 27-ए इंड. एरिया, कतेहाबाद (हरियाणा) 125050	एन्डोसल्फान 35% ईसी	04323-80	
91. सी एम/एल-2156960	1990-10-01	ठाकुर कैमोकल्ल, 30/5 किमी स्टोन जखोडा, बहुपुरगढ़ (हरियाणा)	मोनोक्रोटोफॉस 36% एस एस	08074-83	
92. सी एम-एल-2157043	1990-10-01	एग्रीमास कैमोकल्ल प्रा. लि., एच-2 एम भाई.डी.सी. इंड एरिया, जलोणा, जि. रायगढ़	मोनोक्रोटोफॉस 36 एस एस	08074-83	
93. सी एम/एल-2157144	1990-10-01	हिन्दुस्तान मिडनरल प्राइवेट्स क. प्रा लि 27 मैग्नीज बिपो, हाजी बंदर रोड, स्पुरो, बम्बई-400015	मोनोक्रोटोफॉस 36% एस एस	08074-83	
94. सी एम/एल-2157245	1990-10-01	ठाकुर कैमोकल्ल, 39/5 किमी स्टोन, जखोडा, बहुपुरगढ़ (हरियाणा)	एन्डोसल्फान 35% ईसी	04323-80	
95. सी एम/एल-2157346	1990-10-01	गौतम लैमिनेटर्स, ई-11 इंड. एरिया, रामनगर, बाराणसी	380 ग्रामी 68-39 टारपुलिन से उत्पादित पटसन के बोरे	07406-86	
96. सी एम/एल-2157447	1990-10-01	ग्लोब बेक्स, कुसुम खोरा हल्द्वानी, जि.-नैनीताल	पैराफीन मोम टाइप 3	04654-74	
97. सी एम/एल-2157648	1990-10-01	तुकमनी स्टील कं. लि., सरदार मंगल गोब, हूडी, क्वाइट फील्ड ऐड बंगलौर-560066	कंक्रिट प्रबलन के लिए एच एस डी एरिए मोर तार साइज 8 से 32 मिमी तक ग्रेड एफ ई 415	01786-85	
98. सी एम/एल-2157649	1990-10-03	साबू कैमोकल्ल, एच-26, एल एम एस, मरुधर इंड. एरिया, बूसरा फेज, बासनी, जोधपुर	सल्फेट प्रतिरोधी पोर्टलैंड सीमेंट	12330-88	
99. सी एम/एल-2157750	1990-10-01	सौरभ सीमेंट्स लि., ग्रा. झालडा (महाराष्ट्र), नीम का याना जि.- सीकर	साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, 33 ग्रेड	00369-76	
100. सी एम/एल-2157851	1990-10-01	रत्नलाम बायर्स प्रा. लि., 2 इंड. एस्टेट, रत्नलाम 457001	ए सी एस धार हेतु जस्तीकृत इस्पात के क्रोड तार	00398-76	
101. सी एम/एल-2159952	1990-10-01	श्री दुर्गा सीमेंट प्रा. लि., थोटोपल्ली, डा. ठाकुर सिंह, बाया-गोलनधारा जि. गंजाम	साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, 33 ग्रेड	00269-89	
102. सी एम/एल-2158045	1990-10-01	रिलाईंस इंजीनियर्स प्रा. लि., 118/ए-1 बासवेश्वर इंड. एस्टेट, पीनया स्टेज, बंगलौर -560058	1050 से. पर प्रबलन हेतु निमज्ज्य मोटर के लिए पीपीसी रोहित बेष्टनतार	10051-81	
103. सी एम/एल-2158146	1990-10-01	जिम्बल इरीगेशन सिस्टम् लि., 16 किमी, तुमकुर रोड, बंगलौर-560073	घूर्णी सिप्रकलर, जुड़वां नोजल, पूरा सर्कल अल्प कोण नोजल को छोड़कर	12232-87	

[सं. के प्र वि/13 : 11]

एस. सुब्रह्मण्यम, धपर मन्त्राधिकारक

SO. 450—In pursuance of sub-regulation(5) of regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (certification) Regulations, 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given in the following Schedule.

## SCHEDULE

## List of Licences Granted During the Month of September, 1990

Sl.No. CM/L-No.	Operative Date	Name & address of the Party	Article/Process	IS : No./Part
1. CM/L-2147949	1990-09-01	Amrit Extrusions Pvt. Ltd., 110 A/2, Indl. Area-1 Pethampur Dist. Dhar (MP)	UPVC Pipes for Potable water supplies Class 2 Size 63MM to 160 MM	04985-88
2. CM/L-2148042	1990-09-16	Kishan Chand & Sons D-9, Krishan Nagar, Delhi-110051	Handloom Cotton Gauge Absorbent non-sterilized	00758-88
3. CM/L-2148143	1990-09-16	Raki Industries 2-113, Pithampuram Road, Ramayyapeta Kakinada (AP)-533009	Rockers Sprayer	03062-82
4. CM/L-2148244	1990-09-16	Gujarat Wire Products Near Anupam Nursery Gopalpura Vagarhi N.H. No. 8, Anand-388001.	ACSR Conductors for overhead Transmission purposes	00398-76 (Part-2)
5. CM/L-2148345	1990-09-16	Gujarat Wire Products Near Anupam Nursery Gopalpura Vagarhi N.H. No. 8, Taluka Anand -388001 (Gujarat)	All Aluminium Conductors for overhead Transmission purposes	00398-76 (Part-1)
6. CM/L-2148446	1990-09-01	B.K. Appliances Pvt. Ltd., 14/5, Mathura Road Faridabad-121003.	Domestic gas Stoves for use with LPG Stainless steel body Double Burners.	04246-84
7. CM/L-2148547	1990-09-16	The Champdany Inds. Ltd., Unit: Wellington jute Mills PO Rishra Distt. Hooghly (WB)-712248	Light weight Jute Bags for Packing Cement	12154-87
8. CM/L-2148648	199-09-16	Bharat Steel Company Tingrai Hoogrijan Road, Tinsukia (Assam) 786125	Structural Steel (Standard Quality)	00226-75
9. CM/L-2148749	1990-09-16	Bharat Steel Co. Tingrai Hoogrijan Road, Tinsukia (Assam)-786125	High Strength Deformed Bars	01786-85
10. CM/L-2148850	1990-09-16	Naffar Chandra Jute Mills Ltd., Bhutnath Kolay Road PO Kankinara Distt. 24 Parganas (WB)	A-Twill Jute Bags	01943-64
11. CM/L-2148951	1990-09-16	Tirupati Laminators 66/2 Salkia School Road Howrah-711106	Jute Bags for packing Fertilizers laminated bags manufactured from 407 G/M SQ 85 × 39 Tarpaulin Fabric	07406-84 (Part-I)
12. CM/L-2149044	1990-09-16	Tirupati Laminators 66/2, Salkia School Road Howrah-711106	Jute bags for packing fertilizers Laminated bags manufactured from 380 G/M SQ 68 × 39 Tarpaulin Fabric	07406-86 (Part-2)
13. CM/L-2149145	1990-09-16	Govind Laminators 493 G.T. Road, Bengal Jute Mills Shibpur Howrah.	Jute bags for packing fertilizers laminated manufactured from 407 G/M SQ 85 × 39 Tarpaulin Fabric	07406-84 (Part-I)
14. CM/L-2149246	1990-09-16	Govind Laminators 493, G.T. Road, Bengal Jute Mill Shibpur (Howrah)	Jute bags for packing fertilizers laminated manufactured from 380 G/M S Q68 × 39 Tarpaulin Fabric	07406-86 (Part-2)
15. CM/L-2149347	1990-09-16	Vijal Scale Industries Mahashakti Indl. Estate Part -II Near Nikol Tolnaka Behind R.J. Kinari wala Ahmedabad-380025.	Cast Iron painted single and Double burners stove for use with Bio-Gas	08749-88

1	2	3	4	5	6
16.	CM/L-2149448	1990-09-16	Bajaj Sevashram Ltd., Old Station Road, Udaipur-313001.	Hair Oils type 3 only	07123-84
17.	CM/L-2149549	1990-09-16	Goodluck Steel Tubes (P) Ltd., A-45, Indl. Area Sikandarabad Distt. Bulandshahar-203205	Mild Seel Tubes	01239-79 (Part-1)
18.	CM/L-2149650	1990-09-16	Good Luck Steel Tubes (P) Ltd., A-45, Indl. Area Sikandarabad Distt. Bulandshahar-203205	Steel Tubes for General Engineering Purposes.	03601-84
19.	CM/L-2149751	1990-09-16	Good Luck Steel Tubes (P) Ltd., A-45, Indl. Area Sikandarabad (Distt. Bulandshar)-203205.	Steel Tubes for Structural Purposes	01161-79
20.	CM/L-2149852	1990-09-16	Bhaskar Agro Chemicals Pvt. Ltd., 94/1, Toophranpet Village Malakapur Panchayat Chowtuppal Mandal Nalgonda-Distt.	Monocrotophos, SL	08074-83
21.	CM/L-2149953	1990-09-16	Bhaskar Agro Chemicals Pvt. Ltd., 94/1, Toophranpet Village Malkapur Panchayat Chowteppal Mandal Distt. Nalgonda (MP)	Endosulphan, EC Formulation	04323-80
22.	CM/L-2150029	1990-09-16	Konkan Pesticides Prop Varun Polymol Organics Ltd., A-4, MIDC Mahad Distt. Raigadh-402301	Fenvelerate 20% EC Formulation	11997-87
23.	CM/L-2150130	1990-09-16	Kaveri Steels Ltd., Site-71, CITB Indl. Suburb IInd Phase Bangalore Tumkur Road Layout Yeshwantpur Bangalore-560022	Cold Rolled Stainless Steel Strips for Razoar Blades Thickness Medium width 22.40 MM	09294-79
24.	CM/L-2150231	1990-09-16	Gautam Cements Pvt. Ltd. Konanki Village Piduguralla Manal Guntur (MP)	Ordinary Portland Cement	00269-76
25.	CM/L-2150332	1990-09-16	Bhaskar Agro Chemicals Pvt. Ltd., 94/1, Toophranpet Village Malkapur Panchayat Chowtuppal Mandal Distt. Nalgonda (MP)	Dicofol 18.5 Percent (M/M) EC Formulation	05279-69
26.	CM/L-2150433	1990-09-16	Shree Digvijay Cement Co. Ltd., Digvijay Gram Via Jam Nagar Via Jamnagar-361140	Sulphate resisting portland Cement	12330-88
27.	CM/L-2150534	1990-09-16	B.M. Meters Pvt. Ltd., 84, Aman Nagar Indl. Area Jalandhar-144004	Water Meters Domestic Type	00779-78
28.	CM/L-2150635	1990-09-16	Accurate Pumps Pvt. Ltd., 8/B/2, Sector-I Indl. Estate A.B. Road, Devas-455001	Horizontal Centrifugal pumps for Clear, cold, fresh water for Agricultural purposes.	06595-80
29.	CM/L-2150736	1990-09-16	Techno Electrics Plot No. A-18, IDA Kukatpally Rangareddy Nagar Balanagar Township Hyderabad-500037	Monoset Pumps for Clear, Cold fresh water for Agricultural Purposes	09079-89
30.	CM/L-2150837	1990-09-16	Crown Industries 188-91, Indl. Estate Sangli (MS)-416416	Dry Batteries for Flash lights	00203-84



1	2	3	4	5	6
31. CM/L-2150938	1990-09-16	Ganga Pipe Mfg., Co. W-24/P, MIDC Latur (MS) 413512	UPVC pipes for Potable water Supplies Class 2, 63 to 110 MM Sizes Only	04985-88	
32. CM/L-2150130	1990-09-16	Mira Cement Products Plot No. B-14, MIDC Ind. Area Lohara Distt. Ycetmal-445001	Concrete pipes for NP 2 Class sizes 450, 600 and 800 MM	00458-71	
33. CM/L-2151132	1990-09-16	Metal India Products Indl. Area Hatharas (UP) 204101	Door Handle Type 4	00208-87	
34. CM/L-2151233	1990-09-16	M.K. Electric (India) Ltd., B-17, First Main Road, Indl. Estate, Ambattur, Madras-600058	Three pin Plugs made of Resilient Material.	06538-71	
35. CM/L-2151334	1990-09-16	Steel Engineers 203, Kabiguru Ravindra Path Kancharapara 24 Parganas (WB)-743145	Steel windows and Ventilators	01038-83	
36. CM/L-2151435	1990-09-16	Electrical Manufacturing Co. Ltd., 136, Jessore Road Calcutta-700055	Aluminium Conductors Galvanized steel reinforced for extra high Voltages for overhead transmission	00398-82 Par I-V	
37. CM/L-2151536	1990-09-16	Saraf Metal, 1-45, Marcedhor Indl. Area, Second Phase, Basni, Jodhpur.	43 Grade Ordinary Portland Cement	08112-76	
38. CM/L-2151637	1990-10-01	Venus Engg. Co. 139, Pioneer Mills Road Peelamedu Coimbatore-641001	Three phase squirrel cage Induction Motors for Centrifugal pumps for Agricultural Applications	07538-75	
39. CM/L-2151738	1990-10-01	Backeye Batteries Pvt. Ltd., Sikandarpur Anupshahr Road Aligarh-202001	Multi-purpose dry Batteries of R 6, R 14 and R 20 Designation	08144-78	
40. CM/L-2151839	1990-10-01	Krishna Conductors F-96, Road No. 7, VKI Area, Jaipur-302013	Aluminium Conductors Galvanized Steel Reinforced for overhead Transmission purposes	00398-76 (Part 2)	
41. CM/L-2151940	1990-10-01	Suvidha Appliances A-38, DLF Indl. Area I Faridabad-121003	Domestic Gas stoves for use with LPG, CRO sheets, Nichol/Chromium and Stainless Steel Body with CI Burners	04246-84	
42. CM/L-2152033	1990-10-01	The General Electric Co. of India Ltd., SF No. 568 & 569/1 Pollachi Main Road Eachanari Coimbatore-641021	Monoset pumps for clear, Cold fresh water for Agricultural Purposes	09079-89	
43. CM/L-2152134	1990-10-01	N.C.L. Inds. Ltd., Simhapuri Mettapalli Nalgonda Distt. (AP)	Sulphate resisting portland Cement	12330-88	
44. CM/L-2152235	1990-10-01	The Times Hosieries 2, Laxmi Nagar 4th Street Tirupur-638602	Plain Knitted Cotton Vests of Type RN and RNS Size 75 to 110 CM Gauge 24 G	04964-80	
45. CM/L-2152336	1990-10-01	Minerva Diesel Engines Pvt. Ltd., C-67, Foundary Nagar, Agra	Horizontal Centrifugal water Pumps	06595-80	
46. CM/L-2152437	1990-10-01	Deepak Cables (India) Pvt. Ltd., No. 1, Ind. Estate, Tumkur (Karnataka)-572102	Aluminium Conductors Galvanized Steel reinforced for overhead Transmission purposes	00398-76 (Part 2)	
47. CM/L-2152538	1990-10-01	Govind Cable Industries 207-A, Patpar Ganj Delhi-110092	PVC Insulated (Heavy Duty) Electric cables for working Voltages upto and Including 100 volts	01554-76 (Part 1)	

1	2	3	4	5	6
48. CM/L-2152639	1990-10-01	Omsons Cable Co. Village & PO Hyderpur Delhi-110042	PVC Insulated Heavy Duty Electric Cables for working voltages upto and including 1100 Volts	01554-76 (Part 1)	
49. CM/L-2152740	1990-10-01	N.C. Cable Industries Pvt. Ltd., A-1, Sector-III Noida, Distt. Ghaziabad	PVC Insulated Cables for working voltage upto and including 1100 V	00694-77	
50. CM/L-2152841	1990-10-01	NC Cable Industries Pvt. Ltd., A-1, Sector-III, Noida, (Distt. Ghaziabad)	PVC Insulated Heavy Duty Electric Cables for working Voltages upto and including 1000 V	01554-76 (Part 1)	
51. CM/L-2152942	1990-10-01	Super Burner Industries 357/29, Onkar Nagar "B" Tri Nagar, Delhi-110035.	Domestic stoves for use with LPG with stainless steel and Nichol/Chromium Body	04246-84	
52. CM/L-2153035	1990-10-01	Shivalik Agro Chemicals B-59, Phase-VII SAS Nagar Mohali (Distt. Ropar) Punjab	Penclerate 20% (M/M) EC Formulations	11997-87	
53. CM/L-2153136	1990-10-01	Synorganic Paints Pvt. Ltd., 85 & 86, Indl. Area Bhilai-490026	Enamel, Exterior, Finishing Colour Category Nos. 2 and 14	02933-75	
54. CM/L-2153237	1990-10-01	Heema Pesticides Bijrol Road (Near Railway Crossing) Baraut (Distt. Meerut)-250611	Lindane 20% (M/M) EC Eormulation	00632-78	
55. CM/L-2153338	1990-10-01	Rajasthan Cables & Conductors Pvt. Ltd., A-90 (C), Road No. 1-D, VKI Area Jaipur-302013	Aluminium Stranded Conductors for overhead Transmission purposes	00398-76 (Part-I)	
56. CM/L-2153439	1990-10-01	Chemet Chemicals Pvt. Ltd., Plot No. 82/1, GIDC Estate, Vatva Ahmedabad	BHC 50% WDP Formulation	00562-78	
57. CM/L-2153540	1990-10-01	Kankariya Chemicals Inds. Ltd., 118, GIDC Estate Kaloj-389330	Paraffin wax Type 3 only	04654-74	
58. CM/L-2153641	1990-10-01	Lupin Agrochemicals (India) Pvt. Ltd., 242/P, GIDC Panoli Distt. Bahruch (Gujarat)	Mancozeb, 75% (M/M) Wettable powder	08708-78	
59. CM/L-2153742	1990-10-01	Shiv Chemicals Plot No. B-46 MIDC Area Paithan Distt. Aurangabad-431108	Bleaching Powders, Stable, Grade 2 only	01065-71	
60. CM/L-2153843	1990-10-01	Pooraani Tex 227 Avanashi Road Tirupur-638603	Plain knitted vests RN and RNS type Size 75 to 110 CM Gauge 24 G	04964-80	
61. CM/L-2153944	1990-10-01	Lalwani Industries Plot No. 8 & 9A 1 Sector Indl. Area Govindpara, Bhopal-462023	Safety Requirements for power Threshers, Spike tooth type 5 HP (3.7 KW) Rating	09020-79	
62. CM/L-2154037	1990-10-01	Ajmer Food Products (P) Ltd., F-65-66, Indl. Area Parbat Pura Ajmer-305002	Biscuits	01011-81	
63. CM/L-2154138	1990-10-01	The A.P. Dairy Dev. Co-op Federation Ltd., Milk Products Factory Lalapur Hyderabad-500017	Milk Powder	01165-86	

1	2	3	4	5	6
64.	CM/L-2154239	1990-10-01	ACME Soapworks Ram Mandir Road Goregaon (W) Bombay-400104	Household Laundry Detergent Powder Grade 2	04955-82
Licences Granted During the Month					
65.	CM/L-2154340	1990-10-01	ACME Soap Works Ram Mandir Road Goregaon (W) Bombay-400104	Laundry Soaps Type 2 (Built Soap)	00285-74
66.	CM/L-2154441	1990-09-16	Quality Steel Tubes Ltd., Bindki Road Fatehpur (UP)	M.S. Tubes ERW, Black and Galvanized, Plain and Screwed socketed Endsight, Medium and Heavy (Part-I)	01239-79
67.	CM/L-2154542	1990-10-01	Rajender Pipes Ltd. 23, K.M. Stone Village Chiroura Rania Distt. Kanpur Dehat	Steel Tubes (Black, Plain and Grade Yst-210) for structural purposes	01161-79
68.	CM/L-2154643	1990-10-01	King Batteries N.H. No. 6 PO Baralpali Sambalpur-768003	Lead acid storage batteries for motor Vehicles for 12V 60 AH rating	07372-74
69.	CM/L-2154744	1990-10-01	Parmount Inc. No. 1, Mangesh street T. Nagar Madras-600017	Automatic line voltage correctors (Step Type)	08448-89
70.	CM/L-2154845	1990-10-01	Ganpathy wire & Conductors Gola Ka Mandir Maharaj pura Airport Road Gwalior-474005	Aluminium conductors galvanized Steel reinforced for overhead Transmission purposes	0398-76 (Part-2)
71.	CM/L-2154946	1990-10-01	Electric Lamp Manufacturers India (Ltd.) 1, Taratolla Road Garden Reach Calcutta-700024	Tubular Fluorescent lamps for General lighting service 40 W, 6500 K	02418-77 (Part-1)
72.	CM/L-2155039	1990-10-01	Sangrur Indl. Corporation Sibian Road Sangrur(PB)	Aluminium Conductors Galvanized Steel Reinforced for overhead Transmission purposes	00398-76 (Part-2)
73.	CM/L-2156140	1990-10-01	Pushkar Paint Industries 19th KM Stone Raebareilly Road Mohan Lal Ganj Lucknow	Aluminium Paints for General purposes	02339-63
74.	CM/L-2155241	1990-10-01	Pushker Paint Industries 19th KM Stone Rae Bareilly Road Mohan Lal Ganj Lucknow	Ready Mixed Paints, Brushing, Bituminous, Black, Lead 3 Acid, alkali and heat resistant	00158-81
75.	CM/L-2155342	1990-10-01	Pushker Paint Industries 19th KM Stone Rae Bareilly Road Mohan Lal Ganj Lucknow	Enamel, Interior, Finishing Synthetic, Colour as required	00133-75
76.	CM/L-2155443	1990-10-01	Pushker Paint Industries 19th KM Stone Rae Bareilly Road Mohan Lal Ganj Lucknow	Ready Mixed paints, brushing, wood primer, Pink	03536-66
77.	CM/L-2155544	1990-10-01	Pushker Paint Industries 19th KM Stone Rae Bareilly Road Mohan Lal Ganj Lucknow	Ready mixed paint, brushing, Finishing, semi gloss for general purposes to Indian Standard colours	00123-62

1	2	3	4	5	6
78. CM/L-2155645	1990-10-01	Pushker Paint Industries 19th KM Stone Rai Bareilly Road Mohanlal Ganj Lucknow	Ready Mixed Paints, air Drying Red Oxide-Zinc Chrome, priming	02074-79	
79. CM/L-2155746	1990-10-01	Condor Electricals 4C, Govt. Indl. Estate Kandivli (W) Bombay-400067	PVC Insulated and sheathed Heavy duty cables for working Voltages upto 1100 V	01554-76 (Par: 1)	
80. CM/L-2155847	1990-10-01	Swastik Pumps Ltd. Plot No. 3417 Phase IV, GIDC Vatva Ahmedabad-382445	Monoblock pumpsets	09079-79	
81. CM/L-2155948	1990-10-01	The North Brok Jute Co. Ltd. Baidyabati Champdani (Distt. Hoogly)-712221	A-Twill Jute Bags	01943-64	
82. CM/L-2156041	1990-10-01	Orissa Extrusions Ltd. Ganeshwar pur Indl. Estate Balasore-756015	Aluminium alloy tubes for Irrigation purposes extruded tube size 75 MM	07092-87	
83. CM/L-2156412	1990-10-01	Krirloskar Broters Ltd. Opp. Railway Station Ujjain Road Dewas (MP)	Jet Centrifugal pump Combination	12225-97	
84. CM/L-2156243	1990-10-01	M.S. Industries 4-5-6, Vishal Market Basement Mukherji Nagar New Delhi-110009	Domestic gas stoves for use with LPG both nickel and,chromium plated and and stainless steel Body	04246-84	
85. CM/L-2156344	1990-10-01	New Allied LPG Appliances 266, A/B, Ghondli Krishan Nagar Delhi-110051	Domestic Gas Stoves for use with LPG Niclel/Chromium Plated Body	04246-84	
86. CM/L-2156445	1990-10-01	Shubh Timb-Steel Pvt. Ltd., 22-24, Sector-I Indl Area Parwanoo-173220	Cast Billet Ingots for rolling into Structural Steel (Standard Quality) Grades 1 and 2	06914-78	
87. CM/L-2156546	1990-10-01	Everest Plastics Pvt. Ltd., Near GIDC Bamanbore Talak Chotilla Distt. Surendernagar	UPVC Pipes Class 2 63 to 180 MM	04985-88	
88. CM/L-2156647	1990-10-01	Krishna Enterprises Bypass Road Solani (HP)	Aluminium stranded conductor for overhead Transmission Purposes	00398-60 (Part-1)	
89. CM/L-2156748	1990-10-01	Jainsons Minerals 27-A, Indl. Area Fatehabd (Haryana)-125050	Methyl Parathion, 50% EC	02865-78	
90. CM/L-2156849	1990-10-01	Jainsons Minerals 27-A, Indl. Area Fatehabad (Haryana)-125050	Endosulfan 35% EC	04323-80	
91. CM/L-2156950	1990-10-01	Thakar Chemicals 38/5, KM Stone Jakhoda Bahadurgarh (Haryana)	Monocrotophos 36% SL	08074-83	
92. CM/L-2157043	1990-10-01	Agrimas Chemicals Pvt. L'd. H-2, MIDC Indl. Area Taloja Distt. Raigadh	Monocrotophos 36% SL	08074-83	
93. CM/L-2157144	1990-10-01	Hindustan Minerral Products Co. Pvt. Ltd., 27, Manganese Depot Haji Bunder Road, Sewree Bombay-4400015	Monocrotophos 36% SL	08074-83	

1	2	3	4	5	6
94. CM/L-2157245	1990-10-01	Thakar Chemicals 38/5, K.M. Stone Jakhoda Bahadurgarh (Haryana)	Endosulfan 35% EC	04323-80	
95. CM/L-2157346	199-10-01	Gautam Laminators E-11, Indl. Area Ramnagar, Varanasi	Jute Bags for packing Fertilizers laminated bags manufactured from 380 G/M SQ 68 x 39 Tarpaulin Fabric	07406-86 (Part 2)	
96. CM/L-2157447	1990-10-01	Globe Wax Kusum Khera Haldwani Distt., Naintal	Paraffin wax Type-3	04654-74	
97. CM/L-2157548	1990-10-01	Tikmani Steel Co. Ltd., Sadaramangala Village, Hoody Whitefield road, Bangalore-560066	HSD steel bars and wires for concrete reinforcement, sizes 8 MM upto and including 32 MM Grade FE 415	01786-85	
98. CM/L-2157649	1990-10-01	Saboo Minerals H-26, LMN Marudhar Indl Area IInd Phase, Basni Jodhpur	Sulphate resisting portland Cement	2330-88	
99. CM/L-2157750	1990-10-01	Sorabh Cements Ltd. Village Jhalda (Maunda) Neem-Ka, Thana Distt. Sikar	Ordinary Portland Cement	00269-76	
100. CM/L-2157851	1990-10-01	Ratlam Wires Pvt. Ltd., 2, Indl. Estate Ratlam-457001	Galvanized steel core wire for ACSR	00398-76 (Part-2)	
101. CM/L-2157962	1990-10-01	Shree Durga Cement Pvt. Ltd., Thotodapally PO Kuthar Singh Via Golanthara Distt. Ganjam	Ordinary Portland Cement 33 Grade	00269-89	
102. CM/L-2158045	1990-10-01	Reliance Engineers Pvt. Ltd. 118/A-1 Basaveswara Indl. Estate Peenya-II State Bangalore-560058	PVC Insulated winding wires for Submersible motors for 105 DEG Centigrade Operation	10051-81	
103. CM/L-2158146	1990-10-01	Jindal Irrigation System Ltd., 16 KM Tumkur Road Bangalore-560073	Rotating Sprinklers, Twin nozzle, Full circle excluding low angle Nozzles	12232-87 (Part-1)	

[No. CMD/13 : 11]

S. SUBRAHMANYAN, Addl. Director General

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 14th January, 1991

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1991

का. प्रा. 451—प्रथम सविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 3 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार-एतद्वारा श्री एम. पी. रेगे, निदेशक (वस्तु) को उनके वर्तमान कार्य के अतिरिक्त, श्रीमती विमला कुमार, सवस्य की 23 नवम्बर, 1990 (अपराह्न) से 10 दिसम्बर, 1990 (पूर्वाह्न) तक छुट्टी का अवधि के दौरान उनके स्थान पर वायदा बाजार आयोग, बम्बई के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 3-12-1990 की पिछली अधिसूचना सं. ए. 17011/4/87 प्रशा II को अधिकृत करती है।

[मि सं. ए-17011/1/88 प्रशा. II]

प्रो. ए. खेतपाल, अवर सचिव

S.O. 451.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 3 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri M. P. Rege, Director (Commodities) as a Member of the Forward Markets Commission, Bombay, vice-Smt. Vinala Kumar, Member, during her leave period from 23rd November, 1990 (A.N.) to 10th December, 1990 (F.N.) in addition to his present duties.

2. It supercedes the earlier Notification No. A-17011/4/87-Estt. II dated 3-12-1990.

[F. No. A-17011/1/88-Estt. II]

O. P. KHETRAPAL, Under Secy.

## श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1991

का.आ.-452-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सुराकच्छर कोलियरी आफ साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लि., कोरबा एरिया, सुराकच्छर कोलियरी जिला-बिलासपुर (म.प्र.) के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-1-1991 को प्राप्त हुआ था।

## MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 11th January, 1991

S.O. 452.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, (M.P.) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Surakachhar Colliery of South Eastern Coalfields Ltd., Kosba Area, Surakachhar Colliery, District : Bilaspur (M. P.) and their workmen, which was received by the Central Government on the 10-1-1991.

## ANNEXURE

BEFORE SHRI V. N. SHUKLA, PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-  
CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC (R)(216)/1987

## PARTIES :

Employers in relation to the management of Surakachhar Colliery of South Eastern Coalfields Ltd. Korba Area, Surakachhar Colliery, District Bilaspur (M.P.) and their workmen S/Shri Ummed Das S/o Naval Das, Rangu S/o Firangi, Madan S/o Murali Giri, Nitu S/o Kunjam, Bargeese S/o Firangi and Sasidharan S/o Narayanan, represented through the General Secretary, Chhattisgarh Khadan Karkhana Mazdoor Union, P.O. Bankimonga, District Bilaspur (M.P.)

## APPEARANCES :

For Workmen—Shri Rambilash Shobhnath.

For Management—Shri P. S. Nair, Advocate.

INDUSTRY : Coal Mining

DISTRICT : Bilaspur  
(M.P.)

## AWARD

Dated, December 28, 1990

This is a reference made by the Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-21011/17/87-D.III (B) dated 24-9-1987, for adjudication of the following dispute :—

“Whether the action of the management of South Eastern Coalfields Ltd. Korba Area in relation to their Surakachhar Colliery in not giving preference in employment to S/Shri Ummed Das S/o Naval Das, Rangu S/o Firangi, Madan S/o Murali Giri, Nitu S/o Kunjam, Bargeese S/o Firangi and Sasidharan S/o Narayanan in the Canteen is justified? If not, to what relief are these entitled to and from what date?”

2. Undisputed facts of the case are that the management were running Canteens at Banki and Surakachhar Collieries since 1968 on contract basis. Shri M. K. Nair was the Contractor of Banki Colliery while Shri P. R. Gopalan was the Contractor of Surakachhar Colliery.

3. According to the workmen, there was an Agreement between the management and the contractor that the Canteen workers shall be paid Rs. 5 per day by the contractors. They have been paid from 7-8-68 to 31-3-1981 @ Rs. 5 per day. S/Shri Achchey Lal, Madan, Chandran Pille, Sitaram, Pravin Kumar, Prasann Kumar Setu Madhwan, Vijayan, were working since August, 1968 and S/Shri Pitru, Jethudas, Laxman, Mohardas, Prashann Kumar No. 2 and Raghuthaman were working since 1970. S/Shri Budhram, Tulsii, Amritlal, Baleshwar, Ramlal and Vijay Kumar were working since August 1968 and Ummed Das, Rangu, Madan, Ritu, Vargeese and Sasidharan were working since January, 1969, in Surakachhar Colliery Canteen. Under the Mines Rules 68 management is bound to run the Canteen in accordance with law and not through Contractors. Chief Inspector of Mines Circular No. 21 of 1961 runs as follows :—

“It has been brought to the notice of the Government of India, that at some Mines-Canteens are not being run departmentally but through contractors. This practice is not in accordance with the provisions of rule 68 of Mines Rules, 1965 which clearly specific “that the owner, agent or Manager shall appoint Supervisory and other staff sufficient for the proper working of the canteens.”

(This decision was also agreed to the eight Session of the Industrial Committee on Coal Mines.)

Thus the management cannot carry out the work of the Canteen through the Contractors by paying Rs. 5 per day to the Canteen workers. All India Industrial (Colliery Disputes) Tribunal Award 1956 and the recommendations of the Coal Wage Board 1967, N.C.W.A. 1 of 1975 and N.C.W.A. 11 of 1979 gives but designation, grade and pay scales of the employees which is as under :—

Sl. No.	Designation	Grade	1956A	1967-A	1975A	1979A
1.	Canteen Supervisor	Clerk	2,48-93	105-325	378-570	508-808
2.	Asst. Supervisor	Clerk	3,43-42	180-265	330-438	460-636
3.	Canteen Cook	Gr. F	30-35	165-230	310-400	440-584
4.	Canteen Boy	Gr. H	28-32	140-178	274-344	40-512

That apart, the employees were entitled to Additional D.A. other allowances, Bonus, Leave and Provident Fund etc. All these advantages were denied to these Canteen workers.

4. General Manager, Korba and his Dy. Personnel Manager of Banki and Surakachhar Collieries called for tenders on 6-3-1981 for running the canteens through contractors. Union opposed to it and strike notice was given on 7-4-1981. Management was asked to departmentalise the canteen workers and fix their wages in accordance with the Coal Wage Board. The Settlement was brought about on 11-6-1981. The management agreed to departmentalise the canteens and regularise the canteens workers but refused to pay the arrears of wages etc. Union did not agree to it. However, the management determined the contracts and took over the canteens of both these Collieries and after taking over buildings, furnitures etc. of the contractors of the canteen brought workers from other places and deployed them in the canteens. The management also removed the workers who were working in the canteens since number of years.

5. The matter was again taken up and ultimately Dy. Chief Personnel Manager, Korba, agreed to re-employ the canteen workers with a condition that first they will employ six canteen workers from each canteen who were working since August 1968 and for the remaining six workers of each canteen shall be employed on priority basis. They also insisted upon that the Union should withdraw the demand of the employment of remaining six canteen employees of each canteen. This condition was accepted by the Union on the above assurance and a settlement was signed on 2-9-1982.

6. That in view of the settlement dated 2-9-1982 the management took back S/Shri Vijayan, Madanlal, Sitaram, Pravin Kumar, Prasann Kumar and Chandran Pille of the Banki Colliery and sent those workers back who were brought

to work in the canteen to their original department. That as per another settlement dated 4-1-1984 five out of six workers S/Shri Pitru, Raghunaman, Prasann Kumar, Jethu das and Laxman were also taken back. Then again vide settlement dated 10-11-1984 one disabled workman, Mohar-das was also taken back. Thus 12 workers of the Bank Colliery Canteen were taken back but remaining workers of Surakachhar Colliery Canteen were not taken back.

7. There are two Canteens at Surakachhar Colliery. As per settlement dated 2-9-82 five workers viz. S/Shri Vijay Kumar, Bushram, Tulsi, Amritdas, Baleshwar and Ramlal were taken back but the workers brought from other depart-who were working in the canteen were not sent back to their department, but S/Shri Horilal, Bajrang, Madhulal, Neerat, Rambharose, Kamaldas, Manharan, Madari, Go-vind, Dhaniram, Chatram and Victor were brought into the canteen and absorbed therein and the remaining six workers of Surakachhar Colliery Canteen viz. Umed Das, Rangu, Madan, Ritu, Vergeese and Sasidharan were not absorbed.

8. Despite the assurance they have not been absorbed till now, hence they are entitled to be absorbed with effect from 1-1-1969 as Grade H Canteen Boys and paid accordingly.

9. In substance the management has stated that the settle-ments have been fully implemented. There is no room for absorbing these employees and the reference is liable to be rejected.

10. Reference was the Issue in this case.

11. Management has not filed any document while the workmen have proved 10 documents, Ex. W/1 to Ex. W/10. Management has not examined any witness while the work-men have examined Bundram (WW-1) and Kriparam. These witnesses proved Ex. W/1 to Ex. W/10.

12. Ex. W/1 is the Memo of Settlement dated 3-9-1982. Ex. W/2 is another settlement dated 2-9-82. Ex. W/3 is another Settlement dated 3-9-82. Ex. W/4 is another Settle-ment dated 18-11-84. Ex. W/5 is the Tender Notice dated 6-3-1981. Ex. W/6 is the Strike Notice. Ex. W/7 is the recital of the case. Ex. W/8 is an application of General Secretary addressed to the Regional Labour Commissioner. Ex. W/9 is another application dated 26-6-1981 of the General Secretary Chattishgarh Khadan Karkhana Mazdoor Union, Bankimongra, District Bilaspur addressed to the Regional Labour Commissioner (Central) Jabalpur. Ex. W/10 is a letter of the General Secretary dated 29-11-1985 addressed to the Dy. Chief Personnel Manager, Shri Nand-keoliyar, W.C.L. Korba.

13. Bundram and Kriparam have been respectively exam-ined as WW-1 and WW-2.

14. For the purpose of this case Ex. W/2 and Ex. W/10 are material. Paras 2 and 3 of the Settlement dated 2-9-1982 (Ex. W/2) are being reproduced as under :—

"2. The union withdraw the demand in respect of the remaining persons i.e. S/Shri P. R. Gopalan, Umed Das S/s Naval Das, Rangu C/o Firangi, Madan S/o Murali Giri, Ritu S/o Kunjam, Bar-geese S/o Firangi and Sasidharan S/o Narayanan, because Shri P. R. Gopalan was not an employee and was a contractor and others because they had worked for a lesser period.

3. The management, as a matter of good will, will give preference in employment in the canteen to those persons whose names as mentioned in Sl. 2 above as and when vacancies may arise in the canteen. The workers from other disciplines shall ordinarily not be engaged in the canteen."

(See also para 57 Ex. W/2)

14. A perusal of this part of the settlement would reveal that the case of these workmen was not completely given up because as per term 3 the management, as a matter of good will, was to give preference in employment in the canteen to those persons whose names are mentioned in Sl. No. 2 above as and when vacancies arise in the canteen. The underlined sentence is emphasised by underlining it

and which follows that the workers from other disciplines shall not ordinarily be engaged in the canteen. Here is the crux of the case. Testimony of WW-1, Bundram, to the effect that S/Shri Ram Bharose, Neerath, Bajrang, Horilal, Chatram and Puniram are persons who were brought from other disciplines and were engaged in the canteen. This part of the evidence has remained unchallenged.

15. It follows that due consideration was not given this clause No. 3 and that is the cause of the dispute which was raised as per letter Ex. W/10.

16. In view of the above evidence, it becomes clear that the action of the management of South Eastern Coalfields Ltd., Korba Area in not giving preference in employment to S/Shri Umed Das S/o Naval Das, Rangu S/o Firangi, Madan S/o Murali Giri, Nitu S/o Kunjam, Bargeese S/o Firangi and Sasidharan S/o Narayanan in the canteen is not justified. They are entitled to the relief from the date 29-11-1985 as per Ex. W/10.

17. Accordingly, the workmen would be deemed to be absorbed from 29-11-1985 in Canteen as General Mazdoor Category I with all consequential benefits arising therefrom prospectively and not with retrospective effect.

Reference is answered accordingly without any order as to costs.

V. N. SHUKLA, Presiding Officer  
[No. L-21011/17-87-D.J.HI (B)/JR (Coal-II)]  
RAJALAL, Desk Officer

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1991

का.भा.-453-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक, मद्रास के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण त.मिल-नाडु, मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-1-91 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 16th January, 1991

S.O. 453.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby published the following award of the Industrial Tribunal, Tamil Nadu, Madras as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India, Madras and their workmen, which was received by the Central Government on 15-1-1991

## ANNEXURE

### BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMILNADU MADRAS

Thursday, the 27th day of December, 1990

Industrial Dispute No. 34 of 1987

(In the matter of the dispute for adjudication under Sec-tion 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of State Bank of India, Madras.)

### BETWEEN

The workman represented by  
The General Secretary,  
State Bank Workmen Staff Union,  
62-A, Gengu Street, Egmore,  
Madras-600008.

AND

The Chief General Manager,  
State Bank of India, Local Head Office,  
21, Rajaji Salai, Madras-600001.

## REFERENCE :

Order No. L-12012/185/86-D.II(A), dated 30-3-1987 of the Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on this day for final disposal in the presence of Tvl. T. S. Gopalan, P. Ibrahim Kalifulla, N. C. Srinivasavaradhan and S. Ravindran, Advocates appearing for the management, union pursuing the reference, claim and counter statements and other connected papers on record and the workmen or his counsel being absent, this Tribunal passed the following.

## AWARD

This dispute between the workmen and the management of State Bank of India, Madras arises out of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India, in its Order No. L-12012/185/86-D.II(A), dated 30-3-87 of the Ministry of Labour for adjudication of the following issue :

"Whether the action of the management of the State Bank of India, Region II in relation to their Cuddalore O.T. Branch in dismissing Shri K. Sivagurunathan, Clerk from service w.e.f. 8-12-84 is justified? If not, what relief the workman concerned is entitled to?"

2. Parties were served with summons.

3. Petitioner union filed its claim statement on 29-6-87 putting forth the claim of the workman Thiru K. Sivagurunathan, Clerk. In repudiation thereof the respondent management has filed its counter statement on 28-3-88.

4. In spite of several adjournments, the petitioner union did not appear and no representation was made.

5. Today when the dispute was taken up for enquiry, the petitioner worker is absent. No representation is made for him. Respondent is present.

6. Hence Industrial Dispute is dismissed for default.

Dated, this 27th day of December, 1990.

THIRU M. GOPALASWAMY, Industrial Tribunal  
[No. L-12012/185/86-D.II (A)]  
S. C. SHARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1991

का.प्रा.-454—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे के प्रबंधन के संबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बड़ीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-1-91 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 16th January, 1991

S.O. 454.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway and their workmen, which was received by the Central Government on 15-1-91.

## ANNEXURE

BEFORE SHRI ARVIND KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I. D. 107/90

Employers in relation to the management of Northern Railway.

## AND

Their workman—Ish Kumar

For the workman.—Shri B. N. Sehgal.

For the management.—None.

Industry : Rly.

State—Punjab

## AWARD

Central Govt. vide gazette notification No. L-41012/93/89 I.R. (D. U.) dated 13th August 1990 issued U/S 10(1) (d) of the I. D. Act 1947 referred the following dispute to this Tribunal for decision on a dispute raised by Shri Ish Kumar.

"Whether the punishment of removal of Shri Ish Kumar, Ex. Callman under Loco Foreman, Amritsar, from 25-5-86 is proportionate to his misconduct of unauthorised absence and if not to what relief he is entitled to?"

2. Present case was taken up at Lok Adalat. However Mr. B. N. Sehgal rep. of the workman had made a statement that similar case for similar relief of the workman concerned is pending in the Central Administrative Tribunal, Chandigarh and the workman does not want to pursue with the present reference in this Tribunal. In view of the statement made by the rep. of the workman a no dispute award is returned.

Chandigarh,

21-11-1990

ARVIND KUMAR, Presiding Officer  
[No. L-41012/93/89-IR(DU) (Pt.)]  
K.V.B. UNNY, Desk Officer

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1991

का.प्रा. 455—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मेसर्स बी.सी.सी. एल. की मुषीदीह कोलियरी के प्रबंधन से संबंधित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 1) धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-1-91 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 17th January, 1991

S.O. 455.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1 Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Mudidih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., and their workmen which was received by the Central Government on the 15-1-91.



## ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the  
Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 48 of 1983

## PARTIES :

Employers in relation to the management of Mudidihi  
Colliery of M/s. B. C. C. Ltd.

## AND

Their Workmen.

## APPEARANCES :

For the Employers : Shri G. Prasad, Advocate.

For the Workmen : Shri B. B. Pandey, Advocate.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dated, the 31st December, 1990

## AWARD

By Order No. L-20012(407)/82-D.III(A), dated, the 20th  
June, 1983, the Central Government in the Ministry of Labour  
has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of  
sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act,  
1947, referred the following dispute for adjudication to this  
Tribunal :

"Whether the action of the management of Mudidihi  
Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited,  
Dhanbad in refusing regular employment to the 17  
Stone Cutters listed in the Annexure below and  
not engaging them on wages as per National Coal  
Wage Agreement II is justified? If not, to what  
relief are the workmen entitled and from what  
dated?"

2. The case of the management of Mudidihi Colliery of  
Messrs. Bharat Coking Coal Limited, as disclosed in the  
written statement, details apart, is as follows :

The schedule of the terms of reference has not been properly couched by the appropriate Government i.e. Central Government. Besides, the present reference does not also satisfy the requirement of Section 2(k) of the Industrial Disputes Act. The reference is vague as the parentage, home address, token number, identity card no. of the concerned workmen have not been disclosed in the annexure to the reference. The persons named in the reference are not employees of Mudidihi Colliery and there exists no relationship of employer and employee between the management of Mudidihi Colliery and the persons concerned. Stone cutting job is not a job of permanent nature and regular feature and stone cutting is undertaken only when there is a stone barrier. Stone cutters are employed when necessary but the persons named in the reference were never employed as stone cutters or on any other job under the employer of Mudidihi Colliery. In the circumstances, the management has prayed that its action in refusing employment to the persons concerned is fully justified.

3. The case of the concerned workmen, as disclosed in the written statement submitted on behalf of the sponsoring union, Colliery Shramik Sangh, is as follows :

The concerned workmen are in employment of Mudidihi Colliery for the last seven years on permanent nature of jobs. They have been working under complete control, direction and supervision of the management. They have been producing goods and services for the management and so there exists the relationship of employer and employee between the management and the concerned workmen. The management have been taking work from these workmen but they are being paid meagre amount by way of wages through an intermediary. They have been in continuous service of the management. The management did not pay any attention to the representation of the concerned workmen for payment of wages as per N.C.W.A. II. In the circumstances,

their union was compelled to take up the dispute for conciliation where the management denied that there existed relationship of employer and employee between it and the concerned workmen. The Conciliation Officer was convinced that there existed relationship of employer and employee between the management and the concerned workmen and submitted his report to the Ministry. The Ministry was pleased to refer the dispute for adjudication by this Tribunal. The job of stone cutting through an intermediary has been prohibited by the Government of India under the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970. The management also agreed to see that all these concerned workmen were treated as permanent workmen.

4. In rejoinder to the written statement of the sponsoring union, the management has asserted that the job of stone cutting by contract labour has been prohibited since 15-2-75 and therefore, the question of employing the persons concerned for stone cutting job does not arise. The job of civil contract in underground is still being performed by the contractor but the persons concerned in the reference never worked as stone cutters. These persons may have been engaged by the contractor to do civil work but they have never worked as stone cutters. The management has reiterated that there exists no relationship of employer and employee between it and the concerned persons. The management has also reiterated that it never agreed to treat these persons as permanent workmen.

5. In rejoinder to the written statement of the management, the sponsoring union has asserted that the present reference is perfectly maintainable and that the reference satisfies the requirement of Section 2(k) of the Industrial Disputes Act. The concerned workmen have been working in underground mine in stone cutting job within the premises of the management and producing goods and services for the management. In such circumstances, they should be treated as regular workmen of the management. Form 'C' Register maintained by the management from the period 1978 onwards will show that the concerned workmen were engaged and are still being engaged in stone cutting job through intermediary. The particulars of the concerned workmen are maintained by the management either in Form 'B' Register or in a separate register maintained by the management through intermediary. Besides, the concerned workmen are entitled to better wages in view of the principles of law of equal pay for equal job in a particular industry. Stone cutting job is perennial in nature. In the process of winning coal from the womb of the earth stone cutting is essential. The management's contention that stone cutting is not of permanent nature and that cutting of stone comes up when there is barrier in the mine suffers from lack of knowledge of mining operation. As a matter of fact, stone cutting job is essential and inevitable in the process of mining and winning of coal. In the circumstances, the union has prayed that the management be directed to give regular employment to the concerned workmen and pay them wages as per N.C.W.A. II.

6. In order to justify its action, the management has examined two witnesses, namely, MW-1 Sudarshan Singh, working as Asstt. Manager in Mudidihi Colliery since 1980 and MW-2 Mahadeb Kumar Sengupta, posted to Mudidihi Colliery since 1977 and presently holding the post of Senior Mining Engineer and laid some items of documents (Bonus Registers) which have been marked Exts. M-1 to M-1/5.

On the other hand, the sponsoring union has examined five witnesses, namely, WW-1 Prakash Singh, WW-2 Anil Kumar, WW-3 Soman Nonia, WW-4 Birenchi Paswan and WW-5 Krishna Ballav Sahay, General Secretary of the sponsoring union and laid in evidence some documents which have been marked Exts. W-1 to W-14.

7. The case of the sponsoring union is that the concerned workmen have been employed in different sections of Mudidihi Colliery since 1975 continuously and regularly in the job of stone cutting, a permanent nature of job, under the complete control, direction and supervision of the management. It is also the case of the union that the concerned workmen have been producing goods and services for the management and so there exists relationship of employer and employee between the management and them and although the management has been taking work from them, they are being paid meagre amount of wages through intermediary. It has been

asserted by the union that stone cutting job through an intermediary has been prohibited by the Government of India under the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970.

The case of the management is that the concerned workmen were never employed in the job of stone cutting and that they might have been engaged by the contractor for doing civil work and hence there exists no relationship of employer and employee between the management and the concerned workmen.

8. The schedule to the terms of reference consists of two parts—(i) whether the action of the management of Mudidih Colliery in refusing regular employment to the 17 stone cutters is justified and (ii) whether the action of the management in not engaging them on wages as per N.C.W.A. is justified.

The management is evidently denying employment to the concerned workmen on the ground that there exists no relationship of employer and employee between the management and the concerned workmen. In the circumstances, it has to be ascertained if such relationship exists between the management and the concerned workmen and, if not, the present reference should perforce be answered in the affirmative.

9. In support of its case the management has produced the Bonus Registers marked Exts. M-1 to M-1/5 and produced also the Form 'C' Registers and Cap Lamp Registers marked Exts. W-2 series and W-3 series on the prayer of the sponsoring union. Besides, the management has examined two witnesses, namely, MW-1 Sudarshan Singh, working in Mudidih Colliery as Asstt. Manager since 1980 and MW-2 Mahadeb Kumar Sengupta, posted to Mudidih Colliery since 1977, earlier holding the post of Asstt. Manager and now holding the post of Senior Mining Engineer.

The Bonus Registers (Ext. M-1 series) do not of course bear out the names of the concerned workmen as regular employees of the colliery. MW-1 Sudarshan Singh has stated that the concerned workmen never worked as regular employees of the colliery and that they had worked for their employer, one Md. Ansarul, a contractor employed for executing certain work by the management in the colliery. He has further stated that Benimadhab Lal, Mohisin Khan, and Birendra are also the other contractors operating in the colliery. He has also stated that he is incharge of 7/8 incline and that the concerned workmen were deployed for doing the work of line packing, line carrying, roof fall clearing and for placing of stoppings. MW-2 Mahadeb Kumar Sengupta has stated that the concerned workmen have never worked as employees of the colliery. In cross-examination he has stated that he could not say if the concerned workmen did the job of stone cutting in the colliery from 1975 onwards.

10. On the other hand, the sponsoring union, in support of its case has examined five witnesses including one of the concerned workmen.

WW-1 Prakash Singh has been working at present in Mudidih Colliery as mining sirdar. He has asserted that the concerned workmen are known to him and they are still working in different sections of Mudidih colliery and that they are mainly performing the job of stone cutting in underground mine. He has further stated that as stone cutters they have been working under the supervision of Mining Sirdar including himself and that the management is taking various types of ancillary jobs relating to the main job of stone cutters from them which include stemming of holes, dressing, application of explosives to the holes. WW-2 Anil Kumar has been working in Jorta Section of Mudidih Colliery as Attendance Clerk since 1984 and has been working as Attendance Clerk of Mudidih Colliery since 1983. He has stated that he knows all the concerned workmen and all of them have been working as stone cutters in Mudidih Colliery and he has been seeing them doing these jobs since 1984. He has further stated that all the stone cutting job is being done by the concerned workmen although the management engaged them through contractor. WW-3 Soman Nonia has been working in Mudidih Colliery as Timber Mistry for last 13 years. He has stated that all the concerned workmen have been doing the job of stone cutter in underground mine of Mudidih Colliery at the instance of the management

for the last 10 years. In cross-examination he has admitted that the concerned workmen have been working as contractor's workmen. WW-4 Bunch Paswan is one of the concerned workmen of the present case. He has stated that he knows the other 16 concerned workmen and all of them have been working as stone cutters in Mudidih colliery for the last 11 years. He has complained that they have not been getting full wages and other benefits and amenities from the company. WW-5 Krishna Ballav Sahay is the General Secretary of the sponsoring union and working as Senior Overman in Mudidih Colliery. He has stated that he knows all the concerned workmen and they have been working as stone cutters in Mudidih Colliery, and, according to him, the management is not justified in refusing regular employment to the concerned workmen and that the concerned workmen are entitled to get regular employment and wages as per N.C.W.As.

Cap Lamp Registers Ext. W-3 series indicate that the concerned workmen have been working under contractors. The Form 'C' Register Ext. W-2 series do not indicate any different position. Ext. W-6 series Transit Slips (Explosive Issue and return vouchers) indicate that the same were issued to some of the concerned workmen at different times by the management of Mudidih Colliery. WW-5 Krishna Ballav Sahay has explained the position that Transit Slip Ext. W-6 was issued in favour of Bharat Paswan, one of the concerned workmen for carrying explosive and that the Transit Slip Ext. W-6/1 was issued in favour of Bharat Paswan for carrying explosive in Pit No. 1 for the purpose of drifting. Likewise, he has explained the other slips issued to Nand Kishore Paswan and Ramesh Paswan Exts. W-2 and W-6/3, two of the concerned workmen for carrying explosive for the purpose of drifting. He has further stated that another transit slip was issued to Ramesh Paswan another workman for carrying explosive (Ext. W-6/4). In this connection the evidence of WW-1 Prakash Singh merits reiteration. He has stated that the management is taking various types of ancillary jobs relating to the main job of stone cutting from the concerned workmen including stemming of holes, dressing, application of explosives to the holes. WW-5 Krishna Ballav Sahay has stated that these explosive transit slips were issued for carrying explosive for the purpose of drifting.

The union has produced photo copy of notesheet (Ext. W-9) raised by Senior Personnel Officer of Mudidih Colliery, the relevant portion of which is gleaned hereinbelow :

"Shri K. B. Sahay, General Secretary, Colliery Shramik Sangh raised an industrial dispute before the Asstt. Commissioner (C), Dhanbad on 28-6-82. The case was conciliated on several dates and finally ended in failure. Sri R. Singh, Asstt. Labour Commissioner (C) submitted the failure report to the Central Government and the Government of India, Ministry of Labour referred this case to Labour Court, Dhanbad for adjudication. The case in brief as contended by the union is as under.

... .. Further at the adjudication level management has also taken stand that stone cutting being prohibited category of work, hence it has not been carried out by the management since 15-2-75 contractually. But the factual position is that certain stone cutting work are being done by contractually. It is not possible to ascertain as to how many persons were engaged by contractor if at all and whether these were the very person who were engaged. Further in presence of the documents filed by the union i.e. estimate no. with amount material slip issued in the name of concerned workmen may weaken the case at the tribunal. However, in light of the D(P)'s letter No. D(P)/PS/86/2649-949(H) dated 8-5-86, this case can be reviewed or legal opinion be sought into the matter. On verbal enquiry some concerned workmen are still working with the contractor i.e. Sri Ansarul."

The concerned workmen represented to the management demanding enhancement of wages (Ext. W-10). It appears that the management gave approval of estimates amongst others for dressing roof stone (Ext. W-11), dressing of roof stone (Ext. W-11/1), cutting stone for making step at travel-

ling road, drivage drift in stone and coal (Ext. W-11/2), cutting stone and coal for widening the air shaft and dismantling existing pucca stairs (Ext. W-11/3) an estimate for dressing roof stone (Ext. W-12), cutting stone for dressing roof (Ext. W-12), cutting stone for dressing roof (Ext. W-12) and dressing roof stone (Ext. W-12). The union has also produced tender floated by the management for drivage of inclined shaft from 13 seam to 12 seam in No. 1 Pit Tetulmari Section (Ext. W-13). Even MW-1 Sudarshan Singh has had to admit that drift cutting work is given to the contractor on tender.

11. Considering the hard evidence on record, I am constrained to hold that the concerned workmen, though employed through contractors, have been doing various types of jobs including the job of stone cutting in Mudidih colliery since long.

MW-1 Sudarshan Singh has admitted that materials for work of contractor's men are supplied by the management. He has further admitted that the stone cutting job is supervised by the management although done by the contractors through their workmen and that Mining Sirdars, on behalf of the management, point out the work face for doing stone cutting job to the contractors' workmen. MW-2 Mahadeb Kumar Sengupta has admitted that stone cutting in underground mine is done under the supervision of the Mining Sirdars. MW-1 Prakash Singh is a Mining Sirdar in Mudidih Colliery. He has stated that the concerned workmen have been working as stone cutters under the supervision of Mining Sirdars including himself.

Thus, the evidence on record establishes the position that the management have been exercising supervision and control over the work of the concerned workmen as stone cutters and that the work implements to them are supplied by the management. This being so, it is evidenced that the concerned workmen have been producing goods and services for the management and it follows therefore that there exists relationship of employer and employee between the management and the concerned workmen.

12. This position is also reached by considering other aspects of the case. Admittedly, stone cutting job in underground mine is a prohibited category of job. MW-1 Sudarshan Singh has admitted that stone cutting job is a prohibited category of job. This being so, the management is not permitted to employ contractor's men in this category of job, but the management of Mudidih Colliery has ignored the provision imposed on it by the Government.

The effect of the provision of Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, is that for a valid employment of contract labour, two conditions must be fulfilled, namely, (i) every principal employer of an establishment must be registered and (ii) the contractor must have valid licence. In other words, the mere registration by the principal employer or the holding of licence by contractor alone will not enable the management to treat the workmen as contract labour. The management in this case has not produced the registration of its establishment and the licence of the contractor. Hence, in the circumstances, the contractor's workmen should be considered to be the workmen of the principal employer i.e. the management of Mudidih Colliery. In this view of the matter there exists relationship of employer and employee between the management of Mudidih Colliery and the concerned workmen.

13 MW-2 Mahadeb Kumar Sengupta has, in his evidence, raised the issue of casualness of employment of stone cutters. He has stated that stone cutting job is very casual in nature and is required to be done through the agency of contractor in Mudidih Colliery. But Central Coal Wage Board Recommendation and N.C.W.As provide categorisation of stone cutters and their job descriptions. This by itself indicates that the job of stone cutters is not of casual in nature. Besides, the job of stone cutting in underground mine has been prohibited by the appropriate Government. Had the Government considered the job to be of casual in nature, it would not have imposed the ban on such job being done through contractor. Hence, I am constrained to hold that the stone cutting job in underground mine is not a casual but a permanent nature of job.

14. Considering the facts and circumstances of the case, I am constrained to hold that the management of Mudidih Colliery is not justified in denying regular employment to the concerned workmen and paying them wages as per N.C.W.A.II. But I also consider that it would be onerous on the part of the management to absorb all the concerned workmen in service all at a time. MW-2 Mahadeb Kumar Sengupta has stated that in his unit (Jogta Pit No. 2) there was no regular workmen of the colliery for the job of stone cutting. There is no evidence on record to indicate as to whether the management has since engaged regular workmen for doing stone cutting job. Hence, I direct the management to give regular employment to the concerned workmen and to pay them wages as per N.C.W.As as and when required, preferably within the course of next six months from the date of publication of the award.

15. Accordingly, the following award is rendered—the action of the management of Mudidih Colliery of M/s. B.C.C. Ltd. in refusing regular employment to the 17 Stone Cutters and not paying them wages as per N.C.W.A.II is not justified. The management is directed to give regular employment to the concerned workmen as and when required, preferably within the course of next six months from the date of publication of the award and to pay wages as per N.C.W.As.

In the circumstances of the case, I award no cost.

S. K. MITRA, Presiding Officer

[No. 1-20012/407/82-D.III(A)/IR (Coal-I)]

का.प्रा. 456—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मैसर्स बी.सी. सी.एल. की बलिहारी कोयली के प्रांचल से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 1) धनबाद के प्रांचल को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-1-91 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 456.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No 1 Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Balihari Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., and their workmen which was received by the Central Government on the 15-1-91.

## ANNEXURE

### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 37 of 1984

PARTIES :

Employers in relation to the management of Balihari Colliery of M/s. B.C.C. Ltd.

AND

Their Workmen.

Appearances :

For the Employers.—Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen : Shri S. Bose, Secretary,  
Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.

State : Bihar

Industry : Coal

Dated, the 31st December, 1990

### AWARD

By Order No. L-20012(95)/84-D.III(A), dated, the 2nd July, 1984, the Central Government in the Ministry of Labour, has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Sec. 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

Whether the demand of Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh that Shri Gajadhar Yadav should be allowed by the management of Balihari Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited to resume his duty is justified ? If so, to what relief is he entitled and from what date ?

2. The management of Balihari Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited and the sponsorrig union, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, have filed a joint petition of settlement in the present industrial dispute. In terms of this settlement the union has conceded that there is no merit in the industrial dispute and so, both the union and the management agreed to approach the Tribunal to pass a 'no dispute' award in this case as there is no subsisting dispute. This being so, I am constrained to hold that there exists no dispute between the parties and in the circumstances, I pass a 'no dispute' award in the present industrial dispute.

This is my award.

S. K. MITRA, Presiding Officer  
[No. L-20012(95)/84-D.III(A)/IR(Coal-I)]  
K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1991

का.भा. 457.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इंडियन एयरलाइन्स, बम्बई के प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रतिकारण सं. 1, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-1-91 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 17th January, 1991

S.O. 457.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Indian Airlines, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on 15-1-1991.

### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

Presiding Officer, Justice S. N. Khatri,  
Reference No. CGIT-38 of 1988

#### PARTIES :

Employers in relation to the Management of Indian Airlines, Bombay

#### AND

Their workmen.

#### APPEARANCES :

For the Management—Shri M. M. Verma, Advocate.

For the Workmen—Shri K. P. Menon, Advocate.

INDUSTRY : Airlines

STATE : Maharashtra

Bombay, the 8th January, 1991

### AWARD

The Central Government has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947.

"Whether the action of the management of Indian Airlines, in relation to its establishment at Bombay in dismissing Shri A. S. Dev, a Senior Air Craft Technicians from services with effect from 14-5-86 is justified ? If not to what relief the Workman is entitled to ?"

2. A. S. Dev (hereinafter the 'Workman') had been working under the Indian Airlines, Bombay, (hereafter the 'Management') since 11th April, 1979. He was holding the post of Senior Aircraft Technician at the time of his dismissal on 14th May, 1985. It appears that on 17th December, 1984 he left for Jalandhar in Punjab without obtaining prior leave. He alleges that at Jalandhar he met with an accident on 18th December, 1984, disabling him from joining his duty at Bombay. He continued to take treatment there till 14th August, 1985, when he was declared fit to travel. The workman immediately came down to Bombay but again fell ill in the train journey. He took treatment from 15th to 20th August, 1985 at Bombay and joined duty on 21st August, 1985, after being declared fit by the Management's Medical Officer. It appears that during the period of his absence from duty, he made several applications for leave accompanied by medical certificates on 7-1-85, 14-1-85, 17-1-85, 13-2-85, 12-3-85, 14-4-85, 30-5-85, 26-6-85, 10-7-85, 24-7-85 and 8-8-85. His grievance is that the Management did not reply any of those applications. It is significant to note that the Management do not deny this particular allegation in their written statement, but merely state that para 4 of the statement of claim which contains this allegation, is a matter of record.

3. The Management by their letter dated 25/29th March, 1985 chargesheeted the workman for his unjustified absence from duty from 17th December, 1984 to 29th March, 1985 under clause 28(13) of the Standing Orders. By a second letter dated 13th June, 1985 he was chargesheeted for similar misconduct relating to the period 30th March, 1985 to 13th June, 1985. By a still third letter dated 30th January/3rd February, 1986 he was chargesheeted for the period 14th June, 1985 to 20th August, 1985. Two separate domestic inquiries were held for the first two chargesheets, and the workman was found guilty in both inquiries. In the first inquiry with which we are not concerned in the present case, his basic pay was reduced by one increment with cumulative effect from 1st January, 1986. So far as the second inquiry is concerned, by the impugned order dated 14th May, 1986 the workman was dismissed from service with immediate effect. It is this Order, which is the subject matter of the present reference.

4. The workman has challenged the validity of inquiry mainly on the ground that he was not given opportunity to be defended by an Advocate or at least by a colleague of his own choice. He also takes exception to the Management holding separate inquiries by artificially splitting the period of his absence into three watertight compartments, although the period of absence was one whole caused by a single cause. His suggestion is that the Management took to this dubious device only to create adverse record and justify the extreme penalty of dismissal. Even on merits he challenges the finding as perverse, and the punishment as shockingly disproportionate to the gravity of the misconduct imputed to him. He claims reinstatement with full back wages.

5. The Management resist the workman's claim. They deny that the domestic enquiry is vitiated for any reasons and assert that the finding of guilt and quantum of punishment are justified.

6. The issues that arise for adjudication are given below with my finding thereon :

## ISSUES

## FINDINGS

1. Is the domestic enquiry vitiated by breach of the principles of natural justice or for any other cause ? Yes.
2. Is the finding of guilt perverse ? Yes.
3. Is the punishment unduly harsh and disproportionate to the gravity of the misconduct ? Yes
4. What relief, if any, is the workman entitled to do ? Reinstatement with full back wages and costs Rs. 2,000

## REASONS FOR FINDINGS

7. Issue No. 1.—Before me the workman has filed his Affidavit in support of his case. He has been cross-examined by the Management. The latter have not adduced any oral evidence. Both sides have filed documents, which have been exhibited by consent. The learned counsel of both sides have filed their written submissions.

8. There is substance in the contention of the workman that the Enquiry Officer denied him reasonable opportunity to defend himself, by rejecting his request for time to bring his friend to assist him in the enquiry. Apart from the sworn testimony of the workman which is challenged in cross-examination on this particular point, the proceedings of the enquiry (Ex. M-2) dated 9th September, 1985 themselves bear out the truth of his grievance. On the request of the workman for assistance of a friend, the Enquiry Officer offered him half an hour to bring his Adviser. The workman told him that his Adviser was busy attending some meeting with the Management on the issue of bonus at Nariman Point. The Enquiry Officer refused to adjourn the matter and pressed him to bring some other colleague. The workman pleaded his inability to get one, whereupon the Enquiry Officer proceeded with the enquiry forthwith. He directed the Presenting Officer of the Management to produce the witnesses. The Presenting Officer examined one Mrs. M. P. Rathod, Office Assistant and Mr. M. N. Pote, Office Superintendent. The record shows that the cross-examination of the first witness by the workman was just perfunctory, while he declined altogether to cross-examine Pote. The workman failed to cross-examine either of the witness effectively on vital questions, including the one as to the manner in which his applications for leave, were dealt with. The record shows that the Enquiry Officer sought a clarification from the Presenting Officer, whether it was the responsibility of the employee to confirm from the authorities whether his leave application was received and sanctioned or whether it was the responsibility of the Competent Authority to reply. The Presenting Officer was quick to cast the duty on the employee. Obviously this must have unnerved the workman, who stopped cross-examining Mrs. Rathod. Next Pote was examined-in-chief. The workman declined to cross-examine him. Indeed the workman had supported his applications by medical certificates. The record of the evidence of these two witnesses shows that gross prejudice has been caused to the workman on account of Enquiry Officer's refusal to allow the workman to have assistance of a friend to cross-examine the witness. May be the workman was not entitled to the services of a regular Advocate; but undisputedly he was entitled to assistance of his colleague. The Enquiry Officer's refusal to grant him adjournment on 19-9-85 has resulted in serious breach of the principle of natural justice. The enquiry stands vitiated on this count.

9. The contention of the workman that holding two different enquiries for two artificial segments of the period of his absence, which was a continuous one, has also substance in it. I can understand the Management's argument and that it was not incumbent on them to wait for the workman and postpone the issuance of chargesheet till his final return on duty. However, this did not mean that they should have independent enquiries for each segment of the period of absence, although it was occasioned by a single cause and constituted one continuous whole span. Proper and fair cause would have been to hold a single enquiry

covering the entire period, with the option left over to the Management to issue 3 chargesheets or a single consolidated one. Separate enquiries would have been in order, if the cause for absence relating to each segment, was independent of and separate from the other two. The prejudice caused to the workman in holding multiple enquiries is obvious from the way the Enquiry Officer has assessed the evidence. I have discussed this aspect in para 11 infra. I do not wish to add further to the length of this Award. The enquiry is held to be vitiated for the reasons stated above.

10. The Management have not made any request for permission to lead evidence before the Tribunal on merits of the charges. As such I must proceed to the conclusion of the reference. As the enquiry is held to be vitiated, the workman is entitled to get his dismissal set aside with reinstatement and back wages. All the same, I would like to record my findings on the second and third issues also, with sketchy reasons.

11. The Management examined Mrs. M. P. Rathod, Office Assistant and Shri M. N. Office Superintendent. The former affirms that the workman had sent one letter dated 18th April, 1985 accompanied by medical certificate to the Management from Jalandhar and another dated 3rd June, 1985, which was not accompanied by any medical certificate. In her cross examination she further admitted that the Management received one more letter dated 26th June, 1985 along with a medical certificate. Here I may note that the Enquiry Officer restricted the admission of letters strictly to the second segment of the period of workman's absence that is from 30th March, 1985 to 13th June 1985. At the cost of repetition, I have to emphasize that he consciously excluded other letters which, in his opinion, related to the first and the third segments preceding 30th March, 1985 and following 13th June, 1985 respectively, ignoring the workman's writ that he had in fact sent as many as 11 letters, some of them accompanied by medical certificates from 7-1-85 to 8-8-85, which the Management did not reply. It is here that irreparable prejudice has been caused to the workman's defence by the Management compartmentalising the absence of the workman into three water-tight segments and holding independent inquiries for each segment. Relying on the evidence of Smt Rathod, Shri Pote and the administrative instructions issued in the Management letter dated 27th September, 1984 (Ex. 5 in the domestic enquiry) the Enquiry Officer concluded :

"Shri A. S. Dev produced only one medical certificate during the entire period in question i.e. 30-3-1985 to 13-6-1985. This medical certificate issued by Dr. Savant Singh City Hospital and Martinity home issued on 14-4-85 advising Shri A. S. Dev to take rest for 10 days due to injury on right foot. Thus it is quite evident that Shri A. S. Dev did not fulfil the requirement to keep close liaison with his officer in charge while he was sick at Jalandhar, and he did not submit his fortnightly progress report to his Officer in charge from the private medical practitioner along with the necessary details as laid down in the circular no CEM 301/1503 dated 27-9-1985 (Exhibit No. 5).

Keeping in view above mentioned facts, in my considered opinion the charges under the clauses 28(13) read as :

Absence without leave or overstaying sanctioned leave without sufficient grounds or proper or satisfactory explanation.

Stand fully established and that Shri A. S. Dev is guilty of the charges levelled against him."

12. It is the case of the workman that he had written as many as 9 letters, dates of which have already been adverted to in para 2 supra. These were accompanied by medical certificates. The evidences of Rathod and the documents filed by the workman (Ex. W-1 to Ex. W-8) substantially bear out his aforesaid assertion. The Management also do not deny this factual position. All this creates a ring of truth round his case that immediately on reaching Jalandhar he got his right foot injured in an accident and was unable to join his duty back at Bombay till August, 1985. In the face of the circumstances established on the record, it is difficult to endorse the view of the Enquiry

Officer that the workman had not kept liaison with the Management during the course of his absence. Moreover departmental instructions of this sort are directory in nature. They have been substantially complied with by the workman. I quite appreciate that the corporation being a public utility service, absence of their employees without sufficient cause, cannot be treated lightly. However on the facts and evidence of the present case, no reasonable conclusion is possible, but that the workman's absence was for sufficient cause. The second issue is accordingly answered against the Management.

13. Issue No. 3.—This issue does not survive for decision. Had a finding been necessary I would have held that reduction of the workman's pay by one stage (punishment imposed for the misconduct relating to the first segment of the period of absence) would be more than adequate for the total period. I would have set aside the order of dismissal even in case the Management had succeeded in proving the charge relating to the second segment of the workman's period of absence. No separate punishment of dismissal or any lesser punishment was called for in the second domestic enquiry.

14. Issue No. 4.—The workman is entitled to reinstatement. The Management do not allege that he was gainfully employed elsewhere during the material period. He will therefore be entitled to full back wages also. Hence my award.

#### AWARD

The reference is accepted. The action of the Management in dismissing the workman with effect from 14th May, 1986, is held to be illegal and unjustified. His dismissal is set aside. The Management are directed to reinstate him and pay full back wages. They shall also pay Rs. 2,000 as his costs, and bear their own.

S. N. KHATRI, Presiding Officer

[No. L-11012/31/87-D.II (B)/TR(Misc.)]

का आ 45९—औद्योगिक अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसर्गण में, केन्द्रीय सरकार मद्रास डाक लेबर बोर्ड, मद्रास के प्रबंध तंत्र में संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचाट की प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-1-91 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 468.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Madras Dock Labour Board, Madras and their workmen, which was received by the Central Government on 15-1-91.

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMILNADU MADRAS

Thursday, the 29th day of November, 1990

Industrial Minute No. 121 of 1987

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workman and the management of Madras Dock Labour Board, Madras).

#### BETWEEN

The workmen represented by

The Secretary, The Madras Harbour Workers' Union,  
264, Prakasam Salai, Broadway,  
Madras-600108.

#### AND

The Chairman,  
Madras Dock Labour Board,  
Rajaji Salai, Madras-600001

Reference:—Order No. L-33012/i/87-D.IV(A), dt. 9-10-87 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute after restoration coming on for final hearing on Monday, the 5th day of November, 1990 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru K. K. Parthasarathy, Advocate appearing for the workmen and of Thiru R. Arumugam for Tvl. Aiyar and Dolia and R. Arumugam, Advocates appearing for the management and this dispute having stood over till this day for consideration this Tribunal made the following.

#### ORDER

This dispute between the workman and the management of Madras Dock Labour Board, Madras arises out of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in its Order No. L-33012/i/87-D.IV(A), dated 9-10-87 of the Ministry of Labour for adjudication of the following issue :

"Whether the action of the management of Madras Dock Labour Board Madras in awarding the punishment of stoppage of two increments with cumulative effect to Smt. T. K. Rajakanthamani, Peon, vide order dated 27-7-84 is justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled?"

2. Statement of claimant runs as follows :—The petitioner is working as Ayah (Peon) in the Hospital under the respondent. If any employee working in Colony Dispensary situated at Thondiyarpet goes on leave granted in advance, the employee from the main Dispensary will be disputed to substitute the employee on leave. If leave is not granted in advance then the available staff in the colony dispensary themselves would manage the work. The petitioner while working in the colony dispensary on 13-6-84, was asked to do the work of Attender i.e. issue Out-Patient Cards since a card issue Attender was absent at that time. The petitioner whose post is inferior to that of Attender, hesitated to perform duty of an attender as she did not have skill or capacity. A memo was issued to the petitioner on 16-6-84 alleging that the petitioner disobeyed the directions of the superior officer amounting to misconduct under clause 31(a) of the Standing Orders. The petitioner gave her explanation to the charge. Her explanation was that she could not post entries in the Register and the O.P. Cards while issuing the Out-Patient Cards as she had not the skill to do that job and that it was only the job of an Attender and not that of a Peon or Ayah. Thereafter the Deputy Chairman held an enquiry and passed an order imposing upon the petitioner, penalty of 2 increments cut with cumulative effect. The said order is unjust and illegal. The petitioner preferred appeal, but the same was dismissed by the Chairman on 8-8-84. Due to the cut of two increments the petitioner suffered a loss of Rs. 22 per month w.e.f. November, 1984. Further she was not given promotion at the right time, but her juniors had been promoted on 22-7-87. The petitioner raised a dispute before the Conciliation Authority who submitted a failure report. Hence the Industrial Dispute

3. Counter statement of respondent runs follows.—Even at the beginning of the petitioner's service she has been awarded punishment of termination. However on compassionate ground the termination was revoked and also she was re-appointed w.e.f. 21-1-77 as a fresh entrant without any claim to past service. After sometime she was appointed regularly as an Ayah from 1-11-1977.

The Medical Officer in-charge of Colony Dispensary complained in writing on 4-2-82 that the petitioner Rajakanthamani refused to do job of the issuing O.P. Cards, when directed by her and further behaved disrespectfully and declared that she would not be bothered about any memo and left the dispensary itself in defiant mood. Such is her past conduct. Thereupon she was punished with cut of one increment. Then turning to the present dispute, the petitioner re-



lused to obey instruction of the Medical Officer in-charge on 13-6-84 about which the Chief Medical Officer called for an explanation from the petitioner on 16-6-84 and after obtaining her explanation made a complaint to the Deputy Chairman (Appointing Authority) for taking further action. The Deputy Chairman issued a show cause notice (which is incidentally the charge memo) on 17-7-84 calling upon her to show cause as to why she should not be punished with cut of two increments. To that notice she sent a reply dated 20-7-84 that she did not refuse to do the job, but only expressed that she was not accustomed to or capable of issuing O.P. Cards. The Deputy Chairman after hearing the petitioner in person found her guilty of the charge and awarded the punishment by his order dt. 28-7-84. The petitioner has repeatedly disobeyed on 3rd occasions to perform duty of issuing O.P. Cards. She has admitted before the Deputy Chairman that Peons (Ayahs) had been issuing O.P. Cards whenever necessity arose. Therefore the punishment was rightly imposed by the Deputy Chairman and later petitioner's appeal to the Chairman was rejected. The disciplinary action culminating in the punishment is quite lawful. The petitioner's indiscipline over the years has been considered and suitable punishment has been given.

In the enquiry conducted by the Deputy Chairman, the petitioner did not adduce any oral evidence but only pleaded for excuse. The petitioner cannot raise Industrial Dispute before this Tribunal. The punishment given is quite appropriate. The Industrial Dispute is liable to be dismissed.

4. The points for determination are as follows :—

(i) Whether the punishment imposed on the workman is just and lawful?

(ii) To what relief the workman is entitled ?

5. No oral evidence was let in. On the side of the petitioner Ex. W-1 to W-5 were marked. On the side of the management Ex. M-1 to M-9 were marked. It is not in dispute that the petitioner-Rajakanthamani working in Colony Dispensary as Ayah was directed by the Medical Officer-in-charge to attend to preparation and issue of Out-patient Cards on 13-6-84 and the petitioner did not discharge that duty and carryout the directions on the plea that it was an Attender's job which required higher skill and capacity to write, and that she did not possess the same. This was construed as insubordination a memo calling for her explanation was issued on 16-6-84 by Chief Medical Officer under Ex. M-4. In the reply Ex. M-5 given by the petitioner she replied that out of 2 Card Issue Attenders one was absent and other was present at the relevant time, that she herself was not accustomed to issue O.P. Cards. Seeing this explanation the Chief Medical Officer endorsed on Ex. M-5 itself that the explanation was not satisfactory, that the petitioner has done the same thing several times, inspite of oral warnings and that she may be censured. The matter was then taken up by the Deputy Chairman who being the Competent Authority issued the Charge Memo under Ex. M-6 which also spells out the proposed punishment of cutting 2 increments with cumulative effect. By this, the petitioner was asked to explain why she should not be punished. We can take Ex. M-6 notice as combination of charge memo and intimation of proposed punishment. The petitioner submitted her reply dt. 20-7-84 under Ex. M-7 pleading for mercy and stating that she had only explained her difficulty and inability in the matter of issuing O.P. Cards. The Deputy Chairman has passed the order dated 27-7-84, Ex. M-8 which shows that he has held some kind of enquiry and also heard petitioner's personal plea or oral plea for leniency. Ex. M-8 records that he examined the Medical Officer-in-charge Dr. Padmini whose direction was allegedly flouted. The justification for the Dr. Padmini to direct the petitioner to do card issue duty was that one of the two attenders doing that duty, i.e. Thiru Desapann was on leave and that it was the routine practice to employ for that job a member of the lower grade staff i.e. Ayah or peon whenever the attender concerned is absent. We do not know how many Peons other than the petitioner were available on the relative date. The records reveal that the petitioner has never issued O.P. Cards in the past and that she even invited a punishment in 1982 itself, when she refused to issue O.P. Cards. In spite of such a pass the authorities did not pass or issue any written order or circular making it obligatory upon the Ayahs and Peons to do card issue duty which is actually the duty of attenders when the situation warranted

it. In paragraph 4 of the Ex. M-8, the Deputy Chairman refers to the petitioner's statement that she was never given any Office Order, detailing her duties and responsibilities. It is seen that the issue of O. P. Cards requires making some entries in the register and also the cards without mistake. Even assuming that the petitioner was qualified well to write and post entries one cannot deny that was she only an Ayah doing menial duties under the directions of the Medical Officer. The fact that peons who have the same job status as that of Ayahs are doing card issue duty now and then during the absence of attender cannot establish that the petitioner was duty-bound to do the same job and that it was part of her duties as and when an oral direction came from the superior atleast occasionally. As on 13-6-84 the respondent could not prove existence of any office circular or written procedure allocating and defining the duties of Ayahs or Peons forming a category which is inferior to that of card issue Attenders. But the Deputy Chairman concluded that the petitioner disobeyed the direction of the Medical Officer in-charge, that she was bound to obey the order and that her conduct violates relevant Standing Orders and that she was guilty of misconduct under clause 31(a) and (i) and imposed the punishment of two increments cut with cumulative effect.

6. Petitioner's appeal against this order to the Chairman of the Dock Labour Board has been summarily dismissed under Ex. M-9. The petitioner has produced Ex. W-3 a copy of Office Order dated 21-11-86 prescribing duties and responsibilities of Peons and Attenders. Under the Office order the duty mentioned against Item No. 4 specifies that they will be posted at any point i.e. for duty including that of Card Issue Attenders. This Office order which is undoubtedly binding upon the petitioner can take effect only from 21-11-86. It follows that her failure to perform card issue duty on 13-6-84 cannot amount to refusal to perform the duty in as much as it was not her usual duty according to any of Office regulation, particularly written regulation as on 13-6-84. Oral orders of the Superior cannot be said to define the duty of the petitioner at any given point of time. It is more so when the petitioner pleads that she did not have skill to prepare and issue O. P. Cards after making necessary entries in the register concerned. If the petitioner was asked to perform a menial and normal job and she refused to do the same it can amount to insubordination or misconduct. But when the petitioner pleaded inability to do and ignorance of doing particular clerical work the enquiry officer cannot hold that it was her duty and then she failed to do the same and thus disobeyed the oral order of the Medical Officer-in-charge. It therefore follows that the conclusion reached by the Deputy Chairman and confirmed by the Appellate Authority that the petitioner was guilty of misconduct is against law and due process and therefore unjust. I therefore hold on point No. 1 that the punishment meted out to the petitioner is not lawful and just and that the same has to be set aside. The respondent shall allow to her all the increments which were cut and give the petitioner arrears of increments as it punishment has not been imposed. It will be also the responsibilities of the respondent to consider the petitioner's claim for promotion according to her qualification and suitability. The point No. 2 is answered accordingly.

7. In the result, the award is passed setting aside the punishment imposed by the petitioner and directing the respondent to allow and pay all the increments which had been withheld and consider petitioner's claim for promotion according to law. No costs.

Dated, this 29th day of November, 1990.

THIRU M. GOPALASWAMY, Industrial Tribunal

[No. L-33012/1/87-D.IV(A)] [IR(Misc.)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

WITNESSES EXAMINED

Before restoration & After restoration :

For both sides.—None.

## DOCUMENTS MARKED

Before restoration :  
For workmen &  
Management.—Nil  
After restoration :  
For Workman :

- Ex. W-1/8-84.—Appeal preferred by Tmt. T. K. Rajakanthamani to the Chairman of the management Board against the withholding of two increments. (Xerox copy).  
W-2/21-11-86.—Dispute raised by the petitioner-union on behalf of Tmt. T. K. Rajakanthamani before the Regional Labour Commissioner (Central) Madras. (Xerox copy).  
W-3/21-11-86.—Duties and responsibilities of Peon Attender. (Xerox copy).  
W-4/12-2-87.—Conciliation failure report (Xerox copy).  
W-5—Standing orders for the staff of the Madras Dock Labour Board (Xerox copy).

For Management :

- Ex. M-1/19-1-77.—Extract of Order of Appellate Authority on the appeal petition of Tmt. T. K. Rajakanthamani & Nayagam Ammal. (Xerox copy).  
M-2/4-2-82.—Complaint against Tmt. T. K. Rajakanthamani by Dr. J. Uma Devi, Medical Officer to the Chief Medical Officer, M. D. L. B. Dispensary, Madras-1. (Xerox copy).  
Ex. M-3/30-3-82.—Order of Deputy Chairman punishing Tmt. T. K. Rajakanthamani. (Xerox copy).  
Ex. M-4/16-6-84.—Memo issued to Tmt. T. K. Rajakanthamani requiring explanation for her misconduct. (Xerox copy).  
M-5/22-6-84.—Explanation by Tmt. T. K. Rajakanthamani to Ex. M-4. (Xerox copy).  
M-6/17-7-84.—Show cause Notice issued to Tmt. T. K. Rajakanthamani. (Xerox copy).  
M-7/20-7-84.—Reply by Tmt. T. K. Rajakanthamani to Ex. M-6. (Xerox copy).  
M-8/27-28-7-84.—Order of Deputy Chairman of the Management-Board withholding two increments with cumulative effect of Tmt. T. K. Rajakanthamani (Xerox copy).  
M-9/2-9-84.—Order of the Chairman Madras Dock Labour Board, Madras dismissing the appeal preferred by Tmt. T. K. Rajakanthamani. (Xerox copy).

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1991

का.प्र. 459—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूच में, केन्द्रीय सरकार देना बैंक के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं 2, बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-1-91 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 23rd January, 1991

S.O. 459.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay as shown in the Annexure in the Industrial

dispute between the employers in relation to the Dena Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 10-1-1991.

## ANNEXURE

## BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/54 of 1986

## PARTIES :

Employer in relation to the management of Dena Bank.

AND

Their workmen.

## APPEARANCES :

For the Employer.—1. Shri N. K. Fuladi, Advocate.

2. Shri J. S. Nanda, Manager (P).

For the Workmen.—Shri S. G. Kulkarni, Advocate.

INDUSTRY : Banking STATE : Maharashtra  
Bombay, dated the 13th December, 1990

## AWARD

The Central Government by their Order No. L-12012/40/86-D.II(A) dated 16-12-1986 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication under Section 10(I)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 : —

“Whether the action of the management of Dena Bank in relation to their Sadak Arjuni Branch in Distt. Bhandara in retiring from service Shri Ishwar Udhavrao Nagaraley w.e.f. 18-3-1985 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?”

2. The case of the workman Shri I. U. Negaraley as disclosed from the statement of claim (Ex. 2/W) filed by him, in short, is thus :—

The said workman was appointed in the service of the Dena Bank at Nasik in August 1972 as a Typist-clerk. His services were terminated by the Bank management on 18-3-1985. At that time he was drawing salary of Rs. 1,400/- per month. Due to his transfer to Sadak Arjuni Branch of the Bank he was mentally very much disturbed. Further, his mother also died and there was prolonged illness in his family. He himself was ill, and as such due to mentally disturbed conditions he could not attend his duties on 11-8-1984. However, he had informed the Branch Manager of Sadak Arjuni Branch by ordinary post about his absence and had requested that he may be granted the necessary leave. He had also personally seen the Branch Manager of that Branch and requested for leave. However, his request was not considered. The Branch Manager of the said Bank by his letter dated 17-1-1985



[भाग II—खंड 3(ii)]

directed him to report for duty within 30 days. However, the date 17-1-1985 was later on changed to 12-2-1985 and it was actually served upon the workman on 18-3-1985. He reported for duty on 19-3-1985 and onwards. The Branch Manager did not allow him to resume duty. He was, on the contrary, directed to accept his dues including the dues of provident fund and gratuity in full and final settlement of his claim on the ground that he had abandoned his service and had sought voluntary retirement. In fact the workman never intended to seek voluntary retirement from the service of the Bank. He was ready and willing to work in the Bank. The Bank management did not issue any notice of termination from service, nor held any enquiry into the misconduct of unauthorised absence before his services were terminated. His services were terminated illegally by the Bank, without giving him one month's notice or wages in lieu of notice and also retrenchment compensation. As such the termination of his services is bad in law.

The workman therefore prayed that this Tribunal should direct the Bank management to reinstate him in service with full back wages and continuity of service.

3. The Bank management by their written statement (Ex. 3[M]) and additional written statement (Ex. 7[M]) opposed the said claim of the workman and in substance contended thus :—

The said workman Shri I. U. Nagaraley was working as a clerk-cum-typist in the Sadak Arjuni Branch of the Bank and remained absent from duties from 11-8-1984 onwards without any intimation to the Bank. He did not submit any application for leave, nor informed the Bank about any reason for the absence. The Bank had addressed several letters at the last known address asking the workman to report for duty immediately. The first letter dated 17-1-1985 sent to him was returned unserved and hence the Bank sent the other letter notice dated 12-2-1985 which was received by the workman on 18-2-1985. He was asked to resume his duty within 30 days from the date of the notice. He did not however, resume his duty.

4. The workman is governed by the provisions of 4th Bipartite settlement dated 17-9-1984. Clause XVI of the settlement which is material and relates to voluntary cessation of employment, reads thus :—

“In supersession of clause 2 of the settlement dated 8th September, 1983, the following shall apply :

Where an employee has not submitted any application for leave and absents himself from work for a period of 90 or more consecutive days without or beyond any leave to his credit or absents himself for 90 or more consecutive days beyond the period of leave originally sanctioned or subsequently extended or where there is satisfactory evidence that he has taken up employment in India or the management is satisfied that he has no present intention of joining duties, the Management may at any time thereafter give a notice to the employee's last known address calling upon the employee to report for duty within 30 days of the notice, stating, inter alia, the grounds for the management coming to the conclusion that the employee has no intention of joining duties and furnishing necessary evidence, where available. Unless the employee reports for duty within 30 days or unless he gives an explanation for his absence satisfying the management that he has not taken up another employment or a vocation and that he has no intention of joining duties, the employee will be deemed to have voluntarily retired from the Bank's service on the expiry of the said notice. In the event if the employee submitting a satisfactory reply, he shall be permitted to report for duty thereafter within 30 days from the date of the expiry of the aforesaid notice...without prejudice to the Bank's right to take any action under the law or rules of service.”

5. In spite of the notice received by the workman, he did not comply with the directions made therein, and did not report for duty nor submit any explanation for his not resuming his duty. Further as per the Bank record the workman had remained absent unauthorisedly on previous many occasions and the Bank had orally advised him not to do so. However, the workman continued remaining absent from time to time. Therefore, the Bank rightly drew the inference that the workman had no intention of resuming his duty, and as such voluntarily retired from the service of the Bank as per the provisions contained in the said para XVI of the said Bipartite Settlement.

6. The Bank denied any knowledge about the illness in workman's family and the Bank denied that the workman had sent letters to them informing

them about the reasons for his absence from duty. It is also not true that the workman had personally met the Branch Manager of the Bank in November 1984 and had requested for leave. The letter dated 17-1-1985 sent by the Bank directing him to resume duty within 30 days was received by him on 18-2-85 and not on 18-3-1985. It is not true that the workman had reported for duty on 19-3-1985 and onwards and that the Branch Manager had refused to allow him to resume his duty. It was not necessary for the Bank to hold any domestic enquiry against the workman in view of the provisions contained in Clause XVI of the said Bipartite Settlement and hence no enquiry was held against him. Further, voluntary retirement did not attract the provisions regarding retrenchment of workmen from service. The Bank is ready and willing to make payment of outstanding dues payable to the workman, and the workman may approach the Bank and may receive the dues.

7. The Bank management by their further written statement, in substance contended thus :—

The workman had filed an application on 20-9-85 before the Asstt. Labour Commissioner (C), Nagpur requesting him to start conciliation proceedings, before he approached this Tribunal. Accordingly, conciliation proceedings were started by the ALC(C). The Bank management had taken part therein. During the pendency of those proceedings, the workman filed an application on 18-12-1985 before the ALC(C) for withdrawal of that application for conciliation proceedings. Accordingly the applicant was allowed to withdraw his application and the ALC(C) Nagpur closed the case by order passed on 18-12-85. Thereafter the workman submitted the necessary forms for settlement of his dues to the Bank on 20-12-1985. On settlement of his claim, the Bank sent two cheques dated 27-1-1986 and 31-1-1986 respectively for Rs. 11,970 and 13,474.09 to the workman's last known address. Firstly those cheques were returned back with the endorsement "addressee left the address". The Bank management again sent two cheques to the workman. The workman however, returned back those cheques stating that as the present dispute was pending, he was not prepared to accept them.

8. Thereafter the workman again filed an application before the ALC(C) Nagpur requesting that the conciliation proceedings be re-opened. Accordingly those proceedings were re-opened, and in due course the ALC(C) sent the report regarding the failure of conciliation to the Central Government. Thereafter the Central Government made the present reference as above. The workman was directed

by the Bank's notice dated 12-2-1985 to report for duty within 30 days from the receipt thereof. It was received by him on 18-2-1985 and not on 18-3-1985 as alleged by the workman. The workman did not, however, report for duty upto 18-3-85 or at any time thereafter. As such, as per Clause XVI of the said Bipartite Settlement the workman was deemed to have voluntarily retired from the Bank's service from 20-3-1985. The termination of workman's service is just and proper. The Bank management lastly prayed for the rejection of the claim of the workman.

9. The Issues for decision are :—

- (1) Whether the workman Shri Ishwar Udhav-rao Nagaraley proves that the Bank management wrongfully and illegally terminated his services from the Bank w.e.f. 18-3-1985 ?
- (2) Whether the Bank management proves that the said workman is deemed to have voluntarily retired from the Bank's services on 20-3-1985 ?
- (3) Whether the said workman is entitled to reinstatement in service ?
- (4) To what other reliefs, if any, he is entitled?
- (5) What Award ?

10. My findings on the said Issues are :—

- (1) No
- (2) Yes
- (3) No
- (4) Nil
- (5) As per award below.

## REASONS

ISSUES 1 to 4

11. The workman Shri I. U. Nagarale filed his affidavit in support of his case at Ex. 8/W and he was cross-examined on behalf of the Bank management. Shri V. B. Maniar, the then Branch Manager, It was Branch, Nagpur, and Shri M. P. Kamble, the then Branch Manager of Sadak Arjuni Branch filed their respective affidavit in support of the Bank's contentions at Ex. 10 M and 12/M, and both of them were cross examined on behalf of the workman. The workman deposed in support of his claim in his affidavit.

He further stated in his affidavit that the said two Managers of the Bank had forced him and induced him to withdraw the application for the conciliation proceedings and had induced him to accept the dues towards provident fund, gratuity etc. It is seen from his cross-examination that the workman had passed M.Com examination. As such he is not an illiterate person, but he is a highly qualified person. While he contended in his statement of claim that he had received the notice from the Bank dated 12-2-1985 asking him to report for duty within 30 days on 18-3-85, he admitted in his cross-examination that he had received that notice from the Bank on 18-2-1985, and he put his signature on the A.D. receipt in that respect. Thus, he had received that notice on 18-2-1985, and as per the evidence of the said two Branch Managers, the workman did not report for duty upto 18-3-1983 or thereafter. According to the workman, he reported for duty on 19-3-1985 but he was not allowed to resume his duty by the Bank management. Thus the statement of the workman has been clearly denied by the said two witnesses for the Bank management and they stated that the workman had never reported for duty after he received the notice on 18-2-1985. I believe the said evidence of the two Branch Managers of the Bank. It is the case of the workman that the said two officers forced him to withdraw the conciliation proceedings. However, he admitted in his cross-examination that he himself made the application regarding withdrawal of the conciliation proceedings to the Asstt. Labour Commissioner on 18-12-1985. Therefore his case that he was forced to withdraw that application, cannot be accepted. Both the said Bank witnesses stated in their evidence that the allegation of the workman that they forced or induced him to withdraw the application pending before the ALC(C), Nagpur and to accept the dues of provident fund and gratuity are false. The Bank witness Shri M. P. Kamble stated in his evidence that after the workman remained absent he did not receive any leave application by ordinary post from the workman, and that the workman never reported for duty on 19-3-1985. I see no reason to disbelieve the statements made by the Bank witnesses. I believe and accept the evidence of those two witnesses. Apart from the said oral evidence there is ample documentary evidence to show that the workman had abandoned the services and as such, voluntarily retired from the Bank's service, and that the Bank had not retrenched him from the service of the Bank.

12. Ex. 5 is a copy of the notice dated 12-2-1985 by the Branch Manager, Sadak Arjuni Branch to the workman. It was stated in that notice that the workman had remained absent without any intimation to the Bank from 11-8-1984 and he had not submitted

any request for leave. This notice further stated that the workman had never intimated to the Bank the reasons for his absence. By that notice the workman was asked to report for duty within 30 days from the receipt of the notice. It was further stated in that notice that in case he did not report for duty within the stipulated time or submit a satisfactory explanation to the Bank for his unauthorised absence, he would be deemed to have voluntarily retired from the service of the Bank from the date of expiry of the notice in terms of Clause XVI of the said Bipartite Settlement of 1984. Admittedly the said notice dated 12-2-1985 was received by the workman on 18-2-85. The workman did not, however, report for his duty at any time after he received that notice. I disbelieve the case and evidence of the workman that he reported for his duty on 19-3-1985 but he was not allowed to resume his duty. According to the Bank management the workman never reported for his duty, after he received that notice. Therefore the provisions of Clause XVI of the said Bipartite Settlement clearly applied to the facts of the present case and the Bank was justified in drawing the inference as above.

13. There is other evidence on record to conclude that the workman had abandoned his service, as noted above. The workman had filed the application before the ALC(C) on 27-9-1985 requesting that the conciliation proceedings be started. Accordingly, the conciliation proceedings were started. However on 18-12-1985 the workman himself filed an application (Ex. 14/M) before the ALC(C) Nagpur requesting that he may be allowed to withdraw his application from the conciliation proceedings. He further stated in that application that he undertook to submit to the Bank the necessary forms for the payment of his provident fund and gratuity dues. Exhibits 16 and 17 are the copies of forms regarding payment of provident fund etc. Col. 6 of this form states that the workman had voluntarily retired from service on 20-3-1985. Both these forms are admittedly bearing the signatures of the workman and he himself had filled in those two forms. However, according to the workman, the said Branch Managers had taken him to a hotel, and gave him tea etc. and had forced and induced to withdraw his application from the conciliation proceedings and to accept the necessary provident fund and gratuity dues etc. It may be noted that the said application dated 18-12-1985 (Ex. 14/M) regarding withdrawal of conciliation proceedings, is in the handwriting of the workman himself. It is in English and is bearing his signature. As noted above, he is educated upto M. Com. Therefore, the workman's case that he was forced and induced to withdraw his application from conciliation proceedings, cannot at all be accepted. I find that he himself, of his own accord,

filed that application. This shows that he had no intention to continue in the service of the Bank. He himself had abandoned his service since he remained absent from 11-8-1984. In case he had a desire to continue in service, he would not have filled in the said forms for the payment of his provident fund, gratuity dues etc. In his application dated 5-3-1985 (Ex. 18/M) the workman stated that he had voluntarily retired from his services and as such, requested the Bank to please arrange for the payment of his provident fund, and gratuity dues. It may be noted that even this application (Ex. 18/M) dated 5-3-85 is in the hand-writing of the workman himself and it is in English and is bearing the signature of the workman. Therefore, I believe the case of the Bank Management, and disbelieve the case of the workman. It is true that the workman again filed an application before the ALC(C), Nagpur requesting that conciliation proceedings be re-opened, and on his request the conciliation proceedings were re-opened and the ALC (C) sent the report regarding failure of conciliation proceedings to the Central Government. However, in view the said applications written by him in his own hand, and the filling in of the forms for the payment of provident fund, gratuity etc., no much importance can be given to the workman's subsequent application for the re-opening of the conciliation proceedings.

14. It is seen from the record placed before the ALC(C) Nagpur, and now produced before this Tribunal, that the Bank management had sent several letters to the workman regarding his absence during the years 1982 and 1983 and was being directed to resume his duty immediately, and to submit the medical certificate with the counter-signature of Civil Surgeon thereon. As such, it is quite clear that the workman was in the habit of remaining absent again and again since 1982. It is seen from the statement prepared by the Bank that the workman had remained absent and was on leave for 588 days from July 1983 to 20-1-1985. This clearly shows that the workman was not interested in the service, and as such, the conclusion arrived at by the Bank management that the workman himself had abandoned the service and was deemed to have voluntarily retired, is quite just and proper. This is not a case of retrenchment from service of the workman by the Bank. In the case between Botasahab Devgonda Patil and Managing Director, Shri Panchgonda Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., reported in 1988 Maharashtra Law Journal page 370,

the High Court of Bombay held that when an employed had remained absent for almost three years without any justification, and as such the employer had struck off the name from the muster roll, the inference of abandonment of service drawn by the management was just and proper, and as such the case did not attract the provisions Section 25F of the Industrial Disputes Act. In the result, Issue No. 1 is found in the negative, while Issue No. 2 is found in the affirmative. As such the workman is not entitled to reinstatement in service. Issue No. 3 is found in the negative. Therefore, he is entitled to no relief. Issue No. 4 is found accordingly.

#### ISSUE NO. 5

15. The following award is therefore passed.

#### AWARD

The action of the management of Dena Bank in relation to their Sadak Arjuni Branch in Distt. Bandara in retiring from service Shri Ishwar Udhavrao Nagarals w.e.f. 18-3-85 is justified :

The parties to bear their own costs of Reference.

P. D. APSHANKAR, Presiding Officer

[No. L-12012/40/86-D.II(A)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1991

का.पा 460--ज्ञान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार श्री अशोक कुमार मेघराज को भगवत आदेशों तक मुख्य ज्ञान निरीक्षक के अधीन ज्ञान निरीक्षक नियुक्त करती है।

[नं०. -12025/1/89-एम.-1 घाई एस एस 1]  
राम तिलक पाण्डेय, उप सचिव

New Delhi, the 25th January, 1991

S.O. 460.—In exercise by the powers conferred by sub-section (i) of Section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952) the Central Government hereby appoints Shri Ashok Kumar Meghraj as Inspector of Mines subordinate to the Chief Inspector of Mine, until further orders.

[No. A-12025/1/88-MI/ISH.1]

R. T. PANDEY, Dy. Secy.

**वित्त मंत्रालय**  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
(वैश्विक प्रभाग)

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 1990

का प्रा 461 — भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 53(2) के अनुसूचन में केन्द्रीय निदेशक बोर्ड ने, भारत सरकार को 30 जून 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज पर वार्षिक रिपोर्ट भेजी है जो नीचे उद्धृत की जाती है —

भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट  
वर्ष 1 जुलाई 1989 से जून 1990 तक  
भाग 1 आर्थिक स्थिति

**1 मुख्य बातें**

राजकोषीय वर्ष 1989-90 के दौरान, भारतीय ग्रहणवस्था ने वास्तविक सकल देशी उत्पाद में लगभग 4.5 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के साथ पर्याप्त अच्छे कार्य निष्पादन का हमारे वर्ष भी अनुभव किया। यह 1988-89 की 10.4 प्रतिशत की भारी वृद्धि से अधिक थी। तथापि, अनेक गंभीर स्थूल आर्थिक असंतुलन जो सर्वसाधारण अवधि में बने रहे, हे व्यापक बजट घाटे और भुगतान संतुलन के चालू खाते में घाटे तथा कीमतों पर पड़ने वाले दबाव। 1989-90 कृषि उत्पादन के सूचकांक के 1988-89 में 20.8 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि के बाद लगभग 1.5 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान था। खाद्यान्नों का उत्पादन 1989-90 में 172.7 मिलियन टन रहा जिसके पिछले वर्ष के 170.3 मिलियन टन के सर्वोच्च उत्पन्न से अधिक बढ़ जाने की आशा है। समीक्षाधीन वर्ष में अनेक मुख्य वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 1989-90 की ग्रहणवस्था औद्योगिक वृद्धि में प्रत्यक्ष गिरावट से हुई किन्तु वर्ष के समाप्त होते-होते इसमें पर्याप्त तेजी आ गई जिसके परिणामस्वरूप 8.3 प्रतिशत की समग्र वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष में हुई वृद्धि (8.7 प्रतिशत) की तुलना में थोड़ी ही कम थी। मध्यवर्ती वस्तुओं और उच्चोत्पादिकाओं माल उद्योगों की वृद्धि-दर को धक्का पट्टा जबकि पूर्वीगत माल और उपभोक्ता टिकाऊ माल उद्योगों में उल्लेखनीय सुधार दिखाई पड़ा। कई अन्य व्यापक आर्थिक सूचककों में 1989-90 में तेजी दिखाई पड़ी, संभवतः इसका आंशिक कारण यह था कि पिछले वर्ष की रिकार्ड वृद्धि से विनोदित लाभ हुआ। इस प्रकार, देशी अर्थ की दृष्टि में पर्याप्त सुधार परिलक्षित हुआ और यह 1988-89 के सकल देशी उत्पाद के 20.8 प्रतिशत से बढ़कर 1989-90 में 21.4 प्रतिशत हो गई। कुछ इसके कारण और कुछ विदेशी संसाधनों के प्रवाह का स्तर काफी बढ़ जाने से देशी निवेश की दर, पिछले वर्ष (23.8 प्रतिशत) की तुलना में इस वर्ष 23.9 प्रतिशत के स्तर से थोड़ी-सी अधिक रही। निरंतर निवेश क घटना पूंजीगत माल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि और उनके आयात में वृद्धि तथा 1989 के दोषाव निजी निवेशन कारबार क्षेत्र द्वारा किये गये अनुमानित पूंजीगत धन में स्पष्ट वृद्धि की पुष्टि करती है। 1989-90 के दौरान प्राथमिक और पूंजी गत गौण बजारों में सतत विकास की विशिष्ट घटना थी। इससे अनायास अन्य उल्लेखनीय कार्य-निष्पादन या लगातार बार वर्ष तक निर्यात वृद्धि में भारी तेजी। वाणिज्य व्यापार के आंकड़े बताते हैं कि

जहाँ रुपये के रूप में निर्यात 36.3 प्रतिशत (विशेष आह्वान अधिक के रूप में 22.9 प्रतिशत) तक बढ़ा वहीं निर्यात में 25.6 प्रतिशत (विशेष आह्वान अधिक के रूप में 13.2 प्रतिशत) तक की बढ़ोतरी हुई। अनुमान है कि सकल देशी उत्पाद के चालू खाते के घाटे का अनुपात 1988-89 के 2.7 प्रतिशत से घटकर 1989-90 में 2.3 प्रतिशत हो सकता है। थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रास्फीति दर 1988-89 के 5.7 प्रतिशत से घटकर 1989-90 में 9.1 प्रतिशत हो गई और अनेक कारण से जैसे क्षेत्रीय आपूर्ति-मांग में असंतुलन, अतिरिक्त बजटीय महसूस आयात में लागत में वृद्धि, कोमल-वृद्धि और सामान्य कीमतों में गयी तथा राजकोषीय असंतुलन के कारण अधिक बलनिधि निरंतर जमा होती रहती है। केन्द्रीय सरकार के वित्त पर पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा तीव्र दबाव बढ़ा जो मूल बजट अनुमान के अत्यधिक पारंपरिक घाटे से प्रदर्शित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार केन्द्र का बजट घाटा 1988-89 के 7,337 करोड़ रुपये के बजट आंकड़ों अथवा वास्तविक 5,810 करोड़ रुपये के मुकाबले 1989-90 में 10,624 करोड़ रुपये रहा। इसी प्रकार केन्द्र सरकार को निवल रिजर्व बैंक का ऋण 13,813 करोड़ रुपये अर्थात् 1988-89 के 6,503 करोड़ रुपये के वास्तविक ऋण के तुलने से भी अधिक था। वर्ष 1989-90 में समग्र बलनिधि (एम 3) में 19.9 प्रतिशत की वृद्धि की दर पिछले वर्ष के 18.1 प्रतिशत की तुलना में उल्लेखनीय रूप में अधिक थी। एम 1 के अनुसार मौद्रिक विस्तार की गति 1988-89 के 15.2 प्रतिशत के मुकाबले 1989-90 में 22.5 प्रतिशत थी। ऐसी स्थिति में अभिप्रायी मुद्रागत नीति की बिना यही रही है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि समाव्यता की हानि पहुँचाये बिना मुद्रास्फीति दबावों को रोका जाये। विशेष रूप से खाद्येतर ऋण में विस्तार को सतत करने की आवश्यकता थी। चकि नकदी प्रारक्षित अनुपात के संबंध में सांविधिक उच्चतम सीमा पहले ही प्राप्त की जा चुकी थी, अतः अन्य उपायों पर अधिक निर्भर रहना पड़ा। इन उपायों में निर्यात पुनर्वित्त सुविधा की प्राप्त में कटौती, सांविधिक बलनिधि अनुपात में वृद्धि और वृद्धिगत खाद्येतर ऋण जमा अनुपात की व्यवस्था करना शामिल है। यदि इसमें वृद्धि होती है तो रिजर्व बैंक में पुनर्वित्त पर अतिरिक्त लागत का भार पड़ना है।

**2 रास्ट्रीय आय, बचत और निवेश**

**वृद्धि का रूपरेखा**

2.1 1980-81 के मन्थों पर आधारित सकल देशी उत्पाद (मादेउ) की वृद्धि दर, 1988-89 में प्राप्त 10.4 प्रतिशत (सारणी 2.1) की सर्वोच्च वृद्धि के बाद लगभग 5.0 प्रतिशत पर होने का अनुमान है। 1989-90 में वृद्धि दर में गिरावट 1988-89 में प्राप्त उच्च स्तर पर कृषि जन्य सकल देशी उत्पाद में मासूची वृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में कमी परवर्धित करनी है। मातृवी पञ्चवर्षीय योजना के विमाही वर्ष की वृद्धि की की रेखा के साथ योजना अवधि (1985-86 से 1989-90) की प्राप्त वृद्धि दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के योजना लक्ष्य के मुकाबले लगभग 5.7 प्रतिशत होती है। इसके अलावा, मनी व्यापक क्षेत्र, यथा कृषि विनिर्माण और विद्युत् तथा सेवाओं ने योजना में परिकल्पित की तुलना में अतिरिक्त अधिक उच्चतर देने प्राप्त की।

**सारणी 2.1 वास्तविक सकल देशी उत्पाद में वृद्धि**

क्षेत्र	प्रतिशत वृद्धि (आन्तरिक सकल देशी उत्पाद में)			अन्तर्वृद्धि वृद्धि दर		वृद्धि दर (प्रतिशत)			
	1970-71	1980-81	1988-89	1970-71	1980-81	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
				से	से				स्वरित अनुमान
				1980-81*	1988-89				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. कृषि और संबन्ध									
गतिविधियाँ	14.5	38.0	53.0	1.8	2.7	+0.3	-1.7	+0.5	+17.4
(क) कृषि	39.7	34.7	31.0	2.0	2.9	+0.3	-1.7	+0.7	+18.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. उद्योग	18.6	20.9	24.5	4.8	7.7	+7.7	+8.3	+6.2	+8.3
(क) विनिर्माण	16.1	17.7	20.6	4.6	7.6	+7.8	+7.6	+6.0	+8.2
3. सेवाएं	31.9	36.1	38.3	4.6	6.4	+7.8	+7.0	+6.1	+6.9
कुल सकल देशी उत्पाद@@	100.0	100.0	100.0	3.4	5.2	+4.9	+4.2	+4.1	+10.4

\*यह अर्ध लघुगणकीय (सेमी-नो-गरिकमिक) प्रवृत्तियों पर आधारित है।

@इसमें निर्माण शामिल है।

वर्ष 1970-71 का वास्तविक सकल देशी उत्पाद का क्षेत्रीय बर्गीकरण 1980-81 के मूल्यों पर आधारित है और इस लिए यह पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट (1988-89) में दिये गये 1970-71 के मूल्यों से भिन्न है।

#### बचत और निवेश की प्रवृत्तियां

2.2 परिणामित अनुमान बताते हैं कि बालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद में कुल घरेलू बचत का अनुपात 1987-88 के 19.3 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 1988-89 में 20.8 प्रतिशत हो गया: 1989-90 के अनुमानित अनुमान बताते हैं कि बचत अनुपात के 21.4 प्रतिशत (सारणी 2.2) तक बढ़ाने की आशा है। इसके साथ, सातवीं योजना के दौरान औसत कुल बचत की दर कुल मिलाकर 20.2 प्रतिशत होती है।

2.3 मुद्रा के रूप में 1989-90 के दौरान विदेशी संसाधनों (अनुमानों सहित) के निवल प्रवाह के पिछले वर्ष की तुलना में कम होने की

आशा है सकल देशी उत्पाद की तुलना में ऐसे प्रवाह का अनुपात जो 1987-88 में 2.3 प्रतिशत और 1988-89 में 3.0 प्रतिशत था, 1989-90 में 2.5 प्रतिशत होने की संभावना है। इस पर भी, समग्र घरेलू बचत दर में मुद्रा के साथ सकल देशी उत्पाद में कुल सकल घरेलू बचत का अनुपात 1988-89 के 23.8 प्रतिशत से आंशिक रूप में बढ़कर 1989-90 में 23.9 प्रतिशत होने की आशा है। (ग्राफ "घ" की देखें) सातवीं योजना अवधि में निवेश की दर 1981-82 के दौरान 20.1 प्रतिशत थी, 1989-90 में 3.9 प्रतिशत बढ़ाकर 23.9 प्रतिशत कर दी गई है और योजना अवधि की औसत दर 22.8 प्रतिशत रखी गई है।

सारणी 2.2 : देशी बचत के अनुमान और निवेश अनुपात

(प्रतिशत में)

क्षेत्र/राजकीय वर्ष	वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल बचत और निवेश			वर्तमान बाजार मूल्यों पर शुद्ध देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शुद्ध बचत और निवेश		
	1987-88	1988-89 (अनुमानित)	1989-90 (प्रारंभिक अनुमान)	1987-88	1988-89 (अनुमानित)	1989-90 (प्रारंभिक अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7
1. घरेलू क्षेत्र की बचत : जिनमें से:	15.7	17.3	18.0	12.9	14.8	15.3
वित्तीय परिसंपत्ति में बचत*	8.0	7.6	9.3	8.9	8.5	10.3
2. सार्वजनिक क्षेत्र	2.1	1.6	1.6	—2.7	—3.2	—3.2
3. घरेलू निजी कंपनी क्षेत्र	1.5	1.9	1.8	0.05	0.3	0.3
4. जोड़ें: घरेलू बचत (1+2+3)	19.3	20.8	21.4	10.2	11.9	12.4
5. विदेशी संसाधन की शुद्ध आवश्यक	2.3	3.0	2.5	2.6	3.3	2.8
6. कुल निवेश (4+5) वर्तमान बाजार मूल्यों पर	21.6	23.8	23.9	12.8	15.2	15.2
घ. वे. उ. नि. दे. उ. (करोड़ रुपये)	3,32,553	3,91,158	4,42,769	2,98,677	3,51,703	3,97,540

\*इन्हें वित्तीय वेयताओं के लिए समायोजित किया गया है। चूंकि वित्तीय प्रवृत्तियों में बचत में अचल आस्तियों के लिए पूंजीगत उपयोग शामिल नहीं है, इसलिए विदेशी संसाधन की शुद्ध आवश्यक की तरह शुद्ध अनुपात सकल अनुपातों से अधिक है।

टिप्पणी: 1987-88 तथा 1988-89 के अनुपात उन अनुपातों से भिन्न हैं जो बैंक के पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में दिये गये हैं और 1988-89 के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन त्वरित अनुमानों और भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 1989-90 में भी प्रकाशित हुए हैं, क्योंकि नये आंकड़ों उपलब्ध होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय के अनुमानों और बचत तथा निवेश के अनुमानों में संशोधन किया गया। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपने 1989-90 के त्वरित अनुमान प्रकाशित करने पर इन अनुमानों में और संशोधन होंगे।

सारणी 2.3: सकल वित्तीय धास्तियों में वरेलू क्षेत्र की वचन :

योजना में दर्शाये गये वरीरधास्तविक धाकड़े

सद	छठी योजना अवधि (1980-81 से 1984-85)					सातवी योजना अवधि (1985-86 से 1989-90)			
	योजना में दर्शाये गये (1979-80 के मूल्यों पर प्राधा- रित)	वास्तविक धाकड़े	योजना में दर्शाये गये (1984-85 के मूल्यों पर प्राधा- रित)	वास्तविक धाकड़े					
	राशि (करोड़ रुपये)	कुल सकल वित्तीय धास्तियों के प्रतिशत के रूप में	कुल सकल वित्तीय धा- स्तियों के प्रति- शत के रूप में	वालू बाजार मूल्यों के प्राधार पर रकत दर्शा उत्पाद के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रुपये)	कुल सकल वित्तीय धास्तियों के प्रतिशत पर	कुल सकल वित्तीय धा- स्तियों के प्रति- शत पर	वालू बाजार मूल्यों के प्राधार पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत पर	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. मौद्रिक धास्तियां		36,014	59.0	53.9	5.0	50,815	48.8	51.8	9.4
1) मुद्रा		4,734	7.8	11.9	1.1	8,527	6.3	11.6	1.1
2) जमा राशियां (घनसूचक बाणिज्य बैंक और सहकारी समितियां)		31,280	51.2	42.0	3.9	57,288	42.5	40.2	4.2
2. संविदागत वचन		21,225	34.8	24.5	2.2	44,520	33.1	25.1	2.6
1) जीवन बीमा निधि		5,577	9.1	7.4	0.7	9,845	7.3	7.6	0.8
2) भविष्य और पेंशन निधि		15,648	25.7	17.1	1.5	34,675	25.8	17.5	1.8
3. शेयर, यूनिट और कंपनी जमा राशियां		2,550	4.2	9.3	0.9	14,003	10.4	11.3	1.2
1) गैर बैंकिंग कंपनी जमा राशियां		1,150	1.9	4.8	0.5	8,592	6.4	3.8	0.4
2) निगमित/सहकारी शेयर और डिबेंचर		1,400	2.3	3.4	0.3	2,911	2.2	4.3	0.5
3) भारतीय यूनिट ट्रस्ट		--	--	1.1	0.1	2,500	1.8	3.2	0.3
4. सरकार पर निवल दावे		1,245	2.0	10.1	0.9	8,750	6.5	11.7	1.2
5. अन्य धास्तियां		--	--	2.2	0.2	1,593	1.2	0.3	0.1
6. कुल सकल वित्तीय धास्तियां (1 से 5)		61,034	100.0	100.0	9.2	1,34,681	100.0	100.0	10.5
7. वित्तीय व्ययताएं		11,303	18.5	26.7	2.5	32,428	24.1	24.6	2.3
8. निवल वित्तीय धास्तियां		49,731	81.5	73.3	6.7	1,02,253	75.9	75.4	8.0

@ ये प्रतिशत अलग-अलग वर्षों के ऐसे प्रतिशतों के साधारण औसत हैं। योजना के पांच वर्षों के पूर्ण धाकड़े नहीं जोड़े गये हैं क्योंकि ये वालू (घराना संबंधित वर्ष के) मूल्यों पर प्राधारित हैं। धास्तियों के बीच संबंधित परिवर्तन मूल्यों के बदलते प्रभाव के कारण हो सकता है, इस पर प्रभाव में विचार-विमर्श नहीं किया गया है।

2.4 क्षेत्रवार, 1989-90 में सकल देशी बचत में सुधार पूर्णतया घरेलू बचत, सरकारी क्षेत्र की बचत की दर के पिछले वर्ष के स्तर पर बने रहने के अनुमान और निजी कम्पनी क्षेत्र के मामूली रूप से नीचे जाने के कारण हुआ। इन दो क्षेत्रों का अनुमतीयजनक बचत निष्पादन उनकी भौतिक क्षास्तियों के मूल्यांकन के लिए की गई व्यवस्था के बाद उनकी निवल बचत में बेहतर रूप से दिखाई पड़ता है। इस प्रकार, सरकारी क्षेत्र ने 1988-89 और 1989-90 प्रत्येक सकल देशी उत्पाद का 3.2 प्रतिशत तक निवल बचत प्रदर्शित किया और निजी कम्पनी क्षेत्र ने उपर्युक्त दोनों वर्षों में प्रत्येक से 0.3 प्रतिशत की न्यून दर प्रदर्शित की। पिछले दो वर्षों के दौरान, निजी कम्पनी क्षेत्र की सामान्य लाभप्रवता और प्रतिधारित आमदनी 1987-88 की उनकी स्थिति की तुलना में बेहतर रही है जबकि इस क्षेत्र की निवल बचतों के नकारात्मक रहने का अनुमान था।

#### वित्तीय परिसंपत्तियों में बचत

2.5 वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में घरेलू बचत में 1989-90 के दौरान सकल वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि के अनुमानों के साथ निरपेक्ष सम्बन्ध तथा सकल देशी उत्पाद दोनों के संबंध में भारी उछाल दिखाते हुए मजबूतपूर्ण वृद्धि दिखाई पड़ी। सकल देशी उत्पाद की तुलना में ऐसी सकल वित्तीय बचत का अनुपात, जो पिछले तीन वर्षों के दौरान 10.4 प्रतिशत के आस-पास ही था 1989-90 में बढ़कर 11.6 प्रतिशत हो गया। इसके अतिरिक्त, सकल देशी उत्पाद की अपेक्षा वित्तीय वेयनाओं के अनुपात में गिरावट के कारण घरेलू क्षेत्र की निवल वित्तीय बचत दर में 1988-89 के 7.6 प्रतिशत के मुकाबले 1989-90 में 9.3 प्रतिशत की ज्यादा आनुपातिक वृद्धि दिखाई पड़ी।

#### आस्तियों का गठन

2.6 जहाँ तक घरेलू बचत में धन-धन वितीय आस्तियों के संघटन का प्रश्न है, 1989-90 की प्रबुद्धि मौद्रिक आस्तियों (मुद्रा और बैंक जमा राशियाँ) के रूप में उस बचत की मध्यावधि प्रवृत्ति से थोड़ी भिन्न थी क्योंकि वृद्धिशील सकल वित्तीय आस्तियों तथा सकल देशी उत्पाद के अनुपात में वृद्धि परिलक्षित हुई है। सकल देशी उत्पाद के अनुपात की तुलना में मुद्रा का अनुपात 1988-89 के 1.1 प्रतिशत से बढ़कर 1989-90 में 1.7 प्रतिशत हो गया और सकल देशी उत्पाद के अनुपात की तुलना में बैंक जमा राशियाँ 3.9 प्रतिशत से बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो गई। सकल वित्तीय आस्तियों की तुलना में मुद्रा और बैंक जमा राशियों का हिस्सा 1988-89 के 48.2 प्रतिशत के मुकाबले 1989-90 में 53.2 प्रतिशत रहने की आशा है। सकल देशी उत्पाद की तुलना में सरकार पर दावे की राशियों का अनुपात 1987-88 के 1.1 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 1988-89 में 1.4 प्रतिशत हो गया, किन्तु 1989-90 में इसके 1.2 प्रतिशत तक घटने की संभावना है। मविभाग बचतों (जीवन बीमा और भविष्य पेंशन निधियाँ) का अनुपात 1989-90 के दौरान 2.8 प्रतिशत है जिसके पिछले वर्ष के स्तर 1988-89 में 2.8 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है, यद्यपि सकल वित्तीय आस्तियों में इनका हिस्सा 1988-89 के दौरान 26.5 प्रतिशत से घटकर 1989-90 में 24.8 प्रतिशत रह गया। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों और निजी कम्पनी क्षेत्र के शेयरों/डिविडेंडों के लिये बढ़ते हुए घरेलू अधिमानी के कारण सकल वित्तीय आस्तियों में इनका प्रतिशत हिस्सा 1987-88 के 5.9 प्रतिशत से बढ़कर 1988-89 में 7.1 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है और 1989-90 में इसके और अधिक बढ़कर 8.0 प्रतिशत होने की आशा है। सकल देशी उत्पाद के अनुपात के रूप में, इन लिखतों की बचत राशियाँ 1987-88 के 0.7 प्रतिशत से आंशिक रूप से बढ़कर 1989-90 में 0.8 प्रतिशत और पुनः बढ़कर 1988-89 में 0.9 प्रतिशत हो गई।

#### मध्यावधि में परिवर्तनशील ऋणा

2.7 बदलते हुए घरेलू अधिमानी को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिये सारणी 2.3 छठी और सातवीं योजना अवधियों के लिये योजना में वर्गीय गयी राशियों और वास्तविक आंकड़ों के अनुसार सकल वित्तीय बचत का ऋणा प्रस्तुत करती है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि (i) प्रत्याशित मौद्रिकीकरण की अपेक्षा अधिक मौद्रिकीकरण होने से अधिक मुद्रा कम शेयर बढ़ा (ii) बैंक जमा राशियों का हिस्सा योजना में वर्गीय गये की अपेक्षा कम है क्योंकि अन्य वित्तीय लिखतें अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक हैं, और (iii) वास्तविक अधिमानी में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई पड़ता है जो छठी और सातवीं योजना दोनों में वर्गीय गयी राशियों में प्रत्याशित नहीं था, यह परिवर्तन कम्पनी शेयरों और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों और लघु बचत माध्यम के पक्ष से था जो बैंक जमा राशियों की तुलना में उन्मुखनीय रूप से उच्चतर प्राय वेता था और जिसे बेहतर राजकोषीय सुविधा प्राप्त थी

#### 3 कृषि उत्पादन

3.1 1988-89 में अत्यधिक अच्छे कार्यानिष्पादन के बाद 1989-90 में कृषि उत्पादन के 1.5 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। इसकी कम वृद्धि भी कृषि के जोरदार उत्पादन कार्यक्रमों (1989-90 में उर्वरक के प्रयोग में 10.5 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि प्रमुख निविष्टियों के उपयोग में महत्वपूर्ण वृद्धि से प्रमाणित) के बेहतर तंग लागू करने के कारण सम्भव हुआ है। मोटे अनाज के उत्पादन में लगातार दूसरे वर्ष उन्मुखनीय सुधार हुआ है जिससे शुष्क और असिंचित क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लघु और सीमांत किसानों को लाभ के विस्तार का पता चलता है। तथापि, दालों का उत्पादन पिछले वर्ष के स्तर पर ही रहा। निलहन के अलावा बाणिज्यिक फसलों में भी 1989-90 में पर्याप्त वृद्धि होने का अनुमान है।

#### मानसून की स्थिति

3.2 1989-90 में, दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्यतया अच्छा था। 80 प्रतिशत से ऊपर अर्थात् 35 भीमसी उप खण्डों में से 20 उपखण्डों में सामान्य या अधिक वर्षा हुई और शेष छह में से पाँच उपखण्डों में सामान्य से थोड़ी कम वर्षा हुई। ये उपखण्ड देश के भू-क्षेत्र का 95 प्रतिशत से भी अधिक हैं। कुछ सुखाग्रस्त क्षेत्रों जैसे कर्नाटक के भीतरी क्षेत्रों रायचसीमा और गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ भागों में अच्छी वर्षा हुई। इसके अतिरिक्त वायुमंडल क्षेत्रों जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर-पूर्व भारत के राज्य भारी बाढ़ से मुक्त रहे। तथापि, वर्षा समय पर और समान रूप से नहीं हुई। पूर्वी राजस्थान के भागों दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मध्यावर्ती भागों, बिन्लो और उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश ने मानसून में कमी महसूस की। इसी प्रकार अक्टूबर-दिसम्बर 1989 के दौरान सीसमी वर्षा रही की फसल उगाने वाले प्रमुख राज्यों में कम हुई।

#### समग्र कृषि उत्पादन

3.3 1989-90 के कृषि उत्पादन में 1988-89 के 20.8 प्रतिशत की चिकाई वृद्धि से 1.5 प्रतिशत की मामूली वृद्धि होने का अनुमान है। दो खराब वर्ष के बावजूद, सातवीं योजना अवधि के कृषि उत्पादन की औसत वृद्धि दर 4.0 प्रतिशत प्रति वर्ष के योजना लक्ष्य के निकट है। फिर भी योजना अवधि के दौरान कृषि में वृद्धि को विशेष पर्याप्त उतार-चढ़ाव और फसल असन्तुलनों का सामना करना होगा।

#### खाद्यान्न उत्पादन

3.4 1989-90 के दौरान कुल खाद्यान्नों का उत्पादन 172.7 मिलियन टन होने का अनुमान है, इस प्रकार यह 1988-89 में प्राप्त



170.3 मिलियन टन के शिखर उत्पादन से 1.4 प्रतिशत से अधिक है। खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन 100 मिलियन टन रहा अर्थात् यह 1988-89 के 96.5 मिलियन टन के उत्पादन से 3.0 प्रतिशत अधिक है जबकि रबी खाद्यान्नों का उत्पादन 72.7 मिलियन टन रहा जो पिछले वर्ष (सारणी 3.1) के 73.8 मिलियन टन से 1.5 प्रतिशत कम है। सातवीं योजना के अंतिम वर्ष 1989-90 के लिये

178 से 183 मिलियन टन के बीच खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान था जिसे बाद में योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में निम्नगामी संशोधन करके 173.2 से 175.2 मिलियन टन कर दिया गया। 1989-90 की वार्षिक योजना में 1989-90 का लक्ष्य संशोधित करके 175 मिलियन टन कर दिया गया।

सारणी 3.1: खाद्यान्नों का उत्पादन

(मिलियन टन)

वर्ष	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90 (अनुमान)
	1	2	3	4	5	7
<b>सभी खाद्यान्न</b>	145.5	150.4	143.4	140.4	170.3	172.7
धान	58.3	63.8	60.6	58.8	70.7	72.8
गेहूँ	44.1	47.1	44.3	46.2	54.0	52.5
मोटे अनाज	31.1	26.2	26.8	26.4	51.9	34.0
दालें	12.0	13.3	11.7	11.0	13.7	13.4
खरीफ	84.5	85.2	80.2	74.6	96.5	100.0
चावल	53.8	59.4	53.6	49.0	63.9	65.6
मोटे अनाज	25.9	21.3	22.4	21.2	27.0	28.8
दालें	4.8	4.5	4.2	4.4	5.6	5.6
रबी	61.0	65.2	63.2	65.8	73.8	72.7
धान	4.5	4.4	7.0	7.8	6.8	7.2
गेहूँ	44.1	47.1	44.3	46.2	54.0	52.5
मोटे अनाज	5.2	4.0	4.4	5.2	4.9	5.2
दालें	7.2	8.8	7.5	6.6	8.1	7.8

स्रोत: कृषि मंत्रालय

3.5 फसलवार, 1989-90, में चावल का उत्पादन 72.8 मिलियन टन रहा जो पिछले वर्ष के 70.7 मिलियन टन के शिखर उत्पादन से अधिक था जबकि गेहूँ का उत्पादन 52.5 मिलियन टन रहा जो पिछले वर्ष के 54.0 मिलियन टन के शिखर उत्पादन से कम था। खरीफ और रबी दोनों फसलों में चावल के उत्पादन में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अनुकूल वर्षा और सिंचाई के जलाशयों में संतोषजनक स्तर तक जलसंचय तथा चावल उगाने वाले इलाकों में भू-जल बढ़ने के कारण पिछले वर्ष से अधिक उत्पादन हुआ। गेहूँ का उत्पादन वर्षा के अत्यंतोच्चजनक इंत से क्षतिग्रस्त और प्रमुख गेहूँ उगानेवाले क्षेत्रों में धारिता की कमी के कारण कम रहा। पिछले वर्ष की तरह, मोटे अनाजों के उत्पादन में और उल्लेखनीय वृद्धि हुई और 1983-84 में प्राप्त 33.9 मिलियन टन का शिखर स्तर पार कर गया। इस प्रकार मोटे अनाजों का उत्पादन 1987-88 के 26.4 मिलियन टन के उत्पादन से काफी बढ़कर 1988-89 में 31.9 मिलियन टन (20.8 प्रतिशत) हो गया तथा 1989-90 में और बढ़कर 34.0 मिलियन टन (6.6 प्रतिशत) हो गया। दूधरी और, दालों का उत्पादन जो 1988-89 में 13.7 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच चुका था, 1989-90 में थोड़ा सा घटकर 13.4 मिलियन टन (2.2 प्रतिशत) हो गया। यह गिरावट रबी का उत्पादन कम होने के कारण थी। यह 7.8 मिलियन टन ही जोकि पिछले वर्ष के 8.1 मिलियन टन की तुलना में 3.7 प्रतिशत कम थी, दालों का खरीफ का उत्पादन पिछले वर्ष के 5.6 मिलियन टन के स्तर पर बना रहा।

## खाद्यान्न उत्पादन का क्षेत्रीय अंतर

3.6 खाद्यान्नों के उत्पादन में क्षेत्रीय सुधार का अंतर, कुछ सीमा तक उल्लेखनीय होते हुए भी अभी धीमा है। पंजाब में खाद्यान्न उत्पादन की वार्षिक औसत वृद्धि दर पहले चार वर्षों में छोटी योजना अवधि के दौरान लगभग 7 प्रतिशत वार्षिक के मुकाबले 1.5 प्रतिशत वार्षिक रही। सातवीं योजना अवधि के पहले चार वर्षों के दौरान हरियाणा और उत्तर प्रदेश की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 8.5 प्रतिशत और 4.6 प्रतिशत रही। विशिष्ट बात यह रही कि छोटी और सातवीं दोनों योजना अवधियों के दौरान असम के पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा राजस्थान और मध्यप्रदेश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके विपरीत, दोनों योजना अवधियों के दौरान चार दक्षिणी राज्यों यथा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में खाद्यान्नों का उत्पादन स्तर लगभग ज्यों का त्यों रहा या उनमें निरपेक्ष कमी आई थी, कुछ सीमा तक पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र और गुजरात के मामले में भी यही स्थिति रही।

3.7 पिछले दशक में, तीन उत्तरी राज्यों (पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश) का हिस्सा देश के कुल खाद्यान्नों के उत्पादन में लगातार बढ़ा है। हाल के वर्षों में चार पूर्वी राज्यों के हिस्सों में भी कुछ वृद्धि दिखाई पड़ी है। सभी ने अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि दर प्राप्त की है। राजस्थान और मध्य प्रदेश उत्पादन की अपनी पूर्ण प्रगति नहीं बनाये रख सके। पश्चिमी

क्षेत्र में गुजरात और महाराष्ट्र तथा चार दक्षिणी राज्यों ने कुल खाद्यान्नों के उत्पादन के अपने अनुपात में एक सामान और प्रत्यक्ष कमी पायी (सारणी 3.2)

### सारणी 3.1 : खाद्यान्न उत्पादन का क्षेत्रवार वितरण

(प्रतिशत)

क्षेत्र	क्षेत्रवार खाद्यान्नों के प्रशिक्षित भारतीय उत्पादन का वितरण (तीनवर्षों के औसत)				
	1970-71 से 1972-73	1977-78 से 1979-80	1982-83 से 1984-85	1986-87 से 1988-89	
	1	2	3	4	5
1. उत्तरी राज्य (पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश)	29.5	30.3	25.2	37.1	
2. पूर्वी राज्य (उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम)	22.3	19.8	18.0	19.8	
3. राजस्थान और मध्य प्रदेश	17.2	14.1	15.9	14.6	
4. पश्चिमी राज्य (गुजरात और महाराष्ट्र)	7.9	11.7	10.6	8.6	
5. दक्षिणी राज्य (द्राघ प्रदेश तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल)	20.3	21.3	17.4	17.2	
6. अन्य राज्य/संघराज्य	2.8	2.8	2.9	2.7	
जोड़	100.0	100.0	100.0	100.0	

### प्रनिवार्य वस्तुओं की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता

3.8 1980 के दशक में सामान्य उपयोग की कतिपय वस्तुओं, जैसे अनाज, चीनी और चाय तथा पशुधन उत्पादों (दूध और अंडे) और मछली की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता में सुधार हुआ है। जैसा कि सारणी 3.3 में बताया गया है, अनाजों की प्रतिव्यक्ति दैनिक उपलब्धता 1980-81 में 416 ग्राम से बढ़कर 1988-89 में 456 ग्राम हो गई यद्यपि मुख्यतः जनसंख्या में वृद्धि और अधिक स्टॉक जमा होने के कारण 1989-90 में

बढ़कर यह 435 ग्राम रह गया। चीनी के मामले में प्रतिव्यक्ति दैनिक उपलब्धता 7.2 किलोग्राम से बढ़कर 13.5 किलोग्राम हो गई। इसी अवधि के दौरान चासी की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता में पर्याप्त उतार-चढ़ाव दिखाई पड़ा और इसमें 38 ग्राम से 39 ग्राम तक की केवल मामूली सी वृद्धि हुई। खाद्य तेलों और वनस्पति की प्रतिव्यक्ति दैनिक उपलब्धता 1980-81 के 5 किलोग्राम से बढ़कर उसके बाद 6 से 7 किलोग्राम हो गई। साथ ही अनाजों और कुछ सीमा तक अन्य वस्तुओं की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि के बावजूद जनसंख्या का बढ़ा भाग इन आवश्यक वस्तुओं का उपयोग भारतीय बिक्रिस्ता अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम पोषक आवश्यकताओं से कम करता है। उपयोग में इनकी अत्यधिक कमी अनेक अन्य पोषकीय अपेक्षाओं के मामले में भी मही है, जैसे दूध, सब्जियां तथा फल। अन्तर्व्यक्तिक असमानताओं से उत्पन्न उपयोग में कमी के अलावा, उत्पादन के विप्लव में अन्तर्देशीय असमानता-उन क्षेत्रों में ऐसी कमियों के लिए जिम्मेदार रही है जहां उत्पादन और प्राय के स्तरों तथा प्रभावी खय शक्ति में कमी पाई गई है।

### सरकारी खरीद

3.9 भरपूर फलन के बावजूद निजी व्यापार और मिन मागिकों द्वारा अत्यधिक खरीद के कारण जहां 1988-89 में सरकारी खरीद में कमी आई थी, वहीं उसमें 1989-90 में दूसरी बार लगातार अच्छी फसल के कारण तेजी आ गई। सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की कुल सरकारी खरीद 20.3 मिलियन टन पिछले वर्ष की तुलना में राजकोषीय वर्ष 1989-90 में काफी अधिक थी इसमें अन्य बातों के साथ-साथ खरीद में वृद्धि खेतिहोने की दिव्य गये समर्थित मूल्य, खुला बाजार में खाद्यान्नों की आसानी से उपलब्धता और सरकारी एजेंसीज द्वारा सीधे खरीद से सहायता मिली। चावल की सरकारी खरीद सर्वाधिक 11.3 मिलियन टन रही (सारणी 3.4) 1989-90 में गेहूं की सरकारी खरीद 9.0 मिलियन टन रही जो पिछले वर्ष के 6.5 मिलियन टन की तुलना में अधिक थी किन्तु 1985-86 और 1986-87 की सरकारी खरीद से कम थी। चावल की कुल सरकारी खरीद का सबसे अधिक हिस्सा पंजाब (44 प्रतिशत) और इसके बाद द्राघ प्रदेश (19 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (13 प्रतिशत), हरियाणा (9 प्रतिशत) और तमिलनाडु (8 प्रतिशत) का था। गेहूं के मामले में भी कुल सरकारी खरीद का सबसे अधिक हिस्सा पंजाब (62 प्रतिशत) और इसके बाद हरियाणा (22 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (15 प्रतिशत) का था। मार्च 1990 के विपणन मौसम के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद के नई ऊंचाई पर पहुंचने की आशा है। 30 जून 1990 तक, गेहूं की सरकारी खरीद कुल 11.0 मिलियन टन रही जबकि 1989 विपणन के पूरे मौसम के दौरान गेहूं की कुल सरकारी खरीद 9.0 मिलियन टन थी।

### सारणी 3.3 उपयोग की कतिपय महत्वपूर्ण वस्तुओं की

प्रति व्यक्ति उपलब्धता

वर्ष	अनाज @ (ग्राम प्रतिदिन)	चासी @ (ग्राम प्रतिदिन)	कुस @ (ग्राम प्रतिदिन)	खाद्य तेल वनस्पति समेत (किलो- ग्राम प्रतिवर्ष)	चीनी + (किलोग्राम प्रतिवर्ष)	चाय (ग्राम प्रतिवर्ष)	सूती वस्त्र (मीटर)	मानव निर्मित रेसो (मीटर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1960-61	399.7	69.0	468.7	4.0	4.7	287	13.8	1.2
1970-71	417.6	51.2	468.8	4.5	7.3	387	13.6	2.0
1980-81	416.2	37.5	453.7	5.0	7.2	487	11.0	3.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1983-84 (अनंतिम)	436.1	41.8	477.9	7.0	10.3	399	10.8	4.0
1984-85 (अनंतिम)	415.6	38.1	453.7	6.8	10.5	422	10.6	3.9
1985-86 (अनंतिम)	434.2	41.9	476.1	6.3	10.9	426	10.8	4.0
1986-87 (अनंतिम)	436.1	35.9	472.0	6.2	11.2	420	10.6	4.4
1987-88 (अनंतिम)	413.6	33.0	446.6	7.0	11.7	595*	10.5	4.2
1988-89 (अनंतिम)	456.1	40.5	496.6	6.5	12.2	601*	10.1	4.5
1989-90 (अनुमानित)	434.6	38.9	473.5	5.6	13.3*	568*	—	—

ज्ञापन मध्य  
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  
द्वारा आहार मानदण्डों के अनुसार  
संस्तुत न्यूनतम प्रतिव्यक्ति आवश्यकता अनाज  
अनाज और दालें

अ-अनुमानित  
अ-अनंतिम  
+ घरेलू उपभोग के लिए वस्तुतः वी गई मात्रा  
से संबंधित  
\* प्रारंभिक  
@आंकड़े कलण्डर वर्ष 1961 से  
आगे से सम्बन्धित हैं।

- वयस्क व्यक्ति  
(क) सामान्य कार्य 570 ग्राम प्रतिदिन  
(ख) भारी कार्य 730 ग्राम प्रतिदिन
- वयस्क महिला  
(क) सामान्य कार्य 485 ग्राम प्रतिदिन  
(ख) भारी कार्य 728 ग्राम प्रतिदिन  
दालें 47 ग्राम प्रतिदिन  
खाद्य तेल 6.5 किलोग्राम प्रतिवर्ष  
नोट : आर्थिक सर्वेक्षण, 1989-90 और  
अनुमान

सारणी 3.4 चावल और गेहूं की सरकारी खरीद

(मिलियन टन).

वित्तीय वर्ष	सरकारी खरीद		
	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4
1985-86	9.6	10.3	19.9
1986-87	9.4	10.5	19.9
1987-88	7.0	7.9	14.9
1988-89	7.6	6.5	14.1
1989-90 (अनंतिम)	11.2	9.0	20.3
अप्रैल-जून			
1989	0.8	8.7	9.6
1990	1.2	11.0	12.2

सारणी 3.5 आद्याओं की निकासी

(मिलियन टन)

वित्तीय वर्ष	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़
1	2	3	4	5
1983-84	7.7	7.4	0.2	15.3
1984-85	6.6	6.7	0.1	13.4
1985-86	7.4	11.7 (1.6)	0.2	19.3
1986-87	9.0	10.4 (2.9)	0.2	19.6
1987-88	10.1	12.8 (3.6)	0.1	23.0
1988-89	9.1	8.7 (1.0)	0.2	18.0

1	2	3	4	5
1989-90	8.6	7.3 (0.2)	नं.	15.9
अप्रैल-जून				
1989	2.0	1.6 (0.1)	नं.	3.6
1990	2.2	1.4 (—)	नं.	3.6

टिप्पणी: कोष्ठक में दर्शाये गये प्रांकड़े भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूँ की खुल-बाजार-बिक्री वसति हैं।

निकासी

3.10 वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान खाद्यान्नों की निकासी पिछले पाँच वर्षों में न्यूनतम थी (सारणी 3.5)।

वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान केन्द्रीय पूल में निकासी (खुला बाजार बिक्री सहित) कुल 15.9 मिलियन टन रही जबकि 1988-89 में 18.0 मिलियन टन और 1987-88 के सूखा वर्ष में 23.0 मिलियन टन थी। चावल और गेहूँ दोनों की निकासी पिछले वर्ष की तुलना में कम थी किन्तु यह कमी गेहूँ के मामले में विशेषरूप से थी। वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ ग्रामीण श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम/रोजगार गारंटी योजना/जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत प्राबंदन 1988-89 के 0.8 मिलियन टन और 1987-88 2.9 मिलियन टन की तुलना में इस वर्ष 0.4 मिलियन टन ही था। भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूँ की खुला बाजार बिक्री भी 1987-88 के 3.6 मिलियन टन से कम होकर 1988-89 में 1.0 मिलियन टन और 1989-90 के दौरान और कम होकर 0.2 मिलियन टन रह गयी।

खाद्यान्नों का स्टॉक

3.11 पिछले दो वर्षों में कम हुए स्टॉक की बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किये, यथा, सरकारी खरीद की कीमतें बढ़ाना और सर्वाधिक चावल और गेहूँ उगाने वाले इलाकों में अधिक खरीद केन्द्र खोलना। परिणामस्वरूप, सरकारी एजेंसियों के पास खाद्यान्नों के स्टॉक के स्तर में लगातार वृद्धि हुई है और यह मार्च 1989 के अंत में 7.4 मिलियन टन से बढ़कर मार्च 1990 के अंत में 11.7 मिलियन टन और जून 1990 के अंत में और बढ़कर 20.3 मिलियन टन हो गया।

सारणी 3.6 : खाद्यान्नों का स्टॉक

(मिलियन टन)

वित्तीय वर्ष	चावल	गेहूँ	मोटे धानाज	जोड़
1	2	3	4	5
मार्च के अंत में				
1981	5.4	10.0	0.1	15.4
1985	8.6	12.5	0.1	21.2
1986	10.3	10.2	0.2	20.7
1987	10.0	9.4	0.1	19.5
1988	5.9	3.3	0.2	9.4
1989	4.7	2.7	—	7.4
1990	7.9	3.6	0.2	11.7
जून के अंत में				
1989	3.6	9.4	नं.	13.0
1990	6.9	13.2	0.2	20.3

वाणिज्य फसल

3.12 तिलहन के सिवाय वाणिज्य फसलों के 1989-90 के दौरान उत्पादन में भारी वृद्धि होने की संभावना है। इसका कारण मुख्यतः बेहतर मौसमी स्थितियाँ और इन फसलों के लिए बनाये गये विशेष जोरदार विकास कार्यक्रम हैं। गन्ने का उत्पादन 210 मिलियन टन रहने का अनुमान है जो 1988-89 के 205 मिलियन टन के उत्पादन से 2.4 प्रतिशत अधिक है (सारणी 3.7)। रुई का उत्पादन 1988-89 के 87 लाख गांठों के मुकाबले 115 लाख गांठों के रिकार्ड पर पहुँचने की आशा है अर्थात् उसमें 32.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी, यह वृद्धि उत्पादकता तथा फसल क्षेत्र दोनों में वृद्धि के कारण है। जूट और मेस्ता का उत्पादन पिछले वर्ष के 77 लाख गांठों से बढ़कर इस वर्ष 81 लाख गांठों हो गया। तथापि, तिलहन का उत्पादन मुख्यतया गुजरात के मृगफलों उत्पादक इलाकों और राजस्थान और उत्तरप्रदेश के तोरिया/सरसों उत्पादक क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के कारण 1988-89 के 17.9 मिलियन टन में घटकर 17.2 मिलियन टन हो गया।

सारणी 3.7 : वाणिज्य फसलों का उत्पादन

फसल	इकाई	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90 (अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7	8
तिलहन	मि.ट.	13.0	10.8	11.3	21.7	17.9	17.2
गन्ना	मि.ट.	170.3	170.6	186.1	196.7	204.6	210.4
रुई*	लाख गांठें	85.1 (101.5)	87.3 (107.0)	69.1 (95.0)	63.8 (90.0)	86.9 (106.0)	114.9 (127.0)
जूट और मेस्ता*	लाख गांठें	77.9	126.5	86.2	67.8	77.0	83.5

कोष्ठक में दिये गए प्रांकड़े रुई सलाहकार बोर्ड के अनुमान हैं।

टिप्पणी : \*रुई की गांठें 170 कि.ग्रा. की तथा जूट और मेस्ता की एक गांठ 180 कि.ग्रा. की होती है।

स्रोत : कृषि विभाग

3.13 रुई की भरपूर फसल का देखने हुए, भारतीय कपास निगम और महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य एकाधिकार खरीद योजना के अंतर्गत इसकी भारी मात्रा में खरीद की ताकि किसान जल्दी बिक्री कर सकें। भारतीय कपास निगम जून 1990 के अंत तक रुई की 12.3 लाख गॉटों खरीदी जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में उनसे 5.7 लाख गॉटों खरीदी थी। महाराष्ट्र राज्य एकाधिकार खरीद योजना के अंतर्गत रुई की सरकारी खरीद जून 1990 के अंत तक कुल 20.5 लाख गॉटों थी जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 11.8 लाख गॉटों थी। इन दो ऐजेंसियों ने मिलकर इस वर्ष की रुई की फसल के एक चौथाई से भी अधिक की खरीद की। देशी कीमतों में तीव्र गिरावट से बचने के लिए नियमित के लिए रुई का प्राइंट 13.85 लाख गॉटों के रिकार्ड स्तर तक बढ़ा दिया गया। जूट की फसल के भी 1988-89 की तुलना में 1989-90 में अधिक होने का अनुमान है किन्तु कम स्टॉक उठाने के कारण कड़ी आपूर्ति-मांग की स्थिति बनी रही। इस प्रकार, देशी आपूर्ति बढ़ाने के लिए बांग्लादेश से कच्चे जूट के आयात के लिए सरकार की अनुमति के बावजूद जूट की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई। व्यापार सत्र के परिणामस्वरूप जूट की कीमतें बढ़ गई जिससे प्राधिकारियों को बाध्य होकर जमाखोरी विरोधी कार्रवाई, जूट के बायबा व्यापार पर प्रतिबंध और स्टॉक की सीमा प्रावि निर्धारित करती पड़ी ताकि कीमतों पर कड़ाई से निगरानी रखी जा सके। चीनी का उत्पादन 1989-90 के चीनी के मौसम के दौरान अब तक के सर्वाधिक 108 लाख टन से भी अधिक होने की आशा है। तथापि, तेजी से बढ़ते हुए घरेलू उपयोग ने कड़ी आपूर्ति मांग की स्थिति पैदा कर दी है।

#### आपूर्ति-मांग संतुलन

3.14 लगातार दूसरी अच्छी कृषि फसल ने खाद्यान्नों के संदर्भ में आपूर्ति-मांग संतुलन की स्थिति बनाये रखने में सहायता की। इस संबंध में हाल के महीनों में पुनः विचार का एक पहलू यह रहा है कि सरकारी एजेंसियों के पास खाद्यान्नों के स्टॉक को धीरे-धीरे फिर से तैयार किया जाए। चावल का स्टॉक जो मार्च 1987 के अंत में 10.0 मिलियन टन से कम होकर मार्च 1989 के अंत में 4.7 मिलियन टन रह गया था, मार्च 1990 के अंत में 7.9 मिलियन टन तक फिर से किया गया। रबी 1990 में गेहूं की भारी मात्रा में सरकारी खरीद के साथ जून 1990 के अंत में गेहूं का स्टॉक 13 मिलियन टन से अधिक हो गया। जून 1990 के अंत में कुल खाद्यान्नों का स्टॉक 20.3 मिलियन टन रहा। इस प्रकार वर्ष के इस समय तक के लिए निश्चित किया गया 21 मिलियन टन का मानदंड लगभग प्राप्त हो रहा है। अधिक उत्पादन के बावजूद वाली की आपूर्ति-मांग के अंतराल के कारण 1988-89 में 8.27 लाख टन के आयात की आवश्यकता हुई और उत्पादन में किसी बड़े अंतर के अभाव में 1989-90 में आयात का समान स्तर बनाये रखा गया। भरपूर फसल को देखते हुए रुई की प्रचुर आपूर्ति के कारण अधिक निर्यात की आवश्यकता हुई। चीनी जूट और चाय के मामले में निर्यात की मांग के बजाय ये खाद्य तत्वों के मामले में स्थिति, मुख्यतः गुजरात में कम फसल होने के कारण, और भी खराब हो गई जिसने लगभग 10 लाख टन की आपूर्ति का अंतर हो गया। सरकारी अनुमानों के अनुसार, खाद्य तेल वर्ष 1989-90 की मांग जहाँ तक 57.7 लाख टन बनाई गई और आन्तरिक दोनों में कुल उपलब्धि 47.2 लाख टन दिखाई गई, इस प्रकार लगभग 20 प्रतिशत का आपूर्ति अंतर रहा। 1987-88 में 19.67 लाख टन और 1988-89 में 11.66 लाख टन के खाद्य तेल के आयात में इन वर्षों में काफी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ी। निर्यातों के लिए जोरदार कार्यक्रमों और उनके लाभप्रद समर्थन मुख्य का देखते हुए, उनकी घरेलू उपलब्धता में वृद्धि होने की आशा है।

#### अन्य नीतिगत गतिविधियाँ

3.15 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कृषि और ग्रामीण विकास के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण नीतिगत पहल की गई है। पहला, सरकार ने यह निश्चित करने का निर्णय किया है कि सरकारी क्षेत्र के निदेशात्मक संसाधनों का प्राधा हिस्सा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास हेतु नियोजित किया जाए, दूसरा, यह निर्णय लिया गया है कि 1990-91 के केन्द्रीय बजट में घोषित ऋण माफी योजना के अंतर्गत बैंकों और सहकारी समितियों के बकाया ऋणों के संबंध में किसानों और ग्रामीण कारीगरों को 10,000 रुपये की सीमा तक राहत प्रदान की जाए। हाल में घोषित सरकारी खरीद की अधिक कीमतों से कृषि संबंधी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। विचारार्थन कृषि नीति के संवत्स में कृषि की दीर्घकालिक आधारभूत नीति पर जोर दिया गया है। उद्देश्यपूर्ण संस्थागत परिवर्तनों के माध्यम से कृषि में वृद्धि को और प्रोत्साहित करने के लिए भूमि सुधारों को तीव्र अनुसूची में लाने के लिए संविधान में संशोधन करने पर भी विचार किया जा रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण में एक गहन कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। सरकार द्वारा बनाई जा रही समग्र रोजगार गारंटी योजना के हिस्से के रूप में सूक्ष्मप्रस्तुत क्षेत्रों और बेरोजगारी बिकट समस्या वाले क्षेत्रों में एक रोजगार गारंटी योजना 1990-91 में प्रारम्भ की जाने वाली है। गरीबी विरोधी कार्यक्रमों को मजबूत किया जाना है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए समर्थित प्रयास भी नयी नीति का केन्द्र बिन्दु हैं जिससे ग्रामीण समाज के बड़े हिस्से का लाभ होगा। इन उपायों से ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि होगी, किसानों को बेहतर प्रोत्साहन मिलेगा, किसानों और कृषिश्रमिकों की आमदनी और साथ ही आधुनिक तकनीक के उपयोग में वृद्धि होगी, जिससे भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण विकास होने की आशा है।

#### 4 औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्तियाँ

4.1 राजकोषीय वर्ष 1989-90 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में मुख्यतया मंद वृद्धि के कारण औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में घर्ष के बड़े हिस्से में स्पष्ट कमी परिलक्षित हुई। तथापि, पिछली तिमाही में, विशेष रूप से मार्च, 1990 के अंतिम माह में विनिर्माण उत्पादन में प्रत्यक्ष बदलाव आया। इसके साथ-साथ खनन और उखनन क्षेत्र जिनमें पहली तीन तिमाहियों के दौरान सामान्यतया त्वरित दर पर वृद्धि हो रही थी, उसमें पिछली तिमाही के दौरान काफी कमी आई, इस प्रकार वर्ष के दौरान वृद्धि की दर औसत के साथ कम हुई। तथापि, विद्युत उत्पादन में 1989-90 के सम्पूर्ण वर्ष में वृद्धि की गति बनी रही। इन कारकों के परिणामस्वरूप 1989-1990 के दौरान औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक में आधार (1980=31-100) 8.3 प्रतिशत की पथोक्त वृद्धि हुई जिसकी तुलना 1988-89 में 8.7 प्रतिशत वृद्धि से की गई। उद्योगों का उपयोग आधारित वर्गीकरण दर्शाता है कि मूल वस्तुओं, मध्यवर्ती वस्तुओं और टिकाऊ उपभोग्य वस्तु उद्योगों की वृद्धि की दर में तीव्र कमी आई। जबकि पूर्वागत वस्तुओं और उपभोग्य गैर टिकाऊ वस्तु उद्योगों ने अपनी वृद्धि दर में तेजी का अनुभव किया। समूह के रूप में आधारित उद्योगों में भी सम्पूर्ण 1989-90 के दौरान वृद्धि की दर में कमी का अनुभव किया गया। विद्युत उत्पादन में विस्तार की गति लगभग सम्पूर्ण वर्ष के दौरान उच्चतर बनी रही।

4.2 दशवर्षीय 1989-90 में वृद्धि दर में मामूली सी कमी आई, सातवीं योजना अवधि ((1985-86 से 1989-90 तक) की औसत वृद्धि 8.4 प्रतिशत निकलती है जो 8 प्रतिशत के योजना लक्ष्य की तुलना में कुछ अधिक है। इस संतोषजनक बढ़ोतरी का श्रेय मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्र को है जिसका सामान्य सूचकांक में काफी योगदान रहा जिससे विनिर्माण क्षेत्र के अंतर उत्पादन, योजना में निर्धारित उत्पादन संख्या

से घागे बढ़ गया। तथापि, कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योजना लक्ष्यों के संवर्धन में महत्वपूर्ण कमी महसूस की गई। ग्राम्य प्रमुख क्षेत्र यथा, खनन और उत्खनन तथा विद्युत अपेक्षाकृत काफी पिछड़े गये।

#### समग्र प्रवृत्तियाँ

4.3 वित्तीय वर्ष 1989-90 (अप्रैल-मार्च) के दौरान औद्योगिक उत्पादन के मासिक सूचकांक (आधार: 1980-81=100) के औसत<sup>1</sup>

1988-89 में प्राप्त वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत से थोड़ी कम होकर 8.3 प्रतिशत रह गई। ऐसा औद्योगिक विकास के कुछ धीमा पड़ जाने, विनिर्माण उत्पादन के 8.7 प्रतिशत से घटकर 8.3 प्रतिशत हो जाने, खनन और उत्खनन के 7.9 प्रतिशत से घटकर 5.9 प्रतिशत होने के कारण था। तथापि, विद्युत उत्पादन 9.5 प्रतिशत से बढ़कर 10.7 प्रतिशत (भारण 4.1) हो गया।

सारणी 4:1 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की प्रवृत्तियाँ

आधार (1980-81=100)<sup>1</sup>

क्षेत्र	खनन और उत्खनन		विनिर्माण		बिजली		सामान्य सूचकांक	
भारत :	(11.46)		(77.11)		(11.43)		(100.00)	
वर्ष	सूचकांक वृद्धि दर (प्रतिशत)		सूचकांक वृद्धि दर (प्रतिशत)		सूचकांक वृद्धि दर (प्रतिशत)		सूचकांक वृद्धि दर (प्रतिशत)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>वार्षिक औसत वृद्धि दर</b>								
1970-71 से	--	+4.3	--	+4.0	--	+7.3	--	+4.4
1980-81 <sup>(a)</sup>								
1980-81 से	--	+12.6	--	+5.7	--	+8.9	--	+7.0
1984-85								
1980-81 से	--	+8.7	--	+7.4	--	+9.1	--	+7.8
1989-90								
<b>वार्षिक वृद्धि दर</b>								
1985-86	167.5	+4.2	136.9	+9.7	152.4	+8.5	142.1	+8.7
1986-87	177.9	+6.2	149.7	+9.3	168.1	+10.3	155.1	+9.1
1987-88	184.6	+3.8	161.5	+7.9	181.0	+7.7	166.4	+7.3
1988-89	199.1	+7.9	175.6	+8.7	198.2	+9.5	180.9	+8.7
1989-90	210.09	+5.9	190.2	+8.3	219.4	+10.7	195.9	+8.3
<b>सातवीं योजना अवधि की औसत वृद्धि दर (1985-86 से 1989-90)</b>								
वास्तविक आंकड़े		+5.6		+8.8		+9.3		+8.4
योजना लक्ष्य		+13.0		+8.0		+12.0		+8.0

<sup>(a)</sup> सूचकांकों की 1970 की श्रृंखलाओं पर आधारित

## निर्माण प्रवृत्तियाँ

4.4 राजकोषीय वर्ष 1989-90 की शुरुआत सामान्य सूचकांक की वृद्धि दर में स्पष्ट कमी से हुई, इसका मुख्य कारण विनिर्माण उत्पादन की वृद्धि में तीव्र गिरावट था। यह गिरावट कुछ सीमा तक निम्नलिखित क्षेत्र के लिए एक समान लेखा वर्ष (अप्रैल-मार्च) परिवर्तन और विनिर्माण सूचकांक 1.3.4 प्रतिशत तक बढ़ने पर पिछले वर्ष की पहली तिमाही में अपेक्षाकृत उच्च आधार के कारण थी (सारणी 4.2)। पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान किसी भी-य इस्पात, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात, पिण्ड, दुलाई वाला इस्पात, प्रसारण टावर सरचनाएँ, अल्पमिनियम की आदरे और गोले जैसे अनेक उद्योगों ने नकारात्मक या कम वृद्धि दर दर्ज की। औद्योगिक उत्पादन के समग्र सूचकांक की वृद्धि पर पहली तिमाही के 2.4 प्रतिशत से बढ़कर दूसरी

तिमाही में 6.3 प्रतिशत और बाइबाली की तिमाहियों में बढ़कर क्रमशः 8.3 प्रतिशत और 15.2 प्रतिशत हो गई। दूसरी तिमाही से आगे औद्योगिक उत्पादन में यह वृद्धि मुख्यता विनिर्माण उत्पादन की वृद्धि दर ने महत्वपूर्ण सुधार के कारण थी। खनन और उत्खनन क्षेत्र की वृद्धि दर पहली दो तिमाहियों में 10.0 प्रतिशत से कम होकर तीसरी तिमाही में 3.3 प्रतिशत और वर्ष की अंतिम तिमाही में 1.2 प्रतिशत हो गई। यह कमी मुख्यतः कोयला उद्योग के समक्ष आई कठिनाइयों के कारण आई प्रतीत होती है। यह नियमित कमी विन्धुवार 4 संचित उत्पादन में मास-दर-मास घट-बढ़ में परिलक्षित होती है? (सारणी 4.3) विद्युत उत्पादन में वृद्धि की दर जो पहली तीन तिमाहियों में उच्च स्तर पर थी, अंतिम तिमाही में कुछ-कुछ कम हो गई।

सारणी 4.2 तिमाही आधार पर औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की प्रवृत्तियाँ

आधार (1980-81 = 100)

(अंतिम)

तिमाही	खनन और उत्खनन		विनिर्माण		विजली		सामान्य	
	1988-89	1989-90	1988-89	1989-90	1988-89	1989-90	1988-89	1989-90
अप्रैल-जून	182.2	201.5	170.4	170.3	190.7	207.8	174.1	178.2
	(+6.2)	(+10.6)	(+13.4)	(-0.1)	(-101.4)	(+9.0)	(+12.1)	(+2.4)
जुलाई-सितम्बर	175.3	193.3	167.1	174.5	186.4	213.0	170.2	181.0
	(+5.0)	(+10.3)	(+6.9)	(+4.4)	(+1.9)	(+14.5)	(+6.0)	(+6.3)
अक्तूबर-दिसम्बर	207.1	214.0	176.8	191.8	203.5	229.1	183.4	198.1
	(+9.3)	(+3.3)	(+9.4)	(+8.5)	(+13.4)	(+12.6)	(+10.0)	(+8.3)
जनवरी-मार्च	231.9	234.7	188.1	224.0	212.3	227	195.9	225.6
	(+10.2)	(+1.2)	(+5.7)	(+19.1)	(+12.3)	(+7.3)	(+7.1)	(+15.2)

टिप्पणी . कोष्ठकों में दिये गये आंकड़ों पिछले वर्ष के तदनुसंगी आंकड़ों की तुलना में प्रतिशत बढ़-बढ़ दर्शाते हैं।

## उपयोग आधारित वर्गीकरण

4.5 1989-90 के दौरान औद्योगिक विकास की प्रवृत्ति पिछले वर्ष या सामान्यतया पिछले आठ वर्षों की 1980-81 से 1988-89 प्रवृत्ति से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न थी। जब 1970 के दशक में वृद्धि दर पर औद्योगिक विकास की गति में स्पष्ट वृद्धि दृष्टिगोचर वृद्धि हुई यह उद्योगों के उपयोगों आधारित वर्गीकरण (सारणी 4.4) पर आधारित औद्योगिक उत्पादन की समूहवार वृद्धि दरों में बिखरित है पहले टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु उद्योग जिन्होंने पिछले आठ वर्षों में 8 प्रतिशत से 22 प्रतिशत के बीच औसतन उच्च वार्षिक वृद्धि प्रदर्शित की, ने उपभोक्ता मांग के दबावों के कारण 1989-90 के दौरान अपनी वृद्धि दर में 1.9 प्रतिशत की स्पष्ट गिरावट का सामना किया। गैर टिकाऊ उपभोक्ता क्षेत्र ने पिछले वर्ष के दौरान विकास में 5.1 प्रतिशत से 6.1 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की। पिछले वर्ष के सूखे के कारण कृषि संबंधी कच्चे माल की कम आपूर्ति के कारण 1988-89 में यह निष्पादन की तुलना में 1989-90 में गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि एक महत्वपूर्ण सुधार था जिसे बाद में कुछ कच्चे माल की उपलब्धि में हुए सुधार के साथ जोड़ दिया गया। दूसरे, मूलभूत उद्योगों और मध्यवर्ती वस्तु उद्योगों में पिछले वर्ष 1989-90 और पिछले आठ वर्षों की अवधि के निष्पादन की तुलना में महत्वपूर्ण कमी आई। यह कोयला खनन, इस्पात

और इस्पात से बने उत्पादों, अल्पमिनियम, उर्वरक, पेट्रो रसायन और रसायन-आधारित उद्योगों तथा जूट विनिर्माताओं जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के सम्मुख आने वाले प्रतिकूल आपूर्ति संबंधी कारण हुई है। पूंजीगत वस्तु उद्योगों जिन्होंने उद्योगीकृत आयात नीति के कारण हाल के वर्षों में आयातित वस्तुओं से सामान्यतया कड़ी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला किया है, ने 1989-90 के दौरान समूह के रूप में और वृद्धि का अनुभव किया तथा इस प्रकार समूह की उच्च वृद्धि स्थिति को बनाये रखा। तथापि, इस क्षेत्र के भीतर चित्त का स्वरूप भिन्नित था, जिनमें से कुछ उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि और कुछ अन्य समान रूप से पर्याप्त स्पष्ट कमी दर्शा रहे थे, ये सुधार अधिकांशतः अपने संबंधित उपभोक्ता उद्योगों में हुए सुधार द्वारा निर्धारित किये गये थे। अच्छी मामूली के साथ डीजल इंजनों और शक्ति वाहक पम्पों की मांग में कमी आई जबकि समान कारण से कृषि ट्रैक्टरों और चीनी मिल मशीनों की मांग में वृद्धि हो गई जिसके परिणामस्वरूप इनका उच्चतर उत्पादन हुआ। बिजली उत्पादन की उन्नत गति के साथ बिजली के ट्रांसफार्मरों, ए.एस.टी./एस.एस.एस. और कंडक्टरों, घुमावदार तार और विद्युत जनरेटरों तथा विद्युत संघारित्रों जैसे बिजली के अनेक कलपुर्जों ने बेहतर निष्पादन दर्शाया। तथापि, कागज और लुगदी, मशीन उद्योग के उत्पादन में कमी आई क्योंकि उनके उपभोक्ता उद्योगों के निवेश कार्यक्रमों में धीमापन आ गया।

सारणी 4.3 : औद्योगिक उत्पादन @ के सूचकांक (1980-81 = 100) माहवार और संचयी घट-बढ़

(प्रतिशत)

माह	मासिक +								संचयी ++							
	खनन और उत्खनन		विनिर्माण		विद्युत्		सामान्य सूचकांक		खनन और उत्खनन		विनिर्माण		विद्युत्		सामान्य सूचकांक	
	1988-89	1989-90	1988-89	1989-90	1988-89	1989-90	1988-89	1989-90	1988-89	1989-90	1988-89	1989-90	1988-89	1989-90	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
अप्रैल	2.7	16.4	9.4	1.5	8.1	11.0	8.4	4.5	2.7	16.4	9.4	1.5	8.1	11.0	8.4	4.5
मई	7.3	7.4	17.8	—0.8	13.6	8.7	15.8	1.4	5.0	11.8	13.5	0.3	10.9	9.8	12.0	2.9
जून	8.5	8.3	13.3	—0.8	9.5	7.3	12.3	1.2	6.2	10.6	13.4	—0.1	10.4	9.0	12.1	2.4
जुलाई	5.6	10.0	2.1	3.4	0.1	12.3	2.2	5.2	6.0	10.4	10.4	0.8	7.7	9.8	9.6	3.1
अगस्त	2.4	13.5	10.9	4.9	3.3	14.1	8.9	7.0	5.4	11.0	10.5	1.5	6.8	10.6	9.4	3.8
सितम्बर	7.1	7.5	8.0	5.1	2.5	16.9	7.2	6.8	5.6	10.5	10.1	2.1	6.0	11.7	9.1	4.3
अक्तूबर	9.8	3.6	10.6	5.4	9.9	15.7	10.4	6.5	6.3	9.4	10.1	2.7	6.6	12.2	9.2	4.6
नवम्बर	10.0	3.2	7.5	10.4	14.2	11.9	8.6	9.7	6.7	8.6	9.8	3.7	7.5	12.3	9.2	5.3
दिसम्बर	8.3	3.2	10.2	9.4	16.1	10.4	10.6	8.7	7.0	7.8	9.8	4.4	8.5	12.0	9.3	5.7
जनवरी	9.1	1.0	9.7	13.9	13.9	9.3	10.1	11.6	7.2	7.0	9.9	5.3	9.1	11.7	9.4	6.4
फरवरी	9.0	1.8	3.7	13.3	9.7	6.3	5.1	10.9	7.3	6.5	9.3	6.1	9.2	11.2	9.0	6.8
मार्च	12.3	0.8	4.1	29.0	13.2	6.0	6.2	22.4	7.9	5.9	8.7	8.3	9.5	10.7	8.7	8.3

@ अन्ततिम

+ पिछले वर्ष की तुलना में बिन्दुवार माहवार पर प्रतिशत घट-बढ़।

++ पिछले वर्ष के संचयी औसत की तुलना में वित्तीय वर्ष की औसत घट-बढ़।



## सारणी 4.4: औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर

## उपभोग-आधारित वर्गीकरण

उद्योग समूह	भारत		सभी उद्योग		बहुतेरुण 155 उद्योग		
	वार्षिक औसत प्रतिशत वृद्धि		उद्योगों की संख्या है		भारत अप्रैल-फरवरी के दौरान प्रतिशत परिवर्तन		
	1981-82 से 1984-85		1985-86 से 1988-89		1988-89 से 1989-90		
	1		2		3		
	2	3	4	5	6	7	8
1. मूल वस्तुएं	39.42	+8.8	+8.9	40	36.36	+9.8	+5.0
2. पूंजीगत वस्तुएं	16.42	+6.3	+13.0	32	11.32	+8.7	+24.9
3. मध्यवर्ती वस्तुएं	20.51	+6.1	+7.1	36	16.10	+12.2	+3.1
4. उपभोक्ता वस्तुएं	23.65	+5.3	+8.0	47	21.76	+7.2	+5.4
(क) टिकाऊ उपभोक्ता	2.55	+14.4	+16.9	12	2.20	+19.2	+1.9
(ख) गैर टिकाऊ उपभोक्ता	21.10	+4.0	+6.3	35	19.56	+5.1	+6.1
सामान्य सूचकांक	2100.00	+7.0	+8.5	155	85.54	+9.5②	+8.3②

\* औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक में 85.5 प्रतिशत कुल भारत के साथ 155 उद्योगों में मध्यस्थित अत्यन्तम उत्पादन आंकड़े

(1980-81 = 100)

② 155 उद्योगों के सूचकांकों में घट-वृद्धि

## सारणी 4.5: औद्योगिक उत्पादन के सूचकांकों में वृद्धि दर

प्रमुख समूहों का उत्पादन (आधार: 1980-81 = 100)

मह	भारत	अप्रैल		मार्च
		1987-88	1988-89	
1	2	3	4	5
I. घनात्मक वृद्धि				
(क) वृद्धि				
1. पेय, तम्बाकू, इत्यादि	1.57	84.9	92.1	103.0
		(-13.8)	(+8.5)	(+11.8)
2. कागज और कागज के उत्पाद	3.23	166.3	171.3	181.5
		(+1.9)	(+3.0)	(+6.0)
3. बिजली की मशीनें	5.78	335.2	348.6	458.9
		(+31.6)	(+4.0)	(+31.6)
4. धातु से बनी वस्तुएं	2.29	129.6	135.5	142.6
		(+4.2)	(+3.0)	(+6.8)
5. सूती वस्त्र	12.31	111.2	107.6	111.2
		(-1.2)	(3.2)	(+3.3)
6. चमड़ा और चमड़े की वस्तुएं	0.49	185.5	177.4	188.2
	26.67	(-4.4)	(+4.4)	(+6.1)
(ख) कमी				
7. ग्राह्य उत्पाद	5.33	139.0	148.3	150.9
		(+4.4)	(+6.7)	(+1.8)

1	2	3	4	5
8. वस्त्र उत्पाद	0.82	91.8 (+5.4)	134.2 (+46.2)	150.6 (+12.2)
9. लकड़ी और लकड़ी से बनी वस्तुएं	0.45	161.7 (-34.3)	171.7 (+6.2)	175.8 (+2.4)
10. रबर, प्लास्टिक और पेट्रोलियम उत्पाद	4.00	155.1 (+3.7)	168.2 (+8.4)	173.4 (+3.1)
11. रसायन और रसायन के उत्पाद	12.51	299.0 (+14.5)	235.4 (+16.2)	247.4 (+5.9)
12. धातुिक खनिज उत्पाद	3.00	158.1 (-1.4)	184.1 (+16.8)	180.9 (+2.3)
13. मशीनें और मशीनों की भाँजियाँ	6.24	139.3 (-1.8)	160.5 (+15.3)	170.1 (+6.0)
14. परिवहन उपकरण	6.39	151.8 (+4.8)	172.0 (+13.3)	180.4 (+4.9)
15 विविध	0.90	272.1 (+15.6)	304.6 (+11.9)	334.4 (+9.8)
II. श्रृणात्मक वृद्धि				
16. जूट के वस्त्र	2.00	91.0 (-10.0)	101.9 (+12.0)	96.9 (-4.9)
17. मूलधातु और मिश्रधातु				
विनिर्माण	11.80	135.0 (+6.9)	144.9 (+6.9)	143.7 (-0.8)
	77.11	161.5 (+7.9)	175.6 (+8.7)	190.2 (+8.3)

## विनिर्माण क्षेत्र

4.6 सातवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान हुई 8.9 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि की तुलना में क्षेत्र के उत्पादन की वृद्धि में गिरावट आई और 1989-90 (अप्रैल-मार्च) के दौरान यह 8.3 प्रतिशत

रह गया। विनिर्माण क्षेत्र के निष्पादन की सुधमता से देखने के लिए 17 प्रमुख औद्योगिक समूहों के 1989-90 के अप्रैल-मार्च के वित्तीय वर्ष के उनके द्वि-वर्षक स्तरीय बर्गीकरण (सारणी 4.5) पर आधारित, उपलब्ध समूहवार आंकड़ों को देखा जा सकता है।

सारणी 4.6: मूल भूत उद्योगों के उत्पादन की प्रवृत्तियाँ

उद्योग	यूनिट	भारत का औसत वार्षिक वृद्धि, पी. में	अप्रैल-मार्च के दौरान उत्पादन		
1	2	3	4	5	6
1. बिजली	मिलियन कि. वाट	11.43	201894 (+7.6)	221125 (+9.5)	244971 (+10.8)
2. कोयला	मि. टन	6.61	179.74 (+8.5)	194.57 (+8.3)	200.85 (+3.2)
3. बिजलीय व इस्पात	हजार टन	5.21	8388.0 (+4.5)	9206.0 (+7.2)	9028.7 (-1.9)
4. कच्चा पेट्रोलियम	-वही-	2.41	303.57 (-0.4)	32040 (+5.5)	34076 (+6.4)
5. पेट्रोलियम निष्पादन के उत्पाद	-वही-	1.52	44407 (+2.7)	45384 (+2.2)	48300 (+6.4)
6. सीमेंट	-वही-	1.60	39550 (+8.1)	44295 (+12.0)	45603 (+3.0)
संरचनात्मक उत्पादन का मिला-जुला सूचकांक (1980=81=100)		28.77	178.6 (+6.0)	193.2 (+8.2)	208.1 (+6.9)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़ों की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

4.7 77.11 प्रतिशत बिन्दु भारांक वाले 17 प्रमुख औद्योगिक समूहों में से 51.44 प्रतिशत बिन्दु वाले प्यारह औद्योगिक समूहों में या तो प्रत्यक्ष कमी या गिरावट का अनुभव किया गया। जूट से बने वस्त्र, मूलभूत धातुओं और मिश्र धातु उत्पादों में गिरावट परिलक्षित हुई। जिन महत्वपूर्ण औद्योगिक समूहों के उत्पादन में कमी हुई, वे हैं—रसायन और रसायन उत्पाद, गैर धात्विक खनिज उत्पाद (सीमेंट सहित), सूती वस्त्र उत्पाद, मशीनें तथा मशीनी औजार, खाद्य उत्पाद और परिवहन उपस्कर। परिवहन उपस्कर मर्बों में रेलवे बैगनों के उत्पादन में कमी आई जबकि जीप, से और तीन पहियों वाले बाइको और कारों के उत्पादन में वृद्धि परिलक्षित हुई। सूती वस्त्र उत्पादों जिनमें पिछले कुछ वर्षों में प्रसाधारण दरों पर वृद्धि हुई, में 1989-90 के दौरान वृद्धि दर में कुछ कमी आई। जिन उद्योगों के उत्पादन वृद्धि में 1989-90 के दौरान वृद्धि हुई थी, उनमें विद्युत् मशीनें ही एक समूह है जिसमें बिजली क्षेत्र में सामान्य सुधारों के कारण 31.6 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर परिलक्षित होती है। कच्ची रई की अधिक आपूर्ति के बाद सूती वस्त्रों के उत्पादन में पिछले वर्ष की 3.2 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 3.3 प्रतिशत वृद्धि में विरामकाल वृद्धिशेखर होता है। विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में जबकि सूती धागों और कपड़ों के उत्पादन में कुछ सुधार आया, मिल क्षेत्र में कारड़े उत्पादन पावरलूम क्षेत्र को आधार प्रदान करता रहा, इससे हाल के वर्षों में देखी गई उपसर्गिता की बढ़ती प्रवृत्ति का आभास होता है।

सारणी 4.7 : 1988-89 और 1989-90 के दौरान वृद्धि दरों आधार पर 155 उद्योगों का आवर्ती वितरण

वृद्धि की सीमा	अप्रैल 1988 मार्च 1989		अप्रैल 1989 फरवरी 1990	
	भारांक	उद्योगों की संख्या	भारांक	उद्योगों की संख्या
1	2	3	4	5
<b>घनात्मक</b>				
25% से अधिक	9.2	36	2.6	12
25% से 10% तक	13.8	32	18.8	35
10% से 5% तक	32.3	30	22.0	26
5% से 0% तक	13.5	21	20.7	35
उप जोड़	68.8	119	64.1	108
<b>कृणात्मक</b>				
0% से 5% तक	9.2	15	11.7	22
-5% से -10% तक	3.6	5	6.4	9
-10% से -25% तक	2.8	12	2.0	8
-25% से नीचे	1.1	4	1.3	8
उप जोड़	16.7	36	21.4	47
जोड़	85.5	155	85.5	155

#### आधारभूत उद्योग

4.8 1989-90 (अप्रैल-मार्च) के दौरान आधारभूत उद्योगों के निष्पादन में औद्योगिक वृद्धि में सामान्यतया गिरावट प्रतिबिम्बित हुई। छह आधारभूत उद्योगों यथा, बिजली, कोयला (विस्फोट को छोड़कर) कच्चा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत् उद्योग इत्यादि और सीमेंट (सामान्य सूचकांक में 28.77 प्रतिशत के भारांक के माध्य) के

औसत समिश्र सूचकांक ने पिछले वर्ष (सारणी 4.6) के 8.2 प्रतिशत की तुलना में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर में कमी दर्ज की। छह आधारभूत उद्योगों में से पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों को छोड़कर सभी ने अपने कार्यक्रम में निविष्ट वार्षिक लक्ष्यों की तुलना में वृद्धि में कमी दर्ज की। यद्यपि विद्युत् उत्पादन में वृद्धि की दर दर्शाती, यह पूरे वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए निविष्ट 13.6 प्रतिशत की वृद्धि के लक्ष्य को देखते हुए फिर भी कम रही। आधारभूत उद्योगों के बीच विद्युत् क्षेत्र का निष्पादन 1988-89 में 9.5 प्रतिशत की तुलना में 10.8 प्रतिशत के उत्पादन में वृद्धि के साथ अब तक सर्वोत्तम था। राज्य बिजली बोर्डों के मामले में कार्यक्रम में निविष्ट संयंत्र भार गुणांक के लक्ष्यों में कमी के बावजूद विद्युत् क्षेत्र में त्वरित वृद्धि के बाद मध्यवर्ती और निजी विद्युत् उत्पादक इकाइयों द्वारा उन्माद संयंत्र भार गुणांक की प्राप्ति हुई। इसके प्रतिरूप, संयोगजनक पन बिजली उत्पादन से भी आपूर्ति की स्थिति में सुधार आया। 1989-90 के दौरान कच्चे पेट्रोलियम (5.5 प्रतिशत की तुलना में 6.4 प्रतिशत) और पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों (2.2 प्रतिशत की तुलना में 6.4 प्रतिशत) के उत्पादन में त्वरित वृद्धि भी उल्लेखनीय है। कच्चे पेट्रोलियम के उत्पादन में उच्चतर वृद्धि में मुख्यतया तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के तद्वर्ती तेल क्षेत्रों और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के भण्डार (समुद्र तट से दूर) उत्पादन के साथ भाषण इंडिया लिमिटेड में सहायता की और पिछले वर्ष की तरह वृद्धि में सीमान्त योगदान किया। कुल मिलाकर 1989-90 में कच्चे तेल का कुल उत्पादन 34.1 मिलियन टन रहा जो 34.3 मिलियन टन के उत्पादन लक्ष्य के करीब था। रिफाइनरियों की क्षमता उपयोग के बेहतर निष्पादन से घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन की उच्चतर दर 1988-89 के 96.4 प्रतिशत से बढ़कर 1989-90 में 97.1 प्रतिशत हो गई, इससे पीछोपल उत्पादों का लक्ष्य 47.38 मिलियन टन से लगभग 2 प्रतिशत (वास्तविक उत्पादन 48.3 मिलियन टन था) अधिक हो गया। कोयला और सीमेंट के उत्पादन की वृद्धि में 1988-89 में क्रमशः 8.3 प्रतिशत और 12.0 प्रतिशत से 3.2 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत की कमी आई। कोयला क्षेत्रों का अमनतोषजनक निष्पादन मुख्यतया मशीनें खराब हो जाने, असमस्तोषजनक औद्योगिक सबधों और गैरहाजिरी के कारण रहा। 209.5 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में 1989-90 में कोयले का वास्तविक उत्पादन 201 मिलियन टन रहा। मांग और घरेलू उत्पादन के बीच 12.5 मिलियन टन का अंतराल है जिसे अंशतः 4.5 मिलियन टन कच्चे कोयले का आयात करके पूरा किया जायेगा। विद्युत् उद्योग इत्यादि में 1988-89 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 1.9 प्रतिशत की गिरावट का कारण वर्ष के कुछ हिस्से में बिजली की कमी और आयातित प्राकृतिक कोटि के कच्चे कोयले की कमी था। पिछले वर्ष से अग्रणी स्टॉक की मौजूदगी की मिलाकर कम घरेलू मांग के फलस्वरूप संयंत्र परिवर्तनों के अवरोध स्तरों के कारण सीमेंट का उत्पादन प्रत्यक्षतः उच्चतर पर पहुँच गया है। 1989-90 में 45.6 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन अभिवाही घरेलू मांग के तदनु-रूप था और इस प्रकार अत्यन्त-निर्भरता की स्थिति आ चुकी है।

#### उद्योगवार स्थिति

4.9 1989-90 के पूरे राजकोषीय वर्ष उपलब्ध उद्योगवार आंकड़े दर्शाते हैं कि चुने हुए 155 उद्योगों में से औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में 64.1 प्रतिशत के कुल भार वाले 108 उद्योगों में 1989-90 के दौरान घनात्मक वृद्धि दर्शायी। पिछले वर्ष घनात्मक वृद्धि दर्शाने वाले 68.8 प्रतिशत भारवाले 119 उद्योग थे। 0 से 5 प्रतिशत की कम सीमा में वृद्धि दर्शाने वाले उद्योगों का भार पिछले वर्ष में 13.5 प्रतिशत भारयुक्त ऐसे उद्योगों की तुलना में 20.7 प्रतिशत या पुनः 5 से 10 प्रतिशत की उच्चतर सीमा में वृद्धि दर्शाने वाले उद्योगों का भार पिछले वर्ष के 32.3 प्रतिशत (सारणी 4.7) की तुलना में 1989-90 में 22.0 प्रतिशत था।

4.10 1989-90 के दौरान अलग-अलग उद्योगों के निष्पादन के विश्लेषण से पता चलता है कि कृषि पर आधारित उद्योगों के अन्तर्गत

महत्वपूर्ण उद्योगों का वस्तु, जैसे चीनी, वनस्पति और मिल क्षेत्र के कपड़े में प्रत्येक में लगभग 5-6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। 1989-90 अप्रैल-मार्च में लगभग 1.4 प्रतिशत की सीमा तक चीनी का उत्पादन मुख्यतया इसलिए कम रहा क्योंकि गन्ने को खाइसारी और गुरु के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया गया, साथ ही गन्ने की चीनी का कम उत्पादन भी इस गिरावट का कारण रहा। मिल क्षेत्र के सूती बने के उत्पादन में पिछले वर्ष 7.2 प्रतिशत की भारी गिरावट के बावजूद 5.7 प्रतिशत की कमी न केवल विकेंद्रीकृत क्षेत्र (पावरलूम) में बढ़ती प्रतियोगिता का परिणाम है बल्कि संगठित क्षेत्र में स्थित मिलों के बीच सुरुंगा के बढ़ते प्रभाव का परिणाम भी है। वनस्पति के उत्पादन में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में लगभग 5.7 प्रतिशत की कमी सम्भवतः वनस्पति उत्पादन के लिए निकाले गये सरमा के तेल के उपयोग पर प्रतिबन्धों और गैर परम्परागत स्रोतों को प्रतिस्थापित करने में उद्योग की असमर्थता थी। चाय का उत्पादन दक्षिण भारत में चाय के उत्पादन को प्रभावित करने वाली प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के बावजूद 1989-90 में 5.9 प्रतिशत बढ़कर 723.7 मिलियन किलोग्राम हो गया।

4.11 रसायन आधारित उद्योगों में फास्फोरिक एसिड के आयातों में कमी के कारण फास्फेटिक उर्वरकों के मामले में लगभग 20.3 प्रतिशत की तीव्र गिरावट दर्ज हुई। तथापि, नाइट्रोजनी उर्वरकों में पिछले वर्ष के दौरान 22.8 प्रतिशत की अकेला अधिक वृद्धि के मुकाबले 0.8 प्रतिशत की निम्नतर वृद्धि दर दर्ज हुई। विद्युतिक धातुओं में विस्कोस और पालियस्टर धातुओं के उत्पादन में पिछले वर्ष क्रमशः 21.1 प्रतिशत और 43.83 प्रतिशत की भावनाली वृद्धि की तुलना में मांग की कमी के कारण 3.7 प्रतिशत और 5.7 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। स्टैपल रेशा में विस्कोस और पालियस्टर स्टैपल रेशों के उत्पादन में, बेहतर निर्यात मांग के फलस्वरूप, पिछले वर्ष के दौरान क्रमशः 8.6 प्रतिशत और 5.6 प्रतिशत की तुलना में 17.1 प्रतिशत और 11.7 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई।

4.12 धातु पर आधारित उद्योगों में प्रथम 1989-90 के दौरान आटोमोबाइल क्षेत्र में बहुमुखी वृद्धि दर्ज हुई। वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन में उच्चतर मांग के कारण 1988-89 के 2.2 प्रतिशत की तुलना में 3.2 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। जहाज कारों का उत्पादन (पिछले वर्ष के 16.4 प्रतिशत के मुकाबले) 12.2 प्रतिशत तक बढ़ा, वहीं आटोमोबाइल का उत्पादन पिछले वर्ष के 29.3 प्रतिशत से गिरकर 4.1 प्रतिशत पर आ गया। जोपों में पिछले वर्ष के 59.3 प्रतिशत वृद्धि की अपेक्षा इस वर्ष 21.4 प्रतिशत की कम वृद्धि दर्ज हुई। उत्पादन समूह के रूप में दो पहियों वाले वाहनों (स्कूटर, मोटर साइकल, स्कूटरिंग और मोपेड सहित) का उत्पादन 4.8 प्रतिशत से घटकर 4.6 प्रतिशत रह गया। इसका मुख्य कारण यह था कि मोटर साइकलों के उत्पादन की वृद्धि में गिरावट दर्ज की गई। रेल के डिब्बों का उत्पादन 1988-89 के 35.4 प्रतिशत से घटकर 1989-90 में 4.1 प्रतिशत रह गया। तथापि, दो पहियों वाले वाहनों में से स्कूटरों का उत्पादन, अनिवार्यतः मोटर साइकलों और मोपेडों की मांग में वृद्धि के कारण प्रभावशाली रूप से बढ़कर 20.1 प्रतिशत (23.7 प्रतिशत के मुकाबले) तक बढ़ गया। रेल के डिब्बों की पर्याप्त मांग न होने तथा साथ ही हाल ही के वर्षों में खल स्टोक कम रहने की वजह से, उनके उत्पादन में ठहराव आया।

योजना लक्ष्यों के साथ संश्लिष्ट तुलना

4.13 सातवी योजना अवधि के पांच से छह वर्षों में योजना में की गई कल्पना के अनुसार 8.0 प्रतिशत वार्षिक की दर की तुलना में औद्योगिक वृद्धि की उच्चतर दरें प्राप्त हुईं। इसके परिणामस्वरूप, योजना अवधि की औसत वृद्धि 8.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष के स्तर पर थोड़ी सी उच्चतर होती है। यह विनिर्माण जिसका सामान्य सूचकांक (सारणी 4.1 में) 77.11 प्रतिशत का बना भार है, के लक्ष्य (8.0 प्रतिशत की तुलना में 8.8 प्रतिशत) के मुकाबले उच्चतर वृद्धि द्वारा सम्भव हो सका है। दोनों खनन और उत्खनन तथा विद्युत् क्षेत्रों का निष्पादन सातवी योजना के

लक्ष्यों की देखरेख में हुए महत्वपूर्ण रूप से पिछड़ गया। 226 मिलियन टन के सातवी योजना के लक्ष्य के मुकाबले 1989-90 में वास्तविक कोयला उत्पादन 201 मिलियन टन था—इस प्रकार 11 प्रतिशत की कमी हुई। बिजली उत्पादन में वास्तविक उत्पादन 295.4 बिलियन किलोवाट के मूल लक्ष्य और 278 बिलियन किलोवाट के संशोधित लक्ष्य के मुकाबले 295.4 बिलियन किलोवाट था—इस प्रकार मूल लक्ष्य के संदर्भ में 17 प्रतिशत और संशोधित लक्ष्य के संदर्भ में 12 प्रतिशत की कमी आई। पेट्रोलियम क्षेत्र में पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का वास्तविक उत्पादन योजना लक्ष्य से घाटे बढ़ गया जबकि कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन लक्ष्य के मुकाबले मामूली-सा कम रहा।

4.14 विनिर्माण क्षेत्र में भी कतिपय महत्वपूर्ण गिरावटें आयी जो अत्यन्त स्पष्ट थीं। वे इस्पात के भनावा मूल धातुएं हैं, जैसे अल्युमिनियम, तांबा, जस्ता और सीसा। इसी प्रकार, प्रमुख विद्युत् मशीनों जैसे पावर ट्रांसफार्मर और बिजली के मोटरों में भारी कमी देखने में आयी। आटोमोबाइल क्षेत्र में वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन में सानवी योजना के लक्ष्य के ऊपर लगभग 22 प्रतिशत की गिरावट आयी यद्यपि, संस्थापित क्षमता उत्पादन के स्तर के मुकाबले काफी अधिक है। यात्री कारों, दो पहियों वाले वाहनों और विस्कोस तथा पालियस्टर धातु और रेशों का उत्पादन योजना लक्ष्यों के काफी ऊपर था।

संगठित क्षेत्र में रोजगार

4.15 रोजगार की वृद्धि में मंदी विस्तृतीय क्षेत्र रहा है। 1980 के दशक में औद्योगिक उत्पादन में त्वरित वृद्धि रोजगार में तदनुसूची वृद्धि से मेल नहीं खाता है। कुल उत्पादन के सम्बंध में रोजगार का लचीलापन कम होता प्रतीत होता है। मार्च 1980 के अंत में संगठित निजी क्षेत्र में कुल रोजगार 72.27 लाख था। यह मार्च 1983 के अंत में 75.52 लाख के उच्च स्तर पर पहुंच गया और इसके बाद यह उस स्तर के अनुरूप बना रहा, यह मार्च 1989 के अन्तिम आंकड़ों के अनुसार 74.78 लाख पर था। निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में गिरावट कुछ ज्यादा स्पष्ट थी। यह मार्च 1982 के अंत में 46.61 लाख के उच्च स्तर से गिरकर मार्च 1988 के अंत में 43.95 लाख पर आ गया, इस प्रकार यह 6 वर्षों की अवधि में 5.7 प्रतिशत की स्पष्ट गिरावट दर्शाता है। इसके बाद जून 1988 तक 42.83 लाख की और गिरावट आई। तथापि, सरकारी क्षेत्र में रोजगार 1980 के दशक में लगातार बढ़ता रहा है, यह मार्च 1976 के 133.32 लाख से बढ़कर मार्च 1984 में 168.69 लाख और मार्च 1989 में और बढ़कर 185.05 लाख हो गया।

4.16 केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किये गये त्वरित अनुमानों के अनुसार संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार मार्च 1989 के अंत में 260.3 लाख रहे और मार्च 1988 के अंत के रोजगार के आंकड़ों की तुलना में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों ने क्रमशः 1.3 प्रतिशत और 0.7 प्रतिशत तक वृद्धि करने की रिपोर्ट की है।

4.17 रोजगार केन्द्रों के चालू रजिस्ट्रारों में नोकरी की तलाश करने वालों की संख्या नवम्बर 1989 के अंत में 325.47 लाख थी जो अक्टूबर 1988 के अंत में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। रोजगार केन्द्रों के माध्यम से अधिसूचित रिक्तियों में 1980-81 में 69.6 से 1985 में 54.2 हजार और अंततः 1988-89 में 44.8 हजार के मामिक औसत के समान रूप कम हो गई है। इसी प्रकार तैनातियों में भी क्रमशः 38.3 से 31.3 और आगे 25.7 हजार के मामिक औसत की कमी आई है जो इन आंकड़ों की विभिन्न सीमाओं के बावजूद पुष्टि करने है कि संगठित उद्योगों में रोजगार का आत्मसात्करण महत्वपूर्ण रूप से कम होना गया है।

नई औद्योगिक नीति

4.18 31 मई, 1990 को घोषित नई औद्योगिक नीति का लक्ष्य रोजगार बढ़ाने, उद्योगों को आसानी क्षेत्रों में फैलाने, सामान्यतया

लघु उद्योगों को बढ़ाने और निर्यात में उनका अंशदान बढ़ाने, आधुनिकीकरण और तकनीकी की कोटि उन्नत करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने के उद्देश्यों में सहायक होने के लिए, औद्योगिक वृद्धि की और पुनः उन्मुख होता है। लघु और कृषि संसाधन उद्योगों की उन्नति पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा नई नीति में लाइसेंस देने, विदेशी सहभागिता और पूंजीगत वस्तुओं, कच्चे माल और पुर्जों के आयात जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से सम्बंधित औद्योगिक अनुसंधानों के लिए कार्यविधि में छूट दी गई है।

4.19 लघु उद्योगों के लिए नई नीति में संयंत्र और मशीनों में निवेश की उच्चतम सीमा बढ़ाने की व्यवस्था की गई है, सहायक इकाइयों के लिए 45 लाख रुपये से बढ़कर 75 लाख रुपये, लघु उद्योगों के लिए 35 लाख रुपये बढ़ाकर 60 लाख रुपये और छोटी इकाइयों के लिए 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है। नीति में लघु उद्योगों को अपना उद्यम आधार व्यापक करने, तकनीकी की कोटि उन्नत करने, अधिक मर्दों (वर्तमान 836 मर्दों के अलावा) के आश्रय की व्यवस्था के लिए कार्यक्रमों को क्षेत्र विस्तार करने और आरक्षित क्षेत्रों में बड़ी इकाइयों द्वारा अधिक्रमण और उत्पन्न की रोकने और कागजी कार्रवाई कम करने के लिए अन्य अनेक उपाय भी शामिल हैं।

4.20 कृषि संसाधन उद्योगों के मामले में नई नीति में उत्पादकों और मसाधकों के बीच संयुक्त स्वामित्व, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के फैलाव को बढ़ावा देकर, श्रृंखला निर्माण में प्राथमिकता और तकनीकी के धाराओं के शीघ्र अनुसंधान द्वारा क्षेत्र में नई तकनीकों के निर्माण, रूपांतरण और उन्हें स्वीकार करने को बढ़ावा देकर निकटतम संपर्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

4.21 गैर-पिछड़े क्षेत्रों में अचल परिसंपत्तियों में 25 करोड़ रुपये के निवेश वाली और केन्द्रीय आधार पर अधिसूचित पिछले क्षेत्रों में 75 करोड़ रुपये वाली सभी नई इकाइयों को लाइसेंस मुक्त करने के उपाय लागू करने हुए लाइसेंस प्राप्त करने/पंजीकरण कराने की अपेक्षा से छूट दे दी गई है। निर्यात संसाधक अंशकों में स्थापित निर्यातमुख्य इकाइयों को 75 करोड़ रुपये की निवेश सीमा तक लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। ऐसे निवेश भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषण पर लागू परिवर्तनीय खण्ड से मुक्त होंगे। यदि रॉयल्टी का भुगतान घरेलू विदेशी पर 5 प्रतिशत और निर्यातों पर 8 प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो विदेशी सहभागिता के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करने से छूट की व्यवस्था की गई है और जहां एकमुश्त भुगतान किया गया है और सरकार की अनुमति अपेक्षित है, वहां निर्यात उद्यमकर्ता को 30 दिनों की अवधि के भीतर सूचित कर दिया जाएगा। तकनीकी के प्रभावी अन्तर्बह के लिए ईक्विटी के 40 प्रतिशत तक विदेशी निवेश को विशिष्ट उद्योगों में स्वतः प्राप्त आधार पर अनुमति दे दी जाएगी। सुझाई गई नियंत्रण छूटों में विस्तार के सभी मामले समाहित होंगे और ये केवल नई इकाइयों तक ही सीमित नहीं होंगे। आगे विस्तृत संघटन वाली मौजूदा योजनाएं लागू बनी रहेंगी।

## 5. श्रृंखला नीति संबंधी गतिविधियां

### नीति की रूपरेखा

5.1 जुलाई 1989 से जून 1990 के दौरान मुद्रा नीति के संकालन में विशेष बात अर्थव्यवस्था के विकास की सम्भाव्यता को जोखिम में डाले बिना मुद्रास्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करना था। कीमतों की स्थिरता के लिए अत्यधिक विस्तार अनेक व्यापक आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न हुई। लगातार दो अच्छी कृषि फसलों और सन्तोषजनक वास्तविक आय में वृद्धि के बावजूद मुद्रास्फीतिकारी दबाव और पकड़ते गए। आम उपयोग की अनेक वस्तुओं तथा अनाज, दालों, तेल, चीनी, लिफ्ट और खाद्यतेलों और दूध से बना वस्तुओं पर क्षेत्रीय दबावों के अनिश्चित मुद्रास्फीतिकारी दबाव सामान्यकृत होते गये। इसके अलावा बाह्य स्टॉक और विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के बर्तमान पर, निकालने से नाशुक चीजों की घरेलू आपूर्ति का आधार भरपूर मात्रा में खाली होता गया 211 GI/91—22

साध-साध मांग की ओर (बड़ी मात्रा में चलनिधि के मुकाबले के शिखर पर, जिसको बिना ऐसी स्थायी मुद्रास्फीति लम्बी अवधि तक बनी रहती) केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा बड़ी तेजी से बढ़ कर ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया जिससे प्राथमिक मुद्रा वृद्धि तथा समग्र चलनिधि में वृद्धि अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंच गई।

5.2 राजकोषीय घाटों से उत्पन्न चलानाध स लागू वृद्धि का उपयुक्त परिवर्ण्य इस तथ्य के कारण बदतर हो गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक का पास उपलब्ध साधनों में चलनिधि नियंत्रण का पारम्परिक साधन मरदा आरक्षित अनुपात सांविधिक उच्चतम सीमा पर पहुंच गया।

5.3 वर्ष की पहली छमाही के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंक ने खाद्योत्पन्न श्रृंखला का बड़ा विस्तार किया, यह राजकोषीय वर्ष 1988-89 के दौरान ऐसे श्रृंखला में हुई बड़ी भारी वृद्धि के शिखर पर था। ऐसा महसूस किया गया था कि 1989-90 में अपेक्षित प्रतिरिक्त श्रृंखला समर्थन पिछले वर्ष में किए गए समर्थन को देखते हुए अधिक नहीं होगा औद्योगिक विकास 1989-90 के मुख्य भाग में धीमा पड़ गया था और पूंजी बाजार तथा गैर-बैंकिंग निधियों के अन्य स्रोतों, विशेष रूप से बड़े आकार वाली कम्पनियों के बढ़े हुए वसूली अधिकार, बैंक श्रृंखला को मांग कर देंगे। ऐसी पुष्टि में श्रृंखला नीति की अवस्थिति खाद्योत्पन्न श्रृंखला के विस्तार की गति को स्पष्टतया नियंत्रित करना था। पूंजी मरदा आरक्षित निधि अनुपात पर सांविधिक उच्चतम सीमा के कारण मौद्रिक नियंत्रण के पारम्परिक लिखतों को उपयोग में नहीं लाया जा सकता था, अतः आरक्षित राशि की वृद्धि की गति को संयंत्र करने के लिए अन्य उपायों पर भरोसा किया गया था। इन उपायों में शामिल थे, निर्यात पुनर्वित्त सुविधा की प्राप्ति में कमी, सांविधिक चलनिधि अनुपात में वृद्धि और वृद्धिशील खाद्योत्पन्न श्रृंखला अनुपात की शर्तें। 1989-90 में शुरू किए गए उपाय समग्र श्रृंखला की मार्गदर्शी सिद्धांतों की 1981-82 तक प्रचलन में थीं, से गुणात्मक रूप में भिन्न थे क्योंकि निश्चित स्तर पर श्रृंखला में किसी वृद्धि से रिजर्व बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त पर प्रतिरिक्त लागत आवश्यक हो जाती। यह अनुमान किया गया था कि आरक्षित निधि में भारी वृद्धि के साथ बैंक जमा राशियों में महत्वपूर्ण विस्तार होगा। जबकि वास्तविक उत्पादक प्रयोजन के लिए श्रृंखला की अपेक्षा की जाएगी, यह श्रृंखला का अति विस्तार था और यह अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की संसाधन क्षमताओं में अधिक था जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। शर्तें यह भी, कि भारतीय रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त की लागत बैंक का वृद्धिशील खाद्योत्पन्न श्रृंखला अनुपात 60 प्रतिशत से अधिक हो जाने की स्थिति में बढ़ जाती। इस प्रकार पुनर्वित्त की लागत पर लागू यह उपाय बैंक के श्रृंखला विस्तार से जोड़ दिया गया था। निर्यात पुनर्वित्त सुविधा से संबंधित उपाय अनिवार्यतः अति उच्च स्तर पर पहुंचे पुनर्वित्त के उपयोग को तुलना करने के लिए किये गये थे। सांविधिक चलनिधि अनुपात में ऊर्ध्वमुखी संशोधन और आरक्षित निधि निर्माण की गति को समुचित करने के विचार से किया गया था।

5.4 वर्ष के दौरान किये गये अन्य नीतिगत उपायों को मोटे तौर पर तीन शीर्षों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है : पहला, वे उपाय जिनका उद्देश्य बैंक के कार्यों में सुदृढ़ अनुशासन और सावधानी धरना है, दूसरा, वे उपाय जो सुदृढ़ लचीलापन खाने और सख्ती कम करने और सामान्यतया मुद्रा और वित्त की बाजार में ज्यादा प्रतियोगी वातावरण निर्मित करने के लिए पहले से ही लागू किये गए अनेक उपायों को आगे बढ़ाने के लिए लागू किये गये थे और तीसरा, अस्थिर भाव वाली वस्तुओं के संबंध में कीमत और उत्पादन वृद्धि के संबंध में लागू किये गये उपाय जहां अस्थिर भाव वाली वस्तुओं पर बैंक अधिमो पर न्यूनतम माजिन और श्रृंखला की उच्चतम सीमाओं के अति तीव्र आसोधन किये गये हैं। पहले वर्ग के उपायों में हैं : जब किसी की वित्त बैंक आपाती या विवेका-मयी पुनर्वित्त सुविधाओं के अधीन रिजर्व बैंक के साथ उधार लेने की

स्थिति में हैं और वे शीघ्रावधि ब्रह्म बाजार में उधार देते हैं तो अतिरिक्त प्रभार लगाया जायेगा, विवेकाधीन पुनर्वित्त सुविधा के लिए यह सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित बहुष्करण अवधि की कुल मौद्रिक राशियों में भाग के अंत में अत्यधिक उथल-पुथल न हो, उधार क्रय और उधार बिक्री के संबंध में बिल प्रक्रिया के प्रयोग के संबंध में अनुदेशों का कड़ाई से पालन करने पर जोर देना ताकि बिल संस्कृति विशेष रूप से ऐसे मीयारी बिलों पर स्टाम्प शुल्क के संदर्भ में सरकार द्वारा छूट दिया जाना, नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात में गिरावट के लिए कमिक वण्ड की योजना में संशोधन के साथ मांग और मीयारी देयताओं के 3 प्रतिशत के ऊपर ब्याज का अधोमुखी संशोधन और "182 दिवसीय खजाना बिल" पुनर्वित्त पर ब्याज दर में वृद्धि। दूसरे वर्ष में ऐसे उपाय प्राप्त हैं जो बैंकों की उनके परिवर्तनों यथा, बैंकों द्वारा सावधि ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज की दर में लचीलेपन का उपाय करना, अल्पकालीन जमा दर में इस प्रकार वृद्धि करना ताकि 46 वित्तों और उससे ऊपर किन्तु एक वर्ष से कम की सभी देशी मीयारी जमा राशियों पर 8.0 प्रतिशत का ब्याज लगे और 8.5 प्रतिशत पर नियत प्रतिवर्षी बाह्य जमा राशियों के लिए ब्याज दर का समान सुवृत्तीकरण, मांग सूचना मुद्रा बाजार में साहकारों के रूप में सहभागियों की सख्या में वृद्धि, और जमा प्रमाणपत्रों और वाणिज्यिक प्रपत्र जारी करने के लिए भार्गवर्षी सिद्धांतों को, प्राथमिक बाजार का आधार विस्तृत करने और इन लिखतों के लिए माध्यमिक बाजारों के विकास को प्रोत्साहन देने को भी ध्यान में रखते हुए, उधार बनाना।

5.5 अवधि के दौरान किये गये ऋण नीति उपायों का विवरण क्रमवार नीचे दिया गया है।

जुलाई 1989 गेहूँ, जौ, गुड़ और खादसारी पर अधिमों पर अल्पकालिक ऋण नियंत्रण

5.6 कोमत-उत्पादन गतिविधियों की समीक्षा करने पर अल्पकालिक ऋण नियंत्रणों से संबंधित प्रावधानों में 20 जुलाई 1989 से निम्नलिखित आशोधन किये गये थे (1) गेहूँ के स्टॉक पर अधिमों की न्यूनतम सीमाएं 15 प्रतिशत बिन्दु तक सपाट (एकांस दी बोर्डे) कम कर दी गई थी। (2) संसाधन एकाइयों/मिलों के लिए जीनी के स्टॉक पर अधिमों की न्यूनतम सीमाएं न निकाले गये स्टॉक के मामले में 7.5 प्रतिशत बिन्दु तक बढ़ा दी गयी थी जबकि जीनी के जागी कर दिये गये स्टॉक पर न्यूनतम सीमाएं सपाट 15 प्रतिशत बिन्दु तक बढ़ा दी गई थी। गुड़ और खादसारी के स्टॉक पर अधिमों की न्यूनतम सीमाएं भी सपाट 15 प्रतिशत बिन्दु तक बढ़ा दी गई थी।

अक्टूबर 1989-90 की दूसरी छमाही के लिए नीतिगत उपाय

5.7 यह अनुभव किया गया था कि वास्तविक क्षेत्र में अनुकूल सुधारों के बावजूद कीमतों में उफान बिस्ता का विषय था। इस प्रकार 1989-90 की पहली छमाही में कच्चे स्कीतिकारी वबाधों और बड़े मुद्रागत विचार के पृष्ठभूमि पर 1989-90 की दूसरी छमाही के लिए ऋण नीति की स्थिति पर अवरोध आना अवश्यम्भावी थी। विशेष रूप से, 1989-90 की दूसरी छमाही में खाद्यतर ऋण के विस्तार की गति में संतुलन की नितान्त आवश्यकता थी। इसी संदर्भ में नीचे दिये गये नीतिगत उपाय अक्टूबर, 1989 में घोषित किये गये थे।

(क) निर्यात ऋण पुनर्वित्त

5.8 निर्यात ऋण पुनर्वित्त की सीमाओं की राशि 22 सितम्बर 1989 को 3,770 करोड़ रुपये या शेष निर्यात ऋण का 52 प्रतिशत थी। समग्र मौद्रिक और ऋण स्थिति और प्रारक्षित निधि की वृद्धि में कटौती की आवश्यकता पर विचार करते हुए काफी बड़ी पुनर्वित्त सीमाओं को कम करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। तदनुसार, बैंकों को 4 नवम्बर, 1989 से अब तक की 100 प्रतिशत के बजाय 1987 के मासिक औसत पर निर्यात ऋण में 75 प्रतिशत की वृद्धि के समकक्ष निर्यात ऋण पुनर्वित्त प्रदान किया गया था।

(ख) वृद्धिशील निवल खाद्यतर ऋण-जमा अनुपात

5.9 1988-89 में यह देखा गया था कि अनेक बैंकों का वृद्धिशील निवल खाद्यतर ऋण जमा अनुपात उनके निजी संसाधनों द्वारा समर्थित अनुपात की तुलना में काफी अधिक था। विद्यमान मुद्रागत और ऋण की स्थिति के संदर्भ में बैंकों के खाद्यतर ऋण विस्तार को संतुलित करना आवश्यक समझा गया था। अतः एव, यह निर्दिष्ट कर दिया गया था कि प्रत्येक बैंक यह सुनिश्चित करें कि राजकोषीय वर्ष 1989-90 के दौरान उसका वृद्धिशील निवल खाद्यतर ऋण-जमा अनुपात 60 प्रतिशत से अधिक न होने पाये। जिन बैंकों का अनुपात इससे अधिक था, उन पर निर्दिष्ट अनुपात या प्राप्ति पुनर्वित्त के ऊपर अधिक निवल खाद्यतर बैंक ऋण, जो भी कम हो, की सीमा तक सभी सुविधाओं (निर्यात ऋण, माध्यमिक विवेकाधीन और 182 दिवसीय खजाना बिल) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्ति पुनर्वित्त पर 3 प्रतिशत बिन्दु का अतिरिक्त ब्याज लगाया गया था। यह प्रभार 4 नवम्बर 1989 से प्रारम्भ होने वाले पखवाड़े से लगाया गया था। वृद्धिशील निवल खाद्यतर ऋण-जमा अनुपात 24 मार्च 1989 के संदर्भ में प्रत्येक पखवाड़े निकाला गया था क्योंकि आधार और अतिरिक्त प्रभार जहाँ लागू हैं, पाक्षिक आधार पर लगाया गया था।

5.10 15 प्रतिशत की नकदी प्रारक्षित आवश्यकता और 38 प्रतिशत सांख्यिक चलनिधि अनुपात की व्यवस्था के बाद वृद्धिशील जमा राशियों को केवल 47 प्रतिशत ही खाद्य और खाद्यतर ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध होगा। 1989-90 के लिए 60 प्रतिशत वृद्धिशील निवल खाद्यतर ऋण जमा अनुपात की शर्त से बैंकों को अन्य स्त्रोतों से पुनर्वित्त और मुद्रा बाजार उधार के माध्यम से अतिरिक्त समाधनों की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त दी गई थी। चूंकि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वृद्धिशील निवल खाद्यतर ऋण-जमा अनुपात 1989-90 की पहली छमाही में 35 प्रतिशत था, संपूर्ण वर्ष के लिए 60 प्रतिशत की शर्त से यह प्रतीत होता था कि वह की दूसरी छमाही में बैंकिंग प्रणाली को 85 प्रतिशत की वृद्धि निवल खाद्यतर ऋण-जमा अनुपात प्राप्त हो सकता है। परिणामतः 1989-90 में बैंकिंग प्रणाली के लिए वृद्धिशील निवल खाद्यतर ऋण-जमा अनुपात 57.8 प्रतिशत था (प्राप्त घा) कुछ बैंक 60 प्रतिशत की शर्त से ऊपर चले गये जिसके लिए उन पर रिजर्व से प्राप्त पुनर्वित्त पर उच्चतर ब्याज दर लगाई गई।

(ग) सावधि ऋणों पर ब्याज दर

5.11 बैंकों द्वारा दिये गये कार्यशील पूंजीगत ऋणों पर उधार ब्याज दरों के संबंध में अक्टूबर 1988 में लागू किये गये उपायों के अनुसूप और लागू की गई ब्याज दरों की संरचना को और लचीला बनाने के उपाय लागू करने तथा सावधि ऋणों के उपयोग में कार्यक्षमता की वृद्धि करने के लिए 15.0 प्रतिशत नियत (की ब्याज दर वाले सभी सावधि ऋणों को किसी उच्चतम सीमा की शर्त के बिना न्यूनतम 15.0 प्रतिशत पर रखा गया था। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की 11 अक्टूबर 1989 से प्रभावी सावधि ऋण की ब्याज की दरों में परिवर्तन निम्नलिखित हैं :

(प्रतिशत प्रतिवर्ष)

वर्ग	10 अक्टूबर 1989 तक प्रभावी	11 अक्टूबर 1989 से प्रभावी
अन्य सभी सावधि ऋण	15.0 (नियत)	15.0 (न्यूनतम)
3 या अधिक वाहनों वाले सड़क परिवहन	15.0 (नियत)	15.0 (न्यूनतम)
परिचालक		

बैंकों को सूचित किया गया था कि वे भिन्न दरों पर ब्याज लेने के विवेकाधिकार का व्यापक प्रयोग करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके

कि लगाई गई व्याज दरें उचित सीमाओं के भीतर हों, प्राथमिकता प्राप्त विचारों पर आधारित 15 प्रतिशत से नीचे बाकी व्याज दरें अपरिवर्तित बनी, रही ये कृषि, लघु उद्योग, सड़क परिवहन परिवारिकों (2 गाहनों तक) बेजरूमि विकास सावधि ऋणों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यवसायियों और स्वयंयोजित व्यक्तियों को सावधि ऋणों और व्यवसायियों और स्वयंयोजित महिलाओं और विशेष कार्यक्रमों को सावधि ऋणों से सम्बंधित थी।

#### (घ) आवास के लिए सावधि ऋणों पर व्याज

5.12 1 लाख रुपए से ऊपर के आवास के लिए सावधि ऋणों पर व्याज की दर मार्च 1989 तक 14.5 से 16.0 प्रतिशत के बीच निर्धारित की गई थी और शर्तों के अनुसार बैंक 3 लाख रुपए से अधिक राशि के ऐसे ऋण व्यक्तियों को नहीं दे सकते थे। छोटे घरों के वित्त पोषण की तीव्र आवश्यकता और व्यक्तियों को 3 लाख रुपए से ऊपर के ऋण मंजूर करने के लिए वास्तविक मामलों की संभाव्यता को स्वीकार करते हुए 3 लाख रुपए की उपर्युक्त उच्चतम सीमा वापस ले ली गई थी। साथ ही बैंकों को 3 रुपए से अधिक के आवास ऋणों पर व्याज की उच्चतर दर लगाने के विवेकाधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देना उचित समझा गया था, अतः ऐसे ऋणों को 16.0 प्रतिशत की न्यूनतम व्याज दर के अधीन रखा गया था और ऐसे ऋणों के लिए व्याज दर को कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

#### आवास ऋणों पर व्याज दरें

10 अक्टूबर 1989 तक प्रभावी ऋण की राशि	व्याज की दर (प्रतिशत प्रतिवर्ष)	11 अक्टूबर 1989 से प्रभावी ऋण की राशि	व्याज की दर (प्रतिशत प्रतिवर्ष)
1 *लाख रुपए से ऊपर	14.5-16.0	1 लाख रुपए से ऊपर और 3 लाख रुपए तक	14.5-16.0
		3 लाख रुपए से ऊपर	16.0 न्यूनतम

\*एक व्यक्ति को ऋण की अधिकतम राशि 3 लाख रुपए थी।

#### जमा दरें

5.13 अल्पकालीन जमा राशियों पर प्रतिशत के बेहतर संरक्षण के लिए 48 दिनों से 90 दिनों के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सावधि जमा राशियों (विदेशी मुद्रा अभिवासी खाता/अनिवासी बाह्य खातों को छोड़कर) पर व्याज की दर 8.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.0 प्रतिशत कर दी गई थी। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप 48 दिनों और उससे ऊपर किन्तु एक वर्ष से कम की अवधि के लिए जमा दर 8.0 प्रतिशत हो गई।

#### (च) पुनर्वित्त और मुद्रा बाजार परिचालन

5.14 बैंकों को अक्टूबर 1987 में सतर्क किया गया था कि वे रिजर्व बैंक से साथ-साथ पुनर्वित्त आह्वित न करें और मुद्रा बाजार में उधार की न दें। यह निर्णय किया गया था कि यदि बैंक 21 अक्टूबर 1989 से मांग मुद्रा बाजार (राशि पर्याप्त मांग मुद्रा और 14 दिन तक और 14 दिन की अवधि के लिए अल्प सूचना मुद्रा) में किसी दिन उन पर सहायक और/या विवेकाधीन पुनर्वित्त सुविधाओं के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक से लिया गया ऋण बकाया था उधार देते हैं तो ऐसे उधारों पर प्रतिशत व्याज लगाया जाएगा। अतिरिक्त व्याज दर इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि प्रभावी पुनर्वित्त दर भारतीय मिलाकाटा और वित्त गृह लिमिटेड की मांग मुद्रा उधार दर से 3 प्रतिशत दर दिवस अधिक होगी। अतिरिक्त प्रभार आह्वित वित्त या मुद्रा बाजार, जो भी न्यून हो, में उधार दी गई राशि पर लगाया जाता है। शर्तों के गम्भीर उल्लंघनों के मामले में सहायक और विवेकाधीन पुनर्वित्त सुविधाएं वापस ले ली जाएगी।

#### (छ) विवेकाधीन पुनर्वित्त सुविधा के लिए व्यवधान-अवधि

5.15 बैंकों ने मार्च 1989 के अंतिम सप्ताह में समाप्त होने वाले वर्ष के अंत के दौरान दोनों जमा राशियों और ऋण में उल्लेखनीय भारी वृद्धि की सूचना दी थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कुल मैट्रिक राशियों में मार्च के अंत में उपलब्ध न हो, यह निर्णय किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण अनुमति के बिना विवेकाधीन पुनर्वित्त आह्वित करने की सुविधा 24 मार्च से 6 अप्रैल 1990 तक के पूरे पखवाड़े के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उपलब्ध नहीं होगी। विवेकाधीन पुनर्वित्त सुविधा के अधीन जिन बैंकों का उधार बाकी था, उनके लिए यह घोषित था कि वे 24 मार्च 1990 को या इसके पूर्व इस सुविधा के अधीन किसी भी बकाया राशि की प्रदायगी कर दें और 24 मार्च से 6 अप्रैल 1990 की अवधि के दौरान पूर्ण अनुमति के बिना आह्वितों को अनुमति नहीं दी।

दिसम्बर 1989 में, रई और कपास तथा चीनी, गुड़ और खाइसारी पर ऋणों पर जयनात्मक ऋण नियंत्रण

5.16 क्रोम-उत्पादन गतिविधियों की समीक्षा करने पर जयनात्मक ऋण नियंत्रणों के कुछ प्रावधानों को संशोधित करना उचित समझा गया था। तदनुसार, 30 दिसम्बर 1989 से निम्नलिखित उपाय शुरू किये गये थे।

(क) गेहूं : गेहूं पर बैंक ऋणों पर ऋण की उच्चतम सीमा का स्तर किसी पार्टी द्वारा तीन वर्षों (नवम्बर-अक्तूबर) 1984-85, 1985-86 और 1986-87 में से किसी एक वर्ष में बनाए रखे गये ऋण के उच्च स्तर के 85 प्रतिशत के उस समय के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया था। गेहूं पर ऋणों की ऋण-उच्चतम सीमाओं का बढ़ा हुआ रोकथाम घाटा मिला समेत सभी पार्टियों पर लागू किया गया था।

(ख) रई और कपास : रई और कपास पर बैंक ऋणों को ऋण उच्चतम सीमा का स्तर किसी पार्टी द्वारा तीन वर्षों (नवम्बर-अक्तूबर) 1984-85, 1985-86 और 1986-87 में बनाए रखे गये ऋण के उच्च स्तर के 85 प्रतिशत के उस समय के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके अलावे रई और कपास के स्टॉक पर बैंक ऋणों पर लागू न्यूनतम मार्जिनों को "अस्थिर" के मामलों में 45 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया था, इस प्रकार "अस्थिर" को रई के स्टॉक पर ऋणों और रई के स्टॉक समेत मानगोशम प्राप्ति पर एक समान रूप से 30 प्रतिशत पर रखा गया था।

(ग) चीनी, गुड़ और खाइसारी : संसाधन इकाइयों/मिनों के मामले में चीनी के न निकाले गये स्टॉक पर बैंक ऋणों पर लागू न्यूनतम मार्जिनों को 25 प्रतिशत की शर्त से कम करके 20 प्रतिशत कर दिया गया था। चीनी, गुड़ और खाइसारी पर सभी अन्य बैंक ऋणों पर लागू न्यूनतम सीमाएं अपरिवर्तित हैं।

12 अप्रैल 1990 1990-91 की पहली छमाही के लिए नीतिगत उपाय

5.17 वित्त वर्ष 1990-91 की छमाही के लिए ऋण नीति अप्रैल 1990 में बनाई गई थी। नीति हाथ के वर्षों में प्रारंभित निधि और समय चलनिधि में भारी वृद्धि तथा क्रोमतों पर अनुवर्षी प्रदायों से अर्थ-व्यवस्था पर समन्वित प्रभाव की पुष्टि पर आधारित है। 1989-90 (अप्रैल-मार्च) को समाप्त होनेवाले पांच वर्षों के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की वार्षिक औसत दर के 5.8 प्रतिशत के स्तर पर बने रहने का अनुमान था, जबकि समन्वित चलनिधि 17.6 प्रतिशत तक बढ़ गई। बैंकिंग प्रणाली द्वारा प्रकृत बाह्यतर ऋण 1988-89 में 22.8 प्रतिशत और 1989-90 में 17.4 प्रतिशत तक बढ़ गये। सांविधिक पूर्वकथ अधिकारों के राजस्व जमा राशियों में भारी वृद्धि के साथ वाणिज्य

ओं को बैंकिंग प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराया गया ऋण पर्याप्त से अधिक था। वास्तव में वर्ष के प्रमुख हिस्से के दौरान उद्योग में वृद्धि दर की पुष्टि पर विचार करें तो यह अत्यधिक थी।

5.18 यह मानते हुए कि 1990 में मानसून अनुकूल रहेंगे और 1990-91 में औद्योगिक उत्पादन 1989-90 में हुई वृद्धि की दर की तुलना में कुछ वृद्धि दर्शावेगा मसूदा किया गया था कि 1990-91 में अर्थ-व्यवस्था की लगभग 5 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दर के आधार पर योजना बनाना बेहतर रहेगा। 1989-90 में चलनिधि के बड़े मुकाब और मुद्रा-स्फीति के पुनर्स्थापन को देखते हुए मुद्रा स्फीतिगत अपेक्षाओं में तीव्र श्रवरोध लाना आवश्यक था। राजकोषीय पक्ष में लक्ष्यों के अनुरूप, समग्र बजट घाटे की 1989-90 में 11,750 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 1990-91 में कम करके 7,200 रुपये करोड़ लाना मौद्रिक प्रबंध का उद्देश्य 1990-91 में समग्र मुद्रा विस्तार (एम 3) की गति में 1989-90 में 19.4 प्रतिशत (उम समय उपलब्ध अनंतिम आंकड़े) की अत्यधिक उच्च संख्या से लगभग 4 प्रतिशत बिन्दु तक की तीव्र कटौती करना था।

5.19 अनुसूचित आगोज्य बैंकों को सुविधा किया गया था कि व 1990-91 के दौरान 27,500 (16.6 प्रतिशत) करोड़ रुपये की कुल जमा वृद्धि के कार्यकारी अनुमान के आधार पर अपने ऋण बजट की योजना बनाएं। जमावृद्धि की मौसमी प्रवृत्ति के आधार पर 1990-91 की पहली छमाही के दौरान कुल जमा राशियों में वृद्धि पहली तिमाही (अप्रैल-जून 1990) में 6,800 करोड़ रुपये अनुमानित थी। चूंकि 1990 की रबी गेहूं की फसल अच्छी थी, अतः करीबन 11 मिलियन टन की भारी बसूली प्रत्याशित थी। अतएव, यह अनुमान किया गया था कि 1990 को समाप्त तिमाही के दौरान खाद्य ऋण 1,600 करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगा और सितम्बर, 1990 को समाप्त तिमाही में लगभग 700 करोड़ रुपये कम हो जायेगा। 1990-91 की पहली छमाही के दौरान खाद्योत्तर ऋण में वृद्धि लगभग 4,800 करोड़ रुपये (4.9 प्रतिशत) अप्रैल और जून 1990 की तिमाही में 2,400 (2.4 प्रतिशत) करोड़ रुपये होने की आशा थी।

5.20 1990-91 की पहली छमाही के समग्र उपाय वृद्धिशील अर्थ व्यवस्था की वास्तविक ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए चलनिधि में वृद्धि और ऋण विस्तार के संतुलन को नियंत्रित करता था।

वृद्धिशील निवल खाद्योत्तर ऋण जमा अनुपात को बनाये रखना

5.21 वृद्धिशील निवल खाद्योत्तर ऋण जमा अनुपात की शर्त जो 1989-90 की दूसरी छमाही में शुरू की गई थी, 1990-91 में बनी रही और आधार तिथि 23 मार्च 1990 तक लागू रही थी। बैंकों के मामले में सभी सुविधाओं के अंतर्गत रिजर्व बैंक से प्राप्ति पुनर्वित्त पर 4 प्रतिशत बिन्दु प्रतिरिक्त व्याज प्रभार जो निविष्ट अनुपात से अधिक है, 21 अप्रैल 1990 को प्रारंभ पञ्चवाड़े से प्रभावी हो गया।

उपायों में परिवर्तन (क) सांघिक चलनिधि अनुपात

5.22 उपायों में किये गये परिवर्तन निम्नलिखित थे।

5.23 सितंबर 1990 को प्रारंभ पञ्चवाड़े से प्रारंभित निधि निर्माण और मौद्रिक विस्तार की गति को मर्यादित करने में सहायता करने के लिए सांघिक चलनिधि अनुपात को निवल मांग और सांघिक वेधताओं के एक प्रतिशत बिन्दु के आधे तक बढ़ाकर 38.0 प्रतिशत से 38.5 प्रतिशत कर दिया जाएगा। अनिवासी (विदेशी) रुपया खाता और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता के सदर्थ में 25 प्रतिशत के सांघिक चलनिधि अनुपात को भी 28 जुलाई 1990 को प्रारंभ पञ्चवाड़े से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया जाएगा। ये दो उपाय सांघिक चलनिधि अनुपात की आवश्यकताओं को लगभग 1,800 करोड़ रुपये या निवल मांग और सांघिक वेधताओं के एक प्रतिशत बिन्दु तक बढ़ा देगे। एक सीमा तक बाजार से उधार लेने के कार्यक्रम को बदला नहीं गया है, सांघिक चलनिधि अनुपात में वृद्धि मौद्रिक नियंत्रण के प्रभावी साधन के रूप में कार्य करेगी।

(ख) पुनर्वित्त सुविधाएं

(i) निर्यात ऋण पुनर्वित्त

5.24 23 मार्च 1990 का निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाओं की राशि 3,564 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई जो बकाया निर्यात ऋण के 43.6 प्रतिशत के बराबर है। निर्यात पुनर्वित्त निर्धारित करने के लिए प्रत्येक वर्ष को आधार के रूप में आगे लाने की सामान्य प्रवृत्ति रही है। बैंकों को 25 अगस्त 1990 से फेब्रुअरी वर्ष 1987 के मासिक औसत स्तर के बजाय वित्त वर्ष 1988-89 के लिए निर्यात ऋण के मासिक औसत स्तर पर निर्यात ऋण में 75 प्रतिशत वृद्धि के समकक्ष निर्यात ऋण पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा। यद्यपि बैंकों की पुनर्वित्त सीमाएं प्रारंभ में कम कर दी जाएंगी, विगत का अनुभव यह दर्शाता है कि निर्यात ऋण पुनर्वित्त की उनकी पहुंच तेजी से कम हो जाएगी क्योंकि वे निर्यात ऋण में वृद्धि करते हैं और इस प्रकार बैंकों की पुनर्वित्त सीमाएं व्यस्त मोसम के प्रारंभ के पूर्व एक बार पुनः बढ़ेंगी।

(ii) 182 दिवसीय खजाना बिल पुनर्वित्त

5.25 182 दिवसीय खजाना बिलों की नीलामियों में हुई उच्चतम आय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस सुविधा के अंतर्गत पुनर्वित्त पर ब्याज की दर 16 अप्रैल 1990 से बढ़ाकर 10.75 प्रतिशत से 11.75 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी गई।

(ग) वयनात्मक ऋण नियंत्रण

5.26 वयनात्मक ऋण नियंत्रणों के क्षेत्र में 16 अप्रैल 1990 से निम्नलिखित परिवर्तन किये गये :

(i) गेहूं पर न्यूनतम मार्जिन : गेहूं से संबंधित कीमत उत्पादन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए गेहूं पर सभी बैंक अधिमों की न्यूनतम मार्जिन (रोलर भाटा मिलों को अधिमों सेते) सपाट 15 प्रतिशत बिन्दु तक घटा दी गई।

(ii) रुई और कपास पर अधिमों के लिए छूट : आपूर्ति की स्थिति में स्पष्ट सुधार के संदर्भ में रुई और कपास पर सभी अधिमों को वयनात्मक ऋण नियंत्रण के प्रावधानों से छूट दे दी गई।

(iii) ऋण की उच्चतम सीमाओं का स्तर : ऐसे पण्यों के लिए जहां 1984-85 से 1986-87 (नवंबर-अक्तूबर) तीन वर्षों की अवधि पर आधारित ऋण की उच्चतम सीमाओं के स्तर की शर्त थी, आधारभूत अवधि दो वर्ष आगे लाकर 1986-87 से 1988-89 की तीन वर्ष की अवधि पर लाया गया।

(घ) अनिवासी (विदेशी) रुपया खातों के अंतर्गत जमा राशियों पर ब्याज दरें

5.27 एक वर्ष से कम की अवधियों के लिए घरेलू सांघिक जमा-राशियों पर ब्याज दरों और परिपक्वताओं के युक्तीकरण के अनुश्रव अनिवासी (विदेशी) रुपया खाता की सांघिक जमा दरों और परिपक्वताओं का भी युक्तीकरण किया गया। 15 दिनों से 45 दिनों के बीच की परिपक्वता सीमा 16 अप्रैल 1990 से समाप्त कर दी गई और 8.5 प्रतिशत की एक समान दर 45 दिनों से लेकर 1 वर्ष से कम की परिपक्वताओं की सभी सांघिक जमा राशियों पर लागू कर दी गई। दीर्घकालिक परिपक्वताओं पर लागू ब्याज दरें अपरिवर्तित बनीं रहीं।

(ङ) रिजर्व बैंक के पास बैंकों की सकयी शेष राशियों पर ब्याज

5.28 रिजर्व बैंक के पास बैंकों द्वारा रखी गई सभी पाठ सकयी शेष राशियों पर अब तक 10.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रदा किया गया था। 21 अप्रैल 1990 से प्रारंभ पञ्चवाड़े से ब्याज वृद्धि-स्तरिक पाठों पर प्रदा किया जाता है। (i) 23 मार्च 1990 को निवल मांग और



सावधि जमाराशियों पर आधारित पात्र नकदी शेष राशियों पर 10.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर व्याज भरा दिया जाएगा; (ii) 23 मार्च 1990 के बाद निवल भाग और सावधि जमाराशियों में वृद्धि के मामले में रखी गई पात्र नकदी शेष राशियों पर 8.0 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर व्याज भरा दिया जाएगा। नकदी शेष राशियों पर व्याज का भुगतान मोट्रिक नियंत्रण को कम करना है जिसे नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात का निखल प्राप्त करने का प्रयास करना है और पात्र नकदी शेष राशियों पर कम व्याज पर वर ज्यादा प्रभावी नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात तैयार करती है, हालांकि इस उपाय का प्रभाव बहुत कमिक होगा।

(क) प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमियों के लिए क्रमिक दंडों की योजना में संशोधन

5.29 उपर्युक्त रूप से प्रारंभ की गई नकदी शेष राशियों पर व्याज दर की अन्तर्-मन्त्रीय संरचना में प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी के लिए क्रमिक दंडों की योजना के लिए पेशीदशियां थी। अतएव, योजना को संशोधित कर दिया गया था और संशोधित योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं: प्रथम, प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी के मामले में बैंक 23 मार्च 1990 के बाद निवल मांग और सावधि जमाराशियों में वृद्धि पर रखी गयी अपनी पात्र नकदी शेष राशियों पर कोई व्याज नहीं खोएंगे बशर्ते कमी उस स्तर पर नहीं थी जहाँ पात्र नकदी शेष राशियों पर व्याज की हानि के अलावा बंडात्मक व्याज लिया गया था। दूसरे, क्रमिक दंडों की योजना अपेक्षित प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की संपूर्ण राशि के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई थी। तीसरे, व्याज की क्रमिक हानि कम सीमा कर दी गई थी। चौथे उन मामलों में जहाँ कमी अपेक्षित प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की संपूर्ण राशि के 10 प्रतिशत से अधिक थी, पात्र नकदी शेष राशियों (23 मार्च 1990 के बाद निवल मांग और सावधि देयताओं में वृद्धि से संबंधित ऐसी शेष राशियों समेत) पर कोई व्याज भरा नहीं दिया जाएगा और बंड, चुक की राशि पर भी लागू होगा। संशोधित योजना में कमी की लागत को कम करने की व्यवस्था है बशर्ते कमी उचित सीमाओं के भीतर हो। नकदी शेष राशियों पर क्रमांकित व्याज दरों की संशोधित अनुसूची नीचे दी गई है।

#### (छ) मांग मुद्रा बाजार में पहुंच

5.30 मांग और नोटिस मुद्रा बाजार को फैलाने की ध्यान में रखते हुए भारतीय साधारण बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की 2 मई 1990 से केवल ऋणदाता के रूप में मांग/नोटिस मुद्रा बाजार में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। जब तक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और सहकारी बैंकों तथा भारतीय मितिकाटा और विल गृह विनिर्देश को मांग/नोटिस मुद्रा बाजार में ऋणदाता और ऋणकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई थी तब तक जीवन बीमा निगम और भारतीय युनिट ट्रस्ट को केवल ऋण-दाताओं के रूप में कार्य करने की अनुमति थी।

5.31 मांग मुद्रा बाजार में विशेष रूप से मार्च 1990 के अंत के करीब पर्याप्त परिवर्तनीयता थी। यह व्यापक रूप से कतिपय बैंकों की अति विस्तृत ऋण स्थिति के कारण थी जिन्हें कतिपय दिनों में बड़ी राशियां उधार लेना पड़ा। अतिविस्तृत ऋण स्थितियों वाले बैंकों को सूचित किया गया है कि वे मांग मुद्रा बाजार पर अपनी दीर्घकालिक और बड़े आश्रय को ठीक करने के लिए संरचनात्मक समायोजन करें। मांग मुद्रा बाजार में सहभागियों और सभी प्रारक्षित निधि अनुपात में कमियों पर दंडों को कम करने में वृद्धि से भी मुद्रा बाजार में व्याज दर की ऊँचाईयों को संतुलित करने में सहायता मिलनी चाहिए। उदाहरणस्वरूप, क्रमांकित दंडों की पिछली अनुसूची के आधार पर कमी की लागत 5 प्रतिशत की कमी के लिए लगभग 130 प्रतिशत थी जबकि संशोधित अनुसूची के अंतर्गत दंड लगभग 30 प्रतिशत होगा।

प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के रखरखाव में कमी—7 अप्रैल 1990 से लागू नकदी शेष राशियों पर क्रमिक व्याज दरों की अनुसूची

6 अप्रैल 1990 तक		7 अप्रैल 1990 से प्रभावी	
अपेक्षित प्रारक्षित नकदी निधियों की संपूर्ण राशि के प्रतिशत के रूप में पखवाड़े के दौरान कमी (तक और उसे शामिल करके)	वस्तुतः रखी गयी 3 प्रतिशत की सांविधिक न्यूनतम के ऊपर की राशि पर देय व्याज की दर (प्रतिशत प्रति वर्ष)	रखे जाने के लिए अपेक्षित नकदी की संपूर्ण राशि के प्रतिशत के रूप में पखवाड़े के दौरान कमी (तक और उसे शामिल करके)	23 मार्च 1990 को निवल की निवल मांग और सावधि देयताओं पर वस्तुतः रखे गये 3 प्रतिशत के सांविधिक न्यूनतम के ऊपर की राशि पर देय व्याज की दर
0	10.50	0	10.50
0.5	10.25	2.0	10.00
1.0	10.00	4.0	9.25
1.5	9.50	6.0	8.50
2.0	8.75	8.0	7.00
2.5	7.75	10.0	6.00
3.0	6.50	10.0 अधिक से	0
3.5	5.00		
4.0	3.00		
4.5	1.25		
5.0	0.50		
5.0 अधिक से	0		

#### (ज) जमा प्रमाण पत्र

5.32 जमा प्रमाण पत्रों के लिए प्राथमिक बाजार का आधार विस्तृत करने और माध्यमिक बाजार के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा जमा प्रमाण पत्रों को जारी करने की सीमा 1988-89 की पाक्षिक औसत बकाया कुल जमाराशियों के 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 1989-90 की पाक्षिक औसत बकाया कुल जमाराशियों के 2 प्रतिशत तक कर दी गई थी। इस प्रकार, बैंकिंग प्रणाली की समग्र सीमाएं 1,264 करोड़ से बढ़ाकर 3,017 करोड़ कर दी जाएंगी। इसके अग्रे जमा प्रमाण पत्रों का मूल्य वर्ग पहले निविष्ट किये गये अनुसार 25 लाख रुपये की तुलना में 10 लाख रुपये के गुणकों में हो सकते हैं परन्तु एक निगम के लिए कम से कम राशि 50 लाख रुपये (पहले एक करोड़ रुपये) हो सकती है।

#### (झ) वाणिज्यिक पत्र

5.33 वाणिज्यिक पत्र के निर्गम के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों को प्राथमिक बाजार के आधार को विस्तृत करने और माध्यमिक बाजार के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए भी शिथिल कर दिया गया था। मार्गदर्शी सिद्धांतों में 24 अप्रैल 1990 से निम्नलिखित परिवर्तन किये गये थे:

(i) जमा प्रमाण पत्र जारी करने वाली कंपनी की निवल मूल लागत पहले निविष्ट किये गये अनुसार 10 करोड़ रुपये की तुलना में न्यूनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार 5 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए।

(ii) कंपनी की कार्यशील पूंजी (निधि आधारित) की सीमाएं पहले निविष्ट किये गये अनुसार 25 करोड़ रुपये से कम की तुलना के बजाय 15 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए।

(iii) "ग्राइमिल" से न्यूनतम अणु निष्पन्न पिछली भारीदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्दिष्ट पी 1 + के बजाय पी 1 होना है ।

(iv) वाणिज्यिक पत्र का मूल्यवर्ग 25 लाख रुपये के बजाय 10 लाख रुपये के गुणको से हो सकता है मूल्य एक निर्धारित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए । अर्थात् रूप (अर्थात् मूल्य) के बजाय 50 लाख रुपये (अर्थात् मूल्य) हो सकती है ।

मई 1990 तिलहन और वनस्पति तेलों के अग्रिमों पर चयनात्मक अणु नियंत्रण जुलाई 1990 गेहूँ, ज्वार और वनस्पति तेलों के अग्रिमों पर चयनात्मक अणु नियंत्रण

5.34 तिलहन और वनस्पति तेलों (वनस्पति सहित) से संबंधित कीमत उत्पादन गतिविधियों की समीक्षा करने पर इन पन्नों पर बैंक अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन 4 मई 1990 से सपाट 15 प्रतिशत बिल्कुल तक बढ़ा दिया गया था ।

5.35 गेहूँ, तिलहन और वनस्पति तेलों में संबंधित कीमत उत्पादन गतिविधियों की समीक्षा करने पर चयनात्मक अणु नियंत्रण के प्रावधानों में 2 जुलाई 1990 से निम्नलिखित आशोधन किये गये थे । गेहूँ पर सभी अग्रिमों को चयनात्मक अणु नियंत्रण के सभी प्रावधानों से छूट दे दी गई थी । गेहूँ पर अग्रिमों की यह छूट गोलम आटा मिलों सहित सभी पाटिया के मामले में लागू होगी । तिलहन और वनस्पति तेलों पर बैंक अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन सपाट 15 प्रतिशत बिल्कुल तक बढ़ा दी गई था ।

5.36 चयनात्मक अणु नियंत्रणों के अधीन न्यूनतम मार्जिन और पन्नों पर बैंक अग्रिमों पर अणु की उच्चतम सीमाओं का हार निम्नलिखित है—

चयनात्मक अणु नियंत्रण के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले पन्नों के प्रति बैंक अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन और अणु की उच्चतम सीमा का स्वर

(2 जुलाई 1990 से लागू)

(प्रतिशत)

न्यूनतम मार्जिन मिले 'अन्य' बाजार अभिमर्शक इकाइयों	अणु की उच्चतम सीमाओं का स्तर बाजार वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89			
1	2	3	4	5
1 धान/चावल	45	60	15	85
2 दालें	45	60	45	85
3 अन्य खाद्यान्न	45	60	45	85
4 तिलहन, (मूँगफली, तौरिया/ सरसों, बिमोला, अलसी, अरुण्डो तथा सभी आयातित तिलहन)	60	75	60	100
5 वनस्पति तेल ( मूँगफली तेल, मोरिया, सरसों का तेल, धालसा तातेल अरुण्डो तातेल बिमोला-तेल, वनस्पति तेल)				

	1	2	3	4	5
सभी आयातित वनस्पति तेल	60@	75	60	100	
6 चीनी					
(क) सुरक्षित स्टॉक	0	—	—	—	—
(ख) जारी न किया गया स्टॉक	20	—	—	—	—
(ग) जारी किया गया स्टॉक	75	75	60	—	—
7 गेहूँ और खादसारी	45	75	60	—	—

@प्राप्त तेलमिलों और वनस्पति उत्पादकों पर लागू

—लागू नहीं

6 मुद्रा एवं अणु की प्रवृत्तियाँ

6.1 वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान मौद्रिक गतिविधियों को चल-निधि में हुई तीव्र वृद्धि सरकार के घाटा खर्च से उत्पन्न मजबूत विस्तारक प्रभाव के साथ विविष्ट रूप से चित्रित किया गया था । इसके अलावा, मुद्रा में विस्तार की गति विशेष रूप से तेज थी और जनता के पास मुद्रा तथा बैंकों के पास मांग जमा राशियाँ दोनों में समान तेज वृद्धि इस के लिए उत्तरदायी थी । यद्यपि, सावधि जमा राशियाँ मुद्रा वृद्धि धीमी रही किन्तु स्थूल मुद्रा (एम 1) में विस्तार पिछले वर्ष की तुलना में फिर भी अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण रूप में ऊँचा रहा ।

6.2 स्थूल मुद्रा में परिवर्तन के अंतर्गत जैसा कि बिन्दुवार घट-बढ़ से परिलक्षित है, पिछले वर्ष की तुलना में निम्न स्थिति को दर्शाते हैं, वर्ष 1988-89 में तेज विस्तार की तुलना में वर्ष 1989-90 में वाणिज्यिक क्षेत्र के बैंक अणु में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि रही जबकि वर्ष 1988-89 की धीमी गति की तुलना में वर्ष 1989-90 में सरकार को दिए गए शुद्ध बैंक अणु में काफी तीव्रता आयी । ये प्रवृत्तियाँ वर्षों के धाँकड़ी पर आधारित हैं जो इन दोनों धरातु अणु घटकों के विस्तारक प्रभाव को कम करके दर्शाती हैं । जैसाकि पिछले वर्ष रिजर्व बैंक के सरकार को शुद्ध अणु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व कुछ गिरने से पहले 1989-90 के पूरे वर्ष के दौरान अत्यंत उल्लेखनीय रूप से उच्चस्तर पर रहा । इसी प्रकार वाणिज्यिक क्षेत्रों को बैंक अणु में विस्तार वर्ष 1989-90 की पहली छमाही के दौरान 1988-89 की तुलना में तेज गति से हो रहा था किन्तु दूसरी छमाही में महत्वपूर्ण रूप से धीमा हो गया जिसके कारण 1989-90 के पूरे वर्ष के दौरान वाणिज्यिक अणु में समग्र रूप से विस्तार की गति प्रतिशत के रूप में निम्न रही । तथापि यह धीमी गति धर्मव्यवस्था में धीमी वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में देखी जानी चाहिए और विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष के ज्यादातर भाग के लिए और पिछले वर्ष बैंक अणु में प्रमाणांतर उच्च वृद्धि के रूप में देखी जानी चाहिए । फिर भी वर्ष 1989-90 में वाणिज्यिक क्षेत्र के अणु विस्तार की गति में गिरावट वर्ष की दूसरी छमाही में अणु नियंत्रण की नीतियों के प्रभाव को दर्शाती है ।

6.3 निरंतर उच्च राजकोषीय घाटों के अन्तर्निहित विस्तारक प्रभाव प्रारंभिक मुद्रा की तीव्र वृद्धि के रूप में परिलक्षित हुए । तथापि, पिछले वर्षों के विपरीत अधिक प्राथमिक चलनिधि का परिचालन नहीं किया जा सका क्योंकि प्रारंभिक नकदी अनुपात अपनी सावधिबन्धी सीमाओं तक पहुँच गया था । इसके परिणामस्वरूप, बिन्दुवार आधार पर बैंक प्रारंभिक निधि से सकल जमा राशि के वृद्धिशील अनुपात ( $\Delta$  धार/ $\Delta$  एडी) में उल्लेखनीय गिरावट परिलक्षित होती है जबकि यह कुछ सीमा तक बैंक प्रारंभिक निधियों में बड़े दैनिक उतार-चढ़ाव के परिप्रेक्ष्य में मुद्रागत नियंत्रण पर ध्यान देने की ओर इंगित करती है । प्रारंभिक नकदी अनुपात को बढ़ाने की आवश्यकता वा  $\Delta$  धार/ $\Delta$  एडी में गिरावट के लिए उत्तरदायी बनाना संभव नहीं है । वृद्धिशील मुद्रा में समग्र जमा राशि अनुपात ( $\Delta$  असी/

△एजी) में दीर्घावधि प्रयुक्तियों के विपरीत अपेक्षाकृत उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इन विपरीत प्रभावों की प्रवृत्ति से समायोजित न किए गए मद्रा गुणको में वृद्धि को रोकने में मदद मिली।

64 अनुसूचित बाणिज्य बैंको के परिवारलना में राजकापीय वर्ष 1989-90 के दौरान कुल जमा राशियों और बैंक ऋण की वृद्धि में तेजी दर्शायी। मांग जमा राशियों की वृद्धि में उल्लेखनीय रूप से तेजी आई किन्तु सावधि जमा राशियों में इसकी तुलना में तेजी कुछ कम रही। बैंक ऋण विस्तार में गिरावट खाद्येतर ऋण में एक वर्ष की अति उच्च वृद्धि के परभाव धीमी वृद्धि के कारण रही। वर्ष 1988-89 की भारी गिरावट की तुलना में 1989-90 की तीव्र वृद्धि से खाद्य ऋणों में तीव्र बदलाव आया। रिजर्व बैंक के पास शेष राशियों में पर्याप्त रूप से कम वृद्धि में रिजर्व बैंक से प्राप्त उधारियों पर बैंक निर्भरता में कमी आयी।

#### मुद्रा आपूर्ति

65 स्थूल मुद्रा या एम<sub>3</sub> के रूप में परिभाषित मुद्रा विस्तार वर्ष 1989-90 के दौरान ₹ 38,224 करोड़ या 19.9 प्रतिशत या जो पिछले वर्ष के ₹ 29,425 करोड़ या 18.1 प्रतिशत की तुलना में अधिक था (देखें सारणी 6.1)। मार्च 1989 में घोषित ऋण नीति में 1989-90 के दौरान एम<sub>3</sub> में विस्तार को रोकने की अपेक्षा पिछले चार वर्षों के भीत (16.8 प्रतिशत) की तुलना में निम्न बतायी गयी थी, परन्तु इस धारणा से यह अनुमान लगाया गया था कि केन्द्र सरकार को शुद्ध रिजर्व बैंक ऋण में वृद्धि ₹ 7,337 करोड़ के आस-पास होगी जैसा कि बजट वस्तावेजों में दर्शाया गया था परन्तु सरकारी लेखों की बंदी के परभाव 31 मार्च पर आधारित वास्तविक आंकड़े 31 मार्च 1990 के ₹ 13,813 करोड़ को छुने के पहले ही बिनाकि 16 मार्च 1990 को ₹ 17,102 करोड़ के भीच पर पहुँच गए अतः वर्ष 1978-79 के बाद जब यह विस्तार 21.2 प्रतिशत था, वह 19.9 प्रतिशत का मुद्रा विस्तार सब से अधिक रहा है। शुक्रवारों को दी गई सूचना की भीसत के आधार पर 1989-90 के दौरान एम<sub>3</sub> में हुई वृद्धि 1988-89 की 17.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 18.9 प्रतिशत थी।

66 जनता के पास मुद्रा आपूर्ति या एम<sub>1</sub> की वृद्धि के रूप में परिभाषित मौद्रिक विस्तार की गति जो अभी भी काफी अधिक थी 1989-90 में 22.5 प्रतिशत पर थी जबकि पिछले वर्ष 1988-89 में, यह 15.2 प्रतिशत थी। मुचित शुक्रवारों की भीसत के रूप में 1989-90 में एम<sub>1</sub> विस्तार की दर 20.2 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष 14.5 प्रतिशत थी।

67 वर्ष 1989-90 के दौरान जनता के पास मुद्रा में षटकवार उभार पिछले वर्ष के ₹ 4,765 करोड़ या 14.2 प्रतिशत की तुलना में ₹ 8,153 करोड़ या 21.2 प्रतिशत, वास्तव में अमृतपूर्व था। बैंकों के पास कुल जमा राशियों में 1988-89 के 19.0 प्रतिशत की तुलना में 19.4 प्रतिशत की भिन्नात्मक रूप से अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई। मांग जमा राशियों में 16.2 प्रतिशत की तुलना में 23.4 प्रतिशत की अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई जबकि सावधि जमा राशियों में पिछले वर्ष के 19.7 प्रतिशत की तुलना में 18.5 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि दर्ज की गई।

68 यद्यपि, 1989-90 में बाणिज्यिक क्षेत्र के बैंक ऋण में कुल वृद्धि ₹ 22,630 करोड़ थी जो 1988-89 में ₹ 21,687 करोड़ की कुल वृद्धि से कुछ अधिक थी, प्रतिशत के रूप में वृद्धि काफी कम थी जो 20.5 प्रतिशत की तुलना में 17.8 प्रतिशत थी। सरकार को शुद्ध बैंक ऋण के कुल और प्रतिशत दोनों के रूप में पिछले वर्ष के ₹ 12,771 करोड़ या 15.2 प्रतिशत की तुलना में ₹ 19,686 करोड़ या 20.3 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 1989-90 में सरकार को रिजर्व बैंक के शुद्ध ऋण में वृद्धि ₹ 13,031 करोड़ (21.7 प्रतिशत) थी जो ₹ 7,225 करोड़ (13.7 प्रतिशत) की तुलना में स्पष्ट रूप से काफी अधिक थी। यह वृद्धि अधिकांशतः पिछले वर्ष के ₹ 7,310 करोड़ (13.9 प्रतिशत) की तुलना में केन्द्र सरकार को रिजर्व बैंक के शुद्ध ऋण में ₹ 12,673 करोड़ (21.2 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण थी। यहाँ इस बात का अल्लेख करना उचित होगा कि 1989-90 में केन्द्र सरकार को रिजर्व बैंक के शुद्ध ऋण में वृद्धि का एक भाग अर्थात् ₹ 722 करोड़ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा काय\* से पुनर्खंडों को मुक्ति-अनक बनाने के लिए केन्द्र सरकार पर रिजर्व बैंक के दावों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय

सारणी 6.1 मुद्रास्टॉक (एम<sub>3</sub>) में षटकवार

(करोड़ रुपय)

वर्ष	निम्नलिखित वित्तीय वर्षों के दौरान षटकवार							
	1988-89		1989-90*		1989-90 (अप्रैल-जून)		1990-91** (अप्रैल-जून)	
	संपूर्ण	प्रतिशत	संपूर्ण	प्रतिशत	संपूर्ण	प्रतिशत	संपूर्ण	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I एम <sub>3</sub> (क + ख + ग)	29,425	18.1	38,224	19.9	11,170	5.9	7,247	3.1
(क) जनता के पास मुद्रा	4,765	14.2	8,153	21.2	2,412	6.3	2,718	5.8
(ख) बैंकों के पास कुल जमा राशियाँ (i + ii)	24,495	19.0	29,727	19.4	8,751	5.7	4,558	2.5
(i) मांग जमा राशियाँ	3,875	16.2	6,476	23.1	1,323	8.1	434	1.3
(ii) दीर्घावधि जमा राशियाँ	20,620	19.7	23,251	19.5	6,431	5.1	1,125	2.3
[(ग) रिजर्व बैंक के पास 'अस्थ' जमा राशियाँ]	165	55.6	314	74.5	4	0.9	-29	-4.6
II एम <sub>1</sub> (क + ख (i) + ग)	8,805	15.2	14,973	22.5	4,749	7.1	5,122	3.9
III मुद्रा स्टॉक (एम <sub>3</sub> ) के स्रोत (1 + 2 + 3 + 4 + 5)								
1 सरकार को शुद्ध बैंक ऋण (घ + छा)	12,771	15.2	19,686	20.3	8,443	8.7	9,583	8.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(घ) सरकार को रिजर्व बैंक का मुद्रा ऋण (i+ii) ≠	7,225	13.7	13,031 (क)	21.7	6,079	10.1	6,661 (ख)	9.1
(i) केंद्रीय सरकार पर मुद्रा दावे (क-ख)	7,310	13.9	12,672	21.2	6,186	10.3	7,172	9.9
(क) केंद्रीय सरकार पर दावे	7,334	13.9	12,626	21.1	6,168	10.3	7,259	10.0
(ख) केन्द्र सरकार की जमा राशियाँ	24	31.6	-46	-46.0	-18	-18.0	87	161.1
(ii) राज्य सरकारों पर मुद्रा दावे (क-ख)	-85	-36.8	359	245.9	-107	-73.3	-511	-101.2
(क) राज्य सरकार पर दावे	-90	-36.6	362	232.1	-102	-65.4	-507	-97.9
(ख) राज्य सरकारों की जमा राशियाँ	-5	-33.3	3	30.0	5	50.0	4	30.8
(घा) सरकार को अन्य बैंकों का ऋण	5,546	17.7	6,655	18.1	2,354	6.4	2,922	6.7
2. वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (घ + घा)	21,687	20.5	22,630	17.8	4,531	3.6	2,142	1.4
(घ) वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक का ऋण @	1,144	30.1	257	5.2	-528	-10.7	-246	-4.7
(घा) वाणिज्य क्षेत्र को अन्य बैंकों का ऋण	20,543	20.2	22,373	18.3	5,059	4.1	2,388	1.7
3. बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (घ + घा)	1,146	20.7	85	1.3	64	1.0	-352	-5.2
(घ) रिजर्व बैंक की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	637	12.1	85	1.4	64	1.1	-352	-5.9
(घा) दूसरे बैंकों की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	509	198.8	--	--	--	--	--	--
4. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	95	6.9	42	2.8	31	2.1	--	--
5. सीमावी जमा राशियों के अलावा बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध मुद्रा देयताएं (घ + घा)	6,274	18.5	4,219	10.5	1,889	4.7	4,126	9.3
(घ) रिजर्व बैंक की शुद्ध मुद्रा देयताएं	2,415	17.4	1,952	12.0	298	1.8	218	1.2
(घा) अन्य बैंकों की शुद्ध मुद्रा देयताएं (घ + घा)	3,859	19.3	2,267	9.5	1,591	6.7	3,908	15.0

§ मार्च के अंतिम सूचित गुरुवार के आंकड़ों पर आधारित

@ तादार्थिक की स्थापना के बाद से बैंकों को इसका पुनर्निर्माण शामिल नहीं है।

\* अनुमति

इसमें 7.22 करोड़ रुपये (क) और 240 करोड़ रुपये (ख) का राशि शामिल है, जो भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्र सरकार पर दावों द्वारा अनुमोदित की जा रही  
किये गये अपरक्रम्य, व्यापारिक प्रतिभूतियों के प्रतिस्थापन की द्योतक है ताकि कोष से पुनः प्रयोजन किये जा सकें।

टिप्पणी : -- बैंक चलन-चलन मदों के आंकड़ें पूर्णांकित किये गये हैं, इसलिए उनका जोड़ कुछ जोड़ के बराबर नहीं होगा।

मुद्रा कोष को जारी अपरक्रम्य, व्यापारिक प्रतिभूतियों की प्रतिस्थापना के कारण था। फिर भी, केन्द्र सरकार को रिजर्व बैंक के शुद्ध ऋण में वित्तीय वर्ष के अंतिम पाक्षिक-आंकड़ों का औसत परिवर्तन, वर्ष 1989-90 में रु. 10,635 करोड़ था जो 1988-89 के रु. 7,309 करोड़ और 1987-88 के रु. 5,326 करोड़ की तुलना में काफी ऊंचा था। सरकार को अन्य बैंकों के ऋण गतवर्ष के रु. 5,546 करोड़ (17.7 प्रतिशत) की तुलना में रु. 6,655 करोड़ (18.1 प्रतिशत) तक बढ़ गए। बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियों में 1988-89 के रु. 1,146 करोड़ की तुलना में कम बढ़ि हुई की रु. 85 करोड़ थी।

6.9 वित्तीय वर्ष 1990-91 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान एम<sub>2</sub> और एम<sub>1</sub> दोनों की वृद्धि 1989-90 की तदनुसंग अवधि

की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम रही। सरकार का शुद्ध बैंक ऋण एवं वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण दोनों में प्रतिशत वृद्धि 1989-90 की तुलनात्मक अवधि की तुलना में एक कदम पीछे थी।

प्रारक्षित मुद्रा

6.10 प्रारक्षित मुद्रा में 1989-90 के दौरान रु. 10,770 (17.3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो कि पिछले वर्ष रु. 9,081 करोड़ (17.0 प्रतिशत) की दर से बढ़कर की अपनी उच्चतम सीमा पर थी। औसत के आधार पर प्रारक्षित मुद्रा की वृद्धि दर 1988-89 की 16.8 प्रतिशत की अपेक्षा ऊंची प्रतीत 18.0 प्रतिशत रही। घटकवार दृष्टि से जनता के पास मुद्रा में स्पष्ट बढ़ाव रहा जैसा कि पहले बताया जा चुका है

रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशियों, अन्य प्रमुख घटक, में 1988-89 की रु. 3,904 करोड़ (21.9 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में रु. 2,066 करोड़ (9.5 प्रतिशत) की काफी कम वृद्धि रही (सारणी 6.2)

6.11 अतः, सरकार को शुद्ध रिजर्व बैंक ऋण जो प्रारंभिक मुद्रा के विस्तार में प्रमुख कारक रहे हैं, में रु. 13,031 करोड़ (21.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि 1988-89 में यह रु. 7,225 करोड़ (13.7 प्रतिशत) थी। वाणिज्य और सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के ऋण में रु. 693 करोड़ की गिरावट आयी जबकि इसके विपरीत पिछले वर्ष इनमें रु. 2,395 करोड़ की वृद्धि हुई थी।

6.12 वित्तीय वर्ष 1990-91 की पहली तमाही के दौरान प्रारंभिक मुद्रा वृद्धि 1988-89 के तत्पश्चात् अवधि के 6.2 प्रतिशत से बढ़कर 8.1 प्रतिशत हो गयी। कुल ऋणों के रूप में रिजर्व बैंक के सरकार पर उच्च ऋणों, कुल और प्रतिशत दोनों के रूप में वाणिज्य और सहकारी बैंकों पर ऋणों ने भी प्रारंभिक मुद्रा में इन तीनों वृद्धि में योगदान किया।

6.13 दिलचस्प बात यह रही कि रिजर्व बैंक की वाणिज्य क्षेत्र को प्राथमिक प्रारंभिकता की प्राप्ति (घरों, सावधि वित्तीय सत्यानों को इसकी सहायता के माध्यम से) हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष रूप से उच्च स्तर तक बढ़ी जबकि वाणिज्य और सहकारी बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से प्राथमिक प्रारंभिकता की यह प्राप्ति कम रही (देखें सारणी 6.3)।

सारणी 6.2 प्रारंभिक मुद्रा में घट-बढ़, घटक तथा स्रोत

(करोड़ रुपये)

मद	निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़ \$			
	1988-89	1989-90*	1989-90 (अप्रैल-जून)	1990-91* (अप्रैल-जून)
1	2	3	4	5
प्रारंभिक मुद्रा (1 + 2 + 3 + 4)	9,081 (17.0)	10,770 (17.3)	3,888 (6.2)	5,954 (8.1)
1. जनता के पास मुद्रा	4,765 (14.2)	8,153 (21.2)	2,412 (6.3)	2,718 (5.8)
2. रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा राशियाँ	165 (55.6)	344 (74.5)	4 (0.9)	-29 (-3.6)
3. बैंकों के पास नकदी	247 (16.0)	207 (11.5)	530 (29.6)	318 (16.0)
4. रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशियाँ	3,904 (21.9)	2,066 (9.5)	942 (4.3)	2,947 (12.4)
प्रारंभिक मुद्रा के स्रोत (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)				
1. सरकार को भा. रि. बैंक का शुद्ध ऋण	7,225 (13.7)	13,031 (क) (21.7)	8,079 (10.1)	6,681 (ख) (9.1)
2. वाणिज्य और सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक के ऋण @	2,395 (61.0)	-693 (-11.0)	-1,460 (-23.1)	109 (1.9)
3. वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक का ऋण	1,144 (30.1)	257 (5.2)	-528 (-10.7)	-246 (-4.7)
4. रिजर्व बैंक की शुद्ध विदेशी मुद्रा धारिता	637 (12.1)	85 (1.4)	64 (1.1)	-352 (-5.9)
5. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	95 (0.9)	42 (2.8)	31 (2.1)	-- (--)
6. रिजर्व बैंक की शुद्ध मुद्रा देयताएं	2,415 (17.4)	1,952 (12.0)	298 (1.8)	218 (1.2)

\*अंतिम

@ताबाई सहित

\$मार्च महीने के अंतिम शुक्रवार को सूचित प्रांकड़ों पर आधारित

रु. 722 करोड़ (क) और रु. 240 करोड़ (ख) की राशि शामिल है जो कीच से पुनः खरीद संबंधी सुविधा हेतु केन्द्र सरकार पर भा. रि. बैं. के ऋणों द्वारा प्र. मु. को. को जारी अंतरास्थायी अध्याजी प्रतिभूतियों की प्रतिस्थापना को दर्शाती है।

टिप्पणी 1. बैंकिंग अलग-अलग मदों के आकड़े पूर्णांकित किये गये हैं इसलिए उनका जोड़ कुल जोड़ के बराबर नहीं होगा।

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

सारणी 6.3 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र पर रिजर्व बैंक की दायरे

(करोड़ रुपये में)

निम्नलिखित पर रिजर्व बैंक के दायरे

वर्ष के अन्त में सकाया

वाणिज्य और सहाकारी बैंक वाणिज्य क्षेत्र\* (वित्तीय संस्थाएं)

वर्ष	वाणिज्य और सहाकारी बैंक वाणिज्य क्षेत्र* (वित्तीय संस्थाएं)
1984-85	1,584
1987-88	2,158
1988-89	3,937
1989-90	2,810
30 जून 1989	2,586
29 जून 1990	2,882

\*नाबार्ड सहित वित्तीय संस्थाओं को बॉन्डों/शेयरों में निवेश और उनको दिए गए ऋणों की वसूली है। नाबार्ड की स्थापना से इसको द्वारा बैंकों को दिए गए पुनर्निवेश शामिल नहीं हैं।

मुद्रा का आयगत वेग

6.14 मुद्रा का आयगत वेग अर्थात् स्थूल मुद्रा (एम-3) के औसत से बाह्य बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद का अनुपात जो 1970 के दशक के पूर्व से लगभग लगातार दीर्घकालीन गिरावट दर्शाता रहा है, 1989-89 के 2.20 से घटकर 1989-90 में 2.09 हो गया। भारत में मुद्रा के आयगत वेग में लगातार गिरावट बना रहना अनुभव के आधार पर इस बात की सिद्ध करता है कि इस अवधि के दौरान एम-3 के लिए मांग की वास्तविक आय की लोच पहले की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक रही। सकल देशी उत्पाद/एम-1 और सकल देशी उत्पाद/चलमुद्रा अनुपात में कुछ गिरावट आयी और विशेषकर 1980 के दशक की दूसरी छमाही में। इसकाफ से इस अवधि में जनता के पास चलमुद्रा में बढ़ी तेजी से विस्तार हुआ। साथ ही, सकल देशी उत्पाद/एम-1 और सकल देशी उत्पाद/चल मुद्रा अनुपात में भी 1989-90 में गिरावट दर्ज की गई (देखें सारणी 6.4)।

कतिपय मुद्रागत संबंध

6.15 चलमुद्रा सापेक्ष संबंधी कुल जमाराशियों या एम-3 में भारी वृद्धि के कारण औसत और बिन्दुवार दोनों ही के आधार पर मुख्य मुद्रागत अनुपातों, अर्थात् कुल जमाराशियों में चलमुद्रा और एम-3 में चल-मुद्रा में 1989-90 के दौरान उभार आया। प्रारंभिक राशि का अवैधताओं

में परिवर्तन लाने के लिए असमायोजित वृद्धिशील मुद्रा गुणक ( $\Delta \text{एम-3} / \Delta \text{मरएम}$ ) में औसत और बिन्दुवार दोनों ही के आधार पर वृद्धि दर्ज की गयी (देखें सारणी 6.5)।

बैंकिंग राशि में घट-वृद्ध

6.16 1989-90 वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में रु. 26,809 करोड़ (19.1 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई जो 1988-89 में हुई रु. 22,105 करोड़ (18.7 प्रतिशत) की वृद्धि से अपेक्षाकृत अधिक थी। मार्च 1989 के ऋण नीति संबंधी उपायों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों की वृद्धि से संबंधित कार्यशील अनुमान 1989-90 के लिए रु. 24,000 करोड़ (17.3 प्रतिशत) लगाया गया था। वर्ष 1989-90 में वार्षिक वृद्धि कार्यशील अनुमान से अपेक्षाकृत अधिक रही है (सारणी 6.6)। सातवाँ पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कुल जमाराशियों में (वर्तमान मूल्यों पर) वार्षिक औसत वृद्धि रु. 18,943 करोड़ (या 18.2 प्रतिशत वार्षिक) थी। घटकवार, जबकि मांग जमाराशियों में पूर्ण तथा प्रतिशत दोनों ही के रूप में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि दर्ज की गई, वहां सावधि जमाराशियों में पूर्ण रूप में पर्याप्त वृद्धि देखने में आयी लेकिन प्रतिशत के रूप में इस की वृद्धि की गति धीमी रही। अतः मांग-जमाराशियों में 1989-90 में रु. 5,514 करोड़ (23.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि गतवर्ष के दौरान यह वृद्धि रु. 3,095 करोड़ (15.3 प्रतिशत) थी जबकि सावधि जमाराशियों में रु. 19,010 करोड़ (19.4 प्रतिशत) की तुलना में रु. 21,295 करोड़ (18.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई (सारणी 6.7 देखें)।

6.17 बैंक ऋण में 1989-90 में रु. 16,734 करोड़ की वृद्धि हुई जो 1988-89 की रु. 14,183 करोड़ की वृद्धि से अधिक थी किन्तु प्रतिशत के रूप में हुई वृद्धि पिछले वर्ष की 20.1 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में कम रही जो कि 19.8 प्रतिशत थी। बाह्य ऋण में 1988-89 में हुई रु. 1,421 करोड़ की गिरावट के विपरीत 1989-90 में रु. 1,237 करोड़ की वृद्धि हुई जो सरकारी वितरण प्रणाली की ऊँची खाद्यान्न खरीद और उनके पाम रखे भंडार को प्रदर्शित करती है। बाह्य ऋण में पिछले वर्ष की रु. 15,604 करोड़ (22.8 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में रु. 15,497 करोड़ (18.5 प्रतिशत) की वृद्धि कम रही जो कि वार्षिक रूप से औद्योगिक और कृषि उत्पादनों की वृद्धि

सारणी 6.4 : आयगत वेग की प्रवृत्तियाँ (मुद्रा, एम-1 और एम-3 के अनुपातिक रूप में  
वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद)

वर्ष	औसत @ (करोड़ रुपये)			आयगत वेग अनुपात		
	मुद्रा	एम-1	एम-3	सकल देशी उत्पाद/मुद्रा	सकल देशी उत्पाद/एम-1	सकल देशी उत्पाद/एम-3
1	2	3	4	5	6	7
1985-86	24,058	40,824	1,10,372	19.911	6.430	2.378
1986-87	27,011	46,835	1,29,713	10.863	6.265	2.262
1987-88	31,410	53,866	1,52,096	10.587	6.174	2.186
1988-89	35,842	61,688	1,78,080	10.913	6.341	2.197
1989-90	42,529	74,169	2,11,699	10.411	5.970	2.092

① सूचित शुल्कों का औसत

## सारणी 6.5 : मुद्रा अनुपात-वृद्धिशील

मद	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6
<b>बिन्दु आधार (वृद्धिशील अनुपात)</b>					
(क) चलमुद्रा/कुल जमा (सी/एडी)	0.176	0.182	0.298	0.195	0.274
(ख) चलमुद्रा/एम <sub>3</sub> (सी/एम <sub>3</sub> )	0.153	0.153	0.230	0.162	0.213
(ग) कुल जमा/एम <sub>3</sub> (एडी/एम <sub>3</sub> )	0.869	0.842	0.773	0.832	0.778
(घ) मुद्रा गुणक (एम <sub>3</sub> /भारएम)	2.567	3.206	2.597	3.240	3.549
(ङ.) मुद्रा गुणक (एम <sub>1</sub> /भारएम)	0.619	1.090	0.781	0.970	1.390
(च) बैंक प्रारक्षित/कुल जमा (भार/एडी)	0.297	0.183	0.204	0.169	0.076
<b>श्रीमन्त आधार (वृद्धिशील अनुपात)</b>					
(क) चलमुद्रा/कुल जमा (सी/एडी)	0.183	0.180	0.245	0.206	0.250
(ख) चलमुद्रा/एम <sub>3</sub> (सी/एम <sub>3</sub> )	0.155	0.153	0.197	0.171	0.199
(ग) कुल जमा/एम <sub>3</sub> (एडी/एम <sub>3</sub> )	0.851	0.847	0.801	0.827	0.796
(घ) मुद्रा गुणक (एम <sub>3</sub> /भारएम)	3.918	3.129	2.453	3.099	3.204
(ङ.) मुद्रा गुणक (एम <sub>1</sub> /भारएम)	1.206	0.972	0.771	0.933	1.189
(च) बैंक प्रारक्षित निधियाँ/कुल जमा (भार/एडी)	0.124	0.197	0.261	0.180	0.135

टिप्पणी : बिन्दुवार आधार पर अनुपात मार्च के अंतिम शुक्रवार के आंकड़ों पर आधारित है, जबकि श्रीमन्तवार आधार पर अनुपात सभी सूचित शुक्रवारों के श्रीमन्त आधार पर निकाले गये हैं। इस सारणी में सभी अनुपात वृद्धिशील अनुपात हैं।

मे गिरावट और रिज़र्व बैंक द्वारा खाद्येतर ऋण विस्तार को संतुलित करने के उपायों विशेषकर 1989-90 की दूसरी छमाही में उठाये गये कदमों के कारण हैं इस प्रकार खाद्येतर ऋण पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में रु. 9,937 करोड़ या 13.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में रु. 7,758 करोड़ या 8.5 प्रतिशत बढ़ा।

6.18 सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेशों में हुई रु. 9,707 करोड़ की वृद्धि 1988-89 में रु. 8,158 करोड़ की वृद्धि से काफी ज्यादा रही। रिज़र्व बैंक के पास बैंकों की शेष राशियों में रु. 2,087 करोड़ की वृद्धि रही जो पिछले वर्ष रु. 3,720 करोड़ की वृद्धि से कम थी। रिज़र्व बैंक से बैंकों को दिए गए उधार में रु. 1,128 करोड़ की गिरावट आयी, जबकि गन्तव्य उपमें रु. 1,774 करोड़ का वृद्धि हुई थी।

## सारणी 6.6 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कुल जमा राशियों की वृद्धि

राजकीय वित्त वर्ष अप्रैल-मार्च	(करोड़ रुपये) कुल जमा राशियों की वृद्धि
1.	2.
1985-86	13,160 (18.2)
1986-87	17,320 (20.3)
1987-88	15,321 (14.9)
1988-89	22,105 (18.7)
1989-90	26,809 (19.1)
1985-86 से 1989-90 का औसत	18,943 (18.2)

टिप्पणी : ये वृद्धियाँ मार्च के सूचना देने वाले अंतिम शुक्रवार पर आधारित हैं।

## सारणी 6.7 : महत्वपूर्ण बैंकिंग सूचक--अनुसूचित वाणिज्य बैंक

(करोड़ रुपये)

मद	निम्नलिखित को अवकाश			वित्तीय वर्ष के बीचान घट-बढ़		घट-बढ़	
	24 मार्च 1989	23 मार्च 1990	29 जून 1990*	1988-89	1989-90	1989-90 अप्रैल से जून	1990-91 अप्रैल से जून
1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल मांग एवं मीमांसा देयताएं (इसमें रिज़र्व बैंक/भा. श्री. बि. बैं./तादार्थ से लिये गये उधार शामिल नहीं है)	1,56,637	1,85,845	1,91,183	24,686	29,208	9,158	5,338
2 कुल जमा राशियाँ (व. त. ख.)	1,40,150	1,66,959	1,71,618	22,105 (18.7)	26,809 (19.1)	7,704 (5.5)	4,689 (2.8)

1	2	3	4	5	6	7	8
(क) मांग जमाराशियां	23,342	28,856	29,291	3,095 (15.3)	5,514 (23.6)	1,766 (7.6)	435 (1.5)
(ख) भावधि जमाराशियां	1,16,808	1,38,103	1,42,357	19,010 (19.4)	21,295 (18.2)	5,938 (5.1)	4,254 (3.1)
3. रिजर्व बैंक से उधार	3,527	2,399	2,458	1,774	—1,128	—1,353	59
4. बैंक ऋण (क+ख)	84,719	1,01,453	1,03,837	14,183 (20.1)	16,734 (19.8)	4,361 (5.1)	2,384 (2.3)
क. खाद्य ऋण	769	2,006	3,917	—1,421	1,237	890	1,911
ख. आयेतर ऋण	83,950	99,447	99,920	15,604 (22.8)	15,497 (18.5)	3,471 (4.1)	473 (0.5)
5. निवेश (क+ख)	54,662	64,369	67,444	8,158 (17.5)	9,707 (17.8)	2,898 (5.3)	3,075 (4.8)
क. सरकारी प्रतिभूतियां	35,815	42,292	45,204	5,298 (17.4)	6,477 (18.1)	2,345 (6.5)	2,912 (6.9)
ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	18,847	22,077	22,240	2,860 (17.9)	3,230 (17.1)	553 (2.9)	163 (0.7)
6. हाथ में नकदी	1,444	1,648	1,878	138	204	435	230
7. रिजर्व बैंक के पास शेप राशियां	21,376	23,463	26,026	3,720 (21.1)	2,087 (9.8)	680 (3.2)	2,563 (10.9)
8. ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)	60.4	60.8	60.5				
9. गैर-खाद्य ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)	59.9	59.6	58.2				

\*अनंतिम.

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

2. पूर्णांकित किये जाने के कारण घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ के बराबर नहीं होगा।

3. अनात्मक घट-बढ़ के लिये कोई संकेत नहीं दिया गया है।

### बैंकिंग उतार-चढ़ाव-वर्ष के अन्त में हुआ विस्तार

6.19 31 मार्च 1989 को समाप्त हुए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के वित्तीय वर्ष के अन्तिम सप्ताह में उनके ऋणों और कुल जमाराशियों में तीव्र तथा असामान्य वृद्धि के बारे में गत वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था। बैंकों के वित्तीय वर्ष 1989-90 की तुलनात्मक अवधि में कुल जमाराशियों और ऋण में समानरूप से तीव्र वृद्धि हुई। यद्यपि 23 मार्च और 31 मार्च 1990 के बीच कुल जमाराशियों और बैंक ऋण में क्रमशः 8,169 करोड़ रुपये (4.9 प्रतिशत) और 4,999 करोड़ रुपये (4.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, इन की तुलना में वर्ष 1988-89 के अन्तिम सप्ताह के दौरान हुई कुल जमाराशियों में 7,010 करोड़ रुपये (5.0 प्रतिशत) और बैंक ऋण में 4,851 करोड़ रुपये (5.5 प्रतिशत) की वृद्धियों से की जाती है। 23 मार्च और 31 मार्च 1990 के बीच मांग जमाराशियों में 5,428 करोड़ रुपये (18.8 प्रतिशत) की उल्लेखनीय और भावधि जमाराशियों में भी 2,741 करोड़

रुपये (2 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण वृद्धि परिलक्षित हुई। 31 मार्च, 1990 को समाप्त इसी अवधि के दौरान कुल जमाराशियों में हुई वृद्धि शुक्रवार को सूचित 1989-90 के दौरान जमाराशियों में वृद्धि का लगभग 30.5 प्रतिशत बैठता है; इसी प्रकार से, इसी साठ दिन की अवधि के दौरान मांग जमाराशियों का उपभोग, शुक्रवार को दी गयी सूचना के आधार पर वर्ष 1989-90 की पूरी अवधि के दौरान कुल उपभोग लगभग एक जैसा ही होता था (अर्थात् 99 प्रतिशत) (सारणी 6.8) देखें। 30 मार्च और 31 मार्च 1990 के बीच केवल एक ही दिन की वृद्धि अभी भी काफी आश्चर्यजनक थी; यह कुल जमाराशियों में 1,613 करोड़ रुपये (0.9 प्रतिशत) और बैंक ऋण में 1,002 करोड़ रुपये (1.0 प्रतिशत) थी। इस प्रकार से 1989-90 में सूत्रगत तथा ऋण गति-विधियों के संबंध में किए गए मूल उपायों का मूल्यांकन करने के प्रयोजन से 31 मार्च के आंकड़े अर्थपूर्ण नहीं हैं तथा विशेषकर यह इस तथ्य से भी स्पष्ट होना चाहिए कि 6 अप्रैल 1990 को समाप्त होने वाले प्रथम



सारणी 6.8 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशियों में घट-बढ़ मार्च 1990 का अभिमान सप्ताह

(करोड़ रुपये)

मने	निम्न तारीखों की बकाया			घट-बढ़		(5) के प्रतिशत के रूप में (6)
	24 मार्च 1989	23 मार्च 1990	31 मार्च 1990 (घा.स.)	24 मार्च 1989 की तुलना में 23 मार्च 1990	23 मार्च 1990 की तुलना में 31 मार्च 1990	
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल जमा राशियाँ (क+ख)	1,40,150	1,66,959	1,75,128	+ 26,809 (+ 19.1)	+ 8,169 (+ 4.9)	+ 30.5
(क) मांग जमा राशियाँ	23,342	28,856	34,284	+ 5,514 (+ 23.6)	+ 5,428 (+ 18.8)	+ 98.4
(ख) सीधा सी जमा राशियाँ	1,16,808	1,38,103	1,40,844	21,295 (+ 18.2)	+ 2,741 (+ 2.0)	+ 12.9
2. बैंक ऋण (क+ख)	84,719	1,01,453	1,06,452	+ 16,734 (+ 19.8)	+ 4,999 (+ 4.9)	+ 29.9
(क) खाद्य ऋण	769	2,006	1,867	+ 1,237 (+ 160.8)	- 139 (- 6.9)	- 11.2
(ख) खाद्येतर ऋण	83,950	99,447	1,04,585	+ 15,497 (+ 18.5)	+ 5,138 (+ 5.2)	+ 33.2

घा.स. = आंशिक रूप से संशोधित

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत घट-बढ़ को दर्शाते हैं।

सप्ताह में जमा राशियों और ऋण में आयी गिरावट 23 मार्च और 31 मार्च 1990 के बीच जमा राशियों और ऋण में हुई वृद्धियों की मोटे तौर पर आधी थी। इसलिए, इस रिपोर्ट का विश्लेषण गृहकार्यों की वी गई सूचना से संबंधित आंकड़ों पर आधारित है, न कि 31 मार्च की वी गई सूचनाओं पर।

#### 1990-91 की प्रथम तिमाही की प्रवृत्तियाँ

6.20 जैसा कि पिछले अध्याय में बताया जा चुका है, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमा राशियों की वृद्धि का कार्यभार अनुमान 27,500 करोड़ रुपये (16.6 प्रतिशत) रहा है और 1990-91 की प्रथम तिमाही के लिए तदनुसार मौसमी अनुमान 13,700 करोड़ रुपये और अप्रैल-जून 1990 की प्रथम तिमाही के लिए रु. 1,800 करोड़ रहे। प्रथम तिमाही (29 जून 1990 तक) के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमा राशियों में वार्षिक वृद्धि रु. 4,689 करोड़ (2.8 प्रतिशत) आँकी गई जो कि पिछले वर्ष की तदनुसार अवधि में रु. 7,704 करोड़ (5.5 प्रतिशत) थी। मांग जमा राशियों ने रु. 415 करोड़ (1.5 प्रतिशत) की वृद्धि विखिल गिरावट दिखाई जो कि पिछले वर्ष की तुलना-अवधि में उल्लेखनीय रूप से रु. 1,763 करोड़ (7.6 प्रतिशत) थी। सीधा सी जमा राशियों में वृद्धि रु. 4,254 करोड़ (1.1 प्रतिशत) थी जो कि पिछले वर्ष की तदनुसार अवधि की तुलना में कम (रु. 5,938 करोड़ या 5.1 प्रतिशत) थी। बैंक ऋणों में रु. 2,334 करोड़ (2.3 प्रतिशत) की कम वृद्धि दर्ज की गई जो कि पिछले वर्ष की संबंधित अवधि में रु. 4,381 करोड़ (5.1 प्रतिशत) थी। खाद्य ऋण की वृद्धि रु. 1,911 करोड़ हुई गयी जो कि 1989 की तुलना-अवधि में रु. 899 करोड़ थी जो इस वर्ष सरकारी एजेंसियों द्वारा उंची खरीद को दर्शाती है। 1990-91 की पहली तिमाही में खाद्येतर ऋणों में रु.

473 करोड़ या 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष की संबंधित तिमाही में रु. 3,471 करोड़ या 4.1 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है। बैंक निवेशों, रु. 3,073 करोड़ (4.8 प्रतिशत) की वृद्धि दिखायी, जो पिछले वर्ष की संबंधित अवधि में रु. 2,894 करोड़ (5.3 प्रतिशत) की तुलना में काफी अधिक है।

#### ऋण का क्षेत्रवार वितरण

6.21 सकल बैंक ऋण के क्षेत्रवार वितरण के आंकड़े सारणी 6.9 में दिए गए हैं। ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 1989-90 (अप्रैल-मार्च) के दौरान सकल बैंक ऋण की राशि में वृद्धि पिछले वर्ष के दौरान रु. 15,168 करोड़ (22 प्रतिशत) वृद्धि की तुलना में रु. 17,055 करोड़ (या 19.9 प्रतिशत) हो गई। खाद्यान्न वसूली हेतु दिए गए बैंक ऋण में पिछले वर्ष के रु. 1,421 करोड़ की गिरावट के विपरीत रु. 1,237 करोड़ की काफी वृद्धि रही। तथापि, खाद्येतर सकल बैंक ऋण में रु. 15,818 करोड़ का विस्तार हुआ, जो 1988-89 की रु. 16,883 करोड़ वृद्धि से उल्लेखनीय रूप से कम था। बैंक ऋण की इस वृद्धि में गिरावट खाने खाते स्वीकृत क्षेत्रों में मध्यम तथा बड़े उद्योग, निर्यात ऋण और थोक व्यापार (खाद्यान्नों को छोड़कर) थे। दूसरी ओर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ग्रामों में वर्ष के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

6.22 1989-90 के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को लिए गए बैंक ऋण में रु. 15,256 करोड़ की वृद्धि हुई जो खाद्येतर सकल बैंक ऋण की कुल वृद्धि या 39.5 प्रतिशत या जबकि सन वर्ष यह प्रतिशत 30.5 प्रतिशत था। मार्च 1990 के अंत में गृह बैंक ऋण के अनुपात के रूप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ग्रामों में वर्ष के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। 43.2 प्रतिशत की तुलना में 42.4 प्रतिशत हुआ।

सारणी 6.9 प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का क्षेत्रीय वितरण@

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	निम्नलिखित को बकाया			घट-बढ़ (वित्तीय वर्ष)	
	25 मार्च 1988	25 मार्च 1989	23 मार्च 1990	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6
1 सकल बैंक ऋण	70,260	85,728	1,02,783	+ 15,469	+ 17,055
1. सार्वजनिक खाद्य वसूली ऋण	2,190	769	2,006	—1,421	+ 1,237
2 खाद्योत्पन्न सकल बैंक ऋण	68,070	84,959	1,00,777	+ 16,889 (+ 100.0)	+ 15,818 (+ 100.0)
(अ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	29,070	34,219	40,475	+ 5,149	+ 6,256
(i) कृषि	[44.1]	[43.2]	[42.4]	(+ 30.5)	(+ 39.5)
	12,009	13,950	16,612	+ 1,941	+ 2,662
(ii) लघु उद्योग	[18.2]	[17.6]	[17.4]	(+ 11.5)	(+ 16.8)
	10,820	13,135	15,615	+ 2,315 (+ 13.7)	+ 2,480 (+ 15.7)
(iii) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	6,241	7,134	8,248	+ 893 (+ 5.3)	+ 1,114 (+ 7.0)
(आ) उद्योग (मसाले और वड़े)	25,153	32,185	38,274	+ 7,032 (+ 41.6)	+ 6,089 (+ 38.5)
(इ) थोक व्यापार (खाद्य वसूली के अलावा)	3,598	4,767	5,879	+ 1,169 (+ 6.9)	+ 1,112 (+ 7.1)
(i) भारतीय कपास निगम	91	37	140	—54 (—0.3)	+ 103 (+ 0.7)
(ii) भारतीय खाद्य निगम (उर्वरक वितरण के लिए)	171	202	230	+ 31 (+ 0.1)	+ 28 (+ 0.2)
(iii) भारतीय जूट निगम	142	60	17	—82 (—0.4)	—43 (—0.3)
(iv) अन्य व्यापार	3,191	4,468	5,492	+ 1,271 (+ 7.5)	+ 1,024 (+ 6.5)
(ई) अन्य क्षेत्र	10,249	13,788	16,149	+ 3,539 (+ 21.0)	+ 2,361 (+ 14.9)
II. निर्यात ऋण (मद I (2) के अन्तर्गत शामिल)	3,917	6,141	8,272	+ 2,224	+ 2,131
III. शुद्ध बैंक ऋण (अंत बैंक, सहभागिता प्रमाण पत्रों सहित)	65,968	79,234	95,475	+ 13,266	+ 16,241

@ अन्तिम

टिप्पणी: 1. ये आंकड़े 50 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं, जिनका हिस्सा समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बैंक ऋण में लगभग 95 प्रतिशत है। इसके अलावा सकल बैंक ऋण के इन आंकड़ों में रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, निर्यात-आयात बैंक तथा अन्य अनुमादित वित्तीय संस्थाओं के मुद्रा भुनाये गये बिल और अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र शामिल हैं।

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े वृद्धिशील खात्रेतर सकल बैंक ऋण के अनुपात हैं।

3. चौकोर काष्ठक में दिये गये आंकड़े शुद्ध बैंक ऋण (अन्तर बैंक सहभागिता सहित) के अनुपात हैं, जो मद III में दिये गये हैं।

6.23 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अधिमों की कुल वृद्धि में कृषि और लघु उद्योगों का हिस्सा वर्ष 1989-90 में क्रमशः रु. 2,662 करोड़ (42.6 प्रतिशत) और रु. 2,480 करोड़ (29.6 प्रतिशत) तक बढ़ गया जबकि गत वर्ष यह हिस्सा क्रमशः रु. 1,941 करोड़ (37.7 प्रतिशत) और रु. 2,315 करोड़ (45.0 प्रतिशत) था।

6.14 वर्ष 1989-90 के दौरान मध्यम और बड़े उद्योगों की वृद्धि में गिरावट आयी। इस क्षेत्र के अधिम 1989-90 के दौरान रु. 6,089 करोड़ (18.9 प्रतिशत) बढ़कर रु. 38,274 करोड़ हो गए, जबकि 1988-89 में ये रु. 7,032 करोड़ (28.0 प्रतिशत) बढ़कर रु. 32,185 करोड़ हो गए थे। वृद्धिशाल खाद्येतर सकल बैंक ऋण में इनका हिस्सा 1988-89 में 41.6 प्रतिशत से गिरकर 1989-90 में 38.5 प्रतिशत रह गया।

6.25 थोक व्यापार को प्रदान किए अधिमों में 1989-90 के दौरान रु. 1,112 करोड़ (23.3%) की वृद्धि दर्ज की गई जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की तदनु रूप अधिम के दौरान रु. 1,169 करोड़ (22.5 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई थी।

6.26 "अन्य क्षेत्र" के ऋण जो अवशिष्ट क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिसमें वित्तीय संस्थानों, किराया-खरीद एजेंसियां, पट्टेदारी कंपनियों को दिए जाने वाले अधिम आवास वित्त, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है, ने 1989-90 के दौरान रु. 2,361 करोड़ (17.1 प्रतिशत) की निम्न वृद्धि दर्ज की जबकि 1988-89 के दौरान यह वृद्धि रु. 3,539 करोड़ (34.5 प्रतिशत) थी।

6.27 बैंक ऋण का उद्योगवार (लघु उद्योग, और बड़े उद्योग वितरण सारणी 6.10 में दर्शाया गया है। वर्ष 1989-90 के दौरान जिन उद्योगों ने ऋण का एक बहुत बड़ा भाग प्राप्त किया उन में थे : समस्त इंजीनियरी उद्योग (रु. 1,827 करोड़) लोहा एवं इस्पात (रु. 569 करोड़), सूती वस्त्र (रु. 444 करोड़), अभ्य वस्त्र (रु. 503 करोड़), जूट वस्त्र (रु. 73 करोड़), रबड़ और रबड़ से बनी वस्तुएं (रु. 150 करोड़), चमड़े और चमड़े से निर्मित वस्तुएं (रु. 237 करोड़) और निर्माण उद्योग (रु. 304 करोड़)। 1989-90 के दौरान चीनी (रु. 13 करोड़) और कोयला (रु. 24 करोड़) के ऋणों में गिरावट की सूचना दी गई।

सारणी 6.10 : सकल बैंक ऋण का उद्योगवार विवरण@

(करोड़ रुपये)

उद्योग	निम्नलिखित की बकाया			घट-वृद्धि (वित्तीय वर्ष)	
	25 मार्च 1988	24 मार्च 1989	23 मार्च 1990	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6
उद्योग (लघु उद्योग, मझौले और बड़े उद्योगों का जोड़)	35,973	45,320	53,889	+ 9,347	+ 8,569
1. कोयला	248	210	186	—38	—24
2. लोहा और इस्पात	1,824	2,245	2,814	+ 421	+ 569
3. अन्य धातुएं और धातु उत्पाद	1,203	1,624	1,830	+ 421	+ 206
4. सभी इंजीनियरी	8,697	10,623	12,450	+ 1,926	+ 1,827
5. बिजली (उ. और वि.)	785	1,042	1,279	+ 257	+ 237
6. सूती वस्त्र	2,752	3,216	3,660	+ 664	+ 444
7. जूट वस्त्र	305	276	349	—29	+ 73
8. अन्य वस्त्र	2,152	2,742	3,245	+ 590	+ 503
9. चीनी	640	669	656	+ 29	—13
10. चाय	411	524	574	+ 113	+ 50
11. वनस्पति तेल (वनस्पति सहित)	440	599	685	+ 159	+ 86
12. तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	235	297	384	+ 62	+ 87
13. कागज और कागज उत्पाद	854	1,142	1,333	+ 288	+ 191
14. रबड़ और रबड़ उत्पाद	557	750	900	+ 193	+ 150
15. रसायन, रंग, पेंट आदि : उनमें से उर्वरक	4,210 (913)	5,922 (1,019)	6,794 (1,081)	+ 1,712 (+ 106)	+ 872 (+ 62)
16. सीमेंट	503	689	820	+ 186	+ 131
17. चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	565	691	928	+ 126	+ 237
18. निर्माण	448	759	1,063	+ 311	+ 304
19. पेट्रोलियम	163	30	137	—133	+ 107
20. नयी योजना के अन्तर्गत विदेशों में लिये गये जहाज	231	191	149	—40	—42
21. बाकी उद्योग	8,750	11,079	13,653	+ 2,329	+ 2,574

@अनंतिम

## वित्तीय अनुपातों का उभार-चढ़ाव

6.24 जैसा कि कंपनियों की बी.बी.एन.एल. विनियम सहायता पर रिजर्व बैंक के नमूना अध्ययनों में पता चलता है कृषि वित्तीय अनुपातों के उभार-चढ़ाव मध्यम और बड़े उद्योगों के पत्र में बैंक ऋण

की प्रवृत्तियों से संबंधित कुछ समर्थक तथ्य प्रस्तुत करने हैं। जैसा कि सारणी 6.11 से देखा जा सकता है कि 1988-89 के दौरान जब मध्यम और बड़े उद्योगों द्वारा प्राप्त बैंक ऋण में पर्याप्त वृद्धि हुई, बड़ी कंपनियों का बिक्री से स्टॉक का अनुपात 25.0 प्रतिशत से बढ़कर 28.0 प्रतिशत और स्टॉक से अल्पाधिक बैंक उधारों का अनुपात 44.4 प्रतिशत से 45.6 प्रतिशत हो गया।

सारणी 6.11 : बिक्री की तुलना में माल सूची का तथा माल सूची की तुलना में बैंक उधारों का अनुपात  
(निजी क्षेत्र की सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियाँ)

(प्रतिशत में)

अवधि	नमूना कम्पनियों की संख्या	बिक्री के प्रतिशत के रूप में कुल माल सूची	कुल माल सूची के प्रतिशत के रूप में कच्ची सामग्री और घटक	कुल माल सूची के प्रतिशत के रूप में अल्पाधिक बैंक ऋण	कुल माल के प्रतिशत के रूप में कुल बैंक ऋण	कुटकार देनदार के प्रतिशत के रूप में कुटकार देनदार	ऋण- ईक्विटी अनुपात	ऋण- ईक्विटी अनुपात (पुन- मूल्यन प्राप्तित निधि के लिए समा- योजित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्यम और बड़ी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियाँ								
1975-76	1720	30.7	30.0	49.0	53.5	124.0	45.1	--
1976-77	1720	27.1	30.3	51.7	56.9	115.1	46.8	--
1977-78	1720	26.8	30.2	51.8	57.4	119.3	48.7	--
1980-81	1651	27.5	32.1	43.6	51.0	129.4	62.8	--
1981-82	1651	27.5	31.3	42.2	50.1	129.4	71.3	--
1982-83	1651	27.7	29.1	41.0	50.4	125.8	82.9	--
सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियाँ (लघु, मध्यम और बड़ी)								
1982-83	1838	27.7	29.2	41.4	50.6	124.4	84.5	91.5
1983-84	1838	26.3	28.0	43.9	55.7	118.2	87.7	100.3
1984-85	1838	24.7	28.4	45.3	57.4	117.4	83.6	104.7
1983-84	1867	26.3	28.3	43.8	57.1	117.0	89.3	101.7
1984-85	1867	24.7	28.5	45.5	58.6	115.9	84.3	104.4
1985-86	1867	25.3	28.4	46.5	59.3	111.3	77.1	110.1
1985-86	1953	25.6	28.1	44.4	57.3	111.2	78.7	110.7
1986-87	1953	25.7	27.1	48.0	60.8	104.7	85.1	117.4
1987-88	1953	25.2	27.6	48.8	61.1	105.9	86.8	118.0
बड़ी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियाँ								
1975-76	415	30.4	31.9	47.2	51.1	119.2	45.3	--
1976-77	415		31.6	50.2	54.9	108.1	46.6	--
1977-78	415		32.2	50.3	55.1	112.0	48.2	--
1982-83	535	27.7	30.1	37.5	44.7	123.9	79.8	--
1983-84	535	25.8	30.0	40.0	52.1	114.3	85.5	--
1984-85	535	24.5	29.3	40.5	52.6	112.6	80.0	--
1985-86	621	25.8	29.2	40.0	51.7	110.4	74.3	103.7
1986-87	621	25.2	28.3	42.9	54.1	101.2	80.3	108.6
1987-88	621	24.5	28.9	42.0	52.9	102.6	83.5	111.8
1986-87	622	25.6	28.6	42.8	55.4	102.1	79.8	106.4
1987-88	622	25.0	29.1	44.4	56.1	100.3	79.2	103.2
1988-89	622	26.0	31.0	45.6	57.3	102.2	82.9	104.4

## भारतीय रिजर्व बैंक-पुनर्वित्त (i) निर्वात ऋण पुनर्वित्त

6.29 30 जून, 1989 को समाप्त पखवाड़े में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाएं रु. 4,346 करोड़ रुपये में घटकर 29 जून 1990 को समाप्त पखवाड़े में रु. 4,118 करोड़ हो गई (सारणी 6.12 देखें)। उपयोग का प्रतिशत 12.5 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच रहा, जब बैंकों की निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाएं निर्धारित करने के प्रयोजन से सम्बन्धित आधार (29 जुलाई, 1989 से प्रभावी) 1986 के लिए मासिक औसत निर्यात ऋण, 1987 के लिए बकाया निर्यात ऋण में निर्यात पुनर्वित्त सीमाओं का अनुपात 28 जुलाई 1989 को 62.3 प्रतिशत से घटकर 11 अगस्त 1989 को 51.1 प्रतिशत हो गया, किन्तु 3 नवम्बर 1989 को फिर से बढ़कर 54.7 प्रतिशत तक हो गया। बैंक, 1987 के लिए बकाया निर्यात ऋण के मसिक औसत स्तर के ऊपर उनके निर्यात ऋण की वृद्धि के 75 प्रतिशत की सीमा तक के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त के लिए प्राप्त थे जो 4 नवंबर 1989 से प्रभावी थी

जिनके परिणामस्वरूप, निर्यात ऋण में निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाओं का अनुपात 17 नवंबर 1989 को 41.8 प्रतिशत तक गिरा। इसके बाद 29 जून 1990 तक यह धीरे-धीरे बढ़कर 46.3 प्रतिशत हो गया। जुलाई 1989-29 जून 1990 की अवधि के दौरान 28 जुलाई 1989 को समाप्त पखवाड़े में उपयोगिता का औसत स्तर रु. 4,271 करोड़ या 98.4 प्रतिशत रहा और यद्यपि 1 दिसम्बर 1989 को समाप्त पखवाड़े में दिनांक स्तर रु. 590 करोड़ या 12.5 प्रतिशत था।

## (ii) सहायक पुनर्वित्त

6.30 1 जुलाई 1989 से 29 जून 1990 की अवधि के दौरान तीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रु. 5 करोड़ से रु. 22 करोड़ के बीच सहायक पुनर्वित्त सीमाएं अनुमोदित प्रतिभूतियों की जमानत पर स्वीकृत की गयीं, जो केवल उन बैंकों के लिए हैं जिनके पास प्रतिरिक्त मासिक बचत निधि अनुपात (एम एल एलर) है, जिनका बहुत कम उपयोग किया गया।

सारणी 6.12 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की रिजर्व बैंक की ऋण सहायता  
(जहाँजहाँ ऋणों, शुल्क वापसी इत्यादि पर विशेष पुनर्वित्त को छोड़कर)

(करोड़ रुपये)

निम्नलिखित माह के अन्तिम सूचित शुक्रवार को	निर्यात ऋण पुनर्वित्त		आयाती पुनर्वित्त		विवेकाधीन पुनर्वित्त		182 दिवसीय खजाना बिल पुनर्वित्त		कुल पुनर्वित्त	
	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1989										
मार्च	3,007.1	2,875.8	74.0	54.0	462.5	265.0	53.1	21.3	3,596.1	3,314.2
जून	4,345.8	1,987.8	9.0	--	481.5	--	134.3	--	4,973.6	1,987.8
सितम्बर	3,770.5	2,096.9	--	--	462.5	0.7	383.0	--	4,615.8	2,097.6
दिसम्बर	3,257.4	2,201.0	--	--	460.6	26.5	324.4	--	4,042.4	2,227.5
1990										
मार्च	3,564.0	2,133.4	--	--	476.2	85.2	209.7	2.5	2,249.9	2,221.1
अप्रैल	3,782.6	2,652.6	5.0	--	508.7	89.7	223.3	--	4,519.6	2,742.3
मई	4,057.7	3,716.4	22.0	20.0	511.0	197.7	268.0	3.5	4,858.7	3,925.6
जून	4,118.2	2,338.5	11.0	9.0	433.1	--	429.7	--	4,992.0	2,347.5

टिप्पणी : बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों का बकाया स्तर लगातार रु. 5,900 करोड़ की अवसीमा से नीचे रहा। इसलिए बैंकों को इन सुविधा के अधीन पुनर्वित्त नहीं प्राप्त हो सका।

## (iii) विवेकाधीन पुनर्वित्त

6.31 विवेकाधीन पुनर्वित्त सुविधा के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को स्वीकृत कुल सीमाएं (जिसमें रिजर्व बैंक को पूर्वानुमति के बिना आहरण की सुविधा के अधीन सीमाएं भी शामिल हैं) 30 जून 1989 को समाप्त पखवाड़े में रु. 485 करोड़ से घटकर 29 जून 1990 को समाप्त पखवाड़े में रु. 433 करोड़ हो गई। इस अवधि के दौरान, जबकि इस सुविधा के अधीन स्वीकृत उच्चतम सीमाएं रु. 523 करोड़ रही जिसमें 1 जून 1990 को समाप्त पखवाड़े में प्रतिरिक्त पुनर्वित्त सीमाएं भी शामिल हैं दिनांक 31 मार्च 1990 को उपयोगिता का औसत स्तर रु. 278 करोड़ (69.0 प्रतिशत) था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मार्च 1990 के अंत में कुल मौद्रिक राशिदा अस्थिरस्थित नहीं थी, 24 मार्च से 6 अप्रैल 1990 के पखवाड़े के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दी गयी रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना विवेकाधीन पुनर्वित्त आहरित करने की सुविधा को वापस ले लिया गया। अब कुछ बैंकों ने अनधिकृत

अंश का अनुभव किया जो उन्हें उस पखवाड़े के दौरान वित्तीयक आधार पर रु. 444 करोड़ की सीमा तक विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमाओं की सुविधा दी गयी। दिनांक 31 मार्च 1990 को इन सीमाओं पर उच्चतम उपयोगिता रु. 278 करोड़ (69.0 प्रतिशत) थी।

## (iv) 182 दिवसीय खजाना बिलों पर पुनर्वित्त

6.32 182 दिवसीय खजाना बिलों की जमानत पर पुनर्वित्त सुविधा के अधीन सीमाएं क्रमिक रूप से 30 जून 1989 को रु. 134 करोड़ से बढ़कर 29 जून 1990 को रु. 430 करोड़ बढ़ दी गई। दिनांक 11 नवंबर 1989 को इस सुविधा के अधीन उठाया गया उच्चतम लाभ रु. 106 करोड़ (55.5 प्रतिशत) था। बैंकों को रिवर्य बैंक पुनर्वित्त का उपयोग करने के बजाय भारतीय मितिकाया और वित्त गृह (फिस्कल डेपेंडेंस फंडिंग ऑफ इंडिया) से साथ लेन-देन माफ़ नया अधिक आकर्षक लगा और यह सुविधा पीछे हो गई है और बैंकों द्वारा इस सुविधा का उपयोग बहुत कम अवसरों पर किया जाता है।

## (v) पुनर्वित्त की समग्रस्थिति

6.33 30 जून 1989 को बैंकों की विभिन्न सुविधाओं के अधीन (जहाँजहाँ ऋण, शुल्क वापसी इत्यादि पर विशेष पुनर्वित्त की छोड़कर) प्राप्त कुल पुनर्वित्त सीमाएं रु. 4,974 करोड़ थी। 14 जुलाई 1989 को बैंकों को मंजूर कुल सीमाओं की राशि रु. 5,055 करोड़ थी, जो 1 जुलाई 1989-29 जून 1990 की अवधि के दौरान स्वीकृत शिखर स्तर की सीमाएं थीं। उस तारीख को उपयोगिता की सीमा रु. 1,988 करोड़ (40.0 प्रतिशत) तक की थी। निर्गल ऋण पुनर्वित्त सीमाएं कुल पुनर्वित्त सीमाओं का प्रमुख भाग (86.8 प्रतिशत) थी। 29 जून 1990 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल पुनर्वित्त सीमाएं रु. 4,992 करोड़ थी जिनका रु. 2,347 करोड़ या 47.0 प्रतिशत तक उपयोग किया गया था। 1 जुलाई 1989-29 जून 1990 की अवधि के दौरान उपयोगिता का उच्च स्तर रु. 4,272 करोड़ या 19 जुलाई 1989 की सीमाओं का 84.5 प्रतिशत था।

## ऋण बजट

6.34 आलोच्य वर्ष के दौरान 57 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के 1989-90 के ऋण बजटों की जांच की गई। मई-अगस्त 1989 के दौरान 21 सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा 3 विदेशी बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ चर्चा हुई। चर्चा के दौरान बैंकों को उनके अपने स्थिर संसाधनों की प्रत्याशित वृद्धि के आधार पर अपने ऋण विस्तार की योजना बनाने की सलाह दी गई। दूसरे, बैंकों को निधि प्रबंधन की ओर अधिक ध्यान देने के लिए कहा गया और इस बात पर जोर दिया गया कि मुद्रा बाजार पर निर्भरता को और निधियों के स्रोतों और उपयोगों को संतुलित करने की सीमास्त आवश्यकताओं को पूरा करने तक के लिए सीमित रखा जाए न कि बाजारगत अनुमानों को पूरा करने के लिए। तीसरे, बैंकों को मतकं किया गया कि उन्हें रिश्वत बैंक प्राप्त अपरिचालित पुनर्वित्त सुविधाओं के आधार पर अपनी ऋण की योजना नहीं बनानी चाहिए क्योंकि इन सुविधाओं में समग्र मौद्रिक नीति की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किये जा सकते हैं। बैंकों को इस बात का पुनः स्मरण कराया गया कि उन्हें मुद्रा बाजार में उधार नहीं देना चाहिए जबकि विवेकाधीन और सहायक पुनर्वित्त विधाओं के अधीन उनकी राशि बकाया हो। चौथे, जब बैंकों को देयताएं परिवर्तनीय या अस्थिर किस्म की हों तब बैंक अल्पावधि परिपक्वता और अर्थ सुलभ आस्ति जैसी आस्तियों के तुल्य निवेश भलीभांति कर सकेंगे। इस संबंध में बैंकों से विशेष अनुरोध किया गया कि वे 182 दिवसीय खजाना बिलों में अपनी आभिम्यो के एक भाग का निवेश करें। पाँचवें, जहाँ नयी मुद्रा बाजार लिखते जारी की जा रही थी और बैंकों को इन लिखितों पर ब्याज दर निर्धारित करने की पूरी छूट प्राप्त थी तब बैंकों को इस बात पर जोर दिया गया कि ब्याज दरों और परिपक्वता की अवधि के बीच व्यवस्थित संबंध होना चाहिए। अंत में बैंकों को सूचित किया गया कि वे मार्च 1990 के अंतिम सप्ताह में अपनी जमा राशियों/क्षणों को अमामान्य रूप से दिखाने के लिए कार्य करने से बचें।

## वृद्धिशील शुद्ध खाद्येतर ऋण जमा-अनुपात-मानवंड और उपलब्धियाँ

6.35 17 नवंबर 1989 को समाप्त पखवाड़े से प्रभावी वृद्धिशील शुद्ध खाद्येतर ऋण जमा-अनुपात के संबंध में लागू किये गये उपायों के परिणामस्वरूप दिसंबर 1989-जनवरी 1990 के दौरान सात सरकारी

क्षेत्र के बैंकों के साथ चर्चा हुई थी। न बैंकों को उनके वृद्धिशील और शुद्ध खाद्येतर ऋण जमा अनुपात, जो 60 प्रतिशत के निर्धारित स्तर से काफी ऊंचा था, को नीचे लाने के लिए प्रभावों काम उठाने के लिए कहा गया।

6.36 जैसा कि पहले गंकेत दिया जा चुका है, वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों तर 60 प्रतिशत वृद्धिशील शुद्ध खाद्येतर ऋण जमा अनुपात के निर्धारण से खाद्येतर ऋण वृद्धि पर संतुलित प्रभाव पड़ा। 1989-90 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वृद्धिशील शुद्ध खाद्येतर ऋण जमा अनुपात 57.3 प्रतिशत था जो 1988-89 के दौरान 70.6 प्रतिशत से काफी कम था। जैसा कि ग्राफ "घा" में चित्रित किया है, प्रणाली से संबंधित अनुपात समग्र रूप से पिछले वर्ष की तत्पूरुप अवधि में अक्टूबर 1989 तक लगातार उससे काफी अधिक रहा, किन्तु इस उपाय, जो 4 नवम्बर 1989 से प्रभावी हुआ, के लागू करने के पश्चात् अनुपात पिछले वर्ष की तुलना से कम रहा। यद्यपि जिन बैंकों में निर्धारित अनुपात को पार किया उनकी संख्या अलग-अलग पखवाड़े में भिन्न (10 से 17 की सीमा तक) रही। यह पाया गया कि 23 मार्च 1990 को समाप्त वर्ष में 71 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में से 16 का वृद्धिशील खाद्येतर ऋण जमा अनुपात 24 मार्च 1989 से 23 मार्च 1990 के वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान 60 प्रतिशत से अधिक था और निर्धारण से ऊपर की अधिक राशि कुल रु. 1,051 करोड़ थी। वृद्धिशील शुद्ध खाद्येतर ऋण-जमा अनुपात का 60 प्रतिशत निर्धारण 1990-91 के दौरान चलता रहेगा।

## अल्पावधि मुद्रा बाजार की गतिविधियाँ

6.37 मुद्रा बाजार के संबंध में किए गए नीतिगत उपायों का जितना ऋण नीति की गतिविधियों की समीक्षा करने समय पहले ही कर दिया गया है। वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार की गतिविधियों की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी जा रही हैं :

## भारतीय मित्रीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड

6.38 भारतीय मित्रीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड (डीएफएचआई) मुद्रा बाजार लिखितों में एक सक्रिय गौण बाजार के विकास में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। भारतीय मित्रीकाटा और वित्त गृह ने 182 दिवसीय खजाना बिलों को प्रभावी रूप से उच्च तक लिखित अनाया और भारतीय मित्रीकाटा और वित्त गृह के परिवारलों ने 182 दिवसीय खजाना बिलों के लिए गौण बाजार में व्यापक गतिविधि प्रोत्साहित की। भारतीय मित्रीकाटा और वित्त गृह ने अंतर-बैंक मांग मुद्रा बाजार में बहुमूल्य सेवा प्रदान करना जारी रखा। दिसंबर 1989 में, भा. मि. वि. गृ. को अंतर-बैंक रावधि जमा बाजार में उधार-दाता और उधार-कर्ता दोनों के रूप में काम करने का अनुमति दी गयी।

6.39 मार्च 1990 के अंत में भा० मि० वि० गृ० की 182 दिवसीय खजाना बिलों और वाणिज्यिक बिलों की धारिताये क्रमशः रु० 512 करोड़ और रु० 705 करोड़ के बराबर रहा जबकि मार्च 1989 के अंत में ये धारिताये क्रमशः रु० 382 करोड़ और रु० 628 करोड़ की थी (सारणी 6.13)।

सारणी 6.13 : भारतीय मित्रीकाटा और वित्त गृह द्वारा 182 दिवसीय खजाना बिलों और वाणिज्य बिलों को धारित ।

(करोड़ रुपये)

निम्नलिखित महीने के अंत में	182 दिवसीय खजाना बिल			वाणिज्यिक बिल		
	1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल	10.34	165.97	—	—	133.00	390.25
मई	0.25	256.01	260.50	0.02	230.41	297.00
जून	1.31	4.40	41.05	0.02	120.80	201.25
जुलाई	73.50	88.10	5.20	—	175.93	140.75
अगस्त	69.25	21.31	116.00*	—	127.07	97.25
सितंबर	50.00	102.65	—	—	92.38	—
अक्टूबर	30.25	258.30	—	—	187.14	—
नवंबर	30.75	221.96	—	8.00	175.50	—
दिसंबर	159.50	182.80	—	8.00	80.50	—
जनवरी	94.80	16.00	—	1.50	132.50	—
फरवरी	292.50	445.20	—	85.50	407.50	—
मार्च	381.80	511.50	—	627.79	704.50	—

\* 10 अगस्त 1990 को ।

6.40 इन परिसम्पत्तियों का खजाना बनाने के बजाय मुद्रा बाजार की परिसम्पत्तियों की कुल बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य के अन्तर्गत मुद्रा बाजार परिसम्पत्तियों में भा. मि. वि. गृ. की कुल बिक्री में वित्तीय वर्ष 1989-90 में बड़ा उछाल आया । भा. मि. वि. गृ. की 1989-90 में 182 दिवसीय खजाना बिलों की कुल संख्या बिक्री रु. 21,953 करोड़ थी जो गत वर्ष में कुल बिक्री के करीब बुगुने के बराबर थी । चूंकि अप्रैल 1989—मार्च 1990 के दौरान प्रणाली में 182 दिवसीय खजाना बिलों की मासिक औसत बकाया राशियां रु. 777 करोड़ थी, इसका अर्थ यह हुआ कि भा. मि. वि. गृ. प्रणाली के खजाना बिलों की धारिताओं का कुल कारबार 28 गुना करने में सफल रहा । भा. मि. वि. गृ. द्वारा (बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और पारस्परिक निधियों को) दी गई "खजाना बिल" सुविधा के कारण ये संस्थान अल्पावधि के लिए अपने मुद्रा निवेश करके आय प्राप्त करने में सफल रहे हैं और अल्पावधि के लिए बिना अपने निवेशों को स्वयं के लिए मुद्रा में बंधि भी कर सकते हैं । 1990-91 में (10 अगस्त 1990 तक) भा. मि. वि. गृ. का 182 दिवसीय खजाना बिलों का संख्यी कारबार रु. 11,176 करोड़ था ।

6.41 भा. मि. वि. गृ. का वाणिज्यिक बिलों का संख्यी कारबार वर्ष 1989-90 में रु. 10,682 करोड़ था जो पिछले वर्ष के कारबार अर्थात् रु. 2,866 करोड़ से काफी ऊंचा था (सारणी 6.14) ।

सारणी 6.14 : भारतीय मित्रीकाटा और वित्त गृह का मुद्रा बाजार लिखितों का आवर्ती कारबार

(करोड़ रुपये)

	1989-90 (अप्रैल- मार्च)	1988-89 (अप्रैल- मार्च)	1990-91 (10 अगस्त तक)	1988-89 (12 अगस्त तक)
1	2	3	4	5
182 दिवसीय खजाना बिल	21,953	11,024	11,176	6,045
वाणिज्यिक बिल	10,682	2,866	3,967	4,856
मांग मुद्रा	87,927	20,362	50,375	37,922

1	2	3	4	5
मीयादी जमा	214	—	508	—
जमा प्रमाणपत्र	3	—	—	—
वाणिज्यिक पत्र	26	—	35	—

6.42 मांग मुद्रा बाजार में भा. मि. वि. गृ. का कारबार 1989-90 के दौरान तेजी से बढ़कर रु. 87,927 करोड़ हो गया जबकि 1988-89 में रु. 20,362 करोड़ का कारबार था । भा. मि. वि. गृ. का मांग मुद्रा बाजार में दैनिक औसत कारबार 1988-89 में रु. 82 करोड़ से बढ़कर 1989-90 में रु. 242 करोड़ हो गया । 1990-91 में 10 अगस्त 1990 तक मांग मुद्रा परिसम्पत्तियों में भा. मि. वि. गृ. का संख्यी कारबार रु. 50,375 करोड़ या रु. 382 करोड़ का दैनिक औसत था (सारणी 6.14) ।

6.43 गौण बाजार में प्रचलित रूप से अपनी भूमिका अदा करने के लिए भारतीय मित्रीकाटा और वित्त गृह ने अपनी प्राधिकृत शेयर पूंजी में रु. 100 करोड़ से रु. 250 करोड़ की वृद्धि करके और अपनी प्रदत्त पूंजी रु. 100 करोड़ से रु. 150 करोड़ करके अपने संसाधनों को संवर्धित किया । इसने भारतीय रिजर्व बैंक से 182 दिवसीय खजाना बिलों और अल्पावधि वाणिज्यिक बिलों की जमानत पर भी पुनर्वित्त सुविधाओं का लाभ उठाना जारी रखा । सभीशाहीन वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने भा. मि. वि. गृ. को 182 दिवसीय खजाना बिलों का जमानत पर रु. 600 करोड़ और वाणिज्यिक बिलों की जमानत पर रु. 500 करोड़ को उच्चतम पुनर्वित्त सीमा पर स्वीकृत की (सारणी 6.15) । 1989-90 के दौरान 182 दिवसीय खजाना बिलों पर ब्याज दरें 9.50 प्रतिशत और 12.00 प्रतिशत वाणिज्यिक बिलों पर 13.00 प्रतिशत और 20.00 प्रतिशत वाणिज्यिक के बीच रही (सारणी 6.16) । भा. मि. वि. गृ. को उपलब्ध कराए गए पुनर्वित्त पर ली गतिशील ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में प्रचलित परिस्थितियों के आधार पर समायोजित की जाती है, और पुनर्वित्त दरों में अल्प पृथक परिवर्तन का मुद्रा बाजार के माध्यम से व्यापक प्रभाव पड़ेगा विशेषकर क्योंकि पुनर्वित्त दरों में परिवर्तन भा. मि. वि. गृ. के रिजर्व बैंक के वकालत उधारों पर लागू होते हैं और भा. मि. वि. गृ. को इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्वित्त पर ब्याज दरों

सारणी 6 15 भारतीय मितिकाटा और चित्त गृह को दिया गया रिजर्व बैंक का पुनर्वित्त

(क्राई रुपये)

महीने के अंतिम दिन	182 दिवसीय खजाना बिलों की सप्ताहिक प्रतिभूतियां पर पुनर्वित्त				अल्पावधि वाणिज्यिक बिलों पर पुनर्वित्त			
	सीमा	बकाया	माह के दौरान उपयोग का उच्चतम स्तर	स्तर 4 के अनुसार उच्च उपयोग में अनुरूपी सीमा	सीमा	बकाया	माह के दौरान उपयोग का उच्चतम स्तर	स्तर 8 के अनुसार उच्च उपयोग में अनुरूपी सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1989								
जुलाई	100 00	79 29	79 29	100	100 00	--	--	--
अगस्त	100 00	--	100 00 (2-8-1989)	100	100 00	--	--	--
सितंबर	100 00	92 38	92 38 (29-9-1989)	100	100 00	--	--	--
अक्टूबर	100 00	--	375.97 (18-10-1989)	400	100 00	--	95.77 (26-10-1989)	100
नवंबर	400 00	--	538.69 (22-11-1989)	550	100 00	--	149 72 (16-11-1989)	150
दिसंबर	100 00	--	218 73 (20-12-1989)	300	100 00	--	--	--
1990								
जनवरी	100 00	14 40	200 00 (6-1-1990)	200	100 00	--	--	--
फरवरी	500 00	400 68	400 68	500	200 00	195.61	195.61	200
मार्च	500 00	460 35	506 70 (29-3-1990)	600	500 00	492 64	492 64	500
अप्रैल	300 00	--	460 35 (1-4-1990)	500	100 00	24 05	492 64 (1-4-1990)	500
मई	300 00	--	316 89 (22-5-1990)	400	100 00	--	195 12 (16-5-1990)	200
जून	100 00	--	140 58 (18-6-1990)	200	100 00	--	--	--
जुलाई	100 00	--	169 20 (17-7-1990)	200	100 00	--	--	--

मे परिवर्तन के परिणामस्वरूप उसके बाव किए जानेवाले लेन-देनों पर ही बैंक अपनी दरों को समायोजित करना होगा। 1989-90 (जुलाई—जून) में, रिजर्व बैंक की पुनर्वित्त दर में खजाना बिलों के लिए 40 अक्षरों पर और वाणिज्यिक बिलों के लिए 15 अक्षरों पर परिवर्तन किया गया।

6.44 भा.मि.वि.गु. को सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों से सहायता के आधार पर 12 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर से रु. 100 करोड़ की ऋण सुविधा उपलब्ध करायी गई थी। वर्ष के दौरान भा.मि.वि.गु. द्वारा इस से 1 का प्रावधिक-तौर पर उपयोग किया गया।

विनिमय बिलों पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट

6.45 यद्यपि सीमावी विनिमय बिलों पर स्टाम्प ड्यूटी के अक्षर कम थे परन्तु अपेक्षित मूल्यधर्मों के स्टाम्प प्राप्त करने में होने वाली परेशानी और कुछ क्रियाविधि बिल बाजार के विकास की अवरोधित करती रही। अब यह मुख्य प्रशासनिक बाधा हटा दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिशों पर भारत सरकार ने दिनांक 1 अगस्त 1989 की अपनी अधिसूचना द्वारा सीमावी विनिमय बिलों पर स्टाम्प ड्यूटी को माफ कर दिया जहाँ--



संशोधन 6 16 . भारतीय मितोकाटा और वित्त गृह को रिजर्व बैंक के पुनर्वित्त पर व्याज दरें

18.2 दिवसीय सा आना बियों की धारिताओं पर पुनर्वित्त		वाणिज्यिक दिनों पर पुनर्वित्त	
प्रसारणी तारीख	व्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)	प्रसारणी तारीख	व्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)
1	2	3	4
11 अप्रैल, 1989	10.25	11 अप्रैल, 1989	15.00
3 जून, 1989	10.00	12 अप्रैल, 1989	14.50
6 जून, 1989	9.75	19 अप्रैल, 1989	14.00
28 जून, 1989	9.50	27 अप्रैल, 1989	13.00
11 अक्टूबर, 1989	9.75	16 नवंबर, 1989	11.00
12 अक्टूबर, 1989	10.00	22 नवंबर, 1989	13.00
16 अक्टूबर, 1989	10.25	20 फरवरी, 1990	14.00
17 अक्टूबर, 1989	10.50	28 फरवरी, 1990	15.00
23 अक्टूबर, 1989	10.25	12 मार्च, 1990	15.50
24 अक्टूबर, 1989	11.00	24 मार्च, 1990	16.50
31 अक्टूबर, 1989	9.50	29 मार्च, 1990	18.00
6 नवंबर, 1989	10.00	30 मार्च, 1990	20.00
8 नवंबर, 1989	10.50	5 अप्रैल, 1990	18.00
10 नवंबर, 1989	11.00	10 अप्रैल, 1990	16.50
16 नवंबर, 1989	11.50	11 अप्रैल, 1990	14.00
21 नवंबर, 1989	11.75	17 अप्रैल, 1990	13.00
23 नवंबर, 1989	11.00	14 मई, 1990	14.00
4 दिसम्बर, 1989	10.00	16 मई, 1990	15.00
13 दिसम्बर, 1989	9.50	24 मई, 1990	13.00
18 दिसम्बर, 1989	10.00		
20 दिसम्बर, 1989	10.50		
26 दिसम्बर, 1989	9.50		
1 जनवरी, 1990	10.00		
17 जनवरी, 1990	9.50		
5 फरवरी, 1990	10.00		
8 फरवरी, 1990	9.50		
19 फरवरी, 1990	10.50		
24 फरवरी, 1990	11.00		
28 फरवरी, 1990	11.50		
3 मार्च, 1990	11.00		
20 मार्च, 1990	10.50		
24 मार्च, 1990	11.00		
26 मार्च, 1990	11.50		
29 मार्च, 1990	12.00		
31 मार्च, 1990	11.50		
10 अप्रैल, 1990	10.50		
2 मई, 1990	9.50		
7 मई, 1990	10.00		
16 मई, 1990	10.50		
21 मई, 1990	11.25		
26 मई, 1990	10.75		
2 जून, 1990	10.25		
18 जून, 1990	10.50		
25 जून, 1990	10.00		
2 जुलाई, 1990	10.50		
9 जुलाई, 1990	10.00		
16 जुलाई, 1990	10.50		
21 जुलाई, 1990	10.00		

- (क) ऐसे विनिमय बिल तारीख या प्रस्तुति के तीन महीनों से अनधिक समय के बाद देय है;
- (ख) ऐसे विनिमय बिल वाणिज्य बैंक या सहकारी बैंक पर या द्वारा या के पक्ष से ग्राह्यित है, और
- (ग) ऐसे विनिमय बिल वाणिज्यिक वाणिज्यिक या व्यापारिक लेन-देनों की वजह से इस्तेमाल में लाए गए हैं।

इस उपाय के वाणिज्यिक बिल प्रणाली का प्रोत्साहित करके भुगतान प्रणाली में सुधार लाने से आने वाले समय में लाभदायक निष्ठ हानि की सम्भावना है।

#### वाणिज्यिक बिलों की पुनर्भुनाई

6.46 बिल पुनर्भुनाई बाजार का क्षेत्र और व्यापक बनाने की दृष्टि से वर्ष के दौरान बिल पुनर्भुनाई बाजार में हिस्सा लेने के लिए चयनात्मक आधार पर कुछ और मस्याओं को प्रवेश दिया गया था। तदनुसार ममीक्षधीन वर्ष के दौरान भारतीय निर्यात-आयात बैंक सीवन बीमा निगम पारम्परिक निधि, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भापाल, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, खवाई, तमिलनाडु राज्य शीर्ष सहकारी बैंक लिमिटेड, मद्रास और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को बिल पुनर्भुनाई बाजार में प्रवेश की स्वीकृति दी गई थी।

#### 182 दिवसीय खजाना बिलों की नीलामिया

6.47 जुलाई-जून 1989-90 के दौरान 27 जन 1990 तक 182 दिवसीय खजाना बिलों की 26 पाक्षिक नीलामिया की गईं। नीलामियों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही। स्वीकार की गई बोलियों की उच्चतम औसत वार्षिक आय में सामान्यतया वृद्धि की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई और यह आय 11 जुलाई 1989 को हुई नीलामी में 9.75 प्रतिशत से बढ़कर 27 जन

1990 को हुई नीलामी में 9.97 प्रतिशत हो गई। 29 जून 1990 को प्रणाली में 182 दिवसीय खजाना बिलों का बकाया शीर्ष स्तर रु. 1,439.44 करोड़ था (सारणी 6.17)। बैंकों ने खामकर इस बहुमुखी मुद्रा बाजार लिखन के निर्णीत लाभों को स्वीकार किया और वे प्राथमिक नीलामियों में आगे बढ़कर लाभ ले रहे हैं एवं गण बाजार में सचित्र रूप से कारबार कर रहे हैं।

#### अंतर-बैंक सहभागिता

6.48 केवल कुछ बैंकों ने ही अब तक छोटी राशियों के लिए जोखिम भागीदारी के साथ अंतर-बैंक सहभागिता (आईबीपी) जारी की है। तीन महीने परिपक्वता अवधि वाली अंतर-बैंक सहभागिताएं अधिमानित परिपक्वतया वाली प्रतीत होती हैं। व्याज दरें 14 प्रतिशत से 17 प्रतिशत वार्षिक के बीच रही।

#### जमा प्रमाणपत्र

6.49 वर्ष के दौरान जून 1989 में चालू की गई जमा प्रमाणपत्रों की योजना ने महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाई। 1988-89 (अप्रैल-मार्च) में पाक्षिक आमत बकाया कुल जमा राशियों के 1 प्रतिशत के आधार पर बैंकिंग तंत्र द्वारा जमा प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए कुल अनुमत सीमाएँ रु. 1,264 करोड़ थीं। 20 अप्रैल 1990 को 36 बैंकों द्वारा, जमा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सीमाओं को मशॉरित किये जाने से पहले, जारी जमा प्रमाणपत्रों की बकाया राशि रु. 1,247 थी (सारणी 6.18)। अल्पावधि में 3 महीने की परिपक्वता और दीर्घावधि में एक वर्ष की परिपक्वता सामान्यतया निवेशकों के बीच लोकप्रिय है। यद्यपि, 3 महीने की परिपक्वता अवधि के लिए व्याज दरें 9.0 प्रतिशत में 16.33 प्रतिशत के बीच रही।

सारणी 6.17. भारत सरकार के 182 दिवसीय खजाना बिल

नीलामी की तारीख	दी गई बाली			स्वीकृत बाली				
	संख्या	कुल मूद्रागत राशि (करोड़ रुपये)	राशि	संख्या	कुल मूद्रागत राशि (करोड़ रुपये)	100 रु. के अंकित मूल्य के लिए उच्चतम मूल्य	उच्चतम लाभ (प्रतिशत वार्षिक)	बकाया खजाना बिलों की कुल राशि (करोड़ रुपये)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1989								
जुलाई	11	7	231.50	17	169.00	95.35	9.75	467.90
	26	13	87.00	12	84.00	95.31	9.78	539.80
अगस्त	9	22	179.90	15	143.50	95.34	9.78	657.05
	22	18	122.65	15	106.65	95.33	9.80	749.05
सितम्बर	6	28	162.25	17	96.25	95.33	9.80	840.15
	20	24	216.95	13	127.95	95.33	9.80	965.85
अक्तूबर	4	17	70.50	10	46.00	95.33	9.80	990.85
	18	16	47.00	9	24.80	95.32	9.82	946.65
नवम्बर	1	17	146.50	8	96.50	95.32	9.82	1,002.65
	15	4	6.20	1	2.20	95.36	9.73	995.35
	29	20	100.70	13	90.70	95.31	9.84	1,067.55
दिसम्बर	14	14	36.70	6	17.20	95.31	9.81	1,076.25
	27	23	138.80	17	102.80	95.30	9.86	1,106.55
1990								
जनवरी	10	15	81.00	9	40.00	95.30	9.86	977.55
	23	15	126.50	13	115.50	95.29	9.89	1,009.05

	1	2	3	4	5	6	7	8
फरवरी	7	19	131.35	12	80.10	95.29	9.89	946.65
	20	16	81.55	11	65.95	95.28	9.91	905.95
मार्च	7	18	64.30	11	29.05	95.27	9.93	838.75
	21	15	80.00	10	63.50	95.26	9.95	774.30
अप्रैल	4	13	62.00	5	37.50	95.26	9.95	765.80
	18	24	130.40	16	82.90	95.25	9.97	823.90
मई	2	18	111.34	10	60.84	95.25	9.97	788.24
	16	22	286.10	9	200.10	95.25	9.97	986.14
जून	30	15	351.00	9	305.50	95.25	9.97	1,200.94
	13	19	227.00	8	162.50	95.25	9.97	1,346.24
	27	21	258.00	11	196.00	95.25	9.97	1,439.44
जुलाई	11	21	149.00	10	90.50	95.25	9.97	1,489.94
	25	20	194.00	11	101.50	95.25	9.97	1,475.44
अगस्त	8	27	536.00	19	416.00	95.25	9.97	1,811.34

3 महीनों के लिए विशिष्ट रूप से प्रस्तावित दरें 11.0 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत के अंतर में थी। एक वर्ष की परिपक्वता के लिए दरें 10.5 प्रतिशत और 14.29 प्रतिशत के बीच रहीं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जमा प्रमाणपत्र प्रारक्षित अपेक्षाओं के अधीन है, जमा प्रमाणपत्रों पर प्रस्तावित ब्याज दरें सापेक्ष रूप से काफी उंची है। जमा प्रमाणपत्रों के लिए प्राथमिक बाजारों के विशाल आकार के बावजूद गौण बाजार में वस्तुतः कोई गतिविधि नहीं रही। कुछ सीमा तक इसका कारण यह तथ्य है कि जमा प्रमाणपत्रों की कीमतें बहुत अधिक रखी गई हैं और प्राथमिक बाजार में धारक

सामान्यता यह चाहता है कि जमा प्रमाणपत्रों की परिपक्वता की अवधि तक अपने पास रखे। 1989-90 (अप्रैल-मार्च) में कुल जमा राशियों के पाक्षिक औसत बकाया के 2 प्रतिशत के आधार पर जमा प्रमाणपत्रों की जारी करने के लिए बैंक सीमा बढ़ाने के निर्णय के परिणामस्वरूप जमा प्रमाणपत्र जारी करने हेतु बैंकिंग तंत्र के लिए कुल सीमा रु. 3,017 करोड़ रही और दिनांक 13 जुलाई 1990 को 37 बड़े बैंकों के बकाया रु. 2,000 करोड़ या इन बैंकों की कुल सीमाओं के 70.4 प्रतिशत थे।

सारणी 6.18 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाणपत्र

निम्नलिखित को समाप्त पखवाड़ा	बैंकों की संख्या जिन्होंने जमा प्रमाणपत्र जारी किए (पखवाड़े के अंत में)	कुल बकाया (करोड़ रुपये)	सभी परिपक्वता अवधियों के लिए पखवाड़े के दौरान जारी किए गए जमा प्रमाणपत्रों की लागू ब्याज दर (सीमा) (वार्षिक प्रतिशत)
1	2	3	4
1989			
जुलाई	28	12	9.00--14.00
अगस्त	11	20	9.00--12.50
	25	23	10.25--12.50
सितम्बर	8	25	10.00--12.00
	22	28	10.00--12.50
अक्तूबर	6	30	10.00--12.50
	20	32	10.00--15.00
नवंबर	3	34	10.25--12.50
	17	35	10.25--13.00
दिसंबर	1	36	10.00--12.70
	15	36	9.50--12.67
	29	36	10.00--13.03

1	2	3	4
1990			
जनवरी	13	36	82.4
	26	35	84.6
फरवरी	9	35	89.7
	23	35	92.9
मार्च	9	34	102.3
	23	36	110.3
अप्रैल	6	36	122.8
	20	36	124.7
मई	4	36	131.8
	18	36	144.0
जून	1	36	145.4
	15	36	172.9
	29	37	182.6

## वाणिज्यिक पत्र

6.50 वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान मुद्रा बाजार में आने वाला दूसरा नया लिखत, वाणिज्यिक पत्र है। जनवरी 1990 में रिजर्व बैंक ने बैंकों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जो "गैर-बैंकिंग कंपनी (वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से जमा राशियां स्वीकार करना) निदेश, 1989" में दिए गए हैं। वाणिज्यिक पत्र का निर्गम बैंकिंग तंत्र के लिए समग्र रूप से सूचित करता है कि इसके अग्रणी संविभाग का एक भाग जमानत के रूप में रखा जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक पत्र का निर्गम पाक्षिक अंतर पर प्राधिकृत करता है, यह अंतर वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत कंपनियों को बाजार में कंपनियों के अगले बैंक के प्रवेश करने से पूर्व एक पक्षवाड़े में अपनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कम में रखने के दृष्टिकोण से आवश्यक होगा। इसके प्रतिरुद्ध, वाणिज्यिक पत्र बाजार में प्रवेश करने के लिए पातला मुस्पट मानवण्डों पर आधारित है जिसका कंपनियां अपने लिए बिना किसी कठिनाई के अनुमान लगा सकती हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वाणिज्यिक पत्र एक मजबूत लिखत के रूप में विकसित होता है और इस बात का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि केंद्रीय बैंकों ने विकसित वित्तीय बाजारों में भी वाणिज्यिक पत्र बाजार के विकास के प्रारंभिक चरणों में एक व्यवस्थित श्रम को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक समझा।

6.51 जनवरी 1990 में कंपनियों को वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। 10 अगस्त 1990 को 16 कंपनियों द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्र की बकाया राशि रु. 155.50 करोड़ थी। वाणिज्यिक पत्रों के सभी निर्गमों में प्रत्येक की परिपक्वता धराधि एक समान रूप से 180 दिन की है। जारी किए गए वाणिज्यिक पत्रों की प्रभावी व्याज दरें 11.87 प्रतिशत और 13.32 प्रतिशत के बीच में थी। यह एक छ्यान देने योग्य रोचक विषय है कि सीमित मात्रा के वाणिज्यिक पत्रों के निर्गमों के बावजूद कुछ गौण बाजार कारवार हुआ। अप्रैल 1990 में वाणिज्यिक पत्र के निर्गमों से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों में नगदी के साथ कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक पत्र निर्गम के और अधिक शक्ति पकड़ने की प्रार्थना है।

सारणी 6.19 भारतीय मितिकाटा और बिना गृह की मार्ग मुद्रा उधार दरें

उधार दर (प्रतिशत धराधि)

विनांक को समाप्त पक्षवाड़े के लिए	स्युनतम	उच्चतम	मध्यम दर का औसत*
1	2	3	4
14 जुलाई, 1989	5.50	11.00	9.85
28 जुलाई, 1989	6.50	10.50	8.85

1	2	3	4
11 अगस्त, 1989	8.25	12.00	9.85
25 अगस्त, 1989	7.25	10.75	9.30
8 सितम्बर, 1989	7.25	10.50	9.15
22 सितम्बर, 1989	8.75	10.75	9.60
6 अक्टूबर, 1989	6.50	13.50	11.30
20 अक्टूबर, 1989	10.50	20.00	14.80
3 नवम्बर, 1989	8.74	21.00	15.15
17 नवम्बर, 1989	14.50	27.00	18.70
1 दिसम्बर, 1989	7.00	25.00	13.20
15 दिसम्बर, 1989	7.50	13.50	10.45
29 दिसम्बर, 1989	9.25	15.50	12.35
12 जनवरी, 1990	10.50	15.00	12.35
26 जनवरी, 1990	8.70	14.00	10.85
9 फरवरी, 1990	6.50	12.75	11.10
23 फरवरी, 1990	10.25	25.00	15.80
9 मार्च, 1990	7.00	28.00	16.65
23 मार्च, 1990	10.00	34.00	21.50
6 अप्रैल, 1990	10.00	58.25	40.05
20 अप्रैल, 1990	13.00	22.00	15.90
4 मई, 1990	8.75	23.75	17.50
18 मई, 1990	13.00	36.00	23.00
1 जून, 1990	9.50	38.00	21.65
15 जून, 1990	13.00	14.00	13.50
29 जून, 1990	11.00	11.50	11.50
13 जुलाई, 1990	8.50	13.75	11.45
27 जुलाई, 1990	7.50	12.25	10.10
10 अगस्त, 1990	8.00	11.00	9.50

\*यह दैनिक मध्यम दरों का साधारण औसत है।

मार्ग मुद्रा बरो में घट बढ

6.52 समीक्षाधीन अवधि के दौरान मार्ग मुद्रा बाजार की व्याज दरों में काफी उतार-चढ़ाव का समय देखा गया। मार्ग मुद्रा बरो में पाया गया एक

स्थूल स्वरूप यह था कि मांग मुद्रा दरों सूचनाधीन पखवाड़े के प्रथम सप्ताह में तेजी से बढ़ी और बैंकों द्वारा अपनी नकदी-प्रारक्षित अपेक्षाओं को पूरा कर लेने पर दमरे सप्ताह में उनमें गिरावट आयी। मई 1989 से मांग मुद्रा दरों को मुक्त छोड़ देने से बहुत से बैंक उधार देने और उधार लेने में, इनमें परिवर्तन कर रहे हैं और इस प्रकार बाजार के असंतुलन को कम करने में योगदान दे रहे हैं। मांग मुद्रा बाजार में भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह की ऋण दरों के गत, शीर्ष और मध्यम दरों के औसत सारणी 6.19 में दिए गए हैं।

6.53 मांग मुद्रा दरों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव का उत्तरदायित्व अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर भी है। उत्पाद आधार पर प्रारक्षित नकदी अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु कुछ निश्चित दिनों पर बड़े उधार लिए जा रहे हैं और जब प्रारक्षित नकदी अपेक्षाएँ पूरी हो जाती हैं तो निधियों की मांग तेजी से गिर जाती है। और साथ ही कुछ बैंकों के ऋण परिचालन उनके अपने स्रोतों से नहीं होते हैं और इन बैंकों की ऋण स्थिति अतिविस्तृत रहती है। ये बैंक मांग मुद्रा बाजार को, निधियों के स्रोत और उपयोग में हाँचागत असंतुलन को पूरा करने का स्रोत मानते हैं। अन्य तथ्यों के अलावा मांग मुद्रा बाजारों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव का पता बैंकों में निधियों के प्रबंधन के मामले की निश्चित सीमा तक लगाया जा सकता है। मांग मुद्रा बाजार में भाग लेनेवालों की वृद्धि और प्रारक्षित नकदी अपेक्षाओं की कमियों पर दण्ड में कमी से भी मांग मुद्रा बाजार में व्याज दर शीर्षों को संतुलित करने में सहायता मिलनी चाहिए। उदाहरण के रूप में क्रमिक दण्डों की पूर्व अनुसूची के आधार पर कमी की लागत 5 प्रतिशत की कमी के लिए 150 प्रतिशत के आसपास थी जबकि संशोधित अनुसूची के अनुसार दण्ड 30 प्रतिशत के आसपास होगा। मांग मुद्रा दरों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव केवल तभी कम होगा जब बड़े पुराने उधार लेने वाले कुछ बैंक अपनी प्रारक्षित अपेक्षाओं को बनाए रखने के लिए मांग मुद्रा बाजार पर अपनी निर्भरता कम करें।

## 7. मूल्य स्थिति की समीक्षा

7.1 गत वर्ष की भरपूर फसल के अतिरिक्त खरीफ फसल में उत्पादन में उच्चतम वृद्धि के बावजूद मूल्य वृद्धि की समग्र दर में 1989-90 में पुनः वृद्धि हुई जो वर्ष 1988-89 में कुछ सीमा तक संयत थी। 1989-90 में पुनः इस भारी वृद्धि के अतिरिक्त 1989-90 के दौरान मूल्यों में मौसमी वृद्धि की दर काफी अधिक थी जबकि मौसमी गिरावट की प्रवृत्ति कमजोर थी, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति के दबाव बराबर बने रहे। 'प्राथमिक वस्तुओं' के साथ-साथ 'विनिर्मित' उत्पादों के मूल्यों में भारी तथा व्यापक वृद्धि के कारण ये दबाव सामान्य स्वरूप के भी थे। चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 की पहली तिमाही के दौरान पण्यों के मूल्यों पर इनके दबावों में और वृद्धि हुई और विशेषकर 'प्राथमिक वस्तुओं' के मूल्यों पर। पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में कार्य कर रहे बहुत से घटकों—जैसे कि कुछ आवश्यक पण्यों—उदाहरणार्थ दालों, चाय, चीनी, तिलहन, खाद्य तेल और सीमेंट की मांग-आपूर्ति में असंतुलन विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि की कठिन स्थिति के कारण आयात के माध्यम से कम आपूर्ति वाले पण्यों की आपूर्ति में वृद्धि की कठिनाइयों कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों के सरकारी मूल्यों में वृद्धि, आयात लागतों में वृद्धि और इन सबसे ऊपर पिछले वर्ष की अत्यधिक मौद्रिक वृद्धि से जुड़े वित्तीय घाटों से उत्पन्न चलनिधि की वृद्धि के कारण मुद्रा स्फीति की यह मिलीजुली स्थिति रही है।

7.2 बिन्दुवार आधार पर 1989-90 में थोक मूल्य सूचकांक में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो गत वर्ष की वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक अर्थात् 3.4 प्रतिशत तक अधिक थी जबकि औसत के आधार पर यह कुल मिलाकर एक समान ही थी। वर्ष 1989-90 के दौरान बिन्दुवार आधार

पर ग्राम ज़रूरत की अनेक वस्तुओं जैसे दाल, चाय, चीनी खांडसारी और गुड़, खाद्यतेल तथा सूती-वस्त्र में तीव्र वृद्धि परिलक्षित हुई। गत वर्ष भी खाद्यतेलों को छोड़कर इन सभी पण्यों के मूल्यों में व्यापक वृद्धि दर्ज की गई थी। दालों तथा चीनी, खाण्डसारी और गुड़ के मामले में लगातार तीस वर्ष भी यकायक भारी वृद्धि रही। यहाँ यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि जहाँ खाद्यान्नों के मूल्यों में बिन्दुवार आधार पर गिरावट देखने में आयी वहाँ गतवर्ष मूल्यों में यकायक वृद्धि के कारण औसत के आधार पर इनमें वृद्धि दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त दूध और चीनी, खाण्डसारी तथा गुड़ के मूल्यों में औसत के आधार पर बिन्दुवार आधार पर पायी जाने वाली वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि दर्ज की गई। गेहूँ के मूल्य सूचकांक में आयी गिरावट के कारण, वर्ष 1989-90 में बिन्दुवार आधार पर खाद्यान्नों के मूल्य सूचकांक में आयी गिरावट एक उत्साहवर्धक बात रही।

## वार्षिक प्रवृत्तियाँ

7.3 थोक मूल्य सूचकांक (आधार : 1981-82=100) में वृद्धि की दर, जो बिन्दुवार आधार पर 1987-88 के सूखा वर्ष में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि से वर्ष 1988-89 में गिरकर 5.7 प्रतिशत रह गयी थी, 1989-90 (सारणी 7.1) में इस में पुनः वृद्धि हो गयी जो बढ़कर 9.1 प्रतिशत हो गया, यह वृद्धि वर्ष 1988-89 में भरपूर फसल होने के बाद खरीफ की अच्छी पैदावार के बावजूद हुई। तथापि औसत के आधार पर थोक मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि 7.4 प्रतिशत थी जो गत वर्ष में हुई वृद्धि जैसी ही थी।

7.4 बिन्दुवार आधार पर औद्योगिक कामगारों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1982=100) में वर्ष 1989-90 में 6.6 प्रतिशत वृद्धि हुई। यह वृद्धि औसत के आधार पर और बिन्दुवार आधार पर समान थी जबकि गत वर्ष तदनुसार वृद्धि 8.6 प्रतिशत और 9.1 प्रतिशत हुई थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अपेक्षाकृत कम वृद्धि की दर अंशतया वर्ष 1989-90 में खाद्यान्नों, विशेष रूप से गेहूँ की कीमतों में गिरावट की वजह से रही।

## समूहवार प्रवृत्तियाँ

7.5 समूहवार और बिन्दुवार आधार पर 'प्राथमिक वस्तुओं' के मूल्यों में वर्ष 1989-90 में भारी वृद्धि देखी गयी जबकि इसके ठीक विपरीत 1988-89 में थोड़ी-सी गिरावट आयी थी। वहाँ 'विनिर्मित उत्पादों' के सूचकांक में मामूली बहुतेरी देखने में आयी। 'ईंधन शक्ति, विद्युत और स्तेहकों' वाले तीसरे मुख्य समूह में भी वृद्धि का दर गत वर्ष की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत कुछ कम देखने में आयी। अतः 'प्राथमिक वस्तुओं' के सूचकांक में 6.4 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि गत वर्ष उसमें 0.2 प्रतिशत की गिरावट आयी थी। 'विनिर्मित उत्पादों' के सूचकांक, में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1988-89 में यह वृद्धि 9.2 प्रतिशत थी, ईंधन समूह के सूचकांक में गत वर्ष के दौरान हुई 5.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औसत के आधार पर समूहवार सूचकांकों द्वारा जो प्रवृत्ति पेश की गई उससे उनके विभिन्न मौसमी उतार-चढ़ाव के कारण एक भिन्न स्थिति का पता चलता था। 'प्राथमिक वस्तुओं' से संबंधित समूह ने गत वर्ष की 4.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी, "विनिर्मित उत्पादों" के समूह ने 9.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 11.3 प्रतिशत की अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि दर्शायी जबकि पिछले वर्ष 'ईंधन के समूह' में 5.4 प्रतिशत की तुलना में 3.6 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई।

## सारणी 7 1. थोक मूल्यों के सूचकांक : मुख्य पण्यमूह

(आधार : 1981-82 = 100)

मुख्य समूह	भारतक	वार्षिक मूल्य सूचकांक					प्रतिशत में घट-बढ़			
		28 मार्च	31 मार्च	31 मार्च	1 जुलाई	30 जून	राजकीय वर्ष		प्रथम तिमाही	
		1988	1989	1990	1989	1990	1988-89	1989-90	1989-90	1990-91
							(कालम 3 की तुलना में कालम 4)	(कालम 4 की तुलना में कालम 5)	(कालम 4 की तुलना में कालम 6)	(कालम 5 की तुलना में कालम 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सर्वा पण्य	100.00	148.5	156.9	171.1	162.9	177.5	5.7	9.1	3.8	3.7
प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन, शक्ति,	32.295	157.1	156.8	166.9	162.6	181.3	-0.2	6.4	3.7	8.6
विद्युत और स्नेहक	10.663	147.7	155.2	164.9	155.5	169.2	5.1	6.3	0.2	0.8
विनिर्मित उत्पाद	57.012	143.9	157.2	174.7	164.4	177.4	9.2	11.1	4.6	1.5

अ = अतिम

## सौसमी प्रवृत्ति

7.6 विन्दवार आधार पर थोक मूल्यों की सौसमी प्रवृत्ति के मूल्यांकन से पता चलता है (सारणी 7.2) कि मार्च के अन्त से अगस्त 1989 के अन्त के बीच की अवधि वाले प्रथम चरण के दौरान मूल्य वृद्धि गत वर्ष के तुल्य रूप अवधि की तुलना में काफी भीषण थी। अगस्त के अन्त से दिगंबर के अन्त तक की अवधि का द्वितीय चरण, जिसकी सामान्य विशेषता थोक मूल्यों के सूचकांक में सौसमी गिरावट होती है, में मूल्यों में मामूली भी गिरावट आयी (-0.4 प्रतिशत) गत वर्ष के तुल्य रूपी चरण में थोक मूल्यों

के सूचकांक (सामान्य सूचकांक) में किसी भी तरह का उभार-चढ़ाव देखने में नहीं आया। अन्तिम चरण के दौरान, जिसमें दिसम्बर अन्त से मार्च अन्त तक की अवधि आती है, वर्ष 1988-89 के अन्तिम चरण की तुलना में, मूल्यों में अपेक्षाकृत कुछ अधिक ही वृद्धि हुई। यद्यपि वर्ष 1989-90 में 'प्राथमिक वस्तुओं' के समूह के सूचकांक से सौसमी प्रवृत्ति का पता चलता है कि वे सामान्य सौसमी प्रवृत्ति (गत वर्ष इस प्रकार की स्थिति नहीं थी) के अनुरूप थीं, फिर भी दो वृद्धिशील चरणों में समूह के सूचकांक में वृद्धि की सीमा उल्लेखनीय रूप से अधिक (अर्थात् प्रथम चरण में 6.8 प्रतिशत और अन्तिम चरण में 3.3 प्रतिशत) थी।

## सारणी 7 2 थोक मूल्यों के सूचकांक में उभार-चढ़ाव के तीन चरण

(आधार : 1981-82 = 100)

(विन्दवार आधार पर प्रतिशत घट-बढ़)

मुख्य समूह	प्रथम चरण			द्वितीय चरण			तृतीय चरण		
	मार्च अन्त से अगस्त अन्त तक			अगस्त अन्त से दिसम्बर अन्त तक			दिसम्बर अन्त से मार्च अन्त तक		
	1987-88	1988-89	1989-90	1987-88	1988-89	1989-90	1987-88	1988-89	1989-90
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सर्वा पण्य		8.1	3.9	6.5	0.9	--	-0.4	1.4	1.7
प्राथमिक वस्तुएं		16.3	2.8	6.8	-1.3	-0.5	-3.5	0.8	-2.4
ईंधन, शक्ति, विद्युत और स्नेहक]		1.2	1.5	0.5	3.0	10.7	0.8	1.0	2.8
विनिर्मित उत्पाद		4.8	5.0	7.3	1.9	0.1	1.1	2.0	3.9

## पण्य-वार घट-बढ़

7.7 सारणी 7.3 में बिन्दुवार तथा औसत दोनों के आधार पर मूल्यों के पण्यवार आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। बिन्दुवार आधार पर चाय के मूल्यों में गत वर्ष के दौरान हुई 6.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1989-90 में 1.6 की थोड़ी-सी वृद्धि परिलक्षित हुई जबकि गेहूँ के मूल्यों में 1988-89 के दौरान 12.5 प्रतिशत की वृद्धि के विपरीत 16.6 प्रतिशत की गिरावट आयी, इसका प्रमुख कारण है इन पण्यों की पैदावार में हुई भारी वृद्धि और व्यापक स्तर पर सरकारी खरीद किए जाने के कारण आपूर्ति की स्थिति में काफी सुधार हुआ। दो अच्छी फसलें होने के बावजूद दालों के मूल्यों में 11.2 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई। जउक गत वर्ष यह वृद्धि 11.1 प्रतिशत थी। चाय के उत्पादन में हुई कमी और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चाय की मांग के कारण घरेलू उपलब्धता में कमी आने की वजह से चाय के मूल्यों में 29.7 प्रतिशत की और वृद्धि (1988-89 में 41.4 प्रतिशत) हो गयी। तिलहन की उपलब्धता पर्याप्त न होने के परिणामस्वरूप तिलहन के मूल्यों में 27.4 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई जबकि गत वर्ष के दौरान उनके मूल्यों में लगभग उतने ही प्रतिशत की तीव्र गिरावट (23.3 प्रतिशत) आयी थी। इसी प्रकार खाद्य तेल के उत्पादन में आयी कमी और आयात में कटौती किए जाने की वजह से इसके मूल्यों में 17.2

प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की गयी जबकि इसके विपरीत गत वर्ष के दौरान 7.4 प्रतिशत की कमी हुई थी। चीनी के मामले में, गत वर्ष के दौरान मूल्यों में हुई कुल 5.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वृद्धि का कारण उपभोक्ता-मांग में बढ़ोतरी तथा अत्यधिक सट्टेबाजी थी। सूनी दालों के मूल्यों में वर्ष 1988-89 के दौरान हुई 8.2 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि की तुलना में 16.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रुई ही केवल एक मात्र ऐसा पण्य था जिस के मूल्य सूचकांक में उल्लेखनीय अर्थात् 17.6 प्रतिशत गिरावट देखी गयी। यह गिरावट रुई की भरपूर फसल के कारण थी।

7.8 औसत के आधार पर थोक मूल्यों के आंकड़ों में कतिपय पण्यों के मामले में बिन्दुवार आधार की तुलना में एक भ्रमण ही स्थिति का पता चलता है, जिसका कारण मौसमी प्रभावों का एक वित्तीय वर्ष से दूसरे वित्तीय वर्ष में बना रहना था। अनाजों, दूध, चाय और चीनी, खाण्डसारी तथा गुड़ के मामले में देखी गयी पूर्ववर्ती प्रवृत्तियों के भ्रमावा, जिन अन्य आवश्यक पण्यों में महत्वपूर्ण भिन्न प्रवृत्तियां देखी गयी वे दालें, फल और सब्जियां, मसाले, निसहन, पेट्रोलियम, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, कच्चा कोयला, खनिज तेल तथा खाद्य तेल थे। (सारणी 7.3)

सारणी 7.3: थोक मूल्यों के सूचकांक में घट-बढ़

(आधार: 1981-82 = 100)

## प्रमुख समूह/समूह/पण्य

## निम्नलिखित वर्षों के दौरान प्रतिशत में घट-बढ़

भागक	वित्तीय वर्ष		प्रथम तिमाही				
	बिन्दुवार		औसत		बिन्दुवार		
	1988-89	1989-90	1988-89	1989-90	1989-90	1990-91	(अन्ततिम)
1	2	3	4	5	6	7	8
सभी पण्य	100.000	5.7	9.1	7.4	7.4	3.8	3.7
1. प्राथमिक वस्तुएं	32.195	-0.2	6.4	4.9	2.1	3.7	8.6
खाद्य वस्तुएं	17.386	3.6	2.1	9.9	1.2	5.1	11.2
(क) अनाज	6.824	9.2	-6.2	11.7	2.2	-0.6	7.8
(i) चावल	3.685	6.7	1.6	19.5	4.7	4.8	5.6
(ii) गेहूँ	2.248	12.5	-16.6	14.6	-3.8	-10.1	-13.3
(ख) दालें	1.093	11.1	11.2	30.2	2.9	8.8	6.3
(ग) फल व सब्जियां	4.089	-12.2	1.6	2.9	-8.1	15.7	25.7
(घ) दूध	1.961	13.9	4.5	13.7	8.9	5.8	1.9
(ङ) अंडे, मछली और मांस	1.783	4.2	6.3	8.0	4.5	2.9	1.4
(च) मिर्च-मसाले, बटनी आदि	0.947	-8.6	5.4	10.6	-13.8	-2.5	13.1
(छ) अन्य-खाद्य वस्तुएं	0.689	25.9	26.1	5.2	46.0	9.9	16.7
(i) चाय	0.564	41.4	29.7	5.4	55.0	12.8	16.2
2. गैर-खाद्य वस्तुएं	10.081	-7.0	10.4	-1.7	3.4	1.8	6.8
(क) रेशे	1.791	12.0	-4.0	9.9	11.0	0.8	5.1
(i) कपास	1.335	3.7	-17.6	5.6	4.3	-3.4	10.2
(ख) निसहन	3.861	-23.3	27.4	-15.4	1.1	7.5	11.6

1	2	3	4	5	6	7	8
3. खनिज	4.828	0.4	10.8	-1.9	3.7	1.2	-0.2
i. पेट्रोलियम कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस	4.274	-2.1	12.5	-4.6	2.9	0.8	0.0
ii. ईंधन, रास्मिन, बिजली और स्नेहक	10.683	5.1	6.3	5.4	3.6	0.2	0.8
क. कच्चा कोयला	0.353	13.3	0.0	16.2	9.9	0.0	0.0
ख. खनिज तेल	6.666	1.1	9.1	2.3	0.5	-0.2	0.5
ग. बिजली	2.741	8.3	4.7	5.9	6.3	1.0	1.8
iii. विनिर्मित उत्पाद	57.042	9.2	11.1	9.4	11.3	4.6	1.5
क. चीनी, खाण्डसारी और गुड़	4.059	13.1	13.1	8.3	19.7	16.1	6.3
i. चीनी	2.013	5.8	10.5	7.0	11.6	6.3	-0.8
ii. खाण्डसारी	0.300	8.6	36.4	9.7	32.2	30.4	-2.1
iii. गुड़	1.746	23.1	12.7	9.6	27.0	25.0	15.2
ख. खाद्य तेल	2.445	-7.4	17.2	-2.9	4.0	5.5	9.2
ग. सूती वस्त्र	6.093	8.2	16.6	10.5	13.9	4.2	-0.3
घ. रसायन और रसायन उत्पाद	7.355	2.7	4.8	2.9	3.1	0.3	0.8
ङ. सीमेंट	0.860	11.2	14.9	-4.4	11.0	-0.4	-0.7
च. लोहा और इस्पात	2.441	10.4	11.8	14.1	15.5	4.2	0.0

## भारतक योगदान

7.9 धोक मूल्यों के सामान्य सूचकांक में वृद्धि हेतु विभिन्न समूहों/पण्यों के भारांकित योगदान के मूल्यांकन से पता चलता है कि बिन्दुवार आधार पर 32.3 प्रतिशत भारांक वाली प्राथमिक वस्तुओं के समूह ने सामान्य सूचकांक में 1989-90 की कुल मूल्य वृद्धि में 23.0 प्रतिशत का योगदान किया जबकि 1988-89 में यह योगदान तकारात्मक अर्थात् 1.2 प्रतिशत था। 10.7 प्रतिशत भारांक वाले 'ईंधन समूह' ने सामान्य सूचकांक में 1988-89 के 9.5 प्रतिशत की तुलना में 7.3 प्रतिशत का योगदान

किया। इस संबंध में सब से अधिक योगदान "विनिर्मित उत्पादों" के समूह जिनका भारांक 57.0 प्रतिशत था, ने किया तथा सामान्य सूचकांक में इनका कुल मूल्य वृद्धि का योगदान 1988-89 के 90.3 प्रतिशत की तुलना में 1989-90 में 70.3 प्रतिशत आका गया। "विनिर्मित उत्पादों" के अन्तर्गत सूती वस्त्रों का भारांकित योगदान 10.4 प्रतिशत तथा चीनी खाण्डसारी और गुड़ का 4.9 प्रतिशत था। औसत के आधार पर 1989-90 के दौरान विनिर्मित उत्पादों के समूह का कुल मूल्य वृद्धि में भारांकित योगदान 85.6 प्रतिशत था जो 1988-89 के 69.9 प्रतिशत से काफी अधिक था (सारणी 7.4)। इस से यह पता चलता है कि समीक्षा वर्ष में मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति अत्यधिक सामान्य स्वरूप की रही।

सारणी 7.4 : धोक मूल्यों के सामान्य सूचकांक की वृद्धि में पण्य समूहों का भारांकित योगदान

(आधार : 1981-82 = 100)

(प्रतिशत)

प्रमुख समूह/समूह/पण्य	भारतक	बिन्दुवार आधार पर		औसत के आधार पर	
		1988-89	1989-90	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6
सभी पण्य	100.000	100.00	100.0	100.0	100.0
i. प्राथमिक वस्तुएं	32.295	-1.2	23.0	23.0	9.6
1. अनाज	6.824	11.0	-4.8	10.5	2.0
2. दालें	1.083	3.4	1.6	4.8	0.6
3. फल तथा सब्जियां	4.089	-0.9	1.17	2.0	-5.4
4. दूध	1.961	6.2	1.2	4.1	2.8
5. अण्डे, मछली तथा मांस	1.783	1.5	1.3	2.1	1.2



1	2	3	4	5	6
6 मसाले और गरम मसाले	0.947	-2.4	0.8	2.3	-3.0
7. अन्य खाद्य वस्तुएं	0.639	4.6	2.7	0.6	5.1
8. रेबो	1.791	3.9	-0.8	2.3	2.6
9. तिलहन	3.861	-18.3	9.8	-10.0	-0.1
II. ईंधन, शक्ति, प्रकाश और स्नेहक	10.663	9.5	7.3	7.8	5.1
1. कोयला खनन	1.256	3.8	0.1	3.4	2.2
2. खनिज तेल	6.886	1.1	5.5	1.8	0.4
3. बिजली	2.741	4.6	1.7	2.5	2.7
III. विनिर्मित उत्पाद	57.042	90.3	70.3	69.9	85.6
1. चीनी, खाण्ड और गुड़	4.059	7.3	4.9	3.7	8.9
2. खाद्य तेल	2.445	-3.8	4.8	-1.2	1.5
3. सूती वस्त्र	6.093	8.1	10.4	7.6	10.4
4. कलात्मक रेयार्मा वस्त्र	0.058	0.1	0.1	0.0	0.1
5. जूट, सत और मेरुना वस्त्र	0.689	3.1	3.7	2.6	2.9
6. लोहा और इस्पात	2.441	4.8	3.5	4.7	5.4
7. अलौह धातुएं	1.025	7.8	0.7	4.0	4.1
8. धातु उत्पाद	1.823	8.5	3.5	4.7	6.4

7.10 वित्तीय वर्ष 1990-91 की प्रथम तिमाही में मूल्य-स्थिति और खराब हो गई। वर्ष 1990-91 की प्रथम तिमाही के दौरान (30 जून, 1990 तक) थोक मूल्यों के सामान्य सूचकांक में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1989-90 की प्रथम तिमाही में यह वृद्धि 3.8 प्रतिशत थी। रोजमर्रा के उपभोग की वस्तुओं अर्थात् चावल, फल और सब्जियों, मसालों व गरम मसालों, दालों, चाय, गुड़ और खाद्य तेल में तेजी से वृद्धि हुई। इन वस्तुओं में से दालों, फलों व सब्जियों, चाय, गुड़ तथा खाद्य तेलों के मूल्यों में 1989-90 की प्रथम तिमाही में भी भारी वृद्धि दर्ज की गयी थी। रुई जिसका मूल्य 1989-90 की प्रथम तिमाही में कम हो गया था, 1990-91 की प्रथम तिमाही में फिर से बढ़ गया। दूसरी ओर चीनी और खांडसारी मूल्यों में घाट वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में मामूली-सी गिरावट आयी जबकि 1989-90 में इन के मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। समूहवार, 'प्राथमिक वस्तुओं' के मूल्य सूचकांक में 1989-90 की तदनुषंग अवधि की 3.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 8.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। "ईंधन, शक्ति, बिजली और स्नेहक" के सूचकांक में गत तदनुषंग अवधि की 0.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तथापि, विनिर्मित उत्पादों के समूह में मूल्यों में 1.5 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई जबकि 1989-90 की तदनुषंग अवधि में यह वृद्धि 4.6 प्रतिशत थी।

#### सरकारी मूल्यों में परिवर्तन

7.11 उत्पादन की लागत में वृद्धि होने के कारण उत्पादों की राहत देने की दृष्टि से 1989-90 के दौरान कल्पित औद्योगिक उत्पादों के सरकारी मूल्यों में परिशोधन किया गया यहाँ हमारी ओर कृषि के विभिन्न पण्यों की खरीद समर्थन मूल्यों में व्यापक वृद्धि की गयी ताकि उत्पादकों की अपेक्षाकृत अधिक प्रोत्साहन मिल सके और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि की जा सके तथा विभिन्न कृषि पण्यों की सरकारी खरीद में स्थिति में सुधार लाया जा सके। फसलों के उत्पादन की लागत संबंधी पद्धति की समीक्षा करने वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि

मूल्यों को निर्धारित करते समय कृषि फसलों के उत्पादन की लागत निकालने के कार्मले में श्रम और प्रबन्धकीय लागतों को भी शामिल किया जाए।

#### कृषि मूल्य

7.12 सरकारी खरीद/म्यूनतम समर्थन मूल्यों में हुए मुख्य परिवर्तन सारणी 7.5 में प्रस्तुत किये गये हैं। अनाजों, तिलहन, रुई और पटसन के मामले में ऐसे मूल्यों में औसतन वृद्धि 1989-90 के विपणन मौसम के दौरान पिछले मौसम की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक थी। वर्ष 1990-91 के विपणन मौसम के लिए गेहूँ का सरकारी खरीद मूल्य दो बार बढ़ाया गया, अर्थात् 30 अगस्त 1989 को 183 रुपये प्रति क्विंटल से 200 रुपये प्रति क्विंटल और 21 अप्रैल, 1990 को यह 215 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ गया जिससे 17.5 प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई। मूल्यों में परिवर्तन की घोषणा करने में पूर्व किसानों द्वारा की गयी विक्रयों के लिए पहली अप्रैल, 1990 से पूर्वव्यापी प्रभाव से 215 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य लागू हो जाएगा। वर्ष 1990-91 के लिए जौ और धने के म्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी वृद्धि की गई अर्थात् यह मूल्य क्रमशः 24.1 प्रतिशत और 44.9 प्रतिशत बढ़ाया गया।

7.13 गेहूँ और चावल के सरकारी खरीद मूल्य में संशोधन किए जाने के परिणाम स्वरूप 1 मई 1990 में गेहूँ का निर्यात मूल्य 204 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 234 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया अर्थात् 14.7 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई और 1 जून 1990 से सामान्य, उत्तम और प्रतिउत्तम किस्म के चावल के निर्यात मूल्य को 45 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर क्रमशः 289 रुपये 349 रुपये और 370 रुपये कर दिया गया है।

#### औद्योगिक मूल्य

7.14 औद्योगिक उत्पादों के सरकारी मूल्य सामान्यतया उत्पादन की लागत के अनुसार अथवा कुछ मामलों में उपभोग को नियंत्रित करने के लिए समायोजित किए जाते हैं। निवेश विषयक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायन जुटाने के मामले में कभी-कभी ऐसे परिवर्तन किए जाते हैं।

## सारणी 7 5 : न्यूनतम समर्थन/सरकारी खरीद मूल्य

(रूप में प्रति क्विंटल)

कृषि पण्य	न्यूनतम समर्थन/ सरकारी खरीद मूल्य	1988-89+	1989-90+प्रतिशत में घटबढ़ (कालम 3 की तुलना में कालम 4)	1990-91+प्रतिशत में घटबढ़ (कालम 4 की तुलना में कालम 6)		
1	2	3	4	5	6	7
धान	सरकारी खरीद मूल्य					
झींसन किस्म की	"	160	185	+ 15.6	205	+ 10.8
उत्तम	"	170	195	+ 14.7	215	+ 10.3
अति उत्तम	"	180	205	+ 13.9	225	+ 9.8
गेहूं	"	173	183	+ 5.8	215	+ 17.5
					(200)*	
ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी (उप- युक्त झींसन किस्म)	"	145	165	+ 13.8	180	+ 9.1
जी	न्यूनतम समर्थन मूल्य	135	145	+ 4.7	180	+ 24.1
					(160)*	
चना	"	290	325	+ 12.1	471	+ 44.9
					(370)*	
अरहर, मूंग उड़द तिलहन	"	360	425	+ 18.1	480	+ 12.9
मूंगफली (छिलके सहित)	"	430	500	+ 16.3	580	+ 16.0
सरसों/तोरिया	"	430	460	7.0	510	+ 10.9
भूराजमुखी	"	450	530	+ 17.8	600	+ 13.2
सोयाबीन (पीला)	"	320	370	+ 15.6	400	+ 8.1
सोयाबीन (काला)	"	275	325	+ 18.2	350	+ 7.7
गन्ना	सांविधिक न्यूनतम मूल्य	19 50	22	+ 12.8	23	+ 4.5
दई (उपयुक्त झींसन प्रकार की)	न्यूनतम समर्थन मूल्य	500	570	+ 14.0	620	+ 8.8
कपास (मंकर-4)	"	600	690	+ 15.0	750	+ 8.7
पटसन (इन्सू-5 ग्रेड असम के बाहर)	सांविधिक न्यूनतम मूल्य	250	295	+ 18.0	320	+ 8.5
बीएफसी तंबाकू (एफ-2)						
काली मिट्टी		1175	1250	+ 6.4	--	--

\*कोष्ठको में दिए गए आंकड़े 30 अगस्त, 1989 को घोषित वर्ष 1990-91 के मौसम के लिए समर्थन मूल्यों में वर्ष के दौरान संशोधित मूल्यों में संबंधित हैं।

उन्हें बाद में 21 अप्रैल, 1990 को संशोधित कर दिया गया था।

+ विपणन मीसम।

7.15 रेल भाड़े में वृद्धि होने की वजह से 1989-90 के दौरान कुछ एक मवों जैसे इस्पात के मूल्यों में मामूली-सी वृद्धि हुई। अलौह धातुओं के मामलों में न केवल अल्युमीनियम पर शुल्क नियंत्रण हटा दिया गया बल्कि उसकी बिन्नी पर से भी निषेधण हटा लिया गया। अन्य अलौह धातुओं अर्थात् ताबा, जस्ता, सीसा और क्लैंड के सरकारी मूल्य, जिनको अधिकांशतः आयात किया जाता है और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जिन के मूल्यों में तथा विनिमय दरों में परिवर्तन होता रहता है, को लागू करना जारी रहा। प्रमुख मवों के सूचकांकों में सरकारी मूल्यों में वृद्धि के उपरान्त जिन मवों में परिवर्तन हुआ वे इस प्रकार थे: पेट्रोलियम कच्चा तेल (12.5 प्रतिशत), खनिज तेल (9.1 प्रतिशत), लोहा और इस्पात (11.8 प्रतिशत), अलौह धातुएं (अल्युमीनियम को छोड़कर) (5.2 प्रतिशत), बिजली (4.7 प्रतिशत), और कोयला खनन (0.4 प्रतिशत)।

7.16 औद्योगिक उत्पादों के सरकारी मूल्यों के सम्मिश्र सूचकांक में 1989-90 में लक्ष्युसार 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यह 5.1

प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में अधिक थी। बिन्दुवार आधार पर जिन सात औद्योगिक उत्पाद समूहों के सरकारी मूल्य लागू किये अर्थात्, कोयला, लोहा और इस्पात अलौह, धातुएं (अल्युमीनियम को छोड़कर), पेट्रोलियम कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, बिजली तथा उर्वरक, के थोक मूल्यों में सामान्य सूचकांक में 19.697 प्रतिशत का भारीकृत योगदान गत वर्ष के 16.9 प्रतिशत की तुलना में कम अर्थात् 1989-90 में 11.7 प्रतिशत था। रेल भाड़े में तथा प्रत्यक्ष करों में हुई वृद्धियों सहित इन वृद्धियों से कीमतों पर और दबाव बढ़ने की संभावना है।

उपभोक्ता मूल्य-सूचकांकों की प्रवृत्तियां

7.17 बिन्दुवार और औसत दोनों आधार पर 1989-90 के दौरान औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982-100) के रूप में मूल्यवृद्धि की दर 6.6 प्रतिशत थी जबकि 1988-89 में बिन्दुवार तथा औसत के आधार पर, यह दर क्रमशः 8.6 प्रतिशत

और 9.1 प्रतिशत थी। बिन्दुवार आधार पर, 1989-90 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अस्तित्व खाद्य सूचकांक में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो गत वर्ष की तदनुसृत अवधि की 10.5 प्रतिशत की वृद्धि के आधे से भी कम थी, इसका कारण अनाजों की कीमतों में गिरावट था।

7.18 अन्तर शहरी कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (आधार: 1984-85-100) वर्ष 1989-90 के दौरान 8.0 प्रतिशत वृद्धि हुई, जो औसत के आधार पर गत वर्ष वर्ष की गई वृद्धि से 1.0 प्रतिशत अधिक थी। वर्ष 1989-90 (6.9 प्रतिशत) में हुई वृद्धि गत वर्ष की वृद्धि (8.2 प्रतिशत) से कम थी। कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 1960-61-100) में, बिन्दुवार और औसत दोनों के आधार पर, वर्ष 1988-89 की तुलना में अपेक्षाकृत कम वृद्धि दर्ज की गयी, अर्थात्-बिन्दुवार आधार पर 10.8 प्रतिशत की तुलना में 1.0 प्रतिशत और औसत के आधार पर 12.7 प्रतिशत की तुलना में 5.4 प्रतिशत।

7.19 वर्ष 1990-91 की प्रथम तिमाही (अप्रैल, -जून) के दौरान औद्योगिक कामगारों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बिन्दुवार आधार पर 4.5 प्रतिशत बढ़ा जबकि इसके मुकाबले 1989-90 की प्रथम तिमाही में इसमें 2.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। औसत के आधार पर यदि देखा जाये तो 1990-91 की प्रथम तिमाही में यह सूचकांक 8.1 प्रतिशत

के स्तर पर था जो 1989-90 की प्रथम तिमाही के 7.7 प्रतिशत के स्तर की तुलना में अधिक था।

7.20 थोक मूल्य सूचकांक और उपयुक्त तीन उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की प्रवृत्तियों की आपस में तुलना करने से कतिपय विमलरूप महत्वपूर्ण बातों का पता चलता है। सर्वप्रथम, वृद्धि की उच्चतर दरों के अनेक वर्षों के बाद वर्ष 1989-90 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक की वृद्धि की तुलना में सभी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अपेक्षाकृत कम वृद्धि की प्रवृत्ति अनुभव की गई। इस का कारण यह था कि पहले की मूल्य वृद्धियाँ अपेक्षाकृत अधिक सामान्य स्वरूप की थीं जिन में मेम औद्योगिक पण्यों द्वारा व्यापक रूप से अत्यधिक योगदान किया गया, जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता समूह के अस्तित्व नहीं आती है। दूसरे अपेक्षाकृत अधिक विविध उपभोक्ता समूह होने की वजह से वर्ष 1989-90 में शारीरिक श्रम करने वाले से इतर शहरी कर्मचारियों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई, इसके विपरीत अनाजों (उपभोक्ता वस्तुओं में केवल इन्हीं का मूल्य गिर गया था) के लिए अपेक्षाकृत अधिक भारांक होने के कारण कृषि श्रमिकों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि की दर काफी कम रही। औद्योगिक कामगारों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि अन्य दोनों उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में हुई वृद्धि के बीच की थी।

सारणी 7.6 विभिन्न मूल्य सूचकांकों में व्यापारित मूल्यवृद्धि की वार्षिक दर

(वार्षिक औसतों के आधार पर)

(प्रतिशत वृद्धि)

वर्ष	थोक मूल्य सूचकांक	औद्योगिक कामगारों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	शारीरिक श्रम करने वालों से इतर शहरी कर्मचारियों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	खाद्य वस्तुओं से संबंधित मूल्य सूचकांक	औद्योगिक वस्तुओं से संबंधित मूल्य सूचकांक	सर्वसम मूल्य सूचकांक
				थोकमूल्यसूचकांक का संमिश्र खाद्य सूचकांक (भारत: 27.53%)	उद्योगिक सूचकांक का खाद्य सूचकांक (भारत: 60.92%)	
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	+17.7*	+11.4	+11.8	+14.2	+22.4	+12.3
1981-82	+9.8	+12.5	+12.1	+12.4	+6.5	+13.6
1982-83	+2.6	+7.8	+8.0	+5.2	+0.8	+6.7
1983-84	+7.5	+12.6	+10.2	+11.3	+12.7	+14.4
1984-85	+6.5	+6.4	+8.2	+0.2	+4.7	+4.5
छठी योजना के लिए औसत	+8.8	+10.1	+10.1	+8.7	+9.1	+10.3
1985-86	+4.4	+6.4	+6.7	+4.8	+2.2	+5.1
1986-87	+5.8	+8.8	+7.9	+4.8	+10.2	+9.7
1987-88	+8.2	+9.1	+8.9	+10.0	+8.9	+8.1
1988-89	+7.4	+9.1	+8.2	+12.7	+8.3	+10.5
1989-90	+7.4	+6.6	+6.9	+5.4	+4.9	+5.0
सातवी योजना के लिए औसत	+6.7	+8.0	+7.7	+7.5	+6.9	+7.7

\* आधार 1970-71-100 के अनुसार

सारणी 7. 1. बंबई तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने तथा चांदी के मूल्य

वर्ष	सोना		चांदी			
			बंबई बाजार	बंबई बाजार	बंबई और लंदन	बंबई और न्यूयार्क
			रुपया (स्टैण्डर्ड सोना प्रति 10 ग्राम)	रुपये (0.999 तक परिष्कृत प्रति कि. ग्र.)	के मूल्यों में अन्तर (प्रतिशत के रूप में औसत)	के मूल्यों में अन्तर
	वर्ष के अन्त में	औसत	वर्ष के अन्त में	औसत	सोना	चांदी
1	2	3	1	5	6	7
1980-81	1.700 (27.8)	1.522 (31.3)	2.720 (2.4)	2.617 (13.9)	+2.5	--34.9
1981-82	1.645 (--3.2)	1.719 (12.9)	2.680 (1.5)	2.636 (0.7)	+42.1	+0.3
1982-83	1.800 (9.4)	1.723 (0.2)	3.105 (15.9)	2.799 (8.2)	+37.8	--1.1
1983-84	1.975 (9.7)	1.859 (7.8)	3.570 (15.0)	3.506 (25.3)	+38.5	--0.3
1984-85	2.130 (7.8)	1.984 (6.8)	3.955 (10.8)	3.594 (2.5)	+53.3	+27.9
1985-86	2.140 (0.5)	2.126 (7.1)	4.015 (1.5)	3.918 (9.0)	+64.8	+63.5
1986-87	2.570 (20.1)	2.324 (9.3)	4.794 (19.4)	4.247 (8.4)	+47.3	+91.3
1987-88	3.130 (21.8)	3.082 (32.7)	6.066 (26.5)	5.539 (30.4)	+61.2	+83.6
1988-89	3.140 (0.3)	3.175 (3.0)	6.735 (11.4)	6.367 (14.9)	+62.0	+114.3
1989-90	3.200 (1.9)	3.229 (1.7)	6.463 (--4.3)	6.842 (7.5)	+56.5	+140.1

\*दरों का अन्तर लंदन बाजार में डालर प्रति शुद्ध औंस को रुपये प्रति 10 ग्राम में, लंदन में अमेरिकी डालरों की हाजिर खरीद और बिक्री दरों के दैनिक औसत एवं रिजर्व बैंक के स्टैंडिंग की हाजिर खरीद और बिक्री के औसत की प्रति दरों के आधार पर बदलने के बाद निकाले गए हैं।

\*\*दरों का अन्तर न्यूयार्क बाजार में गेज प्रतिशुद्ध औंस को रुपये प्रति किलोग्राम में लंदन में अमेरिकी डालरों की हाजिर खरीद और बिक्री दरों के दैनिक औसत एवं रिजर्व बैंक के स्टैंडिंग की हाजिर खरीद और बिक्री दरों के औसत की प्रति दरों के आधार पर बदलने के बाद निकाला गया है।

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत के रूप में घट-बढ़ हैं।

7.21 सभी मूल्य सूचकांकों के आधार पर आंकी गई मुद्रास्फीति की दर छोटी योजना अवधि (1980-81 से 1984-85 तक) के दौरान पायी गई दर की तुलना में सातवी योजना अवधि (1985-86 से 1989-90 तक) में थोड़ी कम रही। सातवी योजना अवधि में थोक मूल्य सूचकांक की बढ़ी हुई वार्षिक दर 6.7 प्रतिशत थी जबकि छोटी योजना अवधि के दौरान यह दर 8.8 प्रतिशत थी, इसके अनिश्चित औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की दर 10.1% की तुलना में 8.0% थी (सारणी 7.6)। सातवी योजना में मुद्रास्फीति में अपेक्षाकृत कमी प्रमुखतः आयात भंडार से काफी मात्रा में अनाज निकालने और कीमतों पर अधिक रबाओं को कम करने के लिए आयातों द्वारा कुछ आवश्यक पण्यों की आपूर्ति बढ़ाने की वजह से हुई। सातवी योजना में, मुद्रास्फीति की दर में आयी गिरावट को और कम किया जा सकता था लेकिन राजकोषीय असंतुलन की वजह से उत्पन्न समस्त चलनिधि में भारी वृद्धि होने से ऐसा नहीं किया जा सका। तथापि, सातवी योजना के अन्तिम तीन वर्षों के दौरान मूल्य में हुई वृद्धि इस योजना के प्रथम दो वर्षों में वृद्धि से काफी अधिक थी।

सोने और चांदी के मूल्य

7.22 बम्बई सरफा बाजार में सोने के औसत मूल्य में 1989-90 के दौरान 1.7 प्रतिशत की मामूली सी वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1988-89 में यह वृद्धि 3.0 प्रतिशत थी। लगभग प्रति वर्ष 10 प्रतिशत स्टैण्डर्ड सोने के वैश्व मूल्य में वृद्धि की दीर्घावधि दर की तुलना में गत दो वर्षों के दौरान सोने के मूल्य में हुई वृद्धि मामूली रही। गत पांच वर्षों में सोने के मूल्यों में इस मामूली सी वृद्धि की दीर्घावधि दर की तुलना में गत दो वर्षों के दौरान सोने के मूल्य में हुई वृद्धि मामूली रही। पिछले पांच वर्षों में हुई 7 प्रतिशत से 33 प्रतिशत तक की तीव्र वृद्धि के बावजूद सोने की मूल्य-वृद्धि में तरमी छापी (सारणी 7.7)। इसके साथ-साथ, सोने की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में इसकी देशी कीमत पर प्रीमियम की दर वर्ष 1988-89 (62.0 प्रतिशत) और 1989-90 (56.5 प्रतिशत) मनेन इन वर्षों के दौरान काफी ऊंची रही (ग्राफ 5)।

7.23 बम्बई सरफा बाजार में चांदी के औसत मूल्य में वर्ष 1988-89 में हुई 15 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि की तुलना में वर्ष 1989-90

के दौरान 7.5 प्रतिशत की प्रतिरिक्त वृद्धि दर्ज की गयी। वैश्वी और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के बीच वृद्धि का अंतर 1987-88 में 84 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1988-89 में 114 प्रतिशत हो गया तथा 1989-90 में यह और बढ़कर 140 प्रतिशत हो गया। वैश्वी मूल्य और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के बीच वृद्धि का अंतर वर्ष 1985-86 के बाद से लगातार सभी वर्षों में और अधिक बढ़ता गया (ग्राफ ई देखें)।

#### 8 सरकारी बिल

##### केन्द्रीय सरकार का घाटा

81 वर्ष 1989-90 के दौरान केन्द्रीय सरकार का परम्परागत घाटा बजट अनुमानों में काफी अधिक बढ़ गया है। इस वर्ष के परिशोधित अनुमानों के अनुसार 11,750 करोड़ रुपये (सकल देशी उत्पाद का 2.7 प्रतिशत) के घाटे का अनुमान था जो बजट में प्रावधानित 7,377 करोड़ रुपये में 4,413 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी (या 60 प्रतिशत) का द्योतक है। इस स्तर के संदर्भ में यह घाटा केन्द्रीय सरकार के कुल प्राप्तियों का 15.0 प्रतिशत होता है, जबकि इसकी तुलना में 1988-89 (लेखों के आधार पर) में यह 7.9 प्रतिशत था। रिजर्व बैंक के लेखों के अनुसार सरकार के खाते बन्द होने के बाद 1989-90 में केन्द्र सरकार का बजट घाटा 10,624 करोड़ रुपये रहा जबकि 1988-89 में यह 5,810 करोड़ रुपये था। केन्द्रीय सरकार को रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत निवल ऋण को केन्द्रीय सरकार के बजट में लापत मूल्य के रूप में स्थान दिया जाता रहा है और यह ऋण केन्द्रीय सरकार के बजट संबंधी कार्यकलापों के सहायक प्रभाव के एक बेहतर उपाय के रूप में उपलब्ध है परिशोधित अनुमानों के अनुसार यह ऋण 11,300 करोड़ रुपये के उच्च स्तर पर पहुँचने का अनुमान रखा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के रिकार्डों के

अनुसार अब 1989-90 में इस ऋण का अंतिम उच्च स्तर 13,813 करोड़ रुपये अर्थात् 1988-89 के 6,503 करोड़ रुपये के वास्तविक स्तर से दुगुने से भी अधिक है।

8.2 पिछली रिपोर्ट में सरकारी बिल संबंधी कार्यकलापों की और विशेष ध्यान आकषिप्त किया गया था। विशेष पहलू यह था कि केन्द्रीय सरकार का बजट घाटा वर्ष के अधिकांश भाग के लिए रखे गये बजट अनुमानों से काफी अधिक था, परन्तु वर्ष के अंतिम सप्ताह में सरकारी खाते बंद होने के बाद इस ऋण के स्तर में काफी बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार, रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार को दिया जाने वाला शुद्ध ऋण भी वर्ष के अधिकांश भाग में मूलतः दर्शाये गये स्तर से काफी अधिक रहा; इसके बाद वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में निम्न स्तर पर पहुँचा। 1989-90 के दौरान यह प्रवृत्ति केवल बनी रही जबकि उसमें बहोती हुई। जून 1989 के प्रारम्भ में बजट घाटे का स्तर बजट अनुमानों के स्तर से अधिक हो गया और उसके बाद वह बजट में प्रावधानित स्तर से काफी अधिक स्तर पर रहा (सारणी 8.1)। इस पखवार्डों के आंकड़ों के अनुसार केन्द्रीय सरकार को रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त शुद्ध ऋण का स्तर 16,383 करोड़ रुपये या बजट में मूलतः प्रावधानित आंकड़ों से 123 प्रतिशत तक पहुँच गया।

8.3 वर्ष 1990-91 के बजट में केन्द्रीय सरकार के बजट में प्रावधानित परम्परागत घाटा कम अर्थात् 7,206 करोड़ रुपये दर्शाया गया है। इसमें प्रतिरिक्त सहायन प्रबन्ध और ऋक दरों में प्रस्तावित समायोजन शामिल हैं। यह केन्द्रीय सरकार की कुल प्राप्तियों का 8 प्रतिशत होता है। 1990-91 में केन्द्रीय सरकार का बजट घाटा 29 जून 1990 तक 9,107 करोड़ रुपये था (1 (सारणी 8.2)।

इस में 240 करोड़ रुपये की राशि शामिल है जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पुनः खरीद की सुविधा के लिए केन्द्रीय सरकार पर रिजर्व बैंक के ऋणों के कारण मुद्रा कोष की जारी की गयी व्याज रहित तथा आरम्भ्य प्रतिभूतियों का द्योतक है।

सारणी 8.1 केन्द्र के बजट घाटे तथा केन्द्र सरकार को दिये गये भारतीय रिजर्व बैंक के शुद्ध ऋण के पाक्षिक स्तर @ (1987-88 से 1989-90 तक)

(करोड़ रुपये)

	केन्द्र का बजट घाटा			केन्द्र की रिजर्व बैंक का शुद्ध ऋण		
	1987-88	1988-89	1989-90	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6	7
बजट अनुमान पखवार्ड (वास्तविक)	5,688	7,484	7,337	5,688	7,484	7,337
1वां	2,907	2,401	1,170	2,257	2,036	2,011
2वां	1,128	3,782	3,497	3,388	3,508	3,722
3वां	5,343	4,976	6,045	3,888	4,379	5,461
4वां	4,401	5,539	6,176	3,217	5,001	6,392
5वां	6,475	6,131	8,565	4,807	4,180	7,675
6वां	6,144	7,525	9,508	5,088	6,976	7,784
7वां	7,136	8,667	9,824	4,689	8,582	7,858
8वां	5,699	9,468	11,378	4,283	9,035	9,500
9वां	5,536	8,515	11,382	3,768	7,341	9,140
10वां	6,778	9,300	13,416	4,377	8,331	10,277
11वां	6,382	8,332	12,596	3,239	7,039	9,438
12वां	7,446	9,897	13,265	4,879	7,355	10,664
13वां	7,519	8,831	11,535	4,597	6,723	9,111
14वां	5,825	9,438	12,953	3,560	7,253	11,186
15वां	5,873	9,249	10,375	4,250	7,474	9,869
16वां	7,180	9,079	10,934	5,187	6,424	8,901
17वां	7,022	9,422	13,044	5,755	8,081	12,403

1	2	3	4	5	6	7
18वां	8,965	10,308	13,789	6,173	7,875	12,748
19वां	8,025	10,154	13,317	6,628	9,065	13,634
20वां	7,445	8,546	11,789	6,622	8,060	12,611
21वां	8,283	9,172	14,206	7,553	9,679	15,277
22वां	8,200	9,134	14,158	7,313	9,334	15,255
23वां	9,740	10,187	13,675	8,170	9,965	15,395
24वां	8,331	9,437	13,790	7,496	9,742	15,804
25वां	8,331	8,597	14,266	8,023	9,228	16,383
26वां	7,953	7,184	10,290	7,423	8,175	14,344
मार्च 31	5,870	5,810	10,624	6,559	6,503	13,813
वैमासिक औसत	4,883	5,060	6,398	3,874	3,347	5,843
प्रथम तिमाही	6,642	9,001	12,262	4,262	7,771	9,772
द्वितीय तिमाही	7,118	9,457	12,314	5,259	7,747	11,622
तृतीय तिमाही	8,082	8,503	13,001	7,395	8,947	15,182
चतुर्थ तिमाही	31,8398	8,952	13,398	7,514	9,354	15,410
31 मार्च को छोड़कर चतुर्थ तिमाही	6,790	8,114	10,947	5,326	7,309	10,635
वित्तीय वर्ष का औसत	6,826	8,203	10,959	5,278	7,340	10,513
31 मार्च को छोड़कर वित्तीय वर्ष का औसत						

@ रिजर्व बैंक के अभिलेखों पर आधारित।

टिप्पणी : 1. वर्ष 1989-90 में रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार को दिये गये शुद्ध ऋण में 78 करोड़ रुपये से 721.43 करोड़ रुपये तक की राशि 23 अगस्त 1989 से शामिल है। यह राशि अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से पुनः खरीद की सुविधा के लिए, केन्द्रीय सरकार पर रिजर्व बैंक द्वारा किये गये दावों के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को की गयी अपरकाम्य तथा व्याज रहित प्रतिभूतियों के परिवर्तन का घातक है। 22 मार्च, 1990 तक बजट घाटे में 721.43 करोड़ रुपये की विशेष प्रतिभूतियों के रूप में इस राशि को शामिल किया गया था, क्योंकि 23 मार्च 1990 को इसे विजेरा प्रतिभूति के रूप में सूचित किया गया था।

2. बजट में प्रावधानित आंकड़ों के अनुसार केन्द्रीय सरकार का घाटा वर्ष 1987-88 में 5,316 करोड़ रुपये और वर्ष 1988-89 में 5,642 करोड़ रुपये था।

सारणी 8.2 : बजट घाटा तथा केन्द्र सरकार को रिजर्व बैंक का ऋण :  
वर्ष (1990-91 तथा 1988-89) के प्रथम तिमाही के दौरान वास्तविक राशियाँ

(करोड़ रुपये)

	1988-89*	1989-90*	1990-91			
	बजट घाटा	केन्द्र सरकार को बजट घाटा रिजर्व बैंक का शुद्ध ऋण	केन्द्र सरकार को बजट घाटा रिजर्व बैंक का शुद्ध ऋण	केन्द्र सरकार को बजट घाटा रिजर्व बैंक का शुद्ध ऋण	केन्द्र सरकार को रिजर्व बैंक का शुद्ध ऋण	
1	2	3	4	5	6	7
बजट अनुमान	7,484	7,484	7,337	7,337	7,206	7,206
6 अप्रैल 1990 को	2,401	2,036	1,170	2,011	2,679	2,712
20 अप्रैल 1990 को	3,782	3,508	3,497	3,722	3,204	4,050
4 मई 1990 को	4,976	4,378	6,045	5,461	5,754	4,994
18 मई 1990 को	5,539	5,001	6,176	6,392	6,638	7,058
1 जून 1990 को	6,134	4,180	8,565	7,675	8,228	6,907
15 जून 1990 को	7,525	6,976	9,508	7,784	7,698	7,463
29 जून 1990 को	8,667	8,582	9,824	7,858	9,107	7,703

\* ये आंकड़े ऊर्ध्व पद्धतियों के स्वरूप हैं, जो 1990-91 के पञ्चवार हैं।

टिप्पणी : 1990-91 के लिए, 20 अप्रैल 1990 रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार को दिये गये शुद्ध ऋण और केन्द्रीय सरकार के बजट घाटे में 26 करोड़ रुपये 240 करोड़ रुपये की राशि शामिल है, जो मुद्रा कोष को जारी की गयी अपरकाम्य तथा व्याज रहित प्रतिभूतियों के परिवर्तन का घातक है; ये परिवर्तन, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से पुनः खरीद की सुविधा के लिए, केन्द्रीय सरकार पर रिजर्व बैंक के दावों के माध्यम से किये गये थे।

बजट घाटे और सरकार। ऋण की व्यापक संकलनाएँ।

8.4 बड़े हुए बजट घाटे की परम्परागत परिभाषा के दायरे में भारत सरकार के राजकोषीय कार्यक्रमों का पूरी तरह शामिल नहीं है। इसी संकल्पना के दायरे में समाधनों का आंशिक अंतर्गण ही शामिल है। अर्थात् हमें वे समाधन घाटे हैं जो 91 दिवसीय खजाना बिलों को जारी करने के निम्नोपनिर्णयों हैं और नकदी शेष में किये गये आहरण शामिल हैं। इसमें बाजार में ली गयी उधार राशियाँ और अन्य देयताओं में हुई वृद्धि जैसे अन्य बचत राशियाँ और भविष्य निर्धियाँ शामिल नहीं हैं, उन्हें में देशी ऋण नेजी से बढ़ रहा है और समग्र ऋण का बोझ भी बढ़ रहा है। वित्तपोषण के इन विभिन्न माध्यमों में सर्वश्रेष्ठ में सारणी 8.3 में 1980-81 में सरकारी घाटे के वैकल्पिक उपयोग की प्रवृत्तियों का निरूपण और वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के अनुपातों के रूप में दर्शाया गया है। मुद्रागत घाटे में सरकार की रिजर्व बैंक पर निर्भरता के रूप में राजकोषीय कार्यक्रमों का मुद्रागत प्रभाव शामिल है। यह मुद्रागत घाटा सामान्यतः परम्परागत घाटे से कुछ अधिक रहता है। इस मुद्रागत घाटे के अतिरिक्त सकल राजकोषीय घाटे की व्यापक संकल्पनाएँ इस सारणी में और ग्राफ चित्रों 'ड' और 'ऊ' में दर्शायी गयी हैं।

8.5 सकल राजकोषीय घाटा से यह स्पष्ट होगा कि घाटे की सर्वाधिक व्यापक संकल्पना अनुदानों राजस्व प्राप्तियों में कुल वित्त संचितरण की अधिकता के रूप में कुछ समाधनों के अंतर्गण को आकलित करती है और केन्द्रीय सरकार की ऋण-अस्तित्व राजकोषीय कार्यक्रमों के प्रभाव को पूरी तरह, प्रतिबिम्बित करती है। यह सकल राजकोषीय घाटा, मोटे तौर पर हर पांच वर्ष में निरपेक्षता दुगुना हो गया अर्थात् 1980-81 में यह 8,687 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 1984-85 में 17,783 करोड़ रुपये हो गया था 1989-90 में 38,238 करोड़ रुपये पर पहुँच गया। सकल देशी उत्पाद में सकल राजकोषीय घाटे के संबंधित अनुपात 6.5 प्रतिशत से बढ़कर 7.7 प्रतिशत हो गया तथा अतः 8.6 प्रतिशत पर आ गया। शुद्ध राजकोषीय घाटा भी प्रत्येक पांच वर्ष में लगभग दुगुना हो गया, इस घाटे में केन्द्रीय सरकार के खय भी शुद्ध ऋण

शामिल नहीं है। वर्ष 1989-90 में परम्परागत घाटे में सकल राजकोषीय घाटे से यथा आकलित कुल समाधनों के अंतर्गण का लगभग एक तिहाई या शुद्ध राजकोषीय घाटे के लगभग आधे से कम अंश शामिल है।

8.6 सकल राजकोषीय घाटे के निम्नोपनिर्णय का समग्र दृष्टिकोण से देखा जाये, जैसा कि सारणी 8.1 में दर्शाया गया है, तो समाधनों के अंतर्गण के निम्नोपनिर्णय के स्वरूप से यह पता चलता है कि 1989-90 में परम्परागत बजट घाटा 30.7 प्रतिशत होता है जबकि अन्य देशी उधार राशियों अर्थात् बाजार से लिया गया ऋण और अन्य देयताओं में समाधनों के अंतर्गण को अधिक अर्थात् बाजार से लिया गया ऋण और अन्य देयताओं ने समाधनों को अंतर्गण का अधिक अर्थात् 6.2 प्रतिशत से थोड़ा अधिक बढ़ाया है। यहाँ वित्त पोषण केवल 7.2 प्रतिशत था।

8.7 1980 के दशक के दौरान राजकोषीय असंतुलन में हुई तेज वृद्धि स्वाभाविक रूप से केन्द्रीय सरकार की ऋण-अस्तित्व के रूप में प्रदर्शित हुई। जैसा कि सारणी 8.5 में स्पष्ट है, भारत सरकार की कुल देयताएँ मार्च 1981 के अंत में 59,719 करोड़ रुपये या सकल देशी उत्पाद का 43.9 प्रतिशत थी जो मार्च 1990 के अंत में तेजी से बढ़कर 2,66,913 करोड़ रुपये या सकल देशी उत्पाद का 60.3 प्रतिशत तक पहुँच गयी। यह अवांछनीय स्थिति आंतरिक देयताओं के कारण आयी।

8.8 सरकारी घाटा और देशी ऋण बढ़ने रहने की स्थिति इस बात पर निर्भर करनी है कि जुटाये गये समाधन कितने और किस स्वरूप के हैं और मार्गजतिक धन्य के निपटान का तरीका क्या है। कुल धन्य में धीरे-धीरे मजबूती ने बढ़ते हुए विकसितर धन्य और उपभोग व्यय का अंश बास्तव में एक चिंताजनक विषय है। इसके अतिरिक्त, देशी उधार राशियों पर ही निर्भर रहना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लेवी और सार्वजनिक निधेन पर उच्चतर आय के माध्यम से जुटाने का एक विकल्प हो सकता है।

सारणी 8.3 : मौद्रिक बजट, सकल और शुद्ध राजकोषीय घाटा

(करोड़ रुपये)

वर्ष	सकल राजकोषीय घाटा @	शुद्ध राजकोषीय घाटा @	मौद्रिक घाटा @	पारंपरिक घाटा	राजस्व घाटा	बाजार-मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	8,887	5,698	3,551	2,447	2,037	1,35,812
1981-82	8,667	4,592	3,207	1,392	384	1,59,420
1982-83	12,509	6,112	3,368	1,656*	1,308	1,77,588
1983-84	13,933	8,174	3,949	1,417*	2,540*	2,06,857
1984-85	17,783	11,339	6,055	3,745	4,224	2,30,679
1985-86	24,406	14,461	6,190	4,937*	5,505	3,62,603
1986-87	27,876	18,570	7,091	8,261	7,776	2,93,361
1987-88	28,273	19,060	6,559	5,816	9,137	3,32,553
1988-89	32,008	21,855	6,503	5,642	10,515	3,91,158
1989-90	38,238(क)	25,872(क)	13,813	11,750(क)	12,436(क)	4,42,769\$
1990-91	38,005(ख)	27,198(ख)	7,206(ख)	7,206(ख)	13,032(ख)	—

बाजार मूल्य पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में

1	2	3	4	5	6
1980-81	6.54	4.20	2.61	1.82	1.50
1981-82	5.44	2.88	2.01	0.87	0.24
1982-83	7.04	3.44	1.90	0.93	0.74
1983-84	6.74	4.19	1.91	0.69	1.23
1984-85	7.71	4.92	2.62	1.6	1.83
1985-86	9.29	5.51	2.36	1.88	2.12
1986-87	9.50	6.33	2.42	2.82	2.65
1987-88	8.50	5.91	1.97	1.75	1.75
1988-89	5.18	5.59	1.66	1.44	2.69
1989-90	8.61	5.84	0.12	2.65	2.81

(यह आंकड़ा केन्द्रिय सरकार के बजट के वार्षिक वित्तीय विवरणों पर आधारित है और पहले प्रकाशित उन आंकड़ों से भिन्न है, जो मुद्रा और वित्त रिपोर्ट और मरवा भारतीय रिजर्व बैंक क्वैटर्स में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मन्त्री सचिवों पर आधारित है।

\* भारतीय रिजर्व बैंक के पास राज्यों के ओवरड्राफ्ट चुकाने के लिए उन्हें दिये गये मरवावधि ऋण के लिए 1983-84 में 1,743 करोड़ रुपये, 1984-85 में 400 करोड़ रुपये और 1985-86 में 1,628 करोड़ रुपये के जो मरवावधि ऋण दिये गये, उन्हें छोड़कर।

अनुमानित

— उपलब्ध नहीं है।

(क) परिशोधित अनुमान

(ख) बजट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय सरकार के बजट के वार्षिक वित्तीय विवरण

सारणी 8.4 सकल राजस्व घाटे का वित्तपोषण

(करोड़ रुपये)

वर्ष	द्वितीय वित्त	बाजार ऋण	अन्ध व्यवसाय	पारम्परिक घाटा	आंतरिक वित्त		
					कुल (3+4+5)	कुल वित्त (2+6)	सकल राज-कोषीय घाटा
1	2	3	4	5	6	7	8
1980-81	1,336 (15.0)	2,679 (30.2)	2,395 (26.9)	2,477 (27.9)	7,551 (85.0)	8,887 (100.0)	8,887
1981-82	1,029 (11.9)	2,913 (33.6)	5,333 (58.4)	1,392 (16.1)	7,638 (88.1)	8,667 (100.0)	8,667
1982-83	1,354 (10.8)	3,771 (40.1)	2,955 (31.9)	3,998* (27.2)	11,555 (89.2)	12,509* (100.0)	12,509
1983-84	1,437 (10.3)	4,038 (29.0)	6,641 (47.7)	1,817* (13.0)	12,496 (89.7)	13,933* (100.0)	13,933
1984-85	1,516 (8.5)	4,096 (23.0)	8,426 (47.4)	3,745 (21.1)	16,267 (91.5)	17,783 (100.0)	17,783
1985-86	1,515 (6.2)	4,884 (20.0)	11,442 (46.9)	6,565* (26.9)	22,891 (93.8)	24,406* (100.0)	24,406
1986-87	2,145 (7.7)	5,531 (19.9)	11,939 (13.8)	8,261 (29.6)	25,731 (93.3)	27,876 (100.0)	27,876
1987-88	2,923 (10.3)	5,862 (20.7)	13,672 (48.4)	5,816 (20.6)	25,350 (89.7)	28,273 (100.0)	28,273
1988-89	2,521 (7.9)	8,418 (26.3)	15,427 (18.2)	5,642 (17.6)	29,487 (92.1)	32,008 (100.0)	32,008
1989-90 (पुनः)	1,771 (7.2)	7,400 (19.4)	16,317 (12.7)	11,750 (30.7)	35,407 (92.8)	38,238 (100.0)	38,238
1990-91 (अनुमानित)	3,334 (8.8)	8,000 (21.0)	19,465 (51.2)	7,206 (19.0)	34,671 (91.2)	38,005 (100.0)	38,005

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल वित्त के प्रतिशत के संकेत हैं।

\* इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास राज्यों के ओवरड्राफ्ट चुकाने के लिए उन्हें दिये गये मरवावधि ऋण शामिल हैं। ऋण इस प्रकार दिये गये थे : 1982-83 में 1,743 करोड़ रुपये, 1983-84 में 400 करोड़ रुपये और 1985-86 में 1,628 करोड़ रुपये।

स्रोत : केन्द्रीय सरकार के बजट के वार्षिक वित्तीय विवरण।



संघ का बजट 1990-91<sup>10</sup>

8 9 यह स्वीकार करना होगा कि राजवर्गीय अनुसूचित वर्गों में सुधार लाने और सुवर्णन गति के प्रति स्थिति को जड़ दे बिना सत्ता न अपने 1990-91 के बजट मापण में अपना बृद्ध निष्पत्ति जाहिर किया कि ये बड़े राजवर्गीय अनुसूचित वर्गों में बड़े हुए खर्च में बढ़ती और वेस्टम व अनुसूचित वर्गों में बजट में प्रावधानों में स्मर के आधार हो समग्र पाठों का सामना रहे। उक्त निष्पत्ति को मजबूत करने के लिए बजट निष्पत्ति संबंधी वार्षिक गतिविधियाँ भी निरंतर समीक्षा करने का भी निष्पत्ति किया। इस समीक्षा की सूचना समय पर संसद को दी जायेगी।

बजट में सूखा प्रबंध क्षमता और ग्रामीण बेरोजगार की कठिन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण गारंटी योजना की शुरुआत करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। बजट में कृषि और ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी गयी और इसके लिए पर्याप्त बाँकी बढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त किसानों बुनियादी और गारंटी को शुरुआत प्रदान करने के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया तथा उर्वरक खरीदने में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 4000 करोड़ रुपये का भी बजट में प्रावधान है। इससे भी ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ पहुँचाना।

\* जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाये 1990-91 का उल्लेख बजट अनुमानों में संशोधित और 1989-90 का उल्लेख परिणाम अनुमानों में है।

सारणी 8.5 भारत सरकार का बजट व्यय

(करोड़ रुपये)

वर्ष	आर्थिक श्रेणी	ग्राम विकास	ग्राम विकास	ग्राम विकास	ग्राम विकास	ग्राम विकास	ग्राम विकास
1	2	3	4	5	6	7	8
1980-81	30 864 (22 7)	7 976 (5 9)	5 477 (4 4)	1 634 (2 7)	48 451 (35 7)	11 298 (8 3)	59,749 (14 0)
1981-82	35,653 (22 4)	9 375 (5 9)	7 204 (4 5)	1 627 (2 4)	55 858 (35 0)	12 328 (7 7)	68,186 (42 7)
1982-83	46 939 (26 4)	11 018 (6 2)	8 789 (5 0)	4 364 (2 5)	71 190 (40 1)	13,692 (7 7)	84,872 (47,8)
1983-84	50 261 (24 3)	13 506 (6 5)	10 368 (5 0)	6 001 (2 9)	80 141 (35 7)	15 120 (7 4)	95,261 (46 0)
1984-85	55,537 (25 4)	17 157 (7 5)	12 517 (5 4)	8 563 (3 7)	90 804 (42 0)	10 637 (7 2)	1 13 441 (49 2)
1985-86	71,039 (27 0)	21 449 (8 2)	15 410 (5 9)	11,433 (4 4)	1 19,331 (45 5)	15,153 (6 9)	1,37,484 (52.4)
1986-87	86 312 (29 4)	21 725 (9 1)	20 204 (6 9)	15 006 (5 1)	1 46 217 (49 8)	20 299 (6 9)	1,66,546 (56.7)
1987-88	95 646 (29 7)	25,358 (8 5)	26,170 (7 9)	19 164 (5 7)	1,72 335 (51 8)	23 223 (7 0)	1,95,561 (58 8)
1988-89	1,14,498 (29 3)	33,833 (8 6)	34 702 (8 9)	20,992 (5 3)	2,04 025 (52 1)	25 746 (6.6)	2,29,771 (58 7)
1989-90 (परि अनुमान)	1,33 361 (30 1)	40,583 (9 2)	13 643 (9 9)	20,509 (4 7)	2,38,396 (53 9)	28,517 (6 4)	2,66,913 (60 3)
1990-91 (बजट अनुमान)	1,51 037	45,583	51 590	23,815	2 75,025	31 951	3,06 876

स्रोत: भारत सरकार के बजट प्रलेख।

टिप्पणी: बजटों में दिये गये आंकड़े वर्तमान बाजार मूल्य पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के मानक हैं।

9 10 बजट में उद्योगों का वर्गीय विकास और आधारभूत संरचना के संतुलित विकास विशेष रूप से विद्युत शक्ति और परिवहन के विकास की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया गया। स्पर्धात्मक और एकाधिकार-रहित परिवहन में सार्वजनिक और निजी विकास करने को प्राथमिकता दी गयी तथा बुटीर उद्योग, सड़क और बड़े उद्योगों के बीच संतुलित विकास पर विशेष जोर दिया गया।

8 11 कर संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन में सुधार लाने और कानून धन की वृद्धि को रोकने के लिए 'बेनामी' लेनदेन संबंधी अधिनियम को

नये सिरे से उपबोधित किया जायेगा ताकि आर्थिक अपराधियों के लिए 'बेनामी' रूप में सम्पत्ति का अधिधारण और भी कठिन हो जाये। बजट में विवेकाधीन शक्तियों का दायरा घटाने और सामान्य तथा विवेकाधीन शक्तियों में रहित राजवर्गीय और वित्तीय स्थिरता पर अधिकाधिक निर्भर रहने जैसे आर्थिक उपायों द्वारा वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक प्रतिबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

8 12 1963 में लागू किये स्वर्णनियंत्रण अधिनियम का समाप्त किये जाने की घोषणा बजट की एक प्रमुख विशेषता रही (इस बीच संभव नहीं उसे समाप्त कर दिया)।

सारणी 6 बजट व घाटा बाजार और तथा केन्द्र सरकार के बाजार गुणा के रिजर्व बैंक का मन्वयेन  
(राजकोषीय वर्ष-1988-89 से 1990-91 तक)

(रुपये करोड़)

मने	1988-89 (वर्ष)	1989-90 (वर्ष अनुमान)	1989-90 (अनुमानित)	1990-91 (क) (वर्ष अनुमान)
1	2	3	4	5
1 राजस्व लेखा				
(1) प्राप्तिया (ख)	15 710	55 015	54 616	60 763
(II) व्यय (ग)	56 255	62,030	67 052	73,795
(III) आनयेण ( + )/घाटा ( - )	-10 515	-7 012	-12 436	-13 032
2 गजी लेखा				
(1) प्राप्तिया	25 673	22 100	23 692	29 391
(II) वितरण	20 800	22 141	23 906	23 565
(III) अधिगण ( + )/घाटा ( - )	+ 4,873	-325	+ 686	+ 5,826
3 कुल प्राप्तिया 1 (1) + 2 (1)	71,413	77 127	78 308	90 154
4 कुल व्यय 1 (ii) + 2 (ii)	77 055	84,464	90 058	97,360
5 कुल अधिगण ( + )/घाटा ( - )	-5 612	-7,337	-11,750	-7 206
6 (3) के प्रतिगत के रूप म (5)	7 9	9 5	15 0	8 0
7 कुल बाजार और	8,894	8,039	8 039	8 988
8 (3) के प्रतिगत के रूप म (7)	12 5	10 1	10 3	10 0
9 खजाना बिलो मे इतर सरकारों रुपया प्रतिभूतिया की रिजर्व बैंक की प्रतिभूतिया मे वृद्धि ( + )/ह्रास ( - ) (ग)	+ 1 746	+ 3,000	+ 3 000 (ग)	
10 केन्द्र सरकार को रिजर्व बैंक के मुद्रा और मे वृद्धि ( + )/ह्रास ( - ) (घ)	+ 6,503 (+ 6,503)	+ 7 337 (+ 13,813)	+ 14,300 (+ 13,813)	+ 7,206

(क) इनमे बजट प्रस्तावों के प्रभाव शामिल हैं परन्तु बजटोसर कर रियायते शामिल नहीं हैं।

(ख) इसमे वाणिज्य विभाग शामिल है।

(ग) रिजर्व बैंक के अधिलेखों के अनुसार बड़ी मूल्य के आधार पर।

(घ) केन्द्रीय सरकार के बजट म दिये गये आपत-मद के अनुसार है।

(ङ) बड़ी मूल्य के अनुसार।

नोट: बोधकों मे दिये गये आशयें मन्वयेन रूप के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की बड़ी के अनुसार हैं।

8.13 राजकोषीय प्रणाली के बुनियादी ढांचे तथा कर प्रणाली का व्यापक और उसकी व्यावहारिकता को बनाये रखने की बांछनीयता पर बल देते हुए दीर्घकालीन राजकोषीय नीति पर एक दस्तावेज तैयार कर के मसद के समक्ष प्रस्तुत करने का लक्ष्य दिया गया।

8.14 बजट मे यह प्रयास किया गया है कि समग्र घाटा पिछले वर्ष के घाटे के मुकाबले काफी कम स्तर पर रखा जाये। वार्षिक 1989-90 की दरी पर 1990-91 के दौरान समग्र घाटा 9,165 करोड़ रुपये अनुमानित है जबकि इसके मुकाबले 1989-90 म परिणोक्षित अनुमानों मे 11 750 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था। जुटाये गये अतिरिक्त मसाधनों सहित, 1990-91 मे कुल प्राप्तिया 90,154 करोड़ रुपये अनुमानित है जब कि इसकी तुलना मे 1989-90 मे 75,308 करोड़ रुपये अनुमानित थी। इसी वर्षों मे कुल वितरण तथा 97,360 करोड़ रुपये और 90,055 करोड़ रुपये थे (सारणी 6)। इस दर मसद नय कर उपायों म प्राप्त राजस्व का ह्रास म लन के बाद 1990-91 म केन्द्रीय सरकार का घाटा 7,206 करोड़ रुपये अनुमानित है जबकि इसके मुकाबले 1989-90 म यह 11,750 करोड़ रुपये था।

8.15 इस बजट मे करो और गुल्फो मे मसोधन करने का प्रस्ताव है। यह आशा की जा रही है कि इस मसोधन से 1990-91 मे 2,573 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सकल राजस्व प्राप्त होगा, अब तक का यह सर्वाधिक स्तर होगा। रियायतों और गहलो का समायाजित करने फलस्वरूप 783 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होगी तथा नये कर प्रस्तावों से, 1,790 करोड़ रुपये का शुद्ध अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इसमें से राशियों का अग्र केवल 3 करोड़ रुपये होगा। केन्द्रीय सरकार के कर प्रस्तावों के अतिरिक्त वितरण डाक सबाओं की दरी म मसाधन करने मे 207 करोड़ रुपये वार्षिक तथा 1990-91 म 172 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होगी।

8.16 रिकार्ड स्तर तब अतिरिक्त माधन जुटाने और व्यय को नियंत्रित करने पर बल देने के बावजूद राजस्व खाते म 13,032 करोड़ रुपये का काफी बड़ा घाटा परिणक्षित होगा, जबकि इसका तुलना मे 1989-90 म राजस्व घाटा 12 136 करोड़ रुपये तथा 1988-89 म 10,515 करोड़ रुपये का था। इससे विपरीत 1990-91 म पूजीगत खाते मे 5,826 करोड़ रुपये का उच्चतर अधिशेष होगा जबकि इसकी तुलना मे 1989-90 मे 696 करोड़ रुपये का अधिशेष था। स्पष्ट है

\*अधिक तेल मन्वयेन मसिध की जमा राशि का अनुमान 2,000 करोड़ रुपये काछाड दिश है तो 19 89-90 मे राजस्व घाटा उच्चतर अर्थात् 14,738 करोड़ रुपये होगा।

कि राजस्व घाटे का अधिकांश भाग मजबूत गुंजीगन जाते की प्रधिणेश राशि से वित्तपोषित होगा।

#### केन्द्रीय सरकार का योजना परिध्यय

8.17 वर्ष 1990-91 के लिए केन्द्रीय सरकार का योजना परिध्यय 39,329 करोड़ रुपये रखा गया है। यह परिध्यय 35,713 करोड़ रुपये के परिणोधिष परिध्यय की तुलना में 10.1 प्रतिशत तथा 1989-90 के बजट में प्रावधानित 34,446 करोड़ रुपये के परिध्यय की तुलना में 14.2 प्रतिशत अधिक है। आठवी योजना के लिए आनायी गयी नीति के एक भाग के रूप में योजना के कार्यक्रमों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करने, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने, ग्रामीण परिवेश में सामान्य जनजीवन सुधारने और कृषि को मजबूत करने को प्राथमिकता दी गयी है। राज्यों और संघ शामिल क्षेत्रों को केन्द्रीय सरकार से दी जाने वाली सहायता की राशि 1989-90 में 10,450 करोड़ रुपए (सूखा सहायता को छोड़कर) थी, यह राशि 22.9 प्रतिशत बढ़कर 1990-91 में 12,848 करोड़ रुपये कर दी गयी जिसमें नौवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत योजना राजस्व अनुदान भी शामिल है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए निदेश योग्य समाधानों का 50 प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए 1990-91 में केन्द्रीय योजना के लिए गजट समर्थन में ग्रामीण क्षेत्र का अंश उच्चतर अर्थात् 49 प्रतिशत पर रखा गया है, जबकि 1989-90 में यह 44 प्रतिशत था। 1990-91 में केन्द्रीय योजना परिध्यय के 44.1 प्रतिशत होता है, जबकि इसकी तुलना में 1989-90 में 18,234 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी थी जो योजना परिध्यय का 51.1 प्रतिशत होता है, आशा है कि 1990-91 में सरकारी क्षेत्र के उद्यम अपने आंतरिक संसाधनों और उधार राशियों से 21,985 करोड़ रुपये या केन्द्रीय योजना परिध्यय का 55.9 प्रतिशत का योगदान देंगे जबकि इसकी तुलना में 1989-90 में यह योगदान 17,479 करोड़ रुपये या योजना परिध्यय का 48.9 प्रतिशत का है। 1990-91 में 4,506 करोड़ रुपये के इस वृद्धि के संबंध में तीन चौथाई से भी अधिक 13,138 करोड़ रुपये के उच्चतर आंतरिक संसाधनों से जुटाये जायेंगे। जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष 9,680 करोड़ रुपये जुटाये गये थे। विकास और विकासेतर संवितरण

8.18 वर्ष 1990-91 में केन्द्रीय सरकार के कुल संवितरण 97,360 करोड़ रुपये अनुमानित हैं ये संवितरण 1989-90 के 90,053 करोड़

रुपये का संवितरणों के स्तर से 7,302 करोड़ रुपये (8.1 प्रतिशत) अधिक हैं। विकास व्यय 50,801 करोड़ रुपये अनुमानित है। यह पिछले वर्ष के 48,943 करोड़ रुपये के स्तर से 1,858 करोड़ रुपये या 3.8 प्रतिशत अधिक है। 46,559 रुपये का विकासेतर व्यय 1989-90 के 41,115 करोड़ रुपये के व्यय से 5,444 करोड़ रुपये या 13.2 प्रतिशत अधिक है। इससे यह स्पष्ट है कि कुल व्यय में विकास व्यय के अंश में गिरावट आ रही है। यह गिरावट सामग्री योजना की अवधि के दौरान काफी तेज हुई है। (सारणी 8.7)

#### योजना और योजनाएं व्यय

8.19 वर्ष 1989-90 में योजना व्यय 28,476 करोड़ रुपये था। आशा की जाती है कि यह 1990-91 में 1,716 करोड़ रुपये प्रतिशत बढ़कर 30,192 करोड़ रुपये हो जायेगा। दूसरी ओर योजनेतर व्यय 64,343 करोड़ रुपये अनुमानित है। यह पिछले वर्ष के 59,220 करोड़ रुपये के स्तर से 5,123 करोड़ रुपये (8.7 प्रतिशत) अधिक होगा। (ग्राफ 'ए' देखिए)। ब्याज अदायगी की राशि 20,850 करोड़ रुपये अनुमानित है जो 1990-91 के योजनेतर व्यय का 32.4 प्रतिशत होगा। पिछले वर्ष ब्याज अदायगी की राशि 17,710 प्रतिशत या 29.9 प्रतिशत थी। केन्द्रीय सरकार की कर प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में शुद्ध ब्याज अदायगी (अर्थात् ब्याज अदायगी की राशि में से ब्याज प्राप्तिओं की राशि घटाकर) की 11,331 करोड़ रुपये की राशि 1990-91 में 25.0 प्रतिशत होगी। (1989-90 में यह राशि 9,045 करोड़ रुपये या 23.9 प्रतिशत थी। प्रमुख मदों के लिए आर्थिक सहायता (खाजाना उर्वरक और निर्यात संवर्धन) की राशि 8,516 करोड़ रुपये अनुमानित है, इसके लिए बजट में पिछले वर्ष की 9,166 करोड़ रुपये की राशि से 650 करोड़ रुपये (-7.1 प्रतिशत) की गिरावट का प्रावधान है। 1989-90 में रक्षा के लिए 11,500 करोड़ रुपये का प्रावधान था। इसमें 1990-91 में 1,250 करोड़ रुपये (8.6 प्रतिशत) बढ़ाकर 15,750 करोड़ रुपये हो गया। ब्याज अदायगी, रक्षा और प्रमुख मदों के लिए दी जानेवाली आर्थिक सहायता तीनों मिलाकर 1990-91 में योजनेतर व्यय का लगभग 70 प्रतिशत होता है। यह पिछले वर्ष के स्तर के बराबर है।

सारणी 8.7 : केन्द्र तथा राज्यों के विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय

(करोड़ रुपये)

वर्ष	केन्द्र			राज्य			केन्द्र और राज्यों को मिलाकर				
	विकासा- त्मक व्यय	गैर विकासा- त्मक व्यय	कुल (a)	विकासा- त्मक व्यय	गैर विकासा- त्मक व्यय	अन्य*	कुल विकासा- त्मक व्यय	गैर विकासा- त्मक व्यय	अन्य**	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1980-81	13,932 (57.6)	10,245 (42.4)	24,177 (100.0)	15,961 (70.1)	4,289 (18.8)	2,520 (11.1)	22,770 (100.0)	25,815 (66.0)	11,977 (30.6)	1,338 (3.4)	39,160 (100.0)
1981-82	16,084 (60.9)	10,331 (39.1)	26,415 (100.0)	17,960 (70.2)	4,996 (19.6)	2,615 (10.2)	25,571 (100.0)	28,796 (64.7)	13,609 (30.6)	2,074 (4.7)	44,479 (100.0)
1982-83	19,557 (60.7)	12,673 (39.3)	32,230 (100.0)	20,649 (71.0)	5,883 (20.2)	2,565 (8.8)	29,097 (100.0)	33,643 (64.6)	16,473 (31.7)	1,941 (3.7)	52,057 (100.0)
1983-84	22,207 (58.8)	15,564 (41.2)	37,771 (100.0)	23,972 (71.2)	6,882 (20.4)	2,811 (8.4)	33,668 (100.0)	38,352 (63.9)	19,936 (33.3)	1,701 (2.8)	59,989 (100.0)
1984-85	27,375 (59.6)	18,525 (40.4)	45,900 (100.0)	27,958 (70.3)	8,340 (21.0)	3,418 (8.7)	39,746 (100.0)	46,265 (64.6)	23,390 (32.6)	1,999 (2.8)	71,654 (100.0)

\*पहले दिये गये कुल व्यय के जोड़ में इसे शामिल नहीं किया, गया, क्योंकि बाणिज्य विभागों को लेन देन और डाक सेवाओं को सफल आधार पर दर्शाया जाता है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1985-86	29,979 (58.9)	20,427 (11.1)	50,906 (100.0)	31,733 (70.7)	9,617 (21.1)	3,519 (7.9)	44,869 (100.0)	55,032 (65.1)	27,332 (42.4)	2,106 (2.5)	81,470 (100.0)
1986-87	35,135 (57.7)	26,060 (42.3)	51,558 (100.0)	36,827 (70.6)	11,220 (21.5)	4,149 (7.9)	52,196 (100.0)	64,441 (63.4)	33,652 (33.2)	3,179 (3.4)	101,602 (100.0)
1987-88	36,573 (51.7)	30,261 (45.3)	66,834 (100.0)	42,111 (70.2)	13,754 (22.9)	4,104 (6.9)	59,999 (100.0)	69,087 (62.2)	39,160 (35.5)	2,614 (2.3)	1,11,161 (100.0)
1988-89	41,536 (53.9)	35,519 (46.1)	77,055 (100.0)	47,064 (69.8)	15,803 (23.1)	1,599 (6.8)	67,466 (100.0)	78,983 (61.6)	45,940 (35.8)	3,322 (2.6)	1,28,245 (100.0)
1989-90	48,943 (54.3)	41,115 (45.7)	90,058 (100.0)	53,532 (68.5)	19,775 (25.3)	4,815 (6.2)	78,122 (100.0)	95,717 (62.5)	53,560 (35.0)	3,879 (2.5)	1,53,186 (100.0)
1990-91	58,801 (52.2)	16,559 (47.8)	97,360 (100.0)	55,932 (67.0)	23,085 (27.6)	4,512 (5.4)	83,539 (100.0)	95,907 (59.5)	61,601 (38.2)	3,685 (2.3)	1,61,193 (100.0)

(iv) इनमें आंतरिक तथा बाह्य ऋणों की चुकौती शामिल नहीं है।

5 राज्य सरकारों में सम्बन्धित, 15 राज्यों में सम्बन्धित आकड़े अन्तिम वजट के हैं जबकि शेष 10 राज्यों के आकड़े अन्तिम वजट के हैं। शरीर नागालैण्ड और उत्तर प्रदेश में सम्बन्धित वर्ष 1988-89 के आकड़े संशोधित अनुमान हैं।

55 इनमें आंतरिक ऋणों की चुकौती स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति पथ समनुदेशन, आकस्मिक निधियों के लिए वित्तियोजन, राज्य सरकारों के ऋण प्रेषण शामिल हैं तथा ये गणिता राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार का उन ऋणों की अदायगी में संबंधित आकड़ा के अन्तर्गत के लिए समायोजित की गयी है जो कि उनके संबंधित बजटों में दिये गये थे।

\* इनमें आंतरिक ऋणों की चुकौती केन्द्र सरकार का ऋणों की अदायगी आकस्मिक निधियों तथा प्रेषणों (ऋण) के लिए वित्तियोजन स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं में संबंधित समनुदेशन शामिल हैं।

टिप्पणी (i) कोटकों में दिये गये आकड़े संबंधित कुल व्यय के प्रतिशत प्रदर्शित करते हैं और

(ii) अंतर-सरकारी समझौतों के कारण केन्द्र तथा राज्यों के आकड़े संयुक्त स्थिति में शामिल नहीं किये गये हैं।

#### बजट प्रस्ताव

8 20 वर्ष 1990-91 के बजट प्रस्तावों के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं : कर प्रोत्साहन में अममानताओं को हटाना, अनावश्यक उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, विदेशी मुद्रा के अर्जन को प्रोत्साहित करना और उत्पन्न के राज्यों को कम्पनी कर पुनर्वित्तियोजन कर के बंधन करना। कम्पनी कर के तंत्र को और व्यापक बनाने का और भी विशेष ध्यान दिया गया है।

8 21 व्यक्तिगत आयकर के क्षेत्र में छूट की सीमा 18,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये कर दी गयी है। कर की 20 प्रतिशत की न्यूनतम दर 25,000 रुपये पर लागू होती थी। अब यह सीमा बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गयी है। वर्तमान अधिभार की 8 प्रतिशत की दर जारी रहेगी परंतु यह दर 75,000 रुपये के बाद वाली कर योग्य आय पर लागू होगी। इस समय यह सीमा 50,000 रुपये है। अगर 80 सी और अगर 80 सी सी के अर्जन वर्तमान कर प्रोत्साहनो का परागतात्मक और विषम स्वरूप को दूर करने के लिए, नई योजनाएं तैयार की गयी और अन्य योजनाओं के अन्तर्गत वित्तियोजन बांधे प्रोत्साहनो को और बढ़ाया गया। जवा कि बाद के पैराग्राफों में वर्णित हैं, विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में वित्तियोजन प्रेषण, को उल्लेख विदेशी मुद्रा के अर्जन से प्राप्त व्यावसायिक आय के संबंध में दी गयी स्थिति 25 प्रतिशत की वर्तमान दर बढ़ाकर आय के 50 प्रतिशत तक या अधिक तक बढ़ा दी गयी है। व्यक्तिगत आय कर के क्षेत्र में घोषित विभिन्न स्थितियों में 1990-91 के दौरान 250 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई है।

8 22 कम्पनी कर प्रणाली में प्रस्तावित समझौतों के प्रयोजन इस प्रकार थे : कर की प्राप्ति में वृद्धि करना, कर विन्यास को भंग करना और उसे लघु और बड़ी कम्पनियों के लिए पक्षपातरहित बनाना। इस विन्यास से यह भी आशा की जा रही है कि इस प्रणाली से नये उद्योगों

में निवेश के लिए तथा निर्यात संवर्धन के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। कर सम्बन्धी अपेक्षाओं का बेहतर ढंग से अनुपालन करने के लिए दोहरी नीति का प्रस्ताव किया गया है। प्रथम निजी क्षेत्र कर के वापस के बाहर न रह सके इसलिए निवेश और निवेश जमा खाता जैसे प्रमुख प्रोत्साहनो को समाप्त कर दिया गया है। द्वितीय, व्यापक रूप से अधिभारित कम्पनियों के मामले में देशी कम्पनियों के लिए करों की दर 50 प्रतिशत से घटा कर 40 प्रतिशत कर दी गयी व्यापार और निवेश कम्पनियों के मामले में 60 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दी गयी और अन्य देशी कम्पनियों के मामले में 55 प्रतिशत से घटाकर 45 प्रतिशत कर दी गयी। आशा है कि इस दोहरी नीति से प्रभावी दर बढ़ेगी और इसमें काफी प्रतिफल राजस्व मिलेगा। अब जितने प्रमुख कठोरताओं की अनुमति दी जायेगी व विदेशी मुद्रा के अर्जन और नये औद्योगिक उद्यमों की स्थापना में सम्बन्धित है। आयकर अधिनियम की धारा 115 जे के अन्तर्गत निम्न न्यूनतम लाभ पर कर लगाने सम्बन्धी विशेष उपाय का भी समाप्त कर दिया गया। वास्तविक निवेश को प्रोत्साहित करने और निजी सम्पत्ति के अधिभारण के लिए कम्पनी के विन्यास के उपयोग को निर्माहिन करने के लिए देशी कम्पनियों द्वारा अन्य देशी कम्पनियों में प्राप्त लाभों में उठा सामा तक छूट दी जायेगी जिस सीमा तक सम्बन्धित अवधि के दौरान लाभों की घोषणा की जायेगी। अनुसूचित बैंक और सरकारी बिजली संस्थाओं पर धारा 80 एम के अन्तर्गत उपबन्धों का नियंत्रण जारी रहेगा। कम्पनियों के 75,000 रुपये से अधिक लाभ के लिए 8 प्रतिशत का अधिभार जारी रहेगा। इस समय कम्पनी लाभ की सीमा 50,000 रुपये है। कम्पनी कर में दिये गये समझौतों में वर्ष 1990-91 के दौरान 800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

8 23 पूर्ण विभाजित करने और कोष धन का हिसाब से लाभ के प्रयोजन में भेद देने की व्यवस्था के उपयोग को गहन के लिए "दानकर्ता" पर लगाने वाला वर्तमान भेद कर के स्थान पर 20 मार्च 1990 से क्रयमान में "दान प्राप्त करने" पर आधारित कर लगाया जायेगा।

8.21 अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल और व्यक्तिगत बनाने पर अधिक बल दिया गया है, हालांकि आम आदमी को नुकसान पहुंचाये बिना तथा वर्ग के उपयोग पर नियंत्रण लगाने में मदद करने हुए और करबर्चन को रोकते हुए, समाधान जुटाने के पूरे प्रयास किये गये हैं। विकास और नियंत्रण के समाधान को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया गया है जबकि गुणवत्ता के प्रति चेतना का और औद्योगिक संरचना का विकास करने के लिए शुल्क विन्यास में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। लघु उद्योग कृषि और पर्यावरण संरक्षण जैसे पात्र क्षेत्रों को राहत भी दी गयी। विशेष रूप से आयान शुल्क की दरों को व्यक्तिगत बनाने और उनके आवर्तन को कम करने के लिए सीमाशुल्क की आधारभूत और सहायक शुल्क दरों के जोड़ के वर्गों की संख्या सीमित कर दी गयी है अर्थात् अधिकंग मदों के सम्बंध में वे शुल्क में 125 प्रतिशत तक हैं।

8.25 उत्पाद शुल्क में संशोधन करने से वर्ष 1990-91 में 778 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सकल राजस्व प्राप्त होगा। रियायतों और राहतों के कारण होने वाली 388 करोड़ रुपये की हानि को समायोजित करने के बाद 390 करोड़ रुपये की शुद्ध अतिरिक्त आय होगी, जिसमें से केन्द्रीय सरकार का अंश 217 करोड़ रुपये और राज्यों का अंश 173 करोड़ रुपये होगा। सीमा शुल्क के सम्बंध में कर प्रणाली में 980 करोड़ रुपये का सकल राजस्व प्राप्त होगा, रियायतों के कारण 145 करोड़ रुपये की राजस्व हानि के बाद 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सरकार को 835 करोड़ रुपये की शुद्ध राशि प्राप्त होगी। अतर्दीर्घीय यात्रा कर पहले मुक्त किराये 10 प्रतिशत\* लगाया जाता था, अब हम कर की वर्तमान दर पूर्ण हवाई किराये पर लाएँगे और हमसे 15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। डाक दरों में संशोधन करने से पूरे वर्ष में लगभग 207 करोड़ और 1990-91 में लगभग 172 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

8.26 उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप केन्द्र द्वारा संग्रहित सकल कर 1989-90 (परिणोद्धित अनुमान) 51,030 करोड़ रुपये था, इसमें 17 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1990-91 में (बजट अनुमान) 59,720

करोड़ रुपये होने का अनुमान है। अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में समाधान जुटाने के पर्याप्त प्रयासों के कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा सकल रूप में संग्रहित कर का अंश 19.6 प्रतिशत के स्तर से थोड़ा सा बढ़कर 19.7 प्रतिशत होगा, हालांकि 1980 के दशक के पूर्वार्ध में जिस स्तर पर था उससे यह काफी कम रहेगा (सारणी 8.8)

राज्यों के बजट 1990-91

8.27 1989-90 के कर की दरों पर राज्यों के संयुक्त बजट की स्थिति में यह पता चलता है कि 1990-91 में 2,135 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया गया है, जबकि इसकी तुलना में 1989-90 (परिणोद्धित अनुमान) में 1,197 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया गया था, तथा 1988-89 में 161 करोड़ रुपये का अधिशेष (लेखा बहियों के अनुसार) था। राज्यों द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त संसाधन जुटाने से 1990-91 में 366 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। 1990-91 के बजट में केन्द्रीय सरकार के कर प्रस्तावों में राज्यों का योग 3 करोड़ रुपये होगा। राज्यों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयासों का तथा केन्द्रीय सरकार के कर प्रस्तावों के कारण प्राप्त राशि को हिसाब में लेने के बाद घाटे की राशि कम होकर 1,766 करोड़ रुपये होगी। राज्यों को यह प्राणा है कि वे अपने-अपने बजट घाटे को कारणर वित्तीय प्रबंध अनुत्पादक व्यय में कटौती, समक्ष-कर संग्रहण और नौवे वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता से पूरा करेंगे।

8.28 वर्ष 1990-91 में राज्यों के राजस्व खातों के कराधान के संशोधित दरों पर 4,815 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है जबकि इसकी तुलना में 1989-90 में 4,611 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया गया था। यह घाटा कुछ हद तक राज्यों के पूंजीगत खर्चों में 3,049 करोड़ रुपये के अधिशेष से पूरा होने का अनुमान है। विच्छेद व पूंजीगत खातों में 3,417 करोड़ रुपये का अधिशेष दर्शाया गया था।

सारणी 8.8 : केन्द्र तथा राज्यों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर

(करोड़ रुपये)

वर्ष	केन्द्र (कुल)			राज्य			संयुक्त		
	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1980-81	2,907	10,242	13,149	686	5,929	6,615	3,593	16,171	19,784
(क)	22.1	77.9	100.0	10.4	89.6	100.0	18.2	81.8	100.0
(ख)	2.1	7.6	9.7	0.5	4.4	4.9	2.7	11.9	14.6
1984-85	4,626	18,802	23,428	1,230	11,108	12,338	5,856	29,910	35,766
(क)	19.7	80.3	100.0	10.0	90.0	100.0	16.4	83.6	100.0
(ख)	2.0	8.2	10.2	0.6	4.8	5.4	2.5	13.0	15.5
1985-86	5,563	23,109	28,672	1,401	12,919	14,320	6,964	36,028	42,992
(क)	19.4	80.6	100.0	9.8	90.2	100.0	16.2	83.8	100.0
(ख)	2.1	8.8	10.9	0.5	4.9	5.4	2.7	13.7	16.4
1986-87	6,234	26,559	32,793	1,685	14,934	16,619	7,919	41,493	49,412
(क)	19.0	81.0	100.0	10.1	89.9	100.0	16.0	84.0	100.0
(ख)	2.1	9.1	11.2	0.6	5.1	5.7	2.7	14.1	16.0

\*इसे बाद में बढ़ा कर 1.5 प्रतिशत किया गया।

@ आकड़ें 25 राज्यों से सम्बन्धित हैं।

211 GI/91-27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1987-88	6,751	30,861	37,612	19,60	17,478	19,398	8,711	48,999	57,010
(क)	17.9	82.1	100.0	10.1	89.9	100.0	15.3	84.7	100.0
(ख)	2.0	9.3	11.3	0.6	5.2	5.8	2.6	14.5	17.1
1988-89(अ)	8,824	35,596	44,420	2,419	19,979	22,398	11,247	55,575	66,818
(क)	19.9	80.1	100.0	10.3	89.2	100.0	16.8	83.2	100.0
(ख)	2.3	9.1	11.4	0.6	5.1	5.7	2.9	14.2	17.1
1989-90(ऐ)	9,994	41,036	51,030	2,644	22,739	25,383	12,678	63,775	76,413
(अ)(क)	19.6	80.4	100.0	10.4	89.6	100.0	16.5	81.5	100.0
(ख)	2.3	9.4	11.7	8.6	5.1	5.7	2.9	14.4	17.3
1990-91(ई)	11,774	47,946	59,720	2,913	25,689	28,602	14,697	73,605	88,322
(ग)(क)	19.7	80.3	100.0	10.2	89.8	100.0	16.6	83.4	100.0

(अ) राज्य सरकारों में सम्बन्धित, 15 राज्यों में सम्बन्धित आंकड़े लेखानुसार बजट के हैं जबकि शेष 10 राज्यों के आंकड़े अंतिम बजट के हैं। आर्थिक मामलों के विभाग से सम्बन्धित वर्ष 1988-89 के आंकड़े सहायता अनुमान हैं। \* कृषि क्षेत्र में राज्यों के हितों का ध्यान रखते हुए, जैतपुर, जैतपुर के बजट प्रलेखों में उल्लिखित है।

टिप्पणी : (क) कुल कर राजस्व में प्रतिशतों प्रदर्शित करता है।

(ख) सहाय देशों उत्पाद में कर के अनुपात का प्रतिशत।

उ. 29 वर्ष 1990-91 के बजट में कराधान की संशोधित दरों पर राज्यों की कुल 81,773 करोड़ रुपये की प्रगति का प्रावधान है। इसमें 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी गयी है जबकि इसकी तुलना में 1989-90 में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी गयी थी। दूसरी ओर 1990-91 के बजट में कुल 83,539 करोड़ रुपये के संचित कर का प्रावधान है। इसमें 6.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी गयी, जबकि इसकी तुलना में 1989-90 में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी गयी थी। राज्यों के विकास व्यय के लिए 55,932 करोड़ रुपये का प्रावधान है इसमें 1990-91 में 4.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शायी गयी है जबकि इसकी तुलना में 1989-90 में 13.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शायी गयी थी। 1989-90 में विकास से व्यय में 25.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। 1990-91 में 16.8 प्रतिशत वृद्धि के साथ यह 23,095 करोड़ रुपये अनुमानित है। राज्य के कुल संचित करों में विकास व्यय का अंश 1989-90 में 68.5 प्रतिशत था, इस स्तर से यह घटकर 1990-91 में 67.0 प्रतिशत अनुमानित है जबकि विकास से व्यय 25.3 प्रतिशत से बढ़कर 27.6 प्रतिशत अनुमानित है। अन्य संचित कर, जिनमें आंतरिक ऋण की चुकोती शामिल है, 1990-91 में केन्द्रीय सरकार द्वारा की ऋण की चुकोती कुल संचित करों का 5.4 प्रतिशत होगी जबकि 1989-90 में उनका अंश 6.2 प्रतिशत था।

समेकित बजट स्थिति—केन्द्र और राज्य

उ. 30 अतिरिक्त संशोधन जुटाने संबंधी उपायों से प्राप्त आय को हिसाब में लेते के बाद केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की समेकित बजट स्थिति से यह पता चलता है कि कुल बजट घाटा 8,972 करोड़ रुपये है जबकि 1989-90 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 12,947 करोड़ रुपये का बजट घाटा था। मारणी 8.9 में केन्द्रीय और राज्य सरकारों की मध्यम वित्तीय स्थिति संबंधी आंकड़े दिये गये हैं।

उ. 31 केन्द्रीय और राज्य सरकारों की कुल प्राप्तियों 1989-90 में 1,40,239 करोड़ रुपये थी, 1990-91 में इनके 8.5 प्रतिशत बढ़कर 1,52,221 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। राजस्व और पूंजा प्राप्तियों में 1989-90 के स्तर की तुलना में क्रमशः 8.7 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। 1990-91 में कर प्राप्तियों 88,322 करोड़ रुपये अनुमानित है। इनमें 15.6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है जबकि 1989-90 में इनमें 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। प्रत्यक्ष करों से प्राप्त राजस्व में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी जबकि इसकी तुलना में परोक्ष करों में 15.5 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। कुल प्राप्तियों में परोक्ष कर प्राप्तियों का अंश 1990-91 में 83.4 प्रतिशत होगा जबकि 1989-90 में यह अंश 83.5 प्रतिशत था।

उ. 32 1990-91 में कुल संचित करों का 1,61,193 करोड़ रुपये है। इसमें पिछले वर्ष की राशि की तुलना में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। विकास व्यय 95,907 करोड़ रुपये अनुमानित है। इसमें 1989-90 के स्तर से मात्र थोड़ी-सी घटाई 160 करोड़ रुपये या 0.2 प्रतिशत वृद्धि होगी। दूसरी ओर विकास से व्यय की राशि 61,601 करोड़ रुपये है। बजट में इसमें 1990-91 में 15.0 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान है। इसके परिणामस्वरूप कुल व्यय में विकास व्यय का अंश 1989-90 के 62.5 प्रतिशत के स्तर से घटकर 1990-91 में 59.5 प्रतिशत पर आयेगा। ठीक इसके विपरीत कुल व्यय के अनुपात के रूप में विकास से व्यय का अंश 1989-90 के 35.0 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 1990-91 में 38.2 प्रतिशत होने की आशा की जाती है।

नौवां वित्त आयोग

उ. 33 नौवां वित्त आयोग जून 1987 में गठित किया गया। इस आयोग ने दिसम्बर 1989 में अपनी दूसरी एवं अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में 1990 से 1985 तक की अवधि शामिल की गयी है। वित्त आयोग ने यह सिफारिश की है कि व्यक्तिगत आयकर विशेष उत्पाद शुल्कों सहित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में राज्यों का हिस्सा क्रमशः 85 प्रतिशत और 45 प्रतिशत पर घटाया जाना रहेगा। आयोग ने रेल यात्री किराये पर लगाये जाने वाले कर के बढ़ने से अनुदान की राशि 95 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कर दी है। राहत व्यय का वित्त पोषण करने के लिए आयोग ने यह सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विपत्ति राहत कोष की स्थापना की जानी चाहिए। इस कोष में केन्द्रीय सरकार द्वारा योजनेतर अनुदान के रूप में 75 प्रतिशत तक अंशदान किया जायेगा तथा शेष के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा अपने समाधानों में से अंशदान किया जायेगा। आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों के विपत्ति राहत कोषों के लिए प्रतिवर्ष 804 करोड़ रुपये का वित्तियान किया जाना चाहिए। इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा 603 करोड़ रुपये का अंशदान किया जायेगा। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि अगले पांच वर्षों में (1990-95) राज्यों को 15,017.18 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता दी जाये। इसमें से 6,016.35 करोड़ रुपये योजनेतर राजस्व खाने के अंशदानों को पाने के लिए तथा शेष 9,000.83 करोड़ रुपये योजना राजस्व खाने के प्राथमिक घाटे को पूरा करने के लिए होगा। आयोग ने सिफारिश की है कि विशेषतः श्रेणी के राज्यों को दी जाने वाली योजनागत सहायता का 40 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार के ऋण के रूप में देने के बजाये अतिरिक्त बाजार ऋण के रूप में दिया जाये। आयोग ने केन्द्रीय सरकार से लिये गये बकाया

श्रृणो के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को राहत देने की भी सिफारिश की है। यह राहत श्रृणो की प्रक्षायणी अनुसूचियां बुबारा तैयार करके तथा बट्टे खाने में डालकर दी जाने की सिफारिश है। राज्यों को केन्द्रीय सरकार

द्वारा दिये जाने वाले राहत श्रृणो को नियंत्रित करने वाली शर्तों में कतिपय परिवर्तन करने का सुझाव भी आयोग ने दिया। आयोग अनिश्चित सीमा शुल्क को मूल सीमा शुल्क के साथ मिलाते के पक्ष में नहीं था।

सारणी 8.9 : केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तिश्रं और वितरण

(1988-89 से 1990-91 तक के राजकोषीय वर्ष)

(करोड़ रुपये)

मद	1988-89 (लेखे)	1989-90 (बजट अनुमान)	1989-90 (संशोधित अनुमान)	1990-91* (बजट अनुमान)	कॉलम 2 की तुलना में कॉलम 4 के प्रतिशत का अंतर	कॉलम 4 की तुलना में कॉलम 5 का अंतर
1	2	3	4	5	6	7
I कुल प्राप्तिश्रं (अ + आ)	1,22,767	1,34,192	1,40,219	1,52,221	+ 14.2	+ 8.5
अ राजस्व प्राप्तिश्रं जिसमें से						
कर प्राप्तिश्रं (क + ख)	82,195	95,041	96,945	1,05,376	+ 17.9	+ 8.7
(क) प्रत्यक्ष कर	66,818	75,528	76,413	88,322	+ 14.4	+ 15.6
(ख) परीक्षा कर	11,243	11,722	12,638	14,687	+ 12.4	+ 16.2
(ख) परीक्षा कर	55,575	63,806	63,775	73,615	+ 14.8	+ 15.5
आ पूँजीगत प्राप्तिश्रं	40,572	39,151	43,294	46,845	+ 6.7	+ 8.2
II कुल वितरण (अ + आ + इ)	1,28,245	1,42,201	1,53,186	1,61,193	+ 19.1	+ 5.2
अ विकासात्मक व्यय (क + ख + ग)	78,983	83,698	95,747	95,907	+ 21.2	+ 0.2
(क) राजस्व	52,323	55,344	64,876	66,462	+ 24.0	+ 2.4
(ख) पूँजी	13,339	14,625	14,672	15,603	+ 10.0	+ 6.3
(ग) श्रृण और अधिम	13,321	13,729	16,199	13,842	+ 21.6	- 14.6
आ गैर विकासात्मक व्यय						
(क + ख + ग)	45,940	54,488	53,560	61,601	+ 16.0	+ 15.0
(क) राजस्व	41,507	49,709	48,516	55,955	+ 16.9	+ 15.3
(ख) पूँजी	4,113	4,442	4,702	5,311	+ 14.3	+ 13.0
(ग) श्रृण और अधिम	220	337	342	335	+ 6.9	- 2.0
इ अन्य	3,322	4,015	3,879	3,685	+ 16.8	- 5.0
III समग्र आधेश ( + )/घाटा ( - )	- 5,478	- 8,009	- 12,947	- 8,972	+ 136.3	- 30.7

\* इसमें बजट प्रस्ताव के प्रभाव शामिल हैं और बजट के बाद की कर रियायतों को नहीं लिया गया है।

टिप्पणी : 1 राज्य सरकारों से सम्बन्धित, 15 राज्यों से सम्बन्धित आकरें लेखानुसार बजट के हैं जबकि शेष 10 राज्यों के आकरें अंतिम बजट के हैं।  
आगे कागज और उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित वर्ष 1988-89 संशोधित अनुमान हैं।

2 अन्य वितरणों में शामिल आर बजट श्रृण वृद्धता, स्थानीय निगमों और पंचायतों राज्य सरकारों की अनिपूर्ति और दी गयी राशिदा, आवस्मिक विधियों में वित्तियान और शुद्ध प्रेषण शामिल हैं और राज्य सरकारों द्वारा अपने सम्बन्धित वचता में दणये गये केन्द्र सरकार को दिये गये श्रृण वृद्धता के आकरों में आर के लिए उन्हें समायोजित किया गया है।

8.34 केन्द्रीय सरकार पर राजकोषीय अनुमान लागू करने के उद्देश्य से आयोग ने यह सुझाव दिया कि इस सम्बन्ध में एक ऐसी परम्परा विकसित की जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत किसी भी वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा जिस सीमा तक पाटे का बिल पारण किया जाता है उस सीमा का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के परामर्श से किया जाना चाहिए। यह निर्धारण जिन उद्देश्यों को लेकर किया जाता है उसके अधिक मानक पढ़ने में ही स्पष्ट रूप से बना लेने चाहिए। आयोग ने यह भी निवेदन किया है कि कतिपय असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत यदि रिजर्व बैंक

से सहमत श्रृण सीमाओं से अधिक श्रृण लिया जाता है तो समय में इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए तथा उसके लिए अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

8.35 आयोग की जिन सिफारिशों को तत्काल लागू करना आवश्यक है उन्हें केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया है। ये सिफारिशें इस प्रकार हैं—राज्यों को करों और शुल्कों के अंतर्गत राहत व्यय का वित्तपोषण और श्रृण राहत। जिन सिफारिशों का गहन विवेचन करने को आवश्यकता है उन पर उचित समय पर विचार किया

जायेगा। वर्ष 1990-91 केन्द्रीय सरकार के बजट में यह मत व्यक्त किया गया है कि वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने से 1990-91 में केन्द्रीय वित्त ताल पर 773 करोड़ रुपये का प्रतिरिक्त बोनस आयेगा।

#### बाजार-ऋण\*

8.36 वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने पाँच पात्र निर्गमों के माध्यम से बाजार ऋण लेने सम्बन्धी अपनी गतिविधियाँ संचालित की। इनसे 8,044 करोड़ रुपये की सकल राशि जुटायी गयी, जबकि इसकी तुलना में 1988-

89 में 7,725 करोड़ रुपये की ऋण राशि जुटायी गयी थी। जिन ऋणों की अवधि समाप्त हो गयी थी उन के सम्बन्ध में 639 करोड़ रुपये की धरायगी करने के बाद शुद्ध बाजार ऋण 7,405 करोड़ रुपये हुआ। यह पिछले वर्ष के 7,251 करोड़ रुपये से 154 करोड़ रुपये (2.1 प्रतिशत) अधिक थी (सारणी 8.10)। 8,044 करोड़ रुपये के सकल बाजार ऋण में 7,469 करोड़ रुपये नेकव प्रभिवान था और 575 करोड़ रुपये के अवधि समाप्ति वाले परिवर्तित ऋण थे।

\* ये आंकड़े रिजर्व बैंक के अभिलेखों के वास्तविक आंकड़े हैं।

सारणी 8.10 : केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों एवं केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थाओं द्वारा बाजार से लिये गये ऋण 1988-89 और 1989-90

(राजकोषीय वर्ष)

(करोड़ रुपये)

सरकार/प्राधिकरण	सकल बाजार ऋण		चुकोतियाँ (कुल ऋण जिनकी अवधि पूरी हुई)		शुद्ध बाजार ऋण	
	1988-89	1989-90	1988-89	1989-90	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6	7
1. केन्द्र सरकार	7,725	8,44	474	639	7,251	7,405
2. राज्य सरकार	2,285	2,555	283	306	2,002	2,249
3. सरकार के कुल ऋण (1+2)	10,010	10,999	757	945	9,253	9,654
4. केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाएं	2,224	2,622	309	457	1,935	2,165
	1,417	1,519	374	416	1,043	1,103
5. राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थाएं (स्थानीय निकायों सहित)	3,661	4,141	683	873	2,978	3,268
6. संस्थाओं के कुल ऋण (4+5)						
7. कुल बाजार ऋण (3+6)	13,671	14,740	1,440	1,818	12,231	12,922

\* रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार वास्तविक आंकड़े

8.37 वर्ष 1989-90 में राज्य सरकार की सकल बाजार ऋण राशियाँ 2,555 करोड़ रुपये हुईं, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष के दौरान 2,285 करोड़ रुपये की ऋण राशियाँ थी। इसमें 270 करोड़ रुपये (11.8 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गयी (राज्य सरकारों का 2,555 करोड़ रुपये की सकल बाजार ऋण-राशियों से नेकव प्रभिवान 2,513 करोड़ रुपये था और अवधि समाप्ति के बाद परिवर्तित किये गये ऋण की राशि 42 करोड़ रुपये थी। 306 करोड़ रुपये की चुकोती करने के बाद राज्य सरकारों द्वारा लिये गये शुद्ध बाजार ऋण 247 करोड़ रुपये (12.3 प्रतिशत) बढ़कर 2,249 करोड़ रुपये हुआ, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष 2,002 करोड़ रुपये की राशि थी।

8.38 स्थानीय प्राधिकारियों और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थाओं का सकल बाजार ऋण 1988-89 में 3,661 करोड़ रुपये था; इसमें 480 करोड़ रुपये (13.1 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई और 1989-90 में यह 4,141 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुँचा। फिर भी शुद्ध बाजार ऋण 2,978 करोड़ रुपये के स्तर से थोड़ा सा घटा 2,90 करोड़ रुपये (9.7 प्रतिशत) बढ़कर 3,268 करोड़ रुपये पर पहुँचा, क्योंकि 1989-90 के दौरान चुकोतियों की राशि अधिक थी। इस वर्ष चुकोती की राशि 873 करोड़ रुपये रही, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष 683 करोड़ रुपये थी। इन प्रायोजित संस्थाओं और

स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जुटाये गये 3,268 करोड़ रुपये के शुद्ध बाजार ऋणों में से केन्द्रीय सरकार की प्रायोजित संस्थाओं ने 2,165 करोड़ रुपये (66.3 प्रतिशत) की राशि जुटायी। जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष 1,935 करोड़ रुपये (65.0 प्रतिशत) की राशि जुटायी गयी थी।

8.39 सकल बाजार ऋण (जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की प्रायोजित संस्थाओं द्वारा लिये गये बाजार ऋण शामिल हैं) 1989-90 के दौरान 1,069 करोड़ रुपये (7.8 प्रतिशत) बढ़कर 14,740 करोड़ रुपये हो गयी जबकि पिछले वर्ष यह ऋण 13,671 करोड़ रुपये था। 1989-90, के दौरान शुद्ध बाजार ऋण, 1,818 करोड़ रुपये की चुकोती के बाद 691 करोड़ रुपये (5.6 प्रतिशत) बढ़कर 12,922 करोड़ रुपये हो गया जबकि 1988-89 के दौरान यह 12,231 करोड़ रुपये था।

8.40 केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1990-91 के बजट में सम्पूर्ण वर्ष के लिए 8,988 करोड़ रुपये का सकल बाजार ऋण अनुमानित है। 988 करोड़ रुपये की ऋण की चुकोतियाँ करने के बाद बजट में 8,000 करोड़ रुपये की शुद्ध बाजार ऋण का प्रावधान है, पिछले वर्ष के 7,400 करोड़ रुपये की तुलना में यह ऋण 600 करोड़ रुपये (8.1 प्रतिशत) अधिक था।



केन्द्रीय सरकार के ऋणों पर कूपन दरे

8 41 1989-90 के दौरान केन्द्रीय सरकार के ऋणों की कूपन दरे अपरिवर्तित रही। 20 वर्ष की अवधि के ऋणों के लिए कूपन दरे 11.5 प्रतिशत थी, 15 वर्ष की अवधि के ऋणों के लिए 11.0 प्रतिशत और 10 वर्ष की अवधि के ऋणों के लिए कूपन दरे 10.5 प्रतिशत थी।

केन्द्रीय ऋणों को रिजर्व बैंक का समर्थन

8 42 1989-90 में केन्द्रीय सरकार के बाजार में रिजर्व बैंक का प्रारम्भिक अभिदान 4,861 करोड़ रुपये या सकल बाजार ऋणों का 60.4 प्रतिशत था जो पिछले वर्ष के 2 513 करोड़ रुपये की तुलना में 2,348 करोड़ रुपये (93.4 प्रतिशत) अधिक था, पिछले वर्ष का अभिदान सकल बाजार ऋण का 32.5 प्रतिशत था। यद्यपि रिजर्व बैंक प्रारम्भिक अभिदान के माध्यम से खरीदे गये केन्द्रीय सरकार के ऋण का कुछ भाग कम कर सकने की स्थिति में था, फिर भी बैंक द्वारा धारित केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों का अधिधारण 1989-90 में 3000 करोड़ रुपये के उच्चतर स्तर पर था जबकि इसकी तुलना में 1988-89 में 1,746 रुपये का अधिधारण था। रिजर्व बैंक के साथ क्रय-प्रतिक्रय व्यवस्था के अन्तर्गत सम्पत्तियों द्वारा केन्द्रीय सरकार की सीमादी प्रतिभूतियों का धारण 1989-90 के दौरान 197 करोड़ रुपये बढ़ा जबकि इसके ठीक विपरीत 1988-89 में यह 1,104 करोड़ रुपये था।

घातक ऋण और अन्य देयताएँ :

8 43 बाजार से लिये गये ऋणों के अतिरिक्त केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने लघु बचत और अग्रिम निधियी जैसे अन्य लिखतों के माध्यम से ससाधन जुटाये। इन्हें हिसाब में लेने के बाद केन्द्रीय और राज्य सरकारों की घातक ऋण और अन्य देयताएँ 1989-90 में 39,223 करोड़ रुपये या सकल देशी उत्पाद का 8.9 प्रतिशत हुई जबकि 1988-89 में ये देयताएँ 35,446 करोड़ रुपये या सकल देशी उत्पाद का 9.1 प्रतिशत था।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के ऋण

8 44 केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाने वाले ऋणों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के अनेक उपक्रम अपने विकास कार्यक्रमों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण/डिबेंचर और विदेशी बाणिज्य ऋण प्राप्तिकर्ता का ऋण जुटाने रहे हैं। केन्द्रीय सरकार के 1990-91 के बजट में दर्शाया गया है कि वर्ष के दौरान जुटायी गयी ऋण राशि पिछले वर्ष की ऋण राशि की तुलना में कम है। अनुमान है कि सरकारी क्षेत्र के ये उपक्रम 1990-91 के दौरान देशी बाजार ऋण/डिबेंचर जारी करके 3,942 करोड़ रुपये का ऋण जुटायेगे। तथा विदेशी बाणिज्य ऋण प्राप्तिकर्ता के ऋण के माध्यम से 1,446 करोड़ रुपये जुटायेगे, जबकि इसकी तुलना में 1989-90 के दौरान अमरा 4 494 करोड़ रुपये और 1,922 करोड़ रुपये जुटाये गये थे।

सारणी 8 11 सातवी योजना के परिधाय के वित्तपोषण

भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थपाय अग्रिम

8 45 रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को अपनी धाय और व्यय संबंधी सक्ती सवाह में अस्थायी अमृतुलन का ठीक करने के लिए अर्थपाय अग्रिम प्रदान करना है। मार्च 1988 से 23 राज्यों को उपलब्ध कुल सामान्य अर्थपाय अग्रिमों की सीमाएँ 744.8 करोड़ रुपये हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की प्रतिभूतियों का रूढ़न रखने के बदले राज्य सरकारों को 266 करोड़ रुपये की विशेष अर्थपाय अग्रिम सीमाएं दी जाती हैं। इस प्रकार 23 राज्यों का उपलब्ध अर्थपाय अग्रिम सीमाओं की राशि 1,010.8 करोड़ रुपये है।

8 46 1989-90 में दो राज्यों का छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने ओवरड्राफ्ट विनियमन योजना का पालन किया। चूंकि इन दो राज्यों के खान लगानार 7 कार्यविवरों तक एक जुलाई 1989 में ग्रीन बूसा मार्च 1990 में अधिभारित रहे, अतः उनकी धार से की जाने वाली अदायगियाँ रिजर्व बैंक का सब तक राक दनी पड़ी अब तक उसका निपटान नहीं हुआ।

बचत लिखत

8 47 वर्तमान बचत योजना के सबंध में 1990-91 केन्द्रीय सरकार बजट में किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं :

- (I) आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के अन्तर्गत बचत को प्रोत्साहित करने के लिए दी जानेवाली कर रियायतों सम्बन्धी उपबन्धों के स्थान पर धारा 88 के अन्तर्गत नये उपबन्धों को शामिल किया गया है। नये उपबन्धों के स्थान पर धारा 88 के अन्तर्गत नये उपबन्धों को शामिल किया गया है। नये उपबन्धों के अन्तर्गत जीवन बीमा पॉलिसियों, अग्रिम निधि, अधिवर्षिता निधि, और अन्य पात्र निवेश का 20 प्रतिशत कुल धाय पर देय आयकर में से कटौती करने की अनुमति दी गयी है। देय धाय कर में से अनुमेय अधिकतम कर छूट, 10,000 रुपये होगी। नाटककारों, कलाकारों, समीक्षकों, अभिनेताओं और खिलाड़ियों, जिनमें एथलेटिक्स भी शामिल हैं, के मामलों में अनुमेय कर छूट की सीमा 14,000 रुपये होगी।
- (II) बचत को और अधिक प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत की गयी जमा राशियाँ और धारा 80 सीसीए के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम की अधिसूचित वार्षिकी योजनाओं के लिए की गयी अदायगियों के सबंध में कटौती के लिए पात्र अधिकतम राशि 30,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दी गयी है।
- (III) पिछले वर्ष ईश्वरी सम्प्रदाय बचत योजना धारित की गयी थी, जिने धय नई धारा 80 सीसीसी के अन्तर्गत अंतिम स्वरूप दे दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत कुल धाय में से किये जाने वाले निवेश अधिकतम 10,000 रुपये तक का कटौती के लिए पात्र है। वृत्तों में किये गये निवेश का वार्षिक आय धारा 80 एन के अन्तर्गत कर रियायत के लिए पात्र होगी।

(करोड़ रुपये)

संके	1985-86 से 1989-90 तक (अंशतः अनुमान)			मूल अनुमान		
	1984-85 के मूल्यों पर					
	केन्द्र (र)	राज्य	कुल	केन्द्र (र)	राज्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
i 1984-85 की दूरी टैरिफ और किंगयो पर देशी समाधन	--11,074 (--9 7)	--1,139 (--1 5)	--12,213 (--6 5)	--12,011 (--12 8)	6 762 (8 4)	--5,219 (--2 9)

1	2	3	4	5	6	7
(क) वर्तमान राजस्व की शेष राशि	26,872 (23 6)	--3,757 (--5 0)	23,115 (12 3)	37,454 (37 7)	--1,969 (--2 4)	35,485 (19 7)
(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से प्रशुद्धाव	7,482 (6 6)	-- (--)	7,484 (4 0)			
(ग) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा बांध जारी करना	26,542 (23 3)	9,242 (12 4)	35,748 (19 0)	20,620 (20 8)	9,942 (12 3)	30,562 (17 0)
(घ) बाजार ऋण	8,751 (7 7)	19,070 (25 6)	27,821 (14 8)	8,677 (8 7)	16,566 (20 5)	25,583 (14 0)
(ङ) अल्प बचन और भविष्य निधि	-- (--)	4,445 (6 5)	4,445 (2 4)	-- (--)	4,639 (5 8)	4,639 (2 6)
(च) बाजार ऋण	29,039 (25 5)	--5,113 (-6 9)	23,926 (12 7)	19,809 (19 9)	--7,191 (--8 9)	12,618 (7 0)
(छ) विविध पजीगत प्राप्ति	14,881 (13 8)	18,507 (24 8)	33,388 (17 7)	22,490 (22 7)	22,212 (27 5)	44,702 (24 3)
ii प्रतिष्ठापित संसाधन जुटाना	1,02,495 (90 1)	41,245 (55 4)	1,43,750 (76 4)	97,039 (97 7)	50,961 (63 2)	1,48,000 (82 2)
iii कुल देशी संसाधन (I + II)	16,348 (14 4)	-- (--)	16,348 (8 7)	18,000 (18 1)	-- (--)	18,000 (10 00)
iv विदेश से निधियों का शुद्ध प्रत्यर्पण	28,381 (25 0)	-- (--)	28,381 (15 1)	14,000 (14 1)	-- (--)	14,000 (7 8)
v बजट घाटा	1,47,224 (129 5)	41,255 (55 4)	1,88,479 (100 2)	1,29,039 (129 9)	50,961 (63 2)	1,80,000 (100 0)
vi कुल स्त्रोत (III + IV + V)	--33,545 (-29 5)	33,264 (44 6)	--290 (--0 2)	--29,737 (--29 9)	29,737 (38 8)	-- (--)
vii राज्या का केन्द्र का सहयोग	1,13,670 (100 0)	74,519 (100 0)	1,88,189 (100 0)	99,302 (100 0)	80,698 (100 0)	1,80,000 (100 0)
viii योजना के लिए उपलब्ध संसाधन (VI + VII)	1,13,670	74,519	1,88,189	99,302	80,698	1,80,000

(ii) मध्यमशक्ति क्षेत्र शामिल है।

\* राज्यों के लिए वर्तमान राजस्व की शेषराशि में सूचीगत श्रेणी उन्नयन अनुदान, केन्द्र से विशेष समस्याओं के लिए अनुदान और विशेष श्रेणी के राज्यों द्वारा किये जाने वाले उपाय भी शामिल हैं, ताकि राजस्व की शेषराशि का घनत्व पूरा किया जा सके।

टिप्पणी 1 ये आंकड़े 1985-86 से 1988-89 तक के अद्यतन अनुमानों और 1989-90 के वार्षिक योजना अनुमानों पर आधारित हैं।

2 वर्तमान मूल्यों के आकड़े थोक मूल्य सूचकांक द्वारा कम किये गये थे (1981-82 के आधार पर) ताकि उन्हें 1934-85 (सामान्य योजना का आधार वर्ष) के मूल्यों से परिवर्तित किया जा सके।

3 कोटक में दिये गये आकड़े योजना परिसर की प्रत्येक संवे प्रतिष्ठित हैं।

स्त्रोत भारतीय आर्थिक सांख्यिकी, सरकारी वित्त 1989, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

म्युचुअल फंड या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की पुनः खरीद पर पूंजीगत राशि, (जो यूनिटों के मूल्य का शेष है) पर खरीद वर्ष की आय के रूप में कर लगाया जायेगा और प्रतिष्ठित राशि पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर देय होगा। ईक्विटी सम्बन्धित बचत योजना में धारा 80 सी सी के अन्तर्गत की जाने वाली वर्तमान कटौती प्रणाली का स्थान लेगी।

(iv) आय कर अधिनियम की धारा 80 सी सी में शेषरा के निवेश के सम्बन्ध में 50 प्रतिशत के बराबर की राशि की कटौती का प्रावधान है। ये शेषरा ईक्विटी पूंजी के पात्र निर्माण का भाग है या म्युचुअल फंड भारतीय यूनिट ट्रस्ट की किसी भी योजना के अन्तर्गत

यूनिटों का भाग है। यह कटौती अधिकतम 20,000 रुपये की सीमा के अधीन है। धारा 89 ए के उपबन्ध के अन्तर्गत, पूंजी या यूनिटों के पात्र निर्माण में किये गये निवेश के 20 प्रतिशत की दर से कर में छूट दी जायेगी। कर में छूट के लिए पात्र निवेश की अधिकतम राशि 25,000 रुपये है। तब धारा 88 ए में अब शामिल की गयी धारा 93 सी सी की योजना 31 मार्च 1991 के बाद समाप्त हो जायेगी।

सामान्य योजना का वित्तपोषण

9.48 सामान्य पत्रव्यवस्था योजना के लिए प्रावधानित वित्तपोषण के मूल स्वरूप की तुलना कर प्राप्ति के अद्यतन अनुमानों में (जिसे वर्ष-प्रतिवर्ष आधार पर 1984-85 तक परिवर्तित किया गया है) करने पर

अतिथि उल्लेखनीय विशेषताओं का पता चलता है। पाठ के विस्तारण द्वारा कर प्राप्ति में योगदान योजना के अनुमानों से जुड़ा है, जबकि चाल राजस्व, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त राशियाँ और जुटाये गये अतिरिक्त संसाधनों में उल्लेखनीय कमी परिलक्षित हुई। तदनुसार, इसमें यह स्पष्ट होता है कि मूद्रास्फीतिमुक्त वित्तपोषण पर निर्भरता अधिक है। कुछ हद तक बाजार ऋणों, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा बांडों का निर्गम और अतिथि निधियों के माध्यम से पर्याप्त राजकोषीय रियायतों के साथ इन संसाधनों की अपेक्षाओं ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने का स्थान ले लिया है (देखें सारणी 8.11)।

#### 9. वित्तिय संस्थाएँ और पूँजी बाजार

##### वित्तीय संस्थाएँ

9.1 हाल के वर्षों के दौरान भारत में वित्तीय मध्यस्थता में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। यद्यपि वित्तीय बचत और उसके वितरण के लिए वाणिज्यिक और सहकारी बैंकिंग तंत्र मुख्य माध्यम हैं, फिर भी पिछले दशक के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रदान की जानेवाली सहायता में हुई तीव्र वृद्धि में अब वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं को भारी मात्रा में रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

9.2 सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के संयुक्त तुलन पत्र से पता चलता है कि कुल आस्तरियों में वित्तीय संस्थाओं का अंश मार्च 1981 के अंत के 27.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 1986 के अंत में 31.2 प्रतिशत हो गया तथा मार्च 1989 के अंत में और बढ़कर 33.6 प्रतिशत हो गया (सारणी 9.1)। अब जहाँ बैंकों की आस्तरियाँ 176,500 करोड़ रुपये की हैं वहाँ वित्तीय संस्थाओं की आस्तरियाँ लगभग 89,400 करोड़ रुपये की हैं (सारणी 9.1 और 9.2)। मार्च 1989 के अंत में वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण और अग्रिम, अनुसूचित वाणिज्य और सहकारी बैंकों के संवध में बकाया बैंक ऋण के लगभग 51 प्रतिशत अंश के बराबर थे। इसी प्रकार, सरकारी प्रतिभितियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बांडों और डिबेंचरों तथा निजी कंपनी क्षेत्र के इक्विटी शेयरों एवं डिबेंचरों में इन संस्थाओं के निवेश, बैंकिंग तंत्र के ऐसे निवेश के लगभग 47 प्रतिशत अंश के बराबर थे। इसके अलावा, वार्षिक कार्यों के रूप में जहाँ सभी वित्तीय संस्थाओं (सारणी 9.1 और सारणी 9.2) (नाबार्ड सहित) द्वारा प्रदत्त बकाया ऋणों और अग्रिमों में 1988-89 के दौरान लगभग 9,060 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई वहाँ अनुसूचित

वाणिज्य और सहकारी बैंकों द्वारा प्रदत्त बकाया ऋण में उसी वर्ष में 16,440 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। (यद्यपि वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के बीच कुछ आदान-प्रदान के कारण ये आंकड़े पूर्णतः तुलनीय नहीं हैं, तथापि इन आंकड़ों में उनके संबंधित कार्यों के परिणाम का अंदाजा हो जाता है)।

9.3 साथ ही, विनिर्माण और अन्य गैर-वित्तीय कंपनियों द्वारा अधिकांशतः निवेशयोग्य संसाधन मुख्यतः इक्विटी, डिबेंचरों और जनता से जमा राशियों के रूप में सीधे ही बाजार से जुटाने हैं और उन्हीं कार्यशील पूँजी और निवेश के बीच परंपरागत अंतर धुंधला हो गया है। इस प्रकार जुटायी गयी निधियों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा काफी अनुपात में अंशदान किया गया है, वित्तीय संस्थाओं ने कंपनी क्षेत्र द्वारा जारी किये गये विभिन्न लिखतों में सीधे ही अभिदान किया है। अन्वयार्थ मूद्रा बाजार में पूँजी बाजार के लिखतों के सक्रिय व्यापार में मूद्रा और पूँजी बाजार के बीच अंतर और भी कम हो गया है।

9.4 वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाये गये सहायता की तुलना में उनके ऋण तथा निवेश कार्यों का स्वरूप हाल के वर्षों में कुछ बदल हो गया है। सर्वप्रथम, उनके संसाधनों का मुख्य स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक की दीर्घावधि प्रवर्तन निधि के माध्यम से प्राप्त वित्तीय सहायता और अन्वयार्थ सीमाएं भी रही हैं (सारणी 9.3)। जून 1990 के अंत में सभी दीर्घावधि प्रवर्तन निधियों के अंतर्गत कुल बकाया राशि 8,592 करोड़ रुपये या कुल आरक्षित निधि का लगभग 11.0 प्रतिशत थी। इसके अलावा, अन्वयार्थ ऋण सुविधा के अंतर्गत नाबार्ड को बकाया राशि जून 1990 के अंत में 2,858 करोड़ रुपये थी। वाणिज्य और सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक के दबाव की राशि जून 1990 के अंत में 2,882 करोड़ रुपये थी। उपलब्ध प्रमाण से पता चलता है कि वित्तीय संस्थाओं का संसाधनों संबंधी अवगलन काफी बड़ा है जिसकी पूर्ति रिजर्व बैंक सहायता से की गयी। रिजर्व बैंक सहायता के अतिरिक्त वित्तीय संस्थाएं आम तौर पर बांडों और डिबेंचरों के माध्यम से आंतरिक सहायत जुटाती हैं जिनमें बैंकिंग तंत्र भी अभिदान करता है। बदले में वित्तीय संस्थाएं बैंकिंग तंत्र को पुनर्वित्त और पुनर्भुवाई सुविधाएं उपलब्ध करा कर बैंकिंग तंत्र के संसाधन बढ़ाती हैं। दिसम्बर 1989 के अंत में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और नाबार्ड ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को पुनर्वित्त और पुनर्भुवाई के रूप में 7,130 करोड़ रुपये (उनके अन्वयार्थ मूद्रा बाजार कार्य को छोड़कर) उपलब्ध कराये।

सारणी 9.1 : वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की वित्तीय आस्तरियाँ, 1981 और 1986 से 1989 तक, मार्च के अंत/अंतिम शुक्रवार की स्थिति

(करोड़ रुपये)

संस्था संवर्ग	1981	1986	1987	1988	1989
1	2	3	4	5	6
अ बैंक (1+2+3) <sup>1</sup>	46,987	108,372	127,876	147,186	176,461
1. सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक <sup>2</sup>	44,622	103,627	122,513	140,747	168,480
2 गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक <sup>3</sup>	9	23	30	36	53
3. कुल वाणिज्य बैंक (1+2)	44,631	103,650	122,543	140,783	168,533
3. राज्य सहकारी बैंक <sup>4</sup>	2,356	4,722	5,333	6,403	7,928
घा वित्तीय संस्थाएं	17,911	49,137	58,348	71,571	89,422
4. मीयादी ऋण देनेवाली संस्थाएं (अखिल भारतीय)	7,924	28,132	34,479	43,197	56,088

1	2	3	4	5	6
5 बीमा कंपनियाँ	8,254	16,665	18,579	22,134	26,130
कुल अखिल भारतीय संस्थाएँ	16,178	44,797	53,058	65,331	82,218
6. राज्य-स्तरीय संस्थाएँ	1,733	4,341	5,290	6,241	7,201
इ जोड़ (अ + आ)	64,898	157,509	186,224	218,757	265,883
ई प्रतिष्ठित ऋण					
(क) इ से अ का	72.4	68.8	68.7	67.3	66.4
(ख) इ से आ का	27.6	31.2	31.3	32.7	33.6

1 इसमें निम्नलिखित मदें शामिल हैं (i) ह्वाय से तकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा राशियाँ (ii) बैंकिंग तंत्र का आस्तिर्वा, (iii) निवेश, (iv) बैंक ऋण (कुल ऋण, तकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट तथा खर्चों और भुनाये गये ऋण) और बैंको से प्राप्त राशियाँ।

सारणी 9.2 विनीय संस्थाओं की कुल बकाया विनीय आस्तिर्वा

(करोड़ रुपये)

संस्था	1980-81	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5	6
अ अखिल भारतीय बीयादी वित्त देतेवाली संस्थाएँ					
1 नाबाई*	1635.1	6568.6	7415.4	8776.3	10363.8
2 भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	727.9	2210.6	2799.4	3652.8	4500.1
3. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	3098.6	9633.9	11529.6	13922.3	17087.8
4 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	589.1	1988.3	2426.7	3105.8	3707.3
5. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	92.4	342.3	430.2	505.6	589.9
6 भारतीय यूनित ट्रस्ट	520.6	3346.3	4927.3	7222.7	12323.6
7. आवास और शहरी विकास निगम	274.9	724.3	877.1	1036.6	1305.9
8. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	985.4	2055.1	2370.1	2869.1	3644.6
9. निर्यात-आयात बैंक	--	811.1	1042.2	1276.0	1478.4
10 आवास विकास वित्त निगम	--	451.2	631.4	829.4	1086.9
"अ" का जोड़ (1 से 10 तक)	7924.0	28131.7	34479.4	43196.6	56088.2
आ. राज्य स्तरीय संस्थाएँ					
11 राज्य विनीय निगम	1073.6	2696.7	3264.9	3910.9	4657.0
12 राज्य औद्योगिक विकास निगम	659.5	1643.9	2024.6	2329.6	2547.2
"आ" का जोड़ (11 से 12 तक)	1733.1	4340.6	5289.5	6240.5	7204.2
इ बीमा कंपनियाँ					
13. जीवन बीमा निगम	6814.9	12935.9	14225.2	17086.9	20118.0
14. साधारण बीमा निगम और सहयोगी संस्थाएँ	1198.9	2860.7	3323.0	3735.6	4418.8
15. विशेष बीमा प्रत्यय गारंटी निगम	200.3	781.6	919.1	1168.9	1377.5
16. निर्यात ऋण और गारंटी निगम	39.5	86.9	112.0	142.3	213.3
"इ" का जोड़ (13 से 16 तक)	8253.6	16665.1	18579.3	22133.7	26129.6
कुल जोड़ (अ + आ + इ)	17910.7	49137.4	58348.2	7157.8	89422.0

\* 1980-81 के आंकड़े इधर पुनर्बित्त और विकास निगम से संग्रहित हैं क्योंकि नाबाई की स्थापना 1982 में हुई थी।

2 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अंतर्गत विवरणियों के आधार पर।

3. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अंतर्गत विवरणियों के आधार पर।

नगरणी 9.3 वित्तीय सहायता को भारतीय रिज़र्व बैंक की सहायता, दीर्घकालिक प्रवर्तन निधि, लाभ का आवंटन और मध्यावधि/अल्पावधि ऋण

(बरोह रुपये)

	1985-86		1986-87		1987-88		1988-89		1989-90	
	वर्ष के लिए मजूर	जून के अंत में बकाया/सचयी लिए मजूर	वर्ष के लिए मजूर	जून के अंत में बकाया/सचयी लिए मजूर	वर्ष के लिए मजूर	जून के अंत में बकाया/सचयी लिए मजूर	वर्ष के लिए मजूर	जून के अंत में बकाया/सचयी लिए मजूर	वर्ष के लिए मजूर	जून के अंत में बकाया/सचयी लिए मजूर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>अ निम्नलिखित से दीर्घावधि सहायता</b>										
<b>I. राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालिक प्रवर्तन) निधि</b>										
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	300 0	2 589 9	330 0	2,875 3	360 0	3,198 6	375 0	3,528 3	375 0	3,822 0
2. निर्यात-आयात बैंक	80 0	260 0	85 0	345 0	90 0	435 0	95 0	530 0	95 0	625 0
3. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	10 0	10 0	15 0	25 0	20 0	15 0	25 0	70 0	25 0	95 0
<b>II. राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि/राष्ट्रीय आवास बैंक</b>										
	--	--	--	--	--	--	50 0	50 0	25 0	75 0
<b>आ निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के लाभ का आवंटन</b>										
<b>I. राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि/नाबाई</b>										
	300 0	2,005 0	350 0	2,055 0	300 0	2,655 0	330 0	2,985 5	330 0	3,315 0
<b>II. राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (मिश्रिकरण) निधि/नाबाई जोड़ (अ + आ)</b>										
	25 0	620 0	10 0	630 0	10 0	640 0	10 0	650 0	10 0	660 0
		5,484 9		6,230 3		6,973 6		7,813 3		8,592 0
<b>इ रिजर्व बैंक द्वारा मध्यावधि/अल्पावधि ऋण सहायता</b>										
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	200 0	125 6	300 0	82 5	300 0	24 5	300 0	42 4	400 0	67 6
2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	15 0		15 0		15 0		30 0		40 0	
3. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	15 0		20		25 0		25 0		30 0	
4. राज्य वित्त निगम	38 0		55 2		65 4		82 9		88 0	
<b>ई सामान्य ऋण सुविधा-नाबाई जोड़ (इ + ई)</b>										
	1,300 0	860 9	1,400 0	949 7	1,950 9	1,416 8	2,700 0	2,277 7	3,350 0	2,858 4
		986 5		1,032 2		1,441 3		2,320 1		2,926 0
<b>बकाया/सचयी सहायता का कुल जोड़ (अ + आ + इ + ई)</b>										
		6,471 4		7,262 5		8,414 9		10,133 4		11,518 0

9.5 अन्ततः वित्तीय संस्थाओं द्वारा निजी कंपनी क्षेत्र के विभिन्न प्राथमिक निर्गमों का हांगीदारों और उनमें प्रत्यक्ष अधिभोग द्वारा एवं ऋणों के ईक्विटी में परिवर्तन द्वारा काफी शेषरधारी प्राप्त किये जाने के कारण वे पूँजी बाजार को अधिक प्रभावित करने लगे हैं। जून 1986 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता प्राप्त 575 कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों के स्वामित्व के स्वरूप के अध्ययन से पता चलता है कि कंपनी ईक्विटी में वित्तीय कंपनियों की धारिता कुल ईक्विटी का 22.5 प्रतिशत थी, अधिमान शेयरों में 71 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी तथा डिबेंचरों में 58 प्रतिशत थी। वे गौण बाजार में भी सक्रिय और मुख्य भूमिका निभाने लगी हैं, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम जैसी संस्थाएं अब सबसे बड़ी निवेशकर्ता हैं।

1989-90 के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रवृत्त सहायता

9.6 अन्तिम आंकड़ों के अनुसार 1989-90 (अप्रैल-मार्च) के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम तथा उसकी सहायक संस्थाएं) द्वारा मंजूर सहायता की कुल राशि 15,572.4 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष की उक्त राशि (13,759.8 करोड़ रुपये) की तुलना में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इन संस्थाओं द्वारा 1989-90 के दौरान वितरणों की कुल राशि 9,341.0 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष की उक्त राशि (8,485.8 करोड़ रुपये) की तुलना में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इसकी तुलना में 1988-89 के दौरान इन संस्थाओं की मंजूर राशियों और वितरण राशियों में 1987-88 की अपेक्षा क्रमशः 56.5 प्रतिशत और 34.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 1989-90 में वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर और वितरित सहायता की वृद्धि दरों में गिरावट का आंशिक कारण कंपनी क्षेत्र की पूँजी बाजार पर बढ़ती हुई निर्भरता है।

#### कम्पनी निवेश

9.7 भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दूसरे अध्ययन में अनुमान लगाया है कि 1989 के दौरान कुल 10,907 करोड़ रुपये का पूँजीगत व्यय हुआ होगा जो 1988 में अनुमानित पूँजीगत व्यय से 44.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस अध्ययन निजी कंपनी कारबार क्षेत्र में निवेश के पूर्वानुमान लगाये गये हैं और वे सीमादी ऋण देनेवाली तीन संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा 1989 के अंत तक मंजूर की गयी परियोजनाओं के पूँजीगत व्यय के चरणबद्ध अनुमान पर आधारित है। इसमें बिल पुनर्मुद्राई योजना और तकनीकी विकास निधि योजना के अंतर्गत ऐसा व्यय भी शामिल है। 1989 तक निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए मंजूरीया दी गयी थी उनके संबंध में 1990 के लिए ऐसे ही पूर्वानुमान से पता चलता है कि 14,000 करोड़ रुपये का पूँजीगत व्यय होगा जो 1989 के तदनुसंग अनुमान की तुलना में 29 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अनुमानतः 4,022 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 222 नवी परियोजनाओं थी जो 1989 में मंजूर सभी परियोजनाओं की कुल लागत का 32.4 प्रतिशत थी। उद्योग और देखा जाय तो 1990 के दौरान किये जाने वाले कुल पूँजीगत व्यय में "घातु और धातु के उत्पाद" की 109 परियोजनाओं का 26.9 प्रतिशत का सबसे बड़ा अंश होगा। यद्यपि "ज्योत्सोम" (जूट से मिश्र) परियोजना प्रस्तावों (193) में सबसे अधिक था, परन्तु सभी परियोजनाओं की कुल लागत में इसका अंश केवल 15.0 प्रतिशत था।

#### भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

9.8 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1990 के अर्वात मान्य आयोगिक विकास बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी संस्था के रूप में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गयी थी। लघु उद्योगों के सर्वजनिक वित्तपोषण और विकास के लिए मुख्य दिशानिर्देश संस्था के रूप में उपयुक्त बैंक की स्थापना की गयी है। यह बैंक, इसी प्रकार के कार्य में संलग्न विद्यमान संस्थाओं के कार्यकलाप में तालमेल भी करेगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने 2 अप्रैल 1990 में अपना कार्य शुरू कर दिया है तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से लघु उद्योग विकास निधि तथा राष्ट्रीय ईक्विटी निधि का संचालन उत्तरदायित्व ले लिया है।

#### पूँजी बाजार

9.9 सार्वजनिक योजना के दौरान गैर-सरकारी सार्वजनिक सीमित कंपनियों द्वारा कुल 15,591 करोड़ रुपये (बिलियन रुपये पर) के पूँजी निर्गम किये गये जिनमें से 5,230 करोड़ रुपये को ईक्विटी पूँजी का अंश लगाया एक तिहाई था। इसके अलावा, योजना अधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कुल 10,847 करोड़ रुपये के डिबेंचर/बांड जारी किये। इसके अतिरिक्त, छोटी योजना के दौरान लगभग 3,500 करोड़ रुपये के कुल पूँजी निर्गम किये गये थे। प्राथमिक पूँजी बाजार का सुदृढ़ बनने के अलावा गौण बाजार में कुल कारबार तथा बाजार मूल्यवृद्धि के संदर्भ में काफी वृद्धि हुई। साधारण शेयर सूचकां के भारतीय रिजर्व बैंक के अखिल भारतीय सूचकांक (आधार 1980-81-100) में सार्वजनिक योजना के दौरान अर्वात 24 प्रतिशत वृद्धि की दर से वृद्धि हुई जबकि उद्योग योजना में उक्त वृद्धि लगभग 9 प्रतिशत की थी।

9.10 औद्योगिक उत्पादन की शक्ति धारिता हाव के बावजूद 1989-90 के दौरान पूँजी बाजार में पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक तेजी आयी। प्राथमिक और गौण बाजार की गतिविधि में काफी तेजी परिलक्षित हुई। इस तेजी का कारण था बड़े खनिज शक्ति का मंजूर किये गये औद्योगिक राजस्वों, पूँजीगत माल के आयात के लिए अनुमोदित राशियां तथा विदेशी सहयोग के लिए अनुमति जैसे निवेश के अभिप्राय के सबेरी से प्रकट हुआ।

#### नये निर्गम बाजार

9.11 1989-90 के दौरान गैर-सरकारी सार्वजनिक सीमित कंपनियों के नवीन पूँजी निर्गम 6,341 करोड़ रुपये (404 निर्गमों के माध्यम से) के बिकारें स्वरूप पर पड़ चुके थे, यह राशि पिछले वर्ष के 3,164 करोड़ रुपये (141 निर्गमों के पूँजी निर्गमों से लगभग दुगुनी है (सारणी 9.4)। पिछले वर्ष के लगभग ही पूँजी निर्गमों का राशि में अधिकांश वृद्धि डिबेंचरों, मुख्यतः परिवर्तनीय डिबेंचरों, के कारण हुई। 1989-90 के दौरान कुछ बड़े परिवर्तनीय डिबेंचर निर्गमों की प्रधानता प्राथमिक बाजार का एक उल्लेखनीय पहलू थी। 10 कंपनियों द्वारा 15 बड़े डिबेंचर निर्गम (जिनमें से प्रत्येक 100 करोड़ रुपये से अधिक का था) किये गये जिनकी कुल राशि 3,805 करोड़ रुपये के बिकारें और मुख्यतः सार्वजनिक सीमित कंपनियों ने 5,143 करोड़ रुपये (सारणी 9.3) के कुल डिबेंचर जारी किये थे। इन बड़े निर्गमों में से 12 निर्गम जिसका अंश 32 प्रतिशत (या 3,106 करोड़ रुपये) था, केवल पांच कंपनियों ने प्रस्तुत किये थे प्रत्येक कंपनी ने 500 करोड़ रुपये से अधिक के डिबेंचर जारी किये थे, 1988-89 के दौरान इस प्रकार का केवल एक निर्गम था।

सारणी 9.4 गैर सरकारी सार्वजनिक साक्षि कर्मियों द्वारा पूजा निर्गम  
( करोड़ रुपये )

निर्गम का प्रकार	1988-89 (a) ( अप्रैल-मार्च )		1989-90 (a) ( अप्रैल-मार्च )	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	3	4	5	6
1 ईक्विटी शेयर *	256 (47)	1,028 (109)	267 (57)	1,193 (201)
2 अधिमान शक्ति	0	0	4	8
3 डिबेंचर	79	2,135	133	5,143
(i) परिवर्तनीय	48	1,743	107	4,659
(ii) अपरिवर्तनीय	31	390	26	484
4 जोड़ 1 + 2 + 3	311	3,164	404	6,444

(a) अन्तिम

\* बोनस निर्गमों को छोड़कर

टिप्पणियाँ

- (1) काष्ठकों में दिये गये आकड़े प्रामिथ्य की राशि दर्शाते हैं जो ईक्विटी निर्गमों की राशि में शामिल हैं।
- (2) आकड़ों में दिये गये सरणाओं का हिस्सा निजी रूप में दिये गये निर्गम शामिल नहीं है।
- (3) जहाँ विशिष्ट जानकारी उपलब्ध था वहाँ आकड़ों में प्रति-घातित अल्पमिशन का राशि शामिल का गया है। किन्तु, अन्य अल्पमिशन का राशि शामिल नहीं की गया है क्योंकि जानकारी उपलब्ध नहीं था।

9.12 ईक्विटी निर्गमों की संख्या और राशि में भी काफी वृद्धि हुई। ईक्विटी शेयरों के निर्गम 1988-89 के 1,028 करोड़ रुपये से 1989-90 के 1,193 करोड़ रुपये हो गये।

9.13 अन्तिम आकड़ों के अनुसार 1989-90 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कुल 3,465 करोड़ रुपये के बांड जारी किये जिनमें से 100 करोड़ रुपये जनता के अधिदान के लिए तथा शेयर 3,365 करोड़ रुपये का बांड निजी तौर के लिए थे।

9.14 1989-90 के दौरान नियंत्रक, पूजा निर्गम द्वारा सरकारी और गैर-सरकारी कर्मियों दोनों को मंजूर/अनुमोदित राशि (अर्थात्, बोनस शेयरों को छोड़कर प्रामिथ्य सहित सहमत राशि/स्वीकृति राशि) 11,705 करोड़ रुपये (719 निर्गमों के माध्यम से) के तथे सर्वोच्च स्तर पर थी जो पिछले वर्ष 641 निर्गमों का 8,072 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में 45.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है (सारणी 9.5)। 1989-90 के दौरान नियंत्रक, पूजा निर्गम द्वारा गैर-सरकारी कर्मियों को प्रदान कुल अनुमादनों की 7,555 करोड़ रुपये की राशि पिछले वर्ष की राशि (4,932 करोड़ रुपये) की अपेक्षा 83.8 प्रतिशत अधिक थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांड निर्गमों के लिए (सारणी 9.4) सन्मत्त राशि 1988-89 के 3,190 करोड़ रुपये से काफी बढ़कर 1989-90 में 4,074 करोड़ रुपये

जनता का अधिदान

9.15 शेयर बाजारों से उपलब्ध अन्तिम आकड़ों के आधार पर सार्वजनिक निर्गमों के कार्य-निष्पादन संबंधी विशेषण से यह पता चलता है कि 1989-90 के दौरान सार्वजनिक निर्गमों में समग्र अधिदान बेहतर हुआ, 1989-90 के दौरान प्रचुरता निर्गमों में से लगभग 95 प्रतिशत में अल्पमिशन हुआ जबकि 1988-89 में लगभग 87 प्रतिशत के मामले में अल्पमिशन हुआ था। कई गुना अधिदान वाले निर्गमों की संख्या, जैसे-10 बार अल्पमिशन वाले, 1988-89 की अपेक्षा 1989-90 में अधिक थी।

सारणी 9.5 सरकारी और गैर सरकारी कर्मियों को पूजा जुटाने के लिए नियंत्रक पूजा निर्गम द्वारा प्रदान सहमत राशि/अल्पमिशन राशि

( करोड़ रुपये )

क्रम निर्गम का प्रकार स.	1988-89 ( अप्रैल-मार्च )		1989-90 ( अप्रैल-मार्च )	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
	1	2	3	4
1 शेयर उन्मेष में			484	1,487
(i) प्रारम्भिक निर्गम			145	862
(ii) बाद के निर्गम*			339	625
2 डिबेंचर और बांड			157	6,585
(i) परिवर्तनीय			74	3,134
(ii) अपरिवर्तनीय			83	3,451
3 उप-जोड़ (1+2)			641	8,072
4 बोनस शेयर			267	196
5 कुल जोड़ (3+4)			908	8,268
			1,038	12,079

\* इसमें 1989-89 में 77 निर्गमों के प्रामिथ्य की 112 करोड़ रुपये की राशि और 1988-90 में 77 निर्गमों की 213 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

स्त्रोत : नियंत्रक, पूजा निर्गम।

नौता विषयक पहल

9.16 हाल के वर्षों में पूजा बाजार में भारी वृद्धि के साथ-साथ कुछ मुद्दे और समस्याएँ भी उत्पन्न हो गयीं, जिन्हें ठीक करना पड़ा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तथे निर्गम और शेयर बाजार व्यवस्थित ढंग से कार्य करें तथा निवेशकर्ताओं का विश्वास बना रहे। इन हेतु, आलोच्य वर्ष के दौरान बहुत से नौता संबंधी उपाय किये गये जो नीचे दिये गये हैं।

9.17 नवंबर 1989 में, नियंत्रक, पूजा निर्गम ने 300 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमादित पूजा निर्गमों के अधोल कर्मियों द्वारा घन जुटाने के बारे में मानदंड निर्धारित किये तथा ऐसी कर्मियों से यह अपेक्षा की कि वे क्रमशः पूजा जुटाने तक बड़े पूजा निर्गम इसके साथ ही कम हों। केन्द्रीय सरकार ने वित्तिय संस्थानों से भी कहा कि ऐसे बड़े निर्गमों के माध्यम से जुटाये गये राशि के उपयोग पर वे दूरी निगरानी रखें। जनवरी 1990 में नियंत्रक, पूजा निर्गम ने कुछ और मानक नौता निर्धारित की जो 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक के सभी सार्वजनिक निर्गमों पर लागू होगी। यह शर्त रखी गयी कि सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से जुटायी गयी

निधियों प्रस्तावित कार्यों में लगाये जाने से पहले केवल संस्थाओं तथा राष्ट्रीयकृत और महतारी बैंकों, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, वित्तीय संस्थाओं एवं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिखतों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से भिन्न) में लगायी जा सकती हैं। निर्णयों से प्राप्त राशि को उपयोग पर मामित वित्तीय संस्थाएं निगरानी रखेंगी। जनवरी 1990 में केन्द्रीय सरकार ने नियंत्रक, पूंजी निर्गम को यह भी निदेश दिया कि वे किसी कंपनी को उसका पिछला निर्गम बंद होने के 12 महीने या उसके पिछले निर्गमों के शेयरों अथवा डिबेंचरों के सूचीकरण के छह महीने (इनमें से जो भी बाद में हो) के भीतर कोई नया निर्गम जारी करने की अनुमति न दें। बाद में, सरकार ने यह भी निश्चय किया कि पूंजी निर्गम के लिए नियंत्रक, पूंजी निर्गम को किये जाने वाले सभी आवेदन-पत्रों के साथ कंपनी सचिव के हस्ताक्षर का प्रमाणपत्र होना चाहिए, जिसमें इस बात की पुष्टि की गयी हो कि पिछले निर्गमों के संदर्भ में धन वापसों के सभी आदेश एवं सभी शेयर/डिबेंचर प्रमाणपत्र जारी कर दिये गये हैं।

9.18 जुलाई 1989 में केन्द्रीय सरकार ने विद्यमान कर्मचारी स्टाफ विकास योजना में संशोधन किया है जिसके अनुसार कर्मचारियों के लिए भ्रमण रखे गये शेयरों का जो भ्रमण कर्मचारियों ने नहीं लिया है वह वित्तीय या निवेश संस्थाओं और पारस्परिक निधियों को आबंटित किया जा सकता है। अगस्त 1989 में सरकार ने विभिन्न इक्विटी समर्पित योजनाओं के अधीन निवेश के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को उदार बनाया जिससे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय प्रस्ताव के जरिये जनता को इन योजनाओं के अधीन शेयरों का विनिवेश करने का अधिकार मिला।

9.19 केन्द्रीय सरकार ने अगस्त 1989 में प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम के अधीन प्रोवर-वि-काउंटर एक्सचेंज आफ इंडिया की स्थापना का अनुमोदन किया जिससे प्रतिभूतियों के लिए बहु-स्तरीय बाजार की शुरुआत करने में सहायता मिलेगी। जनवरी 1990 में सरकार ने बोनस निर्गमों के लिए पिछली मंजूरी और नये आवेदन के बीच न्यूनतम अवधि को 24 महीने से घटाकर 12 महीने कर दिया। निबंधकर्ताओं में विश्वास उत्पन्न करने के लिए जनवरी 1990 में निवेशकर्ताओं को यह अनुमति दी गई कि उन्हें डिबेंचरों को इक्विटी में परिवर्तित करने का विकल्प भी है, निवेशकर्ताओं को इस विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए काफी समय भी दिया गया था।

9.20 आलोच्य वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने भी पूंजी बाजार को प्रभावित करने वाले कतिपय नीतिगत उपाय किये। रिजर्व बैंक ने जुलाई, 1989 में बैंकों और उनकी सहयोगी संस्थाओं के म्यूचुअल फंड संबंधी कार्यों के बारे में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये। अक्टूबर 1989 में रिजर्व बैंकों ने सभी बैंकों को यह निवेश दिया कि वे शेयर/डिबेंचर जारी करने वाली कंपनियों द्वारा प्राप्त आवेदन धन तब तक जारी न करें जब तक शेयरों/डिबेंचरों का आबंटन नहीं किया जाता। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और उनकी सहयोगी संस्थाओं को यह भी निदेश दिया कि वे शेयरों और डिबेंचरों के सार्वजनिक निर्गम के लिए सुरक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध न करावें। नवम्बर 1989 में रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों तथा उनकी सहयोगी संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सार्वजनिक निर्गमों की हमीदारी, पुनः न्य सुविधा प्रदान करने तथा उचित व्यवस्था करने के एकल दायित्व के अधीन दायदे की राशि निर्गम राशि के 15 प्रतिशत से अधिक न हों। जनवरी, 1990 में रिजर्व बैंक ने नयी प्रवर्तित कंपनी में प्रवर्तकों के इक्विटी शेयरों के कोटे का कुछ हिस्सा लेते समय पुनः न्य करने से म्यूचुअल फंडों पर प्रतिबंध लगा दिया।

9.21 अप्रैल, 1990 में भारत सरकार ने कंपनियों द्वारा शेयर और डिबेंचर निर्गमों के लिए नवीन मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये ताकि अभिदान-कर्ताओं को और अधिक सुनिश्चित की जा सके। इनमें एक यह शर्त भी शामिल थी कि आबंटन सभी किया जा सकता है जब निर्गम की राशि के 90 प्रतिशत का अभिदान हो चुका हो।

9.22 मई 1990 में भारत सरकार ने वित्तीय संस्थाओं द्वारा शेयरों के लेनदेन को अधिक स्पष्ट बनाने की दृष्टि से मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा औद्योगिक ऋण और निवेश निगम जैसी अखिल भारतीय सार्वजनिक वित्तीय और निवेश संस्थाओं पर लागू होते हैं। अन्य बातों के साथ साथ यह भी निश्चित किया गया है कि किसी कंपनी के चुकता शेयरों या डिबेंचरों के एक प्रतिशत से अधिक कोई भी वित्तीय जनता को सूचित करनी होगी।

9.23 जून 1990 में, भारत सरकार ने सार्वजनिक निर्गमों की लागत के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन किये ताकि कंपनियों व्यापारी बैंकों को उचित भुगतान कर सकें। निर्गम के प्रबंधकर्ताओं को देय शुल्क पर 0.5 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत की सीमा क्रमशः 25 करोड़ रुपये तक (5 करोड़ रुपये के स्थान पर) तथा 25 करोड़ रुपये से अधिक (5 करोड़ रुपये से अधिक के निर्गमों के स्थान पर) के निर्गमों पर लागू होगी।

### भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड

9.24 भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड का व्यापारिक बैंकिंग कार्यों तथा म्यूचुअल फंडों के कार्यों के पर्यवेक्षण का कार्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा शेयरों की वित्तीय और शेयर बाजारों से शेयरों के अभिग्रहण द्वारा कंपनियों का प्रबंध अपने हाथ में लेने से संबंधित लेन देन की स्पष्टता सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा है। व्यापारिक बैंकों के लिए सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार व्यापारिक बैंकिंग का कारबार करने के इच्छुक किसी व्यक्ति या निकाय को भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड का प्राधिकार प्राप्त करना होगा। अखिल भारतीय सार्वजनिक वित्तीय और निवेश संस्थाओं (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और उसकी सहयोगी संस्थाएं) द्वारा शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और अधिमान शेयरों के लेनदेन अधिक बुले तथा स्पष्ट बनाने के लिए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि किसी कंपनी की चुकता पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक की कोई भी वित्तीय और उसके परिणामस्वरूप होने वाले लेनदेन एवं मुख्य की सूचना लेनदेन के लिए एक दिन के भीतर संबंधित संस्था को प्रेस प्रकाशनों के माध्यम से जनता को देनी होगी। इन लेनदेनों से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड तथा संबंधित शेयर बाजारों को भी देनी होगी। सरकार ने अभिग्रहण प्रस्ताव के संबंध में सूचीकरण करार के खंड 40 आ को संशोधित किया है।

9.25 सरकार ने म्यूचुअल फंडों के लिए भी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की घोषणा की है जिसके अनुसार किसी संविधि द्वारा स्थापित म्यूचुअल फंडों के सिवाय सभी म्यूचुअल फंडों को नियंत्रक, पूंजी निर्गम तथा भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। वर्तमान म्यूचुअल फंडों को भी स्वयं को भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड के पास पंजीकृत कराना होगा। म्यूचुअल फंडों का खेला-जोखा तथा प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं का निर्धारण भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड करेगा।

### भारतीय ऋण निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड

9.26 भारतीय ऋण निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड ने जनवरी, 1988 में अपना कार्य शुरू किया। इसने 1989-90 (अप्रैल-मार्च) के दौरान 49 कंपनियों (25 विनिर्माण कंपनियों और 24 वित्त कंपनियों) द्वारा जारी किये गये 2,098.4 करोड़ रुपये मूल्य के 71 ऋण सिखतों (अर्थात् डिबेंचर, सावधि जमा कार्यक्रम) और वाणिज्यिक पत्र कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जबकि पिछले वर्ष 22 कंपनियों (11 विनिर्माण कंपनियों तथा 11 वित्त कंपनियों द्वारा जारी) किये गये 906.2 करोड़ रुपये मूल्य के 26 ऋण सिखतों का मूल्यांकन किया था। लिखतवार भ्रमण अभ्रम



झीरों से पता चलता है कि 681.1 करोड़ रुपये के डिबेंचरों तथा 1,189.5 करोड़ रुपये की सावधि जमा कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया गया जबकि 1988-89 में यह राशि 142.9 करोड़ रुपये (डिबेंचर) तथा 763.3 करोड़ रुपये (सावधि जमा कार्यक्रम) थी। वाणिज्यिक पत्र

कार्यक्रम के मूल्यांकन की शुरुआत 1989-90 में की गई तथा इसका कुल मूल्य 227.8 करोड़ रुपये था। 31 मार्च, 1990 तक जिन ऋण लिखतों का मूल्यांकन किया गया। उनकी कुल संख्या और मूल्य क्रमशः 101 और 3,093.4 करोड़ रुपये था।

सारणी 9.6 : भारतीय रिज़र्व बैंक - साधारण शेयर मूल्यों का औसत भारतीय सूचकांक

(आधार : 1980-81=100)

माह/वर्ष	औसत	अधिकतम*	न्यूनतम*	माह का प्रतिशत सप्ताह/मंथ
1988-89 (अप्रैल-मार्च)	247.5 (+19.4)@	303.2	187.1	308.2
1989-90 (अप्रैल-मार्च)	359.4 (+45.2)@	411.4	317.7	403.6
अप्रैल 1989	335.7	355.7	317.7	355.7
मई	342.9	348.6	338.6	338.6
जून	340.5	347.5	332.7	347.5
जुलाई	350.8	356.9	343.7	343.7
अगस्त	336.5	339.4	333.9	334.6
सितम्बर	350.0	353.6	343.9	353.6
अक्टूबर	358.4	363.4	355.0	363.4
नवम्बर	362.8	366.6	359.7	361.8
दिसम्बर	383.7	396.3	359.9	396.3
जनवरी 1990	400.6	411.4	387.1	387.1
फरवरी 1990	372.5	377.8	368.0	372.6
मार्च 1990	378.1	400.0	367.1	400.0
1990-91				
अप्रैल	399.9	410.6	397.7	404.3
मई	409.4	414.3	405.2	414.3
जून +	414.8	420.6	410.0	412.8

पाँच वर्ष की अवधि का  
अंतर (1985-86 से  
1989-90)

स्थापन वर्ष	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1989-90)
अ. घट-बढ़ का गुणांक (प्रतिशत में)*	12.52	3.65	4.82	16.36	6.10	8.69
घा. विस्तार (सीमा)*	57.0	38.3	40.0	121.1	93.7	70.02

\* साप्ताहिक सूचकांकों पर आधारित।

@ पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाता है।

+ अंशतः

भारतीय स्टॉक धारिता निगम लिमिटेड

9.27 अगस्त, 1988 में निवेशपागर संस्था के रूप में भारतीय स्टॉक धारिता निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी जिसे 1989-90 (अप्रैल-मार्च) के दौरान 349 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों के त्रय और विनियम के संबंध में सुपुर्दगी के आवेदन प्राप्त हुए जबकि पिछले वर्ष यह राशि 110 करोड़ रुपये थी। यह निगम अपने आरंभ से लेकर भारतीय मुनिट ट्रस्ट का कार्य कर रहा है। आलोच्य वर्ष के दौरान न्यू इंडिया इन्श्योरन्स कंपनी लिमिटेड, जीवन बीमा निगम म्यूचुअल फंड और भारतीय साधारण बीमा निगम को भी सेवाएं उपलब्ध करायी गईं।

9.28 भारतीय स्टॉक धारिता निगम लिमिटेड ने मुख्य शेयर बाजारों तथा देश के पूंजी बाजार के विकास से जुड़ी अन्य एजेंसियों के साथ परामर्श करके मसौदा विधान के रूप में अर्थात् स्टॉक धारिता और विशेष अंतरण कार्यविधि अधिनियम, भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य केन्द्रीय प्रतिभूति निवेशपागर के माध्यम से शेयरों के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण की शुरुआत के लिए उचित कानूनी व्यवस्था करना है।

## ईक्विटी मूल्य

9.29 विन्डुवार आधार पर, रिजर्व बैंक के साधारण गेयर मूल्यों के अखिल भारतीय साप्ताहिक सूचकांक (आधार 1980-81=100) में वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान 25.9 प्रतिशत का जो वृद्धि हुई वह 1 अप्रैल 1989 का समाप्त मर्यादा के 317.7 से बढ़कर 31 मार्च, 1990 को समाप्त मर्यादा में 400.0 हो गई। यह वृद्धि पिछले वर्ष हुई 62.8 प्रतिशत की वृद्धि के अनुरिक्त था। रिजर्व बैंक के साधारण गेयर मूल्यों के अखिल भारतीय साप्ताहिक सूचकांक अस्तित्व वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान 359.1 हो गया था पिछले वर्ष 247.5 के औसत सूचकांक में 111.9 अंक (या 45.2 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है (सारणी 9.6), पिछले दो वर्ष के दौरान गौण बाजार में भी गेयरों के लेनदेन में काफी वृद्धि हुई है। बम्बई गेयर बाजार में औसत मासिक वार्षिक 1987 के 743.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 1988 में 1,439.5 करोड़ रुपये हो गया अथवा उसमें 93.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, 1989 में वह और बढ़कर 2,336.0 करोड़ रुपये हो गया अथवा उसमें 62.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

9.30 पिछले वर्ष की अपेक्षा 1989-90 के दौरान ईक्विटी मूल्यों में बहुत कम घट-बढ़ हुई। आलोच्य वर्ष के दौरान 6.10 प्रतिशत के घट-बढ़ के बहुत कम गुणों से इसका पता चलता है, पिछले वर्ष यह अनुपात 16.36 प्रतिशत था। इसी प्रकार 1989-90 के दौरान साधारण मूल्य सूचकांक में 92.9 अंक का विस्तार (अथवा सीमा) 1988-89 के 121.1 अंक (निम्न सूचकांक स्तरों पर उपलब्ध) की तुलना में न्यून था।

9.31 वित्तीय वर्ष 1989-90 में ईक्विटी पर औसत सकल प्राप्ति 3.20 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष के 3.76 प्रतिशत की तुलना में कम है।

## 10. बाह्य क्षेत्र की गतिविधियाँ

## भुगतान संतुलन

10.1 निर्यातों में तीव्र वृद्धि के बावजूद 1989-90 के दौरान भुगतान संतुलन पर वनावट बना रहा। इसका कारण आयात विल में वृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को विस्तारित निधि सुविधा के अग्रान भारी चुकीती है। आयातों में वृद्धि का प्राणिक कारण पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों के आयात में वृद्धि, अस्तित्व विमानों का क्रय तथा कतिपय पण्यों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि है। यद्यपि वर्ष 1989-90 के लिए भुगतान संतुलन के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी उपलब्ध जानकारी के अनुसार रुपये की दृष्टि से चालू खाता घाटा 1988-89 में 10,420 करोड़ रुपये के घाटे से थोड़ा कम होने का अनुमान है। किन्तु विशेष आह्वरण अधिकार की दृष्टि से चालू खाता पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत कम होगा। सकल देशी उत्पाद में चालू खाता घाटे का अनुपात (वर्तमान बाजार मूल्यों पर) 1987-88 के 1.9 प्रतिशत से काफी बढ़कर 1988-89 में 2.7 प्रतिशत हो गया था, किन्तु 1989-90 में कम होकर उसके 2.3 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। इस प्रकार, सातवी योजना अवधि के दौरान चालू खाता घाटा अंशतः 2.2% होगा जबकि योजना आयोग ने योजना अवधि के दौरान 1.6 प्रतिशत का अनुमान लगाया था और यह छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1.3 प्रतिशत के औसत से काफी अधिक है, सारणी 10.1 में छठी योजना अवधि तथा 1985-86 से लेकर 1988-89 तक के लिए, सकल देशी उत्पाद में चालू खाते में भारत के भुगतान संतुलन के प्रतिशत अंश के आंकड़े दिये गये हैं।

10.2 भारी व्यापार घाटे तथा अदृश्य लेनदेन खाते के अधिशेष में गिरावट एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से विस्तारित निधि सुविधा के अग्रान भारी पुनः क्रय (सातवी योजना अवधि में इसकी राशि 2,752 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार थी) के कारण पूरी सातवी योजना अवधि के दौरान भुगतान संतुलन की स्थिति पर दबाव बना रहा है। सातवी योजना के पहले चार वर्षों में, जिसके मध्य में भुगतान संतुलन के आंकड़े उपलब्ध हैं, चालू खाता घाटा औसतन 7,120 करोड़ रुपये (4,363 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार) वार्षिक रहा जबकि छठी योजना अवधि में 2,277 करोड़ रुपये (2,100 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार) का वार्षिक औसत था (सारणी 10.2)।

10.3 सारणी 10.3 में 1985-86 से 1988-89 तक की अवधि के लिए भारत का भुगतान संतुलन संक्षेप में दिया गया है।

## आरक्षित विदेशी मुद्रानिधियाँ

10.4 राजकोषीय वर्ष 1980-90 के दौरान भारत की आरक्षित विदेशी मुद्रा निधियाँ 788 करोड़ रुपये गिरकर 6,251 करोड़ रुपये रह गयीं जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा अस्तित्वों, स्वर्ण और विशेष आह्वरण अधिकार प्राप्त राशियाँ सम्मिलित हैं जबकि 1988-89 के दौरान उनमें 647 करोड़ रुपये की गिरावट आयी थी (सारणी 10.4)। विशेष आह्वरण अधिकार की दृष्टि से मार्च, 1990 के अंत में ये आरक्षित निधियाँ 3,045 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार\* थीं जो 1989-90 के दौरान 670 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार की गिरावट दर्शाती हैं जबकि 1988-89 में 771 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार की गिरावट आयी थी। इस प्रकार सातवी योजना अवधि के दौरान विशेष आह्वरण अधिकार की दृष्टि से आरक्षित विदेशी मुद्रा निधियों में 2,959 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार की गिरावट आयी। यदि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चुकीती राशियाँ छोड़ दी जाएँ तो आरक्षित निधियों में 333 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार की वृद्धि परिलक्षित होती है जबकि छठी योजना अवधि के दौरान उसमें 4,375 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार की गिरावट आयी थी (इसमें 4,496 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अणुओं के आह्वरण शामिल नहीं हैं) (सारणी 10.5) अप्रैल से जून 1990 तक की तिमाही में आरक्षित विदेशी मुद्रा निधियों में 408 करोड़ रुपये की गिरावट आयी जबकि 1989 को वदनुष्य तिमाही में 478 करोड़ रुपये की गिरावट आयी थी। विशेष आह्वरण अधिकार की दृष्टि से अप्रैल से जून 1990 तक आरक्षित निधियों में 261 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार की गिरावट आयी थी जो अप्रैल से जून 1989 तक की तिमाही में आयी 307 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार की गिरावट से कम है।

सारणी 10.1: सकल विदेशी उत्पाद (वर्तमान बाजार मूल्यों पर) में चालू खाता लेनदेनों का अनुपात

(प्रतिशत में)

	1980-85 की अवधि का वार्षिक औसत	1985- 86	1986- 87	1987- 88	1988-89 (संकेत अनुमान)
	1	2	3	4	5
1. निर्यात		5.0	4.4	4.5	5.0
2. आयात		8.4	8.1	7.7	7.8
3. व्यापार घाटा		3.4	3.7	3.2	2.8
4. अदृश्य प्रारितियाँ (आधिकारिक अनुदान सहा- यता सहित)		3.6	3.0	2.8	2.8
5. अदृश्य भुगतान		1.5	1.6	1.6	1.9
6. अदृश्य राशियाँ (निवल) (4-5)		2.1	1.4	1.2	0.9
7. चालू खाता घाटा @ (3-6)		1.3	2.3	2.0	1.9

\*अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्राष्ट्रीय वित्त साठिका के समान है। स्वर्ण का मूल्य निर्धारण विशेष आह्वरण अधिकार 35 प्रति औंस के हिसाब से किया गया है।

@यहाँ आधिकारिक अनुदान को चालू प्रारितियों के रूप में माना गया है, सारणी 2.2 में उन्हें विदेशी सहायता की निवल प्राप्ति के अन्तर्गत प्रारित किया गया है।

## सारणी 10.2: बालू खाता घाटा

वर्ष	रुपये में (करोड़)	विशेष आहरण अधिकार में (मिलियन)	अंतरिकी आवर में (मिलियन)
1	2	3	4
1985-86	-5,927	-4,587	-4,844
1986-87	-5,830	-3,774	-4,562
1987-88	-6,293	-3,675	-4,854
1988-89	-10,429	-5,411	-7,202
अवधि औसत			
1985-86 से 1988-89 तक	-7,120	-4,363	-5,429
1980-81 से 1984-85 तक	-2,277	-2,100	-2,334

अ- अंतरिम  
अनुमान

10.5 राजकोषीय वर्ष 1989-90 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भुक्तियों की राशि 1,688 करोड़ रुपये थी (विस्तारित निधि मुद्रिया के अंतर्गत 1,460 करोड़ रुपये और ग्याम निधि ऋण के अंतर्गत 228 करोड़ रुपये) जबकि राजकोषीय वर्ष 1988-89 में यह राशि 1,710 करोड़ रुपये (विस्तारित निधि मुद्रिया के अंतर्गत 1,547 करोड़ रुपये और ग्याम निधि ऋण के अंतर्गत 202 करोड़ रुपये) थी। सावधानीपूर्वक अवधि के दौरान विस्तारित निधि मुद्रिया के अंतर्गत, 3,900 मिलियन विशेष आहरण अधिकार के आहरणों में से 2,752 मिलियन विशेष आहरण अधिकार की चुकौती की गई। मार्च 1990 के अंत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को विस्तारित निधि मुद्रिया तथा ग्याम निधि के अंतर्गत देय बकाया ऋण क्रमशः 1,118 मिलियन विशेष आहरण अधिकार तथा 56 मिलियन विशेष आहरण अधिकार था। विद्यमान विनिमय दरों पर उनकी राशि क्रमशः 2,572 करोड़ रुपये तथा 125 करोड़ रुपये के समकक्ष थी।]

## सारणी 10.3: भारत का भुगतान संतुलन

(करोड़ रुपये)

मद	1988-89 (अंतिम अनुमान)	1987-88 वास्तविक आंकड़े	1986-87 (अंशतः संशोधित)	1985-86
1	2	3	4	5
अ. बालू खाता				
1. आयात (लागत, बीमा, भाड़ा)	34,513.0	25,692.5	22,668.9	21,163.6
2. निर्यात (जहाज पर निःशुल्क)	20,150.5	16,396.4	13,315.0	11,577.6
3. व्यापार शेष	-14,002.5	-9,296.1	-9,353.9	-9,586.0
4. आधिकारिक अंतरण (निवल)	665.8	532.4	525.3	307.4
5. अन्य अदृश्य राशियां (निवल)	2,907.6	2,471.1	2,998.6	3,322.8
6. बालू खाता (निवल)	-10,429.1	-6,292.6	-5,830.0	-5,927.3
घ. पूंजी खाता				
1. बाहरी सहायता	3,186.2	2,914.8	1,807.6	1,675.9
मंडितरित राशियां	4,589.6	4,453.9	3,056.2	2,481.0
भुक्तौती राशियां	-1,673.4	-1,509.1	-1,248.6	-805.1
2. वाणिज्यिक उधार राशियां*	3,197.9	1,266.0	2,513.2	1,166.0
मंडितरण राशियां	4,293.1	1,945.7	3,115.6	1,827.0
भुक्तौती राशियां	-1,095.2	-679.7	-602.4	-661.0
3. अनिवासी जमा राशियां (निवल)	2,475.2	1,840.1	1,650.0	1,767.0
4. अन्य पूंजी (निवल)	2,261.4	1,442.2	-71.4	284.8
5. कुल पूंजी खाता (निवल)	11,120.7	7,493.1	5,899.4	4,893.7
इ. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (निवल)	-1,547.3	-1,209.0	-672.3	-253.0

1	2	3	4	5
ई. विशेष आहरण अधिकार आवंटन	—	—	—	—
उ. पूंजी खाता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विशेष आहरण अधिकार आवंटन	9,573.4	6,284.1	5,227.1	4,640.7
ऊ. कुल चालू खाता, पूंजी खाता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विशेष आहरण अधिकार आवंटन	-855.7	-8.5	-602.9	-1,286.6
ए. मूल-भूक राशियां	-593.6	-947.7	-129.3	+580.1
ऐ. आरक्षित निधियां तथा मीट्रिक स्वर्ण (बुद्धि—, गिरावट +)	1,449.3	956.2	732.2	706.5

\* इसमें पुनर्वित्त ऋण राशियां शामिल नहीं हैं।

#### विदेशी मुद्रा आस्तियां

10.6 आरक्षित विदेशी मुद्रा निधियों के तीन घटकों में से, भारतीय रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों में 1989-90 (जुलाई-जून) के

दौरान 719 करोड़ रुपये की गिरावट आयी जबकि 1988-89 की-तदनुसंग अवधि के दौरान उन में 265 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

#### सारणी 10.4 : भारत की आरक्षित विदेशी मुद्रा निधियां

निम्नलिखित माह के अंत में	आरक्षित विदेशी मुद्रा निधियां (करोड़ रुपये में)				कुल आरक्षित विदेशी मुद्रा निधियां (मिलियन विशेष आहरण अधिकार में)	कोष में आरक्षित निधि की स्थिति (करोड़ रु.)	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विस्तारित निधि सुविधा संबंधी लेन देन (मिलियन विशेष आहरण अधिकार में)		
	विशेष आहरण अधिकार**	स्वर्ण	विदेशी मुद्रा	कुल (2+3+4)			सकल आहरण राशियां	संचयी पुनः भुगतान राशियां	बकाया निवल आहरण (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मार्च 1987	231.76	274.28	7,645.17	8,151.21	5,113	809.44	3,900.00	562.50	3,337.50
मार्च 1988	125.25	7774.88	7,287.14	7,686.67	4,486	875.15	3,900.00	1,266.67	2,633.33
जून 1988	149.70	274.28	5819.53	6,243.50	3,600	899.91	3,900.00	1,425.00	2,475.00
मार्च 1989	160.74	274.28	6,604.63	7,039.65	3,715	984.14	3,900.00	2,070.85	1,829.15
जून 1989	212.46	274.28	6,075.17	6,561.91	3,408	1,008.26	3,900.00	2,218.77	1,681.23
मार्च 1990	183.55	280.67	5,787.17	6,251.3	3,045	1,091.32	3,900.00	2,752.10	1,147.90
जून 1990	206.64	280.67	5,356.17	5,843.48	2,784	1,128.96	3,900.00	2,862.52	1,037.48

\* अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायिकी के समान ही स्वर्ण का मूल्य निर्धारण विशेष आहरण अधिकार 35 प्रति औंस के हिसाब से किया गया है।

\*\* संबंधित महीनों के अंत में रुपया-विशेष आहरण अधिकार की विनिमय दर पर।

\$ 487 मिलियन विशेष आहरण अधिकार के समकक्ष।

टिप्पणी : सकल आहरण, पुनःभुगतान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रति बकाया देयताएं (अर्थात् निवल आहरण) विस्तारित निधि सुविधा के संबंध में हैं अर्थात् इसमें व्याप्त निधि ऋण शामिल नहीं हैं।

सारणी 10.5. आरक्षित विदेशी मुद्रा निधियों में घट-वृद्धि

(मिलियन विशेष आहरण अधिकार में)

प्रवधि/अवधि के अंत में	आरक्षित विदेशी मुद्रा निधियों का स्तर (इसमें कोष में आरक्षित मुद्रा स्थिति शामिल नहीं है)	आरक्षित विदेशी मुद्रा निधियों में घट-वृद्धि	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विशेष आहरण से निवल आहरण (+)/बुकौती राशियाँ (-)	विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में घट-वृद्धि (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अलग घटाकर)
1	2	3	4	5
1979-80	5,883	—	—	—
छठी योजना अवधि	6,004	121	+ 4,496अ	-4,375
सातवीं योजना अवधि	3,045	-2,959	-3,292आ	+ 333
1988-89	3,715	-771	-909अ	+ 138
1989-90	3,045	-670	-786ई	+ 116

- (अ) विस्तारित निधि सुविधा के अधीन 3900 मिलियन विशेष आहरण अधिकार, अतिपूरक विस्तपोषण सुविधा के अधीन 67 मिलियन विशेष आहरण अधिकार (निवल) और मास निधि के अधीन 529 मिलियन विशेष आहरण अधिकार का आहरण किया गया।
- (आ) विस्तारित निधि सुविधा के अधीन 2752 मिलियन विशेष आहरण अधिकार, अतिपूरक विस्तपोषण सुविधा के अधीन 67 मिलियन विशेष आहरण अधिकार और न्यास निधि के अधीन 473 मिलियन विशेष आहरण अधिकार हस्तेमाल किये गये।
- (इ) विस्तारित निधि सुविधा के अधीन 804 मिलियन विशेष आहरण अधिकार और न्यास निधि के अधीन 105 मिलियन विशेष आहरण अधिकार हस्तेमाल किये गये।
- (ई) विस्तार निधि सुविधा के अधीन 681 मिलियन विशेष आहरण अधिकार तथा न्यास निधि के अधीन 105 मिलियन विशेष आहरण अधिकार हस्तेमाल किये गए।

## विशेष आहरण अधिकार

10.7 1989-90 (जुलाई-जून) के दौरान विशेष आहरण अधिकार की धारिता में 13.5 मिलियन विशेष आहरण अधिकार की गिरावट आयी जबकि 1988-89 की इसी अवधि में उनमें 21.6 मिलियन विशेष आहरण अधिकार की वृद्धि हुई थी। यह गिरावट, 787.0 मिलियन विशेष आहरण अधिकार के अधिग्रहण तथा पारिश्रमिक हेतु 19.5 मिलियन विशेष आहरण अधिकार की प्राप्ति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 643.8 मिलियन विशेष आहरण अधिकार के पुनःत्रय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रभार व्याज हेतु 176.2 मिलियन विशेष आहरण अधिकार (व्याज सहायता घटाने के बाव) के भुगतान का निवल परिणाम थी।

## स्वर्ण

10.8 जून 1990 के अन्त में भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वर्ण धारिता 281 करोड़ रुपये की थी जो जून 1989 के अन्त के 274 करोड़ रुपये से 7 करोड़ रुपये अधिक है।

## बाणिज्य-व्यापार

10.9 1989-90 के दौरान निर्यात वृद्धि में तेजी के बावजूब पिछले वर्ष की अपेक्षा व्यापार घाटा हुआ, हालांकि वह थोड़ा ही अधिक था। यद्यपि निर्यात निष्पादन में सुदृढ़ता 1986-87 से ही अच्छी रही और उसमें और सुधार हुआ, परन्तु आयात में तेज वृद्धि से वह बराबर हो गया। बाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय के अन्तिम आंकड़ों के अनुसार व्यापार घाटा 1988-89 के 7,412 करोड़ रुपये से 319 करोड़ रुपये या 4.3 प्रतिशत बढ़कर 1989-90 में 7,731 करोड़ रुपये हो गया। 1988-89 के अंशतः सशोधित आंकड़ों (7,892 करोड़ रुपये) की तुलना में व्यापार घाटे में 2.0 प्रतिशत की थोड़ी सी गिरावट आयी (गारणी 10.6)।

10.10 हाल ही के वर्षों के दौरान निर्यात वृद्धि में आयी तेजी, 1989-90 में और बढ़ गयी। बाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार निर्यात में रुपये की दृष्टि से 36.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह राशि 27,681 करोड़ रुपये हो गयी। 211 GI/91-29

अमेरिकी डालर और विशेष आहरण अधिकार की दृष्टि से भी निर्यात में क्रमशः 18.6 प्रतिशत और 22.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष में हुई क्रमशः 16.0 प्रतिशत और 15.1 प्रतिशत की उक्त वृद्धि की तुलना में उल्लेखनीय है। आयातों की 35,412 करोड़ रुपये की राशि 25.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है जबकि 1988-89 में उनमें 26.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। विशेष आहरण अधिकार की दृष्टि से 1989-90 में आयातों में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष उनमें 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। अमेरिकी डालर की दृष्टि से 1989-90 के दौरान आयात में हुई 9.2 प्रतिशत की वृद्धि 1988-89 में हुई 13.5 प्रतिशत की उक्त वृद्धि से काफी कम थी।

10.11 आयातों का बचाव बना रहने के बावजूब निर्यात वृद्धि में सुदृढ़ता के परिणामस्वरूप निर्यात की आयात क्य शक्ति में स्पष्ट सुधार हुआ। निर्यात-आयात अनुपात 1988-89 के 72.0 प्रतिशत से बढ़कर 1989-90 में 78.2 प्रतिशत हो गया। किन्तु, भुगतान के आधार पर मूल्यांकन करने पर यह अनुपात बहुत कम होने का अनुमान है।

## निर्यात

10.12 1989-90 के दौरान जब उल्लेखनीय निर्यात निष्पादन हुआ तब विश्व व्यापार में विस्तार हुआ था। निर्यात की मात्रा में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है जो व्यापारिक वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों तथा प्रमुख मुद्राओं के बाह्य मूल्यों में घट-वृद्धि को देखते हुए विश्व व्यापार में वास्तविक दृष्टि से हुई वृद्धि (1989 में 7.5 प्रतिशत) से काफी अधिक थी। असीम वर्ष के दौरान कार्यविधियों को सरल और मुक्तियुक्त बनाने के लिए बहुत से उपाय किये गये ताकि निर्यात कार्य में सहायता के लिए दिये जाने वाले विभिन्न मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन आसानी से उपलब्ध हो सकें। 1988-91 के लिए आयात-निर्यात नीति अपनी अवधि पूर्ण होने से एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दो

गई तथा 30 अप्रैल, 1990 को 1990-93 के लिए एक नयी आयात-निर्यात नीति की घोषणा की गई। नयी नीति का उद्देश्य पिछले कुछ वर्षों में शुरू हुई उदारीकरण की प्रक्रिया की गति को मजबूत करना है। नयी नीति के अंतर्गत पुनः पूर्ति लाइसेंसों को आयात की जा सकने वाली मदों के संवर्गों की दृष्टि से अधिक लचीला बनाया गया है। कार्यविधि संबंधी क्लिब को कम करने के लिए प्रतिष्ठित निर्यातकों के पक्ष में एक नयी

निर्बंध प्रथम लाइसेंसिकरण योजना शुरू की गई है। नयी योजना के अंतर्गत निर्यात निर्यातकों को निर्यात दायित्व के अधीन सीमाशुल्क की रियायती दरों पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति दी गई है। निर्यात से अधिक मात्रा में निर्यात विदेशी मुद्रा प्राप्ति पर बल दिया गया है। समर्थक विदेशी मुद्रा विनिमय दर नीति से भी विदेशों में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार हुआ है।

### सारणी 10. 6: छठी और सातवीं योजना के दौरान भारत का विदेश व्यापार

वर्ष	करोड़ रुपये में			मिलियन अमरीकी डॉलर में			मिलियन विशेष आह्वान अधिकार में ---		
	निर्यात	आयात	व्यापार शेष	निर्यात	आयात	व्यापार शेष	निर्यात	आयात	व्यापार शेष -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>छठी योजना</b>									
1980-81	6,711 (4.6)	12,549 (37.2)	-5,838	8,484 (7.1)	15,865 (40.5)	-7,381	6,594 (7.8)	12,330 (41.5)	-5,736
1981-82	7,806 (16.3)	13,608 (8.4)	-5,802	8,704 (2.6)	15,173 (-4.4)	-6,469	7,553 (14.5)	13,166 (6.8)	-5,613
1982-83	8,803 (12.8)	14,293 (5.0)	-5,490	9,107 (4.6)	14,787 (-2.5)	-5,680	8,334 (10.3)	13,531 (2.8)	-5,197
1983-84	9,771 (11.0)	15,831 (10.8)	-6,060	9,450 (3.8)	15,310 (3.5)	-5,860	8,931 (7.2)	14,470 (6.9)	-5,539
1984-85	11,744 (20.2)	17,134 (8.2)	-5,390	9,878 (4.5)	14,412 (-5.9)	-4,534	9,842 (10.2)	14,359 (-0.8)	-4,517
<b>श्रीसत (छठी योजना)</b>	8,967 (13.0)	14,683 (13.9)	-5,716	9,125 (4.5)	15,110 (6.2)	-5,985	8,251 (10.0)	13,571 (11.4)	-5,320
<b>सातवीं योजना</b>									
1985-86	10,895 (-7.2)	19,658 (14.7)	-8,763	8,905 (-9.8)	16,067 (11.5)	-7,162	8,431 (-14.3)	15,211 (5.9)	-6,780
1986-87	12,452 (14.3)	20,096 (2.2)	-7,644	9,745 (9.4)	15,727 (-2.1)	-5,982	8,061 (-4.4)	13,009 (-14.5)	-4,948
1987-88	15,674 (25.9)	22,244 (10.7)	-6,570	12,089 (24.0)	17,156 (9.1)	-5,067	9,155 (13.6)	12,992 (-0.1)	-3,837
1988-89@	20,302 (28.5)	28,194 (26.7)	-7,892	14,019 (16.0)	19,469 (13.5)	-5,450	10,540 (15.1)	14,637 (12.7)	-4,097
1989-90*	27,681 (38.3)	35,412 (25.6)	-7,731	16,626 (18.6)	21,269 (9.2)	-4,643	12,954 (22.9)	16,572 (13.2)	-3,618
<b>श्रीसत (सातवीं योजना)</b>	17,401 (19.8)	25,121 (16.0)	-7,720	12,277 (11.6)	17,938 (8.2)	-5,661	9,828 (6.6)	14,484 (3.4)	-4,656

@ग्रंथतः संशोधित

\*सर्वात्म

कोष्ठकों में दिय गये आंकड़ें वार्षिक प्रतिशत घट-बढ़ अथवा योजना अवधियों के दौरान श्रीसत वार्षिक वृद्धि दर दर्शाते हैं।

स्त्रोत : वार्षिक आभूषण और अंक संकलन महानिदेशालय

10.13 1989 के पण्यवार उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि हाल की अवधि के समान ही सुदृढ़ निर्यात-कार्य निष्पादन के लिए मुख्य प्रेरणा स्त्रोत विनिर्माण क्षेत्र है। आलोच्य अवधि के दौरान कुल निर्यातों में वृद्धि का 76.8 प्रतिशत अंश विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात का था। रसायनों और संबंधित उत्पादों (40.7 प्रतिशत) तथा सिलेसिलिए वस्त्रों (53.7) प्रतिशत के निर्यात में भारी वृद्धि हुई। विनिर्मित वस्तुओं की कोटि में निम्नलिखित अन्य पण्यों के निर्यात में वृद्धि हुई: चमड़ा और चमड़े की वस्तुएं (30.9 प्रतिशत), रत्न और आभूषण (20.4 प्रतिशत) तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं (40.5) प्रतिशत; किन्तु रत्न और आभूषण तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में आयात का अंश भी काफी था। इसके अलावा, इन मदों के संबंध में कार्य निष्पादन में पिछले वर्षों की तुलना में मदों

रही। प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 36.1 प्रतिशत अधिक हुआ तथा निर्यात में कुल वृद्धि में उसका अंश 21.4 प्रतिशत था (सारणी 10.7)। प्राथमिक वस्तुओं में इस वृद्धि में से 77.6 प्रतिशत की वृद्धि कृषि और संबद्ध उत्पादों के समूह से हुई जो पिछले वर्ष कम किये गये निर्यात योग्य अतिरिक्त माल की पाबंदी से बंचित रहा था। निम्नलिखित मदों के मामले में भारी वृद्धि हुई: रूई (35.7 प्रतिशत) अलसी की खली (48 प्रतिशत), चावल (29 प्रतिशत), चाय (51 प्रतिशत), संसाधित वस्तुएं (32 प्रतिशत), काजू की गिरी (33 प्रतिशत) तथा फल और सब्जियां (27 प्रतिशत)। समुद्री उत्पादों का निर्यात स्थूलतः पिछले वर्ष के स्तर पर ही बना रहा जबकि मसालों के निर्यात में गिरावट आयी। अयस्क और खनिजों, विशेषकर लौह अयस्क का निर्यात (38 प्रतिशत) भी काफी घटता रहा।

## सारणी 10.7 : भारत के मुख्य पथों के निर्यात

(करोड़ रुपये)

पथ-समूह	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89@	1989-90
1	2	3	4	5	6
प्राथमिक उत्पाद					
उनमें से :	3,803	4,139	4,160	4,374	5,951
	(34.9)	(33.2)	(26.6)	(21.5)	(21.5)
1. कृषि और उससे संबद्ध उत्पाद	3,018	3,422	3,411	3,347	4,571
	(27.7)	(27.5)	(21.8)	(16.5)	(16.5)
2. अयस्क और खनिज	785	717	749	1,027	1,380
बिनिर्मित माल					
उनमें से :	6,447	7,902	10,865	14,641	20,310
	(59.2)	(63.5)	(69.3)	(72.1)	(73.4)
1. वस्त्र और बिनिर्मित वस्तुएं, उनमें से	1,795	2,179	3,225	3,700	5,246
मूनी धागा, कपड़े और तैयार वस्त्र	574	637	1,155	1,131	1,480
मिले मिश्रित वस्त्र	1,067	1,331	1,813	2,097	3,224
2. चमड़ा और खमड़े की वस्तुएं	770	922	1,251	1,490	1,951
3. दस्तकारी की वस्तुएं					
उनमें से	1,881	2,548	3,249	5,194	6,285
रत्न और आभूषण	1,503	2,074	2,617	4,399	5,296
4. रसायन और संबद्ध उत्पाद	498	583	801	1,534	2,158
5. इंजीनियरी वस्तुएं	954	1,133	1,502	2,364	3,321
6. खनिज और चिकनाई के पदार्थ*	645	411	649	505	697
	(5.9)	(3.3)	(4.1)	(2.5)	(2.5)
जोड़ (अन्य सहित)	10,895	12,452	15,674	20,302	27,681

अ- अंतिम

@अंशतः संशोधित

\*केवल कच्चे पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित।

फोप्टको में दिये गए आंकड़े कुल निर्यात का प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।

स्त्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय।

## सारणी 10.8: व्यापार की दिशा

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	1984-85		1988-89 (अ)		1989-90 (अ)	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
1	2	3	4	5	6	7
I. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन	44.9	48.7	58.2	60.5	55.9	60.0
उनमें से :						
(क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय	18.0	24.6	24.4	31.4	25.0	33.1
(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका	15.0	9.9	18.4	11.5	16.2	12.0
(ग) एशिया और ओसिनिया						
उनमें से :	10.1	8.6	12.1	12.2	11.2	10.7
जापान	8.8	7.2	10.7	9.5	9.9	8.0
II. पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन	8.0	19.4	6.0	13.3	6.6	14.3
III. पूर्वी यूरोप	19.3	12.9	16.5	7.0	19.3	8.4
IV. विकासशील देश	27.8	19.0	19.3	19.1	18.2	17.3

अ. अंतिम

स्त्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय।

10.14 गंतव्य-वार देखा जाए तो, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में शामिल देशों के समूह का भारत के निर्यातों में एक बड़ा अंश रहा और यूरोपीय आर्थिक समुदाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाजार रहा (सारणी 10.8) भारत के कुल निर्यात में पूर्वी यूरोपीय देशों का अंश भी 1988-89 के 16.5 प्रतिशत से बढ़कर 1989-90 में 19.3 प्रतिशत हो गया।

#### आयात

10.15 1988-89 के दौरान आयात में हुई तेज वृद्धि 1989-90 में भी बनी रही जिसके मुख्य कारण हैं देश में मांग का बना रहना, कतिपय आयातों के यूनिटों में वृद्धि का होना; इससे इन वस्तुओं की कम मात्रा में हुई वृद्धि पर उलटा असर पड़ा तथा आलोच्य वर्ष के दौरान असेनिक हवाई जहाजों के आयात का प्रभाव पड़ा।

10.16 भारी आयात वस्तुओं की श्रेणी, जिसमें मूल उपभोक्ता वस्तुओं तथा उद्योग के लिए मूल निविष्टियों के आयात शामिल हैं, में 1989 में 27.4 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई और वह 14,239 करोड़ रुपये हो गई। इससे इन आयातों में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति का पता चलता है; यह प्रवृत्ति 1987-88 से शुरू हुई थी (सारणी 10.9)। निबल तेल आयात की वस्तुओं (पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई) की निर्यात वस्तुएं घटाने के बाद तेल का आयात की श्रेणी के अन्तर्गत 1988-89 के दौरान 14.0 प्रतिशत (475 करोड़ रुपये) की वृद्धि हुई थी, 1989-90 में 44.1 प्रतिशत (1,708 करोड़ रुपये) की भारी वृद्धि हुई जो भारी आयात वस्तुओं की कुल वृद्धि में 55.7 प्रतिशत का होता है। पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों के आयातों पर अधिक व्यय हुआ जिसका कारण था भारी मात्रा में वस्तुओं का आयात, आयात की उच्च लागत और अमेरिकी डॉलर का सुबूढ़ होना, वह मुद्रा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय तेल के लेनदेनों के बिल बनाये जाते हैं। तेल से इतर भारी आयात की वस्तुओं में जिन वस्तुओं में भारी वृद्धि हुई वे थीं: उर्वरक (91.4 प्रतिशत या 848 करोड़ रुपये); विशेषकर विनिर्मित उर्वरक रुपये; लोहा और इस्पात (19.0 प्रतिशत या 368 करोड़ रुपये) तथा लुग्दी और रूई कागज (20.2 प्रतिशत या 51 करोड़ रुपये)। चीनी का आयात (जो 1988-89 में बन्दूत नहीं ही किया गया), 1989-90 के दौरान 97 करोड़ रुपये का किया गया। लोहा और इस्पात, धातुमय अयस्को तथा छीलन, कच्चे रबड़ और गन्ने की वस्तुओं के संबंध में आलोच्य वर्ष के दौरान उनके आयातों की वृद्धि दर में गिरावट तथा हाल के वर्षों में देश में बेहतर उपलब्धता से स्पष्ट होता है कि इनके आयात की कुछ स्थाना-पन्न व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित थोक उपभोक्ता वस्तुओं के संबंध में काफी आयात की वृद्धि की गई: खाद्य तेल (71.0 प्रतिशत या 516 करोड़ रुपये की), अनाज और उनसे बनी चीजें (40.1 प्रतिशत या 253 करोड़ रुपये की) तथा चालें (40.5 प्रतिशत या 155 करोड़ रुपये की)। 1989-90 के दौरान थोक से इतर आयातों के अन्तर्गत पूंजीगत वस्तुओं में 27.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निर्यात से संबंध आयातों के समूह में वृद्धि की दर कम हो गई, आलोच्य वर्ष के दौरान उनमें केवल 24.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1988-89 में यह वृद्धि 63.0 प्रतिशत थी।

\*भारतीय बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1988-89 पृष्ठ 93-95 तक

सारणी 10.9 : भारत का मुख्य पण्यों का आयात

( करोड़ रुपये )

वर्ष	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89(a)	1989-90(प्र)
1	2	3	4	5	6
1. थोक आयात उसमें से	10,763 (54.8)	8,024 (39.9)	9,084 (40.8)	11,175 (39.6)	14,239 (40.2)

10.17 यूरोपीय आर्थिक समुदाय और संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के आयातों का मुख्य स्रोत बने रहे और 1989-90 के दौरान कुल आयातों का लगभग 45 प्रतिशत अंश उनका था जबकि 1984-85 में यह 35 प्रतिशत से थोड़ा कम था। इस अवधि के दौरान पूर्वी यूरोपीय देशों का अंश 13 प्रतिशत से गिरकर 8 प्रतिशत रह गया जबकि विकसनीय देशों का अंश भारत के कुल आयात के 20 प्रतिशत से थोड़ा सा कम रहा।

#### योजना अवधि के दौरान

10.18 सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान निर्यातों में रुपये की दृष्टि से लगभग 19.8 प्रतिशत अमेरिकी डॉलर की दृष्टि से 11.6 प्रतिशत और विशेष आह्वरण अधिकार की दृष्टि से 6.6 प्रतिशत आर्थिक की औसत वृद्धि हुई (सारणी 10.6 देखें), योजना के पहले वर्ष (1985-86) को छोड़कर जब कच्चे तेल का निर्यात वस्तुतः बंद हो गया था तथा उसके परिणामस्वरूप वास्तविक दृष्टि से निर्यातों में लगभग 8 प्रतिशत की गिरावट आयी थी, योजनावधि के शेष चार वर्षों के दौरान निर्यात में लगभग 10 से 12 प्रतिशत आर्थिक तक की औसत वृद्धि हुई। संपूर्ण योजना अवधि में भी वास्तविक निर्यात में औसत वृद्धि 7 प्रतिशत आर्थिक से थोड़ी अधिक होती है जो योजना में अनुमानित 6.8 प्रतिशत आर्थिक से अधिक है।

10.19 सातवीं योजना अवधि के दौरान आयातों में रुपये की दृष्टि से 16.0 प्रतिशत, डॉलर की दृष्टि से 8.2 प्रतिशत और विशेष आह्वरण अधिकार की दृष्टि से 3.4 प्रतिशत आर्थिक की दर पर औसत वृद्धि हुई। योजना अवधि के पहले दो वर्षों में मात्रा की दृष्टि से आयातों में लगभग 16.5 प्रतिशत आर्थिक की औसत वृद्धि हुई बाद के तीन वर्षों के अनुमानों को देखते हुए योजना अवधि के दौरान मात्रा की दृष्टि से आयात में 9.5 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुई जो सातवीं योजना के लिए मूलतः अनुमानित 5.8 प्रतिशत आर्थिक की वृद्धि दर से काफी अधिक है।

#### व्यापार और भुगतान संतुलन के आकड़ों के बीच अंतर

10.20 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में वार्षिक व्यापार के आकड़ों के बारे में वार्षिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यापार के आकड़ों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित भुगतान संतुलन के आकड़ों के बीच अंतर का उल्लेख किया गया था अंतर के मुख्य कारण भी दिये गये थे। वर्ष 1988-89 के एक और वर्ष के लिए उपलब्ध आकड़ों से यह देखा गया है कि दोनों स्रोतों में दिये गये आयात के आकड़ों के बीच अंतर 1987-88 के 3,293 करोड़ रुपये से बढ़कर 1988-89 में 6,319 करोड़ रुपये हो जाने के उपर्युक्त अंतर और बढ़ गया है। भूतयांकन के तथ्यों के अलावा, इस उच्चतर अंतर का कारण यह है कि लगभग 1,200 करोड़ रुपये की सीमा तक असीनिक विमानों का आयात किया गया, जो भुगतान संतुलन के आकड़ों में सम्मिलित है परन्तु समय के अंतर के कारण व्यापार के आकड़ों में सम्मिलित नहीं है।



1	2	3	4	5	6
(क) पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के उत्पाद तथा संबंधित सामग्री	4,989 (25.4)	2,811 (11.0)	40,43 (18.2)	4,374 (15.5)	6,274 (17.7)
(ख) धातु, उपभोग्य वस्तुएं	1,466 (7.5)	1,179 (5.9)	1,503 (6.7)	1,741 (6.2)	914 (2.6)
(i) अनाज और अनाज से बनी चीजें	110	87	66	631	378
(ii) खाद्य तेल	749	634	969	727	211
(iii) दालें	189	234	275	383	228
(iv) चीनी	413	224	193	(5)	97
(ग) अन्य धातु मटे	4,308 (11.9)	4,034 (10.0)	3,538 (15.9)	5,060 (17.9)	7,051 (19.9)
(i) चूर्णक कच्चा	1456	921	308	928	1,776
सूखे और बिना पानी के गोड़े के पाउडर/स्टिनिमिन	163 270	145 300	139 181	185 250	253 295
(ii) अलौह धातु	1,053	576	188	493	1,228
(iii) कार्बन, रत्ता और उसके बनी (दरतु, अखंडारी कार्बन सहित)	544	517	639	786	1,253
(iv) बरतन वस्तु	236	217	270	306	358
(v) लकड़ी और रूई कागज	101	107	120	173	172
(vi) अतिमृद अयस्क और धातु की छालन	245	241	239	253	304
(vii) लोहा और इस्पात	363	472	442	677	853
2 फुटकर आधान	1,395	1,556	1,350	1,937	2,305
उत्पत्ति से	8,895 (45.2)	12,072 (60.1)	13,160 (59.2)	17,019 (60.4)	21,173 (59.8)
(क) पुरुषों के वस्त्र	1,286 (21.8)	6,488 (31.5)	6,566 (29.5)	6,939 (24.6)	8,831 (24.9)
(ख) महिला वस्त्रों से संबंधित मटे	2,366 (12.0)	2,856 (14.1)	3,351 (15.1)	5,463 (19.1)	6,803 (19.2)
(i) मोती, कौमोती और अन्य कौमोती वस्त्र	1,100	1,489	2,018	3,175	4,242
(ii) रसायन कार्बनिक और अकार्बनिक	1,089	1,145	1,082	1,940	2,135
(iii) अस्त्रोपयोगी धातु, बरतन आदि	159	151	187	287	349
(iv) काजू गिरी, कच्ची	24	71	64	61	77
(ग) अन्य	2,243 (11.4)	2,728 (13.6)	3,243 (14.6)	4,617 (16.4)	5,539 (15.6)
जोड़—1+2	19,658	20,096	22,244	28,194	35,412

प्र=अंतिम @अंशतः संशोधित न = नवम्

टिप्पणी कोष्ठकों से दिये गये आंकड़ों के कुल आयात से प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।

स्रोत वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय।

संख्या 10 10 : वाणिज्यिक आयात

(करोड़ रुपये)

वर्ष	वाणिज्यिक आसूचना और भंड संचालन महाविभाग के आंकड़े			भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े		
	निर्यात	आयात	व्यापार घाटा	निर्यात	आयात	व्यापार घाटा
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	6,711	12,549	—5,838	6,576	12,544	—5,967
1981-82	7,803	13,608	—5,805	7,766	13,887	—6,121
1982-83	8,803	14,293	—5,490	9,137	14,913	—5,776
1983-84	9,771	15,831	—6,060	10,169	16,039	—5,871
1984-85	11,744	17,134	—5,390	11,959	18,680	—6,721
1985-86	10,895	19,658	—8,763	11,578	21,164	—9,586
1986-87	12,452	20,096	—7,644	13,715	22,669	—9,354
1987-88	15,741(अ.स.)	22,399(अ.स.)	—6,658(अ.स.)	16,396	25,692	—9,296
1988-89	20,295(अ.स.)	28,191(अ.स.)	7,896(अ.स.)	20,511(अ.स.)	34,513	—14,003

अ.स. = अंश : संशोधन      अ.स. = अनुमान

अध्यक्ष वस्तुएं

10.21 उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि 1989-90 के दौरान अध्यक्ष वस्तुओं से निर्यात प्राप्त राशियां पिछले वर्ष के स्तर पर ही रहेंगी। बाहरी सहायता के अधीन तथा वाणिज्यिक शर्तों पर प्राप्त शर्तों पर व्याज भुगतान तथा सेवा शुल्क के कारण निर्यात आय पर भुगतानों में पहले की तरह वृद्धि होती रही। आयात वर्ष के दौरान निजी अंतरणों के अधीन श्रेणियों की प्राप्ति में कोई विशेष परिवर्तन परिलक्षित नहीं हुआ होगा। आशा है, यात्रा और पर्यटन में अर्जित राशि में वृद्धि हुई होगी। 1989-90 के दौरान देश में आनेवाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 7.5 प्रतिशत अधिक थी जबकि पिछले वर्ष उनमें 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। अन्य सभी मदों में समग्र दृष्टि से पिछले वर्ष की तुलना में विशेष घट-बढ़ होने की संभावना नहीं है।

बाहरी सहायता, वाणिज्यिक उधार और वित्तीय लेनदेन

10.22 1989-90 के दौरान बाहरी सहायता के अंतर्गत 5,942 करोड़ रुपये के सफल वितरण किये गये अर्थात् वे 1988-89 में किये गये 5,291 करोड़ रुपये के सफल वितरण से 651 करोड़ रुपये अधिक थे। बाहरी सहायता पर 1,987 करोड़ रुपये के परिशोधन भुगतान 1988-89 में 1,646 करोड़ रुपये के उच्च भुगतानों से 341

करोड़ रुपये अधिक थे (सारणी 10.11)। परिणामस्वरूप 1989-90 के दौरान बाहरी सहायता के अंतर्गत 3,955 करोड़ रुपये की निर्यात प्राप्ति हुई जबकि 1988-89 में यह राशि 3,645 करोड़ रुपये थी। इसका मुख्य कारण जापान और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से अधिक मात्रा में सहायता की निर्यात प्राप्ति है, किन्तु अनुरोधों के कारण की दृष्टि से विदेश से प्राप्त सहायता की निर्यात राशि जो 1988-89 5.5 प्रतिशत गिर गयी थी, 1989-90 के दौरान 5.6 प्रतिशत और गिरकर 2,375 मिलियन डॉलर रह गयी। व्यापारिक उधारों के उपयोग की राशि 1988-89 में 4,293 करोड़ रुपये (3.0 बिलियन डॉलर) थी जबकि 1987-88 में यह राशि 1,946 करोड़ रुपये (1.5 बिलियन डॉलर) थी (सारणी 10.12)। चुकोती की राशि घटाने के बाद 1988-89 में वाणिज्यिक उधारों के उपयोग की राशि 2.2 बिलियन डॉलर थी जबकि 1985-86 में 1987-88 के दौरान उच्च राशि का औसत 1.3 बिलियन डॉलर था। सातवीं योजना अवधि के पहले चार वर्ष के दौरान बाहरी सहायता और वाणिज्यिक उधारों के अंतर्गत निर्यात प्राप्ति का औसत क्रमशः 2.0 बिलियन डॉलर और 1.5 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष के लगभग आलोच्य वर्ष के दौरान द्वितीय आयात वर्ष के देशों के साथ लेन देन 842 करोड़ रुपये का निर्यात व्यय दर्शाते हैं जो इन समूह के देशों के साथ चालू खाते में निर्यात अधिशेष का घटक है जबकि 1988-89 में 264 करोड़ रुपये की निर्यात प्राप्ति हुई थी।

सारणी 10.11 : बाहरी सहायता

(करोड़ रुपये)

	1985-86	1986-87	1978-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6
1. ऋण	2,195	3,176	4,575	4,738	5,279
2. अनुदान	413	420	457	553	663
3. सकल उपयोग	2,938	3,596	5,032	5,291	5,942
4. चुकोती राशियां	776	1,176	1,581	1,646	1,987
5. शुद्ध (3-4)	2,162	2,420	3,451	3,645	3,955

टिप्पणी : 1. ऋणों में सरकारी ऋण शामिल है परन्तु आपूर्तिकर्ता ऋण तथा वाणिज्यिक उधार शामिल नहीं हैं।

2. \* अनुमानित

योजना अवधि के दौरान वित्तपोषण की पद्धति

10.23 सातवी योजना के पहले चार वर्षों में वित्तपोषण की पद्धति से पता चलता है कि बहुपक्षीय और द्विपक्षीय देशों से बाहरी सहायता के रूप में प्राप्ति कृणों से वित्तपोषण आवश्यकता के 24 प्रतिशत अंश की पूर्ति हुई (यह छठी योजना अवधि के 55 प्रतिशत अंश की

तुलना में काफी कम है), वित्तपोषण आवश्यकता का 25 प्रतिशत वार्षिक उधार के रूप में, 23 प्रतिशत विदेशी मुद्रा अतिवसी खाता योजना और अतिवसी (विदेशी) रुपया खाता योजना के अधीन अतिवसी जमागणिया के माध्यम से लगभग 12 प्रतिशत अंश अन्य पुंजीगत लेनदेन से तथा शेष 12 प्रतिशत अंश पारंपरिक विविध सहायता से प्राप्त हुआ (सारणी 10.13)।

सारणी 10.13 : वार्षिक उधार

1	(करोड़ रुपये)				
	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89(1)
2	3	4	5	6	
उपयोग (सकल)	1,472	1,827	3,115*	1,946*	4,293*

\*पूर्व भुगतानों को छोड़कर (2) अनुमानित

अतिवसी (विदेशी) रुपया खाता योजना तथा विदेशी मुद्रा अतिवसी खाता योजना के अंतर्गत वृद्धि

10.24 1989-90 के अन्तिम आंकड़ों के अनुसार अतिवसी (विदेशी) रुपया खाता योजना के अंतर्गत 4 करोड़ रुपये (अनुमानित ब्याज घटक को छोड़कर) के आहरण किये गये जबकि पिछले वर्ष 245 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी। विदेशी मुद्रा (अतिवसी) खाता योजना के अंतर्गत 1989-90 के दौरान 2,773 करोड़ रुपये की निवल प्राप्ति हुई जबकि 1988-89 में यह राशि 2,075 करोड़ रुपये थी (सारणी 10.14)।

10.25 मार्च 1990 के अंत में अतिवसी जमागणिया 17,831 करोड़ रुपये थी अतिवसी (विदेशी) रुपया खाता योजना के अधीन 6,507 करोड़ रुपये और विदेशी मुद्रा अतिवसी खाता योजना के अधीन 11,324 करोड़ रुपये (सारणी 10.15)।

अतिवसी जमागणिया के संक्षेप में ब्याज दरें

10.26 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्याज दरों में घट-बढ़ की प्रवृत्तियों को देखते हुए विदेशी मुद्रा अतिवसी खाता योजना के अंतर्गत जमागणियों पर ब्याज दरों में बार-बार परिवर्तन किये गये। सारणी 10.16 में आलोच्य अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा अतिवसी खाता योजना के अंतर्गत जमागणियों पर विभिन्न मुद्राओं के संदर्भ में ब्याज दरें दी गयी हैं।

सारणी 10.13 : वित्तपोषण की आवश्यकता और वित्तपोषण के स्रोत

1	करोड़ रुपये					मिलियन अमरीकी मिलियन विशेष डालर आहरण अधिकार	
	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	जोड़	7	8
2	3	4	5	6	7	8	
1. भूल-भूक सहित चालू खाता घाटा	5347	5959	7240	11094	29560	22539	18340
2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ऋणोत्ती राशियाँ	-253	-672	-1209	-1547	-3681	-2807	-2284
3. वित्तपोषण की आवश्यकता (1+2)	-5600	-6631	-8449	-12551	-33231	-25338	-20617
निम्नलिखित से वित्तपोषित							
4. बाहरी सहायता	1676 (29.9)	1808 (27.3)	2785 (33.0)	3178 (25.3)	9615 (28.5)	7331 (28.9)	5965 (28.9)
5. वार्षिक उधार	1167 (20.8)	2512 (37.9)	1426 (16.9)	3198 (25.5)	8143 (24.5)	6209 (24.5)	5051 (24.5)
6. अतिवसी जमागणियाँ	1767 (31.6)	1650 (24.9)	1840 (21.8)	2475 (19.7)	7732 (23.3)	5896 (23.3)	4797 (23.3)
7. अन्य पुंजी	284 (5.1)	-71 (-1.1)	1442 (17.0)	2251 (17.9)	3906 (11.8)	2978 (11.8)	2424 (11.8)
8. आरक्षित निधिओं का प्रयोग	706 (12.6)	732 (11.0)	956 (11.3)	1449 (11.6)	3843 (11.5)	2930 (11.5)	2384 (11.5)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े वित्तपोषण की आवश्यकता में प्रतिशत अंश दर्शाते हैं (मर 3)।

बाहरी ऋण 10.27 पात्रता योजना अधि के दौरान आनु खाते में बड़े और बार-बार होन वार घाटे का प्रतिकारण अधिकारण : विदेशों में बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सहायता, वारिणनिक उधार तथा अनिवार्य जमागणियों के रूप में प्राप्त होनेवाली पसी से किया गया। परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों में भारत का बाहरी ऋण काफी बढ़

गया है। भारत का वारिणनिक ऋण (ए) जो मार्च 1980 के अंत में (13,130 करोड़ रुपये) प्रवेशाह्न कम था, मार्च 1985 के अंत तक बढ़कर लगभग 33,800 करोड़ रुपये हो गया और मार्च 1989 के अंत तक 69,681 करोड़ रुपये एवं मार्च 1990 के अंत तक 81,163 रुपये हो गया (गणनी 10.17)।

सारणी 10.14 अनिवार्य (बाहरी) रुपया खाना योजना और विदेशी मुद्रा अनिवार्य खाना योजना के अर्धवर्ष प्राप्तिता।

राजकोषीय वर्ष	(करोड़ रुपये)		
	अनिवार्य (बाहरी) रु. खाता (A)	विदेशी मुद्रा (अनिवार्य) खाता	जोड़
1	2	3	4
1984-85	358	225	879
1985-86	287	1,151	1,767

@अनुमानित प्रोद्भूत व्याज को छोड़कर।

1	2	3	4
1986-87	483	1,169	1,650
1987-88	477	1,398	1,840
1988-89	245	2,075	2,475
1989-90	—4	2,773	2,671

सारणी 10.15 अनिवार्य (बाहरी) रुपया खाना योजना तथा विदेशी मुद्रा अनिवार्य खाना योजना के अर्धवर्ष प्राप्तिता।

(करोड़ रुपये)

निम्नलिखित वर्षों के मार्च के अंत में	अनिवार्य रुपया खाना योजना*	विदेशी मुद्रा अनिवार्य खाता (A)				जोड़ (A से 6 तक)	कुल जोड़ (2 + 7)
		अमरीका, बालर	पीड स्टर्लिंग	रूपीय मार्क	येन		
1	2	3	4	5	6	7	8
1985	2,861	618 (499)	337 (218)	--	--	955	3,819
1986	3,461	1,759 (1,419)	430 (236)	--	--	2,189	5,650
1987	4,336	3,048 (2,360)	464 (224)	--	--	3,511	7,847
1988	5,107	4,406 (3,410)	541 (222)	--	--	4,947	10,054
1989	5,899	6,648 (4,245)	535 (203)	700 (848)	372 (31,571')	8,255	14,154
1990	6,507	9,304 (5,409)	337 (119)	1,028 (1,013)	655 (60,527)	11,324	17,831

\*प्रोद्भूत व्याज सहित।

@ इसमें प्रोद्भूत व्याज शामिल नहीं है।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े संबंधित मुद्राओं में बकाया जमागणियों के हैं और ये राशियां मिलियन में हैं।

10.28 सतत रेशो उत्पाद (बाजार मूल्यों पर) के अनुपात के रूप में बाहरी ऋण मार्च 1980 के अंत के 12.5 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 1989 के अंत तक 17.8 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान ऋण निर्यात (वस्तुओं का निर्यात और अवश्य प्राप्तियां) अनुपात 131

प्रतिशत से काफी बढ़कर 223 प्रतिशत हो गया। परिणामस्वरूप, ऋण-चुकोती अनुपात (अनिवार्य जमागणियों पर व्याज को छोड़कर) 1985-86 में चालू प्राप्ति:यों के 16 प्रतिशत से बढ़कर 1987-88 में 24 प्रतिशत हो गया, परन्तु 1988-89 में थोड़ा-सा गिरकर 23 प्रतिशत रह

@मूल रूप से या बाद में बढ़ाई एक वर्ष से अधिक अवधि के किसी भी ऋण के रूप में परिभाषित।

सारणी 10.16 : विदेशी मुद्रा अभिवृद्धि योजना के अंतर्गत जमा राशियों पर व्याज दरें

(प्रतिशत वार्षिक)

अमरीकी डालर					पीड स्टलिंग				इयूग मार्क				येन			
प्रभावी तारीख	6 महीने से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	केवल 3 वर्ष	6 महीने से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	केवल 3 वर्ष	6 महीने से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	केवल 3 वर्ष	6 महीने से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	केवल 3 वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24 अगस्त																
1989	9.50	9.50	9.50	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	7.75	7.75	8.00	8.00	6.00	6.00	6.25	6.25
18 सितम्बर																
1989	9.50	9.50	9.75	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	8.00	8.00	8.25	8.25	6.25	6.25	6.50	6.50
11 अक्टूबर																
1989	9.50	9.50	9.75	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	8.50	8.50	8.50	8.50	6.25	6.50	6.50	6.50
21 अक्टूबर																
1989	9.00	9.00	9.25	9.50	11.50	11.75	12.00	12.00	8.50	8.50	8.50	8.50	6.75	6.75	7.00	7.00
9 नवंबर																
1989	9.00	9.00	9.25	9.50	11.50	11.75	12.00	12.00	8.75	8.75	8.75	9.75	7.00	7.00	7.25	7.25
13 दिसम्बर																
1989	8.75	8.75	9.25	9.50	11.50	11.75	12.00	12.00	8.50	8.75	9.00	9.00	7.00	7.00	7.25	7.25
27 दिसम्बर																
1989	8.75	8.75	9.25	9.50	11.50	11.75	12.00	12.00	8.75	8.75	9.00	9.00	7.25	7.25	7.25	7.25
17 जनवरी																
1990	8.75	9.00	9.50	9.75	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.50	7.50	7.50	7.50
31 जनवरी																
1990	8.75	9.00	9.50	9.75	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.25	9.25	9.25	7.75	8.00	8.00	8.00
20 फरवरी																
1990	8.75	9.00	9.50	9.75	11.50	11.75	12.00	12.00	9.25	9.75	9.75	9.75	7.75	8.00	8.00	8.00
12 मार्च																
1990	9.00	9.25	9.75	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	9.25	9.75	10.00	10.00	8.00	8.25	8.25	8.25
27 मार्च																
1990	9.25	9.50	10.00	10.25	11.50	11.75	12.00	12.00	9.25	9.75	9.75	9.75	8.25	8.50	8.50	8.50
7 मई																
1990	9.25	9.75	10.25	10.50	11.50	11.75	12.00	12.00	9.25	9.75	9.75	9.75	8.00	8.25	8.25	8.25
30 मई																
1990	9.00	9.50	10.00	10.25	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.50	9.75	9.75	7.75	8.00	8.00	8.00
19 जुलाई																
1990	9.00	9.50	10.00	10.25	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.50	9.75	9.75	8.25	8.25	8.25	8.25
13 अगस्त																
1990																

गया। सागरी योजना के पहले चार वर्षों में औसत ऋण - सुकीती अनुपात 21 प्रतिशत था, जो योजना वस्तावेज में मूलतः कल्पित 17.6 प्रतिशत के औसत से काफी अधिक है।

प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दरों की गतिविधियाँ

10.29 अमरीकी डालर का मूल्य निरन्तर बढ़ने से, विशेषरूप से जापानी येन के संबंध में, मसूदा 7 में शामिल देशों के मंत्री और केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों ने सितम्बर 1989 में वार्शिंगटन में हुई अपनी बैठक में विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में निकट सहयोग में कार्य करने के अपने निश्चय 211 GI/81—30

की पुनः पुष्टि की ताकि अमरीकी डालर की ओर अधिक मूल्यवृद्धि न हो अथवा उसमें अत्यधिक गिरावट न हो। प्रमुख औद्योगिक देशों द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में स्थिरता लाने के लिए दृढ़तापूर्वक कार्रवाई न करने के कारण विदेशी मुद्रा बाजारों में प्रमुख मुद्राओं के बाजार में अनियमित घट-बढ़ हुई। न्यून बाजार दरों के कारण जापान से पूँजी के निरन्तर दीर्घवधि बहिर्गमन से जापानी मुद्रा का विनिमय मूल्य गिर गया। जर्मनी के पुनः एकिकरण की संभावना से उत्पन्न मुद्रास्फीति प्रत्यक्षाओं से पश्चिम जर्मनी में व्याज दरें बढ़ा दी गयी। अमरीकी डालर के मुकाबले व्याज संबंधी अंतराल कम हो जाने से विदेशी मुद्रा बाजारों में अमरीकी

मारणी 10.17 : भारत का बाहरी ऋण

(करोड़ रुपये)

निम्नलिखित वर्षों के मार्च के अंत में

	1980**	1985	1986	1987	1988	1989अ	1990अ
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बाहरी सहायता	12,178	24,004	26,638	32,312	36,578	46,838	54,649
2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष		4,888	5,271	5,548	4,732	3,696	2,573
3. बाहरी वाणिज्यिक उधार*	1,252	6,908	8,075	11,243	13,543	19,147	24,580
4. जोड़ (1+2+3)	13,430	35,800	39,984	49,103	54,853	69,681	81,802
शायन पद							
5. सामने दी गयी राशि के समकक्ष अमरीकी डालर (मिलियन में)	16,392	28,801	32,391	37,699	42,993	44,485	47,109

\*इसमें बाहरी सहायता कार्यक्रम के अधीन गैर-सरकारी ऋण और यूरोपीय देशों से रुपये में प्रतिशत प्राप्ति का ऋण शामिल है।

\*\*भारत का अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का सर्वेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक वुलेटिन, अप्रैल 1985 पर आधारित।

#### अ—अंतर्गत

डालर के संवर्ध में ड्यूय मार्कें मुद्रा हो गया विशेषकर अक्टूबर 1981 से अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक की 1989-90 की वार्षिक रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि फरवरी 1987 में हुआ लूवर समझौता कम सफल रहा; यह तर्क दिया जाता है कि मामूली विनिमय दरों की मृदा स्तर से वर्तमान निकटता "बीच में काफी बढ़ा और बार-बार हुई घटवृद्ध का निबल परिणाम है।

10.30 मासिक औसत की दृष्टि से पिछले वर्ष अमरीकी मुद्रा सभी प्रमुख मुद्राओं के संवर्ध में सुझ हो गयी थी, 1989-90 (जुलाई-अप्रैल) के दौरान उसमें मिश्रित प्रवृत्ति परिलक्षित हुई मासिक औसत की दृष्टि से जुलाई 1989 में सभी प्रमुख मुद्राओं के संवर्ध में अमरीकी डालर में थोड़ी गिरावट आयी परन्तु अगस्त और सितंबर 1989 के दौरान उसमें बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति बनी रही, किन्तु उसके बाद अमरीकी मुद्रा, मार्च और अप्रैल 1990, महीनों के सिवाय विशेष आह्वान अधिकार के संवर्ध में नवम्बर 1989 और मार्च 1990 के सिवाय पौंड स्टर्लिंग के संवर्ध में तथा मार्च 1990 के सिवाय ड्यूय मार्क के संवर्ध में कमजोर होने लगी अक्टूबर 1989 के सिवाय आलोच्य अवधि के दौरान अमरीकी डालर में जापानी येन के संवर्ध में दृढ़ता की प्रवृत्ति बनी रही। प्रत्येक महीने की घट-बढ़ में पौंड स्टर्लिंग विशेष आह्वान अधिकार तथा अमरीकी डालर के संवर्ध में स्थिर रहा, परन्तु ड्यूय मार्क के संवर्ध में उसमें मूल्यह्रास हुआ और येन के संवर्ध में मूल्य वृद्धि हुई। इनके विपरीत, सभी प्रमुख मुद्राओं के संवर्ध में जहाँ येन कमजोर हुआ वहाँ ड्यूय मार्क में वृद्धता आयी।

#### रुपये की विनिमय दर

10.31 रुपये का मूल्य व्यापार में भारत के मुख्य सहायियों के भारत मुद्रा समूह के संबंध में निर्धारित किया जाता है और पौंड स्टर्लिंग इसकी मध्यवर्ती मुद्रा है। 1989-90 (अप्रैल-मार्च) के दौरान पौंड स्टर्लिंग दरों में 252 बार समायोजन किये गये जबकि 1988-89 (अप्रैल-मार्च) में 200 बार किये गये थे।

10.32 मार्च 1989 के अंत और मार्च 1990 के अंत के दौरान बिन्दु-दर-बिन्दु आधार पर रुपये में अमरीकी डालर के संवर्ध में 9.6 प्रतिशत तथा पौंड स्टर्लिंग के संवर्ध में 6.7 प्रतिशत की गिरावट आयी जबकि 1988-89 की तदनुगत अवधि में इनमें क्रमशः 16.8 प्रतिशत और 7.8 प्रतिशत का मूल्यह्रास हुआ था। आलोच्य अवधि के दौरान जापानी येन के संवर्ध में रुपये में 6.9 प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई जबकि 1988-89 की तदनुगत अवधि के दौरान उसका मूल्यह्रास (11.7 प्रतिशत) हुआ था। आलोच्य अवधि के दौरान अमरीकी डालर के संवर्ध में यूरोपीय मौद्रिक प्रणाली की मुद्राओं के मुद्रा होने से रुपये का फ्रांसीसी फ्रांक (19.2 प्रतिशत), ड्यूय मार्क (19.0 प्रतिशत) और स्विस फ्रांक (18.0 प्रतिशत) के संवर्ध में मूल्यह्रास हुआ। 1988-89 की तदनुगत अवधि के दौरान इन मुद्राओं के संवर्ध में रुपये में निम्नानुसार न्यून मूल्यह्रास हुआ था—5.9 प्रतिशत (फ्रांसीसी फ्रांक) और 5.4 प्रतिशत (ड्यूय मार्क)। किन्तु, 1988-89 के दौरान स्विस फ्रांक के संवर्ध में रुपये में 0.1 प्रतिशत की थोड़ी-सी मूल्यवृद्धि हुई थी। 1990-91 की पहली तिमाही अर्थात् अप्रैल-जून 1990 के दौरान प्रमुख मुद्राओं के संवर्ध में रुपये का मूल्यह्रास हुआ (मारणी 10.18)।

#### रुपया-रुबल विनिमय दर

10.33 ऋण और व्यापारिक लेनदेन के निपटान पर लागू रुपया-रुबल विनिमय दर में 1989-90 (अप्रैल-मार्च) के दौरान तीन बार परिवर्तन किये गये, अर्थात् 9 जुलाई, 10 अक्टूबर और 16 दिसम्बर 1989 को। तदनुसार, रुपया-रुबल दर मार्च 1989 के अंत में 18.11 प्रति रुबल से 9.1 प्रतिशत कम होकर मार्च 1990 के अंत में 19.92 प्रति रुबल रह गई। 10 मई 1990 को इसे फिर बदलकर 20.5520 रुपये प्रति रुबल कर दिया गया।

## अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक उतार-चढ़ाव

10.34 वर्ष 1989 से तथा 1990 के प्रारंभिक महीनों में विश्व के आर्थिक कार्यकाल में रुकने का प्रारंभिक संकेत है। औद्योगिक देशों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वार्षिक वृद्धि 1988 के 4.4 प्रतिशत से कम होकर 1989 में 3.5 प्रतिशत रह गई जो अधिकांश औद्योगिक देशों द्वारा उत्पादक क्षमता तथा मूल्यों पर पड़ने वाले दबाव दूर करने के लिये अपनायी जाने वाली प्रतिस्पर्धात्मक मुद्रागत नीतियों की वजह से है। आशा है कि इन देशों में 1990 के दौरान वृद्धि की दर और गिर कर 2.7 प्रतिशत रह जायेगी। विकासशील देशों के कार्यकालों पर औद्योगिक देशों के कार्य-निष्पादन और नीतियों के बहुत अधिक प्रभाव को देखते हुए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि समूह के रूप में 1989 में विकासशील देशों के उत्पादन की 3.0 प्रतिशत की वृद्धि दर 1988 के 4.1 प्रतिशत से कम थी। अनुमान लगाया जाता है कि 1990 के दौरान विकासशील देशों में आर्थिक वृद्धि पिछले वर्ष की उक्त वृद्धि के समान ही होगी।

10.35 औद्योगिक देशों में उपभोक्ता मूल्यों में सुधारफाँट 1989 में 1 प्रतिशत अंक से आठ-मी बढ़कर 4.4 प्रतिशत हो गई। इसका कारण क्षमता के उपयोग की उच्च दर, कुछ देशों में परीक्षा करने में वृद्धि तथा विश्व के तेल, खाद्यान्न और धातुओं के मूल्यों में तेल वृद्धि हो सकती है। विकासशील देशों में मुद्रास्फीति की दरों में तेज बढ़ोतरी हुई जिसका कारण, कई उच्च मुद्रास्फीति वाले देश हैं। 1990 के अनुमानों में पता चलता है कि देशों के दोनों समूहों में मुद्रास्फीति की दरें कम हो जायेंगी। इनका आर्थिक कारण माँग में अनुमानित कमी है।

10.36 1989 के दौरान विश्व-व्यापार के परिमाण में 7.2 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है जो 1988 में 9.1 प्रतिशत का अनुपात के रूप में अधिक वृद्धि दर से कम है, इससे भी आर्थिक मंदी परिलक्षित होती है। फिर भी, 1989 में विश्व व्यापार में उत्पादन वृद्धि की दुगुनी वृद्धि हुई। 1990 और 1991 में विश्व-व्यापार की वृद्धि दर और कम होकर 6.0-6.5 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है, जो आर्थिक गतिविधियों में और भी गिरावट एवं विशेष-रूप से विश्वव्यापी निवेश की घाटी वृद्धि की वजह से है, यह माँग का घटक है जो अर्थव्यवस्था के व्यापार प्रधान है। औद्योगिक देशों में संरक्षणवाद बना हुआ है। इस बात से मते हैं कि 1992 में यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच गरीब व्यापार बाधाएँ दूर कर दिए जाने से शेष विश्व के प्रति बाधाएँ कम हो जायेंगी। द्वितीय समझौतों की प्रगति हो रही है जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका-कनाडा समझौते, संयुक्त राज्य अमेरिका-जापान समझौते में पता चलता है, तथा यू.एस. ओमनीवर्स ट्रेड एंड कंपटिबिलिटी एक्ट 1988 के उपबन्धों के अधीन दोनों ओर से प्रतिकारत्मक व्यापार प्रतिबंध लागू किये जाने की आशंका है। उक्त दो ओर में व्यापार संबंधों में भी अभी तक अधिक प्रगति नहीं हुई है।

10.37 तीन सबसे बड़े देशों के बाह्य चालू खाते के असंतुलन अभी तक काफी बड़े हैं जिससे असंतुलन कम करने में की गयी काफी प्रगति के बावजूद भारी आर्थिक स्थिति धंधली होने की संभावना है। जापान के बाहरी अधिशेष में गिरावट आती रही तथा 1989 में वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 2.0 प्रतिशत रह गया जबकि 1988 में वह 2.8 प्रतिशत था। संयुक्त राज्य अमेरिका में घाटा कम होकर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 2.0 प्रतिशत रह गया जबकि 1988 में वह 2.6 प्रतिशत था। किन्तु, आजकल इन संबंधों में समायोजन की प्रक्रिया धीमी हो गई लगती है जैसा कि यूनान के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मूल्यवृद्धि से पता चलता है। जर्मनी गंभीर गणराज्य में बाहरी अधिशेष 1988 के सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 4.0 प्रतिशत से बढ़कर 1989 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 4.4 प्रतिशत हो गया। यदि तीन बड़े देशों में वित्तीय दर के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति बनी रहे और यदि आर्थिक नीतियों में परिवर्तन न हो तो तीन बड़े औद्योगिक देशों के चालू खातों के असंतुलन का वर्तमान आकार कम नहीं होगा एवं अन्य औद्योगिक देशों का चालू खाता असंतुलन बढ़ जायेगा जिसके लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अतः, औद्योगिक देशों के अधिशेष विकासशील देशों में लगाये जाने की कोई आशा नहीं है। पूर्वी यूरोप में बाजार के नाटकीय समायोजन ने इन आशंकाओं को गहरा दिया है जिनके लिये भारी वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी।

10.38 1989 के अंत में सभी विकासशील देशों का कुल ऋण (1,214 बिलियन डॉलर) लगभग पिछले वर्ष के स्तर (1,216 बिलियन डॉलर) पर ही रहा। एशिया के विकासशील देशों के 336 बिलियन डॉलर (सकल देशी उत्पाद का 22 प्रतिशत) के बाहरी ऋण में आलोच्य वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पश्चिमी गोलार्ध में बाजार पर आधारित ऋण षटान के कार्यों जैसे, पुनः ऋण-ईविषटी विनिमय तथा निजी क्षेत्र के बहुमत पूर्व-मुगलानों से पश्चिमी गोलार्ध के ऋण से केवल थोड़ी-सी कमी हुई। वह 1988 के 401 बिलियन डॉलर से कम होकर 399 बिलियन डॉलर हो गया क्योंकि ऋण कटौती के लिये केवल थोड़े से देशों को लिया गया है। अफ्रीका का 195 बिलियन डॉलर (सकल देशी उत्पाद का 50 प्रतिशत) का ऋण लगभग अपरिवर्तित रहा।

10.39 1989-90 के लिये विश्व बैंक की ऋण सारणियों के अनुसार विकासशील देशों को बाहरी समायोजनों की निम्न प्राप्ति 1989 में 26 बिलियन डॉलर थी जो 1988 के 20 बिलियन डॉलर से अधिक है। किन्तु 1981 में वे 84 बिलियन डॉलर थी। इसके अतिरिक्त, उच्च व्याज भुगतानों के कारण विकासशील देशों से उनके लेनदारों को निम्न अंतराणों की राशि पिछले वर्ष के 52 बिलियन डॉलर के स्तर पर अपरिवर्तित रही। यह प्रतिकूल प्रवाह 1983 में शुरू हुआ था और सात वर्षों के दौरान इसमें 243 बिलियन डॉलर व्यय हो गये हैं, इनमें अधिकांश अत्यधिक ऋणग्रस्त देश थे।

## सारणी 10.8: रुपया विनिमय दरें

(विशेष आहरण अधिकार/विदेशी मुद्रा की प्रति यूनिट के बराबर रुपये)

अवधि	विशेष आहरण अधिकार	अमेरिकी डॉलर	पोड स्टर्लिंग	इयूश मार्क	येन
1	2	3	4	5	6
आ. वार्षिक औसत दरें (अप्रैल-मार्च)					
1985-86	12.9232 (—7.7)	12.2349 (—2.8)	16.8467 (—11.8)	4.5553 (—12.5)	0.0562 (—13.3)

1	2	3	4	5	6
1986-87	15.4472 (—16.3)	12.7782 (—4.3)	19.0722 (—11.7)	6.2970 (—27.7)	0.0802 (—29.9)
1987-88	17.1208 (—9.8)	12.9658 (—1.4)	22.0872 (—13.7)	7.4004 (—14.9)	0.0941 (—14.8)
1988-89	19.2619 (—11.1)	14.4817 (—10.5)	25.5959 (—13.7)	8.0494 (—8.1)	0.1130 (—16.7)
1989-90	21.3684 (—9.9)	16.6492 (—13.0)	26.9179 (—4.9)	9.0922 (—11.5)	0.1166 (—3.1)
घा. मासिक भौसत करें					
मार्च 1988]	17.8284	12.9793	23.7897	7.7435	0.1021
मार्च 1989	20.1989	15.5137	26.5858	8.3083	0.1190
मार्च 1990	22.2961	17.1274	17.8218	10.0454	0.1118
मार्च 1989 की तुलना में	(—9.4)	(—9.4)	(—4.4)	(—17.3)	(+6.4)
मार्च 1990 में प्रतिशत					
मूल्यवृद्धि (+)					
मूल्यह्रास (—)					
जून 1989	20.4079	16.4349	25.5284	8.3079	0.1141
जून 1990	22.9224	17.4206	29.7858	10.3484	0.1113
जून 1989 की तुलना में	(—11.0)	(—5.7)	(—14.3)	(—19.7)	(+0.7)
जून 1990 में प्रतिशत					
मूल्यवृद्धि (+)					
मूल्यह्रास (—)					
इ. निम्नलिखित सारीख को विनिमय करें					
31 मार्च 1988	17.9703	13.0318	24.35	7.8308	0.1042
31 मार्च 1989	20.2082	15.6630	26.40	8.2764	0.1180
30 मार्च 1990	22.4090	17.3248	28.30	10.2118	0.1104
30 जून 1989	20.7035	16.5808	25.75	8.4807	0.1156
30 जून 1990	23.1820	17.5439	30.50	10.5180	0.1145

टिप्पणी :—कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े रुपये की प्रतिशत मूल्यवृद्धि (+)/मूल्यह्रास (—) दर्शाते हैं।

10.40 फिलहाल, ऐसे बहुत-से घटक हैं जिनके कारण अन्धवध और मध्यावधि विश्वव्यापी आर्थिक संभावनाओं का पूर्वानुमान लगाना जोखिमपूर्ण है। अन्य बातों के साथ-साथ, 1989 की तीव्र निमात्री से पूर्वी यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं के नेजी से बाजार-उन्मुख होने, चीनो जर्मनी के एकीकरण की संभावना तथा भविष्य में यूरोपीय समुदाय में मुद्रागत तथा आर्थिक एकता की संभावनाओं का उल्लेख किया जा सकता है।

10.41 विकसनीय देशों के दृष्टिकोण से चालू आर्थिक स्थिति तथा संभावनाएं उत्पादक नहीं हैं। प्रारंभ में ब्रेडो प्लान में जो अणु में कारण कटौती की आशा उत्पन्न हुई थी, पूरी नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों की निधियों तक बहुत-से विकसनीय देशों की पहुँच सीमित है। बल्कि, इन देशों के निबल अणु, 1989 में बाजारों से जुटायी गयी निधियों के 10 प्रतिशत में भी कम थे। मुख्यतः, तेल में इनर प्राथमिक पण्यों के निर्यातों में गिरावट के कारण 1990 के दौरान विकसनीय देशों की व्यापार-स्थिति गिर जाने का अनुमान है। 1990 के दौरान विकसनीय देशों का बाहरी चालू

खाता घाटा बढ़ जायेगा। आशा है वार्षिक बँसों में निबल अणु अणुत्मक होगा। निकट भविष्य में विशेष आहरण अधिकार का आबंटन पुनः प्राप्त होने की आशा नहीं है। मई 1990 में हुई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अंतरिम समिति की बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुल फंडा संसाधन 50 प्रतिशत बढ़ाकर 135 बिलियन विशेष आहरण अधिकार कर दिया जाये बनें कोष की वित्तीय स्थिति मजबूत करने से संबंधित कतिपय शर्तें पूरी की जाये। 1991 के अंत तक के कोटे में वृद्धि होने की संभावना है। कोष के काया संसाधनों में उचित बढ़ोतरी किये जाने पर भी पूर्वी यूरोप को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता के कारण विकसनीय देशों का उल्लेख संसाधनों में विशेष वृद्धि नहीं होगी। यह महत्वपूर्ण बात है कि समूह के रूप में बड़े विकसनीय देशों के निधियों के लाना प्रमुख श्रोत अर्थात् आधिकारिक लेनदार, वार्षिक बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अणुत्मक हो गये हैं क्योंकि उनकी चुकौती राशियाँ नई संवितरण राशियों से अधिक हैं।



## 11. मध्योत्तर और संभावनाएं

## विकास परिकल्पना

11.1 1989-90 के दौरान भारतीय ग्रामीण स्थिति ने संतोषजनक वृद्धि दर प्राप्त की। 1988-89 के दौरान वास्तविक सकल देशी उत्पाद में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कृषि जल्य सकल देशी उत्पाद में 18.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस पृष्ठभूमि में, 1989-90 के दौरान वास्तविक सकल देशी उत्पाद में हुई करीब 1.5 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि निम्नलिखित ही प्रशंसनीय है। खाद्यान्न का उत्पादन 173 मिलियन टन के तले शिखर स्तर पर पहुंच गया तथा कई वाणिज्यिक फसलों में भी काफी वृद्धि हुई। एक स्वागत योग्य समीक्षिणी यह थी कि छोटे अनाज और बागों के उत्पादन में लगातार दूसरे वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो अनाज की वृद्धि से कुछ बेहतर क्षेत्रीय विस्तार दर्शाती है। जहां तक औद्योगिक कार्य निष्पादन का संबंध है, वर्ष के अधिकांश भाग में घरेलू औद्योगिक वृद्धि हुई, परन्तु अंतिम तिमाही में उल्लेखनीय वृद्धि होने से समग्र रूप से वर्ष 1989-90 में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि परिणतित हुई जो 1988-89 की वृद्धि (8.7 प्रतिशत) के मुकाबले केवल थोड़ी सी कम है। मूल, मध्यवर्गीय और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु उद्योगों की वृद्धि दर में जहां कमी आयी, वहीं पूंजीगत वस्तुओं तथा गैर टिकाऊ उपभोक्ता औद्योगिक वस्तुओं की वृद्धि दरों में 1989-90 के दौरान सुधार हुआ। निर्माण वृद्धि की दृढ़ गति, जो खास तौर से तैयार वस्तुओं में पायी गयी, से औद्योगिक वृद्धि की गति को बनाये रखने में सहायता मिली। 1989-90 के दौरान निर्यातों में रुपये की दृष्टि से 36.3 प्रतिशत या क्रियेप आहरेण अधिकांश की दृष्टि से 22.9 प्रतिशत, या मात्रा की दृष्टि से करीब 14.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो निर्यात प्रभावशाली कार्य निष्पादन है। 1989-90 के दौरान कुछ निर्यातों का लगभग तीन चौथाई से अधिक अंश तैयार वस्तुओं के निर्यात का था। किन्तु अच्छे मानसून के लगातार दूसरे वर्ष में नीच मूल्य वृद्धि, निर्यात बना हुआ भारी राजकोपीय घाटा और निर्यात में भारी वृद्धि के बावजूद भुगतान संतुलन पर पड़ने वाला बकाया चिन्ता के मुख्य क्षेत्र थे।

11.2 अनेक निर्देशकों से यह आभास मिलता है कि 1990-91 जो कि आठवीं योजना का पहला वर्ष है, में विकास को उत्पादक संभावनाएं हैं, क्योंकि घटक तत्वों में वृद्धि से वास्तविक सकल देशी उत्पाद में लगभग 5.0 प्रतिशत की वृद्धि होना की संभावना है। 1990 की दक्षिण-पश्चिम मानसून की सीमायें विज्ञान संबंधी सूचनारों के अनुसार वर्षों की अब तक पानी नियमित है और खरीफ सीमों की आशापूर्ण संभावना है। इस परिप्रेक्ष्य में, 1990-91 का 176.5 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य तथा साथ ही तिलहन, गेहूँ और कई के उच्च लक्ष्य की प्राप्ति किये जाने की संभावना है, इनमें कृषि उत्पादन के सूचकांक में करीब 3 प्रतिशत की समग्र वृद्धि होने की संभावना है। जहां तक औद्योगिक विकास का संबंध है, घाटे की वित्त व्यवस्था को सीमित करने की अनिवार्य आवश्यकता के कारण सरकारी क्षेत्र के निवेश की गति में कुछ सीमा तक कमी का संकट है। हालांकि निजी कानूनी क्षेत्र की नयी परियोजनाओं में निवेश में कमी के कुछ संकेत हैं, फिर भी पिछले वर्षों में शुरू की गयी परियोजनाओं के कारण हो सकता है कि चारू वर्ष में निजी क्षेत्र के समग्र निवेश में कमी न आयी। विश्व व्यापार की वृद्धि में कमी आने की संभावना व्यक्त की गयी है, यदि यह कमी आती है तो संभाव्य धन में निर्यातों पर प्रभाव पड़ सकता है, परन्तु अव्यवधि में निर्यात की गति बनी रहने की संभावना है। जहां तक धनी उपभोग की मात्रा का संबंध है, यदि कृषि आय में लगातार तीसरे वर्ष भी वृद्धि होती है, जैसा कि आशा है तो गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में 1989-90 में आयी तेजा 1990-91 में भी जारी रह सकती है। औद्योगिक उत्पादन में करीब 8 प्रतिशत की समग्र वृद्धि की आशा की जा सकती है। किन्तु यदि मूल्य वृद्धि का उच्चतम सीमा के सीतर रखता है तो राजकोपीय घाटे और उसके फलस्वरूप होने वाली गुंता जालिंध में काफी कमी आना जरूरी है।

## मानवी योजना कार्य-निष्पादन

11.3 1989-90 मानवी योजना का अंतिम वर्ष है तथा यह समीक्षाधीन वर्ष भी है और चूंकि वह समाप्त हो रहा है अब इस योजना

के समग्र कार्य-निष्पादन पर एक तजर डालना सीनीत होगा। सक्षम देशी उत्पाद की समग्र वृद्धि दर तथा कृषि और उद्योग संबंधी योजना लक्ष्यों को पार कर लिया गया है। तीन खराब फसलों के बावजूद, मानवी योजना अवधि में कृषि उत्पादन की औसत वृद्धि दर वार्षिक 1.0 प्रतिशत के योजना लक्ष्य के करीब ही है। किन्तु क्षेत्रीय असमानताएं और फसल असंतुलन बने हुए हैं। औद्योगिक उत्पादन की औसत वृद्धि 8.1 प्रतिशत है जो वार्षिक 8.0 प्रतिशत के योजना लक्ष्य से अधिक है। उपयोग आधारित श्रमिकों की दृष्टि में जिनके संबंध में योजना के कारण पड़ने वाले वर्गों के आंकड़े उपलब्ध हैं, पूंजीगत वस्तु उद्योगों में 13.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि मूल उद्योगों और मध्यवर्गीय वस्तु उद्योगों में क्रमशः 8.9 प्रतिशत और 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उपभोक्ता वस्तु उद्योगों की वृद्धि दर 8.0 प्रतिशत है। उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के सीतर जहां गैर टिकाऊ वस्तुओं में वार्षिक 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं टिकाऊ वस्तु उद्योगों में वार्षिक 16.9 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की उच्च वृद्धि दर संगठित क्षेत्र में आय में सीधे वृद्धि का प्रतिफल है। किन्तु इस बात पर ध्यान देने का जरूरत है कि गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का वार्षिक 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर भी योजना के पिछले तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र द्वारा प्राप्त की गयी उच्चतम वृद्धि दर है।

11.4 किन्तु वास्तविक क्षेत्र के संतोषजनक कार्य निष्पादन के बावजूद 1989-90 के दौरान अनेक गंभीर स्थूल आर्थिक असंतुलन और विकृतियां उभर आयी हैं। सर्वप्रथम तो है बजट घाटों के उच्च स्तर जो लगभग वर्ष दर वर्ष सामने आये और इसके परिणामस्वरूप मुद्रा उपलब्धि पर विस्तारकारी प्रभाव पड़ा। दूसरी बात है भुगतान संतुलन पर पड़ने वाला बकाया जिसमें सकल देशी उत्पाद के अनुपात के रूप में बाह्य ऋण का घाटा सातवीं योजना के दस्तावेज में उल्लिखित स्तरों में काफी अधिक हो गया है। इन दो बिंदुओं पर आगे के पैराग्राफों में कांफें विस्तार में चर्चा की गयी है।

## राजगार प्रवृत्तियां तथा नीति

11.5 राजगार में सीमा वृद्धि परंपरागत करने वाली एक अस्थिर बात रही है। राजगार की वृद्धि का दर में स्पष्ट गिरावट आयी है, विशेषकर में नौवें दशक में जब प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र के उत्पादन के संदर्भ में राजगार सापेक्षता में कमी आयी। योजना आयोग के एक अध्ययन के अनुसार 1972-73 और 1977-78 के बीच राजगार वृद्धि वार्षिक 2.82 प्रतिशत थी। 1977-78 से 1983 तक की अवधि के दौरान यह घटकर वार्षिक 2.22 प्रतिशत तथा 1983 और 1987 के बीच आगे घटकर 1.55 प्रतिशत हो गयी। राजगार वृद्धि में यह कमी कर्मचारियों के नौवें घटका-आयोग और जारी, पुरुषों और महिलाओं तथा सभी क्षेत्रों में पाया गयी परन्तु खास तौर पर निर्यात इलाका प्रभाव है। कृषि तथा संगठित क्षेत्र में राजगार की वृद्धि दर में गिरावट काफी तीव्र है। नौवें दशक में संगठित क्षेत्र में वृद्धि प्रमुख रूप से सरकारी क्षेत्र के कारण हुई है। इन प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप पहले में चर्चा का रूढ़ी रोजगारी बृद्ध रही है। राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्व के आंकड़ों पर आधारित योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार आठवीं योजना के प्रारंभ में ऐसी बेरोजगारी करीब 28 मिलियन मानी गयी है और अंतिम में अनुमानित वृद्धि में जिन लोगों को राजगार चाहिए, उनकी कुल संख्या 1990-91 से 1994-95 के दौरान 65 मिलियन तथा 1990-2000 के दशक के दौरान 106 मिलियन होगी। यह अनुमान लगाया गया है कि उत्पादन के संदर्भ में 0.38 की वर्तमान राजगार सापेक्षता को बताने स्या जाए तो 1995 तक पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए सकल देशी उत्पाद की अपेक्षित वृद्धि दर वार्षिक 10.5 प्रतिशत होगी और यदि 2000 ईसवी तक उसे प्राप्त करना हो तो वह 8 प्रतिशत होगी। इसी पृष्ठभूमि में आठवीं योजना ने वार्षिक 3 प्रतिशत की राजगार वृद्धि का लक्ष्य रखा है जिसका आशय उत्पादन के संदर्भ में (मूल देशी उत्पाद में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर के अनुमान के आधार पर) करीब 0.6 प्रतिशत रोजगार-सापेक्षता है जबकि पिछले कुछ समय में यह

11 10 हम सर्वभूमि म आशा की एक किण्व पिछले चार वर्षों के धारण निर्यातों म हुई जोरदार वृद्धि है जो अमेरिकी डालर की दृष्टि में औसतन षण्ण 17 0 प्रतिशत और विशेष आह्वण अवधि का वृद्धि में 11 8 प्रतिशत वार्षिक रही । इस अवधि में निर्यातों म वार्षिक

श्रीमत् परिणामगत वृद्धि 10 से 12 प्रतिशत की जो इस तरह मानवी योजना के दस्तावेज में परिकल्पित 7 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि से अधिक है। वित्तीय निर्यात संवर्धन 1986 से निर्यातों में हुई वृद्धि को लक्ष्य रखने में सहायता मिली है। इस नीति में राजकीय विनियमों की गयी हैं, जिनमें आयात के निर्यात लाभों को पूर्ण छूट, व्याज दर रियाज, निर्यात उत्पादन के लिए अमना बढ़ाने हेतु उपाय, आयकर निर्धारणों की बेहतर उपलब्धता तथा समबंध विनिमय दर नीति शामिल है। विषय व्यापार की दृष्टि में तेजी के वातावरण में भी निर्यात प्रयास को सहायता मिली है। हालांकि निर्यातों की स्थिति अच्छी रही है, फिर भी निर्यातों की आयात प्रवृत्ति बढ़ रही है। यदि निर्यात संबंधित आयातों के लिए निर्यात और आयात संबंधी कुल आंकड़ों को समायोजित किया जाए तो वार्षिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार निर्यात-आयात अनुपात में थोड़ी सी ही वृद्धि हुई है और वह 1984-85 के 64 प्रतिशत से बढ़कर 1988-89 में 65 प्रतिशत हुआ है। किन्तु उक्त अनुपात में 1989-90 में तीव्र वृद्धि हुई और वह 73 प्रतिशत हो गया।

11.11 जहाँ तक आयातों का संबंध है शुद्ध तेल आयात 1984-85 के 12.3 मिलियन टन से बढ़कर 1988-89 में 21.8 मिलियन टन होने के बावजूद योजना अवधि के दौरान डालर की दृष्टि से तेल के आयातों (तेल के निर्यातों को घटाकर) में कमी आयी है। तेल के मूल्यों में आयी कमी से तेल के आयात बिल की वृद्धि को कम करने में सहायता मिली। परन्तु तेल के आयात बिल में कमी के कारण सामग्री योजना अवधि के दौरान अमेरिकी डालर की दृष्टि से कुल आयातों की वार्षिक औसत वृद्धि 8.2 प्रतिशत थी जबकि छठी योजना अवधि में यह 6.2 प्रतिशत थी। योजना अवधि के पहले दो वर्षों के दौरान आयातों में मात्रा की दृष्टि से वृद्धि औसतन करीब 16.5 प्रतिशत वार्षिक थी। योजना अवधि के दौरान समग्र रूप से, सौदे अनुमानों के अनुसार मात्रा की दृष्टि से आयातों में वृद्धि वार्षिक 9.0 प्रतिशत से अधिक हो सकती है। अर्थात् वार्षिक 5.8 प्रतिशत के योजना अनुमान से वह काफी अधिक होगी। आयातों की आय आपेक्षित मानवी योजना अवधि के दौरान करीब 1.73 रही है जबकि छठी योजना में वह 1.20 थी।

11.12 ऊपर उल्लिखित आयातों की वृद्धि दरें वार्षिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय के आंकड़ों पर आधारित हैं। भुगतान संतुलन के आंकड़ों के अनुसार आयात वृद्धि और भी अधिक थी क्योंकि वार्षिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय के आंकड़ों में ऐसे कुछ आयात शामिल नहीं हैं जिनके लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति अपेक्षित नहीं है। योजना अवधि के पहले चार वर्षों के दौरान जहाँ वार्षिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय के आंकड़ों आयातों में 8.0 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर्शाते हैं, वहीं भुगतान संतुलन के आंकड़े 11.2 प्रतिशत की उच्च आयात वृद्धि (दोनों ही अमेरिकी डालर की दृष्टि से) दर्शाते हैं।

11.13 यद्यपि योजना अवधि के दौरान व्यापार घाटा अधिक था, तथापि, व्यापार घाटे को समायोजित करने में शुद्ध अव्यय मर्दानों का योगदान प्रसन्न रूप से कम हो गया। इसका कारण था बढ़ते हुए विदेशी ऋण पर न्याज के भुगतान में तीव्र वृद्धि तथा विदेशी सहायता कारागों के अंतर्गत टेक्नोलॉजी के आयात के साथ सम्बद्ध टेक्नोलॉजियों की फीस, तकनीकी जानकारी, रॉयल्टी आदि के भुगतानों में वृद्धि। इसके साथ ही, अव्यय अर्जन के प्रमुख स्रोत निजी अंतरण प्राप्तियों में काफी प्रीमापन रहा। इसके परिणामस्वरूप अधिकारिक अंतरणों में भिन्न गृह अव्यय प्राप्तियों में जहाँ 1984-85 में व्यापार घाटे के 51 प्रतिशत का वित्तपोषण हुआ था वह 1988-89 तक के केवल 21 प्रतिशत भाग का ही वित्तपोषण कर सकी।

11.14 वायुय क्षेत्र के अकार को देखते हुए, मानवी योजना की अवधि में हुआ वायुय क्षेत्र का घाटा काफी अधिक था और वह चिन्ता का विषय है। यह जरूरी है कि वायुय क्षेत्र के घाटे को घटाकर सकल

देशी उद्देश्य के अनुसार 1.5 प्रतिशत तक लाया जाये। इस वर्ष के लिए मुख्य रूप से निर्यात बचाने पर देखा होगा। वस्तुतः यदि निर्यात में आयात के अण का वर्तमान स्तर जारी रहता है तो यह जरूरी है कि निर्यातों में अधिक तेजी से वृद्धि हो, जैसे मानवी की दृष्टि से प्रति वर्ष 12-14 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो ताकि व्यापार घाटे का कम चित्रा आ सके। निर्यातों में आयात के अण की प्रधान की आवश्यकता है। हमारे निर्यातों में अण प्रधान निमित्त उत्पादों और कृषि आधारित उत्पादों पर अधिकाधिक ध्यान दिये जाने की जरूरत है। यह आवश्यक है कि बड़े और मझोले कंपनी क्षेत्र सहित सभी उत्पादक संस्थाएं निर्यात कार्य में गंभीरता से सम्बद्ध हो जाये। इस क्षेत्र को अवतक के मकावने की अधिक मज्बूत भूमिका निभानी है।

11.15 निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ आयातों की संरचना पर भी बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। पूंजीगत वस्तुओं के आयात में सातवी योजना के पहले दो वर्षों में भारी वृद्धि के बाद, अगले दो वर्षों में सामान्य वृद्धि दर्ज हुई, किन्तु 1989-90 में एक बार पुनः पर्याप्त वृद्धि हुई। पूंजीगत वस्तु समूह की कुछ श्रेणियों में वृद्धि परिलक्षित हुई। डालर की दृष्टि से जहाँ विजयों ने अंतर मशीनों के आयात में 1987-88 से कमी आयी है, वहीं विजयों की वस्तुओं और उपकरणों के आयातों में 1988-89 में 32 प्रतिशत के करीब वृद्धि हुई, हालांकि 1989-90 में इनमें सामान्य वृद्धि हुई है। जहाँ मध्यवर्ती और पूंजीगत वस्तु उद्योगों की टेक्नोलॉजी को उन्नत करने और उसकी क्षमता की दृष्टि से औद्योगिक और व्यापार नीतियों में बल दिया जाना है, वहीं कुछ प्रार्थमिकता भी निश्चित करने होगी।

11.16 अव्यय मर्दानों के क्षेत्र में अर्जन के मुख्य स्रोत पर्यटन और निजी अंतरण हैं। पर्यटकों की संख्या में 1987-88, 1988-89 में कमी आई और 1989-90 में सुधार हुआ है। हमें धनार्थ रखने तथा इसमें और सुधार करने की जरूरत है निजी अंतरणों में मुख्य रूप से निवास भारतीयों में प्राप्त जाल प्रेषण आते हैं, इनकी स्थिति 1981-82 में अमान्य पर अपरिवर्तित बनी हुई है। इसका आंशिक कारण खाली क्षेत्र में भारतीय कामगारों की आय में आयी कुछ कमी तथा साथ ही जालू तकदी प्रेषणों के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रतिवासी जमा राशियों को प्रतिस्थापित करने का उपाय हो सकता है।

11.17 अब तक जालू खाने के घाटे का अधिकांश वित्तपोषण विदेशी सहायता, वार्षिक उधारों तथा अतिवासी भारतीयों की जमा राशियों द्वारा किया गया है। रियायती सहायता की संभावना अच्छी नहीं है। बहुपक्षीय संस्थाओं से मिलने वाले ऋण की गतों पहले ही कठोर हो गयी है तथा बहुपक्षीय और द्विपक्षीय प्रदाताओं के संसाधनों के कई दावेदार हो गये हैं। जहाँ तक वार्षिक उधारों का संबंध है वे यद्यपि, हमने सूझ-बूझ की नीति अपनायी है, तथापि, उधार के इस स्रोत पर निर्भरता पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही है। हालांकि भारत ऋण शोधन के अपने अच्छे रिकार्ड के कारण आमतौर पर पूंजी बाजार से उधार लेना जारी रख सकता है, फिर भी और अधिक सतर्कता पर बल देने की हमारी नीति उचित है। विदेश में व्याज दरों में वृद्धि को देखते हुए विदेशी मुद्रा प्रतिवासी खाता योजना के अधीन प्रतिवासी भारतीयों की निधियों का प्रवाह भी वित्तपोषण का एक उच्च लायनवाला स्रोत बनता जा रहा है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पूंजी की प्राप्ति बहुत कम है और वह वार्षिक करीब 200 मिलियन डालर है जबकि इसकी तुलना में एशिया के अन्य कई देशों के सदर्भ में प्राप्ति का काफी अधिक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिक प्राप्ति से हालांकि भुगतान संतुलन पर पड़नेवाले दबाव को कम करने में सहायता मिलेगी।

11.18 खाडी क्षेत्र में हाल की गतिविधियों से देश के भुगतान संतुलन पर दबाव बढ़ने की संभावना है। कच्चे तेल की कीमत प्रारंभ में प्रति बैरल 17 डॉलर से बढ़कर मार्च 1990 में प्रति बैरल 23 डॉलर होने के बाद अगस्त 1990 के मध्य में प्रति बैरल 27 डॉलर तक पहुँच गयी। तेल का जालू मुख्य 27 जुलाई, 1990 के पेट्रोलियम निर्यातक देशों

के संगठन के करार में सहमत प्रति वैद्य 21 जालर के "न्यूनतम सुदमं मूल्य" की तुलना में काफी अधिक है। तेल के मूल्यों में वृद्धि से पेट्रो-लियम, तेल और विक्रान्तों के पवार्थ संबंधी आयात बिल तथा साथ ही आयातित उर्वरकों की लागत बहुत बढ़ जायेगी। इस क्षेत्र से निजी प्रेषण और अनिवार्य जमागणियों के प्रवाह पर पड़ने वाला प्रभाव हम बात पर निर्भर करेगा कि अन्तः स्थिति क्या रूप लेती है। हाल के वर्षों में तेल का आयात बढ़ रहा है क्योंकि तेल की खपत में वार्षिक 7-8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है अतः इस बात की बहुत जरूरत है कि पेट्रो-लियम, तेल और विक्रान्तों के पवार्थ के उत्पादों की खपत को शीघ्र नियंत्रित करने के लिए व्यापक संरक्षण उपाय किये जायें। हालांकि घटनाओं से हम बात की बाधना और बढ़ गयी है कि खालू खाने के घाटे को काफी कम किया जाये।

वित्तीय व्यवस्था पर निगरानी

11.19 हाल के वर्षों में भारतीय वित्तीय व्यवस्था अतिशय विकसित और वैविध्यपूर्ण हुई है तथा वित्तीय बाजार अल्पावधि प्रतिभूतियों से दीर्घावधि प्रतिभूतियों के कारोबार की विधा में सतत रूप से विकसित हो रहा है। पूंजी बाजार के साथ बैंकों का संपर्क बढ़ रहा है और वे अपने कार्यकलापों को वैविध्यपूर्ण बना रहे हैं, और यह कार्य प्रकर उन सहायक संस्थाओं को स्थापित करके किया जा रहा है, जो जमागणियां जुटाती हैं, और कई तरह की वित्तीय सेवाएं हाथ में लेती हैं। अधिकाधिक निजी क्षेत्र की वित्तीय कंपनियों भी इस उद्देश्य से सार्वजनिक जमागणियां इकट्ठा करती हैं कि विविध प्रकार के वित्तीय कार्यक्रमों प्रारंभ किये जायें। साथ ही, भारतीय युनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा नियम, सामान्य बीमा नियम सहित गैर-वैकिंग वित्तीय संस्थाएं भी मियादी वित्त के तथा मुद्रा बाजार के महत्वपूर्ण उधारदाता बन गये हैं। वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों की राशि मार्च 1989 के अंत में 89,000 करोड़ रुपये थी जो वाणिज्य और सरकारी बैंकों की लगभग 1,77,000 करोड़ रुपये की आस्ति के साथ तुलनीय है। कुल वित्तीय आस्तियों में वित्तीय संस्थाओं का अंश मार्च 1981 के अंत के लगभग 27 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 1989 के अंत में 34 प्रतिशत हो गया। ये गतिविधियां इस बात की आवश्यकता रेखांकित करती हैं कि वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के कार्य-कलापों का समेकित पुनरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि मुद्रा और ऋण नीतियों के अमल के लिए एक अधिक व्यापक आधार प्रस्तुत किया जा सके। इसके अलावा चूंकि गैर-वैकिंग वित्तीय संस्थाओं और कंपनियों की वृद्धि और आस्तियां तेजी से बढ़ रही हैं, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वे अपना कारोबार विवेक के साथ चलाती हैं तथा स्वस्थ वित्तीय स्थिति बनाये रखती हैं। इसके लिए जहां कहीं आवश्यक हो वहां तब संगत विनियम लागू करना आवश्यक होगा। अतः रिजर्व बैंक अपने पर्यवेक्षक की सीमा को बैंकों से आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है ताकि व्यापक वित्तीय प्रणाली निर्धारित की जा सके। बैंकों तथा उसकी सहायगी संस्थाओं पर समेकित पर्यवेक्षण लागू करने के लिए उपाय प्रारंभ किये जा चुके हैं। महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के कार्यकलापों के बृद्धाकार को तथा ऋण और मुद्रा क्षेत्रों एवं पूंजी बाजार पर उनके प्रभाव को देखते हुए, रिजर्व बैंक आधिकारिक सफलता की और वित्तीय संस्थाओं के दीर्घस्थायी प्रभावों के साथ संरचनात्मक परामर्श की एक प्रणाली प्रारंभ करना चाहता है। वित्तीय संस्थाओं के संबंध में रिजर्व बैंक की ही भूमिका का, वित्तीय प्रणाली की आस्तियों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करते हुए तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की नीतियों और कार्यकलापों के समन्वयन में सुधार लाते हुए मुद्रा और ऋण नीति के व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता की दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

11.20 सावधानी योजना अवधि के दौरान पूंजी बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि और तेजी पायी गयी है। ये गतिविधियां निम्नलिखित की योग्य हैं कंपनी क्षेत्र का विकास और उसका लाभप्रदता, निवेशकों की वृद्धिशील संख्या, बाजार का अधिकाधिक मात्रा से सन्धानीकरण और बाजार के घटक की विधि मांगों को प्रवर्तित करने तथा उनकी पूर्ति करने संबंधी वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती हुई क्षमता। तथापि शेयर बाजार की सूची

प्रतिभूतियों में वृद्धि होने के बावजूद अधिमानित शेयरों को खरीदने या बेचने के लिए तत्काल उपलब्ध स्टॉक की अपेक्षाकृत कमी अभी भी विद्यमान है जिसके फलस्वरूप प्रायः अत्यधिक परिवर्तनशीलता आ जाती है। कुछ समय पश्चात् इसमें सुधार आ जाना चाहिए। एक उल्लेखनीय गतिविधि यह रही है कि नौवें दशक के उत्तरार्ध में स्थापित म्यूचुअल फंड में तेजी से वृद्धि हुई। इस संदर्भ में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि म्यूचुअल फंड में विशिष्ट क्षेत्र में कार्यरत सभी संस्थाएं एक ही राजकोषीय छत्र तथा विनियामक विन्यास के अन्तर्गत कार्य करती हैं ताकि उनमें से सभी एक जैसा शर्तों पर प्रतियोगिता कर सकें। पूंजी बाजार के संदर्भ में विनियामक विन्यास में संबंधित कई मामले उभर कर आये हैं। सरकार ने पूंजीगत अभिधानों की कमबलता एवं उपयोग तथा सार्व-जनिक निर्मातों की लागत जैसे कई विषयों पर यथाचित निर्देशक सिद्धांत जारी किये हैं। हमारे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उक्त निर्देशक सिद्धांत इस उद्देश्य से जारी किये गये हैं कि वित्तीय संस्थाओं के शेयर संबंधी लेनदेनों का अधिक स्पष्ट और अस्पष्ट बनना जा सके। पूंजी बाजार के संदर्भ में संप्रति बनायी जा रही पर्यवेक्षण प्रणाली तभी आदर्श बन सकती है जब उसमें पूंजी बाजार में प्रत्यक्षतः कार्य करने वालों के स्वयंनिर्णय तथा बाह्य पर्यवेक्षण का तर्कममन मिश्रण किया जाए।

मुद्रा बाजार की गतिविधियां

11.21 समीक्षाधीन वर्ष में मुद्रा बाजार में उल्लेखनीय व्यापकता तथा गहनता पायी गयी है। दो नये निश्चित अर्थात् जमा प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक पत्र परिचालन में आये नये सहयोगियों के प्रवेश के साथ मांग बाजार का विस्तार हो गया, स्टाम्प शुल्क को समाप्त किये जाने के कारण हुंसी बाजार में तेजी आयी, 182 दिन के खजाना बिलों की और लोक-प्रियता मिली और गीण बाजार के कार्यों में काफी प्रगति पायी गयी। व्याज दरों का अविनियमित किये जाने के बाद से मुद्रा बाजार को सदा-कदा व्याज दर की परिवर्तनीयता की समस्या का सामना करना पड़ा है और बैंक अब इस बाजार पर दीर्घकाल तक अत्यधिक निर्भर रहना अलाभ-प्रद महसूस कर रहे हैं। इसलिए बैंकों ने उन्नत निधि प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता देना प्रारंभ कर दिया है। मुख्यस्थान मुद्रा बाजार केवल अल्पकालीन असंतुलनों का दूर कर सकता है परन्तु बड़े संरचनात्मक असमानताओं के विना पोषण का एक अच्छा स्त्रोत नहीं बन सकता। अत्यधिक तगै को कम करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने भारतीय मितिकाटा और बिल गृह लि. को मार्च, 1990 में अस्थायी सहायता के रूप में लगभग 1,000 करोड़ रुपये प्रदान किये, तथापि मुद्रा नीति के समग्र लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में ऐसी सहायता पर कुछ प्रत्यक्ष गीमाएं हैं।

11.22 जैसा कि पहले संकेत किया गया है, आन्वेष्य वर्ष के दौरान दो नये मुद्रा बाजार निश्चित अर्थात् जमा प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पत्र परिदृश्य पर उभरे। 37 प्रमुख बैंकों द्वारा जारी किये गये जमा प्रमाण-पत्रों की कुल राशि 13 जुलाई 1990 तक 2,000 करोड़ रुपये थी जो इन बैंकों की अनुमत सीमाओं के 70.4 प्रतिशत के बराबर थी जमा प्रमाणपत्रों पर प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाएं लागू होती हैं और अब उन पर दी जाने वाली व्याज दर निर्धारित करने समय बैंकों को सावधानी बरतनी चाहिए। यद्यपि जमा प्रमाणपत्रों को व्याज दर संबंधी विनियम से मुक्त रखा गया है, फिर भी जमा प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी बैंक द्वारा सीमाओं का सामान्यतः यह अभिप्राय है कि जमा प्रमाण-पत्रों के कुल बाजार में बैंकों द्वारा यथोचित रूप में बांट दिया जाना है। इन जमा प्रमाणपत्रों का गीण बाजार सभी विनियमित हो सकता है यदि उनके निवेशक उनकी अवधि समाप्ति तक उन्हें धारित न करना चाहते हों।

11.23 यद्यपि एक निश्चित रूप में वाणिज्यिक पत्र की शुल्काय जमा प्रमाणपत्रों के मुकाबले कुछ घीमी थी, फिर भी वह धीरे-धीरे ध्यान आकर्षित कर रहा है और उनके संबंध में राशि 10 अगस्त 1990 के अंत में 155 करोड़ रुपये से कुछ अधिक थी। तथापि वाणिज्यिक पत्र पर व्याज

दरें कुछ कम स्तर की रही है। यह आशंका है कि वाणिज्यिक पत्र जारी करने में बैंकों की विश्वसनीयता श्रावकों को खोना पड़ेगा, नतीजतन कुछ बैंकों के बैंक ही वाणिज्यिक पत्रों के प्रमुख धारक रहे हैं जिनसे बैंकों के अणु सविभाग के प्रतिभूतिकरण का वह एक साधन अभिप्रेत होता है यद्यपि बैंक अपनी ब्याज आय का एक स्रोत खोते हैं, वे अन्य पाठियों का अणु प्रदान कर तथा शुल्कों द्वारा हानि की पूर्ति कर सकते हैं। वाणिज्यिक पत्र जारी करने संबंधी मानदंड यथार्थ परन्तु सुस्पष्ट है। भारतीय संदर्भ में एक निष्कर्ष के रूप में वाणिज्यिक पत्र अणुकर्ता को उपलब्ध निधियों में जड़ोत्तरी करने की अपेक्षा विप्लवापेक्षा का एक वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध करना है क्योंकि इस प्रणाली में सुस्थापित मानदंडों के आधार पर अधिकतम अनुमत बैंक वित्त को निर्दिष्ट किया गया है। रिजर्व बैंक नियमित वार्षिक अंतराल पर वाणिज्यिक पत्रों के निर्वाहों को प्राधिकृत करता आ रहा है।

बैंकिंग में संबंधित मामले :

11.24 जैसा कि पिछली रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है बैंकिंग सुविधाओं के तीव्र विस्तार की एक लंबी अवधि के बाद हाल ही के वर्षों में बैंक समेकन पर जोर दिया गया है। इसका यह अर्थ है कि बैंकों की वित्तीय कार्यक्षमता में सुधार लाने पर अधिक बल दिया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक विद्यमान आर्थिकों को पाठने समय शाखा विस्तार में संयम करना जाए, अत्यन्तमक आधार पर कम्प्यूटर टेक्नॉलॉजी प्रारम्भ की जाए और बैंकों में अधिक प्रभावकारी प्रबंधकीय संरचना अन्तर्निहित की जाए। पिछले कुछ वर्षों से अमल में रही कार्य योजनाओं के परिणाम स्वरूप बैंकों ने अपने संगठनात्मक बिन्याम को तथा पर्यवेक्षण और नियंत्रण की अपनी आंतरिक प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने में प्रगति की है। आंतरिक व्यवस्था, ग्राहक सेवाएं एवं प्रशिक्षण में भी सुधार परिलक्षित होते हैं। यद्यपि प्रति कर्मचारी जमा राशियाँ और अर्थियों में सामान्य अर्थों में वृद्धि हुई है, इस वृद्धि का अधिकांश भाग प्रति कर्मचारी लागत में हुई वृद्धि निष्प्रभावी हो गया है। अणु प्रबंधन के उधार आर्थियों के स्थिति कूटन और वार्षिक पुनरीक्षण अणु युक्तियों का पता लगाने तथा सुधारात्मक उपायों के लिए उनकी व्यवस्थापक क्षमता स्थिति के निर्धारण जैसे साधनों का अधिकाधिक मात्रा में सफलता पूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण और अर्थशास्त्री बैंक शाखा को सर्वेक्षण और अणु आयोजना के बान्ने विशिष्ट संख्या में गाँव आबंटित किये गये हैं। अप्रैल 1989 से अमल में आया और यह अब स्थिर हो रहा है। तथापि इन सभी क्षेत्रों में और प्रगति बांछित है।

11.25 बैंकों द्वारा किये गये विभिन्न उपायों की गति को बनाये रखने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने उन्हें दो और वर्ष की अर्थात् अप्रैल 1990 से मार्च 1992 तक की अवधि के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने का अनुरोध किया है। इन योजनाओं में निम्नलिखित पर अधिक बल दिया जाना है : लाभप्रदता में सुधार लाने के उपाय अधिक मजबूत संगठनात्मक और नियंत्रण व्यवस्थाएं, अर्थ शक्ति का अधिक प्रभावकारी उपयोग, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में और सुधार टेक्नॉलॉजी का आधुनिकीकरण, अणु प्रबंधन का मजबूतीकरण और सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अन्तर्गत अणु की उत्तमतर उत्पादकता को सुनिश्चित करना।

11.26 बैंक लाभप्रदता पर विद्यमान प्रतिबन्धों से संबंधित नीति को उधार बनाने के लिए हाल ही के वर्षों में कई कदम उठाये गये हैं, जैसे कि बांड प्राय में तथा रिजर्व बैंक में रहने वाली पात्र नकदी जमा पर वेध ब्याज में की गयी वृद्धि। ब्याज दरों को निर्धारित करने समय बैंक लाभप्रदता को ध्यान में रखा जाता है। लागतों में हुई वृद्धि की कम से कम आंशिक रूप से पूर्ति करने के लिए बैंक सेवा प्रसारों में वृद्धि कर पाये हैं। परन्तु बैंकिंग प्रणाली की लाभप्रदता निम्नलिखित कारणों से काफी दबाव के अधीन रही है। अणु औद्योगिक युक्तियों की बढ़ती हुई संख्या कई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्रदत्त निधियों के पुनर्निवेश में अनेकाली गंभीर कठिनाइयाँ बैंकों के पास उपलब्ध सहायकों का हटतम से कम प्रयोग और अणु प्रबंधन में विद्यमान आभियाँ। अतः इस बात

की आवश्यकता है कि वेद अर्थी आभियाँ की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विशेष प्रयास करें।

11.27 बैंक लाभप्रदता में सुधार लाने की प्रपञ्चा वसूला कार्य में सुधार लाना अधिक कठिन है। बैंकों के आर्थों के प्रवर्धन के लिए न्यायालयीन कार्यवाही पूरी होने में कई वर्ष लग जाते हैं भले ही ऐसे बाने सामान्य कार्यवाही के दीर्घता बनाये गये गये बड़ी आर्थों पर आधारित हो और उनके सही होने के पक्ष में धारणा विद्यमान रहती है। बड़े बैंक आर्थों पर आश्रय करने के लिए विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना से वसूली संबंधी कार्य तथा आतावरण में सुधार लाने में काफी सहायता मिल सकती है।

11.28 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अधीन बैंक अर्थियों की वसूली का कार्य विशेष समस्याएं उत्पन्न करता है। विशेषता निधियों के पुनर्निवेश के लिए खराब हो रहे आतावरण के कारण भारत सरकार ने हाल ही में कृषकों, ग्रामीण कार्यवाहों और बुनकरों को ग्राह्य प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि और ग्रामीण अणु ग्राह्य योजना की घोषणा की है। इस योजना में प्रत्येक मामले में उत्पादन और निवेश, दोनों अर्थों के अन्तर्गत रहने वाले 10,000 रुपये तक के आतिथ्या की विशिष्ट मानदंडों के आधार पर माफी की परिकल्पना की गयी है परन्तु, जानबूझकर चूक करने वालों को योजना के लाभों में बाहर रहने का प्रयास किया गया है। इस ग्राह्य की पूरी राशि का वहन सरकारी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा सहकारी बैंकों के मामले में केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार ने यह घोषित किया है कि अणु ग्राह्य योजना एक बार उपलब्ध उपाय है। इस योजना पर अब कार्यान्वयन किया जा रहा है। बैंकिंग उद्योग के मामले में निकट भविष्य में यह सुनिश्चित करने की नीती है कि आर्थी वेध राशियों तथा उक्त योजना के अन्तर्गत न आने वाली वेध राशियों को वसूल किया जाए। यदि वाणिज्य और सहकारी बैंकों द्वारा इस संदर्भ में किये जाने वाले प्रयासों का राज्य सरकारों कागमर हंग में समर्थन करे तो काफी सहायता मिल सकती है। ग्रामीण अणु प्रणाली की सुस्थिति को बनाये रखने के लिए यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है ताकि वह ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक कार्यकलापों को पहले की तरह सफलता पूर्वक सहायता कर सकें।

11.29 बैंकिंग प्रणाली एक स्टॉक-प्रधान सेवा उद्योग है और उसकी कार्यक्षमता काफी सीमा तक कार्य पद्धति के विकास, ग्राहक अभिवृद्धता तथा उरकी अर्थशक्ति के हटतम उपयोग पर निर्भर करती है। बैंकों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए शीघ्रतर कारोबारी लेनदेन के लक्ष्य के साथ अधिक प्रभावशीलता क्रियाविधियाँ में युक्त संस्थाएँ होना कर्मचारियों की स्थापक गतिशीलता और पदोन्नति की ऐसी नीतियाँ जो वास्तव में प्रणमनीय कार्य करने वालों को प्रोत्साहन देते हों अत्यावश्यक है। कार्य की बढ़ती हुई मावाधों को देखते हुए तथा बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए प्रबन्ध तन्त्री को चाहिए कि वे नयी टेक्नोलॉजी को, विशेषकर कम्प्यूटरीकरण को इस स्पष्ट ध्येयना के साथ शीघ्रता से अपनायें कि ममत्र कमियाँ की संख्या में कोई कटौती न हो। कम्प्यूटरीकरण से संबंधित समिति की हाल ही में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों बैंकिंग उद्योग के आर्थी कम्प्यूटरीकरण का आधार बन सकती है। बैंक प्रबन्ध तन्त्री तथा कर्मचारी सभी को यह आर्थीभाति समझ लेना चाहिए कि भारतीय बैंकिंग उद्योग में पहले से ही टेक्नोलॉजी की दृष्टि में यह कमी रही है कि वह सम्भार रूप में पिछड़ा हुआ है। और यदि निरन्तर बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय बाजार में बैंकों को अर्थी स्थान बनाये रखना है तो उन्हें इस कमी को शीघ्रनिर्णय दूर करना होगा।

11.30 वाणिज्य बैंकों पर पर्यवेक्षण संबंधी अपनी दायित्व पूरा करते हुए रिजर्व बैंक ने जहाँ बैंक परिपालनो में अधिकाधिक लक्ष्योपन का मवर्धन किया है वहाँ नीतिज्ञता पूर्ण विनियमों को बहू कठोर करता रहा है। इस प्रकार एक ओर जहाँ पूँजी-पर्याप्तता जोखिमों के संकेक्षण से अवन और स्वस्थ लेखापद्धतियों पर बल दिया जा रहा

है वहाँ दूसरी ओर व्याज दरों के मामले में अधिक लचीलेपन, बाजार उम्मीद निखतों के प्रचलन, ऋण प्राधिकरण योजना को वापस लेने और उधारकर्ताओं को अपने खाते एक बैंक से दूसरे बैंक में स्थानान्तरित करने की छूट देने के प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही हाल ही के वर्षों में ऐसे कई उपाय किये गये हैं। जिनसे बैंकों को अपने कार्य-कलापों का प्रत्यक्ष रूप से या वणिज्य बैंकिंग पट्टे के कारोबार, म्यूचुअल फंड वीक्षित पूँजी और आवास वित्त जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत अनुषंगी संस्थाओं के माध्यम से विविधीकरण करने में सहायता प्राप्त हो। पूँजी बाजार के साथ बैंकिंग उद्योग का सामंजस्य बढ़ रहा है। यह बात महत्वपूर्ण है कि अनुषंगी संस्थाएँ व्यावसायिक आधार पर कार्य करें, निवेशशील मानकों का पालन करें, अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करें और लाभप्रद बनें। इनमें से अधिकांश अनुषंगी संस्थाएँ सुसम्बद्ध व्यावसायिक और टेक्नोलाजी आधारित इकाइयों के रूप में गठित की गयी हैं और भविष्य में भी इसकी नितांत आवश्यकता है।

#### मुद्रा और ऋण नीति के परिदृश्य

11.31 हाल ही में जिस पृष्ठभूमि में मुद्रा और ऋणनीति संबंधी उपाय किये गये हैं वह इस प्रकार हैं: 1989-90 के प्रभूतपूर्व रूप से उच्च बजट घाटे के परिणामस्वरूप प्रारंभित निधि में काफी वृद्धि होना, वर्ष 1989-90 में एम 3 के विस्तार की गति काफी होना, जो वर्ष 1978-79 से लेकर अब तक सर्वाधिक था और कृषि उत्पाद के दो क्रमिक अच्छे वर्षों के बावजूब मूल्यों में तीव्र वृद्धि होना। निरंतर बनी रही मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में गंभीर आस्थिरताएँ निर्माण कर रही हैं और इसका प्रभाव विशेषकर निर्धन समूह पर काफी पड़ रहा है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह होना चाहिए कि मुद्रा विस्तार संयत ढंग से हो। यदि वर्ष 1990-91 के लिए केन्द्र सरकार के बजट घाटे को बजट में प्रत्याशित आंकड़ों तक सीमित रखा जाए तो वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद में घाटे का अनुपात 1989-90 के लगभग 2.4 प्रतिशत से गिरकर 1990-91 में लगभग 1.5 प्रतिशत रह जाएगा। इस राजकोषीय उद्देश्य के अनुरूप मुद्रा प्रबंधन का लक्ष्य यह होगा कि एम के विस्तार में वर्ष 1989-90 में हुए विस्तार के मुकाबले वर्ष 1990-91 में लगभग 4 प्रतिशत अंकों की तीव्र कमी लायी जाए।

11.32 प्रारंभित निधि में वर्ष दर वर्ष भारी वृद्धि होने के कारण मुद्रा नीति में इस बात पर ध्यान केन्द्रित करना पड़ा कि प्रारंभित निधि संबंधी आवश्यकताओं के लिए निधि का अत्यधिक उपयोग कर विस्तार के प्रभाव को कम किया जाए। प्रारंभित नकदी निधि अनुपात के निरंतर उपयोग के कारण वह अपनी मासिक सीमा तक पहुँच चुका है। अतः पिछले कुछ समय की मुद्रा नीति में ऋण विस्तार की संयत करने के वास्ते कुछ अन्य उपाय करने पड़े।

11.33 कुल पुनर्वित्त सुविधाओं में निर्यात पुनर्वित्त सीमाओं का प्रांश 80 प्रतिशत से अधिक है। मुद्रा उपायों में से एक उपाय यह रहा है कि निर्यात पुनर्वित्त के अनुपात को 100 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया जाए। इसके फलस्वरूप समग्र निर्यात ऋण में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए क्योंकि निर्यात की पहले की तरह अधि-मागित दर्जा प्राप्त है। इस उपाय का यह अधिप्राय है कि निर्यातों के एक बहुत बड़े अनुपात का वित्तपोषण बैंक अपने ही स्त्रोतों में से करेंगे, न कि रिजर्व बैंक से उधार लेकर। निर्यात ऋण और निर्यातों के कुल स्तर की तुलना करने से यह बात प्रकट होती है कि निर्यात ऋणों में हाल ही के वर्षों में ममानुपातिक से भी अधिक वृद्धि हुई है। रियायती पुनर्वित्त, उपदान, आकर्षक विनियम माजिन और निर्यात ऋणों में अधोध्य ऋणों का न्यून मात्राये सभी मिलकर अवश्य यह सुनिश्चित करते हैं कि निर्यात ऋणों से बैंकों को पर्याप्त प्राय होती है।

11.34 एक अन्य उपाय में, 60 प्रतिशत का वृद्धिशील खाद्यतर ऋण जमा अनुपात निर्धारित किया गया है। कभी कभी यह आशंका की जाती है कि वाणिज्यिक क्षेत्रों को ऋण की उपलब्धता पर इस उपाय से प्रतिबल प्रभाव पड़ेगा। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदत्त खाद्यतर ऋणों की राशि में 1988-89 के 22.5 प्रतिशत की ओर 1989-90 में 18.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 60 प्रतिशत की निर्धारण को आधार पर यह वृद्धि 1990-91 में 17 प्रतिशत के आसपास हो सकती है। वृद्धि की ये मात्राएँ काफी अधिक हैं। वस्तुतः अर्थव्यवस्था में सामान्य तीव्र पर और विशेषकर कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में हुए विकास के परिप्रेष्य में ऋण विस्तार की मात्रा अत्यधिक है। प्रारंभित निधि संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में निर्धारित सीमाओं तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में सविधिक चलनिधि अनुपात में हुई वृद्धि को देखते हुए बैंक स्वयं के जमा स्त्रोतों के आधार पर केवल 40 प्रतिशत का वृद्धिशील खाद्यतर ऋण-जमा अनुपात प्राप्त कर सकेंगे। रिजर्व बैंक और मीयारी ऋणदात्री वित्तीय संस्थाओं के पुनर्वित्त तथा बैंकेतर मुद्रा बाजार उधारों को हिसाब में लेने के बाव भी बैंकिंग तंत्र 60 प्रतिशत के वृद्धिशील खाद्यतर ऋण-जमा अनुपात तक पहुँच पाने में अत्यंत कठिनाई महसूस करेगा। इस प्रकार उचित निर्धारित सीमा द्वारा मूलतः यह सुनिश्चित किया गया है कि जमा वृद्धि और उपलब्ध पुनर्वित्त साधनों के अनुसूप ऋण विस्तार मुद्रा है तथा अलग-अलग बैंक आवश्यकता से अधिक ऋण प्रदान नहीं करते।

11.35 सरकार द्वारा निर्धारित व्याज दर विन्यास इस प्रकार बनाया गया है कि वस्तुतः बैंकों को प्रदाय की निश्चित दर प्राप्त हो सके। कतिपय क्षेत्रों को रियायती व्याज दरों पर ऋण प्रदान किया जाता है और उन अन्य उधारकर्ताओं से प्रति अनुपात हो जानी है जो उच्च दरों पर व्याज भुगत करते हैं। नीतिगत उद्देश्यों की बहुविधता तथा विभिन्न क्षेत्रों द्वारा उनके साथ अधिमानात्मक व्यवहार किये जाने की मांग के कारण व्याज दरों में वृद्धि हुई है और व्याज दर विन्यास को औचित्य युक्त बनाने के लिए किये गये आधिक्य प्रयासों के बावजूब उसके समीक्षा स्वरूप का बन जाने की प्रवृत्ति पायी गयी है। व्याज दरों के औचित्य स्थापन के लिए जहाँ गुंजाइश है वहाँ व्याज दरों के औसत स्तर में कमी लाना सभी संभव होगा जब मुद्रास्फीति की दर में उल्लेखनीय और दीर्घकालीन कमी प्राये।

11.36 सुविक्सित वित्तीय प्रणालियों में खुले बाजार के कार्यकलापों मुद्रा नीति का एक प्रमुख साधन होते हैं। खुले बाजार के प्रभावकारी कार्यकलापों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों पर व्याज की बाजार निर्धारित वर एक पूर्वापेक्षा रहती है यद्यपि सरकारी प्रतिभूतियों पर व्याज की घरेपहेले की तरह सरकार द्वारा निर्धारित की जाती रही है, सरकार प्रतिभूतियों पर प्राय और उनकी अर्थमुल्यता में सुधार लाने के लिए हान ही के वर्षों में कई उपाय किये गये हैं। सरकारी प्रतिभूतियों पर 30 वर्षों की स माप्ति अवधि के लिए अधिकतम व्याज दर 1979-80 में 7 प्रतिशत था जबकि 29 वर्षों तक की सकाप्ति पर संप्रति 11.5 प्रतिशत है। इसके अलावा जालू वित्तिय वर्ष में इसे 5 से 20 वर्षों तक की समाप्ति अवधि के लिए 10.0-11.5 प्रतिशत की दरों की सीमा बढ़कर 10.5-11.5 प्रतिशत हो गयी है। इससे निवेशकों को समाप्ति अवधि और प्राप्ति के बीच बेहतर विनियम अवसर उपलब्ध होने चाहिए। अन्य अवधि की प्रतिभूतियों के संबंध में भी 182 दिनों के खजाना बिलों की प्राय बढ़ती रही है और संप्रति वह 9.97 प्रतिशत पर विद्यमान है। खुले बाजार के कार्यकलापों के लिए यह आवश्यक होगा कि कि केन्द्रिय सरकार के बजट घाटे में पर्याप्त कमी लाते हुए सरकार की निर्माकित प्रतिभूतियों के संबंध में बाजार निर्धारित व्याज दरों को अपनाया जाए। इसके साथ ही कुछेक अन्य सरकारी ऋण की लिखतों पर विद्यमान अस्तित उच्च प्रभावकारी प्राय को राजकोषीय विवेकधकारों की कम करते हुए क्रमशः घटाने के लिए गुंजाइश है। इसके परिणामस्वरूप सरकारी उधारों की समग्र लागत में बड़ोतररी न होने की सम्भावना है, हालांकि सरकारी प्रतिभूतियों का एक स्वस्थ बाजार उभर सकता है। यदि सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में एक लचीला व्याज दर विन्यास हो तो बेहतर मौद्रिक नियंत्रण लाने में उल्लेखनीय योगदान मिल सकता है।

11 37 हाल ही की अवधि में केन्द्रीय बैंक को अधिक स्वायत्तता देने जाने के प्रश्न पर विचारणाओं का निष्ठा हुआ है, भारत में भी इस विषय पर विचार विमर्श किया गया है। भारतीय सदस्यों में स्वायत्तता संबंध में यह अभिप्राय है कि रिजर्व बैंक मुद्रा प्रतिकार के रूप में प्रारम्भिक प्रयासों पर विनियामक निकाय के रूप में अपनी भूमिका कायम रखे और अधिक प्रभाव से विनियामक प्रणाली के विनियामक के रूप में अपनी भूमिका का अधिकार क्षेत्र में विनामक इसलिए यह आवश्यक है कि वाणिज्य बैंक के सदस्यों में सरकार तथा रिजर्व बैंक के कार्यों तथा वास्तविक के वर्तमान अतिरिक्त का काम किया जाए। निरंतर बने हुए और बहुत बड़े बजट घाटे के कारण कुछ वर्षों में मौद्रिक स्थायित्व में कम आया है। केन्द्रीय सरकार के बजट घाटे के स्वयंसेवक मूद्राकरण पर अधिकाधिक निर्भरता होने के परिणामस्वरूप 1989-90 में मूद्राकृत घाटे में तीव्र वृद्धि हुई जो सकल देशी उत्पाद का अनुमानित 3 प्रतिशत है। रिजर्व बैंक ने यह सिफारिश की है कि कुछ समय परवाह केन्द्रिय सरकार के बजट घाटे का समाप्त कर दिया जाना चाहिए। एक अन्य अतिरिक्त लक्ष्य यह है कि केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक से जो राशि उधार ले सकती है उसका वार में स्पष्ट महामति है। इस स्वयंसेवक मूद्राकरण का मध्यम अवधि में समाप्त किया जाना चाहिए और अर्थोपाय अधिमा को प्रणाली स्थापित की जाना चाहिए। कि केन्द्रीय सरकार प्रतियोगिता और भुगतानों के बीच विद्यमान अस्थायी असंतुलनों को दूर कर सके। इसका यह तात्पर्य होगा कि केन्द्रीय सरकार का व्याज की बाजार घटा पर अपने उधारों में अधिकाधिक वृद्धि करनी होगी। जैसा कि पहले मकें किया गया है, ऐसी व्यवस्था के कारण रिजर्व बैंक खुले बाजार संबंधी कार्यों का अधिक कारगर रूप से कर पाएगा। ऐसे करने उद्योगों के लिए जहाँ सरकार के विनियोजन की प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन करना आवश्यक होगा, रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को ऋण प्रदान करने से संबंधित सीधिका प्रावधान समर्थकारी है न कि अधिदेशात्मक और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के वर्तमान विन्यास के भीतर प्रणाली में सुधार लाया जा सकता है।

#### भाग II-बैंकिंग और अन्य गतिविधियाँ

##### 12 मुख्य बातें

12 1 रिपोर्ट के भाग I में समग्र आर्थिक प्रवृत्तियों के विच्छेद के सदस्यों में मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की गई है। हम के अतिरिक्त वित्तीय संस्थाओं, पजी बाजार और वाणिज्य क्षेत्र में संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों की भी समीक्षा की गई है। रिपोर्ट के भाग II में अन्य बैंकिंग गतिविधियाँ तथा रिजर्व बैंक के परिचालनों, संगठनात्मक मामला और लब्धा में संबंधित गतिविधियों की व्यास-व्यास बातें बताई गई हैं।

12 2 इन गतिविधियों की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं

- (i) बैंक बेहतर ऋण प्रबंध और लाभदायकता, धन शक्ति के बेहतर उपयोग, देहतर ग्राहक सेवा और प्रौद्योगिकी के प्रोन्नयन पर विशेष जोर देने के साथ अप्रैल 1990 से मार्च 1992 तक का वर्ष की आली अवधि के लिए कार्य योजनाएँ तैयार कर रहे हैं।
- (ii) सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अंतर्गत ग्रामीणों का उधार देने की नई नीति 1 अप्रैल 1989 से परिचालन में आने ली और 1989-90 में ऋण वितरण का लक्ष्य 15,319 करोड़ रुपये निर्धारित था जिसमें से 10,284 करोड़ रुपये कृषि के लिए थे। 1990-91 के लिए शाखा ऋण योजनाएँ तैयार की जा रही हैं, इन कार्यक्रमों का प्रभावों निगरानी के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (ताबाई) तीन बार वर्षों में क्रमिक रूप से सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यालय खोल रहा है।
- (iii) 1 जनवरी 1989 से मार्च 1990 तक के दौरान बैंको ने कुल 711 शाखाएँ खोली जिनमें से 633 या 93 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में थीं। दश में 31 मार्च 1990 को बैंक शाखाओं की कुल संख्या 58,901 थी जिनमें से 57.8 प्रतिशत ग्रामीण शाखाएँ थीं।
- (iv) सरकारी क्षेत्र के बैंको ने के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रवर्त अग्रिम मार्च 1990 के आ में उनके कुल अग्रिमों का 43.2 प्रतिशत था।

(v) वाणिज्य बैंको ने संबंधित वित्तीय सेवाओं के विविधीकरण की प्रतियोगिता जारी रखी और बैंक सहायक कंपनियाँ/संयुक्त उद्यम, उपस्कर पट्टे पर देना, वाणिज्य बैंकिंग, आवास वित्त कंपनियाँ और म्युचुअल फंड गठन करते रहे।

(vi) बैंक में कृषि क्षेत्र पर गठित समिति ने नवंबर 1989 में अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और निवारण और 1990-94 का अवधि के लिए एक बैंक के लिए एक व्यापक कृषि क्षेत्रीकरण योजना की सिफारिश की है। रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट का विद्वान्त स्वीकार कर लिया है। बैंक ने अर्थात् बैंकिंग उद्योग के लिए आक्रांता सवार तंत्र के पहले ऋण तैयारी अंतर्गत सहायक म्युचुअल चुकी है और इस तंत्र का प्रथम चरण 1990 के दौरान चालू हो जाने की आशा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान देश में 15 नये समीक्षाधीन गृहों ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1 लाख रुपये से अधिक राशि के चेकों के लिए कलकत्ता और नई दिल्ली में विशेष समीक्षाधीन की शुभ्रात के साथ अब सभी चार महानगरीय गृहों में माहक समीक्षाधीन के अन्तर्गत उच्च मूल्य के चेकों के लिए उसी दिन समीक्षाधीन की प्रणाली उपलब्ध है।

(vii) कृषि ऋण पुनरीक्षण समिति ने ग्रामीण ऋण के संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन किया है और अगस्त 1989 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, समिति ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशों की हैं जो विचाराधीन हैं।

(viii) रिजर्व बैंक ने व्यापार, अध्ययन, विनिष्ठा प्रशिक्षण, रोजगार और डाकटरी इलाज के लिए विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने के संबंध में नियमों में छूट दी है।

(ix) प्राधिकृत व्यापारियों को कतिपय निविष्ट सीमाओं के अधीन स्थानीय अंतर-बैंक बाजार में विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डॉलर) उधार देने और लेने की अनुमति दी गई है।

(x) मैसूर (कर्नाटक) और मालबोनी (पश्चिम बंगाल) में दो बैंक नाट मुद्रण प्रेसों की स्थापना के लिए रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक कंपनी बनाये जाने का प्रस्ताव है।

(xi) राष्ट्रीय आवास बैंक ने प्राथमिक ऋणदात्री एजेंसियाँ द्वारा प्रवर्त सीधे आवास ऋणा के अपने पुनर्वित्तपोषण को उधार बनाया है, उसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रदान आवास ऋणों के पुनर्वित्तपोषण की व्याज दर को एक समान बना दिया है।

#### 13 वाणिज्य बैंक में संबंधित गतिविधियाँ

बैंको के लिए कार्य योजनाएँ—1989-90

13 1 बैंको ने अपने समग्र निष्पत्ति में सुधार लाने का दृष्टि से बनाई गई अपनी कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन जारी रखा। इन योजनाओं के कार्यान्वयन में की गई प्रगति का सरकारों क्षेत्र के बैंको के अध्ययन और वरिष्ठ कार्यपालकों के साथ निमाहा आधार पर समीक्षा की गई। बैंको से कहा गया है कि वे ऋण प्रबंध और लाभदायकता, संगठन और नियंत्रण व्यवस्था, अमशक्ति उपयोग में सुधार, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण और ग्रामीण ऋण के प्रति सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के समेकन के लिए आवश्यक उपायों पर विशेष जोर देने हुए वर्तमान स्वरूप पर दो बार वर्ष अर्थात् अप्रैल 1990 से मार्च 1992 तक की अगली अवधि के लिए कार्य योजनाएँ तैयार करें।

#### शाखा विस्तार

13 2 सातवीं पंचवर्षीय योजना के साथ समाप्त होनेवाली शाखा योजनावर्षीकरण नीति 1985-90, 31 मार्च 1990 को समाप्त हो गई।

इस नीति के अंतर्गत 5,360 ग्रामीण/अर्धशहरी केन्द्र बैंकों को आवंटित किये गये थे। इसके अतिरिक्त, 1,454 केन्द्र सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अंतर्गत आवंटित किये गये। 6,814 ग्रामीण/अर्धशहरी केन्द्रों में से, 4,624 केन्द्र सरकारी क्षेत्र के बैंकों, 2,038 केन्द्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 152 केन्द्र निजी क्षेत्र के बैंकों को आवंटित किये गये थे। इनके अलावा, 635 केन्द्र, (309 शहरों में और 326 महानगरीय/पत्तन शहरों में) भी आवंटित किये गये।

13.3 मार्च, 1990 की समाप्ति तक, आवंटित किये गये 7,149 केन्द्रों में से 5,681 केन्द्रों में ही बैंक कार्यालय खोल सके जिसमें से 1985-90 योजना के अंतर्गत 4,434 कार्यालय ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों में थे और 695 सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अंतर्गत तथा 555 शहरी/महानगरीय/पत्तन शहर केन्द्रों में थे। बैंकों का शेष केन्द्रों में कार्यालय खोलने के लिए 30, सितंबर, 1990 तक का समय दिया गया है।

13.4 जुलाई, 1989 से दिसंबर, 1989 तक की अवधि के दौरान कुल 633 शाखाएं खोली गईं, इनमें से 588 या 91.0 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गईं। बैंक का शेष केन्द्रों में कार्यालय खोलने के लिए सितंबर, 1990 तक का समय दिया गया है। देश में 31 मार्च, 1990 को काम कर रही शाखाओं की कुल संख्या 58,901 थी। ग्रामीण शाखाएं कुल शाखाओं का 57.8 प्रतिशत थी। 1989 की जनगणना के संदर्भ में प्रति शाखा कार्यालय औसत जनसंख्या जून, 1989 की समाप्ति में 65,000 से घटकर मार्च, 1990 की समाप्ति में 11,600 रह गई है।

#### विदेशों में भारतीय बैंक

13.5 1989-90 के दौरान किसी भारतीय बैंक ने विदेश में कोई नई शाखा नहीं खोली। तीन शाखाएं बंद हो जाने के बाद, 30 अप्रैल, 1990 को कार्यरत नौ भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं 114 थीं। मनीला (फिलीपीन्स) में भारतीय स्टेट बैंक का एक प्रतिनिधि कार्यालय जमा स्वीकार करने वाली कपनिया की संख्या तीन बनी रही किन्तु अप्रैल, 1990 में मारीशस में भारतीय स्टेट बैंक के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक कंपनी खोल जाने से ऐसी कपनिया की संख्या बढ़कर चार हो गई।

#### भारत में विदेशी बैंक

13.6 वर्ष के दौरान क्रेडिट लायनेज के प्रतिनिधि कार्यालय की कोटि बढ़ाकर शाखा कर दिया गया। इस प्रकार, 22 विदेशी बैंकों की शाखाओं की संख्या बढ़कर 138 हो गई। नैशनल आस्ट्रेलियन बैंक (ऑस्ट्रेलिया) का प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के साथ भारत में विदेशी बैंकों के प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या बढ़कर 22 हो गई।

#### क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

13.7 वर्तमान में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जो 369 जिलों में स्थित हैं। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल 14,079 कार्यालय हैं। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल बकाया जमा राशियां और अधिदा की राशि मार्च, 1989 के अंत में क्रमशः 3,119 करोड़ रुपये और 2,919 करोड़ रुपये थी। वर्ष के दौरान कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया।

#### सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण

13.8 जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, ग्रामीण ऋण की नई मात्रा अर्थात्, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण 1 अप्रैल, 1989 से लागू हुई। इस नये दृष्टिकोण के भाग के रूप में वाणिज्य बैंक की शाखाओं ने 1989-90 (अप्रैल-मार्च) के लिए वार्षिक ऋण योजनाएं तैयार कीं।

1989-90 के लिए तैयार किए गए भारतीय क्षेत्रीय ऋण संचितरण लक्ष्य नीचे दिये गये हैं।

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	संचितरण के लिए निर्धारित लक्ष्य	31 दिसंबर 1989-90 तक वास्तविक संचितरण
कृषि	8,208	8,998
उद्योग	2,218	2,132
सेवाएं	2,334	2,590
जाड़	12,790	13,710

(सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के पूर्व)

	10,284	2,514	2,491	15,319
--	--------	-------	-------	--------

सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रत्येक शाखा के सेवा क्षेत्र में सामान्यतया 15 से 25 गांव आते हैं।

13.9 ग्रामीण शाखाओं में सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के कार्यान्वयन का तरीका सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्षेत्र के बैंकों ने क्षेत्र अध्ययनों का दूसरा दौर दिसंबर 1989 में पूरा किया। योजना के कार्यान्वयन और इसके परिचालनगत पहलुओं में सुधार के लिए आवश्यक कदमों का निर्धारण करने के लिए एक प्रयास किया गया। अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्णय किया गया कि योजना को स्थिर बनाने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए और इस बीच ऋण प्रवाह का भ्रम-व्यस्त न होने देने के लिए अन्य बैंक शाखाओं के सेवा क्षेत्र में रहनेवाले उनके पुराने ग्राहकों को उधार देने के लिए बैंक शाखाओं का पहले दी गई छूटे, यदि वे ऐसा चाहें, जारी रहे। सहकारी बैंकों को भी सूचित किया गया है कि वे ऐसी ही ऋण योजनाएं तैयार करें। बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं कि वे पिछले वर्ष के लिए तैयार की गई ऋण योजनाओं में पाई गई कमियों को दूर करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1990-91 के लिए शाखा-ऋण योजनाएं तैयार करें। बैंक शाखाओं की ऋण योजनाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने और उनके प्रभावी अनुशीलन की दृष्टि से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक देश के सभी जिलों में अगले 3-4 वर्षों में क्रमबद्ध रूप से कार्यालय खोल रहा है। ये कार्यालय प्रत्येक जिले के लिए तालाई द्वारा बनायी जा रही सभायता—संबद्ध ऋण योजनाओं की वाणिज्य बैंकों की ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं तक पहुंचाने तक उन्हें आगे ऋण योजनाएं तैयार करने में मदद मिल सकें। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पत्रों चरण में ऐसे 13 कार्यालय पहले ही खोल चुका है। साथ-साथ, रिजर्व बैंक निर्माण के वास्तव में और अधिक ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं को शामिल कर रहा है।

#### प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को बैंकों की सहायता

13.10 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम मार्च, 1989 के अंत में 34,623 करोड़ रुपये में बढ़कर मार्च 1990 के अंत में 39,118 करोड़ रुपये हो गये। ये 40 प्रतिशत के निश्चित लक्ष्य के मुकाबले मार्च, 1990 के अंत में सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के कुल अग्रिमों का 43.2 प्रतिशत थे। निजी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों के लिए भी विवेक ब्याज दर योजना के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों और उधारों के लिए विविध लक्ष्य और उप-लक्ष्य प्राप्त करना अपेक्षित है। मार्च, 1989 के अंत में निजी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम उनके कुल अग्रिमों का 36.9 प्रतिशत थे।

#### विवेक ब्याज दर योजना

13.11 विवेक ब्याज दर योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिमों की राशि मार्च 1989 के अंत में 17,67 लाख अंशों में 679.59 करोड़ रुपये के मुकाबले मार्च 1990



में 42.29 लाख खातों में 703.59 करोड़ रुपये थी। इस योजना के अंतर्गत इन बैंकों के अग्रिम मार्ग, 1990 के अंत में, मार्च 1989 के अंत में कुल बकाया अग्रिमों के 0.9 प्रतिशत थे। (निर्दिष्ट लक्ष्य 1.0 प्रतिशत है)। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हिताधिकारियों को योजना के अंतर्गत बकाया अग्रिमों की राशि मार्च, 1989 के अंत में 335.85 करोड़ रुपये थी जो विवेकद्वारा दूर योजना के कुल अग्रिमों का 47.7 प्रतिशत है और यह 40 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से अधिक थी।

#### स्वरोजगार और अन्य योजनाएँ

13.12 शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 1989-90 में सहायता प्रदान करने के लिए हिताधिकारियों की सहायता 1.25 लाख नियत की गयी थी। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बैंकों ने 1989-90 (अप्रैल-मार्च) के दौरान 0.97 लाख हिताधिकारियों के लक्ष्य के मुकाबले 1.91 लाख हिताधिकारियों को कुल 404.32 करोड़ रुपये के ऋण सृजित किये गये।

13.13 भारत सरकार द्वारा 1986-87 के दौरान प्रारंभ किया गया ग्रामीण निर्धनों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम 1989-90 के दौरान जारी रहा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 1989-90 के दौरान बैंकों ने 2.65 लाख हिताधिकारियों को 101.53 करोड़ रुपये का ऋण के कुल ऋण वितरित किये।

#### एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

13.14 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1989-90 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बैंकों ने पिछले वर्ष में 37.72 लाख हिताधिकारियों की तुलना में 33.51 लाख हिताधिकारियों की सहायता की। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1989-90 में 1,221 करोड़ रुपये की कुल राशि ऋण के रूप में और 615 करोड़ रुपये आधिक सहायता के रूप में हिताधिकारियों को वितरित की गई। वर्ष 1989-90 के दौरान सहायता प्राप्त 33.51 लाख हिताधिकारियों में से 15.15 लाख अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित थे और 8.59 लाख महिलाएँ थी। मातृबी योजना अवधि के दौरान, बैंकों ने 182 लाख हिताधिकारियों की सहायता की जिनमें से 81.97 लाख अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित थे और 32.34 लाख महिला हिताधिकारियों थे। यद्यपि यह परिकल्पित किया गया था कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मातृबी योजना की अवधि के दौरान 20 मिलियन परिवारों को समाविष्ट किया जाएगा, भारत सरकार ने 16.03 मिलियन परिवारों को सहायता प्रदान करने का कुल लक्ष्य निर्धारित किया था। इस लक्ष्य के मुकाबले उक्त योजना अवधि के दौरान वस्तुतः 18.18 मिलियन परिवारों को सहायता प्रदान की गयी। यन्त्रण : सहायता प्राप्त हिताधिकारियों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला हिताधिकारियों में से प्रत्येक के लिए 30 प्रतिशत का उपलब्ध निर्धारित किया गया था, जिसके मुकाबले उपलब्धि क्रमशः 45 प्रतिशत और 18.9 प्रतिशत थी। मातृबी योजना के दौरान मंचित ऋणों और आधिक सहायता की राशि क्रमशः 5,373 करोड़ रुपये और 3,165 करोड़ रुपये थी। सरकारों क्षेत्र के बैंकों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋणों की वसूली 1988 में भाग के 40.8 प्रतिशत की तुलना में 1989 में 39.0 प्रतिशत थी।

#### अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण

13.15 जून, 1989 के अंत में, 40 अभिनिर्धारित जिलों में अल्पसंख्यक समुदायों को प्रवर्तन सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों की राशि 12.66 लाख उधार खातों में 798.57 करोड़ रुपये थी।

#### अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का ऋण

13.16 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिमों की राशि दिसंबर 1989 में 90.85 लाख उधार खातों में 2,917 करोड़ रुपये हो गई।

#### कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990

13.17 केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 1990-91 के बजट भाषण में घोषित सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋणकर्ताओं को 10,000 रुपये तक ऋण राहत प्रदान करने की कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना; 1990 का अंतिम रूप दे दिया गया और वह कार्यान्वयन के लिए बैंकों को भेज दी गई है, यह योजना 15 मई, 1990 से लागू हुई। सहकारिता क्षेत्र में बैंकों के लिए इसी प्रकार की एक योजना बनाई जा रही और वह राज्य सरकारों द्वारा प्रारंभ की जा रही। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋणकर्ताओं के लिए बनायी गयी योजना में कृषि और अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों में लगे व्यक्ति और कुटीर और ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प, बुनाई आदि में संबंधित ग्रामीण विकास के किसी कार्यकलाप में लगे शिल्पकार शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत ऋण राहत के लिए पात्र ऋण इस प्रकार हैं: (i) किसी ऋणकर्ता द्वारा 1 अप्रैल, 1986 को या इसके बाद लिये गये ऋणान्तरित/पुनः निर्धारित मध्यावधि ऋणों समेत अल्पावधि ऋणा का वह हिस्सा और 2 अक्टूबर, 1986 के बाद देय हिस्सी मातृबी ऋण की वे किस्में जो 2 अक्टूबर, 1989 को किसी बैंक को देय थीं। उक्त राहत उस "जानबूझकर चूक न करनेवाले" को उपलब्ध होगी जिसने देय ऋण या ऋण की किस्म की चुकौती नहीं की तथा जिसे दो या अधिक ऐसे वर्षों का, जहाँ वे क्रमिक हों या नहीं, सामना करना पड़ा जो खराब फसल वर्ष थे तथा जिनके फलस्वरूप फसल की उपज अतिशय घटनेवाली घोषणाओं के आधार पर सामान्य उपज से कम या पचास प्रतिशत से कम हुई और जिसमें से एक वर्ष ऐसा था जिसमें चूक की गयी थी; (ii) "काफी पुरानी अतिदेयो", अर्थात् वे बकाया जिसमें, किसी कृषक, बुनकर या कारीगर या भूमिहीन खेतिहर के बकाया सहित जिसने एक या एक से अधिक बैंकों से ऋण लिया था या लिये थे और जो प्रभावी तिथि अर्थात् 2 अक्टूबर, 1989 को 3 वर्ष से अधिक समय से ऐसे बैंक/बैंकों के पास बकाया थे; (iii) किसी ऐसे ऋणकर्ता द्वारा लिये गये ऋण जिसकी 2 अक्टूबर, 1989 को या इसके पूर्व मृत्यु हो गई हो और (iv) ऐसे ऋणकर्ता की बकाया राशि जो दिवालिया घोषित किया जा चुका है या दिवालिया घोषित किये जाने के लिए 2 अक्टूबर, 1989 को या इसके पूर्व व्यापारिक में उसकी याचिका अभिनीत है।

13.18 केन्द्र सरकार ने 1990-91 के बजट में ऋण राहत योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दी जानेवाली संपूर्ण राहत राशि की हामीदारी की भी वचनबद्ध है। इसके अतिरिक्त, सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले ऋण के लिये 50 प्रतिशत सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार वचनबद्ध है।

#### बैंकों का निरीक्षण

13.19 समीक्षाधीन अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक के 13 स्थानीय प्रधान कार्यालयों के मध्य में वार्षिक वित्तीय समीक्षा प्रारंभ की गयी और उन्हें पूरा किया गया। सरकारी क्षेत्र के पाठ बैंकों, गैर-सरकारी क्षेत्र के 16 बैंकों और सात विदेशी बैंकों के वित्तीय निरीक्षण भी प्रारंभ किये गये थे, जिनमें से सरकारी क्षेत्र के 6 बैंकों, गैर-सरकारी क्षेत्र के 16 बैंकों और पांच विदेशी बैंकों के निरीक्षण पूरे हो गये हैं और शेष बैंकों का निरीक्षण चल रहा है।

#### बैंकों का पूँजी आधार

13.20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूँजी आधार को बढ़ाने के लिए बसाई गयी योजना के अनुसार भारत सरकार ने 1989-90 के दौरान 200 करोड़ रुपये का भ्रमण किया, इस प्रकार योजना के अंतर्गत 1986 से कुल अंशदान 1900 करोड़ रुपये हो गया। सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में बैंकों की रवायित निधियों का ऋण अधिश मजबूत करने के उपाय लिए जा रहे हैं।

पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में बैंकों के ऋणवर्तनीय/ग्राहकों को ऋण-छूट:

13.21 चूंकि जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में व्याप्त अपवादात्मक परिस्थितियों के कारण व्यापार और उद्योग लगातार अनेक कठिनाईयों का अनुभव कर रहे हैं, अतः इन क्षेत्रों में बैंक के ग्राहकों/ऋणवर्तनीयों को कतिपय रियायतें/छूट देने की अनुमति दी गयी है या इन्हें जारी रखा गया है; इनका सम्बन्ध में माजिनों, सेवा प्रभागों, सार्वजनिक ऋणों की चुकौती को पुनः निर्धारित करने, दंडात्मक भ्रष्टाचार पर जेनी न लगाने, योग्य मामलों में चक्रवृद्धि व्याज न लगाने, आवश्यकता-आधारित अतिरिक्त ऋण सीमा आदि की स्वीकृति से है।

बैंकों द्वारा वित्तीय विविधीकरण

13.22 बैंकों ने अपनी महमोही कंपनियों के माध्यम से वाणिज्य बैंकिंग, उपस्कर पट्टे पर देना, आवास वित्त, उद्यम पूंजी, म्यूचुअल फंड आदि जैसे नये क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का विविधीकरण करना जारी रखा है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी प्राधिसूचना के फलस्वरूप आधुनिक कार्य-कलाप भी व्यापार का एक अनुमत रूप हो गया है जिसमें बैंक स्वयं को लगा सकते हैं। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे इसे अपने विभाग के माध्यम से न करें, बल्कि केवल अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से ही करें। इंडियन बैंक द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक कंपनी की स्थापना के साथ बैंकों की उपस्कर पट्टे पर देने और वाणिज्य बैंकिंग की सहायक कंपनियों की संख्या मई 1990 के अंत में 8 हो गई (सरकारी क्षेत्र के 7 बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के 1 बैंक द्वारा स्थापित)। इसके अतिरिक्त, बैंकों द्वारा 1 पूर्ण स्वामित्व वाले आवास वित्त सहायक कंपनी और 2 संयुक्त उद्यम आवास वित्त सहायक कंपनियां स्थापित की गई हैं। कुल मिलाकर सरकारी क्षेत्र के 5 बैंकों ने म्यूचुअल फंड स्थापित किये हैं। म्यूचुअल फंड व्यवसाय के महत्वपूर्ण पहलुओं पर बैंकों को निस्तुत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये जा चुके हैं। वित्तीय विविधीकरण के विविध प्रकारों के लिए सहायक कंपनियों की स्थापना के लिए कुछ और बैंकों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

13.23 आलोच्य अवधि के दौरान, 2 सहायक कंपनियों अर्थात् बांब फिक्स्ड सविसेस लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक कैपिटल सविसेस लिमिटेड के निरीक्षणों की भी व्यवस्था की गई। बैंक आफ इंडिया ने अथ अपनी सहायक कंपनी को बंद करने का फैसला किया है।

ऋण स्थगन और समांगन

13.24 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान युनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड का इलाहाबाद बैंक के साथ समांगन किया गया। भारत सरकार ने ग्लोबल बैंक की सिफारिश पर आर गैर-सरकारी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों अर्थात् द बैंक आफ तमिलनाडु लिमिटेड, द बैंक आफ तंजापुर लिमिटेड, द पार्कर मेट्रल बैंक लिमिटेड और पुर्बोचल बैंक लिमिटेड को 19 अगस्त 1989 को कारबार की समाप्ति से ऋण स्थगन के अंतर्गत रख दिया। इनमें से प्रथम तीन बैंक दिनांक 20 फरवरी 1990 से क्रमशः इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के साथ समांगन किये गये हैं। पुर्बोचल बैंक लिमिटेड पर 20 फरवरी, 1990 को कारबार की समाप्ति से पुनः लगाये गये ऋण स्थगन को 21 मई, 1990 से हटा लिया गया है।

ग्राहक सेवा

13.25 गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के आमोण, अर्धशहरी और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लगभग 1000 शाखाओं में ग्राहक सेवा के कतिपय विशिष्ट क्षेत्रों का नमूना सर्वेक्षण करने का निर्णय किया गया है। तदनुसार गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों में यह कार्य क्रमशः राष्ट्रीय शीघ्रगति इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बंबई; भारतीय

प्रबंध संस्थान; बंगलूर और कलकत्ता तथा पिलानी में विज्ञान साइंस एंड इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी जैसी प्रतिष्ठित एजेंसियों को सौंपा गया है। एक और जहाँ गुजरात के सम्बन्ध में सर्वेक्षण अभी ही पूरा किया गया है। तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के संबंध में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ होने की संभावना है।

बैंकिंग उद्योग में मशीनीकरण/कम्प्यूटीकरण

13.26 जून / 1990 के अंत में सरकारी क्षेत्र को बैंकों ने 1300 से अधिक शाखाओं में 5,007 एट्वांस लेजर पोस्टिंग मशीनें लगाईं जिनमें से 4,759 एट्वांस लेजर पोस्टिंग मशीनें परिचालित की गईं और 3,973 मशीनों पर कार्य किया जा रहा है। बैंक ने क्षेत्रीय आंचलिक कार्यालयों में 253 मिनो कम्प्यूटर लगाये हैं जिनमें से 243 को परिचालित किया गया। तीन बैंकों ने अपने-अपने प्रधान कार्यालयों में केन्द्रीय (मेनफ्रेम) कम्प्यूटर लगा दिया तथा उसे परिचालित भी कर दिया है तथा बहुत से अन्य बैंकों ने केन्द्रीय कम्प्यूटर के लिए आवेदन दे दिये थे और वे लगाये जा रहे हैं। अब तक बैंकों के लगभग 40,500 कर्मचारियों को कम्प्यूटर के बारे में एवं मशीन चलाने के बारे में प्रशिक्षित किया गया।

13.27 भारतीय बैंक सघ द्वारा सरकारी क्षेत्र के 8 बैंकों को शाखा के कार्यकलाप के पूर्ण कम्प्यूटीकरण की प्रायोगिक परियोजना आकटित की गयी थी, ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

13.28 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया था कि सितंबर 1988 में उप-गवर्नर की अध्यक्षता में बैंकों में कम्प्यूटीकरण पर एक समिति गठित की गयी है। उक्त समिति ने नवंबर 1989 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें 1990-91 तक की अवधि के लिए बैंकों के लिए एक बृहद कम्प्यूटीकरण की योजना की सिफारिश की गयी है। इस योजना में निम्नलिखित पर बल दिया गया है—शाखा के अधिकांश कार्यकलाप के लिए एक ही स्थान पर सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से शाखा स्तर पर केन्द्रीय कम्प्यूटर से संबद्ध बैंकिंग व्यवस्था शेष क्षेत्रीय/अंचलीय कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालयों के कम्प्यूटीकरण, सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए आंकड़ों के सामान्य संसूचना तंत्र के रूप में बैंकनेट की स्थापना तथा विभिन्न शाखाओं और क्षेत्रीय/अंचलीय कार्यालयों के बीच संपर्क स्थापित करना ताकि निधियों और जानकारी का स्वरित अंतरण किया जा सके, तथा अतः बैंको एवं ग्राहकों की ओर से विदेश में सरवतृपूर्वक, शीघ्रता से और अल्प मूल्य पर संदेश प्रेषित करने के लिए विश्वव्यापी अंतर-बैंक वित्तीय दूरसंचार समिति (स्विफ्ट) से जुड़ने की व्यवस्था की जा सके।

13.29 बैंकनेट के प्रथम चरण की काफी तैयारी हो चुकी है तथा 1990 में नेटवर्क का कार्य शुरू हो जाने की आशा है। लगभग सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक नेटवर्क में शामिल हुए हैं और प्रथम चरण में सात शहरों (अर्थात् बम्बई, बंगलूर, कलकत्ता, हैदराबाद, मद्रास, नागपुर और नयी दिल्ली) के लगभग 200 कार्यालय परस्पर संबद्ध किये जा रहे हैं। बैंकनेट पर इस्तेमाल करने के लिए कुछ ग्राहक-उन्मुख सेवाओं पर विचार किया जा रहा है, जैसे भांग डाफ्टों का भुगतान निधियों का तार अंतरण, बैंकों का अंतर-शहर समायोजन तथा विदेशी, मुद्रा विनिमय की दर उद्घृत करना एवं साखपक्ष खोलना।

13.30 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया था कि भारत में 37 बैंक (रिजर्व बैंक सहित 28 भारतीय बैंक और 9 विदेशी बैंक) स्विफ्ट के सदस्य बन गये हैं। इन बैंकों ने सामान्य मुद्दों पर विचार विमर्श करने तथा परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी रखने के लिए एक स्विफ्ट उपयोगकर्ता समूह बनाया है। स्विफ्ट ने बम्बई और नई दिल्ली में अप्रैल/मई 1990 के दौरान उपयोगकर्ता बैंकों के नमंजारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

तथा बंबई में अने क्षेत्रीय अभियंताकरण के स्थापन को अंतिम रूप दे दिया है।

सेक नवाभोजन का कंप्यूटीकरण

13.31 जून 1990 से त्रिवेंद्रम में समाशोधन गृह में कंप्यूटीकृत समाशोधन कार्य शुरू हो गया है। पांच केन्द्रों अर्थात्—अहमदाबाद, बंगलूर, हैदराबाद, कानपुर और नागपुर में ये कार्य पहले से ही कंप्यूटीकृत है। अक्टूबर 1989 से कलकत्ता में और मई 1990 से नई दिल्ली में एक लाख रुपये से अधिक राशि के चेकों के विशेष समाशोधन की शुरुआत किये जाने से चारों महानगरो में अब साठकर समाशोधन के प्रतिरिक्त अधिक-मूल्य के चेकों के उसी दिन मूल्य समाशोधन की व्यवस्था है। अंतर-बैंक चेकों का विशेष समाशोधन अक्टूबर 1989 से कलकत्ता में और मई 1990 में अहमदाबाद और नई दिल्ली में शुरू किया गया। यह व्यवस्था बंबई और मद्रास में पहले से ही है।

13.32 समाशोधन गृहों के वर्तमान एकसमान विनियमों और नियमों का सांविधिक आधार प्रदान करने हेतु उनका पुनरीक्षण करने के लिए विशेषज्ञों का एक वर्य बनाया गया जिसमें रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय बैंक संघ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। उक्त वर्य द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को रिजर्व बैंक जांच कर रहा है। आयोज्य वर्य के दौरान वेश में 15 नये समाशोधन गृहों ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

ऋण निगरानी व्यवस्था

13.33 पिछले वर्य की रिपोर्ट में हम बात का उल्लेख किया गया था कि ऋण प्राधिकरण योजना के स्थान पर 10 अक्टूबर, 1988 से ऋण निगरानी व्यवस्था शुरू की गई है तथा बैंकों को बड़े ऋणकर्ताओं के ऋण प्रस्ताव मंजूर करने का प्राधिकार दिया गया है। बशर्ते वे मंजूरी के बाद प्रस्ताव जांच के लिए रिजर्व बैंक को भेजे। ऋण प्राधिकरण योजना बंद किये जाने लेकर 15 महीने की अवधि में ऋण निगरानी व्यवस्था के अंतर्गत मंजूरी के बाद जांच के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या उपर्युक्त योजना बंद करने से पहले 15 महीने की अवधि में प्राप्त ऋण प्राधिकरण योजना के प्रस्तावों की संख्या 47 से प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि मुख्यतः निदिष्ट सीमा 6 करोड़ रुपये (प्राधिकरण के लिए) से घटाकर 5 करोड़ रुपये (मंजूरी के बाद जांच के लिए) कर देने से हुई थी।

13.34 मार्च 1990 तक 1,637 पार्टियों के मामले में बैंकों द्वारा ऋण निगरानी व्यवस्था के अधीन प्रस्ताव मंजूर किये गये थे और सूचित किये गये थे, जबकि मार्च 1989 के अंत में ऋण निगरानी व्यवस्था के अधीन ऐसी कंपनियों की संख्या 931 थी। इन पार्टियों के संबंध में लागू कुल कार्यकारी पूंजीगत सीमाएं मार्च 1990 के अंत में 31,479 करोड़ रुपये थी, उनमें से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अंश 15,061 करोड़ रुपये था या 47.8 प्रतिशत था। मार्च 1990 के अंत में कुल ऋण सीमाओं का सुविधा-वार स्वरूप निम्नानुसार था कार्यकारी पूंजीगत प्रयोजन (पैकिंग ऋण, देशी और विदेशी विलों सहित, 89.5 प्रतिशत, मीयादी विल 9.8 प्रतिशत, और आस्थिति अदायगी के आधार पर मशीनों की बिक्री 0.7 प्रतिशत।

13.35 1989-90 (जुलाई-जून) के दौरान बैंकों द्वारा ऋण निगरानी व्यवस्था के अधीन मंजूर और सूचित ऋण सीमाओं में बहोतरी, पिछले वर्य मंजूर बहोतरी से 16.72 प्रतिशत अधिक थी। ऋण निगरानी व्यवस्था के अधीन सूचित प्रस्तावों की संख्या इसी अवधि में 7.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

13.36 रिजर्व बैंक द्वारा की गयी समीक्षा में यह पता लगता है कि कार्यकारी पूंजी के मूल्यांकन तथा मीयादी ऋण आवश्यकताओं और बैंकों द्वारा वितरण के बाद अनुवर्ती कार्यवाई में सुधार की गुंजाइश है। भले ही उद्योगों के बड़े वर्ग के लिए स्टॉक और विलों हेतु अलग मानदंड

निर्धारित किये गये हैं, फिर भी उधार लेने वाली कंपनियों द्वारा मानदंडों का पालन केवल करीब 60 प्रतिशत रहा है। विल अनुशासन, जिसके अनुसार उधार ऋण-विवरण के 25 प्रतिशत का वितरपोषण विलों की वृद्धि के आच्छरण के माध्यम से किया जाता है, के प्रति प्रतिक्रिया भी सामान्य पायी गयी। ऐसे प्रतिकूल तत्वों को सुधार करने और भविष्य में मार्गदर्शन के लिए संबंधित क्षेत्रों के ध्यान में लाया गया। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी ऋण निगरानी व्यवस्था संबंधी विस्तृत परिचालन अनुदेशों का कड़ाई से पालन करें और साथ ही संगठनात्मक तथा प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करें एवं जहां कहीं भी आवश्यक हो वहां उसे मजबूत बनायें ताकि उनके मूल्यांकन और वितरण के बाद की अनुवर्ती प्रक्रिया में सुधार को सुनिश्चित किया जा सके।

स्टॉक/प्राप्तियों के मानदंडों में संशोधन

13.37 पेट और याचिका के निर्माताओं जिन्हें ग्राहकों की अधि-रुचि की पूर्ति के लिए विविध प्रकार का तैयार माल रखना पड़ता है, द्वारा किये गये प्रतिवेदनो को देखते हुए जुलाई 1989 में बैंकों को सूचित किया गया कि वे तैयार माल तथा प्राप्तियों के धारणों में लचीलेपन की अनुमति दें, ऐसे अलग-अलग मामलों में जहां अन्तर-परिवर्तनीयता की आवश्यकता हो 3.5 महीने के स्टॉक के संयुक्त मानदंड की अनुमति दे तथा अन्य मामलों में तैयार माल के लिए 1.5 महीने और प्राप्तियों के लिए 2.0 महीने के वर्तमान मानदंड की बनाये रखें। राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग निगम और राज्य वस्त्रोद्योग निगमों की गिन यूनिटों ने आयुनिकीकरण के लिए वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त की है, उनके मामले में ऋण देने की पद्धति के अधीन कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं का निर्धारण करने में ही गई रियायत जनवरी 1989 में एक वर्ष तक के लिए थी, उन्हें फरवरी 1991 तक बढ़ा दिया गया है। पॉलिग्रेटर स्टेपल रेशो बनाने वाले यूनिटों के सामने निरन्तर आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए तैयार माल और प्राप्तियों से संबंधित मानदंडों में दी गयी रियायत (2 महीने से बढ़ाकर 3 महीने करना) प्रारम्भ में जुलाई 1988 में ही गई थी, बाद में दिसम्बर 1990 तक बढ़ा दी गई। वस्त्रोद्योग की स्थिति के पुनरीक्षण के आधार पर संमिश्र वस्त्रोद्योग विभाग के मामले में तैयार माल और प्राप्तियों का मानदंड 30 जून, 1990 तक अलग अलग मामले में गुण-वर्ष के अनुसार अत्यन्तस्मक आधार पर 3.5 महीने कर दिया गया है जबकि नियमित मानदंड 3 महीने का है। बैंकों से संगठित गये अभिमतों के प्राप्त होने पर अवधि बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। मानदंडों के पुनरीक्षण के लिए अक्टूबर 1988 में रिजर्व बैंक द्वारा गठित उप-समिति की सिफारिशों को देखते हुए सितम्बर 1989 में उर्वरक उद्योग के मामले में तैयार माल और प्राप्तियों के मानदंड संशोधित कर उन्हें बढ़ा दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के यूनिटों द्वारा स्टॉक और प्राप्तियों की धारिता के बारे में मानदंडों का सुझाव देने के लिए गठित उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के निम्नलिखित छः उत्पाद समूहों के लिए पहली बार मानदंड निर्धारित किये गये हैं: (i) उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक, (ii) संचार, उपकरण, (iii) कंप्यूटर, (iv) नियंत्रक, इस्ट्रुमेंटेशन और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक (v) घटक तथा (vi) अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा। नवंबर 1989 में बैंकों को आय उद्योग के बड़े ऋणकर्ताओं की कार्यकारी पूंजीगत अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिए जारी संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार वर्तमान तकदी वज्रट पद्धति का अनुपालन किया जाता है। तकदी वज्रट फॉर्मेट में संशोधन किया गया है ताकि उसमें ऋणकर्ता यूनिटों के पूंजीगत और राजस्व संबंधी राशियां अलग-अलग दर्शायी जा सकें। आय यूनिटों की शुद्ध कार्यकारी पूंजी सर्वाधिक घाटे का कम से कम 25 प्रतिशत (अथ यूनिटों के मामले में 15 प्रतिशत) होनी चाहिए। आय यूनिटों को चाहिए कि वे महीने की समाप्ति के बाद चार सप्ताह के भीतर आह्वानों के मासिक तकदी वज्रट के प्रोफार्म में ही वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत करें। यदि कुछ वास्तविक कठिनाइयों के कारण यूनिट 4 सप्ताह की निर्धारित अवधि के भीतर वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत करने में असमर्थ रहती है तो बैंक

विवेकानुसार उन्हें 2 सप्ताह का और समय दे सकते हैं। 6 सप्ताह की अवधि के बाद बैंकों को चाहिए कि जिस महीने में वार्षिक आंकड़े प्राप्त नहीं होते उसके लिए वे कुल प्रथमो पर एक प्रतिशत का दण्ड-स्वरूप व्याज लगायें। बाय मुनियों को मासिक तफदी बजट प्रस्तुत करना पड़ता है, अतः उन्हें सूचना प्रणाली के अधीन विहित निमाही/छमाही विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

नवम्बर सीमाओं पर दण्डस्वरूप व्याज

13.38 बैंकों को चाहिए कि वे पोतलदान-पूर्व और पोतलदानोत्तर ऋण सीमाओं के सिवाय ऋणकर्ताओं को मंजूर तथ्य/प्रस्थापी सीमाओं पर सामान्य दर के उपर एक प्रतिशत वार्षिक का अतिरिक्त व्याज लगायें। बैंकों द्वारा इस बात की पुष्टताष्ट किये जाने पर कि क्या विवेकाधीन देशों बिल सीमाओं पर भी अतिरिक्त व्याज लगाया जाना चाहिए, जलाई 1989 में उन्हें यह सूचित किया गया कि अतिरिक्त व्याज दर से तदर्थ वेणी बिल सीमाओं को छूट दी जाये क्योंकि ऐसी ऋण सीमाएं मंजूर करने की बैंकों को शक्ति प्रदान करने का उद्देश्य बिल संस्कृति को बढ़ावा देना था।

ऋणकर्ताओं पर वित्तीय अनुशासन लागू करना

13.39 ऋणकर्ता ऋणकर्ताओं को विस्तार/विश्राज्जन या नये युनिट लगाने के लिए वित्त प्राप्त करने में रोक लगाने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे वित्तीय संस्थाओं से स्थिति का पता लगाये बिना नये मीयादी वित्त की मंजूरी के लिए आवेदनपत्रों पर विचार न करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि ऐसे मामलों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा पूछे जाने पर वे उपलब्ध जानकारी उन्हें दें। जानबूझकर की गयी ऋण कर्ता ऋणकर्ता के नियंत्रण में बाहर वास्तविक कारणों से हुई ऋण से भिन्न ऋण के मामलों की जांच करने के लिए अप्रैल 1990 से शुरू होने वाले प्रत्येक वर्ष के मार्च और सितम्बर के अंत में मीयादी ऋणों और कार्यकारी पूजागत मुविधाओं में जानबूझकर ऋण करने वाले ऐसे ऋणकर्ताओं की सूचना वे जिन्होंने बैकिंग तंत्र से 2 करोड़ रुपये और उससे अधिक की कुल ऋण मुविधाएं (निधि आधारित) प्राप्त की है। बैंकों को एक ही समूह के अन्य सभी ऋणकर्ताओं द्वारा प्राप्त मुविधाओं तथा स्वास्थ्य कूट स्थिति से संबंधित व्योरे प्रस्तुत करने होते हैं।

13.40 मीयादी बिलों पर स्टाम्प शुल्क हटा दिये जाने से (इस रिपोर्ट का पैरा 6.45 देखें) बैंकों को यह कहा गया है कि वे ऋण निगरानी व्यवस्था के अंतर्गत प्रानेवाले ऋणकर्ताओं के संबंध में देश के भीतर उधार बिक्री हेतु प्राप्य वित्त को बही ऋणों के मामले में कुल सीमाओं के 75 प्रतिशत तक तथा विल वित्त के रूप में प्रदत्त के वास्तविक स्तर तक सीमित करके अनुशासन लागू करें।

निर्यात ऋण

13.41 59 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित आंकड़े जो सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (भाग 1 में उल्लिखित) के बैंक ऋण का लगभग 95 प्रतिशत अंश है, यह दर्शाते हैं कि उनका बकाया निर्यात ऋण 6,111 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 1990 के अंत में 8,272 करोड़ रुपये हो गया जिसमें 34.7 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित होती है। इन 50 बैंकों के संबंध में कुल बैंक ऋण में बकाया निर्यात ऋण का अनुपात मार्च 1989 के अंत के 7.2 प्रतिशत से बढ़कर जनवरी 1990 के अंत में 8.0 प्रतिशत हो गया।

निर्यात ऋण (व्याज उपदान) योजना, 1968

13.42 निर्यात ऋण (व्याज उपदान) योजना, 1968 के अधीन वाणिज्य बैंकों और पात्र सहकारी बैंकों को उपलब्ध व्याज उपदान को अक्टूबर 1989 के संशोधित करके नकदी आधार पर पोतलदान पूर्व ऋण के संबंध में 5.0 प्रतिशत वार्षिक तथा पोतलदानोत्तर ऋण के संबंध में 3.85 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया, यह संशोधन 1 मार्च

1989 से लागू होगा। तब तक पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर ऋण पर उपदान की 3 प्रतिशत वार्षिक एक समान दर लागू होती थी।

आवास वित्त

13.43 नवम्बर 1989 में बैंकों को जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार उनके द्वारा आवास और शहरी विकास निगम, आवास विकास वित्त निगम तथा वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रवर्तित/प्रयोजित कंपनियों में भिन्न आवास वित्त कंपनियों को मीयादी ऋण उनकी गृह स्वाधिकृत निधियों तक ही दिये जाने थे। छूट-प्राप्त उपर्युक्त कंपनियों को छोड़कर आवास वित्त कंपनियों को जनता, वित्तीय संस्थाओं और दूसरों से संसाधन जुटाने में कठिनाई हो रही थी, तथा आवास पर दिये जाने वाले बल का भी देखते हुए जनवरी 1990 में यह निश्चय किया गया कि इन कंपनियों को अपनी गृह स्वाधिकृत निधियों के तीन गुना तक बैंकों से मीयादी ऋण का पाव बना दिया जाए।

13.44 जहां तक वर्ष 1990-91 के लिए आवास वित्त आबंटन का संबंध है, प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक से कहा गया है कि वह अपने अंश की गणना मार्च 1989 तथा मार्च 1990 के अन्तिम सूचित शत्रुवारों के दौरान वृद्धिशील जमा राशियों के 1.5 प्रतिशत के हिसाब से करे। किन्तु, बैंकों द्वारा अपने ही माधनों की स्थिति को देखते हुए तथा सर्वाधिकार प्रारक्षित निधि की अपेक्षाओं का अनुपालन करने हुए उचित स्तर तक इस सीमा का उल्लंघन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। बैंकों द्वारा प्रदान किया जाने वाला आवास वित्त जिसके लिए राष्ट्रीय आवास बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त किया जाता है, अब आवास वित्त आबंटन का हिस्सा होगा।

13.45 बैंक अपने कुल आवास वित्त आबंटन का 30 प्रतिशत अंश प्रत्यक्ष ऋण के रूप में आबंटित करने रहेंगे। इसमें से कम से कम आधी राशि ग्रामीण और कम्पाई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष आवास ऋणों के रूप में दी जाड़ी चाहिए। इसके अलावा, आबंटन का 30 प्रतिशत नवम्बर 1988 में जारी पिछले अनुदेशों में विनिर्दिष्ट परीक्ष उधार के लिए है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना है कि यह ऋण मीयादी तलों के रूप में आवास वित्त संस्थाओं, आवास बॉर्डों, अन्य सार्वजनिक आवास एजेंसियों आदि को मूल्यतः तैयार भूमि तथा निर्मित युनिटों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए दिया जाता है। बैंकों का वह भी सुनिश्चय करना है कि भूमि के प्लॉट/मकान की आपूर्ति समयबद्ध है तथा सार्वजनिक एजेंसियों ऋणों का इस्तेमाल केवल भूमि की प्राप्ति के लिए नहीं करती है। इसी प्रकार, इन एजेंसियों द्वारा तैयार प्लॉट सहकारी समितियों, व्यवसायिक विकास-कर्ताओं तथा अलग-अलग व्यक्तियों को इस शर्त पर बेचे जाने चाहिए कि उन पर 3 वर्ष से अधिक की उचित अवधि के भीतर मकान बनाये जाएं। शेष 40 प्रतिशत आबंटन राष्ट्रीय आवास बैंक तथा आवास और शहरी विकास निगम के गारंटीकृत बॉर्डों एवं डिबेंचरों में अधिदान के लिए उपलब्ध होगा।

13.46 अक्टूबर 1989 में घोषित एक नूतन ऋण नीतिगत उपायों के एक अंश के रूप में प्रति व्यक्ति आवास ऋण की राशि पर प्रतिबंध हटा दिया गया। वर्तमान में छोटे मकानों के वित्तपोषण पर दिया जाने-वाला बल बना रहेगा परन्तु पट्टे की अनुभव किया गया कि वास्तव में 3 लाख रुपये से अधिक की ऋण आवश्यकता के मामले में हो सकते हैं। अतः 3 लाख रुपये की पूर्वोक्त उच्चतम सीमा 11 अक्टूबर 1989 से हटा दी गयी। यह बैंकों पर छोड़ा दिया गया कि प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपये से अधिक के आवास ऋणों पर 16 प्रतिशत की न्यूनतम दर से अधिक दर पर व्याज लगायें। किन्तु, प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपये से अधिक के ऐसे आवास ऋण आवास वित्त आबंटन का हिस्सा नहीं होंगे।

राष्ट्रीय आवास बैंक

13.47 राष्ट्रीय आवास बैंक की शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7 सितंबर 1989 की 150 करोड़ रुपये कर दी गयी। प्रासंग्य

वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय आवास बैंक ने ढाँहों की दूसरी शृंखला जारी की तथा उसमें कुल अतिरिक्त 60 करोड़ रुपये हो गया। केन्द्रीय सरकार द्वारा गारंटीकृत इन ढाँहों पर वार्षिक 11.5 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाता है। रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से राष्ट्रीय आवास बैंक को 25 करोड़ रुपये का दीर्घावधि ऋण मंजूर किया।

13.48 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में अमरीकी सहायता कार्यक्रम के अनुमोदन का उल्लेख किया गया था जिसमें अमेरिकी सहायता सरकारी आवास गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए ऋण गारंटी प्रदान की गयी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकासशील देशों की वित्तीय संस्थाएँ 30 वर्ष तक की अवधि के लिए अमेरिकी सरकार की गारंटी के साथ अमेरिकी पूर्ण बाजार से उधार ले सकती हैं। 9 मार्च, 1990 को हस्ताक्षरित करार के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक को ऋण गारंटी कार्यक्रम के पहले भाग के रूप में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण गारंटी उपलब्ध है। इन निधियों का उपयोग आवास वित्त कंपनियों के मुख्य आय वर्ग के निम्न स्तर के परिवारों को दीर्घावधि आवास वित्त उपलब्ध कराने में सहायता करने के लिए किया जाएगा। इस कार्यक्रम से आवास वित्त कंपनियों को अपने ऋण संविभाग के बेहतर प्रबंधन में सहायता भी मिलेगी।

13.49 प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर, प्राथमिक ऋण एजसियों द्वारा दिये जाने वाले प्रत्यक्ष आवास ऋणों के राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पुनर्वित्तपोषण को आलोच्य वर्ष के दौरान उदार बना दिया गया। 1 जनवरी, 1990 से अनुसूचित वाणिज्य बैंक, अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित ग्रामीण सहकारी बैंक, आवास वित्त कंपनियाँ तथा राज्य स्तरीय शिखर सहकारी आवास वित्त समितियाँ, राष्ट्रीय आवास बैंक से अलग-अलग व्यक्तियों को (सहकारी समितियों सहित) 40 वर्ग मीटर से अधिक के निम्न क्षेत्रफल वाले या 1.5 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले (भूमि की लागत सहित) आवासीय यूनिट की प्राप्ति/निर्माण के लिए दिये गये एक लाख रुपये तक के अपने प्रत्यक्ष ऋणों के 100 प्रतिशत की सीमा तक पुनर्वित्त के लिए पात्र हैं। पुनर्वित्त पर ब्याज की दर ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एकसमान कर दी गयी। परिणामतः ऋणकर्तों को घटा कर दोनों क्षेत्रों के लिए तीन कर दिया गया। यह रियायत 1 जनवरी, 1990 को या उसके बाद मंजूर और वितरित आवास ऋणों पर लागू होती है। पुनर्वित्त पहले के समान ही, आवास की भारी मरम्मत और उन्नयन के लिए मंजूर 30,000 रुपये तक के ऋणों के 100 प्रतिशत तक मिलता रहेगा।

#### 13.50 पुनर्वित्त पर ब्याज दरें निम्नानुसार होंगी।

ऋण का प्रयोजन और राशि	ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)	
	राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा लगायी जाने वाली	प्रमुख ऋण-दाता द्वारा ऋणकर्ता को लगायी जाने वाली
1	2	3
I 40 वर्गमीटर से अधिक के निम्न क्षेत्रफल वाले या भूमि की लागत सहित 1.5 लाख रुपये से अधिक के निम्न आवासीय यूनिट की प्राप्ति/निर्माण के लिए		
(i) 20,000 रुपये तक	10.5	12.5
(ii) 20,000 रुपये से अधिक और 50,000 रुपये तक	12.0	13.5

1	2	3
(iii) 50,000 रुपये से अधिक और 1,00,000 रुपये तक	13.0	14.0
II. भारी मरम्मतों सहित उन्नयन या नूतन क्षेत्र किन्ना भी क्यों न हो		
(i) 20,000 रुपये तक	10.5	12.5
(ii) 20,000 रुपये से अधिक और 30,000 रुपये तक	12.0	13.5

जून 1990 के अन्त तक राष्ट्रीय आवास बैंक ने गात आवास वित्त कंपनियों, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, एक राज्य सहकारी बैंक, एक अनुसूचित ग्रामीण सहकारी बैंक, एक शिखर सहकारी आवास वित्त समिति और एक कृषि ग्रामीण विकास बैंक को कुल 131.69 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त (उसके विशेष ग्रामीण आवास डिपेंडेंसी में अतिरिक्त के रूप में) वितरित किया।

13.51 1 जुलाई 1989 को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुसूचित बैंकों के सहयोग से आवास ऋण खाता योजना जिसके अन्तर्गत पिछले वर्ष की रिपोर्ट में दिये गये थे, शुरू की गयी थी। सभी अनुसूचित सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के 24 अनुसूचित वाणिज्य बैंक, 5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक और 8 अनुसूचित ग्रामीण सहकारी बैंक योजना के कार्यान्वयन के लिए सहमत हो गए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने-अपने प्रायोजक बैंक के एजेंट के रूप में योजना चलाते हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि जुलाई 1989 में आवास ऋण खाता योजना की शुरुआत से लेकर जून 1990 के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत 2 लाख खाते खोले गये। गृह ऋण खाता योजना में कतिपय परिवर्तन किये गये हैं। बचत की न्यूनतम अवधि को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में प्लेट/आवास के त्रय के मामले में वर्तमान के 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। आवास ऋण खाते से ऋण की राशि पर विद्यमान 3 लाख रुपये की उच्चतम सीमा को हटा दिया गया है, परन्तु 2 लाख रुपये से अधिक के ऋणों को संवित्त बचतों के डेढ़ गुने तक सीमित रखना है। ऋण की राशि को नीचे की मांगी में दर्शाये गये अनुसार प्रत्यक्ष ऋणों के साथ संबद्ध किया गया है (और न कि आवास के प्रकार के साथ)।

आवास ऋण खाता योजना के अधीन ऋण की राशि और ब्याज की दर

संवित्त बचत के गुण के रूप में ऋण की राशि	ऋण की राशि (रुपये)	ब्याज की दर (प्रतिवर्ष प्रतिशत)
चार गुना	50,000 तक	10.5
तीन गुना	50,001-1,00,000	12.0
दो गुना	1,00,001-2,00,000	13.5
डेढ़ गुना	2 लाख से अधिक	14.5

उदाहरण के लिए, 12,500 रुपये से अधिक की संवित्त बचतों (व्याज सहित) के संदर्भ में 50,000 रुपये तक अर्थात् बचतों का चार गुना ऋण दिया जाएगा।

13.52 राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आवासीय ऋणों तथा क्षेत्र विकास प्राधिकरणों जैसी सार्वजनिक एजेंसियों की भूमि विकास और आवास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धांत अप्रैल, 1989 में कतिपय आशोधनों सहित सहकारी समितियों, व्यावसायिक विकासकर्ताओं और किराये पर आवास की योजनाओं पर भी लागू किये गये।

13.53 राष्ट्रीय आवास बैंक ने जून 1990 तक भूमि विकास और आवास निर्माण के लिए 56 परियोजना प्रस्तावों का निदानतः अनुमोदन किया। जिनके परिचय की कुल राशि 413.80 करोड़ रुपये थी।

#### रुण औद्योगिक ऋकाईयां

13.54 बैंकों को फिर से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि रुण कमजोर औद्योगिक यूनिटों के पुनर्गठन में रिजर्व बैंक के अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है तथा इन अनुदेशों का उल्लंघन किये जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि संघीय व्यवस्था के अधीन स्वस्थ यूनिट का वित्तपोषण करने वाले बैंकों के बीच परस्पर करार के अन्तर्गत इस प्राणय का खंड जोड़ा जाना चाहिए कि यूनिट रुण हो जाने की स्थिति में बैंकों की रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार पुनर्गठन के एकमुश्त कार्यक्रम में भाग लेना होगा और ऐसा खंड सभी विद्यमान पारस्परिक करारों में भी विधिवत् जोड़ा जाए। यदि बहुविध बैंकिंग व्यवस्था के अधीन यूनिट का वित्तपोषण किया जा रहा है तो बड़े प्रभाव वाले बैंकों को चाहिए कि अन्य वित्तपोषण बैंकों से इस संबंध में उपयुक्त वचन प्राप्त करें। साथ ही, बैंकों को यह अनुदेश जारी किये गये हैं कि अपवादस्वरूप मामलों में जहाँ वे चलनिधि संबंधी अस्थाई बाधा के कारण पुनर्गठन एकमुश्त कार्यक्रमों में भाग लेने में असमर्थ होते हैं, वहाँ संबंधित बैंकों द्वारा पुनर्गठन कार्यक्रम शुरू होने से पहले अपने श्रेण से अधिक की ऋण सीमाएं प्रदान करने वाले बैंकों के पक्ष में इस बात की गारंटी प्रस्तुत की जानी चाहिए कि उनकी ओर से उधार दी गयी राशि की वे प्रतिपूर्ति करेंगे।

13.55 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने छः बैंकों को रुण औद्योगिक यूनिटों के लिए पुनर्गठन योजनाएं तैयार करने हेतु "परिचालन एजेंसी" के रूप में विनिर्दिष्ट किया था। दो अन्य बैंक अर्थात् इंडियन बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया भी औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा इसके लिए विनिर्दिष्ट किये गये हैं। इस प्रकार अब छः बैंक हैं जिन्हें औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड "परिचालन एजेंसी" के रूप में नियुक्त कर सकता है।

13.56 जून 1988 के अन्त के आंकड़ों के अद्यतन उपलब्ध अनुसार बैंकों द्वारा "रुण" यूनिट (रुण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 में परिभाषित) के रूप में पता लगायी गयी लघु उद्योग से इतर यूनिटों की कुल संख्या 1,172 थी जिनके बकाया बैंक ऋण की राशि 3,028 करोड़ रुपये थी। इनमें से 944 यूनिटों के संबंध में सक्षमता संबंधी अध्ययन पूरा किया गया और उनमें से 350 यूनिट सक्षम माने गये। सक्षम समझे गये यूनिटों में से 234 यूनिटों के संबंध में बैंकों ने पुनर्गठन कार्यक्रम शुरू कर दिया। बैंकों द्वारा कमजोर के रूप में पता लगाने गये लघु उद्योग यूनिटों से भिन्न यूनिटों की कुल संख्या जून 1988 के अन्त में 743 थी और उनके संबंध में बकाया बैंक ऋण की राशि 1,922 करोड़ रुपये थी। इनमें से 569 यूनिटों के संबंध में सक्षमता संबंधी अध्ययन पूरा किया गया और इनमें से 302 यूनिट सक्षम माने गये। सक्षम यूनिटों में से 164 के संबंध में बैंकों ने पुनर्गठन कार्यक्रम शुरू कर दिया।

13.57 जून 1988 के अन्त में 2,17,436 रुण लघु उद्योग यूनिट थे जिनमें 1,980 करोड़ रुपये का बैंक ऋण था, उनमें से 451 करोड़ रूपयों के बकाया बैंक ऋण से युक्त 12,954 यूनिटों को बैंकों द्वारा संभाव्यतः सक्षम यूनिट माना गया और 8,347 यूनिटों के संबंध में पुनर्गठन कार्यक्रम शुरू कर दिया गया।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बीच कार्यों का सीमांकन

13.58 नाबाई तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के बीच कार्यों के सीमांकन पर रिजर्व बैंक द्वारा परामर्श करके विचार किया गया और यह मान लिया गया है कि इन

संस्थाओं के कामकाज के समान क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन किया जाएगा:

(i) राज्य वित्त निगम गृहरे कार्यवाले राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा गृहरी सहकारी बैंक लघु उद्योग/अर्थवत् लघु/विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के यूनिटों को प्रदत्त सहायता के संबंध में केवल भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से ही पुनर्वित्त प्राप्त करेगा। ऐसे यूनिटों को ग्रामीण क्षेत्रों (नाबाई अधिनियम में परिभाषित) से भिन्न क्षेत्रों में प्रदत्त सहायता का पुनर्वित्तपोषण भी केवल भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा ही किया जाएगा।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों (नाबाई अधिनियम में परिभाषित) में लघु उद्योग/अर्थवत् लघु/विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों के सभी यूनिटों को वाणिज्य बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सहकारी बैंक (गृहरी सहकारी बैंक से भिन्न) द्वारा प्रदत्त सहायता का पुनर्वित्तपोषण नाबाई द्वारा किया जायेगा।

(iii) राज्य सहकारी बैंकों/केन्द्रीय सहकारी बैंकों को या तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जाए।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इन संस्थाओं से पुनर्वित्त उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही प्राप्त किया जाता है।

वित्तीय संस्थाओं को रिजर्व बैंक द्वारा सहायता

13.59 रिजर्व बैंक ने नाबाई को वर्ष 1989-90 (जुलाई-जून) के लिए कुल 3,350 करोड़ रुपये की सामान्य ऋण सुविधा मंजूर की जबकि 1988-89 में यह सीमा 2,700 करोड़ रुपये थी।

13.60 रिजर्व बैंक ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से से वर्ष 1989-90 (जुलाई-जून) के लिए कुल 375 करोड़ रुपये की दीर्घावधि निधियां मंजूर और वितरित की जिनकी श्रुती 15 वर्ष की अवधि में की जानी है तथा इस पर व्याज दर 8 प्रतिशत वार्षिक है। वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा चुकाये गये 81.02 करोड़ रुपये की राशि को हिसाब में लेने के पश्चात् राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से इसकी बकाया उधार राशियां 30 जून 1990 को 3,822 करोड़ रुपये हो गयी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को इसके द्वारा पुनर्गठित प्राप्त मीयाब बिलों की जमात पर 14 मार्च 1990 को 400 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण सीमा भी मंजूर की गयी। यह ऋण सीमा जून 1990 के अन्त तक वैध थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना के फलस्वरूप भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से किया गया समग्र आबंटन वर्ष 1990-91 के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को उपलब्ध कराने के लिए सहमत हुआ।

13.61 पिछले वर्ष की तरह निर्वर्त-प्रायात बैंक को वर्ष 1989-90 (जुलाई-जून) के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण मंजूर किया गया जिसे 7 प्रतिशत वार्षिक व्याज दर पर 15 वर्षों की अवधि में चुकाया जाना था। निर्वर्त-प्रायात बैंक ने उक्त ऋण सीमा का पूरा लाभ उठाया और 30 जून 1990 को दीर्घकालीन प्रवर्तन निधि से इसकी बकाया उधार राशियां 625 करोड़ रुपये हो गई।

13.62 भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को भी पिछले वर्ष की तरह राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से वर्ष 1989-90 (जुलाई-जून) के लिए 25 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण मंजूर किया गया जिसे 6 प्रतिशत वार्षिक व्याज दर पर 15 वर्षों की अवधि में चुकाया जाना था। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने उक्त ऋण सीमा का पूरा लाभ उठाया और 30 जून 1990 को उक्त निधि से इसकी बकाया उधार राशियां 95 करोड़ रुपये हो गयी।

13.63 राष्ट्रीय आवास बैंक को ग्रामीण आवास की प्रगति के लिए राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से वर्ष 1989-90 (जुलाई-जून)

के लिए 25 करोड़ रुपये का वार्षिकालीन ऋण संजूर किया गया जिसे 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 20 वर्षों की अवधि में चुकाया जाता था।

13.64 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को सितंबर वर्ष 1990 के लिए 30 करोड़ रुपये की तदर्थ ऋण सीमा संजूर की गयी।

13.65 भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को वर्ष 1989-90 (अप्रैल-मार्च) के लिए 30 करोड़ रुपये की तदर्थ ऋण सीमा संजूर की गयी। इस सुविधा का लाभ कई बार उठाया गया, हालांकि 31 मार्च, 1990 को इस ऋण सीमा के प्रति कोई राशि बकाया नहीं थी। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को वर्ष 1990-91 (अप्रैल-मार्च) के लिए 33 करोड़ रुपये की नयी ऋण सीमा संजूर की गयी है।

13.66 रिजर्व बैंक ने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत तदर्थ बंधपत्रों (बांणों) की जमानत पर 15 राज्य वित्त निगमों (तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि. सहित) को कुल 88.00 करोड़ रुपये की नयी तदर्थ ऋण सीमा संजूर की। ये ऋण सीमाएं 25 जून 1990 तक वैध थीं। 31 मार्च 1990 को इन ऋण सीमाओं के प्रति कुल बकाया राशि 43.65 करोड़ रुपये थी।

#### प्राथमिक सहकारी बैंक (i) प्रगति

14.1 शहरी बैंकिंग सुविधाओं से रहित जिलों में नये शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस स्वीकृत करने के संबंध में 1986 में घोषित नीति 1989-90 के दौरान जारी रखी गयी। रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान (30 जून 1990 तक) संबंधित राज्यों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए 23 प्रस्तावों को पारित कर दिया और बैंकिंग कारोबार शुरू करने के लिए बैंकों को 17 लाइसेंस जारी किये। जून 1989 के अंत में मौजूद 1,378 प्राथमिक सहकारी बैंकों की तुलना में जून 1990 के अंत में देश में 1390 प्राथमिक सहकारी बैंक थे (जिसमें से 48 समाधानाधीन थे) इनमें 36 महिला बैंक और 92 वित्तयोगियों के बैंक शामिल हैं। वर्ष के दौरान (जून 1990 तक) भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए 14 वर्तमान बैंकों को भी लाइसेंस स्वीकृत किये गये और इस प्रकार लाइसेंस प्राप्त प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या 1013 हो गयी।

14.2 54 नये कारोबार स्थल खोलने के लिए 1989-90 के दौरान 52 प्राथमिक सहकारी बैंकों (दो वित्तयोगियों के बैंकों सहित) को अनुमति दी गयी। साथ ही, छ. शहरी बैंकों को मात विस्तार काउंटर खोलने की अनुमति दी गयी। दिसंबर 1989 के अंत में प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के कार्यलयों की संख्या जून 1989 के अंत में मौजूद 3,279 कार्यलयों की तुलना में 3,283 हो गयी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 381 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को 436 शाखाएं प्राबंठित की गयी जिनमें से 30 जून 1990 के अंत तक 195 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा 225 शाखाएं खोली गयीं।

14.3 अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों की कुल संख्या 11 बनी रही।

14.4 प्राथमिक सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने कुल प्रभिमों का 60 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्रदान करें जिसमें से कम से कम 25 प्रतिशत कमजोर वर्गों को प्रदान किया जाना चाहिए। 532 रिपोर्टकर्ता प्राथमिक सहकारी बैंकों में से 359 बैंक जून 1989 के अंत तक उक्त स्तर तक पहुँच चुके थे। इन 359 बैंक में से 345 बैंक कमजोर वर्गों को उधार देने के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर चुके थे।

#### (ii) पुनर्वित्त सुविधाएं

14.5 1989-90 (अप्रैल-मार्च) के दौरान विनिर्दिष्ट कुटीर/लघु उद्योग इकाइयों की कार्यशील पूंजीगत अपेक्षाओं के वित्तपोषण के लिए 53 प्राथमिक सहकारी बैंकों की ओर से पांच राज्य सहकारी बैंकों को रु० 20.71 करोड़ की कुल अन्ववधि ऋण सीमाएं संजूर की गयीं, जबकि पिछले वर्ष 52 प्राथमिक सहकारी बैंकों की ओर से रु० 26.00 करोड़ की राशि संजूर की गयी थी। 31 मार्च 1990 को इन ऋण सीमाओं के प्रति रु० 20.97 करोड़ की राशि बकाया थी। अंततः पुनर्वित्त को वूर करने के प्रयोजन के लिए सरकारी और

व्यासी प्रतिभूतियों की संगणिक जमानत पर पुनर्वित्त की सुविधा अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को प्रदान की गयी है। पुनर्वित्त सीमा संबंधित बैंक की मांग और आवधिक देयताओं के एक प्रतिशत तक सीमित रखी जाएगी। इस पुनर्वित्त पर वर्तमान ब्याज दर 12.5 प्रतिशत है।

#### (iii) अनिवारी खाने

14.6 जून 1990 के अंत में, 49 प्राथमिक सहकारी बैंकों को रूपयों में अनिवारी (सामान्य/विदेशी) खाते खोलने और उन्हें चालू रखने के लिए प्राधिकृत किया गया।

#### (iv) सांविधिक निरीक्षण

14.7 1 जुलाई 1989 से 30 मार्च 1990 तक की अवधि के दौरान 502 प्राथमिक सहकारी बैंकों का निरीक्षण किया गया।

#### (v) भारतीय मित्रीकाटा और वित्त गृह लि. के साथ लेदेन

14.8 शहरी सहकारी बैंक को भारतीय मित्रीकाटा और वित्त गृह लि. के साथ अंतर बैंक बाजार में ऋण दाता और उधारकर्ता दोनों रूपों में लेनदेन करने की अनुमति दी गयी है। इसे ध्यान में रखते हुए मित्रीकाटा और वित्त गृह लि. से शहरी सहकारी बैंकों को प्राप्त जमा राशियों को समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों पर जारी किये गये निदेशों के प्रावधानों से मुक्त रखा गया है।

#### (vi) ग्राहक सेवा

14.9 बाणिज्य बैंकों को जारी किये गये अनुदेशों के अनुरूप शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे बाहरी चेकों की बसूली में बिजब होने पर देय ब्याज की राशि 25 पैसे या उससे अधिक होने पर उसे ग्राहकों के खाते में जमा करें। साथ ही, शहरी सहकारी बैंकों को रु० 2500 की समग्र सीमा के भीतर एक समय पर एकाधिक बाहरी चेक के लिए तत्काल राशि जमा करने की अनुमति दी गयी है। उन्हें अधिम के प्रयोजन पर विचार करने के बाद तथा रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों पर समय-समय पर जारी किये निदेशों के अनुसार किसान विकास पत्रों की जमानत पर अधिम संजूर करने के लिए भी सूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें सामान्य शर्तों के अधीन राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों (8 वां निर्गम) को गिरवी रखकर अधिम संजूर करने की अनुमति दी गयी है। राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक (i) लाइसेंस

14.10 वर्ष के दौरान भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए तीन जिन मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु-प्रदेश में एक एक) को लाइसेंस स्वीकृत किये गये। इस प्रकार जून 1990 के अंत में लाइसेंस प्राप्त राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की कुल संख्या क्रमशः 8 और 40 हो गयी। वर्ष के दौरान तीन कार्यालय खोलने के लिए तीन राज्य सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी किये गये।

#### (ii) ब्याज दरें

14.11 रिजर्व बैंक द्वारा बाणिज्य बैंकों के संबंध में जमा राशियों पर देय ब्याज दरों की संरचना में समय-समय पर किये गये परिवर्तन राज्य मध्यवर्ती सहकारी बैंकों पर भी लागू किये गये हैं। तदनुसार अन्ववधि अनिश्चित निधियों पर बेहतर दर पर प्रतिकूल प्रदान किये जाने को ध्यान में रखते हुए 46 दिनों से 90 दिनों तक की भी सीमादी जमा पर ब्याज दर 11 अक्टूबर 1989 से 6 प्रतिशत से बढ़कर 8 प्रतिशत वार्षिक कर दी गयी। एक वर्ष के लिए देशी सीमादी जमा राशियों पर ब्याज दरों और परिपक्वताओं के युक्तिकरण के अनुरूप अनिवारी (विदेशी) रूपदा खातों में सीमादी जमा पर देय ब्याज दरों और परिपक्वताओं को 16 अप्रैल 1990 से युक्तिकृत किया गया। तदनुसार 15 दिन से 45 दिन की परिपक्वता अवधि समाप्त कर दी गयी है और 46 दिन से लेकर एक वर्ष से कम अवधि की परिपक्वता अवधि के लिए इस प्रवर्ग की सीमादी जमा राशियों पर 8.5 प्रतिशत की एक समान ब्याज दर लागू की गयी है।

14.12 11 अक्टूबर 1989 से तीन वर्षों से अनुरूप अधिम के सीमादी ऋणों को जिन पर 15 प्रतिशत ब्याज दर लगाई जाती थी, 15 प्रतिशत की न्यूनतम दर के अधीन कर दिया गया, परंतु उनके लिए कोई उच्चतम दर नहीं रखी गयी।

**कृषि पुनरीक्षण समिति**

14.13 ग्रामीण ऋण संबंधी समस्त मामलों का पुनरीक्षण करने के नि भारत सरकार के अनुसूत्र पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त कृषि ऋण पुनरीक्षण समिती ने अगस्त 1989 में अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दी और उक्त रिपोर्ट वर्तमान समय में विचाराधीन है। समिति की प्रमुख सिफारिशें और उनका तर्काधार निम्नानुसार हैं—

(i) समिति का यह मानना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कमजोरियों आंतरिक हैं और अर्थसमर्थनता उनकी संरचना में मौजूद है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थसमर्थनता लक्षित समूह के हितों को पूरा करने में समर्थ नहीं होंगे। अतः प्रायोजक बैंक के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय कर दिया जाना चाहिए।

(ii) समिति ने कृषि क्षेत्र के लिए उधार ब्याज दरों को मुक्तिकरण की सिफारिश की है और यह सुझाव दिया है कि वो प्रकार की ही ब्याज दरें होनी चाहिए, अर्थात्:—

(क) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जमाराशियों पर उच्चतम अनुमत ब्याज दर से 1.5 प्रतिशत अधिक ब्याज दर (जिसका अर्थ है वर्तमान समय में 11.5 प्रतिशत की उधार ब्याज दर) केवल लघु और सीमांत किसानों के लिए और

(ख) अन्य पर अर्थात् शेष उधारकर्ताओं पर लागू ब्याज दर जहाँ ब्याज की दर निर्देशों/विनियमों से मुक्त होगी, तथापि, वह 15.5 प्रतिशत की उच्चतम ब्याज दर के अधीन होगी, जो वर्तमान समय में अधिकतम दर है। (इसका अर्थ होगा परवर्ती प्रवर्ग के लिए 15.5 प्रतिशत की उधार ब्याज दर)।

(iii) कृषि ऋण पुनरीक्षण समिति का यह मानना है कि ऋण सहकारी समितियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष बैंक के अभाव में सहकारी ऋण विन्यास अपनी सेवाओं को कृषक भारतीय को-ऑपरेटिव लि. (कृषको) जैसी शेष सहकारी विन्यासों के अनुरूप हृदयतम स्तर तक नहीं पहुंचा सका है, जिन्हें वाणिज्य बैंकों पर निर्भर रहना पड़ता है। समिति को अनुसार एक राष्ट्रीय बैंक के सुझाव में सहकारी बैंकिंग प्रणाली दो तरह से हानि उठा रही है: एक और, इसके सहकारी बैंकों की अधिशेष जमाराशियां वाणिज्य बैंकों के पास बली जाती हैं और दूसरी ओर, यह बेहतर और अधिक लाभप्रद ग्राहक वर्ग (इसको और कृषकों जैसा) छोड़ देती है। अतः समिति ने एक भारतीय राष्ट्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की सिफारिश की है जो सहकारी ऋण प्रणाली के लिए संतुलन केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

(iv) समिति ने तीन पूर्वी क्षेत्र के राज्यों अर्थात् बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में से प्रत्येक के लिए एवं सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक कृषि और ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निगम की स्थापना का सुझाव दिया है। इन निगमों के लिए परिकल्पित मुख्य कार्य है: कृषि ऋण की गति बढ़ाने के लिए सशक्त नीति अपनाना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक नियम प्राव-प्रयत्न पूर्वापर संपर्कों और समर्थक सेवाओं की स्थापना करने, कृषि में रूपांतरण की गति बढ़ाने हेतु स्थान-विशिष्ट योजनाएं बनाने के लिए और परियोजनाओं के निधिपोषण की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई शुरू करेगा।

(v) वर्तमान फसल बीमा योजना में कमी के संदर्भ में, समिति ने फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए संसद के एक अधिनियम के

अंतर्गत एक पृथक निगम स्थापित करने की और प्रस्तावित योजना को परिष्कृत करने हेतु उसका अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति, जिसमें बीमा विशेषज्ञ, कृषि अर्थशास्त्री आदि शामिल होंगे, बनाने की सिफारिश की है।

(vi) समिति ने देयराशियों की वस्तु की तुल्य समूचे देश के लिए सहकारी और वाणिज्य बैंकों को समाविष्ट करने हुए एक समान विधिक विन्यास सुनिश्चित करने और न्यायनिर्णयन के लिए राज्य स्तरीय न्यायाधिकरण तथा अंशों के निष्पादन के लिए अलग विभाग बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

(vii) समिति ने ग्रामीण बैंकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण नीति तैयार करने के लिए एक शीर्ष एजेंसी स्थापित करने की सिफारिश की है।

(viii) कृषि ऋण पुनरीक्षण समिति ने यह सुझाव दिया है कि जिस प्रकार सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अंतर्गत वाणिज्य बैंक की शाखा को गांव आबंटित किया जाता है, उसी प्रकार एक प्रखंड में जिस वाणिज्य बैंक की शाखाएं सर्वाधिक हों, उसे एक प्रखंड आबंटित किया जाए। इस प्रकार के मुक्तिकरण से पर्यवेक्षण की लागत कम होगी, निगरानी की गुणवत्ता में सुधार होगा और यह ग्राहकों के लिए हितकारी होगा।

**15. अन्य गतिविधियाँ****निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी नियम**

15.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ने बैंकों के छोटे जमाकर्ताओं को बीमा रक्षा प्रदान किया जाना तथा बैंकों द्वारा प्रदान किए गए समस्त प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के लिए और कृषि, छोटे उधारकर्ताओं एवं लघु उद्योगों के लिए अग्रिम देनेवाले अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं के लिए गारंटी सहायता देना जारी रखा है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम पांच ऋण गारंटी योजनाएं चलाता है जिनमें छोटे उधारकर्ताओं के लिए और एक लघु उद्योग क्षेत्र के लिए।

15.2 बीमाकृत बैंकों की संख्या 30 जून 1989 को 1908 थी, जो बढ़कर 31 जून 1990 को 1917 हो गयी, जिसमें 79 वाणिज्य बैंक, 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 1,642 सहकारी बैंक शामिल हैं, जो 16 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों में स्थित हैं। रु० 1,01,682 करोड़ की बीमाकृत राशि जून 1989 के अंत में कुल निक्षेपणीय जमाराशियों का 72.2 प्रतिशत है। पूर्णतः संरक्षित जमाराशियों खातों की संख्या जमाराशि खातों की कुल संख्या का 97.4 प्रतिशत है।

15.3 जून 1990 के अंत में लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 में भाग लेने वाले बैंकों की संख्या 263 थी, जिसमें 67 वाणिज्य बैंक और 196 (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) थे। लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971 में भाग लेने वाले राज्य वित्तीय निगमों (राज्य औद्योगिक विकास निगमों सहित) की संख्या 20 बनी रही। जून 1990 के अंत में सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना, 1971 में भाग लेने वाली ऋण संस्थाओं की संख्या 175 की जबकि लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना में भाग लेनेवाली प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक की संख्या 90 थी। उक्त चार योजनाओं के तहत कुल गारंटीकृत अग्रिम राशि मार्च 1989 के अंत में रु० 25,586 करोड़ हो गयी, जहाँ जून 1988 के अंत में मौजूब स्तर की तुलना में 79 प्रतिशत की वृद्धि



वर्षाता है और इसका कारण है— 1 अप्रैल 1989 से समस्त प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अधिनियमों को समाविष्ट करने के लिए गारंटी सहायता के क्षेत्र का विस्तार किया जाना।

15.4 निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 में भाग लेनेवाली संस्थाओं की संख्या जून, 1989 के अंत में 545 थी, जो बढ़कर जून 1990 के अंत में 555 हो गयी। लघु उद्योग क्षेत्र को दी गयी गारंटीकृत अधिम राशि जून 1988 के अंत में रु. 10,465 करोड़ थी, जो बढ़कर मार्च 1989 के अंत में रु. 14,094 करोड़ हो गयी है, जो 31.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

15.5 निगम को जुलाई 1989-जून 1990 की अवधि के दौरान छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित गारंटी योजनाओं के संबंध में रु. 402 करोड़ के लिए 17.04 लाख बावे तथा लघु उद्योगों के लिए इसकी योजना के संबंध में रु. 153 करोड़ के 0.75 लाख बावे प्राप्त हुए। उसी अवधि के दौरान निगम के छोटे उधारकर्ताओं के संबंध में रु. 376 करोड़ के 17.52 लाख बावे और लघु उद्योग योजना के संबंध में रु. 374 करोड़ के 0.88 लाख बावे निपटा दिये।

15.6 1984 से 1988-89 तक निगम द्वारा प्राप्त किए गये गारंटी दावों की मात्रा इसकी गारंटी शुल्क प्राप्तिओं से अधिक बनी रही है। निगम का गारंटी शुल्क 1 अप्रैल, 1989 से एक समान तौर पर बढ़ाकर 1.50 प्रतिशत वार्षिक करने का उल्लेख गन वर्ष की रिपोर्ट में किया गया था।

जमाराशियों का स्वीकृति को शासित करने वाली गैर-बैंकिंग कंपनी विनियम

15.7 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए में किये गए संशोधन, जिससे कंपनी बोर्ड की गैर-बैंकिंग, गैर-वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशियों की गैर-प्रदायगी का सजान लेने का अधिकार मिला, के अनुक्रम में कंपनी कार्य विभाग ने उक्त संशोधन के संबंध में जनता को सूचित करते हुए प्रेम में एक सूचना जारी की है ताकि श्रद्धालुओं के व्यक्तिगत जमाकर्ता अपनी शिकायतें दूर कराने के लिए कंपनी बोर्ड के संबंधित कार्यवाहियों से संपर्क कर सकें। मार्च 1989 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (रिजर्व बैंक) निवेश, 1977 में किये गये कतिपय परिवर्तनों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से प्रथम अनुसूची में, अर्थात् जमाराशियों को सांख्यिक विवरणी प्रस्तुत करने के फॉर्म को बिनांक 1 फरवरी, 1990 को जारी की गयी अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है।

चिट फंड अधिनियम, 1982

15.8 चिट फंड अधिनियम, 1982 अब तक 19 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लागू हो चुका है जिनमें अमरा और राजस्थान राज्य भी शामिल हैं, और जहां अधिनियम समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू हुआ है। अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाई की जा रही है।

गैर-निगमित निकायों द्वारा जमाराशियों का स्वीकृति

15.9 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान चार अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने अधिसूचना जारी कर उपयुक्त अधिकारियों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45न और 58ए में परिचालित गैर-निगमित निकायों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया है। इस प्रकार छह राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने उक्त अधिनियम के

अध्याय IIIग के प्रविष्टात्मक प्रावधानों को लागू करने की शक्ति प्राप्त कर ली है।

15.10 गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और दिल्ली में स्थित 120 निकायों, जिनका अन्वेषण बैंक के राज्य पुलिस/सरकारी अधिकारियों की सहायता से किया, में से अठारह निकायों के विरुद्ध अध्याय IIIग के प्रावधानों का अनुक्रमण करने के लिए अभियोजन की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। दो मामलों को जमानत लगाकर निपटाया गया है जबकि उच्चतम न्यायालय ने चार मामलों के संबंध में कार्रवाई स्थगित कर दी है और एक अन्य मामले को अभिलेखित कर दिया गया है। शेष मामलों में विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है।

गैर-बैंकिंग कंपनियों क्षेत्र जमाराशियों वृद्धि की प्रवृत्तियां

15.11 31 मार्च 1989 के समाप्त वर्ष के दौरान उपलब्ध-अंतिम प्राकट्यों के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली 10,088 गैर-बैंकिंग कंपनियों की कुल जमाराशियों में 4,445 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और वह रु. 28,649 करोड़ हो गयी जबकि 1988 में 10,323 कंपनियों की जमाराशियां रु. 24,204 करोड़ थी। वर्ष 1988-89 में दौरान विनियमित जमाराशियों में रु. 1,049 करोड़ की वृद्धि हुई और वे रु. 5,784 करोड़ हो गयी। (एक सरकारी वित्तीय कंपनी द्वारा जारी किये गये बांडों पर लिये गये रु. 531 करोड़ के उधार सहित), जबकि छूट प्राप्त जमाराशियों में 3,396 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और वे रु. 22,865 करोड़ हो गयीं। कुल जमाराशियों में गैर-वित्तीय कंपनियों का अंश 62.9 प्रतिशत है जबकि वित्तीय कंपनियों का अंश 34.1 प्रतिशत और विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों का अंश 3.0 प्रतिशत है। गैर-बैंकिंग कंपनी क्षेत्र की विनियमित जमाराशियां 1987-88 के दौरान रु. 4,735 करोड़ से बढ़कर रु. 5,784 करोड़ हो गयीं जो 22.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं और ये जमाराशियां सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों के 4.1 प्रतिशत के बराबर थी। वित्तीय कंपनियों की विनियमित जमाराशियां मार्च 1989 के अंत में रु. 1,136 करोड़ थी, जो बढ़कर मार्च 1989 के अंत में रु. 1,977 करोड़ (अंतिम) हो गयी। एक बड़ी सरकारी कंपनी, जो इस वृद्धि के एक बड़े हिस्से का कारण है, को छोड़कर वित्तीय कंपनियों की विनियमित जमाराशियां मार्च 1988 के अंत में रु. 1,096 करोड़ थी, जो बढ़कर मार्च 1989 के अंत में रु. 1,446 करोड़ हो गयीं अर्थात् उनमें 31.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें से अधिकांश राशि की वृद्धि पट्टे पर देनेवाली कंपनियों और किराया खरीद कंपनियों द्वारा की गई। मार्च 1989 में रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली 6,355 वित्तीय कंपनियों में से 192 कंपनियों (एक बड़ी सरकारी कंपनी को छोड़कर) की जमाराशियां विनियमित जमाराशियों का लगभग 77.0 प्रतिशत है। मार्च 1988 और मार्च 1989 के बीच वित्तीय कंपनियों की छूट प्राप्त जमाराशियों में तीव्र वृद्धि का बहुत बड़ा श्रेय भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय मनीकाटा और वित्त गृह और एम वी आइ कैपिटल मार्केट लिमिटेड जैसी कतिपय संस्थाओं को है जिन्हें वित्तीय कानिनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

15.12 इन प्राकट्यों में शामिल की गयी विभिन्न प्रकार की कंपनियों के अलावा कई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां भी हैं जिनकी जमाराशियां स्थूल रूप से रु. 1,200 करोड़ के आस-पास होने का अनुमान है। मार्च 1983 और 1989 के अंत में विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा धारित जमाराशियों के ब्योरे निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये हैं।

## गैर-बैंकिंग कंपनी क्षेत्र की जमा राशियां

(माप के अन्त में)

(करोड़ रुपये)

1987-88@

1988-89 (अंतिम)

प्रकार	रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या	विनियमित जमा राशियां	छूट-प्राप्त जमा राशियां	कुल	रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या	विनियमित जमा राशियां	छूट-प्राप्त जमा राशियां	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क. कुल जमा राशियां	10,323	4,735	19,469	24,204	10,088	5,784	22,885	28,649
ग. इनमें से निम्नलिखित के द्वारा धारित जमा राशियां :								
(i) विदेशी कंपनियां:	2,725 (26.4)	3,599 (76.3)	13,106 (67.3)	16,705 (69.0)	2,498 (24.8)	3,805 (65.8)	14,211 (62.2)	18,016 (62.9)
(ii) वित्तीय कंपनियां	6,442 (62.4)	1,136* (24.0)	5,590 (28.7)	6,726 (27.8)	6,355 (63.0)	1,977** (34.2)	7,801 (34.1)	9,778 (34.1)
(iii) विविध गैर-बैंकिंग कंपनियां	1,156 (11.2)	-- (--)	773 (4.0)	773 (3.2)	1,235 (12.2)	2 (--)	853 (3.7)	855 (3.0)

@1987-88 के आंकड़ों की व्याप्ति और वर्गीकरण के अनुसार विस्तृत रूप से संशोधित किया गया है ताकि 1988-89 के आंकड़ों के साथ उनकी तुलना की जा सके।

\*एक सहकारी कंपनी द्वारा चल आस्तियों की जमागत पर जारी किये गये बांधों के जरिये जुटाये गये रु. 40 करोड़ शामिल हैं।

\*\*एक सहकारी कंपनी द्वारा चल आस्तियों की जमागत पर जारी किये गये बांधों द्वारा जुटाये गये रु. 531 करोड़ शामिल हैं।

टिप्पणी : कोष्ठकों के दर्शाये गये आंकड़े यथास्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की कुल संख्या/विनियमित/छूट प्राप्त/कुल जमा राशियों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

## 16. विदेशी मुद्रा निबंधन संबंधी गतिविधियां

## निबंध विदेशी मुद्रा परमिट योजना

16.1 निर्यात-आयात बैंक द्वारा चलायी जानेवाली निबंध विदेशी मुद्रा परमिट योजना के अंतर्गत निर्यातकों को दी जानेवाली सहायता को और बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ निर्यात विकास परियोजना के संदर्भ में 295 मिलियन अमेरिकी डालर की एक ऋण व्यवस्था के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इस समझौते से पहले की औद्योगिक निर्यात परियोजना में फर्मों को व्यवस्थित निर्यात योजनाएं बनाने और कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित करने के प्रयासों को मजबूत किया जा सकेगा जिससे निर्यातों में वृद्धि हो। इस परियोजना में मीयादी ऋण घटक (275 मिलियन अमेरिकी डालर) और निर्यात विकास निधि घटक (20 मिलियन अमेरिकी डालर) शामिल हैं। निर्यात विकास निधि में केवल बाजार विकास ही नहीं है बल्कि पारंपरिक स्तर पर उत्पादकता में सुधार के उपाय भी शामिल हैं। उक्त निर्यात विकास निधि चार एजेंसियों अर्थात् निर्यात-आयात बैंक (7 मिलियन अमेरिकी डालर), भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (7 मिलियन अमेरिकी डालर), बैंक ऑफ बड़ोदा (3 मिलियन अमेरिकी डालर), और केनरा बैंक (मिलियन अमेरिकी डालर) द्वारा संचालित की जायेगी।

16.2 उपर्युक्त निर्यात निधि और मीयादी ऋण घटक के अंतर्गत प्राप्त निर्यातकों को रिजर्व बैंक द्वारा निबंध परमिट जारी किये जाने के लिए भी पात्र समझा जायेगा। ऐसे निर्यातकों को रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें जारी निबंध परमिट पर प्राह्वान करने की अनुमति होगी जिसे संबंध संस्था अर्थात् निर्यात-आयात बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, बैंक ऑफ बड़ोदा और केनरा बैंक द्वारा उन्हें जारी मूल पत्र में दी गयी शर्तों के आधार पर और उनके अधीन निर्यात विकास निधि के अंतर्गत अनुमोदित विभिन्न प्रयोजनों के लिए खर्च किया जा सकेगा।

अभिवासी भारतीयों द्वारा निबंध (क) भारतीय कंपनियों की सहायगत नियमों और अंतर्नियमों में प्रतिबद्ध।

16.3 भारत में नयी औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के इच्छुक निवासी भारतीयों को उनके कार्य में सहायता करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने नवम्बर 1986 में निवासी भारतीयों को यह सामान्य अनुमति दी थी कि वे भारतीय कंपनियों के नियमों और अंतर्नियमों में प्रतिबद्ध कर सकते हैं और उसके निगमन के उद्देश्य से शेयर ले सकते हैं। उम्मीदवशता के अनुसार ऐसी किसी भी कंपनी को निवासी भारतीयों को 10,000 रुपये के अधिकृत मूल्य तक के शेयर जारी करने की सामान्य अनुमति दी गयी थी। जिनके पास भारत में अपना औद्योगिक कार्यकलाप शुरू करने के लिए केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय या महाविदेशक तकनीकी विकास महाविदेशालय या किसी अन्य केन्द्रीय/

राज्य सरकार को प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्राथम्य पत्र/प्रौद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्र हो। इसके अलावा, जून 1989 में रिजर्व बैंक ने रियायत दी थी जिसको द्वारा ऐसी किसी भी भारतीय कंपनी में अनिवासी भारतीय द्वारा अभिदान की अनुमति दी गयी थी जो, प्रौद्योगिक कार्यकलाप करने में लगी है या बनायी जा रही है और अपना प्रौद्योगिक कार्यकलाप शुरू करने के लिए यथासंभव से संबंधित सरकारी मंत्रालय/प्राधिकारी से अपेक्षित आशय पत्र, प्राप्ति प्राप्त करने का बचन देती है।

(ख) 74 प्रतिशत योजना को अधीन अनिवासी भारतीयों/विदेश स्थित कंपनी निकायो द्वारा भारत में होटल उद्योग में निवेश

16.4 अब तक, अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रभावित स्वाधिकृत विदेश स्थित कंपनी निकायों को यह अनुमति थी कि वे सरकार द्वारा चलाई जाने वाली 74 प्रतिशत योजना के अंतर्गत 3, 4 या 5 तारा श्रेणी होटलों में पूर्ण प्रत्यावर्तन लाभों के साथ भारत से निवेश कर सकते हैं। भारत में होटल उद्योग में निवेश के लिए अनिवासी भारतीयों को और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि 3, 4 या 5 तारा श्रेणी के होटलों द्वारा जारी किए जाने वाले शेयरों के नये निर्गमों/परिवर्तनीय डिबेंचरों के 100 प्रतिशत तक पूर्ण प्रत्यावर्तन लाभों को साथ ऐसे निवेश की अनुमति दी जाये। उक्त योजना के अधीन अन्य अनुमोदित उद्योगों जैसे कम्प्यूटर साफ्टवेयर, अस्पतालों आदि में अनिवासी भारतीयों के निवेश पर लगी उच्चतम सीमा द्विविटी/परिवर्तनीय डिबेंचर निर्गम के 74 प्रतिशत पर अपरिमित बनी हुई है।

(ग) अनिवासी भारतीयों/समुद्रपारीय कंपनी निकायो द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों का क्रय/विक्रय

16.5 भारतीय राष्ट्रको/मूल के अनिवासियों तथा ऐसे व्यक्तियों के अधिस्वामित्व वाले विदेश स्थित कंपनी निकायों द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों, केन्द्रीय/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों तथा राष्ट्रीय योजना/बचत प्रमाणपत्रों में निवेश या उनका विक्रय/अंतरण किया जा सकता है, परन्तु शर्त यह है कि यह निवेश/विक्रय/अंतरण विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी के जरिए किया जाये। चूंकि रिजर्व बैंक ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट को भी उसके चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के अधीन यूनिट जारी करने/विक्रय/अंतरण की कतिपय शर्तों पर सामान्य अनुमति प्रदान की है अतः अनिवासी भारतीयों/विदेश स्थित कंपनी निकायों को यह विकल्प होगा कि वे यूनिट ट्रस्ट के सीधे ही/उसके माध्यम से या किसी प्राधिकृत व्यापारी के जरिए विदेशी मुद्रा में यूनिटों के विक्रय/क्रय अंतरण की व्यवस्था करें किन्तु सरकारी प्रतिभूतियों और/या राष्ट्रीय योजना/बचत प्रमाणपत्रों में निवेश अब तक की तरह केवल प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से किया जाना जरूरी है।

विदेश यात्रा के लिए दैनिक विनिमय दरों में संशोधन कर बुद्धि

16.6 रिजर्व बैंक कारोबार के प्रयोजनों के लिए विदेश यात्रा हेतु जारी की जाने वाली विदेशी मुद्रा की दैनिक दरों की आवधिक समीक्षा करता है और इसमें दूसरे देशों में होटल प्रशुल्कों और संबंधित खर्चों में होने वाली घट-बढ़ को ध्यान रखा जाता है। पहली जुलाई 1989 से ऐसे प्रयोजनों के लिए जारी की जाने वाली विदेशी मुद्रा की दैनिक दरों को निम्न प्रकार संशोधित किया गया है।

विशेष मान	अमेरिकी डॉलर	सामान्य मान अमेरिकी डॉलर
1	2	3
I समूह 'क' के देश (इसमें सऊदी अरब, जापान, कुवैत और नाइजीरिया सम्मि- लित हैं)	300	240

1	3	3
II. समूह 'ख' के देश (इसमें संयुक्त अरब अमीरात, कतार, ओमान सल्तनत, बहरीन, पश्चिमी गोलार्ध, ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप, ईरान, लीबिया और अल्जीरिया सम्मिलित हैं)	265	210
III. समूह 'ग' के देश (बाह्य समूह के अन्य देश)	215	185
IV. द्विपक्षीय समूह के देश	र 3,000	र. 2,750

विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना अध्ययन

16.7 विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने के संबंध में और रियायत दी गयी है जो नीचे उल्लिखित हैं।

(i) यह निश्चय किया गया है कि विदेश में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने के प्रयोजन के लिए भारत में स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक की अपेक्षा को समाप्त कर दिया जाए।

(ii) विदेश में अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए डाक्टरों को विदेशी मुद्रा जारी की जाती है उन्हें अब तक यह बचन/गारंटी देनी होती थी कि वे अपना अध्ययन/प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भारत लौट आएंगे तथा ऐसा न करने पर उन्हें जारी की गयी विदेशी मुद्रा या उसके सममूल्य रुपया राशि निष्कारित हज्जि के रूप में भ्रष्टा करनी होती थी। अब गारंटी प्राप्त करने की ऐसी आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

विशेषीकृत प्रशिक्षण : विदेश में विशेषीकृत प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम शुल्क हेतु जारी की जाने वाली विदेशी मुद्रा की सीमा की 1000 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 2,000 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है।

डाक्टरों जांच : विदेश में डाक्टरों चिकित्सा/परामर्श हेतु जारी की जाने वाली विदेशी मुद्रा की राशि को उन मामलों में 175 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 500 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है जहां अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं है तथा जहां अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है वहां उसे 350 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 700 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है।

विदेश में रोजगार

16.8 रोजगार लेने के लिए विदेश जाने वाले व्यक्तियों को अपने आरंभिक खर्चों को पूरा करने के लिए प्रत्यावर्तन के आधार पर 500 अमेरिकी डॉलर या उसके बराबर तक की विदेशी मुद्रा जारी की जाती थी। अब इस सीमा को 2,000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दिया गया है।

विदेश यात्रा योजनाओं के अधीन विदेश यात्रा

16.9 4 अगस्त 1989 से सिंगापुर की विदेश यात्रा योजना के देशों के समूह से हटा दिया गया है और उसे पड़ोसी देशों की यात्रा योजना के अधीन आने वाले देशों के समूह शामिल किया गया है। तबनुसार, विदेश यात्रा योजना के अधीन सिंगापुर जाने के इच्छुक निवासी नागरिक अब प्रति व्यक्ति 250 अमेरिकी डॉलर तथा बारह वर्ष से कम के प्रत्येक बच्चे के लिए 125 अमेरिकी डॉलर की दर पर विदेशी मुद्रा लेने के पात्र हैं, बशर्ते वे अवस्था इस योजना के अंतर्गत विदेश यात्रा के पात्र हो किन्तु विदेश यात्रा योजना के अंतर्गत आने वाले किसी अन्य देश/देशों के साथ-साथ सिंगापुर जाने की इच्छुक वाली

विदेशी मुद्रा का विदेश यात्रा का योजना या कोटा ग्राह्यता करने के पात्र होंगे।

विदेशी मुद्रा के ग्राह्यता की अवधि बढ़ाया जाना

16.10 अब तक प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा जारी विदेशी मुद्रा परमिटों पर या विशेष यात्रा योजनाओं (विदेश यात्रा योजना और पड़ोसी देशों की यात्रा योजना) के अन्तर्गत या प्राधिकृत व्यापारियों/नाइसेंस प्राप्त मुद्रा परिवर्तकों में निहित सामान्य अधिकार के अधीन विदेशी मुद्रा की बिक्री यात्रियों के पक्के टिकट पर दर्ज प्रस्थान की तारीख से एक पञ्चमाह से पहले नहीं की जा सकती थी। अब इस समय सीमा को बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है ताकि यात्रियों को अपनी यात्रा व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिये अधिक समय दिया जा सके।

प्रवेश शुल्क/पत्राचार पाठ्यक्रम शुल्क/प्रविष्टि शुल्क

16.11 विदेश स्थित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले व्यक्तियों को प्रवेश शुल्क हेतु प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा जारी करने के लिये प्रति विश्वविद्यालय या संस्था 100 अमेरिकी डालर की मौद्रिक सीमा को बढ़ाकर 200 अमेरिकी डालर कर दिया गया है। इसी तरह पत्राचार पाठ्यक्रम शुल्क हेतु विदेशी मुद्रा जारी करने की मौद्रिक सीमा को किसी एक कैलेंडर वर्ष में 300 अमेरिकी डालर से बढ़ाकर 750 अमेरिकी डालर कर दिया गया है। योग्यता प्राप्त/व्यावसायिक वास्तुविदों, चित्रकारों, छायाचित्रकारों, मुद्रकों, मूर्तिकारों और डाक टिकट संकलनकर्ताओं द्वारा संबंधित क्षेत्रों में विख्यात संगठनों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये प्रविष्टि शुल्क हेतु प्रवेशों की सीमा अब 100 अमेरिकी डालर से बढ़कर 500 अमेरिकी डालर हो गयी है।

अनिवासी सामान्य रुपया खातों में नामे

16.12 अनिवासी भारतीयों और विदेश स्थित निगमित निकायों से भ्रिश अनिवासियों के नाम रहने वाले सामान्य अनिवासी रुपया खातों से खाताधारी और उसके परिवार के खर्चों की पूर्ति के लिये भारत में उनकी यात्रा के दौरान प्रति सप्ताह 3,000 रुपये की सीमा तक के ग्राह्यताओं की अनुमति थी। अब इस सीमा को समाप्त कर दिया गया है।

निर्यात से मिलने वाली राशि को निर्यातकों द्वारा सीधे प्राप्ति

16.13 भुगतान की अनुमोदित पद्धतियों के अनुसार निर्यातकों को निर्यात से प्राप्त होने वाली राशियाँ सामान्य बैंकिंग माध्यमों से प्राप्त करनी होती है। इस नियम के अपवाद के रूप में अस्थायी कार्यशीलता निर्यातकों को, रिजर्व बैंक को आवेदन किये जाने पर प्रति निर्यात 10,000 अमेरिकी डालर की मौद्रिक उच्चतम सीमा की शर्त पर निर्यात से मिलने वाली राशि का भुगतान विदेशी खरीदारों से यात्री बैंकों/बैंकर चेकों/ड्राफ्टों/भुगतान आदेशों के रूप में सीधे स्वीकार करने की सामान्य अनुमति दी जा सकती है। उपर्युक्त तरीके से निर्यात से मिलने वाली राशि की सीधी प्राप्ति की मौद्रिक सीमा को 12 विसंवर 1989 से बढ़ाकर प्रति पोतखदान 15,000 अमेरिकी डालर कर दिया गया है, परन्तु शर्त यह है कि करंसी नोटों की राशि 2000 अमेरिकी डालर से अधिक न हो।

ईरान को निर्यात रिजर्व बैंक के पास विद्यमान सेंट्रल बैंक आफ इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान के विशेष खाते से भुगतान

16.14 भारत और ईरान की सरकारों ने अगस्त 1989 में कर्नाटक में कुदरेमुख लोह अयस्क परियोजना के वित्तपोषण के लिये भारत द्वारा ईरान से लिये गये विदेशी मुद्रा ऋण के भुगतान के संबंध में एक समझौता किया था। उक्त समझौते के अनुसार, इस संबंध में देय 66.89 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि के साथ

रिजर्व बैंक में आर्गेनाइजेशन फार इन्वस्टमेंट एण्ड टेक्निकल असिस्टेंस आफ ईरान के नाम एक खाता खोला गया। बाद में 66.89 मिलियन अमेरिकी डालर की उक्त राशि को बर्बई में रिजर्व बैंक के पास सेंट्रल बैंक आफ दि इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान के नाम खोले गये एक विशेष खाते में अंतरित कर दिया गया है। उक्त विशेष खाते में जमा की गयी राशि का भारतीय निर्यातकों द्वारा ईरान को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान हेतु उपयोग किया जायेगा। भारत से किये जाने वाले निर्यातों के संबंध में इस खाते के माध्यम से भारत स्थित बैंकों द्वारा अनिवार्य प्राप्ति करने की प्रक्रिया भी निर्धारित की गयी है।

सीधे भुगतान प्रणाली के अधीन आयातों हेतु भुगतान के लिये संमिश्र दर की गणना में प्रक्रिया संशुद्धि परिवर्तन

16.15 विदेशी सरकारों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले विदेशी मुद्रा ऋणों/उधारों पर किये जाने वाले आयात के लिये भुगतान सीधे भुगतान प्रणाली (इसे वायदा पत्र प्रणाली भी कहा जाता है) के अन्तर्गत अथवा "प्रतिपूर्ति प्रणाली" के अन्तर्गत किया जाता है। सीधे भुगतान प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले आयातों की विदेशी मुद्रा लागत के बराबर रुपया राशि बसूल करने के प्रयोजन के लिये सरकार परिवर्तन के लिये एक संमिश्र विनियम दर लागू करती है जो सामान्यतः बैंकों की बिल बिक्री दर तथा मार्जिन के रूप में होती है। ऐसी दर को 4 दशमलव बिन्दु तक निकाला जाता है परन्तु जापानी येन, इटली के लीरा और बेल्जियम फ्रांक के संबंध में तीन दशमलव बिन्दु तक तथा अन्य विदेशी मुद्राओं के संबंध में दूसरे दशमलव बिन्दु तक पूर्णांकित किया जाता है। संमिश्र दर की गणना में तथा उससे निकाली गयी रुपया लागत को पूर्णांकित करने की क्रियाविधि में एक रूपता लाने के उद्देश्य से सरकार ने अब यह निश्चय किया है कि 1 जुलाई 1989 से विदेशी मुद्रा के यूनिट के बराबर रुपये का पूर्णांकन सभी मुद्राओं के संबंध में 4 दशमलव अंक तक किया जायेगा।

वाणिज्यिक व्यापार

16.16 भारत में वाणिज्यिक व्यापार में लगे व्यापारियों को होने वाली विनियम हानि को टालने के उद्देश्य से प्राधिकृत व्यापारियों को अब यह अनुमति है कि वे अपने ग्राहकों से विशिष्ट लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर विदेश स्थित खरीदार से प्राप्त अधिम राशि कनिष्ठ शर्तों पर उनके विदेशी मुद्रा खातों में विदेश स्थित आपूर्तिकर्ता से अवायगी की तारीख तक रख सकते हैं।

विदेशी तकनीशियनों/विशेषज्ञों के यात्रा टिकट बुक करना

16.17 रिजर्व बैंक ने भारत आने वाले विदेशी तकनीशियनों/तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मेजबान भारतीय कंपनियों द्वारा रुपये में खरीदे गये हवाई टिकटों पर विदेशी हवाई कंपनी से यात्रा करने के संबंध में लगे प्रतिबंध को मई 1989 से हटा दिया। इसके परिणाम स्वरूप, सहभागिता करारों आदि के अधीन भारत आने वाले विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ/टेक्नीशियन अब दोनों ओर की यात्रा अपनी पसंद की हवाई कंपनी से कर सकते हैं।

वाणिज्यिक जारी कर फेरा कंपनियों द्वारा जमाराशियाँ जुटाना

16.18 विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों (अर्थात् ऐसी भारतीय कंपनियाँ जिनमें अनिवासी हित 40 प्रतिशत से अधिक है) द्वारा वाणिज्यिक पत्र जारी किया जा सकें। इस उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने सितम्बर 1989 में निवेश-कर्ताओं और निवेशित कंपनियों, दोनों को वाणिज्यिक पत्र में निवेश करने/जारी करने के लिये विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 26(7) के उपबन्धों से सामान्य छूट प्रदान की परन्तु इस

26(7) के उपबन्धों में सामान्य छूट प्रदान की परन्तु इस संबंध में शर्त यह थी कि 'गैर-वैश्विक कंपनी' (वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से जमागणियों का स्वीकरण) विदेश, 1989 में दिये गए पात्रता मानक को पूरा किया जाये तथा कंपनी ऐसे वाणिज्यिक पत्र जारी करने के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों का पालन करती हो। सामान्य अनुमति के लिए आवेदन करने वाली फेरा कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वाणिज्यिक पत्र के रूप में जुटायी गयी निधियों का उपयोग केवल कंपनी की कार्यकारी पूर्वापेक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 और 29 के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों करने के लिए ही किया जाए।

16.19 विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 9 (1) (ग) के अधीन रिजर्व बैंक के अक्टूबर 1989 में भारतीय कंपनियों को यह सामान्य अनुमति दी थी कि वे रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अनुगमन भारतीय राष्ट्रकर्ता/मूल के अनिवासियों को (केवल प्रलग-अलग व्यक्तियों को) न कि अनिवासियों द्वारा प्रधानतः स्वीकृत विदेश स्थित कंपनियों को) वाणिज्यिक पत्र जारी कर सकती हैं, परन्तु शर्त यह है कि निवेश की गयी राशि और उस पर अर्जित आय को प्रत्यावर्तित करने की अनुमति नहीं होगी और अनिवासियों को जारी वाणिज्यिक पत्र हस्तान्तरणीय नहीं होंगे। अनिवासियों को वाणिज्यिक पत्र जारी करने वाली भारतीय कंपनियों (फेरा कंपनियों सहित) को रिजर्व बैंक (औद्योगिक और निर्यात अर्थ विभाग) द्वारा जारी अनुमोदन पत्र में निर्दिष्ट शर्तों के विनिष्ट अलावा विदेशी मुद्रा नियंत्रण से संबंधित कतिपय शर्तों का पालन करना आवश्यक है।

#### एशियाई समाशोधन यूनियन

16.20 अब तक, एशियाई समाशोधन यूनियन के सदस्य देशों के बीच किये जाने वाले ऐसे निर्यात या आयात लेन देनों को जिनमें आस्थगित आयातों के आधार पर निपटान किया जाता है, बालू लेनदेनों के रूप में नहीं माना जाता था और ऐसे लेनदेनों के लिए एशियाई समाशोधन यूनियन के तंत्र के माध्यम से आस्थगित किस्तों का अनिवार्य निपटान जरूरी नहीं था। किन्तु ऐसी संविदाओं के संदर्भ में अधिम/तत्काल आयातों/नौवहन दस्तावेजों पर आयातों एशियाई समाशोधन यूनियन के माध्यम से किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। अब एशियाई समाशोधन यूनियन के सदस्य देश इस बात पर सहमत हो गये हैं कि आस्थगित आधार पर किये जाने वाले निर्यात या आयात लेनदेनों के फलस्वरूप होने वाले भुगतानों को 22 मार्च 1990 में एशियाई समाशोधन यूनियन के तंत्र को रोमा के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

16.21 एशियाई समाशोधन यूनियन के सदस्य इस बात पर भी सहमत हो गये हैं कि उनके बीच मुद्रा विनियम व्यवस्था हो ताकि कतिपय शर्तों के अधीन समाशोधन असंतुलनों को निपटाया जा सके। अतः उपर्युक्त परिवर्तनों को शामिल करते हुए एशियाई समाशोधन यूनियन करार तथा एशियाई समाशोधन यूनियन (प्रक्रिया) नियम में आवश्यक संशोधन किये गये हैं।

#### विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी

16.22 विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम की धारा 6 के अधीन भारत में विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए दो विदेशी बैंकों अर्थात् क्रेडिट लॉयनारम तथा सन्वा बैंक लि० को लाइसेंस प्रदान किया गया है।

#### कार्यालय खोलना (i) विदेशी कंपनियों द्वारा विदेश में

16.23 वर्ष 1989-90 (जुलाई-जून) के दौरान विदेशी कंपनियों को भारत में 70 संपर्क कार्यालय, 14 प्रतिनिधि कार्यालय तथा 13 परियोजना कार्यालय खोलने की अनुमति दी गयी।

#### भारत में (ii) भारतीय कंपनियों द्वारा।

16.24 इसी अवधि के दौरान भारतीय कंपनियों की विदेश में 28 व्यापारिक कार्यालय, 70 गैर-व्यापारिक कार्यालय खोले तथा 21 प्रतिनिधि नियोजित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किये गये।

#### भारतीय मुद्रा का आयात और निर्यात।

16.25 रिजर्व बैंक अधिसूचनाओं में दिये अनुसार विदेश यात्रा करने वाले निवासी भारतीयों द्वारा भारतीय मुद्रा भारत से बाहर ले जाने और भारत में लाने से संबंधित विनियमों की समीक्षा की गयी और अगस्त 1989 में नयी अधिसूचनाएं जारी की गयी, जिनके अनुसार नेपाल से भिन्न किसी दूसरे देश के अल्पकालिक दौरे पर जाने वाले निवासी को अनुमति है कि वह अपने साथ 250 रुपये की राशि तक के भारतीय मुद्रा नोट ले जा सकता है तथा साथ ही भारत लौटने के समय उतनी ही राशि तक के भारतीय मुद्रा नोट भारत में वापस ला सकता है। बिना किसी सीमा के भारतीय मुद्रा (100 रुपये के मूल्यवर्ग को छोड़कर) नेपाल ले जाने या उभरे देश से किसी एक समय में प्रति व्यक्ति 75 रुपये से अधिक तक का राशि भारतीय मुद्रा (100 रुपये के मूल्य वर्ग को छोड़कर) लाने से संबंधित वर्तमान विनियमों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

#### निर्यातों पर कमीशन

16.26 ऐसे अपरिचालनीय साधनों के अंतर्गत आने वाले निर्यातों के संदर्भ में, जिनमें कुछ शर्तों पर विदेशी एजेंट को कमीशन की आयातों के लिए निश्चित रूप में प्रावधान किया गया है, कमीशन विदेश भेजने या निर्यात बिल की प्राप्ति होने वाली राशि से उसकी कटौती स्वीकार करने की प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गयी है, परन्तु शर्त यह है कि कमीशन की दर 7.5 प्रतिशत से अधिक हो। यह स्पष्ट किया गया है कि उपर्युक्त व्यवस्था बाह्य समूह के देशों को किये जाने वाले निर्यातों के संदर्भ में ही लागू है और द्विपक्षीय समूह के देश को किये जाने वाले निर्यातों से अधिक के संदर्भ में (आयात के देश में रहने वाले एजेंट को) कमीशन की दर 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

16.27 निर्बंध परिमित योजना के अंतर्गत विदेशी कम्प्यूटर सावधान्य के निर्यातकों द्वारा (विदेशी एजेंटों को) कमीशन के प्रेषण के मामले में प्राधिकृत व्यापारियों को प्रतिशत संबंधी बिना किसी उच्चतम सीमा के ऐसे कमीशन के प्रेषण की अनुमति दी गयी है, परन्तु शर्त यह है कि कमीशन की राशि निर्बंध विदेशी मुद्रा परमित में उपलब्ध जमा शेष के भीतर हो और यह कि दस्तावेजी प्रमाण/एजेंसी करार प्रस्तुत किया जाये जिसमें यह उल्लेख हो कि निर्यात आदेश उस विदेशी एजेंट के माध्यम से प्राप्त किया गया है जिसे प्रेषित किया जाना है।

अंतर बैंक बाजार में विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डालर) को ऋण देना और उधार लेना

16.28 प्राधिकृत व्यापारियों को यह अनुमति है कि वे विदेश स्थित शाखाओं और प्रतिनिधियों के पास ऐसे स्तर तक विदेशी मुद्राओं में जमा शेष रखें जो उनके कारोबार की सामान्य आवश्यकताओं के अनुरूप हों जैसे आयातों हेतु भुगतान या बायबा संविदाओं के अंतर्गत अवधि समाप्त होने वाली सुपुर्बगियां। उन्हें यह भी अनुमति है कि वे दैनिक आधार पर अपने कारोबार की अपनी प्रत्याशित सामान्य आवश्यकताओं से अधिक अधिशेष रहने वाली विदेशी मुद्रा राशि को उन मामलों में उनके बालू खातों में स्वतः पुनः अंतरण की सुविधावाले विशेष ब्याज मुक्त खातों में अंतरित कर दें जहाँ उनकी विदेशी शाखाओं/प्रतिनिधियों द्वारा ऐसी सुविधा दी गयी हो। रिजर्व बैंक को यह अभिवेदन किया गया था कि जहाँ ऐसी रातभर की जमा राशियों पर अर्जित ब्याज तत्समय लागू न्यूनतम ब्याज होता है, वहीं जिन प्राधिकृत व्यापारियों के खातों से अधिक राशि ग्राह्यरहित होती है, उन्हें प्राप्त होने वाली प्रक्रियाधीन निधियों को प्राप्त तक उच्चतम उधार दर या उससे भी अधिक दर पर ब्याज प्रदा करना पड़ता है। इस स्थिति को कुछ सीमा तक हल करने की दृष्टि और इस उद्देश्य से कि प्राधिकृत व्यापारी विदेश में अपनी विदेशी निधियों का अधिक दक्षता से प्रबंध कर सकें, प्राधिकृत व्यापारियों को यह अनुमति देने का निश्चय किया गया है कि वे स्थानीय रूप से अंतर बैंक बाजार में आपस में विदेशी मुद्रा उधार दे सकते हैं और ले सकते हैं। इस योजना की एक वर्ष की अवधि के बाद समीक्षा की जाएगी। फिलहाल ऐसे लेनदेन केवल अमेरिकी डालर तक सीमित है और विदेशी मुद्रा के उधार के संबंध में प्राधिकृत व्यापारियों के लिए अधिकतम सीमा 5 मिलियन अमेरिकी डालर है। प्रत्येक प्राधिकृत व्यापारी को

निए वास्तविक उधार सोमा उसके कार्यकलापों और अन्य संबंधित तत्वों की मात्रा के आधार पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट की जाती है।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्थापित म्यूचुअल फंड में एशियन कन्वर्टिबल एंड इन्कम फंड द्वारा निवेश

16.29 एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में एशियन कन्वर्टिबल एंड इन्कम फंड नामक बहु-देशीय क्षेत्रीय कोष का प्रायाचित किया है। एशियन कन्वर्टिबल एंड इन्कम फंड का उद्देश्य जापान जैसे पूँजी की दृष्टि से समृद्ध देशों में बड़े स्थापना निवेशकर्ताओं को माध्यम प्रदान करने के अलावा एशियाई विकास बैंक के विकासशील सदस्य देशों में पूँजी बाजारों के विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही, इसके निवेश लक्ष्यों का उद्देश्य मुख्यतः परिवर्तनीय डिबेंचरों और अन्य ईक्विटी संबंध प्रविधियों में निवेश के माध्यम से चालू आय निर्मित करना तथा दीर्घावधि पूँजी में वृद्धि करना है। एशियन कन्वर्टिबल एंड इन्कम फंड की आस्तियाँ लक्ष्य देशों, अर्थात् एशियाई विकास बैंक के विकासशील सदस्य देशों के बीच आवंटित की जायेगी, भारत को सर्वाधिक अर्थात् फंड का 20 प्रतिशत (करीब 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर) आवंटन प्राप्त होगा। भारत में एशियन कन्वर्टिबल इन्कम फंड का निवेश भारतीय स्टेट बैंक द्वारा (न्यास के रूप में) एशियन कन्वर्टिबल एंड इन्कम फंड म्यूचुअल फंड नाम से इस कार्य के लिए स्थापित म्यूचुअल फंड के माध्यम से किया जायेगा। उक्त म्यूचुअल फंड द्वारा भारत विदेशी मुद्रा में प्राप्त निधियाँ एशियन कन्वर्टिबल एंड इन्कम फंड को यूनिट जारी कर (प्रत्येक रु. 100 के अंकित मूल्य के लिए भारतीय रुपये में निविष्ट) प्रकट की जायेगी जो एशियन कन्वर्टिबल एंड इन्कम फंड म्यूचुअल फंड का एक साल लाभांश और यूनिटधारी होगा। एशियन कन्वर्टिबल एंड इन्कम फंड को जारी यूनिट ग्रहस्तान्तरणीय है। यूनिटों पर लाभांश के वितरण आदि का निश्चय उक्त फंड के परामर्श बोर्ड (एशियाई विकास बैंक उस परामर्श बोर्ड का सदस्य है) द्वारा किया जाएगा। उक्त यूनिटों का पाँच वर्ष की अवकृता अवधि के बाद प्रतिदान किया जा सकेगा। प्रतिदान के बाद यूनिटों को प्रतिदान के दिन प्रति यूनिट म्यूचुअल फंड के शुद्ध आस्ति मूल्य पर पुन खरीदा जायेगा। यूनिटों के लाभांश/प्रतिदान मूल्य की अदायगी पर भारतीय कर लागू होंगे। भारतीय स्टेट बैंक की पूर्णतः स्वाधिकृत मर्जेंट बैंकिंग सहायक संस्था अर्थात् स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केपिटल मार्केट्स लि भारत में एशियन कन्वर्टिबल एंड इन्कम फंड के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केपिटल मार्केट्स लि अपने विवेकाधीन रहने वाली निधियों का भारत में (प्राथमिक और गौण बाजारों में) कपनियों के परिवर्तनीय डिबेंचरों और अन्य ईक्विटी सम्बंध प्रविधियों में निवेश करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केपिटल मार्केट्स लि भारत में निवेशों के संबंध में एशियन कन्वर्टिबल एंड इन्कम फंड को दी जाने वाली अपनी सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा में प्रबंधन शुल्क (कमीशन) के लिए पात्र होगा।

पड़ोसी देशों के से सहज/रेल द्वारा आयात

16.30 अब तक, प्राधिकृत व्यापारियों को रेल/सड़क परिवहन के माध्यम से किये जाने वाले वस्तुओं के आयात के लिए गोदाम रसीदों, लदान के रेलवे बिलों आदि पर अदायगी के प्रावधान के साथ साख पत्र खोलने के लिए रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करना हाता था। रिजर्व बैंक को दिये गये इस आग्रह के अविवेचना को देखते हुए, कि वस्तुएं अनेकांशतः सप्ते भाड़ा-प्रभारों के कारण अब सहज/रेल द्वारा पड़ोसी देशों के साथ व्यापार के लिए सीमा पार अधिक ले जाया जा रही है, यह निश्चय किया गया है कि पड़ोसी देशों से आयातों के मामले में प्राधिकृत व्यापारियों को अपने आयातक आहूकों की ओर से साखपत्र खोलने की अनुमति दी जाये, जिनमें लॉरो/रेल रसीदों पर अदायगी का प्रावधान हो।

खर्च न का गयी विदेशी मुद्रा का अध्ययन

16.31 यात्रियों द्वारा भारत लौटने पर प्राधिकृत व्यापारियों को अस्पष्टित खर्च न की गयी विदेशी मुद्रा को अब तक प्राधिकृत व्यापारी की मुद्रा और हस्ताक्षर के अधीन यात्री के पासपोर्ट पर साल स्याही

से वर्ष करना होता था। अब यह निश्चय किया गया है कि जब तक कोई यात्री अपने पासपोर्ट पर ऐसा पृष्ठांकन करने का अनुरोध न करे तब तक प्राधिकृत व्यापारी को पासपोर्ट पर पृष्ठांकन नहीं करना चाहिए। किन्तु प्राधिकृत व्यापारी को यात्री से विदेशी मुद्रा खरीबने के ऐसे सभी मामलों में अपने मुद्रित पत्राचार पर त्वदीकरण प्रमाणपत्र अवश्य जारी करना चाहिए, बाह् विदेशी मुद्रा प्रस्तुत करने वाला उसकी मांग करे या नहीं।

विदेश में उच्च अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना—सरकारी क्षेत्र के बका का शक्तियों का प्रयायोजन

16.32 अब तक, उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों तथा भारतीय स्टेट बैंक की कुछ नामित शाखाओं द्वारा अनुमति विदेशी मुद्रा जारी की जाती थी। इस उद्देश्य से कि ऐसे विद्यार्थी निकटवर्ती बैंकों से विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकें, 1 जन 1990 से रिजर्व बैंक ने उच्च अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने का अधिकार सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों की कुछ नामित शाखाओं को प्रयायोजित कर दिया है। अब उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने के इच्छुक विद्यार्थी रिजर्व बैंक के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से या सरकारी क्षेत्र के बैंकों की नामित शाखाओं से आवश्यक विदेशी मुद्रा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

17. मगठनाशनक मामले और बैंक के लेखे

करेन्सी चेस्ट

17.1 मार्च 1990 के अंत में करेन्सी चेस्टों की कुल संख्या 3,791 थी। इनमें से 17 करेन्सी चेस्ट रिजर्व बैंक के पास, 2,745 भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों के पास, 622 राष्ट्रीय-कृत बैंकों के पास, 402 वाणिज्य और उपवाणिज्य के पास और 5 जम्मु एंड काश्मीर बैंक लि के पास थे। इनके अलावा, 494 आधान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में रखे गये थे।

नया नोट प्रेम परियोजना

17.2 भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक उपक्रम नया नोट प्रेम परियोजना कार्यान्वयन तथा बाढ़ की प्रबंध व्यवस्था के लिए रिजर्व बैंक को अग्रित कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त परियोजना जनवरी 1990 में ग्रहण की। इस प्रयोजन के लिए एक संपूर्ण स्वाभिम्व वाली रिजर्व बैंक की सहयोगी कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव है। परियोजना में बैंक नोटों का मुद्रण करने वाले दो प्रेम स्थापित करने की परिकल्पना है—एक मिर्बनापुर जिने (पश्चिम बंगाल) में सलबोनी में तथा दूसरा मैसूर (कर्नाटक) में। दोनों ही प्रेमों को समान सुविधाएँ उपलब्ध होंगी तथा दोनों ही में विभिन्न मूल्यवर्गों के 5,000 मिलियन नोट मुद्रित करने की क्षमता होगी। उक्त परियोजना की कुल लागत 1,500 करोड़ रुपये (प्रेमों के लिए आवश्यक मयत और उपकरणों पर देय सीमा शुल्क सहित) अनुमानित है। उक्त परियोजना मभवत चार वर्ष की अवधि में पूरी हो जायेगी तथा उत्पादन का प्रारम्भिक चरण 24 महीनों की अवधि में अग्रम में आ जायेगा।

मुद्रा प्रबंध समिति

17.3 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में संपूर्ण मुद्रा प्रबंध का अध्ययन करने के लिए रिजर्व बैंक के एक उप-ग्रन्थ की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने संबंधी उल्लेख किया गया था। उक्त समिति ने 30 सितंबर, 1989 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब तक की गयी सिफारिशें चकि भारत सरकार के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले मामलों से संबंधित थीं। अब उनके संबंध में जिन मंत्रालय ने इन्हें कार्यान्वित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने के लिए एक स्थायी दल गठित किया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में भारतीय बैंक सघ के तत्वावधान में बैंकों के अध्यक्षों की एक बैठक आयोजित की गयी थी और उक्त

रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें उनके सम्मुख प्रस्तुत की गयी थीं तथा इनके संबंध में चार महानगरीय केन्द्रों में हुई बैठकों के बैकों के तकदी अधिकारियों को विस्तार से बताया गया। कार्य संबंधी क्रियाविधियां तथा रिजर्व बैंक में आंतरिक व्यवस्थाओं से संबंधित अन्य भिन्न-भिन्न कार्यों के बारे में इनकी जांच करने तथा कार्यान्वयन के लिए एक छोटा-सा आंतरिक दल गठित किया गया है।

#### सर्वेक्षण

17.4 आलोच्य वर्ष के दौरान अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण, 1981-82 पर आधारित सांख्यिकीय सारणियों का तैयार और अंतिम खण्ड प्रकाशित किया गया। “विदेशी मुद्रा अनिवासी जमादारियों और अनिवासी विदेशी खातों” के सर्वेक्षण के और इस सर्वेक्षण के अधीन एकत्रित किये गये आंकड़ों के समाधान-कार्य को पूरा किया गया जैसा कि इस रिपोर्ट के भाग I में कहा गया है, 1990 के लिए निजी कंपनी निवेशों के पूर्वानुमान आलोच्य वर्ष के दौरान तैयार किये गये। भारत की विदेशी मुद्रा देयताओं और आस्तियों की, 1986-87 को संदर्भ अवधि मानते हुए, की गयी गणना में एकत्रित किये गये आंकड़ों का भी आलोच्य वर्ष के दौरान समाधान पूरा किया गया। इस गणना के अंतिम परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के जुलाई अंक में प्रकाशित किये गये हैं। उक्त गणना के अधीन वार्षिक विदेशी निवेश सर्वेक्षण के जरिए एकत्रित किये गये विदेशी निवेश संबंधी आंकड़ों को अद्यतन बनाने की भी व्यवस्था की गयी है। बाह्य ऋण स्थिति पर नियंत्रण रखने तथा भावी ऋण शोधन दायित्वों का अनुमान लगाने की दृष्टि से बाह्य वाणिज्यिक उद्योगों के आधारभूत आंकड़े रखे जा रहे हैं। अधिक कारगर आधारभूत आंकड़े रखने तथा वित्त मंत्रालय में रखे गये आधारभूत आंकड़ों के साथ इन्हें समेकित करने के उद्देश्य से राइटमंडल सचिवालय द्वारा विकसित आंकड़ों के प्रबंधन संबंधी एक साफ्टवेयर पैकेज को 1988 के दौरान बैंक के व्यक्तिगत कम्प्यूटर (पीसी) पर लगाया गया।

#### दूर संचार तन्त्र का विकास

17.5 रिजर्व बैंक के बीम कार्यालय पहले से ही रिजर्व बैंक के स्टोर और फॉरवर्ड टेलीप्रिटर (एम एफ टी) तन्त्र के साथ जुड़े हुए थे। आलोच्य वर्ष के दौरान वित्त मंत्रालय और आर्थिक कार्य विभाग को उपयुक्त तन्त्र के साथ जोड़ दिया गया। इसी प्रकार रिजर्व बैंक के 20 कार्यालयों को जोड़ने वाला द्विचक्रित भाषण तन्त्र बिछाने का कार्य लगभग पूरा हुआ है।

#### कम्प्यूटरीकरण में प्रगति

17.6 लोक ऋण में हानि ही में अवतूर्त वृद्धि होने के कारण प्रतिभूतियों के निर्माण, ऋणों की चुकौती, ब्याज की अवसगी आदि के संबंध में दी जाने वाली सेवाओं में चिन्ताजनक वृद्धि हुई है जिसके फल-स्वरूप बैंक द्वारा अग्राने जानेवाली प्रणालियों और क्रियाविधियों में समग्र रूप से सुधार लाना आवश्यक हो गया। लोक ऋण कार्यालयों में कम्प्यूटर प्रणाली प्रारंभ करने की परिचालनात्मक योजना तैयार करने के लिए एक अंतर विभागीय समिति गठित की गयी ताकि ग्राहक सेवा में सुधार लाया जा सके और आन्तरिक कार्यविधि को सुव्यवस्थित बनाया जा सके। समिति ने जून 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा सिकारियों बैंक के विचाराधीन है। यह परिकल्पना की गयी है कि लोक ऋण कार्यालयों में कम्प्यूटरों का प्रयोग प्रारंभ करने से ग्राहक सेवा में बैंक काफी सुधार ला सकेगा और ऋण का संतुलन ब्याज की अवसगी और अवधि समाप्ति पर चुकौती से संबंधित लेखा-कार्य में भी सुधार ला सकेगा।

17.7 बैंक की यह योजना है कि सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग में विद्यमान सी ii—होतेवल बुल सेनफेम कम्प्यूटर प्रणाली को स्टेट-ट्रांक-ग्रांट लाज सेनफेम प्रणाली द्वारा ज़िम्मे निरस्त

आंकड़े-संचार व्यवस्था की सुविधा हो, प्रतिस्थापित किया जाए। विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग (विमुनिवि) के केन्द्रीय कार्यालय में कम्प्यूटरीकरण के लिए एक सुपर मिनी प्रणाली स्थापित की जा रही है। प्रारंभ में अनिवासी निवेश और विदेशी खाते, आवि जैसा कुछ एक परियोजनाओं का इस प्रयोजन के लिए निर्धारण किया गया है। विमुनिवि के 9 प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए भी व्यक्तिगत कम्प्यूटर (पीसी) प्राप्त किये गये हैं और आस्थापित अदा-यगी परियोजनाओं, भारत में विदेशी सहभागिता, संयुक्त उपक्रम परि-योजनाओं, टन की परियोजनाओं और नियंत्रकों को सावधान सूची में सम्मिलित करने जैसी चुनौती हुई मशों के लिए आंतरिक रूप से सॉफ्टवेयर पैकेज विकसित किये गये हैं। ऋण आयोजना कक्षा, वित्तीय कंपनी विभाग (बंगलूर और नयी दिल्ली) में तथा नयी दिल्ली और कलकत्ता स्थित आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों में भी व्यक्तिगत कम्प्यूटर प्रणालियां स्थापित की गयी हैं। आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, परिभर विभाग, प्रबंध सेवा विभाग, प्रशासन विभाग (प्रशिक्षण प्रभाग) तथा मुद्रा प्रबंध विभाग में कम्प्यूटर लगाये गये हैं। यह प्रस्ताव है कि बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, सचिव विभाग, प्रबंध सेवा विभाग तथा इतिहास कक्षा को पत्राचार तथा प्रलेखों को तैयार करने में तेजी लाने के उद्देश्य से शब्द-संसाधन पुबिधाएं प्रदान की जाएं।

17.8 केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में स्थापित नयी उन्नत कम्प्यूटर प्रणाली और बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग में स्थापित लघु कम्प्यूटर प्रणाली को परिचालन में लाया गया। शहरी बैंक विभाग (केन्द्रीय कार्यालय) के लिए लघु कम्प्यूटर प्रणाली शीघ्र ही स्थापित की जाएगी।

17.9 कर्न्सी वेस्ट के लेखों आदि, संबंधी कार्य के लिए निर्गम विभाग के कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के तुरन्त चरण में बंगलूर, मद्रास और हैदराबाद में कम्प्यूटर प्रणालियां स्थापित की गयीं और उन्हें परिचालन में लाया गया। जेलन पत्रकों के लिए भी इन कम्प्यूटरों का उपयोग किया जाना है और बंगलूर में इस प्रयोजन के लिए तैयार किए गए साफ्टवेयर पैकेज की जांच की जा रही है।

17.10 बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग (बंबई क्षेत्रीय कार्यालय) में तथा विधि विभाग में कम्प्यूटरीकरण के लिए कार्य-संभावना क्षेत्रों का पता लगाया जा रहा है। रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक और वित्तीय संस्थानों में विधिक कार्य के कम्प्यूटरीकरण के लिए गठित अध्ययन दल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

#### कार्यालय सहायता और उपकरण

17.11 बाह्य निवेश और परिचालन विभाग, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग और कामिक नीति विभाग—इन तीन विभागों में तथा नयी दिल्ली कार्यालय में एक-एक, इस प्रकार चार अनुलिपि मशीनें लगायी गयीं। मद्रास और कलकत्ता कार्यालयों में भी शीघ्र ही अनुलिपि मशीनें लगायी जाएंगी।

#### सी. डी. देशमुख स्मारक व्याख्यान

17.12 स्वर्गीय डा. सी. डी. देशमुख, बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर की मूर्ति में रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गयीं चिन्तामन देशमुख स्मारक व्याख्यान माला का छठा व्याख्यान मिस्टर ई. जे. राउल कारिगन, अध्यक्ष, फेडरल रिजर्व बैंक आफ न्यूयार्क द्वारा 11 जनवरी 1990 को बंबई में दिया गया। मि. कारिगन “दशक के अंत में विश्वव्यापी आर्थिक संभावनाएं” विषय पर बोले।

#### गवर्नरों की बैठक की 18वीं सीएनए परिषद

18.13 सीएनए (वर्षा पूर्व एगिगा, न्यूजीलैण्ड और आस्ट्रेलिया) गवर्नर परिषद की 18वीं बैठक 20 अक्टूबर, 1989 को बंबई स्थित

रिजर्व बैंक में आयोजित की गयी थी। रिजर्व बैंक आफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा वर्ष 1988 में चलाए गए 17 वें सीएन्सा केन्द्रीय बैंकिंग पाठ्यक्रम के बारे में उक्त बैंक द्वारा प्रस्तुत डाइरेक्टिंग स्टाफ की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया गया। उक्त परिषद में अन्य बातों के साथ-साथ 18वें सीएन्सा केन्द्रीय बैंकिंग पाठ्यक्रम के लिए, जिसे रिजर्व बैंक के तत्वावधान में अक्टूबर-दिसंबर 1990 में बर्बई में चलाए जाने का प्रस्ताव है, स्थूल विषयों के संबंध में निर्णय लिए गए।

#### रिजर्व बैंक का इतिहास

17.14 1935-51 अवधि से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास मार्च 1970 में प्रकाशित किया गया था। इस खंड में प्रारंभिक वर्षों—1935 के पूर्व से लेकर देश में आर्थिक योजना के युग के प्रारंभ तक की अवधि को शामिल किया गया था। बैंक ने अब यह निर्णय लिया है कि 1951 में लेकर और 1981 तक की गतिविधियों को शामिल करने हुए और खंड प्रकाशित किए जाएं। इस प्रयोजन के लिए एक अलग इतिहास कक्ष की स्थापना की गयी है। इतिहास सफल कार्य का मार्गदर्शन करने तथा देखने के लिए बैंक ने अब एक निवेशक समिति का गठन किया है।

#### इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान

17.15 अपनी स्वर्ण जयंती के स्मरण के एक अंश के रूप में रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1987 में स्थापित इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च) ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कई अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य किया तथा कार्य-शालाएं, सम्मेलन और विचार गोष्ठियां आयोजित की। "आयोजना और नीति विश्लेषण की पद्धतियां" से संबंधित उसकी परियोजना एक प्रमुख अनुसंधान कार्य है जो मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं के लिए आयोजना और नीति निर्धारण के संदर्भ में समेकित दृष्टिकोण विकसित करने तथा योजनागत लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संबंधित विभिन्न नीतियों का पता लगाने पर प्रकाश डालता है। संस्थान की अन्य परियोजनाओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: "विकास की बैंकलिक नितियां", "पूर्वावधारणात्मक नीतियां और आर्थिक नीतियां", "टैक्सोलाजी मूल्यांकन", "पर्यावरण संबंधी मामलों" और "तुलनात्मक अध्ययन"। इन परियोजनाओं के स्थूल विद्यार्थियों के अंतर्गत, निम्नलिखित विषयों पर भी कार्य जारी है: भाग प्रणाली अध्ययन, कृषि विषयक अध्ययन, ऊर्जा नीति अध्ययन, करो, उपदानों, मूल्यों और ईक्षिटी पर अध्ययन, उपयोग सर्वेक्षण पर अध्ययन, औद्योगिक नीति अध्ययन, मोट्रिक अर्थनीति और प्राथमिकता प्राप्त मामलों तथा ग्रामीण निर्धनता के उन्मूलन के लिए नीतिगत उपायों पर अध्ययन।

#### बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, बर्बई

17.16 बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय ने सांख्यिकीय प्रणालियों का प्रयोग, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण, समझौता वार्ता संबंधी कुशलताएं, परामर्श देना, बैंकों के लिए 5 वर्षीय कार्यवाही योजना, प्रशिक्षणाधियों के लिए सम्भवहार विवर्णण, आयात-निर्यात वित्तपोषण, वाणिज्य बैंकों के परंपरेतर क्षेत्र और बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आंतरिक व्यवस्था कार्यक्रम—इन क्षेत्रों में कई नए कार्यक्रम प्रारंभ किए। विदेशी बैंकों के अधिकारियों ने भी "केन्द्रीय बैंकिंग" और "विदेशी मुद्रा" जैसे कार्यक्रमों में भाग लिया। अधिकांश कार्यक्रमों में कम्प्यूटर निविष्टियों का प्रयोग प्रारंभ किया गया ताकि बैंकिंग उद्योग में कम्प्यूटर के प्रयोग से संबंधित जन का प्रसार हो सके। शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के प्रयोग का बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाविद्यालय ने 18 कार्यक्रमों को हिन्दी के माध्यम से चलाया।

17.17 आलोच्य वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने 1,854 सहभागियों के लिए 93 कार्यक्रम चलाए। इससे वर्ष 1954 में महाविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक प्रशिक्षण महभागिया की कुल संख्या बढ़कर 39,293 हो गयी।

#### रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, मद्रास

17.18 पहले की तरह आलोच्य वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, व्यापक रूपरेखा कार्यक्रम चलाता रहा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: ग्रेड "ए" और ग्रेड "बी" में नए भर्ती हुए अधिकारियों के लिए, जिनमें सहायक सुरक्षा अधिकारी तथा अर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग तथा सांख्यिकीय विवर्णण और कम्प्यूटर सेवा विभाग के अनुसंधान अधिकारी भी सम्मिलित हैं, गहन परिचय कार्यक्रम, पदोन्नत/मेरिट अधिकारियों के लिए विकास कार्यक्रम और विशिष्ट कार्यक्षेत्रों में प्रयोजन मूलक कार्यक्रम महाविद्यालय ने निरीक्षण विभाग के अधिकारियों के लिए तथा करेन्सी अम्बु निरीक्षकों/लेखा परीक्षकों के लिए वाचनालयां चलाने के वास्ते माध्यम समय भी उपलब्ध कराया। महाविद्यालय द्वारा प्रारंभ किए गए नए कार्यक्रमों में निवेश और निधि प्रवर्धन, द्वितीय सेवाएं, आवास वित्त और ग्राहक सेवा—इन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। आलोच्य वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने 1,349 अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए कुल 66 कार्यक्रम चलाए, 1963 में महाविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या बढ़कर 25,547 हो गयी। इनमें से कुछ कार्यक्रमों में विदेशी बैंकों के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

17.19 महाविद्यालय ने 7 जुलाई, 1989 को एक समारोह आयोजित कर अपनी स्वर्ण जयंती मनायी। तमिलनाडु के राज्यपाल समारोह के अध्यक्ष थे। इस अवसर पर महाविद्यालय के इतिहास पर 'रिजर्व बैंक स्टाफ कालेज—इवोल्यूशन एण्ड डेवलपमेंट (रिजर्व बैंक महाविद्यालय उद्भव और विकास) शीर्षक की एक पुस्तक प्रकाशित की गयी।

#### कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे

17.20 यह महाविद्यालय सहकारी बैंकों, वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राष्ट्रीय बैंक, रिजर्व बैंक, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों तथा दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देशों की कृषि बैंकिंग, ग्रामीण बैंकिंग और उसमें संबंधित विषयों के क्षेत्र में प्रशिक्षण विषयक आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा। आलोच्य वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने कई नए कार्यक्रम प्रारंभ किए जिनमें सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण, खंड (ब्लॉक) श्रृंखला योजनाएं और अन्य मामलों, श्रृंखला योजनाएं तैयार करना, महिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षाओं के लिए कार्यक्रम और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र के कार्यक्रमों का वित्तपोषण सम्मिलित हैं। महाविद्यालय ने हिन्दी माध्यम में 22 कार्यक्रम चलाए। आलोच्य वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने 2,712 अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हुए 126 कार्यक्रम चलाए जिनमें 1969 में हुई महाविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक प्रशिक्षित अधिकारियों की कुल संख्या 35,980 हो गयी।

#### आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र

17.21 बैंक के भाषाबला (बर्बई), कलकत्ता, मद्रास और नयी दिल्ली स्थित आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र बैंक के श्रेणी III और IV के कर्मचारी वर्ग की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्प्यूटर और ग्राहक सेवा—इन विषयों पर कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र, नयी दिल्ली में श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए दो कार्यक्रम हिन्दी माध्यम में चलाए गए। आलोच्य वर्ष के दौरान श्रेणी III और IV के क्रमशः 1,395 और 367 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, इससे आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित इन कर्मचारियों की संख्या बढ़कर क्रमशः 36,331 और 4,457 हो गयी।

#### वाणिज्य बैंकों में प्रशिक्षण

17.22 बैंक के अधिकारियों को वाणिज्य बैंकों में प्रशिक्षित करने के लिए वर्ष 1986 में प्रारंभ की गयी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के द्वारा समूह में प्रतिनियुक्त 38 अधिकारियों में से 34 अधिकारियों ने



समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपना कार्यक्रम पूरा कर लिया है और भेष अधिकारी शीघ्र ही उसे पूरा करेंगे; आलोच्य वर्ष के दौरान प्रशिक्षण के लिए 40 अधिकारियों के लीसेन समूह का चयन कर लिया गया है, जिसमें से सात ने अपना प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया है। वाणिज्य बैंकों के प्रमुख विभागों की कार्यप्रणाली से गहराई से अभ्यस्त कराने के लिए आलोच्य वर्ष के दौरान चुने गए चार वरिष्ठ अधिकारियों में से दो अधिकारियों ने नियत दायित्व पूरा किया है, एक और अधिकारी प्रशिक्षण पा रहे हैं और चौथे अधिकारी शीघ्र ही प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगे।

कर्मचारियों की भारत में तथा विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति

17.23 बैंक ने भारत के प्रबन्ध मन्त्रों/बैंकिंग संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विचार गोष्ठियों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए 338 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया। दो अधिकारी मप्रति सेंटर फार डेवलपमेंट स्टडीज, त्रिवेन्द्रम में व्यावहारिक अध्ययन में एम. फिल. के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। बैंक ने अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, पश्चिम जर्मनी, जापान, मिरापुर और दक्षिण कोरिया स्थित बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं में प्रशिक्षण और अध्ययन के लिए भी 28 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है।

17.24 बैंक के स्वर्ण जयंती समारोह के एक अंश के रूप में बनायी गयी बैंक के अधिकारियों को विदेश में उच्चतर अध्ययन के वास्ते छात्र-वृत्तियों प्रदान करने की योजना के अंतर्गत तीन अधिकारियों ने विदेश स्थित विभिन्न संस्थाओं में उच्चतर अध्ययन के लिए प्रस्थान किया है।

विदेशी बैंकों के अधिकारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं

17.25 विदेशी केन्द्रीय बैंकों और वाणिज्य बैंकों के अनुरोध पर बैंक उनके अधिकारियों को प्रशिक्षण और अध्ययन की सुविधाएं प्रदान करता रहा। आलोच्य वर्ष के दौरान कुल 45 विदेशी अधिकारियों ने रजर्व बैंक में प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाया जिनमें से नमोबिया से 10, भूटान और अफगानिस्तान प्रत्येक से 5-5, केन्या और सोमालिया प्रत्येक से 4-4, जाम्बिया और अरुंधाबी प्रत्येक के 3-3, सूडान, श्रीलंका और उगांडा प्रत्येक से 2-2 तथा तंजानिया, मालदीव, मलावी, इथियोपिया और गाम्बिया प्रत्येक से एक-एक सहभागी सम्मिलित थे।

कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण

17.26 कम्प्यूटर क्षेत्र में योग्यता अर्जित करने के लिए बनायी गयी प्रोत्साहन योजना को कर्मचारियों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए उबार बनाया गया है और उसे अधिक लक्ष्य बनाते हुए, कर्मचारियों

को कतिपय निर्दिष्ट शर्तों पर अपनी रुचि की किसी भी संस्था में नामांकन कर लेने की अनुमति दी गयी है।

व्यावसायिक योग्यताएं प्राप्त करने पर प्रोत्साहनों की योजना

17.27 विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहित करने की योजना के अनुसरण में, जो कर्मचारी इन्स्टिट्यूट आफ चार्टर्ड फाइनेंसियल एनालिस्ट्स आफ इंडिया (आई सी एफ ए आई) हैदराबाद द्वारा चलाए जा रहे सी एफ कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने की योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना के अंतर्गत, श्रेणी I और III के कर्मचारी पांच वर्षों के भीतर सी एफ कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर उनके द्वारा आई सी एफ ए आई को भुगतान किए गए शिक्षण शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।

नियोजन कर्मचारी संबंध

17.28 आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक में औद्योगिक संबंधों का वातावरण सामान्यतः शांतिपूर्ण बना रहा। इसके लिए एक छोटा सा अपवाद यह रहा कि श्रेणी IV के कर्मचारियों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। आल इंडिया रिजर्व बैंक एम्प्लोई एसोसिएशन (श्रेणी III) और आल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स फेडरेशन (श्रेणी IV) के साथ बैंक द्वारा क्रमशः 29 अगस्त 1989 और 27 नवंबर 1989 को वेतन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बैंक ने अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी आलोच्य वर्ष के दौरान वेतनमानों और अन्य सुविधाओं में संशोधन का घोषणा की।

17.29 बैंक के कामगार कर्मचारियों और अधिकारियों के एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ 16 जनवरी, 1990 को आयोजित बैठक में बैंक ने अंगदायी भविष्य निधि के स्थान पर पेन्शन योजना लागू करने के अपने निश्चय की घोषणा की जो वर्तमान कर्मचारियों के लिए बैकल्पिक आधार पर उपलब्ध होगी। पहली जनवरी, 1986 से लागू होने वाली यह योजना केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू चौथे वेतन आयोग द्वारा यथा संशोधित पेन्शन योजना के लगभग समान होगी। योजना की कार्य प्रणालियों को तैयार किया जा रहा है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आरक्षण श्रेणियों को रोजगार

17.30 कैबिनेट वर्ष 1989 के दौरान की गयी कुल सीधी भर्तियों में, विभिन्न वर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार रहा:

श्रेणी	भर्तियाँ किये गये		उनमें से		
	कुल उम्मीदवार	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
वर्ग					
श्रेणी I	93	11	—	11.8	—
श्रेणी III	650	114	33	17.5	5.1
श्रेणी IV	465	69	128	14.8	27.5
उनमें से मर्यादित कर्मचारियों को छोड़कर	373	35	123	9.4	33.0
मर्यादित कर्मचारी	92	34	5	37.0	5.4

17.31 इससे 1 जनवरी, 1990 को बैंक में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की कुल संख्या बढ़कर श्रेणी IV में क्रमशः 2,262 और 678, श्रेणी III में 2,310 और 1,045 तथा श्रेणी I में 458 और 102 हो गयी है।

#### भूतपूर्व सैनिक

17.32 कैलेंडर वर्ष 1989 के दौरान श्रेणी III और IV में भरी गयी 650 और 465 रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण को 14 1/2 प्रतिशत और 24 1/2 प्रतिशत की निर्धारित दरों पर क्रमशः 94 और 114 रिक्तियां आरक्षित रखी जानी थी। इसके मुकाबले श्रेणी III में 60 और श्रेणी IV में 67 रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरी गयी। इससे 31 दिसम्बर, 1989 को भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या बढ़कर श्रेणी III में 741 और श्रेणी IV में 1,008 हो गयी। भूतपूर्व सैनिकों की सेवा शर्तों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए संयुक्त मुख्य प्रबन्धक को भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है।

17.33 वर्ष 1989 के दौरान यह निश्चय किया गया कि श्रेणी IV के कर्मचारियों के सामान्य वर्गों के लिए निविष्ट न्यूनतम अर्हताओं को भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में समाप्त किया जाए तथा अधिकतम अर्हताओं में छूट दी जाए। वर्ष 1989-90 के दौरान यह भी निश्चय किया गया कि —

- (i) 15 वर्ष की रक्षा सेवा वाले मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिकों को श्रेणी III में उन पदों पर भर्ती के लिए पात्र समझा जाएगा, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक परीक्षा निर्धारित है।
- (ii) बैंक की सेवा में भर्ती होने के बाद श्रेणी IV के भीतर और श्रेणी III के भीतर तथा श्रेणी IV से श्रेणी III और श्रेणी III से श्रेणी I में पहली बार पदोन्नति के लिए 10 वर्षों और 5 वर्षों की रक्षा सेवा के लिए क्रमशः 2 वर्ष और 1 वर्ष की सेवा संबंधी शर्तें में छूट देते हुए अधिमान दिया जाएगा। इस अधिमान का लाभ उन्हें 9 वर्षों की सेवा के बाद कर्मचारियों को प्रदान किये जाने वाले विशेष वेतन के संदर्भ में भी उपलब्ध होगा।

#### विकलांग व्यक्ति

17.34 कैलेंडर वर्ष 1989 के दौरान, 20 विकलांग व्यक्तियों को भर्ती किया गया जिससे बैंक में कार्यरत विकलांग कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 377 हो गयी।

#### हिन्दी की प्रगति

17.35 बैंक ने हिन्दी के प्रयोग में तेजी लाने के लिए न केवल अपने प्रयासों को और भी गहन बनाया बल्कि विभिन्न उपाय भी किये। इनमें से उल्लेखनीय उपाय इस प्रकार थे: हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1989-90 के वार्षिक कार्यक्रम को कर्तार से लागू करने के लिए प्रयास, बैंक की रिपोर्टें और प्रकाशन, जिनमें वार्षिक रिपोर्टें मुद्रा और वित्त की रिपोर्टें, भारत में बैंक व्यवसाय की प्रवृत्ति और प्रगति की रिपोर्टें, भारतीय रिजर्व बैंक बुनेटिन, भारतीय रिजर्व बैंक न्यूज लेटर और ग्रहण सूचना समीक्षा शामिल हैं, द्विभाषिक रूप में प्रकाशित किया जाना। वर्ष के दौरान 48 मैन्युअलों में से लगभग 42 मैन्युअलों का हिन्दी में अनुवाद कार्य पूरा कर लिया गया है।

17.36 आलोच्य वर्ष के दौरान गुजरात विद्यापीठ, सहमदाबाद के तत्वावधान में रिजर्व बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए दो हिन्दी कार्यशालाएं तथा उनकी प्रशिक्षण संस्थाओं के संकाय सदस्यों के लिए दो और कार्यशालाएं चलाई गयी जिनमें 33 वरिष्ठ

अधिकारियों और 33 संकाय सदस्यों ने भाग लिया इसके अलावा अन्य अधिकारियों के लिए हिन्दी टिप्पण, प्रारूप लेखन और पत्राचार में उनकी निपुणता को बढ़ाने के उद्देश्य से गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें 321 अधिकारियों ने भाग लिया। जो वरिष्ठ अधिकारी हिन्दी बोल सकते थे परन्तु लिख-पढ़ नहीं सकते थे उनके लिए दो सप्ताह का एक विशेष पूर्णकालिक प्रायोगिक कार्यक्रम चलाया गया जिसमें 11 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। प्रबोध, प्रबोध और प्राज्ञ परीक्षा में बैठने हेतु 66 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया तथा 17 टंककों को हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण दिया गया।

17.37 हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में तथा सरकार के अनुदेशों के अनुपालन में सुविधा पट्टनो की दृष्टि से बैंक ने अनुदेशों का एक संकलन प्रकाशित किया है। राजभाषा संबंधी अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक के कर्मचारियों के लाभ के लिए केन्द्रीय कार्यालय के राजभाषा प्रभाग में एक संदर्भ कक्ष की स्थापना की गयी है।

17.38 बैंक के केन्द्रीय कार्यालय के विभागों तथा अन्य कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां पहले की तरह सक्रिय रहीं और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर नियंत्रण रखने तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की देखरेख करने के निम्न नियमित रूप से उनकी बैठकें होती रहीं।

17.39. क्षेत्र "क", "ख" और "ग" में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में उल्लेख कार्य निष्पादन के लिए प्रदान की जाने वाली रिजर्व बैंक शील्ड के सदस्य में सहायक क्षेत्र के बैंकों के बीच प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। बैंक की अन्तर्कार्यालयीन और अन्तर्विभागीय प्रतियोगिताओं में भी शील्ड और पुरस्कार प्रदान किये गये। प्रति वर्ष 14 दिसम्बर को मनाये जाने वाले हिन्दी दिवस और हिन्दी सप्ताह के उपलक्ष्य में भी बैंक में विभिन्न प्रतियोगिताएं और समारोह आयोजित किये गये।

17.40 सरकारी क्षेत्र के बैंकों और रिजर्व बैंक द्वारा संचालित प्रशिक्षण महाविद्यालयों/संस्थाओं में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति और भारत सरकार की सफाईयों को लागू करने के उद्देश्य से वर्ष 1988 में गठित हिन्दी प्रशिक्षण संबंधी समन्वय समिति ने कार्य प्रणालियां, कार्य योजनाएं आदि तैयार करने का अपना कार्य जारी रखा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षण सामग्री को द्विभाषिक रूप में बनाया जाए और हिन्दी माध्यम से अधिकाधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाएं। कृषि, सामाजिक बैंकिंग, विदेशी मुद्रा, ग्रहण आदि जैसे विषयों पर शब्दावली से संबंधित बैंकिंग परिभाषा कोश तैयार हो गया है और उसे भी शीघ्र ही प्रकाशित किये जाने की आशा है। बैंकिंग शब्दावली को संशोधित और अद्यतन करने का कार्य प्रगति पर है।

17.41 बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लेखन तथा तकनीकी जानकारी और गन्दावली आदि के प्रसार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "बैंकिंग जितन—अनुचितन" नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन जारी रहा। पूरे बैंकिंग उद्योग में परिष्कार के लिए निकाली जा रही इस पत्रिका का अच्छा स्वागत किया गया है। बैंक अपनी गृह पत्रिका "विवादट रिजर्व" को भी समुचित हिन्दी सामग्री के साथ प्रकाशित करता रहा।

#### कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टर्स

17.42 आलोच्य वर्ष के दौरान कार्यालय भवनों और आवासीय क्वार्टरों के निर्माण/अधिशृण तथा वर्तमान परिसरों में परिवर्तन और परिवर्धन पर तथा जमीन की खरीद पर 20.98 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गयी। आलोच्य वर्ष के दौरान कोचिन में लगभग 42,000 वर्ग फीट के निर्मित क्षेत्र वाले कार्यालय भवनों तथा नोएडा (उ.प्र.) में लगभग 12,000 वर्ग फीट वाले मिक्का वास्ट का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसी प्रकार विरेचम, कोचिन, बंगलूर, कलकत्ता, कानपुर और चंडीगढ़ बंस्वर्ध में अधिकारियों के लिए 365 क्वार्टरों और 918

स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। भोपाल, बम्बू, नयी बंबई में कार्यालय भवनों तथा हूंदराबाद में बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय काम्प्लेक्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। भुवनेश्वर, मद्रास, कलकत्ता गखनऊ, अहमदाबाद और बंबई में अधिकांशियों के लिए 565 क्वार्टरों, और 764 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों पर है।

हॉली डे होम

17.43 उदकमण्डलम के हॉलीडे होम में अन्रिक्त कमरों के निर्माण का दूसरा चरण पूरा हो गया है। दार्जिलिंग में हॉलीडे होम बनाने के लिए भूमि प्राप्त करने के प्रयास जारी है।

आवास ऋण

17.44 वर्ष 1989-90 (जुलाई-जून) के दौरान बैंक द्वारा कर्मचारियों (समितियों/वैयक्तिक) को मंजूर की गयी आवास ऋण की राशि 10.45 करोड़ रुपये थी, जिसके विवरण नीचे दिये गये अनुसार है:—

17.45 वर्ष 1989-90 के दौरान आवास ऋण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख नीतिगत परिवर्तन लागू किये गये:

(i) वैयक्तिक आवास ऋण प्राप्त करने के लिए न्यूनतम पावता अवधि को पहली अप्रैल, 1990 से घटाकर बैंक में कर्मचारी की

सर्वग	समितियों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	ऋणों की राशि (रुपये)
1	2	3	4
अ. सहकारी आवास समितियाँ	47	204	1,12,19,14
i. नये ऋण	18	58	54,67,828
ii. अन्रिक्त ऋण	29	146	57,51,314
आ. केन्द्रीय कार्यालय द्वारा स्वीकृत वैयक्तिक ऋण	—	282	2,47,01,451
i. नये ऋण	—	202	2,33,86,649
ii. अन्रिक्त ऋण	—	80	13,14,802
इ. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्वीकृत वैयक्तिक ऋण	—	976	6,85,96,947
i. नये ऋण	—	902	6,65,15,062
ii. अन्रिक्त ऋण	—	74	20,81,885
अ + आ + इ का योग	47	1,462	10,45,17,54

सेवा की अस्थायी अवधि सहित निरंतर सेवा के तीन वर्ष कर दिया गया है। पहले न्यूनतम पावता अवधि पाँच वर्ष थी।

(ii) संपत्ति के स्वाध्याधिकार की स्वीकृति के लिए आवेदक कर्मचारी/समिति को बिना से पूर्व के 30 वर्षों की अवधि से संबंधित खोज रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। मई 1990 से खोज अवधि को घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया है।

(iii) श्रेणी iii और iv के कर्मचारियों के लिए आवास ऋण की अब तक विद्यमान 1,10,000 रुपये की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर पहली मई, 1990 से 2,50,000 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार विस्तार/परिवर्धन के लिए अधिकतम सीमा को श्रेणी iii और iv के लिए पहले विद्यमान क्रमशः 30,000 रुपये और 24,000 रुपये की अलग-अलग सीमाओं को बढ़ाकर दोनों के लिए 60,000 रुपये कर दिया गया है।

(iv) श्रेणी iii और iv के कर्मचारियों के संदर्भ में 1,10,000 रुपये से अधिक की ऋण राशि पर 1 मई, 1990 से 11 प्रतिशत की ब्याज दर लागू होगी।

केन्द्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड

17.46 श्री रा.ना. मल्होत्रा को 3 फरवरी, 1990 को उनकी वर्तमान सेवा अवधि समाप्त हो जाने पर 4 फरवरी, 1990 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाली और अवधि

के लिए गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। डॉ. पी. डी. भोक्षा उप गवर्नर के रूप में 28 अप्रैल, 1990 को अपनी सेवा अवधि समाप्त होने पर पद मुक्त हुए। बोर्ड उप गवर्नर के रूप में डॉ. पी. डी. भोक्षा द्वारा की गयी सेवाओं की सराहना अभिलेखित करना चाहता है। श्री रा. जानकी रामन को 16 मई, 1990 से तीन वर्ष की अवधि के लिए उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है।

17.47 बोर्ड को यह सूचित करते हुए दुःख है कि श्री छोदीलाल, निदेशक का 6 अक्टूबर, 1989 को निधन हो गया। श्री छोदी लाल जुलाई, 1979 से केन्द्रीय बोर्ड पर थे और बोर्ड उनके द्वारा की गयी सेवाओं की सराहना अभिलेखित करना है।

17.48 श्री जी. के. अरोड़ा के वित्त सचिव का पद छोड़ने के फलस्वरूप वे 9 जनवरी, 1990 से केन्द्रीय बोर्ड में भारत सरकार के नामिती नहीं रहे और वित्त सचिव का पदभार संभालने वाले डॉ. विमल जालान को उम्मी तारीख से उनके स्थान पर नामित किया गया। बोर्ड श्री जी. के. अरोड़ा द्वारा की गयी सेवाओं की सराहना अभिलेखित करना चाहता है।

17.49 अलोक्य वर्ष के दौरान स्थानीय बोर्डों के गठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

17.50 श्री यू. के. शर्मा और श्री मर्यादा बगई 31 दिसम्बर 1989 से कार्यपालक निदेशक के रूप में पदमुक्त हुए। कु. आई.टी. वाज और कु. वि. विषयनाथन को 1 जनवरी, 1990 से कार्यपालक निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया।

लेखे

17 51 30 जून, 1990 को समाप्त हुए लेखा वर्ष के दौरान बैंक की कुल आय की राशिगत वर्ष के 4,030.25 करोड़ रुपये के मुकाबले 4,426.73 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष के लिए बैंक के कुल व्यय की राशिगत वर्ष के 3,005.12 करोड़ रुपये की तुलना में 3,256.61 करोड़ रुपये थी। वर्ष के 1,170.12 करोड़ रुपये (गत वर्ष के 1,025.13 करोड़ रुपये के मुकाबले) के शुद्ध लाभ में से राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्विरो-करण) निधि, राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि के लिए इस वर्ष के लिए किये गये अभिदानों की राशि 375 करोड़ रुपये 10 करोड़ रुपये, 525 करोड़ रुपये और 50 करोड़ रुपये थी जबकि गत वर्ष वह क्रमशः 330 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये, 450 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये थी। चालू वर्ष के लाभ में से केन्द्रीय सरकार को भुगतान के लिए अलग से रखे गये अधिशेष लाभ की राशि 210.12 करोड़ रुपये है जबकि गत वर्ष वह 210.13 करोड़ रुपये थी। बैंक की आयगत वर्ष के 4,030.25 करोड़ रुपये के स्तर में 1989-90 में 396.48 करोड़ रुपये बढ़कर 4,426.73 करोड़ रुपये हो जाने का मुख्य कारण बैंक के व्याज अर्जन में वृद्धि होता था। जो भारतीय

रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की विनिर्दिष्ट अनिवार्य नकदी भेष निधियों पर उनको अंदा किये गये व्याज में तीव्र वृद्धि, मासिक निधियों में अंशदान में वृद्धि और स्थापना व्यय में वृद्धि के कारण काफी हद तक प्रसिन्नित हो गयी।

लेखापरीक्षक

17 52 बैंक के लेखों की लेखा परीक्षा मैसर्स खन्ना और अग्रवाल, नयी दिल्ली, मैसर्स अमित ए एंड कंपनी, इलाहाबाद, मैसर्स मुखर्जी, बिस्वास और पाठक, कलकत्ता, मैसर्स सोराब एम. इंजीनियर एंड कंपनी, बम्बई, मैसर्स एस. विध्वनाथन, मद्रास और मैसर्स एस. के. कपूर एंड कंपनी, कानपुर द्वारा की गयी है। सभी छह लेखा परीक्षकों को भारत सरकार ने वर्तमान वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त किया है। बैंक के सभी कार्यालयों की इस वर्ष भी मासिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गयी। लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए बैंक के कार्यालयों को छह अंचलों में विभाजित किया गया और प्रति अंचल प्रति लेखा परीक्षक अवा की गयी लेखा परीक्षा शुल्क की राशि 90,000 रुपये थी। केन्द्रीय कार्यालय के लेखा परीक्षकों को शाखा लेखों के समेकन के लिए 5,000 रुपये का अनिवार्य शुल्क अंदा किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक

30 जून 1990 की स्थिति का तुलना-पत्र

(हजार रुपये में)

वैयताएं	निर्गम विभाग		आस्तियां		
	1989-90 रु.	1988-89 रु.		1989-90 रु.	1988-89 रु.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	18,21,19	19,05,64	माने का सिक्का और बुलियन		
संचालन में नोट	50082,26,71	41639,52,50	(क) भारत में रखा हुआ	280,66,99	274,27,76
			(ख) भारत से बाहर रखा हुआ	--	--
जारी किए गये कुल नोट	50100,47,90	41658,58,14	विदेशी प्रतिभूतियां	1564,05,75	1564,05,75
			जोड़	1844,72,74	1838,33,51
			रुपये का सिक्का	38,96,21	60,18,20
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	48216,78,95	39760,06,43
			देशी विनिधम बिल और दूसरे वाणिज्यिक पत्र	--	--
कुल वैयताएं	50100,47,90	41658,58,14	कुल आस्तियां	50100,47,90	41658,58,14

वैयताएं	बैंकिंग विभाग		आस्तियां		
	रु.	रु.		रु.	रु.
1	2	3	4	5	6
प्रदान पूंजी	5,00,00	5,00,00	नोट	18,21,19	19,05,64
प्राप्त निधि	150,00,00	150,00,00	रुपया सिक्के	10,50	9,25
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	5150,00,00	4625,00,00	छोटे सिक्के	6,09	4,71
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	125,00,00	75,00,00	अन्य तथा भुनाये गये ऋण :		
जमा राशियां			(क) आंतरिक	--	--
(क) सरकार			(ख) बाहरी	--	--
(i) केन्द्र सरकार	140,86,90	81,68,58	(ग) सरकारी खजाना वित्त	1796,88,08	3606,80,21
(ii) राज्य सरकारें	16,66,85	15,51,22	विदेशों में रखे गये अकाया शेष	2378,33,76	2918,80,18

1	2	3	4	5	6
(ख) बैंक			निवेश <sup>2</sup>	32350,68,89	25654,79,96
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2606,215,09	22057,44,62	निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम		
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	464,62,78	482,32,26	(i) केन्द्र सरकार	--	--
(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	1,37,30	73,49,89	(ii) राज्य सरकार	10,64,00	54,17,00
(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	15,00,46	10,60,28	निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम		
(v) अन्य बैंक	96,93,35	29,99,01	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2467,31,04	2174,24,01
(ग) अन्य	2142,17,20	2197,92,22	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	27,41,25	24,34,65
वैयक्तिक	112,86,03	112,39,05	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	--	--
अन्य देयताएँ	14170,38,53	13186,63,73	(iv) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	--	--
			(v) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	2858,34,67	2277,68,00
			(vi) अन्य	67,61,00	42,43,00
			राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन)		
			निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेश		
			(क) निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम		
			(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	3822,30,46	3528,32,86
			(ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	625,00,00	530,00,00
			(iii) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	95,00,00	700,00,00
			(iv) अन्य	--	--
			(ख) निम्नलिखित द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश:		
			(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	--	--
			(ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	--	--
			(iii) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	--	--
			(iv) अन्य	--	--
			राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन)		
			निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेश		
			(क) राष्ट्रीय आवास बैंक को ऋण एवं अग्रिम	75,00,00	50,00,00
			(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बांडों/डिबेंचरों में निवेश	--	--
			अन्य आस्तियाँ <sup>3</sup>	2145,13,12	2149,21,39
कुल देयताएँ	48738,05,05	43098,00,86	कुल आस्तियाँ	48738,05,05	43098,00,86

1 इसमें आकस्मिक लेखों को शामिल किया गया है।

2 विदेशों में विदेशी मुद्रा में रखे हुए 1413.77 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1592.31 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

3 इनमें विशेष व्यवस्थाओं के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अग्रिम दी गयी या उनके पास जमा रखी गयी राशियाँ भी शामिल हैं।

(हजार रुपये में)

30 जून 1990 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

आय	1989-90	1988-89
1	2	3
व्याज बढ़ा, विनियम शुल्क, कमीशन आदि <sup>1</sup>	4426,72,53	4030,25,49
जोड़	4426,72,53	4030,25,49

1	2	3	4
व्यय			
व्याज		2571,33,44	2312,49,89
स्थापना व्यय		228,38,92	149,76,47
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के शुल्क और व्यय		5,68	4,65
खजाना प्रेषण		5,69,19	4,45,25
एजेंसी प्रभार		261,25,11	259,45,83
प्रतिभूति छपाई (चैन, नोट, फार्म आदि)		143,71,16	187,01,74
मुद्रण और लेखन-सामग्री		2,68,50	2,15,99
डाक और तार खर्च		2,77,54	3,68,97
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि		13,10,37	10,40,75
लेखा परीक्षा के शुल्क और व्यय		9,65	8,75
विधि प्रभार		22,46	7,14
बैंक संपत्ति का मूल्य-ह्रास और उसकी मरम्मत		19,82,26	15,31,44
विविध व्यय		7,46,49	10,15,13
	जोड़	3256,60,77	3005,12,00
उपलब्ध शेष राशि		1170,11,76	1025,13,49
घटाइये : निम्नलिखित में अंशदान			
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण			
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	525,00,00		450,00,00
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण			
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि <sup>2</sup>	375,00,00		330,00,00
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण			
(स्विचिंग) निधि <sup>2</sup>	10,00,00		10,00,00
राष्ट्रीय अ.वा.स. ऋण			
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	50,00,00		
			25,00,00
		960,00,00	815,00,00
केन्द्रीय सरकार की देय अधिशेष		210,11,76	210,13,49

1. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार नियमित या आवश्यक प्रावधान करने के बाद ।

2. ये निधियाँ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा रखी जाती हैं ।

एस. एम. रानडे	रा. जानकीरामन	पी. आर. नाथक	सी. रंगराजन	ए. घोष	रा. ना. महोत्रा
मुख्य लेखाकार	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

#### लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में,

हम भारतीय रिजर्व बैंक के अधोहस्ताक्षरित लेखा परीक्षक इसके द्वारा 30 जून, 1990 की स्थिति के तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे पर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हैं ।

हमने भारतीय रिजर्व बैंक के 30 जून, 1990 की स्थिति के तुलन-पत्र की और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे की जांच की है और यह रिपोर्ट करते हैं कि हमने बैंक से जो स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी, ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दिये गये और वे संतोषजनक हैं । हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक के बही-खातों में दर्शाये गये अनुसार यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही तुलन-पत्र हैं, जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिये गये हैं तथा हमे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उनके अन्तर्गत बनावे गये विनियमों के अनुसरण में सही तरीके से बनाया गया है ताकि हमने बैंक के कार्यों की सच्चाई और सही स्थिति का पता लग सके ।

मेसर्स खन्ना एण्ड अन्नाधनम	मेसर्स अभिनव एण्ड कं. लेखा-परीक्षक	मेसर्स मुखर्जी विश्वास एण्ड पाठक लेखा परीक्षक	मेसर्स एम. विश्वनाथन लेखा-परीक्षक	मेसर्स सोराब एम. इंजीनियर एंड कं. लेखा-परीक्षक	मेसर्स एम. के. कपूर एण्ड कं. लेखा-परीक्षक
-------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

16 अगस्त 1990

[संख्या एफ. 14/15/90-बी.ओ.-I]

एस. एम. सीतारामन, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 9th October, 1990

S.O. 461.—In accordance with section 53(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Board of Directors has submitted to the Government of India the following Annual Report on the working of the Reserve Bank of India during the year ended June 30, 1990 :—

## THE ANNUAL REPORT ON THE WORKING OF THE RESERVE BANK OF INDIA

For the year July 1, 1989 to June 30, 1990

## PART I—THE ECONOMIC SITUATION

## 1. HIGHLIGHTS

During the fiscal year 1989-90, the Indian economy experienced yet another year of reasonably good performance with an estimated growth of about 4.5 per cent in real gross domestic product (GDP) which was on top of a large growth of 10.4 per cent during 1988-89. However, several serious macro-economic imbalances which surfaced in recent years such as, large budgetary deficits and current account deficits in the balance of payments, as also pressure on prices persisted during the period under review. The index of agricultural production in 1989-90 is estimated to have increased by about 1.5 per cent after a record rise of 20.8 per cent in 1988-89. Foodgrains production placed at 172.7 million tonnes in 1989-90 is expected to surpass the peak output of 170.3 million tonnes in the previous year. The year under review has also seen significant increases in the production of a number of major commercial-crops. The year 1989-90 began with a perceptible slow-down in industrial growth but there was a substantial pick-up towards the end of the year, resulting in an overall growth of 8.3 per cent which was only slightly lower than the growth achieved in the previous year (8.7 per cent). The rates of growth of basic, intermediate and consumer durable goods industries suffered a setback, while those of capital goods and consumer non-durable goods industries showed noticeable improvement. Many other macro-economic indicators showed an uptrend in 1989-90, probably in part also due to the lagged benefits from the previous year's record growth. The rate of domestic saving thus showed a sizeable improvement from 20.8 per cent of GDP in 1988-89 to 21.4 per cent in 1989-90. Partly as a result of this and partly as a result of a fairly high level of foreign resources inflow, the rate of domestic investment was higher albeit fractionally at a level of 23.9 per cent than in the previous year (23.8 per cent). The phenomenon of sustained investment is corroborated by the accelerated growth of capital goods output, as also by the rise in their imports, and a distinct rise in estimated capital expenditures incurred by the private corporate business sector during 1989. Continued buoyancy in the primary and secondary capital markets during 1989-90 was also a conspicuous phenomenon. Yet another note-

worthy performance was the robust pace of export growth for the fourth year in succession. Merchandise trade data suggest that while exports, in rupee terms, grew by 36.3 per cent (22.9 per cent in SDR terms), imports grew by 25.6 per cent (13.2 per cent in SDRs). It is estimated that the ratio of current account deficit to GDP may show a fall from 2.7 per cent in 1988-89 to 2.3 per cent in 1989-90, but remained much higher than the estimate of 1.6 per cent for the Seventh Five Year Plan. The inflation rate, as measured by the Wholesale Price Index (WPI), accelerated from 5.7 per cent in 1988-89 to 9.1 per cent in 1989-90 and the price increase became a more generalised phenomenon due to a variety of factors such as, sectoral supply-demand imbalance, additional budgetary imposts, the rise in important costs and the persistent accumulation of excess liquidity due to fiscal imbalances. The pressures on the finances of the Central Government persisted even more sharply than in the previous year, which is reflected in the conventional deficit far exceeding the original budget estimate. As per the Reserve Bank's records, the Centre's budgetary deficit stood at Rs. 10,624 crore in 1989-90 against the budgeted figure of Rs. 7,337 crore or the actual of Rs. 5,810 crore in 1988-89. Likewise, the net Reserve Bank credit to the Central Government worked out to Rs. 13,813 crore, i.e., more than twice the actuals of Rs. 6,503 crore for 1988-89. The year 1989-90 experienced a significantly larger rate of increase in overall liquidity ( $M_2$ ) at 19.9 per cent as compared with 18.1 per cent in the previous year. The pace of monetary expansion, as measured by  $M_1$ , was still higher at 22.5 per cent in 1989-90 against 15.2 per cent in 1988-89. In such a milieu, an overriding monetary policy consideration has been to contain inflationary pressures without jeopardising the growth potential of the economy. In particular, there was a need to moderate the expansion in non-food credit. As the statutory ceiling on the cash reserve ratio (CRR) had already been reached, greater reliance was placed on other measures which included a reduction in access to the export refinance facility increase in the statutory liquidity ratio (SLR) and the stipulation of an incremental non-food credit-deposit ratio which, if exceeded, also entailed additional cost on refinance from the Reserve Bank.

## 2. NATIONAL INCOME, SAVING AND INVESTMENT Growth Profile

2.1 Tentative estimates place the rate of growth of gross domestic product (GDP), at 1980-81 prices, at around 4.5 per cent during 1989-90 after an all-time high growth of 10.4 per cent achieved in 1988-89 (Table 2.1). The show-down in the growth rate in 1989-90 reflects the marginal increase in GDP originating in agriculture over the high level attained in 1988-89 and some deceleration in the growth of the manufacturing sector. With this growth profile for the terminal year of the Seventh Five Year Plan, the average growth rate for the Plan period (1985-86 to 1989-90) works out to about 5.6 per cent as against the Plan target of 5 per cent per annum. Also all broad sectors, viz, agriculture, manufacturing and electricity, and services, attained on an average higher rates of growth than those visualised in the Plan.

Table 2.1 : Growth Rates in Real GDP

Sector	Percentage Share (in real GDP)			Compound Growth Rate		Growth Rate (per cent)			
	1970-71*	1980-81	1988-89	1970-71 to 1980-81*	1980-81 to 1988-89*	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89 (Quick Estimates)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Agriculture and Allied Activities	44.5	38.0	33.0	1.8	2.7	+0.3	+1.7	+0.5	+17.4
(a) Agriculture	39.7	34.7	31.0	2.0	2.9	+0.3	-1.7	+0.7	+18.6
2. Industry	18.6	20.9	24.5	4.8	7.7	+7.7	-8.3	+6.2	+8.3
(a) Manufacturing	16.1	17.7	20.6	4.6	7.6	+7.8	+7.6	+6.0	+8.2
3. Services	31.9	36.1	38.3	4.6	6.4	+7.8	+7.0	+6.1	+6.9
Total GDP <sup>(a)</sup>	100.0	100.0	100.0	3.4	5.2	+4.9	+4.2	+4.1	+10.4

(a) Inclusive of construction.

\*Based on semi-logarithmic trends

+ The sectoral composition of real GDP for the year 1970-71 is at 1980-81 prices and hence it differs from that given at 1970-71 prices in the previous year's Annual Report (1988-89).

## Trends in Saving and Investment

2.2 The revised estimates show that the ratio of gross domestic saving to GDP at current market prices, moved up from 19.3 per cent in 1987-88 to 20.8 per cent in

1988-89, the provisional estimates for 1989-90 suggest that the saving ratio is expected to rise further to 21.4 per cent (Table 2.2). With this, the average gross saving rate during the Seventh Plan as a whole works out to 20.2 per cent.

Table 2.2 : Estimates of Domestic Saving and Investment Ratios

(In percentages)

Sector/Fiscal Year	Gross Saving & Investment as Percentage of GDP at Current Market Prices			Net Saving & Investment as Percentage of NDP at Current Market Prices		
	1987-88	1988-89 (Provisional)	1989-90 (Preliminary estimates)	1987-88	1988-89 (Provisional)	1989-90 (Preliminary estimates)
1	2	3	4	5	6	7
1. Household Sector Saving	15.7	17.3	18.0	12.9	14.8	15.3
of which Saving in Financial assets*	8.0	7.6	9.3	8.9	8.5	10.3
2. Public Sector	2.1	1.6	1.6	-2.7	-3.2	-3.2
3. Domestic Private Corporate Sector	1.5	1.9	1.8	-0.05	0.3	0.3
4. Total Domestic Saving (1+2+3)	19.3	20.8	21.4	10.2	11.9	12.4
5. Net inflow of foreign resources	2.3	3.0	2.5	2.6	3.3	2.8
6. Aggregate investment (4+5)	21.6	23.8	23.9	21.8	15.2	15.2
GDP/NDP at current market prices (Rupees crore)	3,32,553	3,91,158	4,42,769	2,98,677	3,51,703	3,97,540

\*These are adjusted for financial liabilities. As savings in financial assets do not involve capital consumption for fixed assets, net ratios work out higher than gross ratios; like-wise in net inflow of foreign resources.

Note : The ratios for 1987-88 and 1988-89 differ from those given in the previous year's Annual Report of the Bank and those published in the CSO's Quick Estimates for 1988-89, as also in the Government of India's Economic Survey for 1989-90, because of the revision in the estimates of national income and those of saving and investment consequent on the availability of fresh data. These estimates would undergo further revision when the CSO publishes its Quick Estimates 1989-90.

2.3 In nominal terms, the net inflow of foreign resources (including grants) during 1989-90 is expected to be lower than that in the previous year, in relation to GDP, the ratio of such inflow which was 2.3 per cent in 1987-88 and 3.0 per cent in 1988-89, is stated to decline to 2.5 per cent in 1989-90. Even so, with the improvement in overall domestic saving rate, the ratio of aggregate gross domestic investment to GDP is expected to increase albeit fractionally from 23.8 per cent in 1988-89 to 23.9 per cent in 1989-90 (see also Graph A). Over the Seventh Plan period, the investment rate has been augmented by 3.9 percentage points from 20.0 per cent during 1984-85 to 23.9 per cent during 1989-90 and the average rate for the Plan period works out to 22.6 per cent.

2.4 Sector-wise, the improvement in gross domestic saving in 1989-90 is entirely attributable to household saving, with the rate of public sector saving estimated to remain at the previous year's level and that of the private corporate sector marginally edging downward. The underlying unsatisfactory saving performance of these two sectors is better reflected in their net savings after providing for the depreciation of their physical assets. Thus, the public sector reflected a net dissaving of as high an order as 3.2 per cent of NDP each in 1988-89 and 1989-90 and the private corporate sector, a low rate of 0.3 per cent in each of the above-mentioned two years. The general profitability and retained earnings of the private corporate sector during the past two years have been better as compared with those in 1987-88 when the sector's net savings were estimated to be negative.

## Saving in Financial Assets

2.5 Household savings in the form of financial assets showed a significant increase during 1989-90, with the estimates of addition to gross financial assets showing a quantum jump both in absolute numbers and in relation

to GDP. The ratio of such gross financial saving to GDP, which stagnated around 10.4 per cent during the previous three years, jumped to 11.6 per cent in 1989-90. Furthermore, due to the fall in the ratio of financial liabilities to GDP, the household sector's net financial saving rate showed a more than proportionate increase from 7.6 per cent in 1988-89 to 9.3 per cent in 1989-90.

## Composition of Assets

2.6 As for the composition of individual financial assets in household saving, the trend in 1989-90 was somewhat different from the medium-term trend in that saving in the form of monetary assets (currency and bank deposits), as a proportion of incremental gross financial assets as well as GDP, experienced a rise. The currency to GDP ratio rose from 1.1 per cent in 1988-89 to 1.7 per cent in 1989-90 and the bank deposits to GDP ratio, from 3.9 per cent to 4.5 per cent. The share of currency and bank deposits in gross financial assets is expected to be 53.2 per cent in 1989-90 as against 48.2 per cent in 1988-89. The ratio of claims on government to GDP increased from 1.1 per cent in 1987-88 to 1.4 per cent in 1988-89 but is likely to slip down to 1.2 per cent in 1989-90. The ratio of contractual savings (life insurance and provident/pension funds) at 2.8 per cent during 1989-90 is estimated to be at the previous year's level (2.8 per cent in 1988-89), though their share in gross financial assets declined to 24.8 per cent during 1989-90 from 26.5 per cent during 1988-89. On account of the growing household preferences for the units of the Unit Trust of India and shares/debentures of the private corporate sector, the percentage share of these in gross financial assets is estimated to have increased from 5.9 per cent in 1987-88 to 7.1 per cent in 1988-89 and is expected to rise further to 8.0 per cent in 1989-90.



As a ratio of GDP, savings in these instruments have risen marginally from 0.7 per cent in 1987-88 to 0.8 per cent in 1988-89 and further to 0.9 per cent in 1989-90.

#### Changing Structure in the Medium-term

2.7 To place the changing household preferences in perspective, Table 2.3 sets out the structure of gross financial saving, as per the Plan projections and actuals, for the Sixth and Seventh Plan periods. These data reveal that :

(i) the share of currency is much higher than anticipated due to higher than anticipated monetisation ; (ii) the share of bank deposits is smaller than Plan projections as other financial instruments are relatively more attractive and (iii) a distinct shift in asset preferences is discernible, which both the Sixth and Seventh Plan projections did not anticipate, this shift has been in favour of company shares and units of UTI, and small savings media, which, vis-a-vis bank deposits have enjoyed significantly higher yields and better fiscal privilege.

Table 2.3 : Household Sector Savings in Gross Financial Assets (GFA):

#### Plan Projections and Actuals

Item	Sixth Plan Period (1980-81 to 1984-85)				Seventh Plan Period (1985-86 to 1989-90)			
	Plan Projections (at 1979-80 prices)		Actuals		Plan Projections at 1984-85 prices)		Actuals	
	Amount (Rupees crore)	As per- centage of Total GFA	As per- centage of Total GFA <sup>(a)</sup>	As per- centage of GDP at current Market Prices	Amount (Rupees crore)	As per- centage of Total GFA	As per- centage of Total GFA <sup>(a)</sup>	As per- centage of GDP at current Market Prices
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Monetary Assets	36,014	59.0	53.9	5.0	65,815	48.8	51.8	5.4
(i) Currency	4,734	7.8	11.9	1.1	8,527	6.3	11.6	1.2
(ii) Deposits (with scheduled commercial banks and co-operatives)	31,280	51.2	42.0	3.9	57,288	42.5	40.2	4.2
2. Contractual Savings	21,125	34.8	24.5	2.2	41,520	33.1	25.1	2.6
(i) Life funds	5,577	9.1	7.4	0.7	9,845	7.3	7.6	0.8
(ii) Provident and pension funds	15,648	25.7	17.1	1.5	34,675	25.8	17.5	1.8
3. Shares, Units and Company Deposits	2,550	4.2	9.3	0.9	14,003	10.4	11.3	1.2
(i) Non-banking companies deposits	1,150	1.9	4.8	0.5	8,592	6.4	3.8	0.4
(ii) Corporate/co-operative shares and debentures	1,400	2.3	3.4	0.3	2,911	2.2	4.3	0.5
(iii) Unit Trust of India	—	—	1.1	0.1	2,500	1.8	3.2	0.3
4. Net Claims on Government	1,245	2.0	10.1	0.9	8,750	6.5	11.5	1.2
5. Other Assets	—	—	2.2	0.2	1,593	1.2	0.3	0.1
6. Total Gross Financial Assets (1 to 5)	61,034	100.0	100.0	9.2	1,34,681	100.0	100.0	10.5
7. Financial liabilities	11,303	18.5	26.7	2.5	32,428	24.1	24.6	2.5
8. Net Financial Assets (6—7)	49,731	81.5	73.3	6.7	1,02,253	75.9	75.4	8.0

<sup>(a)</sup> These percentages are simple averages of such percentages for individual years, absolute figures for five years of the Plan are not additive as they are at current (i.e. respective year's) prices. The relative shift as between assets may be due to differing impact of prices which is not discussed in the Chapter.

## 3. AGRICULTURAL PRODUCTION

3.1 After experiencing an exceptionally good performance in 1988-89, agricultural production in 1989-90 is estimated to have increased by 1.5 per cent. Even this small growth was possible only because of well structured agricultural thrust production programmes (testified by significant increases in the application of key inputs such as an estimated 10.5 per cent rise in fertiliser use in 1989-90). There has been a noticeable expansion, for the second year in succession, in the output of coarse grains which reflects the spread of benefits in favour of dry and unirrigated areas where small and marginal farmers predominate. Pulses production however, remained at the previous year's level. Commercial crops other than oilseeds are also estimated to show substantial increases in 1989-90.

## Rainfall Situation

3.2 In 1989-90, the South-West monsoon was generally favourable. Over 80 per cent, that is 29 out of 35 meteorological sub-divisions received normal or excess rainfall and five out of the remaining six only slightly below normal these constituted over 95 per cent of the country's land area. Some of the drought prone areas such as interior Karnataka, Rayalseema and parts of Gujarat, Maharashtra and Tamil Nadu, received good rainfall. Moreover, the flood-prone areas such as East Uttar Pradesh, North Bihar, West Bengal, Orissa and the States of North-East India remained free from major floods. The temporal and spatial spread of the rainfall was, however, not even. Parts of

Eastern Rajasthan, adjoining parts of South-West Uttar Pradesh, Delhi and North-Western Madhya Pradesh experienced deficiency of rainfall. Similarly, the seasonal rainfall during October-December 1989 was deficient in the major Rabi growing states.

## Overall Agricultural Production

3.3 Agricultural production in 1989-90 is estimated to show a modest rise of 1.5 per cent on top of the record rise of 20.8 per cent in 1988-89. Despite two bad years, the average growth rate of agricultural production for the Seventh Plan period works out close to the Plan target of 4.0 per cent per annum. Agricultural growth during the Plan period has, however, been characterised by considerable degree of volatility and crop imbalances.

## Foodgrains Production

3.4 Total foodgrains output during 1989-90 is estimated at 172.7 million tonnes, thereby surpassing the peak output of 170.3 million tonnes attained in 1988-89 by 1.4 per cent. Kharif foodgrains output is placed at 100 million tonnes, i.e., 3.6 per cent higher than the output of 96.5 million tonnes in 1988-89, while Rabi foodgrains at 72.7 million tonnes showed a fall of 1.5 per cent over that of 73.8 million tonnes in the previous year (Table 3.1). The Seventh Plan had visualised a foodgrains production range of 178-183 million tonnes for the terminal year (1989-90) which was subsequently revised downwards to 173.2-175.2 million tonnes in the Mid-Term Appraisal of the Plan. The target for 1989-90 was revised to 175 million tonnes in the Annual Plan for 1989-90.

Table 3.1 : Production of Foodgrains

Item	(Million tonnes)					
	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90 (Estimates)
1	2	3	4	5	6	7
All foodgrains	145.5	150.4	143.4	140.4	170.3	172.7
Rice	58.3	63.8	60.6	56.8	70.7	72.8
Wheat	44.1	47.1	44.3	46.2	54.0	52.5
Coarse grains	31.1	26.2	26.8	26.4	31.9	34.0
Pulses	12.0	13.3	11.7	11.0	13.7	13.4
Kharif	84.5	85.2	80.2	74.6	96.5	100.0
Rice	53.8	59.4	53.6	49.0	63.9	65.6
Coarse grains	25.9	21.3	22.4	21.2	27.0	28.8
Pulses	4.8	4.5	4.2	4.4	5.6	5.6
Rabi	61.0	65.2	63.2	65.8	73.8	72.7
Rice	4.5	4.4	7.0	7.8	6.8	7.2
Wheat	44.1	47.1	44.3	46.2	54.0	52.5
Coarse grains	5.2	4.9	4.4	5.2	4.9	5.2
Pulses	7.2	8.8	7.5	6.6	8.1	7.8

Source : Ministry of Agriculture.

3.5 Crop-wise, in 1989-90, rice output at 72.8 million tonnes exceeded the peak output of 70.7 million tonnes of the previous year, while wheat output at 52.5 million tonnes was lower than the previous year's peak of 54.0 million tonnes. In rice, both Kharif and Rabi output recorded increases over the previous year due to favourable rains during the South-West monsoon and satisfactory levels of storage in irrigation reservoirs and groundwater recharge in rice-growing tracts. Wheat output declined because of unsatisfactory distribution of rainfall and moisture deficiency in major wheat-growing areas. As in the previous year, there was a further notable increase in the output of coarse grains

and the peak level of 33.9 million tonnes achieved in 1983-84 was creased. The production of coarse grains thus rose sizeably from 26.4 million tonnes in 1987-88 to 31.9 million tonnes in 1988-89 (by 20.8 per cent) and further to 34.0 million tonnes in 1989-90 (by 6.6 per cent). On the other hand, the production of pulses, which had reached a record level of 13.7 million tonnes in 1988-89, declined slightly to 13.4 million tonnes in 1989-90 (by 2.2 per cent). This fall was on account of the setback in Rabi output, which at 7.8 million tonnes, was lower by 3.7 per cent as compared with 8.1 million tonnes in the previous year; Kharif output of pulses remained at the previous year's level of 5.6 million tonnes.

## Regional Spread of Foodgrains Output

3.6 The spread of improvement in foodgrains output regionally, though noticeable to an extent, is as yet gradual. In Punjab, the annual average growth rate of foodgrains production for the first four years worked out to 1.5 per cent per annum against about 7 per cent per annum during the Sixth Plan period. In Haryana and Uttar Pradesh, the average annual growth rates during the first four years of the Seventh Plan worked out to 8.5 per cent and 4.6 per cent, respectively. A conspicuous development has been, increase in foodgrains production in the Eastern States of Assam, West Bengal, Bihar and Orissa as well as Rajasthan and Madhya Pradesh during both the Sixth and Seventh Plan periods. In contrast, there has been a near stagnation, or even absolute declines, in the foodgrains production levels of the four Southern States of Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during both the Plan periods; to an extent, this has also been the case in Maharashtra and Gujarat in the Western Region.

3.7 Over the past decade, the share of the three Northern States (Punjab, Haryana and Uttar Pradesh) in the country's total foodgrains production has steadily improved. In recent years, some increase is also seen in the share of the four Eastern States all of which have experienced relatively high

growth rates. Rajasthan and Madhya Pradesh did not maintain the earlier progress in production. Gujarat and Maharashtra in the Western Region and the four Southern States have experienced a steady and perceptible erosion in their proportions of total foodgrains output (Table 3.2).

## Per Capita Availability of Essential Commodities

3.8 The decade of the 1980s has seen an important in the per capita availability of certain articles of common consumption such as, cereals, sugar and tea, as also livestock products (milk and eggs) and fish. As depicted in Table 3.3, per capita daily availability of cereals increased from 416 grams in 1980-81 to 456 grams in 1988-89 though it declined to 435 grams in 1989-90 due mainly to the rise in population and higher build-up of stocks. In the case of sugar, per capita annual availability rose from 7.2 kgs. to 13.5 kgs. During the same period, per capita daily availability of pulses exhibited considerable fluctuations and rose only marginally from 38 grams to 39 grams. Per capita annual availability of edible oils and vanaspati improved from 5 kgs. in 1980-81 to 6 to 7 kgs. thereafter. Also, despite increased per Capita availability of cereals and, to some extent, other commodities the consumption of these essential commodities by substantial sections of the population continues to be below the mini-

Table 3.2 : Region-wise Distribution of Foodgrains Production

(Per cent)

Region	Distribution of All-India Production of Foodgrains by Regions (Three-yearly Averages)			
	1970-71 to 1972-73	1977-78 to 1979-80	1982-83 to 1984-85	1986-87 to 1988-89
1	2	3	4	5
1. Northern States (Punjab, Haryana & Uttar Pradesh)	29.5	30.3	35.2	37.1
2. Eastern States (Orissa, Bihar, West Bengal & Assam)	22.3	19.8	18.0	19.8
3. Rajasthan & Madhya Pradesh	17.2	14.1	15.9	14.6
4. Western States (Gujarat & Maharashtra)	7.9	11.7	10.6	8.6
5. Southern States (Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka & Kerala)	20.3	21.3	17.4	17.2
6. Other States/Territories	2.8	2.8	2.9	2.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0

imum nutritional requirements prescribed by the Indian Council of Medical Research. These critical shortfalls in consumption are known to be also true of a number of other nutritional requirements such as milk, vegetables and fruits. Apart from the shortfalls in consumption arising from inter-personal disparities, the inter-regional disparities in production performance contribute to such shortfalls in the regions where production and income levels and effective purchasing power have tended to lag behind.

## Procurement

3.9 Foodgrains procurement, which had suffered a setback in 1988-89 despite the bumper crop due to more intensified purchase operations by the private trade and millers, picked up in 1989-90 following the second successive good crop. Total procurement of foodgrains (rice and wheat) by the

public sector agencies at 20.3 million tonnes in the fiscal year 1989-90 was substantially higher than in the previous year, assisted inter alia by the hike in procurement prices offered to cultivators, easy availability of foodgrains in the open market, and intensified procurement operations by public agencies. The procurement of rice at 11.3 million tonnes was an all-time high (Table 3.4). Wheat procurement in 1989-90 was also higher at 9.0 million tonnes, as compared to 6.5 million tonnes in the previous year but lower than the procurement in 1985-86 and 1986-87. Punjab accounted for the highest share of total rice procurement (44 per cent), followed by Andhra Pradesh (19 per cent), Uttar Pradesh (13 per cent), Haryana (9 per cent) and Tamil Nadu (8 per cent). In the case of wheat also, Punjab accounted for the highest share of total procurement (62 per cent) followed by Haryana (22 per cent) and Uttar Pradesh (15 per cent).

Table 3.3 : Per Capita Availability of Certain Important Articles of Consumption

Year	Cereals <sup>(a)</sup> (in gms. per day)	(In Pulses) <sup>(a)</sup> (in gms. per day)	Total <sup>(a)</sup> (in gms. per day)	Edible Oils including Vanaspatti (Kgs. per year)	Sugar* (kgs. per year)	Tea (gms. per year)	Cotton cloth (metre)	Manmade fibres (metre)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1960-61	399.7	69.0	468.7	4.0	4.7	287	13.8	1.2
1970-71	417.6	51.2	468.8	4.5	7.3	387	13.6	2.0
1980-81	416.2	37.5	453.7	5.0	7.2	487	11.0	3.7
1983-84 (P)	436.1	41.8	477.9	7.0	10.3	399	10.8	4.0
1984-85 (P)	415.6	38.1	453.7	6.8	10.5	422	10.6	3.9
1985-86 (P)	434.2	41.9	476.1	6.3	10.9	426	10.8	4.0
1986-87 (P)	436.1	35.9	472.0	6.2	11.2	420	10.6	4.4
1987-88 (P)	413.6	33.0	446.6	7.0	11.7	595*	10.5	4.2
1988-89 (P)	456.1	40.5	496.6	6.5	12.2	601*	10.1	4.5
1989-90 (E)	434.6	38.9	473.5	5.6*	13.5*	568*	—	—

## Memorandum item

Minimum Per capita  
requirement recommended  
as dietary norms by  
Indian Council of  
Medical Research

E Estimated  
P Provisional  
× Related to actual releases  
for domestic consumption  
\* Preliminary  
@ Figures relate to calendar  
year 1961 onwards

## Cereals

## Rate

## 1. Adult man

(a) Moderate work 570 gm. per day

(b) Heavy work 730 gm. per day

## 2. Adult woman

(a) Moderate work 485 gm. per day

(b) Heavy work 728 gm. per day.

Pulses 47 gm. per day

Edible Oils 6.5 kg. per annum

Table 3.4 : Procurement of Rice and Wheat

(Million tonnes)

Financial Year	Procurement		
	Rice	Wheat	Total
1	2	3	4
1985-86	9.6	10.3	19.9
1986-87	9.4	10.5	19.9
1987-88	7.0	7.9	14.9
1988-89	7.6	6.5	14.1
1989-90	11.3	9.0	20.3
(Provisional)			
April-June			
1989	0.9	8.7	9.6
1990	1.2	11.0	12.2

Wheat procurement during the current Rabi 1990 marketing season is expected to reach a new high. Upto June 30, 1990, wheat procurement amounted to 11.0 million tonnes against the total procurement of 9.0 million tonnes during the whole of the Rabi 1989 marketing season.

## Off-take

3.10 The off-take of foodgrains during the financial year 1989-90 was the lowest in the last five years (Table 3.5). The off-take from the Central Pool (including open market sales) during the financial year 1989-90 aggregated 15.9 million tonnes as against 18.0 million tonnes in 1988-89 and 23.0 million tonnes in the drought year of 1987-88. Off-take of both rice and wheat was lower than in the previous year

but the decline was particularly sharp in the case of wheat. Allocations under NREP/RLEGP/EGS/JRY were lower during the year at 0.4 million tonnes in contrast to 0.8 million tonnes in 1988-89 and 2.9 million tonnes in 1987-88. Open market sales of wheat by FCI also declined from 3.6 million tonnes in 1987-88 to 1.0 million tonnes in 1988-89 and further to 0.2 million tonnes during 1989-90.

## Foodgrains Stocks

3.11 To augment stocks which were depleted in the previous two years, the Government took a series of measures such as raising procurement prices and opening of more purchasing centres in predominantly rice and wheat growing tracts. As a result, the foodgrains stock levels with public

Table 3.5 : Off-take of Foodgrains

(Million tonnes)				
Financial Year	Rice	Wheat	Coarse grains	Total
1	2	3	4	5
1983-84	7.7	7.4	0.2	15.3
1984-85	6.6	6.7	0.1	13.4
1985-86	7.4	11.7 (1.6)	0.2	19.3
1986-87	9.0	10.4 (2.9)	0.2	19.6
1987-88	10.1	12.8 (3.6)	0.1	23.0
1988-89	9.1	8.7 (1.0)	0.2	18.0
1989-90	8.6	7.3 (0.2)	neg.	15.9
April-June 1989	2.0	1.6 (0.1)	neg.	3.6
1990	2.2	1.4 (—)	neg.	3.6

Note : Figures in brackets represent open market sales of wheat by Food Corporation of India.

agencies have steadily increased from 7.4 million tonnes at the end of March 1989 to 11.7 million tonnes at the end of March 1990 and further to 20.3 million tonnes by the end of June 1990 (Table 3.6).

#### Commercial Crops

3.12 Commercial crops, with the exception of oilseeds, are likely to register substantial increases in production during 1989-90. These gains are mainly attributed to better weather conditions and the special thrust/development programmes undertaken for these crops. Sugarcane production is estimat-

ed at 210 million tonnes showing an increase of 2.4 per cent over the 1988-89 production of 205 million tonnes (Table 3.7). Cotton output is expected to reach a record of 115 lakh bales as against 87 lakh bales in 1988-89, showing a rise of 32.2 per cent; this rise is both on account of increase in productivity as well as area under the crop. Production of jute and mesta increased to 84 lakh bales from 77 lakh bales in the preceding year. Oilseeds production, however, declined to 17.2 million tonnes from 17.9 million tonnes in 1988-89, mainly due to adverse weather conditions in groundnut producing tracts of Gujarat and in rapeseed/mustard producing areas of Rajasthan and Uttar Pradesh.

Table 3.6 : Stocks of Foodgrains

(Million tonnes)				
As at	Rice	Wheat	Coarse grains	Total
1	2	3	4	5
End-March				
1984	5.4	10.0	0.1	15.4
1985	8.6	12.5	0.1	21.2
1986	10.3	10.2	0.2	20.7
1987	10.0	9.4	0.1	19.5
1988	5.9	3.3	0.2	9.4
1989	4.7	2.7	—	7.4
1990	7.9	3.6	0.2	11.7
End—June				
1989	3.6	9.4	neg.	13.0
1990	6.9	13.2	0.2	20.3

Table 3.7 : Production of Commercial Crops

Crop	Unit	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90 (Estimates)
1	2	3	4	5	6	7	8
Oilseeds	Million tonnes	13.0	10.8	11.3	12.7	17.9	17.2
Sugarcane	"	170.3	170.6	186.1	196.7	204.6	210.4
Cotton*	Lakh bales	85.1 (101.5)	87.3 (107.0)	69.1 (95.0)	63.8 (90.0)	86.9 (106.0)	114.9 (127.5)
Jute and Mesta*	"	77.9	126.5	86.2	67.8	77.0	83.5

\*Bales of 170 kg. for cotton and 180 kg. for jute and mesta.

Note : Figures within brackets are as estimated by the Cotton Advisory Board.

Source : Ministry of Agriculture.

3.13 In view of a bumper crop of cotton, the Cotton Corporation of India (CCI), and the Government of Maharashtra under the Maharashtra State Monopoly Procurement Scheme (MSMPS), undertook large purchases to avoid distress sale by farmers. CCI purchased 12.3 lakh bales of cotton up to the end of June 1990 as against 5.7 lakh bales in the corresponding period of the previous year. Under MSMPS, cotton procurement aggregated 20.5 lakh bales up to the end of June 1990 as against 11.8 lakh bales in the comparable period of the previous year. These two agencies together purchased over one-fourth of the cotton crop of the year. Allotments of cotton for exports were raised to a record level of 13.85 lakh bales to avoid a precipitous fall in domestic prices. The jute crop is also estimated higher in 1989-90 than in 1988-89 but the tight supply-demand position continued due to low stock carry-over. Thus, jute prices rose steeply despite the Government's permission to allow imports of raw jute from Bangladesh to augment domestic supplies. Widespread speculation resulting in high prices necessitated vigorous monitoring of prices by authorities entailing dehoarding operations, banning forward trading in jute, imposition of stock limits, etc. Production of sugar is expected to reach an all-time high, exceeding 108 lakh tonnes during the 1989-90 sugar season. The rapidly rising domestic consumption has, however, given rise to tight supply-demand position.

#### Supply-Demand Balance

3.14 The second good agricultural crop in succession helped in restoring a degree of supply-demand balance in respect of foodgrains. A redeeming aspect in this regard has been the gradual rebuilding of foodstocks with the public agencies during recent months. Rice stocks, which had been depleted from 10.0 million tonnes at the end of March 1987 to 4.7 million tonnes at the end of March 1989, were rebuilt to 7.9 million tonnes at the end of March 1990. With the large procurement of wheat in Rabi 1990, wheat stocks at the end of June 1990 have exceeded 13.0 million tonnes. Total foodgrains stocks at the end of June 1990 stood at 20.3 million tonnes, almost reaching the norm of 21.0 million tonnes stipulated for this point of time of the year. Despite higher output, the supply-demand gap in pulses has necessitated imports of 8.27 lakh tonnes in 1988-89, and in the absence of any major breakthrough in production, the same order of imports was maintained in 1989-90. The bountiful supplies of cotton in the wake of a bumper crop called for higher exports. In the case of sugar, jute and tea, there were considerable demand pressures. In the case of edible oils, the position worsened further mainly owing to a short crop in Gujarat which created a supply gap of about 10 lakh tonnes. According to official estimates, the demand projection for the edible oil year 1989-90 has been placed at 57.7 lakh tonnes and the total availability from internal sources at 47.2 lakh tonnes thus showing a supply gap of about 20 per cent. Edible oil imports of as much as 19.67 lakh tonnes in 1987-88 and 11.66 lakh tonnes in 1988-89 contributed to sizeable foreign exchange outgo in those years. With the thrust programmes for oilseeds and remunerative support prices for oilseeds, domestic availabilities are expected to show an increase.

#### Other Policy Developments

3.15 There have been certain important policy initiatives on agriculture and rural development during the year under review. First, the Government has decided to ensure that half of the public sector investible resources are deployed for agriculture and rural development, particularly for enhancing employment opportunities in rural areas. Secondly, it has been decided to provide relief up to a limit of Rs. 10,000 to farmers and rural artisans in respect of their loan overdues to banks and cooperatives under a scheme of loan waiver announced in the Union Budget for 1990-91. The higher procurement prices announced recently are expected to give a boost to production of agricultural commodities. Agricultural Policy Resolution, which is on the anvil, provides for a long-term basic policy thrust to agriculture. A constitutional amendment to bring land reforms into the Ninth Schedule with a view to giving further impetus to agricultural growth through purposeful institutional changes has also been contemplated. An intensive programme to increase employment particularly in rural areas has been envisaged in the Approach to the Fifth Five Year Plan. An Employment Guarantee Scheme in drought-prone areas and areas with acute problem of unemployment is to be initiated in 1990-91

as part of an overall Employment Guarantee Scheme being formulated by the Government. Anti-poverty programmes are to be strengthened. A concerted effort to increase production in rainfed areas which will benefit vast sections of rural society also forms the core of the new policy. These measures seek to improve the rural infrastructure, offer higher incentives to farmers, raise incomes of farmers and agricultural labourers, and along with the application of modern technology, are expected to bring about a significant growth in Indian agriculture.

#### 4 TRENDS IN INDUSTRIAL PRODUCTION

4.1 During the fiscal year 1989-90, the growth rate in industrial production experienced distinct deceleration for the major part of the year, mainly on account of sluggish growth in the manufacturing sector. There was, however, a perceptible turn around in manufacturing output in the last quarter, particularly in the last month (March 1990). Simultaneously, the mining and quarrying sector, which was growing generally at an accelerated rate during the first three quarters, slackened considerably during the last quarter, thus resulting in a sharply reduced growth rate over the year. Electricity generation, however, maintained an accelerated pace of growth throughout 1989-90. As a result of these factors, over the year 1989-90, the general index of industrial production (base: 1980-81=100) showed a sizeable growth of 8.3 per cent which compares with 8.7 per cent growth in 1988-89. The use-based classification of industries reveals a sharp deceleration in the rates of growth of basic goods, intermediate goods and consumer durable goods industries, while capital goods and consumer non-durable goods industries experienced acceleration in their growth rates. The infrastructure industries as a group also experienced a reduction in the growth rate during 1989-90 as a whole. The pace of expansion in electricity generation remained higher almost throughout the year.

4.2 Although the year 1989-90 saw a marginal deceleration in the growth rate, the average growth for the Seventh Plan period (1985-86 to 1989-90) works out to 8.4 per cent, which is somewhat higher than the Plan target of 8 per cent. This satisfactory performance is essentially attributable to the manufacturing sector which has a large weightage in the general index and which surpassed the Plan growth target; within the manufacturing sector, however, certain crucial sectors experienced significant shortfalls in relation to Plan targets. The other major sectors, viz., mining and quarrying and electricity, lagged behind rather significantly.

#### Overall Trends

4.3 During the financial year 1989-90 (April—March), the average of the monthly index of industrial production (base: 1980-81=100) registered a slight deceleration in the growth rate to 8.3 per cent from 8.7 per cent achieved in 1988-89. This slight slow-down in industrial growth was on account of reductions in the growth of manufacturing output from 8.7 per cent to 8.3 per cent and in mining and quarrying from 7.9 per cent to 5.9 per cent; the growth in electricity output, however, showed an acceleration from 9.5 per cent to 10.7 per cent (Table 4.1).

#### Quarterly Trends

4.4 The fiscal year 1989-90 began with a conspicuous dip in the growth rate of the general index essentially because of a sharp drop in the growth of manufacturing output. To an extent, this decline could be attributable to the change to a uniform accounting year (April—March) for the corporate sector and the comparatively high base in the first

Table 4.1 : Trends in Index of Industrial Production

(Base : 1980-81 = 100)

Year	Sector	Mining and Quarrying		Manufacturing		Electricity		General Index	
		11.46		77.11		11.43		100.00	
		Index	Growth Rate (per cent)	Index	Growth Rate (per cent)	Index	Growth Rate (per cent)	Index	Growth Rate (per cent)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Annual Average Growth Rates</b>									
1970-71 to 1980-81 @		—	4.3	—	+4.0	—	+7.3	—	+4.4
1980-81 to 1984-85		—	+12.6	—	+5.7	—	+8.9	—	+7.0
1980-81 to 1989-90		—	+8.7	—	+7.4	—	+9.1	—	+7.8
<b>Annual Growth Rates</b>									
1985-86		167.5	+4.2	136.9	+9.7	152.4	+8.5	142.1	+8.7
1986-87		177.9	+6.2	149.7	+9.3	168.1	+10.3	155.1	+9.1
1987-88		184.6	+3.8	161.5	+7.9	181.0	+7.7	166.4	+7.3
1988-89		199.1	+7.9	175.6	+8.7	198.2	+9.5	180.9	+8.7
1989-90		210.9	+5.9	190.2	+8.3	219.4	+10.7	195.9	+8.3
<b>Average Growth Rate for the Seventh Plan Period (1985-86 to 1989-90)</b>									
Actuals			+5.6		+8.8		+9.3		+8.4
Plan Target			+13.0		+8.0		+12.0		+8.0

@Based on 1970 series of index numbers

previous year when the manufacturing index grew by as much as 13.4 per cent (Table 4.2). A number of industries like saleable steel, fertilizers, cement, steel ingots, steel castings, transmission towers, structurals and aluminium sheets and circles, registered negative or deceleration in growth rates during the first quarter (April-June). The growth rate in the overall index of industrial production picked up from 2.4 per cent in the first quarter to 6.3 per cent in the second quarter and accelerated to 8.3 per cent and 15.2 per cent respectively, in the subsequent two quarters. This surge in industrial output from the second quarter onwards was essentially due to a

substantial pick-up in the growth rate of manufacturing output. The growth rate of mining and quarrying sector fell from over 10.0 per cent in the first two quarters to 3.3 per cent in the third quarter and 1.2 per cent in the last quarter of the year, this deceleration is largely attributable to the difficulties faced by the coal industry. This steady deterioration is also reflected in the month-by-month variations in output—point-to-point as well as cumulative (Table 4.3). The rate of expansion in the generation of electricity which was sustained at high levels in the first three quarters, slowed down somewhat in the last quarter.

Table 4.2 : Trends in Index Numbers of Industrial Production—Quarterly Basis

(Base 1980-81 = 100)

(Provisional)

Quarter	Mining & Quarrying		Manufacturing		Electricity		General	
	1988-89	1989-90	1988-89	1989-90	1988-89	1989-90	1988-89	1989-90
April—June	182.2 (+6.2)	201.5 (+10.6)	170.4 (+13.4)	170.3 (—0.1)	190.7 (+10.4)	207.8 (+9.0)	174.1 (+12.1)	178.2 (+2.4)
July—September	175.3 (+5.0)	193.3 (+10.3)	167.1 (+6.9)	174.5 (+4.4)	186.1 (+1.9)	213.0 (+14.5)	170.2 (+6.0)	181.0 (+6.3)
October—December	207.1 (+9.3)	214.0 (+3.3)	176.8 (+9.4)	191.8 (+8.5)	203.5 (+13.4)	229.1 (+12.6)	183.4 (+10.0)	198.7 (+8.3)
January—March	231.9 (+10.2)	234.7 (+1.2)	188.1 (+5.7)	224.0 (+19.1)	212.3 (+12.3)	227.7 (+7.3)	195.9 (+7.1)	225.6 (+15.2)

Note : Figures in brackets are percentage variations over the corresponding preceding period.

## Use-based Classification

4.5 The pattern of industrial growth during 1989-90 was significantly different from that in the previous year, or generally, from the previous eight years (1980-81 to 1988-89) when the tempo of industrial growth witnessed a distinct acceleration over the growth rate in the decade of the 1970s. This is depicted in the group-wise growth rates of industrial production based on use-based classification of industries (Table 4.4). First, the consumer durable goods industries, which exhibited on an average an uninterrupted high annual growth ranging from 8 per cent to 22 per cent for

the past eight years, faced a precipitate fall in their growth rate to 1.9 per cent during 1989-90 due to constraints of consumer demand. The consumer non-durables sector experienced increase in growth to 6.1 per cent from 5.1 per cent during the previous year. As compared with the depressed performance in 1988-89 due to reduced supplies of agricultural raw materials following the drought of the previous year, the growth of 6.1 per cent in the output of non-durable consumer goods in 1989-90 was a significant improvement which in turn was linked to improved availabilities of certain raw materials. Secondly, substantial deceleration occurred in 1989-90 as compared with the preceding year



[भाग 11-खंड 3(ii)]

भारत का राजपद : फरवरी ७, १९७१/मार्च २०, १९७२

\*Percentage variation on a point-to-point basis over the previous year.

767

quarter of the as well as with the performance in the previous eight-year period, in basic industries and intermediate goods industries. This is attributable to adverse supply-side factors faced by such important industries as coal mining, steel and steel-based products, aluminium, fertilizers, petrochemicals and some chemical-based industries, and jute manufactures. Capital goods industries, which have generally faced stiff competition from imported goods in recent years due to liberalised import policy, have experienced as a group further acceleration during 1989-90 and thus sustained the group's high growth profile. Within this sector, however, the picture was a mixed one, with some showing sizeable growth in output and some others equally sizeable absolute declines; these developments were largely determined by developments in their respective user industries. With improved rainfall, demand for diesel engines and power-driven pumps experienced a slow-down while the same factor produced increased demand for agricultural tractors and sugar mill machinery, resulting in their higher production. With the improved tempo of power generation, a number of electrical machinery items such as power transformers, AAC/ACSR conductors, winding wires, electric generators and power capacitors showed improved performance. Paper and pulp machinery industry experienced a decline in output as its user industries experienced a slow-down in investment activities.

#### Manufacturing Sector

4.6 As compared with an average growth in the first four years of the Seventh Plan at 8.9 per cent, the sector's output growth slowed down to 8.3 per cent during 1989-90 (April—March). An insight into the performance of the manufacturing sector could be had from the group-wise data available for 17 major groups of industries based on their two-digit level classification for the financial year 1989-90 (Table 4.5).

4.7 Of the 17 major industrial groups, as many as eleven accounting for 51.44 percentage points out of 77.11 percentage points weightage, experienced either a visible deceleration or a decline. Jute textiles and basic metals and alloy products suffered declines. Amongst the important industrial groups to experience deceleration in output are: chemical and chemical products, non-metallic mineral products (including cement), textile products, machinery and machine tools, food products, and transport equipment. Of the transport equipment items, railway wagons suffered deceleration in output, while jeeps, two and three-wheelers, and cars experienced increases. Textile products, which grew at phenomenal rates in the past few years, showed some deceleration in growth rate during 1989-90. Even amongst the industries which experienced acceleration in output growth during 1989-90, electrical machinery is the only one group showing an impressive growth rate of 31.6 per cent due to a general

Table 4.4 : Growth Rate of Industrial Production—Use-based Classification

Industry Group	All Industries			Selected 155 Industries*			
	Weight	Annual Average Percentage Growth		Number of Industries	Weight	Percentage change during April—March	
		1981-82	1985-86			1988-89	1989-90
		to 1984-85	to 1988-89				
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Basic Goods	39.42	+8.8	+8.9	40	36.36	+9.8	+5.0
II. Capital Goods	16.42	+6.3	13.0	32	11.32	+8.7	+24.9
III. Intermediate Goods	20.51	+6.1	+7.1	36	16.10	+12.2	+3.1
IV. Consumer Goods	23.65	+5.3	+8.0	47	21.76	+7.2	+5.4
(a) Consumer Durables	2.55	+14.4	+16.9	12	2.20	+19.2	+1.9
(b) Consumer Non-Durable	21.10	+4.0	+6.3	35	19.56	+5.1	+6.1
General Index	100.00	+7.0	+8.5	155	85.54	+9.5@	+8.3@

\*Provisional production data relating to 155 industries with a total weight of 85.5 per cent in the General Index of Industrial Production (1980-81=100)

@Variations in the composite index of 155 industries.

improvement in the power sector. A turnaround in cotton textiles output following improved supplies of raw cotton was reflected in a 3.3 per cent increase in contrast to a 3.2 per cent fall in the previous year. While cotton yarn and cloth output in the decentralised sector experienced some improvement, cloth output in the mill sector continued to yield ground to the powerloom sector, reflecting the growing phenomenon of sub-contracting observed in recent years.

#### Infrastructure Industries.

4.8 The performance of infrastructure industries during 1989-90 (April—March) generally reflected the slow-down in industrial growth. The average composite index of the six infrastructure industries, viz., electricity, coal (excluding lignite), petroleum crude, petroleum refinery products, saleable

steel and cement (together accounting for a weight of 28.77 per cent in the general index), recorded a reduction in growth rate to 6.2 per cent from 8.2 per cent in the preceding year (Table 4.6). Of the six infrastructure industries, all except petroleum refinery products recorded shortfalls in growth in comparison to their programmed annual targets. Though electricity generation showed an increase in growth rate, it still fell short of the target of 13.6 per cent increase for the full financial year 1989-90. Amongst the infrastructure industries, the performance of the electricity sector was by far the best with a growth in generation of the order of 10.8 per cent as against 9.5 per cent in 1988-89. The accelerated growth in the power sector followed the attainment of improved plant load factors (PLF) by Central and private power generating

Table 4-5 : Growth Rate in Index Numbers of Industrial Production of Major Group (Base 1980-81 = 100)

Items	Weight	April—March		
		1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5
<b>I. POSITIVE GROWTH</b>				
<b>(a) Acceleration</b>				
1. Beverages Tobacco, etc.	1.57	84.9 (—13.8)	92.1 (+8.5)	103.0 (+11.8)
2. Paper and Paper Products	3.23	166.2 (+1.9)	171.3 (+3.0)	181.5 (+6.0)
3. Electrical Machinery	5.78	335.2 (+31.6)	348.6 (+4.0)	458.9 (+31.6)
4. Metal Products	2.29	129.6 (+4.2)	133.5 (+3.0)	142.6 (+6.8)
5. Cotton Textiles	12.31	111.2 (—1.2)	107.6 (—3.2)	111.2 (+3.3)
6. Leather and Leather Products	0.49	185.5 (+4.4)	177.4 (—4.4)	188.2 (+6.1)
	26.67			
<b>(b) Deceleration</b>				
7. Food Products	5.33	139.0 (+4.4)	148.3 (—6.7)	150.9 (+1.8)
8. Textile Products	0.82	91.8 (+5.4)	134.2 (+46.2)	150.6 (+12.2)
9. Wood and Wood Products	0.45	161.7 (—34.3)	171.7 (+6.2)	175.8 (+2.4)
10. Rubber, Plastic and Petroleum Products	4.00	155.1 (+3.7)	168.2 (+8.4)	173.4 (+3.1)
11. Chemicals and Chemical Products	12.51	200.9 (+14.5)	233.4 (+16.2)	247.2 (+5.9)
12. Non-metallic Mineral Products	3.00	158.1 (—1.4)	184.6 (+16.8)	180.9 (+2.3)
13. Machinery and Machine Tools	6.24	139.2 (—1.8)	160.5 (+15.3)	170.1 (+6.0)
14. Transport Equipment	6.39	151.8 (+4.8)	172.0 (+13.3)	180.4 (+4.9)
15. Miscellaneous	0.90	272.1 (+15.6)	304.6 (+11.9)	334.4 (+9.8)
	39.64			
<b>II. NEGATIVE GROWTH</b>				
16. Jute Textiles	2.00	91.0 (—10.0)	101.9 (+12.0)	96.9 (—4.9)
17. Basic Metal and Alloy Products	9.80	135.6 (+6.9)	144.9 (+6.9)	143.7 (—0.8)
	11.80			
Manufacturing	77.11	161.5 (+7.9)	175.6 (+8.7)	190.2 (+8.3)

Table 4.6 : Trends in Production of Infrastructure Industries

Industry	Unit	Weight	April—March		
			1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6
Electricity	Million KWH	11.43	201894 (+ 7.6)	221125 (+ 9.5)	244971 (+ 10.8)
Coal	Million Tonnes	6.61	179.74 (+ 8.5)	194.57 (+ 8.3)	200.85 (+ 3.2)
Saleable Steel	Thousand Tonnes	5.21	8588.0 (+ 4.5)	9206.0 (+ 7.2)	9028.7 (- 1.9)
Crude Petroleum	-do-	2.41	30357 (- 0.4)	32040 (+ 5.5)	34076 (+ 6.4)
Petroleum Refinery Products	-do-	1.52	44407 (+ 2.7)	45384 (+ 2.2)	48300 (+ 6.4)
Cement	-do-	1.60	39550 (+ 8.1)	44295 (+ 12.0)	45603 (+ 3.0)
Composite Index of Infrastructure Production (1980-81=100)		28.77	178.6 (+ 6.0)	193.2 (+ 8.2)	205.1 (+ 6.2)

Note : Figures in brackets indicate percentage variations over the corresponding figures of the previous year.

units despite slippages in the programmed PLF targets in the case of State Electricity Boards. Moreover satisfactory hydel power generation also augmented the supply position. Acceleration in the growth of output of petroleum crude (6.4 per cent as against 5.5 per cent) and petroleum refinery products (6.4 per cent as against 2.2 per cent) during 1989-90 is also noteworthy. The higher growth in the output of petroleum crude was assisted mainly by the on-shore, oilfields of ONGC and the Oil India Ltd. with the ONGC's off-shore production making a marginal contribution to the increase as in previous year. On the whole, the total crude oil output placed at 34.1 million tonnes in 1989-90 was close to the production target of 34.3 million tonnes. With the improved performance of capacity utilization of the refineries from 96.4 per cent in 1988-89 to 97.1 per cent in 1989-90 following higher domestic crude output, the target for the production of POL products at 47.38 million tonnes was surpassed by about 2 per cent (actual production being 48.3 million tonnes). The growth of output of coal and cement decelerated to 3.2 per cent and 3.0 per cent from 8.3 per cent and 12.0 per cent respectively, in 1988-89. The poor performance of coalfields resulted mainly from breakdown of machinery, poor industrial relations and absenteeism. As against a target of 209.5 million tonnes, the actual coal output in 1989-90 stood at 201 million tonnes. The gap between demand and domestic output is placed at 12.5 million tonnes which will be partly met by the import of 4.5 million tonnes of coking coal. The fall of 1.9 per cent in saleable steel against an increase of 7.2 per cent in 1988-89 was attributable to power shortages during some parts of the year and shortages of imported metallurgical-grade coking coal. Cement output has apparently reached a plateau due to stagnating levels of plant operations following weak domestic demand coupled with the existence of stock carry-over from the previous year. As it is, the production of cement at 45.6 million tonnes in 1989-90 corresponded to the prevailing domestic demand and hence a stage of self-sufficiency has been reached.

#### Industrywise Profile

4.9 Industry-wise data available for the full fiscal year period 1989-90 show that among the selected 155 industries, 108 industries with a total weight of 64.1 per cent in the index of industrial production showed positive growth during 1989-1990. In the previous year, there were 119 industries with a weight of 68.8 per cent showing positive growth. Industries showing growth in the low range of 0 to 5 per cent carried a weight of 20.7 per cent as against such industries constituting 13.5 percentage weight in the previous year again, industries showing growth in the higher range of 5 to 10 per cent carried only a weightage of 22.0 per cent in 1989-90 against 32.3 per cent in the previous year (Table 4.7).

4.10 An analysis of the performance of individual industries during 1989-90 shows that within the agro-based

industries, important consumer items such as, vanaspati and mill sector cloth, registered declines of around per cent each. A reduction in the output of sugar to the extent of about 1.4 per cent during 1989-90 (April-March) can be attributed mainly to the diversion of sugarcane for the production of khandsari and gur, lower sucrose yield of cane was also a contributory factor. The decline in the output of mill sector cotton cloth being 5.7 per cent following a much higher decline of 7.2 per cent last year is the result not only of increasing competition from the decentralised sector (powerloom) but also because of the increasing incidence of sickness among the mills in the organised sector. The decline in the output of vanaspati by about 5.7 per cent against an increase of 1.6 per cent is perhaps the result of restrictions on the use of expeller mustard oil for vanaspati production and the industry's inability to substitute non-traditional oils. The output of tea increased by 6.7 per cent in 1989-90 to 723.7 million kgs. despite adverse weather conditions affecting tea output in Southern India.

Table 4.7 : Frequency Distribution of 155 Industries by Growth Rates During 1988-89 and 1989-90

Range of Growth	April 1988—March 1989		April 1989—March 1990	
	Weight	Number of Industries	Weight	Number of Industries
1	2	3	4	5
Positive				
Over 25%	9.2	36	2.6	12
25% to 10%	13.8	32	18.8	35
10% to 5%	32.3	30	22.0	26
5% to 0%	13.5	21	20.7	35
Sub-Total	68.8	119	64.1	108
Negative				
0% to 5%	9.2	15	11.0	25
-5% to -10%	3.6	5	6.5	0
-10% to -25%	2.8	12	2.2	
Below -25%	1.1	4	1.3	8
Sub-Total	16.7	36	21.0	51
Total	85.5	155	85.5	155

4.11 Among the chemical-based industries, a sharp decline of about 20.3 per cent was registered in case of phosphate fertilizers owing to shortfalls in the imports of phosphoric acid. Nitrogenous fertilizers, however, registered a lower growth rate of 0.8 per cent as against a much higher increase of 22.8 per cent during the preceding year. Among synthetic yarns, production of both viscose and polyester yarns registered declines of 3.7 per cent and 5.7 per cent as against impressive increase of 21.1 per cent and 43.3 per cent, respectively, during the previous year, owing to the weakening of demand. Among staple fibres viscose and polyester staple fibre production recorded, following better export demand, sizeable growth at 17.1 per cent and 11.7 per cent as against 6.8 per cent and 35.6 per cent, respectively, during the preceding year.

4.12. In the metal-based industries, the automobile sector during 1989-90 registered an all-round growth. Output of commercial vehicles increased by 3.2 per cent as compared with 2.2 per cent in 1988-89 on account of higher demand. While output of cars increased by 12.2 per cent (against 16.4 per cent in the previous year) that of autorickshaws decelerated to 4.1 per cent from 29.3 per cent last year. The production of jeeps increased at a lower rate of 21.4 per cent against a rise of 59.3 per cent last year. The output of two-wheelers as a group (including scooters, motorcycles, scooterettes and mopeds) marginally decelerated to 4.6 per cent from 4.8 per cent mainly on account of deceleration registered in the growth of output of motorcycles. The growth in the output of railway wagons decelerated to 4.1 per cent in 1989-90 from 35.4 per cent 1988-89.

#### A Brief Comparison with the Plan Targets

4.13 Four years out of five of the Seventh Plan period experienced higher rates of industrial growth than the rate of 8.0 per cent per annum visualised in the Plan. As a result, the average growth for the Plan period works out to a shade higher at 8.4 per cent per annum. This has been made possible by higher growth than the target (8.8 per cent against 8.0 per cent) in manufacturing which has a large weight of 77.11 per cent in the general index (Table 4.1). The performance of both mining and quarrying and electricity sectors lagged behind the Seventh Plan targets rather significantly. Against the Seventh Plan target of 226 million tonnes, the actual coal output in 1989-90 was 201 million tonnes—a shortfall of 11 per cent. In electricity generation the actual output was 245 billion kwh against an original target of 295.4 billion kwh and revised target of 278 billion kwh a shortfall of 17 per cent with respect to original target and 12 per cent with respect to the revised target. In the petroleum sector, actual production of petroleum refinery products has outstripped the Plan target while output of crude petroleum marginally fell short of the target.

4.14 In the manufacturing sector, too, there are certain crucial shortfalls, the most conspicuous ones being in basic metals other than steel, such as, aluminium, copper, zinc and lead. Similarly, substantial shortfalls are noticed in major electrical machinery like power transformers and electric motors. In the automobile sector, there was about a 22 per cent shortfall over the Seventh Plan target in the production of commercial vehicles, though the installed capacity is substantially higher than the production level. Output of passenger cars, two-wheelers, and viscose and polyester yarns and fibres were substantially above the Plan targets.

#### Employment in the Organised Sector

4.15 The sluggishness in the growth of employment has been an area of concern. Acceleration in industrial output in the 1980s has not been matched by a corresponding growth in employment. The employment elasticity with respect to aggregate output appears to be declining. Total employment in the organised private sector was 72.27 lakh at the end of March 1980. It reached a peak level of 75.52 lakh at the end of March 1983 and thereafter it has consistently remained below that level, with the latest data for March 1989 placing it at 74.78 lakh. Within the private sector, the fall in employment in the organised manufacturing sector has been much more conspicuous. From a peak of 46.61 lakh at the end of March 1982, it fell to 43.95 lakh at the end of March 1988 thus showing an absolute fall of 5.7 per cent over a period of six years. There was a further fall to 42.83 lakh by June 1988. Employment in the public sector has, how-

ever, been steadily rising in the 1980s; it rose from 133.22 lakh in March 1976 to 168.69 lakh in March 1984 and further to 185.05 lakh in March 1989.

4.16 According to quick estimates made by the Union Government total employment in the organised sector stood at 260.3 lakh as at end-March 1989 and showed an increase of 1.1 per cent over the employment figure of end-March 1988. Both the sectors, public and private are reported to have contributed to the increase by 1.3 per cent and 0.7 per cent, respectively.

4.17 The number of job seekers on the Live Register of Employment Exchanges was 324.47 lakh at the end of November 1989 showing a rise of 8.4 per cent over the end of October 1988. Vacancies notified through the Employment Exchanges have been experiencing a consistent decline from a monthly average of 69.6 thousand in 1980-81 to 54.2 thousand in 1985-86 and finally to 44.8 thousand in 1988-89. Likewise, the placements effected fell from a monthly average of 38.3 to 31.3 and further to 25.7 thousand respectively, which despite various limitations of these data, confirm that employment absorption in organised industries has slowed down significantly.

#### New Industrial Policy

4.18 The new industrial policy, announced on May 31, 1990, aims of reorienting industrial growth to subserve the objectives of employment generation, dispersal of industry in rural areas, promotion of small-scale industries generally and enhancing their contribution to exports, modernisation and upgradation of technology and achieving international competitiveness. Apart from focusing on the promotion of small-scale and agro-processing industries, the new policy provides for relaxation in procedures for industrial approvals concerning such important areas as licensing foreign collaborations and import of capital goods, raw materials and components.

4.19 For small-scale industries, the new policy provides for enhancement of investment ceilings in plant and machinery from Rs. 45 lakh to Rs. 75 lakh for ancillary units, from Rs. 35 lakh to Rs. 60 lakh for small-scale industries and from Rs. 2 lakh to Rs. 5 lakh for tiny units. The policy also contains a number of other measures for small-scale industries to widen their entrepreneurial base, upgrade technology, enlarge the scope for activity by providing for the reservation of more items (beyond the present 836 items) and checking encroachment and violation by large units into the reserved areas and reduce paper work.

4.20 In case of agro-processing industries, the new policy aims at forging closer link between growers and processors by encouraging joint ownership, dispersal of industries in rural areas, giving priority in credit allocation and promoting the generation, adaptation and adoption of new technologies in the field by speedy approval of technology imports.

4.21 Extending the measure of delicensing, all new units up to an investment of Rs. 25 crore in fixed assets in non-backward areas and Rs. 75 crore in Centrally-notified backward areas have been exempted from the requirement of obtaining licence/registration. Export-oriented units set up in export-processing zones have been delicensed upto an investment limit of Rs. 75 crore. Such investments shall be exempted from 'convertibility clause' applicable to financing by Indian financial institutions. Exemption from obtaining any clearance from the Government for foreign collaboration, if royalty payment does not exceed 5 per cent on domestic sales and 8 per cent on exports, has been provided and even where lump sum payment is involved requiring Government clearance, the decision would be communicated to the entrepreneur within a period of 30 days. To attract effective inflow of technology, foreign investment up to 40 per cent of equity would be allowed on an automatic basis in specified industries. The deregulations suggested would cover all cases of expansion and would not be restricted to new units. Further, the existing broad-banding scheme would continue to be in force.

## 5. DEVELOPMENTS IN CREDIT POLICY

## Policy Contours

5.1 An overriding consideration in the conduct of monetary policy during the period July 1989 to June 1990 was the containment of inflationary pressures without jeopardising the growth potential of the economy. The heightened concern for price stability arose from a number of macro-economic developments. Despite two successive good agricultural crops and satisfactory real income growth, inflationary pressures continued to remain strong. Apart from the sectoral pressures on several goods of common consumption such as, cereals, pulses, tea, sugar, oilseeds and edible oils; and milk and milk products; the inflationary pressures were getting generalised. Furthermore, with the large draw-down of foodgrains stock and foreign exchange reserves, the cushion for augmenting domestic supplies of critical goods was getting substantially depleted. Concurrently, on the demand side (on top of the overhang of large liquidity without which such persistent inflation over a long period could not have been sustained) the fiscal deficit of the Central Government widened very sharply, to a historical high, leading to excessively high primary money growth as well as growth in over all liquidity.

5.2 The above scenario of rapid growth of liquidity, originating in fiscal deficit, was aggravated by the fact that the traditional instrument of liquidity control in the armoury of the Reserve Bank, viz., the cash reserve ratio, had reached the statutory ceiling.

5.3 There was a large expansion of non-food credit by scheduled commercial banks during the first half of the year on top of the very large growth in such credit during the fiscal year 1988-89. It was perceived that the extend of additional credit support required in 1989-90 was not as large as that extended in the previous year. Industrial growth had showed down during the major part of 1989-90 and increased recourse to the capital market and other sources of non-banking funds, especially by large-sized companies, would reduce the demand for bank credit. Against such a background, the stance of credit policy had to be clearly one of restraint on the pace of expansion of non-food credit. As the traditional instruments of monetary control could not be used because of the statutory ceiling on the cash reserve ratio, reliance was placed on other measures to moderate the pace of growth of reserve money. These measures included a reduction in access to the export refinance facility, increase in the statutory liquidity ratio and the stipulation of an incremental non-food credit-deposit ratio. The measure introduced in 1989-90 was qualitatively different from the guidelines on overall credit which were in vogue till 1981-82 as any increase in credit over the stipulated level entailed additional cost on the refinance obtained from the Reserve Bank. It was perceived that with the large reserve money growth there would be a substantial expansion in bank deposits. While credit requirement for genuine productive purposes would be met, it was the over-extension of credit, beyond the resource capabilities of scheduled commercial banks that was sought to be curbed. What was stipulated was that the cost of refinance from the Reserve Bank would go up in the event of a bank exceeding the incremental non-food credit-deposit ratio of 60 per cent. Thus, this measure operated on the cost of refinance linked to the credit expansion of a bank. The measures relating to the export refinance facility were essentially to moderate the use of such refinance which had reached very high levels. The upward revision in the statutory liquidity ratio (SLR) was also intended to moderate the pace of reserve money creation.

5.4 The other policy measures undertaken during the year could be broadly categorised under three heads; first, those measures which aim at imparting greater discipline and prudence in the banks' operations; second, those which seek to carry forward the several measures already put in place with a view to introducing greater flexibility and reducing rigidities, and in general promoting a more competitive environment in the money and financial markets; and third, measures in response to price and output developments relating to sensitive commodities wherein more frequent modifications of minimum margins and credit ceilings on bank advances

against sensitive commodities have been effected. In the first category of measures are additional charge imposed if banks lend in the call money market when on any day they have a borrowed position with the Reserve Bank under standby or discretionary refinance facilities, shut-out period prescribed for discretionary refinance facility to ensure that monetary aggregates are not disorted at the end of March insistence on strict observance of instructions regarding the use of the bill mechanism in relation to credit purchases and credit sales so as to inculcate the bill culture, particularly in the context of the Government having granted remission of stamp duty on such usance bills the downward revision of interest paid on cash balances with the Reserve Bank beyond 3 per cent of DTL along with revisions in the scheme of graduated penalties for shortfalls in the CRR, and the increase in interest rate on 182 Days Treasury Bill refinance. In the second category are a series of measures conferring greater freedom to the banks in their operations such as the extension of the measure of flexibility to interest rates on term loans charged by banks, the raising of the short-term deposit rate such that all domestic fixed deposits for 46 days and above but less than one year will carry 8.0 per cent of interest and similar rationalisation of interest rate for NRE deposits fixed at 8.5 per cent, increase in the number of participants as lenders in the call/notice money market and liberalisation of the guidelines for the issuance of Certificates of Deposit (CDs) and Commercial Paper (CP) with a view to broad-basing the primary market and also providing a fillip to the development of secondary markets for these instruments.

5.5 The details of the credit policy measures taken during the period are given below in chronological order.

## July 1989

Selective Credit Controls on Advances Against Wheat, Sugar, Gur and Khandsari

5.6 On a review of price-output developments, the following modifications were made in the provisions relating to selective credit controls effective July 20, 1989: (i) The minimum margins on advances against stocks of wheat were lowered across-the-board by 15 percentage points; (ii) The minimum margins on advances against stocks of sugar for processing units/mills were raised by 7.5 percentage points in the case of unreleased stocks while the minimum margins —on released stocks of sugar were raised across-the-board by 15 percentage points. The minimum margins on advances against stocks of gur and khandsari were also raised across-the-board by 15 percentage points.

## October 1989

## Measures for the Second Half of 1989-90

5.7 It was perceived that despite favourable developments in the real sector, the upsurge in prices was a matter of concern. Thus, against the backdrop of strong inflationary pressures and the large monetary expansion in the first half of 1989-90, the stance of credit policy for the second half of 1989-90 had necessarily to be one of restraint. In particular there was an urgent need for moderating the pace of expansion of non-food credit in the second half of 1989-90. It was in this context that the policy measures enumerated below were announced in October 1989.

## (a) Export Credit Refinance

5.8 Export credit refinance limits as on September 22, 1989 amounted to Rs. 3,770 crore or 52 per cent of outstanding export credit. Considering the overall monetary and credit situation and the need to curtail the growth of reserve money, it was felt necessary to reduce the very large refinance limits. Accordingly, with effect from November 4, 1989, banks were provided export credit refinance equivalent to 75 per cent of the increase in export credit over the monthly average for 1987 instead of 100 per cent hitherto.

## (b) Incremental Net Non-food Credit-Deposit Ratio

5.9 It had been observed in 1988-89 that the incremental net non-food credit-deposit ratio of a number of banks was much higher than what could be supported by their own resources. In the context of the prevailing monetary and credit situation, it was felt necessary to moderate the non-food credit expansion of banks. It was, therefore, stipulated

that each bank should ensure that during the fiscal year 1989-90 its incremental net non-food credit-deposit ratio did not exceed 60 per cent. Banks which exceeded this ratio were charged additional interest of 3 percentage points on the refinance drawn from the Reserve Bank of India under all facilities (export credit, standby, discretionary and 182 Days Treasury Bill) to the extent of the excess net non-food bank credit over the stipulated ratio or the refinance drawn, whichever was lower. This charge was imposed with effect from the fortnight beginning November 4, 1989. The incremental net non-food credit-deposit ratio was worked out each fortnight with reference to March 24, 1989 as the base and the additional charge where applicable, was imposed on a fortnightly basis.

5.10 Given the cash reserve requirement of 15 per cent and the statutory liquidity ratio of 38 per cent, only 47 per cent of incremental deposits would be available for meeting food and non-food credit requirements. The stipulation of an incremental net non-food credit-deposit ratio of 60 per cent for 1989-90 left sufficient leeway for the banks to marshal additional resources through refinance and money marked borrowings from other sources. As the incremental net non-food credit-deposit ratio of scheduled commercial banks was 35 per cent in the first half of 1989-90 the 60 per cent stipulation for the whole of the year implied that in the second half of the year, the banking system could have an incremental net non-food credit-deposit ratio of 85 per cent. In the event, the incremental net non-food credit-deposit ratio for the banking system in 1989-90 was 57.8 per cent (Graph B); a few banks exceeded the 60 per cent stipulation and were charged a higher rate on refinance from the Reserve Bank.

#### (c) Interest Rates on Term Loans

5.11 In consonance with the measure introduced in October 1988 regarding lending rates on working capital loans provided by banks, and with a view to imparting a further measure of flexibility to the administered structure of interest rates as also promoting efficiency in the use of term loans, all term loans which carried a rate of interest of 15.0 per cent (fixed) were subjected to a minimum of 15.0 per cent without any ceiling stipulation. The changes in term loans rates of scheduled commercial banks, effective October 11, 1989, were as under:

(Per cent per annum)

Categories	Effective upto October 10, 1989	Effective from October 11, 1989
1	2	3
All other term loans	15.0 (fixed)	15.0 (minimum)
Road transport operators with 3 or more vehicles	15.0 (fixed)	15.0 (minimum)

Banks were advised to use this discretion to charge varying rates judiciously so as to ensure that interest rates charged remain within reasonable limits. The rates of interest which were below 15 per cent based on priority considerations, remained unaltered these related to term loans to agriculture, small-scale industry, road transport operators (up to 2 vehicles), wasteland development, term loans to professionals and self-employed persons belonging to scheduled castes/scheduled tribes and term loans to professionals and self-employed women and special programmes.

#### (d) Interest Rates on Term Loans for Housing

5.12 On term loans for housing of over Rs. 1 lakh, an interest rate range of 14.5 to 16.0 per cent was prescribed till March 1989 and according to stipulations banks could not give such loans for amounts exceeding Rs. 3 lakh to individuals. Recognising that the thrust for financing smaller houses must continue and also that there might be genuine cases for granting loans of over Rs. 3 lakh to individuals, the aforesaid ceiling of Rs. 3 lakh was withdrawn. Simultaneously, as it was felt appropriate to allow banks the

discretion to charge a higher interest rate on housing loans exceeding Rs. 3 lakh, such loans were made subject to a minimum interest rate of 16.0 per cent and no interest ceiling was prescribed for such advances.

#### Interest Rates on Housing Loans

Effective upto October 10, 1989		Effective from October 11, 1989	
Amount of loan	Rate of Interest (per cent per annum)	Amount of loan	Rate of interest (per cent per annum)
1	2	3	4
Above Rs. 1 lakh*	14.5-16.0	Above Rs. 1 lakh and upto Rs. 3 lakh Above Rs. 3 lakh	14.5-16.0  16.0 (minimum)

\*The maximum amount of loan to an individual was Rs. 3 lakh.

#### (e) Deposit Rates

5.13 For better alignment of the return on short-term deposits, effective October 11, 1989, the interest rate on scheduled commercial banks, term deposits (excluding FCNR/NRE accounts) for 46 days to 90 days was raised from 6.0 per cent to 8.0 per cent. As a result of this change, the deposit rate for 46 days and above but less than one year became 8.0 per cent.

#### (f) Refinance and Money Market Operations

5.14 Banks had been cautioned in October 1987 that they should not simultaneously draw refinance from the Reserve Bank and also lend in the money market. It was decided that effective October 21, 1989, if banks lent in the call money market (overnight call money and short notice money for periods upto and including 14 days) on any day when they also had outstanding borrowings from the Reserve Bank of India under standby and/or discretionary refinance facilities, an additional interest charge would be levied on such borrowings. The additional charge is so determined that the effective refinance rate would be 3 percentage points above the call money lending rate of the Discount and Finance House of India (DFHI). The additional charge is imposed on the amount of refinance drawn or the lending in the money market, whichever is lower. In cases of flagrant violations of the stipulation, the standby and discretionary refinance facilities would be withdrawn.

#### (g) Shut-out Period for Discretionary Refinance Facility

5.15 Banks had reported a phenomenally large increase in both deposits and credit during the year-end closing in the last week of March, 1989. To ensure that the monetary aggregates were not distorted at the end of March, it was decided that the facility to draw discretionary refinance without prior sanction from the Reserve Bank of India would not be available to scheduled commercial banks during the entire fortnight from March 24 to April 6, 1990. Banks which had outstanding borrowings under the discretionary refinance facility were required to repay any outstandings under this facility on or before March 24, 1990 and no draws were permitted without prior sanction during the period March 24 to April 6, 1990.

December 1989 Selective Credit Controls on Advances against Wheat, Cotton & Kapas and Sugar, Gur & Khandasari

5.16 On a review of price-output developments, it was considered appropriate to modify some of the provisions of

selective credit controls. Accordingly, the following measures were introduced with effect from December 30, 1989 : -

- (a) **Wheat** : The level of credit ceiling on bank advances against wheat was raised to 100 per cent from the then existing level of 85% of the peak level of credit maintained by a party in any of the three years (November—October) 1984-85, 1985-86 and 1986-87. The enhanced level of credit ceilings for advances against wheat were made applicable to all parties including roller flour mills.
- (b) **Cotton & Kapas** : The level of credit ceiling on bank advances against Cotton and Kapas was raised to 100 per cent from the then existing level of 85 per cent of the peak level of credit maintained by a party in any of the three years (November—October) 1984-85, 1985-86 and 1986-87. Furthermore, the minimum margins applicable on bank advances against stocks of cotton and kapas were lowered to 30 per cent in the case of 'others' from 45 per cent setting them uniformly at 30 per cent on advances against stocks of cotton to 'others' and against warehouse receipts covering stocks of cotton.
- (c) **Sugar, Gur & Khandsari** . The minimum margins applicable on bank advances against unreleased stocks of sugar in the case of processing units/mills were lowered, from the stipulation of 25 per cent to 20 per cent. The minimum margins applicable on all other bank advances against sugar, gur and khandsari remained unchanged.

#### April 1990 Measures for the First Half of 1990-91

5.17. The credit policy for the first half of the financial year 1990-91 was set out in April 1990 against the background of the cumulative impact on the economy of large expansion in reserve money and overall liquidity in recent years and the attendant pressures on prices. Over the five years ending 1989-90 (April-March), the annual average rate of real GDP growth was estimated at that stage at 5.6 per cent, while overall liquidity increased by 17.6 per cent. Non-food credit provided by the banking system rose by 17.4 per cent in 1989-90 and by 22.8 per cent in 1988-89. With a strong growth in deposits, despite statutory pre-emptions, the credit made available by the banking system to the commercial sector has been more than adequate. In fact, considered against the background of the growth rate in industry during the major part of the year, it was excessive.

5.18 Assuming that the 1990 monsoon would not be adverse and industrial output in 1990-91 would show some increase over the rate of growth in 1989-90, it was felt that it would be best to plan on the basis of an overall rate of growth of the economy of around 5 per cent in 1990-91. Given the large overhang of liquidity and the resurgence of inflation in 1989-90, it was necessary to bring about a sharp break in inflationary expectations. Consistent with the objective on the fiscal side, to cut back the overall budget deficit in 1990-91 to Rs. 7,206 crore as against a revised estimate of Rs. 11,750 crore in 1989-90, the objective of monetary management was to bring about a sharp reduction in the pace of overall monetary expansion (M3) in 1990-91 by about 4 percentage points below the extremely high figure of 19.4 per cent (since revised to 19.9 per cent) in 1989-90.

5.19 Scheduled commercial banks were advised to plan their credit budgets on the basis of a working estimate of aggregate deposit growth of Rs. 27,500 crore (16.6 per cent) during 1990-91. Based on the seasonal pattern of deposit growth, the increase in aggregate deposits during the first half of 1990-91 was estimated at Rs. 13,700 crore including Rs. 6,800 crore in the first quarter (April—June 1990). As the 1990 Rabi wheat crop was good, a large procurement of around 11 million tonnes was expected. It was, therefore, estimated that food credit would increase by about Rs. 1,600

crore during the quarter ended June 1990 and decline by about Rs. 700 crore in the quarter ended September 1990. The increase in non-food credit during the first half of 1990-91 was expected to be around Rs. 4,800 crore (4.9 per cent) and the increase in the quarter April-June 1990 at Rs. 2,400 crore (2.4 per cent).

5.20 The package of measures for the first half of 1990-91 were aimed at controlling the growth of liquidity and moderating credit expansion while ensuring that the genuine credit requirements of a growing economy were met.

#### Continuation of the Incremental Net Non-Food Credit-Deposit Ratio

5.21 The stipulation of an incremental net non-food credit-deposit ratio which was introduced in the second half of 1989-90 was continued in 1990-91 and the base date was brought forward to March 23, 1990. The 3 percentage point additional interest charge on refinance drawn from the Reserve Bank under all facilities in the case of banks which exceed the stipulated ratio became effective from the fortnight beginning April 21, 1990.

#### Changes in Measures

5.22 The changes in measures were as follows.

##### (a) Statutory Liquidity Ratio (SLR)

5.23 To help moderate the pace of reserve money creation and monetary expansion, from the fortnight beginning September 22 1990, the SLR will be raised by one-half of one percentage point from 38.0 per cent to 38.5 per cent of net demand and time liabilities (DTL). The statutory liquidity ratio of 25 per cent in respect of Non-Resident (External) Rupee Accounts and Foreign Currency (Non-Resident) Accounts was raised to 30 per cent from the fortnight beginning July 28, 1990. These two measures would enhance the SLR requirements by about Rs. 1,800 crore or one percentage point of net demand and time liabilities. To the extent the market borrowing programme is not altered, the increase in the SLR would operate as an effective instrument of monetary control.

##### (b) Refinance Facilities

###### (i) Export Credit Refinance

5.24 As on March 23, 1990, export credit refinance limits amounted to Rs. 3,564 crore, equivalent to 43.6 per cent of outstanding export credit. It has been the normal practice to bring forward each year the base for determining export refinance. Effective August 25, 1990, banks would be provided export credit refinance equivalent to 75 per cent of the increase in export credit over the monthly average level of export credit for the financial year 1988-89 instead of the monthly average level for the calendar year 1987. Although the banks' refinance limits would initially be reduced, the experience in the past has shown that their access to export credit refinance would be quickly recouped as they expand export credit and as such banks' refinance limits would once again rise before the busy season gets under way.

###### (ii) '182 Days Treasury Bill' Refinance

5.25 In view of the rise in the cut-off yields in the auctions for 182 Days Treasury Bills, effective April 16, 1990, the interest rate on refinance under this facility was increased from 10.75 per cent to 11.25 per cent per annum.



## (c) Selective Credit Controls

5.26 In the area of selective credit controls the following changes were made effective from April 16, 1990:

- (i) Minimum Margins Against Wheat In view of the price-output developments relating to wheat, the minimum margins on all bank advances against wheat (including advances to roller flour mills) were reduced by 15 percentage points across-the-board.
- (ii) Exemption for Advances Against Cotton and Kapas : In the context of the distinct improvement in the supply position, all advances against cotton and kapas were exempted from all the provisions of selective credit control.
- (iii) Level of Credit Ceilings : For commodities where there was a stipulation of level of credit ceilings based on the three-year period 1984-85 through 1986-87 (November-October), the base was brought forward by two years to the three year period 1986-87 through 1988-89.

## (d) Interest Rates of Deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts

5.27 In alignment with the rationalisation of the interest rates and maturities on domestic term deposits for periods under one year, the term deposit rates and maturities for Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts were also rationalised. Effective April 16, 1990, the maturity range of 15 days to 45 days was abolished and a uniform rate of 8.5 per cent was made applicable on all term deposits for maturities of 46 days to less than one year. Interest rates applicable to longer maturities remained unaltered.

## (e) Interest on Banks' Cash Balances held with the Reserve Bank

5.28 Hitherto interest was paid on all eligible cash balances held by banks with the Reserve Bank at a rate of 10.5 per cent per annum. With effect from the fortnight beginning April 21, 1990, interest is paid on a two-tier formula: (i) on the eligible cash balances based on the net DTL as of March 23, 1990, interest would be paid at the rate of 10.5 per cent per annum; (ii) on the eligible cash balances maintained on the increase in net DTL after March 23, 1990 interest would be paid at the rate of 8.0 per cent per annum. The payment of interest on cash balances attenuates monetary control which the instrument of the cash reserve ratio attempts to achieve and the reduced interest rate on the eligible cash balances would provide for a more effective CRR though the impact of this measure would be very gradual.

## (f) Amendment to the Scheme of Graduated Penalties for Shortfalls in CRR

5.29 The two-tier structure of interest rate on cash balances, introduced as above, had implications for the scheme of graduated penalties for shortfalls in the cash reserve ratio (CRR). The scheme was, therefore, amended and the key elements of the amended scheme are as follows : First, in case of a CRR shortfall, banks would not lose any interest on their eligible cash balances maintained on the increase in net DTL after March 23, 1990 provided the shortfall was not at a level where penal interest was charged in addition to the loss of interest on eligible cash balances. Secondly, the scheme of graduated penalties was extended from 5 per cent to 10 per cent of the absolute amount of CRR required to be maintained. Thirdly, the graduated loss of interest was made less steep. Fourthly, in cases where the shortfall was in excess of 10 per cent of the absolute amount of CRR required to be maintained, no interest would be paid on any of the eligible cash balances (inclusive of such balances relating to the increase in net DTL after March 23, 1990) and the penalty would also be applicable on the amount of default. The revised scheme provides for a softening of the cost of a shortfall provided the shortfall is within reasonable limits. The revised schedule of graduated interest rates on cash balances is as follows:

## Short fall in Maintenance of Cash Reserve Ratio—Schedule of Graduated Interest Rates on Cash Balances with effect from April 7, 1990

Upto April 6, 1990		Effective April 7, 1990	
Shortfall during a fortnight as percentage of the absolute amount of cash reserves required to be maintained (upto and inclusive of)	Rate of Interest payable on the amount above the statutory minimum of 3 per cent actually maintained (per cent per annum)	Shortfall during a fortnight as percentage of the absolute amount of cash reserves required to be maintained (upto and inclusive of)	Rate of Interest payable on the amount above the statutory minimum of 3 per cent actually maintained on net demand and time liabilities as on March 23, 1990
0	10.50	0	10.50
0.5	10.95	2.0	10.00
1.0	10.00	4.0	9.25
1.5	9.50	6.0	8.50
2.0	8.75	8.0	7.00
2.5	7.75	10.0	6.00
3.0	6.50	Over 10.0	0
3.5	5.00		
4.0	3.00		
4.5	1.25		
5.0	0.50		
over 5.0	0		

## (g) Access to the Call Money Market

5.30 With a view to widening the call and notice money market, effective May 2, 1990, the General Insurance Corporation of India (GIC), the Industrial Development Bank of India (IDBI) and the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) were permitted to participate in the call/notice money market only as lenders. Until then, while scheduled commercial banks and cooperative banks as well as the DFHI were permitted to act both as lenders and borrowers in the call/notice money market, LIC and UTI were allowed to operate only as lenders.

5.31 There was considerable volatility in the call money market particularly towards the end of March 1990. This was largely due to the over-extended credit position of certain banks which sought to borrow large amount; on certain days. Banks with over-extended credit positions have been advised to undertake structural adjustments to correct their chronic and large dependence on the call money market. The increase in the participants in the call money market and the softening of the penalties on CRR shortfalls should also help to moderate the interest rate peaks in the money market. Illustratively, the cost of a shortfall on the basis of the earlier schedule of graduated penalties was around 150 per cent for a shortfall of 5 per cent while the penalty under the revised schedule would be around 30 per cent.

## (h) Certificates of Deposit

5.32 In order to broad-base the primary market for Certificates of Deposit (CDs) as also to provide a fillip to the development of a secondary market, the limit for issue of CDs by scheduled commercial banks (excluding Regional Rural Banks) was enhanced from 1 per cent of the fort-

nightly average outstanding aggregate deposits in 1988-89 to 2 per cent of fortnightly average outstanding aggregate deposits in 1989-90. Thus, the overall limits for the banking system would be increased from Rs. 1,264 crore to Rs. 3,017 crore. Furthermore, the denomination of CDs could be in multiples of Rs. 10 lakh as against Rs. 25 lakh specified earlier subject to the minimum size of an issue to a single investor being Rs. 50 lakh (Rupees one crore earlier).

#### (i) Commercial Paper

5.33 Guidelines for the issue of Commercial Paper (CP) were relaxed to broad-base the primary market and also to widen the scope for the secondary market. The following changes in the guidelines were made with effect from April 24, 1990:

- (i) The tangible net worth of the company issuing CP should not be less than Rs. 5 crore as per the latest audited balance sheet as against Rs. 10 crore as specified earlier.
- (ii) Working capital (fund-based) limits of the company should not be less than Rs. 15 crore instead of not less than Rs. 25 crore specified earlier.
- (iii) The minimum credit rating from CRISIL can be P1 instead of P1+ specified as per earlier guidelines.
- (iv) The denomination of CP could be in multiples of Rs. 10 lakh instead of Rs. 25 lakh subject to the minimum size of an issue to a single investor being Rs. 50 lakh (face value) instead of Rs. 1 crore (face value).

#### May 1990 Selective Credit Controls on Advances Against Oilseeds and Vegetable Oils

5.34 On a review of price-output developments relating to oilseeds and vegetable oils (including vanaspathi), the minimum margins on bank advances against these commodities were raised by 15 percentage points across-the-board with effect from May 4, 1990.

#### July 1990

#### Selective Credit Controls on Advances Against Wheat, Oilseeds and Vegetable Oils

5.35 On a review of the price-output developments relating to wheat, oilseeds and vegetable oils, the following modifications were made in the provisions of selective credit control with effect from July 2, 1990. All advances against wheat were exempted from all the provisions of selective credit control. This exemption for advances against wheat would be applicable in the case of all parties including roller flour mills. The minimum margins on bank advances against oilseeds and vegetable oils (including vanaspathi), were raised across-the-board by 15 percentage points.

5.36 The minimum margins and level of credit ceilings on bank advances against commodities subject to selective credit controls are as follows:

#### Minimum Margins and Level of Credit Ceilings on Bank Advances Against Commodities Subject to Selective Credit Controls (Effective July 2, 1990)

(In percentages)

	Minimum Margins			Level of Credit Ceilings
	Mills/ Processing Units	Others	Ware- house Receipts	
				(Base years : 1986-87, 1987-88 and 1988-89)
1	2	3	4	5
1. Paddy/Rice	45	60	45	85
2. Pulses	45	60	45	85

1	2	3	4	5
3. Other Food-grains.	45	60	45	85
4. Oilseeds (viz., groundnut, rapeseed/mustard, linseed, castor-seed, cotton-seed and all important oil seeds)	60	75	60	100
5. vegetable oil (viz., groundnut oil, rapeseed, mustard oil, linseed oil, Castor oil, cottonseed oil, vanaspathi and all imported vegetable oils).	60	75	60	100
6. Sugar				
(a) Buffer	0	---		
(b) Unreleased stocks	20	---		
(c) Released stocks	75	75	60	---
7. Gur and Khandsari	45	75	60	---

@Applicable to registered oil mills and vanaspathi manufacturers.

—Not applicable.

#### 6. TRENDS IN MONEY AND CREDIT

6.1 Monetary developments during the financial year 1989-90 were characterised by a striking acceleration in liquidity growth, with strong expansionary influence emanating from the Government's deficit spending. Besides, the expansion in M1 was particularly sharp and was accounted for by equally sharp acceleration in the growth of both currency with the public and demand deposits with banks. Although the growth of time deposits decelerated, the expansion in broad money (M3) was nevertheless significantly higher than in the previous year.

6.2 The sources of change in broad money, as reflected by point-to-point variations, show a picture different from that in the previous year; bank credit to the commercial sector recorded slower growth in 1989-90 as against faster expansion in 1988-89, while net bank credit to Government recorded acceleration in 1989-90 as against deceleration in 1988-89. These trends are based on year-end numbers which understate the expansionary impulses from both of these domestic credit components. As in the previous year, net Reserve Bank credit to Government ruled at a phenomenally high level throughout 1989-90 before dropping somewhat at the close of the financial year. Likewise, expansion in bank credit to the commercial sector during the first half of 1989-90 was running at a faster pace than in 1988-89 but with significant slowing down in the second half, the overall pace of expansion in commercial credit in the whole of 1989-90 turned out lower in percentage terms. This deceleration, however, has to be viewed against the background of a slowing down of the growth of the economy, particularly in the manufacturing sector for the major part of the year, and also an extraordinarily large increase in bank credit in the previous year; moreover, the slowing down of credit expansion of the commercial sector in 1989-90 reflects the impact of the policy of credit restraint witnessed in the second half of the year.

6.3 The underlying expansionary impulses of persistently high fiscal deficits could not but get reflected in a faster growth of reserve money. Unlike in previous years, however, the excess primary liquidity could not be mopped up as the cash reserve ratio (CRR) had reached its statutory limit. As a result, the incremental ratio of bank reserves to aggregate deposits ( $\Delta R/\Delta AD$ ), on a point-to-point basis, registered a marked fall; while this, to some extent, reflects the attenuation of monetary control, in view of the very large day-to-day oscillations in bank reserves, it is not possible to attribute the sharp fall in  $\Delta R/\Delta AD$  entirely to the inability to raise the CRR. The incremental currency to aggregate deposits ratio ( $\Delta C/\Delta AD$ ) contrary to long-term trends, rose rather significantly. These contrary pulls have tended to arrest the rise in the unadjusted money multiplier.

6.4 Operations of scheduled commercial banks showed an acceleration in the growth of aggregate deposits and bank credit during the fiscal year 1989-90. Growth of demand deposits accelerated markedly but that of time deposits decelerated somewhat. The show-down in bank credit expansion was on account of a slower growth in non-food credit after a year of very high growth. There was a sharp turn around in food credit from a decrease in 1988-89 to a large increase in 1989-90. With a substantially lower increase in balances with the Reserve Bank, the banks' dependence on borrowings from the Reserve Bank was reduced.

#### Money Supply

6.5 Monetary expansion, as measured in terms of broad money or  $M_3$  at Rs. 38,224 crore or by 19.9 per cent during 1989-90 was higher than that of Rs. 29,425 crore or 18.1 per cent in the previous year (Table 6.1). In the credit policy announced in March 1989, the desirability of containing the expansion of  $M_3$  during 1989-90 to a level lower than average of the previous four years (16.7 per cent) was indicated, but

it was predicated on the assumption that the increase in net Reserve Bank credit to the Central Government would be around Rs. 7,337 crore as indicated in budget documents but the actuals based on March 31 after closure of Government accounts reached a peak of Rs. 17,102 crore on March 16, 1990, before touching Rs. 13,813 crore as of March 31, 1990. Therefore, monetary expansion at 19.9 per cent has turned out to be the highest since 1978-79 when it was 21.2 per cent. On the basis of the average of reporting Fridays, the growth of  $M_3$  during 1989-90 was 18.9 per cent as against 17.1 per cent in 1988-89.

6.6 The pace of monetary expansion, as measured in terms of growth of money supply with the public or  $M_4$  was still higher at 22.5 per cent in 1989-90 as against 15.2 per cent in 1988-89. In terms of the average of reporting Fridays, the rate of expansion in  $M_1$  was 20.2 per cent in 1989-90 as compared with that of 14.5 per cent in the previous year.

6.7 Component-wise, there was an unprecedented bulge of Rs. 8,153 crore or 21.2 per cent in currency with the public during 1989-90, as against Rs. 4,765 crore or 14.2 per cent in the previous year. Aggregate deposits with banks recorded a fractionally higher rise of 19.4 per cent as compared with 19.0 per cent in 1988-89. Demand deposits recorded a much higher rise of 23.4 per cent as compared with 16.2 per cent, while time deposits recorded a smaller rise of 18.5 per cent than that of 19.7 per cent in the previous year.

6.8 Although the absolute increase in bank credit to the commercial sector in 1989-90 at Rs. 22,630 crore was somewhat higher than that of Rs. 21,687 crore in 1988-89, in percentage terms the increase was much lower at 17.8 per cent as compared with 20.5 per cent. Net bank credit to Government recorded a marked increase both in absolute and

Table 6.1 : VARIATION IN MONEY STOCK ( $M_3$ )

(Rupees crore)

Item	Variations during**							
	1988-89		1989-90*		1989-90 (April—June)		1990-91* (April—June)	
	Absolute	Percentage	Absolute	Percentage	Absolute	Percentage	Absolute	Percentage
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. $M_3$ (a + b + c)	29,425	18.1	38,224	19.9	11,170	5.8	7,247	3.1
(a) Currency with the Public	4,765	14.2	8,153	21.2	2,412	6.3	2,718	5.8
(b) Aggregate Deposits with Banks (i + ii)	24,495	19.0	29,727	19.4	8,754	5.8	4,558	2.5
(i) Demand Deposits	3,875	16.2	6,476	23.4	2,323	8.4	433	1.3
(ii) Time Deposits	20,620	19.7	23,251	18.5	6,431	5.1	4,125	2.8
(c) Other Deposits with RBI	160	55.6	344	74.5	4	0.9	-29	-3.6
II. $M_1$ (a + b (i) + c)	8,805	15.2	14,973	22.5	4,739	7.1	3,122	3.8
III. Sources of Money Stock ( $M_3$ ) (1 + 2 + 3 + 4 + 5)								
1. Net Bank Credit to Government (A + B)	12,771	15.2	19,686	20.3	8,433	8.7	9,583	8.2
A. RBI's net credit to Government (i + ii) +	7,225	17.7	13,031(a)	21.7	6,079	10.1	6,661(b)	9.1
(i) Net claims on Central Government (a - b)	7,310	13.9	12,672	21.2	6,186	10.3	7,172	9.9

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(a) Claims on Central Government	7,334	13.9	12,626	21.1	6,168	10.3	7,250	10.0	
(b) Deposits of Central Government	24	31.6	-46	-46.0	-18	-18.0	87	101.1	
(ii) Net claims on State Government (A+B)	-85	-36.8	359	245.9	-107	-73.3	-511	-101.2	
(a) Claims on State Governments	-90	-36.6	362	232.1	-102	-65.4	-507	-97.9	
(b) Deposits of State Governments	-5	-33.3	3	30.0	5	30.0	4	30.8	
B. Other banks' credit to Government	5,546	17.7	6,655	18.1	2,354	6.4	2,922	6.7	
2. Bank Credit to Commercial Sector (A+B)	21,687	20.5	22,630	17.8	4,531	3.6	2,112	1.4	
A. RBI's credit to commercial Sector @	1,144	30.1	257	5.2	-528	-10.7	-246	-4.7	
B. Other banks' credit to commercial sector	20,543	30.2	22,373	18.3	5,059	4.1	2,388	1.7	
3. Net Foreign Exchange Assets of Banking Sector (A+B)	1,146	20.7	85	1.3	64	1.0	-352	-5.2	
A. RBI's net foreign exchange assets	637	12.1	85	1.4	64	1.1	-352	-5.9	
B. Other banks' net foreign exchange assets	509	198.8	—	—	—	—	—	—	
4. Government's Currency Liabilities to Public	95	6.9	42	2.8	31	2.1	—	—	
5. Banking Sector's Net Non-monetary Liabilities other than Time Deposits (A+B)	6,274	18.5	4,219	10.5	1,889	4.7	4,126	9.3	
A. Net non-monetary liabilities of RBI	2,415	17.4	1,952	12.0	398	1.8	218	1.2	
B. Net non-monetary liabilities of other banks (residual)	3,859	19.3	2,267	9.5	1,591	6.7	3,908	15.0	

\*\*Based on the last reporting Friday of March.

@Excludes, since the establishment of NABARD its refinance to banks.

\*Provisional.

†Includes an amount of Rs. 722 crore (a) Rs. 240 crore (b) representing the replacement of non-negotiable non-interest bearing securities issued to IMF by RBI claims on Central Government for facilitating repurchases from the Fund.

Notes : Constituent items may not add up to totals due to rounding off

percentaged terms—Rs. 19,686 crore or 20.3 per cent as compared with Rs. 12,771 crore or 15.2 per cent in the previous year. The increase in net Reserve Bank credit to Government in 1989-90 at Rs. 13,031 crores (21.7 per cent) was conspicuously higher than that of Rs. 7,225 crore (13.7 per cent), largely on account of an increase of Rs. 12,672 crore (21.2 per cent) in net Reserve credit to Central Government as compared with Rs. 7,310 crore (13.9 per cent) in the previous year. It is pertinent to point out here that a part of the increase in net Reserve Bank credit to Central Government in 1989-90, viz., 722 crore was on account of the replacement of non-negotiable bearing securities issued to

the International Monetary Fund (IMF) by the Reserve Bank's claims on the Central Government for facilitating repurchases from the Fund\*. Even so, the average of successive fortnightly figures of financial year variations in net Reserve Bank credit to Central Government at Rs. 10,635 crore in 1989-90 was much higher than that of Rs. 7,309 crore in 1988-89 and Rs. 5,326 crore in 1987-88. Other banks' credit to Government increased by Rs. 6,655 crore (18.1 per cent) as against Rs. 5,546 crore (17.7 per cent) in the preceding year. Net foreign exchange assets of the Banking sector recorded a small increase of Rs. 85 crore as compared with the increase of Rs. 1,146 crore in 1988-89.

\*With the depletion of the IMF Account No. 1 balances with the Reserve Bank of India constituting mainly the repurchase obligations with the IMF, due to 'maintenance of value' provisions under the Fund's Articles of Agreement, the special securities created by the Government in favour of the Fund had to be encashed leading to an equivalent rise in the Reserve Bank's claims on the Government of India.

6.9 During the first quarter (April-June) of the financial year 1990-91, the pace of both  $M_2$  and  $M_1$  growth has been considerably lower than that in the corresponding period of 1989-90. Percentage increase in net bank credit to Government was a shade lower and that in bank credit to commercial sector was significantly lower than in the comparable period of 1989-90.

#### Reserve Money

6.10 Reserve money recorded an increase of Rs. 10,770 crore (17.3 per cent) during 1989-90 on top of the rise of Rs. 9,081 crore (17.0 per cent) in the previous year. On an average basis, reserve money growth was higher at 18.0 per cent as against 16.8 per cent in 1988-89. Component-wise,

there was a visible acceleration in currency with the public as referred to earlier. Bankers' deposits with the Reserve Bank, the other major component, recorded a markedly smaller rise of Rs. 2,066 crore (9.5 per cent) as compared with an increase of Rs. 3,904 crore (21.9 per cent) in 1988-89 (Table 6.2).

6.11 Source-wise net Reserve Bank credit to Government which has been a major factor in the expansion of reserve money, rose by Rs. 13,031 crore (21.7 per cent) as against Rs. 7,225 crore (13.7 per cent) in 1988-89. The Reserve Bank's credit to commercial and co-operative banks registered a decline of Rs. 693 crore in contrast to an increase of Rs. 2,395 crore in the previous year.

TABLE 6.2 : Reserve Money Variations—Components and Sources

(Rupees crore)

Items	Variation during **			
	1988-89	1989-90*	1989-90 (April-June)	1990-91* (April-June)
1	2	3	4	5
Reserve Money (1+2+3+4)	9,081 (17.0)	10,770 (17.3)	3,888 (6.2)	5,954 (8.1)
1. Currency with the public	4,765 (14.2)	8,153 (21.2)	2,412 (6.3)	2,718 (5.8)
2. 'Other' deposits with RBI	165 (55.6)	344 (74.5)	4 (0.9)	-29 (-3.6)
3. Cash with banks	247 (16.0)	207 (11.5)	530 (29.6)	318 (16.0)
4. Bankers' deposits with RBI	3,904 (21.9)	2,066 (9.5)	942 (4.3)	2,947 (12.4)
Sources of reserve money (1+2+3+4+5+6)				
1. Net RBI credit to Government†	7,225 (13.7)	13,031(a) (17.7)	6,079 (10.1)	6,661(b) (9.1)
2. RBI claims on commercial and co-operative banks @	2,395 (61.0)	-693 (-11.0)	-1,460 (-23.1)	109 (1.9)
3. RBI's credit to commercial sector	1,144 (30.1)	257 (5.2)	-578 (-10.7)	-246 (-4.7)
4. Net foreign exchange assets of RBI	637 (12.1)	85 (1.4)	64 (1.1)	-35 (-5.9)
5. Government's currency liabilities to the public	95 (6.9)	42 (2.89)	31 (2.1)	— (—)
6. Net non-monetary liabilities of RBI	2,415 (17.4)	1,952 (10.0)	2,98 (1.8)	918 (1.2)

\* Provisional.

\*\* Based on the last reporting Friday of March.

@ Including NABARD.

† Includes an amount of Rs. 722 crore (a) Rs 240 crore (b) representing the replacement of non-negotiable non-interest bearing securities issued to IMF by RBI claims on Central Government for facilitating repurchases from the Fund.

Notes: 1. Constituent items may not add up to totals due to rounding off.

2. Figures in bracket indicate percentage variations.

6.12 During the first quarter of the financial year 1990-91, reserve money growth has accelerated to 8.1 per cent from 6.2 per cent in the corresponding period of 1989-90. The Reserve Bank's higher claims on Government in absolute terms, as also those on commercial and co-operative banks, both in absolute and percentage terms, have contributed to this rapid increase in reserve money.

6.13 Interestingly, the Reserve Bank's supply of primary reserves to the commercial sector (i.e. through its assistance to term-financing institutions) has grown to a perceptibly higher level in recent years than its supply of primary reserves through the commercial and co-operative banking system (see Table 6.3).

Table 6.3 : Reserve Bank's claims on Banks and Commercial Sector

Outstandings as at the end of	(Rupees crore)	
	Reserve Bank's claim on	
	Commercial and Co-operative Banks	Commercial Sector* (Financial institutions)
1	2	3
1984-85	1,584	3,984
1987-88	2,158	5,577
1988-89	3,937	7,337
1989-90	2,810	8,028
June 30, 1989	2,588	6,700
June 29, 1990	2,882	7,819

\*Represents investments in bonds/shares of financial institutions including NABARD and loans to them, Excludes, since the establishment of NABARD, its refinance to banks.

Table 6.4 : Trends in Income Velocity (GDP) at current market prices as Ratio of Currency,  $M_3$ , and  $M_1$ 

Year	Averages @ (Rupees crore)			Income Velocity Ratios		
	Currency	$M_1$	$M_3$	GDP/Currency	GDP/ $M_1$	GDP/ $M_3$
	2	3	4	5	6	7
1						
1985-86	24,058	40,824	1,10,372	10,911	6,430	2,378
1986-87	27,011	46,835	1,29,713	10,863	6,265	2,262
1987-88	31,410	53,866	1,52,096	10,587	61,74	2,186
1988-89	36,842	61,688	1,78,080	10,913	6,341	2,197
1989-90	42,529	74,169	2,11,699	10,411	5,970	2,092

@ Averages of reporting Fridays.

#### Some Monetary Relationships

6.15 Key monetary ratios such as, currency to aggregate deposits (C/AD) and currency to  $M_3$  (C/ $M_3$ ), moved upwards during 1989-90 both on an average and point-to-point basis because of the large increase in currency relative to aggregate deposits or  $M_3$ . Increment money multiplier/ ( $A\Delta_s$   $\Delta$  Adjusted for changes in the reserve requirements, both on a point-to-point basis and on an average basis, has registered a rise (Table 6.5).

#### Banking Variables

6.16 During the financial year 1989-90, accretion to aggregate deposits of scheduled commercial banks at Rs. 26,809 crore (19.1 per cent) was higher than that of Rs. 27,105 crore (18.7 per cent) in 1988-89. In the credit policy exercises of March 1989, the working estimate relating to the growth of aggregate deposits of scheduled commercial banks was placed at Rs. 24,000 crore (17.3 per cent) for 1989-90. The actual increase in 1989-90 turned out to be

Table 6.5 : Monetary Rates—Incremental

Item	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6
Point-to-point basis					
(Incremental Ratios)					
(a) Currency/Aggregate Deposits (C/AD)	0.176	0.182	0.298	0.195	0.274
(b) Currency/ $M_3$ (C/ $M_3$ )	0.153	0.153	0.230	0.162	0.213
(c) Aggregate Deposits/ $M_3$ (AD/ $M_3$ )	0.869	0.842	0.773	0.832	0.778
(d) Money Multiplier ( $M_3$ /RM)	2.567	3.206	2.597	3.240	3.549
(e) Money Multiplier ( $M_1$ /RM)	0.619	1.090	0.781	0.970	1.390
(f) Bank Reserves/Aggregate Deposits (R/AD)	0.297	0.183	0.204	0.169	0.076
Average basis					
(Incremental Ratios)					
(a) Currency/Aggregate Deposits (C/AD)	0.183	0.180	0.245	0.206	0.250
(b) Currency/ $M_3$ (C/ $M_3$ )	0.135	0.153	0.197	0.171	0.199
(c) Aggregate Deposits/ $M_3$ (AD/ $M_3$ )	0.851	0.847	0.801	0.827	0.796
(d) Money Multiplier ( $M_3$ /RM)	3.918	3.129	2.453	3.099	3.204
(e) Money Multiplier ( $M_1$ /RM)	1.206	0.972	0.771	0.933	1.189
(f) Bank Reserves/Aggregate Deposits (R/AD)	0.124	0.197	0.261	0.180	0.135

Note : On a point-to-point basis, the ratios are based on last reporting Friday of March while on an average basis the ratios have been worked out on the basis of averages of all reporting Fridays. All ratios in this table are incremental ratios.

higher than the working estimate (Table 6.6). The annual average increase in aggregate deposits (at current prices) during the Seventh Plan period was Rs. 18,943 crore (or 18.2 per cent per annum). Component wise, while demand deposits registered higher increase both in absolute and percentage terms, time deposits experienced larger increase in absolute terms but its growth slowed down in percentage terms. Thus, demand deposits rose by Rs. 5,514 crore (23.6 per cent) during

Table 6.6 : Growth of Aggregate Deposits of Scheduled Commercial Banks

(Rupees crore)

Fiscal year (April March)	Growth of Aggregate Deposits
1985-86	13,160 (18.2)
1986-87	17,320 (20.3)
1987-88	15,321 (14.9)
1988-89	22,105 (18.7)
1989-90	26,809 (19.1)
Average of 1985-86 to 1989-90	18,943 (18.2)

Note : The increases are based on last reporting Friday of March.

1989-90 as against Rs. 3,095 crore (15.3 per cent) during the previous year, while time deposits increased by Rs. 21,295 crore (18.2 per cent) as compared with Rs. 19,010 crore (19.4 per cent) (Table 6.7).

6.17 The expansion in bank credit at Rs. 16,734 crore in 1989-90 was higher than that of Rs. 14,183 crore in 1988-89; but in percentage terms, the increase was lower at 19.8 per cent as compared with 20.1 per cent in the previous year. Food credit recorded a rise of Rs. 1,237 crore in 1989-90 in contrast to a decline of Rs. 1,421 crore in 1988-89, reflecting higher food procurement and stocks with the public distribution system. Non-food credit registered a lower rise of Rs. 15,497 crore (18.5 per cent) than of Rs. 15,604 crore (22.8 per cent) in the previous year which is attributable partly to the deceleration in growth of industrial and agricultural output and partly to the measures taken by the Reserve Bank to moderate non-food credit expansion particularly in the second half of 1989-90, when non-food credit increased by Rs. 7,758 crore or 8.5 per cent as compared with an expansion of Rs. 9,937 crore or 13.4 per cent in the corresponding period of the previous year.

6.18 The increase in banks' investments in government and other approved securities at Rs. 9,707 crore was higher than that of Rs. 8,158 crore in 1988-89. Banks' balances with the Reserve Bank recorded a lower rise of Rs. 2,087 crore as compared with that of Rs. 3,720 crore in the previous year. Bank's borrowings from the Reserve Bank recorded a decline of Rs. 1,128 crore in contrast to a rise of Rs. 1,774 crore in the preceding year.

#### Year-End Bulge in Banking Variables

6.19 Mention was made in the last year's Report about very sharp and unusual increases in aggregate deposits and credit of scheduled commercial banks in the last week of their financial year which ended on March 31, 1989. During the comparable period of the banks' financial year 1989-90,

Table 6.7 : Important Banking Indicators—Scheduled Commercial Banks

(Rupees crore)

Items	Outstanding as on			Variations during the financial year		Variation	
	March 24 1980	March 23 1990	June 29 1990*	1988-89	1989-90	1989-90 (April to June)	1990-91 (April to June)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Total Demand and Time Liabilities (excluding borrowing from RB/DB/ NABARD).	1,56,637	1,85,845	1,91,183	24,686	29,208	9,158	5,338
2. Aggregate Deposits (a + b)	1,40,150	1,66,959	1,71,648	22,105 (18.7)	26,809 (19.1)	7,704 (5.5)	4,689 (2.8)
(a) Demand Deposits	23,342	28,856	29,291	3,095 (15.3)	5,514 (23.6)	1,766 (7.6)	435 (1.5)
(b) Time Deposits	1,16,808	1,38,103	1,42,357	19,010 (19.4)	21,295 (18.2)	5,938 (5.1)	4,254 (3.1)
3. Borrowings from RBI	3,572	2,399	2,458	1,774	1,128	(—)1,353	59
4. Bank Credit (a + b)	84,719	1,01,453	1,03,837	14,183 (20.1)	16,734 (19.8)	4,361 (5.1)	2,384 (2.3)
(a) Food Credit	769	2,006	3,917	1,421	1,237	890	1,911
(b) Non-food Credit	83,950	99,447	99,920	15,604 (22.8)	15,497 (18.5)	3,471 (41)	473 (0.5)
5. Investments (a + b)	54,662	64,369	67,444	8,158 (17.5)	9,707 (17.8)	2,898 (5.3)	3,075 (4.8)
(a) Government Securities	35,815	42,292	45,204	5,298 (17.4)	6,477 (18.1)	2,345 (6.5)	2,917 (6.9)
(b) Other Approved Securities	18,847	22,077	22,240	2,860 (17.9)	3,230 (17.1)	553 (2.9)	163 (0.7)
6. Cash in hand	1,444	1,648	1,878	138	204	435	230
7. Balances with RBI	21,376	23,463	26,026	3,720 (21.1)	2,087 (9.8)	680 (3.2)	2,563 (10.9)
8. Credit-Deposit Ratio (%)	60.4	60.8	60.5				
9. Non-food Credit-Deposit Ratio (%)	59.9	59.6	58.2				

\*Provisional.

Notes : 1. Figures in brackets are percentage variations.

2. Constituent items may not add upto the totals due to rounding off.

3. No sign is indicated for positive variations.

there were similar share increases in aggregate deposits and credit, hus, between March 23 and March 31, 1990, aggregate deposits rose by Rs. 8,169 crore (4.9 per cent), and bank credit by Rs. 4,999 crore (4.9 per cent) respectively these compare with the increase of Rs. 7,010 crore (5.0 per cent) in aggregate deposits and Rs. 4,651 crore (5.5 per cent) in bank credit during the last week of 1988-89. Demand deposits rose markedly by Rs. 5,428 crore (18.8 per cent) and time deposits also rose significantly by Rs. 2,741 crore

(2.0 per cent) between March 23 and March 31, 1990. The increase in aggregate deposits during this period ended March 31, 1990 formed about 30.5 per cent of the increase in deposits during 1989-90 on reporting Friday basis; likewise, the accruals of demand deposits during the same eight-day period was almost equivalent to (ie., 99 per cent) the total accruals during the whole of the year 1989-90 on reporting Friday basis (Table 6.8). The to Rs. 4,689 crore (2.8

Table 6.8 : Variation in Selected Items of Scheduled Commercial Banks : Last week of March 1990 data.

Items	(Rupees crore)					
	Outstanding as on			Variation		
	March 24, 1989	March 23, 1990	March 31, 1990 (PR)	March 23, 1990 over March 24, 1989	March 31, 1990 over March 23, 1990 [	(6) as percentage of (5)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Aggregate Deposits (a+b)	1,40,150	1,66,959	1,75,128	+26,809 (+19.1)	+8,169 (+4.9)	+30.5
(a) Demand Deposits	23,342	28,856	34,284	+5,514 (+23.6)	+5,428 (+18.8)	+98.4
(b) Time Deposits	1,16,808	1,38,103	1,40,844	+21,295 (+18.2)	+2,741 (+2.0)	+12.9
2. Bank Credit (a+b)	84,719	1,01,453	1,06,452	+16,734 (+19.8)	+4,999 (+4.9)	+29.9
(a) Food Credit	769	2,006	1,867	+1,237 (+160.8)	—139 (—6.9)	—11.2
(b) Non-food Credit	83,950	99,447	1,04,585	+15,497 (+18.5)	+5,138 (+5.2)	+33.2

PR : Partially revised.

Note : Figures in brackets indicated percentage variations.

Increase in a single day between March 30 and March 31, 1990 was still more striking; it was Rs. 1,613 crore (0.9 per cent) in aggregate deposits and Rs. 1,0302 crore (1.0 per cent) in bank credit. That March 31 data are not meaningful for purposes of assessment of the basic underlying monetary and credit developments in 1989-90 should be clear particularly in view of the fact that the decline of deposits and credit in the first week ending April 6, 1990 was nearly one-half of the increases in deposits and credit between March 23 and March 31, 1990. The analysis in this report is, therefore, based on data relating to reporting Fridays and not March 31.

#### Trends in the First Quarter of 1990-91

6.20 As explained in the previous chapter, the working estimate of aggregate deposit growth of scheduled commercial banks has been placed at Rs. 27,500 crore (166.6 per cent) and the corresponding seasonal estimates for the first half of 1990-91 at Rs. 13,700 crore and for the first quarter April-June 1990 at Rs. 6,800 crore. The actual growth in aggregate deposits of scheduled commercial banks during the first quarter (upto June 29, 1990) amounted

to Rs. 4,689 crore (2.8 per cent) as compared with that of Rs. 7,704 crore (5.5 per cent) in the corresponding period of the preceding year. Demand deposits showed a lower rise of Rs. 435 crore (4.5 per cent) as compared to a sizeable growth of Rs. 1,766 crore (7.6 per cent) in the comparable period of the previous year. Growth in time deposits at Rs. 4,254 crore (3.1 per cent) was lower than that in the corresponding period of the preceding year (Rs. 5,938 crore or 5.1 per cent). Bank credit recorded a reduced expansion of Rs. 2,384 crore (2.3 per cent) as compared with that of Rs. 4,361 crore (5.1 per cent) in the corresponding period of the previous year. Food credit rose by Rs. 1,911 crore as compared with a rise of Rs. 890 crore in the comparable period of 1989, reflecting higher procurement operations by public agencies this year. Increase in nonfood credit was much lower at Rs. 473 crore or 0.5 per cent in the first quarter of 1990-91 as against Rs. 3,471 crore or 4.1 per cent in the corresponding quarter of the previous year. Banks' investments showed a larger rise of Rs. 3,075 crore (4.8 per cent) as compared with Rs. 2,898 crore (5.3 per cent) in the corresponding period of the previous year.



Table 6.9 : Sectoral Deployment of Gross Bank Credit by Major Sectors@

Sector	Outstanding as on			Variations (Financial Year)	
	March 25, 1988	March 24, 1989	March 23, 1990	1988-89	1989-90
	1	2	3	4	5
I. Gross Bank Credit	70,260	85,728	1,02,783	+15,468	+17,055
1. Public Food Procurement	2,190	769	2,006	-1,421	+1,237
2. Non-food Gross Bank Credit	68,070	84,959	1,00,777	+16,889 (+100.0)	+15,818 (+100.0)
A. Priority Sectors	29,070 (44.1)	34,219 (43.2)	40,475 (42.4)	+5,149 (+30.5)	+6,256 (+39.5)
(i) Agriculture	12,009 (18.2)	13,950 (17.6)	16,612 (17.4)	+1,941 (+11.5)	+2,662 (+16.8)
(ii) Small-scale Industries	10,820	13,135	15,615	+2,315 (+13.7)	+2,480 (+15.7)
(iii) Other Priority Sectors	6,241	7,134	8,248	+893 (+5.3)	+1,114 (+7.0)
B. Industry (Medium & Large)	25,153	32,185	38,274	+7,032 (+41.6)	+6,089 (+38.5)
C. Wholesale Trade (Other than food procurement)	3,598	4,767	5,879	+1,169 (+6.9)	+1,112 (+7.1)
(i) Cotton Corporation of India	91	37	140	-54 (-0.3)	+103 (+0.7)
(ii) Food Corporation of India (for fertilizer distribution).	171	202	230	+31 (+0.1)	+28 (+0.2)
(iii) Jute Corporation of India	142	60	17	-82 (-0.4)	-43 (-0.3)
(iv) Other Trade	3,194	4,468	5,492	+1,274 (+7.5)	+1,024 (+6.5)
D. Other Sectors	10,249	13,788	16,149	+3,539 (+21.00)	+2,361 (+14.9)
II. Export Credit (included under item 1 (2))	3,917	6,141	8,272	+2,224	+2,131
III. Net Bank Credit (including inter-bank participations)	65,968	79,234	95,475	+13,266	+16,241

@Provisional

Note : 1. Data relate to 50 scheduled commercial banks which account for about 95 per cent of bank credit of all scheduled commercial banks. Further, these gross bank credit include bills rediscounted with RBI, IDBI, EXIM Bank, other approved financial institutions and inter-bank participations.

2. Figures in brackets are proportions to incremental Non-food Gross Bank Credit.

3. Figures in square brackets are proportions to net bank credit (including inter-banks participations) given in item III.

### Sectoral Deployment of Credit

6.21 Data on sectoral deployment of gross bank credit are presented in Table 6.9. Data indicate that during 1989-90 (April-March), the expansion in gross bank credit amounted to Rs. 17,055 crore (19.9 per cent) as compared with an increase of Rs. 15,468 crore (22.0 per cent) during the previous year. Bank credit extended for food procurement recorded a substantial rise of Rs. 1,237 crore in contrast to a decline of Rs. 1,421 crore in the previous year. The expansion of non-food gross bank credit at Rs. 15,818 crore was, however, lower than the increase of Rs. 16,889 crore in 1989-90. The broad sectors which accounted for this deceleration in the growth of bank credit were medium and

large industries, export credit and wholesale trade (other than food). Priority sector advances, on the other hand, recorded a marked increase over the year.

6.22 Bank credit to priority sectors recorded a rise of Rs. 6,256 crore during 1989-90 and formed 39.5 per cent of total incremental non-food gross bank credit as compared with its share of 30.5 per cent in the previous year. Priority sector advances as a proportion of net bank credit at the end of March 1990 worked out to 42.4 per cent as against 43.2 per cent a year ago.

6.23 The share of agriculture and small-scale industries in total increase in advances to priority sectors amounted

to Rs. 2,662 crore (42.6 per cent) and Rs. 2,480 crore (39.6 per cent), respectively in 1989-90 as compared with Rs. 1941 crore (37.7 per cent) and Rs. 2,315 crore (45.0 per cent), respectively, in the previous year.

6.24 Advances to medium and large industry showed a deceleration in growth during 1989-90. Advances to this sector registered an increase of Rs. 6,089 crore (18.9 per cent) to Rs. 38,274 crore during 1989-90 as compared with the larger increase of Rs. 7,032 crore (28.0 per cent) to Rs. 32,185 crore during 1988-89. Its share in incremental non-food gross bank credit also fell from 41.6 per cent in 1988-89 to 38.5 per cent in 1989-90.

6.25 Advances to wholesale trade recorded a smaller increase of Rs. 1,112 crore (23.3 per cent) during 1989-90 as compared with a rise of Rs. 1,169 crore (32.5 per cent) during the same period last year.

6.26 Credit to 'Other Sectors' which represent residual sectors and include advances to financial institutions, hire-purchase agencies, leasing companies, housing finance, consumer durable finance, etc. registered a lower increase of Rs. 2,361 crore (17.1 per cent) during 1989-90 when compared with an increase of Rs. 3,539 crore (34.5 per cent) during 1988-89.

6.27 The industry-wise (small, medium and large-scale) distribution of bank credit is presented in Table 6.10. Industries which accounted for major part of the growth in credit during 1989-90 were; all engineering (Rs. 1,827 crore), iron and steel (Rs. 569 crore), cotton textiles (Rs. 444 crore), other textile (Rs. 503 crore), jute textiles (Rs. 73 crore), rubber and rubber products (Rs. 150 crore), leather and leather products (Rs. 237 crore) and construction (Rs. 304 crore). Decline in credit was reported in sugar (Rs. 13 crore) and coal (Rs. 24 crore) during 1989-90.

#### Behaviour of Financial Ratios

6.28 The behaviour of certain financial ratios, as revealed by the Reserve Bank's sample studies on company finances, offer some corroborative evidence regarding the trends in bank credit in favour of medium and large-scale industries. As may be seen from Table 6.11, during 1988-89 when there was a sizeable increase in bank credit absorbed by the medium and large-scale industries, inventory to sales ratio of the large-size companies went up from 25.0 per cent to 26.0 per cent and short-term bank borrowings to inventories ratio from 44.4 per cent to 45.6 per cent.

Table 6.10 : Industry-wise Development of Gross Bank Credit@

Industry	(Rupees crore)				
	Outstanding as on			Variations	
	March	March	March	(Financial Year)	
	25, 1988	24 1989	23, 1990	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6
Industry (Total of Small Medium & Large-Scale)	35,973	45,320	53,889	+9,347	+8,561
(1) Coal	248	210	186	-38	-24
(2) Iron and Steel	1,824	2,245	2,814	+421	+569
(3) Other Metals & Metal Products	1,203	1,624	1,830	+421	+206
(4) All Engineering	8,697	10,623	12,450	1,926	+1,827
(5) Electricity (Gen. and Trans.)	785	1,042	1,279	+257	+237
(6) Cotton Textiles	2,752	3,216	3,660	+464	+444
(7) Jute Textiles	305	276	349	-29	+73
(8) Other Textiles	2,152	2,742	3,245	+590	+503
(9) Sugar	640	669	656	+29	-13
(10) Tea	411	524	574	+113	+50
(11) Vegetable Oils (including vanaspati)	440	599	685	+159	+86
(12) Tobacco & Tobacco Products	235	297	384	+62	+87
(13) Paper & Paper Products	854	1,142	1,333	+288	+191
(14) Rubber and Rubber Products	557	750	900	+193	+150
(15) Chemicals, Dyes, Paints, etc.	4,210	5,922	6,794	+1,712	+872
Of which : Fertilizer	(913)	(1,019)	(1,081)	(+106)	(+62)
(16) Cement	503	689	820	+186	+131
(17) Leather & Leather Products	565	691	928	+126	+237
(18) Construction	448	759	1,063	+311	+304
(19) Petroleum	163	30	137	-133	+107
(20) SAFAUNS*	231	191	149	-40	-42
(21) Other Industries	8,750	11,079	13,653	+2,329	+2,574

@Provisional

\*Ships acquired from abroad under new scheme.

Table 6.11: Ratios of Inventories to Sales and Bank Borrowings to Inventories  
(Public Limited Companies in the Private Sector)

(In percentage)								
Period	No. of Sample Companies	Total inventories as % of sales	Raw Materials and components as % of total inventories	Short-term bank borrowings as % of the total inventories	Total bank borrowings as % of total inventories	Sundry creditors as % of sundry debtors	Debt-equity ratio	Debt-equity ratio (adjusted for revaluation reserve)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Medium and Large Public Limited Companies								
1975-76	1720	30.7	30.0	49.0	53.5	124.0	45.1	—
1976-77	1720	27.4	30.3	51.7	56.9	115.1	46.8	—
1977-78	1720	26.8	30.2	51.8	57.4	119.3	48.7	—
1980-81	1651	27.5	32.1	43.6	51.0	129.4	62.8	—
1981-82	1651	27.5	31.3	42.2	50.1	129.4	71.3	—
1982-83	1651	27.7	29.1	41.0	50.4	125.8	82.9	—
Public Limited Companies (Small, Medium and Large)								
1982-83	1838	27.7	29.3	41.4	50.6	124.4	84.5	91.5
1983-84	1838	26.3	28.0	43.9	55.7	118.2	87.7	100.3
1984-85	1838	24.7	28.4	45.3	57.4	117.4	83.6	104.7
1983-84	1867	26.3	28.3	43.8	57.1	117.0	89.3	101.7
1984-85	1867	24.7	28.5	45.5	58.6	115.9	84.3	104.4
1985-86	1867	25.3	28.4	46.5	59.3	111.3	77.1	110.1
1985-86	1953	25.6	28.1	44.4	57.3	111.2	78.7	110.7
1986-87	1953	25.7	27.1	48.0	60.8	104.7	85.1	117.4
1987-88	1953	25.2	27.6	48.8	61.1	105.9	86.8	118.0
Large Public Limited Companies								
1975-76	415	30.4	31.9	47.2	51.1	119.2	45.3	—
1976-77	415	27.2	31.6	50.2	54.9	108.1	46.6	—
1977-78	415	26.3	32.2	50.3	55.1	112.0	48.2	—
1982-83	535	27.7	30.1	37.5	46.7	123.9	79.8	—
1983-84	535	25.8	30.0	40.0	52.1	114.3	82.5	—
1984-85	535	24.5	29.3	40.5	52.6	112.6	80.0	—
1985-86	621	25.8	29.2	40.0	51.7	110.4	74.3	102.7
1986-87	621	25.2	28.3	42.9	54.1	101.2	80.3	108.6
1987-88	621	24.5	28.9	42.0	52.9	102.6	83.5	111.8
1986-87	622	25.6	28.6	42.8	55.4	102.1	79.8	106.4
1987-88	622	25.0	29.1	44.4	56.1	100.3	79.2	103.2
1988-89	622	26.0	31.0	45.6	57.3	102.2	82.8	104.4

## RBI Refinance

### (i) Export Credit Refinance

6.29 Export credit refinance limits of scheduled commercial banks declined from Rs. 4,346 crore in the fortnight ended June 30, 1989 to Rs. 4,118 crore in the fortnight ended June 29, 1990 (Table 6.12). The percentage utilisation of the limits ranged between 12.5 per cent and 100.6 per cent. When the base for the purpose of determining export credit refinance limits of banks was shifted (with effect from July 29, 1989), from the monthly average export credit for 1986 to that for 1987, the ratio of export refinance limits to outstanding export credit declined from 62.3 per cent as on July 28, 1989 to 51.1 per cent as on August 11, 1989, but

again rose to 54.7 per cent as on November 3, 1989. Effective from November 4, 1989, banks were eligible for export credit refinance limits to the extent of 75 per cent of the increase in their export credit over the monthly average level of outstanding export credit for 1987. As a result, the ratio of export credit refinance limits to export credit declined to 41.8 per cent as on November 17, 1989. Thereafter, it increased gradually up to 46.3 per cent by June 29, 1990. During the period July 1989—June 29, 1990 the peak level of utilisation was Rs. 4,271 crore or 98.4 per cent in the fortnight ended July 28, 1989 and trough level was Rs. 399 crore or 12.5 per cent in the fortnight ended December 1, 1989.

Table 6.12: RBI Accommodation to Scheduled Commercial Banks  
(excluding special refinance against shipping loans, duty drawback, etc.)

(Rupees crore)										
As on the last reporting Friday of	Export Credit Refinance		Stand-by Refinance		Discretionary Refinance		182 Days Treasury Bill Refinance		Total Refinance	
	Limit	Outstand- ing	Limit	Outstand- ing	Limit	Outstand- ing	Limit	Outstand- ing	Limit	Outstand- ing
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1989										
March	3,007.1	2,873.8	74.0	54.0	462.5	365.0	53.1	21.3	3,596.7	3,314.1
June	4,345.8	1,987.8	9.0	—	484.5	—	134.3	—	4,973.6	1,987.8
September	3,770.3	2,096.9	—	—	462.5	0.7	383.0	—	4,615.8	2,097.6
December	3,257.4	2,201.0	—	—	460.6	26.5	324.4	—	4,042.4	2,227.5
1990										
March	3,564.0	2,133.4	—	—	476.2	85.2	209.7	2.5	4,249.9	2,221.1
April	3,782.6	2,652.6	5.0	—	508.7	89.7	223.3	—	4,519.6	2,742.3
May	4,057.7	3,716.4	22.0	20.0	511.0	186.7	268.0	2.5	4,858.7	3,925.6
June	4,118.2	2,338.5	11.0	9.0	433.1	—	429.7	—	4,992.0	2,347.5

Note: As the outstanding level of food credit by scheduled commercial banks continued to remain below the threshold of Rs. 5,800 crore, the banks did not have a access to refinance under this facility.

#### (ii) Stand-by Refinance

6.30 Stand-by refinance limits (granted against the collateral of approved securities, that is, for those banks having excess SLR), ranging between Rs. 5 crore and Rs. 22 crore, were sanctioned to three scheduled commercial banks during the period July 1, 1989—June 29, 1990, which were utilised rather sparingly.

#### (iii) Discretionary Refinance

6.31 Total limits sanctioned to scheduled commercial banks under the discretionary refinance facility (including limits under the facility to draw without prior approval from the Reserve Bank) declined from Rs. 485 crore in the fortnight ended June 30, 1989 to Rs. 433 crore in the fortnight ended June 29, 1990. During this period, while the maximum limits sanctioned under this facility amounted to Rs. 523 crore including additional refinance limits in the fortnight ended June 1, 1990, the peak level of utilisation was Rs. 278 crore (69.0 per cent) as on March 31, 1990. As mentioned earlier, to ensure that monetary aggregates were not distorted at the end of March 1990, the facility to scheduled commercial banks to draw discretionary refinance without prior sanction from the Reserve Bank was withdrawn during the fortnight March 24 to April 6, 1990. When some banks experienced a liquidity bind, they were provided discretionary refinance limits on a selective basis during that fortnight to the extent of Rs. 444 crore. Against these limits, the maximum utilisation was Rs. 278 crore (69.0 per cent) as on March 31, 1990.

#### (iv) Refinance against 182 Days Treasury Bills

6.32 Limits under the refinance facility against 182 Days Treasury Bills gradually increased from Rs. 134 crore as on June 30, 1989 to Rs. 430 crore as on June 29, 1990. The maximum availment under this facility amounted to Rs. 106 crore (55.5 per cent) as on October 18, 1989. Banks clearly find dealings with DFHI more attractive than utilisation of Reserve Bank Refinance and this facility is essentially a fall back and is used by banks on very rare occasions.

#### (v) Overall Position of Refinance

6.33 Total refinance limits available to banks under various facilities (excluding special refinance against shipping loans,

duty drawback etc.) stood at Rs. 4,974 crore as on June 30, 1989. As on July 14, 1989 total limits sanctioned to banks aggregated to Rs. 5,655 crore which was the peak level of limits sanctioned during the period July 1, 1989—June 29, 1990. The utilisation as on that date was to the extent of Rs. 1,988 crore (40.0 per cent). Export credit refinance limits accounted for a major proportion (86.8 per cent) of total refinance limits. Total refinance limits to scheduled commercial banks as on June 29, 1990 amounted to Rs. 4,992 crore which were utilised to the extent of Rs. 2,347 crore or 47.0 per cent. During the period July 1, 1989—June 29, 1990, peak level of utilisation was at Rs. 4,272 crore or 84.5 per cent of the limits as on July 19, 1989.

#### Credit Budgets

6.34 During the period under the review, the credit budgets of 57 scheduled commercial banks for 1989-90 were examined. Discussions were held with the Chief Executives of 21 public sector banks and 3 foreign banks during May-August 1989. During the discussions, the banks were advised to plan their credit expansion on the basis of the expected growth of their own stable resources. Secondly, banks were advised to give increased attention to funds management and it was emphasised that reliance on the money market should be limited to meeting marginal requirements for equilibrating sources and uses of funds and not for meeting structural imbalances. Thirdly, banks were cautioned that they should not plan their credit on the basis of unchanged refinance facilities from the Reserve Bank as overall monetary policy requirements could warrant changes in these facilities. It was reiterated to banks that they should not lend in the money market while having outstandings under discretionary and stand-by refinance facilities. Fourthly, to the extent that banks' liabilities are of a volatile or transient nature, banks would do well to have a matching portfolio of short-maturing and near-liquid assets. In this connection, banks were strongly urged to invest a part of their liquid assets in 182 Days Treasury Bills. Fifthly, it was emphasised to banks that while new money market instruments were being introduced with freedom for banks to determine interest rates on these instruments, there should be an orderly relationship between interest rates and maturities. Finally, banks were advised to desist from window dressing their deposits/credit in the last week of March 1990.

#### Incremental Net Non-food Credit-Deposit Ratio-Norms and Achievements

6.35 Consequent upon the introduction of the measure relating to incremental net non-food credit-deposit ratio,

effective from the fortnight ended November 17, 1989, discussions were held with seven public sector banks during December 1989-January 1990 and these banks were advised to take effective steps to bring down their incremental net non-food credit-deposit ratio which was way above the stipulated level of 60 per cent.

6.36 As indicated earlier, the stipulation of 60 per cent incremental net non-food credit-deposit ratio on scheduled commercial banks, had a moderating influence on non-food credit expansion during the financial year 1989-90. The incremental net non-food credit-deposit ratio of scheduled commercial banks at 57.3 per cent during 1989-90 was thus considerably lower than that of 70.6 per cent during 1988-89. As depicted in Graph B, the ratio for the system as a whole consistently remained sizeably above that in the corresponding period of the previous year till October 1989 but after this measure was introduced effective November 4, 1989 the ratio was lower than in the previous year. Although the number of banks which exceeded the stipulated ratio varied from fortnight to fortnight (ranging from 10 to 17), it was observed that towards the year-end as on March 23, 1990, incremental non-food credit-deposit ratio of 16 out of 74 scheduled commercial banks was in excess of 60 per cent over the financial year period March 24, 1989 to March 23, 1990 and the total amount of the excess over the stipulation was Rs. 1051 crore. The stipulation of an incremental net

non-food credit-deposit ratio of 60 per cent continues to be in operation during 1990-91

#### Developments in the Short-Term Money Market

6.37 The policy measures relating to the money market have already been covered while reviewing the developments in credit policy. The highlights of activities in the money market during the year are set out below :

#### Discount and Finance House of India Limited (DFHI)

6.38 The Discount and Finance House of India Limited (DFHI) continued to play a vital role in developing an active secondary market in money market instruments. The DFHI has effectively made the 182 Days Treasury Bills a highly liquid instrument and the DFHI's operations have stimulated considerable activity in the secondary market for 182 Days Treasury Bills. The DFHI continued to render valuable service in the inter-bank call money market. In December 1989, the DFHI was permitted to operate in the inter-bank term deposit market, both as a lender and a borrower.

6.39 The DFHI's holdings of 182 Days Treasury Bills and commercial bills at the end of March 1990 amounted to Rs. 512 crore and Rs. 705 crore, respectively, while at the end of March 1989 the holdings were Rs. 382 crore and Rs. 628 crore, respectively. (Table 6.13)

Table 6.13 : DFHI's Holdings of 182 Days Treasury Bills and Commercial Bills

(Rupees crore)

As at the end of the month	182 Days Treasury Bills			Commercial Bills		
	1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7
April	10.34	165.97	—	—	133.00	390.25
May	0.25	256.01	260.50	0.02	230.41	297.00
June	1.31	4.40	41.05	0.02	120.80	201.25
July	72.50	88.10	5.20	—	175.93	140.75
August	69.25	21.31	116.00@	—	127.07	97.25@
September	50.00	102.65	—	—	92.38	—
October	30.25	258.30	—	—	187.14	—
November	30.75	221.96	—	8.00	175.50	—
December	159.50	182.80	—	8.00	80.50	—
January	94.80	16.00	—	1.50	132.50	—
February	292.50	445.20	—	85.50	407.50	—
March	381.80	511.50	—	627.70	704.50	—

@As on August 10, 1990

6.40 Consistent with the objective of increasing the turnover of money market assets rather than becoming a mere repository of these assets, DFHI's turnover in money market assets showed a quantum jump in the financial year 1989-90. DFHI's cumulative turnover of 182 Days Treasury Bills in 1989-90 was Rs. 21,953 crore which was nearly double the turnover in the preceding year. As the fortnightly average outstandings of 182 Days Treasury Bills in the system during April 1989-March 1990 amounted to Rs. 777 crore, this meant that the DFHI was able to turnover the system's holdings of Treasury Bills by 28 times. Because of the 'repos' facility provided by the DFHI (to banks, financial institutions and mutual funds) these institutions are able to earn an income by investing their money for short periods and also raise

money for short periods without having to divest their investment. In 1990-91 (upto August 10, 1990), the DFHI's cumulative turnover in 182 Days Treasury Bills was Rs. 11,176 crore.

6.41 The DFHI's cumulative turnover of commercial bills in the year 1989-90 at Rs. 10,682 crore was substantially higher than the turnover in the preceding year which was only Rs. 2,866 crore (Table 6.14).

6.42 The turnover of the DFHI in the call money market during 1989-90 rose sharply to Rs. 87,927 crore, as compared with a turnover of Rs. 20,362 crore in 1988-89. The DFHI's daily average turnover in the call money market rose from

Table 6.14 : Cumulative Turnover of the DFHI in Money Market Instruments

(Rupees crore)				
	1989-90 (April-March)	1988-89 (April-March)	1990-91 (Upto August 10)	1988-89 (Upto August 12)
1	2	3	4	5
182 Days Treasury Bills	21,953	11,204	11,176	6,045
Commercial Bills	10,682	2,866	3,967	3,856
Call Money	87,927	20,362	50,375	37,922
Term Deposits	244	—	508	—
Certificates of Deposit	3	—	—	—
Commercial Paper	26	—	35	—

Rs. 82 crore in 1988-89 to Rs. 242 crore in 1989-90. In 1990-91 upto August 10, 1990, the DFHI's cumulative turnover in call money assets was Rs. 50,375 crore or a daily average of Rs. 382 crore (Table 6.14).

6.43 In order to play its role in the secondary market effectively, the DFHI augmented its resources by raising its authorised share capital from Rs. 100 crore to Rs. 250 crore and its paid-up capital from Rs. 100 crore to Rs. 150 crore. It also continued to avail of refinance facilities from the Reserve Bank of India against the collateral of 182 Days Treasury Bills and short-term commercial bills. During the year under review, the Reserve Bank of India sanctioned to the DFHI peak refinance limits of Rs. 600 crore against the collateral of 182 Days Treasury Bills and Rs. 500 crore against commercial bills (Table 6.15). During 1989-90, the

rates of interest for refinance against 182 Days Treasury Bills ranged between 9.50 per cent and 12.00 per cent annum and for commercial bills between 13.00 per cent and 20.00 per cent per annum (Table 6.16). The rates of interest charged on the refinance made available to the DFHI are adjusted by the Reserve Bank of India, depending on the conditions in the money market and small discrete changes in the refinance rates have a ripple effect through the money market especially as the changes in the refinance rates are applicable on the DFHI's outstanding borrowings from the Reserve Bank while the DFHI in turn has to adjust its rates on only transactions entered into subsequent to the change in the interest rates on Reserve Bank refinance. In 1989-90 (July-June), the Reserve Bank's rate of refinance was altered on 40 occasions for Treasury Bills and on 15 occasions for commercial bills.

Table 6.15 : Reserve Bank Refinance to DFHI

(Rupees Crore)								
Refinance against the collaterals of 182 days Treasury Bills					Refinance against short-term Commercial Bills			
As on the last-day of the month	Limit	Outstanding	Peak level utilisation during the month	Limit corresponding to the peak utilisation as in Col. 4	Limit	Outstanding	Peak level utilisation during the month	Limit corresponding to the peak utilisation as in Col. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1989								
July	100 00	79 29	79.29	100	100 00	—	—	—
August	100 00	—	100 00 (2-8-1989)	100	100 00	—	—	—
September	100 00	92 38	92 38 (29-9-1989)	100	100 00	—	—	—
October	100 00	—	375 97 (18-10-1989)	400	100 00	—	95.77 (26-10-1989)	100
November	400 00	—	338 69 (22-11-1989)	550	100 00	—	149 72 (16-11-1989)	150
December	100 00	—	218 73 (20-12-1989)	300	100 00	—	—	—
1990								
January	100 00	14 40	200 00 (6-1-1990)	200	100 00	—	—	—
February	500 00	400 68	400 68	500	200 00	195 61	195 61	200
March	500 00	460 35	506 70 (9-3-1990)	600	500 00	492 64	492 64	500
April	300 00	—	460 35 (1-4-1990)	500	100 00	24 05	492 64 (1-4-1990)	500
May	300 00	—	316 89 (22-5-1990)	400	100 00	—	195 12 (16-5-1990)	200
June	100 00	—	140 58 (18-6-1990)	200	100 00	—	—	—
July	100 00	—	169 20 (17-7-1990)	200	100 00	—	—	—

6.44 The DFHI was also provided with a line of credit of Rs. 100 crore from 28 public sector banks on a consortium basis at an interest rate of 12 per cent per annum. This limit was periodically utilised by the DFHI during the year.

#### Remission of Stamp Duty on Bills of Exchange

6.45 Although the incidence of stamp duty on usance bills of exchange was small, the cumbersome procedure and the difficulty in obtaining stamps of requisite denominations was greatly inhibiting the development of the bill market. This major administrative constraints has since been removed. On the recommendations of the Reserve Bank of India, the Government of India, vide their Notification dated August 1, 1989 remitted stamp duty on usance bills of exchange, where :

Table 6.16 : Interest Rates for Reserve Bank Refinance to

#### DFHI

##### Refinance against holdings of 182 days Treasury Bills

Effective Date	Rate of Interest per cent per annum)
1	2
April 11, 1989	10.25
June 3, 1989	10.00
June 6, 1989	9.75
June 28, 1989	9.50
October 11, 1989	9.75
October 12, 1989	10.00
October 16, 1989	10.25
October 17, 1989	10.50
October 23, 1989	10.25
October 24, 1989	11.00
October 31, 1989	9.50
November 6, 1989	10.00
November 8, 1989	10.50
November 10, 1989	11.00
November 16, 1989	11.50
November 21, 1989	11.75
November 23, 1989	11.00
December 4, 1989	10.00
December 13, 1989	9.50
December 18, 1989	10.00
December 20, 1989	10.50
December 26, 1989	9.50
January 1, 1990	10.00
January 17, 1990	9.50
February 5, 1990	10.00
February 8, 1990	9.50
February 19, 1990	10.50
February 24, 1990	11.00
February 28, 1990	11.50
March 3, 1990	11.00
March 20, 1990	10.50
March 24, 1990	11.00
March 26, 1990	11.50
March 29, 1990	12.00
March 31, 1990	11.50
April 10, 1990	10.50
May 2, 1990	9.50
May 7, 1990	10.00
May 16, 1990	10.50
May 21, 1990	11.25
May 26, 1990	10.75
June 2, 1990	10.25
June 18, 1990	10.50
June 25, 1990	10.00
July 2, 1990	10.50
July 9, 1990	10.00
July 15, 1990	10.50
July 21, 1990	10.00

##### Refinance against Commercial Bills

1	2
April 11, 1989	15.00
April 12, 1989	14.50
April 19, 1989	14.00
April 27, 1989	13.00
November 16, 1989	14.00
November 22, 1989	13.00
February 20, 1990	14.00
February 28, 1990	15.00
March 12, 1990	15.50
March 24, 1990	16.50
March 29, 1990	18.00
March 30, 1990	20.00
April 5, 1990	18.00
April 10, 1990	16.50
April 11, 1990	14.00
April 17, 1990	13.00
May 14, 1990	14.00
May 16, 1990	15.00
May 24, 1990	13.00

(a) such bills of exchange are payable not more than three months after date or sight ;

(b) such bills of exchange are drawn on or made by or in favour of a commercial bank or a co-operative bank; and

(c) such bills of exchange arise out of bonafide commercial or trade transactions.

This measure was expected to go a long way in improving the payment system by promoting the commercial bill culture.

#### Rediscounting of Commercial Bills

6.46 With a view to further enlarging the scope of bills rediscounting market, a few more institutions were permitted, on a selective basis, to participate in the bills rediscounting market during the year. Accordingly, during the year under review, Export-Import Bank of India, LIC Mutual Fund, Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit, Bhopal, Maharashtra State Co-operative Bank Limited, Bombay, Tamil Nadu State Apex Co-operative Bank Limited, Madras and Small Industries Development Bank of India were granted entry into the bills rediscounting market.

#### 182 Days Treasury Bills Auctions

6.47 During July-June 1989-90, 26 fortnightly auctions of 182 Days Treasury Bills were held upto June 27, 1990. The response to the auctions was encouraging. The cut-off annual yield of the accepted bids generally showed an increase from 9.75 per cent in the auction held on July 11, 1989 to 9.97 per cent in the auction held on June 27, 1990. The peak level of 182 Days Treasury Bills outstanding in the system was Rs. 1,439.44 crore as on June 29, 1990 (Table 6.17). Banks in particular have recognised the decided advantages of this versatile money market instrument and are increasing participating in the primary auctions and dealing actively in the secondary market.

#### Inter-Bank Participations (IBPs)

6.48 Only a few banks have so far issued inter-Bank Participations (IBPs) with risk sharing for small amounts; IBPs with a maturity of three months appear to be the preferred maturity. The interest rates have ranged between 14 per cent and 17 per cent per annum.

#### Certificates of Deposit (CDs)

6.49 During the year, the Scheme of Certificates of Deposit (CDs), introduced in June 1989, has shown significant growth. As regards the total permissible limits, for issue of CDs by the banking system, of Rs. 1,264 crore, worked out on the basis of 1 per cent of the fortnightly average outstanding aggregate deposits in 1988-89 (April-March), the outstanding amount of CDs issued by 36 banks as on April 20, 1990, before the limits for the issue of CDs were revised, was on the order of Rs. 1,247 crore (Table 6.18). The maturity of 3 months at the short end and one year at the long end are generally popular with investors.

Table 6.17 : 182 Days Government of India Treasury Bills

Date of Auction	Bids Tendered		Bids Accepted		Cut off price-for Rs 100 of face value	Cut-off yield (per cent per annum)	Total amount of Treasury Bills outstanding (Rs crore)	
	Number	Aggregate nominal amount (Rs crore)	Number	Aggregate nominal amount (Rs crore)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1989								
July	11	27	231.50	17	169.00	95.35	9.75	467.90
	26	13	87.00	12	84.00	95.34	9.78	539.80
August	9	22	179.00	15	142.50	95.34	9.78	657.05
	22	18	122.65	15	106.65	95.33	9.80	749.05
September	6	28	162.25	17	96.25	95.33	9.80	840.15
	20	24	216.95	13	127.95	95.33	9.80	965.85
October	4	17	70.50	10	46.00	95.33	9.80	990.85
	18	16	47.00	9	24.80	95.32	9.82	946.65
November	1	17	146.50	8	96.50	95.32	9.82	1,002.65
	15	4	6.20	1	2.20	95.36	9.73	995.35
	29	20	100.70	18	90.70	95.31	9.84	1,067.55
December	13	14	36.70	6	17.20	95.31	9.84	1,076.25
	27	23	138.80	17	102.80	95.30	9.86	1,106.55
1990								
January	10	15	81.00	9	40.00	95.30	9.86	977.55
	23	15	126.50	13	115.50	95.29	9.89	1,009.05
February	7	19	131.35	12	80.10	95.29	9.89	946.65
	20	16	81.55	11	65.95	95.28	9.91	905.95
March	7	18	64.30	11	29.05	95.27	9.93	838.75
	21	15	80.00	10	63.50	95.26	9.95	774.30
April	4	13	62.00	5	37.50	95.26	9.95	765.80
	18	24	130.40	16	82.90	95.25	9.97	823.90
May	2	18	111.34	10	60.84	95.25	9.97	788.24
	16	22	286.10	9	200.10	95.25	9.97	986.14
	30	15	351.00	9	305.50	95.25	9.97	1,200.94
June	13	19	227.00	8	612.50	95.25	9.97	1,346.24
	27	21	258.00	11	196.00	95.25	9.97	1,439.44
July	11	21	149.00	10	90.50	95.25	9.97	1,489.94
	25	20	194.00	11	101.50	95.25	9.97	1,475.44
August	8	27	536.00	19	416.00	95.25	9.97	1,811.34

Although the rates of interest for maturity of 3 months ranged between 9.0 per cent and 16.33 per cent, the rates typically offered for 3 months were in the interval of 11.0 per cent to 12.5 per cent. For maturity of one year, the rates ranged between 10.5 per cent and 14.29 per cent. The interest rates offered on CDs are considered relatively high taking into account the fact that CDs are subject to reserve requirements. Despite the large size of the primary market for CDs, there has been virtually no activity in the secondary market. This is, to some extent, attributable to the fact that CDs have been priced very high and holders in the primary market generally prefer to hold the CDs to maturity. Consequent upon the decision to raise the bank's limit for issue of CDs

Table 6.18 : Issue of Certificates of Deposit (CDs) by Scheduled Commercial Bank

Fortnight ended	Number of banks which issued CDs (as at the end of the fortnight)	Total Out-standings (Rupees crore)	Effective interest rate (Range) of CDs issued during the fortnight for all maturities (per cent per annum)	
	1	2	3	4
1989				
July	28	12	125	9.00—14.00
August	11	20	216	9.00—12.50
	25	23	294	10.25—12.50

	1	2	3	4
September	8	25	326	10.00—12.00
	22	28	383	10.00—12.50
October	6	30	457	10.00—12.50
	20	32	502	10.00—15.00
November	3	34	568	10.25—12.50
	17	35	648	10.25—13.00
December	1	36	716	10.00—12.70
	15	36	783	9.50—12.67
	29	36	826	10.00—13.03
1990				
January	12	36	824	10.00—13.50
	26	35	846	10.00—14.16
February	9	35	897	10.50—13.00
	23	35	929	10.00—13.64
March	9	34	1,023	11.00—13.66
	23	36	1,103	11.50—13.50
April	6	36	1,228	10.50—16.25
	20	36	1,247	10.00—12.50
May	4	36	1,318	11.00—13.50
	18	36	1,440	10.00—13.50
June	1	36	1,454	10.00—16.14
	15	36	1,729	10.00—14.71
	29	37	1,826	10.00—16.33



on the basis of 2 per cent of the fortnightly average outstanding aggregate deposits in 1989-90 (April-March), the aggregate limit for the banking system for issue of CDs worked out to Rs. 3,017 crore and the outstandings of 37 major banks as on July 13, 1990 worked out to Rs. 2,000 crore or 70.4 per cent of the total limits of these banks.

#### Commercial Paper

6.50 Commercial Paper (CP) is the second new instrument to appear in the money market during the financial year 1989-90. In January 1990, the Reserve Bank issued detailed guidelines to banks which are set out in 'Non-Banking Companies (Acceptance of Deposits through the Commercial Paper) Directives, 1989'. The issue of CP implies for the banking system as a whole that a part of its loan portfolio will be securitised. The Reserve Bank of India authorises issue of CP at fortnightly interval, this interval being necessitated from the viewpoint of queuing to enable companies authorised to issue CP to complete their formalities in a fortnight before the next batch of the companies enters the market. Moreover, eligibility for entering into the CP market is based on transparent norms which companies can readily assess for themselves. It is important to ensure that CP develops as a sound instrument and it is pertinent to mention that even in developed financial markets central banks found it necessary to regulate an orderly queue in the initial stages of development of the CP market.

6.51 Since January 1990, companies have been authorised to issue CP. As on August 10, 1990, the outstanding amount of CP issued by 16 companies was Rs. 155.50 crore. All the CP issues have a uniform maturity period of 180 days. The effective rates of interest on CP issued ranged between 11.87 per cent and 13.32 per cent. It is of interest to note that despite the limited amount of CP issues, some secondary market transactions have taken place. With the relaxation of guidelines relating to the issue of CP in April 1990, the issue of CP by companies is expected to gain further momentum.

#### Movements in Call Money Rates

6.52 During the year under review the call money market experienced periods of considerable volatility in interest rates. A broad pattern observed was that call money rates rise sharply in the first week of the reporting fortnight and subside in the second week when banks have covered their cash reserve requirements. With the freeing of the call money rates from May 1, 1989, many banks are alternating between lending and borrowing and thus are contributing to a reduction in the lopsidedness of the market. Data relating to trough, peak and average of middle rates of lending rates of DFHI in the call money market are set out in Table 6.19.

6.53 The extreme volatility in the call money rates is attributable inter alia to the following factors. Large borrowings being undertaken on certain days to meet the cash reserve requirements on a product basis, and once CRR is met the demand for funds falls sharply. Also, the credit operations of certain banks are not commensurate with their own resources and these banks have an over-extended credit position. These banks treat the call money market as a source for meeting structural disequilibria in the sources and uses of funds. Apart from other factors, the extreme volatility in the call money market can be traced to a certain extent to the issue of funds management in banks. The increase in the participants in the call money market and the softening of the penalties on CRR shortfalls should also help to moderate the interest rate peaks in the money market. Illustratively, the cost of the shortfall on the basis of the earlier schedule of graduated penalties was around 150 per cent for a shortfall of 5 per cent while the penalty under the revised schedule would be around 30 per cent. The extreme volatility in the call money rates would be reduced only when the few banks which are large chronic borrowers, moderate their reliance on the call money market to maintain reserve requirements

Table 6.19 : Call Money Lending Rates of DFHI

For the Fortnight Ending	Lending Rate (per cent per annum)		
	Trough	Peak	Average* of Middle Rate
1	2	3	4
July 14, 1989	5.50	11.00	9.85
July 28, 1989	6.50	10.50	8.85
August 11, 1989	8.25	12.00	9.85
August 25, 1989	7.25	10.75	9.30
September 8, 1989	7.25	10.50	9.15
September 22, 1989	8.75	10.75	9.60
October 6, 1989	6.50	13.50	11.30
October 20, 1989	10.50	20.00	14.80
November 3, 1989	8.75	21.00	15.15
November 17, 1989	14.50	27.00	18.70
December 1, 1989	7.00	25.00	13.20
December 15, 1989	7.50	13.50	10.45
December 29, 1989	9.25	15.50	12.35
January 12, 1990	10.50	15.00	12.35
January 26, 1990	8.75	14.00	10.85
February 9, 1990	6.50	12.75	11.10
February 23, 1990	10.25	25.00	15.80
March 9, 1990	7.00	28.00	16.65
March 23, 1990	10.00	34.00	21.50
April 6, 1990	10.00	58.25	40.05
April 20, 1990	13.00	22.00	15.90
May 4, 1990	8.75	23.75	17.50
May 18, 1990	13.00	36.00	23.00
June 1, 1990	9.50	38.00	21.65
June 15, 1990	13.00	14.00	13.50
June 29, 1990	11.00	11.50	11.50
July 13, 1990	8.50	13.75	11.45
July 27, 1990	7.50	12.25	10.10
August 10, 1990	8.00	11.00	9.50

\*This is a simple average of daily middle rates.

## 7. REVIEW OF THE PRICE SITUATION

7.1 The overall rate of price increase, which got moderated to some extent in 1988-89, again accelerated in 1989-90, despite a good Kharif output on top of the bumper crop of the previous year. During 1989-90, apart from the marked acceleration, the seasonal rise in prices was high while the seasonal decline was weak, thus reflecting the underlying inflationary pressures. These pressures were also of a generalised character with substantial and widespread price increases amongst manufactured products as much as amongst 'primary articles'. Such pressures on commodity prices have further intensified during the first quarter of the current financial year 1990-91, particularly amongst 'primary articles'. This inflationary situation has been the cumulative result of a number of factors operating in the economy during the past year and a half such as supply-demand imbalances of some essential commodities like pulses, tea, sugar, oilseeds, edible oils and cement, constraints in augmenting supplies of commodities in short supply through imports owing to the tight foreign exchange reserves situation, increases in administered prices of agricultural and industrial products, the rise in import costs, and above all the higher growth of liquidity arising from fiscal deficits coupled with the excessive monetary growth of the previous year.

7.2 On a point-to-point basis, the rise in the Wholesale Price Index (WPI) in 1989-90 was 9.1 per cent which was higher than the increase in the previous year by 3.4 percentage points. A number of articles of mass consumption like

pulses, tea, sugar, khandasari and gur, edible oils and cotton textiles showed sharp increases on a point-to-point basis in 1989-90. All these commodities, excepting edible oils, had also registered large increases in the previous year. In the case of pulses and sugar, khandasari and gur, there was a marked spurt in prices for the third year in succession. It is also pertinent to note that prices of cereals which showed a decline, on a point-to-point basis, registered an increase on an average basis on top of a large spurt in the previous year. Besides, prices of rice, tea, milk and sugar, khandasari and gur, recorded higher price increases on an average basis than is revealed by a point-to-point comparison. An encouraging development has been the decline on a point-to-point

basis in the price index of cereals in 1989-90 on account of a sizeable decline in the price index of wheat.

#### Annual Trends

7.3 The rate of rise in WP1 (base : 1981-82=100), on a point-to-point basis, which decelerated to 5.7 per cent in 1988-89 from a high of 10.7 per cent in the drought year of 1987-88, accelerated again to 9.1 per cent in 1989-90 (Table 7.1), despite the good kharif output which followed the bumper crop of 1988-89. On an average basis, however, the increase in WPI at 7.4 per cent was the same as that in the previous year.

Table 7.1 : Index Numbers of Wholesale Prices : Major Commodity Groups

(Base : 1981-82=100)

Major Groups	Weight	Wholesale Price Indices					Variations in per cent			
		March 26, 1988	March 25, 1989	March 31, 1990	July 1, 1989	June 30, 1990*	Fiscal years		First quarters	
							1988-89 (Col. 4 over Col. 3)	1989-90 (Col. 5 over Col. 4)	1989-90 (Col. 6 over Col. 4)	1990-91 (Col. 7 over Col. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
All Commodities	100.00	148.5	156.9	171.1	162.9	177.5	5.7	9.1	3.8	3.7
Primary Articles	32.295	157.1	156.8	166.9	162.6	181.3	-0.2	6.4	3.7	3.6
Fuel, Power, Light and Lubricants	10.663	147.7	155.2	164.9	155.5	166.2	5.1	6.3	0.2	0.8
Manufactured Products	57.042	143.9	157.2	174.7	164.4	177.4	9.2	11.1	4.6	1.5

\*Provisional

7.4 The Consumer Price Index (CPI) for Industrial Workers (base : 1982=100) increased by 6.6 per cent both on point-to-point and average bases in 1989-90 as compared with corresponding increases of 3.6 per cent and 9.1 per cent in the previous year. The lower rate of increase in terms of the CPI is partly explained by the decline in the prices of cereals, particularly wheat, in 1989-90.

#### Group-wise Trends

7.5 Group-wise, on a point-to-point basis, while the index of 'primary articles' experienced a sizeable increase in 1989-90, in contrast to a marginal decline in 1988-89, the index of 'manufactured products' showed an acceleration in its rate of increase. The third major group fuel, power, light and lubricants' also experienced a slightly higher increase than in the previous year. Thus, while the rise in the index of 'primary articles' was markedly higher at 6.4 per cent in contrast to a decline of 0.2 per cent in the previous year, the index of 'manufactured products' rose by 11.1 per cent as against 9.2 per cent in 1988-89; the 'fuel' group index rose by 6.3 per cent as against 5.1 per cent in the previous year. On an average basis, the trends revealed by the group-wise indices presented a different picture due to their differing seasonal behaviour. The 'primary articles' group showed a rise of 2.1 per cent as compared with a rise of 4.9 per cent,

the 'manufactured products' group showed a higher rise of 11.3 per cent as against a rise of 9.4 per cent, and the 'fuel' group, a smaller rise of 3.6 per cent as compared with 5.4 per cent in the previous year.

#### Seasonal Behaviour

7.6 An analysis of seasonal behaviour of wholesale prices (Table 7.2), on a point-to-point basis, shows that in the first phase, covering the period between end-March and end-August, 1989, the price rise was much sharper than that in the corresponding period of the previous year. In the second phase, covering the period between end-August and end-December, which is normally characterised by a seasonal decline in the WPI, there was only a marginal decline in prices (-0.4 per cent), in the comparable phase of the previous year, the WPI (general index) had shown no variation. During the last phase, covering the period end-December to end-March, there was a somewhat higher price rise as compared with the last phase of 1988-89. Though the seasonal trends revealed by the index of the 'primary articles' group in 1989-90 were consistent with the usual seasonal pattern (it was not so in the previous year), the extent of the increases in the group's index in the two rising phases (i.e. 6.8 per cent in the first phase and 3.3 per cent in the last phase) were noticeably high.

Table 7.2 : Three Phases of Variations in Wholesale Price Index  
(Base : 1981-82=100)

(Percentage variations on a point-to-point basis)

Major Groups	Phase I			Phase II			Phase III		
	End-March to End-August			End-August to End-December			End-December to End-March		
	1987-88	1988-89	1989-90	1987-88	1988-89	1989-90	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
All Commodities	8.1	3.9	6.5	0.9	-	-0.4	1.4	1.7	2.8
Primary Articles	16.3	2.8	6.8	-1.3	-0.5	-3.5	0.8	-2.4	3.3
Fuel, Power, Light and Lubricants	1.2	1.5	0.5	3.0	0.7	0.8	1.0	2.8	4.9
Manufactured Products	4.8	5.0	7.3	1.9	0.1	1.1	2.0	3.9	2.3

## Commodity-wise Variations

7.7 Commodity-wise data on prices are presented on both point-to-point and average bases in Table 7.3. On a point-to-point basis rice prices showed a marginal increase of 1.6 per cent in 1989-90 as against a rise of 6.7 per cent in the previous year while wheat prices recorded a decline

of 16.6 per cent in contrast to a rise of 12.5 per cent in 1988-89, this is attributable to considerable improvement in supplies owing to sustained peak level output and substantially higher procurement of these commodities. Despite two good crops, prices of pulses registered a sharp rise of 11.2 per cent on top of a rise of 11.1 per cent recorded in the

Table 7.3 : Variations in Index Numbers of Wholesale Prices  
(Base : 1981-82=100)

Major Groups/Groups/Commodities	Weight	Percentage Variations during					
		Financial Year				First Quarter	
		Point-to-point basis		Average basis		Point-to-point basis	
		1988-89	1989-90	1988-89	1989-90	1989-90	1990-91 (P)
1	2	3	4	5	6	7	8
All Commodities	100 000	5.7	9.1	7.4	7.4	3.8	3.7
I. Primary Articles	32 295	-0.2	6.4	4.9	2.1	3.7	8.6
1. Food articles	17 386	3.6	2.1	9.9	1.2	5.1	11.2
a. Cereals	6 824	9.2	-6.2	11.7	2.2	-0.6	7.8
(i) Rice	3 685	6.7	1.6	10.5	4.7	4.8	5.6
(ii) Wheat	2 248	12.5	-16.6	14.6	-3.8	-10.1	-13.3
b. Pulses	1 093	11.1	11.2	30.2	2.9	8.8	6.3
c. Fruits and vegetables	4 089	-12.2	3.6	2.9	-8.1	15.7	25.7
d. Milk	1 961	15.9	4.5	13.7	8.9	5.8	1.9
e. Eggs, fish and meat	1 783	4.2	6.3	8.0	4.5	2.9	1.4
f. Condiments & Spices	0 947	-8.6	5.4	10.6	-13.8	-2.5	13.1
g. Other food articles	0 689	35.9	26.1	5.2	46.0	9.9	16.7
(i) Tea	0 564	41.4	29.7	5.4	55.0	12.8	16.2
2. Non-food articles	10 081	-7.0	13.4	-1.7	3.4	1.8	6.8
a. Fibres	1 791	12.0	-4.0	9.9	11.0	0.8	5.1
(i) Raw cotton	1 335	3.7	-17.6	5.6	4.3	-3.4	10.3
b. Oilseeds	3 861	-23.3	27.4	-15.4	1.4	7.5	11.6

1	2	3	4	5	6	7	8
3. Minerals	4.828	0.4	10.8	-1.9	1.7	1.2	-0.2
(i) Petroleum crude & natural gas	4.274	-2.1	12.5	-4.6	2.9	0.8	0.0
II. Fuel, Power, Light & Lubricants	10.663	5.1	6.3	5.4	3.6	0.2	0.8
a. Coking coal	0.353	13.3	0.0	16.2	9.9	0.0	0.0
b. Mineral oils	6.666	1.1	9.1	2.3	0.5	-0.2	0.5
c. Electricity	2.741	8.3	4.7	5.9	6.3	1.0	1.8
III. Manufactured Products	57.042	9.2	11.1	9.4	11.3	4.6	1.5
a. Sugar, Khandsari & gur	4.059	13.1	13.1	8.3	19.7	16.1	6.3
(i) Sugar	2.013	5.8	10.5	7.0	11.6	6.3	-0.8
(ii) Khandsari	0.300	8.6	36.4	9.7	32.2	30.4	-2.1
(iii) Gur	1.746	23.1	12.7	9.6	27.0	25.0	15.2
b. Edible oils	2.445	-7.4	17.2	-2.9	4.0	5.5	9.2
c. Cotton textiles	6.093	8.2	16.6	10.5	13.9	4.2	-0.3
d. Chemicals & chemical products	7.355	2.7	4.8	2.9	3.1	0.3	0.8
e. Cement	0.860	11.2	14.9	-4.4	11.0	-0.4	-0.7
f. Iron & steel	2.441	10.4	11.8	14.1	15.5	4.2	0.0

(P)—Provisional.

previous year. Tea prices recorded a further sharp rise of 29.7 per cent (41.4 per cent in 1988-89) owing to a short-fall in production and reduced domestic availability because of the pressure of international demand. As a result of lower availability, prices of oilseeds rose sharply by 27.4 per cent in contrast to a sharp decline (23.3 per cent) in the previous year. Likewise, with the shortfall in production and curtailment of imports, edible oil prices recorded a sharp rise of 17.2 per cent in contrast to a decline of 7.4 per cent in the previous year. In the case of sugar, prices rose by 10.5 per cent, over and above a rise of 5.8 per cent in the previous year, because of rising consumer demand and excessive speculative activity. Cotton textiles prices rose by 16.6 per cent on top of a rise of 8.2 per cent in 1988-89. Raw cotton is the only major commodity experiencing a marked fall in the price index by 17.6 per cent as a result of the bumper crop.

7.8 Wholesale prices data on an average basis reveal a strikingly different picture from those on a point-to-point basis in the case of certain commodities because of the carryover of seasonal influences from one financial year to another. Apart from the trends noticed earlier in the case of cereals, milk, tea and sugar, khandsari and gur, other important commodities which showed significantly different trends included pulses, fruits and vegetables, condiments and spices, oilseeds, petroleum crude and natural gas, cooking coal, minerals oils, and edible oils (Table 7.3).

## Weighted Contribution

7.9 An analysis of weighted contribution of different groups/commodities to the increase in the general index of wholesale prices reveals that, on a point-to-point basis the 'primary articles' group with a weight of 32.3 per cent in the general index contributed 23.0 per cent to the total price rise in 1989-90 as compared with a negative contribution of 1.2 per cent in 1988-89. The 'fuel' group with a weight of 10.7 per cent in the general index contributed 7.3 per cent as compared with that of 9.5 per cent in 1988-89. The bulk of the contribution came from the 'manufactured products' group which, with a weight of 57.0 per cent in the general index, accounted for 70.3 per cent of the total price rise in 1989-90 as against 90.3 per cent in 1988-89. Amongst the manufactured products, the weighted contribution of cotton textiles was 10.4 per cent and of sugar, khandsari and gur 4.9 per cent. On an average basis, the weighted contribution of the 'manufactured products' group to total price rise in 1989-90 at 85.6 per cent was much higher than that of 69.9 per cent in 1988-89 (Table 7.4), which shows the highly generalised nature of the price increase in the year under review.

7.10 The price situation worsened further in the first quarter of the financial year 1990-91. The general index of wholesale prices rose by 3.7 per cent during the first quarter (up to June 30, 1990) of 1990-91 against the increase of 3.8 per cent in the first quarter of 1989-90. Prices of articles of mass consumption such as rice, fruits and vegetables, condiments and spices, pulses, tea, gur and edible oils rose

Table 7.4 : Weighted Contribution of Commodity Groups to the Increase in the General Index of Wholesale Prices  
(Base : 1981-82=100)

Major Groups/Groups/Commodities	Weight	(Per cent)			
		Point-to-point basis		Average basis	
		1988-89	1989-90	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6
All Commodities	100.000	100.00	100.0	100.0	100.0
I. Primary Articles	32.295	-1.2	23.0	23.0	9.6
1. Cereals	6.824	11.0	-4.8	10.5	2.0
2. Pulses	1.093	2.4	1.6	4.8	0.6

1	2	3	4	5	6
3. Fruits & vegetables	4.089	-10.9	1.7	2.0	-5.4
4. Milk	1.961	6.2	1.2	4.1	2.8
5. Eggs, fish & meat	1.783	1.5	1.3	2.1	1.2
6. Condiments & spices	0.947	-2.4	0.8	2.3	-3.0
7. Other food articles	0.689	4.6	2.7	0.6	5.1
8. Fibres	1.791	3.9	-0.8	2.3	2.6
9. Oilseeds	3.861	-18.3	9.8	-10.0	-0.1
II. Fuel, Power, Light & Lubricants	10.663	9.5	7.3	7.8	5.1
1. Coal mining	1.256	3.8	0.1	3.4	2.2
2. Minerals oils	6.666	1.1	5.5	1.8	0.4
3. Electricity	2.741	4.6	1.7	2.5	2.7
III. Manufactured Products	57.042	90.3	70.3	69.9	85.6
1. Sugar, Khandasari & gur	4.059	7.3	4.9	3.7	8.9
2. Edible oils	2.445	-3.8	4.8	-1.2	1.5
3. Cotton textiles	6.093	8.1	10.4	7.6	10.4
4. Art silk cloth	0.058	0.1	0.1	0.0	0.1
5. Jute, hemp & mesta textiles	0.689	3.1	3.7	2.6	2.9
6. Iron & steel	2.441	4.8	3.5	4.7	5.4
7. Non-ferrous metals	1.025	7.8	0.7	4.0	4.1
8. Metal products	1.823	8.5	3.5	4.7	6.4

sharply; among these articles, pulses, fruits and vegetables, tea, gur and edible oils had recorded sharp price increase in the first quarter of 1989-90 also. Raw cotton prices, which had declined in the first quarter of 1989-90, again rose in the first quarter of 1990-91. On the other hand, sugar and khandasari prices, which had risen markedly in 1989-90, declined marginally in the first quarter of the current financial year. Group-wise, the price index of primary articles' registered a significant increase of 8.6 per cent as compared with an increase of 3.7 per cent in the comparable period of 1989-90. The index of 'fuel, power, light and lubricants' recorded a rise of 0.8 per cent against a rise of 0.2 per cent in the previous corresponding period. The 'manufactured products' group, however registered a relatively smaller increase of 1.5 per cent as compared with an increase of 4.6 per cent in the corresponding period of 1989-90.

#### Changes in Administered Prices

7.11 During 1989-90, while administered prices of some industrial products were revised with a view to compensating the producers for increases in their costs of production, substantial upward revisions in procurement/support prices of various agricultural commodities have been effected with a view to providing higher incentives to producers and thus augmenting production and achieving improved procurement of various agricultural commodities. In the light of the recommendations made by the Expert Committee for Review of Methodology of Costs of Production of Crops, the Government decided to include labour and managerial costs in the formula for computing costs of production of agricultural crops while fixing prices.

#### Agricultural Prices

7.12 The major changes in procurement/minimum support prices are presented in Table 7.5. The proportionate increases in such prices in the case of cereals, oilseeds, cotton and raw jute were considerably higher in the 1989-90 marketing

season than in the previous season. For the 1990-91 marketing season, procurement price of wheat has been raised twice, from Rs. 183 per quintal to Rs. 200 per quintal on August 30, 1989 and further to Rs. 215 per quintal on April 21, 1990, thereby resulting in a total increase of 17.5 per cent. The price of Rs. 215 per quintal came into force with retrospective effect from April 1, 1990 for sales effected by farmers prior to announcement of the change. The minimum support prices for 1990-91 for barley and gram have also been raised substantially by 24.1 per cent and 44.9 per cent respectively.

7.13 Consequent on the revision in procurement prices of wheat and rice, the issue price of wheat was raised from Rs. 204 per quintal to Rs. 234 per quintal or by 14.7 per cent from May 1, 1990 and the issue price of rice has been raised by Rs. 45 per quintal to Rs. 289, Rs. 349 and Rs. 370 for the common, fine and superfine varieties, respectively, from June 1, 1990.

#### Industrial Prices

7.14 Administered prices of industrial products are generally adjusted in line with their costs of production, or in some cases to restrain consumption. Such changes are also occasionally made to raise resources for meeting investment needs.

7.15 Prices of some items like steel were raised marginally during 1989-90 to take account of the increase in Railway freight. Amongst non-ferrous metals, not only price control on aluminium was done away with, its sale was also decontrolled. Prices of other non-ferrous metals such as copper, zinc, lead and nickel, which are largely imported and are subject to fluctuations in international prices and exchange rates, continued to be administered. Changes in the indices of the major items subsequent to upward revisions in their administered prices were petroleum crude

Table 7.5 : Minimum Support/Procurement Prices

(Rupees per quintal)

Agricultural Commodities		1988-89@	1989-90@	Percentage Variation (Col. 4 over Col. 3)	1990-91 @	Percentage Variation (Col. 6 over Col. 4)
1	2	3	4	5	6	7
Paddy	Procurement Price					
Average variety	—do—	160	185	+15.6	205	+10.8
Fine	—do—	170	195	+14.7	215	+10.3
Superfine	—do—	180	205	+13.9	225	+9.8
Wheat	—do—	173	183	+5.8	21	+17.5
					(200)*	
Jowar, Bajra, Maize and Ragi (fair average quality)	—do—	145	165	+13.8	180	+9.1
Barley	Minimum support price	135	145	+7.4	180	+24.1
					(160)*	
Gram	—do—	290	325	+12.1	471	+44.9
					(370)*	
Arhar, Moong, urad	—do—	360	425	+18.1	480	+12.9
Oilseeds	—do—					
Groundnut-in-Shells	—do—	430	500	+16.3	580	+16.0
Mustard/Rapeseed	—do—	430	460	+7.0	510	+10.9
Sunflower	—do—	450	530	+17.8	600	+13.2
Soyabean (yellow)	—do—	320	370	+15.6	400	+8.1
Soyabean (black)	—do—	275	325	+18.2	350	+7.7
Sugarcane	Statutory minimum price	19.50	22	+12.8	23	+4.5
Cotton (fair average quality)	Minimum support price	500	570	+14.0	620	+8.8
Kapas (Hybrid-4)	—do—	600	690	+15.0	750	+8.7
Raw Jute (W-5 grade Ex-Assam)	Statutory minimum price	250	295	+18.0	320	+8.5
VFC Tobacco (F-2) Black Soil	—do—	1175	1250	+6.4		

\*Figures within brackets relate to the mid-year revision of support prices for 1990-91 season, announced on August 30, 1989. They were subsequently revised on April 21, 1990.

@Marketing Season.

(12.5 per cent), mineral oils (9.1 per cent), iron and steel (11.8 per cent), non-ferrous metals (other than aluminium) (5.2 per cent), electricity (4.7 per cent), and coal mining (0.4 per cent).

7.16 The composite index of the administered prices of industrial products accordingly recorded a rise of 7.5 per cent in 1989-90 which was higher than that of 5.4 per cent in the previous year. The weighted contribution of the seven industrial product groups, whose prices are administered, namely, coal, iron and steel, non-ferrous metals (excluding aluminium), petroleum crude and natural gas, minerals oils, electricity and fertilizers with a weight of 19.697 per cent in the general index of wholcase prices, was, on a point-to-point basis, lower at 14.7 per cent in 1989-90 as compared with 16.9 per cent in the previous year. These increases, together with the increases in the Railway freight and indirect taxes, are likely to exert further pressure on prices.

#### Trends in Consumer Price Indices

7.17 The rate of price rise in terms of the CPI for Industrial Workers (base 1982=100) during 1989-90 both on point-to-point and average basis was 6.6 per cent as compared with 8.6 per cent on a point-to-point basis and 9.1 per cent on an average basis in 1988-89. On a point-to-point basis, the food index in the CPI rose by 5.0 per cent in 1989-90 which was less than half the rise of 10.5 per cent in the corresponding period of the previous year, essentially because of lower cereal prices.

7.18 The CPI for Urban Non-Manual Employees (base 1984-85=100) rose by 8.0 per cent during 1989-90 which

was 1.0 percentage point higher than that recorded in the previous year; on an average basis, the rise in 1989-90 (6.9 per cent) was lower than that in the previous year (8.2 per cent). The CPI for Agricultural Labourers (base : 1960-61 =100) registered smaller increases than those in 1988-89 both in terms of point-to-point and average bases : 10 per cent against 10.8 per cent on a point-to-point basis and 5.4 per cent against 12.7 per cent on an average basis.

7.19 During the first quarter (April-June) of 1990-91, the CPI for Industrial Workers rose, on a point-to-point basis, by 4.5 per cent as against a rise of 2.4 per cent in the first quarter of 1989-90. On an average basis also, the rise in the first quarter of 1990-91 at 8.1 per cent was higher than that of 7.7 per cent in the first quarter of 1989-90.

7.20 A comparison of the behaviour of WPI vis-a-vis those of the three consumer price indices reveals certain interesting features. First, after many years of higher rates of increases all the consumer price indices experienced lower increases than the rise in the wholesale price index during 1989-90 due to the fact that the price increases in the latter were much more generalised with substantially higher contribution from those industrial commodities which do not directly enter the consumption basket. Secondly, due to a relatively more diversified consumption basket, the CPI for Urban Non-Manual Employees registered by far the highest increase in 1989-90, in contrast, due to a relatively high weightage for cereals (whose prices alone amongst consumer goods have fallen), the CPI for Agricultural Labourers registered the lowest rate of increase. The increase in the CPI for Industrial Workers fell mid-way between those of the other two consumer price indices.

7.21 Inflation rates as measured by all the price indices, showed moderation during the Seventh Plan period (1985-86 to 1989-90) as compared with those during the Sixth Plan period (1980-81 to 1984-85). WPI rose at an annual rate of 6.6 per cent in the Seventh Plan as against 8.8 per cent in the Sixth Plan and the CPI for Industrial Workers at 8.0 per cent as against 10.1 per cent (Table 7.6). This relative moderation of inflation rate in the Seventh Plan was largely attributable to the drawing down of the large food stocks and augmentation of supplies of certain essential commodities through imports to mitigate excessive pressures on prices. The deceleration in the inflation rate in the Seventh Plan would have been still higher but for the high growth of overall liquidity emanating largely from fiscal imbalances. However, in the last three years of the Seventh Plan, the price rise has been substantially larger than in the first two years.

#### Bullion Prices

7.22 The average price of gold in the Bombay market recorded a marginal rise of 1.7 per cent in 1989-90 as

compared with a rise of 3.0 per cent in 1988-89. In comparison with the long-term rate of increase in the domestic price of standard gold of about 10 per cent per annum, the increase in gold price during the past two years has been moderate. The moderation in the gold price rise follows accelerated increases ranging from 7 per cent to 33 per cent in the previous five years (Table 7.7). Also, the premium on the domestic price of gold over its international price has ruled at very high levels during these years including 1988-89 (62.0 per cent) and 1989-90 (56.5 per cent) (Graph C).

7.23 The average price of silver in the Bombay market registered a rise of 7.5 per cent in 1989-90 on top of a rise of 15 per cent in 1988-89. The spread between the domestic and international prices shot up from 84 per cent in 1987-88 to 114 per cent in 1988-89 and further to 140 per cent in 1989-90. The spread between domestic price and international prices in almost all the years since 1985-86 has widened (see Graph D).

Table 7.6 : Annual Rates of Price increases as Reflected in Different Price Indices  
(Based on Annual Averages)

Year	WPI	CPI for industrial workers	CPI for urban non-manual employees	CPI for agricultural labourers	(Percentage increase)	
					Indices for Food Items	
					Composite Food index of WPI (Weight : 27.53%)	Food Index of CPI (Weight : 60.92%)
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	+17.7*	+11.4	+11.8	+14.2	+22.4*	+12.3
1981-82	+9.8*	+12.5	+12.1	+12.4	+6.5*	+13.6
1982-83	+2.6	+7.8	+8.0	+5.2	-0.8*	+6.7
1983-84	+7.5	+12.6	+10.2	+11.3	+12.7	+14.4
1984-85	+6.5	+6.4	+8.2	+0.2	+4.7	+4.5
Average for Sixth Plan	+8.8	+10.1	+10.1	+8.7	+9.1	+10.3
1985-86	4.4	+6.4	+6.7	+4.8	+2.2	+5.1
1986-87	+5.8	+8.8	+7.9	+4.8	+10.2	+9.7
1987-88	+8.2	+9.1	+8.9	+10.0	+8.9	+8.4
1988-89	+7.4	+9.1	+8.2	+12.7	+8.3	+10.5
1989-90	+7.4	+6.6	+6.9	+5.4	+4.9	+5.0
Average for Seventh Plan	+6.6	+8.0	+7.7	+7.5	+6.9	+7.7

\*As per the base 1970-71 = 100

Table 7.7 : Gold and Silver Prices in Bombay and International Markets

Year	Gold		Silver		Spread between Bombay & London prices	Spread between Bombay & New York prices
	Bombay Market (Rs. per 10 grammes for standard gold)		Bombay Market (Rs. per kg. for 0.999 fineness)			
	Year-End	Average	Year-End	Average	(average in percentages)	
1	2	3	4	5	Gold*	Silver**
1980-81	1,700 (27.8)	1,522 (31.3)	2,720 (2.4)	2,617 (13.9)	+2.5	-34.9
1981-82	1,645 (-3.2)	1,719 (12.9)	2,680 (-1.5)	2,636 (0.7)	+42.1	+0.3
1982-83	1,800 (9.4)	1,723 (0.2)	3,105 (15.9)	2,798 (6.2)	+37.8	-11.1

1	2	3	4	5	6	7
1983-84	1,975 (9.7)	1,159 (7.8)	3,570 (15.0)	3,506 (25.3)	+38.5	—0.3
1984-85	2,130 (7.8)	1,984 (6.8)	3,955 (10.8)	3,549 (2.5)	+53.3	+77.9
1985-86	2,140 (0.5)	2,126 (7.1)	4,015 (1.5)	3,918 (9.0)	+64.8	+63.5
1986-87	2,570 (20.1)	2,324 (9.3)	4,794 (19.4)	4,247 (8.4)	+47.3	+91.3
1987-88	3,130 (21.8)	3,082 (32.7)	6,066 (26.5)	5,539 (30.4)	+61.2	+83.6
1988-89	3,140 (0.3)	3,175 (3.0)	6,755 (11.4)	6,367 (14.9)	+62.0	+114.3
1989-90	3,200 (1.9)	3,229 (1.7)	6,463 (—4.3)	6,842 (7.5)	+56.5	+140.4

\*The spread has been worked out after converting the quotations in dollars per troy ounce in London market into rupees per 10 gram, at the cross rates based on daily average of spot buying and selling rates of U.S. dollars in London and average of Reserve Bank's spot buying and rates of sterling.

\*\*The spread has been worked out after converting the quotation, in cents per troy ounce in New York market into rupees per kg. at the cross rates based on the daily average of spot buying and selling rates of U.S. dollars in London and average of Reserve Bank's spot buying and selling rates of sterling.

Note : Figures in brackets are percentage variations over the previous year.

## 8. GOVERNMENT FINANCE

### Centre's Deficit

8.1 During the year 1989-90, the conventional deficit of the Central Government far exceeded the budgetary estimates. According to the revised estimates for the year, the deficit was placed at Rs. 11,750 crore (2.7 per cent of GDP), which represented an increase of Rs. 4,413 crore (or by 60 per cent) over the budgeted figures of Rs. 7,337 crore. At this level, the deficit constituted 15.0 per cent of the Centre's aggregate receipts compared with 7.9 per cent in 1988-89 (Accounts). After closure of Government accounts, as per the Reserve Bank records, the Centre's budgetary deficit in 1989-90 stood at Rs. 10,624 crore as against Rs. 5,810 crore in 1988-89. Net RBI credit to Central Government, which the Central Budget has been setting out as a memorandum item and which provides a better measure of the monetary impact of the Centre's budgetary operations, was placed much higher at Rs. 14,300 crore as per the revised estimates; the final out turn for 1989-90 as per Reserve Bank records was Rs. 13,813 crore, i.e., more than twice the actuals of Rs. 6,503 crore for 1988-89.

8.2 In last year's Report, pointed attention was drawn to an aspect of the operations of Government finances which was that the Centre's budgetary deficit ruled way above the budgeted estimate for the major part of the year but dropped drastically towards the last week of the year on closure of

Government accounts. Likewise, the figures of net RBI credit to the Central Government also ruled far above that originally envisaged for most part of the year before dropping to lower levels in the last week of the financial year. During 1989-90, the phenomenon not only persisted but was accentuated. The level of budgetary deficit crossed the budget estimates by the beginning of June 1989 and remained much above the budgeted level thereafter (Table 8.1). As per these fortnightly data, the level of net RBI credit to the Central Government touched Rs. 16,383 crore or 123 per cent above the figure originally envisaged in the Budget.

8.3 The conventional deficit in the Central Government Budget for 1990-91 is placed lower at Rs. 7,206 crore after taking into account additional resource mobilisation, including the proposed revision of postal tariffs. This would account for 8 per cent of aggregate receipts of the Central Government. The Centre's budget deficit in 1990-91 was Rs. 9,107 crore\* upto June 29, 1990 (Table 8.2).

### Broader Concepts of Budget Deficit and Government Debt

8.4 Even the growing size of budgetary deficit conventionally defined does not fully capture the structural imbalances in the fiscal operations of the Government of India. It captures only a part of the resource gap that is financed by issuing 91-days treasury bills and withdrawals from cash balances, leaving out market borrowings and increases in other liabilities such as small savings and provident funds,

\* Includes an amount of Rs. 1.40 crore representing the replacement of non-negotiable non interest bearing securities issued to IMF by RBI claims on Central Government for facilitating repurchases from the Fund.



TABLE 8.1 : Fortnightly Levels of the Centre's Budget Deficit and Net RBI Credit to Central Government@ (1987-88 to 1989-90)

(Rupees crore)

	Centre's Budget Deficit			Net RBI Credit to the Centre		
	1987-88	1988-89	1989-90	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6	7
Budget estimates(Fortnight Actuals)	5,688	7,484	7,337	5,688	7,484	7,337
1	2,807	2,401	1,170	2,857	2,036	2,011
2	4,128	3,782	3,497	3,388	3,508	3,722
3	5,343	4,976	6,045	3,888	4,378	5,461
4	4,401	5,539	6,176	3,217	5,001	6,392
5	6,475	6,134	8,565	4,807	4,180	7,675
6	6,144	7,525	9,508	5,088	6,976	7,784
7	7,136	8,667	9,824	4,689	8,582	7,858
8	5,699	9,468	11,378	4,283	9,035	9,500
9	5,536	8,515	11,382	3,768	7,344	9,140
10	6,778	9,300	13,416	4,377	8,331	10,277
11	6,382	8,332	12,596	3,239	7,029	9,938
12	7,446	9,897	13,265	4,879	7,355	10,664
13	7,519	8,831	11,535	4,597	6,723	9,111
14	5,825	9,438	12,953	3,560	7,253	11,186
15	5,873	9,249	10,375	4,250	7,474	9,869
16	7,180	9,079	10,934	5,187	6,424	8,901
17	7,022	9,422	13,044	5,755	8,081	12,403
18	8,965	10,308	13,789	6,173	7,875	12,748
19	8,025	10,154	13,317	6,628	9,065	13,634
20	7,445	8,546	11,789	6,622	8,060	12,611
21	8,283	9,172	14,206	7,553	9,679	15,277
22	8,200	9,134	14,158	7,313	9,334	15,255
23	9,740	10,187	13,675	8,170	9,965	15,395
24	8,334	9,437	13,790	7,496	9,742	15,804
25	8,834	8,597	14,266	8,023	9,228	16,383
26	7,953	7,184	10,290	7,423	8,175	14,344
March 31	5,870	5,810	10,624	6,559	6,503	13,813
Quarterly Average						
First Quarters	4,883	5,060	6,398	3,874	4,347	5,843
Second Quarter	6,642	9,001	12,262	4,262	7,771	9,772
Third Quarter	7,148	9,457	12,314	5,259	7,747	11,622
Fourth Quarter	8,082	8,503	13,001	7,395	8,947	15,182
Fourth Quarter excluding March 31	8,398	8,952	13,398	7,514	9,254	15,410
Financial Year Average	6,790	8,114	10,947	5,326	7,309	10,635
Financial Year Average excluding March 31	6,826	8,203	10,959	5,278	7,340	10,513

@Based on RBI records.

Note : 1. For 1989-90, Net RBI credit to Centre included, from August 23, 1989, amounts ranging from Rs. 78 crore to Rs. 7,143 crore representing the replacement of non-negotiable non-interest bearing securities issued to the IMF by RBI claims on Central Government for facilitating repurchases from the Fund. Till March 22, 1990, budget deficit also included these amounts as a special security for Rs. 721.43 crore was created on March 23, 1990.

2. As per budgetary data, Centre's deficit was Rs. 5,816 crore in 1987-88 and Rs. 5,642 crore in 1988-89.

all of which have contributed to a scenario of rapidly rising domestic debt and debt burden. Taking these various financing media into account Table 8.3 presents trends since 1980-81

of alternative measures of the Government deficit in absolute terms as well as in terms of ratios of GDP at current market prices. Apart from the monetised deficit which captures the

Table 8.2 : Budget Deficit and Net RBI Credit to Central Government : Actuals during the first quarter of 1990-91, 1989-90 and 1988-89

(Rupees crore)

	1988-89*		1989-90*		1990-91	
	Budget Deficit	Net RBI Credit to Central Government	Budget Deficit	Net RBI Credit to Central Government	Budget Deficit	Net RBI Credit to Central Government
1	2	3	4	5	6	7
Budget Estimates	7,484	7,484	7,337	7,337	7,206	7,206
As on April 6, 1990	2,401	2,036	1,170	2,011	2,679	2,712
As on April 20, 1990	3,782	3,508	3,497	3,722	3,204	4,050
As on May 4, 1990	4,976	4,378	6,045	5,461	5,754	4,994
As on May 18, 1990	5,539	5,001	6,176	6,392	6,638	7,058
As on June 1, 1990	6,134	4,180	8,565	7,675	6,228	6,907
As on June 15, 1990	7,525	6,976	9,508	7,784	7,698	7,463
As on June 29, 1990	8,667	8,582	9,824	7,858	9,107	7,703

\*Data relate to fortnights corresponding to those in 1990-91.

Note : For 1990-91, from April 20, 1990, net RBI credit to Centre and Budget deficit of the Union Government include amounts ranging from Rs. 26 crore to Rs. 240 crore representing the replacement of non-negotiable non-interest bearing securities issued to the IMF by RBI claims on Central Government for facilitating repurchases from the Fund.

monetary impact of fiscal operations in terms of the Government's reliance on the Reserve Bank and which has generally remained somewhat higher than the conventional deficit, the broader concepts of gross-fiscal deficit and net fiscal deficit are depicted in this Table as well as in graphical illustrations E and F.

8.5 As may be observed therefrom, gross fiscal deficit, the broadest concept which measures the total resources gap in terms of the excess of aggregate disbursements over revenue receipts including grants and which fully reflects the impact of fiscal operations on the indebtedness of the Central Government, has roughly doubled every five years, in absolute terms, from Rs. 8,887 crore in 1980-81 to Rs. 17,783 crore in 1984-85 and to Rs. 38,238 crore in 1989-90; the respective

ratios of gross fiscal deficit to GDP have steadily risen from 6.5 per cent to 7.7 per cent and finally to 8.6 per cent. The net fiscal deficit, which excludes the Centre's own net lendings, has likewise roughly doubled every five years. In 1989-90 the conventional deficit captured about one-third of the total resources gap as measured by the gross fiscal deficit, or less than one-half of the net fiscal deficit.

8.6 Looking at it differently, as depicted in Table 8.4, the financing pattern of the resource gap or, of gross fiscal deficit, reveals that in 1989-90 the conventional budget deficit accounted for 30.7 per cent, while other domestic borrowings, viz., market borrowings and increases in other liabilities, contributed the bulk, that is, a shade above 62 per cent. The extent of external financing was only 7.2 per cent.

Table 8.3 Monetised, Budget, Gross and Net Fiscal Deficit

(Rupees crore)

Year	Gross fiscal@ Deficit	Not Fiscal@		Conventional Deficit	G.D.P. at	
		Deficit	Monetised Deficit		Revenue Deficit	Market Prices
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	8,887	5,698	3,551	2,477	2,037	1,35,812
1981-82	8,667	4,592	3,207	1,392	384	1,59,420
1982-83	12,509	6,112	3,368	1,656*	1,308	1,17,588
1983-84	13,933	8,674	3,949	1,417*	2,540	2,06,857
1984-85	17,783	11,339	6,055	3,745	4,224	2,30,679
1985-86	24,406	14,464	6,190	4,937*	5,565	2,62,603
1986-87	27,876	18,570	7,091	8,261	7,776	2,93,361
1987-88	28,273	19,660	6,559	5,816	9,137	3,32,553
1988-89	32,008	21,855	6,503	5,642	10,515	3,91,158
1989-90	38,238(a)	25,872(a)	13,813	11,730(a)	12,436(a)	4,42,769\$
1990-91	38,055(b)	27,198(b)	7,206(b)	7,206(b)	13,032(b)	

1	2	3	4	5	6
As a Percentage of GDP at Market Prices					
1980-81	6.54	4.20	2.61	1.82	1.50
1981-82	5.44	2.88	1.01	0.87	0.24
1982-83	7.04	3.44	1.90	0.93	0.74
1983-84	6.74	4.19	1.91	0.69	1.23
1984-85	7.71	4.92	2.62	1.62	1.83
1985-86	9.29	5.51	2.36	1.88	2.12
1986-87	9.50	6.33	2.42	2.82	2.65
1987-88	8.50	5.91	1.97	1.75	2.75
1988-89	8.18	5.59	1.66	1.44	2.69
1989-90\$	8.64	5.84	3.12	2.65	2.81

@ These data are based on the Annual Financial Statements of the Central Government Budget which differ from earlier data published based on the Report on Currency & Finance & articles on Finances of the Government of India in the RBI Bulletin.

\*Excluding medium-term loans of Rs. 1,743 crore in 1982-83, Rs. 400 crore in 1983-84 and Rs. 1,628 crore in 1985-86 given to States to clear their overdrafts with the RBI

\$Estimated.

—Not available.

(a) Revised Estimates

(b) Budget Estimates

Source : Annual Financial Statements of the Central Government Budget.

8.7 The rapid escalation of the fiscal imbalance during the 1980's has naturally manifested itself in the mounting indebtedness of the Central Government. As is evident from Table 8.5, total liabilities of the Government of India, which stood at Rs. 59,749 crore or 43.9 per cent of GDP at the end of March 1981, shot up to as much as Rs. 2,66,913 crore or 60.3 per cent of GDP by the end of March, 1990. Much of this deterioration was due to internal liabilities.

8.8 The sustainability of Government deficits and domestic debt primarily depends upon the size and nature of resource mobilisation as well as the disposition of public expenditure. The steadily rising share of non-developmental expenditure, or consumption expenditure, in total expenditure is indeed disquieting. Again, exclusive dependence on domestic borrowings can become a substitute for mobilisation of resources through direct and indirect levies as well as higher returns on public investment.

TABLE 8.4 : Financing of Gross Fiscal Deficit

Year	External Finance	Internal Finance			(Rupees crore)		
		Market Borrowings	Other Liabilities	Conventional Deficit	Total Finance	Gross Fiscal Deficit	
					(3+4+5)	(2+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1980-81	1,336 (15.0)	2,679 (30.2)	2,395 (26.9)	2,477 (27.9)	7,551 (85.0)	8,887 (100.0)	8,887
1981-82	1,029 (11.9)	2,913 (33.6)	3,333 (38.4)	1,392 (16.1)	7,638 (88.1)	8,667 (100.0)	8,667
1982-83	1,354 (10.8)	3,771 (30.1)	3,985 (31.9)	3,399* (27.2)	11,155 (89.2)	12,509* (100.0)	12,509
1983-84	1,437 (10.3)	4,038 (29.0)	6,641 (47.7)	1,817* (13.0)	12,496 (89.7)	19,933* (100.0)	13,933
1984-85	1,516 (8.5)	4,096 (23.0)	8,426 (47.4)	3,745 (21.1)	16,267 (91.5)	17,783 (100.0)	17,783
1985-86	1,515 (6.2)	4,884 (20.0)	11,442 (46.9)	6,565* (26.9)	22,891 (93.8)	24,406* (100.02)	24,406
1986-87	2,145 (7.7)	5,531 (19.9)	11,939 (42.8)	8,261 (29.6)	25,731 (92.3)	27,876 (100.0)	27,876
1987-88	2,923 (10.3)	5,862 (20.7)	13,672 (48.4)	5,816 (20.6)	25,350 (89.7)	28,273 (100.0)	28,273
1988-89	2,521 (7.9)	8,418 (26.3)	15,427 (48.2)	5,642 (17.6)	29,487 (92.1)	32,008 (100.0)	32,008
1989-90(RE)	2,771 (7.2)	7,400 (19.4)	16,317 (42.7)	11,750 (30.7)	35,467 (92.8)	38,238 (100.0)	38,238
1990-91 (BE)	3,334 (8.8)	8,000 (21.0)	19,465 (51.2)	7,206 (19.0)	34,671 (91.2)	38,005 (100.0)	38,055

Note : Figures in brackets represent percentages to total finance.

\*Including medium-term loans of Rs. 1,743 crore in 1982-83, Rs. 400 crore in 1983-84 and Rs. 1,628 crore in 1985-86 given to States to clear their overdrafts with the RBI

Source : Annual Financial Statements of the Central Government Budget.

The Union Budget 1990-91<sup>a</sup>

8.9 Recognising that fiscal imbalance is the root cause of the twin problems of inflation and the difficult balance of payments situation, the Union Finance Minister in his Budget Speech for 1990-91 indicated his firm determination to limit the overall deficit within the budgeted level through strict fiscal discipline, containment of expenditure growth and better

tax compliance. This is sought to be buttressed by a constant review of the actual developments in the budgetary performance about which the Parliament would be kept informed at frequent intervals. The Budget proposed to make a beginning on an Employment Guarantee Scheme for the drought-prone areas and areas with acute problems of rural unemployment. High priority has been given for agriculture and rural development for which the outlay has been increased substan-

Table 8.5 : Total Liabilities of Government of India

(Rupees crore)

Year	Internal Debt	Small Saving	Provident Funds other Accounts	Reserve Funds and deposits	Total Internal Liabilities	External Liabilities	Total Liabilities
1	2	3	4	5	6	7	8
1980-81	30,864 (22.7)	7,976 (5.9)	5,977 (4.4)	3,634 (2.7)	48,451 (35.7)	11,298 (8.3)	59,749 (44.0)
1981-82	35,653 (22.4)	9,375 (5.9)	7,203 (4.5)	3,627 (2.3)	55,858 (35.0)	12,328 (7.7)	68,186 (42.7)
1982-83	46,939 (26.4)	11,098 (6.2)	8,789 (5.0)	4,364 (2.5)	71,190 (40.1)	13,682 (7.7)	84,872 (47.8)
1983-84	50,263 (24.3)	13,506 (6.5)	10,368 (5.0)	6,004 (2.9)	80,141 (38.7)	15,120 (7.3)	95,261 (46.1)
1984-85	58,537 (25.4)	17,157 (7.5)	12,547 (5.4)	8,563 (3.7)	96,804 (42.0)	16,637 (7.2)	1,13,441 (49.2)
1985-86	71,039 (27.0)	21,449 (8.2)	15,410 (5.9)	11,433 (4.4)	1,19,331 (45.5)	18,153 (6.9)	1,37,484 (52.4)
1986-87	86,312 (29.4)	24,725 (8.4)	20,204 (6.9)	15,006 (5.1)	1,46,247 (49.8)	20,299 (6.9)	1,66,456 (56.7)
1987-88	98,646 (29.7)	28,358 (8.5)	26,170 (7.9)	19,164 (5.7)	1,72,338 (51.8)	23,223 (7.0)	1,95,561 (58.8)
1988-89	1,14,498 (29.3)	33,833 (8.6)	34,702 (8.9)	20,992 (5.3)	2,04,025 (52.1)	25,746 (6.6)	2,29,771 (58.7)
1989-90 (Revised Estimates)	1,33,361 (30.1)	40,583 (9.2)	43,643 (9.9)	20,809 (4.7)	2,38,396 (53.9)	28,415 (6.4)	2,66,913 (60.3)
1990-91 (Budget Estimates)	1,51,037	45,583	54,590	23,815	2,75,025	31,851	3,06,876

Note : Figures in brackets represent percentages to Gross Domestic Product at current market prices.

Source : Budget documents of Government of India.

tially. In addition, the Budget has made provision of Rs. 1,000 crore for debt relief to farmers, weavers and artisans and Rs. 4,000 crore for fertilizer subsidy which would also benefit the rural areas.

8.10 The Budget lays emphasis on the need for faster growth of industries and balanced development of infrastructure, especially power and transport. Priority is given to accelerated industrial growth in a competitive and non-mono-

polistic environment, with an added emphasis on harmonious development of cottage, small and large industries.

8.11 In order to improve tax compliance and to curb proliferation of black money, the Act on 'benami' transactions will be recast to make it more difficult for economic offenders to hold wealth in 'benami' forms. The Budget also emphasised the need to back up administrative curbs against black money by economic measures like reducing the scope of discretionary powers and greater reliance on general, non-discretionary fiscal and financial instruments.

Table 8.6 : Budgetary Deficit, Market Loans and RBI support to Market Loans of the Central Government  
(Fiscal year 1988-89 to 1990-91)

(Rupees crore)

Items	1988-89 (Accounts)	1989-90 Budget (Estimates)	1989-90 (Revised Estimates)	1990-91(a) (Budget Estimates)
1	2	3	4	5
1. Revenue Account				
(i) Receipts (b)	45,740	55,018	54,616	60,763
(ii) Expenditure (b)	56,255	62,030	67,052	73,795
(iii) Surplus (+)/Deficit(-)	-10,515	-7,012	-12,436	-13,032

<sup>a</sup>Unless specified otherwise, all references to 1990-91 relate to the budget estimates and those to 1989-90 relate to the revised estimates.

1	2	3	4	5
<b>2. Capital Account</b>				
(i) Receipts	25,673	22,109	23,692	29,391
(ii) Disbursements	20,800	22,434	23,006	23,565
(iii) Surplus (+)/Deficit (—)	+ 4,873	—325	+ 686	—5,826
<b>3. Total Receipts [1(i)+2(i)]</b>	<b>71,413</b>	<b>77,127</b>	<b>78,308</b>	<b>90,154</b>
<b>4. Total Expenditure [1(ii)+(ii)]</b>	<b>77,055</b>	<b>84,464</b>	<b>90,058</b>	<b>97,360</b>
<b>5. Overall Surplus (+)/Deficit(—)</b>	<b>—5,642</b>	<b>—7,337</b>	<b>—11,750</b>	<b>—7,206</b>
<b>6. (5) as per cent of (3)</b>	<b>7.9</b>	<b>9.5</b>	<b>15.0</b>	<b>8.0</b>
<b>7. Gross Market Loans</b>	<b>8,894</b>	<b>8,039</b>	<b>8,039</b>	<b>8,988</b>
<b>8. (7) as per cent of (3)</b>	<b>12.5</b>	<b>10.4</b>	<b>10.3</b>	<b>10.0</b>
<b>9. Increase(+)/Decrease(—) in RBI holdings of Government Rupee Securities other than Treasury Bills (c)</b>				
	1,746	+ 3,000	+ 3,000 (e)	
<b>10. Increase (+)/Decrease(—) in net RBI Credit to Central Government (d)</b>	<b>+ 6,503</b>	<b>+ 7,337</b>	<b>+ 14,300</b>	<b>+ 7,206</b>
	(+ 6,503)	(+ 13,813)	(+ 13,813)	

(a) Include effects of budget proposals but exclude post-budget tax concessions.

(b) Include commercial departments.

(c) On book value basis, according to the RBI records.

(d) As per memorandum item given in the Union Budget.

(e) As per book value.

Note : Figures within brackets are as per RBI books for respective years.

8.12 Another highlight of the Budget is the announcement of the decision to abolish the Gold Control Act introduced in 1963 (since repealed by the Parliament).

8.13 Emphasising the desirability of keeping the basic structure of fiscal and tax system stable and predictable, a document on the Long-term Fiscal Policy would be presented to the Parliament.

7.14 The Budget seeks to restrict the overall deficit at a much lower level than that in the previous year. At 1989-90 rates of taxation, the overall deficit during 1990-91 is estimated at Rs. 9,165 crore as against Rs. 11,750 crores in the revised estimates for 1989-90. Inclusive of additional resource mobilisation, aggregate receipts are estimated at Rs. 90,154 crore in 1990-91 as compared with Rs. 78,308 crore in 1989-90. Aggregate disbursements amount to Rs. 97,360 crore and Rs. 90,058 crore, respectively, in the same years (Table 8.6). After taking into account the revenue from new measures including revision in postal rates, the Centre's deficit in 1990-91 is estimated at Rs. 7,206 crore as against Rs. 11,750 crore in 1989-90.

8.15 The Budget contains proposals for revision in taxes and duties which are expected to fetch an additional gross revenue of Rs. 2,573 crore in 1990-91 which is an all-time record. Adjusting for concessions and relief resulting in a revenue loss of Rs. 783 crore, the net additional revenue from new tax proposals would be Rs. 1,790 crore. Of this, the States' share will be only Rs. 3 crore. In addition to the Centre's tax proposals, revision in tariffs for certain postal services would yield Rs. 207 crore in a year and about Rs. 172 crore in 1990-91.

8.16 Despite the record additional resource mobilisation and emphasis on containment of expenditure, the revenue account will show a large deficit of Rs. 13,302 crore as com-

pared with the revenue deficit of Rs. 12,436 crore in 1989-90\* and Rs. 10,515 crore in 1988-89. On the contrary, the capital account will show a higher surplus of Rs. 5,826 crore in 1990-91 as compared with Rs. 686 crore in 1989-90. Thus a large part of the revenue deficit has to be financed through the surpluses in the capital account.

#### Centre's Plan Outlay

8.17 The Central Plan outlay for 1990-91 is placed at Rs. 39,329 crore which shows a rise of 10.1 per cent over the revised outlay at Rs. 35,713 crore and 14.2 per cent over the budgeted outlay at Rs. 34,446 crore for 1989-90. As part of the strategy to be adopted in the Eighth Plan, the Plan Programmes give priority to creation of more jobs, generation of self-employment opportunities, improvement in the living environment in villages and strengthening of agriculture. The Central assistance for State and Union Territory Plans will be stepped up by 22.9 per cent from Rs. 10,450 crore (excluding drought assistance) in 1989-90 to Rs. 12,848 crore in 1990-91; the latter includes the Plan revenue grants recommended by the Ninth Finance Commission. As a beginning to ensure 50 per cent of the investible resources for agricultural and rural development, the share of rural sector in budgetary support for the Central Plan in 1990-91 is placed higher at 49 per cent as against 44 per cent in 1989-90. The budgetary support for the Central Plan Outlay in 1990-91 is placed lower at Rs. 17,344 crore which would finance only 44.1 per cent of total Plan outlay as compared with Rs. 18,234 crore which financed 51.1 per cent of the Plan Outlay in 1989-90. Public sector enterprises are thus expected to contribute through their internal resources and borrowings, Rs. 21,985 crore or 55.9 per cent of the Central Plan Outlay in 1990-91 as compared with Rs. 17,479 crore or 48.9 per cent of Plan Outlay in 1989-90. Over three-fourths of this increase of Rs. 4,506 crore is sought to be raised through higher internal resources of Rs. 13,138 crore in 1990-91 as compared with Rs. 9,680 crore in the previous year.

\* If Rs. 2,300 crore transferred from the deposit of OI Co-ordination Committee are excluded, the revenue deficit in 1989-90 would be higher at Rs. 14,736 crore.

Tabl. 8.7 : Developmental and Non-Developmental Expenditure of Centre and States

(Rupees crore)

Year	Centre's			States'			Centre and States (Combined)				
	Develop- mental Expenditure	Non- Develop- mental Expenditure	Total@@	Develop- mental Expenditure	Non- Develop- mental Expenditure	Others*	Total	Develop- mental Expenditure	Non- Develop- mental expenditure	Others\$\$	Total
1	2	3	4	5*	6	7	8	9	10	11	12
1980-81	13,932 (57.6)	10,245 (42.4)	24,177 (100.0)	15,961 (70.1)	4,289 (18.8)	2,520 (11.1)	22,770 (100.0)	25,845 (66.0)	11,977 (30.6)	1,338 (3.4)	39,160 (100.00)
1981-82	16,084 (60.9)	10,331 (39.1)	26,415 (100.0)	17,960 (70.2)	4,996 (19.6)	2,615 (10.2)	25,571 (100.0)	28,796 (64.7)	13,609 (30.6)	2,074 (4.7)	44,479 (100.0)
1982-83	19,557 (60.7)	12,673 (39.3)	32,230 (100.0)	20,649 (71.0)	5,883 (20.2)	2,565 (8.8)	29,097 (100.0)	33,643 (64.6)	16,473 (31.7)	1,941 (3.7)	52,057 (100.0)
1983-84	22,207 (58.8)	15,564 (41.2)	37,771 (100.0)	23,972 (71.2)	6,882 (20.4)	2,814 (8.4)	33,668 (100.0)	38,352 (63.9)	19,936 (33.3)	1,701 (2.8)	59,989 (100.0)
1984-85	27,375 (59.6)	18,525 (40.4)	45,900 (100.0)	27,958 (70.3)	8,340 (21.0)	3,448 (8.7)	39,746 (100.0)	46,265 (64.6)	23,390 (32.6)	1,999 (2.8)	71,654 (100.00)
1985-86	29,979 (58.9)	20,927 (41.1)	50,906 (100.0)	31,733 (70.7)	9,617 (21.4)	3,519 (7.9)	44,869 (100.0)	55,032 (65.1)	27,332 (32.4)	2,106 (2.5)	84,470 (100.0)
1986-87	35,498 (57.7)	26,060 (42.3)	61,558 (100.0)	36,827 (70.6)	11,220 (21.5)	4,149 (7.9)	52,196 (100.0)	64,441 (63.4)	33,682 (33.2)	3,479 (3.4)	1,01,602 (100.0)
1987-88	36,573 (54.7)	30,261 (45.3)	66,834 (100.0)	42,141 (70.2)	13,754 (22.9)	4,104 (6.9)	59,999 (100.0)	69,087 (62.2)	39,460 (35.5)	2,614 (2.3)	1,11,161 (100.0)
1988-89\$	41,536 (53.9)	35,519 (46.1)	77,055 (100.0)	47,064 (69.8)	15,803 (33.4)	4,599 (6.8)	67,466 (100.0)	78,983 (61.6)	45,940 (35.8)	3,322 (2.6)	1,28,745 (100.0)
1989-90\$ (RE)	48,943 (54.3)	41,115 (45.7)	90,058 (100.0)	53,532 (68.5)	19,775 (25.3)	4,815 (6.2)	78,122 (100.0)	95,747 (62.5)	53,560 (35.0)	3,879 (2.5)	1,53,186 (100.0)
1990-91\$ (BE)	50,801 (52.2)	46,559 (47.8)	97,360 (100.0)	55,932 (67.0)	23,095 (27.6)	4,512 (5.4)	83,539 (100.0)	95,907 (59.5)	61,601 (38.2)	3,685 (2.3)	1,61,193 (100.0)

@Exclude discharge of internal and external debt.

\$Regarding State Governments, data relating to 15 States are from Vote-on-Account Budgets while those relating to the remaining 10 States are from final Budget. Further, data in respect of Nagaland and Uttar Pradesh for the year 1988-89 are Revised.

\$\$Comprise discharge of internal debt, compensation and assignment to Local Bodies and Panchayati Raj Institutions, appropriation for contingency funds, net remittances of the State Governments and are adjusted for differences in the figures of repayments of loans by the State Governments to the Central Government given in their respect budgets.

\*Comprise discharge of internal debt, repayment of loans for the Centre, appropriation for contingency fund and remittances (net), compensation and assignments to Local Bodies and Panchayati Raj Institutions.

Note : 1) Figures in brackets represent percentages to respective total expenditure and

2) Figures for the Centre and States do not add up to the combined position due to inter-Governmental adjustments.

#### Disbursements : Developmental and Non-Developmental

8.18 The Central Government's aggregate disbursements are estimated at Rs. 97,360 crore in 1990-91 which are higher by Rs. 7,302 crore (8.1 per cent) over the level of Rs. 90,058 crore in 1989-90. Developmental expenditure at Rs. 50,801 crore would increase by Rs. 1,858 crore or 3.8 per cent over the previous year's level of Rs. 48,943 crore, while non-developmental expenditure at Rs. 46,559 crore would rise by Rs. 5,444 crore or 13.2 per cent over Rs. 41,115 crore in 1989-90 thus persisting with the deterioration in the share of developmental expenditure in total expenditure, particularly rather sharply during the Seventh Plan period (Table 8.07).

#### Plan and Non-Plan Expenditure†

8.19 Plan expenditure is expected to increase by Rs. 1,716 crore (6.0 per cent) from Rs. 28,476 crore in 1989-90 to Rs. 30,192 crore in 1990-91. Non-Plan expenditure estimated

at Rs. 64,343 crore would show a larger increase of Rs. 5,123 crore (8.7 per cent) over the level of Rs. 59,220 crore in the previous year (see also Graph G). Interest payments at Rs. 20,850 crore would constitute 32.4 per cent of non-Plan expenditure in 1990-91 as compared with Rs. 17,710 crore or 29.9 per cent last year. As a percentage of the Centre's tax receipts, net interest payments (i.e., interest payments less interest receipts at Rs. 11,331 crore would be 25.0 per cent in 1990-91 as compared with Rs. 9,045 crore or 23.9 per cent in 1989-90. Major subsidies (food, fertilizers and export promotion) at Rs. 8,516 crore are budgeted to show a fall by Rs. 650 crore (—7.1 per cent) from the last year's figure of Rs. 9,166 crore. Expenditure on defence would, however increase by Rs. 1,250 crore (8.6 per cent) from Rs. 14,500 crore in 1989-90 to Rs. 15,750 crore in 1990-91. Interest payments, defence and major subsidies would together constitute around 70 per cent of non-Plan expenditure in 1990-91, that is, almost the same as that in the previous year.

†These do not add up to total expenditure given earlier wherein transactions of commercial departments and postal service are shown on a gross basis.

## Budget Proposals

8.20 The Budget proposals for 1990-91, are aimed at removing the inequality in tax incentives, curbing conspicuous consumption, giving boost to foreign exchange earnings, reducing in essential imports, and restructuring the corporate tax for closing the escape routes. Care has also been taken to broaden the corporate tax net.

8.21 In the area of personal income-tax, the exemption limit has been raised from Rs. 18,000 to Rs. 22,000 and the lowest rate of tax of 20 per cent extended from the present income limit of Rs. 25,000 to that of Rs. 30,000. The existing surcharge at the rate of 8 per cent would be continued, but made applicable beyond the taxable income of Rs. 75,000 as against the present cut-off limit of Rs. 50,000. In order to remove the regressive and inequitable nature of existing tax incentives under Section 80-C and Section 80-CC, new schemes have been devised and also incentives have been further enhanced in other schemes, as described in a subsequent paragraph. As an incentive for earning foreign exchange, deduction in respect of professional income from foreign sources available to certain categories has been increased from the existing rate of 25 per cent to 50 per cent of the income or 75 per cent of the foreign exchange brought into India, whichever is higher. The various concessions announced in the area of personal income-tax are expected to result in a revenue loss of Rs. 250 crore during 1990-91.

8.22 The modifications suggested in the corporate tax system are intended to increase the buoyancy, simplify the tax structure and make it neutral as between small and large companies. These are also expected to provide strong incentives for investment in new industrial undertakings and for promoting exports. In order to ensure better tax compliance, a twin strategy has been proposed. First, major incentives like Investment Allowance and Investment Deposit Account have been abolished with a view to avoiding the scope for the private sector to go out of the tax net. Secondly, the tax rates for domestic companies are reduced from 50 per cent to 40 per cent in the case of widely-held companies, from 60 per cent to 50 per cent in the case of trading or investment companies and from 55 per cent to 45 per cent in other domestic companies. This twin strategy is expected to raise the effective tax rate as also to give substantial additional revenue. The only major deductions that will now be permitted relate to foreign exchange earnings and for setting up of new industrial undertakings. The special provision regarding tax on minimum profits contained in Section 115J of the Income-tax Act will also be discontinued. In order to encourage genuine investment activity and to discourage the use of corporate framework for holding personal wealth, dividends received by domestic companies from other domestic companies will be exempted to the full extent to which they themselves declare dividends during the relevant period. Scheduled banks and public financial institutions would continue to be governed by the existing provisions of Section 80M. The surcharge would be continued at 8 per cent for the corporate incomes above Rs. 75,000 as against the present

cut-off limit of Rs. 50,000. The modifications in corporation tax are expected to yield additional revenue of Rs. 800 crore during 1990-91.

8.23 With a view to curbing the misuse of the mechanism of gift for splitting up capital and laundering black money, the existing gift tax on 'donors' has been substituted, effective from March 20, 1990, by a 'donee' based on a graduated scale.

8.24 In the area of indirect taxes, the main thrust is for simplification and rationalisation, though efforts have been made to mobilise resources without hurting the common man and at the same time helping to curb elitist consumption and checking tax evasion. Emphasis has also been given for strengthening impulses for growth and exports, while significant changes in duty structure are made to develop quality-consciousness and culture in industry. Reliefs have also been extended to deserving sectors like small-scale industry, agriculture and environmental protection. In particular, with a view to rationalising the import duty rates and bringing down their multiplicity, the total of the basic and auxiliary duty rates of customs are placed in a limited number of slots ranging from zero to 125 per cent in respect of most items.

8.25 The modifications in excise duties would yield an additional gross revenue of Rs. 778 crore in 1990-91. After adjusting for the loss of revenue of Rs. 388 crore on account of concessions and reliefs, the net additional yield would be of the order of Rs. 390 crore, of which Rs. 217 crore would be the Centre's share and Rs. 173 crore the States' share. The tax efforts in respect of customs duties will yield a gross revenue of Rs. 980 crore, which after revenue loss of Rs. 145 crore on account of concessions will net in Rs. 835 crore to the Central Government during 1990-91. Inland Travel tax leviable earlier at 10 per cent\* of the basic fare will now be levied at the existing rate on full air fare to net in an additional revenue of Rs. 15 crore. Revision in Postal Tariff is expected to net in an additional revenue of about Rs. 207 crore in a full year and about Rs. 172 crore in 1990-91.

8.26 As a result of the above measures, the gross tax collections by the Centre are estimated to go up by 17 per cent from Rs. 51,030 crore in 1989-90 (Revised Estimates) to Rs. 59,720 crore in 1990-91 (Budget Estimates). Due to substantial measures of resource mobilisation under direct taxes, the share of direct taxes in gross collections by the Centre would edge up fractionally from 19.6 per cent to 19.7 per cent, though it would remain considerably lower than what it was in the early 1980s (Table 8.8).

## State Budgets : 1990-91

8.27 The combined budgetary position of States, \*\* at 1989-90 rates of taxation, reveals a deficit of Rs. 2,135 crore in 1990-91 as compared with the deficit of Rs. 1,197 crore in 1989-90 (Revised Estimates) and surplus, of Rs. 164 crore in 1988-89 (Accounts). The Additional Resource Mobilisation

Table 8.8 : Direct and Indirect Tax Revenues of the Centre and States

(Rupees crores)

Year	Centre (Gross)			States+			Combined		
	Direct	Indirect	Total	Direct	Indirect	Total	Direct	Indirect	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1980-81	2,907	10,242	13,149	686	5,929	6,615	3,593	16,171	19,764
(a)	22.1	77.9	100.0	10.4	89.6	100.0	18.2	81.8	100.0
(b)	2.1	7.6	9.7	0.5	4.4	4.9	2.7	11.9	14.6

\* This was subsequently raised to 15 per cent.

\*\*Data relates to 25 States.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1984-85	4,626	18,802	23,428	1,230	11,108	12,338	5,856	29,910	35,766
(a)	19.7	80.3	100.0	10.0	90.0	100.0	16.4	83.6	100.0
(b)	2.0	8.2	10.2	0.6	4.8	5.4	2.5	13.0	15.5
1985-86	5,563	23,109	28,672	1,401	12,919	14,320	6,964	36,028	42,992
(a)	19.4	80.6	100.0	9.8	90.2	100.0	16.2	83.8	100.00
(b)	2.1	8.8	10.9	0.5	4.9	5.4	2.7	13.7	16.4
1986-87	6,234	26,559	32,793	1,685	14,934	16,619	7,919	41,493	49,412
(a)	19.0	81.0	100.0	10.1	89.9	100.0	16.0	84.0	100.0
(b)	2.1	9.1	11.2	0.6	5.1	5.7	2.7	14.1	16.8
1987-88	6,751	30,861	37,612	1,960	17,438	19,398	8,711	48,299	57,010
(a)	17.9	82.1	100.0	10.1	89.9	100.0	15.3	84.7	100.0
(b)	2.0	9.3	11.3	0.6	5.2	5.8	2.6	14.5	17.1
1988-89@	8,824	35,596	44,420	2,419	19,979	22,398	11,243	55,575	66,818
(a)	19.9	80.1	100.0	10.8	89.2	100.0	16.8	83.2	100.0
(b)	2.3	9.1	11.4	0.6	5.1	5.7	2.9	14.2	17.1
1989-90@	9,994	41,036	51,030	2,644	22,739	25,383	12,638	63,775	76,413
(RE) (a)	19.6	80.4	100.0	10.4	89.6	100.0	16.5	83.5	100.0
(b)	2.3	9.4	11.7	0.6	5.1	5.7	2.9	14.4	17.3
1990-91@	11,774	47,946	59,720	2,913	25,689	28,602	14,687	73,635	88,322
(BE)(a)	19.7	80.3	100.0	10.2	89.8	100.0	16.6	83.4	100.0

@Regarding State Governments, data relating to 15 States, are from Vote-on-Account Budgets while those relating to the remaining 10 States are from Final Budgets. Further, data in respect of Nagaland and Uttar Pradesh for the year 1988-89 are Revised Estimates.

+Excluding States' share in Central taxes as reported in central budget documents.

Note: (a) Represents percentages to total tax revenue; and

(b) Indicates tax to GDP ratio in percentages.

(ARM) measures proposed by States would yield an additional revenue of Rs. 366 crore in 1990-91. The share of States in the Centre's new tax proposals in the Budget for 1990-91 would be Rs. 3 crore. After taking into account the impact of ARM measures of States and accrual of revenue owing to the Centre's tax proposals, the deficit would come down to Rs. 1,766 crore. The States expect to cover their budgetary deficits through effective financial management, curtailment of unproductive expenditure, efficient tax collections and enhanced Central assistance following the implementation of the Ninth Finance Commission's recommendations.

8.28 Revenue account of States at revised rates of taxation would show a deficit of Rs. 4,815 crore in 1990-91 as compared with a deficit of Rs. 4,614 crore in 1989-90. This would be offset partly by an estimated surplus of Rs. 3,049 crore in the capital account of States in 1990-91. Last year, the capital account had shown a surplus of Rs. 3,417 crore.

8.29 Aggregate receipts of States, at revised rates of taxation, budgeted at Rs. 81,773 crore for 1990-91 would show a rise of Rs. 6.3 per cent as compared with a rise of 13.7 per cent in 1989-90. Aggregate disbursements, on the other hand, are budgeted at Rs. 83,539 crore for 1990-91, showing an increase of 6.9 per cent as against a rise of 15.8 per cent in 1989-90. Developmental expenditure of States at Rs. 55,932 crore would rise by 4.5 per cent in 1990-91 in comparison with an increase of 13.7 per cent in 1989-90. Non-developmental expenditure, which increased by 25.1 per cent in 1989-90, would rise by 16.8 per cent to Rs. 23,095 crore in 1990-91. The share of developmental expenditure in aggregate disbursements of the states would decline from 68.5 per cent in 1989-90 to 67.0 per cent in 1990-91, while that of non-developmental expenditure would show a rise from 25.3 per cent to 27.6 per cent. Other disbursements comprising discharge of internal debt, repayments of loans to the Centre,

etc., would account for 5.4 per cent of aggregate disbursements in 1990-91 as against their share of 6.2 per cent in 1989-90.

#### Consolidated Budgetary Position : Centre and States

8.30 The combined budgetary position of Centre and States, after taking into account the yield from additional resource mobilisation measures reveals a total deficit of Rs. 8,972 crore as compared with that of Rs. 12,947 crore in the revised estimates of 1989-90. Table 8.9 sets out the data relating to the combined financial position of the Central and State Governments during 1990-91.

8.31 Aggregate receipts of the Centre and States are estimated to go up by 8.5 per cent to Rs. 1,52,221 crore in 1990-91 over those of Rs. 1,40,239 crore in 1989-90. Both revenue and capital receipts are estimated to improve by 8.7 per cent and 8.2 per cent, respectively, over the levels in 1989-90. Tax receipts estimated at Rs. 88,322 crore in 1990-91, would witness an increase of 15.6 per cent over the increase of 14.4 per cent in 1989-90. Revenue from direct taxes would rise by 16.2 per cent as against the growth of 15.5 per cent estimated for indirect taxes. The share of indirect tax receipts in total tax receipts would be 63.4 per cent in 1990-91 as against 63.5 per cent in 1989-90.

8.32 Aggregate disbursements in 1990-91 at Rs. 1,61,193 crore, would record an increase of 5.2 per cent over the previous year. Developmental expenditure, which is estimated at Rs. 95,907 crore, would rise only marginally by Rs. 160 crore or 0.2 per cent over the level in 1989-90. On the other hand, non-developmental expenditure at Rs. 61,601 crore is budgeted to rise by 15.0 per cent in 1990-91. Consequently, the share of developmental expenditure in total expenditure would fall from 62.5 per cent in 1989-90 to 59.5



Table 8 9 Combined Receipts & Disbursements of Central & State Governments  
(Fiscal Years 1988-89 to 1990-91)

(Rupees crore)						
Item	1988-89 (Accounts)	1989-90 (Budget Estimates)	1989-90 (Revised Estimates)	1990-91* (Budget Estimates)	Percentage Variations of Col. 4 over Col. 2.	Percentage Variations of Col. 5 over Col. 4
1	2	3	4	5	6	7
I. Total Receipts (A+B)	1,22,767	1,34,192	1,40,239	1,52,221	+14.2	+8.5
A. Revenue Receipts	82,195	95,041	96,945	1,05,376	+17.9	+8.7
Of which :						
Tax Receipts (a+b)	66,818	75,528	76,413	88,322	+14.4	+15.6
(a) Direct Taxes	11,243	11,722	12,638	14,687	+12.4	+16.2
(b) Indirect Taxes	55,575	63,806	63,775	73,635	+14.8	+15.5
B. Capital Receipts	40,572	39,151	43,294	46,845	+6.7	+8.2
II. Total Disbursements (A+B+C)	1,28,245	1,42,201	1,53,186	1,61,193	+19.4	+5.2
A. Developmental Expenditure (a+b+c)	78,983	83,698	95,747	95,907	+21.2	+0.2
(a) Revenue	52,323	55,344	64,876	66,462	+24.0	+2.4
(b) Capital	13,339	14,625	14,672	15,603	+10.0	+6.3
(c) Loans and Advances	13,321	13,729	16,199	13,842	+21.6	+14.6
B. Non-Developmental Expenditure (a+b+c)	45,940	54,488	53,560	61,601	+16.6	+15.0
(a) Revenue	41,507	49,709	48,516	55,955	+16.9	+15.3
(b) Capital	4,113	4,442	4,702	5,311	+14.3	+13.0
(c) Loans and Advances	320	337	342	335	+6.9	-2.0
3. Others	3,322	4,015	3,879	3,685	+16.8	-5.0
III. Overall Surplus (+)/Deficit(—)	—5,478	—8,009	—12,947	—8,972	+136.3	—30.7

\*Include effects of Budget proposals and exclude post-budget tax concessions.

Note : 1. Regarding State Governments, data relating to 15 states are from Vote-on-Account Budgets, while those relating to the remaining 10 states are from Final Budgets. Further, data in respect of Nagaland and Uttar Pradesh for the year 1988-89 are Revised Estimates.

2. Other disbursements comprise discharge of internal and external debt, compensation and assignments to local bodies and Panchayat Raj Institutions, appropriation to contingency funds and net remittances and are adjusted for difference in figures of repayments of loans by State Governments to the Central Government given in their respective budgets.

per cent in 1990-91. Correspondingly, non-developmental expenditure as a proportion of total expenditure is expected to rise from 35.0 per cent in 1989-90 to 38.2 per cent in 1990-91.

#### Ninth Finance Commission

8.33 The Ninth Finance Commission, constituted in June 1987, submitted its second and final report in December, 1989 covering the period 1990-95. The Commission has recommended that the States' share in personal income-tax and Union excise duties including special excise duties should be retained at 85 per cent and 45 per cent, respectively. The Commission has increased the grants in lieu of the Tax on Railway Passenger Fares from Rs. 95 crore to Rs. 150 crore per annum. For financing relief expenditure, the Commission has suggested that a Calamity Relief Fund should be constituted for each State to which the Central Government should contribute to the extent of 75 per cent in the form of non-Plan grants, the balance being contributed by each State from its own resources. The Commission has recommended that an amount of Rs. 804 crore per annum should be allocated for the States' Calamity Relief Funds; of this, Rs. 603 crore will be contributed by the Central Government. The Commission has also recommended total grants-in-aid of Rs. 15,017.18 crore to be given to the States in the next five years (1990-1995). Of this, Rs. 6,016.35 crore will be for covering the non-Plan revenue account gaps and

the remaining Rs. 9,000.83 crore for financing part of the deficit on Plan revenue account. The Commission has recommended that 40 per cent of the Plan assistance to non-special category States should be given in form of additional market loans instead of loans from the Central Government. The Commission has also recommended debt relief to the State Governments against outstanding loans from the Centre by way of rescheduling and write-off of loans and suggested some changes in the terms and conditions governing Central loans which would provide relief to States. The Commission did not favour the merger of additional duties of excise with basic duties of excise.

8.34 In order to enforce fiscal discipline on the Central Government, the Commission has recommended that a convention should be developed under which the extent of deficit financing by the Central Government in any year should be limited to an amount to be determined in consultation with the Governor of the Reserve Bank of India on the basis of certain objective economic criteria to be clearly laid down in advance. The Commission has also urged that if under certain extraordinary circumstances, the agreed limits of credit from the Reserve Bank are to be exceeded, the matter should be discussed in the Parliament and its approval obtained.

8.35 The Central Government has accepted such of the recommendations as would need immediate implementation, i.e., recommendations relating to devolution of taxes and duties to States, grant-in-aid, financing of relief expenditure and debt relief while some recommendations which need in-depth analysis would be considered in due course. According to the Central Budget for 1990-91, the implementation of the Finance Commission's recommendations would create an additional burden of Rs. 773 crore on Central Finances in 1990-91.

#### Market Borrowings\*

8.36 During 1989-90, the Central Government conducted its market borrowing operations through five tranches, mobilising a gross amount of Rs. 8,044 crore compared with Rs. 7,725 crore during 1988-89. After making repayments of maturing loans of Rs. 639 crore, the net market borrowings amounted to Rs. 7,405 crore which were higher by Rs. 154 crore (2.1 per cent) as compared with the previous year (Rs. 7,251 crore) (Table 8.10). The gross market borrowings of Rs. 8,044 crore comprise cash subscription of Rs. 7,469 crore and conversion of Rs. 575 crore of maturing loans.

Table 8.10 : Market Borrowings of Central and State Governments, Local Authorities and Institutions sponsored by Central and State Governments—1988-89 and 1989-90 (Fiscal Year)\*

(Rupees crore)

Government/Authority	Gross Market Borrowings		Repayments		Net Market Borrowings	
			(Total Maturities)			
	1988-89	1989-90	1988-89	1989-90	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6	7
1. Central Government	7,725	8,044	474	639	7,251	7,405
2. State Governments	2,285	2,555	283	306	2,002	2,249
3. Total Government Borrowings (1+2)	10,010	10,599	757	945	9,253	9,654
4. Institutions Sponsored by Central Government	2,244	2,622	309	457	1,935	2,165
5. Institutions sponsored by State Governments (including Local Authorities)	1,417	1,519	374	416	1,043	1,103
6. Total Institutions' Borrowings (4+5)	3,661	4,141	683	873	2,978	3,268
7. Aggregate Market Borrowings (3+6)	13,671	14,740	1,440	1,818	12,231	12,922

\*Actuals as per R.B.I. records.

8.37 The gross market borrowings of the State Governments amounted to Rs. 2,555 crore during 1989-90 compared with Rs. 2,285 crore during the previous year, recording a rise of Rs. 270 crore (11.11 per cent). Of the States' gross market borrowings of Rs. 2,555 crore, cash subscription amounted to Rs. 2,513 crore and conversion of maturing loans to Rs. 42 crore. The net market borrowings by the States, after repayment of Rs. 306 crore, rose by Rs. 247 crore (12.3 per cent) to Rs. 2,249 crore compared with Rs. 2,002 crore in previous year.

8.38 The gross market borrowings by the Local Authorities and the institutions sponsored by the Central and State Governments rose by Rs. 480 crore (13.1 per cent) from Rs. 3,661 crore in 1988-89 to Rs. 4,141 crore in 1989-90. The net market borrowings were, however, marginally higher by Rs. 290 crore (9.7 per cent) from 2,978 crore to Rs. 3,268 crore, as repayments were higher during 1989-90. The repayments amounted to Rs. 873 crore compared with Rs. 683 crore in the previous year. Of the net market loans of Rs. 3,268 crore raised by these sponsored institutions and local authorities, the amount raised by the institutions sponsored by the Central Government amounted to Rs. 2,165 crore (66.3 per cent) compared with Rs. 1,935 crore (65.0 per cent) in the previous year.

8.39 aggregate gross market borrowings (comprising market borrowings by the Centre/States, Local Authorities and institutions sponsored by the Central and State Governments) rose by Rs. 1,069 crore (7.8 per cent) to Rs. 14,740 crore during 1989-90 compared with Rs. 13,671 crore in the previous year. The net market borrowings during 1989-90, after repayments of Rs. 1,818 crore, rose by Rs. 691 crore (5.6 per cent) to Rs. 12,922 crore as compared with Rs. 12,231 crore during 1988-89.

\* Data are actuals as per the Reserve Bank Records.

8.40 The Union Budget for 1990-91 assumed gross market borrowings for the year at Rs. 8,988 crore. Net market borrowings, after making repayments of Rs. 988 crore, were budgeted at Rs. 8,000 crore compared with Rs. 7,400 crore in the previous year or higher by Rs. 600 crore (8.1 per cent). Coupon Rates on Central Government Loans.

8.41 The coupon rates on Central Government loans remained unchanged during 1989-90. They were : 11.5 per cent for loans with maturity period of 20 years, 11.0 per cent for 15-years loans, and 10.5 per cent for 10-year loans.

#### Reserve Bank Support to Central Loans

8.42 The Reserve Bank's initial subscription to the Central Government market borrowings amounted to Rs. 4,861 crore or 60.4 per cent of the gross market borrowing during 1989-90 which was higher by Rs. 2,348 crores (93.4 per cent) as compared with the initial subscription of Rs. 2,513 crore which was 32.5 per cent of the gross market borrowings in the previous year. Although the Reserve Bank was able to offload a portion of the Central Government's loan purchased through initial subscription, the increase in the Bank's holdings of Central Government securities was higher at Rs. 3,000 crore in 1989-90 as compared with Rs. 1,746 crore in 1988-89. Holdings of Central Government dated securities by institutions under buy-back arrangements with the Reserve Bank increased by Rs. 197 crore during 1989-90 in contrast to a reduction of Rs. 1,104 crore during 1988-89.

#### Internal Debt and Other Liabilities

8.43 In addition to market borrowings, the Centre and States mobilised resources through other instruments such as small savings and provident funds. Taking account of such other resources mobilised, the net addition to the outstanding

internal debt and other liabilities of the Centre and States amounted to Rs. 39,223 crore or 8.9 per cent of GDP in 1989-90 as against Rs. 35,466 crore or 9.1 per cent of GDP in 1988-89.

#### Bonds of Public Sector Undertakings

8.44 In addition to the borrowings by the Central Government, a number of Central public sector undertakings have also been raising resources through bonds/debentures and external commercial borrowings/suppliers' credit to meet their financial requirements for developmental programmes. The Union Budget for 1990-91 envisages a lower amount of borrowings during the year as compared with those in the previous year. It is estimated that these public sector undertakings would raise Rs. 3,942 crore through issue of bonds/debentures in the domestic market and Rs. 1,466 crore through external commercial borrowings/suppliers' credit during 1990-91 compared with Rs. 4,494 crore and Rs. 1,922 crore respectively, raised during 1989-90.

#### Ways and Means Advances from Reserve Bank of India

8.45 The Reserve Bank of India provides Ways and Means Advances (WMA) to the States to tide over temporary imbalances in their cash flow of receipts and expenditure. Since March 1988, the total normal WMA limits of 23 States amounted to Rs. 744.8 crore; in addition, special WMA limits against the pledge of Government of India securities amounted to Rs. 266 crore. The aggregate WMA limits available to 23 States thus stand at Rs. 1,010.8 crore.

8.46 During the financial year 1989-90 all State Governments, excepting two, abided by the Overdraft Regulation Scheme. Since the accounts of these two State Governments remained overdrawn beyond the stipulated period of seven consecutive working days—one in July 1989 and another in March 1990, the Reserve Bank of India had to stop payments on their behalf till the overdrafts were cleared.

#### Savings Instruments

8.47 Some of the important changes effected in the Central Budget for 1990-91 in regard to the existing saving schemes are as follows :

(i) The provisions relating to tax concessions to promote savings under Section 80C of the Income-tax Act have been replaced by a new provision under Section 88. Under the new provision, deduction is allowed of 20 per cent of the amount invested in Life Insurance policies, provident fund superannuation fund, and other eligible investments from the income-tax payable on total income. The maximum tax rebate allowable from the income-tax payable will be Rs. 10,000. In case of authors, playwrights, artists, musicians, actors and sportsmen including athletes, the maximum tax rebate allowable will be Rs. 14,000.

(ii) With a view to providing further incentive for savings, the maximum amount which would qualify for deduction in respect of deposits made under the National Savings Scheme and payments made towards notified annuity plans of the LIC under Section 80CCA has been increased from Rs. 30,000 to Rs. 40,000.

(iii) The Equity-Linked Savings Scheme (ELSS) announced last year has been now finalised on a netting principle under a new Section 80CCB. Investment in units under the scheme will be eligible for deduction up to a maximum of Rs. 10,000 from the total income. The annual return on the investment in the units will be eligible for tax concession under Section 80I. On repurchase of units by the Mutual Funds or the UTI, the capital amount representing the cost of the units will be taxed as income in the year of repurchase and the excess will be liable to tax as capital gains. The ELSS will eventually replace the existing scheme under Section 80CC.

(iv) Section 80CC of the Income-tax Act which provides for a deduction of an amount equal to fifty per cent in respect of investment in shares forming part of eligible issue of equity capital or units issued under any scheme of a mutual

Table 8.11 : Financing Pattern of Seventh Plan Outlay

(Rupees crore)						
Items	1985-86 to 1989-90 (Latest Estimates)			Original Estimates		
	As at 1984-85 prices					
	Centre <sup>(a)</sup>	States	Total	Centre <sup>(a)</sup>	States	Total
1	2	3	4	5	6	7
I. Domestic Resources at 1984-85 rates of taxes, tariffs, and fares						
(a) Balance from Current Revenue*	—11,074 (—9.7)	—1,139 (—1.5)	—12,213 (—6.5)	—12,011 (—12.1)	6,762 (8.4)	—5,249 (—2.9)
(b) Contribution from Public Sector Enterprises (PSEs)	26,872 (23.6)	—3,757 (—5.0)	23,115 (12.3)	37,454 (37.7)	—1,969 (—2.4)	35,485 (19.7)
(c) Issue of Bonds by PSEs	7,484 (6.6)	.. (—)	7,484 (4.0)			
(d) Market Loans	26,542 (23.3)	9,242 (12.4)	35,784 (19.0)	20,620 (20.8)	9,942 (12.3)	30,562 (17.0)
(e) Small Savings and Provident Funds	8,751 (7.7)	19,070 (25.6)	27,821 (14.8)	8,677 (8.7)	16,566 (20.5)	25,243 (14.0)
(f) Term Loans from Financial Institutions	.. (—)	4,445 (6.0)	4,445 (2.4)	.. (—)	4,639 (5.8)	4,639 (2.6)
(g) Miscellaneous Capital Receipts	29,039 (25.5)	—5,113 (—6.9)	23,926 (12.7)	19,809 (19.9)	—7,191 (—8.9)	12,618 (7.0)

	1	2	3	4	5	6	7
II. Additional Resource Mobilisation	14,881 (13.1)	18,507 (24.8)	33,388 (17.7)	22,490 (22.7)	22,212 (27.5)	44,702 (24.8)	
III. Total Domestic Resources (I+ II)	1,02,495 (90.1)	41,255 (55.4)	1,43,750 (76.4)	97,039 (97.7)	50,961 (63.2)	1,48,000 (82.2)	
IV. Net Inflow from Abroad	16,348 (14.4)	.. (—)	16,348 (8.7)	18,000 (18.1)	.. (—)	18,000 (10.0)	
V. Budgetary Deficit	28,381 (25.0)	.. (—)	28,381 (15.1)	14,000 (14.1)	—.. (—)	14,000 (7.8)	
VI. Aggregate Resources (III+ IV+ V)	1,47,224 (129.5)	41,255 (55.4)	1,88,479 (100.2)	1,29,039 (129.9)	50,961 (63.2)	1,80,000 (100.0)	
VII. Centre's Assistance to States	—33,554 (—29.5)	33,264 (44.6)	—290 (—0.2)	—29,737 (—29.9)	29,737 (36.8)	.. (—)	
VIII. Resources Available for the Plan (VI+VII)	1,13,670 (100.0)	74,519 (100.0)	1,88,189 (100.0)	99,302 (100.0)	80,698 (100.0)	1,80,000 (100.0)	
Plan Outlay	1,13,670	74,519	1,88,189	99,302	80,698	1,80,000	

@Including Union Territories.

\*Balance from current revenue for States also includes upgradation grant for capital works, grants for special problems from the centre and the measures to be undertaken by special category States to meet the gap in the balance from current revenues.

Note : (1) The data are based on the latest estimates for 1985-86 to 1988-89 and the Annual Plan estimates for 1989-90.

(2) Figures at current prices were deflated by the WPI (with base 1981-82) to convert them into 1984-85 prices (base year of Seventh Plan).

(3) Figures in brackets are percentages of each item to Plan Outlay.

Source : Indian Economic Statistics, Public Finance 1989, Ministry of Finance, Government of India.

fund or the UTI subject to a maximum amount of Rs. 20,000 would be replaced by a new Section 88A of the Income-tax Act. Under the provisions of Section 88A, a tax rebate at the rate of 20 per cent of the investment in the eligible issue of capital or units subject to a maximum amount of investment eligible for tax rebate of Rs. 25,000 will be allowed. The Scheme of Section 80CC now incorporated in the new Section 88A will lapse after 31st March 1991.

#### Seventh Plan financing

8.48 A comparison of the original pattern of financing envisaged for the Seventh Five-Year Plan with the latest estimates of the outturn (converted to 1984-85 prices year-by-year) reveals certain noteworthy features. The contribution made by deficit financing has been twice the Plan projection, whereas significant shortfalls are noticed in balance from current revenues, contribution from public sector enterprises and additional resource mobilisation, thus depicting a clear picture of greater dependence on inflationary financing. To an extent the draft on resources through market loans, issue of bonds by public sector enterprises, and small savings and provident funds with substantial fiscal concessions has substituted additional resource mobilisation (see Table 8.11).

### 9. FINANCIAL INSTITUTIONS AND CAPITAL MARKET

#### Financial Institutions

9.1 The process of financial intermediation in India has been undergoing significant changes in recent years. Though the commercial and cooperative banking system has remained the predominant conduit for financial savings and their deployment, the rapid growth of assistance rendered by the financial institutions directly or indirectly during the past two and a half decades has now conferred on them an important position in the overall process of financial intermediation. There has been a provision of substantial concessive financial support from the Reserve Bank of India to the financial institutions.

9.2 The combined balance sheet of all banks and financial institutions indicates that the share of financial institutions in

the total assets increased from 27.6 per cent at the end of March 1981 to 31.2 per cent at the end of March 1986 and further to 33.6 per cent at the end of March 1989 (Table 9.1). While the banks now possess an asset position of Rs. 176,500 crore, the financial institutions possess about Rs. 89,400 crore (Tables 9.1 and 9.2). The outstanding loans and advances of the financial institutions were equivalent to about 51 per cent of bank credit outstanding in respect of scheduled commercial and cooperative banks as at the end of March 1989. Likewise, investments of those institutions in Government securities in bonds and debentures of public sector undertakings, and in private corporate sector equities and debentures, were equivalent to about 47 per cent of such investments by the banking system. Furthermore, in terms of annual operations, while the increase in outstanding loans and advances by all financial institutions (including NABARD) amounted to about Rs. 9,060 crore in 1988-89 the increase in outstanding credit by scheduled commercial and cooperative banks was of the order of Rs. 16,440 crore during the same year. (While these figures are not strictly comparable because of some flows between financial institutions and banks, they do give a dimensional idea of their relative operations).

9.3 Again, the increasing recourse of manufacturing and other non-financial companies to raising investible resources directly from the market mainly in the form of equities, debentures and public deposits, with the freedom to deploy them for working capital purposes has blurred the traditional distinction between working capital and investment capital. A significant proportion of the funds so mobilised have been contributed by the financial institutions through direct subscriptions to various instruments floated by the corporate sector. The active trading of capital market instruments in the short-term money market has further diluted the distinction between money and capital market.

9.4 The pattern of resources raised by the financial institutions vis-a-vis their lending and investment operations have assumed some complexity in recent years. In the first place, a major source of resource for them has been the Reserve

Table 9.1 : Financial Assets of Financial Institutions and Banks:

1981 and 1986 to 1989 as at the end of/last Friday of March

(Rupees crore)

Institution Category	1981	1986	1987	1988	1989
1	2	3	4	5	6
I A. Banks (1+2+3) <sup>1</sup>	46.987	108.372	127.876	147.186	176.461
1. All Scheduled Commercial banks <sup>2</sup>	44.622	103.627	122.513	140.747	168.480
2. Non-scheduled Commercial Banks <sup>3</sup>	9	23	30	36	53
Total Commercial Banks (1+2)	44.631	103.650	122.543	140.783	168.533
3. State Co-operative Banks <sup>4</sup>	2.356	4.722	5.333	6.403	7.928
B. Financial Institutions	17.911	49.137	58.348	71.571	89.422
4. Term lending institutions (All-India)	7.924	28.132	34.479	43.197	56.088
5. Insurance companies	8.254	16.665	18.579	22.134	26.130
Total All-India Institutions	16.178	44.797	53.058	65.331	82.218
6. State-Level Institutions	1.733	4.341	5.290	6.241	7.204
C. Aggregate (A+B)	64.898	157.509	186.224	218.757	265.883
D. Percentage Share					
(a) A to C	72.4	68.8	68.7	67.3	66.4
(b) B to C	27.6	31.2	31.3	32.7	33.6

1. Includes the following items (i) cash in hand and balances with the Reserve Bank, (ii) assets with the Banking system (iii) Investments (iv) Bank credit (total loans, cash credit and overdrafts and bills purchased and discounted) and dues from banks.

2. As per returns under Sec. 42 of the RBI Act, 1934.

3. As per returns under Sec. 27 of the Banking Regulation Act, 1949.

Table 9.2 : Financial Institutions : Total Outstanding Financial Assets

(Rupees crore)

Institution	1980-81	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4		
A. All-India Term Lending Institutions					
1. NABARD <sup>a</sup>	1635.1	6568.6	7445.4	8776.3	10363.8
2. ICICI	727.9	2210.6	2799.4	3652.8	4500.1
3. IDBI	3098.6	9633.9	11529.6	13922.3	17087.8
4. IFCI	589.1	1988.3	2426.7	3105.8	3707.3
5. IRBI	92.4	342.3	430.2	505.6	589.8
6. UTI	520.6	3346.3	4927.3	7222.7	12323.6
7. HUDCO	274.9	724.3	877.1	1036.6	1305.9
8. RFC	985.4	2055.1	2370.1	2869.1	3644.6
9. EXIM BANK	..	811.1	1042.2	1206.0	1478.4
10. HDFC	..	451.2	631.4	829.4	1086.9
Total of 'A' (1 to 10)	7924.0	28131.9	34479.4	43196.6	56088.2
B. State-Level Institutions					
11. SICs	1073.6	2996.7	3264.9	3914.9	4657.0
12. SIDCs	659.5	1643.7	2024.6	2329.6	2547.2
Total of 'B' (11 to 12)	1733.1	4340.6	5289.5	6244.5	7204.2
C. Insurance Companies					
13. LIC	6814.9	12935.9	14225.2	17086.9	20118.0
14. GIC and Subsidiaries	1198.9	2860.7	3323.0	3735.6	4418.8
15. DICGC	200.3	781.6	919.1	1168.9	1377.5
16. ECGC	39.5	86.9	112.0	142.3	215.3
Total of 'C' (13 to 16)	8253.6	16665.1	18579.3	22133.7	26129.6
Grand Total (A+B+C)	17910.7	49137.4	58348.2	71570.8	89422.0

<sup>a</sup>Figures relating to 1980-81 are pertaining to A.R.D.C. as NABARD was formed only during 1982.

Table 9 3: RBI Assistance—LTO Funds, Profit Allocation and Medium/Short-term Credit to Financial Institutions

(Rupees crore)

	1985-86		1986-87		1987-88		1988-89		1989-90	
	Sanctioned for the year	Outstanding/cumulative at end June	Sanctioned for the year	Outstanding/cumulative at end June	Sanctioned for the year	Outstanding/cumulative at end June	Sanctioned for the year	Outstanding/cumulative at end June	Sanctioned for the year	Outstanding/cumulative at end June
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A. Long-term Assistance from:</b>										
I. NIC (LTO) Fund										
1. I.D.B.I.	300.0	2,589.9	330.0	2,875.3	360.0	3,198.6	375.0	3,528.3	375.0	3,822.0
2. Exim Bank	80.0	260.0	85.0	345.0	90.0	435.0	95.0	530.0	95.0	625.0
3. I.R.B.I.	10.0	10.0	15.0	25.0	20.0	45.0	25.0	70.0	25.0	95.0
II. NHC (LTO) Fund/NHB							50.0	50.0	25.0	75.0
<b>B. RBI Profit allocation for the purpose of:</b>										
I. NRC (LTO) Fund/NABARD	300.0	2,005.0	350.0	2,355.0	300.0	2,655.0	330.0	2,985.0	330.0	3,315.0
II. NRC (Stabilisation) Fund/NABARD	25.0	620.0	10.0	630.0	10.0	640.0	10.0	650.0	10.0	660.0
Total (A+B)		5,489.9		6,230.3		6,973.6		7,813.3		8,592.0
<b>C. Medium/Short-term Credit Assistance by RBI</b>										
1. I.D.B.I.	200.0	125.6	300.0	82.5	300.0	24.5	300.0	42.4	400.0	116.6
2. I.F.C.I.	15.0		15.0		15.0		30.0		40.0	
3. I.C.I.C.I.	15.0		20.0		25.0		25.0		30.0	
4. S.F.C.s	38.6		55.2		65.4		82.9		88.0	
D. General Line of Credit—NABARD	1,300.0	860.9	1,400.0	949.7	1,950.9	1,416.8	2,700.0	2,277.7	3,350.0	2,858.4
Total (C+D)		986.5		1,032.2		1,441.3		2,320.1		2,925.0
Grand Total of outstanding/cumulative assistance (A+B+C+D)		6,471.4		7,262.5		8,414.9		10,133.4		11,517.0

Bank of India's financial assistance through its long-term operations (LTO) funds and also through short-term limits (table 9.3). The total outstanding under all LTO funds together amounted to Rs. 5,592 crore or about 11.0 per cent of the total reserve money as at end of June 1990. In addition, the outstanding of the NABARD under the short-term line of credit was Rs. 2,858 crore at the end of June 1990. The Reserve Bank's claims on commercial and cooperative banks amounted to Rs. 2,882 crore at the end of June 1990. Available evidence suggests that the resources gap of financial institutions funded by the Reserve Bank assistance has been significant. Apart from the Reserve Bank assistance, financial institutions raise domestic resources generally through bonds and debentures to which the banking system also subscribes. In turn, the financial institutions augment the resources of the banking system by way of extending re-finance and rediscounting facilities. The IDBI and NABARD provided Rs. 7,130 crore by way of re-finance and rediscount to scheduled commercial banks at the end of December, 1989 (excluding their short-term money market operations).

9.5 Finally, with the financial institutions acquiring substantial shareholding of the private corporate sector by way of their underwriting of, and direct subscriptions to, various primary issues, as also through conversion of loans into equity, they have started exerting greater influence on the capital market. Studies on the ownership pattern of shares and debentures of 5/5 IDBI-assisted companies as of June, 1986 reveal that the holdings by financial institutions in company equities constituted 22.5 per cent of the total equities, in preference shares as high as 71 per cent and in debentures as high as 58 per cent. They have also become active and dominant players in the secondary market; institutions like UTI, LIC and GIC are now the largest investors.

#### Assistance by Financial Institutions during 1980-90

9.6 According to the provisional data, assistance sanctioned by all-India financial institutions (viz., IDBI, IFCI, ICICI, IRBI, UTI, LIC and GIC and its subsidiaries) during 1989-90 (April-March) aggregated Rs. 15,572.4 crore, showing an increase of 13.2 per cent over the previous year (Rs. 13,759.8 crore). Disbursements during 1989-90 by these institutions totalled Rs. 9,341.0 crore recording a rise of 10.1 per cent over those of the previous year (Rs. 8,485.8 crore). As against this, during 1988-89 sanctions and disbursements by these institutions recorded increases of 56.5 per cent and 34.2 per cent, respectively, over 1987-88. The slow-down in the growth rates of the assistance sanctioned and disbursed by the financial institutions during 1989-90 appears to be attributable partly to the increasing reliance of the corporate sector on the capital market.

#### Corporate Investment

9.7 The Reserve Bank of India in its second study generating forecasts of investment in the private corporate business sector based on expected phasing of capital expenditures of projects sanctioned by three term-lending institutions, viz., IDBI, IFCI and ICICI up to the end of 1989, has estimated that capital expenditure aggregating Rs. 10,907 crore would have been incurred during 1989 which worked out to an increase of 44.3 per cent over the capital expenditure expected to have been incurred during 1988, including such expenditure under Bills Rediscounting Scheme and Technical Development Fund Scheme. Similar forecasts for 1990 in respect of various projects for which sanctions were accorded up to 1989 point to a total capital expenditure of about Rs. 14,000 crore representing an increase of 28 per cent over the corresponding estimate for 1989. There were in all 222 new projects with an estimated cost of Rs. 4,022 crore which accounted for 33.4 per cent of the total cost of all projects for which sanctions were accorded in 1989. Industry-wise, 'metals and metal products' would account for the largest share of 26.9 per cent, with 109 projects, in the total capital expenditure that is likely to be incurred during 1990. Although the 'textiles' (other than jute) industry had the largest number of project proposals (193), it accounted for only about 15.0 per cent of the total cost of all projects.

#### Small Industries Development Bank of India (SIDBI)

9.8 Small Industries Development Bank of India (SIDBI) was set up as a wholly-owned subsidiary of IDBI under the

Small Industries Development Bank of India Act, 1990, as the principal financial institution for promotion, financing and development of small-scale industries. It is also expected to coordinate the functions of existing institutions engaged in similar activities. SIDBI commenced its operations on April 2, 1990 and has taken over from IDBI the responsibility of administering the Small Industries Development Fund and the National Equity Fund.

#### Capital Market

9.9 The total capital issues by non-Government public limited companies during the Seventh Plan aggregated about Rs. 15,592 crore (at current prices), of which equity capital at Rs. 5,230 crore accounted for about one-third. Besides, during the Plan period, public sector undertakings issued debentures/bonds aggregating about Rs. 10,847 crore. In contrast, during the Sixth Plan, the total capital issues were of the order of around Rs. 3,500 crore. Apart from the strengthening of the primary capital market, the secondary market witnessed substantial growth in terms of turnover and market appreciation. The Reserve Bank of India All-India Index Numbers of Ordinary Shares Prices (base : 1980-81=100) recorded an average annual growth rate of about 24 per cent in the Seventh Plan as compared with about 9 per cent in the Sixth Plan.

9.10 Despite a slow-down in industrial production, the buoyancy in the capital market continued much more vigorously during 1989-90 than in the previous year. The primary as well as the secondary market exhibited considerable spurt in activity. Reflective of this buoyancy was the increased tempo shown by such indicators of investment intentions as industrial licences granted, approvals for the import of capital goods and clearances for foreign collaborations.

#### New Issues Market

9.11 During 1989-90, new capital issues by non-Government public limited companies reached a record level of Rs. 6,344 crore (through 404 issues) which was almost double the amount of capital issues of Rs. 3,164 crore (341 issues) in the previous year (Table 9.4). As in the previous year,

Table 9.4 : Capital Issues by Non-Government Public Limited Companies  
(Amount in Rupees Crores)

Type of Issue	1988-89@ (April—March)		1989-90@ (April—March)	
	Number	Amount	Number	Amount
1	2	3	4	5
(1) Equity Shares*	256 (47)	1,028 (109)	267 (57)	1,193 (261)
(2) Preference Shares	6	3	4	8
(3) Debentures	79	2,133	133	5,143
(i) Convertible	48	1,743	107	4,659
(ii) Non-Convertible	31	390	26	484
Total (1+2+3)	341	3,164	404	6,344

(a) Provisional.

\* Exclude bonus issues.

Notes :

- (1) Figures in brackets indicate premium amount which is included in the amount of equity issues.
- (2) Data exclude issues privately placed with financial institutions, etc.
- (3) Data include amount of over-subscriptions retained in cases where specific information was available. However, the amount of under-subscription was not taken into account as the information was not available.

the bulk of the increase in the amount of capital issues was on account of debentures, mainly convertible debentures. Dominance of a few large-size convertible debenture issues was a conspicuous aspect of the primary market in 1989-90. There were 18 large debenture issues (of over Rs. 100 crore each) by 10 companies which together accounted for Rs. 3,805 crore out of total debenture issues of Rs. 5,143 crore by non-Government public limited companies. Of these large issues, 12 issues accounting for as much as 82 per cent (or Rs. 3,106 crore) were offered by only five companies with each company issuing debentures for over Rs 500 crore; during 1988-89 there was only one such issue.

9.12 There was a significant increase in the number as well as the amount of equity issues also, with issues of equity shares increasing by 16.1 per cent from Rs. 1,028 crore in 1988-89 to Rs. 1,193 crore in 1989-90.

9.13 In 1989-90, according to provisional data, the Public Sector Undertakings (PSUs) issued bonds aggregating Rs. 3,465 crore, of which Rs. 100 crore were offered to the public and the balance Rs. 3,365 crore were for private placement. In 1988-89, PSU bonds of Rs. 2,498 crore were issued of which Rs. 100 crore were for public subscription and Rs. 2,398 crore by way of private placement.

9.14 Approvals (i.e., consents/acknowledgements including premium but excluding those of bonus shares) granted by the Controller of Capital issues (CCI) to both Government and non-Government companies during 1989-90 reached a new peak level at Rs. 11,705 crore (through 719 issues), showing an increase of 45.0 per cent over the previous year's issues of Rs. 8,072 crore through 641 issues (Table 9.5). Total approvals given by the CCI to non-Government companies during 1989-90 at Rs. 7,555 crore were 53.2 per cent higher than those in the previous year (Rs. 4,932 crore). The consents for the issue of PSU bonds increased sizeably from Rs. 3,140 crore in 1988-89 to Rs. 4,074 crore in 1989-90.

Table 9.5 : Consents/Acknowledgement Granted by the Controller of Capital Issues to Government and Non-Government Companies for raising capital

(Amount in Rupees crore)

Sr. No.	Type of Issue	1988-89		1989-90	
		April-March		April-March	
		Number	Amount	Number	Amount
1	2	3	4	5	6
1. Share of which:		484	1,487	514	1,752
(i) Initial		145	862	189	906
(ii) Further*		339	625	325	846
2. Debentures & Bonds		157	6,585	205	9,953
(i) Convertible		74	3,134	155	7,155
(ii) Non-Convertible		83	3,451	50	2,798
3. Sub-Total (1+2)		641	8,072	719	11,705
4. Bonus Shares		267	196	319	374
5. Grand Total (3+4)		908	8,268	1,038	12,079

\*Including premium of Rs. 112 crore for 77 issues in 1988-89 and Rs. 213 crore for 77 issues in 1989-90.

Source : Controller of Capital Issues.

#### Public Response

9.15 Performance analysis of new public issues, based on provisional data available from the stock exchanges, reveals that there was improvement in the overall response to public issues during 1989-90 : approximately 95 per cent of the number of issues offered during 1989-90 were oversubscribed

as compared with about 87 per cent during 1988-89. The number of issues with multiple responses, like 10 times over-subscription, were relatively higher in 1989-90 than in 1988-89.

#### Policy Initiatives

9.16 The tremendous growth, in recent years, of the capital market brought in its wake some issues and problems which had to be addressed with a view to ensuring that new issue and stock markets functioned in a healthy and orderly manner and that investors' confidence was sustained. Towards this end, a number of policy measures were initiated during the year, which are noted below.

9.17 In September, 1989, the Controller of Capital Issues (CCI) prescribed norms for mobilising funds by companies under approved capital issues of more than Rs. 300 crore and such companies were required to phase out calls with a view to reducing bunching of large capital issues. The Union Government also asked the financial institutions to closely monitor the utilisation of capital raised through such large issues. In January 1990, the CCI further laid down some standard conditions which would be applicable to all public issues of Rs. 50 crore and above. It was stipulated that the funds raised through public issues could be invested, before their deployment in the proposed activities, only in institutions and instruments of nationalised and co-operative banks, UTI, financial institutions and public sector undertakings (other than public sector bonds). The utilisation of the proceeds of the issues would be monitored by the designated financial institutions. In January 1990, the Union Government also directed CCI not to permit any company to make any fresh issues within 12 months from the closure of its earlier issue or within six months of listing of its shares or debentures of its earlier issues, whichever was later. It was further decided by the Government that all applications to CCI for issue of capital should be accompanied by a certificate signed by the company secretary confirming that all refund orders against the previous issues and all shares/debentures certificates have been issued.

9.18 The Union Government modified the existing Employees' Stock Option Scheme in July 1989 in terms of which the portion of shares earmarked for the employees but not taken up by them, can be allotted to the financial or investment institutions and mutual funds. In August 1989, the Government liberalised the guidelines for investment under the various equity support schemes which empowered the banks and financial institutions to disinvest shares under these schemes to the public through offer for sale.

9.19 The Union Government approved the creation of Over-the-Counter Exchange of India (OTC) under the Securities Contract (Regulation) Act in August 1989 which would help in introducing a multi-tiered market for securities. In January 1990, the Government reduced the minimum period between a previous sanction and a fresh application for bonus issues from 24 months to 12 months. With a view to instilling confidence among investors, in January 1990, investors were allowed the choice to opt out of converting debentures into equity, investors were also given a reasonable period to exercise this option.

9.20 During the year under review, the Reserve Bank of India also undertook certain policy measures having a bearing on the capital market. It issued detailed guidelines governing mutual funds operations of banks and of their subsidiaries in July 1989. In October 1989, the Reserve Bank directed all banks not to release the application money received by the companies issuing shares/debentures until their allotments were made. It also directed all banks and their subsidiaries not to offer safety net facilities for public issues of shares and debentures. In November 1989, the Reserve Bank directed all banks and their subsidiaries to ensure that the commitments under a single obligation for underwriting public issues, providing buy-back facilities and stand-by arrangements do not exceed 15 per cent of the issue amount. In January 1990, the Reserve Bank banned mutual funds from entering into buy-back deals while picking up part of promoters' quota of equity shares in newly promoted companies.



9.21 In April 1990, the Government of India issued fresh guidelines for share and debenture issues by companies with a view to ensuring improved protection for subscribers. These included a stipulation that allotment can be made only if 90 per cent of the amount issued is subscribed.

9.22 In May 1990, the Government of India issued a set of guidelines with a view to making share transactions by financial institutions more transparent. These guidelines are applicable to all-India public financial and investment institutions like IDBI, UTI, LIC, GIC, IFCI and ICICI. It has been specified, inter alia, that any sale of over one per cent of a company's paid-up shares or debentures would have to be notified to the public.

9.23 In June 1990, the Government of India modified the guidelines regarding cost of public issues with the objective of enabling companies to make suitable payments to merchant bankers. The limits of 0.5 per cent and 0.2 per cent of fees payable to managers to the issue would, respectively, be applicable for issues up to Rs. 25 crore (instead of Rs. 5 crore) and for issues exceeding Rs. 25 crore (instead of issues exceeding Rs. 5 crore).

#### Securities and Exchange Board of India (SEBI)

9.24 The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has been entrusted with the task of supervision of merchant banking activities and activities of mutual funds and also of ensuring the transparency of transactions relating to sales of shares by the financial institutions and takeover of the management of companies through acquisition of shares on the stock exchanges. As per the Government guidelines for merchant bankers, any person or body proposing to engage in the business of merchant banking would need authorisation by SEBI. In order to make the transactions in shares, convertible debentures and preference shares by all-India public financial and investment institutions (IDBI, ICICI, IFCI, UTI, LIC, GIC and its subsidiaries) more open and transparent, it has been decided by Government that any sale of over 1 per cent of the paid-up capital of a company and the resultant transaction and price shall be disclosed to the general public by the institution concerned through press release within a day of the transaction. Information on these transactions are also to be sent to SEBI and the concerned Stock Exchanges. The Government has amended clause 40B of the listing agreement in respect of take-over offer.

9.25 The Government has also announced the guidelines for mutual funds which prescribe that all mutual funds except those established by a statute would require the approval of the Controller of Capital Issues and SEBI. Existing mutual funds also should get themselves registered with SEBI. The accounting and disclosure requirements of mutual funds would be prescribed by SEBI.

#### Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL)

9.26 The Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL), which started its operations in January 1988, rated 71 debt instruments (i.e., debentures, fixed deposit programmes, and commercial paper programmes) issued by 49 companies (25 manufacturing companies and 24 finance companies) covering a value of Rs. 2,098.4 crore during 1989-90 (April-March) as compared with 26 debt instruments issued by 22 companies (11 manufacturing companies and 11 finance

companies) for a value of Rs. 906.2 crore during the previous year. The instrumentwise break-up indicates that debentures of Rs. 681.1 crore and fixed deposit programmes of Rs. 1,189.5 crore were rated as compared with Rs. 142.9 crore (debentures) and Rs. 763.3 crore (fixed deposit programmes) in 1988-89. The rating for the commercial paper programmes was introduced during 1989-90 and the value aggregated Rs. 227.8 crore. The cumulative number and value of debt instruments rated up to March 31, 1990 were 101 and Rs. 3,093.4 crore, respectively.

#### Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL)

9.27 The Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL), which was set up as a depository institution in August 1988, received delivery instructions for purchase and sale of securities of Rs. 349 crore during 1989-90 (April-March) as compared with Rs. 110 crore in the previous year. The Corporation has been handling the operations of UTI since its inception. During the year under review, the services were extended to New India Assurance Company Limited, LIC Mutual Fund and General Insurance Corporation of India.

9.28 SHCIL in consultation with major stock exchanges and other connected agencies concerned with the development of country's capital market has submitted to the Government of India proposals by way of draft legislation, viz., Stock Holding and Special Transfer Procedure Act. The Act aims at making suitable legal provisions for the introduction of electronic transfer of scrips through a Central Securities Depository.

#### Equity Prices

9.29 On a point-to-point basis, the Reserve Bank's All-India weekly index numbers of ordinary share price (base: 1980-81=100) registered an increase of 25.9 per cent during the financial year 1989-90 from 317.7 for the week ended April 1, 1989 to 400.0 for the week ended March 31, 1990. This was on the top of an increase of 62.8 per cent recorded during the previous year. The average of the Reserve Bank's All-India weekly index numbers of ordinary share prices during the financial year 1989-90 reached a new peak at 359.4 registering an increase of 111.9 points (or 45.2 per cent) over the average index for the previous year of 247.5 (Table 9.6). The past two years have also seen phenomenal increases in share transactions in the secondary market. The average monthly turnover at the Bombay Stock Exchange rose from Rs. 743.6 crore in 1987 to Rs. 1,439.5 crore in 1988 or an increase of 93.6 per cent and further to Rs. 2,336.0 crore in 1989 or a increase of 62.3 per cent.

9.30 The volatility in equity prices was much less during 1989-90 as compared with the previous year. This is reflected in such a low coefficient of variation as 6.10 per cent for the year as compared with that of 16.36 per cent for the previous year. Likewise, the dispersion (or the range) in the index of ordinary prices was lower at 92.9 points during 1989-90 as compared with 121.1 points (experienced at lower index number levels) during 1988-89.

9.31 The average gross yield on equities for the financial year 1989-90 was lower at 3.20 per cent as compared with 3.76 per cent in the previous year.

Table 9.6 : Reserve Bank of India—All India Index Numbers of Ordinary Share Prices  
(Base : 1980-81=100)

Month/Year	Average	Highest*	Lowest*	Last week-end of the month
1	2	3	4	5
1988-89 (April-March)	247.5 (+19.4)@	308.2	187.1	308.2
1989-90 (April-March)	359.4 (+45.2)@	411.4	317.7	403.6
April 1989	335.7	355.7	317.7	355.7
May	342.9	348.6	338.6	338.6

June	340.5	347.5	332.7	347.5		
July	350.8	356.9	343.7	343.7		
August	336.5	339.4	333.7	334.6		
September	350.0	353.6	343.9	353.6		
October	358.4	363.4	355.0	363.4		
November	362.8	366.6	359.7	361.8		
December	383.7	396.3	359.9	396.3		
January 1990	400.6	411.4	387.1	387.1		
February	372.5	377.8	368.0	372.6		
March	378.1	400.0	367.1	400.0		
1990-91						
April	399.9	410.6	397.7	404.3		
May	409.4	414.3	405.2	414.3		
June*	141.8	420.6	410.0	412.8		
Memorandum Items	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	Average for the five-year period (1985-86 to 1989-90)
A. Coefficient of variation (In percentage)*	12.52	3.65	4.82	16.36	6.10	8.69
B. Dispersion (The Range)*	57.0	38.3	40.0	121.1	93.7	70.02

\* Based on weekly indices.

@ Indicates percentage variation over the previous year.

† Provisional.

## 10. DEVELOPMENTS IN THE EXTERNAL SECTOR

### Balance of Payments

10.1 Despite a strong growth in exports, the balance of payments continued to be under pressure during 1989-90 due to a rise in the import bill and large repayments to the IMF under the Extended Fund Facility (EFF). The rise in imports was partly due to an increase in POL imports, purchase of civilian aircrafts and the rise in international prices of certain commodities. Although the balance of payments data for the year 1989-90 are not yet available, based on available information, the current account deficit in rupee terms is estimated to be marginally lower than the deficit of Rs. 10,429 crore in 1988-89. In SDR terms, however, the current account deficit would be lower by about 10 per cent than in the previous year. The ratio of the current account deficit to GDP (at current market prices), which went up sharply from 1.9 per cent in 1987-88 to 2.7 per cent in 1988-89, is estimated to have come down to 2.3 per cent in 1989-90. Thus, the current account deficit during the Seventh Plan period would average around 2.2 per cent as against the Planning Commission's estimate of 1.6 per cent for the Plan period and much higher than the average of 1.3 per cent during the Sixth Five Year Plan. Table 10.1 presents data on India's balance of payments on current account as a percentage of GDP for the Sixth Plan period and from 1985-86 to 1988-89.

10.2 The balance of payments situation has remained under pressure throughout the Seventh Plan period owing to large

trade deficits and a fall in the surpluses on invisible account, as well as due to large repurchases from the IMF under the EFF which amounted to SDR 2,752 million during the Seventh Plan period. During the first four years of the Seventh Plan, for which balance of payments data are available, the current account deficits have averaged around Rs. 7,120 crore (SDR 4,363 million) per annum as against an annual average of Rs. 2,277 crore (SDR 2,100 million) during the Sixth Plan period (Table 10.2).

10.3 Table 10.3 presents a summary of India's balance of payments for the period 1985-86 to 1988-89.

### Foreign Exchange Reserves

10.4 During the fiscal year 1989-90, India's foreign exchange reserves, comprising foreign currency assets of the Reserve Bank of India, gold and SDR holdings, declined by Rs. 788 crore to Rs. 6,251 crore as against a decline of Rs. 647 crore during 1988-89 (Table 10.4). In SDR terms, these reserves amounted to SDR 3,045 million@ at the end of March 1990, showing a fall of SDR 670 million during 1989-90, as against a decline of SDR 771 million during 1988-89. Thus, during the Seventh Plan period, foreign exchange reserves in SDR terms declined by SDR 2,959 million. If repayments to IMF are excluded, the reserves show an increase of SDR 333 million as against a loss of SDR 4,375 million (excluding drawals of IMF credits amounting to SDR 4,496 million) during the Sixth Plan period (Table 10.5). During April to June 1990 quarter, foreign exchange

@ Gold is value at SDR 35 per ounce, as in the International Financial Statistics (IFS) of the IMF.

Table 10.1 : Current Account Transactions as Proportion of GDP at Current Market Prices

	(In percentage)				
	1980-85 Period annual average	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89 (Provisional Estimate)
1	2	3	4	5	6
1. Exports	5.0	4.4	4.5	5.0	5.2
2. Imports	8.4	8.1	7.7	7.8	8.8
3. Trade deficit	3.4	3.7	3.2	2.8	3.5
4. Invisible Receipts (including official grant assistance)	3.6	3.0	2.8	2.8	2.9
5. Invisible payments	1.5	1.6	1.6	1.9	2.0
6. Invisible (net) (4—5)	2.1	1.4	1.2	0.9	0.9
7. Current Account Deficit@ (3—6)	1.3	2.3	2.0	1.9	2.7

@Official grants are treated as part of current account receipts here they are covered under net inflow of foreign resources presented in Table 2.2.

Table 10.2 : Current Account Deficit

Year	In Rs. Crore	In SDR Million	In U.S. \$ Million
1	2	3	4
1985-86	—5,927	—4,587	—4,844
1986-87	—5,830	—3,774	—4,562
1987-88	—6,293	—3,675	—4,854
1988-89P	—10,429	—5,414	—7,202
Period Average			
1985-86 to 1988-89	—7,120	—4,363	—5,429
1980-81 to 1984-85	—2,277	—2,100	—2,334

P—Provisional Estimates.

Table 10.3 : India's Balance of Payments

Item	(Rupees crore)			
	1988-89 (Provisional) Estimates)	1987-88 Actuals	1986-87 (Partially Revised)	1985-86
1	2	3	4	5
A. Current Account				
1. Imports, c.i.f.	34,513.0	25,692.5	22,668.9	21,163.6
2. Exports, f.o.b.	20,510.5	16,396.4	13,315.0	11,577.6
3. Trade Balance	—14,020.5	—9,296.1	—9,353.9	—9,586.0
4. Official transfers (net)	665.8	532.4	752.3	307.4
5. Other invisibles (net)	2,907.6	2,471.1	2,998.6	3,322.8
6. Current Account (net)	—10,429.1	—6,292.6	—5,830.0	—5,927.3
B. Capital Account				
1. External Assistance	3,186.2	2,944.8	1,807.6	1,675.9
Disbursements	4,859.6	4,453.9	3,056.2	2,481.0
Repayments	—1,673.4	—1,509.1	—1,248.6	805.1
2. Commercial Borrowings*	3,197.9	1,266.0	2,513.2	1,166.0
Disbursements	4,293.1	1,945.7	3,115.6	1,827.0
Repayments	—1,095.2	—679.7	—602.4	—661.0
3. Non-Resident Deposits (net)	2,475.2	1,840.1	1,650.0	1,767.0
4. Other Capital (net)	2,261.4	1,442.2	—71.4	284.8
5. Total Capital Account (net)	11,120.7	7,493.1	5,899.4	4,893.7
C. IMF (net)	—1,547.3	—1,20.9	—672.3	—253.0
D. SDR Allocation	—	—	—	—
E. Capital Account, IMF and SDR Allocation	9,573.4	6,284.1	5,227.1	4,640.7
F. Total Current Account, Capital Account, IMF, and SDR Allocation	—855.7	—8.5	—692.9	—1,286.6
G. Errors and Omissions	—593.6	—947.7	—129.3	1,580.1
II. Reserves and Monetary Gold (Increase,— Decrease+)	1,449.3	956.2	732.2	700.5

\*Excluding refinancing credits.

Table 10.4 : India's Foreign Exchange Reserves

End of the month	Foreign Exchange Reserves (In Rupees Crore)				Total Foreign Exchange Reserves* (In SDR million)	Reserve Position in the Fund* (Rupees Crore)	EFF Transactions with the IMF (In SDR million)		
	SDRs**	Gold	Foreign Exchange	Total (2+3+4)			Gross Drawings	Cumula- tive Repur- chases	Out- standing Net Drawing (7—8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
March 1987	231.76	274.28	7,645.17	8,151.21	5.113	809.44	3,900.00	562.50	3,337.50
March 1988	125.25	274.28	7,287.14	7,686.67	4.486	875.15	3,900.00	1,266.67	2,633.33
June 1988	149.70	274.28	5,819.52	6,243.50	3.600	899.91	3,900.00	1,425.00	2,475.00
March 1989	160.74	274.28	6,604.63	7,039.65	3.715	984.14	3,900.00	2,070.85	1,829.15
June 1989	212.46	274.28	6,075.17	6,561.91	3.408	1,008.26	3,900.00	2,218.77	1,681.23
March 1990	183.55	280.67	5,787.17	6,251.39	3.045	1,091.32	3,900.00	2,752.10	1,147.90
June 1990	206.64	280.67	5,356.17	5,843.48	2.784	1,128.96	3,900.00	2,862.52	1,037.48

\*Gold is valued at SDR 35 per ounce as in the International Financial Statistics of the IMF.

\*\*At Rupee—SDR exchange rate at the end of the respective months.

+Equivalent to SDR 487 million

Note : Gross drawings, repurchases and outstanding liabilities to the IMF (i.e. net drawings) are in respect of the Extended Fund Facility, that is, exclusive of Trust Loans.

Table 10.5 : Movement in Foreign Exchange Reserves

(In SDR Million)

Period/Period End	Level of Foreign Exchange Re- serves (exclud- ing Reserve Position in Fund)	Movement in Foreign Exchange Reserves	Net Drawals (+)/Repay- ments (—) of IMF Credit	Movement in Foreign Ex- change Reserves (net of IMF Credit)
1	2	3	4	5
1979-80	5,883	—	—	—
VI Plan Period	6,004	121	—4,496(A)	—4,375
VII Plan Period	3,045	—2,959	—3,272(B)	+333
1988-89	3,715	—771	—909(C)	+138
1989-90	3,045	—670	—786(D)	+116

(A) SDRs 3,900 million were drawn under EFF, SDRs 67 million under CFF (net) and SDRs 529 million under Trust Fund.

(B) SDRs 2,752 million were used under EFF, SDRs 67 million CFF and SDRs 473 million under Trust Fund.

(C) SDRs 804 million were used under EFF and SDRs 105 million under Trust Fund.

(D) SDRs 681 million were used under EFF and SDRs 105 million under Trust Fund.

reserves declined by Rs. 408 crore as against a fall of Rs. 478 crore in the corresponding quarter of 1989. In SDR terms, the fall in reserves during April to June 1990 was SDR 261 million, that is, somewhat lower than the fall of SDR 307 million during the quarter April to June 1989.

10.5 Repayments to the IMF during the fiscal year 1989-90 amounted to Rs. 1,688 crore (Rs. 1,460 crore under the Extended Fund Facility and Rs. 228 crore under the Trust Fund Loan), as against Rs. 1,749 crore (Rs. 1,547 crore under EFF and Rs. 202 crore under the Trust Fund Loan) in the fiscal year 1988-89. During the Seventh Plan period, out of EFF drawings of SDR 3,900 million, SDR 2,752 million was repaid. At the end of March 1990, outstanding debt to the IMF under the EFF and the Trust Fund aggregated SDR 1,148 million and SDR 56 million, respectively. These were equivalent to Rs. 2,572 crore and Rs. 125 crore respectively at the prevailing exchange rates.

#### Foreign Currency Assets

10.6 Among the three components of foreign exchange reserves, foreign currency assets of the RBI declined during 1989-90 (July—June) by Rs. 719 crore as against a rise of Rs. 256 crore during the corresponding period of 1988-89.

#### SDRs

10.7 Holdings of SDRs fell by SDR 13.5 million during 1989-90 (July—June) as compared with a rise of SDR 21.6 million during the comparable period of 1988-89. This decline was the net result of acquisition of SDRs worth SDR 787.0 million and receipts on account of remuneration of SDR 19.5 million, repurchases of SDR 643.8 million from the IMF, and payments of charges/interest amounting to SDR 176.2 million (net of interest subsidy) paid to the IMF.

10.8 Gold holdings of the Reserve Bank of India at Rs 281 crore at end-June 1990 were higher by Rs. 7 crore than the level of Rs. 274 crore at end-June 1989

#### Merchandise Trade

10.9 During 1989-90, despite an accelerated pace of export growth, the trade deficit increased, although marginally, over the preceding year. While the strength of export performance

that has asserted itself since 1986-87 was sustained and further improved upon, this was more than offset by a sharp growth in imports. According to the provisional data of the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), the trade deficit widened marginally by Rs. 319 crore or by 4.3 per cent to Rs. 7,731 crore in 1989-90 from Rs. 7,412 crore in 1988-89. As compared with partially revised data for 1988-89 (Rs. 7,892 crore), the trade deficit was marginally lower by 2.0 per cent (Table 10.6).

Table 10.6 : India's Foreign Trade during Sixth and Seventh Plans

Year	In Rupees crore			In Million of US\$			In Millions of SDRs		
	Exports	Imports	Trade Balance	Exports	Imports	Trade Balance	Export	Imports	Trade Balance
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Sixth Plan</b>									
1980-81	6,711 (4.6)	12,549 (37.2)	-5,838	8,484 (7.1)	15,865 (40.5)	-7,381	6,594 (7.8)	12,330 (41.5)	-5,736
1981-82	7,806 (16.3)	13,608 (8.4)	-5,802	8,704 (2.6)	15,173 (-4.4)	-6,469	7,553 (14.5)	13,166 (6.8)	-5,613
1982-83	8,803 (12.8)	14,293 (5.0)	-5,490	9,107 (4.6)	14,787 (-2.5)	-5,680	8,334 (10.3)	13,531 (2.8)	-5,197
1983-84	9,771 (11.0)	15,831 (10.8)	-6,060	9,450 (3.8)	15,310 (3.5)	-5,860	8,931 (7.2)	14,470 (6.9)	-5,539
1984-85	11,744 (20.2)	10,134 (8.2)	-5,390	9,878 (4.5)	14,412 (-5.9)	-4,534	9,842 (10.2)	14,359 (-0.8)	-4,517
Average (Sixth Plan)	8,967 (13.0)	14,683 (13.9)	-5,716	9,125 (4.5)	15,110 (6.2)	-5,985	8,251 (10.0)	13,571 (11.4)	-5,320
<b>Seventh Plan</b>									
1985-86	10,895 (-7.2)	19,658 (14.7)	-8,763	8,905 (-9.8)	16,067 (11.5)	-7,162	8,431 (-14.3)	15,211 (5.9)	-6,780
1986-87	12,452 (14.3)	20,096 (2.2)	-7,644	9,745 (9.4)	15,727 (-2.1)	-5,982	8,061 (-4.4)	13,009 (-14.5)	-4,948
1987-88	15,674 (25.9)	22,244 (10.7)	-6,570	12,089 (24.0)	17,156 (9.1)	-5,067	9,155 (13.6)	12,992 (-0.1)	-3,837
1988-89 (PR)	20,302 (29.5)	28,194 (26.7)	-7,892	14,019 (16.0)	19,469 (13.5)	-5,450	10,540 (15.1)	14,637 (12.7)	-4,097
1989-90 (P)	27,681 (36.3)	35,412 (25.6)	-7,731	16,626 (18.6)	21,269 (9.2)	-4,643	12,954 (22.9)	16,572 (13.2)	-3,618
Average (Seventh Plan)	17,401 (19.8)	25,121 (16.0)	-7,720	12,277 (11.6)	17,938 (8.2)	-5,661	9,828 (6.6)	14,484 (3.4)	-4,656

P=Provisional

PR=Partially revised

Figures in brackets represent annual percentage changes, or annual average growth rates for the Plan Periods.

Source : DGCI & S.

10.10 During 1989-90, the robust pace of export growth achieved in recent years was further accelerated. According to DGCI&S data, exports rose by 36.3 per cent in rupee terms to Rs. 27,681 crore. In terms of U.S. dollars and SDRs too, the growth rates of exports of 18.6 per cent and 22.9 per cent, respectively, were noteworthy when compared with those of 16.0 per cent and 15.1 per cent, respectively, recorded during the preceding year. Imports at Rs. 35,412 crore, were up by 25.6 per cent, as compared with a growth of 26.7 per cent recorded during 1988-89. In SDR terms, imports rose by 13.2 per cent in 1989-90 as against an increase of 12.7 per cent during the preceding year. In terms of US dollar, import growth at 9.2 per cent during 1989-90 was significantly lower than that of 13.5 per cent in 1988-89.

10.11 In spite of the pressures from imports continuing, the strength of export growth resulted in a distinct improvement in the import-purchasing power of exports. The export-import ratio rose from 72.0 per cent in 1988-89 to 78.2 per cent in 1989-90. These ratios are, however, expected to be much lower when assessed on a payments basis.

#### Exports

10.12 The noteworthy performance of exports during 1989-90 occurred in an environment of expansion in world trade. The volume growth of exports, estimated at approximately 14 per cent, taking into account movements in international prices of tradeables and in the external values of major currencies, was well above the growth of world trade

in real terms (7.5 per cent in 1989). During the year, several steps were taken to simplify and rationalise procedures so as to provide easier access to the various monetary and fiscal incentives in place to support export efforts. The Import-Export Policy 1988-91 was terminated a year earlier than scheduled and a new Import-Export Policy 1990-93 was announced on April 30, 1990. The new policy aims at strengthening the momentum of the process of liberalisation set in motion over the past few years. Under the new policy, replenishment licences have been endowed with greater flexibility in terms of categories of items that can be imported. A new Blanket Advance Licensing Scheme has been introduced in favour of established exporters with a view to reducing procedural delays. Imports of capital goods at concessive rates of customs duty have been allowed under a new scheme for manufacturer-exporters, subject to export obligation. **Emphasis has been brought to bear on increased net foreign exchange earnings from exports.** The supportive exchange rate policy has also contributed to improving the competitiveness of Indian products abroad.

10.13 Available commoditywise data for 1989-90 indicate that, as in the recent past, the major impetus for the strong export performance emanated from the manufacturing sector. Exports of manufactured goods accounted for 76.8 per cent of the increase in total exports during the period. Significant increases were recorded in exports of chemicals and allied products (40.7 per cent) and readymade garments (53.7 per cent). Other commodities which recorded increases in the category of manufactures were leather and leather manufactures (30.9 per cent), gems and jewellery (20.4 per cent) and engineering goods (40.5 per cent), the latter two, however, having substantial import content. Besides, the performance of these items tended to be subdued in comparison with the preceding years. Exports of primary products rose by 36.1 per cent over those in the preceding year and contributed 21.4 per cent of the total increase in exports (Table 10.7). Of this increase in primary products, 77.6 per cent was provided by the group of agricultural and allied products which

recovered from the constraint of reduced exportable surplus, experienced in the preceding year. Items which recorded substantial increases were cotton (357 per cent), oilmeals (48 per cent), rice (29 per cent), tea (51 per cent), processed items (32 per cent), cashew kernel (33 per cent), and fruits and vegetables (27 per cent). Exports of marine products remained broadly at the preceding year's level, while those of spices declined. Exports of ores and minerals, particularly iron ore (38 per cent), also performed well.

10.14 Destinationwise, the OECD group of countries continued to account for the major share of India's exports, with EEC as the most important market (Table 10.8). The share of East European countries in India's total exports also went up from 16.5 per cent in 1988-89 to 19.3 per cent in 1989-90.

#### Imports

10.15 The sharp surge in imports witnessed during 1988-89 continued in 1989-90, reflecting mainly the continuing strength of domestic demand, escalation in the unit values of certain imports which counterbalanced the subdued volume growth of these items and the imports of civilian aircraft effected during the year.

10.16 The category of bulk imports, which represent imports of basic consumption goods as well as basic inputs for industry, rose sharply by 27.4 per cent to Rs. 14,239 crore in 1989-90, thereby reflecting the continuing rising trend in these imports that has emerged since 1987-88 (Table 10.9). Under the category, net oil imports (oil imports net of POL exports), which had increased by 14.0 per cent (or Rs. 475 crore) during 1988-89, registered a substantial increase of 44.1 per cent (Rs. 1,708 crore) during 1989-90, accounting for 55.7 per cent of the total increase in bulk imports. The higher outgo on account of POL imports was due to the larger volume of imports, higher import costs and the firming up of the U.S. dollar, the currency in which international oil transactions are invoiced. Among the non-oil bulk imports, commodities which recorded major increases were: fertilisers

Table 10.7 : India's Exports of Principal Commodities

Commodity Group	(Rupees crore)				
	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89 (PR)	1989-90 (P)
1	2	3	4	5	6
Primary Products	3,803 (34.9)	4,139 (33.2)	4,160 (26.6)	4,374 (21.5)	5,951 (21.5)
Of which :					
1. Agricultural and Allied Products	3,018 (27.7)	3,422 (27.5)	3,411 (21.8)	3,347 (16.5)	4,571 (16.5)
2. Ores and Minerals	785	717	749	1,027	1,380
Manufactured Goods	6,447 (59.2)	7,902 (63.5)	10,865 (69.3)	14,641 (72.1)	20,310 (73.4)
Of which :					
1. Textile Fabrics and Manufactures	1,795	2,179	3,225	3,700	5,246
Of which :					
Cotton yarn, fabrics, made-ups	574	637	1,155	1,131	1,480
Readymade Garments	1,067	1,311	1,813	2,097	3,224
2. Leather and Leather Manufactures	770	922	1,251	1,490	1,951
3. Handicrafts	1,881	2,548	3,249	5,194	6,285
Of which :					
Gems and Jewellery	1,503	2,074	2,617	4,399	5,296
4. Chemicals and Allied Products	498	583	801	1,534	2,158
5. Engineering Goods	954	1,133	1,502	2,364	3,321
Minerals and Lubricants*	645 (5.9)	411 (3.3)	649 (4.1)	505 (2.5)	697 (2.5)
<b>TOTAL (including others)</b>	<b>10,895</b>	<b>12,452</b>	<b>15,674</b>	<b>20,302</b>	<b>28,681</b>

P=Provisional

PR=Partially Revised.

\* =Relates to petroleum crude and petroleum products only

Figures in brackets represent percentages to total exports.

Source : DGCI & S.

Table 10.8 : Direction of Trade

(In percent)

Region	1984-85		1988-89(P)		1989-90(P)	
	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports
I	2	3	4	5	6	7
I. OECD	44.9	48.7	58.2	60.5	55.9	60.0
Of which						
(a) EEC	17.0	24.6	24.4	31.4	25.0	33.1
(b) USA	15.0	9.9	18.4	11.5	16.2	12.0
(c) Asia and Oceania	10.1	8.6	12.1	12.2	11.2	10.7
Of which :						
Japan	8.8	7.2	10.7	9.5	9.9	8.0
II. OPEC	8.0	19.4	6.0	13.3	6.6	14.3
III. East Europe	19.3	12.9	16.5	7.0	19.3	8.4
IV. Developing Countries	27.8	19.0	19.3	19.1	18.2	17.3

P : Provisional

Source : D.G.C.I. &amp; S.

major increases were : fertilisers (91.4 per cent or by Rs. 848 crore), particularly manufactured fertilisers (149.1 per cent or Rs. 735 crore); non-ferrous metals (59.4 per cent or Rs. 467 crore); iron and steel (19.0 per cent or Rs. 368 crore); and pulp and waste paper (20.2 per cent or Rs. 51 crore). Imports of sugar, which were virtually absent in (1988-89) amounted to Rs. 97 crore during 1989-90. Some import substitution was possible in respect of iron and steel, metalliferous ores and scrap, crude rubber and paper board and manufactures as is evident in the decelerating growth rates of these imports during the year and

the improvement in domestic availability that has taken place in recent years. Considerable import saving was secured in respect of bulk consumption goods, namely, edible oils (by 71.0 per cent or by Rs. 516 crore), cereals and preparations (40.1 per cent or by Rs. 253 crore), and pulses (by 40.5 per cent or by Rs. 155 crore). Among non-bulk imports, capital goods rose by 27.3 per cent during 1989-90. The group of export-related imports experienced a slackening of growth as they went up by only 24.5 per cent as against 63.0 per cent during 1988-89.

Table 10.9 : India's Imports of Principal Commodities

(Rupees crore)

Commodity Group	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89 (PR)	1989-90 (P)
I	2	3	4	5	6
I. Bulk Imports	10 763	8,24	9 084	11,175	14,239
Of which :	(54.8)	(39.9)	(40.8)	(39.6)	(40.2)
(a) Petroleum, petroleum products & related materials	4,989	2,811	4,043	4,374	6,274
	(25.4)	(14.0)	(18.2)	(15.5)	(17.7)
(b) Bulk consumption goods	1 466	1,179	1,503	1,741	91.4
	(7.5)	(5.9)	(6.7)	(6.2)	(2.6)
(i) Cereal and cereal preparations	110	87	66	631	378
(ii) Edible oils	749	634	969	727	211
(iii) Pulses	189	234	275	383	228
(iv) Sugar	418	224	193	Neg.	97
(c) Other bulk items	4,308	4,034	3,538	5 060	7,051
	(21.9)	(20.0)	(15.9)	(17.9)	(19.9)
(i) Fertilisers	1,436	921	508	928	1,776
Crude	163	145	139	185	253
Sulphur & unroasted iron pyrites	220	220	181	250	295
Manufactured	1,053	576	188	493	1,228
(ii) Non-ferrous metals	342	517	639	786	1,253
(iii) Paper, paperboard and manufactures thereof (including newsprint)	226	217	270	306	358
(iv) Crude rubber	101	107	120	172	172

1	2	3	4	5	6
(v) Pulp and Waste paper	245	244	239	253	301
(vi) Metalliferrous ores & metal scrap	363	472	442	677	884
(vii) Iron & steel	1,395	1,556	1,320	1,937	2,305
2. Non-bulk imports	8,895	12,072	13,160	17,019	21,173
Of which :	(45.2)	(60.1)	(59.2)	(60.4)	(59.8)
(a) Capital Goods	4,286	6,488	6,566	6,939	5,831
	(21.6)	(32.3)	(29.5)	(24.6)	(24.9)
(b) Mainly export-related items	2,366	2,856	3,351	5,463	6,803
	(12.0)	(14.2)	(15.1)	(19.4)	(19.2)
Of which :					
(i) Pearls, precious and semi-precious stones	1,100	1,489	2,018	3,175	4,242
(ii) Chemicals, organic & inorganic	1,089	1,145	1,082	1,940	2,135
(iii) Textile yarn, fabrics etc.	153	151	187	287	349
(iv) Cashew nuts, raw	24	71	64	61	77
(c) Others	2,243	2,728	3,243	4,617	5,539
	(11.4)	(13.6)	(14.6)	(16.4)	(15.6)
Total 1+2	19,658	20,096	22,244	28,194	35,412

P=Provisional

PR=Partially revised

Neg.—Negligible

Note : Figures in brackets represent percentage to total imports.

Source : DGCIS.

10.17 The EEC and the USA continued to be major sources of India's imports accounting for 45 per cent of total imports in 1989-90 as against a little less than 35 per cent in 1984-85. The share of East European countries declined over the same period from 13 per cent to 8 per cent while the share of developing countries continued to account for a little less than one-fifth of India's total imports.

#### Over the Plan Period

10.18 During the Seventh Five Year Plan period, the annual average growth in exports was about 19.8 per cent in rupee terms, 11.6 per cent in U. S. dollar terms and 6.6 per cent in SDR terms (see Table 10.6). Excluding the first year of the Plan, 1985-86, when there was a virtual cessation of crude oil export, which resulted in a decline by about 8 per cent in exports in real terms, the volume growth in exports during the remaining four years of the Plan averaged approximately 10 to 12 per cent per annum. For the Plan period as a whole also, the average growth in real exports works out to a little over 7 per cent per annum which is above the Plan estimate of 6.8 per cent per annum.

10.19 Imports grew at an annual average of 16.0 per cent in rupee terms, 8.2 per cent in dollar terms and 3.4 per cent in SDR terms during the Seventh Plan period. The volume growth in imports during the first two years of the Plan period averaged around 16.5 per cent per annum. Taking into account the estimates for the subsequent three years, the volume growth in imports during the Plan period works out to about 9.5 per cent per annum which is far above the annual growth rate of 5.8 per cent postulated in the Seventh Plan document.

#### Difference Between Trade and BOP Data

10.20 The last year's Report made a reference to the difference in regard to the data on merchandise trade as between the trade data published by the DGCIS and the balance of payments data published by the Reserve Bank @ The main sources of the differences were also explained. From the data for 1988-89 (Table 10.10) it is seen that the difference in import figures as between the two sources has risen from Rs. 3,293 crore in 1987-88 to Rs. 6,319 crore in 1988-89. Apart from valuation factors, the higher difference is attributable to the imports of civilian aircrafts to the extent of about Rs. 1,200 crore included in the balance of payments data but not in the trade data because of the timing difference.

#### Invisibles

10.21 The available information indicates that the net receipts from invisibles during 1989-90 might be maintained around the previous year's level. The investment income payments continued to rise, as in the past, on account of interest payments and service charges on borrowings both under external assistance and on commercial terms. The inflow of remittances under private transfers might not have shown any significant change during the year under review. The earnings from travel and tourism are expected to have shown an increase. The number of foreign tourist arrivals in the country during 1989-90 was higher by 7.5 per cent as against the rise of 6.2 per cent in the preceding year. Other items taken together are not expected to show a significant variation over the previous year.



Table 10-10 : Merchandise Trade

(Rupees crore)

Year	DGCI & \$ data			RBI data		
	Exports	Imports	Trade deficit	Exports	Imports	Trade deficit
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	6,711	12,549	-5,838	6,576	12,544	-5,967
1981-82	7,806	13,608	-5,802	7,766	13,887	-6,121
1982-83	8,803	14,293	-5,490	9,137	14,913	-5,776
1983-84	9,771	15,831	-6,060	10,169	16,039	-5,871
1984-85	11,744	17,134	-5,390	11,959	18,680	-6,721
1985-86	10,895	19,658	-8,763	11,578	21,164	-9,586
1986-87	12,452	20,096	-7,644	13,315	22,669	-9,354
1987-88	15,741(PR)	22,399(PR)	-6,658(PR)	16,396	25,692	-9,296
1988-89	20,295(PR)	28,194(PR)	-7,899(PR)	20,511(PE)	24,513	-14,003

PR = Partially Revised.

PE = Provisional Estimates.

## External Assistance, Commercial Borrowings and Bilateral Transactions

10.22 Gross disbursements under external assistance amounted to Rs. 5,942 crore during 1989-90, i.e., higher by Rs. 651 crore than those of Rs. 5,291 crore during 1988-89. Amortisation payments on external assistance at Rs. 1,987 crore were higher by Rs. 341 crore than those of Rs. 1,646 crore in 1988-89 (Table 10.11). Consequently, net inflow of external assistance during 1989-90 amounted to Rs. 3,955 crore as against Rs. 3,645 crore in 1988-89

mainly due to larger net inflow of assistance from Japan and the IBRD. In terms of U. S. dollar, however the net inflow of foreign aid, which declined by 5.5 per cent in 1988-89, fell further by 5.6 per cent to \$ 2,375 million during 1989-90. The utilisation of commercial borrowings was of the order of Rs. 4,293 crore (\$3.0 billion) in 1988-89 as against Rs. 1,946 crore (\$1.5 billion) in 1987-88 (Table 10.12). Net of repayments, the utilisation of commercial borrowings was \$2.2 billion in 1988-89 as against an average of \$1.3 billion during 1985-86 to 1987-88. During the first four years of the Seventh Plan period, the net inflow of external assistance averaged around

Table 10-11 : External Assistance

(Rupees crore)

	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6
1. Loans	2,495	3,176	4,575	4,738	5,279
2. Grants	443	420	457	553	663
a. Gross Utilisation	2,938	3,596	5,032	5,291	5,942
4. Repayments	776	1,176	1,581	1,646	1,987
5. Net (3-4)	2,162	2,420	3,451	3,645	3,955

Notes : 1. 'Loans' are inclusive of Government loans but excluding suppliers' credits and commercial borrowings.

2. @Estimated.

Table 10-12 : Commercial Borrowings

(Rupees crore)

	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89@
1	2	3	4	5	6
Utilisation (Gross)	1,472	1,827	3,115*	1,946*	4,293*

Excluding pre-payments

q) Estimated

\$2.0 billion a year and commercial borrowings around \$1.5 billion. Transactions with bilateral account countries during the year showed a net outflow of Rs. 882 crore reflecting a net surplus on current account with this group of countries, as against a net inflow of Rs. 264 crore during 1988-89.

#### Modes of Financing over the Plan period

10.23 The mode of financing during the first four years of the Seventh Plan, indicates that loans by way of external assistance from multilateral and bilateral donors provided 28 per cent of the financing need (much lower than that of 55 per cent in the Sixth

Plan period), 25 per cent by way of commercial borrowings, 23 per cent through non-resident deposits under Foreign Currency Non-Resident Account (FCNRA) Scheme and Non-Resident External Rupee Accounts (NRERA) Scheme, about 12 per cent from other capital transactions and the balance of 12 per cent by drawing down reserves. (Table 10.13).

#### Accretions under NR(E)RA and FCNRA Schemes

10.24 Under Non-Resident (External) Rupee Accounts[NR(E)RA] Scheme, provisional data for 1989-90 indicate a withdrawal of Rs. 4 crore (excluding estimated interest element) as compared with an inflow of Rs. 245 crore in the previous year.

Table 10.13 : Financing need and sources of financing

	Rupees crore					Millions of Millions of	
	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	Total	US Dollars	SDRs
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Current Account deficit including errors & omissions	5,347	5,959	7,240	11,023	29,569	22,546	18,345
2. Repayment to IMF	—253	—672	—1,209	—1,547	—3,681	—2,807	—2,228
3. Financing Need (1 + 2)	—5,600	—6,631	—8,449	—12,570	—33,250	—25,353	—20,629
Financed by							
4. External Assistance	1,676 (29.9)	1,808 (27.3)	2,945 (34.8)	3,186 (25.3)	9,615 (28.3)	7,331 (28.9)	5,965 (28.9)
5. Commercial Borrowings	1,167 (20.8)	2,512 (37.9)	1,266 (15.0)	3,198 (25.5)	8,143 (24.5)	6,209 (24.5)	5,051 (24.5)
6. Non-Resident Deposits	1,767 (31.6)	1,630 (24.9)	1,840 (21.8)	2,475 (19.7)	7,732 (23.3)	5,896 (23.3)	4,097 (23.3)
7. Other Capital	284 (5.1)	—71 (—1.1)	1,442 (17.1)	12,261 (18.0)	3,916 (11.8)	2,986 (11.8)	2,430 (11.8)
8. Use of Reserves	706 (12.6)	732 (11.0)	956 (11.3)	1,449 (11.5)	3,843 (11.5)	2,930 (11.5)	2,384 (11.5)

Note : Figures in brackets indicate percentage to the Financing Need (Item 3).

The net inflow under the Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (FCNRA) Scheme during 1989-90 was Rs. 2,773 crore as against Rs. 2,230 crore in 1988-89 (Table 10.14).

10.25 As at the end of March 1990, non-resident deposits stood at Rs. 17,831 crore [Rs. 6,507 crore under NR(E)RA and Rs. 11,324 crore under FCNRA] (Table 10.15).

#### Interest Rates on Non-Resident Deposits

10.26 The interest rates on deposits under FCNRA Scheme were revised frequently in view of the developments in interest rate movements in the international markets. Table 10.16 sets out the

rates of interest on FCNRA deposits for different currencies during the period under review.

#### External Debt

10.27 The large and recurrent current account deficits that emerged during the Seventh Plan period had to be financed largely through inflows of capital from abroad by way of multi-lateral and bilateral assistance, commercial borrowings and non-resident deposits. As a result, India's external debt has risen rather significantly in the past few years. India's long-term debt@ which was relatively small at the end of March 1980 (Rs. 13,430 crore) rose to around Rs. 35,800 crore by end-March 1985, to Rs. 69,681 crore by end-March 1989, and further to Rs. 81,168 crore by the end of March 1990 (Table 10.17).

Table 10.14 : Inflows under NR(E)RA and FCNRA Scheme

(Rupees crore)

Fiscal Year	Non-Resident (External) Rupee Account <sup>(a)</sup>	Foreign Currency (Non- Resident) Account	Total
1	2	3	4
1984-85	604	275	879
1985-86	616	1,151	1,767
1986-87	477	1,173	1,650
1987-88	477	1,363	1,840
1988-89	245	2,230	2,475
1989-90	— 4	2,773	2,671

(a) Excluding the estimated accrued interest.

Table 10.15 : Deposit Liabilities Under NR(E)RA and FCNRA Schemes

(Rupees crore)

As at end-March	Foreign Currency Non-Resident A/c					Total @ (3 to 6)	Grand Total (2 + 7)
	NR(E)RA*	US Dollar	Pound Sterling	DM	Yen		
1	2	3	4	5	6	7	8
1985	2,864	618 (499)	337 (218)	—	—	955	3,819
1986	3,461	1,759 (1,419)	430 (236)	—	—	2,189	5,650
1987	4,336	3,047 (2,360)	464 (224)	—	—	3,511	7,847
1988	5,107	4,406 (3,410)	541 (222)	—	—	4,947	10,054
1989	5,899	6,648 (4,245)	535 (203)	700 (848)	372 (31,571)	8,355	14,154
1990	6,507	9,304 (5,409)	337 (119)	1,028 (1,013)	655 (60,327)	11,324	17,821

\*Inclusive of accrued interest

@Do not include accrued interest.

Note : Figures in brackets are outstanding deposits in the relevant currencies in million.

Table 10.16 Interest Rates of FCNRA Deposits

Effective Dates	(Per cent per annum)															
	US \$				SSPound Sterling				DM				Yen			
	6 months to 1 year	1 year to 2 years	2 years to 3 years	3 years only	6 months to 1 year	1 year to 2 years	2 years to 3 years	3 years only	6 months to 1 year	1 year to 2 years	2 years to 3 years	3 years only	6 months to 1 year	1 year to 2 years	2 years to 3 years	3 years only
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
August 24, 1989	9.50	9.50	9.50	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	7.75	7.75	8.00	8.00	6.00	6.00	6.25	6.5
September 18, 1989	9.50	9.50	9.75	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	8.00	8.00	8.25	8.25	6.25	6.25	6.50	6.50
October 11, 1989	9.50	9.50	9.75	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	8.50	8.50	8.50	8.50	6.25	6.50	6.50	6.50
October 21, 1989	9.00	9.00	9.25	9.50	11.50	11.75	12.00	12.00	8.50	8.50	8.50	8.50	7.65	7.65	7.00	7.00
November 9, 1989	9.00	9.00	9.25	9.50	11.50	11.75	12.00	12.00	8.75	8.75	8.75	8.75	7.00	7.00	7.25	7.25
December 13, 1989	8.75	1.75	9.25	9.50	11.50	11.75	12.00	12.00	8.50	8.75	9.00	9.00	7.00	7.00	7.25	7.25
December 27, 1989	8.75	1.75	9.25	9.50	11.50	11.75	12.00	12.00	8.75	8.75	9.00	9.00	7.25	7.25	7.25	7.25
January 17, 1990	8.75	9.00	9.50	9.75	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.50	7.50	7.50	7.50
January 31, 1990	8.75	9.00	9.50	9.75	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.25	9.25	9.25	7.75	8.00	8.00	8.00
February 20, 1990	8.75	9.00	9.50	9.75	11.50	11.75	12.00	12.00	9.25	9.75	9.75	9.75	7.75	8.00	8.00	8.00
March 12, 1990	9.00	9.25	9.75	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	9.25	9.75	10.00	10.00	8.00	8.25	8.25	8.25
March 27, 1990	9.25	9.50	10.00	10.25	11.50	11.75	12.00	12.00	9.25	9.75	9.75	9.75	8.25	8.50	8.50	8.50
May 7, 1990	9.25	9.75	10.25	10.50	10.50	11.75	12.00	12.00	9.25	9.75	9.75	9.75	8.00	8.25	8.25	8.5
May 30, 1990	9.00	9.50	10.00	10.25	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.50	9.75	9.75	7.75	8.00	8.00	8.00
July 19, 1990	9.00	9.50	10.00	10.25	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.50	9.75	9.75	8.25	8.25	8.25	8.5
August 13, 1990	9.00	9.25	9.75	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.50	9.75	9.75	8.50	8.50	8.50	8.50

Table 10.17 : India's External Debt

(Rupees crore)

As at end—March							
	1980**	1985	1986	1987	1988	1989P	1990P
1	2	3	4	5	6	7	8
1. External Assistance	12,178	24,004	26,638	32,312	36,578	46,838	54,095
2. IMF		4,888	5,271	5,548	4,732	3,696	2,573
3. External Commercial Borrowings*	1,252	6,908	8,075	11,243	13,543	19,147	24,500
4. Total (1+2+3)	13,430	35,800	39,984	49,103	54,853	69,681	81,168
Memorandum item							
5. U.S. dollars in Million equivalent to	16,392	28,801	32,391	37,699	42,993	44,485	47,109

\* Include non-Government loans under external assistance programme and suppliers, credits from East European countries repayable in rupees.

\*\* Based on survey of India's International Investment Position. Reserve Bank of India Bulletin, April 1985.

P=Provisional.

10.28 As a proportion of GDP (at market prices), the external debt went up from 12.5 per cent at end-March 1980 to 17.8 per cent by the end of March 1989. During the same period, the debt-export (export of goods plus invisible receipts) ratio rose sharply from 131 per cent to 223 per cent. As a result, the debt-service ratio has been rising in the past few years. The debt-service ratio (excluding interest on non-resident deposits) went up from 16 per cent of current receipts in 1985-86 to 24 per cent in 1987-88 but declined marginally to 23 per cent in 1988-89. The average debt-service ratio during the first four years of the Seventh Plan was 21 per cent substantially higher than the average of 17.6 per cent postulated in the plan document.

#### Developments in Exchange Rates of Major Currencies

10.29 Faced with persistent appreciation of the U. S. dollar, particularly against the Japanese yen, Ministers and Central Bank Governors of G-7 countries, at their meeting in Washington in September 1989, reaffirmed their resolve to co-operate closely in exchange markets so as to avoid further appreciation or an excessive decline in the US dollar in the absence of a strong initiative on the part of the major industrial countries to stabilise the exchange rates, foreign exchange markets showed erratic movements in the major currency markets. Continued long-term capital outflow from Japan on account of low interest rates drove down the exchange value of the Japanese currency. Interest rates in West Germany were raised following inflationary expectations arising from possible German reunification. The narrowing down of the interest differentials vis-a-vis the US rates helped the DM, particularly since October 1989, to strengthen against the US dollar in the exchange markets. The Annual Report for 1989-90 of the Bank for International Settlements (BIS) admits the limited measure of success of the February 1987 Louvre Accord; it argues that the present proximity of nomi-

nal exchange rates to the Louvre levels has been "the net outcome of fairly large and frequent fluctuations in between".

10.30 In terms of monthly averages, the US currency, which strengthened against all major currencies in the preceding year, exhibited a mixed trend during 1989-90 (July-April). In terms of monthly averages, the US dollar showed initial set-back during July 1989 but maintained an uptrend during August and September 1989 against all major currencies. Thereafter, however, the US currency started weakening against the SDR except in the month of March and April 1990, against the pound sterling except in November 1989 and March 1990, and against the DM except in March 1990. Against the Japanese yen, the US dollar maintained a firm trend during the period except in October 1989. In month-to-month fluctuations, the pound sterling was broadly stable against the SDR and the US dollar but depreciated in relation to the DM and appreciated in relation to the yen. On the contrary, as against the weakening of the yen, the DM firmed up in the relation to all major currencies.

#### Exchange Rate of the Rupee

10.31 The value of the rupee continues to be determined in relation to the weighted basket of currencies of India's major trading partners with the pound sterling as the intervention currency. The number of adjustments in the rupee-sterling rate went up further to 252 during 1989-90 (April-March) as against 200 during 1988-89 (April-March).

10.32 Between end-March 1989 and end-March 1990 on a point-to-point basis, the rupee weakened by 9.6 per cent against the US dollar and by 6.7 per cent against the pound sterling as compared with higher depreciations of 16.8 per cent and 7.8 per cent respectively, in the corresponding period of 1988-89. Against the Japanese yen, the rupee strengthened by

6.9 per cent during the period in contrast to its weakening (by 11.7 per cent) during the corresponding period of 1988-89. In view of the strengthening of the EMS currencies against the US dollar during the period under review, the rupee weakened in relation to the French franc (by 19.2 per cent), the DM (by 19.0 per cent) and the Swiss franc (by 18.0 per cent). In the corresponding period of

1988-89, the depreciation of the rupee against these currencies was lower : 5.9 per cent (French franc), and 5.4 per cent (DM). However, against the Swiss franc, the rupee strengthened marginally by 0.1 per cent in 1988-89. During the first quarter of 1990-91, i.e., April-June 1990 the rupee continued to depreciate against major currencies (Table 10.18).

Table 10.18 Rupee Exchange Rates

(Rupees per unit of SDR/Foreign currency)

Period	SDR	US\$	£Stg.	D.M.	Yen
1	2	3	4	5	6
<b>A. Annual Average Rates</b> (April—March)					
1985-86	12.9232 (-7.7)	12.2349 (-2.8)	16.8467 (-11.8)	4.5553 (-12.5)	0.056 (-13.3)
1986-87	15.4472 (-16.3)	12.7782 (-4.3)	19.0722 (-11.7)	6.2970 (-27.7)	0.0802 (-29.9)
1987-88	17.1208 (-9.8)	12.9658 (-1.4)	22.0872 (-13.7)	7.4004 (-14.9)	0.0941 (-4.8)
1988-89	19.2619 (-11.1)	14.4817 (-10.5)	25.5959 (-13.7)	8.0494 (-8.1)	0.1130 (-16.7)
1989-90	21.3684 (-9.9)	16.6492 (-13.0)	26.9179 (-4.9)	9.0922 (-11.5)	0.1166 (-3.1)
<b>B. Monthly Average Rates</b>					
March 1988	17.8284	12.9793	23.7897	7.7435	0.1021
March 1989	20.1989	15.5137	26.5858	8.3083	0.1190
March 1990	22.2961	17.1274	17.8218	10.0454	0.1118
% Appreciation (+)/Depreciation (—) of March 1990 over March 1989	(-9.4)	(-9.4)	(-4.4)	(-17.3)	(+6.4)
June 1989	20.4079	16.4349	25.5284	8.3079	0.1141
June 1990	22.9224	17.4206	29.7858	10.3484	0.1133
% Appreciation (+)/Depreciation (—) of June 1990 over June 1989	(-11.0)	(-5.7)	(-14.3)	(-19.7)	(+0.7)
<b>C. Exchange Rates as on</b>					
March 31, 1988	17.9703	13.0318	24.35	7.8308	0.1042
March 31, 1989	20.2082	15.6630	26.40	8.2764	0.1180
March 30, 1990	22.4090	17.3248	28.30	10.2118	0.1104
June 30, 1989	20.7035	16.5808	25.75	8.4807	0.1156
June 30, 1990	23.1820	17.5439	30.50	10.5180	0.1145

Note : Figures in brackets indicate % appreciation (+)/depreciation (—) of rupee.

### Rupee-Rouble Exchange Rate

10.33 The rupee-rouble exchange rate applicable for settlement of credit and commercial transactions was changed three times during 1989-90 (April-March), i.e., on July 9, October 10, and December 16, 1989. Accordingly, the rupee-rouble rate softened by 9.1 per cent from Rs. 18.11 per rouble at end-March 1989 to Rs. 19.92 per rouble at end-March 1990. It was further changed to Rs. 20.5520 per rouble on May 10, 1990.

### International Economic Developments

10.34 The year 1989 and the initial months of 1990 were characterised by a slow-down in world economic activity. The real GNP growth in the industrial countries moderated from 4.4 per cent in 1988 to 3.5 per cent in 1989, essentially reflecting the restrictive monetary policies followed in most industrial countries to deal with the pressures on

productive capacity and prices. It is expected that the growth rate would decelerate further to 2.7 per cent in 1990 in these countries. Given the strong influence of the performance and policies of industrial countries on the activities in developing countries, it is not surprising that developing countries as a group recorded a lower rate of output growth of 3.0 per cent in 1989 as against 4.1 per cent in 1988. It is expected that economic growth in the developing world in 1990 would not be much different from that of the previous year.

10.35 Consumer price inflation in the industrial countries accelerated by a little over 1 percentage point in 1989, to 4.4 per cent. This may be attributed to high rates of capacity utilisation, increases in indirect taxes in a few countries and the steep rise in world prices for oil, food and metals. In the developing countries, there was a sharp acceleration in inflation rates attributable to several high-inflation countries. Projections for 1990 show that inflation rates would decelerate in both the groups of countries partly because of the expected dampening of demand.

10.36 Reflecting the economic slow-down, the volume of world trade expanded by a lower rate of 7.2 per cent in 1989, down from the unusually high growth rate of 9.1 per cent in 1988. Even so, the growth of world trade in 1989 remained twice as high as the growth of output. In 1990 and 1991, there might be a further reduction in the growth of world trade to 6.0—6.5 per cent, reflecting the expected further deceleration of economic activity and particularly the weakening growth of global investment, a component of demand which is relatively trade-intensive. Protectionism in industrial countries continues to be unabated. There are expressions of doubt that Europe 1992 which is to eliminate all trade barriers among the countries of the Community would help reduce barriers against the rest of the world. There has been a tendency to move towards bilateral settlements as illustrated by the USA-Canada pact, the US-Japan understandings, and the threat of imposing retaliatory trade restriction bilaterally under the provisions of the U.S. Omnibus Trade and Competitiveness Act, 1988. The trade negotiations at the Uruguay Round have to far as shown only limited progress.

10.37 External current account imbalances among the three largest countries continue to be large tending to cloud the future economic outlook, in spite of considerable progress made in reducing imbalances. Japan's external surplus has continued to decline reaching 2.0 per cent of GNP in 1989, as compared with 2.8 per cent in 1988. In the United States, the deficit continued to fall to about 2.0 per cent of GNP, as compared with 2.6 per cent in 1988. More recently, however, the adjustment process in this regard may have slowed, as reflected in the U.S. dollar appreciation vis-a-vis the yen. In the Federal Republic of Germany, the external surplus increased from 4.0 per cent of GNP in 1988 to 4.4 per cent of GNP in 1989. If the exchange rate relationships among the three countries continue to be as they are at present and if economic policies do not change, there is little hope for bringing down

the present size of current account imbalances among the three large industrial countries and there are distinct signs of growing current account imbalance amongst other industrial countries. Any hope of recycling surpluses from industrial countries to developing countries, therefore, appears far-fetched. The dramatic market adjustments in Eastern Europe requiring massive financial support have only gone to intensify these misgivings.

10.38 The total debt of all developing countries at the end of 1989 (\$ 1,214 billion) remained more or less at the same level as in the previous year (\$ 1,216 billion). The external debt of the Asian developing countries at \$ 336 billion (22 per cent of GDP) changed little over the year. In the Western Hemisphere, market-based debt reduction operations such as buy-backs, debt-equity swaps and private sector discounted pre-payments, helped to reduce the Western Hemisphere's debt only marginally to about \$ 399 billion from \$ 401 billion in 1988. This is because only a few countries have been considered for debt reduction. Africa's debt was largely unchanged at \$ 195 billion (50 per cent of GDP).

10.39 According to the World Bank's Debt Tables for 1989-90, net flows of external resources to the developing countries reached an estimated \$ 26 billion in 1989, up from the 1988 level of \$ 20 billion, however, they were at \$ 84 billion in 1981. Besides, because of higher interest payments, net transfers from developing countries to their creditors remained almost unchanged at the previous year's level of \$ 52 billion. This reverse flow, which began in 1983, has already absorbed \$ 243 billion in seven years, largely from the severely-indebted countries.

10.40 There are at present a number of factors which make it hazardous to make forecasts of short-term and medium-term global economic prospects. Among others, mention may be made of the rapid developments towards market-orientation of the economies of Eastern Europe since about the third quarter of 1989 the prospects of unification of the two Germanys, and the possibilities of a monetary and economic union to emerge in the European Community in the near future.

10.41 From the point of view of developing countries, the current economic situation and prospects are not encouraging. The initial expectations about effective reductions in debt, raised by the Brady Plan have not materialised. Access for most developing countries to funds in the international capital markets continues to be limited. In fact, net borrowings of these countries hardly accounted for less than 10 per cent of the funds raised in the markets in 1989. Mainly because of the decline in non-oil primary commodity exports, terms of trade of developing countries are expected to deteriorate in 1990. Developing countries are expected to experience a widening of their external current account deficits in 1990. Net credit from commercial banks is expected to be negative. There is little hope of any resumption of SDR allocation in the foreseeable future. At the IMF's Interim Committee Meeting in May 1990, agreement was reached to raise the total quota resources of the IMF by 50 per cent to SDR 135 billion,

on the fulfilment of certain conditions relating to the strengthening of the financial position of the Fund. The increase in the quotas is expected to materialise only by the end of 1991. Even with the modest increase in quota resources of the Fund, considering the need to extend financial support to East Europe, there may not be any significant increase in the resources that might be available to the developing countries. It is significant that for the LDCs as a group, all the three major sources of funds, namely, the official creditors, the commercial banks and the IMF, have turned negative with repayments exceeding fresh disbursements.

## 11. ASSESSMENT AND PROSPECTS

### Growth Scenario

11.1 The Indian economy achieved a satisfactory growth rate during 1989-90. During 1988-89, real GDP grew by 10.4 per cent and the GDP originating in agriculture by 18.6 per cent. Against this background, the estimated real GDP growth of about 4.5 per cent during 1989-90 is indeed creditable. The foodgrains output attained a new peak at about 173 million tonnes and several commercial crops also experienced significant increases. A welcome development was the marked increase, for the second year in succession, in the output of coarse grains and pulses, reflecting also some better regional spread of foodgrains growth. As regards industrial performance, the major part of the year experienced subdued industrial growth, but benefitting from a phenomenal pick-up in the last quarter, the year 1989-90 as a whole showed a growth rate of 8.3 per cent which is only a shade lower than that in 1988-89 (8.7 per cent). While the growth rates of basic, intermediate and consumer durable goods industries slowed down, those of capital goods and consumer non-durable industrial goods improved during 1989-90. The robust pace of export growth, particularly in manufactured goods, helped to keep up the tempo of industrial growth. Exports during 1989-90 grew by 36.3 per cent in rupee terms, or by 22.9 per cent in SDR terms, or by about 14.0 per cent in volume terms which is indeed an impressive performance. Exports of manufactured goods accounted for nearly three-fourths of total exports during 1989-90. However, a sharp increase in prices in the second successive year of good monsoon, continuing fiscal deficits of a large order and pressure on balance of payments despite strong growth in exports were the major areas of concern.

11.2 Many indicators suggest encouraging growth prospects for 1990-91, the first year of the Eighth Plan, with the component elements adding up to a possible real GDP growth of about 5.0 per cent. Meteorological reports on the 1990 south-west monsoon indicate that the rainfall has so far maintained a steady progress and the outlook for the Kharif season is optimistic. In view of this, the foodgrains production target for 1990-91 at 176.5 million tonnes is likely to be achieved as also the higher targets for oilseeds, sugarcane, and cotton; these should produce an overall growth of about 3 per cent in the index of agricultural production. As for industrial growth, the tempo of public sector investment may slow down to some extent because of the imperative need to

contain deficit financing. Even though there are some signs of a slackness in investment in new projects by the private corporate sector, overall private investment may not decline in the current year because of the projects initiated in the previous years. The projected slow-down in the world trade growth, if it materialises may affect exports in the medium term, but in the short run the export momentum is expected to continue. As for domestic consumption demand, if farm incomes rise for the third year in succession, as is expected, the impetus received for the production of non-durable consumer goods in 1989-90 should continue in 1990-91 also. Overall, growth of about 8 per cent in industrial output may be expected. A significant moderation in the fiscal deficit and consequently in money supply are, however, essential if price rises are to be kept within reasonable limits.

### The Seventh Plan Performance

11.3 With 1989-90, the terminal year of the Seventh Plan, which is also the year under review, drawing to a close, a brief look at the overall performance of the Plan is in order. The Plan targets in terms of the overall growth rate in GDP as well as those for agriculture and industry have been exceeded. Despite three bad harvests, the average growth rate of agricultural production for the Seventh Plan period works out close to the Plan target of 4.0 per cent per annum. Regional disparities as well as crop imbalances, however, continue to persist. The average growth of industrial output works out to 8.4 per cent, which is higher than the Plan target of 8.0 per cent per annum. In terms of use-based classification for which full data are available only for the first four years of the plan, the capital goods industries grew at 13.0 per cent while basic industries and intermediate goods industries rose by 8.9 per cent and 7.1 per cent, respectively. The growth rate for the consumer goods industries is 8.0 per cent. Within the consumer goods industries, while non-durable goods rose by 6.3 per cent per annum, the durable goods industries recorded an annual growth rate of 16.9 per cent. The high growth rate in durable consumption goods is a reflection of the sharp increase in the income of the organised sector. It needs to be noted, however, that the growth rate in non-durable consumption goods at 6.3 per cent per annum is also the highest growth rate achieved by this sector during the past three Plans.

11.4 Despite the satisfactory performance of the real sector, several serious macro-economic imbalances and distortions have, however, surfaced during 1985-1990. The first is the high levels of budget deficits incurred almost year after year with consequent expansionary impact on money supply. The second is the strain on the balance of payments with current account deficits as a proportion of GDP far exceeding the levels indicated in the Seventh Plan document. These two issues are dealt with in greater detail in subsequent paragraphs.

### Employment Trends and Strategy

11.5 Another disquieting feature has been the slow growth in employment. There has been a distinct deceleration in the rate of growth of employment, particularly during the 1980s when employment elasticity with respect to output in every major sector declined. According to a study by the Planning Commission, between 1972-73 and 1977-78, the



employment growth was 2.82 per cent per annum. It declined to 2.22 per cent per annum during the period 1971-78 to 1983, and further to 1.55 per cent per annum between 1983 and 1987. This deceleration in the employment growth is noticed in all components of the work force—rural and urban, male and female and in all sectors except in mining and construction. The decline in the growth rate of employment in agriculture as well as in the organised sector is quite sharp. Whatever growth that has taken place in the organised sector in the 1980s has been contributed primarily by the public sector. As a result of these trends, the backlog of unemployment has been rising. Estimates by the Planning Commission, based on NSS data, place such backlog at around 28 million in the beginning of the Eighth Plan and with the projected increase in labour force, the total number requiring employment would be 65 million during 1990-91 to 1994-95, and 106 million during the decade 1990-2000. It has been estimated that if the present employment elasticity with respect to output of 0.38 is maintained, the rate of GDP growth required to achieve full employment by 1995 would be 10.5 per cent per annum and 8 per cent if it is to be achieved by 2000 AD. It is against this background that the Eighth Plan Approach Document has strongly argued that employment generation must be made the central thrust of the Eighth Plan. The Planning Commission has targeted for a 3 per cent annual growth of employment which implies an employment elasticity with respect to output of approximately 0.6 (on the assumption of a 5 per cent growth rate in GDP) as against 0.38 witnessed in the recent past. The Planning Commission has, therefore, argued for an output growth strategy which will be more labour intensive.

11.6 The strategy for employment growth needs to be carefully worked out so that the increase in employment goes hand in hand with technical and economic efficiency. Otherwise, growth itself cannot be sustained over a long period. In any programme for increasing the employment potential, agriculture still has to play a major role even though the labour absorptive capacity of agriculture in the regions with high output growth has declined. This calls for a greater emphasis on a geographically diversified growth of agriculture including development of rain-fed areas, wastelands, forestry and pasture. Employment implications of irrigation are found to be quite significant and as such a major thrust on provision of irrigation must continue to form part of the agricultural production strategy.

11.7 In a labour-abundant economy, the choice of technology in industry has a natural bias in favour of labour. However, in a wide area of manufacturing activity relating to the production of basic and capital goods which involve the use of high technology, opportunities for shifting factor proportions in favour of labour are not available. The production of these goods by their very nature is capital-intensive. In this context, the renewed emphasis on the development of small-scale industry, both traditional and modern, particularly for the production of consumption goods, is appropriate. One dimension of economic growth is that the choice of technology must be such as to generate adequate surpluses so as

to ensure sustained investment and growth. While there are many possibilities of labour-intensive techniques producing goods which are acceptable to the consumers and generating adequate surpluses, the relevant products need to be identified carefully and provided with adequate support including an efficient market mechanism. Protection of the output of certain small-scale industries which employ large labour and which may not meet the normal criteria of economic efficiency may still be necessary on a selective basis. The broad policy framework must be such as to promote efficient labour-intensive techniques. If factor proportions are to respond to relative factor prices, greater attention needs to be paid to the determination of the prices of capital and labour. While fiscal incentives that favour capital intensity must in general be avoided, rigidities in the labour market must also be reduced if employment in the organised industrial sector is to expand. The largest potential for employment growth will, however, be in the non-formal sector.

### The Fiscal Scene

11.8 Fiscal deficits have been a matter of serious concern now for several years. In 1989-90, there was a further aggravation of the problem with the Centre's budget deficit touching a record level of 2.4 per cent of GDP. The fortnightly average of budgetary deficit for 1989-90 at Rs. 10,959 crore was higher by 33 per cent than the previous year's figure of Rs. 8,203 crores. The gross fiscal deficit of the Centre, which measures its total resource gap, reached Rs. 38,238 crore in 1989-90 which constituted 8.6 per cent of GDP. With current expenditures rising faster than current revenues, the revenue deficit of the Centre has been increasing year after year. Whereas the ratio of the Centre's revenue receipts to GDP rose from 11.1 per cent in 1985-86 to 12.3 per cent in 1989-90, the Centre's expenditure on revenue account rose from 13.2 per cent of GDP in 1985-86 to 15.1 per cent of GDP in 1989-90. Revenue deficits by their very nature are self-perpetuating because when borrowed funds are diverted towards meeting current expenses, no productive asset is created, and consequently no income is generated to earn revenue which can help to repay borrowings. Reliance on borrowing in general leads to rapid accumulation of debt and concomitantly to increased interest burden. The total internal liabilities of the Central Government have increased from Rs. 96,804 crore at the end of March 1985 to Rs. 2,38,396 crore at the end of March 1990, or a rise from 42.0 per cent of GDP to 53.8 per cent during this period. Net interest payments as a proportion of revenue receipts of the Central Government have risen from 10.0 per cent in 1985-86 to 16.6 per cent in 1989-90. The increased interest burden invariably leads to a squeeze on capital expenditures thereby inhibiting investment and growth. If this vicious circle of higher deficits, higher debt and higher interest burden is to be broken, the overall budget deficit, as currently defined, needs to be brought down substantially from the level of 2.4 per cent of GDP in 1989-90. The Centre's budget for 1990-91 has placed the deficit at Rs. 7,206 crore which works out approximately to 1.5 per cent of GDP. It is imperative to ensure that the estimated budget deficit is not exceeded in 1990-91 and that its ratio to GDP is brought down over the next few years

to 1 per cent. This will require adoption of policies aimed at enhancing revenue and cutting expenditures. A strong adjustment is called for in this regard.

#### External Sector

11.9 The large and sustained current account deficits in the balance of payments, which averaged around 2.2 per cent of GDP during the Seventh Plan period, substantially higher than the Plan estimate of 1.6 per cent has been a major issue of concern. This has occurred despite a strong growth in exports in the last four years. The large current account deficit was caused by a high level of imports and a deterioration in the invisibles account. At the same time, India had to make large repayments to the IMF under EFF, CFF and Trust Fund loans aggregating SDR 3.3 billion. As a result, foreign exchange reserves declined during the Plan period by SDR 3.0 billion. The large current account deficits had to be financed by way of substantial inflows of capital in the form of loans from multilateral and bilateral donors and commercial banks and inflow of funds from non-resident Indians under special deposit schemes. Consequently, during the Plan period, the medium and long-term debt in US dollar terms went up to \$ 48 billion and NRI deposit liabilities more than trebled to \$ 10.3 billion. The debt-service ratio (excluding interest on non-resident deposits) rose sharply from 13.6 per cent in 1984-85 to 23 per cent in 1988-89, but is estimated to have fallen by about one percentage point in 1989-90. The annual average debt-service ratio during the Seventh Plan works out to about 22 per cent. With the completion of repayments to the IMF, the continued growth in exports, and a conservative stance on external commercial borrowings, the expectation is that over the Eighth Plan period the debt-service ratio would decline somewhat from the 1989-90 level.

11.10 A silver lining in the picture is the impressive growth of exports during the last four years which averaged around 17.0 per cent in U.S. dollar terms and 11.8 per cent in SDR terms per annum. The annual average volume growth in exports in this period was about 10 to 12 per cent thus exceeding the annual average growth of 7 per cent postulated in the Seventh Plan document. A dynamic export promotion policy which provided for fiscal reliefs including complete exemption of export profits from income tax, interest rate concessions, measures to facilitate capacity expansion for export production, improved access to imported inputs and a supportive exchange rate policy, have helped the sustained growth in exports since 1986. The environment of buoyant world trade growth has also helped the export effort. Although exports have performed well, the import intensity of exports has been increasing. If the aggregate data on exports and imports are adjusted for export-related imports, according to DGCIS data, export-import ratio has gone up only marginally from 64 per cent in 1984-85 to 65 per cent in 1988-89. However, the ratio showed a sharp increase in 1989-90 to 73 per cent.

11.11 As for imports, oil imports (net of oil exports) in dollar terms have shown a decline during the Plan period despite an increase in net oil imports from 12.3 million tonnes in 1984-85 to 21.8 million tonnes in 1988-89. It is the softening of oil prices which helped to contain the increase in the oil import bill.

The non-oil import bill went up in every year of the Plan. But, because of the decline in the oil import bill, the annual average growth in total imports in US dollar terms during the Seventh Plan period was 8.2 per cent as against 6.2 per cent in the Sixth Plan period. The volume growth in imports during the first two years of the Plan period averaged around 16.5 per cent per annum. For the Plan period as a whole, rough estimates suggest that the volume growth in imports might have been at over 9.0 per cent per annum, i.e. much higher than the Plan estimate of 5.8 per cent per annum. The income elasticity of imports has ruled at around 1.73 during the Seventh Plan period against 1.20 during the Sixth Plan.

11.12 Growth rates in imports indicated above are based on DGCIS data. According to balance of payments data import growth was even higher, as DGCIS data do not cover certain imports not requiring customs clearance. During the first four years of the Plan period, while DGCIS data show an annual average growth in imports of 8.0 per cent, balance of payments data show a higher imports growth of 11.2 per cent (both in US dollar terms).

11.13 While the trade deficits during the Plan period ruled high, the contribution of net invisibles to offset the trade deficit progressively diminished. This was mainly because of a sharp rise in interest payments on growing external debt and increasing payments on account of technicians fees, technical know-how, royalties, etc. associated with the import of technology under foreign collaboration agreements. At the same time private transfer receipts, a major source of invisible earnings, remained subdued. Consequently, net invisible receipts other than official transfers which financed 51 per cent of the trade deficit in 1984-85 could finance only 21 per cent by 1988-89.

11.14 Given the small size of the external sector, the current account deficits experienced in the Seventh Plan period were of a large order and are worrisome. It is necessary that the current account deficit is reduced to around 1.5 per cent of GDP. In this task, the main emphasis has to be on higher exports. In fact, if the present level of import intensity of exports continues, it becomes imperative that exports grow much faster say, at a rate of 12-14 per cent per year in volume terms to bring down the trade deficit. There is a need for reducing the import intensity of exports. Greater attention needs to be given to labour-intensive manufactured products and agro-based products in our export basket. It is essential that all productive entities involve themselves seriously in the export effort, including the large and medium corporate sector which needs to play a much more active role than it has done so far.

11.15 Side by side with promoting exports, a close look at the structure of imports is needed. The capital goods imports, after showing a strong increase in the first two years of the Seventh Plan, registered a moderate increase in the following two years, but rose sizeably once again in 1989-90. Some categories within the capital goods group showed a steady increase. In dollar terms, while imports of non-electrical machinery have declined since 1987-88, imports of electrical goods and appliances went up by as much as 32 per cent in 1988-89 though these increased moderately in 1989-90. While the stance of industrial and trade

policies must be aimed at technological upgradation and efficiency of the intermediate and capital goods industries, some prioritisation may be called for.

11.16 On the invisibles side, the main sources of gains are tourism and private transfers. The growth in tourist traffic, which was depressed in 1987-88 and 1988-89, has shown an improvement in 1989-90. This needs to be sustained and improved upon. Private transfers representing mainly current remittances from non-resident Indians, have remained more or less unchanged since 1981-82. This may partly be due to some slackening in the income of Indian workers in the Gulf area and also a measure of substitution of current cash remittances by foreign currency non-resident deposits.

11.17 So far the bulk of financing the current account deficit has been provided by external assistance, commercial borrowings, and NRI deposits. The outlook for concessional aid is not bright. There has already been a hardening of terms from multilateral institutions and there are many more claimants to the resources of multilateral and bilateral donors. As regards commercial borrowings, although we have pursued a prudent policy, the recourse to this source of borrowing has been rising in the last few years. While India can continue to borrow from the capital market at fine terms on account of its impeccable record of debt service, the recent policy stance for still greater caution is appropriate. The inflow of NRI funds under FCNRA scheme is also becoming a high-cost source of financing given the rise in the interest rates abroad. The inflow of direct foreign investment capital into India is very small being around \$200 million a year compared with much higher inflows in respect of many other countries in Asia. A larger inflow of direct foreign investment will help to reduce the pressure on the balance of payments.

11.18 The recent developments in the Gulf region are likely to add to the strain on the country's balance of payments. Crude oil price after rising initially from \$17 a barrel in March 1990 to \$23 a barrel, touched \$27 a barrel in the middle of August 1990. The current price of oil is substantially higher than the "minimum reference price" of \$21 a barrel agreed to at OPEC Agreement of July 27, 1990. The increase in oil prices would considerably raise the POL import bill as well as the cost of imported fertilisers. The impact on private remittances and flow of non-resident deposits from the region will depend upon how the situation ultimately develops. Oil imports in recent years have been rising as oil consumption has grown at a rate of 7-8 per cent per annum. There is, therefore, an imperative need for comprehensive conservation measures to bring about an early restraint on consumption of POL products. Recent events have made it even more compelling to moderate substantially the current account deficit.

#### Monitoring the Financial System

11.19 In recent years, the Indian financial system has grown and diversified greatly and the financial market from the short end to the long is developing into a continuum. Banks links with the capital market are increasing and they are diversifying their activities, often through establishment of subsidiaries which

mobilise deposits and undertake several kinds of financial services. An increasing number of private sector financial companies also collect public deposits to take up a growing variety of financial activities. At the same time, non-banking financial institutions including the UTI, LIC and GIC have become important lenders of term finance as well as in the money market. The financial assets of the financial institutions at the end of March 1989 were over Rs. 89,000 crore which compares with the asset position of commercial and co-operative banks of around Rs. 1,77,000 crore. The share of financial institutions in the total financial assets increased from about 28 per cent at the end of March 1981 to 34 per cent at the end of March 1989. These developments underscore the need for taking an integrated view of the operations of financial institutions and banks in order to provide a more comprehensive basis for the conduct of monetary and credit policies. Further, as the liabilities and assets of the non-bank financial institutions and companies are growing rapidly it is important to ensure that they conduct their business prudently and maintain sound financial health.

This would call for extension of prudential regulation wherever necessary. Therefore, the Reserve Bank is taking steps to widen the scope of its oversight beyond banks so as to gradually encompass the broader financial system. Measures have already been initiated to subject banks and their subsidiaries to consolidated supervision. Considering the large size of operations of important financial institutions and their impact on the credit and monetary areas and the capital market, the Reserve Bank intends to shortly introduce a system of periodic data collection and structured consultations with the heads of financial institutions. The role of the Reserve Bank in relation to the financial institutions has to be seen essentially in terms of the need for a macro-perspective of monetary and credit policy assessing the quality of assets of the financial system and improving coordination of the policies and operations of banks and financial institutions.

11.20 The capital market has shown remarkable growth and buoyancy during the Seventh Plan period. The developments reflect the growth and profitability of the corporate sector, burgeoning number of investors, increasing institutionalisation of the market, and growing ability of the financial sector to innovate and respond to the diverse demands of market participants. However, despite the increase in listed scripts, relative scarcity of floating stock of preferred equities still persists leading frequently to excessive volatility. This should improve over time. A noteworthy development has been the rapid growth of mutual funds established in the second half of the 1980s. In this context, it is necessary to ensure that all institutions in a given sphere such as mutual funds operate under the same fiscal umbrella and regulatory framework so that all of them compete on equal terms. Many issues relating to the regulatory framework for the capital market have come to the fore. The Government has issued appropriate guidelines on such matters as phasing and use of capital subscriptions and cost of public issues. More importantly guidelines have been issued with a view to making share transactions of financial institutions more transparent. The system of oversight in relation to the capital market which is now evolving

should ideally be a judicious mix of self-regulation by those who are directly operating in the capital market and external supervision.

### Money Market Developments

11.21 The year under review has witnessed significant widening and deepening of the money market. Two new instruments, viz., Certificate of Deposit (CDs) and Commercial Paper (CP) have become operative; the call market was broadened with the induction of new participants; the bill market received an impetus with the abolition of the stamp duty; the 182-day Treasury Bills gained further popularity, and the development of the secondary market showed considerable progress. Since deregulation of interest rates, the money market has been subject to occasional bouts of interest rate volatility and banks now find it unremunerative to have a chronic excessive dependence on this market. As such, banks have begun to accord high priority to improved funds management. A well-functioning money market can only smoothen short-term imbalances but cannot be a good source for financing structural disequilibria. To ease extreme stringency the Reserve Bank did provide to the DFHI as much as Rs. 1,000 crore in March 1990 by way of temporary support; there are, however, obvious limits to such support in view of the overall objectives of monetary policy.

11.22 As already indicated, during the year under review, two new money market instruments, viz., CDs and CP appeared on the scene. The total issue of CDs by 37 major banks has been Rs. 2,000 crore up to July 13, 1990, equivalent to 70.4 per cent of the permissible limits of these banks. CDs are subject to reserve requirements, and as such banks need to be careful in fixing the rate of interest offered on them. Although CDs have been freed from interest rate regulation, the bank-wise limits on issue of CDs implies that, by and large there is a reasonable sharing by banks of the total market for CDs. A secondary market in CDs may develop only if investors do not wish to hold them till maturity.

11.23 While the CP as an instrument has had a somewhat slower start than CDs, it is gradually gaining attention and outstandings as on August 10, 1990 were a little over Rs. 155 crore. The interest rates on CP have, however, been on the low side. The apprehension that the issue of CP would imply a loss of blue-chip clients to banks has been belied as banks have been the major holders of CP implying a measure of securitisation of the loan portfolio of banks. Although, banks lose a part of their interest income they can recoup the loss through issuing fees and lending to other parties. The norms for issue of CP are exacting but transparent. In the Indian context, the CP as an instrument provides an alternative source of financing rather than an augmentation of funds available to a borrower as the system stipulates a maximum permissible banks finance based on well-established norms. The Reserve Bank has been authorising issue of CP at regular fortnightly intervals.

11.24 As mentioned in the previous Reports, after a prolonged period of rapid expansion of banking

facilities the emphasis in recent years has been on bank consolidation. This implies a greater stress on improvement of the financial viability of banks, moderation in branch expansion while covering gaps in rural areas, introduction of computer technology on a selective basis and inculcation of a more effective managerial culture in banks. As a result of the action plans now in place for some years, banks have made progress in strengthening their organisational structure and internal systems of supervision and control. There have been improvements in housekeeping, customer service and training. Though the deposits and advances per employee have grown in nominal terms, a major part of the gain has been neutralised by the increase in cost per employee. Tools of credit management such as health coding and annual reviews of borrowal accounts, identification of sick units and determination of their viability status for remedial measures are being increasingly used with a measure of success. The Service Area Approach under which each rural and semi-urban bank branch is allocated a specified number of villages for survey and credit planning came into effect from April 1, 1989 and is getting stabilised. However, further progress in all these areas is called for.

11.25 To maintain the tempo of various measures initiated by banks, the Reserve Bank has requested them to draw up action plans for a further period of two years, i.e., April 1990 to March 1992. These plans are to place special emphasis on measures to improve profitability, stronger organisational and control arrangements, more effective manpower utilisation, further upgradation of the quality of customer service, modernisation of technology, strengthening of credit management and ensuring higher productivity of credit under the Service Area Approach.

11.26 Several steps have been taken in recent years to ease policy-related constraints on bank profitability such as improvement in bond yields and in interest on eligible cash balances with the Reserve Bank. In determining interest rates, bank profitability is kept in view. Banks have been able to raise service charges to keep in step at least partly with the increase in costs. Profitability of the banking system, however, continues to be under strain, thanks to the large and growing number of sick industrial units, serious difficulties encountered in recycling of funds advanced to several priority sectors, less than optimal use of resources at the disposal of banks and deficiencies in credit management. It is, therefore, essential that banks devote special efforts to the improvement of the quality of their assets.

11.27 Improved recovery performance is critical to improving bank profitability. Court proceedings for enforcement of bank claims take many years to settle even though such claims are based on books of accounts kept in the normal course of business and there is a presumption in favour of their correctness. The establishment of special tribunals to deal with large banks' claims can go a long way in improving recovery performance and climate.

11.28 The recovery of bank overdues under priority sectors poses special problems, particularly due to the

deteriorating climate for recycling of funds. The Government of India has recently announced the Agricultural and Rural Debt Relief Scheme for affording relief to farmers, rural artisans and weavers. The scheme envisages waiver up to Rs. 10,000 in each case, of overdues under both production and investment credit, subject to specified criteria which, inter alia, seek to exclude willful defaulters from the benefits of the scheme. The cost of the relief is to be fully borne by the Central government in respect of public sector commercial banks and regional rural banks and by the Central and State Governments for co-operative banks. The Government of India has announced that the debt relief scheme is a one-time measure. This scheme is now under implementation. The major challenge that faces the banking industry in the immediate future is to ensure that current dues and those not covered by the aforesaid scheme are recovered. It will be of great help if State Governments effectively back up the efforts of commercial and co-operative banks in this behalf. This is crucial for maintaining the health of the rural credit system so that it continues to effectively support productive activity in the countryside.

11.29 Banking is a staff-intensive service industry and its efficiency depends considerably on the work culture, customer orientation and optimal utilisation of its manpower. Institution of more effective procedures aimed at speedier transaction of business, greater staff mobility and promotion policies which provide incentives to the truly meritorious are essential to improve productivity in banks. In the face of growing volumes of work and for better customer service, management must expeditiously introduce new technologies, especially computerisation, on the clear understanding that there would be no reduction in the overall workforce. The recommendations of the Report of the Committee on Computerisation submitted recently can form the basis of future computerisation in the banking industry. Bank management and staff associations should appreciate that the Indian banking industry is already handicapped by a serious technological lag which should be quickly overcome if banks are to hold their own in an increasingly competitive financial market.

11.30 In the exercise of its supervision over commercial banks, the Reserve Bank has been tightening prudential regulation while promoting increasing flexibility in bank operations. Thus, while on the one hand, there is the emphasis on capital adequacy, avoidance of risk concentration and sound accounting practices, there is, on the other hand, a move towards greater flexibility in the matter of interest rates, introduction of market-oriented instruments, withdrawal of the credit authorisation scheme and freedom to borrowers to shift their accounts from one bank to another. Simultaneously, several measures have been taken in recent years to help banks in diversifying their activities either directly or through specialised subsidiaries into areas like merchant banking, leasing, mutual funds, venture capital and housing finance. The interface of the banking industry with the capital market has been growing. It is important that the subsidiaries function on professional lines, adhere to prudential norms, render good customer service and

are profitable. Most of these subsidiaries have been organised as compact, professional and technology-based outfits and this augurs well for their future.

### Monetary and Credit Policy Perspectives

11.31 The backdrop against which recent monetary and credit policy measures have been taken are a substantial increase in reserve money as a result of an unprecedentedly high budget deficit in 1989-90, a very high pace of expansion of  $M_1$  in 1989-90, the highest since 1978-79, and a strong increase in prices despite two successive good years of agricultural output. Persistent inflation is causing serious distortions in the economy and its impact is particularly severe on the poor. One important element in inflation control has to be a moderation in monetary growth. If the Centre's overall budget deficit in 1990-91 is kept within the budgeted figure, the ratio of the deficit to GDP at current market prices would fall from around 2.4 per cent in 1989-90 to about 1.5 per cent in 1990-91. Consistent with this fiscal objective, the aim of monetary management would be to bring about a sharp reduction in expansion of  $M_1$  in 1990-91 by about 4 percentage points over the expansion in 1989-90.

11.32 With the large increase in reserve money, year after year, monetary policy has had to concentrate on reducing the expansionary impact by aggressive use of reserve requirements. The continued use of the cash reserve ratio has already pushed it to its statutory limit. Monetary policy in the recent period has, therefore, to deploy other instruments to moderate credit expansion.

11.33 Export refinance limits account for over 80 per cent of total refinance facilities. One of the monetary measures taken was to reduce the proportion of export refinance from 100 per cent to 75 per cent. This should not lead to any curtailment of overall export credit as exports continue to enjoy a preferred status. What the measure implies is that banks will finance a larger proportion of exports out of their own resources rather than from the Reserve Bank. A comparison of export credit and the total level of exports reveals that there has been a more than commensurate increase in export credit in recent years. The policy mix of concessional refinance, subsidy, attractive exchange margins and a lower degree of bad debts in export credit do together ensure that export credit provides a reasonable yield to banks.

11.34 Another measure stipulates a 60 per cent incremental non-food credit-deposit ratio. It is sometimes apprehended that the measures would adversely affect the flow of credit to the commercial sector. Non-food credit provided by the commercial banks rose by 22.8 per cent in 1988-89 and 18.5 per cent in 1989-90. On the basis of the 60 per cent stipulation the increase could be of the order of about 17 per cent in 1990-91. These are substantial increases. In fact, considered against the background of the growth of the economy in general and that of agricultural and industrial sectors in particular, the credit expansion is excessive. Given the reserve requirement stipulations and the increase in the SLR in the current

financial year, banks would be able to have an incremental non-food credit-deposit ratio of only 40 per cent on the basis of their own deposit resources. Even allowing for refinance from the Reserve Bank and the term-lending financial institutions and non-bank money market borrowings, the banking system would find it extremely difficult even to reach the 60 per cent incremental non-food credit-deposit ratio. Thus, the stipulation essentially ensures that credit expansion is commensurate with deposit growth and available refinance facilities and that individual banks do not over-extend themselves.

11.35 The administered interest rate structure has been designed to provide a positive real rate of return to savers. Credit to certain sectors is provided at concessional interest rates and there is an element of cross subsidisation from other borrowers who pay higher rates. The multiplicity of policy objectives and the demand for preferential treatment by different sectors have given rise to a proliferation of lending rates and the structure has tended to become complex despite periodic attempts at rationalisation. While there is scope for rationalisation of lending rates, a reduction in the average level of lending rates would be feasible only if there is a significant and enduring reduction in the inflation rate.

11.36 Open market operations are a major instrument of monetary policy in well-developed financial systems. A prerequisite for effective open market operations is market-clearing rates of interest on Government securities. Although interest rates on Government securities continue to be administered, several measures have been taken in recent years to improve the yield and liquidity of Government securities. The maximum coupon rate on Central Government securities in 1979-80 was 7 per cent for a 30 years maturity while the maximum coupon rate is now 11.5 per cent on a 20 years maturity. Furthermore, in the current financial year the range of rates for 5—20 years maturity has been telescoped from 10.0—11.5 per cent to 10.5—11.5 per cent; this should provide an improved trade-off to investors between maturity and yield. Again, at the short end of the spectrum, the yield on the 182 days Treasury Bills has been rising and now stands at 9.97 per cent. For open market operations to be a major instrument of monetary policy it will be necessary to move towards market clearing interest rates on Government dated securities together with substantial moderation of the monetisation of the Centre's budgetary deficit. At the same time, there is a case for gradually reducing the very high effective yields on some other Government debt instruments by moderating the extent of fiscal privilege. As a result, the overall cost of Government borrowing may not go up while there would emerge a healthy Government securities market. A flexible structure of interest rates on Government securities would contribute significantly to better monetary control which is a prerequisite for monetary stability.

11.37 In the recent period, there has been a world-wide debate, including in India on the question of greater autonomy for central banks. Autonomy in the Indian context would mean that the Reserve Bank should be able to effectively discharge its role as a

monetary authority and as a regulatory body over the financial system. To enable the Reserve Bank to discharge its role more effectively as a regulator of the financial system, the existing overlap of functions and responsibilities between the Government and the Reserve Bank over commercial banks needs to be minimised. The persistent and growing budgetary deficits have, over the years, led to an erosion of monetary stability. The increasing reliance on automatic monetisation of the budgetary deficit of the Central Government is reflected in a sharp rise in the monetised deficit to an estimated 3 per cent of GDP in 1989-90. The Reserve Bank has advocated that the automatic monetisation of the budgetary deficit of the Central Government should be phased out over time. An interim objective could be to have a specific understanding on the amount that the Central Government can borrow from the Reserve Bank. Over the medium term, such automatic monetisation should be phased out and a system of ways and means advances established to enable the Central Government to meet temporary mismatches between receipts and payments. An implication of this approach is that the Central Government would need to increasingly raise its borrowings at market rates of interest. Such a development would also enable the Reserve Bank, as already indicated, to carry out effective open market operations. While these steps require a fundamental change in the system of financing the Government, the statutory provisions regarding Reserve Bank lending to the Government are enabling and not mandatory and as such a reform of the present system can be undertaken within the current framework of the Reserve Bank of India Act.

## PART II—BANKING AND OTHER DEVELOPMENTS

### 12. Highlights

12.1 In Part I of the Report, the monetary and credit policy developments have been reviewed against the backdrop of the overall economic trends; besides, important developments relating to financial institutions, the capital market and the external sector have also been reviewed. Part II of the Report sets out the salient features of other banking developments, as also developments relating to the Reserve Bank's operations, organisational matters and accounts.

12.2 The major highlights of these developments are :

- (i) The banks are drawing up action plans for a further period of two years from April 1990 to March 1992 with special emphasis on improved credit management and profitability, better manpower utilisation, improved customer service and upgradation of technology.
- (ii) Under the Service Area Approach, the new strategy for rural lending which became operational from April 1, 1989, the target for credit disbursements in 1989-90 was fixed at Rs. 15,319 crore of which Rs. 10,284 crore was for agriculture. Branch credit plans for 1990-91 are being prepared. To effectively monitor these programmes,



NABARD is setting up offices in all districts in a phased manner over three to four years.

- (iii) During July 1989 to March 1990, banks opened a total of 711 branches of which 663 branches or 93 per cent were in rural areas. The total number of bank branches in the country as on March 31, 1990 was 58,901 of which 57.8 per cent were rural branches.
- (iv) Priority sector advances of public sector banks constituted 43.2 per cent of their total advances as at the end of March 1990.
- (v) The process of diversification by commercial banks into related financial services continued with banks setting up subsidiaries (joint ventures), equipment leasing, merchant banking, housing finance companies and mutual funds.
- (vi) The Committee on Computerisation in Banks, which submitted its report in November 1989, has recommended a comprehensive computerisation plan for the banks for the period 1990—94. The report has been accepted in principle by the Reserve Bank. Preparations for the first phase of BANK-NET—a data communication network for the banking industry—has reached an advanced stage and the first phase of the network is expected to be commissioned during 1990. During the year under review, 15 new Clearing Houses started functioning in the country. With the introduction of special clearing for cheques of amounts above Rs. 1 lakh at Calcutta and New Delhi, all the four metropolitan cities have now the system of same-day clearing for high-value cheques besides MICR clearing.
- (vii) The Agricultural Credit Review Committee (ACRC), which went into the entire gamut of rural credit, submitted its report in August 1989; the Committee has made many important recommendations which are under consideration.
- (viii) The Reserve Bank has relaxed the rules regarding release of foreign exchange for travel abroad for business, studies, specialised training, employment and medical check-up.
- (ix) Authorised dealers have been permitted to lend and borrow foreign currency (US dollars) in the local interbank market, subject to certain stipulated limits.
- (x) A wholly-owned subsidiary of the Reserve Bank is proposed to be formed for setting up of two bank-note printing presses at Mysore (Karnataka) and Salboni (West Bengal).
- (xi) The National Housing Bank liberalised its refinancing of direct housing loans by primary lending agencies; it has made the rate of interest uniform for refinancing of housing loans for rural and urban areas.

## 13 DEVELOPMENTS RELATING TO COMMERCIAL BANKS

### Action Plans for Banks—1989-90

13.1 The banks continued implementation of the action plans drawn by them with a view to bringing about improvement in their overall performance. Progress in the implementation of these plans was reviewed quarterly with the Chairman and senior executives of public sector banks. Banks have been asked to draw up action plans for a further period of two years, i.e., from April 1990 to March 1992, on the existing pattern but with special emphasis on the measures needed to improve credit management and profitability, organisation and control arrangements, manpower utilisation, upgrading the quality of customer service, modernisation of technology, and consolidation of the Service Area Approach to rural lending.

### Branch Expansion

13.2 The branch licensing policy 1985-90, co-terminus with the Seventh Five-Year Plan, came to an end on March 31, 1990. Under the policy, 5,360 rural/semi-urban centres were allotted to banks. Besides, 1,454 centres were allotted under the Service Area Approach. Of the 6,814 rural/semi-urban centres, 4,624 centres were allotted to public sector banks, 2,038 centres to RRBs and 152 centres to private sector banks. In addition, 635 centres, 309 in urban and 326 in metropolitan/port towns were also allotted.

13.3 Up to end of March 1990, out of 7,449 centres allotted, banks were able to open offices at 5,684 centres, of which 4,434 were in rural/semi-urban areas under the 1985-90 Plan, 695 under the Service Area Approach, and 555 in urban/metropolitan/port town centres. Banks have been allowed time up to September 30, 1990 to open offices at the remaining centres.

13.4 The total number of branches operating in the country as on March 31, 1990 was 58,901. Rural branches constituted 57.8 per cent of total branches. The average population per branch office, with reference to the 1981 Census, has come down from 65,000 as at the end of June 1969 to 11,600 as at the end of March 1990.

### Indian Banks Abroad

13.5 During 1989-90, no new branch was opened abroad by any Indian bank. Following the closure of three branches, the overseas branches of nine Indian banks operating as on April 30, 1990 stood at 114. With the opening of a representative office of the State Bank of India in Manila (Philippines), the number of representative offices of four Indian banks has gone up to 11. The number of deposit-taking companies remained at three but with the addition of one wholly-owned subsidiary of the State Bank of India in Mauritius in April 1990, the number of such companies increased to four.

### Foreign Banks in India

13.6 During the year, the representative office of Credit Lyonnais was upgraded into a branch. The number of branches of 22 foreign banks thus increased to 138. With the opening of a representative office of the National Australian Bank (Australia) the number of representative offices of foreign banks in India increased to 22.

### Regional Rural Banks

13.7 There are at present 196 RRBs covering 369 districts: these RRBs have a total of 14,079 offices. Total outstanding deposits and advances of all RRBs amounted to Rs. 3,119 crore and Rs. 2,919 crore, respectively, as at the end of March 1989. No new RRB was established during the year.

### Service Area Approach

13.8 As mentioned in last year's Report, the new strategy of rural lending, viz., the Service Area Approach (SAA) became operational from April 1, 1989. As part of this new approach, commercial bank branches prepared Annual Credit Plans for 1989-90 (April-March). The all-India sector-wise credit disbursement targets fixed for 1989-90 are as indicated below :

(Rupees crores)

Sector	Targeted disbursements	Actual disbursement upto December 31, 1988	1989-90 Target
(Prior to SAA)			
Agriculture	8,208	8,988	10,284
Industry	2,248	2,132	2,544
Services	2,334	2,590	2,491
Total	12,790	13,710	15,319

Under SAA, the service area of each branch normally comprises 15 to 25 villages.

13.9 The second round of field studies was conducted in December 1989 by public sector banks with a view to ascertaining the manner of implementation of SAA in rural branches. An attempt was made to assess the implementation of the scheme and the steps needed for improving its operational aspects. It was decided, inter alia, that efforts should be made to stabilise the scheme and, meanwhile the relaxations already granted to bank branches to lend to their old clientele residing in the service area of other bank branches, if they so choose, was continued so as not to disrupt credit flows. Co-operative banks have also been advised to prepare similar credit plans. Guidelines have been issued to banks for the preparation of branch credit plans for the year 1990-91 keeping in view the need to remove the deficiencies

observed in the credit plans prepared for the previous year. With a view to improving the quality of credit plans of bank branches and effectively monitoring them, NABARD is setting up offices in all districts in the country in a phased manner in the next 3-4 years. These offices would also transmit potential linked credit plans being prepared for each district by NABARD to rural and semi-urban branches of commercial banks to help them prepare their credit plans. NABARD has already opened 43 such offices in the first phase. Simultaneously, the Reserve Bank is enlarging the coverage of rural and semi-urban branches for inspections.

### Banks' Assistance to Priority Sectors

13.10 Total priority sector advances of the public sector banks increased from Rs. 34,623 crore as at the end of March 1989 to Rs. 39,418 crore as at the end of March 1990 constituting 43.2 per cent of total advances of public sector banks as at the end of March 1990 as against the stipulated target of 40 per cent. Private sector commercial banks are also required to achieve various targets and sub-targets for priority sector advances and lending under the Differential Rate of Interest Scheme. As at the end of March 1989, priority sector advances of private sector commercial banks formed 36.7 per cent of their total advances.

### DRI Scheme

13.11 The outstanding advances of public sector banks under the Differential Rate of Interest Scheme as at the end of March 1990 amounted to Rs. 703.59 crore in 42.29 lakh accounts as against Rs. 679.59 crore in 47.67 lakh accounts as at the end of March 1989. The advances of these banks under this scheme as at the end of March 1990 formed 0.9 per cent of total advances outstanding as at the end of March 1989 (the stipulated target is 1.0 per cent). The outstanding advances under the scheme to the beneficiaries belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes amounted to Rs. 335.85 crore as at the end of March 1990, forming 47.7 per cent of total DRI advances which exceeded the prescribed target of 40 per cent.

### Self-Employment and Other Schemes

13.12 The number of beneficiaries to be assisted under the Self-Employment Scheme for Educated Unemployed Youth (SEEU) in 1989-90 was fixed at 1.25 lakh. According to the available data, banks sanctioned to 0.97 lakh beneficiaries loans aggregating Rs. 190.00 crore during 1989-90 (April-March); in 1988-89 as against the target of 2.50 lakh beneficiaries, 1.91 lakh beneficiaries were sanctioned loans aggregating Rs. 404.32 crore.

13.13 The Self-Employment Programme for the Urban Poor (SEPUP) introduced by the Government of India during 1986-87 was continued during 1989-90. As per data available total loans amounting to Rs. 101.53 crore were sanctioned by banks under this scheme during 1989-90 to 2.65 lakh beneficiaries.

### IRDP

13.14 Under the Integrated Rural Development Programme (IRDP), in 1989-90, as per available



data, banks assisted 33.51 lakh beneficiaries as compared with 37.72 lakh beneficiaries in the preceding year. A total amount of Rs. 1,221 crore as loans and Rs. 615 crore as subsidy was disbursed to the beneficiaries under IRDP in 1989-90. Out of 33.51 lakh beneficiaries assisted during the year 1989-90, 15.45 lakh belonged to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and 8.59 lakh were women. During the Seventh Plan period, banks assisted 182 lakh beneficiaries of which 81.97 lakh belonged to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and 34.32 lakh were women beneficiaries. Even though it was envisaged that 20 million families would be covered during the Seventh Plan period under IRDP, Government of India have fixed the total target at 16.03 million families to be assisted. As against this target, 18.18 million families were actually assisted during the Plan period. Against the sub-target of 30 per cent each of actual assisted beneficiaries fixed for SC/ST and women beneficiaries, the achievement was 45 per cent and 18.9 per cent, respectively. Loans and subsidy disbursed during the Seventh Plan amounted to Rs. 5,373 crore and Rs. 3,165 crore, respectively. The recovery of public sector banks of their IRDP loans was 39.0 per cent of demand in 1989 as compared with 40.8 per cent in 1988.

#### Credit to Minority Communities

13.15 As at the end of June 1989, priority sector advances of public sector banks to the minority communities in the 40 identified districts amounted to Rs. 798.57 crore in 12.66 lakh borrowal accounts.

#### Credit to SCs/STs

13.16 Outstanding advances from public sector banks to Scheduled Castes and Scheduled Tribes increased from Rs. 2,502 crore in 81.00 lakh borrowal accounts in December 1988 to Rs. 2,917 crore in 90.85 lakh borrowal accounts in December 1989.

#### Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, 1990

13.17 The Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, 1990, providing debt relief up to Rs. 10,000 to the borrowers of public sector banks and RRBs, which was announced by the Union Finance Minister in his budget speech for the year 1990-91 has been finalised and communicated to banks for implementation; the scheme came into force from May 15, 1990. For banks in the cooperative sector, a scheme on similar pattern will be framed and put into operation by the State Governments. The scheme for borrowers of public sector banks covered those engaged in agriculture and other allied activities and artisans engaged in any activity of rural development relating to cottage and village industry, handicrafts, weaving, etc. The eligible loans for debt relief under this scheme cover (i) that part of the short-term loans, including converted/rescheduled medium term loans, availed of by an individual borrower on or after April 1, 1986, and instalments of a term loan falling due after October 2, 1986, which were overdue to a bank on October 2, 1989, the relief will be available to a "non-wilful defaulter" who did not repay loan or loan instalments due, and experienced two or more years, whether consecutive or not, which were bad crop

years resulting in crop yield being less than fifty per cent or less of the normal yield on the basis of Annawari declarations and one of which was the year in which the default occurred; (ii) 'chronic overdues', i.e., overdues, including overdue interest of an individual farmer, weaver or artisan or landless cultivator who borrowed a loan or loans from one or more banks, and had overdues with such bank(s), aged more than years as on the effective date, i.e., October 2, 1989; (iii) the loans taken by a borrower who has died on or before October 2, 1989; and (iv) the overdue loan of a borrower who has been declared insolvent or whose petition is pending in the court on or before October 2, 1989 for being declared insolvent.

13.18 In the Budget for 1990-91 the Central Government has made a provision of Rs. 1,000 crore towards the debt relief scheme and has committed to underwrite the entire burden of the relief which will be provided by commercial banks and RRBs. In addition, the Central Government is committed to providing 50 per cent assistance for the relief to be provided by the co-operative credit institutions.

#### Inspection of Banks

13.19 During the period under review Annual Financial Reviews in respect of 28 public sector banks and 13 Local Head Offices of State Bank of India were taken up and completed. Financial inspections of seven public sector banks, 16 private sector banks and seven foreign banks were also taken up; out of these, inspections of six public sector banks, 16 private sector banks and five foreign banks have been completed and the remaining inspections are in progress.

#### Capital Base of Banks

13.20 In accordance with the scheme evolved to augment the capital base of nationalised banks, the Government of India contributed Rs. 700 crore during 1989-90 bringing the aggregate contribution since 1985 to Rs. 1,900 crore under the scheme. Measures to further strengthen the owned funds of the banks in the public as well as private sector are being pursued.

#### Credit relaxation to borrowers/customers of banks in Punjab and Jammu and Kashmir

13.21 As trade and industry have been experiencing several difficulties continuously due to exceptional circumstances prevailing in Jammu and Kashmir and Punjab, permission for extension of certain concessions/relaxations to bank customers/borrowers in these areas has been granted or continued; these relate to margins, service charges, rescheduling repayment of term loans, non-levy of penal interest, not charging compound interest in deserving cases, grant of need-based additional credit limits, etc.

#### Financial Diversification by Banks

13.22 The banks continued to diversify their activities in new areas like merchant banking, equipment leasing, housing finance, venture capital, mutual funds, etc. through their subsidiaries. By virtue of a notification issued by the Government of India under the Banking Regulation Act, 1949, Factoring activity has also become a permissible form of business for banks

to engage in. Banks have been advised that this activity may not be undertaken departmentally, but only through their subsidiaries. With the setting up of a wholly-owned subsidiary by Indian Bank, the number of equipment leasing and merchant banking subsidiaries of banks stood at eight as at the end of May 1990 (seven established by public sector banks and one by a private sector bank). In addition, there is one wholly-owned housing finance subsidiary and two joint venture housing finance companies set up by banks. In all, five public sector banks have set up mutual funds. Detailed guidelines to banks on important aspects of mutual fund business have been issued. Proposals from some more banks for setting up of subsidiaries for various types of financial diversification are under consideration.

13.23 During the period under reference, inspection of two subsidiaries, viz. BOB Fiscal Services Ltd. and Punjab National Bank Capital Services Ltd. were also arranged. A decision has since been taken by Bank of Baroda to wind up its subsidiary.

#### Moratorium and Amalgamation

13.24 During the year under review, the United Industrial Bank Ltd. was amalgamated with Allahabad Bank. The Government of India on the recommendation of the Reserve Bank of India, placed under moratorium, four private sector scheduled commercial banks, viz., The Bank of Tamilnad Ltd., The Bank of Thanjavur Ltd., The Parur Central Bank Ltd. and the Purbanchal Bank Ltd. with effect from the close of business on August 19, 1989. Of these, the first three have been amalgamated with Indian Overseas Bank, Indian Bank and Bank of India, respectively, with effect from February 20, 1990. The moratorium which was reimposed on the Purbanchal Bank Ltd. from the close of business of February 20, 1990 was lifted on May 21, 1990.

#### Customer Service

13.25 It has been decided to conduct sample surveys covering certain specific areas of customer service in the States of Gujarat, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal covering about 1,000 branches of public sector banks functioning in rural, semi-urban and urban areas. Accordingly, the work has been entrusted to reputed agencies like NITIE in Bombay, Indian Institute of Management in Bangalore and Calcutta, and Birla Institute of Science and Technology in Pilani covering the States of Gujarat, Tamil Nadu, West Bengal and Uttar Pradesh respectively. While survey work in respect of Gujarat is just completed, the survey work in respect of Tamil Nadu and West Bengal are in progress. The survey work in Uttar Pradesh is likely to be commenced shortly.

#### Mechanisation/Computerisation in the Bank Industry

13.26 As at the end of June 1990, public sector banks had installed 5,007 Advanced Ledger Posting Machines (ALPMs) at over 1,300 branches, of which 4,759 ALPMs were operationalised with 3,973 on 'live' run. Banks had installed 253 mini-computers at Regional/Zonal offices, of which 243 were operationalised. Three banks had installed and operationalised mainframe computers at their respective Head Offices

and several other banks had placed orders for mainframes which are in the process of installation. About 40,500 members of staff of banks had been imparted training so far in computer awareness, machine operation, etc.

13.27 The pilot project of total computerisation of branch operations had been allocated to eight public sector banks by the Indian Banks' Association (IBA) and the projects are in various stages of implementation.

13.28 Reference was made in last year's Report about the constitution of a Committee on Computerisation in Banks in September 1988 headed by a Deputy Governor. The Committee, which submitted its report in November 1989, has recommended a comprehensive computerisation plan for banks for the period 1990-94. The plan envisages a major thrust to one-line banking at branch level with a view to providing a single window service for the majority of branch activities, computerisation of the remaining Regional/Zonal offices and Head Offices, setting up of BANKNET as a common data communication network for public sector banks and financial institutions and establishing links between identified branches and Regional/Zonal offices to facilitate quick transfer of funds and information and eventually providing gateway to the Society for worldwide Inter-Bank Financial Telecommunications (SWIFT) for easier, faster and cheaper transmission of messages abroad on behalf of banks and customers.

13.29 Preparations for the first phase of BANKNET have reached an advanced stage and the network is expected to be commissioned during 1990. Almost all public sector banks have joined the network and approximately 200 offices in seven cities (viz., Bombay, Bangalore, Calcutta, Hyderabad, Madras, Nagpur and New Delhi) are being connected in the first phase. Some customer-oriented applications for use on BANKNET are being considered such as payment of demand drafts, telegraphic transfer of funds, inter-city clearing of cheques and quoting of foreign exchange rates and opening of letters of credit.

13.30 Mention was made in last year's Report to 37 banks in India (28 Indian banks, including the Reserve Bank and 9 foreign banks) becoming members of SWIFT. These banks have formed a SWIFT User Group to deliberate on common issues and to monitor the progress of implementation of the project. SWIFT organised training programme for staff of user banks in April/May 1990 at Bombay and New Delhi and has finalised the location of its Regional Processor at Bombay.

#### Computerisation of Cheque Clearance

13.31 Computerised clearing house settlement operations have commenced at Trivandrum from June 1990. These operations have already been computerised at five centres, viz., Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, Kanpur and Nagpur. With the introduction of special clearing for cheques of amount above Rs. 1 lakh at Calcutta and New Delhi from October 1989 and May 1990, respectively, all four metropolitan cities have now the system of the same day value clearing for high-value cheques besides MICR clearing. The

special clearing of inter-bank cheques was introduced in Calcutta in October 1989 and in Ahmedabad and New Delhi in May 1990. The arrangement is already operative in Bombay and Madras.

13.32 An Expert Group comprising senior officers of the Reserve Bank, State Bank of India and IBA was constituted to review the existing uniform regulations and rules for clearing houses in order to place them on a statutory basis. The Report submitted by the Group is being examined by the Reserve Bank. During the year under review, 15 new clearing houses started functioning in the country.

#### Credit Monitoring Arrangement

13.33 Mention was made in last year's Report about the introduction from October 10, 1988, of the Credit Monitoring Arrangement (CMA) in place of the Credit Authorisation Scheme (CAS) and the delegation of authority to banks to sanction credit proposals of large borrowers with a requirement that the proposals be submitted to the Reserve Bank for post-sanction scrutiny. During the 15-month period since the withdrawal of CAS, the number of credit proposals received under the CMA for post-sanction scrutiny showed an increase of 47 per cent as compared with the number of CAS proposals in the 15-month period preceding the withdrawal of the scheme. This increase was mainly on account of the lowering of the cut-off point from Rs. 6 crore (for authorisation) to Rs. 5 crore (for post-sanction scrutiny).

13.34 The number of parties in whose cases proposals were sanctioned and reported by banks under CMA by the end of March 1990 increased to 1,637 from 931 under CMA at the end of March 1989. Total working capital limits in force relating to these parties were Rs. 31,479 crore as at the end of March 1990, of which the share of public sector undertakings was Rs. 15,061 crore or 47.8 per cent. The facility-wise distribution pattern of total limits at the end of March 1990 was as follows: working capital purposes (including packing credit, inland and foreign bills) 89.5 per cent; term finance 9.8 per cent and sale of machinery on deferred payment basis 0.7 per cent.

13.35 During 1989-90 (July-June), enhancement in credit limits sanctioned by banks and reported under CMA showed an increase of 16.72 per cent over enhancements sanctioned in the previous year. Number of proposals reported under CMA showed an increase of 7.11 per cent over the same period.

13.36 Reviews carried out by the Reserve Bank suggest scope for improvement in appraisal of working capital as well as term loan requirements and post disbursement follow-up on the part of banks. Even though separate norms have been prescribed for inventory and receivables for a large category of industries, compliance by the borrowing companies with the norms has been only about 60 per cent. The response to the bills discipline, in terms of which 25 per cent of credit sales and credit purchases are to be financed through drawal of bills/acceptances, was also bound to be lukewarm. Such adverse features

were brought to the notice of the bank, concerned for rectification and future guidance. Banks have also been advised to strictly comply with the detailed operational instructions regarding CMA issued by the Reserve Bank from time to time and also to review, and wherever necessary, strengthen the organisational and administrative set-up to ensure improvement in their appraisal and post-disbursement follow-up procedures.

#### Revision of Inventory/Receivable Norms

13.37 In the light of representations made by manufacturers of paints and varnishes, who are required to hold a variety of finished products to cater to consumer preferences, banks were advised, in July 1989, to permit flexibility in the holding of finished goods and receivables by allowing a combined norm of 3.5 months in individual cases wherever interchangeability was found necessary and in other cases to continue the existing norms of 1.5 months for finished goods and of 2.0 months for receivables. The relaxation in assessing working capital limits under Method I of lending in the case of units of the National Textile Corporation and the State Textile Corporations, which have availed of financial assistance from financial institutions for modernisation, initially allowed for one year in January 1989, has been further extended upto the end of February 1991. Keeping in view the continued difficulties faced by polyester staple fibre manufacturing units, the relaxation in norms in respect of finished goods and receivables (from two months to three months) originally allowed in July 1988, was further extended up to December 1990. Based on a review of the situation prevailing in the textile industry, the norms for finished goods and receivables for composite textile mills have been allowed to continue at 3.5 months up to June 30, 1990 on a selective basis on merits of individual cases instead of the regular norm of 3 months. Decision regarding further extension will be taken on receipt of comments called for from banks. In the light of recommendations of the Sub-Group constituted by the Reserve Bank in October 1988 for the purpose of review of norms, the norms for finished goods and receivables for the fertiliser industry were revised upwards in September 1989. Based on the recommendations of the Sub-Committee which was set up to suggest norms for holding of inventory and receivables by units in the electronics industry, the norms for the following six product groups of the electronics industry have been prescribed for the first time: (i) consumer electronics (ii) communication equipment, (iii) computers (iv) control instrumentation and industrial electronics, (v) components; and (vi) aerospace and defence. Revised guidelines were issued in November 1989 to banks for assessing working capital requirements of large borrowers in the tea industry, in terms of which the existing method of cash budget has to be followed but the cash budget format has been revised so as to indicate capital and revenue flows of borrowing units separately. Net working capital of tea units should be at least 25 per cent (15 per cent for sick units) of the peak deficit. Tea units should submit the actuals in the same proforma of monthly cash budget for drawings within 4 weeks after the end of the month. If due to some genuine difficulties the units

are unable to furnish actuals within the prescribed time limit of 4 weeks, banks are allowed to grant 2 week extension at their discretion. Beyond the outer limits of 6 weeks, banks are required to charge penal interest of one per cent on total advances for the month in which data on actuals was not received. As tea unit, have to submit monthly cash budget, they are not required to submit quarterly/half-yearly statements prescribed under the information system.

#### Penal Interest on ad-hoc limits

13.38 Banks are required to charge additional interest of one per cent per annum over and above the normal rate on ad-hoc/temporary limits sanctioned to borrowers except on pre-shipment and post-shipment credit limits. In the light of enquiries from banks as to whether discretionary inland bill limits should also be subject to additional interest, banks were advised in July 1989 to exempt ad-hoc inland bill limit from the applicability of additional interest considering that the intention of vesting powers with banks to sanction such limits was to encourage the bill culture.

#### Enforcement of Financial Discipline on Borrowers

13.39 With a view to preventing borrowers who have defaulted from obtaining finance for expansion/diversification or setting up new units, banks had been advised not to consider applications for sanction of fresh term finance without ascertaining the position from financial institutions. Banks had also been advised to share information available with them in such cases when approached by financial institutions. In order to monitor instances of wilful defaults, i.e., defaults other than those caused by genuine factors beyond the control of borrowers, instructions were issued to banks in April 1990 to furnish at the end of March and September every year commencing from March 1990, reports on wilful defaults in both term loans and working capital facilities in respect of borrowers enjoying aggregate credit facilities (fund-based) of Rs. 2 crore and above from the banking system. Banks are required to furnish particulars relating to facilities enjoyed and health code status of all other borrowers belonging to the same group.

14.40 With the remission of stamp duty on usance bills (see paragraph 6.45 of this Report), banks have been advised to enforce the discipline by restricting receivable finance towards inland credit sales to the extent of 75 per cent of the aggregate limits for book debts and actual level of credit extended by way of bill finance in respect of CMA borrowers.

#### Export Credit

13.41 Data relating to 50 scheduled commercial banks which account for about 95 per cent of bank credit of all scheduled commercial banks (referred to in Part D) show that their outstanding export credit increased from Rs. 6,141 crore to Rs. 8,272 crore at the end of March 1990 registering a rise of 34.7 per cent. The proportion of outstanding export credit to total bank credit in respect of these 50 banks rose from 7.2 per cent at the end of March 1989 to 8.0 per cent at the end of January 1990.

#### Export Credit (Interest Subsidy) Scheme 1968

13.42 Under the Export Credit (Interest Subsidy) Scheme, 1968, the interest subsidy to commercial banks and eligible co-operative banks was revised in

October 1989 to 5.0 per cent per annum in respect of pre-shipment credit and 3.85 per cent per annum in respect of post-shipment credit on cash basis with retrospective effect from March 1, 1989. Till then, a uniform subsidy rate of 3 per cent per annum was applicable to both pre-shipment and post-shipment credit.

13.43 In terms of the instructions issued to banks in November 1988 term loans granted by them to housing finance companies other than HUDCO, HD-FC and companies promoted/sponsored by commercial banks, were restricted to their net owned funds.

As the housing finance companies, barring the exemptions quoted above, were finding it difficult to mobilise resources from public financial institutions and others and also keeping in view the thrust for housing, it was decided in January 1990 to make such companies eligible for term loans from banks to the extent of three times their net owned funds.

13.44 As regards housing finance allocations for the year 1990-91, each scheduled commercial bank has been asked to compute its share at 1.5 per cent of incremental deposits between the last reporting Fridays of March 1989 and March 1990. There is, however, no objection to banks exceeding this level up to a reasonable limit having regard to their resources position and compliance with the statutory reserve requirements. Housing finance provided by banks for which refinance is availed of from the National Housing Bank (NHB) will now form part of housing finance allocation.

13.45 Banks will continue to allocate 30 per cent of their total housing finance allocation by way of direct lending. Of this at least one-half should be lent as direct housing loans in rural and semi-urban areas. Furthermore, 30 per cent of the allocation is intended for indirect lending as stipulated in earlier instructions issued in November 1988. Banks have to ensure that this credit is channelled by way of term loans to housing finance institutions, housing boards, other public housing agencies, etc. primarily for augmenting the supply of serviced land and constructed units. Banks have also to ensure that the supply of plots/houses is time-bound and public agencies do not utilise the loans merely for land acquisition. Similarly, serviced plots have to be sold by these agencies to co-operative societies; professional developers and individuals with the stipulation that the houses should be constructed thereon within a reasonable time, not exceeding 3 years. The balance 40 per cent of the allocation will be available for subscription to the guaranteed bonds and debentures of NHB and HUDCO.

13.46 As part of the package of credit policy measures announced in October 1989, the restrictions on the quantum of housing loan per individual was removed. While continuing the present thrust on financing smaller houses, it was felt that there may be genuine cases with need for loans of over Rs. 3 lakh. The aforesaid ceiling of Rs. 3 lakh was, therefore, withdrawn with effect from October 11, 1989. It was left to the banks to charge a higher rate of interest over the minimum rate of 16 per cent on housing loans exceeding Rs. 3 lakh per individual. Such housing loans exceeding Rs. 3 lakh per individual will, however, not form part of the housing finance allocation.

## National Housing Bank

13.47 The share capital of the National Housing Bank (NHB) was raised from Rs. 100 crore to Rs. 150 crore on September 7, 1989. During the year under review, NHB issued its second series of bonds and the total subscription amounted to Rs. 60 crore. These bonds, guaranteed by the Central Government carry an interest rate of 11.5 per cent per annum. The Reserve Bank sanctioned a long-term loan of Rs. 25 crore to NHB out of the National Housing Credit (Long-Term Operations) Fund.

13.48 Mention was made in the last year's Report about the approval by USAID of the programme to provide a loan guarantee for US \$50 million to NHB under the USAID Government Housing Guarantee Programme; under this programme, financial institutions from developing countries can borrow in the US capital market with a guarantee of the US Government for periods up to 30 years. Under the agreement signed on March 9, 1990, a loan guarantee of US \$25 million is available to NHB as the first part of the loan guarantee programme. The funds will be utilised to support housing finance companies (HFCs) in making long-term shelter finance available to households below the median income. The programme will also assist HFCs in better management of their loan portfolios.

13.49 Based on the feedback received, refinancing by NHB of direct housing loans by primary lending agencies was liberalised during the year. Effective January 1, 1990, scheduled commercial banks, scheduled State co-operative banks, scheduled urban co-operative banks, HFCs and State-level apex co-operative housing finance societies, are eligible for refinance from NHB to the extent of 100 per cent of their direct loans to individuals (including co-operative societies) up to Rs. 1 lakh for acquisition/construction of a housing unit with built-up area not exceeding 40 sq. m. or cost (including cost of land) not exceeding Rs. 1.5 lakh. The rate of interest on refinance was made uniform for rural and urban areas. Consequently, the loan slabs were reduced to three, common to both types of areas. The relaxations are applicable to housing loans sanctioned and disbursed on or after January 1, 1990. Refinance will continue to be available as before, to the extent of 100 per cent of loans up to Rs. 30,000 sanctioned for major repairs and upgradation.

13.50 The interest rates on refinance will be as under :

Purpose and amount of loan	Rate of interest (per cent per annum)	
	To be charged by NHB	To be charged by primary lender to borrower
(1)	(2)	(3)
I. For acquisition/construction of new housing unit with built-up area not exceeding 40 sq. m. or cost of accommodation including cost of land not exceeding Rs. 1.5 lakh		
(i) Upto Rs. 20,000	10.5	12.5

(1)	(2)	(3)
(ii) Above Rs. 20,000 and upto Rs. 50,000	12.0	13.5
(iii) Above Rs. 50,000 and upto Rs. 1,00,000	13.0	14.0
II. Upgradation including major repairs irrespective of built-up area		
(i) upto Rs. 20,000	10.5	12.5
(ii) above Rs. 20,000 and upto Rs. 30,000	12.0	13.5

Till the end of June 1990, NHB had disbursed refinance aggregating Rs. 131.69 crore to seven HFCs and scheduled commercial banks, one scheduled state co-operative bank, one scheduled urban co-operative bank, one apex co-operative housing finance society and one agricultural rural development bank (by way of subscription to its Special Rural Housing Debentures).

13.51 The Home Loan Account Scheme (HLAS), the details of which were given in last year's Report, was launched by NHB on July 1, 1989 with the co-operation of scheduled banks. All scheduled public sector banks, 24 scheduled commercial banks in the private sector, 5 scheduled State co-operative banks, and 8 scheduled urban co-operative banks agreed to implement the Scheme. RRBs can operate the Scheme as agents of their respective sponsor banks. It is estimated that till the end of June 1990 about 2 lakh accounts were opened under HLAS since its introduction in July 1989. Certain changes have been effected in the HLAS. The minimum period of saving has been reduced from the present 5 years, to 3 years in the case of purchase of a flat/house in projects financed by NHB. The ceiling of Rs. 3 lakh on the amount of HLA loan has been removed, but loans above Rs. 2 lakh are to be limited to one and a half times the accumulated savings. The amount of loan is now related to the accumulated savings (and not to the size of accommodation) as shown in the table below. For instance, accumulated savings (including interest) upto Rs. 12,500 will give a loan eligibility upto Rs. 50,000, i.e. four times the savings.

Amount of Loan and Rate of Interest under the Home Loan Account Scheme

Loan amount as a multiple of accumulated savings	Amount of loan (Rs.)	Rate of interest (per cent per annum)
Four times	Upto 50,000	10.5
Three times	50,001—1,00,000	12.0
Two times	1,00,001—2,00,000	13.5
One and a half times	Above 2,00,000	14.5

13.52 In April 1989, guidelines formulated by NHB for providing financial assistance for Land Development and Shelter Projects undertaken by public agencies such as Housing Boards and Area Develop-

ment Authorities were made applicable with certain modifications to co-operative societies, professional developers and also rental housing schemes.

13.53 Up to June 1990, NHB had cleared, in principle, 56 project proposals for land development and shelter construction involving a total outlay of Rs. 413.80 crore.

#### Sick Industrial Undertakings

13.54 Banks have again been advised to ensure that the Reserve Bank's instructions in the matter of rehabilitation of sick/weak industrial units, are complied with and any violation of these instructions would be viewed seriously. Banks have also been advised that the inter se agreement among banks financing a healthy unit under consortium arrangement should provide for a clause to the effect that should the unit turn sick, banks would be required to participate in the rehabilitation package as per the instructions of the Reserve Bank, and that such a clause may be duly incorporated in all the existing inter se agreements as well. In the case of units being financed under multiple banking arrangement, banks having major share should obtain a suitable undertaking in this regard from the other financing banks. Furthermore, instructions have been issued to banks that in exceptional cases, where they are unable to participate in rehabilitation packages on account of temporary liquidity constraints, the concerned banks during the interregnum should provide guarantees in favour of the banks, which take up additional share of the limits, for reimbursement of the amount lent on their behalf.

13.55 The Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) had specified six banks as 'Operating Agency' for preparation of rehabilitation schemes for sick industrial units. Two more banks, viz., Indian Bank and United Bank of India, have since been so specified by BIFR. Thus, there are now eight banks, which could be appointed by the BIFR as an 'Operating Agency'.

13.56 According to data as at the end of June 1988 (latest available), the total number of non SSI units identified by banks as 'sick' [as defined in Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (SICA)] was 1,172 with outstanding bank credit of Rs. 3,026 crore. Out of these, viability studies in respect of 944 units were completed and 350 units were considered viable. Of the units considered viable, 234 units were put under nursing programmes by banks. The total number of non-SSI units identified by banks as 'weak' as at the end of June 1988 was 743 with outstanding bank credit of Rs. 1,922 crore. Out of these, viability studies in respect of 569 units were completed and 302 units were considered as viable. Of the viable units, 164 units were put under nursing programme by banks.

13.57 As at the end of June 1988 there were 2,17,436 sick SSI units involving bank finance of Rs. 1,980 crore. Of these, 12,954 units with outstanding bank credit of Rs. 451 crore were considered by banks as potentially viable and 8,347 units were put under nursing programme.

#### Demarcation of Functions between IDBI/SIDBI and NABARD

13.58 The question of demarcation of functions as between NABARD and IDBI/SIDBI was considered by the Reserve Bank in consultation with them and it has been agreed that the following guidelines will be adhered to in regard to the functional areas common to these institutions :

- (i) State Finance Corporations, twin-function State Industrial Development Corporations and urban co-operative banks will seek refinance from IDBI/SIDBI exclusively in respect of the assistance provided by them to SSI/tiny/decentralised sector units. Assistance provided to such units in areas other than rural areas (as defined in the NABARD Act) will also be refinanced exclusively by IDBI/SIDBI.
- (ii) Assistance provided to all units in SSI/tiny/decentralised sectors in rural areas (as defined in NABARD Act) by commercial banks/regional rural banks/cooperative banks (other than urban cooperative banks) will be refinanced by NABARD.
- (iii) Assistance to State cooperative banks/central/cooperative banks may be provided either by IDBI/SIDBI or NABARD.

Scheduled commercial banks have been advised to ensure that refinance is availed of from these institutions in accordance with the above guidelines.

#### Reserve Bank's Assistance to Financial Institutions

13.59 The Reserve Bank sanctioned to NABARD a total general line of credit of Rs. 3,350 crore for the year 1989-90 (July-June) as against a limit of Rs. 2,700 crore for 1988-89.

13.60 The Reserve Bank sanctioned and disbursed long-term funds aggregating Rs. 375 crore to IDBI out of the National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund [NIC (LTO) Fund] for the year 1989-90 (July-June) repayable over a period of 15 years at an interest rate of 8 per cent per annum. After taking into account the amount of Rs. 81.02 crore repaid during the year by IDBI, its outstanding borrowings from the NIC (LTO) Fund stood at Rs. 3,822 crore as on June 30, 1990. IDBI was also sanctioned a short-term credit limit of Rs. 400 crore on March 14, 1990, against the security of eligible finance bills rediscounted by it, this limit was valid till the end of June 1990. Consequent upon the establishment of the Small Industries Development Bank of India (SIDBI), IDBI agreed to make available the entire allocation from out of NIC (LTO) Fund to SIDBI for the year 1990-91.

13.61 As in the previous year, EXIM Bank was sanctioned a long-term loan of Rs. 95 crore out of NIC (LTO) Fund for the year 1989-90 (July-June) repayable over a period of 15 years at an interest rate of 7 per cent per annum. EXIM Bank fully availed of the limit and its outstanding borrowing from the LTO Fund stood at Rs. 625 crore as on June 30, 1990.

13.62 The Industrial Reconstruction Bank of India (IRBI) was also sanctioned, as in the previous year, a long-term loan of Rs. 25 crore for the year 1989-90 (July-June) out of NIC (LTO) Fund repayable over a period of 15 years at a rate of interest of 6 per cent per annum, IRBI fully availed of the limit and its outstanding borrowing from the Fund as on June 30, 1990 stood at Rs. 95 crore.

13.63 The National Housing Bank (NHB) was sanctioned a long-term loan of Rs. 25 crore out of the National Housing Credit (Long-Term Operations) Fund [NHC (LTO) Fund] for the year 1989-90 (July-June) repayable over a period of 20 years at a rate of interest of 6 per cent per annum for promoting rural housing.

13.64 An ad hoc borrowing limit of Rs. 40 crore was sanctioned to the Industrial Finance Corporation of India (IFCI) for the calendar year 1990.

13.65 An ad hoc borrowing limit of Rs. 30 crore was sanctioned to the Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI) for the year 1989-90 (April-March). The facility was availed of on several occasions, though no amount was outstanding against this limit as on March 31, 1990. A fresh limit of Rs. 33 crore has been sanctioned to ICICI for the year 1990-91 (April-March).

13.66 The Reserve Bank sanctioned fresh ad hoc borrowing limits aggregating Rs. 88.00 crore to 15 State Financial Corporations (including Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Ltd.) against ad hoc bonds guaranteed by the respective State Governments. These limits were valid up to June 25, 1990. The aggregate amount outstanding against these limits was Rs. 43.65 crore as on March 31, 1990.

#### 14. DEVELOPMENTS RELATING TO COOPERATIVE BANKING

##### PRIMARY COOPERATIVE BANKS

###### (i) Progress

14.1 The policy enunciated in 1986 to grant licences to new urban cooperative banks in districts devoid of urban banking facilities was continued during 1989-90. The Reserve Bank cleared during the year (up to June 30, 1990) 23 proposals for registration by the Registrar of Cooperative Societies of the States concerned and issued 17 licences to banks to commence banking business. At the end of June 1990, there were 1,390 primary cooperative banks in the country (of which 48 were under liquidation) as compared with 1,378 primary cooperative banks at the end June 1989, these included 36 Mahila banks and 92 salary earners' banks. During the year (up to June 1990), 14 existing banks were also granted licences to carry on banking business in India taking the total number of licensed primary urban cooperative banks to 1,013.

14.2 Permission was granted to 52 primary cooperative banks (including two salary earners' banks) during 1989-90 to open 54 new places of business.

Furthermore, six urban cooperative banks were granted permission to open seven extension counters. At the end of December 1989, the number of offices of primary urban cooperative banks stood at 3,283 as against 3,279 as at the end of June 1989. During the Seventh Five Year Plan, 436 branches were allotted to 381 primary urban cooperative banks of these 225 branches were opened by 195 primary urban cooperative banks by the end of June 30, 1990.

14.3 The total number of scheduled primary cooperative banks remained unchanged at 11.

14.4 Primary cooperative banks are required to lend 60 per cent of their total advances to priority sectors, of which at least 25 per cent should be to weaker sections. Out of 532 reporting primary cooperative banks, 359 banks had achieved this level as at the end of June 1989, 345 banks out of these 359 banks had achieved the target specified for lending to weaker sections.

###### (ii) Refinance Facilities

14.5 During 1989-90 (April-March), short-term credit limits aggregating Rs. 20.71 crore were sanctioned to five State cooperative banks on behalf of 53 primary cooperative banks for financing working capital requirements of specified cottage/small-scale industrial units as against Rs. 26.00 crore sanctioned on behalf of 52 primary cooperative banks in the previous year. An amount of Rs. 20.97 crore was outstanding against these limits as on March 31, 1990. The facility of refinance against the collateral of Government and trustee securities has been extended to scheduled urban cooperative banks for the purpose of clearing imbalance. The refinance limit will be restricted to one per cent of demand and time liabilities of the concerned bank. The present rate of interest on this refinance is 12.5 per cent.

###### (iii) Non-Resident Accounts

14.6 As at the end of June 1990, 49 primary cooperative banks were authorised to open and maintain Non-Resident (Ordinary/External) Accounts in Rupees.

###### (iv) Statutory Inspections

14.7 During the period July 1, 1989 to June 30, 1990, inspections of 502 primary cooperative banks were conducted.

###### (v) Dealings with DFHI

14.8 The urban cooperative banks have been permitted to deal with the Discount and Finance House of India Ltd. (DFHI) in the inter-bank market both as lenders as well as borrowers. In view of this, deposits received by urban cooperative banks from DFHI are exempted from the provisions of the directives on interest rates issued by the Reserve Bank from time to time.

###### (vi) Customer Service

14.9 On the lines of instructions issued to commercial banks, urban cooperative banks have been advised to afford credit of interest to the customers if the amount of interest payable on account of delay



in collection of outstation cheques works out to 25 paise or more. Furthermore, urban cooperative banks are allowed to extend immediate credit for more than one outstation cheque at a time within the overall limit of Rs. 2,500. They have also been advised to sanction advances against the security of Kisan Vikas Patra taking into consideration the purpose of advance and in accordance with the directives issued by the Reserve Bank from time to time on interest rates. Besides, they are allowed to sanction advances against the pledge of National Savings Certificates (VIII Issue) subject to usual terms and conditions.

## STATE AND CENTRAL COOPERATIVE BANKS

### (i) Licences

14.10 During the year, three district central co-operative banks (one each in Karnataka, Punjab and Tamil Nadu) were granted licences to carry on banking business in India. Thus, the total number of licensed State cooperative banks and Central cooperative banks stood at 8 and 40, respectively, at the end of June 1990. During the year, licences were issued to three State cooperative banks for opening three offices.

### (ii) Interest Rates

14.11 The changes in the structure of interest rates on deposits made periodically by the Reserve Bank in respect of commercial banks are also made applicable to State Central cooperative banks. Accordingly, with a view to providing a better rate of return on short-term surplus funds, the term deposit rate for 46 days to 90 days was raised from 6 per cent to 8 per cent per annum with effect from October 11, 1989. In alignment with the rationalisation of the interest rates and maturities on domestic term deposits for one year, the term deposit rates and maturities for Non-resident (External) Rupee (NRE) Accounts were rationalised with effect from April 16, 1990. Accordingly, the maturity range of 15 days to 45 days has been abolished and a uniform rate of 8.5 per cent has been made applicable on term deposits in this category for maturities of 46 days to less than one year.

14.12 Term loans with maturity period of not less than three years which carried a rate of interest of 15 per cent were made subject to a minimum of 15 per cent, but without a ceiling rate, with effect from October 11, 1989.

## AGRICULTURAL CREDIT REVIEW COMMITTEE

14.13 The Agricultural Credit Review Committee (ACRC), appointed by the Reserve Bank of India at the request of the Government of India to go into the entire gamut of rural credit, submitted its report to the Reserve Bank in August 1989 and the report is currently under consideration. The major recommendations of the Committee and the rationale thereof are as follows :

- (i) The Committee has observed that weaknesses of RRBs are endemic and non-viability is built into their structure and that the RRBs would not be able to serve the interests of the target group in the manner expected

of them. Hence, RRBs should be merged with the sponsor banks.

- (ii) The Committee has recommended rationalisation of lending rates for the agricultural sector and suggested that there should be only two categories of rates, namely, (a) a concessional rate, exclusively for small and marginal farmers, at 1.5 per cent above the highest rate of interest on deposits allowed by scheduled commercial banks (implying a lending rate of 11.5 per cent at present), and (b) a rate applicable to others, i.e. the rest of the borrowers where the rate of interest will be free from directions/regulations subject, however, to a ceiling of 15.5 per cent which is the existing maximum (this would in effect, imply a lending rate of 15.5 per cent for the latter category).
- (iii) The ACRC has observed that in the absence of an apex bank at the national level for the credit cooperatives, the cooperative credit structure has not been able to optimise its services to the rest of the cooperative structures like the Krishak Bharathi Cooperative Ltd. (KRIBHCO) who have to rely on commercial banks. According to the Committee, in the absence of a national bank, the cooperative banking system has been a two way loser : first, it losses out to the commercial banks the deposits of co-operative surpluses and second the better and more profitable clientele (like IFFCO and KRIBHCO). The Committee has, therefore, recommended establishment of a National Cooperative Bank of India which will function as a balancing centre for the cooperative credit system.
- (iv) The Committee has suggested the establishment of Agricultural and Rural Infrastructure Development Corporation for each of the three Eastern Region States, viz., Bihar, Orissa and West Bengal and one for all the North-Eastern States. The main tasks envisaged for these corporations are to adopt a bolder strategy for increasing the tempo of agricultural lending and towards this objective each corporation would initiate action for building up necessary backward and forward linkages and supporting services, formulating location-specific schemes for accelerating the transformation of agriculture and to arrange for funding of the projects.
- (v) In the context of deficiency in the present crop insurance scheme, the Committee has recommended setting up under an Act of Parliament a separate Corporation for implementing the crop insurance scheme and setting up of an expert committee consisting of actuaries, insurance experts, agricultural economists, etc. to conduct a study of the proposed scheme with a view to operationalising it.
- (vi) The Committee has emphasized the need for ensuring a single common legal framework



covering cooperatives and commercial banks for recovery of dues for the country as a whole and constitution of statelevel tribunals for adjudication and separate departments for execution of awards.

- (vii) The Committee has recommended the establishment of an apex agency to develop comprehensive training strategy for rural bankers; and
- (viii) The ACRC has suggested that just as a village is allotted to a commercial bank branch under the Service Area Approach, a block may be allotted to one commercial bank, which has the largest presence through its branches in the block. Such rationalisation would reduce the cost of supervision, improve quality of monitoring and be beneficial to the customers.

## 15. OTHER DEVELOPMENTS

### Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

15.1 During the year under review, the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) continued to provide insurance cover to small depositors in banks and guarantee support for the entire priority sector advances by banks and other approved financial institutions to agriculture, small borrowers and small-scale industry. The DICGC operates five credit guarantee schemes—four for small borrowers and one of the SSI sector.

15.2 The number of insured banks increased from 1,908 as on June 30, 1989 to 1,917 as on June 30, 1990 comprising 79 commercial banks, 196 RRBs, and 1,642 cooperative banks in 16 States and 3 Union Territories. The insured deposits at Rs. 1,01,682 crore formed 72.2 per cent of total assessable deposits at the end of June 1989. The fully protected deposit accounts formed 97.4 per cent of the total number of deposit accounts.

15.3 The number of banks participating in the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 at the end of June 1990 was 263 which included 67 commercial banks and 196 RRBs. The number of State Financial Corporations (including State Industrial Development Corporations) participating in the Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971 remained unchanged at 20. At the end of June 1990, the number of credit institutions participating in the Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971 was 175, while the number of primary urban cooperative banks participating in the Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme was 90. Total guaranteed advances under the above four schemes aggregated Rs. 25,586 crore at the end of March 1989 showing a rise of 79 per cent over the level at the end of June 1988, due to the extension of the scope of guarantee support to cover the entire priority sector advances from April 1, 1989.

15.4 The number of institutions participating in the Corporation's Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 rose from 545 at the

end of June 1989 to 555 at the end of June 1990. The guaranteed advances to small-scale industrial sector increased from Rs. 19,465 crore at the end of June 1988 to Rs. 14,094 crore at the end of March 1989, indicating a rise of 34.7 per cent.

15.5 During the period July 1989—June 1990, the Corporation received 17.04 lakh claims for Rs. 402 crore in respect of the guarantee schemes relating to small borrowers and 0.75 lakh claims for Rs. 210 crore in respect of its scheme for small-scale industries. During the same period, 17.52 lakh claims for Rs. 376 crore in respect of small borrowers and 0.88 lakh claims for Rs. 374 crore in respect of the SSI scheme were disposed of by the Corporation.

15.6 The guarantee claims received by the Corporation had been exceeding its guarantee the receipts from 1984 till 1988-89. Mention was made in the last year's Report about raising of the Corporation's guarantee fee to 1.50 per cent per annum uniformly from April 1, 1989.

### Non-Banking Companies Regulations Governing Acceptance of Deposits

15.7 Further to the amendment made to section 58A of the Companies Act, 1956 empowering the Law Board to take cognizance of non-payment of deposits by non-banking non-financial companies, the Department of Company Affairs has issued a notice in the press informing the members of the public of the said amendment so that aggrieved depositors of defaulting companies may approach the respective offices of the Company Law Board for redressal of their grievances. With a view to giving effect to certain changes made in the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1977 in March 1989, the First schedule, i.e., the format for submission of statutory return of deposits, has been amended vide Notification issued on February 1, 1990.

### Chit Funds Act, 1982

15.8 The Chit Funds Act, 1982 has so far come into force in nineteen States/Union Territories including the States of Assam and Rajasthan where the Act has become operative during the year under review. Necessary follow-up action is being taken to bring the Act into force in other States/Union Territories.

### Acceptance of Deposits by Unincorporated Bodies

15.9 During the year under review, four more States/Union Territories have issued notifications authorising suitable officers to take action against unincorporated bodies as envisaged in Sections 45T and 58E of the Reserve Bank of India Act, 1934. Twenty three States/Union Territories have thereby empowered themselves to enforce the prohibitory provisions of Chapter IIIC of the Act.

15.10 Of the 120 bodies located in Gujarat, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Delhi which were investigated by the Bank with the assistance of State Police/Government Officials, prosecution proceedings have been initiated against eighteen such bodies for

violation of the provisions of Chapter III. Two cases have been disposed of by levy of fine while the Supreme Court has stayed the proceedings in respect of four cases and another case has been quashed. The remaining cases are at various stages of trial.

#### Trends in Growth of Deposits with Non-Banking Corporate Sector

15.11 As per provisional data available, during the year ended March 31, 1989, the aggregate deposits of 10,088 reporting non-banking companies rose by Rs. 4,445 crore and stood at Rs. 28,649 crore as against Rs. 24,204 crore held by 10,323 companies in 1988. During 1988-89, the regulated deposits recorded an increase of Rs. 1,049 crore and stood at Rs. 5,784 crore (including borrowing of Rs. 531 crore by a Government financial company against bonds issued) while exempted deposits rose by Rs. 306 crore to Rs. 22,865 crore. Non-financial companies accounted for 62.9 per cent of aggregate deposits while financial companies accounted for 34.1 per cent and miscellaneous non-banking companies 3.0 per cent. Regulated deposits of the non-banking corporate sector rose from Rs. 4,735 crore in 1987-88 to Rs. 5,784 crore, an increase of 22.2 per cent and the deposits were equivalent to 4.1 per cent of the total deposits of all scheduled commercial

banks. The regulated deposits of the financial companies rose from Rs. 1,136 crore at the end of March 1988 to Rs. 1,977 crore (Provisional) at the end of March 1989. Excluding the one large Government company which accounts for a large part of this increase, the regulated deposits of the financial companies rose from Rs. 1,096 crore at the end of March 1988 to Rs. 1,446 crore at the end of March 1989 i.e. an increase of 31.9 per cent. The bulk of this increase is accounted for by leasing and hire purchase companies. Of the 6,355 reporting financial companies in March 1989, 192 companies (excluding the one large Government company) accounted for about 77.0 per cent of regulated deposits. The sharp increase in the exempted deposits of financial companies between March 1988 and March 1989 is largely attributable to certain institutions like Industrial Credit and Investment Corporation of India, Discount and Finance House of India and SBI Capital Market Ltd. which are classified as financial companies.

15.12 Quite apart from the various types of companies covered in these data, there are a number of Residuary Non-Banking Companies whose deposits are broadly estimated to be in the region of Rs. 1,200 crore. Details of deposits held by different categories of companies as at the end of March 1988 and 1989 are presented in the Table below.

#### Deposits with the non-Banking Corporate Sector

(as at the end of March)

(Rupees crore)

Category	1987-88@				1988-89 (Provisional)			
	No. of reporting companies	Regulated deposits	Exempted deposits	Total	No. of reporting companies	Regulated deposits	Exempted deposits	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aggregate Deposits	10 323	4.735	19.469	24.204	10 088	5 784	22 865	28 649
of which held by								
(i) Non-financial companies	2 725 (26.4)	3 599 (76.0)	13.106 (67.3)	16.705 (69.0)	2 498 (24.8)	3.805 (65.8)	14.211 (62.2)	18.016 (62.9)
(ii) Financial companies	6 442 (62.4)	1.136* (24.0)	5.590 (28.7)	6.726 (27.8)	6,355 (63.0)	1.977** (34.2)	9.801 (34.1)	8.778 (34.1)
(iii) Misc. Non-Banking Companies	1,156 (11.2)	— (—)	773 (4.0)	773 (3.2)	1,235 (12.2)	2 (—)	583 (3.7)	855 (3.0)

@ The figures for 1987-88 have been revised largely in terms of coverage and classification to facilitate comparison with the figures for 1988-89.

\*includes Rs. 40 crore raised by a Government company through bonds issued against the securities of movable assets.

\*\*includes Rs. 531 crore raised by a Government company through bonds issued against the securities of movable assets.

Note : Figures in brackets are percentages to total number of reporting companies/regulated/exempted/aggregate deposits as the case may be.

## 16. DEVELOPMENTS RELATING TO EXCHANGE CONTROL

### Blanket Exchange Permit Scheme

16.1 The scope of assistance to exporters under the Blanket Exchange Permit Scheme as operated by the Exim Bank has been further enlarged. The Government of India has signed an agreement with the World Bank for line of credit for US \$ 295 million for the Export Development Project which will strengthen efforts made in the earlier Industrial Export Project to motivate firms to draw up and implement systematic export plans resulting in incremental exports. This project include a term loan component (US \$ 275 million) and an Export Development Fund (EDF) component (US \$ 20 million). The EDF covers not only market development but also productivity improvement measures at the firm level. The EDF will be operated by four agencies, viz., Exim Bank (US \$ 7 million), ICICI (US \$ 7 million), Bank of Baroda (US \$ 3 million) and Canara Bank (US \$ 3 million).

16.2 Exporters eligible under the aforesaid Export Development Fund and term loan component would also be considered eligible for issue of blanket permit by the Reserve Bank. Such exporters would be permitted to draw exchange against the blanket permit issued to them by the Reserve Bank for expenditure towards various purposes approved under EDF on the basis of, and subject to, the terms and conditions laid down in the original letter issued to them by the respective institution, viz., Exim Bank, ICICI, Bank of Baroda and Canara Bank.

### Investments by NRIs—

#### (a) Subscription to the Memorandum and Articles of Association of Indian Companies

16.3 With a view to facilitating the work of Non-resident Indians (NRIs) intending to set up new industrial projects in India, the Reserve Bank had granted, in November, 1986, general permission to NRIs to subscribe to the Memorandum and Article of Association and take up shares of an Indian company for the purpose of its incorporation. In terms of the same Notification, general permission was granted to any such company to issue shares to NRIs up to the face value of Rs. 10,000, provided the company held a letter of intent/industrial licence/certificate of registration issued by the Union Ministry of Industry or the Director General of Technical Development or any other Central/State Government authority for undertaking its industrial activity in India. Furthermore, relaxation was made by the Bank in June 1989, permitting such subscription by NRIs in any Indian company which is engaged in, or is being formed for, taking up industrial activity and which undertakes to obtain the requisite letter of intent, etc., from the concerned Government Ministry/authority in due course for undertaking its industrial activity.

#### (b) Investment in Hotel Industry in India by NRIs/OCBs under 74 per cent Scheme

16.4 Hitherto, non-resident Indian persons of Indian origin (NRIs), and overseas corporate bodies (OCBs) predominantly owned by NRIs, were per-

mitted to invest in India with full repatriation benefits in 3, 4 or 5-star hotels under the 74 per cent scheme administered by the Government of India. With a view to giving further encouragement to NRIs to invest in the hotel industry in India, it has been decided to permit such investment with full repatriation benefits up to 100 per cent of the new issues of shares/convertible debentures made by hotels in the 3, 4 or 5-star category. The ceiling on NRI investment under the scheme in other approved industries such as computer software, hospitals, etc., remains unchanged at 74 per cent of the equity/convertible debenture issue.

#### (c) Purchase/sale of Units of UTI by NRIs/OCBs

16.5 Investment in, or sale/transfer of, units of the Unit Trust of India, securities of the Central/State Government and National Plan/Savings Certificates can be made by non-residents of Indian nationality/origin (NRIs) and overseas corporate bodies predominantly owned by such persons (OCBs), provided the investment/sale/transfer is arranged through an authorised dealer in foreign exchange. Since the Unit Trust of India has also been granted general permission by the Reserve Bank for issue/sale/transfer of units under various schemes operated by the Trust, subject to certain conditions, NRIs/OCBs will have the option to arrange for sale/purchase/transfer of units either directly from/through the Trust or through an authorised dealer in foreign exchange. Investment in Government securities and/or National Plan/Savings Certificates is, however required to be made only through authorised dealers, a hitherto.

#### Upward Revision in the per Diem Rates of Exchange for Travel Abroad

16.6 The Reserve Bank undertakes periodic reviews of the per diem rates of foreign exchange released for travel abroad for business purposes taking into consideration the movement in hotel tariffs and related expenses in foreign countries. With effect from July 1, 1989, the per diem rates of foreign exchange released for such purposes have been revised as under :

	Special scale	General Scale
	US\$	US\$
I. Group A Countries (Comprising Saudi Arabia, Japan, Kuwait and Nigeria)	300	240
II. Group B Countries (Comprising UAE, Qatar, Sultanate of Oman, Bahrain, Western Hemisphere, U.K. Western Europe, Iran, Libya and Algeria)	265	210
III. Group C Countries (Other countries in the External Group)	215	185
IV. Bilateral Group Countries	Rs. 3,000	Rs. 2,750

## Release of Exchange for Travel Abroad

16.7 Further liberalisations in respect of release of foreign exchange for travel abroad have been made as indicated below :

Studies : (i) It has been decided to do away with the requirement of minimum percentage of 55 per cent marks in the degree examination in India for the purpose of release of exchange for pursuing post-graduate courses abroad.

(ii) Doctors who are released exchange for studies/training abroad were hitherto required to give an undertaking/guarantee that they would return to India after completion of their studies/training, and in case of failure to do so, were required to pay as liquidated damages the amount of foreign exchange released or its rupee equivalent. Such requirement of obtaining a guarantee has been done away with.

Specialised Training : The limit of foreign exchange released towards course fee for specialised training abroad has been raised from US \$ 1,000 to US \$ 2,000.

Medical Check-up : The amount of foreign exchange to be released towards medical check-up/consultation abroad has been enhanced from US \$ 175 to US \$ 500 in case where no hospitalisation is required and from US \$ 350 to US \$ 700 where hospitalisation is required.

## Employment Abroad

16.8 Persons proceeding abroad for taking up employment were released foreign exchange up to US \$ 500 or its equivalent on repatriation basis to meet their initial expenses. This limit has since been enhanced to US \$ 2,000.

## Foreign Travel under Special Travel Schemes

16.9 With effect from August 4, 1989, Singapore has been removed from the Foreign Travel Scheme (FTS) group of countries and included in the group of countries covered under Neighbourhood Travel Scheme (NTS). Accordingly, resident citizen intending to visit Singapore under the Special Travel Scheme are now entitled to draw foreign exchange at the rate of US \$ 250 per adult and US \$ 125 per child under twelve, provided they are otherwise eligible to travel abroad under the scheme. Travellers wishing to visit Singapore along with any other country/countries covered by FTS will, however, be eligible to draw the FTS quota of exchange.

## Advancement in the Period of Drawal of Exchange

16.10 Hitherto, sale of foreign exchange by authorised dealers either against exchange permits issued by the Reserve Bank or under the Special Travel Schemes (FTS and NTS) or under general authority vested in authorised dealers/licensed money-changers, was to be made not earlier than a fortnight from the date of departure recorded on the confirmed ticket of the traveller. This time limit has since been raised to 30 days in order to afford more time to travellers for finalising their travel arrangements.

## Admission Fee|Correspondence Course Fee|Entry Fee

16.11 The monetary limit of US \$ 100 per university or institution for release of exchange by authorised dealers towards admission fees to person seeking admission to overseas educational institutions has been enhanced to US \$ 200. Likewise, the monetary limit for release of exchange towards correspondence course fee has been enhanced from US \$ 300 to US \$ 750 in any one calendar year. The limit for remittance by qualified|professional architect, painters, photographers, printers, sculptors and philatelists towards entry fee for participation in international competitions arranged by reputed organisation in the respective fields now stands increased from US \$ 100 to US \$ 500.

## Debits to NRO Rupee Accounts

16.12 Withdrawals from Ordinary Non-resident Rupee Accounts in the name of non-residents other than NRIs and OCBs were allowed upto a limit of Rs. 3,000 per week for meeting the expenses of the account holder and his family during their visit to India. This limit has since been done away with.

## Receipt of Export Proceeds Directly by the Exporters

16.13 Exporters are required to receive export proceeds through normal banking channels in accordance with the approved methods of payment. As an exception to this rule, exporter, of proven record could be granted general permission, on application to the Reserve Bank, to accept payment of export proceeds directly from the overseas buyers in the form of travellers cheques/banked cheques/drafts/pay orders subject to a monetary ceiling of US \$ 10,000 per instrument. The monetary limit for direct receipt of export proceeds in the above manner has been enhanced to US \$ 15,000 per instrument with effect from December 12, 1989 subject to the condition that the amount of currency notes should not be more than US \$ 2,000.

## Exports to Iran—Payment out of Special Account of Central Bank of the Islamic Republic of Iran with Reserve Bank

16.14 Governments of India and Iran had entered into a Memorandum of Understanding (MOU) in August 1989 with regard to repayment of the foreign currency loan obtained by the former from the latter for financing the Kudremukh Iron Ore Project in Karnataka. In terms of the MOU, an account with a sum of US \$ 66.89 million due on this account was opened in the name of the Organisation for Investment and Economic and Technical Assistance of Iran with the Reserve Bank. The said fund of US \$ 66.89 million has subsequently been transferred to a Special Account opened in the name of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran (CBIRI) with the Reserve Bank at Bombay. The funds credited to the Special Account are to be utilised towards payments to Indian exporters exporting goods and services to Iran. The procedure for obtaining reimbursement by banks in India through this account in respect of exports from India has also been laid down.

## Procedural Change in the Computation of Composite Rate for Payment Towards Imports Under Direct Payment Method.

16.15 The payments for import against foreign currency loans/credits extended by foreign governments/

financial institutions are made either under the 'Direct Payment Method' (also known as Letter of Commitment Method) or 'Reimbursement Method'. For the purpose of recovering the rupee equivalent of the foreign currency cost of imports made under the Direct Payment Method, the Government applies a composite rate of exchange for conversion, which is generally the banks' Bills Selling Rate plus a margin. Such rate was worked out up to 4 decimal points but rounded off the third decimal point in respect of Japanese Yen, Italian Lira and Belgian Franc and upto the second decimal point in respect of other foreign currencies. With a view to bringing about uniformity in the calculation of the composite rate and in the procedure for rounding off of the rupee cost arrived therefrom, the Government have since decided that with effect from July 1, 1989, the rounding off of the rupee equivalent of a unit of foreign currency will be done up to 4 decimal points in respect of all currencies.

#### Merchanting Trade

16.16 In order to avoid the exchange loss to the merchants in India engaged in merchanting trade, the authorised dealers, on receipt of specific written requests from their customers, are now permitted to hold in their foreign currency accounts the amount received in advance from the overseas buyer till the date of payment to the overseas supplier subject to certain conditions.

#### Booking of Passage-Foreign Technicians/Experts

16.17 The Reserve Bank removed in May 1989, the restriction regarding travel on foreign carrier by foreign technicians/technical experts visiting India against the air tickets purchased in rupees by the host Indian companies. Consequently, foreign technical experts/technicians visiting India under collaboration agreements, etc., can now travel on carriers to their choice both ways.

#### Raising of Deposits by FERA Companies through Issue of Commercial Paper

16.18 In order to facilitate issue of Commercial Paper (CP) by FERA companies (i.e., Indian companies in which non-resident interest exceeds 40 per cent), the Reserve Bank granted in September 1989, general exemption from the provisions of Section 26(7) of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (FERA) to both the investors and the investee companies to invest in issue CP, provided the eligibility criteria as laid down in the 'Non-Banking Companies (Acceptance of Deposits through Commercial Paper) Directions, 1989' are satisfied and the company complies with the terms and conditions stipulated by the Reserve Bank (IECD) relating to the issue of such commercial paper. FERA companies applying for general permission are to ensure that funds raised by way of CP are used only for the purpose of meeting the working capital requirements of the company and for carrying on the activities approved by the Reserve Bank under Sections 28 and 29 of FERA.

16.19 The Reserve Bank granted in October 1989, general permission under Section 9(1) (c) of FERA  
211 GI/91—46

to Indian companies to issue CP to non-residents of Indian nationality/origin (NRIs) (only individuals and not overseas corporate bodies predominantly owned by NRIs) in accordance with the terms and conditions stipulated by the Reserve Bank and provided the amount invested and income earned thereon shall not be allowed to be repatriated and that the CP issued to NRIs shall not be transferable. Indian Companies (including FERA companies) issuing CP to NRIs are required to comply with certain conditions specific to the Exchange Control in addition to the conditions stipulated in approval letter by the Reserve Bank (IECD).

#### Asian Clearing Union (ACU)

16.20 Hitherto, export or import transactions between the member countries of the Asian Clearing Union involving settlement on deferred payment basis were not to be treated as current transactions and hence such transactions did not call for compulsory settlement of deferred instalments through the ACU mechanism. There was, however, no objection to the advance/down payment/payment against shipping documents in respect of such contracts being routed through ACU. The ACU member countries have since agreed that payments arising out of export or import transactions on deferred payment basis should be brought under the purview of the ACU mechanism with effect from March 22, 1990.

16.21 The ACU members have also agreed upon a currency swap arrangement amongst themselves for facilitating the settlement of clearing imbalances subject to certain conditions. Necessary amendments to the ACU Agreement and ACU (procedure) Rules have, therefore, been made incorporating the above changes.

#### Authorised Dealers in Foreign Exchange

16.22 Two foreign banks, viz., Credit Lyonnais and Sanwa Bank Ltd., have been granted licence under Section 6 of FERA to deal in foreign exchange in India.

#### Opening of Offices (i) By Overseas Companies in India

16.23 During the year 1989-90 (July-June) approval for opening 70 liaison offices, 14 representative offices and 13 project offices in India were granted to foreign companies.

#### (ii) By Indian Companies Abroad

16.24 During the same period, approvals were granted to Indian companies for opening 26 trading offices, 70 non-trading offices and posting 21 representatives abroad.

#### Import and Export of Indian Currency

16.25 The regulations relating to taking out of India and bringing into India the Indian currency by

resident Indians travelling abroad as incorporated in the Reserve Bank notifications were reviewed and new notifications issued in August 1989, in terms of which any resident proceeding on a short tour to any foreign country, other than Nepal, is permitted to take with him Indian currency notes up to an amount of Rs. 250 and also to bring back into India, the Indian currency notes up to the same amount at the time of his return to India. There is no change in the existing regulations relating to taking out of Indian currency (excluding the denomination of Rs. 100) without any limit to Nepal or the bringing in Indian currency (excluding the denomination of Rs. 100) upto an amount not exceeding Rs. 75 per person at any one time from that country.

#### Commission on Exports.

16.26 Authorised dealers have been permitted to remit commission abroad or accept its deduction from proceeds of the export bill in respect of exports covered by irrevocable letters of credit providing specifically for payment of commission to an overseas agent subject to certain conditions, provided the rate of commission does not exceeds 7.5 per cent. It has been clarified that the above arrangement is applicable only in respect of exports to countries in the External Group and that the rate of commission, (to an agent resident in the country of import) in respect of exports to a country in the Bilateral Group, should not exceed 5 per cent.

16.27 In case of remittance of commission to overseas agents, by exporters of computer software, under the Blanket Permit Scheme, authorised dealers have been permitted to remit such commission without any percentage ceiling, provided the amount of commission is within the balance available in the blanket exchange permit and subject to submission of documentary evidence/agency agreement indicating that the export order was secured through the overseas agent to whom the commission is sought to be remitted.

#### Lending and Borrowing of Foreign Currency (US dollars) in Inter-Bank Market

16.28 Authorised dealers are permitted to maintain with overseas branches and correspondents, balances in foreign currencies at levels which are commensurate with normal needs of their business, such as payments towards imports or maturing deliveries under forward contracts. They are also permitted to transfer foreign currency funds rendered surplus over normal anticipated needs of their business on a day to day basis to special interest-bearing accounts with the facility of automatic retransfer to their current accounts where such facility is offered by their overseas branches/correspondents. It was represented to the Reserve Bank that while the interest earned on such overnight deposits in the lowest ruling on the day, authorised dealers whose accounts are overdrawn pending receipt of funds in the pipeline, are required to pay interest at the prime lending rate or even higher. In order to meet this situation to some extent and to enable authorised dealers to manage their foreign funds abroad more efficiently, it has been decided to permit authorised dealers to lend and borrow

foreign currency among themselves in the inter-bank market locally. The scheme will be reviewed after a period of one year. For the present, the transactions are restricted to U.S. dollars only and the maximum limit for an authorised dealer in regard to lending of foreign currency is US \$ 5 million. The actual lending limit for each authorised dealer is to be fixed by the Reserve Bank depending upon the size of its operations and other relevant factors.

#### Investment by 'Asian Convertibles and Income Fund' in a Mutual Fund set up by SBI

16.29 The Asian Development Bank (ADB) has recently sponsored multi-country Regional Fund called Asian Convertibles and Income Fund (ACIF). ACIF's objective is to promote development of capital markets in the developing member countries (DMCs) of ADB, besides providing a window to large institutional investors in capital rich countries like Japan. Further, its investment objective aims at generation of current income and long term capital appreciation through investment primarily in convertible debentures and other equity-linked securities. Assets of ACIF would be allocated amongst the target countries, i.e., DMCs of ADB; India will be receiving the highest allocation, i.e., 20 per cent of the Fund (about US \$12 million). ACIF's investment in India will be channelised through a dedicated mutual fund established by State Bank of India (SBI) (as a trust) under the name 'Asian Convertibles and Income Fund—Mutual Fund' (ACIF-MF). Funds in foreign exchange received in India by ACIF-MF will be evidenced by issue of units (denominated in Indian rupees for face value of Rs. 100 each) to ACIF who will be the sole beneficiary and unit holder of ACIF-MF. Units issued to ACIF are not transferable. The distribution of dividend, etc., on the units will be decided by the Advisory Board of ACIF (ADB being a member of the Advisory Board). The units could be redeemed only after a 'lock in' period of five years. On redemption, the units will be repurchased at the mutual fund's net asset value per unit on the day of redemption. Payment of dividend/redemption value of the units will be subject to Indian taxes. State Bank of India Capital Markets Ltd. (SBI CAP), a wholly owned merchant banking subsidiary of SBI, would act as investment manager in India for ACIF. SBI CAP will be investing the funds at its discretion in convertible debentures and other equity linked securities of the companies in India (both primary and secondary markets). SBI CAP will be entitled to management fee (commission) in foreign exchange for its services to ACIF in connection with investments in India.

#### Import by Road/Rail from Neighbouring Countries

16.30 Hitherto, authorised dealers were required to obtain the Reserve Bank's approval for opening letters of credit providing for payments against warehouse receipts, railway bills of lading, etc., for import of goods arranged through rail/road transport. Considering the representations made to the Reserve Bank that goods are now being carried across the border for trade with neighbouring countries more by road/rail due to relatively cheaper freight charges, it has been decided to permit opening of letters of credit by authorised dealers, on behalf of their importer constituents, providing for payments against lorry/rail receipts, in

the cases of imports from neighbouring countries.

#### Surrender of Unspent Foreign Exchange

16.31 The unspent foreign exchange surrendered by travellers on their return to India to an authorised dealer (A. D.) was hitherto required to be recorded in red ink in the passport of the traveller under the stamp and signature of the A. D. It has now been decided that unless a traveller requests for such an endorsement to be made in his/her passport, the A. D. need not make an endorsement on the passport. However, the A. D. must issue an encashment certificate on his printed letterhead in all such cases of purchases of foreign exchange from the traveller irrespective of whether the tenderer asks for it or not.

16.32 Till now students proceeding abroad for higher studies were being released admissible foreign exchange by all the Regional Offices of the Exchange Control Department of the Reserve Bank and some designated branches of State Bank of India. With a view to enabling such students to obtain foreign exchange from nearby banks, the Reserve Bank has delegated, with effect from June 1, 1990, the authority to release exchange for higher studies to certain designated branches of all public sector banks. Students intending to go abroad for higher studies can, therefore, avail of necessary foreign exchange facilities from any of the Regional Offices of the Reserve Bank or designated branches of public sector banks.

### 17. ORGANISATIONAL MATTERS AND ACCOUNTS OF THE BANK

#### Currency Chests

17.1 The total number of currency chests as at the end of March 1990 was 3,791. Of these, 17 currency chests were with the Reserve Bank, 2,745 with State Bank of India and its associate banks, 622 with nationalised banks, 402 with treasuries and subtreasuries and 5 with Jammu and Kashmir Bank Ltd. In addition, 494 repositories were maintained with the branches of public sector banks.

#### New Note Press Project

17.2 The New Note Press Project, a venture initiated by the Government of India, was transferred to the Reserve Bank for implementation and subsequent management. The Reserve Bank took over the project in January 1990. A wholly-owned subsidiary company of the Reserve Bank is proposed to be set up for the purpose. The project envisages setting up of two bank-note printing presses—one at Salboni, Midnapur district (West Bengal) and the other at Mysore (Karnataka). Both the presses will have comparable facilities, each having printing capacity of the order of 5,000 million pieces of notes of various denominations. The total cost of the project is estimated at Rs. 1,500 crore (inclusive of customs duty on plant and equipment required for the presses). The project is likely to be completed in about four years' time with an initial line of production becoming operational in 24 months.

#### Committee on Currency Management

17.3 Mention was made in the last year's Report about the constitution of a Committee to study the

entire gamut of currency management under the Chairmanship of a Deputy Governor of the Reserve Bank. The Committee submitted its Report on September 30, 1989. In regard to the recommendations so far as they relate to matters coming within the purview of the Government of India, the Ministry of Finance has formed a standing group to take early steps for their implementation. Regarding public sector banks, a meeting of the Chairmen of the banks was convened under the aegis of the Indian Banks' Association and the salient features of the Report were placed before them and subsequently explained to the Cash Officers of the banks at meetings held at the four metropolitan centres. In respect of the remaining recommendations which relate to work procedures and internal arrangements in the Reserve Bank, a small In-House Group has been constituted for examining the same and their implementation.

#### Surveys

17.4 During the year under review, the third and last volume of statistical tables based on the results of the All-India Debt and Investment Survey, 1981-82 was published. The survey of 'Foreign Currency Non-Resident Deposits and Non-Resident External Accounts' and the processing of the data collected under this survey were completed. As mentioned in Part I of this Report, the forecast of private corporate investments for 1990 was generated during the year. The processing of data collected in the Census of India's foreign liabilities and assets with 1986-87 as the reference period was also completed during the year, the provisional results of this Census have been published in the July issue of the Reserve Bank of India Bulletin. Arrangements have also been made to update the foreign investment data collected under the Census, through the Annual Foreign Investment Survey. The data-base relating to external commercial borrowings is being maintained with a view to monitoring the external debt position and estimating future debt service obligations. With the objective of having a more efficient data-base and integrating the data with the data-base maintained in the Ministry of Finance, a software package on Debt Management developed by the Commonwealth Secretariat was installed on a personal computer of the Bank during 1988.

#### Development of Telecommunication Network

17.5 Twenty offices of the Bank were already connected by the Store and Forward Teleprinter (SFT) Network in the Reserve Bank. The Ministry of Finance and Department of economic Affairs were also connected to the above network during the year. Similarly, dedicated speech network connecting 20 Reserve Bank Offices is nearing completion.

#### Progress in Computerisation

17.6 In the recent past, due to phenomenal increase in public debt, the services rendered pertaining to issue of scripts, repayment of loan, payment of interest, etc., increased alarmingly requiring a thorough overhaul of the systems and procedures followed by the Bank. An inter-departmental committee was constituted to prepare an operational plan for the introduction of computers in Public Debt Offices (PDOs) with a view to improving customer service and



streamlining internal procedures. The committee submitted its Report in June 1990 and the recommendations are under consideration of the Bank. It is envisaged that with the introduction of computers in PDOs, the Bank will be in position to improve customer services substantially and also improve the accounting work related to loan balancing, interest payment and repayment on maturity.

17.7 The Bank plans to replace the present Cii-Honeywell Bull Mainframe Computer System in the Department of Statistical Analysis and Computer Services by a state-of-art large mainframe computer system with on-line data communication facility. One super-mini system for the central office of the Exchange Control Department (ECD) is being installed for computerisation. A few projects such as non-resident investments and foreign accounts, etc., have been identified initially. Personal Computers (PCs) for 9 major regional offices of ECD were also acquired and software packages have been developed in-house for selected items like deferred payment projects, foreign collaboration in India, joint venture projects, turnkey projects and caution listing of exporters. Personal computers were also installed in the Credit Planning Cell, Department of Financial Companies (Bangalore and New Delhi) and at Zonal Training Centres at New Delhi and Calcutta. Computers will also be installed in the Department of Economic Analysis and Policy, Department of Government and Bank Accounts, Premises Department, Management Services Department, Department of Administration (Training Division) and Department of Currency Management. It is proposed to provide word-processing facilities in the Department of Banking Operations and Development, Exchange Control Department, Secretary's Department, Management Services Department and History Cell to expedite correspondence and preparation of documents.

17.8 The new upgraded computer system installed at Central Accounts Section, Nagpur and the mini-computer system installed in Department of Banking Operations and Development, Central Office, were operationalised. The mini-computer system for the Urban Banks Department (Central Office) will be installed shortly.

17.9 In the second phase of computerisation of the Issue Department offices for handling currency chest accounts, etc., computers were installed and operationalised at Bangalore, Madras and Hyderabad. These computers are also to be used for payrolls and software package developed for the purpose is under test at Bangalore.

17.10 Work areas have been identified for computerisation in the Department of Banking Operations and Development (Bombay Regional Office) and in the Legal Department. The study group constituted for computerisation of legal work in the Reserve Bank, Commercial Banks, and Financial Institutions has submitted its interim Report.

#### Office aids and Equipments

17.11 Four facsimile machines were installed, one each in three Central Office departments, namely

Department of External Investment and Operations, Exchange Control Department and Personnel Policy Department, and in the New Delhi Office. The facsimile machines will also be installed at Madras and Calcutta shortly.

#### C. D. Deshmukh Memorial Lecture

17.12 In the Chintaman Deshmukh Memorial Lecture series, instituted by the Reserve Bank in memory of the late Dr. C. D. Deshmukh, the first Indian Governor of the Bank, the sixth lecture was delivered by Mr. E. Gerald Corrigan, President, Federal Reserve Bank of New York, on January 11, 1990, in Bombay. Mr. Corrigan spoke on 'Global Economic Prospects at the Turn of the Decade'.

#### 18th SEANZA Council of Governors' Meeting

17.13 The 18th SEANZA (South East Asia, New Zealand and Australia) Council of Governors' meeting was held in the Reserve Bank at Bombay on October 20, 1989. The Council considered the Report of the Directing Staff on the 17th SEANZA Central Banking Course, presented by the Reserve Bank of Australia which conducted that Course in 1988. The Council, inter alia, took decisions regarding the broad subjects for the 18th SEANZA Central Banking Course which is scheduled to be held at Bombay under the auspices of the Reserve Bank in October—December 1990.

#### History of Reserve Bank

17.14 The History of the Reserve Bank of India, covering the period 1935—51, was published in March 1970. That volume covered preparatory years pre-1935 till the commencement of the era of economic planning in the country. The Bank has now decided to bring out further volumes covering the developments since 1951 and up to 1981. For this purpose a separate History Cell has been set up. The Bank has since set up a Committee of Direction to guide and oversee the history compilation work.

#### Indira Gandhi Institute of Development Research

17.15 The Indira Gandhi Institute of Development Research, set up by the Reserve Bank in 1987 as part of the commemoration of its Golden Jubilee, carried on work on a number of research projects and also conducted workshops, conferences and seminars during the year under review. Its project on 'Methods of Planning and Policy Analysis' is a major research activity which focuses on developing integrated approaches to planning and policy formulation for mixed economies and identification of specific policies relevant for the fulfilment of planning targets. Other research projects include 'Alternative Strategies of Development', 'Redistributive Policies and Food Policy', 'Energy Systems Studies', 'Technology Assessment', 'Environmental Issues', and 'Comparative Studies'. Under the broad themes of these projects, work is also continuing on Demand System Studies, Studies on Agriculture, Energy Policy Studies, Studies on Taxes, Subsidies, Prices and Equity, Studies on Consumption Survey, Industrial Policy Studies, Monetary Economics and Study on Priority Issues and Policy Measures to Alleviate Rural Poverty.

#### Bankers Training College (BTC), Bombay

17.16 The MTC introduced a number of new programmes in the areas of application of statistical



methods, service area approach, negotiating skills, counselling, 5-years action plan for banks, transactional analysis for trainers, import-export financing, non-traditional areas of commercial banking and housekeeping programme for senior officers of the Bank. Officials of foreign banks also participated in programmes such as Central banking and foreign exchange. Computer inputs were also introduced in most of the programmes to facilitate dissemination of knowledge relating to computer applications in the banking industry. With a view to propagating the use of Hindi as the medium of instruction, the college conducted as many as 18 programmes through the medium of Hindi.

17.17 During the year, the College conducted 93 programmes with 1,854 participants, bringing the total number of participants trained at the College since its inception in 1954 to 39,293.

#### Reserve Bank Staff College (RBSC), Madras

17.18 The RBSC continued to conduct during the year, broad spectrum programmes which included intensive Induction Programmes for newly recruited officers in Grades 'A' and 'B' including Assistant Security Officers and Research Officers in Department of Economic Analysis and Policy and Department of Statistical Analysis and Computer Services, Development Programme for the promotee/merit officers and functional programmes in specific work areas. The College also provided channel time for conduct of workshops for officers of Inspection Department and for Currency Chest Inspectors/Auditors. The new programmes initiated by the College covered the areas of investment and funds management, financial services, housing finance and customer service. During the year, the College conducted 65 programmes, imparting training to 1,349 officers, raising the total number of officers trained since its inception in 1963 to 25,547. Officials of several foreign banks also participated in some of these programmes.

17.19 The Staff College celebrated its Silver Jubilee with a function on July 7, 1989. Governor of Tamil Nadu was the Chief Guest. A book on the history of the College entitled 'Reserve Bank Staff College—Evolution and Development' was released. College of Agricultural Banking (CAB), Pune

17.20 The College continued to cater to the training needs of personnel of co-operative banks, commercial banks and regional rural banks, NABARD, Reserve Bank, DICGC, Government officials and also South Asian and African countries in the field of agricultural finance, rural banking and allied subjects. During the year, the College introduced several new programmes, including Service Area Approach, Block Credit Plans and other issues, preparation of credit plans, programmes of Chairpersons of women co-operative banks and financing of non-farm sector activities in rural areas. The College conducted 22 programmes through the medium of Hindi. During the year, the College conducted 126 programmes imparting training to 2,742 officers, raising the total number of officers trained since its inception in 1969 to 35,980.

#### Zonal Training Centres

17.21 The Zonal Training Centres (ZTCs) of the Bank, at Byculla (Bombay), Calcutta, Madras and

New Delhi continued to cater to the training needs of the Bank's Class III & Class IV staff. Programmes on Computer and Customer Service were introduced during the year. Two programmes for Class IV staff were conducted through the medium of Hindi at ZTC, New Delhi. During the year, 1,395 Class III and 367 Class IV staff received training, raising the total number of staff trained by the ZTCs to 36,331 and 2,457 respectively.

#### Training in Commercial Banks

17.22 Under the scheme of training of the Bank's officers in commercial banks introduced in 1986, of the 38 officers deputed in the second batch for training, 34 have completed their programme of training during the year, and the others would be completing it shortly, the third batch of 40 officers have also been selected for training during this year, of whom seven have commenced their training. Of the four senior officers selected during the year for in-depth exposure in key departments of commercial banks, two have completed the assignment, one is undergoing training and the fourth will commence training shortly.

#### Deputation of Staff for Training in India and Abroad

17.23 The Bank deputed 338 officers to participate in training programmes, seminars and conferences organised by management/banking institutes in India. Two officers are currently attending the M. Phil course in Applied Economics at the Centre for Development Studies, Trivandrum. The Bank also deputed 28 officers for training and study to banking and financial institutions in the USA, UK, Switzerland, West Germany, Japan, Singapore and South Korea.

17.24 Under the scheme for award of scholarships to the Bank's officers for higher studies abroad, formulated as a part of the Golden Jubilee Celebrations of the Bank, three officers proceeded for higher studies at various institutions abroad.

#### Training Facilities to Officers of Foreign Banks

17.25 The Bank continued as before to extend training and study facilities to officials from foreign central and commercial banks, on request. In all 45 foreign officials 10 from Namibia, five each from Bhutan and Afghanistan, four each from Kenya and Somalia, three each from Zambia and Abu Dhabi, two each from Sudan, Sri Lanka and Uganda and one each from Tanzania, Maldives, Malawi, Ethiopia and Gambia availed themselves of training facilities in the Bank during the year.

#### Training in Computer Technology

17.26 In view of the encouraging response from the staff the incentive scheme for acquiring computer qualifications has been revised and made more flexible, by allowing employees to enrol themselves in any institution they like, subject to certain stipulations.

#### Scheme of Incentives for Acquiring Professional Qualifications

17.27 Pursuant to the policy of encouraging staff members to acquire professional knowledge in different sphere, a scheme offering incentives to the employees who successfully complete the CFA Pro-

gratime conducted by the Institute of Chartered Financial Analysts of India ICFAI, Hyderabad has been introduced. Under the scheme, employees in Classes I and III are eligible for reimbursement of tuition fees, etc., paid by them to the ICFAI for successfully completing the CFA Programme within five years.

#### Employer-Employee Relations

17.28 The industrial relations climate in the Bank continued to be largely peaceful during the year under review. The only minor exception was when the Class IV employees went on a day's token strike. Wage settlements were signed by the Bank with the All-India Reserve Bank Employees' Association (Class III) and the All-India Reserve Bank Workers' Federation (Class IV) on August 29, 1989 and November 27, 1989, respectively. The Bank also announced revision of pay scales and other facilities for its officer staff during the year under review.

17.29 At a meeting with the representatives of the recognised associations of workmen employees and officers of the Bank convened on January 16, 1990, the Bank announced its decision to introduce a Pension Scheme in lieu of Contributory Provident Fund, on an optional basis, for the existing employees. The scheme, which will be effective from January 1, 1986, will be generally on the pattern of the pension scheme applicable to employees of the Central Government as revised by the Fourth Pay Commission. The modalities of the scheme are being worked out.

Employment to Reserved Categories—Scheduled Castes/Scheduled Tribes

17.30 Of the total direct recruitment in the Bank during the calendar year 1989, the representation to Scheduled Castes/Scheduled Tribes in different categories was as under :

Category/Class	Total No. of candidates recruited	Of them		Percentage	
		SC	ST	SC	ST
Class I	93	11	—	11.8	—
Class III	650	114	33	17.5	5.1
Class IV	465	69	128	14.8	27.5
Of whom					
Excluding Sweepers	373	35	123	9.4	33.0
Sweepers	92	34	5	37.0	5.4

17.31 This has raised the total number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees in the Bank as on January 1, 1990 to 2,262 and 678 in Class IV 2,310 and 1,045 in Class III and 458 and 102 in Class I respectively.

#### Ex-Servicemen

17.32 During the calendar year 1989, out of 650 and 465 vacancies filled in Classes III and IV, 94 and 114 were required to be reserved for Ex-Servicemen at the prescribed rates of reservation of 14½ per cent and 24½ per cent respectively. As against this, 60 vacancies in Class III and 67 in Class IV were filled by Ex-Servicemen raising the total strength of Ex-Servicemen to 744 in Class III and 1,008 in Class IV as on December 31, 1989. The Joint Chief Manager has been designated as the Liaison Officer for Ex-Servicemen to oversee the implementation of instructions from the Union Government relating to service conditions of Ex-Servicemen.

17.33 It was decided during 1989 that the minimum qualifications prescribed for general categories of Staff in Class IV be done away with for Ex-Servicemen, while the maximum qualification be relaxed. It was also decided during 1989-90 that —

- Matriculate Ex-Servicemen with 15 years' defence service would be considered eligible for recruitment to Class III posts for which graduation is the minimum educational qualification; and
- Weightage for blocks of 10 years' and 5 years' defence service would be given by relaxing two years and one year's service requirement respectively for promotion of the first time after joining the Bank within Class IV and within Class III and from Class IV to Class III and from Class III to Class I. The benefit of this weightage would also be admissible to them in respect of special pay granted to employees after 9 years' service.

#### Handicapped persons

17.34 During the calendar year 1989, 20 handicapped persons were recruited raising the total number of handicapped employees in the Bank to 377.

#### Promotion of Hindi

17.35 The Bank further intensified its efforts and introduced various measures to accelerate the use of Hindi. Notable among these were the efforts to vigorously implement the Annual Programme of the Union Government for 1989-90 to promote the use of Hindi. The Bank's Reports and publications, including the Annual Report, Report on Currency and Finance, Report on Trend and Progress of Banking in India, Reserve Bank of India Bulletin, RBI Newsletter and Credit Information Review were published bilingually. Translation into Hindi of as many as 42 out of 48 manuals has been completed.

17.36 During the year, two Hindi workshops for senior officers of the Bank and of nationalised banks as also two for faculty members of their training establishments were conducted under the aegis of Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad, which were attended by 33 senior officers and 33 faculty members. Besides, intensive training programmes for other officers to improve their proficiency of Hindi in noting, drafting and correspondence were organised in which 321 officers participated. A special full-time pilot programme of two weeks for senior officers who could speak Hindi but were unable to read and

write was conducted in which 11 senior officers participated. Sixty-six staff members were trained to prepare for the Prabodh, Praveen and Pragya examinations and 17 typists were trained for typing in Hindi.

17.37 The Bank published a compendium of instructions to facilitate progressive use of Hindi and compliance with Government instructions. With a view to making available up-to-date information relating to Rajbhasha a 'Reference Section' has been set up in Rajbhasha Division of Central Office for the benefit of the employees of the Bank.

17.38 The Official Languages Implementation Committees in the Central Office departments and at other offices of the Bank continued to be active and met regularly to monitor the progressive use of Hindi and oversee implementation of the provisions of the Official Languages Act, 1963 and the Official Languages Rules, 1976.

17.39 Competitions were organised among public sector banks for the Reserve Bank Shield for outstanding performances in the progressive use of Hindi in Regions 'A', 'B' and 'C'. Shields and prizes were also awarded for inter-office and inter-departmental competitions within the Bank. Various Hindi competitions and functions were also organised in the Bank on the occasion of 'Hindi Saptah' and Hindi Divas which falls on September 14 every year.

17.40 With a view to implementing the recommendations of the Bank's Official Languages Implementation Committee and the Government of India on the use of Hindi in training colleges/institutions run by public sector banks and the Reserve Bank, the Co-ordination Committee on Hindi Training constituted in 1988 continued to work out modalities, action plans etc. The thrust is on bringing out training material bilingually and conducting more training programmes through the Hindi medium. A 'Banking Paribhasha Kosh' covering terminology on subjects such as agriculture, social banking, foreign exchange, credit, etc., has been completed and is expected to be published shortly. Work is in progress to revise and update the 'Banking Shabdavali'.

17.41 With a view to encouraging original writings and disseminating know-how and terminology, etc., on banking and allied subjects in Hindi, the quarterly journal titled 'Banking Chintan-Anuchintan' was continued to be published. This journal, meant for circulation throughout the banking industry, has been well received. The Bank also continued to publish its house magazine, "Without Reserve", with appropriate coverage in Hindi.

#### Office Building and Residential Quarters

17.42 During the year a sum of Rs. 20.98 crore was spent on construction/acquisition of office buildings and residential quarters additions and alterations to the existing premises and purchase of land. The construction of office buildings at Cochin, with a built-up area of about 42,000 sq. ft. and Coin Vault at NOIDA (U.P.) with about 12,000 sq. ft., were completed during the year. Similarly, 365

Officers' Quarters and 918 Staff Quarters were completed at Trivandrum, Cochin, Bangalore, Calcutta Kanpur, Chandigarh, and Bombay. The work on construction of Office buildings at Bhopal, Jammu, New Bombay and that of a Bankers' Training College Complex at Hyderabad is in progress. Construction of 565 Officers' Quarters and 764 Staff Quarters are in various stages of progress at Bhubaneshwar, Madras, Calcutta, Lucknow, Ahmedabad and Bombay.

#### Holiday Homes

17.43 The second phase of construction of additional rooms for the Holiday Home at Udhagamandalam has been completed. Acquisition of property, for establishing a Holiday Home at Darjeeling is being pursued.

#### Housing Loans

17.44 During the year 1989-90 (July-June), housing loans sanctioned by the Bank to employees (societies/individuals) amounted to Rs. 10.45 crore as detailed below :

Category	No. of Societies	No. of Employees	Amount of loans (Rupees)
1	2	3	4
A. Co-operative			
Housing Societies	47	204	1,12,19,142
(i) Fresh Loans	18	58	54,67,828
(ii) Additional Loans	29	146	57,51,314
B. Individual loans sanctioned by Central Office		282	2,47,01,451
(i) Fresh Loans	—	202	2,33,86,649
(ii) Additional Loans	—	80	13,14,802
C. Individual loans sanctioned by Regional Offices		976	6,85,96,947
(i) Fresh Loans	—	902	6,65,15,062
(ii) Additional Loans	—	74	20,81,885
Total of A + B + C	47	1,462	10,45,17,540

17.45 The following major policy changes in regard to the Housing Loan Scheme were effected during the year 1989-90.

- Effective from April 1, 1990, the minimum eligibility period to avail of individual housing loan has been reduced to three years of continuous service including temporary service of an Earlier in the Bank. Earlier, the minimum eligibility period was five years.
- Search report covering a period of 30 years preceding the sale to the applicant employee/society was required to be submitted for acceptance of the title to the property. Effective from May 1990, the search period has been reduced to 12 years.

- (iii) Effective from May 1, 1990, maximum limit of housing loan for Class III and IV employees has been raised to Rs. 2,50,000 from the limit of Rs. 1,10,000 prevailing till then. Likewise, the maximum limit of loan for extension/enlargement has been raised to Rs. 60,000 for both the Class III and IV employees from their prevailing separate limits of Rs. 30,000 and Rs. 24,000 respectively.
- (iv) The loan amount above Rs. 1,10,000 would bear interest at the rate of 11 per cent per annum, effective from May 1, 1990, in respect of Class III and IV employees.

#### Central Board/Local Boards

17.46 On the expiry of his current term on February 3, 1990, Shri R. N. Malhotra was reappointed as Governor for a further period commencing on February 4, 1990 and ending with March 31, 1992. Dr. P. D. Ojha relinquished office as Deputy Governor on the expiry of his term on April 28, 1990. The Board wishes to place on record its appreciation of the services rendered by Dr. P. D. Ojha as Deputy Governor. Shri R. Janakiraman was appointed as Deputy Governor for a period of three years from May 16, 1990.

17.47 The Board regrets to report the said demise of Shri Chhedi Lal, Director, on October 6, 1989. Shri Chhedi Lal has been on the Central Board since July 1979 and the Board places on record its appreciation of the services rendered by him.

17.48 Shri G. K. Arora ceased to be Government nominee on the Central Board from January 9, 1990 on his relinquishing the post as Finance Secretary and Dr. Bimal Jalan, who took over as Finance Secretary, was nominated in his place from that date. The Board wishes to place on record its appreciation of the services rendered by Shri G. K. Arora.

17.49 There was no change in the constitution of Local Boards during the year.

17.50 Shri U. K. Sarma and Shri S. N. Bagai relinquished charge as Executive Directors on December 31, 1989. Kum. I. T. Vaz and Kum. V. Viswanathan were appointed as Executive Directors with effect from January 1, 1990.

#### Accounts

17.51 During the accounting year ended June 30, 1990, the Bank's total income amounted to Rs. 4,426.73 crore as against Rs. 4,030.25 crore for the previous year. Total expenditure of the Bank for the year amounted to Rs. 3,256.61 crore as against Rs. 3,005.12 crore for the previous year. Out of the net profit for the year of Rs. 1,170.12 crore (as against Rs. 1,025.13 crore for the previous year), contributions made to the National Rural Credit (Long Term Operations) Fund, National Rural Credit (Stabilisation) Fund, National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund and National Housing Credit (Long Term Operations) Fund for the year amounted to Rs. 375 crore, Rs. 10 crore, Rs. 525 crore and Rs. 50 crore as against Rs. 330 crore, Rs. 10 crore, Rs. 450 crore and Rs. 25 crore, respectively, in the previous year. The surplus profit set aside for payment to the Central Government out of the current year's profit is Rs. 210.12 crore as against Rs. 210.13 crore in the previous year. The rise of Rs. 396.48 crore in the income of the Bank from the previous year's level of Rs. 4,030.25 crore to Rs. 4,426.73 crore in 1989-90 was mainly due to increase in the interest earnings of the Bank which was largely offset by a steep increase in the interest payments to scheduled commercial banks on their specified additional cash balances under Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934, increased contribution to Statutory Funds and increase in establishment expenses.

#### Auditors

17.52 The accounts of the Bank have been audited by M/s. Khanna & Annadhanam, New Delhi, M/s. Amit Ray & Co. Allahabad, M/s. Mookherjee, Biswas & Pathak, Calcutta, M/s. Sorab S. Engineer & Co., Bombay, M/s. S. Viswanathan, Madras and M/s. S. K. Kapoor & Co., Kanpur. All the six auditors were reappointed by the Government of India for the current year. This year also, all the offices of the Bank were audited by the Statutory Auditors. For the purpose of audit, the offices of the Bank were divided into six zones and the audit fees paid per zone/per auditor were Rs. 90,000. An additional fee of Rs. 5,000 was paid to the Central Office Auditors for consolidation of branch accounts.

#### RESERVE BANK OF INDIA BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE, 1990

(Rs. in Thousands)

LIABILITIES	1989-90 Rs.	1988-89 Rs.	ISSUE DEPARTMENT ASSETS	1989-90 Rs.	1988-89 Rs.
Notes held in the Banking Department	18,21,19	19,05,64	Gold Coin and Bullion:		
Notes in circulation	50082,26,71	41639,52,50	(a) Held in India	280,66,99	274,27,76
Total Notes issued	50100,47,90	41658,58,14	(b) Held Outside India	—	—
			Foreign Securities	1564,05,75	1564,05,75
			Total	1844,72,74	1838,33,51
			Rupee Coin	38,96,21	60,18,20
			Government of India		
			Rupee Securities	48216,78,95	39760,06,43
			Internal Bills of Exchange and other Commercial Paper	—	—
Total Liabilities	50100,47,90	41,658,58,14	Total Assets	50100,47,90	41658,58,14

## BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
1	2	3	4	5	6
Capital paid up	5,00,00	5,00,00	Notes	18,21,19	19,05,64
			Rupee Coin	10,50	9,25
Reserve Fund	150,00,00	150,00,00	Small Coin	6,09	4,71
			Bills Purchased and Discounted		
National Industrial Credit (LTO) Fund	5150,00,00	4625,00,00	(a) Internal	—	—
			(b) External	—	—
National Housing Credit (LTO) Fund	125,00,00	75,00,00	(c) Government Treasury Bills	1796,88,08	3606,80,21
Deposits			Balances Held Abroad	2378,33,76	2918,80,18
(a) Government			Investments	32350,68,89	25652,79,96
(i) Central Government	140,86,96	81,68,58	Loans and Advances to:		
(ii) State Governments	16,66,85	15,51,22	(i) Central Government	—	—
			(ii) State Governments	10,64,00	54,17,00
(b) Banks			Loans and Advances to:		
(i) Scheduled Commercial Banks	26026,15,69	22057,44,62	(i) Scheduled Commercial Banks	2467,31,04	2174,24,01
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	464,62,78	482,32,26	(ii) Scheduled State Co-operative Banks	27,42,25	24,34,65
(iii) Other Scheduled Co-operative Banks	122,37,20	73,49,89	(iii) Other Scheduled Co-operative Banks	—	—
(iv) Non-Scheduled State Co-operative Banks	15,00,46	10,60,28	(iv) Non-Scheduled State Co-operative Banks	—	—
(v) Other Banks	96,93,35	29,79,01	(v) NABARD	2358,34,67	2277,68,00
(c) Others	2142,17,20	2192,92,22	(vi) Others	67,61,00	42,43,00
Bills Payable	112,86,03	112,39,05	Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund		
Other Liabilities	14170,38,53	13186,63,73	(a) Loans and Advances to:		
			(i) Industrial Development Bank of India	3822,30,46	3528,32,86
			(ii) Export Import Bank of India	625,00,00	530,00,00
			(iii) Industrial Reconstruction Bank of India	95,00,00	70,00,00
			(iv) Others	—	—
			(b) Investments in bonds/debentures issued by:		
			(i) Industrial Development Bank of India	—	—
			(ii) Export Import Bank of India	—	—
			(iii) Industrial Reconstruction Bank of India	—	—
			(iv) Others	—	—
			Loans, Advances and Investments from National Housing Credit (Long Term Operations) Fund:		
			(a) Loans and Advances to National Housing Bank	75,00,00	50,00,00
			(b) Investments in bonds/debentures issued by National Housing Bank	—	—
			Other Assets	2145,12,13	2149,21,39
Total Liabilities	48738,05,05	43098,00,86	Total Assets	48738,05,05	43098,00,86

1 Includes contingency accounts.

2 Includes Rs. 1413.77 crore (previous year Rs. 1592.31 crore). held abroad in foreign currencies

3. Includes amounts advanced to or deposited with scheduled commercial banks under special arrangements.

(Rs. Thousands)

## PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 1990

INCOME	1989-90 Rs.	1988-89 Rs.
Interest, Discount, Exchange, Commission, etc.	4426,72,53	4020,25,49
Total	4426,72,53	4020,25,49
EXPENDITURE		
Interest	2571,33,44	2312,49,89
Establishment	228,38,92	199,36,47
Directors' and Local Board Members' Fees & Expenses	5,4	4,65
Residence of Treasure	5,60,19	4,45,05
Agency Charges	261,25,11	259,41,83
Security Printing (Cheque, Note forms, etc.)	143,71,16	187,01,74
Printing and Stationery	2,68,50	2,15,99
Postage and Telecommunication charges	2,77,54	3,68,97
Rent, Taxes, Insurance, Lighting, etc.	13,10,37	10,40,75
Auditors', Fees and Expenses	9,65	8,75
Law Charges	22,46	7,14
Depreciation and Repairs to Bank Property	19,82,26	15,31,44
Miscellaneous Expenses	7,46,49	10,16,13
Total	3256,60,77	3005,12,00
Available Balance	1170,11,78	1025,13,49
LESS: Contribution to		
National Industrial Credit	525,00,00	450,00,00
(Long Term Operations) Fund		
National Rural Credit	375,00,00	330,00,00
(Long Term Operations) Fund <sup>a</sup>		
National Rural Credit	10,00,00	10,00,00
(Stabilisation) Fund		
National Housing Credit	50,00,00	25,00,00
(Long Term Operations), Fund		
	960,00,00	815,00,00
Surplus Payable to Central Government	210,11,78	210,13,49

1. After making the usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act, 1934.
2. These funds are maintained by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).

S.S. Ranade	R. Janakiraman	P.R. Nayak	C. Rangarajan	A. Ghosh	R.N. Malhotra
Chief Accountant	Deputy Governor	Deputy Governor	Deputy Governor	Deputy Governor	Governor

## REPORT OF THE AUDITORS

TO THE PRESIDENT OF INDIA

We, the undersigned Auditors of the Reserve Bank of India, do hereby report to the Central Government upon the Balance Sheet of the Bank as at 30th June 1990 and the Profit and Loss Account for the year ended on that date.

We have examined the above Balance Sheet of the Reserve Bank of India as at 30th June, 1990 and the Profit and Loss Account of the Bank for the year ended on that date and report that where we have called for explanation and information from the Bank, such information and explanations have been given and have been satisfactory. In our opinion and according to the best of our information and explanations given to us and as shown by the books of accounts of the Bank, the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and is properly drawn up in accordance with the Reserve Bank of India Act, 1934 and Regulations framed thereunder so as to exhibit a true and correct view of the state of the Bank's affairs.

M/s. Khanna & Annadhanam Auditors	M/s. Amit Roy & Co. Auditors	M/s. Mookherjee Biswas & Pathak Auditors	M/s. S. Vis- wanathan Auditors	M/s. Sorab S. Engineer & Co. Auditors	M/s. S.K. Kapoor & Co. Auditors
---	------------------------------------	--	--------------------------------------	---	---------------------------------------

Dated 16th August, 1990

[F. No. 19/15/90-B.O.I.]

M.S. SEETHARAMAN, Under Secy.